



भारत मे  
आर्थिक राष्ट्रवाद का  
उद्भव और विकास

दि मैकमिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड  
नई दिल्ली न्यू रोड बनारस मद्रास

समस्त विद्व म सहयोगी कंपनीया

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद  
अनुवाद डी आर चौधरी

प्रथम जगरजी सस्करण 1966

'दि राइज एंड ग्रोथ आफ इकनामिज  
नेशनलिज्म इन इंडिया वा अनुवाद

प्रथम हिंदी सस्करण 1977

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित

एम जी वसानी द्वारा दि मैकमिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड  
के लिए प्रकाशित तथा ग्रंथ भारतीय दिल्ली 110032 में मुद्रित।

B Chandra BHARAT MEN ARTHIK RASHTRAVAD  
KA UDBHAVA AUR VIKAS

## अनुसंधान परिषद की ओर से

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अनेक उद्देश्यों में एक है शोध की उपलब्धियाँ को उस पाठकवर्ग तक पहुँचाना जो हमसे यह अपेक्षा रखता है कि हम भारतीय भाषाओं में इतिहास संबंधी रचनाएँ तैयार तथा प्रकाशित करें। अंगरेजी भाषा के माध्यम से भारतीय इतिहासविद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पहुँच सकते हैं नाम और प्रतिष्ठा अर्जित कर सकते हैं, किंतु भारतीय पाठकवर्ग का यह छोटा अंश ही इससे लाभ उठा पाता है। शिक्षण और अनुसंधान के माध्यम के रूप में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग की प्रवृत्ति चल पकड़ रही है। ऐसी स्थिति में इतिहास की स्तरीय पुस्तकों की कमी गंभीर रूप से अनुभव की जा रही है। सबसे पहले हमें भारतीय इतिहास की ओर ध्यान देना है। अतः भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने कुछ गौरव ग्रंथों (क्लासिक्स) तथा इतिहास विषयक शोध की निर्दोष पद्धतियों पर आधुनिक और इतिहास की समकालीन प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करने वाली कुछ अन्य पुस्तकों का अनुवाद कराने का निश्चय किया है।

ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए किए जाने वाले राष्ट्रीय आंदोलन कई अवस्थाओं से गुजरा था। भारतीय नेताओं के आर्थिक विचारों से इस आंदोलन को नया आधार मिला जिसकी वजह से यह और ज्यादा सुदृढ़ हुआ। हमारे नेता आग्रहपूर्वक जिन आर्थिक विचारों को प्रस्तुत कर रहे थे उनमें धनोत्सरण (वैल्थड्रेन) का सिद्धांत प्रमुख था। इसमें इस बात की ओर इंगित किया गया था कि भारत का धन लगातार ब्रिटेन जा रहा था क्योंकि विदेशी शासकों के अत्यंत महंगे सैनिक तथा गरमनिक तथा का रखरखाव बहुत ही महंगा था जिसकी वजह से जनता के ऊपर कर्ज का दबाव बढ़ता जा रहा था।

भारतीय नेताओं ने लोगों के सामने ब्रिटिश शासन के औपनिवेशिक चरित्र को खोल कर रखा और उसके ऊपर कल्याणकारी राज्य का जो मुलम्मा बँदा था उसे पोछ दिया। ब्रिटिश शासकों ने इस मुलम्मे को बनाए रखने की जी तोड़ कोशिश की थी। इस वाद के चरण में पहुँचने पर आंदोलन को बाँकी बल मिला।

प्रस्तुत कृति समाचारपत्रों, पत्रिकाओं तथा अन्य विविध स्रोतों से उपलब्ध प्रमाणाँ के आधार पर भारतीय नेताओं की आर्थिक नीतियों का विश्लेषण विवेचन करती है। इनकी



आग चलकर स्वदेशी आदालत न सवया गिता तथा ऊ ग परागत प्रगत किया ।

पुस्तक का प्रवाशन पटना यूनिट के प्रयासा गत परिणाम है त्रिगत निग अनुगत  
डी० आर० चौधरी तथा अन्य मभी मत्वागिया न प्रति हम पापवाद गगत करता है ।

10 मार्च 1977

नई दिल्ली

रामारण शर्मा

अध्यक्ष

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद

## प्राक्कथन

भारत में ब्रिटिश शासन से मुक्ति की प्रक्रिया की शुरुआत पिछली शताब्दी के आरंभ में हुई। इस आंदोलन का अनेक उतारचढ़ाव देखने पड़े। इसमें बहुत से तत्व थे परंतु इसका मूल स्वरूप शांतिपूर्ण क्रांति का था। विदेशी प्रभुत्व की अग्रगति को रोकने का प्रथम उत्साह तथा आक्रमणशील साम्राज्य के पहले शिकार भारतीय रियासतों द्वारा विरोध जब नाम शेष रह गया तो उस समय पनपते शिक्षित नागर मध्यम वर्ग ने देश के प्रशासन में अपनी भावना के प्रदर्शन के लिए सांविधानिक आंदोलन का मांग अपनाया। उनकी गतिविधि का प्रमुख साधन सावजनिक प्रेस और राजनीतिक अथवा सामाजिक सङ्गठन थे जिनने मंच का उठाने जनता की भांगों को मनवाने के लिए और जनता के कष्टों को दूर करने के लिए उपयोग किया। लोकमत की यह प्रारंभिक अभिव्यक्ति प्रधान-रूप में बड़े बड़े नगरों तक ही सीमित थी और उसका एकमेव उद्देश्य अधिकारियों को आवदनपत्र प्रस्तुत करना ही था। यह प्रधान रूप से उस समय इंग्लैंड में व्याप्त उसकी न्यायवृत्ति तथा उदारतावाद की भावना को जगाने के लिए उसकी आत्मा के प्रति एक प्रकार से विश्वास को लेकर किया गया निवेदन मात्र था। बहुत सारे भारतीय प्रशासक उपयोगितावाद के विचारों से अत्यंत प्रभावित थे और भारत में लोकहित के ही राज्य का एकमात्र उद्देश्य होने के सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखते थे। फिर भी उनकी नीतियों का निर्धारण भारतीय जनता के हित की दृष्टि से न होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के लाभ के उद्देश्य से ब्रिटिश उद्योग के विकास की दृष्टि से और ब्रिटिश जनता की समृद्धि और प्रगति की भावना से ही होता था। भारत की अधिकांश जनता की आर्थिक दशा पर इनके अपरिहाय प्रतिघातों का होना स्वाभाविक ही था। भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आने लगा था। उसकी आत्मनिर्भरता और स्वस्थ संतुलन तथा अतीत में पश्चिम की दृष्टि से भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाला कृषि और उद्योग के मध्य सम्बन्धन सीधेता से नष्ट होता जा रहा था। भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटन की अर्थव्यवस्था के अधीन हो गई और उसकी कृषि का प्रमुख उद्देश्य इंग्लैंड के पनपते उद्योग की आवश्यकता के लिए कच्चे माल की पूर्ति करना रह गया। भारत के औद्योगिक

के तियाता का स्थान बपान और गान्धारी १३ तिया । अत्र आशा भी वेया मां पांी तथा अय गिनी चुनी विलाम सामग्रिया तर ही भीमित १३ १३ । आशा म्या भी मृी वस्त्र और अयान्य दनिक् उपभाग की उत्तातित वस्त्रुआ १३ तिया । प्रिग ध्याता की प्रवृति म यह परिवतन भारतीय उद्योगा व द्वाग का वृधि पर वही निरता का तथा इस सबके फास्वरूप भारत के तजी म तिधाता की ओर धरेन जाने का मृाव था । १३ परिस्थिति के प्रति जागरूकता १३ वारमत्त का अभिपरित म एत प्रयत्न परिग्रन मा दिया । अत्र तमश डाट मोट प्रशामनिव गुधारा व निग विनाम ओर मृु प्रायतात्रा का स्थान शामका की नीतिया जोर उाके ध्यवहार की उद्देश आनागत न १३ तिया ।

1857 व विद्रोह को मं वगिनि तथा अफगणशाहा द्वाग अमातीय वृम म श्वाण जान मे वृछ समय के लिए राजनीतिक अभिपरिति जवस्य पयध्दष्ट १३ मं भी परतु विद्रोह की ज्वाला भीतर ही भीतर गुनगनी रही तथा गजरीतिर सम्घात्रा व जम तथा पनकारिता उद्योग के विनाम के रूप म भारतीय जाता १३ अपन आशा का अतिरता किया । उमका आकार निरतर वन्ता गया ओर अपनरतापी की श्योमिया मा वनाहुनर प्रस एक्ट जस हथकड उसरी प्रगति को रानन म गफन नही १३ पाण । गमातरपना और पत्रिकात्रा की सम्घा म अभूतपूव वदि हुई और उनम म अधिराण १३ अपन अपन तालम जनता (विशेषन नागर मध्य वग) की भावनात्रा का अधिपरिति दन १३ निग अधिपर कर दिए । विभिन्न प्रातीय केंद्रों म अनक राजनीति मगठना की भी म्यापता ही गई । इनमे मे वहुता न अखिन भारतीय प्रवृति की ममस्यात्रा पर विचार करन का व्यापक दृष्टिाण अपनाया । उनीसवीं शताब्दी की आठवां शताब्दी म निग जा रह प्रयत्ने १३ परिणाम गत शताब्दी की नवीं दशाब्दी के मय म भारतीय राष्ट्रीय वाग्नेम का म्यापता के रूप म सामन आया । इस मस्या न भारतीय जनता की क्षिनायतों का वाणी देने के लिए तथा सरकार की प्रवृति म क्रातिकारी परिग्रन लाने की दृष्टि स आर्थिक तथा राजनातिव भाग पेश करन के लिए एक निरतर मशकन हाने वाला मच जुटाया । इन मगठना का एत प्रमुख उद्देश्य मवधानिक विकास के लिए जोर उमके फनम्बमण राज्य की नीतिया के निवारण जोर कायावयन म भारतायो के अधिवाधिन भाग लन के लिए सरकार पर दवान गलना था । तत्कालीन परिस्थितियो को देखन हुए मवगाधारण के लिए तथा जनता के विशान समुदाय के लिए इन राजनीतिक मगठनो के साथ श्वेच्छापूवक सजधित होना कठिन था जोर जनता के व्यापक रूप से भाग न लेने के कारण सरकार पर वाछनीय रूप से दवान नही डाला जा सकता था । इस प्रकार सरकार अपक्षावृत्त रूप म उच्च वग के राजनातिवो के तर्कों म अग्रभाधित ही रही । जनता कोरी सवधानिन प्रगति के वायक्रम स विशेष रूप से पभाधित न हा सकी क्यकि यह सस्थाओ की प्रतिनिधिरूपता और सवाओ व भारतीयकरण की दृष्टि स काई विणेप अथ ही नही रखता था । लाग भारी कर, वषारी तथा जीवनोपयागी वस्तुआ के अभाव से पीडित थे आर यह सब उम समय की भारताय अयवस्था की निरतर विशपताए थी । आर्थिक अपील ही एक एगी अपीन थी जो इन लागों की मूछा को भग कर सकती थी । उनके सक्रिय और स्पष्ट समथन के बिना भारतीय राजनीतिक आगलन का दुबल रह जाना निश्चित था । अत उनकी अममण्यता

को दूर करने के लिए तथा सरकार पर भारी दबाव डालने के लिए राजनीतिक नेताओं को अपना सारा ध्यान जनता की दीन हीन दशा की ओर लगाना ही पड़ा। उन्हें लोगों के कष्टों के निदान तथा उनके आर्थिक कष्टों के लिए उत्तरदायी तत्वों का विश्लेषण करना ही पड़ा। भारतीय नेताओं के आर्थिक विचारों का उदय इसी सदम में हुआ।

दादाभाई नौरोजी ने इस दिशा में नेतृत्व दिया तथा 19वीं शताब्दी के अंतिम कुछ दशकों में आर्थिक चिंतन में कितने ही प्रतिभाशाली आर्थिक विचारकों ने उनका अनुसरण किया। रानाडे, जोशी, गोखले, जी०एस० अय्यर, वाचा और दत्त आदि कुछ ऐसे प्रतिभाशाली महानुभावों में से हैं जिनका योगदान बहुमुखी है और जिन्होंने उस समय के आर्थिक चिंतन की रूपरेखा निर्धारित की। भारतीय पत्र-पत्रिकाओं ने इस कार्य को बड़े उत्साह के साथ अपने हाथ में लिया और सारे देश में विभिन्न मंचों से इसका प्रचार-प्रसार किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्तावों और भाषणों में इन्हीं लोगों के विचारों को मूल रूप मिला। इस प्रकार इन नेताओं के आर्थिक विचारों ने पनपते हुए स्वदेशी आंदोलन को पुष्ट किया, उसके लिए नया आधार जुटाया और उस सुदृढ़ बनाया। उस समय मूल प्रश्न भारत में ब्रिटिश राज्य के समाघात और उसके परिणामों का था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश राजनीतिज्ञों और भारत की जफ़्फ़रशाही ने गोरों के उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर बल देते हुए यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि भारत ने ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत सबसे बड़ी प्रगति की है और इसलिए यहाँ साम्राज्यवादी प्रभुत्व उचित है। सभी यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों ने क्षेत्रीय अधिकार और विश्व में अपने प्रसार का मुख्य उद्देश्य वहाँ की जनता को सुसभ्य बनाना घोषित किया था। इस प्रकार उपनिवेशवाद को एक नए रूप में और एक नए ढंग से पेश किया जा रहा था जबकि आर्थिक शोषण की उसकी मूल प्रवृत्ति में नाममात्र का भी अंतर नहीं आया था। भारत में भी ब्रिटिश राज्य के समर्थक इसकी विभिन्न देनो—शांति, नवीन शिक्षा और इन सबसे बढ कर रेलों सड़कों तथा अर्धलाक कर्मों के विस्तार के रूप में अभिव्यक्त देश की बढ़ती हुई संपन्नता के लिए अंगरेजी राज्य का गुणगान करने लगे। वृद्धों ने मुगल शासनकालीन और 19वीं शताब्दी की (ब्रिटिश शासनकालीन) आर्थिक स्थितियों के अंतर का विवेचन किया और तथ्यों को तोड़मरोड़कर प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश राज्य में वर्तमान आर्थिक दशा का स्वर्णिम चित्र प्रस्तुत किया। नरम दलीय नेता सांस्कृतिक संपर्कों से प्रभावित थे तथा ब्रिटिश साम्राज्य की ससदीय शासन प्रणाली के प्रति आदर का भाव रखते थे। इसके अतिरिक्त देश में ऐसे बहुत लोग थे जो ब्रिटिश शासन के परिणामस्वरूप देश में हानि वाली समृद्धि के प्रचार से प्रभावित थे। ब्रिटिश शासन से मुक्ति के आंदोलन की किसी प्रकार की प्रगति और सफलता के लिए इन भ्रंत धारणाओं का निमूल करना आवश्यक था। दादाभाई नौरोजी और अन्य नेताओं का उल्लेखनीय योगदान यह था कि उन्होंने इस भ्रम को तोड़ा और ब्रिटिश राज्य की वास्तविकता को उजागर किया। इस कार्य को करते हुए उन महानुभावों ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया और सुदृढ़ आधार दिया और उपवादी दृष्टिकोण के विकास में सहायता दी जिसने स्वराज्य का माग तयार किया।

भारतीय नेताओं के आर्थिक विचारों का मुख्य विषय था, निवासी सिद्धांत, जिसका

सीधे-सादे गन्तम अनिप्राय था, आयातो पर विद्यापी अधिरता क म्पम तथा विद्वशी राज्य क अत्यन्त महग मन्त्र और ताम्रिण प्रतामरात्र की व्यवस्था के निम्न भारत म द्गुनड का निरन्तर धन की विवागी जा एक प्रकार का गिराज था । उन्नी इग नय्य का भो उतामर तिया मि भारतीय पर शता अपन गन्त का अय तब प्रतुर मूय्य अदा कर तक हैं क्याकि क्षत्रीय विन्तार क निण निण गण मुद्धो एा तार भाग्रीय विा व्यवस्था की ही ग्गना पडा है । वदत हुए मरकारी ऋण जाता के निण भागी बान बन गए है । उन्नी प्रकार ग्गज र ग्गगान क म्पम रन गया का विन्तार तथा अन्व्याय महग मरकारी तार निर्माण भी भारतीय राजग्य क निण ग्गुन हुए भार मिड हा ग्ग है । रनें भी साम्राज्यवा की अपनी सुरक्षा का एक माधन है । जग भारताय दृष्टि का जनता का पट नरन के निण निचाई की आवश्यकता है का ग्गिण पूत्रीपी और द्गुपा उद्याग भारत का जकात से छुटकारा दिनात क निण ग्ग गया क मीना-मीन विन्तार मे ला हुए है । दन नताआ क विन्तार के अगुमार गिरागा क उन्नगनीय ग्ग प, ग्ग प्रभार द्गुलड का भजी जान चाली ग्गिण जपिवागिया और द्गुपागिया की बानें तथा गंनिर प्रभार । इस विषय का भारतीय गानों की जा के निण नियुक्त रायस बमीगन क गामन गामन न वपी ही यापयता से य निदेंग ररत एग प्रगुन किया कि भारतीय गाना का दाना स्थाना पर नारा की मीमाआ प तथा अमग गानो उद्देया क निण ही उन्वो किया जा रहा है । यह निनामी भारत की दरिद्रता का कारण है, भारत के आदिग विनाग का शिथिल बनान का तथा औद्योगिक विनाग को पगु चान का कारण है । भारतीय नताआ द्वारा प्रहार का दूसरा लय्य ग्गिण सरकार की सीमा गुन्व नीति थी जान कंत्रल अन्वयपूण ही थी प्रत्युत दग क शिगु उद्याग का गला स्थान और कुटीर उद्याग की हत्या करन के निरिचत उद्देय से भी प्रगित थी । वदत की भावना ग क्गग पर सीमा शुल्क का लगाना और क्पास पर आयत गुल्क का हटना ग्गिण मूती वस्त्र उद्याग क ग्गिन म भारत क साथ निण जा रह अन्वय के प्रत्यग और सगष्ट प्रमाण थे । बार० मी० दन न कृपका के रग का चूसन वाली और लगानार अनाला को जम न्गर भारत की दरिद्र बनान वाली भारत सरकार की राजग्य नीति का नगा करन का बीडा उठाया । भारतीय जनता को अनामान्य रूप से प्रभावित करने चान ग्ग मगोन्म के तर्कों का वान की सरकार तिनमिता उठी ।

इस प्रकार इन प्रारभिक भारतीय अन्वयास्त्रिया न ग्गिण राज्य के उपनिवेशवाती चरित्र का नगा करक रख दिया । ग्गिण राजनीति का और अन्वयास्त्रिया न स्थिति की वास्तविकता को छुपाने का जो प्रयास किया था इन भारतीय ने उस पर पानी फेरत हुए ग्गिण राज्य के सोण कल्याणकारी नबली मुसोटा का उघाट कर रख किया । इसका परिणाम यह हुआ कि ग्गिण सरकार के विरुद्ध लेखो की भडी लग गई, जिनम भारतीय जनता के हिता की धार उपक्षा का सरकार पर आरोप लगाया गया । राजनैतिक आदो लन की परबर्ती उल्लेखनीय धाराओ न भी इसी सोन से उद्गम हुआ तथा विन्वो शासत के विरोध ने तजी पकडी ।

डा० विपनचन्द्र ने ममवालीन लेखा का उपयोग किया है तथा भारतीय आदोलन

के प्रारम्भिक नेताओं के आर्थिक विचारों के विश्लेषण के लिए समाचारपत्रों का प्रचुर प्रयोग किया है। इस प्रकार उन्होंने विकास काल के राष्ट्रीय आंदोलन को और उसके विकास को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुझे इस कार्य को व्यापक जनता के समक्ष प्रस्तुत करने में महान हृष का अनुभव हो रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह ग्रथ अर्थात् लोगो को उपनिवेशवादी अधीनता से स्वतंत्रता की ओर भारतीयों को उन्मुख करने वाली आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक स्थितियों के विश्लेषण के लिए प्रोत्साहित करेगा।

—विशेश्वर प्रसाद



## आमुख

यह पुस्तक 'भारतीय राष्ट्रीय नेतृत्व की आर्थिक नीतियाँ (1880 से 1905)' शोध प्रबंध का संशोधित रूप है, जो 1963 में दिल्ली विश्वविद्यालय में पी०एच०डी० की उपाधि के लिए स्वीकार किया गया था। स्वदेशी आंदोलन द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक ऊँचे और भिन्न स्तर तक ले जाए जाने से पहले राष्ट्रीय नेताओं की जो आर्थिक नीतियाँ रही, उन्हीं की जाँच करना इस पुस्तक का उद्देश्य है।

मैंने उन सभी व्यक्तियों को नेता माना है जिन्होंने आर्थिक प्रश्नों पर उभर रहे राष्ट्रीय जनमत को बनाने और दिशा देने का कार्य किया। इसी तरह मैंने इस अध्ययन में न केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रांतीय सम्मेलन, दूसरी लोक सभाओं एवं विधान परिषदों की कार्यवाहियों तथा प्रमुख राष्ट्रवादी व्यक्तियों के व्याख्यानो तथा रचनाओं पर, अपितु उन राष्ट्रवादी पत्र-पत्रिकाओं पर भी निभर किया है जो उन दिनों राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य मंच और जनमत के प्रभावशाली निर्माता थे। वास्तव में उस समय निरंतर क्रियाशील और सुसंगठित किसी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल के अभाव में, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तब तक इस प्रकार का संगठन नहीं बन पाई थी और तब तक विशाल ग्रौर आम सभाओं की परंपरा भी नहीं प्रारंभ हुई थी राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने ही दैनिक प्रशासन में विरोध पक्ष की भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा दूसरी राष्ट्रीय सभाओं के प्रस्ताव तथा उनकी कार्यवाहियाँ भी मात्र जितना राष्ट्रवादी समाचारपत्रों के माध्यम से छनकर जनता तक पहुँच पाती थी उसी सीमा तक जनमत को बनाने में मग्न हो पाती थी। यह भी उल्लेखनीय है कि उस समय की बहुत सी पत्र-पत्रिकाओं को उनके मालिक और संपादक व्यावसायिक दृष्टि से नहीं बल्कि स्वयं कुछ हानि उठाकर भी राष्ट्रवादी पत्र के रूप में निकालते थे। इतना ही नहीं बहुत से संपादकों का गहरी निम्न मध्यवर्गीय जीवन से घनिष्ठ संबंध था।

मैंने अंगरेजी या आंग्ल भाषा में प्रकाशित तत्कालीन अनेक प्रमुख राष्ट्रवादी पत्र-पत्रिकाओं का जिनमें मराठा, 'हिंदू' 'अमृत बाजार पत्रिका', तथा बंगाली सम्मिलित हैं मूल रूप में अध्ययन किया है। इसके अलावा भारतीय भाषाओं के सम्बन्ध में



अध्ययन के लिए मैंने विभिन्न प्रांतों के लिए अप्रकाशित 'रिपोर्ट्स आन द एडिटिव प्रेस' का उपयोग किया है। रिपोर्ट्स आन द एडिटिव प्रेस में भारतीय पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित सप्ताहकीय टिप्पणियाँ व समाचार-पत्रों में प्रकाशित या पूर्ण विवरण सरकार द्वारा किया जाता था। उनीसवीं शताब्दी के अंत तक, जब मॉरिस ट्रॉय रिपोर्टों में भारतीयों द्वारा उल्लेखित समाचारपत्रों की सामग्री का भी समाचार दिया जाना था, बर्कट रिपोर्ट में अंगरेजी और भारतीय भाषाओं में समाचारपत्रों की सामग्री रखी थी, जबकि अन्य प्रांतों की रिपोर्टों में केवल भारतीय भाषाओं के पत्रों की। ये रिपोर्टें पूर्ण रूप से सारणीबद्ध थीं और केवल स्थानीय समाचार या समाचारपत्रों के रूप में समाचारियों का ही उपबन्ध नहीं थी। उनमें सामग्री के निष्पत्ति एवं सही पुनः प्रस्तुतीकरण में उच्च स्तर का निर्वाह किया जाता था, हाना-विनाश रिपोर्टों, विशेषकर मद्रास की रिपोर्टों के विवरण पर्याप्त नहीं रहते थे।

प्रस्तुत कृति में उन तमाम व्यक्तियों, संस्थाओं और पत्र-पत्रिकाओं का राष्ट्रीय माना गया है जिन्होंने भारत को एक उभरते हुए राष्ट्र के रूप में देखा, जहाँ के लोगों के हित एवं नियति व्यापक अर्थ में सामंजस्य, जिनका अंतिम लक्ष्य अपने लोगों के लिए स्वायत्तता प्राप्त करना था और जिन्होंने सामाजिक विषयों पर मुट्ठी भर लोगों के दृष्टिकोण को अपनाएँ की बजाय देश की समस्त या अधिकांश जनता के दृष्टिकोण में सोचने की चेष्टा की। इस विषय में बसोटी इस बात का माना गया है कि वे क्या दावा करते थे, न कि इस बात को कि वे व्यवहार में क्या चाहते थे। इस दूसरे पहलू का गोप्य प्रवचन के मुख्य भाग में विस्तार से विवरण दिया गया है। दूसरे शब्दों में मैंने केवल उनके राष्ट्रीय मूल्यों का माना है जिन्होंने खुलेआम भारत को एक राष्ट्र या इस की जनता के सामंजस्य राजनीतिक भाग्य का मानने में इनकार किया, या उन्हें जो सुलामसुल्ला पाड़े स लागे व प्रतिनिधि बन कर सामने आए। इस प्रकार मैंने हिंदू-मुस्लिम और पारसी संप्रदायवादियों तथा 1888 के बाद के 'रास्त गोपतार' और 1901 के बाद के 'हिंदुस्तान जैसे समाचारपत्रों' को छोड़ दिया है। दि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन' तथा हिंदू पब्लिशिंग' को भी छोड़ दिया है क्योंकि 1881 तक वे अपना मौलिक राष्ट्रीय स्वरूप खोज चुके थे और सुलकर जमींदारों के हितों की बकालत करने लगे थे।

इस अध्ययन में मेरी रुचि इस बात में उतनी अधिक नहीं रही है कि किसी आर्थिक विचारधारा या नीति के जन्मदाता कौन थे जितनी कि उसके प्रचारकों तथा प्रचार की सीमा और उसके पीछे चलने वाले राजनीतिक आंदोलन के परिमाण और प्रकार में। पाठ टिप्पणियों में बहुत से उदाहरण एवं समाचारपत्रों का हवाला इसलिए दिया गया है ताकि इस प्रयत्न से उस काल में व्यापक रूप से प्रचलित कुछ नीतियों को प्रकाश में लाया जाए। इसी प्रकार मैंने यह जानने की चेष्टा नहीं की है कि अधशास्त्र के नियमों के अनुसार उक्त राष्ट्रवादी रुझानों की नीतियाँ सही थीं या नहीं। मैंने अपने आप को इस बात तक ही सीमित रखा है कि राष्ट्रीय नेताओं ने क्या कहा और कैसे कहा तथा हम इससे उनकी आधारभूत आर्थिक और राजनीतिक समझ तथा दृष्टिकोण के बारे में क्या जान सकते हैं। उपर्युक्त पहले काय को करने के लिए तो उस काल के भारत का एक बृहद्

आर्थिक इतिहास ही लिखना पडेगा और सम्भवत इससे भी बहुत कुछ अधिक करना पडेगा। मैंने समकालीन आर्थिक विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए गीण स्रोतों का उपयोग किया है।

निश्चय ही यह अध्ययन भारतीय राष्ट्रवाद के सांस्थानिक आधार के बारे में नहीं है जिसके मूल में वग तथा दूसरे मानवीय सबध होते हैं बल्कि यह इसके सैद्धांतिक कार्यक्रम सबधों पहलुआ के बारे में है। या पहले को जाने बिना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा ज्ञान सम्भव नहीं है। फिर भी मैं आशा करता हूँ कि प्रारम्भिक राष्ट्रीय नेताओं के मानस में पडे आर्थिक यथायता के प्रतिबन्ध का यह अध्ययन उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि यद्यपि सामाजिक सबधों का अस्तित्व इस बात पर निर्भर नहीं होता कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं फिर भी इन सबधों के बारे में लोगों की सम्झ उनकी सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों के लिए निर्णायक होती है। इस प्रकार किसी आंदोलन के द्वारा यथाय को सम्झने, इसके लक्ष्यों का निर्धारण करने और सही दिशा में परिवर्तन लाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले राजनीतिक एवं बौद्धिक साधनों का अध्ययन उतना ही आवश्यक है जितना कि आंदोलन को जन्म देने वाली सामाजिक एवं आर्थिक शक्तियों का अध्ययन। अतः यह अध्ययन औपनिवेशिक आर्थिक सबधों के विकास या भारत की आधुनिक आर्थिक शक्तियों या वर्गों के उदय की रूपरेखा प्रस्तुत नहीं करता। हमारी समस्या 1880 से 1905 के बीच भारत में 'अंगरेजी साम्राज्यवाद के आर्थिक आधार एवं नीतियों की राष्ट्रीय बोध शक्ति के क्रमिक विकास के साथ साथ एक स्वतंत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सबधों के लिए एक कल्पित राष्ट्रीय कार्यक्रम के विकास का अध्ययन करना रही है। मुझे आशा है कि मैं उप परिणाम के रूप में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रदूतों की बौद्धिक क्षमता के स्तर और उनकी राजनीतिक एवं बौद्धिक ईमानदारी तथा साहस को प्रकाश में लाने में भी सफल हुआ हूँ। प्रस्तुत अध्ययन में उद्धरणों की अधिकता के मूल में राष्ट्रीय आर्थिक आंदोलन के प्रकार तथा विशेषता का सही सही रूप में प्रकाश में लाने की इच्छा ही निमित्त कारण रही है। प्रायः राष्ट्रीय नेताओं का किसी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का तरीका उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि स्वयं वह दृष्टिकोण। इसके अतिरिक्त उसे मूल रूप में प्रस्तुत करने से उनके अर्थशास्त्रीय ज्ञान का स्वरूप भी और अधिक अच्छी तरह सामने आ जाता है। हर हालत में, जैसा कि विंस्टन चर्चिल ने कहा है 'मौके पर कहीं-गई एक बात बाद में कहीं-गई हजार बातों के बराबर होती है'।

मैं अपने उन बहुत से मित्रों का अत्यधिक आभारी हूँ जिन्होंने इस कार्य में मेरी सहायता की है। दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष डा० विशेश्वर प्रसाद का मैं कितना ऋणी हूँ, यह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस अध्ययन का आरम्भ मैंने पूरा उनसे प्रोत्साहन से ही किया। मुझे विचारों की पूरा स्वतंत्रता देते हुए उन्होंने धैर्य व प्रेमपूर्वक मेरा मार्गदर्शन किया है। उन्होंने उत्तरदायक इस अध्ययन का प्राक्कथन लिखने की भी कृपा की है। उनकी निरंतर बहुमूल्य समालोचना और सुझावों के बावजूद इसमें यदि बहुत सी गलतियाँ रह गई हों तो उसका एकमात्र कारण मेरे अपने ज्ञान की अपूर्णता है। मोहित सेन, बी० एम० भाटिया, सुलेख

मुप्ता, ओ० पी० तोगिन और गद्यगाथी भट्टापाय जग मित्रों का पांडुलिपि क बना ता पडा है और वामन्य मुभाय लिए हैं। मैं अपनी 1961-63 की एम० ए० बना का ऋणी हूँ माय ही विनोदवार श्री अजितगुमार गुप्त का भी, जिन्होंने प्रायः प्रथम के अन्तिम रूप से टरण मवधी आता छोट भाग काय किए तथा भर साय मगातर धयपूर्वक विचार विमर्श किया।

मैं अपना राजज हिंदू वाचक, के अधिचारिया का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे काय के अध्ययन के लिए अवसरान दिया तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिचारिया का भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे सार्वजनिक पाठशाला द्वारा शिक्षा विभाग को शिष्ट गण अनुदान म मे विभावृत्ति प्रदान की।

मैं इस अवसर पर हिंदू वाचक पुस्तकालय (दिल्ली), दिल्ली मुनियसिपल लाइब्रेरी (दिल्ली) दिल्ली स्कूल आफ इनामिग लाइब्रेरी (दिल्ली), गेंड्रल मेन्स रिपट लाइब्रेरी (नई दिल्ली) पालियामट लाइब्रेरी (नई दिल्ली), इण्डिया वाउमिग आफ बन्ड अफयस लाइब्रेरी (नई दिल्ली) एगियाटिव गोमादटी लाइब्रेरी (बम्ब) गायन स्मिंटयूट आफ इनामिग ऐंड पालियाम (पूना) परगुमन वाचक लाइब्रेरी (पटना), इण्डियन एसोसिएशन लाइब्रेरी (बलकत्ता), और मपरता ब्राह्मण गमान लाइब्रेरी (बलकत्ता) के पुस्तकालय तथा अय कमचारिया के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता चाहता हूँ। स्व० श्री हम्नत प्रसाद घोष ने मुझे पुस्तक, एम्पनेटो व मगाचारपना की कतरना के निजी संग्रह का प्रयाग करने की आना दी, श्री तच० सी० मित्रा ने अपने घर पर 'एन' पत्रिका का पढन, 'अमृत बाजार पत्रिका', 'हिंदू', व 'केमरी मराठा' ट्रस्ट के प्रवचना न इन समाचारपना की पुरानी फाइला को दया तथा कायस्थ सभा इलाहाबाद के अधि कारिया ने 'हिंदुस्तान रिव्यू और कायस्थ समाचार' की पुरानी फाइला के प्रयोग करने की आना दी। मैं विनोद रूप से इन सबका आभारी हूँ। मैं नेशनल आरनाइवज आफ इण्डिया नई दिल्ली और नेशनल लाइब्रेरी, बलकत्ता के कमचारिया को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बिना किसी सक्च के अपना सहयोग दिया।

अतः मैं अपनी धमपत्नी कया चद्र को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस पुस्तक को पूरा करने में हर चरण पर मुझे बहुमूल्य सहायता दी। उन्होंने पांडुलिपि के हर पन्ने को पडा, कीमती सुझाव दिए, आवश्यकता पडने पर मुझे प्रोत्साहन दिया तथा टाइप व प्रूफ-प्रति को ठीक करने में मेरी सहायता की। वास्तव में यदि भाषा एव छपाई की कोई गलतिया इस पुस्तक में रह गई हो तो इसके लिए मेरे साथ वह भी जिम्मेदार हैं।

## अध्यायानुक्रम

भारत की निधनता	1
उद्योग एक	51
उद्योग दो	82
विदेश व्यापार	126
रेलें	152
शुल्क पद्धति	193
मुद्रा और विनिमय	241
श्रम	286
वृषि एक	349
वृषि दो	387
लोकवित्त एक	442
लोकवित्त दो	512
निवासी	572
भारतीय राजनीतिक अथव्यवस्था	636
आर्थिक राष्ट्रीयतावाद	660
ग्रथ सूची	680
अनुक्रमणी	691



## भारत की निर्धनता

‘यदि यह सिद्ध किया जा सके कि अंगरेजी शासनकाल में भारत भौतिक संपन्नता की दृष्टि में पहले की तुलना में और अधिक पिछड़ गया है—तो इसे मैं आत्मनिंदा मानने का एकदम तैयार हूँ और स्वीकार करता हूँ कि इस स्थिति में हम भारत का अपने नियंत्रण में रखने का कोई अधिकार नहीं।’ जाज हैमिन्टन भारत सचिव

‘भारत की घोर दरिद्रता इतनी अधिक उद्वेगजनक है कि किसी भी अन्य देश की सरकार इस प्रकार की स्थिति में इस प्रश्न को गंभीरतापूर्वक सोचने को विवश हाती, अन्यथा देश में त्राति हो गई हाती।’ जनरल आफ पूना सावजनिक सभा<sup>1</sup>

1857 के विद्रोह के तत्काल बाद की दशाब्दियों में शिक्षित भारतीयों, पनपती राष्ट्रीय भावना के उभरते नेताओं, की यह एक आम धारणा थी कि भारत में अंगरेजी शासन जनता के लिए काफी लाभदायक था। किंतु समय के बीतने पर और राजनीतिक चेतना तथा गतिविधि के बढ़ने के परिणामस्वरूप इन लाभों के महत्व तथा इनकी उपयोगिता में सदेह किया जाने लगा यद्यपि लगभग हमारे अध्ययन काल (1880-1905) तक भारतीय राष्ट्रीय नेताओं का एक बड़ा अंगरेजी प्रभाव में इस देश में आई कानूनी, सांविधानिक तथा अन्य भौतिकेतर परिणतियों का न केवल वाछनीय ही मानता था अपितु उन्हें अभिस्वीकार भी करता था। सामान्य रूप से यह धारणा बटती गई कि आर्थिक दृष्टि से अंगरेजी शासन का परिणाम निराशाजनक ही नहीं प्रत्युत कदाचित् हानिकारक भी था। 1867 में दादाभाई नौरोजी पहले ही कह चुके थे, ‘जनसमूह आज तक अंगरेजी शासन के लाभों को समझ ही नहीं पाया है।’ 1871 में उन्होंने लिखा—‘देश निरंतर दरिद्र तथा पगु बनता जा रहा है।’<sup>4</sup> 1865-66 में उड़ीसा में पड़े अकाल के साथ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में<sup>5</sup> भारत में पड़े दुर्भिक्षों की शृंखला ने देश को इस बुरी तरह से जकड़ा कि उसके भयंकर परिणाम ने अंगरेजों द्वारा स्वतः प्रस्तुत विदेशी शासन में शांतिपूर्वक तथा सामान्य गति से अनतिशील भारत के चित्र को भ्रमभोर कर रख दिया और साथ ही

## 2 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विराग

विवेक प्रजा की स्थिति की ओर ध्यान देने के लिए सामान्य का विवेक कर दिया।<sup>9</sup>

प्रारंभ में बहुत से भारतीय राष्ट्रीय नेताओं का विरागण था कि उनका मान और प्रतिष्ठा जाता भारत की मर्याद स्थिति से अग्रिम है। अतएव य प्रतिष्ठा जनता ससद तथा प्रशासनिक सेवा विरागण का मान कराने के लिए एक समझौते की विवेकण के प्रति उनका ध्यान आकृष्ट कराता है कि देश की गरी स्थिति की पूरी जान पकाने कराता चाहत थे।<sup>10</sup> इनके अतिरिक्त उत्तरी इलाके की भारतीयों की वर्तमान आर्थिक स्थिति अवश्य ही अपने सही रूप में जानी तथा आरी जाण और इन सदम में भारतीयों की आर्थिक स्थिति की यथाथ आवश्यकताओं का भी उपायपूर्वक स्वीकार कर लिया जाए ताकि सामान्य प्रभावशाली दम में दस समझौते और सुधारों का सर्वोत्तम रूप निवाले सके।<sup>11</sup> इनके अलावा भारतीय, अपनी एकता तथा राष्ट्रियता की भावना के प्रति सजग होकर, भारत में समकालीन ब्रिटिश अर्थनीतिया के प्रति अपने दृष्टिकोण का भी निश्चित करना चाहत थे। इसमें पूर्व भारतीयों का इन नीतियों के प्रति दृष्टिकोण तथा राजनीतिक एवं आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र में उत्तरी वायव्यीय ब्रिटिश नीतिया के मूल्यांकन और उनके आर्थिक परिणामों में ही प्रभावित हानी थी।<sup>12</sup>

1870 में भारतीय नेताओं में अपने देश की आर्थिक वृद्धि का गहरी छानबीन आरंभ की। 27 जुलाई 1870 को दादाभाई नौरोजी ने 'व्यापक-परिपद सदन' की बैठक में अपना प्रसिद्ध लेख 'भारत की आवश्यकताएँ और माधन' पढ़ा।<sup>13</sup> इस लेख में उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया 'क्या इस समय भारत अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त उत्पादन की स्थिति में है?' और फिर इसका उत्तर उन्होंने नकारात्मक दिया।<sup>14</sup> 1873 में अल्पजीवी बंगाली श्रमिक 'मुजर्जी मंगजीन' के पृष्ठों में भाग्यनाथ चंद्र ने भारत में अंगरेजों की आर्थिक नीति पर घातक प्रहार किया।<sup>15</sup> 1876 में दादाभाई नौरोजी ने अपना 'दी पावर्टी आफ इंडिया' नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित किया।<sup>16</sup> 1870 के अंत में महादेव गोविन्द रानाडे ने पूना से 'सावजनिक सभा' श्रमिक पत्रिका निवाली तथा जी० बी० जोशी के साथ लगभग दस दशकों तक भारतीय अर्थनीति का और व्यावहारिक रूप से उसके सभी अंगों का अत्यंत सजीव और सूक्ष्म विवेक प्रस्तुत किया।<sup>17</sup> सत्य तो यह है कि सामयिक विषयों पर लेख लिखनेवाले अत्यंत तत्कालीन भारतीयों ने भारत की आर्थिक स्थिति पर या तो लेख अथवा पुस्तकें लिखी, अथवा इस विषय पर सावजनिक मंचों या 'क्वैज' और 'कौंसिल' में भाषण दिए। इस प्रकार व्यावहारिक रूप से उस समय के राजनीतिक क्षेत्र का सारा साहित्य प्रधान रूप से आर्थिक विषयों से ही संबंधित था। 1901-1903 में आर० सी० दत्त के दो खंडों वाले बहुमूल्य ग्रंथ 'इकानामिक हिस्ट्री आफ इंडिया' ने इन छानबीनों को अपने चरम शिखर पर पहुंचा दिया। उपयुक्त ग्रंथ अंगरेजी राज्य में भारतीयों के व्यापार, उद्योग, कृषि तथा आर्थिक स्थिति आदि के इतिहास को प्रस्तुत करने के विशिष्ट उद्देश्य को लेकर कर्तव्यपालन के रूप में ही लिखा गया था। वस्तुतः उस समय पराधीन भारत की आर्थिक दुःशाला की गाथा का वर्णन करना तथा भारतीयों की दरिद्रता के गहरी जड़ पकड़े हुए कारणों का विश्लेषण करना कर्तव्य काम ही था।<sup>18</sup>

भारतीयों की जाच पड़ताल के आगे बढ़ते ही उनके कपटों की सूची अधिकाधिक लची होने लगी। आर्थिक स्थिति को बाले-घुघले रंग में रंगा जाने लगा और यह विश्वास फैल गया कि भारतीय मन्त्रिमंडल द्वारा भारत की अभूतपूर्व समृद्धि की चर्चा तथा भारत को गण्य माय समृद्ध दश बनाने का आदर्श वाक्य सत्य से बिल्कुल दूर है।<sup>19</sup> शीघ्र ही दरिद्रता का विषय भारत की सभी आर्थिक समस्याओं की चर्चाओं पर हावी हान लगाने और भारतीय नेता इस विषय का सर्वोच्च महत्व प्रदान करने लगे। दादाभाई नौरोजी ने इसे एक ऐसी शिखा, एक ऐसा तत्व तथा एक ऐसी कसौटी बताया जो अपने निपटारे में या तो ब्रिटेन को भारत के लिए वरदान बना देगी अथवा ईश्वर जाने कौन सी भयंकर विपत्ति उपस्थित करेगी।<sup>20</sup> इस दरिद्रता का जनका न इस प्रकार से परिभाषित किया 'आज की बहुत बड़ी समस्या' 9, 'सभी प्रश्नों का प्रश्न', 'भारत की समग्र आर्थिक दुर्दशा की मूल व्याधि', 'सर्वोच्च समस्या'।<sup>21</sup> 1901 में आर० सी० दत्त ने लिखा था, 'मेरे विचार में ब्रिटिश राज्य के किसी प्रदेश में कोई भी प्रश्न भारत की वर्तमान स्थिति की अपेक्षा अधिक विषम नहीं।' 4 जबकि उग्रवादी दल के एक प्रवक्ता विपिनचंद्र पाल ने उसी वर्ष अपने सघनपरक साप्ताहिक 'यू इंडिया' के प्रथम अंक में ही लिखा 'मर विचार में नवीन भारत को व्यग्र बनानेवाली सभी उलझनभरी समस्याओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक सपीडक आर्थिक समस्या है।' 5 न्यायाधीश रानाडे ने 1892 में अपने 'इंडियन पालिटिकल इकोनॉमी' निबंध में राजनतिक प्रश्नों की अपेक्षा आर्थिक समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया था।<sup>6</sup> अपने जन्मकाल से ही राजनीति में 'उग्रवादी' तथा 19वीं शताब्दी के प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय समाचार पत्र 'अमृत बाजार पत्रिका' ने 2 जुलाई 1885 के अंक में लिखा 'सत्य तो यह है कि यदि भारतीयों को केवल भरपट भाजन और कुछ अशा में 'याय ही उपलब्ध हो सके तो वे सतुष्ट होकर अंगरेजी राज्य के अधीन रहने को तयार हैं।' 7 भारतीय नेता भारत में अंगरेजी शासन के सभी कृत्य इस कसौटी पर परखत थे कि<sup>28</sup> वे करोड़ों भारतीयों की दशा को किस रूप में प्रभावित करते हैं? और क्या देश की प्रगति अतंत देश की आर्थिक स्थिति में किसी भी रूप में सुधार लाती है? 9

भारत में अंगरेज अधिकारी भी भारतीयों द्वारा निधनता की समस्या को सर्वोच्च महत्व देने के प्रति जागरूक थे और उन्होंने इस चुनौती को अपने प्रशासन की सफलता के मापदंड के रूप में स्वीकार किया। तदनुसार 15 अगस्त 1894 को 'हाउस आफ कॉमंस' में भारत सचिव सर हेनरी फौलर ने कहा

'मैं इस प्रश्न पर विचार करना चाहता हूँ कि सरकार ने भारत में विद्यमान अपने सारे शासन-तंत्र के साथ भारत की सामान्य समृद्धि का बढ़ावा दिया है या नहीं और भारत ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत एक प्रांत के रूप में अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में है अथवा बुरी? यही एक मापदंड है।'<sup>30</sup>

इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीयतावाद के प्रारंभिक काल में निधनता की समस्या भारतीय राजनैतिक मंच का केंद्रबिंदु बनी रही। भारत में ब्रिटिश शासन के प्रवक्ताओं और उभरते भारतीय राष्ट्रीय नेतृत्व ने केवल इसी एक समस्या पर दीर्घ काल तक बहस



#### 4 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विनाश

चलाई। तत्कालीन परिस्थिति में लोगों की रीति का अर्थ कोई भी ऐसा विषय नहीं था जिसे प्रारंभ में गणतंत्र और गणतंत्र के विचारों में अंतर गहरा मतभेद रहा हो और एकात्मिक विचार भी किसी अन्य विषय पर कम हुआ होगा, जिसे समाज अधिक प्राथमिकता से विचार को उठाया है।<sup>31</sup>

#### 1 क्या भारत दरिद्र था ?

एक गंभीर विवाद का प्रथम पक्ष निधनता के अस्तित्व का प्रश्न था। दत्तभाई नारायण भारत में व्याप्त अपरिमित निधनता के अस्तित्व का उद्घाटन करना चाहते प्रथम गणतंत्र मान्यता थे। उन्होंने 1876 में अपने विषय 'पावर्टी इन इण्डिया' में घोषणा की 'भारत एक प्रकार में गंभीर रूप में विपन्न है और दरिद्रता में दूरी हुआ है।<sup>32</sup> यद्युक्त भारतीय जनता को मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी उपयुक्त प्राप्ति नहीं है।<sup>33</sup> उन्होंने दरिद्रता को अपना 'विशिष्ट विषय'<sup>34</sup> बनाया तथा अपने 'जीवन के सत्य', भारत की वास्तविक स्थिति के प्रति अग्रजों जनता का जगाना, की पूर्ति के लिए वर्षों तक सार्वजनिक अभियान जारी रखा।<sup>35</sup> यद्युक्तवस्था के साथ यह महान वृद्ध पुष्प (प्रड आन्ड मैन) को मल होने की अपेक्षा अधिमाधिक उग्रात गणतंत्र का ही नहीं प्रत्युत हिमापत्त नापा का भी प्रयाग करने लग। 1881 में उन्होंने 'भारत की दुभाग्यवस्तु हृदय विदारक तथा खून खौलानवाली स्थिति' की भत्सना की<sup>36</sup> और दुर्गी भाव में उन्होंने कहा, 'इस समय जहाँ तक अग्रजों भारत का सम्बन्ध है, उसमें आज प्राच्य वैभव की बात जानकारिय बर्णन अथवा एक स्वप्न के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।<sup>37</sup> 1895 में उन्होंने घोषित किया 'भारत भूखा मर रहा है, अग्रापत्त भोजन पर रहने को विना भारतवासी हृदय से धक्के से भी मरने की स्थिति में है।'<sup>38</sup> 1900 में उन्होंने कहा, सत्य यह है कि भारतवासी एक प्रकार के दास हैं। उनकी दशा अमरीकी लोगों से भी बुरी है क्योंकि अमरीकी दासों के स्वामी अपनी संपत्ति के रूप में अपने दासों की देखभाल का बरतते हैं।<sup>39</sup>

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1886 में इस प्रश्न को उठाया और शीघ्र ही भारत में व्याप्त घोर दरिद्रता को अपने कार्यक्रम का एक अंग बना लिया।<sup>40</sup> 1891 में अपने सातवें अधिवेशन में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया 'पूरी पांच करोड़ जनता, जिसकी सख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है—एक शोचनीय स्थिति में घसी हुई भुखमरी के कगार पर खड़ी है और प्रति दशक लाखों व्यक्ति सचमुच ही भुखमरी के कारण मृत्यु का श्रास बनते हैं।<sup>41</sup> यह प्रस्ताव प्रतिवर्ष कांग्रेस अधिवेशन में बराबर दोहराया जाना लगा।<sup>42</sup> परवर्ती कांग्रेस सभासमितियों ने निधनता की समस्या का अपने वार्षिक भाषणों का अनिवार्य भाग बनाते हुए ही उनका उपसंहार किया।<sup>43</sup> राष्ट्रवादी लेखकों और वक्ताओं ने निधनता को अपनी रीति का विषय ही बना लिया।<sup>44</sup> उदाहरणार्थ 1881 के प्रारंभ में ही एक अग्रज लेखक ने 'जरनेल आफ दी पूना सावजनिक सभा' में घोषित किया, भारत की उजागर घोर दरिद्रता इतनी अधिक उद्देगजनक है कि किसी भी अन्य देश की सरकार इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार न करने की स्थिति में शक्ति का सामना करना पड़ती है।<sup>45</sup> भारत का प्रेस भी निरंतर प्रतिदिन प्रतिरूपताह भारत की आर्थिक

दुदशा तथा दुर्भाग्य के रोने को वाणी देता रहा।<sup>46</sup> भारतीयों की स्थिति का वणन इन शब्दों में किया गया 'दुर्भाग्यपूर्ण', 'गभीर', 'शोचनीय', 'दयनीय' तथा 'निरीह जतुजा से भी सवधा हीन और विवृत'। भारतीयों को इस रूप में चित्रित किया गया 'भुलमरी से अधमृत', 'जीव मात्र अवशिष्ट', 'साक्षात् रेंगती, मिमियाती तथा लुडक्ती दरिद्रता'।<sup>47</sup> कुछ समाचारपत्रों ने भारतीय दरिद्रता का सजीव चित्र पेश किया। उदाहरणार्थ वगला पत्र 'सुलभ दैनिक' ने भारतीय नागरिकों की स्थिति का वणन निम्नलिखित शब्दों में किया

'वह अपनी जीवनशक्ति खो चुका है, वह अपना प्राणतत्व नष्ट कर चुका है। उसका रक्त खूस लिया गया है और अधनीति की दृष्टि से दसा जाए ता वह वास्तव में हड्डियों का ढाचा मात्र होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वह आधा भूखा है, आधा नगा है। उसका दैनिक आहार थोड़े से चावल और वटूत से कदमूल तथा पौधों के पत्तों हैं। उसने जीवन में कभी स्वादिष्ट भोजन का आनंद नहीं लिया। उसके वस्त्र फटे हुए चीथड़े मात्र हैं। उसका निवासस्थान एक टूटी फूटी भापड़ी मात्र है, जो मौसम के बफ्टों से उसकी रक्षा ही नहीं कर पाती।'<sup>48</sup>

1896 में लोकमान्य तिलक द्वारा संपादित मराठी साप्ताहिक 'वेमरी' में 'गिवाजीज अटर मेस' शीर्षक से पद्य प्रकाशित हुए, जिनमें शिवाजी क्रिटिंग राज्य के अतगत देश की दुदशा पर इस प्रकार से शिकायत करते हुए दिखाए गए हैं हाय ! हाय ! यह मैं अपनी आंखों से देश की विनाशलीला को देख रहा हूँ हाय ! यह कैसा विनाश का ताडव नृत्य है। समृद्धि समाप्त हो चुकी है और उसके बाद स्वास्थ्य भी। देश में दुर्भाग्य का दानव सारे देश का अकाल के शिकजे में जकड़े हुए है।<sup>49</sup> इसी पत्र के 26 जनवरी 1893 के अंक में पंजाब के 'विक्टोरिया पेपर' में यहाँ तक दडतापूवक कहा गया कि भारतीयों को खाता पीता चतानेवाले भारतीय वस्तुतः देशद्रोही हैं।<sup>50</sup>

भारतीय राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान उस समय वग विशेष की दशा पर न हाकर सब-साधारण की दशा पर ही केंद्रित था। दश के विशाल जनसमूह की घोर दरिद्रता और उनकी आर्थिक दुदशा ही चिंता तथा विचार के विषय थे।<sup>51</sup> उस समय समाज के निम्न तथा मध्य वग के खेतियारों की स्थिति इस प्रकार थी, वे मुलमरी के शिकार थे, मिडुडवर ठठरी मात्र बन गए थे, उनके चेहरे झुरियों से भरे हुए थे। उन वेचाराओं को दिन निकलने से अधेरा होने तक उस थोड़े से भोजन के लिए कठोर श्रम करते करते थककर चूर हो जाना पडता था जो देश के अपक्षाकृत अधिक दरिद्र करांडा लोगों को सामान्य काल में भी बड़ी कठिनता में मिल पाता था। वे प्रायः आधे भूखे रहते थे तथा अकाल पडने पर ता कीडा-मकोडा के समान मरते थे। इस प्रकार देश की संपन्नता और विपन्नता की सही कसौटी के लिए जनता के अपेक्षाकृत निम्नवग को ही लिया गया।<sup>52</sup> कृषकवग के अतगत भी कृषि श्रमियों की स्थिति की ही तीव्र भत्सना की गई<sup>53</sup> क्योंकि ये ही लोग थे जो वष के प्रारंभ से अत तक कभी पर्याप्त भोजन उपलब्ध न होने के कारण दुखी रहते थे।<sup>54</sup>

राष्ट्रीय भावना के प्रमुख प्रवक्ताओं ने दरिद्रता की समस्या के कारण की खान

## 6 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास

म दगा कि विनय प्रणाली के दोषपूर्ण हानि प्रणाली उत्पादन की ही कमी है। उन्होंने अनुभव किया कि यह प्रश्न अपने आपमें चाहें बिना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो कि सभी लोगों के बीच वित्तों द्वारा और बिना ग्यात न मागी जाय विचारित की जाती है किनु इसमें भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या भारत का कुल उत्पादन वहां के निवासियों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है? 43 ममम्या को जब इस दृष्टिकोण से ज्ञात गया तो यह स्पष्ट हो गया कि भारत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त उत्पादन नहीं करता और यह सिद्धांत रूप में स्वीकार किया गया कि देश का उत्पादन देश में ही रचना चाहिए। 44 अतएव भारत के अधिकांश विचारकों ने भारतीयों की आर्थिक समृद्धि के लिए कुल उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। 45 निधनता का समझना के इस विविष्ट विश्लेषण ने भारतीय राजनीति के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राजनीति ने निधनता का व्यापक राष्ट्रीय प्रश्न बनाया तथा उमर उमरों की समुक्त मांग के प्रस्तुतीकरण हेतु विभिन्न वर्गों का विभाजित धरन के बन्धन उद्देश्य मंगटित करने में सहायता दी। 46 यह विश्लेषण ही भारतीय आर्थिक विकास के लिए विभिन्न भीमा तब अपवादालमय सिद्धांत (निम्नी भी अथ राष्ट्र द्वारा अपनाए गए मांग से भिन्न मांग पर उन्ना) के लिए उत्तरदायी था। बहुत सारे भारतीयों ने निधनता की समझना व आर्थिक विकास के अभाव के कारण का इन रूपों में देखा, उत्पादन क्षमता तथा मांगना में गिरावट और आर्थिक विकास की अपागृहृत निम्न दर। 47

कुछ समय तक तो ब्रिटिश प्रशासकों ने भारत की घणित तथा विषम दरिद्रता व अस्तित्व को स्वीकार तक नहीं किया। वनमान तथा भूतपूर्व सरकारी अधिनारिया ने वान्तधियता के विपरीत वृषवों की सम्पन्न तथा सतुष्ट दशा का चित्र ही प्रस्तुत किया। भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा, भारतीयों के चरम अभाव के सतत अभियाग से पीड़ित होकर 1885-88 में भारत के वायसरॉय लॉड डफरिन ने 1887 में भारतीय समाज के निम्न वर्गों की दशा को गुप्त सरकारी जाच पडताल का आदेश दिया। जाच-पडताल के प्रतिवेदन को प्रकाशित नहीं किया गया परंतु भारत सरकार ने 1888 में प्रातीय प्रतिवेदना के आधार पर एक प्रस्ताव प्रकाशित किया। प्रस्ताव के परिशिष्ट 'ए' में प्रतिवेदना का संक्षेप प्रस्तुत किया गया। 48 प्रातीय प्रतिवेदन इस बारे में एकमत थे कि भारत में साध पदार्थों की कमी कमी नहीं। किसानों के अपक्षाकृत निम्न वर्ग की स्थिति भी अभी कोई विशेष चिन्तनीय नहीं, 49 सामान्य वर्षों में तो लोगों के पास आवश्यकता से अधिक सामग्री संचित हो जाती है। 50 1893 में भारत सरकार इससे भी अधिक आशावादी थी। 1881-91 तक 'भारतीय जनता की आर्थिक स्थिति' पर प्रातीय प्रतिवेदना की समीक्षा करते हुए सरकार ने घोषणा की कि देश समृद्ध दशा में है। 51 तृतीय दशवापिक नैतिक तथा भौतिक प्रगति प्रतिवेदन (थड डिसिनिअल मारल एंड मैटिरियल प्रोग्रेस रिपोर्ट) (1891-92) में इस बात की पुष्टि की गई कि क्रमशः और निरंतर बढ़ते हुए जीवनस्तर के सदम में खेतिहर किसानों की दशा भौतिक दृष्टि से आत्मनिभरता की है। 52 गैरसरकारी ब्रिटिश लेखकों ने सरकारी मत की पुष्टि की तथा कम उत्तरदायी होने के कारण उन्होंने अपने मत को अधिक खुलकर अभिव्यक्त किया। 53

## 2 दरिद्रता का प्रमाण

भारतीय राष्ट्रीय नेताओं का भारत में व्याप्त दरिद्रता को प्रमाणित करने का सर्वाधिक प्रचलित ढंग था, ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के लेखों से अवतरण उद्धृत करना। इसका स्पष्ट उद्देश्य विरोधी का उसी के शस्त्र से परास्त करना था। अधिकांश उद्धृत दो अवतरण मर डालू हटर की पुस्तक 'इंग्लैंड्स वक् इन इंडिया तथा सर चार्ल्स एनोट की टिप्पणी' से प्रमत्त इस प्रकार थे प्रथम, 'भारत की चालीस करोड़ जनता अपयाप्त भोजन पर जीवन निवाह करती है।' द्वितीय, 'मुझे यह कहने में कोई सवाब नहीं कि आधी सेंटिहर जनता पूरे के पूरे बप के वीतन पर भी एक बार भरपट भोजन नहीं कर पाती।'<sup>66</sup>

प्रति व्यक्ति की आय के अनुपात के अका को प्रायः साध्य रूप में उद्धृत किया जाता था। कुल राष्ट्रीय आय का कुल जनसंख्या में बाटकर ये आकड़े निकाले जाते थे। इस अकेली अनुक्रमणिका में प्राप्त आर्थिक योगक्षेम की यूनता अथवा अभाव का उपयोग समन्दा को उजागर करने, उसे नाटकीय रूप देने तथा अय देशों के समकालीन निवासियों के स्तर से तुलना करने में किया जाता था।<sup>67</sup> इसके अतिरिक्त ये स्पष्ट तथा सुबोध अक अपने म तक का काम करते थे, ठोस आधार लिए ये आकड़े<sup>68</sup> ऐसा जादू का प्रभाव रखते थे कि इनसे अशिक्षित भारतीयों की जड़-बुद्धि भी सचेत हुए बिना न रह सकी।<sup>69</sup>

सांख्यिकी गणना के आधार पर आनुपातिक प्रति व्यक्ति आय का प्रथम विवरण प्रस्तुत करने का श्रेय दादाभाई नौरोजी को है। उन्होंने 1873 में सरल किंतु प्रभावी ढंग का प्रयोग करते हुए गणना की कि 1867-68 में ब्रिटिश भारत की साह करोड़ जनसंख्या की कुल राष्ट्रीय आय 3 4 अरब रु० है, अथवा दूसरे शब्दों में, इस देश की आय बीम रुपये प्रति व्यक्ति है।<sup>70</sup> दादाभाई अपने इस निष्कर्ष के मांड अनुमान से भली प्रकार परिचित थे परंतु उनकी दृष्टि में उह उस समय तक उपलब्ध सांख्यिकी सूचना का यही सर्वोत्तम सम्भव अनुमान था।<sup>71</sup> परवर्ती वर्षों में 'बीम रुपये प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का अक' राष्ट्रीय जादोलन का संगठन मंत्र बन गया तथा इस अक को विनाशात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए सभी राष्ट्रवादी समाचारपत्रों, पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा भाषणा में बड़े विस्तार से उद्धृत किया गया।

दादाभाई द्वारा प्रस्तुत चित्र इतना अधिक विनोदा था कि अधिकारियों के लिए उस समय दादाभाई द्वारा अपनाए गए उसी सरल तथा सुबोध सांख्यिकी आधार पर ही उमका उत्तर ढूढना आवश्यक हो गया। 1882 में भारत सरकार ने वित्त सदस्य मेजर ऐवेरीन तथा डेविड ब्रावर द्वारा तैयार किए गए तख्तीने को प्रचारित किया, जिसके अनुसार ब्रिटिश भारत की कुल आय सवा पाच अरब रुपये और प्रतिव्यक्ति आय 27 रु० कृतां गई थी।<sup>72</sup> 1901 में लाड वजन ने घोषणा की कि 1897-98 में प्रति व्यक्ति आय तीस रुपये थी।<sup>73</sup> जब विलियम डिग्वी ने सांख्यिकी तर्कों के शस्त्र से इस अक पर प्रहार किया,<sup>74</sup> तो भारत सरकार के लेखा विभाग के एक उच्चाधिकारी फ्रेड जे० १८०५ बचाव के लिए आगे बढ़े। उन्होंने 'रायल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी' के सामने 1902 में

## 8 भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदभव और विभाग

पण्डित जिनमल शर्मा की प्रेरणा से भारत की आनुमानिक प्रतिक्रिया आय 1875 में 30 5 वर्ष की मुद्रापर 1895 में 39 5 वर्ष की मर्यादित थी।<sup>3</sup>

भारतीय नेता प्रमुख रूप से भारत में व्याप्त विघ्नता का ही प्रमाणित करना चाहते थे जो कानूनी अथवा साम्प्रदायिक शक्ति के अभाव में उनकी कार्य प्रतिक्रिया थी। यही कारण था कि लार्ड रिडिंग नौकरों की अकांक्षित शक्ति पर विचार करने लगे थे और भीतर ही भीतर मानते हुए भी कि प्रति व्यक्ति आय का सम्बन्धी अधिकाधिक द्वारा नकार दिया गया और न-वर्तन नगरीना एक ही अर्थात् ही बुद्धि का जोच म पूरक म मुक्त है, दुर्गर वह अनिश्चित भी है फिर भी वे उस पर समान विचार-विमर्श करने का नकार ही नहीं करते थे और भी नकार भारत की धार प्रतिक्रिया प्रकट होती थी।<sup>4</sup>

प्रति व्यक्ति आय का अर्थ अर्थात् आय में भारतीय प्रतिक्रिया का स्पष्ट उद्घाटन है। भारतीय प्रवक्ताओं का मत था कि भारत की प्रतिक्रिया—तत्कालीन और माया—दाना रूप में है अतः भारत की वास्तविक प्रतिक्रिया की मही जानना ही एक ही तभी मित्त मकती है जो भारत की आय की तुलना दूसरे देशों की आय से की जाय, अथवा मानव की मूल आवश्यकताओं में उपाय अंतर सिद्धांत जाय, अतः उक्त यह सिद्ध करने का बीड़ा उठाया कि इन मानदंडों से भी भारतीयों की स्थिति अपना ही विषय ही सिद्ध होती है। उक्तने मयप्रथम भारत की प्रति व्यक्ति आय पर विचार किया जो उक्त उपरान्त अन्य देशों की आय से उक्त तुलना प्रमाण पर विचार दिया। उक्त मवधा प्रतिकूल था। यह तुलना एक बार फिर सामान्य के रूप में प्राप्त करने सुबोध साम्प्रदायिक शक्तियों में अभिव्यक्त की गई।<sup>5</sup> भारतीय नेताओं के अनुसार तानिनायक तुलना भारतीयों की आर्थिक स्थिति का अधकारमय रूप प्रस्तुत करती है। यह प्रमाणित करती है कि बुध्दिसिद्ध टर्की अतः देश भारत की अपेक्षा प्रति व्यक्ति दुगुना उत्पादन करते हैं अथवा भारत इंग्लैंड में उनीम गुना पीछे है, अथवा भारत का प्रतिक्रिया की तुलना में अत्यंत निम्नीकित तथा बुध्दिसिद्ध रूप से अपेक्षाकृत ममूद है। इस प्रकार हमारे अध्ययनकाल तथा उक्त परवर्ती वर्षों में यह एक व्यापक धारणा बन गई थी कि सम्य ससार में भारत प्रतिक्रियम देश है।<sup>6</sup> यह धारणा भारतीयों के हृदय में निश्चिन्ता के प्रति सन्तत तथा गहन चिन्तन की सूचक थी।<sup>7</sup>

भारतीय नेताओं ने अगला प्रश्न प्रति व्यक्ति आवश्यक व्यय का उठाया। उनके विचार में समस्या का मही रूप का दखने के लिए आनुमानिक आय की जाच वतमान जीवननिर्वाह व्यय के सदम में ही की जानी चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सामान्य भारतीयों की आय इतनी अपर्याप्त है कि वह वचारा मनुष्य हान के नाते अपन जीवन का अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर सकता। उनका यह भी विचार था कि भारत में निधनता की व्यापकता का विषय इस प्रकार अनाध्यात्म धरातल पर अवस्थित हो जायगा। फलतः भारतीय राष्ट्रवादियों में अध्यात्म के पठितों ने इस दिशा में जाच पडताल प्रारंभ कर दी। उन दिनों जीवननिर्वाह व्यय के अथवा पापण स्तर के अध्ययन का अस्तित्व ही नहीं था। इसके लिए प्रवामी बुलिया, अकाल वर्षों में लग भूमिका, अथमिकी, भारतीय सिपाहिया, खेतिहरा तथा जेल के कदियों के जीवन की

आवश्यकताओं जैसे बिखरे अनुमानों पर निर्भर करना पड़ता था। उपर्युक्त सभी श्रेणियों के लोगों की प्रति व्यक्ति आय इतनी कम पाई गई कि उससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं थी।<sup>81</sup> जेल के कदियाँ के भोजन और भरण-व्यय के सदन में प्रति व्यक्ति आय की तुलना भारत की स्थिति का सर्वाधिक प्रभावी विवरण था। दादाभाई नौरोजी ने विभिन्न प्रांतों के 1867-68 के प्रतिवेदन के आधार पर जेल में कैदी के भोजन और वस्त्रों पर सरकारी खर्च की गणना इस प्रकार में प्रस्तुत की<sup>82</sup>

सेंट्रल प्राक्सिञ्ज	31 ₹०
पंजाब	27 ₹० 3 आने
नाथ-वैस्ट प्राक्सिञ्ज	21 ₹० 13 आने
बंगाल	31 ₹० 11 आने
मद्रास	53 ₹० 2 आने
बवई	47 ₹० 7 आने

इस प्रकार की गणना कुछ एक अथ भारतीय लेखकों द्वारा भी की गई।<sup>83</sup> जेल के कैदियों पर होनेवाले प्रति व्यक्ति व्यय-अर्क के साथ प्रति व्यक्ति आय की तुलना से यह निष्कर्ष स्वतः स्पष्ट तथा आत्मनिरूपक हो गया कि अनुकूल ऋतु में भी भारत का उत्पादन एक अपराधी को मिलनेवाले भोजन की तुलना में भी पर्याप्त नहीं। फिर थोड़ी-बहुत बिनासिता के लिए सामाजिक और धार्मिक आवश्यकताओं के लिए, दुःख-सुख के अवसरों पर होनेवाले खर्चों के लिए तथा बुरे दिनों के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था एक पूर्ति आदि का तो प्रश्न ही कहाँ उठता है।<sup>84</sup> इस प्रकार के सही तार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारतीयों की बड़ी संख्या स्थायी रूप से भुखमरी की शिकार है और 'यूनतम जीवन स्तर से नीचे रहती है।

दादाभाई नौरोजी, जी० वी० जोशी, जी० सुब्रह्मण्य अय्यर तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने यह सम्यक् रूप से अनुभव किया कि 'औसत शब्द' एक आर्थिक कल्पना होने के कारण अपार दोषों को छुपा देता है, क्योंकि जनता का अपेक्षाकृत अधिक निधनवग तो औसत आय का पूरा भाग ले ही नहीं पाता है। औसत प्रति व्यक्ति आय में तो विदेशी पजीपतियाँ, सिविल सर्विस के उच्च वेतनभोगियाँ, विदेशी अधिकारियों, बड़े बड़े भूमिपतियाँ, शहरी व्यापारियों, नगर तथा ग्राम के मध्यवर्गीय तथा उच्च मध्यवर्गीय लोगों की आय सम्मिलित है। अतएव समाज के निम्न वर्ग की आय तो प्रति व्यक्ति औसत आय से बहुत नीची होगी और इस रूप में प्रति व्यक्ति औसत आय के अर्क से अनुमित स्थिति की अपेक्षा उन्हें अधिक कठिनाइयों का सामना करते हुए जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता होगा।<sup>85</sup>

इसके अतिरिक्त लगातार आनेवाले विनाशकारी दुर्भिक्षों ने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से समस्या पर पूरा प्रकाश डाला और जनता की दयनीय दरिद्रता तथा स्थायी भुखमरी का प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किया। उन्होंने सामान्य वर्षों में भारत की स्थायी दरिद्रता का

अपेक्षाकृत अधिक बड़ी बुराई के रूप में सूचित किया। उन्होंने 'राष्ट्र की पूरा क्षीणता का नाडा फोटा 'इस देश में बहुसंख्यक जनता के गरम दुर्भाग्य, उसी उदासीनता और विवशता के अनिश्चित प्रमाण का प्रस्तुत किया, 'अब सभी तथ्यों और अज्ञान से बहकर निष्पक्ष रूप में भारत में व्याप्त घोर दरिद्रता को स्पष्ट प्रमाणित किया।' यन्तुन के भाग्य की दरिद्रता के 'वास्तव चिह्न' थे।<sup>88</sup>

राष्ट्रीय नेताओं ने भारत में व्याप्त घोर दरिद्रता को प्रमाणित करने के लिए निश्चित प्रमाणा का प्रस्तुत करने के साथ-साथ ब्रिटिश भारतीय प्रशासन और तत्कालीन देश में समृद्धि और संपन्नता सिद्ध करने के लिए यन्तुन तर्कों का प्रयत्न महत्त्वपूर्ण भी प्रारंभ कर दिया। भारतीयों की संपन्नता के सूत्र किसी भी यन्तुगत मानदंड के अभाव में ब्रिटिश प्रशासकों ने व्यक्तिगत मानदंड का अपनाने का मांग ग्रहण किया। उनका तर्क था कि भारतीय जनता अपनी इच्छानुसार ही समृद्ध है। भारतीयों की निम्न आय उनकी दरिद्रता की सूचक नहीं होकर उनकी आवश्यकताओं की स्वल्पता की ही द्योतक है।<sup>89</sup> इस प्रकार निरपेक्ष रूप से दमन पर भारत की स्पष्ट दिशा दे देनेवाली दरिद्रता जनता की सीमित आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में देखने पर सवधा भिन्न रूप ग्रहण कर गई। इस तर्क का निर्देशक यह था कि खेतिहरों की सतृप्ति का अर्थ तथ्यतः उनकी संपन्नता भी है। 1880-91 के वर्षों की 'बंगाली रिपोर्ट' ने भारतीयों की भौतिक स्थिति पर इस प्रकार टिप्पणी की 'बंगाल का किसान अपने मानदंड के आधार पर ही जांचे जाने पर प्रसन्न तथा संपन्न पाया गया है।'<sup>90</sup> उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध की रिपोर्ट लिखनेवाले ने तो इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया 'हिंदू कृषक किस प्रकार घटिया खाना खाता है जबकि वह बहुत स अच्छे खाते पीते लोग की अपेक्षा अधिक मोटा नहीं, पूणतः स्वस्थ और प्रसन्न अवश्य है।'<sup>91</sup> इस तर्क का पोषक सिद्धांत यह कल्पना थी कि धार्मिक शिक्षा तथा दीर्घ काल से प्रचलित सामाजिक मूल्यों के कारण भारतीय कृषक भौतिक आवश्यकताओं की सतृप्ति की अपेक्षा आध्यात्मिक सतोष में अधिक रुचि रखता है।<sup>92</sup> ब्रिटिश भूतपूर्व तथा वर्तमान अधिकारी भारतीयों की प्रतिव्यक्ति आय की यूरोप के लोगों की आय से तुलना की प्रवृत्ति के मुकाबल व्यक्तिनिष्ठ और सापेक्ष सिद्धांत पर जाकर विरोधी दृष्टिकोण प्रस्तुत करने लगे। उनमें से अपेक्षाकृत अधिक गंभीर व्यक्तियों ने घोषित किया 'जीवा आवश्यकताओं और मूल्यों में गहरे अंतर के कारण यूरोप के लोगों के साथ भारतीयों के जीवन निवाह तथा जीवन स्तर की तुलना एक जयहीन चेष्टा है। उनकी जाच पड़ताल ता देश की अपनी आवश्यकताओं के सदम में ही करनी उचित है।'<sup>93</sup> कम सतक सरकारी अधिकारी तो टिप्पणी करते हुए इस सीमा तक बढ़ गए कि तुलना की दृष्टि से यूरोप के खेतिहरों की अपेक्षा भारत के किसान की दशा बहतर है। इसी प्रकार सामान्य भारतीय कृषकों को प्राप्त सुख-सुविधाओं की दृष्टि से उनकी तुलना यूरोप के बहुत बड़े भाग में विद्यमान किसानों से करते हुए जान स्ट्रुचे ने 1898 में यह मत व्यक्त किया 'निस्संदेह भारतीय कृषक ही अधिक लाभसंपन्न है।'<sup>94</sup> मद्रास के भूतपूर्व गवर्नर फ्रांट डफ 1887 में एक पत्रिका में प्रकाशित अपने लेख में पहले ही '... चूके थे।'<sup>95</sup> छोटे अधिकारी तो और भी अधिक असंत थे।

ढाका का कमिश्नर 1888 में इस चीजानेवाले परिणाम पर पहुंचा अपनी आवश्यकताओं के मदद में बंगाल का किसान विद्रोह में समृद्धतम है। टुंगली का कलक्टर टायनर भी उद्धतता में पीछे नहीं था। उसने महा तब लिखा इस जिले के दरिद्रतम वर्ग की स्थिति इंग्लैंड के उसी वर्ग की स्थिति की तुलना में सभी दृष्टियों से निस्संकोच रूप से बेहतर कही जा सकती है। और मुझे इस बात में लेशमात्र भी संदेह नहीं कि हजारों-हजार निधन अंगरेज भारतीयों के साथ स्थान परिवर्तन करने में प्रसन्नता अनुभव करेंगे।<sup>94</sup>

भारतीय नताशा ने इस विचारधारा के आधारभूत दृष्टिकोण का सवथा क्रूर तथा भावनाशून्य<sup>95</sup> बताया। उन्होंने बड़ी तीव्रता से इस सिद्धांत को अस्वीकार किया कि भारतीयों की आवश्यकताएं सीमित हैं<sup>96</sup> अथवा वे जीवन में भौतिक सुख-सुविधाओं का आनंद लेने तथा उनकी आवश्यकता अनुभव करने के अयोग्य हैं।<sup>97</sup> उनके वर्तमान निम्न जीवनस्तर को उनकी स्थिति में सुधार के अधिभार को नकारने के पोषक तत्व के रूप में नहीं लिया जा सकता।<sup>98</sup> विषय का सार इस प्रकार था

ब्रिटेन में प्रथम उनके साधन छीन लिए, उन्हें अधिक उत्पादन के अयोग्य बना दिया, अवशिष्ट तुच्छ साधनों की सीमा तब उन्हें अपनी आवश्यकताओं को घटाने को विवश कर दिया और फिर उन्हें कोसना शुरू कर दिया। धाव पर नमक छिड़कते हुए उन्हें कहना प्रारंभ कर दिया देखा, तुम्हारी आवश्यकताएं सीमित हैं। तुम्हें अवश्य ही सीमित आवश्यकताओं वाले निधन व्यक्ति बने रहना चाहिए। तुम्हारे लिए धा सेर चावल, हम तुम्हें अधिक उदारता से सेर भर चावल रखने की अनुमति दे देंगे, थोड़े से वस्त्र और आश्रय पर्याप्त हैं। बड़ी बड़ी मानवीय आवश्यकताओं की सतुष्टि और सुखा का उपभोग तो हमारे लिए है। तुम्हें हमारे भाड़े के टटू के रूप में हमारे पशुओं के समान हमारी दासता करनी चाहिए और हमारे लिए श्रम करना चाहिए।<sup>99</sup>

भारतीय नेताओं ने वैराग्यपरक दृष्टिकोण तथा आध्यात्मिकता के नाम पर निधनता को महिमा देने की प्रवृत्ति की निंदा की। उन्होंने भौतिक सुख-सुविधाओं को बहुत ऊँचा स्थान दिया।<sup>100</sup> उन्होंने राष्ट्र की भौतिक उत्पादकता में सभावित वृद्धि के साथ राष्ट्र की भौतिक संपदा में वृद्धि की इच्छा को जोड़ दिया क्योंकि उनके अनुसार भौतिक सामग्री के उपलब्ध परिमाण का मानवीय आवश्यकताओं की सतुष्टि से मापेक्ष संबंध है।<sup>101</sup> उनकी सारी आर्थिक गतिविधि का केंद्र दरिद्रता को दूर करना था न कि अप्रसन्नता को। उन्होंने अपना तात्कालिक लक्ष्य भूखे मरते लोगों के लिए रोटी के दा टुकड़े जुटाना बताया और इस रूप में उनके तर्क का सार यह था कि बचारे भारतीयों की सीमित आवश्यकताओं की भी सतुष्टि नहीं होती।<sup>102</sup>

### 3 क्या दरिद्रता बढ़ रही थी ?

राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्र जाच पडतालो तथा बहुत बड़े क्षेत्र और बहुत बड़ी जनसंख्या को बहुत बुरी तरह प्रभावित करनेवाले और साथ ही संपन्नता का पर्दाफाश करनेवाले दुर्भिक्षा की निरंतरता के फलस्वरूप सारे देश में व्याप्त घोर दरिद्रता के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को न्यूनाधिक रूप में न केवल भारतीय जनता ने ही अपितु शासकवर्ग में भी निर्विवाद



रूप से स्वीकार किया। 1888 की आर्थिक जांच पर प्रस्ताव में यह तो कहा गया था कि खेतिहरों के निम्न वर्गों की स्थिति भी बतमात्र में नहीं होगी जिसे बिना का विषय बना जा सके किंतु यह भी स्वीकार किया गया कि देश के सभी भागों में जटिल जनता का अभावग्रस्त हान के प्रमाण उपलब्ध हैं<sup>103</sup>, और यह कथन अनिश्चित नहीं कि उन देशों में बहुत बड़े भूभाग के छोटे किसान तथा मजदूर, दासगण का भाजा भी नहीं जुटा पाते।<sup>104</sup> 1898 में 'लायल दुर्भिक्ष आयोग' ने यह पाया कि कृषक जनता का निम्नवर्ग अभी धार खरिदता के शिक्के में इतना बुरा हुआ है कि उनके पास सामान्य वर्षों में भी पर्याप्त भोजन नहीं होता।<sup>105</sup> अपनी वापसगारों के अंतिम वर्षों में लाइल जनता की स्थिति में स्वीकार किया 'भारत में पर्याप्त, यहाँ तक कि पर्याप्त में बहुत अधिक खरिदता है।<sup>106</sup> मेजर वेरिंग तथा लाइल जनता द्वारा प्रमाणित प्रति व्यक्ति आय के अनुमान यद्यपि अन्य रूपों में विवादास्पद हैं तथापि उनमें प्रभावशाली ढंग में भारतीय जनसमुदाय की धार खरिदता का पता चलता है। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में व्याप्त धार खरिदता के विद्वानों ने मध्य के रूप में प्रचार और प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली।

भारत के उदीयमान राष्ट्रीय नेतृत्व तथा ब्रिटिश प्रशासन ने मध्य प्रचार-बुद्ध का केंद्र एवं अर्थ अधिक विस्फोटक यह प्रश्न बन गया कि 'भारत की खरिदता परत की अपक्षा बढ रही है अथवा घट रही है?'<sup>107</sup> यह प्रश्न इस दृष्टि में महत्वपूर्ण था कि इनके उत्तर में एक निष्पत्ति निहित था और इसीलिए दोनों पक्षों ने इस प्रश्न को इस रूप में प्रस्तुत किया 'भारत ब्रिटिश उपनिवेश बनने पर परत की अपक्षा अक्षय स्थिति में है अथवा बुरी स्थिति में है?'<sup>108</sup> भारत में विद्यमान ब्रिटिश अधिकारी देश में व्याप्त खरिदता के प्रश्न की अपक्षा इस प्रश्न पर अधिक संवेदनशील थे क्योंकि भारत का पूर्वापक्षा खरिद होते जाना माना का अर्थ केवल धार खरिद ही नहीं था प्रत्युत उनके गंभीर राजनीतिक प्रतिष्ठात भुगतना भी था। उच्च ब्रिटिश अधिकारी मध्य के इस रूप में भली प्रकार परिचित थे। भारत मन्त्रि लाइल जाज हेमिलटन ने समस्या की इस बुनियादी का स्वीकार करते हुए 16 अगस्त 1901 को 'हाउस ऑफ कामंस' में घोषणा की 'यदि यह सिद्ध किया जा सके कि हमारे प्रशासन में भारत नीतिक मपन्नता की दृष्टि से और अधिक पिछड़ गया है तो मैं इसे एकदम धार खरिद मानने को तैयार हूँ तथा स्वीकार करता हूँ कि इस स्थिति में हम भारत की और अधिक समय तक अपने नियंत्रण में रखने के विश्वमनीय अधिकारी नहीं।'<sup>109</sup> यह विषय इस दृष्टि से भी अधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि यदि रोग को अभी स्वीकार ही नहीं किया गया तो उसके कारणों और उपचारों के ढूँढने का क्या लाभ हो सकता था?

वर्षों तक भारतीय नेता इसी स्थिति को सिद्ध करने में लगे रहे कि भारत खरिद ही नहीं प्रत्युत दिन प्रतिदिन खरिदतर होता जा रहा है। उन्होंने भारतीय जनता की निरंतर बढती हुई और उत्तरोत्तर अधिक गहरी जड़ पकड़ती हुई निवृत्तता को दिखाने के लिए अर्थ और निरंतर प्रयत्न किए। उदाहरणार्थ गापालकृष्ण गोयने ने इस 1902 के अपने प्रसिद्ध वक्तव्य का केंद्रबिंदु बनाया और उसके बाद इस समस्या के सभी पक्षों पर विचार करने के उपरांत वह इस निष्पत्ति पर पहुँचे कि भारत के जनसमुदाय की

भौतिक स्थिति निरन्तर बढ़ से बढ़तर होती जा रही है तथा यह दृष्टिगाचर है कि यह न्यून विद्व के आधिक इतिहास के क्षेत्र विम्नार के अतगत सवाधिक दुग्द स्थिति है।<sup>110</sup> भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने द्वितीय अधिवेशन में ही भारतीय जनता की विनाश सम्प्रा की बढ़ती हुई दरिद्रता के अपने दृढ़ विश्वास की चाणी दी<sup>111</sup> तथा एक के पदचात दूसरे अधिवेशन में इस प्रस्ताव को दोहराया। राष्ट्रीय प्रेस न भी प्रतिदिन बढ़ती दरिद्रता को 'स्पष्टगाचर' तथा 'पूणत सिद्ध वास्त्विवना' कहते हुए अत्यत उग्रता से उसकी घोर निंदा की।<sup>112</sup>

दूसरी ओर भारत में रहनवाले ब्रिटिश अधिकारी तथा सामान्यत मभी ब्रिटिश लेखक यह मानते रह कि ब्रिटिश राज्य से भारतीय जनता की भौतिक दगा निरन्तर न केवल सुधर रही है प्रत्युत देश की सपन्नता में वृद्धि भी हो रही है। उनके अनुसार दरिद्रता की कल्पना सबथा निराधार और पूण रूप से पाखड है। मत्य यह है कि भारत पहले से ही समृद्धि के राजपथ पर चलना शुरू कर चुका है, अत उसका भविष्य उज्वल तथा उत्साहवध है।<sup>113</sup> इस सिद्धात के प्रबलतम समयक व्याख्याता लाड कजन थे जिन्होंने बार बार, यहा तक कि लगभग अपने सभी वजट भाषणा में इस विषय को उठाया।<sup>114</sup> 1901 में उन्होंने, जसा हम पूव निर्देश कर चुके हैं, सगणना द्वारा यह सिद्ध किया कि भारत की 1882 में 27 रुपये प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1898 में 30 रुपये प्रति व्यक्ति हो गई है। वृद्धि की इस दर से असतोप प्रकट करते हुए भी उन्होंने दावा किया कि आधिक गनिविधि निश्चित रूप से प्रगति की ओर उमुख है, अवनति की ओर नहीं।<sup>115</sup> 1901 तक तो वे और अधिक विश्वास हा गए थे। उन्होंने गोपालकृष्ण गोखले जैसे भारतीय नेताओं का उपहास करते हुए, 'तपती धूप में वर्षा होन की बात कहकर आत्मरक्षा के लिए छाता ताननेवालो' से उनकी तुलना करते हुए बलपूर्वक कहा कि भारत सभी दिशाओं में हृष्ट-पुष्टता, क्षमता और सपन्नता के सकेतो का स्पष्ट प्रदर्शन कर रहा है।<sup>116</sup> 1906 तक तो उनका यह निश्चित मत था कि भारत की भौतिक प्रगति न केवल भारतीय इतिहास की अभूतपूर्व घटना है प्रत्युत विश्व के किसी भी देश के इतिहास की एक विरल घटना है।<sup>117</sup>

प्रतिद्वंद्वी विवादा की विस्तृत परीक्षा के समय दोनों पक्षाने समान रूप से स्वीकृत परंतु भिन्न विधि से और विपरीत रूप में विश्लेषित निर्देशको पर न केवल तर्क-वितर्क किया प्रत्युत भारतीय नेताओं ने भौतिक सपन्नता सबधी कतिपय पक्षों पर सहमत होत हुए भी यह स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय सपन्नता सबधी बड़े कारणों के अभाव में ये पक्ष आवश्यकता से अधिक कमजोर पड गए थे।

राष्ट्रीय नेताओं की दृष्टि में दुर्भिक्ष भारत की दरिद्रता के स्पष्ट प्रमाण थे। दुर्भिक्षों की निरन्तर बढ़ती हुई तीव्रता, प्रसार तथा विनाशलीला<sup>118</sup> भारत की बढ़ती हुई अशक्तता के पक्के अभिसूचक थे।<sup>119</sup> इसके विपरीत ब्रिटिश दृष्टिकोण यह था कि दुर्भिक्ष प्राकृतिक प्रकाप के परिणाम थे और इनके साथ मानवीय प्रयत्ना का कोई संबंध नहीं था।<sup>120</sup> भारतीयों की दृष्टि में खेतिहरा पर बढ़ता हुआ ऋण तथा भूमि जोतनवानों द्वारा भूमि न जोतनवालो के हाथों भूमि की चिकी, साधनों के वढते अभाव के सूचक थे।<sup>1</sup> कुछ एक ब्रिटिश अधिकारियों तथा लेखकों ने इस तथ्य को मानने से इनकार कर

दिया कि ऋणप्रस्तता गेतिररा ती निधाता की दशा ती सूत्र है ।<sup>1</sup> <sup>2</sup> विवन्पत उन्हीने ऋणप्रस्तता ती निधाता का कारण भाता, परिणाम गही ।<sup>1</sup> <sup>3</sup> जी० बी० जागी आर गोपले न भी अतात और प्नेग म अलग एटरर वदती हुई मृत्यु-र के आनहे प्रन्तुत वरा यह दिवाने का प्रयत्न किया कि बहुत अधिव जनमन्था को भरपट साना नहा मिलता ।<sup>121</sup> एव ओर जहा भारतीय नता प्रिटिंग अधिकारियों के भारतीय मपन्तता व दावे को भूठा गिद्ध करने के लिए निश्चयात्मक प्रमाण जुटा रहे थे, वहा के अथ यह नी मानन लगे थे कि वन्तुत प्रमाण जुटान का उत्तरदायित्व तो निश्चिन धारणा के प्रस्तानात्रा का ही है ।

प्रिटिंग प्रवक्ताआ ने इतिहास को बहुत बडा 'यायाधीन मानकर उमव आग अपील करते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत किया । उनका मतव्य था कि प्रिटिश राज के सापक्षिक भौतिक परिणामा पर निषम देन म पूव तुनना के लिए यह दगना चाहिए कि प्रिटिश पूववर्ती शासका के अधीनम्य भारत की क्या दशा थी । इस तुलनात्मक विवरण म उनका तव था कि अगरजा के आने से पूव भारत अत्यधिक दरिद्र था और प्रिटिश राज का पक्ष इस दृष्टि से उज्वल है ।<sup>1</sup> <sup>5</sup> भारतीय नेता अपन अतीत पर आधारित निषय को स्वीकार करन पर सहमत थ । कुछएक महानुभाव न तो बडी तत्परता से मान लिया कि भारतीय दरिद्रता की जडे इतिहास के अतराल म हँ और इस प्रकार दरिद्रता एन पुरानी बहुत पुरानी विरासत मे प्राप्त बुराई है ।<sup>1</sup> <sup>6</sup> भारत अतीत मे कभी समृद्धि का भंडार नहीं रहा ।<sup>1</sup> <sup>7</sup> परंतु उनम स बहुतो की मायता यह थी कि वतमान युग की दरि द्रता और दुर्भाग्य अतीत के किसी भी युग मे गही रहे ।<sup>1</sup> <sup>8</sup> इनसे घ्राज ने भारत को जकडन वाला अगरेजी राज्य सबसे बडा अभिशाप है ।<sup>19</sup> उांमे स कुछएक ने ता यह प्रमाणित करने की चेष्टा भी की कि अक्बर तथा अन्य भारतीय शासका के समय भारतीय का स्थिति अपेक्षावृत्त अच्छी थी ।<sup>130</sup> कुछएक राष्ट्रवादी प्रवक्ताआ न तो अतीत का गौरव गान किया और अतीत की समृद्धि और गरिमा के विनाश पर उच्च स्वर से विलाप किया ।<sup>131</sup> ऐल्फ्रेड नडी के इस विषम प्रदन ने बडी सफाई से सरकारी दृष्टिकोण का खडन किया—क्या अगरेज व्यापारी भारत मे गरीबो के दुसा के निवारण के लिए इस देस म आने को आकृष्ट हुए थे ? अथवा उनके अपने ऐतिहासिक कथन के अनुसार, क्या वे इस देस की सफल से आकृष्ट होकर यहा आये थे ?<sup>132</sup>

प्रिटिश भारतीय अधिकारियों तथा लेफानो ने भारत मे असह्य विभिन्न मूल्यवान घातुआ के बढ़ते हुए आयात तथा उसका फलस्वरूप लोगों के पास उन घातुआ के सचित भंडार को देश की बढ़ती हुई सपत्ति का निश्चित सकेत के रूप मे ग्रहण किया ।<sup>133</sup> उनम से एव महानुभाव फ्रेड जे० एटकिंसन ने तो 1902 मे सगणना की कि 1800 1895 की अवधि मे भारत न 141,705 000 पौंड का साना तथा 4792 403 000 पौंड को चाँदी आयात की है । सिखा आदि के लिए कटीती के पश्चात उसने जाकडो मे सिद्ध किया कि भारत की सचित आय 26 स० प्रति व्यक्ति है ।<sup>134</sup> उल्लेखनीय यह है कि उसका यह तक भारतीय नेताओं की किसी प्रकार दिग्भ्रात न कर सका । भारतीय नेताओं ने यह स्वीकार किया कि 19वीं शतादी की पूरी अवधि मे मूल्यवान घातुआ का आयात हुआ है परंतु

इसे वे बढ़ती समृद्धि का अथवा राष्ट्रीय आय में वृद्धि का उदाहरण मानने का उदाहरण नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चांदी के मुद्रा आयात का उक्त बड़ा भाग मद्रास अथवा आंध्र प्रदेश के काम न आकर मुद्रा की अनिवार्य आर्थिक तथा व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के ही काम आता है। आयातित चांदी प्रमुख रूप में मद्रानिमाण में ही काम आती है जिसकी मांग इन वर्षों में भगवत्स्य की नव्य अत्यागी तथा नव्य विलुप्त व्यापार के आर्थिक भुगतान के कारण काफी बढ़ गई थी।<sup>133</sup> मद्रानिमाण उक्त तथा राजनाय जमा आदि के पदचाल आयातित मूल्यवान धान आ का अवधिगत जनता की वृद्धि मद्रास को निरान के लिए प्रयाग किया जानेवाला एक नव्य प्रमाण है।<sup>134</sup> उनका ही नहीं इस तुच्छ राशि का उपयोग भी प्रमुख रूप में उक्त तथा म यवक न ताग ही करत है। यह धातु तो बचाचित ही जनता के निम्नवर्ग के हाथ में पड़ने वाली है।<sup>135</sup> तथाभाई नौरोजी ने जोर देते हुए कहा कि मोना चानी के जापान मपनि म मुद्रा प्रान्तरी नहा करते क्याकि उनका उद्देश्य व्यापार के निश्चित मनलन का प्रनाग रचना नहीं है। भारत का निर्यात आयात की अपेक्षा अधिक है। इन मूल्यवान धान आ न आयात के बल उमी मूल्य की अय वस्तुओं का निर्यात करना पड़ता है अतः उक्त रूप में मूल्यवान धान आ व आयात से संपत्ति में वृद्धि की अपेक्षा जीवननिर्वाह के माधना की हानि ही अधिक होती है।<sup>136</sup>

ब्रिटिश भारतीय अधिकाारिया ने हर्षोत्फुल्ल होकर वग प्रतिवच मूल्य और परिमाण में शीघ्र गति से फैलत भारत के विदेश व्यापार का उक्त की उदगी मपन्नता के साथ रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने एक ओर यह तक प्रस्तुत किया कि वचन वृद्धि मपनतावाला देश ही नियमित रूप से और ऊंची दर पर विदेशी सामग्री के आयातों में वृद्धि कर सकता है। दूसरी ओर उनका तर्क था कि बढ़ते हुए निर्यातों में विमानता की जेड अधिकाधिक भर रही होगी।<sup>137</sup> भारतीय नेताओं ने इस प्रपच के प्रति विपरीत दृष्टिकोण अपनाया। विदेश व्यापार के प्रति उनके दृष्टिकोण की समीक्षा तो आग के एक अध्याय में प्रस्तुत की गई है। यहा इतना लिखना पर्याप्त होगा कि उनके अनुसार विदेश व्यापारिक लाभ का साधन न होकर राष्ट्रीय क्षति का ही एक बहुत बड़ा साधन है क्योंकि आयात से थोड़ा सा लाभ की अपेक्षा बहुत बड़ी हानि इस रूप में होती है कि स्वदेशी उत्पादकों के अपने क्षेत्र से हट जाने में औद्योगिक उदासीनता छा गई है। इससे अनिश्चित आयातों में वृद्धि दश के योगक्षेम में वदोत्तरी की अपेक्षा देश स धन के निवास में वृद्धि की ही सकेतक है। मजे की बात यह है कि उसकी बुराईया तो भारतीयों को भुगतनी पड़ती है और उसके लाभों का आनंद ब्रिटिश भारतीय प्रशासकों ने निरंतर सुधरत हुए भारत के राजस्व की ओर सकेत किया जो करो के अतिरिक्त बोनस को बढ़ाए बिना ही बढ़ता जा रहा था। उन्होंने राजस्व के प्रमुख विषयों द्वारा लचीलापन दिखाए जाने के लिए तथा प्रयोज्य और समृद्धि के सूचक साधना में प्राप्त में निरंतर विकास के लिए अपने आपको बधाई दी।<sup>138</sup>

उन्होंने देश में मुविधाओं और समृद्धि के सीमात में सुधार के द्योतक के रूप में सीमा शुल्क, डाक कर नमक कर, आय कर मुद्राक तथा उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व में वृद्धि

का उल्लेख विशेष रूप से किया।<sup>141</sup> भारतीय, जिन्होंने दृष्टिकोण को गोपालकृष्ण गोसले ने सभी राष्ट्रवादी विचारकों द्वारा बहुप्रामाणिक 1902-3 के अपने बजट भाषणा में प्रस्तुत और प्रबलता से प्रस्तुत किया था, राजस्व में बढ़ोत्तरी को देश की मौलिक प्रगति का संकेत मानने को सहमत नहीं थे। उनके अनुसार ऊँचा बराधान दश की दरिद्रता का बहुत बड़ा कारण है।<sup>142</sup> वह राजस्व के खाना में विनाश को भारतीय जनता की दरिद्रता के निवारण का सूचक मानने के ब्रिटिश दृष्टिकोण का भी स्वीकार नहीं करते थे। उनका विश्वास था कि उत्पादों राजस्व में वृद्धि राष्ट्र की संपन्नता की अपेक्षा राष्ट्र के विनाश और दुर्भाग्य के पथ पर बढ़ने की सूचक है। एक सम्य सरकार को इस स्थिति का अनुपात करने के बदले उसकी निंदा करनी चाहिए।<sup>143</sup> सीमागुल्य में वृद्धि केवल यथादृष्ट विदेश व्यापार के प्रसार मात्र की जा सकती है जिसकी निन्दा पहले ही की जा चुकी है। केवल दो बरा आयकर तथा विप्रीवर से प्राप्त आय दश की भौतिक स्थिति का पान कर सकता है। आयकर मध्यम की और विप्रीवर जनसाधारण की स्थिति के परिचायक हैं।<sup>144</sup> यह निर्देश किया गया कि आयकर से प्राप्त होनेवाली आय वर्षों में न्यूनधिक रूप में स्थिर ही रही है।<sup>145</sup> विप्रीवर की आय भी जनसंख्या के विस्तार के अनुपात में नहीं बढ़ी है।<sup>146</sup> नमक जैसी मानवीय उपयोग की मूल तथा आवश्यक वस्तुओं की प्रति व्यक्ति सपत में गिरावट का सूचक यह तथ्य जनसमुदाय की गिरती दशा का सचमुच एक बहुत बड़ा साक्ष्य है।<sup>147</sup>

ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों ने कृषियोग्य भूमि के क्षेत्र में विस्तार तथा कृषि उपज में वृद्धि को भारतीय संपन्नता के विकास के एक अन्य प्रमाण के रूप में उद्धृत किया क्योंकि उनके अनुसार इनका परिणाम था कृषि आय में अपेक्षाकृत अधिकता तथा खाद्य पदार्थों की अपेक्षाकृत प्रचुरता से उपलब्धि।<sup>148</sup> भारतीय नेताओं ने इस तक का खंडन निम्नलिखित युक्ति से किया। उसके अनुसार देश में, विशेषतः पुराने प्रांतों में, कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र तथा कुल खाद्य समर्पण बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप नहीं बढ़ रहे।<sup>149</sup> इसके अतिरिक्त व्यापारिक फसलों के क्षेत्र की वृद्धि के मुकाबले खाद्य फसलों के क्षेत्र की वृद्धि भी नगण्य है।<sup>150</sup> कृषिक्षेत्र का विस्तार कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि के परिणाम के अनुरूप नहीं।<sup>151</sup> प्रत्येक स्थिति में यह विस्तार जंगलों प्राकृतिक चरागाहों तथा परती धरती पर अनुचित बच्चा का ही परिणाम है।<sup>152</sup> इसके अतिरिक्त उन्होंने अग्रजों के धरती की उत्पादकता में सुधार के लक्ष्यों को गलत मानते हुए उसका प्रबल खंडन किया। उनके अनुसार धरती पर जनसंख्या के दबाव और उसके फलस्वरूप स्वदेशी उत्पादकों के हट जाने से, घटिया धरती पर व्यवसाय होती के विस्तार से<sup>153</sup> तथा निरंतर खाद के बिना ही फसल उगाते रहने से धरती की उर्वराशक्ति क्षीण हो जाने से उत्पादन घट गया है।<sup>154</sup> अतएव निष्कर्ष रूप में उनकी मान्यता थी कि भारत कृषि के क्षेत्र में निरंतर और भयंकर अपक्षय से विपन्न होता जा रहा है जिसका परिणाम यहाँ दार-द्वार पड़नेवाला दुःख है।<sup>155</sup>

सुधरती दशा का सरकारी तंत्र द्वारा प्रस्तुत एक सूचक साक्ष्य मूल्यों में वृद्धि था। उनके अनुसार यह एक सत्य था क्योंकि इससे एक जोर खेतिहरो की जेबें भारी हो रही

घी और दूसरी ओर लोगो की क्रयशक्ति में वृद्धि से प्रेरित खाद्यान्नो तथा अन्न उपभोग वस्तुओ की मांग बढ़ रही थी।<sup>157</sup> राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों की दृष्टि में मूल्यवृद्धि की भूमिका का तक सबथा निस्सार और भ्रातिमूलक था। उन्होंने वर्षों तक तो आर्थिक, स्थानीय तथा अस्थायी वृद्धि को छोड़कर देश में सामान्य अथवा उल्लेखनीय रूप में मूल्य वृद्धि का स्वीकार ही नहीं किया।<sup>158</sup> आगे चलकर उन्होंने मूल्यवृद्धि के तथ्य को ता स्वीकार किया परन्तु उसकी साथकता का विश्लेषण भिन्न रूप से प्रस्तुत किया। उनके विचार में मूल्यवृद्धि क्रयशक्ति में वृद्धि की सूचक न होकर राष्ट्रीय उत्पादन में गिरावट की और कृषि उत्पादन में ह्रास की द्योतक थी।<sup>159</sup> इसके अतिरिक्त यह कृषि उपजों के बढ़त निर्यात तथा यूरोप के बाजारों की ऊँची कीमतों का प्रभाव था।<sup>160</sup> उनमें से कुछ एक ने समेत किया कि किसी भी रूप में बढ़ी कीमतों का लाभ वास्तविक उत्पादक को न मिलकर विचो लिया, ऋणदाता साहूकारों तथा निर्यात व्यापारियों द्वारा ही हड़प लिया जाता था।<sup>161</sup> उन्होंने अविलंब यह भी सकेत किया कि खेती तथा अन्न प्रकार के श्रम कार्यों में नये समाज के निम्नतम वर्ग के मजदूरों की आय बढ़ती कीमतों के साथ उसी गति से नहीं बढ़ी है। बल्कि कुछ लोगो की आय तो घट गई है। ऐसे लोगो का तथा उन छोट किमानों का, जिनके पास बेचन के लिए फालतू अनाज नहीं होता और जिन बेचारी का अपनी आवश्यकता के खाद्यान्न का कुछ भाग खरीदना पड़ता है ऊँची कीमतों से समृद्धि के बदले दुर्भाग्य ही बढ़ा है।<sup>162</sup>

आधुनिक उद्योगों तथा यातायात साधनों का उदय और विकास समकालीन भारतीय आर्थिक विकास का एक ऐसा पहलू था जिसे दानो पक्षों ने प्रचारात्मकता से हटकर एक मत से समर्थन दिया तथा उसे आर्थिक क्षमता का स्रोत स्वीकार किया। परन्तु इस सबंध में भी भारतीय अर्थशास्त्रियों ने स्वदेशी उद्योगों के द्रुतगामी ह्रास पर गभीर चिन्ता और निराशा प्रकट की। इस औद्योगिक उदासीनता से भारतीय समाज द्वारा अनुभूत आर्थिकता की भारी क्षति की पूर्ति आधुनिक मशीनी उद्योग के विकास द्वारा होती दिखाई नहीं देती।<sup>163</sup> उल्लेखनीय यह है कि विदेशी धन का आधुनिक भारतीय उद्योगों पर प्रभुत्व लाभप्रद परिणामों के बहुत बड़े भाग को अपने अधिकार में कर लेता है।<sup>164</sup> उनकी दृष्टि में रेलों भी विशुद्ध वरदान रूप नहीं थी।<sup>165</sup>

भारतीय नेताओं ने एक दृष्टि से अंगरेजी प्रशासन का नीचा दिखाया। भारत में व्याप्त घोर दरिद्रता और उसकी उत्तरोत्तर बढ़ती गति के सबंध में उनकी धारणाएँ दृढ़ थीं। वे सदैव इस तथ्य की सत्यता की परीक्षा के लिए तथा वास्तविकता को उसकी गह-गई में देखने के लिए निष्पक्ष तथा खुली जाच-पड़ताल का समर्थन करते थे। वस्तुतः उन्होंने जाच-पड़ताल को भारत की दरिद्रता समस्या सबंधी अपने आंदोलन का अभिन्न अंग बना लिया। दादाभाई नौरोजी अपने संपूर्ण सक्रिय राजनीतिक जीवन में, अपने निबंधों में, हाउस आफ कामर्स में, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में तथा सिलेक्ट कमिटी आन इस्ट इंडियन फाइनेंस एंड दि रायल कमीशन आन दि ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ दि एक्म-पेंडेंसी आफ इंडिया' (विलेवी कमीशन) के सामने साक्ष्य देने हुए, निरंतर जाच-पड़ताल की मांग करते रहे।<sup>166</sup>

राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1900 में भारतीयों की आर्थिक दशा की पूरा तथा निर्माण जान की मांग प्रस्तुत की।<sup>167</sup> 1901 में इंग्लैंड स्थित भारतीय अवकाश सच ने भारत के बहुत से विशिष्ट ग्रामों की आर्थिक स्थिति की विस्तृत जान की याचना बनाई तो कांग्रेस ने उस योजना को अपना हार्दिक समर्थन दिया।<sup>168</sup> भारतीय नेताओं ने 1882 का बार्नर जाच के और 1888 की डफरिन जाच के परिणामों के प्रमाणों का बार-बार आग्रह किया। उन्होंने इन प्रवासनों का राबन का विचारमंचात बताने हुए अपने गुण व गुण दावा की पूर्ति के प्रति उपेक्षा के लिए सरकारी तंत्र की अच्छी राबर ली।<sup>169</sup>

#### IV दरिद्रता के कारण

भारत की बढ़ती दरिद्रता अथवा गणन्यता विषयों का गुरुद्वारा दोना पक्षों द्वारा प्रबल पराक्रम और उत्तर साहसपूर्वक लडा गया। यद्यपि यह मतभेद वर्षों तक भारतीय राजनीति का जीवन प्रदान करता रहा तथापि अधिकाधिक इसे दो तथ्यों की स्थापना में सफलता मिली, प्रथम, भारतीय जनता के अपेक्षाकृत अधिक निधन योग का जीवन स्तर अत्यंत ही निम्न है। इतना अधिक निम्न है कि उन और अधिक नीचे नहीं घबेना जा सकता। द्वितीय, यदि भौतिक प्रगति अथवा परागति नाम की कोई स्थिति है भी तो उसकी दर इतनी स्वल्प तथा अपन-आप में उसका क्षेत्र इतना मरुचिन्त है कि उसे बर्णनिक दृष्टि से स्थापित ही नहीं किया जा सकता।<sup>170</sup> दूसरे शब्दों में भारत की भौतिक स्थिति दरिद्रता के निम्न स्तर पर स्थिरता की ही है।

भारतीय नेताओं की दृष्टि में भारत की अर्थव्यवस्था की गति की शिक्षा का प्रदान इस दृष्टि से महत्वपूर्ण था कि इसमें प्रमुख रूप से तो भारतीय जनता और सरकार का दरिद्रता की समस्या पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता था और दूसरे बाद में यह निष्कर्ष करने में कि इसके लिए किसका दायित्व है—सहायता भी ली जा सकती थी।<sup>171</sup> अध्ययन काल की अवधि के अधिकांश वर्षों में उनका प्रमुख लक्ष्य भारत की विषमगमन और दरिद्रता का उन्मूलन था न कि चिड़िया द्वारा खेत चुगने जान के बाद पछताना था।<sup>172</sup> विदेशी शासकों तथा भारतीय नेताओं ने देश की चरम दरिद्रता के लिए उत्तर दायी तत्वों की समीक्षा करने में तथा उनके मुलभान में अधिक ध्यान दिया क्योंकि वे इस तथ्य से भलीभांति परिचित थे कि आर्थिक विकास के मांग की बाधाओं को भला प्रकार जान लेने पर ही उनके हटाने के उपायों का अनुगमन अथवा प्रयोग किया जा सकता है।<sup>173</sup> समय समय पर ब्रिटिश भारतीय लेखकों और अधिकारियों ने भारत का असाधारण दरिद्रता के सबंध में अनेक विश्लेषण प्रस्तुत किए। भारतीय राष्ट्रवादियों ने उन्हें प्रायः निस्तार अपर्याप्त तथा असतोषप्रद बताते हुए अस्वीकार कर दिया।

ब्रिटिश प्रशासकों ने अनेक बार भारत की निधनता के लिए भारत की जनसंख्या के आकार व वृद्धि को दोष दिया। उनके अनुसार जनसंख्या की वृद्धि आजीविका के साधनों को शीघ्रता से पीछे छोड़ती जा रही है और इस प्रकार निधनता को अनिवार्य बनाती जा रही है।<sup>174</sup> लॉर्ड डफरिन ने 1888 में सेंट ऐंड्रयूज के भोज में पूछा जब इस देश में बड़े-बड़े जिलों और इलाकों में जनसंख्या बढ़ की तरह बढ़ती जा रही है और





संपत्ति को अधिक प्रभावी बनाए रखने की स्थिति का विकास का माध्यम जुड़ जाती है ता उम्मीदों के परिणाम हाना है उत्पादन में वृद्धि। भारत में भी जनशक्ति बाह्यीय है क्योंकि इस देश के आर्थिक विकास का आधारभूत प्राकृतिक माध्यम अमीन तथा अप्रयुक्त है। इस प्रकार निम्नलिखित स्पष्ट है कि भारत में बुलाई की जड़ बन्धित अधिक जनसंख्या के होकर माफनौर में कम जनसंख्या है।<sup>154</sup> जी०बी० जागी के निम्नलिखित अवतरण में विषय का अधिक स्पष्टीकरण तथा विश्लेषण इस प्रकार में प्रस्तुत किया है

जनसंख्या और उत्पादन में मंदवृद्धि प्राकृतिक अनुपात रहना है जो प्रत्येक समाज के औसत जीवनस्तर का निर्धारण करता है। जब सामान्य और उत्पादन दोनों सामान्य तथा बराबर दर में आगे बढ़ते हैं और अनुपात बनाए रखने हैं तब राष्ट्र के जीवनस्तर में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती। इसके विपरीत जब जनसंख्या असामान्य गति में बढ़ती है और उत्पादन अपनी सामान्य स्थिति में रहता है तब सही अर्थों में अत्यधिक जनसंख्या का रोग माना जाता है। जब उत्पादन गिर जाए और जनसंख्या सामान्य गति में बढ़ रही हो तो हम अपर्याप्त उत्पादन का रोग ही कहना चाहिए। पश्चिम की पूँजीपति राजनीतिक अर्थव्यवस्था केवल एक 'अनुपात' शब्द का ही देयती हुई दो नितान्त भिन्न प्रकृति की बुराईयों को परम्पर मित्रा देती है। इसी रूप में यह भारत के संवर्धन में दाना स्थिति का 'अत्यधिक जनसंख्या' का प्रयोग करती है। जैसा कि हम पहले देग चुके हैं, यहाँ जनसंख्या सामान्य गति का अतिप्रमाण करने नहीं बढ़ रही है और यदि देश का कुल उत्पादन आवश्यकता के परिमाण के अनुरूप नहीं बढ़ता जैसा कि देश में भौतिक साधनों की प्रचुरता है, तो यह स्पष्टतः राजनीतिक अर्थशास्त्रियों द्वारा घोषित अत्यधिक जनसंख्या का रोग न होकर अपर्याप्त उत्पादन का ही रोग है जिसे वे लागू मायता नहीं देते।<sup>155</sup>

इसके अतिरिक्त यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो भी उसके परिणामस्वरूप दरिद्रता में वृद्धि होना आवश्यक नहीं, क्योंकि तेजी से उद्योगीकरण करने इसका प्रतिकार किया जा सकता है। इस देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए राटी जुटाने का प्रश्न इस समय निम्नलिखित गंभीर है और दुनिवार है, परंतु हमारी समझ में बढ़ते हुए मजदूरों के लिए पर्याप्त काम जुटाना उससे भी अधिक गंभीर और दुनिवार प्रश्न है।<sup>156</sup> परोक्ष रूप से उस समय सभी भारतीय नेताओं ने यही सिद्धांत अपनाया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारतीय कृषि पर सचमुच आवश्यकता से अधिक दबाव है परंतु यह दबाव अत्यधिक जनसंख्या का फल न होकर देशी उद्योग के बलपूर्वक विनाश तथा निर्यात के अभाव का परिणाम है और यह भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता की देन है।<sup>157</sup> इस समय अत्यधिक जनसंख्या की बात कहना किसी व्यक्ति के हाथ काटकर उसपर अपना काम करने में अक्षम अथवा काम करने में अपयोग्य हान का व्यर्थ करने के समान है।<sup>158</sup> यह कहा गया कि इन परिस्थितियों में अत्यधिक जनसंख्या का सिद्धांत मूल समस्या से जनता का ध्यान हटाने की एक चेष्टा है और यह दुम्बने धावों पर नमक छिड़कने के समान भयंकर रूप से पीड़ादायक तथा अपमानजनक है।<sup>159</sup>

भारतीयों की दरिद्रता के संवर्धन में एक अत्यधिक पिछा पिछा सरकारी स्पष्टीकरण



भारत की निधनता का बहाना न होकर एक सामाजिक रोग है। इस रूप में भारतीय नेताओं ने सामाजिक उत्सवों पर अनुचित तथा अधिब व्यय की भूमना भी की तथा आत्मसंयम का प्रचार भी किया।<sup>००</sup> जहाँ तक बचहरिया द्वारा किसानों के गरीब होने का प्रश्न था राष्ट्रवादियों की दृष्टि में इसके लिए स्वयं ब्रिटिश राज्य ही दोषी था, क्योंकि बचहरिया उमकी देन थी, राष्ट्रवादियों ने तत्परता में इन बचहरियों का समझौता समिति का स्थापना अथवा पुरानी पचायत व्यवस्था के पुनर्द्वार द्वारा हटाने का समयन किया।<sup>०१</sup>

भारतीय नेताओं ने इस मत का भी पडन किया कि भयंकर दर से मूद बमूलन जाने साहूकार ग्रामीण जीवन के विनाश का तथा भारत की दरिद्रता का महत्वपूर्ण कारण थे।<sup>०</sup> उनके दृष्टिकोण का विस्तृत विवरण इंगी ग्रंथ के दशम अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। उनके विचार में किसानों की दरिद्रता में साहूकार की भूमिका गौण थी। वस्तुतः वह किसानों की दरिद्रता के लिए उत्तरदायी कारणभूत तत्व ही नहीं था। वह तो परिस्थितियों का कारण न होकर परिणाम था क्योंकि वेवल पहले से ही अभावग्रस्त और अमहाय किसान ही उसके पास महायता के लिए जात थे।

१९वीं शताब्दी के अंत में जब बार-बार पडने वाले भयंकर अकालों से भारत विनाश का ऐसा बुरा शिकार बना कि उसने समस्त विश्व की आत्मा का भ्रमण कर रखा दिया और जमाकि हम पडने देख चुके हैं, उन्होंने भारत की दरिद्रता की समस्या का देश की राजनीति का प्रमुखतम प्रश्न बना दिया—दरिद्रता के कारणों को अकालों के उद्गमों से मिला दिया गया—तो ब्रिटिश अधिकारियों ने अकालों के वर्षों में और उसके परवर्ती वर्षों में पहले दुर्भाग्य तथा भौतिक पदार्थों के नाश को देखते हुए अकालों को भारत की दरिद्रता के लिए दोषी ठहराया। परंतु इस धारणा के विरुद्ध भारतीय नेताओं ने देशवासियों की दरिद्रता को ही निरंतर, तीव्र और विनाशकारी अकालों के लिए उत्तरदायी स्वीकार किया। इस प्रकार प्रश्न उठा कि अकालों के क्या कारण थे? लाड वजन न उत्तर देने का दायित्व लेते हुए १९०० में अपनी सामान्य सशक्त शैली में कहा, 'अकालों का वास्तविक कारण समय पर वर्षों का न होना और उसके फलस्वरूप फसल का सूख जाना ही था। उसका तक था कि यदि भारत में पडे बहुत बडे सूखे के फलस्वरूप अपरिहाय कृषि उत्पादन की भारी हानि को ध्यान में रखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि कोई भी सरकार न तो आकाश पर नियंत्रण रख सकती है और न ही प्रकृति के इतने बडे पमाने पर विनाशकारी रूप की तथा उसके परिणामों की पहले से ही कल्पना कर सकती है।'<sup>०३</sup> १९०२ तक तो भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल 'यूनाधिक रूप से यह मानने लगे थे कि भारत के अकाल ईश्वर का विधान थे और उन्हें रोकने अथवा हटाने की दिशा में मानव कुछ भी करन में असमर्थ है

किसी सरकार को उस देश में पडनेवाले अकालों को रोकने के लिए कहना जिसकी मौसम सबंधी स्थिति ऐसी हो जैसी भारत देश की है और जिसकी जनसंख्या उस परिमाण में बढ रही हो जैसी इन समय भारत में बढ रही है सवशक्तिमान विधाता के हाथ से विश्व का नियंत्रण छीनकर अपने हाथ में करने को कहना है। गत वर्ष



अनुकूल परिस्थितियाँ के रूप में प्रकृति से मौभाग्य का चरदान भिन्न हुआ है।<sup>10</sup> इस विश्लेषण में समस्या का और अधिक चर्चा बना दिया और प्रश्न उठा कि जब देश मजबूत है तो देशवासी क्या विषय हैं? 11

राष्ट्रवादियों ने अंगरेजों के भारत की दरिद्रता विषय विश्लेषण को निम्नानुसार तथा पक्षपातपूर्ण प्रस्ताव दिए उस अभाव पर किया। वे भारत की दरिद्रता के सही कारणों को जानने के लिए प्रयत्न हुए और अपनी खोज के फलस्वरूप एक निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारत की दरिद्रता पाश्चिमी और अपरिहाय नहीं। यह मानव निर्मित है अतः इसका विश्लेषण तथा निवारण किया जा सकता है। "भारत कुछ एक आर्थिक तत्वा के फलस्वरूप निधन है। उन तत्वा की राज-समीक्षा तथा उत्पन्न नियंत्रण किया जा सकता है।"<sup>12</sup> इस प्रकार समस्या के प्रति शासक और शासित के दृष्टिकोण में एक मौलिक अंतर था जिसका अभी ऊपर निर्देश किया गया है। ब्रिटिश भारतीय प्रशासकों का भारत की दरिद्रता के दो सभ्य कारण प्रस्तुत किए। प्रथम यह तो यह प्रकृति के दूर दूर का परिणाम है अतः यह अमाध्य रोग है। कम से कम इस बाड़े में समय में तो हमें प्रतिवार नहीं किया जा सकता अथवा यह भारतीयों की अपनी सामाजिक अथवा आर्थिक भुक्तियाँ का फल है जिसका प्रतिवार यदि किया जा सकता है तो स्वयं भारतीयों द्वारा अपने आप ही किया जा सकता है। "इस दाना अवस्थाओं में निर्यतता के अस्तित्व तथा निराकरण के लिए शासकों का कोई विशेष शक्ति नहीं।"<sup>13</sup> दूसरी ओर भारतीय नेताओं ने भारत की दरिद्रता के जन्म के तत्वों और शक्तियों को रेखांकित किया। उनके अनुसार जिन तत्वों ने भारत की निधनता में वृद्धि की वे ब्रिटिश राज्य के वे ज्ञान-अज्ञान ज्ञान तत्व और शक्तियाँ थी जिन्हें पूरी डील दी गई और जिनका प्रमुख रूप संप्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन द्वारा प्रतिवार किया जा सकता था।<sup>14</sup> इस प्रकार इतिहास के एक विशिष्ट चरण के रूप में यह तथ्य सामने आया कि बचानिर्देश दृष्टि में उन्नत पश्चिम प्रकृति के तथा वर्तमान सामाजिक शक्तियों के अपरिहाय प्रभाव की भाग्यवादी धारणा का पुष्टि करना है और पिछड़ा हुआ पूर्व मनुष्य की प्रकृति और समाज को नियंत्रित तथा शासित करने की क्षमता को स्वीकार करता है।

भारतीय जनता की दरिद्रता के लिए उत्तरदायी कारणों और तत्त्वों के अनुसार उनके निवारण के उपायों की खोज की घुम में ही भारतीय नेताओं ने कुछ एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रश्नों तैयार किए ताकि उनपर अपनी जांच पड़ताता, वाद विवाद तथा आदालतें चलाए जा सकें। अतः उन्होंने अपनी आर्थिक नीतियों और दृष्टिकोण निर्धारित किए तथा भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक तथ्य तथा उसकी प्रकृति को समझने की चेष्टा की। निधनता को हटाने के सघन के समय तथा आर्थिक नीतियों का कार्यरूप में परिणत करने के समय उनकी राजनीति चेतना एक रूप ग्रहण करती गई। इस विकास की प्रक्रिया का अर्थ यह है हमें अगले अध्यायों में करेंगे। यहाँ इतना स्मरण रखना आवश्यक है कि निधनता की समस्या ने भारतीय नेताओं की सभी परवर्ती खोजों, मतभेदों तथा प्रचार आदि के लिए निरंतर सजीवनी का काम किया।

सदस्य

1 दादाभाई नौरोजी के 'स्पीचेज ऐंड राइटिंग्स (मद्रास तिथिरहित) (निर्देश के लिए इस जाग 'स्पीचज से सक्तित किया जाएगा।) पृ० 669-670

2 जिन लोगों की बहुधा धारणा की जाती थी वे इस प्रकार थे

शांत बानून और व्यवस्था पश्चिमी गिगा केंद्रीकृत प्रशासन देश का राजनीतिक एकीकरण और इन सबके फलस्वरूप राष्ट्रीय भावना का विकास रेल तार अस्पताल आदि।

दिए—सी० एस० पारीय द्वारा सापादिन—नौरोजी व एमज स्पीचेज ऐंड राइटिंग्स (बयई 1887) (निर्देश के लिए इसे आगे एगेज से सक्तित किया जाएगा) पृ० 267 37, 131 2. 'स्पीचेज—पृ० 235-6 इटियन नेशनल काग्रस भाग 1 काग्रस प्रमिडटो (अध्ययन) के एडुसेज (भाषण) मद्रास, तिथिरहित (निर्देश के लिए इस जाग सी० पी० ए० से सक्तित किया जाएगा।) पृ० 6-10 धरजेजी शासन के अर्थ लागू की समीक्षा के लिए उगाहरण व रूप में दिये, सी पी ए म अनव काग्रस अध्ययन पृ० 4 81 115 307 11 546 375 6 738 जी० वी० जोशी के राइटिंग्स ऐंड स्पीचज (पना 1912), पृ० 616 जार० एन० मुधोनकर की रचना दि इकोनामिक बडीशन आफ दि पीपुल आफ इंडिया इटियन पारिनिटिक्स (मद्रास, 1898), पृ० 3-8 ऐन्प्रड नडी दि पावर्टी आफ इंडिया वहा पृ० 106 सी० वी० चिनामणि कृत' इंडिया ऐंड लाड बजन हिंदुस्तान रिब्यू तथा वायस्य समाचार (निर्देश के लिए इसे आगे एच० जार० से सक्तित किया जाएगा)—जून 1901 पृ० 451 जार० सी० दत्त द्वारा लिखित, 'इकोनामिक हिस्ट्री आफ इंडिया अर्ली ब्रिटिश काल (1901 में प्रथम प्रकाशित मस्वरण का सदन में 1956 में मुद्रित रूप) (निर्देश के लिए इसे जाग इ० एच०' से सक्तित किया जाएगा) पी० वी० एस० एन० बनर्जी के स्पीचेज ऐंड राइटिंग्स (मद्रास, तिथिरहित) (सदस्य के लिए इसे आगे एस० डार्लू० से सक्तित किया जाएगा) पृ० 219 20 258-9, 303 5 331 इसके अतिरिक्त देखिए दि अमृतवाजार पत्रिका (निर्देश के लिए इस जाग ए० वी० पी० से सक्तित किया जाएगा)—दिसंबर 1878 24 नवंबर 1877

3 नौरोजी एमज, पृ० 28

4 वही पृ० 134 5 भोलानाथ चंद्र मुर्जी के मगजीन (कलकत्ता) में 1875 6 में बिना नाम के प्रकाशित) अपने अपेक्षाकृत अप्रसिद्ध परन्तु अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण लेख ए वाइस फार दि कामस ऐंड मनुफबचरस आफ इंडिया—(निर्देश के लिए इसे जाग एम० एस० से सक्तित किया जाएगा) में लिखत हैं 'देश के लिए वास्तविक जनता का सुभान में जन्म भारतीयों ने अपने चारा और की धोया चबाचौध से चौधिया कर अपने शासकों पर विश्वास करत हुए उनके दृष्टिकोण को बिना किसी आलोचन प्रत्यालोचन के स्वीकार कर लिया। भारतीयों ने बन् क समान धरजेजी अधिकारियों का व्यापार नीति पर अग्रविश्वास ही किया, परन्तु दिन प्रतिदिन पान का प्रकाश उनके दिमाग को धुंध को साफ कर रहा है। भारतीय जितना अधिक गहराई से विचार करते गए उतना ही यह तथ्य अपने मन रूप में उनके सामने स्पष्ट होता गया कि 'अगरजा व्यापार नीति जनता के मांग की निरंतर सकीष बनाती हुई उन्हें और दरिद्रता की ओर ले जा रही है'

—खंड II 1873 पृ० 83-4

बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में राष्ट्रीय दृष्टिकोण के इस परिवर्तन की अत्यंत ही सजीव

## 26 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास

रूप में इन शान्ति में प्रकट किया 'सर्वप्रथम भारतीय कांग्रेस के अनुशासन से अत्यंत समतुल्य हुए। रेल तार सड़कों पुलों तथा स्मूला आदि ने उन्हें विस्मय विभोहित कर दिया। उपद्रव समाप्त हो गए तथा सौग शान्ति और स्थिरता का आनंद भोगने लगे। साग यह कहने लगे कि एक भ्रष्ट व्यक्ति भी धुले रूप में सोना लेकर बनारस से रामेश्वर तक का यात्रा कर सकता है परंतु जिस प्रकार मन्ट्रि का नशा दीध वास्तव नहीं बना रहता, उसी प्रकार शान्ति का कारण उत्पन्न यह मतिभ्रम भी वाक्यी समय तक न बना रहा साग यह अनुभव करने लगे कि एक भ्रष्ट व्यक्ति भी धुला सोना लेकर यात्रा अवश्य कर सकता है परंतु दिन प्रतिदिन सोना दुर्लभ होता जा रहा है

—जी० पी० प्रधान तथा ए० के० भागवत के 'लोकमाय तिलक' (बंबई 1958) पृ० 72 से उद्धृत

और देखिए बंगाली 10 मई 1884 'इंडियन स्पेक्टर', 18 मई 1884 मराठा 21 दिसंबर 1884 6 जून 1886 के मराठा में प्रकाशित ए० एल० राय का लेख जी० मुबद्दय्य अय्यर की रचना 'सम इकोनामिक आम्पेचटस आफ ब्रिटिश इंडिया (मार्च 1903) (निर्देश के लिए इसे आगे इ० ए० से संकेतित किया जाएगा), पृ० 337 एल० एम० घोष की कृति सी० पी० ए० पृ० 762

5 1901 (नदन) में प्रकाशन के समय से ही भारतीय राष्ट्रवादिता के लिए सचमुच पाठमस्तक बनने योग्य कृति प्रायः ब्रिटिश इंडिया में पृ० 127 9 131 में विलियम डिग्वी महोपाय ने 1876-1900 तक 18 अवकाशों की क्रमशः गणना की है जिनमें चार ता अभूतपूर्व रूप से भयंकर जवाल थे

6 परंतु हमसे भी गंभीर प्रश्न यह उठा कि भारत में इतने दुर्भिक्ष क्या पड़ते हैं? मूल से मूल्य दर इतनी भयंकर क्या है? विश्व के किसी अन्य सम्य देश में उन्होंने ऐसे दुर्भिक्ष कभी नहीं सुने थे

आर० सी० दत्त 'स्पीचज एंड पेपस आन इंडियन क्वेश्चंस 1897 1900 (बलवत्ता 1908) (निर्देश के लिए इसे आगे 'स्पीचज संकेतित किया जाएगा), पृ० 36

इंडियन नेशनल कांग्रेस (सदम के लिए इसे आगे आइ० एन० सी० से संकेतित किया जाएगा) के 1900 वर्ष का प्रस्ताव 11 भी देखिये

7 उदाहरण के लिए देखिए नौरोजी एसेज पृ० 135 तथा जब आप हमारी वास्तविक इच्छाओं को जान लेंगे तब "याय करेंगे इसमें भुझ लेशमात्र भी सदह नहा। वही और भी देखिए सी० पी० ए० पृ० 13 22 3 91 2 129 149 188 324 380 397 405 475 490, 532

8 उदाहरण के लिए देखिए नौरोजी एसेज पृ० 128

9 जी० के० गाखले 'स्पीचज (मद्रास 1916) पृ० 52

10 उदाहरण के लिए देखिए नौरोजी पावर्टी एंड अन ब्रिटिश इंड इन इंडिया (सन् 1901) (निर्देश के लिए इसे पावर्टी से संकेतित किया जाएगा) पृ० 147 तथा आई० एन० सी० का 1900 का द्वितीय प्रस्ताव

11 उदाहरण के लिए देखिए रानाडे 'एसेज आन इंडियन इकोनामिक्स' (बंबई 1892) (निर्देश के लिए इसे एसेज से संकेतित किया जाएगा) पृ० 191 2 तथा जा० बा० जोशी की पूर्वोक्त रचना पृ० 754





## 28 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास

25 यू.ई.डी.या (कलकत्ता) 12 अगस्त 1901 शपादश्रीय म आगे कहा गया है 'और यह मय का उत्पादन करता है कि सभी उपवादी राष्ट्रीय नता प्रमुख रूप से भावात्मक राष्ट्रीयतावादी में रचि नहा वेत थ और यद्यपि थ नवीन भारत का प्रभावित करन धाने किमी भा— राजनीतिक सामाजिक अथवा धार्मिक—प्रश्न की उपेक्षा कदापि नता करना चाहत थ तथापि वे जाज का आर्थिक और शारीरिक सामस्याआ क लिए निरंतर आंगानन को हा अपना विशिष्ट विषय बनाना चाहते थे

26 रानाड एमड ५० 5

27 इसी पत्र न 7 नवंबर 1894 क अंग मे इन दृष्टिकोण क एक जय मौलिक पत्र की आर इन प्रकार सक्न किया शरीर जीर आत्मा को एक भाष रय पात्र क माधना मे हीन राष्ट्र कभा सतुष्ट नहा हो सक्ता कभा स्वामिभक्त नहा हो सक्ता

28 1886 मे भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस के मभापनि पत्र से अपन भाषण म दागभाई नौराजी न पापणा की यदि अन्त भारत दुर्भाग्य क गट्टे म गट्टे स गट्टर घमना ही गया तो मगरेजा रा य से प्राप्त नाम तथा अगरेजो शासक की सदर कल्पनाए सक्ता निरयक ही हा जाएगा

—मो०पा०ए० ५०22

सुरद्रनाथ बनर्जी द्वारा सपान्ति दि दगानी न 9 माच 1902 म निघा म दान की कीन अस्वाकार करेगा कि अशक्त और भूय साया क लिए वानून जीर व्यवस्था देन वाला एन अच्छी जीर वशानिक सरकार को अपेक्षा प्रतिदिन की राटी अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है निस्सदह कानून और व्यवस्था बहुत अच्छा चाजे है परतु रोग उनस भा अधिक अच्छा है

साथ ही देखिए एन०एन० बनर्जी स्पीचेज (1880 84 घड II) (कलकत्ता 1885) ५०35 सा०पा०ए० ५०697 बगाली, 28 जनवरी 1882 मराठा 30 दिसबर 1894, ५० मन्हा स्पाचज एंड राइनिंग (इलाहाबाद 1905) (निर्देश क लिए इस आगे स्पीचज से सक्नित किया जाएगा) ५० 451 नौराजी स्पीचेज ५० 389 भारतजावन 11 दिसबर 'इन दी रिपोन आन मटिव प्रस इन नाथ-वेस्ट प्राविसेज एड अक्ध (निर्देश के लिए इमे आ आर०एन० पी०एन० से सक्नित किया जाएगा) 19 दिसबर 1899 एडवोकेट 27 नवंबर (वर्षा 29 नवंबर 1901)

29 कांग्रेस ने 1902 क सत्र म तीसरे प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए जा एम० अय्यर का तर्क था कांग्रेस अपनी सारी शक्ति और सारा ध्यान जहा तक सभव हा विशिष्ट तथा अनिमन्वपूर्ण प्रश्ना पर ही केन्द्रित करे जनता की दरिद्रता का प्रश्न सर्वोच्च और ध्यानाकर्षक प्रश्न है वस्तुतः दस एक प्रश्न का सतापत्र तथा सही समाधान ही अन्य सभा दिशाओ म देश के सुधार का एकमात्र आधार है। रिपोट आफ इन्डियन नेशनल कांग्रेस—1902 (निर्देश के लिए इमे आगे रिप आई०एन०सी० से सक्नित किया जाएगा) ५० 72 साथ ही देखिए एन०के०एन० अय्यर रिप०आई०एन०सी० —1901 ५० 142

30 इसाड (चतुथ बग) खड 27 लगभग 1135

31 15 अगस्त 1947 तक क्राध और भत्तना जारी रही भारताय इन्डिहाम के ब्रिटिश काल के इतिहासकारो म आज भी दस सबध म मनभद है

32 नौराजी पावटी ५०1

33 वही ५० 31

34 नौराजी इन एमिनेंट इन्डियस ५० 161

- 35 उनके द्वारा इंग्लैंड में अपने प्रिय विषय पर सनडो भाषाया म से अधिकांश उनकी उपयुक्त तीन प्रकाशित कृतियाँ एसेज, स्पीचेज 'एंड पावर्टी' म भा गिए गए हैं। बहुत सारे अन्य भाषण पूरा अथवा सक्षिप्त रूप म भारत म खोज का विषय हैं। आई०एन०सी० की ब्रिटिश कमेटी का 1890 से सदन में प्रकाशित जर्नल
- 36 नोरोजी पावर्टी, प० 161
- 37 वही प० 88
- 38 नोरोजी स्पाचेज परिशिष्ट ए, प० 6
- 39 नोरोजी पावर्टी, प० 652
- 40 प्रस्ताव II 1886 के वाद्यम क प्रतिवेदन की भूमिका म कहा गया है कि जनता में व्याप्त घोर दरिद्रता के प्रति किसी एक प्रतिनिधि ने भी किसी रूप म सहह अथवा प्रश्न प्रस्तुत नहीं किया। ब्रिटिश राज्य क प्रत्येक एकल प्रांत तथा उपप्रांत के सभी प्रतिनिधियों म एक क उपरान दूसरे ने अपने प्रांत के निम्न वर्ग में व्याप्त दुर्भाग्य के भुक्तभोगी होने का वर्णन किया। (प० 18)
- 41 प्रस्ताव III
- 42 दखिए 1892 का प्रस्ताव X 1893 का VII 1894 का III 1895 का XXII 1896 का XII तथा XIII, और इसी प्रकार से अन्य
- 43 उदाहरणार्थ वारहवें कांग्रेसी सभापति आर०एम० सायानी न दुःख प्रकट करते हुए कहा, 'भारत एक इतना दरिद्र राष्ट्र है कि भारतीय दो समय का भोजन भी नहीं जुटा पाते। सचमुच इनमें से कुछ भारतीय तो वास्तव में ही भुखमरी के शिकार हैं और बहुत सारे कठिनता स बवल एक समय का भोजन जुटा पाते हैं। (सी०पी०ए० प० 351) 1897 क सभापति सी शंकरन नयर ने शोकाविह्वल हाकर कहा, भारत की दरिद्रता प्रत्येक िशा में प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक रूप म अपने आपको नुभारे सामने स्वतः प्रकट कर रही है, (वही प० 604) सी०पी०ए० प० 506 म एन०पी० चणवरकर ने सी०पी०ए० प० 761 में एल०एम० घाघ ने तथा अन्य बक्ताओं ने कांग्रेस मच स वर्षों तक भारतीय जनता की निर्धनता का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया
- 44 प्रमाणस्वरूप, बगाली किसान को उदघत करते हुए सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने उसके दुर्भाग्य की अत्यंत दयनाय स्थिति की उसके भूखे मरत बच्चा की, सूखकर भाटा बन उसक पशुओं की तथा सूखे बजर पड़े उसके खेतों की दुखमरी कहानी का वर्णन करके बताया कि वस्तुतः उसकी दरिद्रता की गहराई का अथवा उसके दुर्भाग्य की जनतता का वर्णन करने म भाषा अनमथ है एस० एन० बनर्जी स्पीचेज 1886-1890 खंड III (कलकत्ता 1890) प० 13 1890 म उन्होंने कांग्रेस का ध्यान करोड़ों भारतीयों को अपमानित करने वाली दुर्भाग्यपूर्ण और कुलित दरिद्रता की ओर खींचा। (वही प० 195) जस्टिस रानाडे ने 1890 में लिखा 'इस प्रकार की दरिद्रता के अस्तित्व के प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं। इस दश की दरिद्रता तो विलक्षण है।' हमें केवल अपने रास्ते पर चलना है और अपनी आर्थिक अवस्था के अत्यंत धाय पणों का अध्ययन करना है। मह सत्य हमारे सामने उजागर है कि हमारे साधन सीमित हैं। एसेज प० 182 उसी वर्ष जी०बी० जाशी ने लिखा 'बढ़ती हुई असामाय दरिद्रता समाज क निम्न स्तर क लाखों-करोड़ों को पहले से ही चूसने और अपमानित करनेवाली दरिद्रता सारे देश म पहल से ही व्याप्त दुखों और दुर्भाग्य म और अधिक बढ़ि करने वाली दरिद्रता पूर्वोद्धत प० 818 आर० एन० मधोलकर ने 1891 में कांग्रेस अधिवेशन म भारत की दरिद्रता प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा था, 'आज का भारत अत्यंत विषाणपूर्ण तथा सबया अम्राट्टनिक चित्त प्रस्तुत करता है।

- रिप०आई०एन०सी० 1891 पृ०19 आर०मी० दत्त ने 1901 म लिखा था आज के भारतीयों की दरिद्रता की तुलना किसी भी सम्पन्न देश के नागरिकों से नहीं की जा सकती।' इ०एच० 1 पृ० 6 साथ ही दक्षिण उनका 'इंग्लैंड और इंडिया' (सन् 1897) पृ०125-6 तथा 'इकोनामिक हिस्ट्री आफ इंडिया इन दी विकटोरियन एज' (सन् छठा संस्करण प्रथम 1903 म प्रकाशित) (निर्देश के लिए इसे आगे ई० एच० II से संकेतित किया जाएगा), पृ०5 भारत म वृषि-श्रमिकों की दरिद्रता के विस्तृत विवरण के लिए देखिए ई०एच०II पृ०606. 1902 म सी०वाई० चिंतामणि ने लिखा, 'दुर्भाग्य और महामारा भारत की सामान्य प्रवृत्तियाँ बन गई हैं और मेरे देश के लाखों निरपराध और शान्तिप्रिय नागरिक भ्रष्टमरी तथा उनके प्रभाव से मृत्यु का श्रावण बन रहे हैं। एच०आर० जुलाई 1901 पृ०447 और देखिए मातृवीय की स्पीचज मद्रास तिथि रहित)
- 45 रिब्यू आफ इंडियन साल्ट टक्स (भारत नमन कर की समीक्षा) जर्नल आफ पूना 'मावजिनिक समा (निर्देश के लिए आगे 'जे०पी०एम०एम०' से संकेतित किया जाएगा) जुलाई 1881 (खंड IV स०1) पृ० 60
- 46 ऐसे हवाल इतने अधिक हैं कि उन्हें यहां देना कठिन है' अमृत बाजार पत्रिका 'दि बंगाली रिहिदू मराठा और विभिन्न प्रान्तों के देशी प्रेम पर प्रतिवेदन तथा ममीनाघात अवधि के विभिन्न ममाचारपत्र भारत का निर्धनता की टिप्पणियों से भरे पडे हैं।
- 47 उदाहरणार्थ देखिए 'दि अमृतबाजार पत्रिका 13 अप्रैल, 'इन दि रिपोर्ट आफ नेटिव प्रस फार बंगाल (निर्देश के लिए इस आगे आर०एन०पी० बग से संकेतित किया जाएगा) 24 अप्रैल 1880 मित्रविलास—8 अक्टूबर 'इन दि रिपोर्ट आन दि नेटिव प्रस फार दि पंजाब नाथ वस्तु प्राविसज एंड अवध' (निर्देश के लिए इस आगे 'आर०एन०पी०पी०एन०' से संकेतित किया जाएगा) 7 अक्टूबर 1880 सजीवनी—14 जून आर०पी०एन०बग०—21 जून 1884 निबधमाला, मद्र इन दि रिपोर्ट आन नेटिव प्रस फार बर्बई (निर्देश के लिए इस आगे आर०एन०पी०बग से संकेतित किया जाएगा) 23 नवंबर 1880 'नरग'—2 मार्च 'आर० एन०पी०एन०—10 मार्च 1891 प्रपंच मित्रन—10 नवंबर 'इन दि रिपोर्ट आन नेटिव प्रस फार मद्रास (निर्देश के लिए इसे आगे आर०एन०पी०एम० से संकेतित किया जाएगा) 30 नवंबर 1899 निबधमाला—जून आर० पी० एन० बग—31 दिसंबर 1881 बंगाल सजीवनी' 30 दिसंबर आर० पी० एन० बग 10 जनवरी 1881 हिंदी प्रपंच नवंबर आर० एन० पी० पी० एन० 11 नवंबर 1880 हरिश्चंद्रिका स०8 (वही० 25 नवंबर 1880 बंगाली 23 जनवरी, 1891 तथा हिंदू 25 अप्रैल 1884
- 48 नवंबर 1895 आर एन०पी०बग 9 नव० 1893
- 49 रामगोपाल द्वारा लिखित लोचमाय तिलक ए बायोग्राफी मे उद्धृत (बर्बई 1956) पृ० 186-8 दाद म सरकार ने तिलक को विद्रोह के अभियोग म दंडित करने के लिए इन पद्यों का उपयोग किया था।
- 50 रिपोर्ट आन दि नेटिव प्रस फार दि पंजाब' (निर्देश के लिए आगे आर०एन० पी पी से संकेतित किया जाएगा) 4 फरवरी 1893
- 51 गोखल स्पीचज पृ०16 1873 के प्रारंभ मे ही भालानाय चंद्र घोषित कर चुके थे वहुं संभव जनममुखाय को खुशहाल बनाए बिना देश की भौतिक संपन्नता की धात एक भ्रम कल्पना तथा बचवास के अतिरिक्त और कुछ नहीं। पूर्वोद्धृत पृ० 66 1881 मे तिलक ने यह विचार

- व्यक्त किया था जब तक देश के बहुसंख्यक मेहनतकशा की स्थिति में सुधार नहीं होता तब तक आर्थिक दृष्टि से देश के सुधार की बात ही नहीं की जा सकती डी०वी० ताम्बुणवर के 'लोकमान्य तिलक' से उद्धृत (सदन 1956), पृ० 319
- 52 गोखले स्पीचेज पृ० 934 (तथा जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 753) त्रमण नदी इंडियन पार्लिटिव्स पृ० 106 गोखले रिप०आइ०एन०सी 1895, पृ० 105 जी०सी० अम्बर ई०ए०, पृ० 6, जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 818 देखिए। यू०पी० कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ए० नदी ने 1898 में 'इंडियन पार्लिटिव्स' में प्रकाशित अपने एक निबन्ध 'पावर्टी आफ इंडिया' में स्पष्ट विज्ञापित किया कि वस्तुतः आज कपक ही भारत हैं अर्थात् भारत व्यवहारिक रूप से कृपका का ही देश है और यदि कपका की स्थिति दयनीय है तो अवशिष्ट अन्य भौतिक प्रगति का कोई मूल्य ही नहीं' उन्होंने एडम स्मिथ को उद्धृत किया 'जिस समाज का अपेक्षाकृत विशाल समुदाय निधन और दुर्भाग्यग्रस्त है वह कभी समृद्ध और विकसित नहीं कहा जा सकता।' (पृ० 106) उन्होंने आगे कहा यह देखकर कैसे सतोष किया जा सकता है कि ऋण धन वाले साहूकार निधनों के दुर्भाग्य से लाभ उठा रहे हैं अथवा निर्यात व्यापारी देश के जीवन रक्त को ही चूसकर उससे ऊँचा मुनाफा कमा रहे हैं? (पृ० 105) उन्होंने स्वीकार किया ब्रिटिश राज्य में मुटठी भर राजा और नवाब धनी जमींदार हैं। मुटठी भर महाजन और व्यापारी भी धनी हैं। कुछ एक व्यापारी और व्यवसायी भी खाते-पीते हैं। उन्होंने सारा मोना चांदी इकट्ठा कर रखा है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट उल्लेख किया 'जनता का बहुत बड़ा बग धार दरिद्रता में गात खा रहा है।' (पृ० 112) और देखिए एन०के०एन० अम्बर रिप०आइ०एन०सी० 1901, पृ० 140-1
- 53 जोशी पूर्वोद्धृत पृ० 658 दत्त ई०एच० II पृ० 605 6 जी०एस० अम्बर ई०ए० पृ० 191
- 54 दत्त ई०एच० II पृ० 606
- 55 नौराजी पावर्टी पृ० 188 उनके एसेज भी पृ० 98 स्पीचेज पृ० 591
- 56 नौराजी एसेज पृ० 98 जोशी ने इस बात से इनकार किया कि भारतीय दरिद्रता का कारण धन का अगमान वितरण है जैसा कि पश्चिम के कुछ देशों में है (पृ० 75) उन्होंने आगे बताया हमारी समस्या समाजवादी समस्या नहीं है जिसे समाजवादी तरीकों से सुलभ किया जा सके (पृ० 753) हमारी दरिद्रता की बुराई कुछ विशिष्ट वर्गों तक सीमित नहीं है हमारे घर धन के वितरण में अधिक असमानता, एक वर्ग के दूसरे वर्ग में अंतर मजदूरों की मांग 'पूजी का दायित्व और संपत्ति का अधिकार' की समस्याएँ नहीं हैं जिनका सुलभाना आवश्यक है। (पृ० 819)
- 57 पी० के० गोपाल कृष्णन डबलपमेट आफ इकोनामिक आइडिया इन इंडिया 1880 1950 (नई दिल्ली 1959) पृ० 183 जोशी ने इस बात पर बल दिया कि निधनता की समस्या अनिवाय रूप से तथा निश्चित रूप से एक औद्योगिक समस्या है
- 58 जोशी (पूर्वोद्धृत, पृ० 819) हमारी स्थिति अपवाद रूप है। प्रतिद्वंद्वी वर्गों के विरोध में खड़े सारे समाज का प्रश्न है। हम न तो महारानी एलिजाबेथ के पगु कानून का आवश्यकता हैं और न ही फ्रांस का प्रांतीय सरकार के चित्तालय में सजाय योग्य कानून की। हम ता सामूहिक प्रश्न की एक विस्तृत तथा बुद्धिमत्तापूर्ण योजना इसी संकेत से भारत में ब्रिटिश प्रवृत्ता एकाएक बगमदवादी बन गए और सारा शेष जमींदारों साहूकारों और बकीना पर

## 32 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास

डालबर एक बग को दूसरे बग में दिखाने करने में प्रयत्न में लग गए

- 59 द्वितीय अध्याय में इंग्लैंड विभिन्न विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। जोर देकर, गानाह एमेज पृ० 23 183 185 191 जाना पूर्वोक्त पृ० 738 760 803-4, दस ई०एच० पृ० VII बमरा 31 मार्च (जारीकरण 1903) 'बढ़ते हुए हाथा के लिए उत्तरोत्तर काम की कमा तथा मनुष्या के लिए छाया की कमी' यह हमारी वर्तमान सामान्य औद्योगिक स्थिति की महिष्य रूपरेखा है

(जोशी, पूर्वोक्त पृ० 804)

- 60 दक्षिण भारत सरकार का प्रस्ताव परिषद सं० 96 एफ/6-59 दिनांक 19 अक्टूबर 1888 (परमिन प्राग सं० 19 निसंग 1888)

- 61 वहा कडिका 4

- 62 वहा परिशिष्ट-ग मद्रास में यह पाया गया कि 6 द० मासिक वनभोगा व्यक्ति गार परिवारों को पूरा महाना तान समय प्रतिदिन चावल बाजरा ताडा अथवा मछली के साथ समस्त के तिनारे के पास का भाजन तथा मत्पाह में एक दो-चार हनात किया माग किया गया है। बबर में छाछ पदार्थों की अपर्याप्तता के अभियोग का पूर तौर पर अस्वीकार कर लिया गया। प्रांतीय सरकार ने मण्डल प्रस द्वारा धन विषय में निधनता का व्यापकता के अभिमाग का खर्चा बरत हुए इस बात से इनकार किया कि दक्षिण में कहां भी व्यापक रूप से चुरा दसा है। मध्य प्रांत में मुख्य आयुवन मि० भूराजी दस निष्पत्त पर पहुंच कि निस्संशुद्ध देश में निधनता है फिर भी अवस्था बुरी नहीं। लाग अच्छा घात-घात है। नाथ-वेस्टर्न प्राविंस (उत्तर-पश्चिमी प्रांत) में एटा के कमिश्नर मि० चुर न विचार प्रकट किया छतिहर जनता हृष्टपुष्ट है और यह उनका संपन्नता का प्रमाण है

- 63 भारत सरकार का प्रस्ताव दिनांक 27 नवंबर 1893 (राजस्व तथा रपि विभाग) (सामान्य) पाहल सं० 95 प्रमाक 7) बगाल के प्रतिवन्दन में दायी किया गया है निम्न बग के लोप संपन्नता के ऊच और प्रतिदिन उत्तरोत्तर बढ़ते स्तर का आनन्द भोग रहे हैं

- 64 1891 2 तथा परवर्ती 9 वर्षों में भारत का स्थिति और नतिज भौतिक प्रगति का प्रदत्त विवरण (सत्ताय दसवापिनी प्रतिवेदन) ज०ए० बस द्वारा तयार किया गया (सदन 1804) पृ० 427

- 65 उदाहरण के लिए भारत सरकार के भूतपूर्व वित्त सन्स्य सर जान स्ट्रुची ने अपने 'इंडिया (नया तथा अद्य सशोधित-परिवर्द्धित संस्करण सन् 1894) में लिखा अब प्रत्येक किसान प्राचाय काल के ब्राह्मणों अथवा जमानरा जसी वेशभूषा धारण करता है। उसकी पत्नी को प्राय अवकाश रहता है। उसके चाल के गहने कमवत रहते हैं। अपनी जीवन की आवश्यकताओं का तथा सामान्य विलास की पूर्ति के परचात भी उमक पास महन घरीदने के लिए निरतर कुछ बचा रहता है। (पृ० 303), और देखिए जान स्ट्रुच रिचाड स्ट्रुच की 'फार्नेस एंड पालिस बकन आफ इण्डिया 1869-1881 (सदन 1882), पृ० 8 'आज वेस्ते की इंडियन पोलिटी' (सन् 1884) पृ० 314 340

- 66 सर डब्ल्यू० इटर भारत सरकार के सांख्यिकी विभाग के महानिर्देशक थे और सर चार्ल्स हिलट गवर्नर जनरल की कैबिनेट के सांख्यिकी निर्माण सन्स्य थे। ये दोनों टिप्पणियाँ असद्व्य लेख और पुस्तकों में दुनूराई गई। उदाहरण के लिए देखिए 'मैरोजी स्पीचर' पृ० 587 'मालवीय स्पीचर' पृ० 227 'जोशी पूर्वोक्त पृ० 76 पी सी० राज दि पावर्टी प्राब्लम इन इंडिया (बलभता 1893) (निर्देश के लिए इसे आगे पावर्टी संसकेतित किया जाएगा) पृ० 149

नयी 'इन इंडियन पालिटिक्स', पृ० 115 मधोलकर वही पृ० 36 उस समय के राष्ट्रीय साहित्य में अधिकशक्तता मिलन वाले अर्थ अवतरणों में से साइ सारंग (1864) का यह अवतरण कुल मिलाकर भारत एक अति निधन देश है 'बहुसंख्यक जनता कठिनता से जीवन निर्वाह कर पाती है' सर ई० बरिंग (1881) का कथन 'भारतता समाज अत्यंत निधन है सर ए० बालविन का कथन 'भारत की जनता का बड़ा दग इन प्रकार के व्यक्तियों का है जिनकी आय जावन रक्षा के लिए अनिवाय आवश्यक मामलों के घरीदने के लिए कठिनता से पर्याप्त है अतः वे जीवन के लिए अनिवाय उपयोग वस्तुओं का अभाव में जीवन बिताने को विवश हैं' रडोल्फ फर्चिल तथा 1898 क बकाल आयाग क प्रतिवेदन को भी प्रायः उद्धृत किया जाता था अन्व सेजको और बकनामा न 1888 की इन्फरिन्स जाच क परिणामों तथा जिला अधिकारियों के प्रतिवेदन का उद्धृत किया दक्षिण जाशी पूर्वोद्धृत पृ० 763-6 बी०एन०धर रिप०आई०एन०सी०—1892 पृ० 102, ए०नदा रिप०आई०एन०सी०—1894 पृ० 55-6 मधोलकर 'इंडियन पालिटिक्स पृ० 36 एन०एन०बनर्जी सी०पा०ए० पृ० 686

दक्षिण नोरोजा 'पावर्टी', पृ० 188 तुलनीय वा०क०आर०वी० राव दि नशनल इनकम आफ ब्रिटिश इंडिया 1931 32 (सदन 1940), पृ० 7 तथा पी०ए० वधवा और क० टी० मर्सेट आकर इकोनामिक प्रॉब्लम (बंबई, 1946) पृ० 522

इंडियन धारन 'लाग टम ट्रेड्स इन आउटपुट इन इंडिया इन इकोनामिक ग्रोथ ब्राजील इंडिया जापान सीमन कुजनिटम तथा इतर द्वारा संपादित (इरहम एन०सी० 1955) पृ० 105 राव दि नशनल इनकम आफ ब्रिटिश इंडिया 1931 2 पृ० 2

उनकी सगणना विधि को जानने के इच्छुन व्यक्ति देखें उनकी 'पावर्टी तथा अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया' पृ० 4-25 और पृ० 147 73 संक्षेपत उन्होंने कुल वापिस कृषि उत्पादन में खानों कारखानों मछली उद्योग के अनुमानित उत्पादन तथा मामूली से विदेशी व्यापार के वापिक लाभ के साथ साथ बड़ी सख्या में होने वाले दबी उत्पादों को गिन जोड़कर 1867 8 की कुल राष्ट्रीय आय की सगणना की यहा यह उल्लेखनीय है कि उन्होंने सेवाओं से प्राप्त आय को स्पष्ट रूप से आय नहीं माना क्योंकि उनका तर्क था कि यह वास्तविक आय न होकर पूव संचित आय का उपयोग मात्र है (पृ० 180-5 तथा 220) दादाभाई के राष्ट्रीय आय संबंधी विचार के औचित्य का समीक्षा के लिए देखिए आर०पी० मसानी दादाभाई नोरीजी दि ग्रैंड ओल्डमन आफ इंडिया' (सदन 1939) पृ० 203-4 के०टी० शाह तथा के०जी०खन्नात वर्य एंड टक्सेवल क्पेसिटी आफ इंडिया (बंबई 1924) पृ० 7 बी०के०आर०वी० राव 'एन ग्लोबल इंडियन नशनल इनकम 1925 9 (सदन 1939) पृ० 19 22 वाडिया और मर्सेट पूर्वोद्धृत पृ० 520 3 सुरेंद्र जे० पटेल लाग टम चेंजेस इन आउटपुट एंड इनकम इन इंडिया' 1896 1960 इन इंडियन इकोनामिक जनरल जनवरी 1958 (खंड V, सख्या 3) पान ए बरन रि पोलिटिक्स इकोनमी आफ ग्रोथ (भारतीय सरकार नई दिल्ली 1957) पृ० 36 7 दादाभाई के राष्ट्रीय आय संबंधी दृष्टिकोण क सद्धातिक गुण-दोषों को चर्चा किए बिना संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि 'राष्ट्रीय आय को कुल वास्तविक उत्पादन से जाडना उनके दृष्टिकोण की उपयोगिता का एक प्रबल पक्ष था वस्तुतः पिछड़े देशों में छिपी व्यापक बकारी की सामाजिक क्षेत्र में सेवा पक्ष के एक बहुत बड भाग की परीपजीविता की तथा समाज के गठन संबंधी एव सस्थागत परिवर्तनों उदाहरणार्थ पश्चिम के सपक में भ्राने के समय से ही मद्रा निर्माण अथवा छपयोगी मामलों के उत्पादन में वृद्धि आदि की सही जानकारी का तुलनात्मक

### 34 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास

अथवा अन्य आर्थिक विस्तारण के उद्देश्य का, गन्ना आधार उपभोग सामग्री का वास्तविक उत्पादन ही बन सकता है

71 नौरोजी पावर्टी पृ० 4 अपने निष्कर्षों को परिणामाप्ति पर दावाभाई ने टिप्पणी करत हुए निष्कर्ष 'एक बात स्पष्ट है कि मैं उत्पादन के अवमूल्यन का दोषी नहीं हूँ' (पावर्टी पृ० 25) उन्होंने और अधिक स्पष्ट सूचनाओं का आग्रह करत हुए कहा कि भी भारतीय द्वारा पूरी सूचनाएँ देने पर ही क्या प्रतिवक्ष भारत का वास्तविक भौतिक स्थिति को सही रूपरेखा प्रस्तुत की जा सकती है (वही, पृ० 147) सभी प्रकार का सीमाप्राप्त होने पर भी उनका 20 द० प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का भ्रम इस क्षेत्र के सभी परवर्ती अनुसंधानों की समीक्षा बना, यह उनके लिए एक बड़ा बड़े गौरव की बात है (मसानी पूर्वोद्धृत पृ० 204) शाह और खान पूर्वोद्धृत पृ० 201 राव एन एसे आन इंडियाज नेशनल इनकम—1925-29 पृ० 16-22

72 डिग्वी पूर्वोद्धृत पृ० 364 442 3 इस तथ्यमाने में कुल सामग्री का उत्पादन तथा मजदूरी को सम्मिलित किया गया था उल्लेखनाय यह है कि भारत सरकार ने इन गणनाओं का मजदूरी भूत विस्तृत जांचा कि प्रतिवेदना को कभी प्रकाशित नहीं किया

73 किडिल्टन के ताड़ बजान स्पीचज खंड I IV (कलकत्ता 1900 1902 1904 1906) पृ० 1 पृ० 289 90

74 डिग्वी पूर्वोद्धृत अध्याय XII

75 फ्रेड जे० अनविशन ए स्टैटिस्टिकल रिव्यू आफ इंडिया एंड बल्य आफ ब्रिटिश इंडिया जनरल आफ दि रायल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी खंड 65 भाग 2 (जून 1902) पृ 238

76 देखिए नौरोजी सा०पा०ए० पृ० 160 1 स्पीचेज पृ० 114 527, जोशी पूर्वोद्धृत पृ० 753 मधालकर इन इंडियन पालिटिक्स पृ० 38 जो०सी० अम्बर सि वापसराय आन सि इको नामिक कडीशन आफ इंडिया' एच०आर० मई 1901 पृ० 355 ई० पृ० 37-8 गायन स्पीचेज पृ० 17 दत्त ई एच II, पृ० 603 एस० एन० बनर्जी ने 1895 में पूना काँग्रेस में सभापति पद से दिए गए अपने भाषण में सारे राष्ट्रीय दृष्टिकोणों का निष्कर्ष को इन शब्दों में प्रस्तुत किया प्रति व्यक्ति आय बीस रुपये है अथवा मताईस रुपये इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता। सत्य यह है कि यह भारत की जनता की गृहित दरिद्रता का एक विश्वमनीय प्रमाण है।' —(मी०पी०ए पृ० 257)

77 इंग्लैंड	41 पौंड	स्वित्जरलैंड	32 पौंड	आयरलैंड	16 पौंड
यूनाइटेड किंगडम	35 2	फ्रान्स	25 7	~	
रूस	9 9	ऑस्ट्रिया	16 3	जर्मनी	18 7
स्पेन	13 8	युनाइटेड स्टेट्स	13 6	इटली	12
इंग्लैंड	26	डेनमार्क	23 2	बेल्जियम	22 1
स्विट्जरलैंड	16	यूरोप	18	स्वीडन तथा	
				नार्वे	16 2
टर्की	4	ऑस्ट्रिया	43 4	यूनाइटेड	
				स्टेट्स	27 2
कनाडा	26 9			इंडिया	2

नौरोजी स्पीचेज पृ० 590 जाशी पूर्वोद्धृत पृ 758 राय पावर्टी, पृ० 340 बनर्जी

सी०पी०ए०, पृ० 257 8 भार० एम० सायानी सी० पी० ए० पृ० 346

- 78 बनर्जी सी०पी०ए०, पृ० 257 8 'नोरोजी इन ऐमिनेंट इंडियन्स प० 164 भार०एम० सायानी सी०पी०ए०, प० 347 नोरोजी स्पीचेज पृ० 310 त्रमश
- 79 'नोरोजी इन ऐमिनेंट इंडियन्स पृ० 164 और देखिए उल्हाहरणाय बनर्जी स्पीचेज, खड III पृ० 12, ए०बी०पी० 30 मार्च 1882
- 80 बहुत से आधुनिक अर्थशास्त्रिया की धारणा है 'बहुत सी साम्प्रदायिक कठिनाइया तथा सबद मूल्यो में सद्भाविकता जुडी होने के कारण राष्ट्रीय आय के घन भूतराष्ट्रीय तुलना की दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं रखते — (बाडिया तथा मर्सेट पूर्वोद्धत प० 523) परंतु यह स्पष्ट है कि इस प्रकार का तुलना के लिए सामान्य व्यवहार को ही उपयुक्त सूत्र (विधि) के रूप में ग्रहण किया जा सकता है' देखिए कोलिन क्लार्क पूर्वोद्धत 'कंडीशंस आफ इकोनामिक प्रोग्रेस प० 528 किसी भी ऐसे विषय में जहां आय का भूत अर्थिक गहरा है यहाँ तक कि उसे दो अथवा अधिक घन से गुणा करके मापा जा सकता है जसा कि तुलना द्वारा भारतीय नताआ ने पाया था, इस प्रकार के भूत की साक्ष्यता त्वरित और अस्पष्ट' ही मानी जाएगी
- 81 नोरोजी पावर्टी, प० 25 31 जोशी पूर्वोद्धत, प० 759-60 मघोलकर रिप०आई०एन०सी० 1891 पृ० 20 जे०सी० अय्यर ई ए प० 28
- 82 नोरोजी पावर्टी, प० 30 और स्पीचेज, परिशिष्ट-डी प० 187
- 83 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 759-60 मघोलकर रिप०आई०एन०सी० 1891, पृ० 19 और इन इंडियन पार्लिटिवस, प० 38
- 84 नोरोजी पावर्टी प० 31 समस्या के इस पक्ष पर डफरिन की जाच तथा 1888 के प्रस्ताव ने सुदूर प्रकाश डाला। नोरोजी (मद्रास) के सिविल सजन ने रिपोर्ट की कि जेल में रहने के कुछ देर उन्नीस कदमों का घजन बढ़ गया है मद्रास के राजस्व मंडल का उत्तर था कि इसका कारण जेल में अत्यंत उदारतापूर्ण भोजन का सभरण और कठोर श्रम न कराना है इसका अति रिक्त जल उसे घरेलू चिताओं से मुक्ति प्रदान करती है। प्रातीय प्रतिवेदना पर आधुत सरकारी टिप्पणी का संक्षेप इस प्रकार है कद की अर्वाधि में घजन का बढ़ जाना एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह स्थिति अन्य प्राता में भी पाई गई है देखिए भारत सरकार का 19 अक्तूबर 1888 का प्रस्ताव, पूर्वोद्धत परिशिष्ट-ए
- 85 नोरोजी पावर्टी प० 31 सी०पी०ए० पृ० 260, स्पीचेज प० 528 580 परिशिष्ट प० 186 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 62 3 बनर्जी सी०पी०ए०, प० 258 जी०सी० अय्यर ई ए प० 28 दादाभाई न आय के वितरण में क्षेत्रीय असमानताओं के अस्तित्व को भी स्वीकार किया देखिए, स्वाधज परिशिष्ट, पृ० 186
- 86 दत्त ई एच II प० 6 ए० बी० पी० 11 मार्च 1897 एन०एम० समय रिप०आई०एन०सी० 1896 पृ० 158 9 सायानी सी०पी०ए० प० 366 एडवोकेट 2 फरवरी (भार०एन०पी० एन० 4 फरवरी 1905) क्रमश उदाहरणाथ और नी देखिए मालवीय स्पीचेज प० 248 आई०एन०सी० 1966 का प्रस्ताव 12 आई०एन०सी० 1897 का प्रस्ताव 9 सी० सक्करन नयर सी०पी०ए० प० 383 डी०ई०वाचा सी०पी०ए०, पृ 360 दत्त स्पीचेज II प० 35 बेसरी 22 जून (भार०एन०पी० बवई, 26 जून 1897) दरिद्रता और अनाल के पारस्परिक संबंध की विस्तृत जाच नीचे की गई है
- 87 साइ एलगिन ने 'दरिद्रता और संपन्नता का भूत सापेक्षिक शब्द घोषित करते हुए अपनी राय



## 36 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास

इस प्रकार स्पष्ट की मैं यह नहीं मानता कि बहुमूल्य जनता अपने को विपन्न समझती है यदि उनकी आय कम है तो उसका कारण उनकी सीमित आवश्यकताएँ हैं' स्पीचेज (कलकत्ता 1899) पृ० 491

88 भारत के भौतिक साधना पर 1880-91 के प्रांतीय प्रतिवेदन (शिमला, 1894) बंगाल रिपोर्ट पृ० 9

89 वही नाथ घस्ट प्रांतीय तथा अथवा के प्रतिवेदन पृ० 19 और देखिए, स्ट्रुचे इंडिया 1894 पृ० 301 3 ब्रिटिश प्रशासकों ने बार बार भारत के संबंध में सपनता के इस भाग्यवादी दृष्टिकोण का प्रस्तुत किया स्ट्रुचे ने लिखा 'भारत के जलवायु में जीवन का प्रतिदिन का आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हाँ जाती है भारतवासी को मिट्टी से सिपी-मुनी भाग्य उमक अपने विचारानुसार शुद्ध और विश्रामप्रद आश्रय है सामान्य स्थिति में उसके पास अपनी रचि का आहार पर्याप्त मात्रा में रहता है। उसके पास अधिक वस्त्र भहा है परंतु अधिक वस्त्रों की उसे आवश्यकता भी नहीं यहाँ तक कि शीत ऋतु में भी उसे कोई विशेष कष्ट नहीं होता (इंडिया 1894 पृ० 301 3)

1888 की डफरिन जाच के लिए बहुत स मद्रास और प्रांतीय के अधिकारियों ने इसी दृष्टिकोण पर आधारित अपने निष्पक्ष भोजे उपाहणाय, मालदा के क्लबटर ने लिखा सामान्य वर्षों में एक छोट से किसान के पास भी देश की जलवायु तथा उसकी अपनी प्रकृति के अनुरूप उसे हृष्टपुष्ट बनाने वाला आहार आवश्यकता से अधिक मात्रा में रहता है' हुगली के क्लबटर का तो निश्चित मत था भारतीय जन माय दृष्टिकोण और अपने अपेक्षित स्तर के अनुसार सपन तथा सतुष्ट है (दंडतापूर्वक कहा गया) भारत सरकार का 19 अक्टूबर 1888 का प्रस्ताव पूर्वोद्धृत परिशिष्ट ए

90 जनता का भौतिक स्थिति पर प्रांतीय प्रतिवेदन 1880-91 बंगाल प्रतिवेदन पृ० 9 तथा हुगली के क्लबटर ने भारत सरकार के 19 अक्टूबर 1888 के प्रस्ताव को उद्धृत किया पूर्वोद्धृत परिशिष्ट-ए तुलनीय— भारत के आर्थिक प्रश्न पर विचार हुए यह विशय रूप से कभी नहीं झूलना चाहिए कि धन सचय अथवा उच्च आय की अपेक्षा मानसिक सुख तथा आत्मिक शांति की प्राप्ति ही भारतीयों का जीवन लक्ष्य है गवर्नर जनरल की कौंसिल के स्वर्णय सदस्य जे०डा० रोस ने प्रकाशनाधीन रियल इंडिया' में इसे ब्रिटिश राज्य की अनेक देनों में एक बहुत बड़ी देन बताया (सदन 1908) पृ० 319 20

91 सि थड डिमिनियल मारल ऐंड मटिरियल प्रोग्रेस रिपोर्ट पृ० 419 और देखिए प्रस्ताव पूर्वोद्धृत पृ 318 थोडोर मोरीसन इकोनामिक ट्रांजीशन इन इंडिया पृ 159 60 मोरीसन का मत था अनुभव की तुलना से विचारों में उलभाव के अतिरिक्त कुछ भी परिणाम नहीं निकलता (पृ० 160)

92 इंडिया (1894) पृ० 301 जिन अकाल आयुक्तों को वह उद्धृत कर रहा था उन्होंने यह मन्त्रा परंतुक जोड़ी जो अनजाने तौर पर व्यर्थपूर्ण है यद्यपि उसकी आय अपेक्षाकृत थोड़ी और बड़ जाखिमा से भरी हुई है इसी प्रकार 1894 में भारत सचिव एच०एच फीनर ने दंडतापूर्वक कहा जलवायु की दृष्टि से ग्रामीण भारत की दरिद्र जनता का इंग्लैंड की जनता की अपेक्षा आवश्यकताएँ कम हैं और भारत का निधन इंग्लैंड के निधन की अपेक्षा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अधिक आसानी से कर सकता है हसाड (चतुर्थ बंग) 15 अगस्त 1894 खंड 27 लगभग 1138 9

- 93 नोराजी की स्पीचेज से उद्धृत, प० 583 और देखिए अतर्विसन के लख पर रीस की टिप्पणी, पूर्वोद्धृत, प 276
- 94 बल दिया गया भारत सरकार का 19 अक्तूबर 1888 का प्रस्ताव—पूर्वोद्धृत परिशिष्ट-ए बहुत से अन्य सरकारी अधिकारिया ने अपने प्रतिवेदनो मे यही दृष्टिकोण अपनाया
- 95 जी०सी० अघ्यर ई ए प०20
- 96 दूसरी ओर आर०सी०दत्त ने लिखा 'जीवन भर की भूख बेचारे अधिक निधन लोगा को आवश्यकता कम करने का प्रशिक्षण देती है' ई एच I पृ०22
- 97 दादाभाई नौरोजी ने सकल किया 'बबई निवासी धनी हिंदुओ और मुसलमानो की रहन-सहन की स्थिति तो देखिए एसेज, प० 134
- 98 दादाभाई ने पूछा एक समय ब्रिटेन के लोग इस देश के जंगला म घूमत थे और उनकी आवश्यकताएं कुछ न था यदि वे उमी स्थिति मे रहत तो आज का ब्रिटेन कसा हाता ? (स्पाचेज, प० 311)
- 99 वही पृ० 311 2
- 100 जी०वी० जोशी ने इस अत्यन्त स्पष्ट करत हुए कहा 'सुख सुविधाआ का उच्च स्तर तो हमारे लिए एक प्रकार का अवच्छेद न तिक बल है जा हुमे सकट काल म अधिव धम करन और कष्ट सहन के लिए उत्साहित करता है तथा परिस्थितियो पर विजय पान के योग्य बनाता है देश पर पडने वाला बुरे से बुरा सकट यदि देश के जीवन स्तर को बुरी तरह प्रभावित नहा करता तो वह किसी भी रूप म भयकर अथवा शोचनीय नहा कहा जा सकता इसके विपरीत बल पूर्वक चांगी गई शांति का बरदान यदि देशवासियो को अपने निम्न जीवन स्तर स समझौता करने के लिए विवश कर दता है तो उसे अमिशाप ही कहा जा सकता है (पूर्वोद्धृत प०768)
- 101 गोपालकृष्णन पूर्वोद्धृत प० 183 तथा काग्रस का 1892 का नवा प्रस्ताव
- 102 देखिए आई०एन०सी० 1882 का प्रस्ताव 9 तथा काग्रस के इसी प्रकार के परवर्ती प्रस्ताव
- 103 भारत सरकार का 19 अक्तूबर 1888 का प्रस्ताव पूर्वोद्धृत कडिका-4
- 104 वही परिशिष्ट ए अपन ही प्रस्ताव पर लाड डफरिन का मत था इस परिणाम स पर्याप्त सतुष्ट व्यक्तित या ता जाशावादी है या कठोर प्रकृति का है लाड डफरिन स्पाचेज (कलकत्ता 1889) प० 241 वस्तुतः प्रस्ताव के परिशिष्ट-ए म प्रकाशित बहुत स मटलाय तथा प्रातीय प्रतिवेदनो मे भारत मे व्याप्त घोर दरिद्रता और दुर्भाग्य के अस्तित्व को प्रमाणित किया गया था सरकारी प्रस्ताव केवल यह सिद्ध करने म सफल हुआ कि भारत मे स्याई अकाल नहीं है वस्तुतः यह एक क्षुद्र सात्वना थी
- 105 1898 के अकाल आयोग का प्रतिवेदन (कलकत्ता 1898) कडिका 591 2.
- 106 बजन स्पीचेज खड III प० 149 इसी प्रकार भारत सचिव आज हैमिल्टन इस तथ्य से सहमत थे कि भारत म 'धनी जनसंख्या दरिद्र है —इंडियन डिबेटस 3 फरवरी 1902 सगभग 103
- 107 लाड बजन ने इस रूप मे बड़ी विशदता से प्रश्न प्रस्तुत किया —स्पीचेज खड IV पृ० 36 1838 मे ही बगानी युधक सभ स संबधित बाबू रामगोपाल घोष ने इस प्रश्न को जाच पडनाम करन की इच्छा व्यक्त की—'संपत्ति बढ़ रही है अथवा घट रही है ? क्या बहुसंख्यक जनता की सुविधाआ म विस्तार हो रहा है अथवा सशोचन ? तथा इस सबके क्या कारण हैं ?'
- 'रामगोपाल सांग्याल के 'ए जनरल बायोग्राफी आफ बगाल सतिब्रिटीन' म उद्धृत (कलकत्ता

# 8 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विवास

- 1889) प० 175
- 08 और इस बात का उत्तर दना आवश्यक था सापक्षिता का कोई तब प्रश्न को घुमित नहीं कर सकता दाना पक्ष सही नहीं है। सक्ते एक को तो गलत होना ही पड़ेगा—तुलनीय, द्विपक्ष
- पूर्वोद्धत
- 109 हमाड (चतुथ वग) खड XCIX लग० 1209 इसी प्रकार 3 फरवरी 1902 का उक्त पुन थापणा का मैं एक से अधिच बार अपना मन व्यक्त कर चुका हूँ कि भारत में हमारे प्रशासन का मुख्य और एकमात्र उद्देश्य केवल हमारा यह विश्वास है कि हम दक्षिण भारतीय जनता का भौतिक दृष्टि से समृद्ध बना सकते हैं (इंडियन डिबेट्स 3 फरवरी 1902 लगभग 105)
- 110 गाखले स्पीचेज प० 19 और देखिए वही प० 934 नोरोजी पावटी प० 186 तथा स्वीज परिशिष्ट डी प० 167 लानमोहन घोष स्पाचेज (कलकत्ता 1883) प० 87 सी०पी०ए०, प० 756 मातवाय स्पीचेज प० 219 238 जोशी पूर्वोद्धत प० 738 752 3 मधोतर इंडियन पार्लियामेंट प० 35 नदी पूर्वोद्धत प० 101 बाबा सी०पी०ए० प० 560
- 111 आइ०एन०सी० 1886 का प्रस्ताव II तथा बाबा रि०आइ०एन०सी० 1886 प० 60
- 112 उदाहरण रूप में देखिए टिप्पणी 10 मित० 1884 29 अगस्त 1887 1 फरवरी 1888 मराठा 21 दिनबर 1884 11 नवंबर 1900 नेटिव आपोनियन 13 अप्रैल (आर०एन०पी०) बंबई 19 अप्रैल 1884) नव विमावर 7 जनवरी (आर०एन०पी०) वग 7 जून 1884) माधारीजी 27 जुलाई (वहा 27 अगस्त 1884) सजीवनी 18 जुलाई (वही, 25 जुलाई 1885) जान प्रकाश 19 मार्च (आर०एन०पी०) बंबई 21 मार्च 1885) 'वादम आफ इंडिया द्वारा आत ममाचारपत्र (निर्देश के लिए आगे वी०ओ०आई०) से संकेतित किया जाएगा) अक्टूबर 1887 अवाला गजट 27 जून (आर०एन०पी०) 7 जुलाई 1888) पत्ता अद्यकार' 13 अप्रैल (वही 18 अप्रैल 1891) दोस्ते हिंद 12 जून (वही, 20 जून 1891) केसरी 22 जून (आर०एन० पी०) बंबई 26 जून 1897) भारत जीवन 25 जुलाई (आर० एन० पी०) ए०, 3 अगस्त 1898) ए० वा० पी० 17 जून 1898 12 अक्टूबर 1901, बंगाली 9 मार्च 1902
- 113 नौरानी स्पीचेज (1886) में उद्धृत ग्रांट डफ पृ 583 पूर्वोद्धत के अध्याय 1 में जान स्ट्र. और रिचाड स्टुडी उद्धृत 1888 के 'स्पीचेज में डफरिन उद्धृत पृ० 241, स्टुडी 'इंडिया (1894) प० 303 जनरल सर जाज वसनी 'इंडियन पार्लियामेंट (लंदन 1894) पृ० 394 हनरा फौजर हुआड (चतुथ वग) 15 अगस्त 1894 खड XXVIII लग० 1139 ऐलगन स्पीचेज प० 360-1 1898 के अवाल आयोग का प्रतिवेदन बडिका 592 1901 2 और 9 पूर्ववर्ती वर्षों की अर्वाधि में भारत की स्थिति और उसकी नैतिक तथा भौतिक प्रगति का विवरण प्रस्तुत करने वाला प्रतिवेदन (चतुथ दशाब्दिक प्रतिवेदन होने के कारण) फाम सी० ड्रेक द्वारा तयार किया गया (लंदन 1903) 1901 2 का आर्थिक वक्तव्य (बडिका 136) 1902 3 का वक्तव्य (बडिका 90) 1902-4 (बडिका 117) 1902 में डेड जे० अंतर्विसन ने सगणना की कि 1875 95 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 29 5 प्रतिशत बढ़ गई है (पूर्वोद्धत स्थल प० 238)
- 114 वजन स्पाचेज खड I पृ० 158 खड II पृ० 165 288 90 खड III पृ० 148-9 तथा खड IV पृ० 36-7 211 2
- 115 वही खड II पृ० 290 इसी प्रकार जाज हैमिलटन ने दावा किया यद्यपि मद गति के कारण वह लगभग अगोचर भी हो गई है तथापि भौतिक अग्रगति में निरंतरता बनी रही है—हसाड

- (चतुर्थ वग) 16 अगस्त 1901, खंड XCIX लग० 1208 9 तथा इंडियन डिबेट्स 3 फरवरी 1902 लगभग 108 110
- 116 वही खंड III, पृ० 389
- 117 वही खंड IV प० 212
- 118 गत 19वीं शती के अंतिम पच्चीस वर्षों की अवधि में भारत को निधन बनाने वाले दुर्भिक्ष अपने विस्तार और तीव्रता में प्राचीन जयवा आधुनिक काल के इतिहास में अभूतपूर्व उदाहरण हैं (दत्त, इ एच I प० VI)
- 119 1902 में कांग्रेस सभापति के पद पर आसान सुरदनाय बनर्जी ने प्रश्न प्रस्तुत किया क्या अपनी वृद्धता हुई तीव्रता तथा बहुलता के साथ जनता की भौतिक अयोग्यता का मौन किंतु निर्णोक्त प्रमाण प्रस्तुत करने वाले इन दुर्भिक्षों की साधकता को नकारना संभव है ? (सी० पी० ए० प० 68) और देखिए जी० सी० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1900, प० 29 दत्त स्वावज II, प० 28 तथा नाचे देखिए
- 120 इस दृष्टिकोण की विस्तृत जांच नीचे की गई है।
- 121 जागी पूर्वोद्धृत, प० 420 पी०पी० विल्ले रिप०आई०एन०सी० 1892, प० 98, मधोलकर इंडियन पार्लियामेंट, प० 39 नदी वही, प० 166 7 जी०एस० अय्यर भारत के खर्चों के प्रशासन पर रायल कमीशन का प्रतिवेदन (निर्देश के लिए इसे आगे बेलबी कमीशन से संकलित किया जाएगा) मिनिट्स आफ इविडेंस (साक्ष्य के सन्निप्ताश) खंड III पार्लियामेंटरी पेपर्स (हाउस आफ कामंस) 1900 खंड 29 लगभग 130 प्रश्न 19615 6 तथा ई ए प० 13 नाचा सा०पी०ए०, प० 360 दत्त ओपन लेटर्स टू लाड कजन (लाड कजन का नाम खुली चिट्ठीया) कनकता 1904 (निर्देश के लिए इसे आगे ओपन लेटर्स से संकलित किया जाएगा) प० 17 बेनर्जी, सी०पी०ए० प० 689 गोखले स्पीचज प० 53 1904 की आई०एन०सा० का प्रस्ताव और प्रस्ताव पर भाषण की रिप०आई०एन०सी० 1904 प० 128 तथा नाचे अध्याय X
- 122 ऋणप्रसन्नता आवश्यक रूप से न निधनता है और न ही दुर्दशा सामान्य ऋणकर्ता की स्थिति की तुलना उम्र-युक्ति से की जा सकती है जो बक में अपना खालू खाता रखता है और कभी-कभी अधिकविक्रय करता (जमा पूजा से अधिक निकालता) है दि थंड डिस्टन्सियन भारत एंड मटिरियल प्रोग्राम रिपोर्ट पृ०435 एक अन्य सरकारी प्रकाशन इससे भी आगे बढ़ गया 'ऋण तो आवश्यकताओं की अपेक्षा समाधानों की अधिकता पर अधिकार का सूचक है।' प्राविशल रिपोर्ट आन डि मटोरियन कडीशन आफ दि पीपुल 1881 91 प०8 आफ दि बंगाल रिपोर्ट तथा प्रेजिडेन्स रिवाजन और पटना के कमिश्नरों तथा एन०डब्ल्यू०पी० एंड ओ० म एटा क कलक्टर सेंट्रल प्राविसेज म दमोह तथा भडारा के कमिश्नरों के प्रतिवेदन तथा भारत सरकार के 19 अक्टूबर के प्रस्ताव का स्वयं सरकार द्वारा संक्षेप पूर्वोद्धृत परिशिष्ट ए
- 123 ऊपर देखिए अध्याय X
- 124 जागी पूर्वोद्धृत प०227 769 70 गोखले स्पीचज प० 18 52.
- 125 भूतपूर्व सैनिक सदस्य जनरल जाज जिमनी ने 1894 में लिखा 'संपत्ति हमारे शासन की ही मर्ति है हमने भारत को गरीबी में जकड़ा हुआ पाया जमाकि यह पहले से रहता आया है यदि हम इस देश में न आते तो यह आज भी उसी प्रकार विपन्न होता (पूर्वोद्धृत प० 397) साइ कजन ने 1904 में टिप्पणी की कि यदि आज के भारत की मित्रदर अंग्रेज अवर अरबा

## 40 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास

जीरगजेब के भारत से तुलना करें तो पाएंगे कि पूर्वकाल में अनुभूत पराश्रितता की अपणा आज भौतिक समृद्धि का स्तर काफी ऊंचा है (स्पीचज खंड IV, प० 37)

- 126 रानाडे एसेज प० 182
- 127 राष्ट्रीय कांग्रेस के बंगाल के विपणन में सश्रिय भाग लेने वाले एक भारतीय युवा लेखक ने तो यहाँ तक स्वीकार किया कि भारतीय इतिहास की बमब और सपन्नता की सभी विभिन्न अवस्थाओं और युगों में भारतीय कृषक जनता कुचली और विपन्न रही है (राय पावर्टी प० 199) परंतु उन्होंने साथ में यह अवश्य जोड़ा ब्रिटिश राज्य में ता दुर्भाग्य और अधिन विपन्न हो गया है' वही प० 224 इसके साथ देखिए मघानकर रिप०आई०एन०सी०—1891 प० 21
- 128 आनंद बाजार पत्रिका 13 अप्रैल (आर०एन०पी०बग 24 अप्रैल 1880)
- 129 नोरोजी पावर्टी प० 579 कलकत्ता रिब्यू में एक भारतीय लेखक कलाशचंद्र बाबालाल ने लिखा ब्रिटिश राज्य ने एक ऐसी दुर्भाग्य की स्थिति उत्पन्न कर ली है जो हमसे पूर्व किसी भी हिंदू जयवा मुगल शासक अथवा टीपू साहब अथवा पेशवा के राज्य में कभी नहीं रही (कलकत्ता रिब्यू/अक्टूबर 1901, प० 309 10)
- 130 उदाहरणार्थ देखिए सजीवनी 14 जून (आर०एन०पी० बग 22 जून 1884) ग्राम यात्रा प्रवाशिका 9 अगस्त (वही 16 अगस्त 1884) एस०एन० बनर्जी रिप०आई०एन०सी०—1896, प० 135 6 कसरी 22 जून (आर०एन०पी० बर्डी 26 जून 1897) तथा 14 जनवरी (वही 18 जनवरी 1902) एन०के०एन० अय्यर रिप०आई०एन०सी०—1901 प० 140-1 सी०वाई० चितामणि दि इकोनामिक आसपेक्टस आफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एच०आर०दिम० 1901, प० 485 6 बंगाली 22 अक्टू० 1903 साथ ही देखिए नोरोजी स्पीचज प 389 प्रथम जीर भागवत में उद्धृत तिलक पूर्वोद्धृत प० 72 राय पावर्टी प 75
- 131 अमृत बाजार पत्रिका ने 22 मई 1884 में लिखा एक समय भारत विश्व में समृद्धतम देश था' वर्षों तक एक के बाद एक दूसरे कांग्रेसी प्रतिनिधियों ने भारत की विगत सपन्नता का गौरवगान किया 1899 1904 तक के आई०एन०सी० के प्रतिवेदन देखिए दानामाई नोरोजी ने अपनी पुस्तक पावर्टी एंड जन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में 1853 में लिख एक निबंध दि स्टेट ऐंड दि गवर्नमेंट आफ इंडिया अडर दि नेटिव रूलस को 1901 में पुनः प्रकाशित किया इसमें उन्होंने अनेक ब्रिटिश लेखकों को उद्धृत करते हुए यह दिखाने की चेष्टा की कि सिकंदर के जाक्रमण का निधि और उससे शताब्दियों पूर्व से लेकर मुगल शासनकाल तक भारतीय सपन्नता के उच्च स्तर पर थे (प० 584) इसी निबंध को वास्तव में 1903 में जी०सी० अय्यर ने अपने सम इकोनामिक आसपेक्टस आफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया में पुनः प्रकाशित किया और देखिए नया इंडियन पालिटिक्स प० 103 105 110 रानाडे दि राइज आफ मराठा पावर इन इंडिया (बर्डी 1900) वास्तव में इसी बात के उल्लेख के लिए लिखा गया था और देखिए आर० एन० सायानी ऐबस्ट्रक्ट आफ दि प्रोसीग्रेस आफ दि इपीरियस लेजिस्लेटिव कौंसिल' (निर्देश के तिए इसे आग एल०सी०पी० से सन्दर्भित किया जाएगा) 1897 खंड XXXVI प० 190 पी०ए चार्लू वही प० 232
- 132 इन इंडियन पालिटिक्स प० 110
- 133 नोरोजी की स्पीचज में उद्धृत फ्रांट डफ प० 610 फौलर हमाड (चतुर्थ खंड) 15 अगस्त 1894 खंड XXVIII 1139-40 जे० पीले बेलबी आयोग खंड III प्रथम 18235



- बढ़ातरी का भी भारतीय निग्रहता के एक कारण के रूप में उद्धृत किया गया नीचे दिये
- 143 नीचे IX अध्याय दिये
- 144 नीचे XI अध्याय में सीमा शुल्क प्रकरण दिये इसके साथ ही दिये गोयल स्पीचर, पृ० 17 मातवाय स्पाचेज पृ० 380-1
- 145 गोखले स्पीचर, पृ० 17
- 146 वही तथा 1904 की रिप० आई० एन० सी०, पृ० 166-7 मातवीय स्पाचेज, पृ० 381 इसके अतिरिक्त इस बात का स्पष्ट निष्पत्ति किया गया कि इस तरह से बहुत कम बहूती भारत की निम्नतम दरिद्रता को प्रमाणित करती है नदी इंडियन पालिटिक्स, पृ० 119
- 147 गोखले स्पाचेज पृ० 17 तथा 1904 की रिप० आई० एन० सी०, पृ० 166-7
- 148 गोखले स्पीचर पृ० 18 जाशी पूर्वोद्धृत पृ० 200, 227 डी० ई० वाचा ने कायम के अध्यक्ष भाषण में निम्नलिखित आंकड़े प्रस्तुत किए 1886-7 में प्रति व्यक्ति खपत 139 पौ० धी और 1899 1900 में 127 पौ० धी—सी०पी०ए० पृ० 603 बनर्जी सी०पी०ए०, पृ० 680
- 149 फोय निम्नियल मारल ऐंड मटिरियल प्रोग्रेस रिपोर्ट पृ० 332 वजन स्पीचर, खंड II, पृ० 290 1 अतर्विषय पूर्वोद्धृत पृ० 215 20 269 1901 में वजन में समता द्वारा सिद्ध किया कि कृषि भूमि का क्षेत्र 1880 में 1940 एकड़ के स्थान पर 1898 में बढ़कर 2170 एकड़ हो गया है अथवा दूसरे शब्दों में कृषि भूमि का विस्तार समया जन्मद्वारा में बढ़ि में अनुरूप हुआ है उसने यह भी सिद्ध किया कि 1880 में 730 पौ० प्रति एकड़ उपज के मुकाबले 1898 में 840 पौ० उपज का जान से प्रति व्यक्ति के लिए खाद्यान्न प्रचुर परिमाण में उपलब्ध है स्पीचेज खंड II पृ० 290 1 अतर्विषय के अनुसार जो खाद्य उत्पादन 1875 में 1 701 पौ० प्रति टिन या वह 1895 में बढ़कर 1 739 हुआ गया
- 150 जोशी पूर्वोद्धृत पृ० 227 334 335 839 नदी इंडियन पालिटिक्स पृ० 109 सायानी सी०पी०ए० पृ० 361 वाचा सी०पी०ए० पृ० 395 सायाना 15 फरवरी (आर० एन० पी० बग) 27 फरवरी 1890 गोखले स्पीचर पृ० 33 जोशी न 1890 में वहा 1871 2—1888-9 की अवधि में बढ़ई, मद्रास, नाथवेस्ट प्राविंस तथा अवध और सेंट्रल प्राविंस तथा पंजाब में कृषि भूमि के क्षेत्र में 45 लाख एकड़ की बढ़ि हुई है जबकि इसी अवधि में इन प्रांतों में जनसंख्या 110 लाख बढ़ी है (यदि सर डब्ल्यू० हटर का एक एकड़ का तीसरा-चौथा भाग खाद्यान्न प्रति व्यक्ति का तखमीना स्वीकार कर लिया जाए) तो 45 लाख एकड़ कृषि भूमि का वही माननी पड़गी पृ० 839
- 151 सायाना सी० पी० ए० पृ० 363-4 जोशी पूर्वोद्धृत पृ० 900
- 152 जाशा पूर्वोद्धृत पृ० 839 सायानी सी० पी० ए० पृ० 363
- 153 जोशी पूर्वोद्धृत पृ० 841 3 नदी इंडियन पालिटिक्स पृ० 109
- 154 जाशी पूर्वोद्धृत पृ० 832, 835 841 844 852 नदी इंडियन पालिटिक्स पृ० 109
- 155 जाशी पूर्वोद्धृत पृ० 227, 333 338 753 गोखले स्पीचेज पृ० 19
- 156 जोशा पूर्वोद्धृत पृ० 836 गोखल स्पीचर पृ० 18 32
- 157 एड निम्नियल मारल ऐंड मटिरियल प्रोग्रेस रिपोर्ट पृ० 428 रिपोर्ट आफ इंडियन फाइनेंस कमीशन 1898 कडिका 590 आर्थिक विवरण 1904 5 कडिका 67
- 158 नीरोनी पापर्टी पृ० 66 72 79 जोशी पूर्वोद्धृत पृ० 663 898 जो सी० अग्रर 'रलवेज इन इंडिया इन इंडियन पालिटिक्स'—पृ० 191 चलकी कमीशन खंड III प्रश्न





#### 44 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास

- 22 मार्च 1902 1807 में बहुत सारे भारतीय राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने ऐसी मांग का समर्थन किया था देखिए मराठा 28 फरवरी 1897 एडवोकेट 23 फरवरी इंडियन मिरर, 28 फरवरी बिहार हेराल्ड 27 फरवरी, इंडियन स्पेक्टर तथा वाइम आफ इंडिया (निर्देश के लिए इन आंग आई० एस० सी० ओ० आई० से मंचित किया जाएगा) 28 मार्च 1897
- 169 आई० एन० सी० 1903 प्रस्ताव III एस० एन० बर्नार्ड प० 630-1 गोखले स्थावर पृ० 20 और देखिए, वाचा भी० पी० ए० पृ० 589 595
- 170 अनेक सरकारी तथा अधसरकारी अधिकृत घोषणाओं में यह दृष्टिकोण स्वीकार किया गया था देखिए ऊपर 1898 के अवाल आयोग ने एक प्राय उद्धृत में टिप्पणी में कहा 'शत्रु सत्त तथा घटिया फसल के कारण इस देश के समाज का अपेक्षाकृत निम्न वर्ग सुखमुविधाओं के निम्न स्तर तथा अमान का जीवन सदा से जीता आया है और आज भी उसी रूप में जी रहा है यह निम्न वर्ग अपनी विशालता में मजदूरों तथा उपकुशल कारीगरों को बहुत बड़ी संख्या में समेटे हुए है इस कठिन प्रश्न पर साक्ष्यों को मुनने तथा प्रस्तुत आंकड़ों को देखने के उपरांत हम यह धारणा बना पाए हैं कि इन मजदूरों की आय पिछले बीस वर्षों में जीवन की आवश्यकताओं में मूल्यवर्द्धि के उचित अनुपात में बढ़ी नहीं है वर्तमान दुर्भाग का अनुभव यह सिद्ध नहीं कर पाया कि समाज के इस वर्ग के पास साधनों की प्रचुरता अथवा सहजशक्ति की अधिकता है यह वर्ग कम होने के बन्ने और अधिक विशेषतः अधिक धनी आबादी वाले जिनका मधोरे घोर फसल जा रहा है उसकी परामर्शता अथवा परास्त होने की भावना क्षीण होने के बन्ने और प्रबल हो रही है (भारतीय अवाल आयोग 1898 का प्रतिवेदन कृषि 592) एक अमरीकी विद्वान जॉर्ज ब्लेक का नवीन अध्ययन 'दि ऐग्रीकल्चरल प्रॉप्स आफ इंडिया 1893 4 ट 1945-6 ए स्टैटिस्टिकल स्टडी आफ आउटपुट्स ऐंड टू ठस' (अप्रकाशित, पाइलिपि) पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय के दक्षिण एशिया शास्त्रीय अध्ययन विभाग में अनुमान लगाया है अध्ययन काल की अवधि में प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति खास उत्पादन में निरंतर ह्रास हो रहा था 1893-94 वर्षों में उत्पादन 587 पौंड था 1936-37 से 1945 6 तक यह गिरकर 399 पौंड हो गया—धरम उद्धृत पूर्वोद्धृत पृ० 123 एक अन्य समकालीन लेखक ने सगणना की है कि सभी साधनों से होने वाली भारत की प्रति व्यक्ति आय 1896 से 1945 में आठ प्रतिशत गिर गई थी—मुरद ज० पटल 'प्लग टम चेंज इन आउटपुट ऐंड इनकम इन इंडिया 1896-1960 इंडियन इकोनॉमिक जर्नल जनवरी 1958 खंड V स 3
- 171 वाचा भी० पी० ए०, पृ० 598
- 172 एन० पी० चंदावरकर सी० पी० ए० पृ० 512 दादाभाई नौरोजी ने 1898 को इंडियन करसी कमेटी को भेजे गए अपने एक बयान में अकालत करते हुए कहा 'मान लीजिए, इस देश का भूतकाल खराब था रक्तुरजित और अपमानजनक था आप भविष्य को तो उत्तम सपना और गौरवपूर्ण बनाकर दिखाइए (पावर्टी पृ० 548) जस्टिस रानाडे का तो सदा से यह विश्वास था कि विदेशी शासन में उन्नति अथवा अवनति के प्रश्न को तुलनात्मक रूप में पुरातन विषयक इतिहास के प्रश्न के समान है हम सबके लिए व्यावहारिक प्रश्न तो देश की सामान्य रूप से सापेक्षिक नहीं पूरा दक्षिणता और वर्तमान विवशता पर ध्यान केंद्रित करना है उन्हीं में स्वीकार किया कि 'कुछ सीमा तक तो स्थिति का ऐतिहासिक विश्लेषण शिक्षाप्रद ही है— (एसेज पृ० 182)
- 173 ओसी पूर्वोद्धृत पृ० 770 भारतीय स्वीचर पृ० 262 3 वत इल्लड ऐंड इंडिया—

- प० 126 आई० एन० सी० 1900 प्रस्ताव II तथा परवर्ती काग्रस का प्रस्ताव वाचा सी० पी० ए०, पृ० 539, दत्त ई० एच० I, पृ० VI
- 174 फजन स्पीचेज खंड III, पृ० 180 तथा वही खंड II प० 194 289 भारत सरकार के 19 अक्टूबर 1888 में बंगाल सरकार का संधेप पूर्वोद्धत, परिशिष्ट A चित्तनी पूर्वोद्धत, प० 395
- 175 इफरिल पूर्वोद्धत, प० 240 I
- 176 लसडोन स्पीचेज (एलक्ता) खंड II पृ० 376 तथा थर्ड डिनिसियल मारल एंड मटिरियल प्राप्रेस रिपोर्ट, पृ० 432 3 और जाज हैमिल्टन हसाड (चतुप वग) 26 जुलाई 1900 खंड XLV लगभग 539, भारतीया ने इस असगति के बड़े मज से बटखारे लिए एक ने तो तत्काल व्यय करते हुए कहा कि सचमुच ही जनसख्या की वृद्धि एक साथ दो प्रयोगन मिद्ध करती है एक समय वह देश की भौतिक प्रगति का सूचक है तो दूसरे समय देश की बढ़ती दरिद्रता का कारण है (नदी इडियन पालिटिक्स', प० 107)
- 177 नोरोजी पावर्टी पृ० 266 7 स्पीचेज प० 620 जोशी पूर्वोद्धत प० 773 जी० एन० अय्यर रिप० आई० एन० सी०—1900 प० 29 एन० जी० चदावरकर सी० पी० ए० प० 514 एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए० प० 684 पिरराजू रिप० आई० एन० सी०—1902 प० 75 दत्त इंग्लड एंड इडिया, प० 132 स्पीचेज I प० 26 ई० एच० आई० प० VI साधारणी, 27 जुलाई (आर० एन० पी० वग, 2 अगस्त 1884) हिंदू 6 जुलाई 1898 मद्रास स्टड्ड 5 अगस्त स्वदेश मिन्नन 5 अगस्त (आर० एन० पी० मद्र 10 अगस्त 1901)
- 178 जोशी पूर्वोद्धत, प० 773 तथा दत्त सी० पी० ए०, पृ० 477 एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए० पृ० 684
- 179 नोरोजी स्पाचेज, पृ० 325 6 621 ए० बी० पी० 5 अगस्त 1886 राय पावर्टी प० 168 9
- 180 नोरोजी पावर्टी प० 620 I स्पीचेज पृ० 324 जोशी पूर्वोद्धत प० 772 राय पावर्टी, प० 197 दत्त इंग्लड एंड इडिया प० 132 ओपन लटस (खुली चिट्ठिया) प 17 एन पी० चलावरकर सी० पी० ए० प० 514 5 एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए० प० 684 जी० एन० अय्यर बेलवी कमीशन खंड III प्र० 18648 9 रिप० आई० एन० सी० 1900 प० 29 हिंदू 6 जुलाई 1898 सजीवनी 15 फरवरी (आर० एन० पी० वग 22 फरवरी 1900) केसरी 31 मान (आर० एन० पी० बवई 4 अप्रल 1903) एन० श्रीनिवासाचारियर रिप० आई० एन० सी० 1903 प० 766
- 181 पूना के सावजनिक सभा के जनवरी तथा अक्टूबर 1890 के अको में प्रकाशित तथा उनके भाषणा और लेखों में पुन तथाकथित
- 182 जोशी पूर्वोद्धत प० 773 5 (बल दिया गया)
- 183 वही प० 774 5 कुछ वष पूर्व अमत बाजार पत्रिका ने 5 अगस्त 1886 को यही दृष्टिकान छोड़े अस्पष्ट एवं असबद्ध रूप में इन शब्दों में प्रस्तुत किया था यह मिद्ध हो चुका है कि किसी भी उद्धत सभ्य राज्य में किन्ही निश्चित विरतत सीमाओं के अतगत वृधि अथवा अय कार्यों में लग लोग की थोड़ी सख्या की अपेक्षा बड़ी सख्या को ही सामूहिक रूप से अधिक साधन जुटाए जा सकते हैं तथा देखिए नोरोजी स्पीचेज प० 391—ब्रिटिश राज्य भारत पर अपना नियतण छोडकर देख ले कि जनसख्या की वृद्धि उसके द्वारा कल्पित अकाल और दरिद्रता का कारण है अथवा इसके सर्वथा विपरीत शक्ति और उत्पादन में वृद्धि का आधारभूत कारण है ? 4
- दक्षिण जी० एस० अय्यर बेलवी कमीशन, खंड III प्रश्न 18733-6

## 46 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास

- 184 जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 852, तथा रानाडे एसेज, पृ० 207, वाचा सी० पी० ए०, पृ० 600
- 185 देखिए अध्याय II
- 186 नीरोजी पावर्टी प० 217
- 187 पी० सी० राम 'इंडियन फार्मिस (भारतीय अनाज) (बलकत्ता 1901) पृ० 35 और नीराजी पावर्टी प० 217 प्रमत्त
- 188 डफरिन स्पीचेज प० 240 यह इनिमिग्रल मारल गेंड मॅटिरियल प्रोग्रेस रिपोर्ट प० 434 फाय इनिमिग्रेशन मारल गेंड मॅटिरियल प्रोग्रेस रिपोर्ट, पृ० 354 वजन स्पीचेज घ० III, प० 149 भारत सरकार का प्रस्ताव स० 1 दिनांक 16 जनवरी 1902 (बलकत्ता 1902) कठिका 31
- 189 भारत सरकार का प्रस्ताव दिनांक 19 अक्टूबर 1888 पूर्वोद्धत परिशिष्ट ए
- 190 वजन स्पीचेज प० 166 खंड II भारत सरकार का प्रस्ताव दिनांक 16 जनवरी 1903, पूर्वोद्धत कठिका 31
- 191 भारत सरकार का प्रस्ताव, दिनांक 19 अक्टूबर 1888 पूर्वोद्धत परिशिष्ट ए
- 192 दत्त ई० एच० I प० VI तथा रानाडे 'लैंड ला रिफॉर्म ऐंड एग्रिकल्चरल ब्रम्' (भूमि कानून में सुधार तथा कृषि बन्ध) जे० पी० एस० एम० अक्टूबर 1881 (खंड IV स० 2), प० 55 (जी० ए० मानेकर के साक्ष्य के आधार पर यह लेख रानाडे का ही निश्चय हुआ है देखिए उनकी पुस्तक 'ए स्वेच आफ दि लाइफ ऐंड वरम आफ दि सेट मिस्टर जस्टिस एम० जी० रानाडे दो खंड बर्बई 1902 खंड I पृ० 215) जोशी पूर्वोद्धत पृ० 778 राम पावर्टी पृ० 194 5 पी० मेहता स्पीचेज प० 663-4 एन० जी० चंदावरकर सी० पी० ए० प० 516 दत्त सी०पी०ए० प० 478 490 ओपन लैंडस प० 17 ई० एच० II प० XIII एन० बे० एन० अम्बर रिप० आई० एन० सी०—1901 प० 140 श्रीराम एल० रा० पी० 190 खंड XLI प० 146 7 एम० एन० बंनर्जी सी० पी० ए० प० 684 5 जे० ब्रजामिन रिप० आई० एन० सी०—1904 प० 128
- 193 सामान्य किसान के विषय में भी सत्य यह है कि जीवन भर सूर्योदय से सूर्यास्त तक अनवरत और अथवा थम करने के उपरान्त भी वह बेचारा जीवन में समारोह के अवसर पर घर गृहस्त्री में आनन्द मनाने के लिए मिट्टी के कुछ नए घरतनों याड़े बहूत जगली फूलों गाव की टमटम पैद भर खाना, घटिया पात-सुपारी तथा तबाकू के पत्तों और बही बही कभी कभी घटिया मिश्रणों गहना को जुटाने में ही टूटकर रह जाता है (पी० मेहता स्पीचेज पृ० 663) वस्तुतः भारतीय किसान के लिए कोई भी दिन उत्सव-समारोह का नहीं वह तो सारा वष सूर्योदय से सूर्यास्त तक बटोर आम करता है उसे वष में एक दिन का भी अवकाश नहीं मिलता (ए० बी० पी० 2 अगस्त 1901)
- 194 नीराजी स्पीचेज पृ० 619 स्वदेश मित्रा 3 अप्रैल (आर० एन० पी० एम० 30 अप्रैल 1897) नदी इंडियन पालिटिक्स प० 117 पी० मेहता स्पीचेज पृ० 663 जी० एम० अम्बर ई० ए० प० 14 एन०पी० चंदावरकर सी०पी० ए० पृ० 516 एम० एन० बंनर्जी सी० पी० ए० पृ० 684-5
- 195 नीरोजी स्पीचेज पृ० 312 तथा बही प० 619 पी० मेहता स्पीचेज, पृ० 664 एन० पी० चंदावरकर सी० पी० ए० पृ० 516
- 196 पूर्वोद्धत प० 775 और वाचा रिप० आई० एन० सी० 1886 प० 61



## 48 भागत मे आर्थिक राष्ट्रवाद वा उद्भव और विकास

- एन० पी० चदावरकर सी० पी० ए०, पृ० 514 दत्त 'ओपन सेंटर्स', पृ० 18 राय फमिस  
 प० 24 एन० के० रामास्वामी अय्यर रिप० आई० एन० सी०—1901, पृ० 134 केसरी 25
- 208 जिसवर आर० एन० पी० बर्बई 29 दिस० 1900)  
 जोशी पूर्वोदघत पृ० 346 869 हिंदू—2 अप्रल 1900 रामास्वामी अय्यर रिप० आई० एन०  
 सी० 1900 प० 134 दत्त ओपन सेंटर्स प० 18
- 209 ए०बी०पी० 1 माच 1897 मघोलकर पूर्वोदघत, प० 33 आई० एन० सी० 1896 वा प्रस्ताव  
 XII आई० एन० सी० 1900 वा प्रस्ताव II आई० एन० सी०—1892 वा प्रस्ताव III  
 दत्त ई० एच० I प० VII राय फमिस, पृ० 29 30
- 210 दत्त ई० एच० I प० VII केसरी 10 अप्रल (आर० एन० पी० बर्बई 14 अप्रल 1900) भागत  
 स्टड्ड 5 अगस्त स्वदेशमित्रन 5 अगस्त (आर० एन० पी० एम० 10 अगस्त 1901) बाबा  
 सी० पी० ए० प० 537 तुलनीय—भारत सरकार बम से बम इग तय्य से तो सतुष्ट हो सकती  
 है कि भारत मे खाद्यान समरण की लगभग कोई कठिनता नह।। महा तक कि सूद्यो के लिनो मे  
 भी इस महाद्वीप म पर्याप्त पाद्य उपलब्ध है —भारत सचिव जाज हैमिल्टन वा 26 जुलाई 1900  
 को हाउस आफ कामस म बयन ईसाई (चतुय वग) छड LXXXVI लगभग 1346
- 211 राय फमिस प० 78 और देखिए एन० जी० चदावरकर सी० पी० ए० पृ० 514 श्रीराम  
 एल० सी० पी० 1901 छड XL प० 238 तथा एल० सी० पी० 1902 XLI प० 147 ए०  
 बी० पी० 13 नवंबर 1901 एन० एन० बनर्जी सी० पी० ए० प० 683 केसरी—21 जुलाई  
 (आर० एन० पी० बर्बई 25 जुलाई 1903)
- 212 जी० सी० अय्यर रिप० आई० एन० सी०—1900, पृ० 31 नोरोजी पावटी प० 656  
 बाबा सी० पी० ए० पृ० 559
- 213 नोरोजी पावटी प० 656 और स्पीचेज प० 237 राय फमिस पृ० 32 दत्त ई० एच० I  
 प० VII तथा ई० एच II प० VI बनर्जी सी० पी० ए० 683-4
- 214 वस्तुत अन्न की न्यूनता अथवा अभाव नही प्रत्युत निघनता के कारण क्रयशक्ति के अभाव को  
 ही वस्तुत भारतीय अकाल बहा जाता है (ए० बी० पी० 22 मई 1892) और शानप्रकाश 16  
 जनवरी (आर० एन० पी० बर्बई 18 जून 1879) साम प्रकाश 1 दिस० (आर० एन० पी० वग  
 6 दिस० 1884) मराठा 29 माच 1891 मघोलकर पूर्वोदघत पृ० 38 नोरोजी पावटी पृ०  
 656 केसरी, 3 अप्रल (आर० एन० पी० बर्बई 7 अप्रल 1900) राय फमिस प० 31 बाबा  
 सी० पी० ए० प० 557 श्रीराम एल० सी० पी० 1901 छड XL प० 238 एम० के०  
 पटेल रिप० आई० एन० सी० 1902 पृ० 76 बगाली 9 माच 1902
- 215 गोखले बेलवी ममीशन छड III प्रश्न 18314-8 भारत जावन 25 जुलाई (आर० एन० पी०  
 एन० 3 अगस्त 1898) निलक रिप० आई० एन० सी० 1900 प० 36 बनर्जी सी० पी० ए०  
 प० 684 केसरी, 25 दिस० (आर० एन० पी० बर्बई 29 दिसंबर 1900) श्रीराम एल० सी०  
 पी०—1902 छड XLI पृ० 147
- 216 आई० एन० सी०—1896 वा प्रस्ताव XII आई० एन० सी०—1897 वा प्रस्ताव IX आई० एन०  
 सी०—1901 वा प्रस्ताव VII सी० सक्कर नगर सी० पी० ए० प० 383 जी० सी० अय्यर  
 रिप० आई० एन० सी०—1900 प० 29 एन० के० एन अय्यर रिप० आई० एन० सी०—  
 1901 पृ० 140 राय फमिस प० 29 नोरोजी स्पीचेज प० 251 एल० एन० बनर्जी  
 सी० पी० ए०, पृ० 683

- 217 जोसा पूर्वोदघत, पृ० 152 आई० एन० सा०—1896 का प्रस्ताव XII मघालकर पूर्वोदघत पृ० 33 आई०एन० सा०—1900 का प्रस्ताव II बद्रावरकर सा०पा०ए० प० 514 याचा सी० पी० ए०, पृ० 560 दत्त ओपन सटस पृ० 18 रामास्वामी अय्यर रिप० आई० एन० सा०—1901, पृ० 134 क सरे हिं 22 सितंबर (आर० एन० पी० बयई 28 सितंबर 1901)
- 218 महा तक कि लाग अछा पयल के यपो म आधे भूय रहत थ और जब बुरे तिन जात थ तो वे बचारे शाघ्र ही मृत्यु का प्राप्त बन जात थ—(नौराजा पावर्टी प० 656) और दखिए बर्पा क जमाव से तो देश क निमी भाग की ही फसल नष्ट होती है वस्तुतः लाग की दरिद्रता ही लोग अवालो का निमित्त बनती है —(दत्त ई एच II प० 5)
- 219 ऊपर दखिए
- 220 जामो पूर्वोदघत प० 752 उपजाऊ घरती उत्तम भौगोलिक स्थिति तथा उत्पादन के अनुसून बानावरण की विविधता से सपन ऊंचे स्तर क घनिष्ठ साधनो से समृद्ध तथा अल्पव्ययी विवेकी, शांतिप्रिय तथा परिश्रमा जनसंख्या वाला यह देश संपत्ति के उत्पादन और सचय क लिए अपवादात्मक सुविधाओं से सपन है इस प्रकार की स्पृहणीय स्थिति में ऐसा कोई कारण नहीं होना चाहिए कि भारत न केवल कविद्या द्वारा प्रशंसित अपितु इतिहासकारों तथा समकालीन लेखकों द्वारा भी समर्पित व भव्य म अतीत की श्रेष्ठता को प्राप्त न करे—(मघानकर पूर्वोदघत प० 35) जा० एस० अय्यर न अठारहवीं कांग्रेस को निर्दिष्ट किया भारत के पास समृद्धि की पूर्वाशानि आवश्यकताओं में एक है सभी सभव कृषि उत्पादना तथा दस्तकारिया को खपाने के लिए बहुत बड़ी मंडी है रिप० आई० एन० सी०—1902 पृ० 72 और नौराजा पावर्टी प० 40 सी सवरन नयर सी० पी० ए०, पृ० 384 दत्त स्पीचेज II प० 37 ई एच II पृ० 611 एन० क० एन० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1901 प० 140-1 जी० सी० जय्यर ई ए—परिशिष्ट ए प० 3
- 221 जान आदम दि परमानेंट सेंटलमट क्वेश्चन इन इंडियन पालिटिक्स प० 80 जान स्ट्रुची के मायन फाइनेंश्ल स्टेटमट—1878 9 कडिका 2 म पहले ही इस विरोधाभास को अभिव्यक्ति दी थी
- 222 हमारे अपन ही देश के इतिहास का अध्ययन इस महान सत्य का बड़ विलक्षण ढंग से उदघाटन करता है कि हम कितने विपन्न और कितने अपमानित हैं? हमारा दुर्भाग्य श्रणीबद्ध और श्रुद्धना बद्ध रूप में आता रहा है जिसकी प्रत्येक कड़ी का विश्लेषण किया जा सकता है हम भाग्य के कुर हाथा क शिकार नहीं हुए, हम अभूतपूर्व सकटों का शिकार नहीं हुए और जहां परिस्थितियों ने वास्तव में ही हमारी नियति पर पूरा प्रकुश लगाया है वहां भी यदि हम प्रयत्न करत तो आशिक रूप से उन परिस्थितियों पर नियंत्रण कर सकते थे और इससे फलस्वरूप देश का और कालचित व्यापक रूप से विश्व का चहरा बन सकते थे—एन० एन० बनर्जी स्पीचेज I प० 26 अमृत बाजार पत्रिका ने अपने 12 जनस्त 1886 क अंक में लिखा—भारत की दरिद्रता और दुर्भाग्य का वास्तविक कारण ईश्वर की कृपणता न होकर मानव की चोम-बालसा है
- 223 आर्थिक नियमों का तो यूरोप और एशिया में एक ही रूप है। यदि भारत दरिद्र है तो यह आर्थिक कारणों का ही व्यापारगत प्रभाव है आर्थिक नियम तो अपने व्यापार में जबल और अपरिवर्तित रहते हैं दत्त ई एच II प० XVI XVIII और दखिए उनकी पुस्तक इन्डि एंड इंडिया प० 144 स्पांचेज II प० 63 ई एच I प० VI XII XIV तथा याचा सी० पी० ए० प० 560 थोड़ी पूव सूचना के लिए भारतीय मेनाओ द्वारा भारतीय दरिद्रता के प्रस्तुत कारण थे 'भारत के देशी उद्योगों का विनाश और उसके फलस्वरूप देश ।

विशानो से भारी भू राजस्व की मांग, महंगा प्रशासन और परिणाम म ऊंचे बराधान तथा भारत से इंग्लड की धन की निवासो

- 224 1900 मे लाड वजन ने मद्रास महाजन सभा क सदस्यो को परामश किया कि सरकार का आला चना करने की अपेक्षा वे विशान को साहूबार और कानून क बचहरिया स बचाने म अपना समय लगाए —वजन स्पीचेज, खड II पृ० 166 तथा देखिए, डफरिन स्पाचज पृ० 241-2
- 225 1902 के भू राजस्व प्रस्ताव ने समीगता की चेतावनी दी कि व स्वयं अपन द्वारा तयारकियन पहचाने रोग और सरकार के कतव्य अथवा शक्ति क्षेत्र क मतगत उसक उपचार क प्रयोग क सबध म अत्यंत विकृत विरलेपण प्रस्तुत न कर (बल दिया गया, पूर्वोदघत, कडिका 31)
- 226 आई० एन० सी०—1891 का प्रस्ताव III प्रस्ताव क उपसहार म घेट ब्रिटन तथा थायरलड का जनता से अनुनय विनय की गर्द कि वह निस्सन्देह शुभ इच्छाओ से प्ररित होत हुए भी पर्याप्त रूप से असतोपप्रद बतमान प्रशासन की दृटिया से और अधिक जनहानि न होत दें —प्रस्ताव का समथन करते हुए मदनमोहन मालवीय ने जार दिया इस प्रस्ताव म हम उन कारणा का उल्लेख कर रहे हैं जिसके लिए सरकार ही प्रमुख रूप स उत्तरदायो है और साथ ही हम वे उपचार मुभा रहे हैं जिनक प्रयोग का प्रत्यक्ष सबध सरकार से है परंतु यह तभी सभव है जब सरकार हम आर ध्यान देने की चिंता करे वस्तुत यदि सरकार को अपन को सम्य सरकार कहाना की चिंता है तो इन उपचारो का प्रयोग उमका प्रमुखतम कतव्य है —(मालवीय स्पीचेज प० 229) और देखिए उदाहरणाय नोरोजी पावर्टी प० 216-7 स्पीचेज प० 225 228 306 परिशिष्ट प० 17 78 एसेज पृ० 368 जोशी पूर्वोदघत प० 785 6 818 आई० एन० सी० 1892 का प्रस्ताव IX नैयर सी०पी०ए० पृ० 384 दत्त इंग्लड ऐंड इटिया पृ० 144 स्पीचज II प० 37 ई एच II प० 611 2 614 (वस्तुत यही भावना उनके आर्थिक इतिहासा के दाना ब्रडो की भूमिवासा म सनिहित है) जी० सी० अथ्यर वेलनी कमाशन खड III प्र० 18644 ई ए प० 3 नदी इंडियन पालिटिक्स प० 134 निलक रिप० आई० एन० सी०—1900 प० 36 तथा प्रधान ऐंड भागवत म उद्धृत —पूर्वोदघत प० 102 143 4 याचा सा०पी०ए० प 626 एन० श्री निवास वरदाचारी रिप० आई० एन० सी०—1903 प० 66 9 माच 1902 क घफ म वगाली न टिप्पणी की सरकार स्वामाविक रूप से स्पष्ट कारणा से ही राष्ट्रीय दल द्वारा भारत के अबातो के सबध म प्रस्तुत विरलेपण की स्वीकार करने को उद्यत त्ही । क्योंकि इसकी स्वीकृति का अथ बतमान सारी प्रशासन व्यवस्था का एसे आधार पर पुनगठन हागा जो भारत पहले भरेजो के लिए और बाद म भारतीयो क लिए बाल सिद्धात क विरुद्ध पडगा ।

# उद्योग I

भारतीयों की विशाल जनसंख्या श्रमिकों में प्रशिक्षित है। भारतीय शारीरिक दृष्टि में श्रमिकों के उपयुक्त हैं। वे श्रमिकों को छोड़ अन्य किसी उद्योग में प्रवृत्त ही नहीं हो सकते।

भारत पर राजनीतिक प्रभुत्व जमाने के दिन से ही इंग्लैंड की निश्चित नीति भारत को इंग्लैंड के शिल्पकारों और औद्योगिक व्यापारियों के लाभ के लिए कच्चा माल पैदा करने वाले देश के रूप में बदलने की रही है।

## I स्वदेशी उद्योग-वर्धन का ह्रास

भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक था भारतीय कस्बा की हस्तकलाओं और ग्रामों के हस्तशिल्प उद्योगों के नश्वर बढ़ते क्षय और विध्वंस का फलस्वरूप श्रमिकों और उद्योग व्यवसायों के सदियों पुराने ऐक्य का छिन्न भिन्न होना।<sup>1</sup> 18वीं शताब्दी तक भारत की आर्थिक दशा अपेक्षित रूप से उन्नत थी तथा भारत की उत्पादन विधियाँ तथा उसके व्यापारिक और औद्योगिक संगठन विश्व के किसी भी अन्य देश में प्रचलित इस प्रकार की विधियाँ और संगठनों की तुलना में रखे जा सकते थे।<sup>2</sup> हाँ 19वीं शताब्दी के अंत तक बहुत से स्वदेशी उद्योग घटते हुए अंतिम सास लें रहे थे जबकि आधुनिक उद्योग न अभी पर्याप्त उन्नति नहीं की थी।<sup>3</sup> प्रारंभिक भारतीय नेताओं की प्रमुख आर्थिक समस्या थी, देश की औद्योगिक दशा। उन्होंने भारत की दरिद्रता का विश्लेषण अधिकांशतः स्वदेशी उद्योगों के विनाश के पत्र-स्वरूप औद्योगिक पशुता तथा इस विनाश की पर्याप्त क्षतिपूर्ति के लिए आधुनिक उद्योग के द्रुत विकास में असफलता के रूप में ही प्रस्तुत किया।<sup>4</sup> प्रचलित विषयों पर लेख लिखनेवालों ने प्रतिदिन इस विषय पर अनवरत प्रहार किए तथा एक अथवा दूसरे उद्योग के विनाश पर निरंतर विलाप किया।<sup>5</sup> इस ह्रास की ऐतिहासिक प्रक्रिया



की खोज करते हुए उन्होंने बताया कि भारत कभी एक बहुत बड़ा गिल्प उत्पादक राष्ट्र था जोर उसके औद्योगिक उत्पादन शताब्दिया तक एशिया तथा यूरोप के बाजार की मांग की पूर्ति करते रहे हैं।<sup>6</sup> इस देश के कताई-युनाई तथा अन्य उद्योग धंधों ने लाखों नर-नारियों को पूणकालिक अथवा अशकालिक आजीविका जुटाई है।<sup>7</sup> परंतु ब्रिटिश सत्ता के साथ यह सब कुछ लुप्त हो गया है। भारत ने अपना विदेशी बाजार ही नहीं खोया, प्रत्युत अपनी घरेलू मंडी भी खो दी है। इस समय भारत को बरानर बहुत बड़े परिमाण में विदेशी सामान का आयात करना पड़ रहा है।<sup>8</sup> फनस्वरूप जो देश अपन दशवामिया के लिए 50 वर्ष पूर्व तक स्वयं वस्त्रों का उत्पादन करता था, आज वस्त्रों के लिए दूर के मालिकों पर निर्भर हो गया है। यही स्थिति हमारे रेशम, ऊन, चर्बी तथा खाल उद्योगों की है। कुल मिलाकर यही हमारी शाचनीय दशा है और इस सारी स्थिति की सामूहिक समीक्षा करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि हम पतन के उस भयंकर कगार पर खड़े हैं कि जहाँ से मामूली सा धक्का ही हम निश्चित और पूण विनाश के गहर गड्ढे में धकेल सकता है।<sup>9</sup> आर०सी० दत्त के अनुसार 'विदेशी उत्पादन द्वारा भारतीय गिल्प उत्पादन की स्थानापन्नता ब्रिटिश भारत के इतिहास का निवृत्ततम अध्याय है।'<sup>10</sup> क्योंकि इसमें भारत के आर्थिक स्रोतों में हुए सकाच और भारतीयों की आजीविका में जाई जोर अधिक कृच्छता तथा विपन्नता के स्पष्ट संकेत मिलते हैं।<sup>11</sup> भारतीय नाना ने स्पष्ट किया कि अथव्यवस्था के कृषि संबंधी और उद्योग संबंधी क्षेत्रों के सतुलन में विकार न और इसके फलस्वरूप औद्योगिक ह्रास ने न केवल राष्ट्रीय आय के एक बहुत बड़े तथा महत्वपूर्ण स्रोत को ही नष्ट-भ्रष्ट किया है प्रत्युत लाखों कारीगरों का परंपरागत व्यवसाय में वंचित करके उन्हें आजीविका के अन्य साधनों के अभाव के कारण, आजीविका के एकमात्र अवशिष्ट साधन कृषि पर अधिकाधिक निर्भर होने को विवश भी किया है।<sup>12</sup> इस प्रकार हस्तशिल्प उद्योगों के ह्रास ने भूमि पर लागों का दबाव बढ़ा दिया है।<sup>13</sup> इसके फलस्वरूप भारत का ग्रामीकरण बढ़ता जा रहा है और भारतीयों की अकेले कृषि के ही विपन्न साधनों पर निर्भरता में वृद्धि हो रही है।<sup>14</sup> भारतीय जनता के आजीविका के लिए कृषि पर निर्भरता के बढ़ते अनुपात से भारत के ग्रामीकरण के विस्तार को नापा जा सकता है।<sup>15</sup> कृषि पर एकांत निर्भरता भी चिंतनीय है क्योंकि अनिश्चित कृषि के रूप में प्रकृति की कृपा पर निर्भर होने के कारण यह एक अविश्वमनीय उद्योग है।<sup>16</sup> इसके अतिरिक्त देश का ग्रामीकरण भी एक भयंकर आर्थिक राग है क्योंकि कृषि भूमि के सीमित होने के कारण उसमें नए प्रवेशकों खपाने की क्षमता नहीं है।<sup>17</sup> विचारणीय यह है कि एकांत और पूणतया कृषि पर निर्भर रहने वाले राष्ट्र का दरिद्र होना निश्चित ही है।<sup>18</sup> बहुत से राष्ट्रीय नेताओं ने 1880 के अकाल आयोग की राय का अनुमान करत हुए उसे उद्धृत किया भारत के तागा की अधिकांश दरिद्रता का तथा अभाव के दिनों में अनुभूत खतरों का मूल कारण यह दुभाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि अधिकांश भारतीय जनता के लिए एकमात्र व्यवसाय कृषि है।<sup>19</sup> कृषि पर अवाछनीय भार कृषि संबंधी दक्षता को भी प्रभावित करता है।<sup>20</sup> इसके अतिरिक्त इसमें खेता का उपविभाजन

11 है, आवश्यकता से अधिक जुताई होने लगती है, पटिया और अनुत्पादक धरती

पर जुताई होने लगती है तथा जगला और चरागाहों पर अनुचित कब्जा किया जाने लगता है।<sup>1</sup> इन सबका परिणाम ग्रामों की प्रच्छन्न बवारी है। जी० बी० जोशी न भी निर्देश किया कि एक ओर भूमि को अवाञ्छनीय श्रमिका का भार सहन करना पड़ता है और दूसरी ओर वचत के अभाव के फलस्वरूप भूमि में सुधार के लिए आर्थिक साधना की बन्नी होती है।<sup>2</sup> भूमि पर दबाव खेतिहरों में सवथा अलाभकारी तथा बहुत ऊँच निरायों पर धरती को लेन में विनाशकारी प्रतियोगिता की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है।<sup>3</sup> इस प्रतियोगिता के कारण कृषि श्रमिक एक-दूसरे की मजदूरी का अवमूल्यन करते हैं।<sup>4</sup> रानाडे ने भी अनुभव किया कि आधुनिक भारत के ग्रामीकरण का अर्थ है उस असम्य बनाना अर्थात् उसकी प्रकृति, प्रतिभा और आत्मरक्षा की भावना का विनाश करना।<sup>5</sup> पारपरिक उद्योग धंधा के इस बढ़ते हुए विनाश के साथ उनके स्थान पर नवीन उद्योगों की स्थापना में असफलता का निकटतम परिणाम यह था कि भारत का आर्थिक जीवन अधिकाधिक विदेशी प्राधिक प्रभुत्व के अधीन हो गया था। विदेशी शासक न तुच्छ दृष्टि से भारत को ब्रिटिश अभिकर्ताओं द्वारा ब्रिटिश जहाजा पर लादन के लिए कच्चा माल उत्पन्न करनेवाली एक बस्ती के रूप में ही लिया। भारत का कच्चा माल न तुच्छ बारीगरी और ब्रिटिश घन से बस्तियों के रूप में परिणत होता था और फिर वही ब्रिटिश ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा भारत तथा अन्य अधीनस्थ राज्या में ब्रिटिश व्यापार तथा क माध्यम से पुनः निर्यातित किया जाता था। परंतु ग्रामीण तथा शहरी हस्त उद्योगों का यह द्रुत विनाश हुआ कैसे? क्या यह समय अथवा परिस्थितियों के परिवर्तन का अपरिहाय परिणाम था? यदि ऐसा था तो यह एक दुःखद प्रतिनिधा के मित्र और कुछ नही था। इस सबध में भी भारतीय नेताओं का विश्वास था कि मनुष्यों के नियंत्रण से बाहर की घटनाओं की भी भूमिका रही होगी। किंतु बस्तुतः भारत के उद्योग-धंधों का विनाश तो निश्चित रूप से हृदयहीन स्वायत्तरता तथा नूर अयाय की एक बरुण कहानी थी।<sup>6</sup> उन्होंने इसका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व ब्रिटेन पर तथा भारत में स्थित ब्रिटिश अधिकारियों के कंधे पर ही डाला, जिन्होंने एक निश्चित सक्त्व तथा विनाशक दृढता के साथ<sup>7</sup> भारत के उद्योगों के विनाश की सुविचारित नीति का अनुसरण किया।<sup>8</sup>

भारतीय नेताओं का विश्वास था कि ब्रिटिश अधिकारी ब्रिटेन के व्यापारियों और शिल्प उत्पादकों के दबाव के कारण भारतीय उद्योगों पर उनके दुष्प्रभाव की चिंता किए बिना और यहाँ तक कि उनके मूल्य पर भी, इंग्लड के विनाशशील उद्योगों को प्रोत्साहन देने को दृढसत्त्व थे।<sup>9</sup> उनक अनुसार भारत में ब्रिटिश नीति का द्विपक्षीय उद्देश्य था, एक तो ब्रिटेन के औद्योगिक उत्पादनों की खपत के लिए भारत को एक मूल्यवान मंडी बनाना, भले ही इसके लिए भारतीय उद्योग धंधों को कुचलने के लिए विविध तीव्र साधन ही क्यों न अपनाएँ पड़ें।<sup>10</sup> दूसरा, ब्रिटेन के तेजी से बढ़ते हुए उद्योगों के लिए ब्रिटेन की बढ़ती हुई आवश्यकता के बच्चे माल को सस्ती दर और सुनिश्चित परिमाण में मतोप-जनक सभरण के लिए भारत को बच्चे माल के उत्पादक कृषि देश के रूप में परिवर्तित करना।<sup>11</sup> इन दोनों उद्देश्यों की सिद्धि भारतीय उद्योग धंधों को आघात पहुँचाकर और

इस प्रकार भारतीय अर्थ व्यवस्था को ब्रिटिश उद्योगों की सहायक बनाकर ही की जा सकती थी।<sup>34</sup>

भारतीय नेताओं को पूरा यकीन था कि ब्रिटेन ने अपने राजनीतिक नियंत्रण का दुरुपयोग करते हुए भारत और ब्रिटेन में व्यापार में प्रतियोगिता की अत्यायुष्ण परिस्थितियाँ उत्पन्न करके भारत के उद्योगों का बर्ही ही तत्परता और तेजी से विनाश किया है।<sup>35</sup> उन्होंने इतिहासकार एच०एच० विलमन के इस मत से सहमति प्रकट की कि विदेशी उत्पादन समान शर्तों पर समझौता अथवा बराबरी न कर सकने पर अपने प्रतियोगी का नीचा दिखाने और अतंत उसका गला घोटने के लिए राजनीतिक अत्याय के शस्त्र का प्रयोग करता है।<sup>36</sup> 1765 में बंगाल में ब्रिटिश प्रशासन के प्रारंभ काल से यह कहा जाने लगा कि शासक ने स्वदेशी हस्तशिल्पों का कुचलने के लिए आदेश जारी किए हैं।<sup>37</sup> 1813 और 1833 की सप्तदशवीं शताब्दी का एकमात्र उद्देश्य भारतीय बाजार में ब्रिटिश निमाताओं के स्वदेशी उत्पादनों को अपदरय करने के साधन खोजना था।<sup>38</sup> भारतीय नेताओं के अनुसार इस उद्देश्य की मिद्धि के लिए खोजा गया अति महत्वपूर्ण उपाय था, नेत्रमूलक सीमा शुल्कों का कराधान। भारतीय उत्पादकों के लिए जहाँ प्रतिस्पर्धा और अत्यधिक ऊँची शुल्क पद्धति के कारण अगरेजी बाजार तेजी से संकुचित होता जा रहा था, वहाँ उन्मुक्त व्यापार लागू होने के कारण भारतीय बाजार अगरेज व्यापारियों के लिए अधिकाधिक विस्तृत होता जा रहा था।<sup>39</sup> 1848 में भारत के इंग्लैंड को निमाता पर निषेधक करों को हटा दिया गया परंतु उस समय तक के कर अपना सहायक प्रहार कर चुके थे।<sup>40</sup> भारत का आंतरिक व्यापार भी अतर्देशीय सीमा शुल्कों तथा सत्रमण शुल्कों की प्रथा के लागू होने से प्रतिव्यवित तथा संकुचित था तथा इससे अपने ही बाजार में स्वदेशी उत्पादन में एक दूसरे के विरुद्ध भेदभाव पनपता था।<sup>41</sup> ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी जुनाहो तथा अन्य दूसरे उत्पादकों पर एकाधिकारी नियंत्रण रखने के लिए, उन्हें अलाभकारी समेते दामों पर माल का उत्पादन करने के लिए विवश किया और इस प्रकार उन्हें अपना पैसक व्यवसाय छोड़ने को बाध्य करने के लिए राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग किया।<sup>42</sup>

भारतीय अधनीति के विचारकों ने विदेशी शासकों द्वारा भारतीय उद्योग घटा के विनाश के सुविचारित प्रयत्नों की भूमिका पर विचार करते हुए अपने अंतिम विश्लेषण में इस तथ्य को तत्परता से अभिस्वीकार किया कि वाण्यशक्ति और उत्तम मशीनरी पर आधृत उत्पादन कला की श्रेष्ठता के कारण ही ब्रिटिश उत्पादक स्वयं भारत के बाजारों में ही भारतीय कारीगरों के उत्पादन के मुकाबले अपना बढ़िया और सस्ता उत्पादन खपा कर वास्तव में ही भारतीय उद्योग घटा को मटी से बाहर धकेलने में सफल हुए हैं।<sup>43</sup> उदाहरणार्थ जस्टिस रॉय ने इस तथ्य की पुष्टि की कि विदेशी प्रतियोगिता विदेशी हान के कारण नहीं प्रत्युत मानव श्रम के माध्यम प्राकृतिक शक्ति की प्रतियोगिता, अनान और अव्ययता के साथ मुनियोजित शिल्प कौशल तथा विनाश की प्रतियोगिता हान के कारण न केवल सफल पर प्रत्युत उससे भी अधिक उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण दूसरों के बाजार, प्रतिभा तथा मनीविधि पर एकाधिकार को स्वानांतरित कर रही है।<sup>44</sup> बहुत से राष्ट्रवादी ने मायता थी कि केवल शिल्प कौशल की श्रेष्ठता से भारतीय हस्तशिल्प का

समूल विनाश सम्भव नहीं था।<sup>43</sup> वस्तुतः सत्य यह है कि इसमें सहायक तत्व थे, नेलवे के शीघ्र निर्माण के रूप में भारतीय यातायात साधनों का विकास<sup>44</sup> तथा भारत में उद्युक्त व्यापार की अनुमति।<sup>45</sup> यद्यपि तत्त्व भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य के ही राजनीतिक परिणाम थे। इसके अतिरिक्त उनका प्रदान यह था कि भारत को पराजित करनेवाली इंग्लैंड की द्रुत गति से विकसित शिल्पकला की उत्पत्ता का आधार क्या था? उनके विचार में इन दश के तथा अन्य अधीनस्थ देशों के वासियों से अपरिमित धन की लूट से ही ब्रिटेन के मशीन उद्योग का पोषण और विकास सम्भव हुआ था।<sup>46</sup> कुल मिलाकर भारतीय नताशा का यह मत था कि राजनीतिक शक्तियाँ के प्रयोग से प्रतिष्ठित श्रेष्ठता समाप्त हाने से अनीत में भारतीय शिल्पकला की इंग्लैंड के उद्योगों पर प्रतिष्ठित श्रेष्ठता समाप्त होने के विरोधी को हस्ताक्षरित हो गई है।<sup>47</sup> यह उल्लेखनीय है कि इस युग के जन नेताओं ने ग्रामों के शिल्पों और कलाओं के ह्रास और विस्थापन पर ध्यान देने के बजाय वस्त्रों के न्यूनाधिक रूप में कच्चे माल के निर्यात तथा ग्राम पंचायतों के ह्रास और लोप के फलस्वरूप भारतीय समाज के उच्च और मध्यवर्ग के लोगों की रुचियाँ में आए परिवर्तन के प्रभावों की उपेक्षा कर दी।

राष्ट्रवादियों ने मन्वैशी उद्योगों के ह्रास को भारत की दरिद्रता का मूल कारण मानते हुए जनता की भौतिक स्थिति में और अधिक गिरावट को रोकने के लिए तथा देश के आर्थिक पुनर्जागरण के लिए भारतीय हस्त उद्योगों की सुरक्षा, पुनर्स्थापना, पुनर्नियोजन तथा आधुनिकीकरण का स्वाभाविक ही अपने कर्तव्य का प्रमुख अंग बताया।<sup>48</sup> भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बार-बार अपनी घोषणाओं में दोहराया कि देश में पड़नेवाले अवाला के निवारण की सही औपधि अर्थात् उपायों के साथ वास्तव में नष्टप्राय स्वदेशी और स्थानीय कलाओं और उद्योगों के विकास को आगे बढ़ानेवाली नीति अपनाना है।<sup>49</sup> इसके साथ ही भारतीय नताशा ने यह भी स्पष्ट रूप से अभिस्वीकार किया कि अन्य देशों का अनुभव इस ओर संकेत करता है कि आज के मशीनी युगों तथा विशाल उत्पादन के युग में सस्ते प्राकृतिक अभिकरणों द्वारा संचालित उद्योगों के मुकामल में हस्तसंचालित उद्योगों का विश्वास था कि भारतीय हस्तशिल्पों के ह्रास का प्रक्रिया कितनी ही अपरिहार्य क्या न थी, उमका सशोधन और व्यवस्थापन इस रूप में हो सकता है और अवश्य होना चाहिए कि इससे लोगों को यथासम्भव न्यूनतम क्षति हो। इसके अतिरिक्त इन उद्योगों को बड़े पैमाने पर एक अभियोग यह था कि उसने तकनीकी शक्तियों के प्रवर्तन में मशीनों अथवा निष्पन्न की कोई चेष्टा नहीं की।<sup>50</sup> इस सम्बन्ध में आर्थिक चिन्तन की उनमें गहराई लिए कोई भी समझदार, दूरदर्शी जपनी सत्ता के प्रति जागरूक तथा दायित्वों को सम्भालनेवाले सरकार अपने अधिष्ठित देशों के औद्योगिक गठन में ऐसे विनाशकारी भौतिक परिवर्तनों को जहाँ रोकने के सक्रिय उपाय किए बिना कदापि न होने देती।

निस्मदेह हस्त उद्योगों का भाषशक्ति वाले उद्योगों में परिवर्तन सवथा अनिवाय है और इसे किसी भी देश में रोना नहीं जा सकता, परंतु भारत जैसे पिछड़े और अर्थ-विकसित देशों में स्पष्ट रूप से इन देशों की सरकारों का यह वैधानिक दायित्व है कि वह सामयिक और अस्थायी हस्तक्षेप द्वारा इस परिवर्तन को इस प्रकार से नियंत्रित करे कि जिससे वह बर्ताने के निवासियों के लिए लाभप्रद बन सके।<sup>55</sup>

## II आधुनिक उद्योगों को प्रोत्साहन

प्रारंभिक भारतीय नेताओं ने आधुनिक उद्योगों की स्थापना और उन्नति पर तात्कालिक सहायता दी, किंतु आधुनिक उद्योगों के विकास के विरोध में अथवा विकल्प के रूप में हस्त-शिल्प उद्योगों के संरक्षण और पुनरुज्जीवित करने की इच्छा का कभी मन में स्थान नहीं दिया।<sup>56</sup> उन्होंने लगभग एक मत से यह स्वीकार किया कि आधुनिक मशीनों द्वारा देश के अर्थ-व्यवस्था का पूर्ण रूप में परिवर्तन उनकी अर्थनीतियों का प्रमुख लक्ष्य तथा देश के सभी आर्थिक रोगों की जड़ थी। भारतीयों द्वारा आधुनिक उद्योगों की स्वीकृति और बर्ताने की आधुनिक भारत में उद्योगीकरण के अग्रदूत जस्टिस रानाडे ने अपने देशवासियों का सर्वोचित निम्नलिखित प्रयागन में सर्वोत्तम रूप से इस प्रकार प्रकट किया है— हमने सर्वोत्तम शिक्षकों से सीखने के लिए यह ईश्वर द्वारा सुस्थापित व्यावहारिक काय है। हम अपने कच्चे माल के स्तर को सुधारना है अथवा हमारी धरती के उत्तम स्तर के उत्पादन को अनुकूल न होने पर उसका आयात करना है। हमें सहयोग द्वारा श्रम और पूँजी का संग्रहित करना है और उच्च रूप से विदेशी कौशल तथा मशीनों का तब तक आयात करना है जब तक हम अपने आप मशीन प्रकार काय करना सीख नहीं जाते हैं तथा उनकी सहायता की अपेक्षा छोड़ नहीं देते। हम बहुत अधिक पिछड़े गए हैं अब हम नए कामों में हाथ डालना है तथा और अधिक कठोर श्रम के लिए ईमानदारी से काम करने की है। यह एक नागरिक गुण है जो हमें सीखना है। यदि हम इस गुण को अपनाते हैं तो युद्ध में हमारी विजय निश्चिंत है। इससे विपरीत यदि हम इस गुण की अपेक्षा करते हैं तो पराजय मुझे बाएँ राड़ी है— मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही कठोर श्रम सारे देश का धर्म बन जाएगा तथा प्राचीन भारत में स्थाई रूप से नवीन भावनाओं का बिगुल बजेगा।<sup>57</sup>

भारतीय नेताओं ने नए उद्योगों की स्थापना की दिशा में उठाए गए प्रत्येक पग का स्वागत किया तथा किसी भी प्रत्यक्ष रूप से यत्नमाध्य क्षेत्र में भारतीयों की निश्चेष्टता पर बिनाप किया और उन्हें अपने सभी साधनों को जुटाकर उद्योग तथा व्यापार में प्रवृत्त होने के लिए प्रभावित किया।<sup>58</sup> उनका युद्धघोष था— श्रम अवश्य ही पूँजीपति तथा उद्योगी बनना चाहिए। अपने देश का व्यापारियों का देश मशीन बनाने वालों का देश तथा दुकानदारों का देश बनाना चाहिए।<sup>59</sup> कुछ महानुभावों की दृष्टि में उद्योगीकरण जनता की प्रगति की एकमात्र भले न सही अत्यधिक महत्वपूर्ण कमीठी अवश्य था।<sup>60</sup> यह एक मात्र कमीठी थी जिसके आधार पर देश के आर्थिक विकास की गतिशीलता को दगा परखा जा सकता है।<sup>61</sup>

उद्योगीकरण के बहुत से बढ़ते हुए लाभों के कारण भारतीयों की दृष्टि में आधुनिक

उद्योगो पर बल देना सवथा न्यायमगत था, यथाकि वस्तुतः भारत की आर्थिक बठिनाइया के मूल कारण अपूण उत्पादन तथा अपूण रोजगार ही थे। दरिद्रता तथा हास के और अधिक विवास को रोक्ने की सही औपधि राष्ट्रीय सपदा को बढाना तथा लाखो-करोडा लागो को स्पन बनने के लिए प्रो साहित करना था। यह सब आयुनिक उद्योगो और उत्पादनो के विवास द्वारा ही सभव था।<sup>15</sup> इमके अतिक्रि भारत म अधिकाश जातन योग्य भूमि को पहल ही जाता जा चुका था और इस प्रकार वृषि विस्तार अपनी सीमा पर पहुच गया था।<sup>16</sup> इस स्थिति म आयुनिक उद्योग एक एसा अभिवरण था जिसम भूमि पर आवान्ती के बढत हुए दनाव को बम किया जा सकता था तथा दश की निरतर बढती हुई आवादी के दहाती अपूण रोजगारी और बेरजगारी बम की जा सकती थी और साथ ही आजीविका के वैकल्पिक साधन जुटाए जा सकत थ।<sup>17</sup> इस प्रकार किसी भी रूप म आजीविका के अन्दिचत और सदिध साधन वृषि पर एवात निमरता वा समाप्त करन के लिए तथा दश को और अधिक असम्य बनने स रोक्न के लिए दश वा उद्योगीकरण आवश्यक था।<sup>18</sup> उद्योगो के विवास से ही कच्चे माल के नियात तथा उत्पादना के आयात स होन वानी दश की सपदा की निकासी और थम तथा पूजी की हानि आदि को घटाया जा सकता था।<sup>19</sup>

कुछ एक भारतीय नेता एक अय दृष्टि देश की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति की दृष्टि से भी बडे पमान के उद्योगो की आवश्यकता मानत थ। उनके अनुसार आधुनिक उद्योगो से अधिक सपदा वा ही उत्पादन नही हागा प्रत्युत उससे भी अधिक महत्वपूण काय उत्पादक शक्तिया का पूण और बहुमुखी विकास भी होगा।<sup>20</sup> वृषि और उद्योग द्वारा कुल उत्पादित पूजी की राशि समान होन पर भी वृषि वा सर्कीर्ण और सकुचित क्षेत्र आर्थिक विकास के निम्न स्तर को और इसके विपरीत उद्योग और वाणिज्य वा क्षत्र उमुक्त तथा उन्नत विकास को सूचित करता है।<sup>21</sup> इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता था कि औद्योगिकता सम्यता के उच्च स्तर तथा विशिष्ट आदश वा प्रतिनिधित्व करती है।<sup>22</sup> साथ ही यह देश की संस्कृति चरित्र और प्रतिभा के विकास और विस्तार म सहायक होती है।<sup>23</sup> 1890 मे रानाडे न लिखा स्कूलो और कालेजा की अपक्षा कारवाने और मिलें अधिक प्रभावशाली ढग से राष्ट्र की गतिविधियो को जम दे सकती है।<sup>24</sup> इमके अतिरिक्त सक्षप मे आयुनिक उद्योग ही एक ऐसी शक्ति है जा भारत क विभिन्न लागो वा सामाय लाभ के आधार पर एक राष्ट्रीय सत्ता के रूप म संगठित करन म सहायक हो सकती है।

राजनीतिक अधिकारो के लिए आदोलन भारत के विभिन्न राष्ट्रवादिया को कुछ समय के लिए एकता के सूत्र मे अवश्य बाध सकता है परतु इन अधिकारो की उपलब्धि पर हिता की समानता समाप्त हो सकती है। इसके विपरीत विभिन्न भारतीय राष्ट्रवादिया का एक वार वाणिज्य संगठन स्थापित हो जान पर वह कभी अस्तित्वपूय नही हो सकता। अतएव वाणिज्य और उद्योग सबधी गतिविधि बडा सुदढ संगठन है तथा भारत के महान राष्ट्र के निर्माण वा एक सशक्त तत्व है।<sup>25</sup>

इस प्रकार 19वीं शताब्दी के अत तक देश के आयुनिक ढग से उद्योगीकरण की माग

को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो गई थी। समीक्षाधीन काल की अवधि में एक भी ऐसा राष्ट्रवादी समाचारपत्र अथवा लोकनायक नहीं था जिसने भारत में पश्चिमी तकनीक और उद्योग के प्रवर्तन और उत्थान की वाछनीयता और उपयोगिता पर कभी सन्देह किया हो अथवा उद्दण्ड नवारा हो। बड़े पैमाने के पूँजीमूलक उद्योग के विरुद्ध अकला स्वयं-व्यक्तता में प्रकाशित 'दि डैन' पत्रिका के संपादन सतीशचन्द्र मुखर्जी का था। 1905 में पूँज के वर्षों में तो उनका मन्त्र अपेक्षाकृत कम था परन्तु उनके उपरांत उठाने प्रयुक्त तथा अपने बहूत सारे प्रसिद्ध गिण्या के प्रभाव के कारण बंगाल के राजनीतिक जीवन में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया था। मजिप्त रूप में इस अवधि में प्रस्तुत उनके विचार दो दृष्टियों में महत्वपूर्ण थे। एक ओर वे कुछ रूपों में महात्मा गांधी द्वारा अपनाई गई नीति में मिलत जुलत थे और दूसरी ओर वे निगम पद्धति से मेल खात थे।<sup>1</sup> उनमें अनुभार आधुनिक उद्योग पद्धति में दो प्रमुख दोष थे। एक ओर यह पूँजीपतियों के एक छोटे में परन्तु सुसंगठित अल्पसंख्यक वर्ग को जन्म देता है और दूसरी ओर यह भयंकर धर्म सगठनों के रूप में धर्मिता का इच्छा होने की प्रेरणा देता है जो विश्वपतया भारत में विंगाल दंग के लिए निश्चित रूप से एक स्थाई सामाजिक तथा राजनीतिक खतरा बन सकती है। इसके उपचार के लिए उठाने दो उपायों का सुझाव दिया। प्रथम, अधिकांश उद्योगों को पारिवारिक हस्तकलाओं के आधार पर संगठित किया जाए तथा बड़े पैमाने के पूँजीमूलक उद्योगों में केवल उन कुछ एक उद्योगों (इंजिनियरी खान, रेलवे, आदि) को ही विनियमित किया जाए जिनकी आवश्यकता समाज के बहुत बड़े वर्ग को धार्मिक रूप में तथा पारिवारिक शिल्पों के लिए रहती है। द्वितीय, सामूहिक नैतिक जीवन का इस प्रकार से संयोजन करना चाहिए कि इसके अंतर्गत सामाजिक जीवननय में प्रत्येक वर्ग को एक निश्चित सम्मानित तथा स्वतंत्र स्थान हो। प्रत्येक व्यक्ति पारस्परिक सहयोग और समन्वय को भावना से इस प्रकार काय करे कि उससे सभी को समान रूप में लाभ मिले सारे भारतीय समाज का समुक्त रूप से भौतिक उत्थान और आध्यात्मिक विंगम हो।<sup>2</sup>

कुछ एक अन्य भारतीय लेखकों ने भी पश्चिम की प्रतियोगिता और स्तानुप प्रवृत्ति वाली औद्योगिक संस्थाओं की आलोचना की। उनके विचार में इन संस्थाओं में सामाजिक मरधा का भ्रष्ट करके रख दिया है और मनुष्य को अपने द्वारा अपने लिए जीन पर बाध्य कर दिया है। 'पूना मावजनिक् सभा' के अप्रैल 1893 के अंक में प्रकाशित 'दि एग्जीक्यूटिव आफ प्राप्ति इन इंडिया' लेख के अनांत लेखक द्वारा समकालीन पश्चिमी यूरोपीय पूँजीवाद पर निहित स्वर में घापित अभियोग में उदा अभिवाग किसी भी सत्कालीन अन्य लेखक द्वारा नहीं लगाया गया

अनीति को सभी ब्रूताएँ मितकर भी अपनी तीव्रता में जीवन की आवश्यकताओं का असमान वितरण, धन संपत्ति के केंद्रीकरण धर्म पर पूँजी की वैध दासता, अपवाप्त आजीविका के कारण दुःख और वदनाओं सुखमयी से हान वाली अनस्य मृत्युओं तथा कुटा और निरंगा के कारण हुई अनभिलिगित जात्रमहत्याओं के रूप में प्रस्तुत दीवकाय दुर्भाग्य का मुकाबला नहीं कर सकती।<sup>3</sup>

इन लेखको ने पश्चिमी औद्योगिकता के दोषों का जानत हुए भी उसे उसके मूल रूप में भी नकारा नहीं क्योंकि मूलतः वे लेखक पूर्वी जीवनपद्धति की अपेक्षा पश्चिमी जीवन-पद्धति में ही विश्वास करते थे। इसके अतिरिक्त वस्तुतः अब भारत के चाहने या न चाहने की कोई बात ही नहीं रह गई थी क्योंकि अब तक तो वह सांसारिक पूजावादी प्रणाली का एक अंग बन चुका था और जब उसके लिए अलग अलग रहना संभव ही नहीं था। अतएव उस समय अपरिहाय भाग को स्वीकार करना, समय की मांग के अनुसार अपने आपको ढालना तथा सभ्यता के बढ़ते कदम के साथ कदम मिलाना ही अधिक उपयुक्त था।<sup>77</sup>

कालक्रम की दृष्टि से भारत में सबसे प्रथम नील, चाय तथा काफी वागान के उद्योग ही गुरु हुए। उनका स्वामित्व एकांततः यूरोपीयों का था और वे पूणतः आधुनिक मशीनी आविष्कारों पर निर्भर नहीं थे। अतएव भारतीयों का इस ओर विशेष ध्यान ही नहीं गया। भारतीय नेता तो फैक्टरी उद्योग के प्रति दत्तचित रह और इनकी उन्नति के साथ ही अपना प्रमुख नाता जोड़े रहे। रेलवे का आगमन भारत में आधुनिक मशीनरी के प्रवेश की घोषणा थी और 1850 की अवधि में भारत में सूती कपड़ा, पटसन तथा कोयला खान उद्योग स्थापित हो चुके थे। अंतिम दो औद्योगिक क्षेत्र प्रमुख रूप से यूरोपीय पूजा के अंतर्गत थे अतः भारतीयों के उद्यम और आशा का केंद्र एकमात्र सूती कपड़ा उद्योग ही था। यही कारण है कि इसे अपने जन्मकाल से ही दश के कारखाना उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त रहा है। 1879 में देश में 56 सूती मिलें थीं और इनमें लगभग 43,000 व्यक्ति काम करते थे। इनमें 75 प्रतिशत कारखाने बंबई प्रांत में स्थित थे। 1882 में केवल 22 पटसन मिलें थीं और उनमें से अधिकांश मिलें बंगाल में थीं। इनमें लगभग 20,000 व्यक्ति कार्यरत थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि 1880 तक भारत में आधुनिक उद्योग का विस्तार अत्यंत स्वल्प था, पुनरपि वह स्वल्प विस्तार भारतीय नेताओं और उद्यमियों के दूरदर्शी वगैरे में आधुनिक उद्योग के प्रति रचि उत्पन्न करने में तथा उनसे प्रलोभन को बढ़ाने में पर्याप्त समय था। 1880 के उपरांत दश में औद्योगिक विस्तार में मदद होने पर भी निरंतरता ग्रहण की और इसके फलस्वरूप 1901-02 में भारत में 1,14,795 व्यक्तियों का सेवारत करनेवाली 36 पटसन मिलें, 1904-05 में 1,96,369 व्यक्तियों को जाजीविका देने वाली 206 सूती कपड़ा मिलें और 1906 में लगभग 99,000 लोगों को काम देने वाले कोयला खान आदि उद्योग अस्तित्व में आए। इस अवधि में अपेक्षाकृत कम विस्तार से बनपने वाले अन्य उद्योग थे रई बलन यंत्र, चावल, आटा और इमारती लकड़ी की मिलें, चमड़ा कमान के कारखाने, ऊनी कपड़े की मिलें, कागज और चीनी मिलें तथा नमक, अभ्रक, शीरा, पेट्रोल तथा लोहा जैसी धातुओं के उद्योग, घाटी में इंजीनियरी और रेलवे कर्मशालाएँ तथा लोहे और पीतल की ढलाई करने के कारखाने भी अस्तित्व में आए।<sup>78</sup> स्पष्ट है कि हमारे अध्ययन के काल की अवधि में भारत में औद्योगिक प्रगति कुल मिलाकर बहुत ही धीमी थी तथा रई और पटसन उद्योगों तक ही सीमित थी।<sup>79</sup> अतः यह स्वदेशी हस्तशिल्पा के विस्थापन की क्षतिपूर्ति में भी समय नहीं था।<sup>80</sup>

यह स्वाभाविक था कि भारतीय नेताओं का ध्यान दश की औद्योगिक प्रगति का



विलंबित करने वाले कारणों की जाच की ओर तथा साथ ही प्रयाग में लाए गए वान उपचारों की खोज की ओर जाता। सवप्रथम भारतीय नेताओं ने इंग्लैंड में तथा भारत में सरकारी क्षेत्र में व्यापक रूप से अत्यंत लाभप्रिय इस धारणा का खंडन तथा विनाश किया कि भारत के भाग्य में एक महान औद्योगिक देश बनना नहीं वंदा था और एक उष्ण कटिबंधीय देश होने के नाते उसकी प्राकृतिक भूमिका यूरोपीय देशों के प्राकृतिक तकनीकी और वैज्ञानिक अभिरुचि रखने वाले उत्पादकों के प्रयोग में आनेवाले कच्चे माल के उत्पादन की थी।<sup>181</sup> भारत के अति प्राचीन पान में ही एक अत्यंत उपयुक्त महान उत्पादक देश होने के साथ ही भारतीय नेताओं ने अनेक उत्पादन कलाओं में देश की अतीत की उपलब्धियों का उल्लेख किया।<sup>182</sup> इसके अतिरिक्त उन्होंने इस तथ्य का स्वतः सिद्ध प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया कि भारत आधुनिक उद्योग के लिए अपरिचित कच्चे माल का उत्पादक है और इन प्रकार यह स्वाभाविक रूप से सर्वाधिक सभ्यता उत्पादक देश होने के योग्य है।<sup>183</sup> यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीयों में किसी भी देश की व्यावसायिक तथा औद्योगिक दृष्टि से महान बनाने में सहायक बहुत ही विशेषताएँ, दूरदर्शिता, प्रतिभा, कौशल, आत्मनिर्वास तथा बटोर थप की क्षमता विद्यमान हैं।<sup>184</sup> फलतः भारतीय नेता कुछ एक अर्थ मानवनिर्मित न कि ईश्वरनिर्मित वित्तीय बाधाओं को समुचित सामाजिक प्रयत्नों द्वारा माग से हटा दिए जाने पर भारत के औद्योगिक भविष्य की उज्ज्वलता के संबंध में आशावादी ही नहीं थे, प्रत्युत पूर्ण रूप से विश्वस्त थे।<sup>185</sup>

### III पूजा की कमी

राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों का अनुमान भारत के पास भूमि और श्रम की तो प्रचुरता थी परंतु बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना के माग में औद्योगिक चैप्टरों के लिए अपेक्षित पूजा की कमी एक बड़ी भारी अड़चन थी।<sup>186</sup> रानाडे ने लिखा कि जिस प्रकार भारत की भूमि प्यास से तड़प रही है उसी प्रकार देश का उद्योग पूजा के अभाव में झुलसा रहा है।<sup>187</sup> पूजा के अभाव की समस्या का पहला उपाय (क) जमा पूजा तथा चाल बचत का विवरलता।<sup>188</sup> इसके कारण थे निर्यात भूतनाल में शान्ति और सुरक्षा का अभाव।<sup>189</sup> भारत की अत्यधिक निधनता, जिसके कारण सामान्य बचत असंभव न सही परंतु अति कठिन अवश्य थी।<sup>190</sup> हिंदुओं की सामाजिक प्रथाएँ तथा धार्मिक मान्यताएँ जिसके अनुसार व सपदा के संप्रहृ की अपेक्षा उससे उपविभाजन से ही विद्वान् गण्य थे।<sup>191</sup> लोगो की पैर बाटने वाले उच्च सरकारी कर्मचारियों तथा सपदा की आर्थिक निकासी, जिसके अंतर्गत मजदूरी की मशकत बचत का बहुत बड़ा भाग विदेशों का चला जा रहा था।<sup>192</sup> (ख) आधुनिक उद्योगों की दशा में उपलब्ध परंतु बिखरे हुए आर्थिक साधनों का मजान तथा उच्च गति से म असफलता।<sup>193</sup> यह असफलता एक ठो बड़े उद्योगों के प्रवर्तन तथा उनमें सफलता प्राप्ति के लिए अनिवाच्य रूप से अपेक्षित पूजापतिवग में पारस्परिक विश्वास के साथ मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति के पारस्परिक सहयोग की भावना के तथा नियमित और संगठित रूप में कार्य संचालन की प्रवृत्ति में अभाव का<sup>194</sup> और दूसरे आधुनिक बकों जैसे अपेक्षा पर्याप्त साख संगठनों के अभाव का परिणाम थी और केवल इन्हीं साधनों के

जगिण असम्य निवेशको की छोटी बचतो को पूजी के अभाव से ग्रस्त आधुनिक उद्योगो की ओर प्रवाहित किया जा सकता था।<sup>96</sup> बड़े पैमाने के उद्योगो का पूजी को अपनी ओर त म्बिच पाने का आगिक कारण यह भी था कि भारतीय धनाढ्य अनुद्यमी थे और वे किसी प्रकार का सत्तरा मोल लेन को उद्यत नहीं थे।<sup>97</sup>

भारतीय नेता इस तथ्य से सहमत थे कि सचित पूजी की राशि रातोरात नहीं बढ़ाई जा सकती परन्तु उतना कथन यह था कि ग्रेट ब्रिटेन के लिए भारत स होने वाली निकामी को रोककर<sup>98</sup> तथा भारतीया मे ददतापूवक मितव्ययिता से रहन तथा बचत करने की प्रवृत्ति को पनपाकर चालू बचनों बढ़ाई जा सकती हैं।<sup>99</sup> इसके अतिरिक्त उन्होंने देण के उपलब्ध पूजी स्रोतों के उपयुक्त उपयोग के लिए भी सुझाव दिए। उहारा जमींदारा और राजाओं का दश के एकमात्र सपन व्यक्ति होने के नाते देण के विकास-शील बड़ पैमाने के उद्योगों का वित्तीय सहायता देन के लिए आगे आने का परामश दिया।<sup>100</sup> उन्होंने लागो से अपने गुप्त सचया को बाहर निकालने का अनुरोध किया।<sup>101</sup> उन्होंने आधुनिक बको, वीमा कपनिया आदि के माध्यम से उत्तम साख सगठन की स्थापना की वकालत की जिसमें धन के छोटे छोटे, बिखरे हुए निर्जोब कणों को निस्सीम विस्तार के योग्य सुनियोजित तथा सजीव पूजी मे परिवर्तित किया जाए।<sup>102</sup> उन्होंने सवा-धिव बल पश्चिमी देशा मे अत्यंत सफल सिद्ध होने वाली 'मिथित पूजी समुदाय' नामक पूजीवादी सस्था अपनाने के रूप मे पारस्परिक विश्वास की प्रवृत्ति के प्रसार पर तथा वैयक्तिक प्रयासों के संयोजन पर दिया।<sup>103</sup> उहाने इस सबध मे दूसरे अभीष्ट उपायो (अगले अध्याय मे विवेचित) के रूप मे राज्य द्वारा सहायता और प्रात्साहन पर विशेष बल दिया।

#### IV तकनीकी शिक्षा

औद्योगिक विकास की दिशा मे उल्लेखनीय बाधक तत्वो मे प्रमुख था, भारत मे पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित तकनीशियनो की कमी। पलत समीक्षाधीन अवधि मे राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा बार बार दुहराई गई महत्वपूर्ण माग मे एक विशेष माग थी, देश भर म तकनीकी शिक्षा और ज्ञान के प्रसार के लिए तकनीकी स्कूला, कॉलेजा और सस्थाओं की स्थापना।<sup>104</sup> प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की चालू माग अधिकांशत उच्च वेतनभोगी विदेशी तकनीशियनो के आयात द्वारा ही पूरी की जाती है। इस प्रकार यह निश्चिन दृष्टि-बाण बना कि जबतक भारतीयों के अपने ही जनसमुदाय का उत्पादन और व्यापार के प्रत्येक विभाग को सुनियोजित करने, व्यवस्थित करने तथा निपुणता और सस्ती धरेलू कुशलता के साथ संचालित करने की दिशा म प्रशिक्षित नहीं किया जाता तब तक बड़ पैमाने के उद्योग दश मे कभी अड नहीं जमा सकते।<sup>105</sup> भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1887 मे अपने तृतीय अधिवेशन म तकनीकी शिक्षा के मामले को उठाया और माग की कि सरकार को जनता की दरिद्रता का नजर मे रखते हुए तकनीकी शिक्षा पद्धति के समुचित विकास की जर ध्यान देना चाहिए।<sup>106</sup> अपने अगल अधिवेशन म 1888 मे कांग्रेस ने अन्याय वस्तुओं मे सामान्य तकनीकी शिक्षा पद्धति लागू करने के प्रारंभिक कदम के रूप म देश की औद्यो-

गिक स्थिति की जाच के लिए एक मिलेजुले आयोग की नियुक्ति का आग्रह किया।<sup>107</sup> 1891, 1892 और 1893 में उसने अपना अनुरोध दोहराया।<sup>108</sup> 1894 में उसने अत्यंत प्रभावशाली ढंग से तकनीकी स्कूलों और कालेजों की स्थापना के औचित्य का प्रतिपादन किया।<sup>109</sup> कांग्रेस ने तदुपरांत प्रायः हर वर्ष अपनी इस मांग का दोहराया। 1904 में उसने देश में कम से कम एक पूर्णतः उपस्कृत केंद्रीय पार्लियामेंटरी संस्था की और विभिन्न प्रांतों में छोटे बड़े स्कूलों और कालेजों की स्थापना की वकालत की।<sup>110</sup> इस संबंध में यहाँ यह उल्लेखनीय है कि हाल ही में आविष्कृत तकनीकी शिक्षा पद्धति को आशिक रूप में यूरोप महाद्वीप में और विशेष रूप में जर्मनी, अमरीका और जापान में बड़े पैमाने के उद्योगों की उन्नति में उपनव्य उल्लेखनीय तथा स्पष्ट सफलता से भी भारत में तकनीकी शिक्षा पद्धति की मांग को प्राप्तसाहज मिला।<sup>111</sup>

भारतीय नेता विश्वस्त थे कि तकनीकी संवर्ग के वारे में जाधुनिक उद्योग की मांग की पूर्ति की लिखा में तब तक अग्रगति नहीं हो सकती जब तक कि सरकार स्वयं इस दिशा में उपनम न करे और देश में तकनीकी शिक्षा के प्रसार का बोधा अपने कर्तव्य पर न ले।<sup>11</sup> कुछ एक नेताओं ने स्थानीय मंडला तथा नगरपालिकाओं से अपने अपने क्षेत्रों में तकनीकी स्कूलों और कालेजों की स्थापना के लिए अपनी धनराशि के कुछ भाग को समर्पित करने का प्रस्ताव किया।<sup>113</sup> इस प्रकार उनका विचार था कि धन के अभाव के कारण तकनीकी शिक्षा को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। यद्यपि वे सामान्यतः मिन वयवी प्रवृत्ति के थे परंतु इस विषय में उन्होंने सरकार को इस क्षेत्र में आवश्यक धनराशि वह कितनी ही बड़ी क्या न हा, व्यय करने का परमण दिया।<sup>114</sup> उनके अनुसार भारतीय युवकों द्वारा तकनीकी शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह के अभाव का प्रमुख कारण देश के औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़े होने के कारण इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरा का अभाव था।<sup>115</sup> अतएव सरकार से अनुरोध किया गया कि वह तकनीकी शिक्षा पानेवाला क लिए काय जुटाए और विशेषतः भारतीयों को सावजनिक निमाण जगल, तार विभागा और रेलवे में ऊँचे पदा पर प्रतिष्ठित करे।<sup>116</sup> सरकार से बहुत अपेक्षा की गई थी और जाशा के विपरीत सरकार का वास्तविक योगदान देश की आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी शिक्षा के विकास में वर्षों तक निराशाजनक रहा, जत भारतीयों ने आगामी वर्षों में सरकार की तीव्र भत्सना की।<sup>117</sup>

भारतीय नेताओं ने जहाँ एक ओर देश में तकनीकी शिक्षा के प्रसार को सरकार का दायित्व बतलाया, वहाँ दूसरी ओर भारतीय जनता के खुद अपने परा पर खड होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने सामान्य रूप से सारी जनता से और विशेष रूप से शिक्षित वर्ग से लक्षपतिया, जमींदारों और रिवासतों के गासका से तकनीकी स्कूलों और कालेजों के खोलने के लिए तथा भारतीय विद्यार्थियों का विदेशों में पढ़ने के लिए सहाय तथा छात्रवक्तियों के निमित्त उदारतापूर्वक धन प्रदान करने का अनुरोध किया।<sup>118</sup> 1876 में कलकत्ता की इंडिया लीग ने एक तकनीकी संस्था की स्थापना के रूप में अपना ही समा घना से तकनीकी शिक्षा प्रसार के आदोतन का गति देने का प्रयत्न किया।<sup>119</sup> 1899 में जब एन० टाटा ने देश में उच्च वैज्ञानिक शिक्षा और अनुसंधान की उन्नति के लिए 30

लाख रुपयो का दान दिया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आगे बढ़कर उनके इस देश भक्तिपूण तथा उदार उपहार के प्रति कृतज्ञतापूण प्रशंसा की अभिव्यक्ति के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया।<sup>1</sup> १९०४ में कलकत्ता में के० सी० वैनर्जी, सुरेंद्रनाथ वैनर्जी, ए० एम० घोस तथा अय गण्यमाय नेताओं के नेतृत्व में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा की प्रगति के लिए एक संस्था का संगठन आत्मसहायता की दिशा में कदाचित्त एक सर्वाधिक सफल उदाहरण था। संस्था ने छात्रों को विदेशों में शिक्षा प्राप्त के लिए भेजने, भारतीय विशेषज्ञों को विदेशों से भारत लौटने में सहायता देने, नए उद्योगों को प्रारंभ करने तथा कलकत्ता की सेंट्रल लाइब्रेरी को मराम बनाने और व्यवस्थित ढंग में चलाने के लिए एक लाख रुपया प्रतिवर्ष उगाहने का निश्चय किया। संस्था का वार्षिक 'यूनितम' सदस्यता शुल्क चार आना निर्धारित किया गया।<sup>2</sup>

भारतीय नेताओं का ध्यान नई खुली तकनीकी संस्थाओं में दी जाने वाली तकनीकी शिक्षा की प्रवृत्ति की ओर भी गया। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक भारत में केवल चार इंजीनियरी कॉलेज थे जिनसे निकलनेवाले स्नातक विभिन्न सरकारी विभागों में खप जाते थे। कलकत्ता, मद्रास, बंबई और लाहौर के कला विद्यालयों में भी औद्योगिक अनुभाग थे। परंतु ये अनुभाग रईस युवकों, मिट्टी के बरतन बनाने, नक्काशी करने, मीनाकारी करने, लकड़ी पर खुदाई करने, सोने-चांदी तथा अन्य धातुओं के गहने बनाने के काम जैसे शिल्पों में ही प्रशिक्षण देने तक सीमित थे। १९०२ में देश में औद्योगिक संस्थानों की संख्या बढ़कर १२३ हो गई परंतु इन सब संस्थानों में सामान्यतया प्रशिक्षण के विषय में तक्षण बना, धातु कला चमकला तथा सिलाई कला।<sup>1</sup> राष्ट्रवादी नेताओं ने इसे बहुत बुरा माना और सरकार की तकनीकी शिक्षा को अधिकांशतः तक्षण लोहार और मुनार जैसे हस्त कलाकारों की काय शैली में सुधार तक सीमित रखने की नीति की घोर भत्सना की।<sup>2</sup> उन्होंने स्पष्ट निर्देश किया कि भारत के पास प्रशिक्षित हस्तशिल्पियों का पहले से ही बड़ा भंडार है। देश का तात्कालिक आवश्यकता है। तकनीकी शिक्षा का लक्ष्य नष्टप्राय अथवा विनाशमुख उद्योगों को पुनर्जीवित करना नहीं, प्रत्युत बाहर से मंगाई जानेवाली सामग्रियों का उत्पादन करने वाले बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना करना है।<sup>3</sup> अतः इस शिक्षा में भारतीयों को आधुनिक मशीन और मशीनी औजारों की चरम विकसित तकनीकी की सैद्धांतिक और व्यावहारिक जानकारी संपूर्ण परिचित कराने और उन्हें नए उद्योगों के संचालन में सहायता देने की सामर्थ्य होनी चाहिए।<sup>4</sup> यही कारण था कि भारतीयों ने जहां तकनीकी सबंध में विदेशी प्रशिक्षण और प्रशिक्षण पर अत्यधिक बल दिया।<sup>5</sup> वहां देश में अत्युन्नत तकनीकी शिक्षा देनेवाले ऊंचे स्तर के संस्थान खोलने का भी दृढ़ता से समर्थन किया।<sup>6</sup>

## V उद्यम की भावना

बुद्ध-एक भारतीय नेताओं के अनुसार देश के औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण दोगा यामियों में उपश्रम और उद्यम संबंधी अपभ्रान्त भावना का अभाव था।<sup>1</sup> १८२५ में जी०वी० जोशी ने अत्यंत दुःख से कहा कि भारतीयों में व्यक्तिगत, स्वतंत्र तथा आत्म-

पूण उपक्रम के लिए आवश्यक कमशक्ति का अभाव शोचनीय है।<sup>130</sup> कुछ एक अन्य राष्ट्रवादी नेताओं के अनुसार भारतीयों में निम्नलिखित अन्य गुणों की कमी थी पारस्परिक सहयोग तथा विश्वास की भावना, जाच-पडताल की प्रवृत्ति, विचारा और काय व्यापार में स्वतंत्रता, माहस तथा आत्मविश्वास, सकल्प, माहम तथा दृढ़ निश्चय,<sup>130</sup> अतिरिक्त विरोध का मुवाबला करने और उस पर विजय पान की तत्परता।<sup>131</sup> नेताओं की दृष्टि में इन गुणों के अभाव का कारण राष्ट्रीय चरित्र की परंपरागत दुबलता नहीं थी अपितु देश में प्रचलित सामाजिक प्रथाएँ, रीति रिवाज तथा परंपराएँ ही प्रमुख रूप से सामान्यतः भारत के आद्योगिक पिछड़ेपन के लिए ज़ोर विशेषतः भारतीयों में उद्यमी भावना के अभाव के लिए उत्तरदायी थी। भारत की जाति प्रथा एक जोर श्रम जोग पूँजी की गतिशीलता में बाधक थी और दूसरी ओर उच्चकुलीन प्रतिभाशाली नवयुवकों के तकनीक और उद्योग क्षेत्र में जाने के माँग में एक बाधा थी, इसके फलस्वरूप उच्च प्रतिभा उच्च कौशल से विच्छिन्न हो गई थी।<sup>132</sup> विदेश यात्रा पर प्रतिबन्धों ने भारतीय व्यापार के विदेशों में प्रसार को संकुचित कर दिया था।<sup>133</sup> भारतीय धार्मिक जादू एक ओर मतोप का प्रचार करते थे और दूसरी ओर धन के प्रति उत्कट प्रवृत्ति की निंदा करते थे। इसके फलस्वरूप भारतीयों की भौतिक सफलता की महत्वाकांक्षा दब गई थी तथा सामाजिक संपत्ति में वृद्धि का महत्वपूर्ण प्रोत्साहन ठंडा पड़ गया था।<sup>134</sup> भारत में पूरी तरह निराशावाद व्याप्त था। यहाँ यह धारणा प्रचलित थी कि मानव जीवन का दुर्भाग्य पूर्वनिर्दिष्ट है तथा मानव की दशा को बहतर बनाने के सभी प्रयत्नों की अमफलता निश्चित है।<sup>135</sup> भारतीय रीति रिवाजों तथा आचार-व्यवहारों के अनुसार भारतीयों का निवृत्ति अकमप्यता, विश्रान्ति, उदासीनता तथा निरुद्योगिता का जीवन ही ग्रहणनद की प्राप्ति के लिए आदर्श जीवन था।<sup>136</sup> भारतीय न प्राप्त होने वाली वस्तु की निरंतर खोज में विचारों व स्वप्नों की दुनिया में खोए रहते थे।<sup>137</sup> परंतु आधुनिक औद्योगिक सभ्यता पूर्णतः व्याहारिक थी।<sup>138</sup> अतः, भारतीयों की व्यक्तिगत आध्यात्मिक मोक्ष की धारणा व जातपात की भावना उस समय भारत में सामाजिक चेतना के अभाव का कारण बनी।<sup>139</sup>

जमिंदार रानाडे के नेतृत्व में भारतीय समाजसुधारकों ने भारत में आधुनिक उद्योग तथा व्यापार के स्वस्थ विकास के लिए भारतीय सामाजिक रूढ़ियों में मूलभूत परिवर्तन का प्रचार किया।<sup>140</sup> रानाडे का तथ्य था सामाजिक व्यवस्था के दूषित हान पर उत्तम जायिक पद्धति के प्रवर्तन की आशा नहीं की जा सकती।<sup>141</sup> अतः सुधारकों ने लागू की रीति रिवाजों तथा परंपराओं के अत्यंत शक्तिशाली प्रभाव से मुक्ति पाने तथा पश्चिम की नई प्रवृत्ति को अपनाएँ और नए दृष्टिकोण, पूँजीवादी प्रवृत्ति को मन में स्थान देने का अनुरोध किया।<sup>142</sup> उन्होंने निम्नलिखित आधुनिक धारणाओं का प्रासनीय और स्पष्टनीय घोषित किया प्रगति तथा विज्ञान, विचार और बल की स्वतंत्रता, परिवर्तन तथा साहसिक कार्यों में रुचि मन की आशावादिता तथा व्यावहारिकता जीवन स्तर में सुधार की इच्छा, आदि आदि।<sup>143</sup> भारतीय नेताओं में अपेक्षाकृत पुरातनपथी नेता कुछ एक सामाजिक सुधारों की आवश्यकता को तो अनुभव करते थे परंतु हिंदुओं के आचार-



चालू कर दिया।<sup>147</sup> रानाडे ने पूना में स्थापित 'काटन ऐंड सिल्क स्पिनिंग ऐंड वीविंग फैक्टरी', 'मैटल मैन्युफैक्चरिंग फैक्टरी', 'दि पूना मक्काइल बक', 'दि पूना डाइग कम्पनी', 'दी रिए पेपर मिल' आदि के प्रवर्तन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।<sup>148</sup> गाखते के अनुसार 'पिछले 20 वर्षों में पूना में उदित औद्योगिक और व्यापारिक संस्थानों में अधिकांश उनकी प्रेरणा, प्रासाहन, परामर्श तथा सहायता के लिए उनका आभारी है।'<sup>149</sup> भारत की कलाआ और उद्योगों की उत्थिति के लिए नवोत्पन्न उत्साह स सपन यत्नशील व्यक्तियों में वं०टी० तैलग और फीरोजशाह मेहता ने तो 1870 में बंबई में एक साबुन का कारखाना ही खोल दिया।<sup>150</sup> वास्तव में फीरोजशाह मेहता का भारत के मित उद्योग से घनिष्ठ संबंध था।<sup>151</sup> तिलक ने भी थोड़े समय के लिए ही सही, 1891 में अपने दो मित्रों की साझेदारी में निजाम के अधीनस्थ पदेस लातूर में रुई में दिनीला िकालने वाला कारखाना चालू करने के रूप में औद्योगिक क्षेत्र में जपन उत्साह का परिचय दिया।<sup>15</sup> डी०ई० वाचा बड़े पैमाने की फूलती-फलती मोरारजी गाकुलदास और शोलापुर मिलों के प्रबंधक अभिक्ता थे। वे बहुत वर्षों तक बंबई के मिलमालिक संघ की प्रबंध समिति के सदस्य रहे।<sup>153</sup> 19वीं शताब्दी के प्रमुख कांग्रेसी नेता आर०एन० मधोलकर वरार में आधुनिक उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने वाले में एक थे। 1861-82 में उन्होंने अपने कुछ मित्रों के सहयोग से वरार के प्रथम मिश्रित पूजा समुदाय वरार टेंटिंग कंपनी की स्थापना की तथा उसके सचिव के रूप में कार्य किया। बाद में 1885 में उन्होंने अपने मित्रों के सहयोग से वरार में प्रथम कपडा बुनने की मिल की स्थापना की। इसके अतिरिक्त एक तेल निकालने की मिल और रुई बिनने तथा सपीडन के अनेक कारखानों की स्थापना का पयाप्त श्रेय भी इन्हीं का प्राप्त है।<sup>154</sup> कांग्रेस के एक अग्र बड़े नेता मदनमोहन मालवीय ने 1881 में इलाहाबाद में 'दसी तिजारत कंपनी' की स्थापना में सहायता दी और बालातर में प्रयाग में चीनी मिल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।<sup>155</sup> विस्तृत व्यापारों से संबंधित लाला लाजपतराय एक अन्य प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने एक प्रारंभिक भारतीय बक पंजाब नेशनल बक के निर्माण की हैसियत से अनेक रुई मिलों और रुई प्रेसों की स्थापना में सहायता की। वे बड़ निदेशक मंडलों के सदस्य थे।<sup>156</sup> बंगाल के राष्ट्रवादी नेता औद्योगिक क्षेत्र में इतन सक्रिय नहीं थे जितने पश्चिमी और उत्तरी भारत के नेता थे। किंतु बहा भी ए० एम० बाग, दुर्गामोहनदास और भुवनमाहन दास जैसे अन्य दो महानुभाव व्यक्तियों के साथ मिल कर 1880 में 'बंगाल बकिंग निगम व्यावसायिक' संघ की स्थापना की।<sup>15</sup> इस अतिरिक्त सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ए०एम० बोस तथा नरेंद्रनाथ मेन ने बंगाल में अपने वाणिज्यपरक प्रयासों से बंगाल राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के अवतनिक सदस्य बनते हुए नाममात्र रूप से ही सही, अपने को उससे संबंधित रखा।<sup>158</sup>

पूजा के आंतरिक गांधना और साहसवर्ति का उपयोग करते हुए देश के उद्योगीकरण की अदम्य राष्ट्रीय आकांक्षा का एक रोचक उदाहरण है 'पंसा निधि'। रानीगज (बंगाल) के तारापत्र मुक्ती ने 1865 में इटियन प्रिंटर में इस पंसा निधि के उद्देश्य, निधन और मध्यस्थितीय लोगों की बचत का उपयोग तथा नए औद्योगिक प्रतिष्ठानों की वितीय

अनुदान को स्पष्ट किया है। इस योजना को कुछ तत्कालीन नेताओं का समर्थन भी मिला। 1873 में बंबई के जी० बी० जोशी ने 'जनता फंड निधि' चालू करने का प्रयत्न किया परन्तु वह केवल 150 रुपये उगाहने में ही सफल हो सके। 1899 में इस विचार से एक युवक अध्यापक ए० डी० बाले इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी गोदारी सत्यागपत्र दे दिया तथा 'पैसा निधि' के लिए धन संग्रह का काम प्रारंभ कर दिया। इस निधि में प्रत्येक व्यक्ति से प्रति वर्ष केवल एक पैसा देने की अपेक्षा की जाती थी और यह संचित निधि आधुनिक उद्योग को प्रतिष्ठित करने और उसे लोकप्रिय बनाने में प्रयुक्त होती थी। साहसिक षाय में बाले को तिलक तथा अन्य महाराष्ट्रीय नेताओं से प्रोत्साहन तथा समर्थन मिला। बाले के अनुराग और श्रम को शीघ्र ही सफलता मिली और 1908 में इस 'पैसा निधि' की सहायता से महाराष्ट्र के तिलगाना प्रदेश में शीशे का कारखाना (प्रशिक्षण केंद्र सहित) स्थापित किया गया।<sup>159</sup>

भारतीय नेताओं ने औद्योगिक संघ बनाए औद्योगिक सम्मेलनों का आयोजन किया तथा औद्योगिक प्रदर्शनियां लगाईं। इन सबका उद्देश्य था औद्योगिकता के सिद्धांत को आगे बढ़ाना, औद्योगिक और वाणिज्य संबंधी रुचि जागृत करना, उद्यम की भावना को उभारना, विश्वासपूर्ण तथा आशाजनक औद्योगिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, विरसित औद्योगिक तबनीक का जनता में प्रसार करना, विभिन्न उद्योगों के अयसर और अयत्नास के संबंध में उपयुक्त जानकारी देना, आदि।<sup>160</sup> इस दिशा में पथप्रदर्शन मार्ग साठे महोदय का है जो 1890 में बने पश्चिमी भारत के औद्योगिक संघ के तथा उसी वर्ष पूना में प्रथम बार आयोजित होने वाले औद्योगिक सम्मेलन के प्रधान संयोजक थे। इससे पूर्व व उस नगर में एक औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन भी कर चुके थे।<sup>161</sup> उन्नीसवीं शताब्दी गतिविधियों में जी० बी० जोशी तथा महाराष्ट्र के एम० बी० तामजोशी आदि अन्य नेताओं ने भी सहायता की। 1890 से आगे के कई वर्षों तक प्रतिवर्ष औद्योगिक सम्मेलन आयोजित होते रहे तथा "हान भारतीय औद्योगिक और आर्थिक समस्याओं पर विधि पूर्वक तथा क्रमानुसार विचारों की अभिव्यक्ति के रूप में इस दिशा में बहुत बड़ी सेवा की। वस्तुतः रानाडे तथा जोशी के भारतीय आर्थिक समस्याओं पर लिखे बहुत सारे सुप्रसिद्ध निबंध इन सम्मेलनों में पढ़ने के लिए लिखे गए परन्तु ही थे। पूना के अनुसरण में अक्टूबर 1891 में कलकत्ता में भी एक सम्मेलन हुआ।<sup>162</sup> परन्तु दुर्भाग्यवश यह सम्मेलन अपना विशेष प्रभाव नहीं छोड़ पाया। निश्चय ही कलकत्ता के औद्योगिक प्रदर्शनीया के आयोजन में अधिक सफलता मिली। इस दिशा में प्रथम साधारण प्रयास जे० गोधरी तथा अन्य लोगों द्वारा कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में 1890 में एक औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन था।<sup>163</sup> परन्तु यह प्रयास अनेक ही सिद्ध हुआ, परन्तु अधिवेशनों में यह परंपरा का रूप धारण न कर सका। 1900 में कांग्रेस ने अपने लाहौर के 16वें अधिवेशन में विधिवत इस मामले का उठाया और उसने औद्योगिक समस्याओं पर विचारों के लिए कम से कम आधा दिन लगाने का निर्णय किया। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम विधि की प्रगति में कांग्रेस के सभावित सहयोग के रूप और दिशाओं पर विचारों के लिए एक औद्योगिक समिति का गठन भी किया।<sup>164</sup> इस समिति के विचार



फलस्वरूप ही 1901 में कलकत्ता में कांग्रेस के अग के रूप में श्रीचोगिक प्रदर्शनी लगाई गई<sup>165</sup> और उसके उपरांत यह कांग्रेस अधिवेशन की एक अविभाज्य परंपरा बन गई।

भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं का यह भी मत था कि द्रुत उद्योगीकरण के भारतीय प्रत्यक्षों के मांग में एक महत्वपूर्ण बाधा सरकार की उन्मुक्त व्यापार की नीति थी। यह नीति दश के प्रारंभिक तथा अविक्सित उद्योगों का, पश्चिम के ऊंचे स्तर पर सुनियोजित तथा सुविकसित उद्योगों के साथ, अपरिपक्व और असमान होने के कारण अनुचित प्रतियोगिता के लिए बाध्य करती थी। भारतीयों के इस दृष्टिकोण का तथा भारत सरकार की उन्मुक्त व्यापार नीति को लागू करने के विभिन्न उपायों के विरुद्ध उनके सघन का इस पुस्तक के अगले अध्यायों में विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

## संदर्भ

- 1 भारतीय हस्तकलाओं के विनाश का विवरण भारतीय अर्थशास्त्र की अनेक पुस्तकों में उपलब्ध है सरल निर्देश के लिए देखिए डी० आर० गाडगिल 'दि इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन ऑफ इंडिया इन रीसेंट टाइम्स (कलकत्ता 1942 में चतुर्थ संस्करण का पुनर्मुद्रण) अध्याय III और XII आर० चौधरी 'दि इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज' (कलकत्ता 1939) अध्याय I तथा डॉ० डी० बसु 'दि इंडियन इंडस्ट्रीज (कलकत्ता 1935)
- 2 बरा अनस्टे 'दि इकॉनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया (सदन तृतीय संस्करण), पृ० 5
- 3 गाडगिल पूर्वोद्धृत, अध्याय III और XII पृ० XXII अनस्टे पूर्वोद्धृत, पृ० 5 207
- 4 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने घोषित किया कि भारत का शीघ्र दरिद्रता का प्रमुख कारण एक था स्वदेशी शिल्प और उद्योग का ह्रास (प्रस्ताव III) जाया का 1885 में कथन था तेजी से बढ़ता हुआ विनाश जिस हम अपने विभिन्न हस्तशिल्प उद्योगों का सहसा पूर्णतया नष्ट कर सकते हैं वस्तुओं की शोचनीय स्थिति का मूल कारण है (पूर्वोद्धृत पृ० 738) 1896 की कांग्रेस को संबोधित करते हुए आर० एन० मधोलकर ने सकेत किया हमारी घनपोर और व्यापक दरिद्रता हमारे प्राचीन बना शिल्पा तथा उद्योगों के ह्रास, लगभग पूर्ण विनाश का ही परिणाम है (रिप० आई०एन० सी० 1896 पृ० 157) भोलानाथ चंद्र ने 1876 में लिखा था नवीन प्रचलित शिल्पा और उद्योगों में किए गए सुधारों की अपेक्षा पुराने शिल्पा उद्योगों पर किए गए प्रहार अधिक विचारणीय हैं वस्तुतः यह तो हमारे राष्ट्र के लिए बड़ा गंवाकर हुआ जाने के समान एक क्षुद्र सात्वना है (एम० एम० खंड V, पृ० 5) उस युग में राष्ट्रीय भाषण और लेखों में इन प्रकार के असंख्य निर्देश उपलब्ध हैं उदाहरणार्थ देखिए, एजुकेशन गजट 2 मई (आर० एन० पी० बग 10 मई 1883) जोशी पूर्वोद्धृत पृ० 63<sup>7</sup> 753 778-79 802-4 चाच दत्त 9 फरवरी (आर० एन० पी० बग 14 फरवरी 1885) वाचा रिप० आई०एन० सी० 1886 पृ० 64 बन्वान सजीवनी 29 नवंबर (वही 10 दिस० 1887) गंध कादिर बरक रिप० आई० एन० सी० 1887 पृ० 142 पत्राची अक्टूबर 21 अगस्त (आर० एन० पी० 31 अगस्त 1889) खरभनेल 13 अक्टूबर (वही 19 अक्टूबर 1889) राम पावटी, पृ० 85 निरामूलमुक्त 16 जनवरी (आर० एन० पी० एन० 20 जनवरी 1897) भारत जीवन 20 नवंबर (वही 1 दिसंबर 1897) नदा पूर्वोक्त स्थल, पृ० 122 दत्त सा०

- पी० ए, प० 489 वनात वित्तामणि, 15 मार्च (आर० एन० पी० एम०, 15 मार्च 1900), हिंदुस्तान, 13 अप्रैल (आर० एन० पी० एन, 17 अप्रैल 1900) स्वदशमित्र, 28 अप्रैल (आर० एन० पी० एम० 20 अप्रैल 1900) केसरी, 8 मई (आर० एन० पी० वव 12 मई 1900) मराठा 11 नवंबर 1900 मद्रास स्टैंडर्ड, 21 जनवरी (आर० एन० पी० एम०, 25 जनवरी 1902), आई० एन० सी० 1902 और 1904 के प्रस्ताव III और III एन० के० रामास्वामी अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1901, पृ० 137 एम० के० पटेल रिप० आई० एन० सी०—1902 पृ० 77 जी० सी० अय्यर ई० ए, पृ० 218 249 गोखले स्पीचेज पृ० 52 दत्त ई० एच० II पृ० 345 और सी० पी० ए०, पृ० 469 बंगाला 12 मार्च 1902
- 5 उदाहरण के रूप में देखिए ए० बी० पी०, 5 अगस्त 1872 भोलानाथ चंद्र एम० एम० वड V (1876) पृ० 5 जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 227 780 गोखले स्पीचज, पृ० 52 आर० सी० दत्त ने अपनी दो छाया वाली 'इन्डियाना मिक् हिस्टरी आफ इंडिया पुस्तक' में तथा अनक सम बालीन पत्रों में प्रकाशित अपने लेखों में इन प्रक्रिया का बड़ा गहरा और सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया है पी० सी० राय ने भी अपनी पुस्तक 'दि पावर्टी प्राब्लम आफ इंडिया' में इस प्रक्रिया का विस्तृत विवेचन किया है
- 6 दत्त स्पीचेज, II पृ० 106 नदी पूर्वोक्त स्थल, 122 एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए० पृ० 691 2 जी० सी० अय्यर ई० ए अग्रिम XVI और XVII
- 7 दत्त ई० एच० I, पृ० 256
- 8 भारत से इंग्लैंड को कपास के गट्टों के निर्यात-आकड़ा के लिए देखिए दत्त ई० एच० I पृ० 295, ई० एच० II पृ० 109 भारत में कपड़ों के आयात आकड़ा के लिए देखिए दत्त ई० एच० I, पृ० 257, ई० एच० II, पृ० 108 तथा देखिए, एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए० पृ० 692 3
- 9 रानाडे एसेज पृ० 185
- 10 दत्त इंग्लैंड ऐंड इंडिया' पृ० 128
- 11 दत्त ई० एच० I पृ० VII VIII और देखिए के० सी० ए० चौधरी रिप० आई० एन० सी० 1886 पृ० 64 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 785 रानाडे एसेज, पृ० 185 राय पावर्टी पृ० 93 मघोलकर रिप० आई० एन० सी०—1898 पृ० 121 दत्त ई० एच० I पृ० VIII गोखले स्पाचज पृ० 52
- 12 रानाडे एसेज पृ० 27 जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 784-5 दत्त ई० एच० II, पृ० 103 345 स्पीचेज II, पृ० 81 गोखले स्पीचेज पृ० 52
- 13 आर० एन० मघोलकर रिप० आई० एन० सी०—1890 पृ० 47 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 785 835 दत्त 'इंग्लैंड ऐंड इंडिया' पृ० 129 ई० एच० II पृ० 345 बंगाली 12 मार्च 1902
- 14 रानाडे एसेज पृ० 191, वाचा सी० पी० ए० पृ० 624 दत्त ई० एच० I पृ० VIII ई० एच० II पृ० VIII एम० के० पटेल रिप० आई० एन० सी० 1902, पृ० 77 दत्त आदि के समान रानाडे ने भी यह अभिस्वाकार नहीं किया कि भारत प्राचीनतम काल से पूर्ण रूप से तथा एकात्मत कृषि प्रधान देश रहा है उन्होंने यह अवश्य कहा कि ब्रिटिश राज्य ने स्थिति की गभीरता को और अधिक भयंकर बनाया है—(एसेज पृ० 183) साथ ही देखिए ट्रिम्बून (लाहौर) 8 जुलाई (आई० एम० पी० ओ० आई०, 2 अगस्त, 1891)
- 15 दत्त ने समझना की कि 80 प्रतिशत भारतीय जनता कृषि पर निर्भर है (ई० एच० I पृ० IX)

## 70 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदभव और विकास

- जोशी का अनुमान था कि लगभग 86 प्रतिशत औद्योगिक जनता भूमि से संबंधित थी (पूर्वोद्धत, पृ० 784) और देखिए वाचा सी० पी० ए०, पृ० 624 एम० के० पटेल रिप० आई० एन० सी० 1902, पृ० 77
- 16 रानाडे एसेज, पृ० 26, 183 जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 360 मधोलकर 'इंडियन पालिटिक्स', पृ० 44, बेमरी, 11 नवंबर (आर० एन० पी० बग, 15 नवंबर 1902)
- 17 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 849 50, 868, मधोलकर 'इंडियन पालिटिक्स', पृ० 45
- 18 दत्त स्पीचेज I पृ० 24 तथा देखिए मराठा, 19 जून, 1881, 12 फरवरी 1882. सोमप्रकाश, 6 फरवरी (आर० एन० पी० बग, 11 फरवरी 1882) ए०वी०पी०, 22 मई 1884 भारत मिहिर 17 जून (आर० एन० पी० बग 28 जून 1884) स्वदेश मित्तन, 5 मार्च (आर० एन० पी० एन० मार्च 1885) रानाडे एसेज पृ० 27 राय पावर्नी, पृ० 97 बेमरी 11 नवंबर (आर० एन० पी० बग 17 नवंबर 1902) एम० ए० बनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 69
- 19 1880 के अनाल आयोग का प्रतिवेदन भाग II बडिया I इस अवतरण की अर्थों के अतिरिक्त रानाडे ने उद्धृत किया था, एसेज, पृ० 121 जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 642 मधोलकर 'इंडियन पालिटिक्स' पृ० 44 रिप० आई० एन० सी०—1899, पृ० 88 9
- 20 बी० सी० पाल रिप० आई० एन० सी०—1888 पृ० 159 मधोलकर 'इंडियन पालिटिक्स', पृ० 47
- 21 रानाडे एसेज पृ० 66 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 871 874 ए० बी० पी० 2 अगस्त 1901 मधोलकर 'इंडियन पालिटिक्स' पृ० 45 जी० सी० अय्यर, ई ए पृ० 218
- 22 मराठा 23 जनवरी 1881 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 700-2 804 840-52
- 23 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 702 इस विषय में उसके प्रश्न की 1880 के अकाल आयोग के प्रतिवेदन में पृ० 853 पर देखिए
- 24 वही पृ० 350 638
- 25 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 658 तथा जी० सी० अय्यर ई ए अध्याय XII
- 26 रानाडे एसेज पृ० 27
- 27 रानाडे एसेज पृ० 90 तथा वही, पृ० 183 185 हिंदू—16 जनवरी 1883 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 675 76 गोपले स्पीचेज पृ० 52 'इंडियन पीपल', 27 फरवरी 1903 दत्त स्पीचेज II, पृ० 42 3 ई० एच० पृ० VIII, 276 ई० एच० II पृ० 114 129 518 जी० एन० अय्यर ई ए पृ० 116-7 123 5 1873 में श्रीलालाया चंद्र ने राजनीतिक दायता के अतिरिक्त औद्योगिक शक्त में भी दासता के गठ में घबरेलने वाली नीति की निंदा की (एम० एम० खड II पृ० 110)
- 28 एम० एम० बनर्जी सी० पी० ए०, पृ० 694
- 29 दत्त ई० एच० I पृ० VIII
- 30 श्रीलालाया चंद्र एम० एम० खड V पृ० 13 एम० एन० बनर्जी रिप० आई० एन० सी०—1896 पृ० 136 तथा सी० पी० ए० पृ० 691 694 वी० मेहता स्पीचेज पृ० 750 दत्त ई० एच० I पृ० VIII और ई० एच० II पृ० VIII सी० आई० चितामणि 'द्वानामिब' आलेखन आर्य ब्रिटिश हून इन इंडिया, एच० आर० जनवरी 1902, पृ० 32 जी० एन० अय्यर, ई ए, पृ० 125 240
- 31 दत्त ई० एच० I पृ० VIII 261 ई० एच० II पृ० VIII IX पिछली एक डेढ़ शताब्दी में ब्रिटिश शासकों की वाणिज्य नाविक का आधार भारतीय उत्पादकों के दिवों की अनेक ब्रिटिश

- उत्पादको के हित की रक्षा ही रहा है' तथा वही प० 120
- 32 भालानाथ चद्र, एम०एम० खड V, प० 14 15 हिंदू 16 जून 1883 समय 2 दिसंबर (आर० एन० पी० बग 10 दिसंबर 1887) दत्त, ई० एच० II प० 518 स्पीचेज II, प० 108, 113 जी० एस० अय्यर ई ए, प० 125 ऊपर 27वीं पादटिप्पणी में उद्धृत नेतागण
- 33 भारत में अपने शासनकाल में प्रारंभिक दिन से ही इंग्लंड के उत्पादको और शिल्पकर्मियों के लाभ के लिए इस देश का कच्चे माल के उत्पादन की बस्ता के रूप में बदलना ब्रिटिश शासको की एक निश्चित नीति रही है (एम० एन० बनर्जी सी० पी० ए०, प० 691) तथा देखिए, भालानाथ चद्र, एम०एम० खड III प० 99 100 ऊपर 27वीं पादटिप्पणी में उद्धृत नेतागण जी० एस० अय्यर, रिप० आई० एन० सा—1902 प० 72 दत्त ई०एच० I प० VIII तथा ई०एच० II प० 129 केसरी 11 अप्रैल (आर० एन० पी० बग 15 अप्रैल 1905) फलतः किसी समय ब्रिटिश सरकार की भारतीय कृषि के विकास पर अत्यधिक बल देने की प्रवृत्ति की ऊपर लिखे नेताओं उदाहरणार्थ केसरी भोलानाथ चद्र तथा जी० एस० अय्यर द्वारा आलाचना की गई थी
- 34 दत्त ई० एच० II प० 518 स्पीचेज II प० 42.
- 35 वाचा सी० पी० ए० प० 622 एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए० प० 694 ज्ञान फरवरी 30 1903 प० 207 स्वदेश मित्र 13 अगस्त (आर० एन० पी० एम० 15 अगस्त 1903), हितकारी, अक्टूबर (आर० एन० पी० बग नवंबर 1903 मधोलकर, रिप० आई० एन० सी० 1904, प० 102
- 36 मिल हिस्टरी आफ ब्रिटिश इंडिया' विल्सन काटोन्यूएशन पुस्तक I अध्याय VII मधोलकर की इन्डियन पालिटिक्स में उद्धृत प० 43 पी० मेहता स्पीचेज प० 750 दत्त, ई० एच० I प० 260-3 एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए० प० 692
- 37 दत्त ई० एच० I प० 45 जी० एस० अय्यर, ई ए प० 250 चितामणि एच० आर० जनवरी 1902 प० 32.
- 38 वाचा सी० पी० ए० प० 623 दत्त ई० एच० I प० 257 ई० एच० II प० VIII स्पीचेज II प० 42 चितामणि एच० आर० जनवरी 1902 प० 32
- 39 भालानाथ चद्र एम०एम० खड V प० 42 वाचा, रिप० आई० एन० सी० 1894, प० 32 मधोलकर 'इन्डियन पालिटिक्स, प० 44 वाचा सी० पी० ए० प० 625 एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए० प० 692 3 696 जी० सी० अय्यर ई ए प० 242 चितामणि एच० आर० जनवरी 1902 प० 32 एल०एम० घोष सी० पी० ए०, प० 754 दत्त ई०एच० I प० 7 इनसे बढकर आर० सी० दत्त ने अपनी पुस्तको ई० एच० I अध्याय III XIV XV में तथा ई० एच० II अध्याय VII VIII IX में भेदमूलक चुगी दरों के तरीके की ओर उसका विनाशकारी प्रभाव का खोज की 1812 32 तक भारत के निर्यातका के भारत से इंग्लंड को निर्यात पर लगाए गए करों के सारणीबद्ध अध्ययन के लिए देखिए, दत्त स्पीचेज II प० 117 1831 में तालिका रूप में 117 प्रतिष्ठित भारतीयों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका परम श्रेष्ठ महाराजा धिराज की प्रिन्सी कामिल को एक अपील भेजी गई थी जिसमें यह याचना की गई थी कि बंगाल के भूमी और रेशमी कपड़े के इंग्लंड को निःशुल्क अथवा बंगाल में खपने वाले ब्रिटिश वस्त्रों पर वमूल किए जाने वाले कपड़े की दर पर निर्यात की अनुमति प्रदान की जाए (सी० डी० बनू की पूर्वोद्धृत पुस्तक प० 32 3 में उद्धृत)
- 40 दत्त स्पीचेज, II, प० 80 तथा ई० एच० II प० 123 चितामणि एच० आर०, जनवरी 1902 प० 32.

## 72 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास

- 41 दत्त ई० एच० I प० 303-04
- 42 दत्त ई० एच० I प० VIII 264-7 हितवादा, 30 अक्टूबर (आर० एन० पी० वग 7 नवंबर 1903)
- 43 कादिर बग्श रिप० आई० एन० सी०—1887 पृ० 142 जोशी, पूर्वोद्धत प० 683 785 6 राय पावर्टी प० 34 मधोलकर इंडियन पालिटिक्स प० 44 दत्त ई० एच० I प० VIII एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए०, प० 694 एम० के० पटल रिप० जाइ० एन० सी० 1902 प० 77 मधोलकर रिप० आई० एन० सी० 1904 प० 103 यहाँ तक कि दत्त सहमत थे भारत के हस्तबला उद्योग इंग्लंड के भाप और मशीन उद्योग का मुकाबला नहीं कर सकते (दत्त इंग्लंड ऐंड इंडिया प० 81)
- 44 रागाडे एसेज प० 183 तथा प० 100
- 45 डान फरवरी 1903 प० 207 तथा देखिए वाचा सी० पी० ए० प० 623 जोशी पूर्वोद्धत प० 680 683-4 एस० एन० बनर्जी सा० पी० ए० प० 694
- 46 देखिए नीचे अध्याय 6 तथा 14 और ऊपर 39 की पाण्टिप्पणी
- 47 देखिए नीचे अध्याय 5
- 48 हितवादी 30 अक्टूबर (आर० एन० पी० वग 7 नवंबर 1903) जी० एस० अय्यर के अगुआर ब्रिटिश साहित्यिकी न भारत की निधि को खूब लूटा और हम प्रकार अगुआर भारतीय धन के अत्यधिक समग्र के फलस्वरूप एक पूजीपति वग अस्तित्व में आ गया इस धन के कारण इस वग की साख बढ़ गई तथा शक्ति उद्योग और साहस में गतिशीलता आ गई 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भारत और आयरलैंड की लूट पर ब्रिटिश समृद्धि की आधारशिला मनी प्रकार से रखी जा चुकी थी (ई० ए० प० 243) तथा देखिए ए० बी० पी० 27 अक्टूबर 1886 एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए० प० 695 बनर्जी न अपने कांग्रेस के भाषण में द्रुप आदम की पुस्तक 'ला आफ सिविलाइजेशन ऐंड रिच' से एक उद्धरण उद्धृत किया जिसे 19वीं शताब्दी में परवर्ती भारत पर बोलने और लिखने वाला का नियमित सहारा बनना था
- 49 दि डान फरवरी 1903 प० 207
- 49-ए इसमें अपवाद रूप में पी० ए० चारलू आई० सा० पी० 1899 खंड XXXVII पृ० 177 8
- 50 भोलानाथ चंद्र एम० एम० खंड 5 प० 2 जोशी पूर्वोद्धत प० 738 753 मराठा 24 जनवरी 1886 श्रु प्रकाश 25 जनवरी 1886 हिन्दी बगवासी 30 मार्च (आर० एन० पी० वग 11 अप्रैल 1891) राय पावर्टी प० 98 145 मधोलकर रिप० आई० एन० सी०—1898 प० 121 ए० एन० बोस सी० पी० ए० प० 427 एम० एन० बनर्जी सी० पी० ए०, प० 691 707 जी० सी० अय्यर 9 ई ए प० 171 दत्त स्पीचज प 24 163 ई० एच० II प० 519 528 612
- 51 आई० एन० सी 1896 का प्रस्ताव 12 और देखिए 1888 का प्रस्ताव 10 1897 का प्रस्ताव 9 1899 का प्रस्ताव 13 1902 का प्रस्ताव III
- 52 रानाड एसेज प० 193 1898 में इकट्ठे कांग्रेस प्रतिनिधियों का आर० एन० मधोलकर न सकते किया वाप्य शक्ति द्वारा सञ्चालित करणों के साथ हथकरघे का मुकाबला इस प्रकार का है जिस प्रकार एक भाष-इजन के साथ दोड़ में बसगाड़ी का मुकाबला (रिप० आई० एन० सी० 1898 पृ० 121) और देखिए जोशी पूर्वोद्धत पृ० 785 974 वाचा सी० पी० ए० प 622 जी० एस० अय्यर इंडियन पालिटिक्स पृ० 193



एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र पर अपनी स्थापित श्रेष्ठता के आधार पर ही की जाती है —दि एक्मीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इंडिया, जे० पी० एस० एस० अप्रिल 1893 (खंड स० 4) प० 6 तथा जोशी पूर्वोद्धत प० 816, राय पावर्टी प० 43, 111, जी० एस० अय्यर रिप० आई० एन० सी०—1901 प० 124

- 61 नेटिव ओपीनियन 25 मई 1884 रानाडे एमेज प० 19 पी० ए० चारलू आई० सी० पी० 1901 खंड XI प० 283 जी० एस० अय्यर ई ए प० 131
- 62 भोलानाथ चंद्र एम० एम खंड 5 प० 2 नोरीजी एसेज, प० 103 ए० बी० पी० 16 जुलाई 1704 अखबारे आम 8 जनवरी, 1 माच (आर० एन० पी० एन०, 11 जनवरी 8 माच 1879) ब्रह्मो पत्रिक ओपीनियन 24 जून 1880 बाबे समाचार 19 अगस्त (आर० एन० पी० व० 20 अगस्त 1881) मराठा 23 जनवरी 1881 1 जनवरी 12 फरवरी 1882, 24 जनवरी 1886 स्वदेशमित्रन, 17 दिसंबर (आर० एन० पी० एम० 31 दिस० 1887) बन्वान सजीवनी 29 नवंबर (आर० एन० पी० बग 10 दिसंबर 1887) ए० एस० मुत्सिपर रिप० आई० एन० सी० 1886 प० 65 जोशी पूर्वोद्धत प० 751, 804-05 रानाड एसेज, प० 121 केरल पत्रिका, 4 नवंबर (आर० एन० पी० एम० 30 नवंबर 1893) एक्मीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इंडिया, पूर्वोक्त स्थल प० 13 अखबारे आम, 30 जुलाई (आर० एन० पी०, प० 28 अगस्त 1897) भारत जीवन 1 अगस्त (आर० एन० पी० एन० 10 अगस्त 1898 आई० एन० सी० 1899 का प्रस्ताव XIII तथा 1902 का प्रस्ताव III सियालकोट पेपर 1 माच (आर० एन० पी० पी० 10 माच 1900) मघोलकर रिप० आई० एन० सी०—1899 प० 89 बेसरी 23 जुलाई (आर० एन० पी० व० 28 जुलाई 1900) एन० सी० चदावरकर सी० पी० ए०, प० 524 पी० ए० चारलू एल० सी० पी० 1901 खंड XI प० 283 वाचा सी० पी० ए०, प० 624 जी० एस० अय्यर रिप० आई० ए सी० 1901 प० 124 5 और ई ए प० 65 इंडियन नेशन 23 दिस० 1901 (बी० अं आई०—8 फरवरी 1902) पी० मेहता स्पीचेज प० 746 एम०के० पटेल रिप० आई० ए सी० 1902 प० 79 तथा रिप० आई० एन० सी०—1904 प० 115 दत्त ई० एच० प० XIII XIV
- 63 रानाडे एसेज प 207, जोशी पूर्वोद्धत प० 868
- 64 मराठा 23 जनवरी मितंबर 1881 नेटिव ओपीनियन, 25 मई 1884 जोशी पूर्वोद्धत प० 368 751 804 05 851 3 रानाडे एसेज प० 113 207 बी० एन० सी० रिप आई० एन० सी० 1892 प० 95 राय पावर्टी प० 98 जी० एस० अय्यर साड कज रिजल्ट्युमान आफ लड रवयू ऐंड फमिन (साड कजन का भूराजस्व तथा अकाल पर प्रस्ताव एच० आर० फरवरी 1902 प० 148-9 एम० के पटेल रिप० आई० एन० सी०—190 प० 114 5 एथीवल्चर ऐंड इंडस्ट्री का नीचे अध्याय 10 का संवर्धित भाग
- 65 मराठा 19 जून 1881 12 फरवरी 1882 स्वदेशमित्रन 5 मार्च (आर० एन० पी० एम० माच 1885) सहृषर 6 मई (आर० एन० पी० बग 16 मई 1885) रानाडे एसेज प० 25-6 100 जोशी पूर्वोद्धत प० 642 667 दत्त स्पीचज I, प० 24-5 बेसरी 11 न (आर० एन० पी० व० 15 नवंबर 1902)
- 66 ऐन्कुरेशन गजट 2 मई (आर० एन० पी० बग 10 मई 1883) बगाली 26 अप्रिल 1884 मराठा 24 जून 1886 जोशी पूर्वोद्धत प० 645-8 666-7 मघोलकर रिप० आई० एन० सी० 1892, प० 121 जी० एम० अय्यर ई ए, प० 85. एच० एन० धनवी सी० पी० ए०

- पृ० 637 सियालकोट पेपर, 24 अगस्त (आर० एन० पी० पी०, 6 सितंबर 1902) और देखिए नीचे अध्याय 4 और 13
- 67 रानाडे एसेज, प० 19 जी० एस० अय्यर ई ए प० 131
- 68 जोशी पूर्वोद्धत प० 829 के० टी० तलंग जर्नल आफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, खंड XI, प० 9 भाग I रानाडे एसेज प० 19
- 69 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 616 और भोलानाथ चंद्र एम० एम० खंड 5 पृ० 2 के० टी० तलंग श्री ट्रेड ऐंड प्रोटेक्शन फॉर्म एन इंडियन प्वाइंट आफ व्यू, (बंबई 1877) पृ० 513
- 70 रानाडे एसेज प० 19 दि ऐक्सिजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इंडिया पूर्वोक्त स्थल, पृ० 223-जी० एस० अय्यर ई ए, प० 266
- 71 रानाडे एसेज प० 96
- 72 बंगाली 18 जनवरी 1902 और देखिए, ए० बी० पी० 16 जुलाई 1874 जमीयत उलुम 28 जून (आर० एन० पी० एन० 7 जुलाई 1897) बंगाली ती और आगे बढ़ा और 1900 में उसने यह विचार प्रकट किया, 'देशभक्ति का गुण व्यापार की भावना से जुड़ा हुआ है' (6 जुलाई)
- 73 दि इंडियन इकॉनॉमिक प्रालम, 'दि डान, माघ जून 1900
- 74 वही अप्रैल 1900 पृ० 265-6
- 75 'दि ऐक्सिजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इंडिया', पूर्वोक्त स्थल, पृ० 8
- 76 वही, पूर्वोद्धत, पृ० 8-9 और देखिए जी० एस० अय्यर ई ए पृ० 209
- 77 'दि ऐक्सिजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इंडिया पूर्वोक्त स्थल पृ० 112 जी० एस० अय्यर ई० ए० पृ० 300 राय पावर्टी पृ० 110-1
- 78 भारत में आधुनिक उद्योग के विकास का प्रस्तुत सक्षिप्त विवरण श्री० डी० आर० गाडगिल के ग्रन्थ, 'दि इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन आफ इंडिया', के 4,6 तथा 8 अध्यायों पर आधारित है
- 79 साय ही देखिए, दत्त ई० एच० II, पृ० 520-1
- 80 इसी अध्याय-पाठ्यपुष्पी स० 4 देखिए और गाडगिल पूर्वोद्धत, प० 185
- 81 इस दृष्टिकोण के प्रचलित होने के साक्ष्य के रूप में देखिए, 1916-18 के इंडियन इंडस्ट्रियल कमिशन का प्रतिवेदन, प० 2 तथा अनस्ट पूर्वोद्धत प० 210 अपने को भारत में औद्योगिक प्रवृत्तियों का प्रमुख संचालक मानने वाले साहू बज्रन तन ने 1903 में यह मत प्रकट किया भारत की बहुसंख्यक जनता कृषि काम में ही प्रशिक्षित है व्यावहारिक (शादीरक) दृष्टि से भी यह कृषि काम के ही योग्य है और वह कृषि काम का छाड़कर अन्य किसी उद्योग में प्रवृत्त नहीं होगी (स्पीचिंग खंड III पृ० 133) भारतीयों द्वारा इस दृष्टिकोण को नकारने के सबूत में देखिए, भोलानाथ चंद्र एम० एम०, खंड II, पृ० 557 के० टी० तलंग श्री इंडियन ऐंड प्रोटेक्शन पृ० 34-5 जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 642 रानाडे एसेज, प० 24-5 जी० एस० अय्यर ई ए, पृ० 258-274
- 82 भोलानाथ चंद्र एम० एम० खंड II, प० 560-617 रानाडे एसेज पृ० 24, 159-60 राय पावर्टी प० 82-4 जी० एस० अय्यर ई ए पृ० 258 275 अध्याय 16 17 18 दत्त स्पीचिंग II पृ० 79 106 एम० एन० बैनर्जी ने 1903 में अय्यर एन से कांफरेंस को संबोधित करने हुए एक बहुत ही उपयुक्त तर्क का उल्लेख किया यूरोपीय सभ्यता हमारे बीच आने से नहीं प्रत्युत उत्पत्ति सामग्री की उत्कृष्टता से ही प्रभावित और आकर्षित हुए थे (सी० पा० ए०, पृ० 691)



## 76 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदभव और विकास

- 83 भोलानाथ चद्र एम० एम०, छठ II पृ० 57 रानाडे एसेज प० 24 राय पावर्टी पृ० 109 जी० एस० अय्यर ई ए पृ० 145
- 84 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 668 रानाडे एसेज पृ० 24 राय पावर्टी पृ० 109 जी० एस० अय्यर ई ए पृ० 147 149
- 85 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 668, 742 रानाडे एसेज पृ० 120 जी० एस० अय्यर ई ए पृ० 146-7
- 86 नौरोजी एसेज पृ० 105 ए० बी० पी० 2 अप्रैल 1881 मराठा 9 अगस्त 1885 जागी पूर्वोद्धत पृ० 666 741 743 रानाडे एसेज, पृ० 22 91 2 गोखले बेलबी कमीशन छठ III प्रश्न 18140 वाचा सी० पी० ए० पृ० 625 जी० सी० अय्यर बतबी कमीशन छठ III प्रश्न 18675 18690 ई ए पृ० 145 लाजपत राय जि म न इन हिज बड (सा० लाजपत राय के भाषणों और सखों का संग्रह) (मद्रास 1907) पृ० 39-41 अपने साधना से ही बड पैमाने के उद्योग खडा कर सकन में समय धनो वित्त विनियोजका की अनुपस्थिति पर बल गिया गया —बंगाली 28 जनवरी 1882 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 742
- 87 रानाडे एसेज, पृ० 92
- 88 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 666 741 2 745 803 रानाडे एसेज पृ० 22 91
- 89 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 793 रानाडे एसेज पृ० 22
- 90 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 761 794-6 803
- 91 रानाडे एसेज पृ० 23 ओर नीचे देखिए
- 92 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 795 रानाडे एसेज पृ० 91 तथा वित्त पर अध्याय 11
- 93 देखिए दि डून अध्याय 13
- 94 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 747 796 रानाडे एसेज पृ० 22 41 जी० एम० अय्यर ई ए पृ० 146
- 95 जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 740 और देखिए रानाडे एसेज पृ० 22 जी० एस० अय्यर ई ए पृ० 150 लाजपतराय पूर्वोद्धत, पृ० 142
- 96 जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 797 8 रानाडे एसेज पृ० 40 42
- 97 जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 746 रानाडे एसेज 22 91
- 98 देखिए नीचे अध्याय 13 डून पर
- 99 मराठा 13 फरवरी 1881 तथा जी० एस० अय्यर रिप० आई० एन० सा०—1901 पृ० 127
- 100 ए० बी० पी० 2 अप्रैल 1881 सबाद प्रभाकर 9 मई (आर० एन पी० बग 17 मई 1883) मराठा, 9 अगस्त 1883 राय पावर्टी पृ० 127 7 जमीयुल उनुम, 28 जून (आर० एन० पी० एन० 7 जुलाई 1807) 26 मई 1903 में चारुनित्त ने लिखा राजा और जमानार लोग कमर कम से और मुद्द में सडने का उद्यत हो जाए इन दिनों धन की सहायता से दश व मनाघरों का परिरक्षण तथा दश की प्रगति का सरक्षण ही सत्रियों का कतम्य कम है इन दिनों उन्नत विचारवाला टाटा राजा तथा सनिक का एक उच्छ्रुत उगाहरण है (आर० एन पी० बग 6 जून 1901)
- 101 रानाडे एसेज पृ० 188
- 102 जी० एम० अय्यर ई ए पृ० 15 तथा देखिए, वही पृ० 150-4 जागी पूर्वोद्धत पृ० 797-8

रानाड एसेज प० 43 49 118 जी० एस०, अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1901 प० 127

- 103 ब्राह्म पब्लिक आपीनियन, 24 जून 1880 बंगाली 28 जनवरी 1882 बड़वान सजीवनी, 27 मई (आर० एन० पी० बग 7 जून 1881) मराठा 9 अगस्त 1885, हिंदू 29 दिसंबर 1883 जोशी पूर्वोद्धत, प० 800, 806 रानाडे एसेज प० 193 एजूकेशन गजट, 13 नवंबर (आर० एन० पी० बग 21 नवंबर 1891) भारत जीवन 10 जुलाई (आर० एन० पी० 19 जुलाई 1891) मुरलीधर रिप० आई० एन० सी० 1901 प० 174 लाजपत राय पूर्वोद्धत, प० 39, 41
- 104 कलकत्ता म 1883 म नेशनल काफेस का प्रथम प्रस्ताव बंगाली 5 जनवरी 1884 मराठा 20 जनवरी 1884 9 अगस्त 1885, 19 सितंबर 1886 पी० मेहता स्पीचेज प० 747 8 भारत-मिल 5 जून, नवविभाकर, 28 जुलाई अकुलात बक्ता, 5 सितंबर गुरमि तथा सहचर, 30 सित० (आर० एन० पी० बग, 14 जून 2 अगस्त 12 सित० 3 अक्टूबर 1884 क्रमश) हिंदू 21 जनवरी 1884 3 जुलाई 1885, 10 अगस्त 1886 21 अप्रैल 1902 हनु प्रकाश 23 जन० (वी० ओ० आई०, फरवरी 1886) बंगाली 17 अप्रैल और 31 जुलाई 1886 इंडियन नेशन 2 अगस्त ट्रिब्यून, 14 अगस्त रिहार हेराल्ड 17 अगस्त (वी० ओ० आई० अगस्त 1886) 'दाना प्रकाश', 7 मार्च (आर० एन० पी० बग 11 सित० 1886) भारत मिहिर 8 अप्रैल (आर० एन० पी० बग 17 अप्रैल 1886 सजीवनी 4 सित०, भारतवासी 4 सित०, नवविभाकर, साधारणी 6 सित० (आर० एन० पी० बग 11 सित० 1886), स्वदेशमित्र 8 फरवरी (आर० एन० पी० एम० फरवरी 1886), एम० आर० एन० मधोलकर रिप० आई० एन० सी० 1887, प० 137 8 एम० एन० बनर्जी स्पीचेज ऐंड राइटिंज (मद्रास तिथिरहित) (निर्देश कं लिए इसे आगे 'एस० ऐंड एड० बल्ड्यू' से संवेतित किया जाएगा) प० 260 सी० पी० ए० प० 696-7 टा० एन० सिंह रिप० आई० एन० सी० 1888, प० 150 जाया पूर्वोद्धत प० 632, 666 743 तथा और आगे पावर्टी प० 138 9 भारत जीवन 3 अक्टूबर (आर० एन० पी० ए० 12 अक्टू० 1898) ए० एन० बोग सी० पी० ए० प० 427 ए० बी० पी० 2 मार्च 3 मई 1901 मालवीय स्पीचेज प० 269 लाजपतराय पूर्वोद्धत प० 39 एम० के० पटेल, रिप० आई० एन० सी० 1902 प० 79 जी० एस० अय्यर ई ए प० 90 97 पसा अखबार, 22 फरवरी (आर० एन० पी० पी० 8 मार्च 1922) श्रीराम एल० सा० पी० 1903 खंड XVII, प० 103 04 मद्रास स्टड्ड 16 जन०, ट्रिब्यून 15 जन० (वी० ओ० आई० 6 फरवरी 1904) इंडियन पीपुल 1 जन० ऐडवोकेट 24 जून (वही 13 फर० 1904) तथा देखिए, बजन स्पीचेज खंड II प० 330
- 105 जी० पी० एन० एस० जनवरी 1882 प० 31 पूना सांख्यिक सभा की शिक्षा समिति द्वारा एक अपील
- 106 प्रस्ताव VII
- 107 प्रस्ताव X
- 108 क्रमश प्रस्ताव XIII VIII और XII
- 109 प्रस्ताव XV
- 110 प्रस्ताव II जी० एस० अय्यर न थोडा और आगे बढ़ते हुए तथा वर्तमान भारत सरकार की योजनाओं को प्रत्याशित करते हुए भारत की पांच बड़ी राजधानियों म मि० टाटा के विमान

संस्थान' के समान पांच संस्थानों की स्थापना का अनुरोध किया, ई ए प० 97

- 111 टी० एन० सिंह रिप० आई० एन० सी० 1888, पृ० 156 जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 745 1059 एन० जी० चदावरकर, सी० पी० ए०, प० 525 मालवीय स्पीचेज, प० 269 वाचा सी० पी० ए० पृ० 628 जी० एस० अय्यर ई ए, प० 92 तथा कजन स्पीचेज, पृ० II पृ० 330
- 112 इस मुद्दे पर आई० एन० सी० के प्रस्ताव के लिए ऊपर देखिए पाद टिप्पणियां 106 110 और भारतमित्र 3 जून (आर० एन० पी० बग, 14 जून 1884) बंगाली 31 जुलाई 1886 27 अगस्त 1887 4 सितंबर 1897 इंडियन नेशन 2 अगस्त ट्रिब्यून, 14 अगस्त, बिहार हेराल्ड 17 अगस्त (बी० ओ० आई० अगस्त 1886), हिंदू 27 अक्टूबर 1884, 10 अगस्त 1886 मराठा 15 अगस्त 1886 जोशी पूर्वोद्धत प० 667 811 मालवीय स्पीचेज, प० 269 जी० एस० अय्यर ई ए पृ० 97 9 पसा अक्टूबर 5 अगस्त (आर० एन० पी० पी०, 15 अप्रैल 1899)
- 113 मराठा, 20 जनवरी 1884, जी० एस० अय्यर ई ए पृ० 98
- 114 मराठा 24 जून 1880 बंगाली 31 जुलाई 1886 हिंदू 10 अगस्त 1886 ट्रिब्यून 14 अगस्त, (बी० ओ० आई० अगस्त 1886) जोशी पूर्वोद्धत, प० 745 आई० एन० सी० 1898 1899 1900 1901 और 1904 के प्रस्ताव क्रमशः XVIII, XV, VIII, XIV और II जी० एम० अय्यर ई ए प० 99 100
- 115 राय पावर्टी प० 140 हिन्दुस्तानी 5 दिस० (आर० एन० पी० एन०, 11 दिस० 1900) वाचा भी० पी० ए० प० 626
- 116 बंगाली 31 जुलाई 1886 हिंदू 10 अगस्त 1886 मराठा 15 अगस्त 1886 इंडियन नेशन 2 अगस्त ट्रिब्यून 14 अगस्त बिहार हेराल्ड 17 अगस्त (बी० ओ० आई० अगस्त 1886) बंगाली 4 सितंबर 1897, हिन्दुस्तानी 5 दिसंबर (आर० एन० पी० एन० 11 दिसंबर 1900)
- 117 नव विभाकर 28 जुलाई (आर० एन० पी० बग, 2 अगस्त 1884) भारतमित्र, 15 अप्रैल सहकर 14 अप्रैल (आर० एन० पी० बग 24 अप्रैल 1886), साधारणी 25 अप्रैल दास प्रकाश 23 अप्रैल (आर० एन० पी० बग 1 मई 1886), सुरभि और पताका 12 मई (आर० एन० पी० बग 22 मई 1886) मुरलीधर रिप० आई० एन० सी० 1892 प० 90 भारत जीवन 3 अक्टूबर (आर० एन० पी० एन०, 12 अक्टूबर 1892) ए० एम० बोस सी० पी० ए० पृ० 427 8 मराठा 18 नव० 1900 श्रीराम एल० सी० पी०—1903 पृ० XLII प० 103-4 मानवाय स्पीचेज प० 269 राजपतराय पूर्वोद्धत पृ० 39 जी० एम० अय्यर ई ए पृ० 92 फ्रांसिस न 1898 के अपने चौन्वें अधिवेशन में अपनी दृढ़ धारणा को इस शक्ति में व्यक्त किया इस समय प्रचलित तकनीकी शिक्षा पद्धति पूर्णतः अपर्याप्त और अक्षय प्रद है (प्रस्ताव XVIII) 1899 1900 तथा 1901 के क्रमशः XVI, VIII तथा XII प्रस्तावों में इस राय को दोहराया गया
- 118 गिवाजी 1 अक्टूबर (आर० एन० पी० बग 9 अक्टू० 1880) पूना सावजनिक सभा की नव वारिणी समिति द्वारा एक अपील ज० पी० एस० एम० जनवरी 1880 पृ० 30-31 पत्राची अक्टूबर 10 नवंबर (आर० एन० पी० पी० 14 नव० 1883) कसबता में नेत्रनल वारिणी का प्रथम प्रस्ताव बंगाली 5 जनवरी 1884 मराठा 20 अप्रैल 1884 नव विभाकर 28 जुलाई (आर० एन० पी० बग 2 अगस्त 1884) जोशी पूर्वोद्धत प० 812 जमीउन जनुम 28 जून (आर० एन० पी० एन० 7 जुलाई 1897) भारत जीवन 3 अक्टूबर (आर० एन० पी० एन०,

- 18 अक्टूबर 1898) अल्मोडा अक्टूबर 8 अक्टू० (आर० एन० पी० एन० 19 अक्टू० 1898) लाजपतराय पूर्वोद्धत प० 40-1 नेटिव ओपीनियन, 30 जुलाई इंदु प्रकाश, 31 जुलाई (आर० एन० पी० बब 2 अगस्त 1902)
- 119 जे० सी० वागल हिस्ट्री आफ दि इंडियन एसोसिएशन' 1876-1951 (कलकत्ता 1953) पृ० 10
- 120 प्रस्ताव XVI 1900 में इसी भावना की पुन अभिव्यक्ति की गई 1898 में कांग्रेस अधिवेशन ए० एम० बोस ने पहले ही टाटा की देश के सच्चे लोकपोषक के रूप में प्रशंसा की थी— (सी० पी० ए०, पृ० 456)
- 121 ए० बी० पी० 11 मार्च 23 जून 1904 कलकत्ता प्रेस में सस्या का बड़े चढ़ उरसाह के साथ स्वागत किया देखिए बंगाली 16 मार्च 8 सितंबर 1904, ए० बी० पी० 23 जून 1904 इंडियन मिरर, 4 मई (आर० एन० पी० बग 14 मई 1904) तथा दुनिया प्रकाश, 7 अप्रैल (आर० एन० पी० बब 9 अप्रैल 1904)
- 122 इपीरियल गजेटियर आफ इंडिया 1909 खंड IV पृ० 436-9
- 123 मराठा 1 15 अगस्त 1886 18 नव० 1900 भारत मिहिर 8 अप्रैल नव विभावर, 12 अप्रैल (आर० एन० पी० बग 17 अप्रैल 1886) सुबोध पत्रिका, 6 फरवरी (आर० एन० पी० बब 12 फर० 1887) बंबई समाचार 12 अप्रैल (आर० एन० पी० बब 16 अप्रैल 1887), हिंदुस्तानी 5 दिसंबर (आर० एन० पी० एन० 11 दिन० 1900) स्वदेशमित्र 1 मार्च (आर० एन० पी० एम० 2 मार्च 1901) वाचा सी० पी० ए० प० 628 जी० एस० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1901 पृ० 126 इंडियन पीपुल 1 जन० एडवाक्ट 24 जन० (बी० ओ० आई० 13 फर० 1904) तुलनीय इ० बा० हावेल तकनीक एडवेंशन इन इंडिया' कलकत्ता रिज्यू अप्रैल 1897 हावेल ने प्राथमिक तकनीकी शिक्षा पर बल दिया तथा उच्च तकनीकी शिक्षा की मांग का तिरस्कार किया
- 124 सुबोध पत्रिका 6 फरवरी (आर० एन० पी० बब, 12 फरवरी 1887), बंबई समाचार, 12 अप्रैल (आर० एन० पी० बब 16 अप्रैल 1887) स्वदेशमित्र 1 मार्च (आर० एन० पी० एम० 2 मार्च 1901) इंडियन स्पेक्टर 9 जून 1901 हिंदू 23 फरवरी 1901, इंडियन पीपुल 1 जन० ऐडवोकेट 24 जन० (बी० ओ० आई० 13 फरवरी 1904)
- 125 हम हस्तकिल्पियों को प्रशिक्षित करने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि उच्च स्तर के नययुवकों के हृदय को प्रशिक्षित करने का आवश्यकता है क्योंकि यही लोग भारत की औद्योगिकता को नीचे से ऊपर उठान में पुरोगामी बनेंगे (जी०एस० अय्यर रिप०आई० एन० सी० 1901 पृ० 126) तथा पाठ टिप्पणी 124 ऊपर और मराठा 15 अगस्त 1886 भारतवासी 4 सित० (आर० एन० पी० बग 11 सित० 1886) वाचा सी० पी० ए०, प० 627 8 इनके विरुद्ध भारतीय दृष्टिकोण को दर्शाने के लिए देखिए दि इंडियन इकॉनॉमिक प्रॉब्लम' दि डान जून 1900 पृ० 31 2.
- 126 सपना पादटिप्पणिया 118 और 121 तथा जी० एस० अय्यर ई ए प० 98
- 127 देखिए ऊपर पादटिप्पणियों 110 तथा भारतवासी 4 सितंबर (आर० एन० पी० बग 11 सित० 1886) वाचा सी० पी० ए० प० 628 आई० एन० सी०—1902 का प्रस्ताव IX इंडियन पापुल 1 जनवरी ऐडवोकेट, 24 जनवरी (बी० ओ० आई० 13 फरवरी 1904)
- 128 ज० एन० सिंघ रिप० आई० एन० सी० 1888 प० 156-7 आर० बी० बही

- रानाडे एसज, प० 122, 187 दि ऐक्सीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इंडिया, पूर्वोक्त स्थल प० 4 जी० एस० अय्यर ई ए प० 149 बी०सी० पाल दि नेशनल प्रालम', 26 जनवरी 1903 को बलवत्ता में दिया गया एक भाषण 'यू स्पिरिट (बलवत्ता, 1907) प० 175
- 129 जोशी पूर्वोक्त प० 740 तथा प० 826
- 130 आर० बोस रिप० आई० एन० सी० 1888 प० 162
- 131 रानाडे एसज प० 122 तथा जोशी पूर्वोक्त प० 740 801-02 दि ऐक्सीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इंडिया', पूर्वोक्त स्थल, प० 4 23 जी० एस० अय्यर ई ए प० 149 50 लालकृष्णम पूर्वोक्त प० 42
- 132 दि ऐक्सीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इंडिया पूर्वोक्त स्थल, प० 23 जाशी पूर्वोक्त प० 625 मराठा 1 फरवरी 1884, बंगाली, 17 दिसंबर 1901 गोखले स्पिचेज प० 1057 जी० एस० अय्यर ई ए प० 216
- 133 जोशी पूर्वोक्त प० 625 बंगाली 17 मई 1902
- 134 रानाडे एसज प० 23 122 बी० सी० पाल दि नेशनल प्रालम, पूर्वोक्त स्थल प० 179 80 तथा देखिए जी० एस० अय्यर ई ए प० 132-4 भारतीय दृष्टिकोण के विरुद्ध दि ऐक्सीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इंडिया क अनातनाम लेखक न सचेतित किया आधुनिक सभ्यता अस्तित्व की स्थिति है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जीवन में अपनी दशा को सुधारने अपनी शक्तियों के विकास तथा जीवन की सुख सुविधाओं में वृद्धि का अथक प्रयास कर रहा है (पूर्वोक्त स्थल, प० 5)
- 135 दि ऐक्सीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इंडिया पूर्वोक्त स्थल, प० 5
- 136 वही प० 3 जे० एन० सिंह रिप० आई० एन० सी० 1888 प० 157 जी० एस० अय्यर ई ए प० 151
- 137 दि ऐक्सीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इंडिया पूर्वोक्त स्थल प० 5 जे० एन० सिंह रिप० आई० एन० सी० 1886 प० 157
- 138 दि ऐक्सीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इंडिया पूर्वोक्त स्थल प० 5-6 23 बी० सी० पाल दि नेशनल प्रालम, पूर्वोक्त स्थल प० 186
- 139 जी० एस० अय्यर ई ए प० 150 बी०सी० पाल दि नेशनल प्रालम पूर्वोक्त स्थल प० 179
- 140 अज्ञात अनुमानों में सफलता के लिए हम अपने निजी जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है हम उन पारंपरिक प्रतिबंधों से अपने आपको मुक्त करना है जो सुधार में बाधक हैं तथा विचारों को अस्पष्ट बनाने वाले और निष्पत्ति को विषयस्त करने वाले पूर्वग्रहों एवं भावनाओं के त्याग से समझौते पर विवश करते हैं दि ऐक्सीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इंडिया पूर्वोक्त स्थल प० 12
- 141 रानाडे मिसलेनियस राइटिंग (बवई 1915) प० 131 तुलनीय बी० सी० कर्ण, रानाडे दि प्रोफेट आफ लिबरेटिड इंडिया (पूना 1944) रानाडे की इच्छा थी कि जनता का सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक मारुत जीवन पुनर्गठित करना चाहिए ताकि भारत के लोग आधुनिक व्यवसाय तथा उद्योग की आवश्यकताओं के आधार पर व्यवसायपरक दृष्टिकोण वाले बनें (प० 106)
- 142 वही प० 116 जी० एस० अय्यर ई ए प० 300 तथा भोलानाथ चंद्र—एम० एम० चर 5 प० 79
- 143 दि ऐक्सीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इंडिया पूर्वोक्त स्थल प० 1 23 तथा ऊपर 130 131 के पादटिप्पणियाँ

- 144 भारत जीवन 6 नवंबर (आर० एन० पी० एन०, 14 नवंबर 1899) प्रधान ऍड भागवत मे तिलक ने कहा—पूर्वोद्धत, प० 50 63 96 एन० जी० चदावरकर स्पीचेज ऍड राइटिंज एल० वी० क्विनी द्वारा संपादित (बंबई 1912) प० 75 (अथवा वह सुधारक वग से संबंधित था) लाजपतराय पूर्वोद्धत प० 114-28
- 145 1904 मे लाजपतराय ने अपना मत प्रकट किया हमारे धर्मग्रथा से इतनी पर्याप्त समझी है कि हम सामाजिक शक्ति और सुधार के लिए उस पर निर्भर कर सकते है (पूर्वोद्धत प० 90) तथा वही, प० 73 116, 122 124 प्रधान ऍड भागवत मे तिलक ने कहा—पूर्वोद्धत, प० 76-7 119
- 146 प्रधान ऍड भागवत, म तिलक ने कहा—पूर्वोद्धत प० 63-4 लाजपतराय पूर्वोद्धत, प० 76-7 119
- 146-ए ए० सी० मजूमदार 'इंडियन नेशनल इवोल्यूशन (मद्रास 1917) प० 187
- 147 भसानी पूर्वोद्धत, प० 71 78
- 148 जी० ए० मनकर पूर्वोद्धत, खड I, प० 82 3
- 149 गोखले स्पीचेज प० 927
- 150 पी० मेहता स्पीचेज प० 747
- 151 दि इंडियन नेशन बिल्डस (मद्रास, तिविरहित), भाग I प० 182
- 152 राम गोपाल पूर्वोद्धत, प० 42
- 153 दि इंडियन नेशन बिल्डस, भाग II, प० 93 296
- 154 वही प० 361, 372
- 155 वही, भाग I प० 155-6
- 156 लाजपतराय पूर्वोद्धत इट्रोडक्शन प० XXIII
- 157 ब्राह्मो पब्लिक ओपीनियन 22 जनवरी, 8 अप्रैल 1880
- 158 बंगाल नेशन चेंबर आफ कामस—1887 का प्रतिवेदन प० 71 2.
- 159 ये तथ्य पसा निधि की रजत जयंती शक (पूना 1933) से लिए गए हैं
- 160 मराठा, 9 अगस्त 1885, 22 सितंबर 1895, रानाडे एजेज प० 120 180, जोशी पूर्वोद्धत प० 971 8 तथा डी० पी कर्वे पूर्वोद्धत प० 106
- 161 बेलाफ महादेव गोविंद रानाडे (कलकत्ता 1926) प० 321 2 गोखले स्पीचेज, प० 927
- 162 बंगाली 12 सितंबर 7 नवंबर 1891
- 163 एस० एन० बैनर्जी 'ए नेशन इन मेकिंग' (आक्सफोर्ड प्रेस 1925) प० 146
- 164 आई० एन० सी०—1900 के प्रस्ताव VII और XXV
- 165 बा० पट्टाभि सीतारमया लि हिस्टरी आफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1883-1935 (मद्रास 1935) प० 68 प्रश्नानियों की लोकप्रिय भारतीय समाचारपत्रों से प्रोत्साहन और समर्थन मिता देविए बंगाली 18 जनवरी 1902 इंडियन नेशन 23 दिसंबर 1901 एडवोकेट—9 जनवरी 1902 इंडियन मिरर 19 जनवरी 1902 वी० ओ० आई०, 8 फरवरी 1902.

## उद्योग II

ब्रिटिश पूजी (भारत की) राष्ट्रीय प्रगति के लिए एक अपरिहार्य आवश्यकता है।

साइ कजन

विदेशी, अठ्ठाईसवीं शताब्दी ब्रिटिश, पूजी का देश के ससाधनों के विनाश में विनियोजन देशवासियों की आर्थिक दशा के सुधार में सहायक होने की अपेक्षा इस दिशा में एक बहुत बड़ी बाधा ही सिद्ध हुआ है।

विपिनचन्द्र पाल

### I विदेशी पूजी की भूमिका

भारत में एक ओर स्वदेशी पूजी की कमी थी और यहाँ के लोग सकोचवश अथवा सतरो से घबराकर नए क्षेत्रों में पूजी के निवेश से बचताते थे जिसके फलस्वरूप भारत के औद्योगिक विकास का क्षेत्र सकुचित और सीमित हो गया था तो दूसरी ओर ब्रिटिश पूजी अपने देश में पूरी तरह न खप पाने के कारण निवेश के लिए नए क्षेत्रों की खोज में थी। ब्रिटेन का विचार यह था कि इस ब्रिटिश पूजी को भारत के आर्थिक विकास की सून्यता को भरने के काम में लगाया जाए तथा इसका प्रयोग उद्योगीकरण के विकास में किया जाए। ग्रेट ब्रिटेन के तथा भारत के अधिकारियों का विचार था कि ब्रिटिश पूजी को भारत में आकृष्ट करने तथा सभी बाधाओं को हटाकर उसका प्रयोग करने से न केवल भारत के सभी आर्थिक रोगों का उपचार हो जाएगा प्रत्युत ब्रिटेन की अतिरिक्त पूजी का भी सुरक्षित और लाभदायक विकास मिल जाएगा।<sup>1</sup>

ब्रिटिश सत्ता ने भारत में ब्रिटिश पूजी के प्रवाह को सुरक्षा और आकर्षण प्रदान किया। स्वदेशी पूजी तथा साहस के अभाव तथा ब्रिटिश राजनीतिक सर्वोच्चता के परिणामस्वरूप प्रारम्भिक अवस्था में ब्रिटिश पूजीपति ही भारत में आधुनिक उद्योगों के अग्रदूत तथा प्रधान प्रोत्साहक बन। इस पर भी आश्चर्यजनक बात यह है कि ब्रिटिश पूजी का मूल निवेश अत्यल्प था। भारतीय साम्राज्य की विजय का आधार भारतीय वित्त तथा यही स जुटाए गए बज थे। 19वीं शती के प्रवाह में जन्म लाने वाले व्यवसाय नए बज तथा





व्यावसायिक और औद्योगिक सस्थाओं में निवेशित थी। स्पष्ट है कि इस प्रकार औद्योगिक निवेश का भाग अपेक्षाकृत और भी कम था।<sup>10</sup> तृतीयत, यद्यपि आधुनिक उद्योगों में निवेशित विदेशी पूँजी की राशि किसी भी मानदंड से तुच्छ थी तथापि उसने भारत के औद्योगिक मंच पर एकधिकार जमाएँ रखा तथा इस क्षेत्र में भारतीय पूँजी को दबा कर रखा। बहुत सारी पटसन मिलों, ऊँ और सिल्क की मिलों, बागज मिलों, चीनी के कारखानों, चमड़े के कारखानों, लोहा तथा पीतल के ढलाई कारखानों के मालिक विदेशी निवेशक ही थे।<sup>11</sup> भारतीयों का प्रारंभ से ही प्रमुख भाग केवल सूती कपड़ा उद्योग में ही था किंतु यहाँ भी आशिक पूँजी विदेशी थी, प्रबंध अधिकांशतः विदेशी था तथा तकनीकी सवग में अधिकांश का जवरदस्ती ही आयात करना पड़ता था।<sup>12</sup>

भारतीय राष्ट्रवादी नेता विदेशी पूँजी के उपयोग के सबंध में पर्याप्त समय तक सभ्रम, मतभेद तथा सकोच का शिकार बने रहे। प्रारंभ में विदेशी संरक्षण में जब रेलवे और नहरों, खानों, बागान और आधुनिक उद्योगों का प्रागमन हुआ, उस समय विदेशी पूँजी के भारत में अंतःप्रवेश का कोई विरोध नहीं हुआ, परंतु ज्योंही भारतीयों के स्वामित्व के उद्योग धीरे धीरे विकसित होने लगे और भारतीयों को विदेशी पूँजी के अधिकार के दुष्प्रभाव का पता चलता गया, त्योंही विदेशी पूँजी के विरुद्ध आलोचना की प्रवृत्ति जोर पकड़ने लगी। 19वीं शताब्दी के अंत तक भारतीयों का एक बग तो अंत भी विदेशी पूँजी के उपयोग के पक्ष में था, परंतु बहुमत उसका तीव्र विरोधी था।<sup>13</sup> राष्ट्रीय दृष्टिकोण में परिवर्तन का सर्वोत्तम उदाहरण दादाभाई नौरोजी हैं, जो पहले विदेशी पूँजी के प्रबल समर्थक थे परंतु कालांतर में उसके तीव्र आलाचक तथा प्रखर विरोधी बन गए।<sup>14</sup> यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जहाँ विदेशी पूँजी के निवेश के समर्थक अनेक भारतीय नेताओं ने उसके कुछ विशेष पहलुओं का निंदा की, वहाँ उसके विरोधी उमते होने वाले कुछ लाभों से सहमत थे। बहुसंख्यक राष्ट्रवादी नेताओं का यह जटिल व डावाडोल दृष्टिकोण उनके मत की वास्तविकता में प्रायः असंबद्ध और कभी कभी तक हीन बना देता था। यह बात अवश्य है कि 1905 तक उन्होंने विदेशी पूँजी की तत्कालीन और आने वाले वर्षों में निमाई जानेवाली भावी भूमिका के सबंध में सकारण और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली थी।

विदेशी पूँजी के उपयोग के समर्थक भारतीय नेताओं के एक बग के समर्थन का आधार यह था कि भारत जैसा निधन देश अपनी देशी पूँजी से अपने नए उद्योगों का उपभोग करने में असमर्थ है अतः उसे अपने उद्योगों और यातायात के साधनों के विनाश तथा इसके फलस्वरूप अपने लोगों की भौतिक दशा को उन्नत बनाने के लिए निश्चिन्त रूप से ही विदेशी पूँजी की जरूरत है।<sup>15</sup> अमृतबाजार पत्रिका ने अपने 23 फरवरी 1903 के अंक में तो यह मत प्रकट किया वतमान परिस्थितियों में विदेशी पूँजी के अंतःप्रवाह का विरोध मूढतापूर्ण तथा आत्महत्या जैसा काम है। यह आशा की जाती थी कि विदेशी उद्यम एक उदाहरण और एक आदर्श का काम करते हुए स्वदेशी उद्योगों और व्यापारों को प्रेरणा प्रदान करेगा।<sup>16</sup> इससे अन्ततः ही भारतीय उद्यमियों के लिए गिद्धर का करने की अपेक्षा की गई थी।<sup>17</sup> राष्ट्रीय नेताओं के इस बग का विरुद्ध था कि



भारतीय पूजीपतियों द्वारा औद्योगिकता की प्रक्रिया के उपक्रम और विकास किए जाने पर ही देश का वास्तविक आर्थिक विकास और सुधार संभव था, विदेशी पूजीपति इस कार्य के संपादन में अममथ थे।<sup>8</sup> जी० एस० अय्यर ने 1901 में कहा 'आधुनिक काल के अथवा प्राचीन काल के ऐसे किसी देश का कोई एक भी उदाहरण उपलब्ध नहीं जहाँ शासक जाति के होने के नाते सभी संभव राजनीतिक और सामाजिक सुविधा प्राप्त विदेशी पूजीपतियों ने शासित प्रदेश के लोगों की औद्योगिक समृद्धि में सहायता की हो।'<sup>9</sup> उन्होंने तो साथ में यह भी कहा, 'मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि अपने देशवासियों को ही अच्छे माल का उत्पादन अपने हाथ में लेने के योग्य बनाने के लिए शिक्षित तथा प्रशिक्षित करने से देश में कृषि से इतर संपत्ति का उपाजन किया जा सकता है।'<sup>10</sup>

आलोचकों की दृष्टि में विदेशी पूजी अपने मूल में राष्ट्रविरोधी थी, की क्योंकि यह भारतीय पूजी की सहायता करने तथा उसे प्रोत्साहित करने के बदले उलट खदेड़ कर उसे कुचल रही थी।<sup>11</sup> विदेशी तकनीक अथवा मशीनरी की अपेक्षा न रखने वाले तथा भारतीयों के कार्य व्यापार के स्वतंत्र सिद्ध अधिकारक्षेत्र वक जस व्यवसायों सभी विदेशी उद्यम भारतीय उद्यम को जबरदस्ती बाहर धकेल रहा था।<sup>12</sup> भारतीय उद्यम विदेशी पूजीपतियों द्वारा अपना माग जवरुद्ध ही पाते रहे हैं।<sup>13</sup> जिस प्रकार अप्रतिबंधित विदेशी आयातों ने पहले भारत के शहरी उद्योगों को नष्ट किया है, उसी प्रकार अब विदेशियों के स्वामित्व के उद्यम ग्रामीण हस्तशिल्पों का नष्ट-भ्रष्ट करने में लग हैं।<sup>14</sup> विदेशी उत्पादन की देश के उत्पादनों के साथ प्रतियोगिता और भी अधिक भयंकर है क्योंकि वह देश के सस्ते श्रम पर निर्भर है। समालोचकों का उन लोगों को, जो यह मानते थे कि विदेशी पूजी के अभाव में अविक्सित रह जानेवाले साधनों के विदेशियों द्वारा विकसित किए जाने से कोई हानि नहीं उत्पन्न था कि यह हानि आनेवाली पीढ़ियों का ही दस्ताई पड़ेगी। कालांतर में काफी वर्षों के बाद जब भारतीय पूजी की विपुल राशि का विकास तथा संचालन की स्थिति में हो जाए तब उस समय उन्हें पता चलना कि औद्योगिक उद्यमों के बहुत सारे क्षेत्र विदेशियों ने पहले ही बुरी तरह से अपने अधिकार में कर लिये हैं और इस दिशा में नए उद्यमों के लिए कोई अवकाश ही नहीं है। इस प्रकार आज का क्षुद्र लाभों के लिए सारा भविष्य अधिकारमय हो जाएगा। अतः उनका कथन था कि इसकी अनुमति कदापि नहीं देनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि वर्तमान पीढ़ी को भी यह अधिकार कदापि नहीं है कि वह स्याई रूप से भारत के औद्योगिक क्षेत्र का पराधीन करने के रूप में देश के भविष्य की स्याई लाभा का वलिदान कर दे।<sup>15</sup> उन्होंने लाड कजन की इस टिप्पणी का भी तत्पूर्वक विरोध किया 'सारा औद्योगिक और व्यापारिक विद्वत् एक प्रकार का क्षेत्र है, जिस पर कपक का कपि करनी है, और यदि स्थानीय व्यक्ति अपनी बुद्धि से उम्र खेत की जुताई नहीं करता तो उस अपने हान के साथ उसके लान को जोतने के लिए आने वाले बाहरी व्यक्तियों को दोष देने का कोई अधिकार नहीं।'<sup>16</sup> उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत का औद्योगिक क्षेत्र, अधिकतम अथवा अनधिकतम, भारतीयों का ही है, किसी अन्य का नहीं।<sup>17</sup> और पूछा

यदि बाइसराय के तब सही है तो हम जानना चाहें कि फिर आस्ट्रेलिया और

दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के विरुद्ध, अमरीका में चीनियों के विरुद्ध, इंग्लैंड में अमरीकी पूजापतिया के आगमन के विरुद्ध तथा ब्रिटेन द्वारा अपने पूण एकाधिकार के रूप में स्वीकृत बाजारों में सस्ते माल के प्रवाह के विरुद्ध विस्फोट के क्या कारण हैं ? यहाँ तक कि स्वयं लाड कज्जल ने अमरीकी तेल कंपनी को वर्मा की तेल खानों में काम करने की अनुमति क्यों नहीं दी ? क्या इन सबके कारण वही नहीं हैं जिनके लिए हमारे देशवासी विदेशी शोषण के विरुद्ध आपत्ति करते आ रहे हैं ?<sup>38</sup>

वस्तुतः विदेशी पूजा के इन विरोधियों ने यह कभी स्वीकार नहीं किया कि भारत में विदेशी पूजा के निवेश के बिना औद्योगिक विकास संभव नहीं होगा।<sup>39</sup> वे इस विडवना से सहमत नहीं थे कि या तो विदेशी पूजा का उपयोग कीजिए, अन्यथा पूजा से संवत्सा वंचित रहिए। उनके अनुसार वास्तविक विफल्य विदेशी और स्वदेशी पूजा के मध्य है। उनके अनुसार स्वदेशी पूजा का उदय और उसकी प्रौढता प्राप्त समय सापेक्ष भले ही हो परंतु विदेशी पूजा का आगमन और प्रयोग संशुभ ही उसे अपनी पूजा से या तो वंचित कर देगा या उसके उदय को विलंबित करेगा।<sup>40</sup>

विदेशी पूजा के आलोचकों द्वारा विदेशी पूजा के प्रयोग के विरुद्ध प्रस्तुत तर्क यह था कि वह देश की पूजा की देश के बाहर निकासी करती है क्योंकि विदेशी उद्यमी केवल अपनी पूजा के ब्याज की राशि ही नहीं प्रत्युत सारे ही लाभ भारत से बाहर भेज देते थे।<sup>41</sup> उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि विदेशी पूजा के निवेश ने संयुक्त राज्य अमरीका अथवा इंग्लैंड अथवा अन्य स्वतंत्र देशों में संबंधित राष्ट्रों और देशवासियों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ पहुंचाए हैं। उन राष्ट्रों को इन लाभों के मूल्य के रूप में केवल पूजा का ब्याज ही देना पड़ा है।<sup>4</sup> परंतु उन्होंने संकेत किया कि भारतीय लोगों को अपनी विशिष्ट आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इस विदेशी पूजा से कोई लाभ नहीं हो पाता। वस्तुतः इसके विपरीत उन्हें इससे हानि ही उठानी पड़ती है। वे विशिष्ट परिस्थितियों को नहीं सी थी, उनका विवरण इस प्रकार है

प्रथम, विदेशी पूजा का आयात स्वेच्छाप्रेरित नहीं था, वह विदेशी शासन के कारण बलपूर्वक लादा हुआ था। ब्रिटिश राज्य के प्रत्यक्ष प्रमाण, ऊंचे कराधान तथा विपुल सामग्री की निकासी देश की पूजा का बहुत बड़ा भाग स्वायत्त कर लेते थे, अतः देशवासियों के पास नाममात्र की पूजा अवशिष्ट रह पाती थी। इस स्थिति में पूजा की क्रमिक वृद्धि की संभावना लगभग असंभव थी। भारतीय पूजा की विरलता के कारण नए औद्योगिक क्षेत्रों के उपक्रम नहीं किए जा सकते थे अतः विदेशियों ने आकर इनपर अपना अधिकार कर लिया। प्रथम तो इस तरीके से भारतीय उद्यमियों के मार्ग में बाधा डाली गई और उसके उपरांत आर्थिक आवश्यकता का बहाना करके देश पर विदेशी पूजा बलपूर्वक थोप दी गई।<sup>43</sup> इस प्रकार भारतीय नतावा का मतलब था कि विदेशी पूजा भारत में इस देश की पूजा की वृद्धि के लिए नहीं, प्रत्युत उसके ह्रास के लिए, उसकी से लिए नहीं, प्रत्युत उसे अपने अधीन बनाने के लिए, इसके विकास के लिए नहीं, इसके साधनों के अपहरण के लिए ही आई है।

द्वितीय, आलोचकों ने निर्दिष्ट किया कि विदेशी पूजा भारतीय पूजा को वि

कर देती है। इसका कारण यह नहीं कि विदेशी पूजीपति आर्थिक दृष्टि से अधिक योग्य है अथवा भारतीय पूजीपति सकोची वृत्ति के हैं, अथवा विदेशी पूजीपति अधिक उत्साही साहसी है। इसका वास्तविक कारण यह है कि भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा विदेशी पूजी को आने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, सभी प्रकार की रियायतों से उसकी सहायता की जाती है, उसे सभी प्रकार के प्रलोभन और विशिष्ट सुविधाएँ दी जाती हैं। उदाहरणार्थ, लाभों की गारंटी, मुफ्त अथवा सस्ते दाम पर भूमि, उसके हितों की रक्षा के लिए प्रशासनिक तथा सांविधानिक उपाय आदि। इसके विपरीत स्वदेशी पूजीपतियों को निररसाहित किया जाता है, उन्हें सभी साधनों में वंचित किया जाता है तथा उन्हें अपनी हालत पर छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार स्वदेशी और विदेशी पूजी में यथार्थतया समता के आधार पर प्रतियोगिता नहीं है। विदेशी पूजीपति भारतीय पूजीपतियों के मुकाबले अनुचित सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं।<sup>44</sup>

तृतीय, आलोचना का तब था कि जहाँ अन्य देशों में विदेशी पूजी के, विदेशी निधि के आयात द्वारा उस देश की पूजी के आंतरिक सकीण साधना के विकास में सहायक हान से दोष किसी भीमा तक सतुलित हो जाते थे, वहाँ भारत में विदेशी पूजी का निवेश इन देश में विदेशी निधि का आयात नहीं करता था, क्योंकि इस देश में विदेशी पूजी का प्रवाह स्वाभाविक न होकर अप्राकृतिक ही था। वस्तुतः इस देश में विदेशी निवेशकों ने अपने देश के साधनों में पूजी संचित नहीं की, प्रत्युत भारत की पूजी की ही प्रथम विदेशियों द्वारा नियंत्रित व्यापारों, बैंकों, उद्योगों तथा प्रशासनिक व्यय के माध्यम से विदेश में निकासी हुई और पुनः उसका कुछ अंश निवेश पूजी के रूप में लौटकर भारत आ गया। राष्ट्रीय खातों की दृष्टि से समीक्षा करने पर सारा काय व्यापार बाजार पर अका का बोरा खेल तमाशा था।<sup>45</sup> देश के व्यापार खातों के अध्ययन से यह भी स्पष्ट हो जाता था कि भारत वास्तविक विदेशी निधि का आयात नहीं करता था। दादाभाई नौरोजी ने 1887 में सकेत किया था कि यह स्मरणयोग्य है कि भारत के शुद्ध आयात में सभी विदेशी ऋणों और निवेशकों को जाड़ देने के बाद भी उसके शुद्ध निर्यात बढ़चढ़कर हैं।<sup>46</sup> इस प्रकार भारत अपनी ही पूजी से अपने ही गोपण की अपरिहाय स्थिति में पहुँच गया है। प्रायः समय में भारतीयों ने अपने ही राजनीतिक दमन के लिए अंगरेजों को जिस प्रकार सहायता की है, उसी प्रकार आज वे अपनी ही आर्थिक उदासीनता का काय संपन्न करने के लिए अंगरेजों की सहायता कर रहे हैं। यह एक रोचक तथ्य है कि देश की पुनर्निष्क्रान्त संपत्ति की विदेशी पूजी के रूप में वापसी तथा भारत के विदेशी उद्यमियों द्वारा प्राप्त लाभों के पुनर्निवेश में बहुत सारे भारतीय नेताओं को असजाल में उलभाए रखा तथा विदेशी पूजी के प्रति आंतरिक रूप से असंगत प्रतीत हान वाली स्थिति को भी स्वीकार करने के लिए विवश किया। एक ओर उन्हीं विदेशी पूजी के लाभों के निर्यात का विरोध किया तथा दूसरी ओर इन लाभों के पुनर्निवेशन का समयन नहीं किया, क्योंकि इससे स्वतः ही लाभों की राशि में वृद्धि हो जाती थी और उसका परिणाम भविष्य में संपत्ति का निष्क्रान्त था।<sup>47</sup> भारतीय नेताओं की यह असमति उनकी गलत चिंतन प्रक्रिया का न होकर एक प्रकार से स्वाभाविक ही थी। उन्होंने इस जटिल प्रक्रिया का न

कि आतरिक विसर्गतियों से परिपूर्ण थी, सही तौर पर व द्वात्मक रूप से समझा।<sup>49</sup> उनका कथन था कि विदेशी पूजी से अर्जित लाभ के पुनर्निवेश ने धन की स्वतः विस्तृत होने वाली तथा कभी समाप्त न होने वाली निकासी की प्रक्रिया को जन्म दिया था। 1887 में दादाभाई नौरोजी ने लिखा, 'सबप्रथम ब्रिटिश भारत की संपत्ति बाहर ले जाई जाती है और फिर उसी संपत्ति को ऋणों के रूप में यहाँ वापस लाया जाता है और फिर उही ऋणा पर ऊँचा ब्याज वसूल किया जाता है। इस प्रकार यह सारा दुश्चक्र अत्यंत घृणित तथा उत्तेजक रूप में चल रहा है।<sup>50</sup> इसके फलस्वरूप इस समस्या के प्रति उनका दृष्टिकोण भी द्वात्मक था। उनके अनुसार चुनाव का प्रश्न विदेशी पूजी की स्वीकृति अथवा उसे सहन करने में, तथा लाभों के निपात अथवा उनके पुनर्निवेश से ही संबंधित नहीं था, बल्कि दुश्चक्र के साथ गतिशील बने रहने और संपत्ति की निकासी को रोकने और औद्योगिक विकास के लिए स्वदेशी संपत्ति पर निर्भर रह कर इस दुश्चक्र को गतिशून्य करने का था। इस प्रकार दोनों रोगों से बचाव किया जा सकता है।

भारतीय नेताओं ने इस ओर भी संकेत किया कि विदेशी पूजी की सहायता से भारत के विकसित होने वाले नए साधनों के लाभ अत्यंत सीमित थे क्योंकि यह अपनी विशिष्ट राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के कारण देश की विशाल जनसंख्या के एक छोटे से भाग के लिए ही अतिरिक्त आजीविका जुटाती है और इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय मजदूरी निधि में साधारण सी वृद्धि होती है।<sup>51</sup> आजीविका की इस तुच्छ वृद्धि का प्रमुख भाग विदेशी उद्यमों के निर्माण तथा संचालन में उच्च पदां पर प्रतिष्ठित तथा उच्च वेतन-भोगी अधीक्षक पदों पर एकाधिकार किए विदेशियों के पास चला जाता है।<sup>52</sup> दुर्भाग्यवश राज्य व्यवसायों की भी धरावर यही स्थिति थी।<sup>53</sup> यह तथ्य भारतीयों को न केवल उनके 'यायमगत अतिरिक्त आजीविका के अवसरों से वंचित करता था तथा उपभोग में वृद्धि करता था,<sup>54</sup> प्रत्युत अनेक महत्वपूर्ण तथा दूरगामी बुराइयाँ भी पनपाता था। बहुत सारे विदेशी भारत की पूजी के संचय और निवेश के लाभप्रद साधनों से वंचित करत हुए, अपने वेतन का बड़ा भाग विदेश में भेज देते थे।<sup>55</sup> इसके अतिरिक्त विदेशी पूजी के विनियोग भारतीयों की औद्योगिक तकनीक और व्यापार संचालन में उन्नत प्रशिक्षण से वंचित करते थे। इस प्रकार विदेशी पूजी का एक समग्र घापित लाभ व्यवहारत उपलब्ध ही नहीं था तथा एक समृद्ध औद्योगिक व्यवसाय से लोगों का प्राप्त ज्ञान वाली शिक्षा और जानकारी सबथा अनुपलब्ध थी।<sup>56</sup> इसके साथ साथ नवीन आशिक' नियोजन भी भारत में नहीं किए जाते थे प्रत्युत विदेशी उद्यमों की घरेलू व्यवस्था द्वारा स्वयं निवेशकों के अपने ही देश में किए जाते थे।<sup>57</sup> विदेशी पूजी के आलोचकों की एक अन्य शिकायत यह थी कि यदि थोड़े बहुत भारतीयों को कुलियों और अकुशल मजदूरों के रूप में विदेशियों के अधीनस्थ बागों, खानों, फैक्टोरियों तथा रेलवे में नौकरी मिलती भी है तो वहाँ उन्हें बहुत ही कम वेतन दिया जाता है। बहुतांश तो शोचनीय रूप में एक या दो आने प्रतिदिन के हिसाब में काम करना पड़ता है, जिससे वे अपना दुर्भाग्यग्रस्त जीवन भी नहीं जी पाते।<sup>58</sup> यह स्थिति भारतीयों को सचमुच ही जीवमृत श्रमिकों के स्तर पर ला रही है<sup>59</sup> तथा इस देश को 'पानी खींचने वालों का, लकड़ी काटने वालों<sup>60</sup> का और इससे भी

बढकर 'दासो का' देश बना रही है।<sup>61</sup> भारतीयों को अपने ही देश मे श्रीतदास की स्थिति से सतुष्ट होना पडता है।<sup>62</sup> दादाभाई नौरोजी का कथन था कि 'वास्तव मे वे तुच्छ दासो के रूप मे ही काय करते थे। ब्रिटिश पूजीपतियों को अपने उत्पादन सौपने के लिए उन बचारो ने अपनी ही धरती और अपने ही साधनो को पराधीन कर रखा था।'<sup>63</sup> फिर भी कुछ एक आलोचक आजीविका के नए साधनो को जन्म देने के लिए विदेशी पूजी के स्वागत को तैयार थे परंतु वे इस दिशा मे स्पष्ट सूचित करते थे कि इससे देश का वास्तविक आर्थिक विकास कदापि सम्भव नहीं।<sup>64</sup> उन्होंने यह भी स्पष्ट सूचित किया कि विदेशियों से मजदूरी के रूप मे मिलने वाले इस तुच्छ वेतन से भारतीय सदा के लिए सतुष्ट नहीं रहेंगे। एक दिन वे निश्चित रूप से सदा के लिए कुली और मजदूर बनाए रखने की प्रवृत्ति के प्रति विरोध प्रकट करेंगे।<sup>65</sup>

विदेशी पूजी के विरोधिया ने यह मत भी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया कि भारतीयों को मजदूरी के रूप मे मिलने वाला पारिश्रमिक उनके ससाधनो के शोषण<sup>66</sup> तथा स्वदेशी उद्योग धंधा के विनाश<sup>67</sup> के परिप्रेक्ष्य मे किसी भी कसौटी पर बसने पर सबधा तुच्छ तथा अपर्याप्त था। प्राकृतिक उपज सबधी उद्योगो के सबध मे तो यह स्वतः सिद्ध सत्य था। बागान उद्योगो के विषय मे भी यह पर्याप्त अशा मे सत्य ही था। समालोचका न म्यति का इस सद्बन्ध मे प्रस्तुत करते हुए अपना मत प्रकट किया कि खान उद्योगो का विदेशियों द्वारा शोषण एक अत्यधिक गभीर प्रश्न है क्योंकि खानो से निकलने वाली सामग्री के चुक जाने पर उनको फिर से चालू करना सम्भव ही नहीं है।<sup>68</sup> विदेशिया द्वारा लूटे जाने की अपेक्षा अच्छा यही है कि खानो की संपदा खानो मे ही दबी तथा अविकसित बनी पडी रहे ताकि कालांतर मे भारतीय स्वयं उसका सदुपयोग कर सकें।<sup>69</sup> आलाचको का कथन था कि एक वास्तविक भारतीय सरकार से कम से कम इतने आवश्यकता की अपेक्षा तो की जा सकती थी।<sup>70</sup> इसी प्रकार बागान उद्योग भी धरती की उर्वरता को समाप्त करते जा रहे थे।<sup>71</sup> इन उद्योगो के सबध मे तो जी० वी० जोशी की टिप्पणी यह थी कि इनके द्वारा भारतीयों के प्रति अतिरिक्त अन्याय हुआ है क्योंकि प्रथम, राज्य ने सरकारी व्यय से अधिकांश बागान का विकास किया है और पुन क्षतिपूर्ति किए बिना ही ये उद्योग विदेशियों को सौंप दिए गए हैं। उन्हें यहां पर भूमि भी नाममात्र की दरों पर दी गई है। वस्तुतः इन उद्योगो पर बहुत थोडी सी ही विदेशी पूजी का निवेश हुआ है। य उद्योग सामान्य रूप मे भारतीय उद्यमियों को ही सुविधापूर्वक सौंपे जा सकते हैं।<sup>72</sup>

भारतीय नेताओं की दृष्टि मे विदेशी पूजी के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले आर्थिक खतरे के साथ साथ राजनीतिक खतरा भी था।<sup>73</sup> इस आलोचनापरक दृष्टिकोण का आधार यह विश्वास था कि विदेशी पूजी द्वारा किसी देश मे घुसने का अर्थ उस देश का राजनीतिक दमन है अथवा जिस प्रकार रानाडे नबहा व्यावसायिक तथा उत्पादन विधि पटता स्वभावतः ही राजनीतिक प्रभुत्व मे परिवर्तित हो जाती है।<sup>74</sup> यह सकारण सबध इस तथ्य से भी सिद्ध था कि विदेशी पूजी समय के साथ साथ निहित स्वार्थों एवं प्रबल विदेशी अभिमान तंत्र को जन्म देती है<sup>75</sup> जो देश की प्रणामनिक नीतियों पर निरंतर बढ़ते प्रबल प्रभाव को दृढ़ बनाने का काय करता है।<sup>76</sup> 'हिंदू' ने अपने 23 मिनट

1889 के अक मे लिखा कि जिस देश मे विदेशी पूजी लगने लगती है, उस देश का प्रशासन तत्काल समृद्ध तत्वों के हाथ मे चला जाता है।

भारतीय नेताओं की चिंता यह थी कि भारत जैसे पहले से ही विदेशी प्रशासन से अधिकृत देश मे यह राजनीतिक सतरा और कई गुना बढ जाता है। इस प्रकार की स्थिति मे विदेशी निहित स्वार्थों से प्रेरित होकर देशवासियों की न्यायोचित राजनीतिक आकांक्षाओं के प्रति शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हैं तथा उनकी राजनीतिक उन्नति के माग का रोडा बनते हैं।<sup>77</sup> 23 सितंबर 1889 के अक मे हिंदू ने विलक्षण राजनीतिक दूरदर्शिता से यह भविष्यवाणी की कि यदि राजनीतिक सुधारों की अवधि मे देश मे विदेशी पूजीपतियों के प्रभाव को बढने दिया गया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सफलता के अवसरों को नमस्कार करना पड़ेगा क्योंकि उसका स्वर विदेशी पूजीपतियों के, 'साम्राज्य खतरे मे है', के भयकर गजन मे दबकर रह जाएगा।<sup>78</sup> कालांतर मे जब कजन के शासनकाल मे राजनीतिक प्रतिक्रिया इतनी अधिक उग्र हो गई कि उसे लगभग प्रत्येक भारतीय जन नेता अनुभव करने लगा, तब मुरेंद्रनाथ बैनर्जी के 'बंगाली' ने अवसरोचित टिप्पणी की इस प्रतिक्रिया का मूल भारत मे विदेशी पूजी द्वारा प्रयुक्त प्रभाव ही है।<sup>79</sup> तथ्यात्मक दृष्टि से देखें तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ मे ही भारतीय नेताओं ने यह भली प्रकार समझ लिया था तथा स्पष्ट निर्देश किया था कि भारत सरकार और भारत के ब्रिटिश पूजीपतियों म साथ गाठ है तथा भारत सरकार ब्रिटिश पूजीपतियों के हिता के अधीन है। इस दृष्टिकोण का 1903 मे उस समय शचींद्रनाथ सिंह द्वारा संपादित, इलाहाबाद के 'इंडियन पीपुल' ने बड़ी स्पष्टता तथा प्रबलता के साथ प्रस्तुत किया

लाड कजन के साक्ष्य पर अंगरेजों का प्रशासनिक काय केवल शोपका के शोपण काय मे उनकी चाकरी करना है। बिना कुशल प्रशासन के व्यापार फल फूल नहीं सकता और व्यापार के लाभरहित होने पर प्रशासन, प्रशासन नहीं कहला सकता। भारत सरकार सदैव वाणिज्य सदन की स्वीकृति तथा अधिकांशतः उसके आदेश के अनुसार ही काय करती है और यह गोरो के 'दायित्व' का रहस्य है।<sup>79</sup>

और यहा तक कि रानाडे ने भी टिप्पणी की कि विदेशी आर्थिक प्रभुत्व ने विदेशी राजनीतिक प्रभुत्व को और अधिक द्वेषजनक बना दिया है।<sup>80</sup>

बहुत सारे भारतीय नेता समस्या के दूसरे पक्ष से भी अभिज्ञ थे कि यह मूलतः विदेशी शासन ही था जिसके कारण इस देश मे विदेशी पूजी ने एक बढ भारी रोग का रूप ले लिया। यदि भारत एक स्वतंत्र देश होता, तो वह अमरीका जैसे स्वतंत्र देश के समान संपत्ति की निकासी से मुक्त होता, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपने ससाधनों के विकास के लिए स्वतंत्र होता, समान शर्तों पर विदेशी पूजी से प्रतियोगिता के लिए स्वतंत्र होता, विदेशी पूजी से अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर उस अपदस्य करने मे स्वतंत्र हाता तथा उसका एक ऐसा स्वतंत्र प्रशासन होता जो स्वदेशी उद्यम को सहायता तथा प्रोत्साहन देता और यह देखता कि विदेशी पूजी का प्रयोग स्वदेशी उद्यम के विकास मे पूरक और सहायक सिद्ध हो।<sup>81</sup>

अधिकांश भारतीय नेता विदेशी पूजी के नियोजन के राजनीतिक तथा आर्थिक



प्रतिघातो के अध्ययन के परिणामस्वरूप इस तथ्य पर सहमत थे कि भले ही भारत को विदेशी पूँजी की आवश्यकता हो परंतु उसे विदेशी पूँजीपतियों की तो कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने ऋण पूँजी तथा औद्योगिक पूँजी के अंतर को समझा था तथा उसे रेखांकित किया था।<sup>82</sup> जहाँ औद्योगिक पूँजी उद्यम के सारे लाभों को हड़प लेती है तथा सारे क्षेत्र पर एकाधिकार जमा लेती है।<sup>83</sup> वहाँ ऋण पूँजी ब्याज के रूप में केवल एक निश्चित तथा निर्धारित राशि की ही अधिकारी होती है। इस प्रकार वह अवशिष्ट लाभों, और मूल धन की अदायगी के पश्चात्, सारे लाभों को उस देश में ही रहने देती है। इस प्रकार आवश्यकता होने पर स्वदेशी उद्यम के विकास के लिए विदेशी पूँजी उधार लेना तथा विदेशी तकनीकी लोगों से काम लेना तो बुरा नहीं, परंतु सीधे विदेशी निवेश की तथा सीधे विदेशी पूँजीपतियों द्वारा अपने स्वामित्व के उद्योग के संचालन को अनुमति बंदापि नहीं देनी चाहिए।<sup>84</sup> दादाभाई नौरोजी का कहना था कि भारत का विदेशी पूँजी की उल्टी आवश्यकता है न कि उसकी पूँजी और उत्पादकों को हड़पने वाले अंगरेजी धावों की।<sup>85</sup>

इस दृष्टिकोण में दो दोष थे। भारतीय पूँजीपतियों के पास अधिकांश बड़े पमानों के नए उद्योगों, खानों तथा परिवहन संस्थानों के संचालन के लिए न तो पर्याप्त पूँजी थी और न ही विदेशी पूँजी बाजार में वांछित निधि के ऋण लेने की अपेक्षित साक्ष्य। इस स्थिति में विदेशी पूँजीपतियों को व्यक्तिगत रूप से इस दश में आने तथा अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र का स्वामित्व संभालने से किस प्रकार रोका जा सकता था? इस समस्या का राष्ट्रीयकरण के रूप में एक संभव नवीन उत्तर देने के लिए 19वीं शताब्दी के प्रमुखतम नेता, दादाभाई नौरोजी तथा जी० वी० जाशी आगे आए। उन्होंने 60 वर्ष पीछे स्वतंत्र भारत की सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले मांग को अपनी उल्लेखनीय मूढ़ दृष्टि से उस समय ही देख लिया था। उनका सुभाव था कि विदेशी पूँजी के हानिप्रद आर्थिक तथा राजनीतिक दुष्परिणामों से बचकर उससे लाभान्वित होने का एकमात्र उपाय उन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण था, जिनके लिए अपरिमित विदेशी धनराशि अपेक्षित थी। इस प्रकार की स्थिति में सरकार अपने राजस्वों की गारंटी पर ब्याज की थोड़ी दर पर विदेशों से पूँजी ऋण में ले सकती है तथा उसका देश के प्राकृतिक संसाधनों के विकास के लिए उपयोग कर सकती है।<sup>86</sup> यहाँ यह भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि उस समय राष्ट्रीयकरण की कल्पना केवल विदेशी पूँजीपतियों के प्रवेश को रोकने के उपाय के रूप में की गई थी। इसके सिवाय उनका समाजवाद के प्रवर्तन जसा कोई अन्य उद्देश्य नहीं था। वस्तुतः सरकारी पूँजीवाद तब तक के लिए एक अंतरिम तथा अस्थायी उपाय था जब तक कि भारतीय उद्यमी इस पर्याप्त सीमा तक जागरूक तथा विवक्षित नहीं हो जाते कि इन उद्योगों को स्वदेशी पूँजीपतियों के हाथों में ही सौंपा जा सके।<sup>87</sup>

निष्पत्त उपयुक्त विवेचन में हम इन परिणामों पर पहुँचते हैं प्रथम, विदेशी पूँजी के उपयोग के समयक अथवा विरोधी भारतीय राष्ट्रवादी नेता भारत में विदेशी निवेश के आर्थिक तथा राजनीतिक कारणों तथा परिणामों के प्रति अत्यंत जागरूक थे। द्वितीय, सभी राष्ट्रवादी नेताओं का दृढ़ विश्वास था कि दश का वास्तविक औद्योगिक विकास दश के अन्त में प्रयत्नों तथा अपनी पूँजी पर निर्भर था। विदेशी पूँजी के प्रयोग के समयकों का

भी स्पष्ट मत यह था कि देश के सवथा अनुद्योगीकरण जैसी अपेक्षाकृत बड़ी बुराई की तुलना में उद्योगीकरण के लिए विदेशी पूँजी के निवेश की छोटी बुराई अपनाना ही अच्छा है। अधिकांश नेता तो विदेशी पूँजी के साधन द्वारा देश के औद्योगिक विकास के निष्पादन की अपेक्षा उसके स्थगन के ही पक्षधर थे। इस प्रकार समीक्षाधीन काल के राष्ट्रीय आन्दोलन की अवधि में दलाल पूँजीवादी के दृष्टिकोण का 'यूनाधिक' रूप से अभाव ही था। यहाँ यह भी भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि सभी राष्ट्रवादियों में समवेत स्वर में औद्योगिक पूँजी के विकास का समर्थन किया था, न कि व्यापारिक पूँजी के विकास का। तृतीय, विदेशी उद्योगों के द्रुत विस्तार के कारण रेलवे आदि ने परोक्ष रूप से भारतीय उद्योग के विकास को प्रोत्साहन दिया था। दोनों में श्रुता अभी महत्वपूर्ण अथवा निर्णायक नहीं बन पाई थी। उदाहरणार्थ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस प्रश्न पर पूर्णतः मौन ही रही। 1885-95 की अवधि के अधिवेशनों में उसने इस प्रश्न पर न तो विचार विमर्श किया और न ही इस पर कोई प्रस्ताव पारित किया तथा न ही सभापति पद से दिए गए किसी भाषण में इसका स्पष्ट उल्लेख हुआ। इस विषय पर कांग्रेस की ओर से प्रथम भाषण 1898 के अधिवेशन में जी० एस० अय्यर का था। हाँ, 20वीं शताब्दी के उदय के साथ ही भारतीय औद्योगिक प्रयास बाल्यकाल से आगे बढ़ने लगे तथा विदेशी पूँजीपतियों से जिन्हें अपने उद्यम का लार्ड कजल जैसा प्रबल उन्नायक तथा शक्तिशाली वकील मिल चुका था, सघप करने लगे। इसके फलस्वरूप 1900 के पश्चात् राष्ट्रवादी समाचारपत्र तथा कांग्रेस मंच से वक्ता विदेशी पूँजी पर निरन्तर तीव्र प्रहार करने लगे।

## II राज्य की भूमिका

भारतीय उद्यमी वर्ग के ज्ञान, शक्ति तथा पूँजी के अभाव की तथा उद्योगीकरण के मार्ग की प्रारम्भिक कठिनाइयों पर काबू पाने में सुरक्षा तथा सहायता के अभाव की पूर्ति राज्य की सहायता और सहयोग से ही कदाचित् संभव थी। अतः भारतीय नेता उद्योगीकरण की प्रक्रिया में राजकीय सहायता के प्रखर समर्थन में 'यूनाधिक' रूप से एकमत ही थे।<sup>88</sup> उनका यह दृढ़ विश्वास था कि औद्योगिक प्रयास के प्रत्येक क्षेत्र तक प्रसृत सरकारी सहायता की व्यापक नीति के बिना तथा स्वदेशी तथा आधुनिक दोनों औद्योगिक उद्यमों की प्रत्येक रूप और दिशा में प्रगति सबधी सरकार की प्रत्यक्ष, सूझबूझवाली तथा सहानुभूतिपूर्ण नीति के बिना देश की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती। यद्यपि भारतीय अर्थशास्त्री नेताओं ने इस दृष्टिकोण का विस्तृत विवरण सरकार के सामने काफी देर के बाद प्रस्तुत किया तथापि देश के उत्पादकों और वाणिज्य की प्रोत्साहन देने की माँग को सवप्रथम 1853 में कलकत्ता की ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की घोषणा के नवीकरण के समय हाउस आफ कामस की निवेदित प्रज्ञप्ति में प्रस्तुत किया।<sup>89</sup> 1891 में पूना में आयोजित द्वितीय औद्योगिक सम्मेलन में निजी उद्योग को सरकार द्वारा सीधे वित्तीय तथा अन्य सहायता देने की माँग प्रस्तुत की गई।<sup>90</sup> कांग्रेस ने 1902 में स्वदेशी कला और उत्पादन के उद्धार तथा विकास के लिए तथा नए उद्योग लगाने के लिए सरकारी प्रोत्साहन की माँग की।<sup>91</sup> अन्य भारतीय नेताओं में कदाचित् जी० वी० जोशी और रानाडे इस नीति के

सबसे पहले तथा मुखर समयक थे।<sup>90</sup> इस अवधि में जी० सुब्रह्मण्यम के शब्दों में मीजी की वापसी के बाद आधुनिक उद्योग के प्रोत्साहन में जापानी सरकार की भूमिका भारतीय अर्थशास्त्री नेताओं के लिए अत्यधिक रोचक तथा आकर्षक सिद्ध हुई<sup>91</sup> और उन्होंने भारत सरकार से इसकी प्रतिस्पर्धा करने का अनुरोध किया।<sup>91</sup>

भारतीय राष्ट्रवादियों ने औद्योगिक प्रयासों में सरकारी हस्तक्षेप की मांग की तथा उनकी भारतीयों के स्वामित्व के उद्योगों के प्रति भारत सरकार के सैद्धांतिक और व्यावहारिक बरतों के बारे में सरकार के साथ सीधी टक्कर हुई। ब्रिटिश शासकों ने अपने को तटस्थता सिद्धांत का अनुयायी बताते हुए उस समय यह मत अभिव्यक्त किया कि औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने में सरकार अयोग्य है, अतः सभी ऐसे मामलों में निजी उद्यमियों पर ही छोड़ देने चाहिए।<sup>92</sup> इस प्रकार समीक्षाधीन अवधि के दौरान उद्योगों को प्राप्त सरकारी सहायता नगण्य सी ही थी। इस सहायता के दो रूप थे तकनीकी शिक्षा की सहायता अपर्याप्त व्यवस्था तथा टूटे मन से औद्योगिक जानकारी के संचय तथा प्रसार की चेष्टा।<sup>93</sup> इस क्षेत्र में सरकार के और अधिक प्रत्यक्ष तथा ऊजस्वी योगदान की मांग करने वाले भारतीयों को अपने आपको औद्योगिक प्रयासों के प्रबल समयक मानने वाले लाइफ जन ने बुरी तरह से इन शब्दों में लताड़ा वतमान सरकार अथवा अन्य कोई भारतीय सरकार जादू की छड़ी घुमाकर ही इस विस्तृत देश की आर्थिक, सामाजिक तथा औद्योगिक स्थितियों में शक्ति ला सकती है।<sup>94</sup>

भारतीय अर्थशास्त्रियों ने इस बारे में भारत की नीति की दिशा बदलने की चेष्टा की। उनका विश्वास था कि इस नीति का दृढ़ता से पालन करने का एकमात्र कारण शासकों का क्लामिकी राजनीतिक अव्यवस्था में विश्वास व इसका अनुसरण ही था। अतः उन्होंने तटस्थता सिद्धांत की सरकारी कार्यक्षेत्र में व्यावहारिकता पर विशेषतः भारत जैसे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश के सदर्भ में, कटु सैद्धांतिक प्रहार करने आरंभ कर दिए। तटस्थता सिद्धांत के विरुद्ध किए गए सैद्धांतिक प्रहारों का विस्तृत विवरण इस पुस्तक के एक अगले अध्याय में प्रस्तुत किया गया है।

इसके अतिरिक्त तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी महान प्रतिभाशाली अर्थशास्त्री नेता रानाडे न भारतीय शासकों के वतमान तथा भूतकालीन आचरणों को उनकी सैद्धांतिक मायताओं के विरुद्ध बताया। उन्होंने यह निर्देश किया कि विगत वर्षों में सरकार ने औद्योगिक तथा व्यावसायिक उद्यमों के प्रवर्तन तथा उनमें मजदूरों के प्रति भारत में ब्रिटिश पूंजीपतियों को अतिरिक्त विशेषाधिकार प्रदान करने में प्रत्यक्ष तथा सक्रिय भाग लिया है।<sup>95</sup> सरकार ने सर्वप्रथम रेल कंपनियों को सरकारी तौर पर गारंटी प्रदान की और बाद में सरकारी रेलों के निर्माणकार्य को अपने हाथ में लिया।<sup>96</sup> सरकार ने ही भारत में सरकारी मर्चें पर और बड़े महंगे दामों पर कुनीन, चाय तथा काफी के पौधे उगाने के लिए चांगान उद्योगों का प्रारंभिक प्रवर्तन किया है।<sup>97</sup> सरकार ने लोहा उद्योग की उन्नति के लिए उम अनुकूल रियायतें देने के अतिरिक्त भूगर्भीय सर्वेक्षण, प्रयागात्मक परीक्षण तथा उत्पादनों के रूप में राज्य की भारी धनराशि खर्च की है।<sup>98</sup> उनमें अपनी दृष्टि में कितनी ही शोषणा मानो पर लंबे समय तक काम किया है।<sup>99</sup> इन प्रकार

सरकारी सहायता का सिद्धांत तो व्यावहारिक रूप से मान्यता प्राप्त है। समझ नहीं आता कि उसी प्रकार की सहायता अब अयाय औद्योगिक उद्यमों को प्रदान क्यों नहीं की जाती? इस समय किसी नए सिद्धांत के प्रस्थापन की आवश्यकता नहीं, प्रत्युत इस तथ्य के निर्धारण की आवश्यकता है कि किस प्रकार के उद्योगों को राजकीय सहायता प्रदान की जाए। गत वर्षों के समान वागान और परिवहन साधनों को बढ़ावा देने के स्थान पर अब देश में आधुनिक उत्पादक उद्योगों के प्रोत्साहन में सरकारी सहायता का और अधिक लाभदायक ढंग से प्रयोग किया जा सकता है।<sup>103</sup>

उद्योगों को सरकारी सहायता और प्रोत्साहन के कई भिन्न भिन्न प्रकार के रूप हो सकते हैं। उनमें से अधिक महत्वपूर्ण की, जिनके आवश्यकतानुसार एकल अथवा संयुक्त रूप से ग्रहण के लिए बहुत सारे भारतीय नेताओं ने बकालत की, संक्षिप्त समीक्षा निम्न लिखित है

भारतीयों की दृष्टि में भारत के औद्योगिक विकास की प्रबलतम बाधाओं में से एक भारतीय औद्योगिक उद्यमियों के पास अपेक्षित पूंजी का अभाव था अतः उन्होंने उपलब्ध व्यापारिक तथा साहूकारी पूंजी को औद्योगिक पूंजी में बदलने के लिए सरकारी सहायता की प्रबल आवश्यकता की मांग की। इस महत् कर्म के संपादन के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाया जा चुका था। प्रथम, ऋण प्रणाली को आधुनिक रूप में पुनर्गठित करना होगा ताकि देश के आंतरिक परंतु बिखरे हुए उपलब्ध साधनों को गतिशील बनाया जा सके।<sup>104</sup> यह तक भी प्रस्तुत किया गया कि ऋण प्रणाली का निजी विकास ऋणदाता तथा ऋणकर्ता के आपसी विश्वास पर निर्भर है अतः उसकी प्रक्रिया का अत्यंत मद होना निश्चित ही है। देश की विशाल धनराशि की तथा सावदेशिक साख और विश्वास की एकमेव पात्र होने के कारण सरकार जमा और निक्कासी करने वाले बकों का सरकारी संरक्षण अथवा गारंटी देकर बचत करने वालों और उधार लेने वालों के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित करने में अपनी साख तथा अभिकरण का उपयोग कर सकती है।<sup>105</sup> राज्य के निर्देशन तथा नियंत्रण में कार्य करने वाले संयुक्त पूंजी-बकों का बहुत बड़ा जाल बिछाने की आवश्यकता थी।<sup>106</sup> इस कार्य में सरकार का एक पैसा भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं। उसे केवल बकों को ऋण उगाहने की सुविधाएं जुटाना मंडलीय शेष राशि का उपलब्ध कराना तथा नियंत्रक लेखा परीक्षा की व्यवस्था करना है।<sup>107</sup> इसमें भी अधिक अच्छा यह है कि सरकार स्वयं प्राइवेट पूंजीपतियों को अपनी उचित देखरेख में व्याज की घाड़ी दर पर अग्रिम ऋण देने की व्यवस्था करे।<sup>108</sup> इसके लिए सरकार धन उधार ले सकती है अथवा बचत खातों पर निर्भर कर सकती है।<sup>109</sup> इस संबंध में रानाडे ने एक रायच सुझाव यह दिया कि सरकार अथवा स्थानीय समितियां विशिष्ट वित्त निगमों की स्थापना करें। ये निगम सरकार से सस्ती दर पर रुपया उधार लें तथा भावी उद्योग पतियों को अग्रिम ऋण प्रदान करें।<sup>110</sup> इसके अतिरिक्त सरकार रेल कंपनी के प्रति अपनाई सहायता की नीति के समान आधुनिक उद्योगों के प्रति अपनी नीति निर्धारित कर सकती है तथा पूंजी जुटाने वाले भारतीयों को न्यूनतम निश्चित व्याज चुपाने की गारंटी देकर उन्हें नए उद्योगों में पूंजी लगाने को प्रेरित कर सकती है।<sup>111</sup> सरकार दोनों

के समान भारतीय पूँजीपतियों को विदेशी बाजार से ऋण लेने में गारंटी दे सकती है<sup>112</sup> तथा सस्ते ऋणों की प्राप्ति के प्रतिफल के रूप में सरकार औद्योगिक व्यवस्था के दखलाल और नियंत्रण की शक्ति प्राप्त कर सकती है। कालांतर में तो लाभों की भागीदार बन सकती है।<sup>113</sup> सरकार से तो इसमें भी और आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार कहा गया कि सरकार जम और शैशवकालीन प्रारंभिक कठिनाइयों से जूझते हुए पनपन वाले उद्योगों की अनुग्रहो अनुदानों के रूप में सीधे ही सरकारी ऋण से सहायता करे<sup>114</sup> ताकि वे उद्योग अपनी कठिनाइयों पर काबू पा सकें तथा अपने पैरों पर खड़े हो सकें।<sup>115</sup>

भारतीय नेताओं का सरकार से दूसरा अनुरोध सरकारी तथा रेल भंडारों की त्रय सत्रधी नीति के पुनर्निर्धारण का था। भारत में आयातित कुल उत्पादन सामग्री का उल्लेखनीय भाग इन भंडारों में था। आयातित सामग्री में ये वस्तुएँ सम्मिलित थीं: भारतीय सेना तथा पुलिस के उपयोग के उपकरण, नगर सुधार की सामग्री, जल, गैस, मलमूल व्यवस्था, मैट्रिकल स्टोरो तथा हस्पतालो के उपयोग की सामग्री, गोदी, पुलो बिल्डिंगो तथा सड़कों के बनाने के लिए लोहा तथा सीमेंट, तार तथा टेलीफोन के लिए अपेक्षित सामान, प्रशासन के उपयोग में आने वाली स्टेशनरी तथा अन्य वस्तुएँ। इन सबसे बढ़कर और अधिक सामान था रेलों की पटरियाँ, पुल, गाड़ी के डिब्बे तथा रेलों के लिए भवन निर्माण की सामग्री। इन भंडारों के लिए थोड़े बहुत नगण्य सामान को छोड़कर प्रायः सारा ही सामान इंग्लैंड से खरीदा जाता था। फलतः भारतीय नेताओं की शिकायत थी कि सरकार की भंडारों की ऋयनीति भारतीय उत्पादकों के प्रति विद्वेषपूर्ण थी तथा ब्रिटिश उत्पादकों को सहायता पहुँचाती थी। उनका तर्क था कि सरकार इन भंडारों के लिए भारतीय उत्पादकों से माल खरीद कर भारतीय उत्पादकों के लिए लाभदायक दरों पर 'यूनितम सुरक्षित बाजार की गारंटी देकर भारतीय औद्योगिक प्रयत्नों को जबरदस्त प्रोत्साहन दे सकती है।<sup>116</sup> पर्याप्त रोचक तथ्य यह है कि इस मांग का समयन भारत में कायम कुछ एक ब्रिटिश पूँजीपतियों ने भी किया और इसे 1880 के अर्धकाल आयाग का, लाड रिपन की सरकार का तथा 1916-18 की अवधि के भारतीय उद्योग आयाग का भी अनुमोदन प्राप्त हुआ।<sup>117</sup> अतः इसका परिणाम यह निकला कि भारत स्थित फर्मों में भी माल खरीदा जाने लगा। इसके फलस्वरूप 1898 में लखनऊ के 'हिंदुस्तान' न सरकार की भारत स्थित भारतीयों की फर्मों की उपेक्षा तथा यूरोपीयों के स्वामित्व की फर्मों से माल खरीदने की प्रवृत्ति का विरोध किया।<sup>118</sup>

भंडारों की सभी वस्तुएँ भारत में उपलब्ध नहीं अथवा उत्पादित नहीं होतीं इस आपत्ति का उत्तर कुछ एक भारतीय नेताओं ने और भी अधिक मौलिक सुभाव के रूप में इस प्रकार दिया कि सरकार स्वयं इन वस्तुओं का उत्पादन करे।<sup>119</sup> अतः भारतीय सरकार ने यह सुभाव तथा सरकार द्वारा प्रत्यक्ष उद्यम का अपनाते का और इस प्रकार तटस्थता की नीति के परित्याग का सुभाव एक अन्य आधार पर भी दिया। उनका सुभाव था कि नए उद्योगों के प्रारंभ करने में असम्य विषय प्रकृतितगत कठिनाइयों के कारण सरकार को आगे आना चाहिए तथा उनकी व्यावहारिक उपयोगिता तथा लाभकारी चरित्र की जाँच करते हुए प्रारंभिक कठिनाइयों पर<sup>120</sup> काबू पाकर उद्यम का मांग प्रशस्त करना

चाहिए तथा निजी उद्यमियों को इस कार्य में प्रवृत्त होने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए।<sup>1</sup>

भारतीय नताओं द्वारा भारतीय उद्योगों की उन्नति के लिए सरकार को मुक्त गये अन्य महत्वपूर्ण उपाय थे वाणिज्य और उत्पादन के एक पृथक विभाग की स्थापना<sup>2</sup> - जिसे उपलब्ध साधनों<sup>3</sup> को जुटाने की, सरकार और निजी कंपनियों की विशेषज्ञता के ज्ञान तथा शीघ्रता में सहायता करने व परामर्श देने की, सर्वेक्षण आदि के द्वारा जानकारी के संग्रह तथा उसके व्यापक प्रसार की, सुलभ-व्ययिता में सरलण प्रदान करने की, मशीनरी पर निर्यात शुल्क हटाने की तथा तनवीवी शिक्षा को प्रोत्साहन देने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो।<sup>4</sup> उद्योगीकरण की प्रक्रिया में राजकीय प्रोत्साहन की भारतीयों की मांग उम समय अपने चरम पर पहुँच गई जब 1904 में गोपालकृष्ण गोखले ने कुछ एक राजकीय आर्थिक योजनाओं की कालत की। उम वष के अपने वजट भाषण में उन्होंने कहा, वास्तव में परिस्थितियों की मांग यह है कि पूर्ण विदेश तथा दूरदृष्टि का उपयोग करत हुए जनता की नैतिक तथा भौतिक उन्नति के लिए व्यापक तथा विस्तृत योजना बनाई जाए और फिर उमपर दृढ़ता तथा निरंतरता के साथ अमल किया जाए तथा लगभग वष प्रतिवष उसकी प्रगति की पूरी समीक्षा की जाए।<sup>5</sup>

औद्योगिक प्रयासों में सरकारी सहायता की मांग में उल्लेखनीय स्पष्टता को देखते हुए इस तथ्य को नहीं भूल जाना चाहिए कि निष्पक्ष रूप में इस मांग को प्रधान रूप से तो भारतीय नताओं में अर्थशास्त्रियों ने ही अभिव्यक्त किया। उस समय राष्ट्रीय समाचारपत्र तथा कांग्रेस के अधिवेशन में सामान्य रूप में इस बात की जोरदार मांग नहीं की गई। स्पष्टतः इस लाभकारी मांग के लिए उत्साहपूर्ण चेष्टा के अभाव का कारण यह व्यापक सदृश था कि क्या एक विदेशी सरकार, चाहे वह कितनी भी उदार क्यों न हो, अपने देश के उत्पादन के हितों के विरुद्ध जाने वाली कोई नीति अपनाएगी? उदाहरणार्थ जी० वी० जोशी द्वारा जनवरी 1890 के 'पूना सावजनिक सभा' जनरल में प्रकाशित एक लेख 'इकानामिक सिचुएशन इन 'इंडिया' में विश्लेषित राज्य की आर्थिक भूमिका का समर्थन करने हुए हिंदू ने अपने 3 फरवरी 1890 के अंक में पंजी अतदृष्टि में लिखा

स्वदेशी उद्योगों के प्रत्यक्ष विकास के लिए उन्हें यथासंभव किमी भी मूल्य पर कोई प्रोत्साहन न देकर उन्हें अवनत बनाए रखना ब्रिटिश राष्ट्र के हित में ही है। ब्रिटिश शासक भारत की अधीनता के फलस्वरूप एक सबसे बड़े लाभ की आशा करते और उस यथाथ में प्राप्त करते हैं कि भारत उन्हें अपने औद्योगिक उत्पादन की खपत के लिए एक असीमित बाजार जुटाता है। इस प्रकार की परिस्थिति में पूना के नेताओं के सुझाव के अनुरूप सरकार से कुछ भी करने की आशा की सम्भावना नहीं है।

31 मई 1890 के अंक में बगबासी ने इस तथ्य को और भी स्पष्ट रूप दिया

<sup>1</sup> निस्संदेह स्वदेशी उद्योगों के उद्धार और विकास के लिए सरकारी सहायता अति आवश्यक है परंतु क्या उस सरकार से भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने की आशा

की जा सकती है जो न केवल विदेशियों की है, विरोधी धर्म वालों की है प्रत्युत उन लोगों की है जो स्वयं उत्पादक और व्यवसायी हैं? तथ्य यह है कि अगरज उत्पादक भारतीयों द्वारा स्वदेशी उत्पादन की अत्यंत साधारण वस्तुओं के प्रयोग को भी फूटी आंख नहीं देख सकते और वस्तुतः वे तब तक चैन नहीं लेंगे जब तक भारत में उत्पादित पदार्थों को भारतीय बाजार से बाहर न फिकवा दें। और यह अंगरेज उत्पादक ही अंगरेजी राष्ट्र हैं, जिनका हित अथ सत्के हितों में ऊपर है। इस हित की देखभाल और सुरक्षा ही अंगरेजी कूटनीति का उद्देश्य है।<sup>16</sup>

भारतीय लोकमत के अथ अनेक प्रवक्ताओं ने भी इसी प्रकार के सदेह प्रकट किए।<sup>17</sup> इन सदेहों का आधार उस समय ब्रिटिश विचारधारा पर आधिपत्य जमाए हुई औपनिवेशिक अर्थनीति के चरित्र का तथा ब्रिटिश की भारत में वास्तविक राजनीतियों का अध्ययन था। उनके अनुसार अपनी कथनी के प्रतिकूल व्यवहार करते हुए ब्रिटिश भारतीय सरकार व्यवहार में न केवल भारतीय उद्योग की सहायता में असफल रही है प्रत्युत उसने विदेशी प्रतियोगियों—जिन्होंने यहाँ के उद्योगों को आमूल चल नष्ट भष्ट कर दिया है—को सहायता देकर उसे हानि भी पहुँचाई है।<sup>18</sup> यह तथ्य उनके भय की सर्वोत्तम संपुष्टि करने वाला था।

### स्वदेशी

भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा देश की बढ़ती दरिद्रता को रोकने तथा परंपरागत और आधुनिक उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उपायों में वर्षों तक स्वीकृत तथा समर्थित एक उपाय था स्वदेशी की भावना का प्रचार प्रसार। स्वदेशी आंदोलन का अर्थ था भारत निर्मित सामग्री के प्रयोग को प्रोत्साहन देना तथा विदेशी माल न खरीदना, उसका परि त्याग और यहाँ तब कि उसका बहिष्कार। यद्यपि आधुनिक भारत के इतिहास में स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध अखिल भारतीय आंदोलन के समय उल्लेखनीय सफलता मिली तथापि स्वदेशी भावना की तत्काल तथा विस्तृत स्वीकृति के लिए तथा आन्दोलन की उस विशिष्ट घटना में मिली प्रभावशाली सफलता के लिए सा दशाब्दिका से ही उपयुक्त ढोंग प्रस्तुत किया जा रहा था। वस्तुतः स्वदेशी भावना और स्वदेशी आंदोलन दोनों उतने पुराने हैं जितनी कि स्वयं उदीयमान राष्ट्रीय चेतना। सत्त्व भाव से और अत्यधिक अव्यवस्थित तथा विच्छिन्न रूप से पनपे स्वदेशी आन्दोलन को अपने प्रारंभिक वर्षों में ही न केवल अपने समय की मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्थाओं का, प्रत्युत भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों तथा असंख्य अप्रतिबद्ध लोगों के स्थानांत प्रयासों का भी व्यापक समर्थन प्राप्त हो गया। इस विषय पर प्रामाणिक सामग्री की अत्यंत स्वल्पता के कारण इस आंदोलन के प्रारंभिक इतिहास का यहाँ मरिप्त विवरण कदाचिन् अनुचित न होगा।

1849 में ही 'प्रभाकर' पत्र के लेखकों में आयोजित सामान के स्थान पर भारतीय उत्पादों के प्रयोग का समर्थन करवा धान पूना के गणपाल राम दत्तमुण्ड भारतीय जनता के मर्तुभावा में एक प।<sup>19</sup> बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के इतिहास का सूत्रपात

नवगोपाल मित्र के प्रयासों से होता है जिन्होंने 1867 में एक हिंदू अथवा राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया, जो नियमित रूप से चौदह वर्षों तक प्रतिवर्ष लगता रहा। अथ राष्ट्रनिर्माण संबंधी गतिविधियों के अलावा इस मेले के प्रमुख उद्देश्यों में से एक भारतीय शिल्पकला के उत्पादनों की प्रदर्शनी लगाकर स्वदेशी उत्पादनों के प्रयोग का बढ़ावा देना था।<sup>130</sup> नवगोपाल मित्र को इस क्षेत्र में प्रवृत्त तथा यत्नशील होने की प्रेरणा राजनारायण मु से मिली। राजनारायण प्रारंभिक बंगाली राष्ट्रवादी नेताओं में आदरणीय शक्तिशाली व्यक्ति थे। वह विदेशी उत्पादनों के परित्याग तथा स्वदेशी वस्त्रों व अथ वस्तुओं के प्रयोग को प्रोत्साहन देने वालों में अग्रणी थे।<sup>131</sup>

उन्नीसवीं शताब्दी के आठवें दशक में स्वदेशी भावना का अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हो गई। 1870 में विश्वनाथ नारायण मित्र द्वारा संचालित नेटिव ओपीनियन ने देशप्रेम की भावना वाले लोगों में अनुरोध किया तथा उन्हें अपने देशवासियों में महंगे दाम पर भी स्वदेशी वस्तुओं के खरीदने का परामर्श दिया।<sup>132</sup> 1872 में रानाडे ने पूना में आर्थिक विषय पर एक सावजनिक भाषणमाला का आयोजन किया जिसमें उन्होंने स्वदेशी भावना को इस रूप में लोकप्रिय बनाया कि अपने देश के बने सामान भले ही विदेशी उत्पादनों से महंगे हों और उनकी अपेक्षा भले ही कम सतीषजनक हों, हमारे लिए उनको ही प्राथमिकता देना उचित है।<sup>133</sup> इन गौरवमंडित भाषणों ने श्रोताओं को इतना अधिक उत्तेजित किया कि उनमें से बहुतों ने जिनमें प्रमुख रूप से थे, गणेश वासुदेव जोशी<sup>134</sup> जो अपनी लोकप्रियता में सावजनिक रूप में 'बाबा' के नाम से प्रसिद्ध थे तथा पूना सावजनिक सभा के संस्थापक में तथा प्रधान सक्रिय कार्यकर्ताओं में अग्रणी थे और वासुदेव फडके ने जिन्होंने बाद में सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया था उत्साहित होकर केवल स्वदेशी वस्त्र धारण करने तथा एकमात्र स्वदेशी वस्तुओं के ही प्रयोग की वसम खाई।<sup>135</sup> जी० वी० जोशी अपनी धाती, कुरते और साफे के लिए प्रतिदिन स्वयं सूत कातते थे, उन्होंने स्वदेशी सामान को लोकप्रिय बनाने तथा उसका प्रचार करने के लिए अनेक स्थानों पर दुकानें खोली तथा 1873 के तड़क-भड़क और धूमधाम वाले दिल्ली दरबार में अपने हाथों की बनी रादी की वेशभूषा में ही सावजनिक सभा का प्रतिनिधित्व किया।<sup>136</sup> फडके महोदय भी समान रूप से स्वदेशी के प्रचार के दीवान थे। उन्होंने सैकड़ों युवकों को स्वदेशी प्रयोग की वसम खाने को तैयार किया।<sup>137</sup> 1873 में 'गम्ल गोप्लार' ने अपने 13 जुलाई के अंक में मराठी के 'निश्चय पत्रिका' अथवा 'जन प्रस्ताव पत्र' का गुजराती अनुवाद प्रकाशित किया जिसके संबंध में कहा जाता है कि वह अनेकानेक लोगों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होकर परिचलित किया जा रहा था। प्रस्ताव में लोगों का आह्वान किया गया था कि जो लोग अपने देश से प्यार करते हैं उन्हें देश के अपने उद्योगों के द्रुत विनाश को रोकने के लिए विदेशी सामग्री खरीदना बंद कर देना चाहिए तथा थोड़े-बहुत महंगे तथा स्तर में थोड़े-बहुत घटिया होने पर भी अपने देश के उत्पादन ही खरीदना चाहिए।<sup>138</sup> 'इंदु प्रकाश' के 23 अगस्त 1875 के अंक में भी इसी प्रकार के भाव अभिव्यक्त किए गए थे।<sup>139</sup> विपिनचरण घोष के अनुसार 1874 में नागपुर में गृहनिर्मित वस्तुओं के उपयोग की प्रोत्साहित करने के लिए एक संगठन प्रतिष्ठित म आ गया था।<sup>140</sup> उन्नीस वर्ष केवल भारत



में ही उत्पादित सूती सामान के व्यापार के लिए बंगलौर में एक कंपनी का गठन किया गया। कंपनी ने माचेस्टर के सामान का व्यापार करने का सकल्प किया।<sup>141</sup> अमृत बाजार पत्रिका के 6 जनवरी 1876 के अंक में राजकोट के एक पाठक ने लिखा 'हमने विदेशी सामान का इस्तेमाल न करने का सकल्प कर लिया है। हम एक ओर अंगरेजी सामग्री को अपदस्थ करने के साधनों की खोज का और दूसरी ओर जनता की स्वदेशी वस्तुओं के प्रति रूचि बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं।'<sup>142</sup>

'ए वाइस फार दि कामस एंड मैनुफैक्चर्स आफ इंडिया' शीपक से बंगाल में 1873-76 की अवधि में मुकर्जी की पत्रिका में प्रकाशित विस्तृत लेख में भोलानाथ चंद्र ने स्वदेशी के पक्ष में अपनी बुलंद आवाज उठाई। उन्होंने देशवासियों से अनुरोध किया कि वे विदेशी सामान की खरीद छोड़कर थोड़ी सी देशभक्ति का परिचय तो दें।<sup>143</sup> उन्होंने अपने देशवासियों के यूरोप में बने सामान के प्रति सामान्य उमाद को अराष्ट्रीय प्रवृत्ति बताते हुए उसकी भत्सना की। इस सबध में उन्होंने निर्देश किया

अब अपने राष्ट्र के प्रति अत्यंत झूठे और राष्ट्रीय उत्पादनो की गिरावट के लिए प्रेरक लोग हैं राजा, जमींदार, बाबू तथा हमारे बड़े बड़े कस्बों और शहरों के लोग। उत्कृष्टता तथा सस्तेपन की इच्छा वास्तविक इच्छा न होकर चापलूसी और बुद्धिब्यामोह ही अधिक है। इस व्यवहार का वास्तविक कारण यही है। उनके इस विश्वासघात को रूचि-परिष्कार कहकर क्षमा नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके इस आचरण से देश के सर्वोत्तम हितों को आघात पहुंचता है।

उन्होंने अपनी जाति की अप्रतिम दासवृत्ति तथा भ्रष्टता पर विलाप किया परंतु आशा प्रकट की कि सदा के लिए सवस्व समाप्त नहीं हो गया है। उन्होंने राजनीति, दूरदर्शिता, तक तथा बौद्धिक से अपने देशवासियों से विनष्ट समृद्धि की पुनः प्राप्ति के लिए नतिक विरोध के शस्त्र का प्रयोग करने के रूप में विदेशी सामान का बहिष्कार करने का अनुरोध किया।<sup>144</sup> उनके इस दृष्टिकोण के प्रतिपादक पूरे अवतरण को महा प्रस्तुत करते ही उस समझा जा सकता है

बल की गलतियां से जो हानि हुई है उसकी पूर्ति आज की बुद्धिमत्ता से की जा सकती है। किसी प्रकार के शारीरिक बल प्रयोग के बिना, किसी प्रकार के राजद्रोह के बिना तथा किसी प्रकार की सांविधानिक मकड़वालीन सहायता के लिए प्रायण के बिना ही, अपनी पूर्वस्थिति को पुनः प्राप्त करना संभव है। हमारे अपने ही हाथ में है। और कुछ नहीं केवल हमारी सक्रिय सहानुभूति न माचेस्टर के लक्ष्य का निम्न किया है। हमारी सहानुभूति यदि उनके विरुद्ध हो तो उतका परिणाम भी निश्चित ही विपरीत होगा। हमारे लिए एकमात्र परंतु अत्यंत प्रभावशाली नतिक विरोध के आसिरी शस्त्र का प्रयोग अपराध नहीं। हम अंगरेजी सामग्री के प्रयोग न करने के सकल्प रूप संशुद्ध शस्त्र का प्रयोग करना चाहिए और फिर देखिए कि इस प्रकार के सकल्प की प्रवृत्ति के पत्रस्वरूप गलत विषयों को किम तरह ठीक किया जा सकता है।<sup>145</sup>

75 में दावा के लोग पहले से ही नतिक विरोध के इस शस्त्र के प्रयोग का निम्न

तथा माचेस्टर के वस्त्रों के बहिष्कार का संकल्प कर चुके थे।<sup>146</sup> बंगाल के अनेक समाचारपत्रों ने अपने पाठकों में अंगरेजी वस्त्रों के प्रयोग को बंद करने तथा भारतीय मिलों को संरक्षण देने का अनुरोध किया।<sup>147</sup>

1880-1895 की अवधि के पंद्रह वर्षों में स्वदेशी की लहर देश में उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। जब भारत सरकार ने लकागायर के उत्पादन को सन्तुष्ट करने के लिए सूती कपड़ों पर आयात शुल्क हटा दिए तो सरकार की इस करनीति से स्वदेशी की लहर को बड़ा प्रोत्साहन मिला।<sup>148</sup> पश्चिमी भारत के लोगों में स्वदेशी उद्योगों के विनाश के विरुद्ध तथा अंगरेजी मशीनों से बने सामान के प्रयोग के विरुद्ध रचित लोकप्रिय गीत बहुत प्रचलित हो गए।<sup>149</sup> उस समय दश में एक शक्ति समझी जाने वाली अमृत बाजार पत्रिका ने 1881 में एक लोकप्रिय संगठन बनाने का प्रबल आह्वान किया ताकि भारत के बाहर उत्पादित सूती वस्त्रों के बहिष्कार का प्रचार करते हुए माचेस्टर की चुनौती का सामना किया जा सके। भारत के सभी प्रमुख नगरों में अपने शिष्टमंडल भेजिए भारत की सभी भाषाओं में इशतहार छापिए। उसी स्वदेशी आंदोलन के भावी विकास को बड़ी बुद्धिमत्ता से पहचने से ही देखते हुए यह मांग प्रस्तुत की कि विदेशी उत्पादनों के व्यापारियों के जाति बहिष्कार का प्रयत्न करना चाहिए।<sup>150</sup>

1881 में देशी उत्पादनों के प्रयाग को बढ़ाने के लिए इलाहाबाद में एक देशी तिजारत कंपनी शुरू की गई। मदनमोहन मालवीय इसके प्रमुख जन्मदाताओं में एक थे।<sup>151</sup> 18 अप्रैल 1883 के कोहेनूर के प्रतिवेदन के अनुसार लाहौर में वृत्तिपय शिक्षित भारतीयों ने 'इंडियन नेशनल एसोसिएशन' नामक एक संस्था की स्थापना की थी। इसके सदस्यों को एक लिखित शपथ ग्रहण करनी पड़ती थी जिसके अंतर्गत यथासंभव स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग उनके लिए अनिवार्य था।<sup>152</sup> अजमेर में भी इसी प्रकार की संस्था के संगठन की सूचना मिलती है।<sup>153</sup> 1890 में ढाका कालेज के छात्रों ने एक स्वदेशी भंडार खोला।<sup>154</sup> बंबई के विभिन्न भागों में अंगरेजी वस्त्रों के स्थान पर भारतनिर्मित वस्त्रों के प्रयाग के प्रचार के लिए असह्य जनसभाएं हुईं और इन बहुत सी सभाओं में नियुक्त प्रतिनिधियों ने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बंबई मिलमालिक संघ से सलाह और सहायता की याचना की।<sup>155</sup> देश के सभी भागों में भारतीय समाचारपत्रों ने भारतीयों से विदेशी माल का बहिष्कार करने का, एकमात्र भारतीय सामान के प्रयोग का, स्वदेशी उत्पादनों की बिक्री के लिए भंडार खोलने का तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोकप्रिय संघों के संगठित करने का प्रबल अनुरोध किया। उत्तर-पश्चिमी प्रांतों तथा अवध के अल्मोड़ा अखबार ने 1 मई 1882 के अंक में, 'नसीमे आगरा' ने 7 जून 1889 के अंक में 'रहबर' ने 16 जुलाई 1889 के अंक में, हिंदुस्तानी ने 11 अप्रैल 1894 के अंक में, पंजाब के 'इपीरियल अखबार' ने 9 फरवरी 1889 के अंक में, पंजाब पंच ने 30 जुलाई 1891 के अंक में, पैसा अखबार ने 10 अगस्त 1891 के अंक में, 'अखबारे आम' ने 18 जुलाई 1895 के अंक में, मद्रास से, 'आय जन पारपालिनी, ने 1 मितंबर 1889 के अंक में, बरार से 'बृहद समाचार' ने 22 जून 1891 के अंक में, बंबई से 'मराठा' ने 13 मार्च 1881 के तथा 8 जुलाई 1894 के अंक में, 'नेटिव ओपीनियन' ने 26 मार्च 1891 के अंक में,

'पूना वैभव' ने 10 मई 1891 के अंक में, 'हिंदू पत्र' ने 22 मार्च 1894 के अंक में, 'आर्योदय' ने 18 मार्च 1894 के अंक में, 'मादवत्त' ने 2 अगस्त 1894 के अंक में, बंगाल में 'सोम प्रकाश' ने 23 जनवरी 1882 के अंक में, 'आनंद बाजार पत्रिका' ने 27 मार्च 1882 के अंक में, 'भारत मिहिर' ने 16 मई 1882 के अंक में, 'सर्जोवनी' ने 14 जून 1884 के अंक में, 'समय' ने 22 जून 1882 के अंक में, 'बगदासी' ने 16 तथा 23 नवंबर 1889 के अंक में, 'समय और साहित्य' ने 5 अप्रैल 1891 के अंक में तथा 'एजुकेशन गजट' ने 5 जून 1891 के अंक में इस कार्यक्रम का बड़ा जोरदार समर्थन किया।<sup>154</sup> जनता तथा प्रशासकों में अधिक सुसंस्कृत तथा सम्मानित दिखाई देने के लिए पश्चिमी वस्त्रों तथा अन्य उत्पादनों का प्रयोग करने वाला की तीव्र भूमना की गई। जर्मन बाजार पत्रिका ने अपने 19 जुलाई 1891 के अंक में लिखा

विभिन्न प्रकार के यूरोपीय वस्त्रों की आवश्यकता केवल उन लोगों को है, जो अपने को छैलछबीला दिखाने के शौकीन हैं। हम हिंदुओं की तो हजारों वर्ष पुरानी आस्था सस्त्रुति है, हम इन रातोंरात धनी बन जाने वालों तथा सब प्रकार की सौम्यता का विद्वृत करने वालों की अनुचित रीति से निश्चित रूप से वरिष्ठ सिद्ध हो सकते हैं। वस्तुतः इन लोगों के आचार व्यवहार में तो अपने को सम्मानित एवं कुलीन दिखाने को कुछ होता नहीं अतः वे लोग धन से उपलब्ध होने वाले साधनों से ही अपने को ऊंचा दिखाने की चेष्टा करते हैं।

इस अवधि में स्वदेशी भावना को देश की माय जन संस्थाएँ भी अपना लगीं। पश्चिमी भारत औद्योगिक संघ के तत्वावधान में हुए द्वितीय औद्योगिक सम्मेलन में प्रमुख विधिवेत्ता, शिक्षाशास्त्री, उद्योगपति तथा लाबनायक पूना के एम० थो० नामजाशी ने संस्था के सदस्यों से आग्रह किया कि वे आयातित वस्तुओं के स्थान पर भारतीय उत्पादनों के प्रयोग का प्रयत्न करें तथा अगले वार्षिक सम्मेलन में अपने प्रयत्नों के परिणामों की सूचना दें।<sup>155</sup> बंगाल में आयोजित पहले के कुछ एक प्रांतीय सम्मेलनों में स्वदेशी की आवश्यकता पर उत्साहपूर्वक बल दिया गया। इन सम्मेलनों में 1894 में बंदरान में आयोजित सम्मेलन विशेष उल्लेखनीय है।<sup>156</sup> कांग्रेस में से यह नारा 1891 के अधिवेशन में उस समय सुनाया गया जब पंजाब के प्रचंड कांग्रेसी नेता लाला मुरलीधर ने प्रतिनिधियों का आड हाथ लेते हुए कहा कि आयातित सामान खरीदने का अर्थ अपने भाइयों के हृदय को रक्त में हलक रगना है।<sup>157</sup> 1894 में उन्होंने इस विषय को फिर उठाया और प्रतिनिधियों में विदेशी वस्त्रों तथा विलासितावादी चीजों का छोड़ना तथा व्यवहार में भी निषेधना में सच्चा सहानुभूति रखने का नारा बंद करने का अनुरोध किया। अधिवेशन के महासचिवों का अनुसार श्रमताओं तथा लालाजी के इस अनुरोध पर दर तक प्रचंड जयजयकार की।<sup>158</sup>

1896 में स्वदेशी आंदोलन उस समय प्रचल रहा उठा जब राजनीतिक दृष्टि में मंचन गारा भारत भारतीय वस्त्रों पर बंदन की भावना से लगाए गए सीमा शुल्क का विरोध मुख्य में आगे बढ़ाया गया।<sup>159</sup> वस्तुतः अनुभव किया कि धर्म तथा अन्य भेदभावों का मुलाकात सभी भारतीयों के लिए गणित है तथा लकावायर के वस्त्रों के धारकों की आपस में हुए राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए जागत हानि का उपयुक्त समय मही था।<sup>160</sup>

भी अनुभव किया गया कि इस आंदोलन को बोरी प्राथनाओ, मौखिक विरोधा तथा प्रस्तावा मे बहुत उपर ले जाने और आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। समय की माग मन्चेस्टर के साथ सभी प्रकार के व्यापार का बंद करन के मगठित प्रयास करने की थी।<sup>163</sup> भारत मे आधुनिक वस्त्र उद्योग के केंद्र की गरिमा के अनुरूप बंबई प्रात ने आंदोलन को नया आयाम देने का नेतृत्व किया। इस प्रात के विभिन्न भागा मे लकाशायर के उत्पादनो का बहिष्कार करने के लिए सस्थाआ और समितिया को मगठित किया गया।<sup>164</sup> बंबई प्रात के सारे समाचारपत्र बहिष्कार के आंदोलन के समर्थन के लिए सक्रिय हो उठे।<sup>165</sup> स्वदेशी वस्त्र के अतिरिक्त न कुछ पहनने और न कुछ बेचने की सावजनिक प्रतिज्ञाए प्राप्त करने के लिए तथा विदेशी वस्त्रो के बहिष्कार का सुगठित करने के लिए पूना, अहमदनगर, सतारा, बारसी, जलगाव, मनमाड तथा राजापुर म विशाल जनसभाए हुईं। बंबई की गतिविधि की लोकप्रियता का परिचय अहमदनगर की स्वदेशी गतिविधि पर 17 मार्च 1896 के 'टाइम्स आफ इंडिया' मे प्रकाशित एक रिपोर्ट<sup>166</sup> से प्राप्त किया जा सकता है। रिपोर्ट म कहा गया था कि लकाशायर के उत्पादनो के बहिष्कार के लिए स्थानीय समिति नगर के विभिन्न भागो मे जनसभाओ का आयोजन तथा जिले के जन साधारण मे परिचालन के लिए परिपत्र तथा पुस्तिकाए तैयार कर रही है। अगरेजी वस्त्रो के बहिष्कार के लोकप्रिय दृढ़ निश्चय का प्रत्यक्ष तथा स्पष्ट प्रमाण देने के लिए इसने एक जन-प्रदर्शन का आयोजन किया जिसमे जनता ने अपन अगरेजी कपडा की हाली जलाई।<sup>167</sup> टाइम्स के सवाददाता का कथन था कि किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए बिना सैकडो जटिल प्रश्नो का सामना किए नए अगरेजी वस्त्र का एक टुकडा तक ले जाना संभव नहीं था। पूना के 'यू इंगलिश स्कूल' के छात्रा न भी अगरेजी कपडो की सावजनिक होली जलाने के लिए इसी प्रकार की जनसभा का आयोजन किया।<sup>168</sup> बहिष्कार आंदोलन की इस अपरिपक्व अवस्था मे बाल गंगाधर तिलक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी।<sup>169</sup> बहिष्कार आंदोलन की नई तहर् यद्यपि प्रमुख रूप से बंबई तक ही सीमित रही तथापि इसे देश के अय भागो के समाचारपत्रो से भी पूरा पूरा समर्थन मिला।<sup>170</sup>

सूती कपडे पर कराधान के विरुद्ध जन जागो के कम होते ही स्वदेशी का आंदोलन भी शिथिल पड गया परंतु पूण रूप से यह समाप्त कभी नहीं हुआ। समाचारपत्र स्वदेशी की आवश्यकता को लोगो के सम्मुख उजागर करत रह।<sup>171</sup> 1899 मे बनारस के 'भारत जीवन' ने देशभक्ति की भावना से आप्लावित भाषण दन वाले तथा लेख लिखन वाले भारतीय शिक्षिता से इस दिशा मे देशवासियो के सामने उदाहरण प्रस्तुत करन की अपील की।<sup>1</sup> सजीवनी कुछ वर्षों के उपरांत 1905 मे विदेशी बहिष्कार और स्वदेशी प्रयोग के आह्वान का नेतृत्व करने वाला पत्र बन गया और उसन स्वदेशी कार्यक्रम की आवश्यकता तथा उसे लागू करने के उपायो और साधना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उसने अपक्षित स्तर की स्वदेशी वस्तुओ की विद्यमानता से जनता के अपरिचय को तथा इन वस्तुओ की सुलभ प्राप्ति के लिए दुकानो तथा अभिकरणो के अभाव को स्वदेशी सघप के माग की वृद्ध बडी बाधाए बताया। उसन इस बात की ओर भी संकेत किया कि बडे बडे थोक व्यापारी और छोट दुकानदार यदि चाहें तो जनता को स्वदेशी

माल खरीदने के लिए विवश कर सकते हैं।<sup>173</sup> पैसा बखवार ने 15 मार्च 1902 के अपने अंक में वचन दिया कि वह विदेशी वस्तुओं के प्रयोग न करने की प्रतिज्ञा करने वाले देश भक्ता के नाम प्रकाशित करेगा।<sup>174</sup>

बरशी जैशीराम ने कांग्रेस के मंच से चौदहवें अधिवेशन के प्रतिनिधियों से भारत में बनी सामग्री के प्रयोग का तथा उसके प्रचार के लिए सस्थाओं की स्थापना का अनुरोध किया।<sup>175</sup> 1901 में कलकत्ता कांग्रेस कमेटी के स्रक्रेटरी ने सावजनिक रूप से कलकत्ता में कांग्रेस के आगामी अधिवेशन के प्रतिनिधियों तथा दशका से प्रायना की कि वे यथा संभव स्वदेशी उत्पादनों से निर्मित वस्त्र पहनकर ही अधिवेशन के सम्मेलनों में सम्मिलित हों।<sup>176</sup> आगामी वर्ष सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने कांग्रेस सभापति पद में स्वदेशी की अपील की।<sup>177</sup> 1902 में प्रथम बार कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन की योजना को औपचारिक मान्यता देने के लिए उसे अहमदाबाद कांग्रेस की विषय समिति को सौंपा परंतु उन्नेखनीय यह है कि प्रस्ताव को व्यापक समर्थन न मिलने के कारण समिति ने इसे अस्वीकार कर दिया।<sup>178</sup> फिर भी बहुत सारे लोगों ने स्वदेशी विचारधारा को व्यावहारिक रूप देने के लिए उपयोगी उपाय जारी रखा। 1898 में पंजाब में 'स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा' नाम की एक सस्था विद्यमान थी जिसका घोषित उद्देश्य भारतीय वस्तुओं का स्तर सुधार और उनका उपयोग बढ़ाना था।<sup>179</sup> 1902 में पूना में एक लाख रूपए की साधारण धन राशि से एक स्वदेशी दुकान खोली गई जिसे शीघ्र ही सफलता मिली।<sup>180</sup> उसी वर्ष स्वदेशी आंदोलन के बंगाली अग्रदूत जे० चौधरी के सक्रिय नेतृत्व में कलकत्ता में 'इंडियन स्टोस लिमिटेड' खोला गया।<sup>181</sup> आगामी वर्ष अहमदाबाद में 'स्वदेशी वस्तु संरक्षण सस्था' बनाई गई और इसका उद्घाटन दीवान बहादुर अबालाल साकेरलाल ने किया।<sup>18</sup>

इस प्रकार भारत में स्वदेशी भावना का उद्भव और विकास हमारे अध्ययन काल की अवधि में एक खास रूप में हुआ जिसमें इस बात को स्वीकार किया गया कि स्वदेशी वस्तुओं का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए वे विदेशी वस्तुओं की तुलना में महंगी तथा स्तर में घटिया ही क्यों न हों।<sup>182</sup> विभिन्न कालों तथा विभिन्न लोगों के व्यवहार में भले ही स्वदेशी भावना के पथक अथवा संयुक्त रूप में अनेक उद्देश्य रहे हों परंतु समीक्षाधीन काल में इसका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक ही था, राजनीतिक नहीं। वस्तुतः इस भावना का जन्म ही भारत की अशक्त तथा शोचनीय औद्योगिक स्थिति की अनुभूति से हुआ था। इस आंदोलन के अस्तित्व का सत्य इसी आशा में निहित था कि यह भारतीय उद्योगों का संरक्षण और प्रोत्साहन देकर देश की औद्योगिक और आर्थिक स्थिति का उद्धार और सुधार करने में सहायक होगा। स्वदेशी के अनेक प्रस्तावकों ने इस दृष्टिकोण का स्पष्ट प्रतिपादन किया।<sup>183</sup> उदाहरणार्थ लोकमान्य तिलक के अंगरेजी भाषा के मुख्यपत्र 'मराठा' ने 2 अप्रैल 1896 के अंक में लिखा

आंदोलन का उद्देश्य दशप्रैम की भावना का संचार है जिसमें भारत में सूनी उद्योग का प्रबल प्रोत्साहन मिल सके। स्वदेशी वस्त्रों की व्यापक मांग क्षण प्रतिक्षण अधिना धिन व्यापक रूप ग्रहण करती जा रही है। अतः विदवासा है कि शीघ्र ही इसी मांगीनी सुधार का द्रुतगति तथा दश में पूंजी के नियंत्रण का प्रोत्साहन मिलेगा।<sup>184</sup>

एक महीने के बाद उगने (मराठा पत्र) आशाओं की आशिक प्रति की सूचना दी और उल्लाम प्ररट किया कि स्वदेशी आंदोलन के फलस्वरूप बर्बई प्रांत में गुन 13, बर्बई में 7 और अहमदाबाद में 6 नई मिलें अस्तित्व में आ गई हैं और मिला के लिए अधिक बटिया बपास उगाय के प्रयत्न किए जा रहे हैं।<sup>188</sup> बंगाल में इस आंदोलन को निरंतर गतिशील बनाने वाले तथा अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे० वे० मित्र की 'सजीवनी' में भी औद्योगिक लाभ को इस आंदोलन का उद्देश्य बताया।<sup>189</sup> सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने भी 1902 की कांग्रेस के महापति पद में दिए गए भाषण में इसी पक्ष को उजागर किया।<sup>190</sup>

अनेक लोगों ने विदेशी प्रतिस्पर्धियों के हाथों परलू कारीगरों तथा हस्तशिल्पियों को निश्चित विनाश में बचाने के लिए स्वदेशी का प्रयोग तथा प्रचार किया।<sup>189</sup> यह एक पर्याप्त रोचक तथ्य है कि स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी हस्तशिल्पकारों को स्वदेशी मशीन उत्पादकों की प्रतिस्पर्धिता से बचाने की ओर किसी का ध्यान नहीं गया।

भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा स्वदेशी की रक्षा और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए प्रस्तुत तर्कों में एक सर्वाधिक आमपक तर्क यह था कि सरकार ने ब्रिटिश उत्पादकों की हित रक्षा के हेतु अथवा उन्मुक्त व्यापार सिद्धांत पर आस्था रखने के कारण भारत के नवजात उद्योगों को नितांत आवश्यक मरक्षण देना अस्वीकार कर दिया है अतः अब लोगों का स्वयं ही प्रबल स्वदेशी आंदोलन चलाने पर उसे मरक्षण देने का दायित्व लेना चाहिए।<sup>190</sup> इससे अतिरिक्त यह अभियान न्यूनाधिक रूप से व्यावहारिक और मभव की परिधि में आता था। इसकी सफलता विदेशी सरकार की शृणा और इच्छा अथवा कानून में परिवर्तन पर नहीं प्रत्युत जनता के अपने प्रयासों तथा आत्मविश्वास पर निर्भर थी। वस्तुतः अधीन प्रजा के लिए यही तो एक साधन अवशिष्ट था।<sup>191</sup> 1902 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने कांग्रेस के महापति पद में दिए गए भाषण में इस दृष्टिकोण का अत्यंत मुत्तरित रूप से प्रस्तुत किया 'कानूनी व्यवस्था से स्वदेशी को संरक्षण देना भले ही असभव हो परंतु हम राष्ट्रीय सक्ल्प से तो यथाशक्ति उसे संरक्षण प्रदान कर सकते हैं।'<sup>192</sup>

राष्ट्रवादियों के अनुसार सामान्य रूप से स्वदेशी आंदोलन और विशेष रूप से विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार लकाशायर के उन स्वार्थी उत्पादकों के विरुद्ध प्रभावी विरोध तथा प्रतिवार के उपयुक्त शस्त्र थे जो भारत के जनपते सूती वस्त्र उद्योग की लूला-लगाडा बनाने के लिए भारत सरकार पर अपना राजनीतिक प्रभाव डाल रहे थे। यह तक प्रस्तुत किया गया कि इन शस्त्रों से विदेशी उत्पादकों को इस प्रकार की हुरकतों को छोड़ने के लिए बाध्य किया जा सकता है अथवा कम से कम उनके परिणामों का आनंद लेने से तो उन्हें वंचित किया ही जा सकता है। यह सब तभी संभव है जब सशक्त बहिष्कार आंदोलन द्वारा उनके मुनाफे कम किए जाएं।<sup>193</sup> मराठा ने 9 फरवरी 1896 के अंक में लिखा 'यदि लकाशायर की अतन्त लोभवृत्ति को ही भारत पर शासन करना है तो भारतीयों को लकाशायर को नष्ट करने के लिए दृढ़ निश्चय करना है। भारत कुछ वर्षों के लिए लकाशायर के वस्त्रों का ही बहिष्कार कर ले तो माचेस्टर के अतिलोभुषण व्यापारियों के होश ठिकाने आ जायेंगे। विदेशी उत्पादकों के स्थान पर स्वदेशी उत्पादकों के प्रयोग के

आंदोलन का एक उद्देश्य यह भी था कि विदेशी उत्पादनो के फलस्वरूप भारतीय धन की निकासी को कम किया जा सके।<sup>191</sup>

इस युग के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के सूक्ष्म अध्ययन से विदित होता है कि इस युग के राष्ट्रीय नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन को राजनीतिक युद्ध लड़ने के लिए प्रभावशाली शस्त्र के रूप में ग्रहण नहीं किया। यह बात नहीं कि स्वदेशी को राजनीतिक शस्त्र के रूप में प्रयोग करने का विचार उनमें से कुछ के दिमाग में भी नहीं आया अथवा इस सावजनिक अभिव्यक्ति नहीं मिली। 1891 में पूना वैभव ने जनता से अपील की कि वह 'कामेट ऐक्ट' का रद्द करवाने के लिए सरकार पर दबाव के रूप में अंगरेजी वस्त्रों का प्रयोग बंद कर दें।<sup>192</sup> 1894 में मराठी के 'मोदवत्त' ने जिमके संपादक के ० बी० वाले को 1897 में राजद्रोह के अभियोग में नौ महीने का कारावास मिला था, बवालत की कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार सरकार के विरुद्ध जनता की आम शिकायतें दूर कराने का शांतिपूर्ण सधप के बहुत बड़े कार्यक्रम का एक अंग था।<sup>193</sup> काफी समय बाद 1901 में लखनऊ के विख्यात राष्ट्रीय साप्ताहिक 'एडवोकेट' ने तो स्वदेशी के प्रयोग को आत्म रक्षा के लिए अपने पास बचा एकमात्र शस्त्र बताया। उसके अनुसार इसी शस्त्र से हम आस्ट्रेलिया सरकार को आस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीयों पर थोपे प्रतिबंध हटाने के लिए तथा हमारे प्रति तनिक शिष्ट जना जैसा सम्य आचरण करने के लिए विवश कर सकते हैं।<sup>194</sup> भारतीय नेताओं के समक्ष चीनिया द्वारा अमरीकी सामान के सफल बहिष्कार का उदाहरण भी था।<sup>195</sup> ऐसा प्रतीत होता है कि उनका अनुमान था कि स्वदेशी को राजनीतिक शस्त्र के रूप में प्रयोग करने का अभी उपयुक्त समय नहीं था। किंतु 1880 में ही दादाभाई नौरोजी ने बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण तथा 'यायसगत भविष्यवाणी की थी कि वह समय अवश्य आएगा। लोकप्रिय गीतों द्वारा विदेशी उत्पादनो के जायान का रोकने की लोकप्रिय चेष्टा का निर्देश करते हुए उन्होंने लिखा था

हाथ के बने महंगे सामान के मुकाबले अंगरेजी मशीनों से बने सस्ते सामान के बहिष्कार का एक निस्सार चेष्टा मानकर आज हम उसका उपहास भले ही कर लें परंतु हम यह नहीं भूलना चाहिए कि इस आंदोलन का पनपना और समय जाने पर नया रूप ग्रहण करना निश्चित है। यदि अंगरेज अपने अविश्वेक का परिचय देते हैं तो इस समय के अंगरेजी वस्त्रों के विरुद्ध लिखे गीत समय आने पर अंगरेजी वस्त्रों के विरुद्ध भी स्वाभाविक रूप में प्रभावी प्रचार का काम करेंगे। परंतु यदि भारत की वर्तमान पतन प्रतिज्ञा जारी रहती है यदि जनता का बहुत बड़ा वर्ग अतंत निजी भी प्रचार की उन्नति के लिए निराशा अनुभव करने लगता है, यदि विवेक तथा सासारिक अनुभव से रहित शिथिल युवक ही जनता के नेता बनने लगते हैं तो यह दृष्ट में अनिष्ट की दिशा में, अंगरेजी वस्त्रों में अंगरेजी शासन की आर एक अत्यंत छोटा सा काम होगा। गीत तो बहरी रहें परंतु हा, शासन के बार में एक अप्रत्याशित विगारी का काम करेगा।<sup>196</sup>

एक आदि आंदोलन के रूप में भी गमीगाधीन अवधि में स्वदेशी भावना का अंगिन भारतीय तथा गवध्यापन आंदोलन का रूप ग्रहण न कर मरी क्यारि

राष्ट्रवादी नेताओं के एक वग ने तथा पनपते भारतीय उद्योगपति वग ने इसका विरोध किया। वही वही तो इस विरोध का मुखर रूप देगन का मिला परंतु अधिकांशत आदोलन के प्रति ममयन के निषेध के रूप में ही इसने अपन को अभिव्यक्त किया। इन्होंने स्वदेशी आदोलन को देशप्रेम का प्रत्यक्ष रूप ता माना परंतु इस व्यावसायिक दृष्टि से अव्यावहारिक, यहा तक कि लाजशक्ति का हानिप्रद मोड़ बताया।<sup>100</sup> उनकी प्रमुख आपत्ति यह थी कि इस आदोलन का प्रमुख आधार आर्थिक भ्रांतिया हैं।<sup>101</sup> लोगों के लिए आयातित उत्तम और मध्यम दर्जे के वस्त्रों के प्रयाग का तिलाजलि देना संभव नहीं था। वे सदैव सत्ता और बड़िया माल सरोदेंगे। यह सोचना भ्रांति थी कि देशप्रेम की अपीलें इस प्रवृत्ति को पलट देंगी। अतः इस प्रकार के सभी प्रयत्न अस्मय असफल होंगे।<sup>102</sup> देशभक्ति की उत्कण्ठता दान की विशाल जनता को विगुद व्यापार के माग में एक इंच भी इधर-उधर न हटा सकेगी।<sup>103</sup> जनसाधारण का तो कहना ही क्या, यहा तक कि सुशिक्षित और विचारशील व्यक्तिना से भी इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। याचा का प्रश्न था 'क्या व एसा कर सकते थे? उगाहरणार्थ आप उनकी महिलाओं और बच्चा स जरा साडिया और चोलिया, छोटों और छाप वान बपडे पहनना छाडने का बटिए तो सही?'<sup>104</sup> अरुचिकर वास्नविवना यह थी कि एक साधारण उपभोक्ता चाह वह किसी भी बौद्धिक स्तर का क्यों न हा, केवल देशप्रेम की भावुकता के बसीभूत होकर आर्थिक श्रेष्ठता आर सस्तेपन के बठार सत्य की उपेक्षा करता हुआ अपनी स्वतंत्र इच्छा से आर नही मूद सकता है।<sup>105</sup> इसके अतिरिक्त भारतीय मिलें उस समय भारत द्वारा इंग्लड से आयातित वस्त्रों के परिमाण में उत्पादन की स्थिति में नहीं थी। भारतीय उद्यमिया के पास या तो मशीनें नहीं थी अथवा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मशीनें खरीदने का पूजा नहीं थी। बहिष्कार आदालन के पास कोई ऐमा अलातीन का चिराग नहीं कि वह एकदम ऐस बारगाने लगा सके जो एक दिन में अथवा एन वष में अथवा पाच वर्षों में सारे भारत के लिए उतन परिमाण में वस्त्र जुटा सकें जितने परिमाण में इस समय भारत इंग्लड से आयातित करता है।<sup>106</sup> इस सदम में वाचा ने टिप्पणी ही नहीं प्रत्युत भविष्यवाणी की कि भारतीय वस्त्र उद्योग को बदाचित्त अपनी अपक्षित पूर्ण क्षमता प्राप्ति के लिए बीस वर्ष लोंगे।<sup>107</sup> और इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि स्वदेशी आदालन चलान का कदाचित्त वही उपयुक्त समय होगा। इस सारी बहस के पीछे यह तक काम कर रहा था कि मिलों का उत्पादन स्वदेशी आदालन के ब्याद नहीं प्रत्युत पहले बडना चाहिए।<sup>108</sup> यहा यह उल्लेखनीय है कि हयवरघा स बना वस्त्र दश में वस्त्र की आवश्यकता तथा मिल के उत्पादन के बीच के अंतर की पूर्ति कर सकता था। सत्य तो यह है कि स्वदेशी के विभिन्न समर्थकों ने उस समय यह सुझाव दिया भी था<sup>109</sup> परंतु उस समय वाचा तथा उसकी विचारधारा के महानुभाव उसी प्रकार के भारतीय वस्त्रों में नहीं प्रत्युत भारतीय मिलों से निर्मित वस्त्रों के ही पक्ष में थे। स्वदेशी का अर्थ उन लोगों के लिए लकाशायर के वस्त्र के स्थान पर भारतीय मिलों में बने वस्त्रों के प्रचार का साधन मात्र था। लकाशायर के वस्त्रों के हटान में हथकरघों की भूमिका को उहोद कोई महत्व ही नहीं दिया। उनका लक्ष्य भारतीय उद्योगों, उनकी प्रगति और सुधार का पुन गतिशील बनाना था न कि सडी-



गली वस्तुओं को आश्रय देना।<sup>20</sup> हथकरघों के वस्त्र को तो उन्होंने वस्त्र उद्योग के विकास से एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा। उदाहरणार्थ 1901 में वाचा ने हथकरघा जुलाहों को मिलमालिकों के विरुद्ध संरक्षण देने के लिए कपास सीमा शुल्क लगाने की निम्नोक्त शब्दों में निंदा की

कररहित भारतीय सूत का प्रयोग करने वाले हथकरघा जुलाहों के उत्पादन मिलों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की प्रतियोगिता में हैं। अत्यंत दुःशाश्रय हथकरघा जुलाहों के दृष्टिकोण से निस्संदेह यह अच्छी बात है कि वे अपने उद्योग को उन्नत करें परंतु जहां तक मिलमालिकों का संबंध है, यह सवथा असहनीय है। यह तो संरक्षण के भीतर ही संरक्षण है।<sup>21</sup>

अतएव सुविधापूर्वक यह निष्कर्ष निवाला जा सकता है कि बंबई की मिलों के मालिक तथा उनके राष्ट्रवादी प्रतिनिधि उस समय तक विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के पक्ष में नहीं थे जब तक भारतीय मिलें अप्रतिशोधित मार्ग को पूरा करके विदेशी वस्त्रों के आयात को बंद करने की स्थिति में नहीं आ जाती। इसका अर्थ उनके अपने अनुमान के अनुसार बीस वर्ष थे।<sup>22</sup> उस समय के खादी आंदोलन का समर्थन देने के लिए भी सहमत हो जाते क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि खादी के उस समय उनका प्रतिद्वंद्वी बन पाने की संभावना ही नहीं थी।<sup>23</sup>

स्वदेशी आंदोलन के औचित्य पर संदेह करने वालों के मन में छुपा हुआ एक और भय यह था कि ब्रिटिश उत्पादक भारत की नई मिलों को मशीनरी देने से इकार करें अथवा अथ इसी प्रकार के साधनों का प्रयोग करके भारत के विरुद्ध बदले की भावना से काम कर सकते हैं। उनके विचार में शासक पक्ष सुदृढ़ और शक्तिशाली था और उसने विरुद्ध शासित भारतीय पक्ष शोचनीय रूप से दुबल था। अतः उनके तथा मिलमालिकों के समर्थन के अभाव तथा उनके विरोध का विश्लेषण निम्नलिखित दो बातों से किया जा सकता है। उनका विश्वास था कि भारतीय मिलों की वर्तमान उत्पादन क्षमता के लिए आंतरिक बाजार में पर्याप्त अवकाश है। इस बाजार का कृत्रिम रूप से अथवा जबरदस्ती किया गया प्रसार उनके लिए अपेक्षित रूप से उपयोगी नहीं होगा क्योंकि देश में मोटे वस्त्र उद्योग पर पहले ही उनका एकाधिकार है और इससे उनके वास्तविक प्रतिद्वंद्वी हथकरघा उद्योग की सहायता मिलेगी और 2 अपनी आर्थिक शक्ति पर तथा जनता के बलिदान की भावना की दृष्टि पर और मुदृढ़ता पर अविश्वास और विदेशी शासकों की शक्ति को घटा-चढ़ाकर आका जाना।

भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के प्रभावशाली वक्ता तथा मिलमालिकों के विरोध का परिणाम यह हुआ कि देश के राष्ट्रवादी शिक्षित मध्यवर्ग का व्यापक समर्थन उपलब्ध होने पर भी स्वदेशी आंदोलन देश का शक्तिशाली आंदोलन न बन पाया। यद्यपि कि उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का औपचारिक समर्थन तब प्राप्त नहीं हो सका।

सदर्भ

- 1 भारत से बाहर निवेश के अ्य स्रोत धारे धीरे न केवल ब्रिटिश पूजी से प्रस्तुत विषय के सभी पूजी उत्पादक देशों की पूजी से भरते जा रहे हैं और यदि यही स्थिति रही तो वह समय शीघ्र आ जाएगा कि बैंगलम दीर्घकाल से घाली पडां हुई ब्रिटिश धानू पूजी को वहां से निवालकर नए स्रोतों में लगाना होगा और इस रूप में 'आधुनिक मुद्रतावपण' के नियम के अनुसार उसकी गति भारत की ओर ही होगी ब्रिटिश कानूना और ब्रिटिश सस्थाओं द्वारा ब्रिटिश पूजी को मुद्रता प्राप्त होने से इसे भारत के लिए अतिरिक्त आवश्यक बनना चाहिए (एजन स्प्रीचज, खंड III पृ० 134) इससे पूर्व वह पोषित कर चुका था कि ब्रिटिश पूजी भारत की राष्ट्रिय प्रगति के लिए अपरिहाय आवश्यकता है (स्प्रीचज खंड I, पृ० 34) और भी देखिए, एलगिन स्प्रीचज, पृ० 489
2. लिज्ड हैमिस्टन जैक्स दि साइप्रेशन आफ ब्रिटिश कपिटल टु 1875 (यूयाक, 1927) पृ० 208
- 3 वही, पृ० 225 तथा देखिए भारतीय अकान आयोग 1880 का प्रतिवेदन भाग II अनुभाग VIII कडिका 3
- 4 पी० पी० पिल्ल की इकानामिक कंडीशंस इन इंडिया, (लदन 1925) पृ० 281 में उद्धृत
- 5 आज पाइस थ्रट ब्रिटेंस कपोटल इनवेस्टमेण्ट इन इंडीवीज्युअल कालोनीयस फारन बट्टोज, जर्नल आफ रायल स्टटिस्टिकल सोसाइटी, खंड LXXIV, भाग II (जनवरी 1911), पृ० 180
- 6 पिल्ले में पूर्वोद्धृत पृ० 28
- 7 जैक्स पूर्वोद्धृत पृ० 230 1880 के अकाल आयोग का प्रतिवेदन भाग II, वग VIII कडिका 3
- 8 आज पाइस पूर्वोद्धृत
- 9 जोशी पूर्वोद्धृत चाटफोर्सिंग पृ० 780 राय पावर्टी, 113-4, 125-6
- 10 जोशी पूर्वोद्धृत पृ० 652 757
- 11 भारतीय अर्थशास्त्र के बहुत से विचारधियों ने ही नहीं बल्कि अर्थशास्त्रीय समस्याओं के प्रति जागरूक हमारे बहुत सारे विद्वान लेखकों ने भी इस तथ्य का उपेक्षा की है (बवाई 1946) प्रोफेसर पी० ए० वाडिया तथा के० टी० मर्सेट ने इस तथ्य को प्रामाणिकता दी है कि प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद तक भारतीय नेताओं के पास विदेशी पूजी के सबध में कुछ कहने को ही नहीं था उन्होंने लिखा है 1922 तक भारतीय लोकमत ने भारत में विदेशी पूजी के निवेश के सबध में अपने आपको निश्चित रूप में अभिव्यक्त नहीं किया फिसकल आयोग ने ही निर्देश किया था कि गवाहा ने अपना मत व्यक्त किया है कि कतिपय निश्चित प्रतिबन्धों के बिना भारत में विदेशी पूजी के प्रवेश को अनुमति नहीं मिलनी चाहिए (पृ० 479-80)
12. 8 दिसंबर 1886 को लदन में हुई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में प्रस्तुत एक लेख में दावाभाई ने लिखा था मैं सभी अंगरेज उद्यमियों से विनयपूर्वक प्रार्थना करता हू कि वे भारत जाकर उत्पासमय अधिकाधिक लाभ उपाजित करें वे हम इससे बड़ा न कोई और लाभ पहुंचा सकते हैं और न ही अनुग्रह कर सकते हैं वस्तुतः हमारे देश में अंगरेजों द्वारा निवेशित प्रत्येक कौड़ी हमारी स्थिति के सुधार में हमारे लिए महत्व रखती है (जर्नल आफ ईस्ट इंडिया

एसोसिएशन खंड III 1969 सं० 1 प० 13) तथा दक्षिण नौरोजी एसेज, पृ० 39-41 102 104 106, 124 7 130-1, 135 विदेश पूजी के उत्तरगामी विरोध के लिए दक्षिण अधोलिखित विवेचन

- 13 नौरोजी एसेज प० 39-40 106 127 एस० एन० बैनर्जी स्पीचेज I पृ० 190 हिंदुस्तान 21 23 24 अगस्त (आर० एन० पी० एन० 26 अगस्त 1888) वेस्लाक पूर्वोद्धत म उद्धत रामाडे का वक्तव्य प० 122 तथा एमेज प० 105 हितवाणी 13 जून (आर० एन० पी० वग 20 जून 1891) ए० बी० पी० 8 फरवरी 1895 6 जनवरी 15 अक्टूबर 1900 10 अगस्त 1903 एम० एन० बैनर्जी सी० पी० ए० प० 270 आर० एम० सायानी आई० सी० पी० 1897 खंड XXXVII प० 524 हिंदुस्तान 8 अक्टूबर (आर० एन० पी० एन०, 11 अक्टूबर 1988)
- प्रारंभिक वर्षों में दादाभाई का विचार था कि भारतीय धन और पूजी के ब्रिटन में अपरिहार्य निवास के मांग में विदेशी पूजी का आयात आशिव रूप में निरोध तथा क्षतिपूर्ति स्वरूप था
- 14 दादाभाई नौरोजी ने इस मुद्दे के लिए जोन स्टूअर्ट मिल को उद्धृत किया (एसज, प० 104) तथा दक्षिण, जोशा पूर्वोद्धत प० 789 90 आर० एम० सायानी एल० सी० पी०, खंड XXXVII, प० 524
- 15 रामाडे एसज, प० 186
- 16 सरकार का सबसे प्रथम कृतव्य इंग्लैंड से और अमरीका तक से पूजीपतियों को भारत में उद्योग खोलने के लिए निमंत्रित और उत्साहित करना है (ए० वा० पी० 17 मार्च 1903) सामाजिक पत्रों में ता विदेशी निवेशकों के प्रारंभिक प्रति उदासीनता और अनुदारता निवारण के लिए भारत सरकार का निदा की तथा दक्षिण एम० एन० बैनर्जी स्पीचेज I पृ० 190 हिंदुस्तान 21 23 24 अगस्त (आर० एन० पी० एन 15 नव० 1898) ए० बी० पी० 15 जनवरी 1893 और नौरोजी ऊपर उद्धृत पादटिप्पणी सं० 12
- 17 हिंदुस्तान 21 23 24 अगस्त (आर० एन० पी० एन० 28 अगस्त 1888) एस० एन० बैनर्जी सी० पी० ए० पृ० 270
- 18 जोशी पूर्वोद्धत 756 हिंदू 23 फरवरी 1900 बंगाली 25 मई 1902 जी एस० अय्यर 'वि विवटरी आन दि इकानामिक कडीशस आफ इंडिया एच० आर० जून 1901 पृ० 443-7 नौरोजी स्पीच ऐट पोट स माउथ इंडिया 20 मार्च 1901 प० 140
- 19 नौरोजी स्पीचेज प० 250-1 382 398 परिशिष्ट प० 3 जी० एम० अय्यर रिप० आई एन० सी० 1898 पृ० 107 परिशिष्ट 30 जुलाई (आर० एन० पी० वग 5 अगस्त 1899) हिंदू 23 फरवरी 1900 बंगाली 25 मई 1901 निष्ठा पूजा के प्रवाह की बलगत करने वाली को प्रयुक्त देने हुए डॉ० ई० वाचा ने 1898 में निष्ठा का जब ता नेत्र में विदेशी सटरे का समस्या में निष्ठा दल की तरफ फल रत्न और रमने गव और मांग को ध्यान रत्न तब तब यहाँ के लोग निष्ठा प्रकार सामाजिक है सरत है? विदेशी निवेशक एन ही अपने देश के साम्राज्य को दूरे स्थान पर ग्राह ले जाने रत्न और इनके अनिश्चित समय था पर पत्रों को भी लोग संग (रिप० आई० एन० सी० 1890 पृ० 50)
- 20 परिशिष्ट 24 निष्ठा (आर० एन० पी० वग 30 अक्टूबर 1887) दत्त एन० एच० एच० इंडिया पृ० 13 परिशिष्ट 30 जनवरी (आर० एन० पी० वग 5 अगस्त 1899) हिंदू 23 फरवरी 1902 बंगाली 25 मई 1901

- 21 नौराजा स्पोचेज, पृ० 133 तथा देविए, वही, पृ० 240, 382, 398 परिशिष्ट पृ० 7 जासी पूर्वोद्धत पृ० 700
- 22 जी० एस० अय्यर ई ए पृ० 122 तथा देविए हिंदू 23 फरवरी 1900 यू इडिया 26 अगस्त 1901
- 23 नौरोजी पावटी पृ० 34 568 9 स्पोचेज पृ० 196 परिशिष्ट, पृ० 7 इडिया 10 मई 1901 में प्रकाशित एक पत्र, पृ० 233 और स्पोचेज ऐट पोटेम माउथ, इडिया 20 मार्च 1903 पृ० 140 बंगाली 25 मई 1901 इडियन पीपुल 23 फरवरी 1905 हिंदुस्तान रिव्यू तथा 'वापस्य समाचार' के संपादक न जिदेशी पूजा के प्रयोग को एक घतराष्ट्रीय सूट छसोट पद्धति' की सजा दी (फरवरी 1903 पृ० 193) तथा गोपल बेलवी आयोग खंड III, पृ० 18140-1
- 24 नौरोजी स्पोचेज परिशिष्ट पृ० 3 बंगाली 25 मई 1901 जी० एस० अय्यर 'लाड वजन का वजत भाषण—एच० आर०, अगस्त 1903, पृ० 318
- 25 बंगाली 1 जून 1901 तथा मराठा 30 जून 1881
- 26 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 673 700 739-40 तथा नौरोजी पावटी पृ० 227 मद्रास स्टड्ड 28 मई (आर० एन० पी० एम० 1 जून 1901) 18 जुलाई 1883 व 'भारत मिहिर' में एक लेखक ने संकेत किया 'ब्रिटिश पूजा अमरीकिया का स्थिति के गुधार के लिए और हिंदुस्तानियों को पश्ची से नामशय करन तथा अमीकी हाशिया की अमरीकिया के दास बनाने में तथा मिस्र को अपना उपनिवेश बनाने के लिए उत्तरदायी है (आर० एन० पी० एम०, 21 जुलाई 1883)
- 27 'यू इडिया 12 अगस्त 1901 (बल दिया गया) 'यू इडिया के अगल अक्ष' में उसने लिखा वतमान आर्थिक और वित्तीय परिस्थितिया में हम इंग्लंड के उद्यम द्वारा प्रवर्तित तथा ब्रिटिश पूजा द्वारा संचालित प्रत्येक उद्योग को आर्थिक खतरे के एक नए स्रोत के रूप में देखने को विवश हो गए हैं (19 अगस्त 1901) 1890 में 'केसरी' में प्रकाशित एक लेख में तो यहा तक घोषित किया गया कि 'विष्णा पूजा के गुणगान करन वाला महादेव राताड देशद्रोही है' (कलाक में उद्धत, पूर्वोद्धत, पृ० 123)
- 28 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 757 केसरी 22 जून (आर० एन० पी० एम० 26 जून 1897) दत्त स्पोचेज II पृ० 82 एल० एम० घोष सी० पी० ए० पृ० 781
- 29 जी० एस० अय्यर रि० आइ० एन० सी० 1901 पृ० 121 तथा मद्रास स्टड्ड, 28 मई (आर० एन० पी० एम० 1 जून 1901)
- 30 जी० एस० अय्यर रि० आइ० एन० सी० 1901 पृ० 132 वाचा ने 1899 में टिप्पणी की 'स्वदेशी पूजा ही एकांतत लाभदायक हो सकती है वह पूजा ही भारी पूजा का सबधन करेगी इसकी प्रक्रिया में हान पर भी निश्चित अवश्य होगी (रि० आइ० एन० सी० 1899, पृ० 59)
- 31 भारत मिहिर 17 जुलाई (आर० एन० पी० एम० 21 जुलाई 1883) जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 682 700 नौरोजी स्पोचेज परिशिष्ट पृ० 556 हिंदू 23 फरवरी 1900 जी० एस० अय्यर बलवी आयोग, खंड III प्रश्न 18664 ई ए—परिशिष्ट, पृ० 2
- 32 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 682
- 33 जोशी पूर्वोद्धत पृ 782 वाचा, सी० पी० ए० पृ० 626 मद्रास स्टड्ड 28 मई (आर० एन० पी० एम० जून 1901)
- 34 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 756 779 789 जी० एस० अय्यर ई ए पृ० 257

- 35 जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 673, 700, 739-40 746 गोखले बेलवी आयोग, खंड III, प्रश्न 18140 18145 मद्रास स्टेट्स 28 मई (आर० एन० पी० एम० 1 जून 1901) जी० एस० अय्यर रिप० आई० एन० सी 1901, पृ० 74 ई ए, पृ० 123 127
- 36 कजन स्पाचेज III पृ० 141
- 37 जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 673 जी० एस० अय्यर ई ए, पृ० 123
- 38 एच० आर०, फरवरी 1903 का सपादकीय, पृ० 193-4 तथा जी० एस० अय्यर ई ए पृ० 123
- 39 उदाहरण देखिए जी० एस० अय्यर ई ए, पृ० 124 स्वीटन तन्त्र के लिए देखिए स्वयं कजन स्पाचेज पृ० 140
- 40 देखिए नीचे तथा अध्याय XIII दि इन्
- 41 यद्यपि दादाभाई नौरोजी ने इस दृष्टिकोण का अत्यंत सशक्तता तथा सुस्पष्टता से विश्लेषण किया था तथापि निकासी सिद्धांत के इस भविष्यवक्ता का समकालीन नेताओं ने भी व्यापक रूप से अनुमोदन किया देखिए नौरोजी पावर्टी पृ० 38, 54 567 8, स्पाचेज, पृ० 250-1 395 6 614 परिशिष्ट पृ० 7 8 इन इंडिया, 2 सितंबर 1904 मराठा 30 जनवरी 1881 हिंदू 30 अक्तूबर 1885 23 फरवरी 1900 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 756-7 राम पावर्टी पृ० 126 गोखले बेलवी आयोग खंड III प्रश्न 18140 18142, 18170 18176 जी० एस० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1898 पृ० 107 रिप० आई० एन० सी० 1902, पृ० 121 ई ए पृ० 128 हितवादी 10 फरवरी (आर० एन० पी० एम० 5 अगस्त 1899) स्वदेशमित्र 22 जनवरी (आर० एन० पी० एम० 26 जनवरी 1901) बंगाली 25 मई 1901, 'यू इंडिया 18 नवंबर 1901, मराठा 7 दिसंबर 1902
- 42 नौरोजी पावर्टी पृ० 194 बंगाली 25 मई 1901 1903 में भारतीय राष्ट्रवादीयों पर बरनेसे हुए साठ कजन ने कहा  
विदेशी पूंजी के भारत में भूत प्रवाह के विरुद्ध प्रस्तुत तर्क कि यह भारतीयों को निधन बनाने का साधन है तथा यह देश की संपत्ति को विदेशों में खर्च से जाता है मग तो मूधनापूर्ण और खतरनाक मतिभ्रम दिखाई देता है जब ब्रिटेन न अमरीका और चीन ने अपनी पूंजी प्रवाहित की तो उन देशों के वासियों ने कभी यह शिकायत नहीं की कि उनका सत्त्वाना किया जा रहा है विदेशी सरकार द्वारा मिस्र के साधनों और नील बाधनी व्यवस्था करने पर किसी को भी उस देश पर दया नहीं आई आज अपने देश के साधनों का साधन बनने जा रहे हम के उद्योगों का विकास विदेशी पूंजी तथा विदेशी मस्तिष्क द्वारा ही हुआ अब जब अमराका अपनी संचित पूंजी, अपनी आरक्ष्यजनक आविष्कार कविन अपना व्यावसायिक प्रतिभा आदि सामानों को इंग्लैंड में बाढ़ सा रहा है तो हमसे कोई भी विदेशी निवासी से अपन चुन जान के दुर्भाग्य पर बटार आसू नहीं बहाता (स्पाचेज खंड III पृ० 140-1)
- 43 नौरोजी स्पाचेज पृ० 152 3 319 312 395 परिशिष्ट पृ० 5 7 8 पावर्टी पृ० 38 135 दादाभाई नौरोजी और गोखले बेलवी आयोग खंड III प्रश्न 18168 9 18183-4 हिंदू 23 फरवरी 1900 और अध्याय XIII दि इन् पर बनबी आयोग का प्रस्तुत विवरण में 1900 दादाभाई ने निम्न अध्यायपूण तथा निरस्तुत शासनपद्धति ब्रिटिश भारतीयों को बन ही उल्लान्तों अथवा साधनों का उपभोग नहीं करने देनी उन्हें पूंजीविहान तथा अगहाय बनाने है जब विदेशी पूंजाति आते हैं और बिनाग की बची-भूची बनर पूंजी कर देते हैं (स्पाचेज



- जनता और अधिक तथा स्याई दरदता का उपभोग करेगी (यू इंडिया 18 नवंबर 1901) तथा दखिए, नौरोजी पावर्टी, पं० 38, 567, स्पीचेज पं० 397 परिशिष्ट पं० 6-7 तथा अंतर्राष्ट्रीय समाज कांग्रेस में भाषण, इंडिया 2 सितंबर 1904 पं० 116 मद्रास स्टूडेंट्स, 28 मई (आर० एन० पी० एम० 1 जून 1901), बंगाली 1 जून 1901, जी० एस० अम्बर ई ए, पं० 128
- 51 नौरोजी पावर्टी पं० 228 जोशी पूर्वोद्धत पं० 699 779, राय पावर्टी, पं० 322 324 गांधले बेलवी आयोग खंड III प्रश्न 18146 18156, 18171 18176 जी० एस० अम्बर रिप० आई० एन० सी०, 1898 पं० 107 और एच० आर० जून 1910 पं० 445 447 बाबा रिप० आई० एन० पी० एम० 59 स्वदेशमित्र 22 जून (आर० एन० पी० एम० 26 जनवरी 1901), हिंदू 13 जून 1904
- 52 नौरोजी पावर्टी पं० 54 194 228 एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए०, पं० 270
- 53 नौरोजी पावर्टी पं० 228
- 54 वही पं० 194 228
- 55 वही पं० 54 194 228
- 56 हिंदू 6 अक्टूबर 1885 तथा जोशी पूर्वोद्धत पं० 756 779 नौरोजी स्पीचेज पं० 398
- 57 नौरोजी पावर्टी पं० 194
- 58 नौरोजी स्पीचेज पं० 634 राय पावर्टी पं० 322 बाबा रिप० आई० एन० सी० 1899 पं० 59 स्वदेशमित्र 22 जनवरी (आर० एन० पी० एम०, 26 जनवरी 1901) आ० एस० अम्बर रिप० आई० एन० सी० 1901 पं० 121
- 59 जोशी पूर्वोद्धत पं० 70
- 60 वही पं० 757 नौरोजी एंड गोखल बलबी आयोग, खंड III प्रश्न 18170 नौरोजी सावर परिशिष्ट पं० 7 और पादटिप्पणी 21 तथा 22 उपयुक्त
- 61 जी० एम० अम्बर इंडियन रिप्यू फरवरी 1912 पं० 83 तथा दखिए राय पावर्टी पं० 3-4
- 62 यू इंडिया 26 अगस्त 2 मिनबर 1901
- 63 स्पीच एंड पार्लामेण्ट माउथ इन इंडिया' 20 मार्च 1903 पं० 140
- 64 जोशी पूर्वोद्धत पं० 699 700 आ० एम० अम्बर रिप० आई० एन० सी० 1898 पं० 107 एच० आर० अप्रैल 1903 पं० 320 में प्रकाशित दत्त स्पीचेज II पं० 82
- 65 यूनान स्टड इंडिया 9 जून (इंडियन स्पेक्टर 9 जनवरी 1904) जी० एम० अम्बर रिप० आई० एन० सी० 1901 पं० 121
- 66 जोशी पूर्वोद्धत पं० 699 बंगाली 25 मई 1901 यू इंडिया 26 अगस्त 1901
- 67 जी० एम० अम्बर ई ए पं० 24)
- 68 आशा पूर्वोद्धत पं० 788 बंगाली 1 जून 1901 17 फरवरी 1903 जी० एम० अम्बर रिप० आई० एन० पी० 1902 पं० 73-4 ई ए पं० 177 हिंदू 13 जून 1904 बंगाली 9 मई (आर० एन० पी० एम० 13 मई 1904)
- 69 बंगाली 9 जून 1901 दादाभाई नौरोजी का जे० एन टांग को पत्र तिथि 16 मिनबर 1901 मंगलि की रचना में उद्धृत पूर्वोद्धत पं० 448
- 70 बंगाली 17 फरवरी 1903 जी० एम० अम्बर ई ए पं० 127
- 71 बंगाली 1 जन 1901

- 72 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 688 9
- 73 उदाहरण के रूप में देखिए जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 700 हिंदू 10 अक्टूबर 1885
- 74 रानाडे एसेज पृ० 186
- 75 जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 673
- 76 1885 में जोशी ने लिखा राजनीतिक दृष्टि से यदि हम इतिहास का गलत अध्ययन नहीं करते तो यह निश्चित है कि धन-संपत्ति की ओर शक्ति का भाषण रहेगा तथा देश में सुदृढ़ विदेशी 'वापारिक हित राज्य में निश्चित रूप से अत्यंत कष्टदायक सक्रिय तत्व बनेंगे यह सबक अपने निजी स्वार्थों तथा उद्देश्यों के लिए अपन वश भर शक्ति और प्रभाव का प्रयोग करेंगे तथा सरकारी विधियों को अपने पक्ष में करने के लिए दबाव डालेंगे (पूर्वोद्धत पृ० 640) तथा देखिए वही पृ० 700, बंगाली 10 जून 1901
- 77 मद्रास स्टैंडर्ड 28 मई (आर० एन० पी० एम० 1 जून 1901) बंगाली, 10 जून 1901
- 77-ए देखिए लांड डफरिन का भाषण तिथि 6 नवंबर 1888
- 'इन दायित्वों के साथ मातृभूमि के अपरिमित व्यावसायिक हितों का दायित्व भी जुड़ा है जिनका प्रतिनिधित्व भारतीयों के महान लाभ के लिए सरकार की उम्मीद थी गई अथवा रखे जाते कतिपय उद्यमों में लगाई गई 2200 लाख पाँड स्टर्लिंग की पूंजी करती है हम इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि इन देश में सबसे प्रथम इस देश के हितों का संरक्षण सबका उचित ही है परन्तु सरकार द्वारा उन लोगों के प्रति जिन्होंने सरकारी गारंटी के विश्वास पर भारत के साधनों के विकास में बहुत बड़ी रकम लगाई है अथवा जिन्होंने शाही भारतीय सरकार के निमंत्रण पर अपनी पूंजी का निवेश किया है अपने दायित्व की उपमा एक कानूनी अपराध होगा मही स्थिति सामबागानों और नील क खेतों पटसन तथा अन्य इस प्रकार के उद्योगों में निजी ब्रिटिश 'वापारियों' द्वारा उत्पादन में निवेशित विपुल पूंजी की है क्योंकि उन्होंने भी इसी विश्वास पर पूंजी का निवेश किया है कि भारत में अंगरेजी शासन तथा अंगरेजी 'याम सुदृढ़ रहेगा' (गवर्नर जनरल का भारत सचिव की प्रेषण सं० 67 तिथि 6 नवंबर 1888)
- 78 बंगाली ने 10 जून के अंक में लिखा ब्रिटिश पूंजी का देश में बढ़ता हुआ निवेश तथा उसपर अर्जित चक्रवर्ति व्याज ही भारत सरकार की ब्रिटिश प्रकृति तथा परंपराओं का पूषण तथा स्वतंत्र विकास में संचमुच ही बाधक है गत वर्षों से भारत सरकार की चरित्रगत यह नीति ही प्रति क्रिया के लिए उत्तरदायी है सही कारण यह है कि क्यों हमारे प्रतिनिधियों को बजट निर्माण में भाग नहीं लेने दिया जाता और यदि भारतीयों को यह अधिकार नहीं दिया जाता तो इसका परिणाम यह होगा कि भारतीय संचमुच हा विदेशी शापका क हितों के विरुद्ध साधनों की खोज करेंगे
- 79 27 फरवरी 1903 इसी प्रकार श्री० पी० पाल ने 'यू इंडिया' के 2 नवंबर 1902 के अंक में लिखा भारत सरकार यह दोहराते हुए स्वीकार कर चुकी है कि वह देश के प्राकृतिक साधनों के उत्पादक विकास के लिए भारत में यथासंभव अधिकाधिक ब्रिटिश पूंजी लाना चाहती है इस नियंत्रण के पश्चात् सरकार ब्रिटिश पूंजी तथा उसके अभिक्ताओं को उनके द्वारा मागी जान वाला सुरक्षा देने को विवश है भारतवाियों को बजट के सबंध में बोलने देने के अधिकार से वंचित करने का वास्तविक कारण भी यही है 'यू इंडिया' के 11 दिसंबर 1902 के अंक में उन्होंने लिखा वही की आवश्यकता नहीं कि केवल दरिद्र बंगाल पर ही नहीं प्रयुक्त सारे असहाय भारत पर अधिकांशतः ब्रिटिश पूंजी ही शासन करती है 14 फरवरी 1903 के अंक



म बंगाली ने टिप्पणी की जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी को मनचाहा रूप देता है उसी प्रकार सरकार वाणिज्य सदन का हाथ में है और उसकी इच्छा से कार्य करती है' तथा दक्षिण द्वि 6 माच 1894 मद्रास स्टड्ड 28 मई (आर० एन० पी० एम० 1 जून 1901) बंगाली 10 जून 1901 रंगालय 18 फरवरी हितवादी 20 फरवरी वसुमती 21 फरवरी (आर० एन० पी० एम० 28 फरवरी 1903) सजावनी 5 माच (आर० एन० पी० एम० 14 माच, 1901), जी० एम० अय्यर ई ए प० 120-2

80 रानाडे एसेज प० 66

81 नोरोजी पावर्टी प० 34, 135 567 8 स्पाचेज प० 322 परिशिष्ट, प० 55-6 गोयले वेलबी आयोग खंड III, प्र० 18170 जी० एम० अय्यर वही प्र० 19636 19680-1 19644 रिप० आई० एन० सी० 1901 प० 121 2 मद्रास स्टड्ड 28 मई (आर० एन० पी० एम० 1 जून 1901)

82 विदेशी पूंजी की सहायता से किसी देश के विकास में और विदेशी पूंजीपतियों द्वारा जिस देश के साधनों के शोषण में आकाश-पाताल का अंतर है (बंगाली 25 मई 1901)

83 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 739

84 इस तक की सारी रूपरेखा का विकास उपलब्ध है नोरोजी पावर्टी पृ० 228 9 जोशी पूर्वोद्धत, 673 739, मराठा 30 अगस्त 1891, मद्रास स्टड्ड 28 मई (आर० एन० पी० एम० 1 जून 1901) जी० एम० अय्यर रिप० आई० एम० पी० 1901 पृ० 121 2 डा० जी० बर्बे के अनुसार जस्टिस रानाडे भी इसी दृष्टिकोण के थे दक्षिण उनकी पुस्तक, रानाडे रिपोर्ट आफ लिबरटेड इंडिया पृ० XXIX

85 नोरोजी पावर्टी, पृ० 229

86 1881 में दादाभाई ने लिया भारत की वर्तमान उदासीनता की विशिष्ट परिस्थितियों में अंगरेजों की पूंजी से भारत के लाभ उठाने का असंस्थित रूप से सर्वोत्तम साधन सरकार द्वारा कार्यों का संचालन होगा भारत के निश्चित रूप से लाभार्थित हानि का योजना यह है कि सरकार सभी प्रकार के पूंजीसापेक्ष सांख्यिक कार्यों अथवा धाना अथवा मारे ही कारों को अपने हाथ में ले उनमें अंगरेजी पूंजी भले ही हो परंतु अभिकरण स्वामी हो तथा वे सब अपरिहार्य स्थिति में ही योग्य यूरोपीयों को उनका प्रधान बनाया जाए (पावर्टी पृ० 228) तथा दक्षिण वही पृ० 229 जोशी के दृष्टिकोण को देखने के लिए दक्षिण उनकी राइटिंग ऐंड स्पीचिंग पृ० 672 3 तथा 746 और दक्षिण यू इंडिया 16 नवंबर 1901 इससे पूर्ववर्ती बाब समाचार के 18 मई 1880 के अंक का दृष्टिकोण तो और भी राब है भारत में अभी अभी आधिपत्य सार्वभौमिक धाना के विदेशी स्वामित्व पर आपत्ति करत हुए अपने अपना मत इस प्रकार प्रकट किया क्योंकि देशवासी अपना सम्बन्ध बनाने में अक्षम हैं अतः सांख्यिक में सरकार का धाना का धुन्दी का कार्य अपने हाथ में ही करना चाहिए इस अनिश्चित हानि धाना के लाभ का उपयोग देशवासियों पर लागू करके लाभ को बनाने में ही करना चाहिए (आर० एन० पी० एम० 8 मई 1880)

87 जाणा पूर्वोद्धत पृ० 672 3 698 नोरोजी पावर्टी पृ० 229 हमने साथ ही जोशी मद्रास सरकार की प्रवृत्ति को पर्यटन और अपने निम्न विरोध प्रकट करने में अक्षम परंतु उन्होंने जाणा जैसे उद्योगों को भारतीय निधि में और भारतीयों के व्यय तथा मूल्य पर विचार करके विदेशी पूंजीपतियों का गायारण मूल्य दर पर तोड़ने का साधन निम्न की (दक्षिण पृ० 677)

और यह कि व्यवहार में सरकार भारताया की नही प्रत्युत विदेशी उद्यमिया की सहायता कर रही थी तथा उन्हें उपदान प्रदान कर रही थी (पृ० 825)

88 इस सबध में एकमात्र उपलब्ध अपवाद बंगाली के 28 जुलाई 1883 के धक का निम्नलिखित अवतरण है न ही हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि किस प्रकार एक सरकार दूर की बौड़ी लाने की बात छोड़कर व्यापार और वाणिज्य के विश्वमक कानूना को लौटाए बिना उन्हें उस्ताहित कर सकती है

89 उद्धत भोनानाथ चंद्र राजा गिबेर मिल (दो घड) (कलकत्ता 1896) खड I प० 75

90 मराठा II सितंबर 1891

91 1896 का प्रस्ताव III तथा दखिए प्रस्ताव XIII 1899 का XIII 1901 का VIII

92 जी० बी० जोशी के विचारों के लिए देखिए उनकी 'राटिंग ऐंड स्पेचिज', पृ० 743 750 785-6 807 1885 में उन्होंने लिखा सबप्रथम हमारी आवश्यकता यह है कि सरकार पूरे तौर से दिल और दिमाग से हमारे साथ हो उसको सहायता के बिना हम अपनी वर्तमान दुबलता तथा ना-तैयारी की स्थिति में राष्ट्रीय प्रगति का दिशा में कुछ भी नहीं कर पाएंगे इस भयकर प्रतियोगिता के सामने जिसके विचार हम हैं सरकार को राष्ट्र की सच्ची आवश्यकताओं को अवश्यमेव अभिस्वीकार करना चाहिए और मित्रतापूर्वक राष्ट्रीय उद्योगों के हित के साथ अपने को जोड़ना चाहिए (वही, प० 743) तथा देखिए वही, प० 746, जस्टिस रानाडे के विचारों के लिए देखिए उनके निबंध 'बीदरलडस इंडिया ऐंड दि कल्चर सिस्टम आइरन इंडस्ट्री पायनीयर अटम्प्ट्स' और 'इंडिस्ट्रियल कार्फरेंस तथा देखिए, के० टी० तन्नग 'ट्रेड ऐंड प्राटवशन (बंबई 1877) प० 49, बंबई समाचार' 8 जुलाई (आर० एन० पी० बव, 9 जुलाई 1881) मराठा 14 फरवरी 1886 22 सितंबर 1895, 18 नवंबर 1900 30 मार्च 1902 बगवासी 31 मई (आर० एन० पी० बग 7 जून 1890) मालवीय स्पेचिज प० 250 जा० एन० अय्यर वेलबो आयोग, खड III प्रश्न 18661, और 'ई ए, प० 264 एन० के० एन० अय्यर, रिप० आई० एन० सी० 1902 प० 138 हिंदू 21 अप्रैल 1902 वस्तुतः चिंतामणि 15 मार्च (आर० एन० पी० एम, 15 मार्च 1900) पी० मेहता स्पेचिज प० 750 दत्त, ई० एच० II प० XVII स्पेचिज I प० 24 सी० पी० ए०, प० 490-1 आर० सी० दत्त ने 1904 में बडौला कं राजस्व मंत्रा बनन पर सबप्रथम काय यह किया कि उन्होंने निजी उद्यमिया का गए उद्योग खोलने में सहायता का वचन दिया —जे० एन० गुप्ता लाइफ ऐंड बक आफ रमेशचंद्र दत्त (लदन 1921) प० 402

93 रिप० आई० एन० सी० 1901 पृ० 123

94 वही मराठा 12 सितंबर 1895 18 जनवरी 1900 दत्त ई० एच० I प० 289 गोखले स्पेचिज पृ० 28

95 भारतीय उद्योग जायोग 1916 18 का प्रतिवेदन प० 2 1880 के अब्बाल आयोग ने इस नीति का प्रतिपादन स्पष्ट शब्दों में किया उसने यद्यपि देश के उद्योगीकरण की आवश्यकता पर बल दिया तथापि उसने स्वतः सिद्ध सत्य के रूप में यह अनुभव किया कि राज्य के किसी भी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से जनता का स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता उलटे इस प्रकार के हस्तक्षेप से बहुत बड़ा खतरा यह है कि एक ती इससे व्यापार के सशक्त सिद्धांतों के प्रसार को ठस पड़चेगी तथा दूसरे निजी उद्यम के प्रवर्तन में भी बाधा उपस्थित होगी हमारा विश्वास है कि परीण उपाया राव क विस्तार तथा स्थानीय व्यापार और विदेशी वाणिज्य के विकास

- आदि से ही लक्ष्य प्राप्त होगी उद्योग की किसी शाखा विशेष को अनिश्चित सहायता देने से कोई भी लाभ नहीं होगा (रिपोर्ट आफ इंडियन कमिशन नमोशन 1880 भाग II अन्तर्भाग कडिका, 2 तथा 3)
- 96 भारतीय उद्योग आयोग 1916-18 का प्रतिवेदन, अध्याय VIII तथा अनस्टे पूर्वोद्धत पं० 210
- 97 वजन स्वीचेज II पृ० 164
- 98 रानाडे एसेज पं० 88 165 166
- 99 वही, पृ० 33 86-7
- 100 वही पं० 32, 89 तथा देखिए जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 743, 809
- 101 रानाडे एसेज, पं० 165
- 102 वही, पृ० 94
- 103 वही पं० 87 9, 91 95 उदाहरणार्थ रानाडे द्वारा प्रस्तुत स्थिति का निम्नलिखित तीसरा उपस्थापन देखिए रेलवे नीति के समर्थकों के लिए आपत्ति प्रस्तुत करना उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि इस सिद्धांत को स्वीकार करने का अर्थ होगा कि सरकार को रेलवे अपना नहीं होने के लिए अथवा चाय काफी उद्योगों के प्रवर्तन के लिए धन जुटाने का कोई अधिकार ही नहीं — (वही पृ० 91) और देखिए, जोशी पूर्वोद्धत पृ० 740 809, मराठा 18 नवंबर 1900
- 104 जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 797 812 रानाडे एसेज पं० 91
- 105 जोशी पूर्वोद्धत, पं० 797 तथा वही पं० 812 826 रानाडे एसेज पृ० 91 2 190 193 जी० एस० अय्यर ई ए पृ० 155
- 106 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 812.
- 107 वही तथा रानाडे एसेज, पं० 190 193 जी० एस० अय्यर, ई ए पृ० 163 5
- 108 रानाडे एसेज पृ० 89 92 3 178 193 जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 797
- 109 रानाडे एसेज पं० 95 जोशी पूर्वोद्धत पं० 797 दि इंडियन स्पेक्टर ने अपने 26 अक्टूबर 1884 के अंक में यह इच्छा प्रकट की कि सरकार हार्नेड से ऋण ले और भारतीयों को ऋण दे
- 110 रानाडे एसेज पं० 95-6
- 111 वही पृ० 177 तथा वही पं० 89 169 189 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 809-10 एम० बी० नामजोशी मराठा 30 अगस्त 1891 में, तृतीय औद्योगिक सम्मेलन पूना का प्रस्ताव मराठा 11 सितंबर 1891 दिवसानी 10 फरवरी (आर० एन० पी० अग 18 फरवरी 1892) स्वर्ण मित्रन, 13 अक्टूबर (आर० एन० पी० एम० 17 अक्टूबर 1903) जी० एस० अय्यर ई ए पृ० 264 या मारटो सोहा और इस्पान जैसे उद्योगों के लिए विशेष रूप से आवश्यक की बर्तन इन उद्योगों में प्रारंभिक कतिपय प्रयोगात्मक वर्षों में लाभ की आशा नहीं की जा सकती। इन इनमें कोई पूंजीपति तब तक पूंजीनिवेश का माहूम नहीं करेगा जब तक उसे पर्याप्त उद्योगों का विश्वस्त आश्वासन प्रतिभूत रेलवे कंपनियों को पूंजी पाने में सहायक आश्वासन जैसा म मिले (रानाडे एसेज पृ० 168 9)
- 112 मराठा 9 अगस्त 1885 जोशी पूर्वोद्धत पं० 746.
- 113 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 747 रानाडे एसेज पं० 137
- 114 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 747
- वही पृ० 648 680 689 747 8 810 826 रानाडे एसेज पृ० 89 187 193 पृ०

- 23 मार्च 1885 द्वितीय औद्योगिक सम्मेलन पूना का प्रस्ताव मराठा 11 सितंबर 1891 मराठा 30 मार्च 1902. राय 'पावर्टी', पृ० 143 जी० ए० ए० अम्पर, ई० ए० पृ० 155
- 16 1887 की राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार से अनुरोध किया कि वह पहले से ही अस्तित्व में आए आदशा पर और अधिक बठोर आचरण करके भारतीय उत्पादना को सरकारी कार्यों के उपयोग में लाकर उन्हें प्रोत्साहित करे प्रस्ताव VII और दक्षिण एंड्र प्रकाश 19 मई (आर० ए० पी० बग 15 जून 1881) बंबई समाचार 6 जुलाई (वही, 9 जुलाई 1881) बंबई प्रान्तिज्ञ 19 नवंबर द्वितैच्छ 23 नवंबर, गुजराती 19 नवंबर, बंबई समाचार 20 नवंबर, अष्टवार सोदागर 20 नवंबर (वही 25 नवंबर 1882) लोचमित्र 26 नवंबर (वही, 2 दिसंबर 1882) रास्त गुफनार 10 जुलाई (वही 16 जुलाई 1887), ए० पी० 14 अप्रैल 1881, 23 मार्च 1882 नव विभावर 20 जून 25 जुलाई (आर० ए० पी० बग 2 जुलाई, 6 अगस्त 1881) चाखवत्त 8 जुलाई (वही 16 जुलाई 1881) बग 11 मार्च 9 सितंबर 1882 काशी सावजनिक सभा का स्मरण प्रपत्र 1886 के अवाल आयोग का प्रतिवेदन प० 451 मराठा 14 फरवरी 1886 हिन्दुस्तानी 6 अक्टूबर (आर० ए० पी० ए० 8 अक्टूबर 1891) अष्टवारे आम 25 अक्टूबर (आर० ए० पी० ए० 1 नवंबर 1887) केशरी 23 सितंबर (आर० ए० पी० बाबे 27 सितंबर 1890) रानाडे एसेज पृ० 178 189 190 193 के० जी० नाटू इन मराठा 30 अगस्त 1891 में उद्धृत द्वितीय उद्योग सम्मेलन पूना का प्रस्ताव मराठा 11 सितंबर 1891 ए० के० नम्पर, रिप० आई० ए० सी० 1895 पृ० 74 राय पावर्टी, पृ० 39-40
- 17 बलकृष्ण के व्यापारसभ का 31 जनवरी 1890 का अभिभाषण कृजत स्पीचिज पृ० 33 पर उद्धृत 1880 के अवाल आयोग का प्रतिवेदन उद्योग आयोग इस निष्पत्ति पर पहुंचा कि भारत की औद्योगिक प्रगति को तीव्र बनाने के लिए भारत में सरकार के तथा रेलों के भंडार खरीदने के उपायों में आमूल परिवर्तन किया जाना चाहिए
- 18 30 जून (आर० ए० पी० ए० 6 जुलाई 1898)
- 19 युनाइटेड इंडिया 11 अगस्त (बी० ओ० आई० 31 अगस्त 1884), मराठा 14 फरवरी 1886 रानाडे एसेज, पृ० 189 193 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 810
- 20 जोशी पूर्वोद्धृत पृ० 743
- 21 वही प० 743 813, 819 20 रानाडे एसेज पृ० 32 3 193 नेटिव ओपिगीयन 20 दिसंबर 1885 हिंदू 21 अप्रैल 1902 1870 के वर्षों में बंबई के स्वदेशी पत्रों का यह एक अत्यंत लोकप्रिय सुभाव का उदाहरणार्थ देखिए गुजरात मित्र 22 जनवरी (आर० ए० पी० बग 27 जनवरी 1871) जामे जमशेद 21 मार्च (वही 22 मार्च 1873) शमशेर बहादुर 12 अप्रैल (वही 12 अप्रैल 1873) बंबई समाचार 16 दिसंबर (वही 22 दिसंबर 1873) 6 जून 1886 के मराठा ने सरकार से देश के खनिज साधनों के विकास को अपने हाथ में लेने का अनुरोध किया ताकि इससे अन्य उद्योगों में खालों में सहायता मिले
- 122 द्वितीय औद्योगिक सम्मेलन पूना का प्रस्ताव मराठा 11 सितंबर 1892 और रानाडे एसेज पृ० 178
- 123 रानाडे एसेज पृ० 177 जोशी पूर्वोद्धृत पृ० 743 मराठा, 22 सितंबर 1895
- 124 अंतिम तीन उपायों की चर्चा इस पुस्तक के अन्य भागों में की गई है
- 125 गोखले 'स्पीचिज' पृ० 70

- 126 आर० एन० पी० बंग 7 जून 1890
- 127 1900 में आर० सी० दत्त ने लिखा यह सोचना समभव है कि औद्योगिक विकास को दृष्टि में रखकर काम करने वाली सरकार हमारी पीढ़ी की अवधि में ही जापान के लोगों में प्रचलित उत्तम ढंगों से भारत के परिस्थिती और कुशल ध्येयों को भी परिचित कराती परंतु अपने ही लाभों के लिए काम करने वाले विदेशी व्यापारियों तथा प्रतियोगी उत्पादकों से इस उद्देश्य की पूर्ति होना कदापि समभव नहीं यही कारण है कि इस दिशा में कभी कोई प्रयत्न नहीं हुआ (ई० एच० I, प० 289) और देखिए गुजरात मित्र, 22 जन० (आर० एन० पी० बब 28 जनवरी 1871) 'राजनारायण बोस स्टडीज इन बंगाल रेलवे', ए गुप्ता द्वारा संपादित (कलकत्ता 1958), प० 210 पर उद्धृत भालानाथ चंद्र एम० एम० छद्म 1876 पृ० 17 राय पावर्टी प० 124 5 जी० एस० अय्यर ई० ए०, पृ० 125 6 जमीयत उलूम 28 जन (आर० एन० पी० एन० 7 जुलाई 1897) दावा गजट, 11 जुलाई (आर० एन० पी० बंग 16 जुलाई 1904) बहुत बड़े आशावादी रानाडे भी इस संबंध में प्रासंगिक सन्नेह और निराशा प्रकट करने को विवश हो गए उदाहरणार्थ हम इस देश में सरकार से उम प्रकार का कुछ करने की आशा नहीं कर सकते, जिस प्रकार मास और जमनी की सरकारी ने अपने पीछे व्यापार और चीनी उद्योगों के लिए किया है तथा सरकार को गिने जाने वाले सामान्य करों में से उपदान अधिदान इन निरर्थक विवेचन में शक्ति का प्रयोग उमका अपव्यय ही है (एनेब पृ० 189)
- 128 जोशी पूर्वोद्धृत पृ० 780 786 801 दत्त ई० एच० I प० 251 तथा देखिए अध्याय II
- 129 रामगोपाल पूर्वोद्धृत प० 15 16
- 130 शिवनाथ शास्त्री मन आई हैव सीन (कलकत्ता 1919) पृ० 190
- 131 बिपिनचंद्र पाल मिमोरॉज ऑफ माई लाइफ ऐंड टाइम्स (कलकत्ता 1932) पृ० 264 और शिवनाथ शास्त्री पूर्वोद्धृत पृ० 200
- 132 3 जुलाई (आर० एन० पी० बब 9 जुलाई 1870)
- 133 बबे पूर्वोद्धृत
- 134 ये अधिकास्त्री तथा साहित्यिक राय बहादुर जी० बी० जोशी जी के नाम से जाने जाते थे
- 135 बबे पूर्वोद्धृत पृ० XX प्रधान एंड भागवत पूर्वोद्धृत पृ० 8 रामगोपाल पूर्वोद्धृत पृ० 13
- 136 प्रधान एंड भागवत पूर्वोद्धृत प० 8 10 रामगोपाल पूर्वोद्धृत पृ० 18
- 137 रामगोपाल पूर्वोद्धृत पृ० 13
- 138 आर० एन० पी० बब, 19 जुलाई 1873 तथा आयमित्र 13 जुलाई (बही)
- 139 बही 28 अगस्त 1875 और बाय मुघावर 5 फरवरी (बही 15 फरवरी 1879) मुखोप पत्रिका 20 अग्रन (बही 26 अप्रैल 1879)
- 140 बी० के० बोस स्टु घाटग (कलकत्ता 1919) पृ० 47 बोस ने बाय निर्या कि तागुर के मोहरीयों से आनधीन कर मा गई है और वे एरे कविया बनाने को तयार हो गए हैं य एरे तथा कवियों इस उद्देश्य से ही उपायों गई विगत धनराशि में धरीये गए और देश क विभिन्न भागों में भेजे गए जन्ताहा के करपा उत्पादन को सत्ता बनाने के लिए उनक प्रयोग में आने वाले अविश्वसित उपकरणों को भी मुधारन के प्रयाग किए गए हैं (पृ० 47)
- 141 15 फिनंबर 1874 के इतिहास में द्वारा उद्धृत बंगाली हेराल्ड जमा कि भोजनाय का प्रयाग प्रस्तुत एम० एम० छद्म 1876 पृ 12

142. उसी में प्रस्तुत
- 143 वही खंड II 1873 पृ० 621
- 144 वही, खंड V, 1876, पृ० 10 2
- 145 वही खंड 1876, पृ० 12
- 146 बी० बी० मजूमदार हिस्ट्री ऑफ पालिटिकल घाट फाम राममोहन टु दयानंद (1821 84) खंड I, बंगाल (कलकत्ता 1934) पृ० 379
- 147 उदाहरणार्थ भारत मिहिर, 15 मार्च ए० बी० पी०, 16 मार्च (आर० एम० पी० बग 25 मार्च 1876)
- 148 शल्व नीति का समीक्षा के लिए दक्षिण अध्याय 6
- 149 नोरोजी पावर्टी, पृ० 207
- 150 8 दिसंबर 1881 और 10 फरवरी 1881
- 151 मालवीय स्पीचेज, पृ० 22
- 152 आर० एन० पी० पी० एन०, 26 अप्रैल 1883
- 153 सजीवनी, 9 फरवरी (आर० एन० पी० बग 16 फरवरी 1884) पत्र के सवादादाता न आग यह सूचना दो कि उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के निवासी बंगाली, पंजाबी, राजपूत और मराठे, सभी सदस्य बन रहे हैं
- 154 केलक पूर्वोद्धत पृ० 122
- 155 बर्देई मिनमालिक सच का 1895 का प्रतिवेदन पृ० 2
- 156 सदन के लिए विभिन्न संबद्ध प्रांतों के नटिव प्रेस के संबद्ध सप्ताहों के प्रतिवेदन को देखिए 5 जून 1891 के ग्रन्थ में एजुकेशन गजट ने बकायत करते हुए लिखा भारतीय उत्पादनों की अछाईं बुराई की चिंता किए बिना उनका प्रति ठीक उमी प्रकार सहानुभूतिशील होना चाहिए जिस प्रकार व्यक्ति अपने माता पिता के गुण दोषों की चिंता किए बिना उनका आदर करने हैं
- 157 मराठा 30 अगस्त 1891
- 158 ए० सी० मजूमदार इंडियन नेशनल इवोल्यूशन (मद्रास 1917) पृ० 188
- 159 और जब थोताओ ने 'नहीं नहीं कहा तो लालाजी भडक उठे और बोले हा ' मैं कहता हू हा ' अपने चारा ओर देखिए य भाइफातूस में लप और ये यूरोप में बनी कुतिया और मेजें चुल्ल बपडे टोपिया अगरेजी बोट स्त्रियों की टोपिया फाक चादी से मनी हुई बेंतें और आपके धरो की बिलासितापूर्ण सजावट आदि य सब और कुछ न हाकर भारत के दुर्भाग्य के उपहार हैं, भारत की भुखमरी के विजयस्तम्भ हैं आपने जो भी रुपया यूरोप के बने सामान पर खच किया है वह प्रत्येक रुपया आपने अपने गरीब भाइयों से लूटा है, अपने ईमानदार कारीगरों से लूटा है जिसके फलस्वरूप अब वे बचारे रोटी कमाने के योग्य तक नहीं रहे (रिप० आई० एन० सी० 1891 पृ० 21)
- 160 रिप० आई० एन० सी० 1894 पृ० 38
- 161 इस पुस्तक का अध्याय 6 देखिए 15 मार्च 1896 के ग्रन्थ में मराठा ने लिखा यह इस अन्वय का ज्वलत प्रमाण है कि शिक्षित भारतीय मानिस्टर के वस्त्रों के विरुद्ध धर्मयुद्ध का प्रचार कर रहा है
- 162 मराठा 15 मार्च 1896 तथा वही फरवरी 1896, बग निवासी 9 फरवरी (आर० एन० पी० बग 15 फरवरी 1896) तथा देखिए धारावार वक्त (6 फरवरी आर० एन० पी० बग 8

- फरवरी 1896) अरुणोदय 16 फरवरी नान सागर 17 फरवरी (वही 22 फरवरी)
- 163 अमृत बाजार पत्रिका न 3 फरवरी 1896 के अक्षर म लिखा भारत के सभी प्रधान नगरों में वैतनिक अभिवृत्ता निष्पन्न कीजिए और उन्हें सहायता के लिए सहायक दीजिए पत्रिका के अनुसार इस उद्देश्य के लिए घन सीधे मिलमालिका की जवा स आना चाहिए और देशी मित्र 20 फरवरी नागा समाचार 15 फरवरी, अरुणोदय 16 फरवरी नान सागर 17 फरवरी जगदादश 16 फरवरी प्रभाकर 19 फरवरी (आर० एन० पी० वग, 22 फरवरी 1896)
- 164 मराठा 15 मार्च 1896
- 165 जामे जमना 24 जनवरी (आर० एन० पी० वग 25 जन० 1896) मादवत 30 जनवरी और जगदादश 26 जनवरी (वही 1 फरवरी 1896), सुबोध पत्रिका 5 फरवरी धारवार वत 6 फरवरी अरुणोदय 2 फरवरी (वही, 8 फरवरी 1896) मराठा 9 फरवरी 15 मार्च 1896 और महाराष्ट्र स नेटिव औपनियन 2 फरवरी, 26 मार्च 1896 तथा दक्षिण पादटिप्पणी 161
- 166 आर० एन० पी० वग 22 29 फरवरी 1896 तथा नीचे 169 की पादटिप्पणी म प्रस्तुत सम्प
- 167 2 मार्च 1896 के 'याय सिधु के अनुसार उम वष अंगरेजी कपडों के बड़े मोट मोट गट्टर होनी की आग म फेंके गए आर० एन० पी० वग 7 मार्च 1896
- 168 जगद्वित्तच्छा 7 मार्च (आर० एन० पी० वग 14 मार्च 1896)
- 169 बर्दई के गृह (पत्रिका) गोपनीय विभाग के विशेष साक्षात्गृह द्वारा नियुक्त हिस्ट्री आफ् पी० वी० जी० निलक अक्तूबर 1899 प्रोग 29 (रिपोजिट) प० 14
- 170 देखिए ए० वी० पी० 5 फरवरी 1896 सजीवनी 1 फरवरी (आर० एन० पी० वग 8 फरवरी 1886) चारुमिहिर 3 फरवरी (वही 15 फरवरी 1896) बग निवामी 9 फरवरी (वही) सहचर 11 मार्च (वही 21 मार्च 1896) सजीवनी 14 मार्च (वही) दावा गज 23 मार्च (वही 28 मार्च 1896) बंगाल विचार से हेराड 14 अप्रैल (आर० एन० पी० वग 18 मार्च 1896) 17 मई 1896) बिहार स उत्कल दीरिका 22 फर० (आर० एन० पी० वग 18 मार्च 1896) उडिया और नामसवाद 7 अप्रैल (वही 23 मई 1896) सञ्चालनिका 17 मिन० (वही 14 नवंबर 1896) उडोसा और मद्रास से स्टड्ड 23 मार्च (आर० एन० पी० वग 10 मई 1896) मद्रास स हिंदुस्तानी 12 फरवरी (आर० एन० पी० एन० 19 फर० 1896) नागरी नीर 13 फरवरी (वही 26 फर० 1896) रत्नवर 24 फर० (वही 4 मार्च 1896) नजमल हिंद 29 फरवरी अजमेर हिंद 7 मार्च और अमाना 5 मार्च (वही 11 मार्च 1896) धलमोडा अग्रवार 9 मई और उत्तर-पश्चिम प्रांता तथा अग्रध मे नगामे धागरा 7 मई (वही 12 मई 1896)
- 171 देखिए ए० वी० पी० 14 नवंबर 1898 अग्रवारे धाम 30 जनार्द (आर० एन० पी० वी० 28 अग्रवत 1897) नसीम धागरा 15 जनार्द (आर० एन० पी० एन० 21 जनार्द 1897) रियाजुल अग्रवार 28 नवंबर (वही 6 मिनवत 1898) मुरमाग रोडगार 24 अग्रवत (वही 10 मई 1899) भारत जीवन 26 जून (वही 5 जनार्द 1899) और 17 जनार्द (वही 2 जन 1901) सजीवनी 14 नवंबर (आर० एन० पी० वग 26 जनार्द 1901) प्रकाश 7 मिनवत (वही 13 मिनवत 1902) पता अग्रवार 15 मार्च (आर० एन० पी० वग 29 मार्च 1901) बंगामी 12 मार्च 27 मिनवत 1901 मंगल 17 अग्रवत 1902 सुवर्ण्य प्रकाश 18 मई (आर० एन० पी० एम० 21 मई 1904)
- 26 जून (आर० एन० पी० एन० 5 जनार्द 1899)

- 173 14 नवंबर (भार० एन० पी० पी० बग 23 नवंबर 1901)
- 174 भार० एन० पी० पी०, 29 मार्च 1902
- 175 रिप० आई० एन० सी० 189९, प० 125
- 176 इडमन डेसी मिरर, 22 नवंबर (भार० एन० पी० एन० 28 नवंबर 1901) भारत जीवन ने 14 नवंबर के अंक में हंगु गुभाय का बड़ा जोरदार समर्थन किया (भार० एन० पी० एन० 15 नवंबर 1898) सजीवनी ने 12 दिसंबर 1901 के अंक में लिखा हिंदुमा में पवित्र भवधरा पर देवम पत्नी की प्रथा है मातृभूमि की पूजा से बढ़कर कोई पवित्र भवधर नहीं और मातृभूमि की पूजा के स्थान-अहास से विदेशी सामान से बनी वैपभूया वाले व्यक्ति को कभी प्रविष्ट नहीं होना चाहिए (भार० एन० पी० बग 21 नवंबर 1901)
- 177 सी० पी० ए० पृ० 636
- 178 मजूमदार पूर्वोद्धत, पृ० 188
- 179 बाबू असीराम, रिप० आई० एन० सी० 1898 पृ० 125
- 180 मराठा 17 अगस्त 1902
- 181 बंगाली 26 सितंबर 1902 वस्तुतः वह एक तरह का स्वदेशी मंदार 1896 में ही खोल चुके थे (बागल पूर्वोद्धत पृ० 124)
- 182 प्रजाबधु, 18 जनवरी (भार० एन० पी० बग, 24 जून 1903) और 15 फरवरी (वही 21 फरवरी 1903)
- 183 यह काफी मजेदार बात है कि स्वदेशी को लोकप्रिय बनाने के लिए स्वदेशी उत्पादकों द्वारा कीमतें घटाने का मुझाव किसी ने भी नहीं दिया जबकि स्वदेशी उत्पादक यत्न उद्योग में काफी ऊंचे लाभ बना रहे थे
- 184 संक्षेप तथा पुनरावृत्ति न होने देने के लिए हम यहां इस विषय पर उपलब्ध असंख्य सदर्भों को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं अधिकांश तो ऊपर प्रस्तुत किए ही जा चुके हैं
- 185 और मद्रास स्टैंडर्ड 23 मार्च (आई० एस० वी० ओ० आई० 10 मई 1896)
- 186 17 मई 1896
- 187 उदाहरणार्थ 14 मार्च 1896 का अंक (भार० एन० पी० बग 21 मार्च 1896)
- 188 सी० पी० ए० पृ० 636-7
- 189 उदाहरणार्थ देखिए बी० वे० बोस पूर्वोद्धत पृ० 47 भोलानाथ चंद्र एम० एम० खंड V 1876 प० 10-2 सजीवनी 22 जून (भार० एन० पी० बग 28 जून 1884) नसीम आगरा, 7 जून (भार० एन० पी० एन० 12 जून 1889) ए० वी० पी० 12 जुलाई 1891 पूना बभय 10 मई (भार० एन० पी० बग 16 मई 1891) भारत जीवन 26 जून (भार० एन० पी० एन० 5 जुलाई 1899)
- 190 मराठा 13 मार्च 1881, बहुद समाचार 22 जून (भार० एन० पी० बरार 27 जून 1891) मराठा 15 मार्च 1896 प्रजाबधु 7 सितंबर (भार० एन० पी० बग 13 सितंबर 1902) बंगाली 26 सितंबर 1902
- 191 और भी देखिए भोलानाथ चंद्र एम० एम०, खंड V 1896 प० 32 बंगाल रिनेसा में राजनारायण बोस का उद्धरण इन पृ० 210 मराठा 9 फरवरी 1896 एडवोकेट, 1 फरवरी (भार० एन० पी० एन०, दो फरवरी 1901)
- 192 सी० पी० ए०, पृ० 636



## 124 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास

- 193 देखिए, सुबोध पत्रिका 20 अप्रैल (आर० एन० पी० व० 26 अप्रैल 1879), मराठा 13 मार्च 1881 ए० बी० पी० 10 फरवरी 1881 सोम प्रकाश, 23 जन० (आर० एन० पी० व०, 28 जनवरी 1882) आनंद बाजार पत्रिका, 27 मार्च (वही, 8 अप्रैल 1882) भारत मिहिर 6 मई (वही, 27 मई 1882) पूना वक्त्र, 10 मई (आर० एन० पी० व० 16 मई 1891) हिंदुस्तानी 11 अप्रैल (आर० एन० पी० ए० 18 अप्रैल 1789), मराठा 8 जनवरी 1894 1896 में पत्रवार्ता तथा अधिक प्रचंड अभियक्ति के लिए देखिए प० 130 ऊपर सी० वार्ड चितामणि की इंडियन पालिटिक्स सिंस दि म्यूटिनी (इलाहाबाद, 1937) में एक राक्षस विवरण इस प्रकार है बी० के० भद्रोक वायसराय की कौमिल में वस्त्र उद्योग पर आयात माल्ट हंगने के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट करने वाले दिन घर के बने वस्त्र पहनकर यहाँ पहुँचे
- 194 एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए० प० 617 और देखिए सजीवनी 21 जून (आर० एन० पी० व० 28 जून 1884) समय 22 जून (वही 27 जून 1885) महत्तर 11 मार्च (वही 21 मार्च 1896) सुरमा ए रोजगार 24 अप्रैल (आर० एन० पी० ए० 10 मई 1899) मोहरे सि 26 जुलाई (आर० एन० पी० ए० 2 अगस्त 1902) पसा अक्बार, 15 मार्च (आर० एन० पी० पी० 20 मार्च 1902)
- 195 5 अप्रैल (आर० एन० पी० व० 11 अप्रैल 1891)
- 196 2 अगस्त (आर० एन० पी० व०, 8 अगस्त 1894 वास्तविक तथ्य यह है कि शोषित ने लोग से स्वदेशी वस्त्रों के प्रयोग का सरकारी बचहरिया में दीवानी या फौजदारी मुकदमे में ले जाने का तथा अपने आपको सरकारी नौकरी से स्वतंत्र रखने का अनुरोध करने एक प्रकार से असहयोग आन्दोलन की ही प्रवृत्तियाँ कर दी थी
- 197 1 फरवरी (आर० एन० पी० ए० 2 फरवरी 1901)
- 198 तिलक रामगोपान पूर्वोद्धृत पृ० 231
- 199 नोरोजा पावर्टी पृ० 207
- 200 यह दृष्टिकोण मिलमासिक तथा उस समय काग्रम के संयुक्त सचिव और 1901 में राष्ट्रपति डॉ० ए० वाचा व 11 तथा 18 मार्च 1896 के टाइम्स आफ इंडिया के प्रको में प्रकाशित दो पत्रों में भली प्रकार व्यक्त किया गया है इनके अनिश्चित उन्ने लेख नि इतानामिक हेरेनीय आफ नि स्वदेशी मूवमेंट इकोनामिक्स इंडियन रिव्यू सितंबर 1903 और पृ० पी० कुस्तिनय का दि स्वदेशी मूवमेंट इंडियन रिव्यू दिसंबर 1903 दि डिस्कान आफ नि प्वाइज अट प्यु आफ नि इतिहास आफ दि स्वदेशी मूवमेंट अट फालोअर' उपर जो स्रोत सामग्री पर आधारित है और देखिए कसरे हि 8 मार्च (आर० एन० पी० व० 14 मार्च 1896) और वही 1 अप्रैल (आई० ए० बी० आ० आई० 17 मई 1890) वाचा न किया महत्त्व दत्तय का सूचक है परन्तु जब इन सकेल्य को कार्यक्रम के परिणत किया जाएगा तो यह प्रायतः तथा निरपेक्ष हरियानुगी विचार माल बनकर रह जाण्गा
- 201 कुस्तिनय पूर्वोक्त स्थान पृ० 763
- 202 वाचा टाइम्स आफ इंडिया 12 मार्च 1896
- 203 कुस्तिनय पूर्वोक्त स्थान पृ० 763
- 204 वाचा पूर्वोक्त स्थान पृ० 11 मार्च 1896.
- 205 इतानामिक्स पूर्वोक्त स्थान पृ० 541
- 206 वाचा पूर्वोक्त स्थान 11 मार्च 1896

- 207 वही
- 208 हमका स्वतंत्री पक्षीय उत्तर यह था माग आने दीजिए आपूर्ति हो जाएगी (ए० बी० पी०, 12 जुलाई 1891) और दखिए, मराठा, 12 अप्रैल 1896 मद्रास स्टड्ड, 23 मार्च (आई० एस० बी० ओ० आई०, 10 मई 1896)
- 209 उदाहरणार्थ, बगवासी 2 मई (आर० एन० पी० बग 9 मई 1891) तथा राजीवनी 14 नवंबर (वही 23 नव० 1901)
- 210 कुविल्लिय पूर्वोक्त स्थल, पृ० 763
- 211 3 मई 1901 का भाषण बंबई मिलमालिक संघ का 1901 का प्रतिवेदन पृ० 53 बंबई मिलमालिक संघ का अध्यक्ष राष्ट्रवाणी नेता नहा था अतः 22 मार्च 1899 को संघ की साधारण वार्षिक बैठक में उसने अपने भाषण में और अधिक स्पष्ट शब्दों में कहा हम मिलमालिक समता सान बात सीमाशुल्क को भारत और इंग्लैंड में प्रतियोगिता की दृष्टि से भारत के लिए पातक मानकर उसका विरुद्ध बार्ड शिवायत नहा रखते हैं अर्थात् संघ पहले ही स्पष्ट कर चुका है लकाशायर का बड़िया बपडे में और भारत के मोट बपडे में किसी प्रकार की प्रतियोगिता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है इसमें कोई संदेह नहीं कि सीमाशुल्क ने हथकरघा जुलाहा को सरक्षण प्रदान किया है और इसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि जहां हथकरघे का प्रतिवप मूल की घपत का उत्तरात्तर बढ़ाते जा रहे हैं, वहां 1896 के पश्चात् बंबई में मशानी करपा द्वारा घपत में बार्ड बढ़ोत्तरी नहा हुई (बंबई मिलमालिक संघ 1898 वप का प्रतिवेदन, पृ० 85)
- 212 वाचा पूर्वोक्त स्थल, 18 मार्च 1896 1903 में नीरोजी द्वारा वाचा को लिखा पत्र, मशानी में उद्धृत, पूर्वोक्त पृ० 450
- 213 हम बात पर क्लृप्त अधिक विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता है 19वीं शती के अन्तिम पचीस वर्षों में भारतीय वस्त्र उद्योग में लकाशायर के बपडे के व्यापार को धीरे धीरे दश के माटे वस्त्र के क्षेत्र में निजात केंवा परतु यह अभी तक उत्तम तथा मध्यम काटि के वस्त्रों का स्तरीय उत्पादन काफी मात्रा में नही कर पाया था बीसवीं शताब्दी का प्रारंभ में स्वदेशी हथ करपा उद्योग मोट बपडे के उत्पादन में तथा लकाशायर के उद्योग मध्यम तथा उत्तम वस्त्र के उत्पादन में भारतीय मिला से प्रतियोगिता की स्थिति में थे अतः एक खास समय में तो स्वदेशी आंदोलन न हथकरघा उद्योग के ही फूलने फलने में योग दिया प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् स्थिति अवश्य मौलिक रूप से बल गई थी उस समय भारतीय मिलें मध्यम ही नहीं, उत्तम काटि के वस्त्र का भी पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करने लगी थी —तुलनीय परिमल राय इंडियाज फारेन ट्रेड सिंस 1870 लंदन 1914 पृ० 184)
- 214 201 से 205 सख्या तक की पादटिप्पणियां में उद्धृत सद्भ

## विदेश व्यापार

पिछली अघशताब्दी की अवधि में भारत के विदेश व्यापार का उल्लेखनीय विकास हुआ है और यह देश की समृद्धि में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण निदान है। — ज्ञान सूत्र

भारत के व्यापार को प्राकृतिक आधार पर प्रतिष्ठित करना होगा और वह प्राकृतिक आधार यह होगा कि देश की बढ़ती जनसंख्या के समर्थन की विशाल और अपरिमित मंडी मुख्य रूप से उसके स्वदेशी उत्पादों के लिए ही सुरक्षित रखनी होगी तथा अवशिष्ट अतिरिक्त सामग्री का यहाँ अनुत्पन्न तथा अनुत्पादित सामग्री के विनिर्माण के रूप में निर्यात करना होगा। ऐसा करने से ही निकट भविष्य में भारत के पूरा आर्थिक विनाश की चेतावनी देने वाले सवट को टाला जा सकता है।

—जी० मुबद्दाम् बन्सर

19वीं शताब्दी में, विशेषतः 1850 के उपरांत भारत में विदेश व्यापार में बहुत उन्नति की जिससे देश में वास्तव में ही व्यापारिक प्राप्ति का श्रीगणेश हो गया। आयात और निर्यात के परिणाम तथा मूल्य उल्लेखनीय गति में बढ़ गए। उनमें विस्तारक्षेत्रों के स्वरूप में मौलिक परिवर्तन आया। 19वीं शताब्दी की अवधि में भारत के विदेश व्यापार के विनाश का विवरण पृष्ठ 127 की तालिका में प्रस्तुत है। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के आयात नियंत्रण के ढांच में भी आमूल परिवर्तन हुए। 1813 में तथा पूर्व अतीत काल में ही जहाँ भारत गन्धक निर्यात वस्तुओं का निर्यात तथा मूल्यवान् धातुओं और तिलाम उत्पादों का आयात तथा वहाँ वृद्धि के विषय में 1858 के पश्चात् प्रमुख रूप से कृषि मन्दी के सामान तथा साठ पत्तों का निर्यात तथा निमित्त सामान का आयातक बन गया। परंपरागत निर्यात की वस्तुओं में सूती और रेशमी वस्त्र तथा चाय का स्थान धीरे धीरे कृषि के विविध उत्पादों में प्रमुख रूप में कच्ची कपास और पट्टा, चाय और काफी, अफीम निर्यात तथा गेहूँ और धान के निर्यात। 1881-82 में तथा 1904-5 में कुल निर्यात का क्रम 17 प्रतिशत तथा

26 प्रतिशत भाग गेहूँ और चावल का था। आयातित सामग्री में सूती धागे और सूती कपड़ा, घातुआ, मंगीना, गीनी तथा तला का अनुपात बढ़ा लगा। 1881-2 में तथा 1904-5 में आयातित सूती उत्पाद ही कुल आयात का क्रमशः 24 तथा 39 प्रतिशत था।

### मूल्य लाख रुपये में

वार्षिक औसत	आयात			निर्यात
"	1834-5	1838-9	7,32	11,32
"	1849-50	1853-4	15,85	20,02
"	1859-60	1863-4	41,06	43,17
"	1869-70	1873-4	41,30	57,84
"	1879-80	1883-4	61,81	80,41
"	1889-90	1893-4	88,70	108,67
"	1899-1900	1903-4	110,69	136,59
वर्ष	1904-5		143,92	174,14

टिप्पणी—इन मूल्यों में सरकारी प्रवारा का भाग के आयात नियामक सम्मिलित हैं।

पिछली शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारत के विदेश व्यापार में यह एक नई तथा सुखद प्रवृत्ति देखने को मिली कि एन जोर भारत में रहा, इसका, मशीनों तथा कारखानों के धंधे निरंतर बढ़ने लग तथा दूसरी ओर आधुनिक मशीना के उत्पादन के रूप में सूती कपड़ा और पटसन के माना का निर्यात एक बार पुनः निर्यात व्यापार में स्थान पाने लगा तथा निरंतर उत्तरोत्तर महत्व प्राप्त करने लगा।

18५6 के बाद सात वर्षों की सक्षिप्त अवधि को छोड़कर सारी 19वीं शताब्दी में भारतीय विदेश व्यापार का एक उल्लेखनीय परंतु सामान्य तत्व था आयात के मुकाबले निर्यात का निरंतर बढ़ता हुआ आधिक्य। इस तत्व ने भारतीय आर्थिक चिंतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

### राष्ट्रीय दृष्टिकोण

विदेश व्यापार के विषय में भारतीय नेताओं के चिंतन को सक्रिय रूप में आकृष्ट अथवा प्रवृत्तता से उत्तेजित नहीं किया गया। इसका एक आंशिक कारण यह था कि यह आंदोलन का विषय नहीं बन सका, हाँ उन्होंने इस प्रश्न पर चिंतन किया तथा उसके विविध पक्षों पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी की परंतु इसे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं समझा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य में कोरी वृद्धि को अपने आप में एक लाभ तथा विचारणीय विषय नहीं माना। उनके अनुसार विदेशी व्यापार केवल इस रूप में महत्वपूर्ण था कि यह भारत की अधोलिखित केंद्रीय आर्थिक समस्याओं का प्रभावित करती था दरिद्रता, उद्योगीकरण तथा विदेशी आर्थिक शोषण। फलतः उन्होंने विदेश व्यापार के

विस्तार की विशुद्ध रूप में, अर्थात् पक्षों से विच्छिन्न रूप में अथवा उसके लाभदायक अथवा घातक प्रभावों के सैद्धांतिक आधारों पर प्रशंसा अथवा निंदा करने से इकार कर दिया।

ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों तथा प्रवक्ताओं के अनुसार विदेश व्यापार का द्रुति विकास देश के हित में था। उन्होंने प्रायः इसे जनता की बढ़ती हुई संपन्नता के प्रत्यक्ष प्रमाण बताया।<sup>3</sup> भारतीय राष्ट्रवादियों ने कुल मिलाकर इस धारणा को स्वीकार नहीं किया। कुछ एक ने तो इस विश्वास पर ही शका व्यक्त की कि भारत का विदेश व्यापार, विशेषतः देश के आकार और जनसंख्या के अनुपात में संपन्न स्थिति में है अथवा तीव्रगति से विकास कर रहा है। 1887 में ही दादाभाई नौरोजी ने निर्देश किया कि यूरोप के देशों के व्यापार के साथ और यहाँ तक कि ब्रिटिश राज्य के अन्य भागों के व्यापार के साथ भारत के विदेश व्यापार की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटिश भारतीय व्यापार कितना निकृष्ट है। आर० सी० दत्त, डी० ई० वाचा तथा जी० एस० अम्बरन इस तथ्य पर उचित ध्यान दिया।<sup>4</sup> किसी भी रूप में उन्होंने विदेश व्यापार के विस्तार को अपने आप में समृद्धि का लक्षण अथवा हॉप्लैंड का कारण नहीं माना। सामग्री के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के सामान्य लाभों को न नकारते हुए भी उन्होंने व्यापार की कुल मात्रा तथा मूल्य में वृद्धि को वास्तविक आर्थिक प्रगति के विश्वस्त संकेतक अथवा विशुद्ध हित मानना स्वीकार नहीं किया। उनके अनुसार यूरोप के व्यापारिक देशों के संबंध में यह मापदण्ड सही हो सकता है क्योंकि वहाँ व्यापार की मात्रा राष्ट्रीय आय की स्थिति का पर्याप्त अंश में संकेतक होती है परंतु भारत अभी तक व्यावसायिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं था अतः उसके संबंध में यह कसौटी लागू नहीं होती थी। वस्तुतः इस देश के संबंध में इस प्रकार के तर्कों का निष्कार, मिथ्या तथा भ्रामक होना ही अधिक संभव था।<sup>5</sup> अथ सत्य होने के कारण यह और भी अधिक भयंकर था। 'बंगाली' ने 7 दिसंबर 1872 के अंक में लिखा 'केवल ऊँची सल्ल्या आ अथवा साधारण सत्रियता से व्यापार की सुदृढ़ता का अनुमान उमी प्रकार मिथ्या सिद्ध हो सकता है जिस प्रकार किसी व्यक्ति की आयु तथा अथ परिस्थितियाँ पर ध्यान दिए बिना केवल उसके शरीर में रक्त-संचार को गति यता में ही उसके उत्तम स्वास्थ्य की कल्पना।'<sup>6</sup> राष्ट्रीय भौतिक उत्पादन के विनाश का दृष्टि में इसपर विचार करते हुए जी० बी० जानी ने 1884 में बल देकर कहा 'बंगाली' विदेश व्यापार अपने आप में घरेलू उत्पादन में वृद्धि का सूचक नहीं। व्यापार ता उत्पादन का केवल वितरण करता है और प्रत्यक्ष स्थिति में आवश्यक रूप से सभरण की सहायता नहीं करता।'<sup>7</sup> इस विषय को आर० सी० दत्त ने गहरी ढंग में पकड़ा और आगमन भूत का हवाला देते हुए कहा

1881-82 में साठ रिपन के शांत और अपेक्षाकृत समृद्ध शासनकाल में भारत का कुल आयात और निर्यात 830 लाख स्ट्रिंग पौंड था। 1900 में केवल और दुर्भाग्य के वर्षों में कुल निर्यात और आयात 1220 लाख पौंड थे। जा भारत का जानता है अपना जिनमें भारत के विषय में अभी कुछ गुना है, निश्चित रूप से कहेंगे कि भारत 1900-01 की अपेक्षा 1881-82 में अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में था और अधिक संपन्न था।<sup>8</sup>

भारत के विषय में विदेश व्यापार और राष्ट्रीय समृद्धि के बीच के सरल, सहेतुक संबंध को असंगत बनाने वाले तत्व कौन थे ? इस विषय में भारतीय नेताओं के मत में एक कारण यह था कि भारतीय विदेश व्यापार का विस्तार स्वाभाविक स्वतंत्र तथा आर्थिक गतिविधि के सामान्य पथ के रूप में नहीं हुआ था। अधिकारियों द्वारा इसे अस्वाभाविक रूप से बढ़ावा दिया गया था। अतः इस रूप में वह लादा हुआ, कृत्रिम, अस्वस्थ तथा आर्थिक दृष्टि से अशक्त था।<sup>9</sup> हम आगे चलकर इसी अध्याय में भारतीय नेताओं के विचारों के अनुसार भारतीय विदेश व्यापार के विनाश रूप तथा ढंग का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करेंगे परंतु यहाँ संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि 'उनके दृष्टिकोण का आधार यह विश्वास तथा आस्था थी कि भारत के भाग्य में केवल वृष्टि संबंधी कच्चे सामान का उत्पादन नहीं बरखा है। भारत का एका दश बनाना अप्राकृतिक है क्योंकि इस देश की धरती घाटी और पूर्ति सीमित है जबकि श्रम बड़ी मात्रा में उपलब्ध है।'<sup>10</sup>

द्वितीय, उनकी धारणा थी, इस संबंध में यह उनके मत को मवाधिक सुनिश्चित रूप देने वाला तत्व था, कि किसी देश के विदेश व्यापार की महत्ता का निर्णय उसके स्वरूप के विश्लेषण के द्वारा ही सही रूप में किया जा सकता है। उनकी उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता का निर्णायक तत्व उनकी कुल मात्रा न होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनिर्मित सामान का स्वरूप तथा राष्ट्रीय वृष्टि और उद्योग पर उस विनिर्मित का प्रतिफल ही अप्रत्याशित अधिक प्रबल निर्णायक तत्व है। वस्तुतः मौलिक प्रश्न यही था।<sup>11</sup> उन्होंने व्यापार के आकड़ों की पूरी जांच की और निर्यात की कच्चे सामान के प्रति तथा आयात के उत्पादित सामान के प्रति विध्वंसक तथा सपीडक प्रवृत्ति और उसके फलस्वरूप देश के क्षरित होकर केवल ब्रिटेन के वृष्टिक उपकरण के रूप में रह जाने की आशंका व्यक्त की।<sup>12</sup> उनमें से बहुतों को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि भारत की विपन्नता प्राकृतिक शक्तियों का दुष्परिणाम न होकर इंग्लैंड की भारत के प्रति निर्धारित नीति का ही कुफल था।<sup>13</sup> यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रमुख राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों ने 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक की अवधि में स्वतंत्र अनुभव किए जाने वाली व्यापार की विरोधी प्रवृत्ति, आधुनिक उद्योगों के उत्पादन के निर्यात तथा मशीनरी, मिल्स की सामग्री और कच्चे सामान के आयात, की आशंका उचित ध्यान दिया।<sup>14</sup> उन्होंने प्रवाह के इस परिवर्तन का स्वागत किया परंतु इस प्रवृत्ति की क्षत्रता सीमा तथा मदता की ओर भी मकत किया।<sup>15</sup> आगे चलकर इसी अध्याय में तथा 'ट्रिफ', 'बरसी', 'एक्सचेंज' आदि अध्यायों में देखा गया है। वास्तव में विदेश व्यापार में यही एक प्रवृत्ति थी जिसे राजनीतिक दबाव के द्वारा प्रोत्साहित करने का उद्देश्य प्रयत्न किया।

तृतीय, उनके विश्वास के अनुसार व्यापार के फूलने फलने की परिस्थितियाँ और यातावरण भी विषय के अनुरूप अर्थात् विचारणीय तत्व थे। क्या देश को व्यापारिक स्वायत्तता प्राप्त हुई है ? किसने इस व्यापार का संचालन किया है ? किसने इस व्यापार पर नियंत्रण रखा है ? और किसने इन लाभों का उपभोग किया है ? क्या व्यापार राष्ट्र की अवशिष्ट और विलास सामग्री का हुआ है अथवा राष्ट्र के उपयोग के आवश्यक सामान का ? व्यापारांतर क्या था और उसके क्या कारण थे ? किसी निश्चित निर्णय पर पहुँचने

में पूव उन्होंने इन कुछ एक जिज्ञासाओं को उठाया और उन पर विचार विमर्श किया।<sup>14</sup>

उनका निष्कर्ष यह था कि विदेश व्यापार के विस्तार को अपने आप में सार्विक नीति का लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता। मूलप्रथम इससे दश को होने वाली लाभ हानियों पर विचार करना आवश्यक है। इसके लिए सतक विचारकों को व्यापार के कुल आकड़ों से भी आगे जाना पडा तथा उनके उदगम की, उनके स्वरूप की तथा राष्ट्रहित पर उनके प्रभाव की जांच करनी पडी।

### विदेश व्यापार के लाभ

भारतीय नेताओं ने कुल मिलाकर विदेश व्यापार के व्यापक रूप से प्रचारित उपमायी स्वरूप को भारतीय जनसाधारण के सदस्य में मानने से इकार कर दिया। उन्होंने तो इसके विपरीत यह मन अभिव्यक्त किया कि समष्टि रूप में भारतीय जनता पर विदेश व्यापार का हानिप्रद प्रभाव ही पडा है।<sup>15</sup> उन्होंने सवप्रथम बढ़ते निर्यातों के स्वरूप और उनके समघातकों की जांच की और उसके आधार पर उन्हें अपने आप में पनपनी राष्ट्रीय समृद्धि का मकेत अथवा देश की संपदा जुटाने का साधन मानने से इकार कर दिया। उन्होंने इस तथ्य की ओर मकेत किया कि आशियन रूप से उत्पादित सामग्रियों के अनिश्चित आयातों के भुगतानों के लिए कृषि सत्रधी कच्चे माल का निर्यात बढ़ता जा रहा था और जनसाधारण के हितों को भयकर क्षति उठाती पड रही थी<sup>16</sup> तथा आर्थिक रूप से गरीब शान्तों का विध्वंसक रूप से महुगी नौकरिया देने के रूप में विदेशी शासन ने दस्त रक्ते का चुकाना पड रहा था।<sup>17</sup> उन्होंने इस दृग्ने तत्व (महुगी नौकरियों) की मारी 19वीं शताब्दी में और उसके उपरांत आयात पर निर्यात की बढ़ती अधिवृत्ता के मन्त्र में जांच की। 1834-5 में 1838-9 तक के पाँच वर्षों की अवधि में निर्यात और आयात में वार्षिक अंतर औसत चार करोड रुपए था। 1869-70 से 1873-4 की अवधि में 165 करोड, 1899-1900 में 1903-4 की अवधि में 259 करोड तथा 1904-5 में 302 करोड रुपए था।<sup>18</sup> भारतीय नेताओं ने भारतीय निर्यात और आयात के मध्य की लक्ष्य अप्रतिघातित तथा मत्तन वद्विशीत मन्त्री खाई का देपन हुए व्यापार के मन्त्र प्रसार में जुक्त व्यापारगत पर हर्षितुन्त हान के बढ़ते इस दृग्मनीय रूप में विचार करने वाला तत्व बताया।

राष्ट्रवादियों द्वारा इस समस्या का विचारपण उठाती उन्नतनीय अर्थशास्त्रीय बुद्धि मत्ता का एत अत्यंत सारक प्रमाण प्रस्तुत करता है। उनका बयन था कि आयात की अपेक्षा निर्यात की अतिरिक्त वास्तव में अनिश्चित निर्यात ही म जर्वात म् उन्नत व्यापारगत रही था। यदि एता हान्य ता दृग्म माता चानी अथवा सामग्री अथवा म योगी पदार्थों के आयातों में वद्वि हानी। वस्तुतः उनका अनुसार यह एत निश्चित प्रमाण थी, विरिक्त महुगी व्यापारगत था जिमका आयात की म् एत हान्य का मत्ता में हान्य रूप में कोई लाभ न पडू मा मत्त निर्यात की अतिरिक्त पर जीव बचाना शक्ति व मत्त तान पर कोई ममापन ही नहीं था। मत्ताना नौराजी के आयात की अथवा निर्यात की अधिवृत्ता की आर सकेत किया जिमक अन्तत न तो चानी म् रूप में और न,। विन्नी

सामग्री के रूप में 1871 में अथवा उससे पूर्व किसी प्रकार का आयात हुआ है।<sup>22</sup> अपने 'दि पावर्टी आफ इंडिया' लेख में उन्होंने अपने भाव और भी अधिक सफलता के साथ अभिव्यक्त किए। भारत के पक्ष में व्यापारांतर और भारत को इसमें कभी न कभी लाभ प्राप्ति के सिद्धांत पर विश्वास करने वाले लेखकों की प्रताड़ना करते हुए उन्होंने कहा वे महानुभाव इस तथ्य की ओर ध्यान न देते हुए ही प्रतीत होते हैं कि निर्यात से प्राप्ति के रूप में भारत को एक भी पाई का अथवा सामान का लाभ नहीं होता और इस प्रकार दंग को आयात में घाटा ही उठाना पड़ता है।<sup>23</sup> 1898 की भारतीय करंसी कमेटी को अपना विवरण प्रस्तुत करते हुए दादाभाई और भी अधिक क्रुद्ध थे। उन्होंने वर्तमान स्थिति में भारतीय विदेश व्यापार को 'भारत पक्षीय व्यापारांतर' कहना विशुद्धतम रूप से भाषा का दुरुपयोग करना घोषित किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा 'यह न तो कोई व्यापार है और न ही व्यापारांतर।' भारत की प्रतिवप 400,000,000 रुपये की विपुल राशि के बदले उसे कभी एक कौड़ी तक निजी धन के रूप में वापस नहीं मिलेगी।<sup>24</sup> रोनाडे को छोड़कर भारतीय नेताओं में जयशास्त्रिया ने बल देकर तत्काल यह निर्देश किया कि निर्यात की अधिकता में भारत का किसी प्रकार का व्यापारिक लाभ नहीं होगा।<sup>25</sup>

निर्यात की अधिकता को फिर किस रूप में ग्रहण करना चाहिए? इस दुखद असंगति का वास्तविक अभिप्राय क्या है? वस्तुतः भारतीय नेताओं के अनुसार निर्यात की अधिकता निम्नलिखित कारणों से आवश्यक और निश्चित सी ही थी

- (क) भारत पर विदेशों के बढ़ते ऋणा के व्याज के मुगतान के लिए<sup>26</sup>
- (ख) द्रुतगति से बढ़ते हुए गृह प्रभारों को अथवा ब्रिटेन में भारत सरकार के खर्च जुटाने के लिए,<sup>27</sup> तथा
- (ग) ब्रिटिश प्रशासकों, व्यापारियों, खेत मालिकों, और पूजीपतियों को इस देश के बढ़ते आर्थिक गोपण के फल के रूप में उगाह अपने लाभ और वचत को अपनी जन्मभूमि में भोजन की व्यवस्था के लिए।<sup>28</sup>

सक्षम में निर्यात और आयात का अंतर विदेशी शासकों द्वारा भारत पर बढ़ाए जाने वाले कर शुल्क का ही निदर्शन था।<sup>29</sup> निर्यात की अधिकता में राष्ट्रीय संपत्ति की वृद्धि में ही बाधा नहीं उपस्थित होती थी प्रत्युत ये भारत में इंग्लैंड का संपत्ति की निकासी अथवा स्थानांतरण के रूपविशेष भी थे। साना चादी उपलब्ध न होने से निधि के इस एक पक्षीय स्थानांतरण को सामग्री का रूप ग्रहण करना ही था। अतः भारत द्वारा अनुकूल व्यापारांतर को बनाए रखना अनिवार्य था अथवा दूसरे शब्दों में निर्यात की अधिकता का भारतीय विदेश व्यापार के एक महत्वपूर्ण तत्व, 'यूनाधिक रूप से कानून का रूप लेना ही था। विदेश व्यापार, निर्यात की अधिकता तथा भारत में संपत्ति की निकासी के निवृत्त संघर्ष पर सबसे प्रथम 1871 में दादाभाई नौरोजी ने ही टिप्पणी की।<sup>30</sup> बालांतर में 1895 में उन्होंने इसे इस प्रकार स्पष्टतः प्रस्तुत किया 'अधिकतागत घरेली एक अकेला तरीका है जिससे ब्रिटिश भारत के निधन लोगों द्वारा विदेशियों के निरंतर बढ़ते हुए समर-तोड़ करों की व्यापार-लाभा की तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था की



जाती है।<sup>31</sup> अथ भारतीय अर्थशास्त्रियों ने भी इस तथ्य का अनुमोदन किया।<sup>32</sup> अपने सामाज्य सूक्ष्म दृष्टि से जोशी महोदय ने सकेत किया कि निर्यात की अधिकता बुच संपत्ति की निकासी को अशत ही प्रदर्शित करती है<sup>33</sup> तथा अधिक निर्यात के रूप में इंग्लैंड को वार्षिक विशाल भुगतानों की विवशता हमारे निर्यातों के बहुत बड़े भाग का अनिवाय स्वरूप प्रदान करती है।<sup>34</sup> आर० सी० दत्त ने इस दूसरे पक्ष पर बल देते हुए लिखा गृह अधिकारों के लिए भारत से आर्थिक निर्यातों देना का संभव आयात का अपभ्रंश अधिक निर्यातों के लिए वाध्य करनी है।<sup>35</sup> इस प्रक्रिया की अनिवायता पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। उन्होंने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि भारत को 1896-1900 के दुर्भिक्ष के वर्षों में भी इस अधिकता का बनाए रखना पड़ा था।<sup>36</sup> उन्होंने इस बात का भी स्पष्ट किया कि इस समय निर्यातों की अधिकता तथा कर गुल्मों के बीच संबंध अप्रत्यक्ष होने के कारण लोकदृष्टि में छुप हुए हैं परंतु अतीत में मंदैव ऐसा नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के दिनों में कंपनी के निवेश साम्राज्य के राजस्व में खरीदे जाते थे अतः उन दोनों के बीच के संबंध न केवल प्रत्यक्षोत्तर पर प्रयुक्त उच्च अधिकारियों द्वारा सावर्जनिक रूप से अभिस्वीकार भी किए जाते थे।<sup>37</sup>

अमृत बाजार पत्रिका ने, जिसके संपादक मोतीलाल घोष महत्वपूर्ण राजनीतिक आर्थिक विषयों को सहज बुद्धिमत्ता के स्तर पर लाने में सिद्धरत थे, अपने 11 जनवरी 1896 के अंक में संपत्ति की निकासी और निर्यातों की अधिकता में घनिष्ठ तथा अपरिहाय संबंध का विश्लेषण एक अन्य विधि से करते हुए स्पष्ट रूप में घोषित किया कि मान विदेश व्यापार के अभाव में विदेशी शासन भारत के शोषण को जारी नहीं रख सके। अंतरराष्ट्रीय विनिमय के अभाव में भारत सचिव और सिविल तथा मत्त अधिकारी भारत का रूपया ही ले पाते। भारत निरंतर अपने रूप से रिक्त अवश्य होना जाता परंतु उसकी उपज दूसरे देशों में उसकी वास्तविक संपत्ति उसमें अपने बच्चों के पोषण के लिए उसके अपने पाम ही रहती।<sup>38</sup>

निर्यातों की अधिकता के इस विनिष्ठ पक्ष में संपत्ति की निकासी स्वतः मिट्टी थी, अतः अधिकार भारतीय नता इस स्वस्थ निर्यातों के अथ व्यवस्थापक निर्यात पर प्रसन्न न हो सके। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार प्रकट की कि श्रृंषि संबंधों के बढ़ते हुए निर्यात श्रृंषिपरक संपन्नता के सूचक न होकर यह सबत करते हैं कि श्रृंषि जगत की बहुसंख्यक जनता और अधिन अधीन बनती जा रही है। जनता पर अनिश्चितता बाध पड़ता जा रहा है तथा देश की सामाजिक शून्यता और फलस्वरूप अरिद्रता बढ़ती जा रही है।<sup>39</sup> परंतु क्या यह उस उदार विदेशी शासन का सूचक न है जिसका देश और देशवासियों के लिए इतना कुछ किया है जैसा कि हम इन अध्याय में निर्यातों में। राष्ट्रवाधियों ने मूलतः इसका स्वीकार करने से इंकार कर दिया। अतः अनिश्चितता उनका मत था कि यह सबका एक भिन्न विषय है। जो ० वी० जागी न निर्यात और दृष्टिया में यह कुछ भी नहीं है, व्यापारिक दृष्टि में बहना चाहें ता इस निर्यातों का आयात और देश का सामाज्य व्यापार मान में देश का सामर्थ्य के इस अनुभव पर ध्यान देना ही होगा।<sup>40</sup>

राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसके उपरांत आयात, जो प्रायः अपने समग्र रूप में ही उत्पादित सामग्री का था, के समघात की जाच-पड़ताल की। जहाँ ब्रिटिश अधिकारियों के अनुसार बढ़ते आयात देश की बढ़ती क्रयशक्ति के सूचक थे, वहाँ भारतीय नेताओं की दृष्टि में ये भारत के उत्पादनो का क्षतिग्रस्त करने का सबसे बड़ा कारण थे। राष्ट्रीय हानि के खौफ थे तथा राष्ट्र की आर्थिक और औद्योगिक मृत्यु के प्रबल सूचक थे। विषय का पूरा अध्ययन करने पर उन्होंने टिप्पणी की कि आयातित सामग्री न तो देशी उत्पादन का बढ़ाती है, न उनकी शेष पूर्ति करती है, न ही नई आवश्यकताओं तथा नए उद्योगों को जन्म देती है अथवा तकनीकी ढंग से कहना चाहें तो यह किसी नई तथा प्रभावी मांग की सृष्टि नहीं करती है।<sup>41</sup> इसके विपरीत उक्त व्यापार की अनुकूल स्थिति में अपने सस्तेपन तथा स्पर्धा की योग्यता के कारण वह भारत के अपने बाजार से ही भारत की हस्तनिर्मित सामग्री को अपदस्थ कर रही है।<sup>42</sup> भारतीयों ने आयात व्यापार के इस पक्ष पर 1831 में उस समय ध्यान दिया जब लगभग सौ प्रतिशत भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार से एक प्रार्थना के रूप में शिकायत की कि आपके प्रार्थियों ने यह पाया है कि बंगाल में ग्रेट ब्रिटेन के वस्त्रों के प्रवेश ने हमारे व्यापार को लगभग नष्ट करके रख दिया है। इसके आयात में प्रतिवर्ष वृद्धि स्वदेशी उत्पादनो के लिए हानिकारक है।<sup>43</sup> इसके उपरांत 1873 में भोलानाथ चंद्र ने देशवासियों को आयात के सबंध में इस प्रकार सावधान किया कि भारतीय उद्योग और गृहनिर्मित उत्पादनो के विनाश का शिखर पर पहुंचाने वाले इन आयातों का वर्दान न समझकर अभिशाप ही मानना चाहिए।<sup>44</sup> 1897 में आर० सी० दत्त ने टिप्पणी की कि भारत में आयात के मूल्य में वृद्धि का वास्तविक परिणाम यह निकला है कि भारत के शिल्पबला उद्योग की इंग्लैंड के भाप और मशीनी उद्योग में अनम प्रतियोगिता में मृत्यु ही हो गई है। 1903 में गांधी ने पापणा की कि विदेशी सामग्री का प्रायः प्रत्येक आयात देश की क्रयशक्ति में किसी प्रकार की वृद्धि करने का सूचक होना तो दूर रहा, वह तो उल्टे स्वदेशी उत्पादनो का ही केवल तन्त्रुरूप अपदस्थ करने का संकेतक है। जी० सी० अय्यर ने इस समस्या का विस्तारपूर्वक और अधिक आर्थिक दृष्टिकोण से किया। भारत में अंतर्राष्ट्रीय विनिमय शेष पूर्ति तथा गृहविनिमय को सुदृढ़ नहीं करता। यह गृहविनिमय का स्थान लेता है अतः इस प्रकार यह उसका सबनाश करता है।<sup>45</sup>

जी० वी० जोशी आयात व्यापार के एक अन्य परीक्ष्य दुष्प्रभाव नगर शिल्प बलाघात के विध्वंस को प्रकट करने में समर्थ हुए। उनके अनुसार यह एक आर उपभोग सामग्री के संचार की सीमा का तथा भीतरी मंडी के क्षेत्र का विस्तार करता था और दूसरी ओर जनता के एक पूरे ढंग का वेक्षण करके अपरिमित मस्ते श्रम का आयाजन करता था। इससे ही विदेशी पंजी देश में घुसन तथा उत्पादक उद्योगों की स्थापना में समर्थ हुई है और अब इन उत्पादक उद्योगों से देश के दूरतम भाग में भी हमारे अपने उत्पादक उद्योगों का विध्वंस लगभग पूरा होने जा रहा है।<sup>46</sup>

भारतीय उत्पादनो के अपदस्थ करने की प्रक्रिया की सुस्पष्ट ढंग से रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए भारतीय नेताओं ने कच्ची कपास के निर्यात तथा सूती वस्त्रों के आयात



इसमें प्रथम जी० वी० जोशी महोदय ने 1888 में अपने एक लेख 'दि ग्री वॉर्ल्ड ट्रेड आफ इंडिया' में इस हानि की स्थूल सांख्यिकी समझना की चर्चा की और इस परिणाम पर पहुंचे कि एक स्थूल तगमी को अनुसार हमारी व्यापारिक स्थिति के कारण हम पारिश्रमिका और लाभों में प्रतिवर्ष 58 करोड़ रुपए की हानि उठानी पड़ती है। उन्होंने बताया कि तीनों प्रतिभागों की व्याज दर में पूंजीरुत यह राशि 1600 करोड़ रुपए हो जाती थी।<sup>154</sup> उठाने यह भी निर्देश दिया कि घट प्रतिशत स्वयं ही मघटव प्रतिभा को अपनत्व करने और मुताबक रूप में प्रगतिशील प्रत्यक्ष समुदाय की रीढ़ मध्यवर्ग को दुगल बनाने का म भारतीय प्रभाव टांकी है।<sup>155</sup>

यह बड़ा आश्चर्य की बात है कि इस समय में भारतीय लगवाने में प्रामीण और नाग रिक हलानिगा हस्तकलाओं में विनाश की निम्न तो भी परंतु उनमें म किसी न भी देश के प्रामीणरण तथा देश की श्रुति में व्यवसायीकरण में पत्रस्वरूप हस्तकी श्रुति और उद्योग के परिच्छेद मरधा में टूटन पर दुःख प्रकट नहीं किया। इसी पुस्तक में द्वितीय अध्याय में हम इसमें कारणों का विवरण यन्तुन फल ही पर चुक है कि भारतीय नवा बढती उद्योगी यन्तुआ में प्रसार में अथवा देश रूप में नीतरी मधी में विस्तार में विरुद्ध नहा है। आपुनिक उद्योगों, जिनका प्रामीण आत्मनिभरता पर विनाश प्रभाव पडना है। अथवा भावी धा के प्रथम समय में हानि में कारण में आंतरिक व्यापार में अथवा व्यापार के तद्रूप विनाश में विरुद्ध नहीं है। वे तो फल व्यापार के वर्तमान ढांच के ही विरुद्ध थे। उनकी आपत्ति विन्सी उत्पादना के प्रामीण मधी पर एकांगी अधिकार में विरुद्ध थी। उनमें आपत्ति विन्सी उत्पादना के प्रामीण मधी में तथा स्वयंसी उद्योगपतियों का अपने लाभों के तद्रूप विनाश में विरुद्ध नहीं है। वे तो आपुनिक उद्योगीकरण के प्रवर्तन में प्रतिशत की और अधिक ध्यान देते हुए अथव्यवस्था की आत्मनिभरता को विनाश में बचाने की ओर कई विचार ध्यान नहीं किया।

अधिकांश राष्ट्रवादी अथवास्त्री तो इस बात में भी स्वीकार नहीं करते थे कि श्रुति उत्पादना में बढते हुए उत्पादों और उनके फलस्वरूप उनके मूल्यों में बढि में श्रुतिनाय म सतन पुरुषों का ही सही किसी प्रकार का लाभ पहुंचा है। उदाहरणार्थ, 1873 में भोलानाथ चंद्र ने लिखा 'भल ही उसमें (भारतीय खेतिहर) में चारा और व्यापार का बहुत विस्तार हुआ है परंतु अभी तक वह उगी प्रकार दीनहीन, अपमानित तथा अवहलित है जसा वह पहले मभी था। वह अभी तक न तो साहूकार के पजा में मुक्त है और न ही गदगी असहायता तथा दुर्भाग्य में छुटारा पा सका है।'<sup>157</sup> सर्वप्रथम, कई वर्षों तक कुछ अधिकास्त्रियों की तो यह धारणा रही कि श्रुतिसामग्री के मूल्य घट रहे हैं बढ नहीं रहे अथवा अधिन में अधिक स्थिर हैं।<sup>158</sup> हा अधिकांशतः मान्य धारणा यह रही कि श्रुति-उत्पादना की ऊंची मांगों और मूल्यों के लाभों का एक बहुत बड़ा भाग वास्तविक रूप में का नहीं मिल पाता क्योंकि उस बेचारे को ऊंच और आवधिक राजस्वों अथवा मालिकों का मूलगतन के लिए साहूकार के मूलधन अथवा उसपर व्याज की मांग की पूर्ति के लिए तथा जीवन की अनिवाय आवश्यकताओं के समरण के लिए फसल काटने के समय ही



लाभप्रद रूप से देश में खपत नहीं हो सकती, निर्यात नहीं करता, प्रत्युत निकासी के दबाव के अंतर्गत उसे गेहूँ, चावल, कपाम, जूट तथा तिलहन का निर्यात करना पड़ता था, और यह स्थिति देश को भयंकर रूप से ग्राह्यता से वंचित कर रही थी। बदले में उसे सुविधा और विलास की बहुत सारी वस्तुएँ लेनी पड़ती हैं, जिनके बिना आसानी से निर्वाह किया जा सकता है।<sup>69</sup> बगवासी ने इस दृष्टिकोण को 6 जुलाई 1889 के अंक में अत्यंत सशक्त ढंग से इस प्रकार प्रकट किया

हमें अपने चेहरे की दमक को बढ़ाने के लिए पाउडर और घुंघराले वालों की चमक बढ़ाने के लिए सुगंधित क्रीम की आवश्यकता नहीं है। हम अपने लोगों का आकषक सुगंध, घड़ियों और छड़ियाँ से मोहित करने की कोई इच्छा नहीं है। हम रेशमी और ऊनी वस्त्रों में चमकना नहीं चाहते। हम आपकी शेरों और शपन से अपनी पापी प्यास नहीं बुझाना चाहते। हम आपके वस्त्रों द्वारा अपनी लज्जा ढकना नहीं चाहते। यदि भारतीय जुलाहा की जाति का समूल नाश हो जाए तो हम उस स्थिति में वृक्षों की छालें भी ओढ़ लेंगे और यदि वृक्ष की छालें भी उपलब्ध न हों तो हम नगे ही रह लेंगे परंतु आपके वस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे। हम आपसे केवल यही प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने ही हाल पर छोड़ दीजिए और जीवित तो रहने दीजिए।<sup>70</sup>

राष्ट्रवादियों ने विदेशियों द्वारा तथा स्वयं देशवासियों द्वारा संचालित व्यापार के बीच आधारभूत अंतर को भी स्पष्ट किया। उन्होंने इस स्थिति पर शोक प्रकट किया कि भारत का व्यापार अधिकांशतः विदेशी तथा बरतानवी व्यापारियों के हाथ में था जो जी० वी० जोशी के अनुसार उसके लाभों का बहुत बड़ा 90 प्रतिशत भाग हड़प जाते थे तथा इस देश से बाहर ल जाते थे।<sup>1</sup> सारे व्यापार तंत्र के अतिरिक्त हमारे सारे वाणिज्य का संपूर्ण संचालन विदेशी नियंत्रण और निदेशन के अधीन था। रत्ने, जहाजरानी, बक बीमा कप-निया यहा तक कि एक सीमा में सामान की गाव से समुद्र तट पर पहुंचन की जातिरिक्त गतिविधि सभी कुछ विदेशी प्रयत्नों के ही अधीन था।<sup>7</sup> जी० वी० जोशी महोदय के अनुसार भारतीय व्यापार पर विदेशी नियंत्रण के फलस्वरूप भारत को प्रतिवर्ष लगभग 26 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ रही थी। यह राशि गृहप्रभारों की उस कुल राशि से अधिक थी जिसकी हम प्रायः शिकायत किया करते हैं।<sup>73</sup> कुछ नेताओं ने इस तथ्य की ओर भी संकेत किया कि सारी हानि को पूर्ण रूप से न सही आंशिक रूप से रोकना तो भारतीयों के अपने हाथ में है ही। विदेशी व्यापार के प्रति उपेक्षा चरतन के लिए स्वदेशी व्यापारियों की प्रताड़ना करते हुए तथा उन्हें प्रवर्धित करते हुए नेताओं ने कहा कि उन्हें विदेश व्यापार के लाभ के साथ साथ उसके समुचित भार का भी वहन करना चाहिए।<sup>74</sup> जोशी की टिप्पणी थी कि निस्संदेह हमें इस कार्य में तो तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता है और न ही पूँजी की विशाल राशि की, पुनरपि यह अतंत हमारा अपना ही तो कार्य है।<sup>5</sup> इसके अतिरिक्त वर्द्ध के खोजा और पारसी इस क्षेत्र में अग्रदूत बनकर चीन और पूर्वी अफ्रीका के बाजारों में पहले से ही कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। उनका उदाहरण निश्चित रूप से अनुकरणीय है तथा निर्यात-आयात अभिकरणों की स्वदेश में और

प्रतिरूप शर्तों पर अपनी उपज का बचाव पड़ता है। वास्तविक लाभ का गती क्रम जम विन्नी नियम व्यापारी तथा उच्च भारतीय श्रमिकों उठाता है, जो विन्नी की उपज को अत्यन्त नरम ढंग पर खरीदते हैं।<sup>15</sup> लाभ का दूसरा बड़ा भाग उन व्यापारियों को प्राप्त होता है जो विन्नी की उपज को मिलाते हैं।<sup>16</sup> उच्च भारतीय श्रमिकों की स्थिति में और लाभ पर अपनी उपज का बचपान है जो उच्च भी उच्च गार वास्तव में छिपे हुए प्राप्त ही हैं।<sup>17</sup> दूसरे अतिरिक्त सरकार जो जमीन भूगर्भ और मानव म धर्म द्वारा लाभ के एक अल्प भाग का हस्तगत है।<sup>18</sup> इस प्रकार ग्रामीण समाज का एक बहुत बड़ा भाग श्रमिक और छोटे किसान का अपन उत्पादन म अधिकृत आता उपभोग करता है। उन वस्तु तो प्रचलन स्थिति में मूल्यवृद्धि म विन्नी रूप में प्रति उठाता जाता है।<sup>19</sup> उच्च भी उच्च जमीन म विन्नी न समाज है कि यदि यह स्वीकार कर भी विन्नी का विन्नी व्यापार म फल का एकमात्र भाग विन्नी है ता भी यह लाभ श्रमिकों का प्रतिफल प्रति व्यक्ति कुछ रूप में प्राप्त वचना है और यह साधारण लाभ आजीविका, उद्योग की हार्ति जम अपरिमित अतिता के मूल्य पर ही मिलता है जमा कि पढ़ने विन्नी जा चुका है।<sup>20</sup>

राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाया कि विन्नी व्यापार के बहुत से चाय, नील काफी तथा पटमन पत्राज जम मोर विन्नी पूजा और प्रचलन के विनियोजन के ही परिणाम थे। अतः विन्नी पूजापति ही इनके लाभ उठाते थे तथा व लोग इनके आयाता तथा उत्पादन म हानि वान सभी लाभ म म भारतीयों की श्रमिकों के रूप में उच्च भाग छोड़कर अवशिष्ट साधन लाभ इन देश से अपनी देश को ले जाते थे।<sup>21</sup> यह पचास तक तथ्य है कि रानाडे ने समकालीन लगभग सभी राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों द्वारा स्वीकृत तब का मानने से श्रमिकों को दिया तथा इसके पत्राज रूप उच्च भारत की श्रमिकों के बीच माल के उत्पादन देश में घटने की नीति के विरुद्ध रूप में टच इस्ट इंडीज की सांस्कृतिक प्रणाली का आदर मानने को एक विचित्र मूल्यवृद्धि पती।<sup>22</sup> वे यह दखना भूत गए कि ईस्ट इंडीज के वाणिज्य पर पूर्ण विदेशी नियंत्रण और स्वाभित्व न इंडोनेशिया के लोग के उद्योग का न केवल अवमूल्यन कर दिया था प्रत्युत स्वदेशी पूजापतिवर्ग के विकास का अवरोध करके वहां की जनता की स्थिति भारतीयों की स्थिति से बदतर कर दी थी।

प्रासंगिक रूप से कुछ भारतीय लेखकों ने स्थिति के इस पक्ष पर भी ध्यान दिया और वे इस परिणाम पर पहुंचे कि भारतीय आयातों का बहुत बड़ा भाग या तो भारत म रहने वाले विदेशियों की अथवा थोड़े बहुत अंगरेजों के स्वदेशी लोगों की दिन प्रतिदिन की आवश्यकता की पूर्ति के काम आता है अथवा विदेशी उद्यमों और रेलवे के काम आता है अथवा सरकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के काम आता है।<sup>23</sup> सबसाधारण द्वारा उपभोग में लया जाने वाला आयात मात्रा में स्वल्प था और उसका मूल्य प्रति व्यक्ति कुछ पैसे ही बैठता था।<sup>24</sup>

उनमें से कुछ ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत अपने फलतु माल का जमकी

लाभप्रद रूप से देश में खपत नहीं हो सकती, निर्यात नहीं करता, प्रत्युत निकासी के दबाव के अंतर्गत उसे गेहूँ चावल, बपास, जूट तथा तिलहन का निर्यात करना पड़ता था, और यह स्थिति देश को भयंकर रूप से खाद्यान्न से वंचित कर रही थी। बदले में उसे सुविधा और विलास की बहुत सारी वस्तुएँ लेनी पड़ती हैं, जिनके बिना आसानी से निर्वाह किया जा सकता है।<sup>68</sup> बगवासी ने इस दृष्टिकोण को 6 जुलाई 1889 के अंक में अत्यंत सशक्त ढंग से इस प्रकार प्रकट किया

हमें अपने चेहरे की दमक को बढ़ाने के लिए पाउडर और घुघराले वाला की चमक बढ़ाने के लिए सुगंधित फ्रीम की आवश्यकता नहीं है। हम अपने लागे को आफपक सुगंध, घड़ियों और छड़िया से माहित करने की कोई इच्छा नहीं है। हम रेशमी और ऊनी वस्त्रों में चमकना नहीं चाहते। हम आपकी शरीर और शपन से अपनी पापी प्यास नहीं बुझाना चाहते। हम आपके वस्त्रों द्वारा अपनी लज्जा ढकना नहीं चाहते। यदि भारतीय जुलाहा की जाति का समूल नाश हो जाए तो हम उस स्थिति में वृक्षों की छालें भी ओढ़ लेंगे और यदि वृक्ष की छालें भी उपलब्ध न हों तो हम नगे ही रह लेंगे परन्तु आपके वस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे। हम आपसे केवल यही प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने ही हाल पर छोड़ दीजिए और जीवित ता रहने दीजिए।<sup>69</sup>

राष्ट्रवादियों ने विदेशियों द्वारा तथा स्वयं देशवासियों द्वारा संचालित व्यापार के बीच आधारभूत अंतर को भी स्पष्ट किया। उन्होंने इस स्थिति पर शोक प्रकट किया कि भारत का व्यापार अधिकांशतः विदेशी तथा बरतानवी व्यापारियों के हाथ में था जो जी० वी० जोशी के अनुसार उसके लाभों का बहुत बड़ा, 90 प्रतिशत भाग हड़प जाते थे तथा इस देश से बाहर ले जाते थे।<sup>70</sup> सारे व्यापार तंत्र के अतिरिक्त हमारे सारे वाणिज्य का संपूर्ण संचालन विदेशी नियंत्रण और निदेशन के अधीन था। रेलें, जहाजरानी तक बीमा कपनिया यहाँ तक कि एक सीमा में मामान की गाव से समुद्र तट पर पहुँचने की आंतरिक गतिविधि सभी कुछ विदेशी प्रयत्नों के ही अधीन था।<sup>71</sup> जी० वी० जोशी महोदय के अनुसार भारतीय व्यापार पर विदेशी नियंत्रण के फलस्वरूप भारत को प्रतिवर्ष लगभग 26 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ रही थी। यह राशि महत्प्रभारों की उस कुल राशि से अधिक थी जिसकी हम प्रायः शिकायत किया करते हैं।<sup>72</sup> कुछ नेताओं ने इस तथ्य की ओर भी संकेत किया कि सारी हानि को पूर्ण रूप से न सही आशिक रूप से रोकना तो भारतीयों के अपन हाथ में है ही। विदेशी व्यापार के प्रति उपेक्षा बरतने के लिए स्वदेशी व्यापारियों की प्रताड़ना करते हुए तथा उन्हें प्रबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि उन्हें विदेश व्यापार के लाभ के साथ साथ उसके समुचित भार को भी वहन करना चाहिए।<sup>73</sup> जोशी की टिप्पणी थी कि निस्संदेह हमें इस काय में न तो तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता है और न ही पूँजी की विशाल राशि की, पुनरपि यह अतंत हमारा अपना ही तो काय है।<sup>74</sup> इसके अतिरिक्त वर्बर्दे के म्बोजा और पारसी इस क्षेत्र में अग्रदूत बनकर चीन और पूर्वी अफ्रीका के बाजारों में पहले से ही काय प्रारंभ कर चुके हैं। उनका उदाहरण निश्चित रूप से अनुकरणीय है तथा निर्यात-आयात अभिवर्णों की स्वदेश में और



विदेशों में स्थापना करनी चाहिए। इसी प्रकार बंबई, मद्रास और कर्नाटक में स्थानीय स्वामित्व वाली कम से कम तीन पान कंपनियों की स्थापना करनी चाहिए।<sup>6</sup> उत्तर-पश्चिमी प्रांतों तथा अवध के प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी समाचारपत्र 'एण्टवायट' ने राष्ट्रवादी स्थिति का संश्लेषण इस प्रकार प्रस्तुत किया

यदि हम अपनी सम्यक्ता में ही अपना भू-सागर करना है तो हम स्वयं की पंजी में भारतीय प्रतिभा द्वारा प्रशिक्षित भारतीय वाणिज्य का संचालन करना होगा। यदि संभव हो तो हम भारतीयों के स्वामित्व वाले पाता घर प्रिंटिंग मशीन उद्योगों द्वारा व्यापार करना होगा। यह एक स्वयं चलाता ही निर्यातक है मगरना है परंतु भारतीयों की एक राष्ट्र के रूप में प्रगति के लिए हमें इन सभी को अपनाना होगा।<sup>7</sup>

अतः हम इस तथ्य का ध्यान में रखना है कि छोटे में राष्ट्रवादी अधिकांश अप्रतिष्ठित पानतु नियंत्रण के उत्पादन की विनाशकारी पानस्वरूप भारत के विनाश जानकारी व्यापार शर्तों के सिद्धांत का समर्थन में भी सफल हो गए। इस संबंध में उनका पत्र प्रकाशन दादाभाई नौरोजी द्वारा 1870 में उद्धृत जान स्टुअर्ट मिन की इस उक्ति ने किया विदेशों का निर्यातक मुगलान करने वाला देश न केवल मुगलान की नई धनराशि का खोता है प्रत्युत कम लाभदायक शर्तों पर विदेशी सामग्री के बल्कि अपना उत्पादन के विनिमय की बाध्यता के रूप में और भी बहुत कुछ गवाता है।<sup>8</sup> अतः मगर भारतीयों में मिल के इन वचनों का प्रतिबन्धित अथवा पुनः उच्चरित किया। उदाहरणार्थ, 1888 में जोशीजी ने अत्यंत तीव्र स्वर में टिप्पणी की अधिकांश निर्यातों के रूप में इंग्लैंड का इतने बड़े बाजार मुगलानों की आवश्यकता हमारे निर्यातों के बहुत बड़े भाग का एक अनिवाय चरित्र प्रदान करती है जिसमें मूल्यों में अत्यधिकता की प्रवृत्ति जन्म लेती है।<sup>9</sup> इसी प्रकार डॉ० ई० वाचा ने निर्यातक स्वर में कहा बज्रदार देण कम कीमत पर अपना उत्पादन बचाना या बाध्य होना है और इस प्रकार की परिस्थितियों में विस्तृत निर्यातों का अथ राष्ट्रीय संपत्ति के विस्तृत बलिदान में कम कुछ नहीं।<sup>10</sup> अधिकांशियों के अतिरिक्त अथवा मंत्रमूर्त बाजार पत्रिका ने अपन 17 जुलाई 1892 के अंक में इस विषय का बड़ी विवेकता से उजागर किया।

### अनाजों का निर्यात

विदेश व्यापार के एक पक्ष अनाजों के निर्यात पर भारतीय नेताओं ने अवेक्षाजनक अधिकांश विस्तार के साथ छोट समाचारपत्रों में लानप्रिय माध्यम से विचार प्रचार किया। राजनीतिक दृष्टि से भारत के अत्यधिक जागरूक भाग बंगाल में ही नहीं, द्रुतिगति से बढ़ते अनाजों के निर्यात के प्रमुख स्तर उत्तर पश्चिमी प्रांतों, अवध और पंजाब में भी इस प्रश्न को अत्यधिक मुखर स्वर प्राप्त हुआ।

माग और पूति के बल्लत रहने के कारण वर्ष प्रतिवर्ष अनाजों के विदेश व्यापार की मात्रा और मूल्यों में तो विविधता है, फिर भी निम्नलिखित अंका में उसकी सामान्य प्रवृत्ति का निदान प्रस्तुत है<sup>11</sup>

औसत	हडरडवेट	रूपये (लाखों में)
1882-3—1891-2	48,267,117	17,82
1892-3—1901-2	42,268,345	17 89
1904 5	102,021,341	41 11

चावल प्रमुख रूप से बर्मा से, गेहूँ और दालें भारत से निर्यातित की जाती थी। भारत ने 1869 में 275,481 हडरडवेट 1873-4 में 1,755,954 हडरडवेट, 1882-83 में 14,193,763 हडरडवेट और 1891-2 में 32,740 000 हडरडवेट गेहूँ का निर्यात किया।<sup>85</sup>

अनाजों के निर्यात के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण अनेक कारणों से अत्यंत आनाचनात्मक था किंतु प्रमुख कारण यही था कि ये निर्यात ही देश में अनाज की दुर्लभता, अकाल की स्थितियों और यहां तक कि दरिद्रता के प्रमुख कारणों में अग्रतम थे।<sup>83</sup> उदाहरणार्थ, 1891 में जिस वर्ष अकाल नहीं पड़ा था, लखनऊ के व्यंग्यबुद्दाल राष्ट्रावादी उर्दू साप्ताहिक अवधपत्र ने ममवेधी टिप्पणी की

इस समय देश से निर्यात किया जाने वाला अनाज वास्तव में अनाज न होकर अकालग्रस्त देशवासियों का जीवन-रक्षक है। अनाज की बोरिया अनाज से भरी बोरिया न होकर वस्तुतः देश के लोगों से भरी बोरिया है, जिन्हें इंग्लैंड के सुसभ्य नरपिशाच उन्मुक्त व्यापार की तनवार से मारकर अपना भोजन बनाएंगे।<sup>84</sup>

उत्तर भारत में हिंदी के प्रमुख पत्र 'भारत जीवन' ने अपने 19 जनवरी 1900 के अंक में चेतावनी दी 'यदि ये निर्यात न रोके गए तो समय आने पर भारत उजर भूमि बन जाएगा।'<sup>85</sup>

राष्ट्रावादियों का विश्वास था कि अनाज का निर्यात भारत की निधनता और दुर्भिक्षा का कारण था क्योंकि भारत केवल अपने फालतू अनाज का ही निर्यात नहीं करता था प्रत्युत अपनी दिन प्रतिदिन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्धारित भंडार में ही यह निर्यात करता था। अनाजों के इस व्यापार को सभ्य बनाने के लिए भारतीयों को आधा भूखा रहना पड़ता था।<sup>86</sup> हितवादी ने अपने 25 जुलाई 1891 के अंक में लिखा था कि विदेशी भारतीयों के मुंह का ग्रास छीन रहा है और भारतीय कृषक जनता को विदेशियों का पेट भरने के लिए अपने परिवार को भूखा मारना पड़ रहा है।<sup>87</sup> इसी प्रकार आर० सी० दत्त ने बल देकर कहा कि अनाज व्यापार के मुसकराने चेहरे के भीतर निहित तथ्य यह है कि कृषि उत्पादक देश अपने घर-परिवार और गांव को भूखा नगा रखकर उन्हें मृत्यु के कगार पर ला रहा है। यह बात इस तथ्य से भी सिद्ध होती थी कि बड़े बड़े अकालों में भी अनाज का निर्यात यथावत तीव्र गति से हो रहा था।<sup>88</sup> अकाल के वर्षों में निर्यात कम कर दिया गया था, ऐसा भारतीयों के अनुभव में था परंतु इस सबंध में भारतीयों का कथन यह था कि सामान्य वर्षों के निर्यात से पहले ही वास्तविक हानि तो पहुंचाई जा चुकी थी क्योंकि अनाज का फालतू अथवा सुरक्षित भंडार जो अकाल के वर्षों में कृच्छता की स्थिति को बदलने में सहायक सिद्ध होता, निर्यात द्वारा पहले ही खपाया जा चुका था।<sup>89</sup> भारत जैसे देशों में जो ऋतु की विषमताओं के प्रायः ही शिकार रहते हैं, फालतू अनाज का अनुमान तो खाद्यान्नों के घाटे के वर्षों की 'यूनता' की पूर्ति की व्यवस्था

के उपरांत ही लगाता चाहिए,<sup>90</sup> यह भारतीयों का तर्क था।

यदि भारतीय जनता के पास घासतब म पानतू आजाज नती है ता व उत्पादन का विषय और निर्यात क्या करत हैं ? व अपन उत्पादन का दुदित के लिए सुरक्षित क्या नहा ररत ? इस मसला पूरतिदिष्ट उतर एक ही था कि भारत का ममप्र व्यापार विनाना की स्थिति म तथा अस्वाभाविक था। सरकार का तथा नागरिक का नियम अवधि म आर नकर रूप म उद हुए भूराजस्व जधवा मारिण ता पुनरा की जावपनना निमान का जपना अनाज बचन का विवश कर नती थी। इमक साथ पानतू रियाा बगाए रगन व सा म जुडी हुई मडी की ममस्था दश का विनाना बाजारो म ही धपना आजाज व नन को बाध्य करती थी।<sup>91</sup>

अनाज का नियान एक अय दृष्टि म भी हानिप्रत् था। इमन नागा की मवधा मून आवश्यक्ता की वस्तुआ के मूल्य ऊच उद जात थ आर इमन अपरिहाय परिणाम व मूस मरी और म यु।<sup>92</sup> बाग्रम के 1891 के नागपुर अधिवेशन म साता सुराोधर न गटा चीस वप पूव गहू एक रूप का डेन मन जोर दूसरा आजाज एक रूप का दा मा विरना था। इसका कारण यह था कि उस समय हमारे अनाज का विनानो म नियात नहा हाना था। अब यह छ गुना महगा हो गया है और उमी अनुपात म निधना के लिए अपना पद भरना छ गुना कठिन हो गया है।<sup>93</sup>

इस चिन्तन के फलस्वरूप राष्ट्रीय नतत्व के एक बहूत बडे वग न अनाजो के स्वतय तथा असीमित निर्यात पर सरकार स कुछ प्रतिबध लगान की सिपारिण की।<sup>94</sup> अथ पुछ न तो अनाजा के नियात पर ऊचे नियात गुल्व के आधान की वरानत की।<sup>95</sup> कुछ और लोगो न तो यहा तक भाग की कि अनाजो के नियात पर ही पूण प्रतिबध लगा देना चाहिए।<sup>96</sup> 1896-98 के अकाल के वर्षों म तो इस माग के ममथन मे स्वर विनेप रूप से ही मुग्रित हो उठा।<sup>97</sup> साथ ही कुछ नेताओ ने इम तथ्य को अनुभव किया कि सरकार अकाल के दिनो म भी अनाज के निर्याता को रोक्ने जथया प्रतिबधित करने की दिशा म वाई पग नही उठाती। अतएव उन्होंने यह तक देना प्रारभ किया कि सरकार की नीति ही इग्लड के लागे के लिए सन्ती खाद्यसामग्री जुटाने की दृष्टि स अनाजा के नियात का किसी भी मूल्य पर बटान की ही है।<sup>98</sup> इस प्रवृत्ति निर्यात विरोधी वातावरण के युग म अकाल के अतिरिक्त वर्षों म भी अनाज के नियात के समथक समाचारपत्र मुट्ठीभर हो के।<sup>99</sup>

आशा के विपरीत न होने हुए भी यह एक पर्याप्त राखव तथ्य है कि अनाजो के व्यापार म सतन्म भारतीय व्यापारियों का दृष्टिकोण राष्ट्रीय नन्तव के दृष्टिकोण स विपरीत था। उन्होंने तो इस व्यापार के विस्तार का ममथन किया तथा चावल पर लगे नियात गुल्व का तीव्र विरोध किया। उदाहरणार्थ इपीग्विल रीजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य कलकत्ता के प्रसिद्ध व्यापारी दुर्गाचरण लाहा ने चावल पर गुल्व के आधान की प्रापतिजनक बताया और दावा किया कि इसके हटा देने से जनता का अच्छा वातार मिलन तथा अपन उत्पादना का अच्छा मूल्य मिलन के रूप म भारी लाभ हागा।<sup>100</sup> इसी प्रकार बंगाल बाणिज्य सदन के सचिव न 8 अप्रिल 1889 मे सदन के वार्षिक सम्मेलन को

संबोधित करते हुए इस देश से चावल के निर्यात पर लगाए गए ऊँचे शुल्का के विरुद्ध जोरदार विरोध प्रकट किया।<sup>101</sup>

## निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रवादी नेता भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेश व्यापार की भूमिका के मूल्यांकन में अपने समय से काफी आगे बढ़े हुए थे। उन्होंने मात्र अंतर्राष्ट्रीय श्रमविभाजन के लाभों के प्रचलित सिद्धांत को नकारते हुए इसे अपने आप में लक्ष्य अथवा अपने आप में ही अच्छाई मानने से इकार कर दिया। भले ही इस विषय पर उनकी टिप्पणियाँ भारतीय अर्थव्यवस्था के अर्थ पक्ष पर प्रस्तुत टिप्पणियों के समान विस्तृत नहीं थीं<sup>102</sup> फिर भी उन्होंने भारत के विदेश व्यापार के केंद्रीय स्वरूप को उजागर किया तथा उसे लोकहित पर उसके सामान्य प्रभाव के सदम में ही देखा। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, भारतीय प्रवक्ताओं ने विदेश व्यापार के गुण-दोषों का निष्कर्ष एकांततः राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उद्योग तथा आजीविका के साथ उसके संबंध तथा उनपर उसके प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में ही किया। इसी कारण से उन्होंने मूल रूप अथवा मिश्रित रूप से विदेश व्यापार की उपेक्षा नहीं की और न ही सब प्रकार के विदेश व्यापार को हानिप्रद माना। वे स्वाभाविक अर्थात् देश के उद्योग, देश के हित तथा देश की आवश्यकताओं पर आधारित विदेश व्यापार के विरुद्ध नहीं थे। उन्होंने तो केवल अवाञ्छनीय, औपनिवेशिक स्वरूप तथा बाध्य प्रकृति के भारतीय विदेश व्यापार के विरुद्ध ही आपत्ति की। वे चाहते थे कि औद्योगिक आवश्यकता का ही विदेश व्यापार की सीमा के स्वरूप तथा दिशा के निर्धारण का आधार बनाना चाहिए न कि विदेश व्यापार की आवश्यकता को यह महत्व देना चाहिए। जी० एस० अय्यर ने 1901 के कांग्रेस के अधिवेशन में इस दृष्टिकोण को अत्यंत स्पष्टता से इस प्रकार प्रस्तुत किया

भारत के व्यापार को स्वाभाविक आधार देना ही निकट भविष्य में भारत के पूण आर्थिक विध्वंस की चेतावनी देने वाली विपत्ति से उसके बचाव का एकमात्र उपाय है।<sup>103</sup> स्वाभाविक आधार प्रधानतः यह है कि प्रथम, स्वदेशी उद्योगों के उत्पादन का विस्तृत और असीम बाजारू सभरण देश की विशाल जनसंख्या के लिए सुरक्षित कर लिया जाए और फिर फालतू बचे हुए सामान का विदेशों में निर्यात किया जाए और विनिमय में वे पदाथ मगाए जाए जो भारत में पैदा अथवा निर्मित नहीं किए जा सकते।

इसी दृष्टिकोण की त्कालत इससे पूर्व रानाडे महोदय इन शब्दों में कर चुके थे

हम प्रत्यक्ष स्थिति में सुसंगठित सहयोग द्वारा विदेशियों से प्रतियोगिता करना सीखना है। अपनी आवश्यकतानुसार कच्चा माल विदेश से मगाना है, यहाँ उसे पक्के माल का रूप देना है और अपने कच्चे माल के निर्यात की जगह हमें उसी मात्रा में भारत में काम, बित्तु अधिक कीमती ऐस माल का निर्यात करना है जो कलात्मक ढंग से ढले हुए ह, और हमारे औद्योगिक बग को व्यवसाय प्रदान करते हैं।<sup>104</sup>

इस प्रकार भारतीय नेताओं की दृष्टि में, उद्योग प्रधान रूप में तथा व्यापार गौण रूप

## 144 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विनाश

- 6 भोलानाथ चंद्र द्वारा उद्धृत, एम एम एच II (1873), पृ० 85
- 7 जोशी पूर्वोद्धृत पृ० 696 इसमें पूर्व उद्धृति पतावाची की या कि कक्षा का विस्तार जाह इससे प्रवृत्त के वास्तविक चरित्र का सचित्र म ननुष्य का हस्तप्रम ही कर देना है (पृ० 680) और देखिए जी० एम० अय्यर इंडियन पारिनिगम पृ० 188
- 8 दत्त ई० एच० II पृ० 536
- 9 हिंदू 21 अप्रैल 1884 16 जनवरी 1885 मराठा 25 मई 1884 बगबागा, 2 फरवरी (भार० एन० पी० बग 9 फरवरी 1889) नीरानी स्पीचर पृ० 323 गा० पी० ए० पृ० 164 पर मधोलकर पूर्वोद्धृत पृ० 43 दत्त ई० एच० II पृ० 127 348 534 536 जी० बी० जोशी ने कहा क्या यह अमानाय स्थिति का मंग उद्गारन नहीं है (पूर्वोद्धृत पृ० 617)
- 10 देखिए अध्याय II
- 11 जोशी पूर्वोद्धृत पृ० 641 और रविण जी० एम० अय्यर ई० ए० पृ० 131
- 12 भार० सी० दत्त न अपना पुस्तक इवानामिष हिस्टरी आफ इंडिया, खंड II में रविण एम ए इस प्रक्रिया का सुनिश्चित नेत्रा जोषा प्रस्तुत किया है किमंत कारण यह स्थिति और उनका साथ जुड़ परिणाम अस्तित्व में आए रिणपा रविण पृ० 101 105 108 161-4 34९ 529-32 दूसरा व निर दक्षिण हिंदू 21 अप्रैल 1884 रानाड एमज पृ० 99-101 183-4 जोशी पूर्वोद्धृत पृ० 620-3 641 एव आग रामगायान पूर्वोद्धृत, पृ० 145 पर उद्धृत निरक मधोलकर पूर्वोद्धृत पृ० 41 जी० एम० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1901 पृ० 126 गोखले स्पीचर पृ० 52 और रविण ऊपर अध्याय II
- 13 देखिए अध्याय I
- 14 जोशी पूर्वोद्धृत पृ० 651 (तथा पृ० 622 3 652 680), और रानाडे एसेज पृ० 103 (और पृ 103 एव आग और 119) तथा देखिए दत्त ई एच II प 348 सुधारक 1 अगस्त कसरी 2 अगस्त (भार० एन० पी० बव 6 अगस्त 1898 ने जापान में भारतीय व्यापार की हानि व विरुद्ध विरोध प्रकट किया अध्याय 7 आगे भी देखें
- 15 जोशी पूर्वोद्धृत पृ० 652 रानाड एसेज पृ० 13 एव आग दत्त ई एच II पृ० 531 2 दत्त ने विशेष रूप से मशीनों और मिन सामग्री के आयात व घटने पर शोक प्रकट किया
- 16 जोशी पूर्वोद्धृत पृ० 611 दत्त ई० एच० II पृ० 348 535 6 जी० एम० अय्यर ई ए 352 और अय जिन्का यथोचित स्थान पर बाग म निरेश किया जाएगा
- 17 व तिपय महानुभावा ने आर्थिक रूप से यह स्वीकार किया था कि विदेश व्यापार व कुछ लाभ भी हो सकते हैं रानाडे का यह दृष्टिकोण था कि (विदेश व्यापार में) वृद्धि की अच्छाई तो माना जा सकता है परंतु यह खालिस अच्छाई नहीं (एसेज पृ० 184) तथा देखिए, जोशी पूर्वोद्धृत पृ० 622 और 624 तथा सयानी सी० पी० ए० पृ० 346
- 18 मराठा 25 मई 1884 दत्त इण्ड एंड इंडिया पृ० 127 ई० एच० I पृ० 226 ई० एच० II पृ 132 163 तथा आग
- 19 मराठा 25 मई 1884
- 20 इपीरियल गेजेटियर (1908) खंड III पृ० 298 से गृहीत आयातों में सरकारी भंडारों और कोश की भी परिगणना है
- 21 वस्तुतः यथाथ रूप से अतप्रस्त रशिया के संबंध में भारतीय नेताओं में मतभेद था देखिए भोलानाथ चंद्र एम एम एच II (1873) पृ० 89 इंडियन स्पेक्टेटर 18 मई (भार०

एन० पी० बब, 24 मई 1884) मराठा 25 मई 1884 नोरोजी स्पीचेज, पृ० 321 और पावर्टी पृ० 569 70 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 636-8, 683 मधोलकर पूर्वोद्धत पृ० 40 नदी पूर्वोद्धत पृ० 112, दत्त ई० एच० II, पृ० 528 9 भारतीय नेताओ ने यह भी देखा कि यदि पूजा के आयात और सरकारी ऋण न होते जिनके कारण एक बड़ी सीमा तक आयातों के मूल्य में वृद्धि हो गई है और निर्यातों की अधिकता क्षीण हो गई है तो आयात निर्यात के मध्य की खाई और भी अधिक गहरी होती यह तथ्य 1857 से पूव के कतिपय वर्षों की अवधि में भारतीय व्यापार में आयातों की अपेक्षा निर्यातों की अधिकता की सामान्य प्रवृत्ति के अपवाद का ही सूचक है इन वर्षों में निर्यातों की अपेक्षा आयात अधिक थे इसके कारण से सरकार द्वारा भारी ऋण लेना और रेलों के निर्माण के लिए बड़े पमाने पर विदेशी पूजा का आयात देखिए जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 638 नोरोजी पावर्टी, पृ० 599 जी० एस० अय्यर ई० ए० पृ० 336 553

- 22 नोरोजी एसेज पृ० 113 और पृ० 112 5
- 23 नोरोजी पावर्टी पृ० 141
- 24 वही पृ० 569 और देखिए पृ० 568 74
- 25 जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 618, 637 683 राय पावर्टी पृ० 6, लालमोहन घोष, सी० पी० ए० पृ० 753 मधोलकर - पूर्वोद्धत, पृ० 41, नदी पूर्वोद्धत पृ० 112 3 वाचा सी० पी० ए०, पृ० 602 दत्त इग्लड एंड इंडिया, पृ० 143 ई० एच० II पृ० 348 528 जी० एस० अय्यर ई० ए०, पृ० 336
- 26 इंडियन स्केटेटर 18 मई (आर० एन० पी० बब 24 मई 1884) मराठा, 25 मई 1884 हिंदू 16 जनवरी 1883 दत्त इग्लड एंड इंडिया पृ० 145 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 683 वाचा रिप० आई० एन० सी० 1898 पृ० 101 2 नदी पूर्वोद्धत पृ० 113 जी० एस० अय्यर इंडियन पालिटिक्स पृ० 188 और ई० ए०, पृ० 353 यदि अमरीका के विदेशी ऋणों के सम्मान पृथक भुगतान का प्रयोजन होता तो इसमें मराठा आपत्ति न करता
- 27 समय 30 जून (आर० एन० पी० बग० 5 जुलाई 1884) एल० एम० घोष सी० पी० ए०, पृ० 753 राय पावर्टी पृ० 6 गोखले वेलवी कमीशन, खंड III प्रश्न 18240 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 618 637 8 683 नदी पूर्वोद्धत पृ० 113 दत्त इग्लड एंड इंडिया पृ० 143 ई० एच० II पृ० 127 और जी० एस० अय्यर ई० ए० पृ० 353 1862 से 1888 तक की अवधि के यह प्रभावों की रकमों की अधिक निर्यात की रकमा से तुलना करत हुए जोशी महोदय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे लगभग एक दूसरे के समतुलन में ही थी (पूर्वोद्धत पृ० 637 8) और एल० एम० घोष पूर्वोद्धत स्थल
- 28 समय 30 जून (आर० एन० पी० बग० 5 जुलाई 1884) जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 638 683 695 राय पावर्टी पृ० 6 नोरोजी स्पीचेज पृ० 323 नदी पूर्वोद्धत पृ० 113 दत्त ई० एच० II पृ० 536 जी० एस० अय्यर ई० ए०, पृ० 270-1
- 29 भोलानाथ चंद्र एम० एम० खंड III (1874) पृ० 346 नोरोजी एसेज पृ० 115 6 स्पीचेज, पृ० 323 समय 30 जून (आर० एन० पी० बग०, 5 जुलाई 1884) न्यू इंडिया, 19 अगस्त 1901 दत्त ई० एच० II पृ० 163 343-4 348 528 9 536
- 30 नोरोजी स्पीचेज, पृ० 113
- 31 नोरोजी स्पीचेज पृ० 323 तथा पावर्टी पृ० 182 569

## 146 भारत मे आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास

- 32 भोलानाथ चंद्र एम० एम० छट II, पृ० 89-90 जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 639 राय पावर्टी, पृ० 6-7 मघोनकर पूर्वोद्धत पृ० 41 46 दत्त ई० एच० II, पृ० 127 159 529 536 यू इंडिया 16 गिनकर 1901 इंडियन वीकली 28 जुलाई 1903 और एन० एम० पार मो० पी० ए० पृ० 750 753 और दैयिण ए० बी० पी० 6 फरवरी 1850 17 जुलाई 1892
- 33 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 639 शस्तुन निवासी की कुल राशि निर्माता की दृष्टिगोचर अधिरता से बड़बड़कर की क्योंकि जसा हम ऊपर निर्णय कर चुके हैं निर्माता की वास्तविक अधिरता दृष्टि गोचर से बड़ी भिन्न थी और दैयिण भौरोजी पावर्टी, पृ० 569 और जी० एम० अय्यर ई० ए० पृ० 336
- 34 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 641 तथा पृ० 683
- 35 दत्त ई० एच० II पृ० 127 और दैयिण उनकी स्पीचेज II, पृ० 40
- 36 दत्त ई० एच० II पृ० 348 9 528
- 37 ई० एच० I पृ० 48-9 69 ई० एच० II पृ० 125-7
- 38 केंजवादी यह विचार कि यदि ब्रिटेन जमनी से दक्षिणपूर्व दिशा उगाहना चाहता है तो या तो वह अनिवाय रूप से जमनी का सामान धरीदे अथवा अपने देशवासियों का जमाता जाकर वहाँ की मदिरा पीने की अनुमति दे अनंत मौलिक नहाना था
- 39 भोलानाथ चंद्र एम० एम० छट II (1873) पृ० 90 भौरोजी एसेज पृ० 114 ग्वाचर पृ० 315 इंडियन स्पेक्टेटर, 18 मई (धार० एन० पी० बग 24 मई 1884) मराठा 25 मई 1884 हिंदू 16 जनवरी 1885 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 683 राय पावर्टी पृ० 6-7 मघोनकर पूर्वोद्धत पृ० 46-7 ए० बी० पी० 11 जनवरी 1896 दत्त ई० एच० II पृ० 127 एन० एम० घोष सी० पी० ए० पृ० 752 जा० एन० अय्यर ई० ए०, पृ० 357 8 तथा दैयिण आर० अम्बाम XIII नि ड्रेन
- 40 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 640-1
- 41 बट्टी पृ० 681
- 42 मराठा 25 मई 1884 हिंदू 16 जनवरी 1885 समय, 30 जून (धार० एन० पी० बग 5 जुलाई 1884) हिंदू राजका 28 जनवरी (बही 7 फरवरी 1885) जोशी पूर्वोद्धत पृ० 650-1 696 रानाडे एसेज पृ० 183 185 राय पावर्टी पृ० 93-4 दत्त ई० एच० II पृ० 101 344-5 जी० एन० अय्यर ई० ए०, पृ० 355 357 जे० ए० वाडिया रिप० आई० एन० सी० 1901 पृ० 176
- 43 वा० बी० बसु मे उद्धत पूर्वोद्धत पृ० 52
- 44 एम० एम० छट II (1873) पृ० 90
- 45 दत्त इमलड एंड इंडिया पृ० 127 गोखले स्पीचेज, पृ० 51 (तथा दैयिण गोखले रिप० आई० एन० सी० 1904 पृ० 166) जी० एन० अय्यर ई० ए० पृ० 357
- 46 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 788 9
- 47 रानाडे एसेज पृ० 184-5 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 643 650 दत्त ई० एच० I पृ० 293 6 ई० एच० II पृ० 105 स्पीचेज II पृ० 120-1 गोखले स्पाचेज पृ० 51 2. जी० एन० अय्यर ई० ए० पृ० 355
- 48 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 644-5 रानाडे एसेज पृ० 185
- 49 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 680

- 50 भोलानाथ चद्र एम० एम० खड II (1873), प० 115 मराठा 25 मई 1884 हिंदू, 16 जनवरी 1885 समय, 22 जून (आर० एन० पी० बग० 27 जून 1885) जोशी पूर्वोद्धत, प० 611, 643, 650-1, 683, 696 रानाडे एसेज प० 183 185 राय पावटी प० 93-6 दत्त ई० एच० I प० VIII 276 ई० एच० II, प० 103 345, 531 गोखले स्वीचेज, प० 52 जी० एस० अय्यर ई० ए० प० 355 हितवादी 16 दिसंबर (आर० एन० पी० बग० 31 दिसंबर 1904) और अध्याय II पीछे हां राष्ट्रवादियो ने यह अभिस्वीकार विया कि इस शोचनीय स्थिति के लिए आघात एकमात्र उत्तरदायी तत्व नहीं था और वस्तुतः यह देश पर विदेशी सत्ता के विभिन्न प्रभावो से ही उत्पन्न दुष्परिणाम थे
- 51 जोशी पूर्वोद्धत, क्रमश प० 682 611 651 तथा 645 और रानाडे एसेज प० 184 दत्त ई० एच० II प० 350 जी० एस० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1901 प० 125 अखबारे आम 18 फरवरी (आर० एन० पी० पी० 21 फरवरी 1891) दैनिक-ओ-समाचार चद्रिका 18 अक्तूबर (आर० एन० पी० बग, 22 अक्तूबर 1892)
- 52 जोशी पूर्वोद्धत प० 653 और राय पावटी, प० 95-6 दत्त ई० एच० II प० 345 350
- 53 जी० एस० अय्यर ई० ए०, प० 85
- 54 मधोलकर पूर्वोद्धत, प० 43 और देखिए एन० के० आर० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1901, प० 138
- 55 जोशी पूर्वोद्धत, प० 645 7 मधोलकर ने 50 से 60 करोड़ रुपया की रकम का उल्लेख करते हुए स्पष्टतः जोशी की सगणना पर ही विश्वास किया
- 56 वही प० 682 और 651 क्रमश
- 57 भोलानाथ चद्र एम० एम० खड II (1873), प० 86
- 58 जोशी पूर्वोद्धत, प० 654 वाचा रिप० आई० एन० सी० 1898 प० 101 2 जी० एस० अय्यर इंडियन पालिटिक्स प० 191
- 59 इंडियन स्टेकटैटर ने 18 मई 1884 के अंक में लिखा 'भारतीय खतिहर तो केवल विदेशी निर्यात का पावचक्की उद्योगवाला दास था (आर० एन० पी० बग० 24 मई 1884) और देखिए, हिंदुस्तानी 13 अप्रैल (आर० एन० पी० एन० 21 अप्रैल 1892) वाचा नेलबी आयोग खड III, प्रश्न 17509 10 17516 17524 सी० पी० ए० प० 601, राय इंडियन फॉर्मिस, प० 63 जी० एस० अय्यर इंडियन पालिटिक्स, प० 192 दि वायसरय आन दि इकानामिक कमीशन आफ इंडिया एच० आर० मई 1901 प० 352 और जून 1901 प० 445 रिप० आई० एन० सी० 1901 प० 101 ई० ए०, प० 225 दत्त ई० एच० II प० 348 9
- 60 वाचा सी० पी० ए०, प० 601 और वाचा नेलबी आयोग, खड III प्रश्न 17525 7, 17529 राय इंडियन फॉर्मिस प० 62 3 जी० एस० अय्यर ई० ए० प० 225
- 61 मराठा 16 नवंबर 1902
- 62 जोशी पूर्वोद्धत प० 658 दत्त ई० एच० II प० 350
- 63 जोशी पूर्वोद्धत प० 658 राय इंडियन फॉर्मिस प० 62 3 जी० एस० अय्यर इंडियन पालिटिक्स प० 192 ई० ए० प० 223-6
- 64 जोशी पूर्वोद्धत प० 657
- 65 वही भोलानाथ चद्र एम० एम०, खड II (1873), प० 86 नीरोजी स्वीचेज, प० 596 मधोलकर पूर्वोद्धत प० 42 वाचा सी० पी० ए० प० 603 यू इंडिया 19 अगस्त जी० एस० अय्यर ई० ए० प० 353



- 66 रानाडे एसेज पृ० 65-97 उद्दिष्टि त्रिया सांस्कृतिक पद्धति ने नीरव्यय द्रष्ट इदिया की उच्चतम स्तर का भौतिक समृद्धि प्राप्त म महायता का है (पृ० 79) तथा यन् स्थिति उपयक्त नहीं थी क्योंकि उत्पात्ति सामग्री के ब्रिटिश भारत से निर्यातित कच्चे माल का तयार मान से अनुपात चार के मुकाबल एक था यहाँ नीरव्यय इदिया में यह एक क मुकाबल चार था (पृ० 85) यहाँ यह उल्लेखनीय है कि रानाडे तक तो एक दष्टि, विनशा पूजी की अंगेग भारतीय पूजी प्रयाग से सांस्कृतिक प्रणाली का उत्पन्न विषय था (पृ० 92-3)
- 67 मराठा 25 मई 1884 राय पावर्टी पृ० 15-16 याचा सी० पी० ए०, 603 जा० एम० अम्यर ई ए पृ० 353-55 तुननीय इपीरियल गजटियर खड III पृ० 278 किन्नेन ध्यापार क त्रिए भारत में बाजार अत्यन्त सामित है और उपयुक्त आयाता का एक भारवान भाग भारत में बढ़ते यूरोपीय लोगों का आवश्यकताओं और आवागताओं की पूर्ति के ही काम आता था
- 68 जी० एस० अम्यर ई ए पृ० 355 (तथा पृ० 12) और याचा भा० पी० ए० पृ० 603 गोखले स्पीचेज पृ० 16
- 69 दिडू 21 अप्रैल 1884 बगवासी 2 फरवरी (आर० एन० पा० एन० 9 फरवरी 1889), ताम्रन अखबार 4 जनवरी (आर० एन० पा० पी० 10 जनवरी 1801) राय पावर्टी पृ० 13-4 35 दत्त ई० एच० II, पृ० 348-9 534 536 जी० एम० अम्यर ई ए, पृ० 85
- 70 आर० एन० पी० बग० 13 जुलाई 1889
- 71 भोलानाथ चद्र एम एम खड II (1873) पृ० 82 85-9 खड III (1874) पृ० 310-11 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 611 622 624 5 666 784 788 रानाडे एसेज, पृ० 66 185-6 हिंदुस्तानी 16 सितंबर (आर० एन० पा० एन० 24 सितंबर 1801) पसा अखबार 27 अक्टूबर (आर० एन० पी० पी० 10 नवंबर 1894) नीरोजी स्पीचेज पृ० 341 राय पावर्टी पृ० 321 3 326 भारत जीवन 4 जुलाई (आर० एन० पी० एन० 13 जुलाई 1898) मघोलकर पूर्वोद्धत पृ० 46 नसीम आगरा 15 मई (आर० एन० पी० एन० 18 मई 1901) यू इदिया 19 अगस्त 1901 एडवोकेट 10 जुलाई (आर० एन० पा० एन० 19 जलाई 1902) दत्त ई० एच० II पृ० 536
- 72 भोलानाथ चद्र एम एम खड II (1873) पृ० 88-9 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 631 3 666 783 787 रानाडे एसेज पृ० 185-6 मघोलकर पूर्वोद्धत पृ० 41 नीरोजी स्पीचेज पृ० 341
- 73 जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 66
- 74 वही पृ० 625 और पृ० 633 666 हिंदुस्तानी 16 सितंबर (आर० एन० पी० एन० 24 सितंबर 1891) भारत जीवन 4 जलाई (आर० एन० पी० एन० 23 जुलाई 1898)
- 75 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 634
- 76 वहा पृ० 806-7
- 77 एडवोकेट 19 जून (आर० एन० पी० एन०, 21 जून 1902)
- 78 नीरोजी एसेज पृ० 101 पर उद्धत
- 79 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 641
- 80 याचा रिप आई० एन० सी० 1898 पृ 105 और देखिए राय पावर्टी पृ० 36 नदी पूर्वोद्धत पृ० 125 जी एम० अम्यर ई ए पृ० 357-8
- 81 इपीरियल गजटियर (1908) खड III पृ० 284

- 82 दुर्गाप्रसाद पूर्वोद्धत, 224
- 83 आपताव ए पत्राव, 9 मई (आर० एन० पी० पी० एन० 19 मई 1883) समय, 27 अक्टूबर सोम प्रकाश, 27 अक्टूबर (आर० एन० पी० बग० 1 नवंबर 1884) दाका प्रकाश 2 नवंबर (वही, 8 नवंबर 1884) विस्ता-ए अखबार, 3 जून (आर० एन० पी० पी० 9 जून 1888) रोजाना ए पत्राव, 21 जून (वही, 2 फरवरी 1889) बगवासी 2 फरवरी 6 जुलाई (आर० एन० पी० बग० 9 फरवरी, 13 जुलाई 1889) नवविभाकर साधारणी 27 मई (वही 27 मई 1889), हिंदुस्तानी, 22 अप्रैल (आर० एन० पी० एन० 30 अप्रैल 1891) हिंदी प्रदीप माच, याय सुधा 13 मई कानपुर गजट 15 मई नरग 11 मई (वही, 21 मई 1891) भारत जीवन 15 फरवरी (वही 18 फरवरी 1892) आर० एन० पी० पी० 10 24 जनवरी 21 फरवरी 21, 28 माच 4 11 18 25 अप्रैल, 2, 23 मई 19 दिसंबर 1891 28 जनवरी 21 फरवरी 11 माच, 22 29 अप्रैल 1893 20 जुलाई 1895 26 माच, 28 मई 4 जून 30 जुलाई 1898 28 अक्टूबर 1899 30 जून 1900 म उद्धत पत्राव के लगभग सभी पत्र सम्मिलित हैं दैनिक-ओ-समाचार चट्टिका, 22 जून (आर० एन० पी० बग० 30 जून 1891) हितवादी 25 जुलाई (आर० एन० पी० बग०, 1 अगस्त 1891) बदवान सजीवनी 28 जुलाई (वही 8 अगस्त 1891) बगाली 23 जनवरी 1892 बगनिवासी, 22 नवंबर (आर० एन० पी० बग 23 नवंबर 1895) भारत जीवन 18 मई, भ्रजुमने हिंद, 23 मई (आर० एन० पी० एन० 26 मई 1896) हिंदुस्तान, 13 अक्टूबर (वही 14 अक्टूबर 1896) रहबर 16 फरवरी (वही 24 फरवरी 1897) नज्मउल हिंद 18 अप्रैल दबदबा ए-केसरी 16 अप्रैल (वही 20 अप्रैल और 27 अप्रैल 1898 त्रमश ) हिंदुस्तान 20 मई हिंदुस्तानी, 18 मई (वही, 25 मई 1898) काशी यमव, 26 मई अवध अंधवार 25 मई (वही, 1 जून 1898) भारत जीवन 27 जून सुदेश प्रवतक, जून (वही 6 जुलाई 1898) भारत जीवन 7 अगस्त, 2 अक्टूबर (वही 16 अगस्त 11 अक्टूबर 1899) नदी पूर्वोद्धत प० 113 जी० एम० अय्यर इंडियन पालिटिक्स प० 189 ई ए प० 278 9 285 नक्षीमे आगरा 15 मई रोजानामाच ए केसरी 15 मई (आर० एन० पी० एन० 18 मई 1901) इंडियन पीपल (24 जुलाई 1903) दत्त ई० एच० II, प० 127 (पादटिप्पणी)
- 84 अवध पत्र, 21 मई (आर० एन० पी० एन०, 28 मई 1891)
- 85 आर० एन० पी० एन० 30 जनवरी 1900
- 86 बगवासी 2 फरवरी (आर० एन० पी० बग० 9 फरवरी 1889) दैनिक ओ समाचार चट्टिका, 22 जून (वही, 30 जून 1891) नदी पूर्वोद्धत प० 113 जी० एम० अय्यर ई ए प० 85 110
- 87 आर० एन० पी० बग०, 1 अगस्त 1891
- 88 दत्त ई० एच० II प० 349 और पृ० 536
- 89 दैनिक ओ-समाचार चट्टिका 22 जून 1891 4 सितंबर 1895 (आर० एन० पी० बग०, 30 जून 1891 और 7 सितंबर 1895) हितवादी 25 जुलाई (वही 1 अगस्त 1891) बदवान सजीवनी 28 जुलाई (वही 8 अगस्त 1891) भारत जीवन 18 मई, भ्रजुमन ए हिंद, 23 मई (आर० एन० पी० एन० 26 मई 1896) भारत जीवन 2 अक्टूबर (वही, 11 अक्टूबर 1899) वाचा सी० पी० ए० प० 585 6 जी० एम० अय्यर ई ए प० 110-11
- 90 हितवादी 25 जुलाई (आर० एन० पी० बग० 1 अगस्त 1891)
- 91 दत्त ई० एच० II पृ० 348 9, 534-6 और देखिए अध्याय 13

- 92 याच सौ० पी० ए० पृ० 587 तथा देविण जोषी पूर्वोद्धत पृ० 611, 613 विरसा ए अघवार 3 जून (आर० एन० पी० पी०, 9 जून 1888), अघवार ए आम, 29 जनवरी (वही 2 फरवरी 1889) आपताव ए पजाव 5 जून (वही, 15 जून 1889), हिन्दुस्तानी 22 अप्रत (आर० एन० पी० एन० 30 अप्रत 1891) याच गुधा 13 मई, बानपुर गजट 15 मई, नरग 11 मई (वही 21 मई 1891) भारत जीवन, 15 फरवरी (वही 18 फर० 1892), निराज उल अघवार 16 फरवरी (आर० एन० पी० पी०, 21 फरवरी 1891) केसर उल अघवार 18 माच (वही 21 माच 1891) आपताव ए पजाव 20 माच (वही 28 मार्च 1891) इमीरियल वेपर 11 अप्रैल (वही 18 अप्रत 1891), निम्नी पच 22 अप्रत (वही 2 मई 1891) घरधवाह ए आलम 8 मई (वही, 23 1891) अफताव ए हिं, 16 मई (वही 6 जून 1891) रहबर ए हिंद 20 जुलाई (वही 1 अगस्त 1891) पसा अघवार 14 सितबर बोहिनूर 12 सितबर (वही 19 सितबर 1891) पसा अघवार, 13 मई (वही, 28 मई 1898) अम्बाला गजट 24 मई (वही 8 जून 1898) हितवादी, 25 जुलाई (आर० एन० पी० बग०, 1 अगस्त 1891) बगाला, 23 जनवरी 1892. राय पावटी, पृ० 174-5 रहबर 16 फरवरी (आर० ए० पी० एन० 24 फरवरी 1897) नजमुल हिंद 8 अप्रत (वही 20 अप्रत 1898) देवदा ए केसरी 16 अप्रत (वही 27 अप्रत 1898), हिंदुस्तानी, 18 मई, हिन्दुस्तान, 20 मई (वही 25 मई 1898), काशी धभव 26 मई अघ अघवार 25 मई (वही, 1 जून 1898) राष्ट्र घादियों के इस दृष्टिकोण कि सामान्य मूल्यवद्धि अनहित में न होकर उनमें लिए हानिप्रद है, भी समीक्षा उपर की गई है
- 93 साला भुरलीघर रिप० आई० एन० सी० 1891, पृ० 21
- 94 आपताव ए पजाव 9 मई (आर० एन० पी० पी० एन०, 19 मई 1883), अघवार ए आम, 29 जनवरी (आर० एन० पी० पी०, 2 फरवरी 1889) आपताव ए पजाव 5 जून (वही, 15 जून 1889) पसा अघवार 14 दिसबर (वही 19 दिसबर 1891) भारत जीवन 15 फरवरी (आर० एन० पी० एन०, 18 फरवरी 1892) सिंह सहाय, 11 जनवरी (वही, 21 जनवरी 1893), ताज उल अघवार, 8 अप्रत (वही, 22 अप्रत 1893) भारत जीवन 19 जनवरी (आर० एन० पी० एन० 30 जनवरी 1900) राय इन्डियन फर्मिस, पृ० 64 बगाली 28 अप्रत 1901
- 95 नवविभावर साधारणी 27 मई (आर० एन० पी० बग०, 1 जून 1889), हिंदुस्तानी 22 अप्रत (आर० एन० पी० एन० 20 अप्रत 1891) याच सुधा 13 मई बानपुर गजट 15 मई नरग 11 मई (वही 21 मई 1891) रहबर ए हिंद 20 जुलाई (आर० एन० पी० पी०, 1 अगस्त 1891) पसा अघवार 13 मई 20 जुलाई (वही 28 मई, 30 जुलाई 1898) पसा ए हिंद 16 अक्टूबर (वही 28 अक्टूबर 1899) हिंदी हिंदुस्तान 24 मई (आर० एन० पी० एन०, 1 जून 1901) ए० वा० पा०, 9 जुलाई 1901 जी० एस० अय्यर ई ए, पृ० 111-2 290
- 96 बेसे ए अघवार, 3 जून (आर० एन० पी० पी० 9 जून 1888) रोजाना ए पजाव 28 जनवरी (वही 2 फरवरी 1889) दास्त ए हिंद 3 अप्रत (वही 11 अप्रत 1891) आपताव ए पजाव 20 माच (वही 28 माच 1891) दिल्ली पच 22 अप्रत (वही 2 मई 1891) बोहिनूर 4 फरवरी 8 22 अप्रत (वही 21 फरवरी 22 29 अप्रत 1893) पसा अघवार 27 फरवरी (वही, 11 माच 1893) दैनिक-आ-समाचार चद्रिका 12 मई (आर० एन० पी० बग० 14 मई 1892) और 4 सितबर (वही 7 सितबर 1895)

- 97 ताज उल अखबार 6 जुलाई (आर० एन० पी० पी० 20 जुलाई 1895), पसा अखबार, 20 माच, 20 जुलाई (वही), 10 अप्रल, 30 जुलाई 1897) भवाला गजट 24 मई (वही, 4 जून 1898) सिविल एंड मिलट्री यूज 18 अक्टूबर ताज उल अखबार 14 अक्टूबर (वही) 28 अक्टूबर 1899) ए कारेसपेंडेंट इन सियालकोड पेपर 1 अप्रल (वही, 7 अप्रल 1900) हमदद ए हिंद, 16 जून, (वही 30 जून 1900) भ्रजुमन ए हिंद, 23 मई (आर० एन० पी० एन०, 26 मई 1896) जमाना, 17 सितंबर अनीसे हिंद 16 सित० (वही 23 सित० 1896) हिंदुस्तान, 13 अक्टू० (वही 14 अक्टू० 1896) हितवादी 13 नवंबर (आर० एन० पी० बग०, 21 नवंबर 1896) सजीवनी 26 दिसंबर (वही 2 जनवरी 1897) 13 जनवरी के सप्ताह के सभी उडिया पत्र (आर० एन० पी० बग०, 6 फरवरी 1897) ए० बी० पी० 22 जनवरी 1897 नान प्रकाश, 26 मई बचई समाचार 28 मई (आर० एन० पी० बव० 28 मई 1898), भारत जीवन 3 जनवरी (आर० एन० पी० एन०, 5 जनवरी 1898) जमायुल उल्लाम 18 सितंबर (वही 9 अक्टूबर 1900)
- 98 नेटिव ओपीनियन 25 मई 1884 नवविभाकर साधारणी 27 मई (आर० एन० पी० बग०, 1 जून 1889) पसा अखबार 3 अप्रल (आर० एन० पी० पी०, 15 अप्रल 1893) भारत जीवन, 9 अप्रल (आर० एन० पी० एन० 17 अप्रल 1900) जी० एस० अय्यर ई ए प० 115-7
- 99 मराठा, 24 फरवरी 1884 विकटोरिया पेपर 16 दिसंबर (आर० एन० पी० पी०, 23 दिस० 1893), 8 नवंबर (वही 17 नवंबर 1900)
- 100 एल० सी० पी०, 1882 खड XXI कलकत्ता के अग्रेज व्यापारियों ने स्वभावत ही इस दृष्टि कोण का समर्थन किया (ए० बी० इग्लिस का भाषण वही, प० 300) डी० सी० लाहुरा ने 1889 में इस माग को दुहराया (एल० सी० पी० 1880 खड XXVIII प० 141)
- 101 बंगाल राष्ट्रीय वाणिज्य सदन का 1888 का प्रतिवेदन प० 5
- 102 आशिक्ष रूप से यह इस तथ्य के कारण था कि अयशास्त्रियों को छोड़कर भारतीय नेताओं ने जिन विशिष्ट आर्थिक विषयों पर तथा विदेश व्यापार पर सामान्य चर्चा की, वे वस्तुतः अत्यंत व्यापक विषय थे और उन्हें आसानी से सघन का विषय नहीं बनाया जा सकता था उदाहरणार्थ वपों तथा कांग्रेस के असह्य प्रस्तावों में विदेश व्यापार का उल्लेख नहीं हुआ इसके अतिरिक्त विदेश व्यापार के संबंध राष्ट्रवादी मत की स्वल्पता इस प्रश्न पर अपने आप में उनकी रचि ने अभाव की ही सूचक है
- 103 जी० एस० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 11901, प० 126
- 104 रानाडे एसेज प० 118 तथा देखिए नोरोजी सी० पी० ए०, प० 164 जोशी पूर्वोद्धृत, प० 666-7 वाचा रिप० आई० एन० सी० 1898 प० 105 दत्त स्पीचेज II प० 127
- 105 उाहरणार्थ देखिए भोलानाथ चंद्र का निबन्ध आर० सी० दत्त राइटिंग एंड स्पीचेज जी० एस० अय्यर सम इकानामिक आस्पेक्टस आफ ब्रिटिश इल इन इंडिया
- 106 नोरोजी स्पीचेज क्रमशः प० 601 603 और 604 तथा देखिए नोरोजी वही प० 115-6 190 503 सी० पी० ए० प० 164
- 107 दत्त स्पीचेज II प० 82 3 और देखिए ई० एच० II प० 344 617
- 108 के० एस० शेलवकर दि प्रॉब्लम आफ इंडिया (सदन, 1940) प० 151 3 166-7

## रेले

रेलो के निर्माण द्वारा देश का विकास ही बहू उपाय है जिसके द्वारा कृषि पर निर्भर विशाल जनसंख्या को हालत में अत्यंत सुनिश्चित रूप में निरंतर सुदृढ़ सुधार लाया जा सकता है।

—साइं एलफिन

भारतीय जनता अनुभव करती है कि यह निर्माण काम मुख्य रूप से ब्रिटिश व्यापारी तथा धनी वर्गों के हितों की दृष्टि में ही किया जाता है और यह उन्हें हमारे साधनों के और अधिक शोषण में सहायता देता है।

—गोपालकृष्ण गोयले

रेला के निर्माण का भारतीय जनता के जीवन, संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर एक शक्ति कारी प्रभाव पडा। रेलों की स्थापना से पूर्व अंगरेज शशासक में न भारतीय जीवन में प्रवेश पा सके थे, न भारत को विकासशील विद्यमान की साथ जोड़ सके थे और न ही भारत का पूँजीवादी विकास पथ की दिशा पर डाल सके थे। वस्तुतः देश के विदेशी शासकों ने समय बीतते बीतते रेलों के निर्माण को देश के सभी आर्थिक रोगों की रामबाण औषधि के रूप में लिया और अन्य सभी योजनाओं से उसे प्राथमिकता देते हुए उसके विकास पर शक्ति तथा तीव्रता से बल दिया।

निस्संदेह भारतीय रेलों के निर्माण का इतिहास एक सचिदित तथ्य है, फिर भी देश में रेलों के निर्माण में उत्पन्न होने वाले विविध प्रश्नों पर प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के दृष्टिकोण को सम्यक रूप से समझने के लिए इस विषय का सक्षिप्त विवेचन अनुचित न होगा।

### सक्षिप्त ऐतिहासिक रूपरेखा<sup>1</sup>

ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे प्रथम 1831-2 में मद्रास में ही रेल के निर्माण की योजना बनाई गई। परंतु यह रेलगाड़ी अपनी गति के लिए पशुओं पर निर्भर थी। भारत के लिए सबसे प्रथम भाप रेल गाड़ियों की योजना 1843 में इंग्लैंड में ही तैयार की गई। ईस्ट

इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल ने इस योजना के संचालन के बारे में उत्सुकता नहीं दिखाई क्योंकि उसकी दृष्टि में भारत में इस योजना की असफलता पूर्वसिद्ध थी परंतु वह भारत के साथ व्यापाररत इंग्लैंड के वाणिज्य सदनों, धनकुचेरो तथा रेलपथ के उन्नायको तथा लकाशायर के वस्तु उत्पादको के अपने देश में ही पडने वाले प्रबल आर्थिक और राजनीतिक दबाव को दीर्घ काल तक सहन न कर सका। भारत में कंपनी के अपने ही गवर्नर जनरल लार्ड हार्डिंग ने शांतिपूर्वक यह प्रतिवेदित किया कि भारत के सीधे स्थल-मार्ग रेलपथों के निर्माण के लिए उल्लेखनीय सुविधाएँ जुटाते हैं और रेलपथों का निर्माण वाणिज्य के लिए, सरकार के लिए और देश पर सैनिक नियंत्रण के लिए बहुत ही उपयोगी होगा।<sup>2</sup> ज्यों ही भारत में रेलों के निर्माण की योजना को स्वीकृति मिली त्यों ही कंपनी के निदेशक मंडल और रेलवे के उन्नायको में भारतीय रेल के निर्माण में लगने वाली निजी धनराशि के न्यूनतम लाभार्थ अथवा प्रतिलाभ की शासकीय गारंटी के प्रश्न पर छोटा सा विवाद उत्पन्न हो गया। इस विवाद का निणय भी उन्नायको के पक्ष में गया और 1849 में भारत राज्य सचिव ने ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी तथा ग्रेट इंडिया पेनिंसुला रेलवे कंपनी के साथ प्रथम रेलवे इकरारनामा पर हस्ताक्षर किए। इन अनुबंधों की स्वीकृति की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थीं

- 1 निजी कंपनीया भारत में रेलों का निर्माण और संचालन करेंगी।
- 2 निजी कंपनियों द्वारा जुटाई पूंजी पर 99 वर्ष की अवधि के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी पांच प्रतिशत प्रतिभूत वार्षिक सूद का भुगतान करेगी।
- 3 ईस्ट इंडिया कंपनी का निजी कंपनियों को आवश्यकतानुसार 99 वर्ष के पट्टे पर बिना मूल्य के भूमि देने का दायित्व होगा।
- 4 इन सुविधाओं के प्रतिपादन में कंपनी ने रेलवे के खर्चों और संचालन का नियंत्रण अपने हाथ में रखा।
- 5 रेलों को डाक बिना प्रभारों के और सैनिकों तथा सैनिक भंडारों को घटी दरों पर ले जाना होगा।
- 6 जब तक प्रतिभूति के रूप में उगाही अग्रिम राशियों का भुगतान नहीं हो जाता तब तक प्रतिभूति पांच प्रतिशत वार्षिक ब्याज की राशि से अधिक होने वाले अतिरिक्त लाभ को ईस्ट इंडिया कंपनी और रेलवे कंपनीया आपस में बांट लेंगी। अग्रिम राशियों के चुक जाने के उपरांत सारा लाभ रेलवे कंपनियों को मिलेगा।
- 7 99 वर्षों के उपरांत रेल कंपनीया बिना किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के रेलों सरकार को सौंप देंगी। सरकार केवल मशीनों, सयंत्रों तथा रेलगाड़ी के डिब्बों का मूल्य चुकाएगी।
- 8 ईस्ट इंडिया कंपनी 99 वर्षों से पूर्व, प्रथम पच्चीस अथवा प्रथम पचास वर्षों के उपरांत पूंजीगत सामान्य हिस्सों और सहभागों का पूरा मूल्य चुकाने पर रेलवे को खरीद सकेगी।
- 9 उपर्युक्त अनुबंध के अनुरूप रेलवे कंपनीया किसी भी समय छ मास की चेतावनी देने पर रेलवे व्यवसाय को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप सकेंगी। और उसके उपरांत

निवेशित मूल पूँजी की बसूली की माग कर सकेंगी।

य प्रारम्भिक अनुबन्ध अगली दशक-दियों में हस्ताक्षरित गभीर परिवर्तनों समझौता के लिए जादग रूप बन गए। परन्तु इस समय तब रेल के निर्माण से संबंधित सर्वोत्तम नीति, गति तथा सर्वोत्तम उपायों का विषय में विवाद किसी भी रूप में समाप्त नहीं हो पाया था। कुछ वर्षों तक और इस विवाद में उग्रता तथा क्षुब्धता बनी रही। फिर इंग्लैंड में समाविष्ट प्रतिभूत कंपनियों के माध्यम से ब्रिटिश पूँजी के साथ द्रुत निर्माण में इंग्लैंड अस्याई रूप से हल हो गया। लाड डनहोली ने 1853 में लिखे अपने प्रसिद्ध तथा सर्वांगपूर्ण लेख में इस नीति का स्पष्ट प्रकाशन किया। इस लेख में उन्होंने निर्देश दिया कि यदि ब्रिटिश पूँजी के निवेश क्षेत्र की सम्भाव्यता के सदृश में तथा सनाआ की गतिविधि और युद्धकाल में द्रुतगति के लिए रेलों में अधिक लाभ उठाने की दृष्टि से भारत के यातायात के माधना का एक बार वैधानिक विकास किया जाए तो भारत ब्रिटिश उत्पादकों के माल को खपाने की मंडी के रूप में और वृषि संबंधी वस्त्रों के सभरणकर्ता के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।<sup>4</sup> उन्होंने प्रथम पग के रूप में चार मुख्य चौमुखे रेल मार्गों की पद्धति का सुझाव दिया। इन रेलमार्गों के अंतर्गत अनेक प्रेजिडेंसियों को एक दूसरे से जोड़ा जाए और प्रत्येक प्रेजिडेंसी का अंतरंग प्राकृतिक पतन से जुड़ा हो। चौमुखे रेलमार्ग का देश के वृषिउत्पादकों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए ठोस आधार के रूप में ही लिया गया।

1969 की समाप्ति तक जब इस नीति में परिवर्तन किया गया, प्रतिभूत कंपनियों द्वारा 4255 मील लंबे रेलपथों का निर्माण किया जा चुका था और इस अवधि में प्रतिभूत व्याज की दर साठे चार से पांच प्रतिशत रही।

1869 से पूर्व रेलों के निर्माण के मूल्य बहुत अधिक और अलाभकारी रहे। प्रारम्भ से ही प्रतिभूति के पत्रस्वरूप सरकार द्वारा कंपनियों को ऊँचे भुगतान करने पड़े। लाड डनहोली ने जहाँ प्रतिमील रेलपथ के निर्माण का औसत व्यय 8000 पाँड बूता था, वहाँ वेमोल दी गई भूमि के मूल्य के अतिरिक्त ही वास्तविक व्यय लगभग 18000 पाँड प्रति मील आया।<sup>5</sup> इस अधिक व्यय के अनेक बहुमुखी कारण थे काय का प्रारम्भिक स्वरूप, कुशल श्रमिका का अभाव स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी का अभाव अनुभवहीनता, चौड़े रेलपथों का चुनाव निर्माण का अनावश्यक रूप से ऊँचा स्तर अनावश्यक दोहरी पटरियाँ आदि परन्तु ऊँचे व्ययों के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी तत्व था, अत्यधिक प्रतिभूति पद्धति जिसने कंपनियों के लिए रेलपथों के निर्माण और संचालन में मित्त व्यय की प्रेरणा अथवा प्रोत्साहन का कोई अवकाश ही नहीं छोड़ा था, इसने उलटे कंपनियों को लगभग अनावश्यक व्ययों के लिए ही प्रोत्साहित किया क्योंकि जितना ऊँचा पूँजीगत व्यय होगा उतनी ही अधिक सुरक्षित और प्रतिभूत व्याज की बसूली होगी।

भारत के एक भूतपूर्व वित्त सदस्य डब्ल्यू० एन० मसी ने 1872 में अपने साक्ष्य में कहा 'रेलपथों पर व्यय की जाने वाली सारी धनराशि अंगरेज पूँजीपतियों से आती थी और जब तक उसे भारत के राजस्व में से पांच प्रतिशत व्याज की प्रतिभूति प्राप्त थी, तब तक उसकी बला से चाहे उधार दी गई धनराशि हुगली में फँकी जाए अथवा ईंट गारा

बनाने के काम में ली जाए।<sup>6</sup> इस दृष्टिकोण के फलस्वरूप जहां उचित व्यय पर सूद की रकम के भुगतान के लिए पर्याप्त आय होने की संभावना थी, वहां वास्तविक व्यय पर प्रतिभूत सूद के भुगतान के लिए ही आय अपर्याप्त रही और सरकार को स्वयं ही घाटा पूरा करना पड़ा।<sup>7</sup> इस नियमित और बढ़ते हुए घाटे ने राज्य के राजस्व को बुरी तरह से प्रभावित किया<sup>8</sup> और इसका अपरिहाय परिणाम यह निकला कि रेलपथों के निर्माण की गति को मंद कर देना पड़ा। गवर्नर जनरल जान लारेंस ने जनवरी 1869 में लिखे अपने विस्तृत और सुबद्ध लेख में यह सुझाव दिया कि वर्तमान व्यवस्था को, जिसके अंतर्गत सारा लाभ कर्पणियों को मिलता है और सारा घाटा सरकार को उठाना पड़ता है,<sup>9</sup> समाप्त कर देना चाहिए। प्रतिभूति के लौटा लेने के फलस्वरूप यदि निजी उद्यम भविष्य में रूपया लगाने को अग्रसर नहीं होते तो सरकार प्रतिभूति दर की अपेक्षा अथवा सीधे राजस्वों से रूपया लेने की अपेक्षा स्वयं ही सूद की सस्ती दर पर ऋण लेकर रेलों का निर्माण तथा संचालन करे। भारत सचिव ने इस योजना को स्वीकार कर लिया और 1870-80 की अवधि में स्वयं सरकार ने अपने व्यय से ही रेलों का निर्माण किया। कुल 8,494 मील लंबे रेलपथों में से 1880 तक लगभग 2493 मील रेलपथ का निर्माण सरकारी अधिकारणों ने ही किया।

यद्यपि राज्य द्वारा संचालित रेल व्यवस्था प्रतिभूत रेल व्यवस्था की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत सस्ती और अधिक सफल थी तथापि प्रधान रूप से निर्माण की गति को तीव्रता देने में उसकी असफलता के कारण उसपर शीघ्र ही प्रहार किए जाने लगे।<sup>10</sup> लक्ष्यसिद्धि में राज्य के राजस्व अपर्याप्त सिद्ध हुए। 1880 के अकाल आयोग के सुझाव के अनुसार अकालों से सुरक्षित रहने के लिए देश को 20,000 मील लंबे रेलपथ की आवश्यकता थी।<sup>11</sup> अकाल आयोग द्वारा अनुशंसित रेलपथों के निर्माण में द्रुतगति की प्राप्ति के लिए वर्तमान नीति से प्रत्यावर्तन की सर्वप्रथम लाइ रिपन के नेतृत्व में स्वयं भारत सरकार द्वारा ही जबदस्त बकालत की गई। इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिए 1884 में एक संसदीय प्रवर सीमित नियुक्त की गई। उसने रेलों के निर्माण के द्रुतविकास और उसके लिए दोनों, राज्य तथा निजी, अधिकारणों से लाभ उठाने की सिफारिश की। इस उद्देश्य की प्राप्ति में निजी उद्यम स्वतः साहसपूर्वक आगे नहीं आ रहे थे अतः सरकार को एक बार पुनः प्रतिभूति व्यवस्था का सहारा लेना पड़ा। हा, यह बात अवश्य है कि इस बार शर्तें उतनी दुस्रह नहीं थी। राज्य अधिकारण का भी साथ साथ उपयोग चलता रहा। इसके उपरान्त तो रेलपथों का विस्तार ऐसी तीव्र गति पकड़ गया जिसे कुछ लोगों के अनुसार चरम गति कहा जा सकता है। 30 जून 1905 तक 359 करोड़ रुपये (अथवा 240,000,000 पाउंड) से निर्मित लगभग 28054 मील रेलपथों का यातायात के लिए उद्घाटन हो गया था।

अंत में 1905 तक भारतीय रेलपथ विकास के संक्षिप्त ऐतिहासिक सर्वेक्षण से प्राप्त उससे प्रमुख चार पक्षों को रेखांकित करना अनुचित न होगा

(क) सभी प्रकार की व्यावहारिकता की दृष्टि से भारतीय रेलपथों के निर्माण में भारतीय पूंजी की भूमिका नगण्य ही थी। इस काय की मिट्टि में ब्रिटिश पूंजी का ही



योगदान महत्वपूर्ण है। रेलपथों के निर्माण काय के लिए ब्रिटन से भारत आने वाली पूंजी इतनी अधिक थी कि उस 19वीं शताब्दी के विदेशी निवेश की सबसे बड़ी एकाकी इकाई कहा जा सकता है।<sup>1</sup>

- (स) भारतीय रेलपथों के संवर्धन में घाटे के सतत होने का तैयार वास्तविक निजी उद्यम का लगभग अभाव ही था क्योंकि इनके उन्नायक और रपया लगाने वाले इस उद्यम की सामान्य आगवाआ को ही भेजने के लिए तैयार नहीं थे। वे या तो सरकारी प्रतिभूति मिलने पर ही काय मचालन को प्राथमिकता देते थे अथवा रेलपथों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए ऋणपत्रों में धन के निवेश के पक्ष में थे।
- (ग) शताब्दी के अंत तक तो भारतीय रेलों अपने पर निवेशित पूंजी पर देय ब्याज का ही चुकाने के योग्य नहीं थी। 1900 तक, जब उन्होंने प्रथम बार शुद्ध लाभ बनाया, उस समय तक सरकार को प्रतिभूत ब्याज राशि के भगतान के लिए 76 करोड़ रपयों का भारी बोझ उठाना पड़ा।
- (घ) समीक्षाधीन अवधि के अंतिम वर्षों के दौरान कुल मिलाकर सरकार के लिए आर्थिक कठिनाइयाँ और जनता के लिए अकाल और प्लेग जैसे रोगों के वायजुद रेलपथों का निर्माण पर्याप्त तीव्र गति से हुआ। जहाँ 1850-1891 की अवधि में 17308 मील लंबे रेलपथों का निर्माण हुआ, वहाँ 1892-1905 की अपेक्षाकृत स्वल्प अवधि में 10746 मील लंबे रेलपथों का निर्माण हुआ। बैंक के निदेशानुसार ग्रेट ब्रिटन तक में रेलपथों का विकास इस तीव्र गति से नहीं हुआ था और फ्रांस में जिन रेलपथों को अपने यहाँ सपाया उनके निर्माण की गति भारत की अपेक्षा मद थी।<sup>23</sup>

### रेल विस्तार का गति विषयक राष्ट्रीय दृष्टिकोण

ज्यों ही कुछ वर्षों में रेल के निर्माण काय ने वेग पकड़ा त्योंही भारतीय मत के प्रवक्ताओं ने रेलपथों के विस्तार, मगठनात्मक तथा वित्तीय व्यवस्था पर अपने विचार और दृष्टिकोण के निर्धारण और प्रकाशन की आवश्यकता अनुभव की। उन्होंने रेल के निर्माण की गति विषयक अपने में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार किया और उसकी आवश्यकता के बारे में कोई संदेह नहीं किया।

भारतीय नेताओं ने न तो विशुद्ध सैद्धांतिक आधार पर इस प्रश्न का उत्तर दिया और न ही रेलों के गुण दोषों पर उनके शुद्ध रूप में विचारविमर्श किया। उनका दृष्टिकोण प्रमुखतया वर्तमान रेलों के भारतीयों के हितों पर और देश के आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी के संदर्भ में ही निर्धारित था। जी० वी० जोशी महोदय ने अपने लेख, 'दि इकानामिक रिजल्ट्स आफ़ फ्री ट्रेड ऐंड रेलवे एक्सपेंशन' में इस तथ्य का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया। उनका यह लेख पूना सावजनिक सभा के अक्टूबर 1884 के जनरल में प्रकाशित हुआ। इस लेख में उन्होंने भारत के रेलपथों के असीमित प्रसार की मांग के संवर्धन में नाकाम को अभिव्यक्ति देने का दावा करते हुए लिखा

जो सज्जन इसकी पूव प्रदर्शित बुराइयों को तथा भविष्य में और अधिक सपीडक बुराइयों की चेतावनी को भली प्रकार और पूण रूप से सिद्ध मानते हैं, उनका यह क्तव्य हो जाता है कि वे उन सिद्धांतों पर शांत चित्त से विचारविमश करें जिनके आधार पर एक पक्षीय विकास की क्वालत की जा रही है। वे सज्जन इस सबध में देश की अयव्यवस्था पर भविष्य में सम्मानित दुष्परिणामों के सदम में स्थिति की समीक्षा करें। इस सबध में राज्य के विगत काय के देश की आर्थिकता और आय-व्यय स्थिति पर पडे प्रभावों पर गभीर विचार किए बिना इस प्रश्न का उत्तर देना सगत नहीं होगा।<sup>14</sup>

### रेलो का आर्थिक प्रभाव

ब्रिटिश दृष्टिकोण के अनुसार देश पर वतमान रेलों का प्रभाव पूणत सुखद ही पडा है।<sup>15</sup> प्रारभ में ही रेलों के द्रुत विकास की क्वालत करते हुए ब्रिटिश अधि कारियों ने लोकोपकार की अपील की और घोषणा की कि रेलों से दश की दरिद्रता और दुर्भिक्ष के उमूलन में सहायता मिलेगी। 1844 में भारत में रेलों के अग्रदूतों में प्रमुख जान चैपमैन ने निम्नलिखित टिप्पणी में भारतीय रेलों के उद्देश्य का समथन प्रस्तुत किया 'राजमार्गों का अभाव दरिद्रता का अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट कारण है और रेलें भारतीयों को दरिद्रता से समृद्धि की ओर लाने का साधन है।'<sup>16</sup> 1884 की ससदीय प्रवर समिति ने इस तक पर रेलों के द्रुत विस्तार का समथन किया कि इससे देश की दुर्भिक्षा से सरक्षण मिलेगा, बाहरी और भीतरी व्यापार को गति मिलेगी, उपजाऊ प्रदेश और बौयले की खानें खुलेंगी और कुल मिलाकर जनता की जाधिक स्थिति में सुधार होगा।<sup>17</sup> 1896 में गवनर जनरल लाड एलगिन ने बडे ही आत्मविश्वास के साथ घाषणा की कि रेलों का निर्माण कृपि पर निमर भारत की बहुसख्यक जनता की भौतिक स्थिति में एक निश्चित और निरतर सुधार का साधन है। उसने आशा प्रकट की कि भारत की महान रेल व्यवस्था को देश की जनता की भौतिक सपनता, सामाजिक प्रगति और राजनीतिक शाति का एक अत्यंत सशक्त अभिकरण बनाया जा सकता है।<sup>18</sup>

दूसरी ओर भारतीय नेताओं का निष्कप सवथा विपरीत था। हा, उन्होंने रेलवे के वास्तविक और सभव निम्नलिखित प्रधान लाभों को दृष्टिगोचर अवश्य किया सस्ती और द्रुत परिवहन की व्यवस्था, राष्ट्रीय सद्भाव और सगठन में प्रगति, नई मडी का उद्घाटन, आजीविका के नवीन साधनों की सृष्टि, स्वदेश तथा विदेश व्यापार को प्रोत्साहन, दुर्भिक्षों का निरोध, कृपि फसलों के उत्पादन में गतिशीलता, उद्योगीकरण की प्रक्रिया पर प्रत्यक्ष प्रभाव इजिनियरिंग उद्योगों और कर्मशालाओं को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन और सामान्य रूप से देश के उद्यम का क्षेत्रविस्तार।<sup>19</sup> परंतु उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के समान सभव और यथाथ के अतर को विहृत नहीं होने दिया। यह सत्य है कि रेल के प्रारभिक वर्षों में और विरल रूप से कालांतर में भी कुछ भारतीय नेता रेलों द्वारा सपन किए जाने वाले कार्यों से चुधिया गए थे तथा रेलों के द्रुत विकास की माग में ब्रिटिश नेताओं का हृदय से साथ देने लगे थे।<sup>20</sup> किंतु, जब उन्होंने वास्तविक लाभों की यथाथ

परीक्षा की तो उन्हें निराशा ही हाथ लगी क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ लाभ का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था और कुछ रेलों के निर्माण से होने वाली हानियों के परिणामों में ही नामशेष हो गए थे।

1883 में दादाभाई नौरोजी ने शिवायत की कि भारत का दुर्भाग्य यह है कि अन्य प्रत्येक देश में रेलों से मिलने वाले लाभ इस उपलब्ध नहीं। 1888 में जोगी महान्य ने टिप्पणी की कि राष्ट्र की औद्योगिक गतिविधि के विविध विवास के लिए रेलों का अर्थ व्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव अत्यंत हानिकारक सिद्ध हुआ है। उन्होंने भारत जैसे देश में सामाजिक गति से स्वस्थ भौतिक विवास की दिशा में बाधक बनने की रेलों की प्रवृत्ति की निंदा की। 1897 में डी० ई० वाचा ने वेल्बी आयोग के समक्ष कहा 'रेलवे से जथव्यवस्था तथा प्रबन्ध व्यवस्था की दृष्टि से जनता को कुछ हानियाँ ही पहुँची हैं।' 1898 में जी० एस० अथर ने बलपूर्वक कहा कि वर्तमान रेलवे नीति देश के लिए 'बहुमुखी रोग' सिद्ध हुई है। आर० सी० दत्त का विश्वास था कि कुन मिलानर रेलवे के आर्थिक प्रभाव लाभप्रद नहीं थे। तिलक महोदय ने तो इनके विवास के समय ही अपना विश्वास प्रकट करत हुए कहा था 'रेल तार और मजदूरी जैसे साधनों की भारत के लिए कोई उपयोगिता नहीं। वे तो एक प्रकार से 'दूमरे की पत्नी को अलटूत करने' के समान हैं। यहाँ तक कि जस्टिस रानडे का भी यही मत था कि रेलों ने भले ही और कितना लाभ पहुँचाए हों परन्तु उन्होंने राष्ट्र की प्रगति को पगु बनाने वाली निधनता स्त्री विशेष दुबलता का कोई प्रतिहार नहीं किया।<sup>21</sup> बहुत सारे भारतीय समाचारपत्रों ने इसी प्रकार के परन्तु अत्यधिक उग्र समीक्षापरक विचार प्रकट किए। उदाहरणार्थ, 30 अप्रैल 1884 के अंक में सहचर ने तीव्रता से लिखा 'लौहपथों के विस्तार का अर्थ लौहवहन' है। 31 मई, 1891 के अंक में दैनिक-ओ-समाचार चंद्रिका ने घोषणा की कि 'रेलें देश की दरिद्रता के गन में घकेल रही हैं। 29 जून 1903 के अंक में 'मदोवत' ने अपनी धारणा प्रस्तुत करते हुए लिखा 'वरदान के स्थान पर अभिघात' ही सिद्ध हुई है। इंदु प्रकाश ने अभियोग लगाते हुए लिखा 'रेलों ने भारतीय समृद्धि को घातित पहुँचाई है।

राष्ट्रवादियों ने रेलों का घातक प्रभाव सबसे प्रथम औद्योगिक गतिविधि को पहुँची घातित के रूप में ही देखा। भारतीय बड़े उद्योगों के रूप में ममकालीन औद्योगिक क्रांति के अभाव में परिवहन क्रांति ने भारत के वर्तमान भारवाहक उद्योगों को विनष्ट कर दिया था। इंग्लैंड के सस्ते मशीनी उत्पादन ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के उत्पादकों की विक्री को प्रभावित करके इन उद्योगों का गना ही घोट दिया। भारत की अर्थव्यवस्था को सहारा देने के बदले रेलों ने तो उसे गढ़े में ही घकेल दिया। भारत का धीरे धीरे ग्रामीकरण होता गया और वह धीरे धीरे ग्रीटन की अन्न उगाने वाली बस्ती में बदल गया। 1884 में जी० वी० जाशी ने लाड इलहीजी और उसके उत्तराधिकारियों की उस रेलनीति पर शाक प्रकट किया जिसने आश्चर्यजनक रूप से धोड़े ही समय में देशी उद्योगों का सफाया कर दिया था और देश को दिवालियपन और विनाश के कगार पर खड़े करके उस चरम पतन की ओर उन्मुख कर दिया था।<sup>22</sup> जस्टिस रानडे भी वर्तमान रेलनीति

की निंदा में पीछे नहीं थे। उन्होंने कहा 'रेलो ने अनेक क्षेत्रों में भारत की यूरोप के साथ निराशाजनक प्रतियोगिता उत्पन्न कर दी है और यूरोप के सामान को परिवहन की सुविधाएँ इस हद तक जुटाई हैं जो किसी भी अन्य साधन से संभव नहीं थी। कुछ प्रमुख नगरों को छोड़कर रेलों ने स्थानीय देशी उद्योगों को नष्ट भ्रष्ट ही कर दिया है और एकमात्र अवशिष्ट साधन—कृषि पर लोगों की निर्भरता बढ़ाकर उन्हें पहले से भी अधिक अमहाय बना दिया है।'<sup>4</sup> जी० एस० अय्यर ने पूणतेजस्विता के साथ उदघोष किया 'इस देश में रेलपथ के प्रत्येक अतिरिक्त मील का निर्माण देश के किसी न किसी उद्योग के कफन में एक नया कील है।'<sup>5</sup> और इसी तेजस्विता के साथ उन्होंने लिखा 'रेलो को भारतीय जनता को उन्हे दुर्भाग्यग्रस्त बनाने वाली निधनता के फँसान के लिए उत्तर देना ही पड़ेगा।'<sup>6</sup> इसी प्रकार के विचार अथ लोकनेताओं तथा भारतीय समाचारपत्रों ने भी प्रकट किए।'<sup>7</sup>

जी० बी० जोशी न और गहराई से अनुभव किया कि वस्तुतः रेलों पर प्रतिभूत व्याज के सरकारी व्यय विदेश व्यापारी के लिए एक प्रकार के सहायक का ही कार्य करते थे। उन्होंने विरोध प्रकट करते हुए कहा 'इस प्रकार तो भारत को विदेशी व्यापारी अथवा उसके देशवासियों को अनुग्रह राशि देने के रूप में उसे स्वदेशी उत्पादकों के साथ प्रति योगिता की सुविधाएँ जुटाने के लिए विवश किया जा रहा है।'<sup>8</sup> विदेशियों के साथ पहले से ही प्रतियोगिता में असमान भारतीय व्यापारी को इस विधि से तो और भी अधिक पगु बनाया जा रहा है।

कुछ भारतीय नेताओं का कथन था कि रेलपथों का निर्माण स्वदेशी उद्योगों के विनाश की एक अपरिहार्य प्रक्रिया नहीं है। इस औद्योगिक और परिवहन क्रांति का यह परिणाम अन्य देशों में नहीं हुआ है। रेलों ने सभी देशों में नए प्रकार की आर्थिक गतिविधियों की प्रतिष्ठा चाहे की हो परंतु भारत के विषय में इस दुखद स्थिति का कारण यह है कि यहाँ रेलों ने उत्पादक गतिविधियों की रक्तवाहक धमनियाँ में रक्तसंचार का कार्य ही नहीं किया क्योंकि उनका प्रधान उद्देश्य इंग्लैंड में कारखानों में काम करने वालों, इस्पात और मशीनी निर्माण कार्य में सलग्न लोगों को काम जुटाना था न कि भारत में। स्वभावतः आंतरिक मंडी के विस्तार के सारे लाभ ब्रिटिश उत्पादकों को ही उपलब्ध हुए, भारतीय उत्पादकों को नहीं।<sup>9</sup> इससे रेलों का विकास भारतीय अर्थव्यवस्था के अतगत और क्रमिक रूप से समजन करत हुए नहीं हुआ परंतु घातक दुष्प्रभावों की उपेक्षा करते हुए इसे भारत पर थोप दिया गया। इसपर क्षुब्ध होकर जी० एस० अय्यर ने पूछा 'क्या विनाशकी प्रक्रिया को मद और क्रमिक नहीं बनाया जा सकता जिससे लोगों को सास लेने का समय तो प्राप्त हो सके।'<sup>10</sup>

हाँ, नई पद्धति के कुछ एक उद्योगों, विशेषतः आगान उद्योगों, को रेलव से संपन्नता अवश्य मिली परंतु उससे अधिकांश लाभ भी विदेशी उद्योगियों ने उठार लिए। इस प्रकार का आर्थिक विकास निश्चित रूप से विदेशी पूँजी द्वारा दत्त का शोषण ही था।<sup>11</sup>

रेलों का दूसरा हानिप्रद परिणाम था देश से धन की निःकासी में बढ़ोतरी। भारतीय नेताओं का कथन था कि 'भारत की विचित्र राजनीतिक स्थिति के कारण रेलपथों का

निर्माण विदेशी पूँजी से किया गया है और उनका प्रशासन भी वहाँ के विदेशी कर्मचारियों के हाथ में है। इसके फलस्वरूप भारत द्वारा व्याजा और लाभों के, आयातित सामान के, यूरोपीय कर्मचारियों की सेवाओं के और इन्डम प्रवृद्ध व्यवस्था पर हानि वाले व्ययों के मुगलान रूप में धन की विपुल राशि इंग्लैंड को भेजनी पड़ती है। व्याजा के मुगलान की राशि भले रेल व्यय का एक स्वल्प भाग थी परन्तु विदेशी धन में रेलों का निर्माण करने वाला सभी दशाओं में यह राशि सामान्य रूप से ही चुगानी पड़ रही थी। राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र अर्थात् दशा की अव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के मुकाबले भारत की अव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव नितान्त और स्पष्ट रूप से भिन्न था।<sup>17</sup> धन की कटौती हुई निकामी ने रेलों के अत्याय लाभों को संवदा नष्ट भवे ही न किया हा परन्तु उह धुधला अवश्य कर दिया था। यही कारण था कि दादाभाई नौरोजी ने 1876 में विस्मित हात हुए कहा था 'यहाँ रेलों तथा दूसरे लाभों की व्यवस्था ता होनी चाहिए परन्तु उनका स्वाभाविक लाभ हम पहुँचना चाहिए अन्यथा एक भूखे व्यक्ति के सामान बढ़िया खाने के आनंद की चर्चा करना व्यर्थ है।'<sup>18</sup> जी० एम० अय्यर ने टिप्पणी करते हुए कहा 'स्वतंत्र भारत रेल द्वारा प्रदत्त अय लाभों के बढ़ते इन धन की निकामी को भी सहन कर लेता परन्तु भारत को तो पहले से ही अत्याय मद में लगभग तीन करोड़ पाँच विदेशों को दना पड़ता है। अतएव भारत रेलों द्वारा की जा रही धन की अतिरिक्त निकामी को किसी भी प्रकार सहन करने की स्थिति में नहीं है।'<sup>19</sup>

राष्ट्रवादियों द्वारा रेलों की एक अय कट्टी समीक्षा का कारण यह था कि रेलें अनाज के निर्यात को सुविधाजनक बनाकर देश में सामान्य काल में भी अनाज की अपर्याप्तता की स्थिति उत्पन्न कर रही थी तथा देश का अपन सामान्य अतिरिक्त अनाज से धूय करके उस प्राय आने वाले दुर्भिक्षों का आसान शिकार बना रही थी।<sup>20</sup> इस धारणा ने इतना अधिक व्यापक रूप ल लिया कि अतत लाड कजन को 1901-02 के वित्त प्रतिवेदन के समापन भाषण में इसका उत्तर देने को विवदा हाना पडा। उसने इन तर्कों का प्रथम स्तर का और संवदा निराधार एक भ्रम बतात हुए इस तथ्य का संवदा नकार दिया कि रेलों से अनाज के निर्यात में किसी प्रकार की वृद्धि हुई है अथवा इस प्रकार की वृद्धि में रेल किसी प्रकार से कारणभूत है। उनके विचारानुसार तो यह भी सत्य नहीं था कि भारत के कुल उत्पादन का एक बहुत बड़े भाग का निर्यात किया जाता था। उसका कथन था कि सत्य इसके विपरीत है। रेलों ने फालतु अन्न क्षेत्र से अभावग्रस्त क्षेत्र में अन्न पहुँचाने की, विदेशी बाजारों से अन्न के आयात को संभव बनाने की तथा इस प्रकार से दुर्भिक्षों की प्रचंडता का मद करने की सामर्थ्य जुटाई है।<sup>21</sup> इस कथन के विरुद्ध भारतीयों ने तत्काल अपनी प्रतिनिधियाँ इस प्रकार व्यक्त की, रेलों के प्रधान समय का नहीं यह दावा करना छोड़ दिया है कि रेलें दुर्भिक्षों का राकने में समर्थ हैं। उनका कथन था कि आयातों तथा आंतरिक पुनर्वितरण रेलों के द्वारा दुर्भिक्षों की तीव्रता को मद करने के दावे को भी 19वीं शती में पडे लो दुर्भिक्षों के अनुभव न भुठलाकर रख दिया है।<sup>22</sup> जी० एस० अय्यर ने तर्क दिया कि इन दुर्भिक्षों के समय बर्मा के सिवाय किसी भी अन्य देश से अनाज का आयात नहीं किया गया। इतना ही नहीं प्रत्युत उस अकाल की अवधि में भी अनाज के द्रुत निर्यातों द्वारा

क्षुद्र आतंरिक सभरण को और भी मद कर दिया गया।<sup>39</sup> समस्या का एक अय दृष्टिकोण से परखते हुए 'बंगाली' न 28 अप्रैल 1901 के अय में तब प्रस्तुत किया रेलों ने वाणिज्य फसला के निर्यात को उत्तेजित करने अप्रत्यक्ष रूप से दक्ष के साथ सभरण को क्षतिग्रस्त किया है क्योंकि इसका परिणाम यह हुआ है कि कृषक साथ फसलों के स्थान पर नकदी फसलों उपजाने लगे हैं।'

राष्ट्रवादी नेताओं ने इस ओर भी निर्देग किया कि भारतीय रेलें व्यापारिक दृष्टि से भी मफल नहीं थी क्योंकि वे पिछली एक लबी अवधि में विशेषतः 19वीं शताब्दी के अंत तक आत्मनिर्भर ही नहीं थी और घाट को पूर्ति विदेशी निवेशकों के बदले भारतीय सरकार के रूप में भारतीय जनता द्वारा ही की जाती थी। उन्होंने बार बार और जोर देकर कहा कि भारतीय जनता की घोर दरिद्रता के सदम में इन घाटा का बोझ असह्य रूप से भारी था और किसी भी रूप में रेलों से प्राप्त लाभों के समवक्ष नहीं था।<sup>40</sup> डी० इ० वाचा महादय ने 1901 में कांग्रेस के सभापतीय अभिभाषण में रेलों की उप योगिता को स्वीकार करते हुए स्पष्ट शब्दों में प्रश्न उठाया कि 'क्या भारत जैसे किसी भी दरिद्रतम देश के लिए इन वार्षिक घाटों की विलासिता का जुटा पाना संभव है?'<sup>41</sup>

कुछेक भारतीय नेताओं ने यह भी देखा कि प्रचलित रेल नीति न जहा सामान के आयात निर्यात को निरंतर प्रोत्साहन दिया है, वहा देश के आतंरिक व्यापार और उद्योग के विकास के प्रति उपक्षा ही नहीं दिखाई प्रत्युत उसपर प्रहार भी किया है।<sup>42</sup> जी० एम० अय्यर महोदय 1898 में रेलें व्यापार का जीवन हं गार की सारथकी जाच करते हुए इस परिणाम पर पट्टे के कि 1891-2 से 1896-7 की अवधि में रेलों तथा नौकाओं द्वारा एक प्रांत से दूसरे प्रांत में ढोए गए माल की कुल मात्रा, पत्तनों के लिए ढोए गए सामान को छोड़कर, प्रतिवर्ष 130 451 000, से 167, 65, 640 मन के बीच थी, जबकि इसी अवधि में पत्तनों के लिए ढोए गए व्यापारिक माल की मात्रा 165,105,000 से 185, 199,000 मन के बीच थी।<sup>43</sup> उन्होंने एक अय स्थान पर कहा कि यदि प्रशासन का उद्देश्य आतंरिक उद्योग का विकास करना होता तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही पत्तन सावनों की ओर अधिक ध्यान दिया जाता।<sup>44</sup> 1888 में आयात निर्यात को प्रोत्साहन देने वाला दर नीति की प्रवृत्ति पर जी० वी० जोशी ने अत्यंत विलक्षण सूक्ष्म बुद्धि से गहरे विचार प्रकट किए। उन्होंने इस तथ्य की ओर देखा और इसकी तीखी मालोचना की कि भारतीय रेलपथा पर सामान ढुलाई की दर बहुत ही नीची है यहा तक कि इंग्लैंड के दरों से और कितन ही अन्य यूरोपीय देशों के रेलों की दरों में नीची है। यही कारण है कि उससे सेवा प्रभार तथा यात्रियों का भुगतान ही नहीं जुट पाता और प्रतिभूत प्रणाली के अंतगत नारा घाटा राजस्व से पूरा करना पड़ता है। उन्होंने निरूप रूप में कहा, नीची दरों के कारण किए जाने वाले भुगतान विदेशी व्यापार के सवधान के लिए ही चालू रहे जा रहे हैं और यह वस्तुतः राज्य द्वारा विदेश को उसके व्यापार पर दिए जाने वाला उपहार ही है।<sup>45</sup> इन कुछेक कुशल निरीक्षकों को छोड़कर अन्य भारतीय नेताओं ने रेल समस्या के इस पक्ष की कुल मिलाकर उपेक्षा ही की।<sup>46</sup> इसका एक प्रधान कारण यह था कि भारतीय उद्योग अभी रेलों की दर नीति को चुनौती देने में पर्याप्त मशवत नहीं था।

उनका विकास अधिकांश पत्तन तगरा में हो रहा था, जहाँ वे पत्तना के हज़ में रेल दरो से सामान रूप से लाभान्वित हो सकते थे। इस प्रकार न तो राष्ट्रीय नेतृत्व के किसी भी वर्ग ने किसी भी स्थिति में सामान दुर्गम पी दरा का सामान्य रूप में और विदगा व निर्धारित किए जाने वाले कच्चे माल की दुलाई की दरा का विशेष रूप से घटाने का आग्रह किया और न ही दश के विकासशील व्यवसायी उद्यमी वर्ग ने इस प्रकार की काद माग प्रस्तुत की।<sup>47</sup>

भारतीय नेताओं के अनुसार यदि सरकार ने उद्यम के क्षेत्र में एक मवया नए उद्योग के रूप में आविर्भूत रेल उद्योग को समुचित समय पर भारतीयों द्वारा अपने हाथ में सभालने के लिए तथा पशासन में उहू अधिनाधिक भागीदार बनाने के लिए समुचित प्रवध किए होते तो भारतीय जयव्यवस्था का विरुद्ध करने वाले तथा पूजा के भार में दमाने वाले रेल उद्योग के धूमिल चित्र में भी आशा की एक रजत किरण दिखाई देती, परंतु उनका यह स्पष्ट अनुभव था कि रेलों के निमाण का प्रात्माहण देत समय यह विचार विदेशी शानकों के मस्तिष्क में ही नहीं था। इससे विपरीत राज्य और रेल कपनियों दोनों में भारतीयों को ऊंचे पदा और तकनीकी स्थानों में फोसा दूर रखा। इसी का परिणाम था कि आज सरकार के निरंतर पन्चीस वर्षों के दिशा निर्देशन व उपरात भी देशवासी रेलपथ के निमाण काय का जयवा रेल प्रवध को सभानन में उतन ही अव्योग्य थे जितने उस समय थे जब लाड डलहीजी न पहनी वार भारत को रेलपथा व जाल में ढकने की योजना का स्वीकृति दी थी।<sup>48</sup>

जी० वी० जोशी और जी० एस० अय्यर महानुभावों के अनुसार रेलों का एक राज नीतिक प्रभाव भी था जो अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता था। जाशीजी के अनुसार राष्ट्र के हिता के लिए सवया हानिकारक जमाखोरा का एक प्रवध विदेशी बुलीन तत्र अस्तित्व में आ रहा था। अय्यर महादय के अनुसार विदेशी रेल कपनिया तो भारतीयों के हिता को आघात पहुचाने वाले तथा पहल से ही अत्यधिक शक्तिशाली विदगियों के निहित स्वार्थों में और अधिक वद्धि ही करेंगी।<sup>49</sup>

उस युग के किसी भी महत्वपूर्ण भारतीय विचारक की दृष्टि में न आए हुए रेलों के प्रभाव के कुछ पक्षों का यहाँ अध्ययन रोचक होगा। प्रथम, कृषि में व्यावसायिक क्रांति अर्थात् नवद उपजा की जोतमीमा में विस्तार तथा स्थानीय उपजा में विविधताकरण पर जो कदाचित पूणतमा न सही जाशिक रूप में जवदय ही रेलों की ही दन थी, किसी विचारक ने टिप्पणी नहीं की। दूसरे यद्यपि कभी कभी मूल्यों की समानता के तथ्य को अभिलिखित किया गया<sup>51</sup> तथापि रेलों द्वारा सारे देश में मूल्यों की समानता की बल्पना के अथवाश्रीय महत्व को भां भुला ही दिया गया। अंतिम, रेलों द्वारा भारतीय ध्यापार और पूजा के भारत के ग्रामों में पहुचन के लिए जुटाए गए अवसरों की ओर भी किसी का ध्यान नहीं गया जोर इसलिए इन किसी न अनुकूल विकास के रूप में स्वीकार नहीं किया।

यहाँ मह ध्यान में रखना आवश्यक है कि जैसाकि अभिवोग लगाया गया है सामाजिक रूढ़िवांता के साथ साथ स्थिर अप्रगतिशील अव्यवस्था के आदश की दृष्टि से रेलों

और रेलो के भारत पर प्रभाव की भारतीय नेताओ द्वारा आलोचना नहीं की गई।<sup>5</sup> रेलो के सभी भारतीय आलोचक न केवल आधुनिक उद्योग के प्रबल पक्षधर थे प्रत्युत उनमे से अधिकांश प्रगतिशील विचारो के व्यक्ति थे। यह हम पूर्ववर्ती अध्याय मे पहले ही दिखा चुके हैं कि लोकप्रिय समाचारपत्रा तब मे जहा थाडी-बहुत रूढिवादिता छाई हुई थी वतमान समाजव्यवस्था को नष्ट-भ्रष्ट करन वाली के रूप मे, रेलो की मामूली सी ही आलोचना की गई।<sup>53</sup>

वस्तुतः भारतीय नेता रेलो के विरुद्ध कदापि न थे। वे तो उस विशेष समय मे उसकी संचालन पधति के ही विरोधी थे।<sup>54</sup> भारतीय अथव्यवस्था पर रेलो के वास्तविक प्रभाव की जांच करने पर उहे यह विदित हुआ कि अधिकारियो द्वारा पहले से दिलाई गई आशाओं और अपेक्षाओ के विरुद्ध रेलें, पूण वरदान नहीं थी और भारतीय अथव्यवस्था के सतुलन पर उनका प्रभाव निषेधात्मक था। वे भारतीय अथव्यवस्था के वतमान पिछडेपन को जारी रखन वाली और उसे बढ़ाने वाली ही थी। रेलो से जो कुछ भी लाभ उपलब्ध हुए थे, वे सारे के सारे विदेशी व्यापारियो न ही हडप लिए थे। अतएव उनका यह निष्कप था कि रेलें, जो सशकन समद्विप्रद हो सकती थी इस समय एक सकट बनी हुई थी। भारत के राजस्व पर पडने वाले आर्थिक भार के अनुरूप वे कदापि वाछनीय नहीं थी और जसाकि हम आगे चलकर दिखाएंगे, भारतीय नेताओ की उस समय निश्चित धारणा थी कि यदि भारतीय अथव्यवस्था को प्रोत्साहन देना ही उद्देश्य है तो इन आर्थिक साधनो का रेलो के बदले और कही अच्छी प्रकार से उपयोग किया जा सकता है।

### ब्रिटिश उद्देश्य

भारतीय राष्ट्रीय नेताओ के इस निष्कप से यह प्रासंगिक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि ब्रिटिश अधिकारी और लेखक रेलो के द्रुत निर्माण के लिए इतना अधिक दबाव क्यों डाल रहे हैं ? भारत के शासक विशेषतः 1884 के उपरांत और लाड एलगिन और लाड रुजन की वायसरायो की अवधि मे इस काय के लिए असाधारण रुचि और उत्साह क्यों दिखा रहे हैं ? अथवा प्रश्न का इस रूप मे प्रस्तुत किया जा सकता है कि रेलो का उद्देश्य किसके हितो की सेवा करना है ? ब्रिटेन द्वारा प्रस्तुत यह विश्लेषण सहजता से भारतीयो के गले के नीचे नहीं उतर पा रहा था कि रेलपथो का निमाण लोकसवा के उद्देश्य से प्रेरित है। उह यह विश्वास ही नहीं होता था कि उनके गणतन्त्र भारतीयो के हितसाधन की भावना से ही इन काय मे प्रवृत्त हुए हैं अथवा रेल निर्माण के पीछे भारत के आर्थिक विकास की सच्ची प्रेरणा ही काम कर रही है। वे इस तथ्य को स्वीकार करते थे कि किन्ही मामलो मे रेलो के प्रति उत्साह अज्ञान और यूरोप की स्थितियो के साथ भारत की स्थितियो की गलत तुलना का परिणाम हो सकता है।<sup>55</sup> उनका निश्चित मत था कि ब्रिटेन के उद्देश्य वास्तव मे ही कुल मिलाकर अत्यंत निम्नस्तर के कल्पित और स्वाधपूण थे। ये प्रयोजन अपन तात्विक रूप मे उन ब्रिटिश व्यापारियो उत्पादको और निवेशको के हितो की पूर्ति करते हैं जिनके निरंतर दबाव के अन्तगत भारतीय राजस्व के व्यय और खतरे के मूल्य पर



रेलवे का निर्माण किया गया है और किया जा रहा है। रेलपथों का जाल विद्यमान या वास्तविक उद्देश्य ब्रिटिश उद्यमता भारत के प्राकृतिक भाषना के मापण में सहायता देना ही है।<sup>15</sup>

भारतीयों के अनुसार भारत में रेल निर्माण का गतिशील बनना वाला एक महत्वपूर्ण कारण भारत के गामना की यह इच्छा थी कि भारत में आन्तरिक प्रान्तों में एक विस्तृत आर वास्तव में अथ तब न दाही गई एक एसी मंडी गाली जाए जो एक आर ब्रिटिश उद्योगों के उत्पादनों को खपाए और दूसरी आर ब्रिटन की भूखी मशीनों और प्राणियों के लिए प्रयोग कच्चे माल और साधनों के निर्यातों की सुविधाएं जुटाए। इन प्रकार भारत को ब्रिटन में लिए कच्चे माल का गभरण करने वाले वृष्टि उपनिवेशों के रूप में परिवर्तित करना ही भारत के गामनों की इच्छा थी।<sup>16</sup>

सरकारी रेल नीति के प्रवर्तन में विदेशी व्यापार की आधारभूत भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बहुत से भारतीय विचारकों ने इन नीतियों की मरचना में अपनी अपनी दृष्टि में उत्तरदायी अथ अनव दायों और प्रयाजनों की भी चचा की। उनमें एक इंग्लैंड के इस्पात उद्योग के सामान की रस्ताव भठारा लोह की पटरियां, इजिन, ड्रिं व और दूसरी मशीनों तथा मयंत्र के निर्यातों के द्वारा निर्यातों की व्यवस्था की आवश्यकता थी।<sup>17</sup> रेल अस्मय्य अगरेजा का विदेशक से लेकर टिकट वमूनन वाले तब के रूप में लाभप्रद नीवरिया की सुविधाएं भी जुटाती थी।<sup>18</sup> कुछ भारतीय नेता सही तौर पर यह समझ में भी सफत हो गए, यह समझ उनकी समकालीन आर्थिक प्रक्रियाओं की गहरी समझ की परिचायक है, कि राज्य के स्वामित्व वाली तथा कंपनी के स्वामित्व वाली दोनों रेलें फालतू ब्रिटिश पूंजी के सुरक्षित और लाभप्रद निवेश के सात वा फाय वगन का उद्देश्य लिए हुए हैं और इस दिशा में प्रवृत्त भी हैं। इस सत्रध में कुछ विचारकों की इस समझ की भी भठक मिलती है कि रेलें भारत पर विदेशी शासकों के राजनीतिक प्रभुत्व को सुदढ बनाने का ही आधार थी।

सरकारी नीति के उद्देश्यों के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण का जी० एस० ज्यर महोदय ने 1898 में बड़ी सफलतापूर्वक संक्षेपत निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया इंग्लैंड के निवेशक, कंपनी के उन्मायक, धनकुचर, लोहाधिपति, कायला स्वामी, रस्ताव इजीनियर और निदेशक तथा इन सबसे बढचटकर अपनी पेंशन में महत्वपूर्ण बढि की इच्छा रखन वाले सेवानिवृत्त पेंग्लो भारतीय कमचारी, सबके सब भारत में रेलों के निर्माण को द्रुतगति देने में रुचि रखते हैं। वे यूरोपीय व्यापारी भी जिनके हाथ में भारत का सारा विदेश व्यापार है और जिनका व्यापार अब ममुद्र के तटवर्ती नगरों तक सीमित न रहकर भारत के ग्राम प्रान्तों में फलन जा रहा है, समान रूप में भारतभूमि में रेलों के जात के प्रसार के लिए उत्सुक हैं।<sup>19</sup>

बहुत गार भारतीयों ने अनुभव किया कि यह सारी दुखद स्थिति अत्यंत क्षोभप्रद हो जाती थी जब भारतीयों के हिता की धनि बढाकर रेलों के सारे लाभ इंग्लैंड उठाता था और उनके भारत को भारत उठाता था।<sup>20</sup> इससे यह विचित्र प्रक्रिया दखन में आई कि 'पन्व दायित्व के नाम पर ब्रिटिश शासक उस देश की सहायता कर रहे थे जिसे कम से

चम भारत की महान दुभाग्यवस्तु निभरता को भी शक्तिहीन करने के मूल्य पर, उसकी आवश्यकता बढ़ाए नहीं थी।<sup>61</sup>

## भारतीय कसौटी

भारत सरकार की रेल नीति को ब्रिटेन की आवश्यकताओं से प्रेरित सिद्ध करने के उपरांत कुछ भारतीय नेताओं ने रेल विधायन की गति और इस महत्त काय की प्राथमिकता के निर्धारण के लिए अपनी एक् कसौटी निश्चित की आवश्यकता अनुभव की। इस समस्या पर उनका विचारविमर्श न केवल उनकी परिवहन नीति पर और उनके विचारानुरूप देश की अव्यवस्था के विनास में उसकी भूमिका पर प्रकाश डालता है, प्रत्युत स्वयं उनके दृष्टिकोण के आर्थिक विकास की रूपरेखा को भी उजागर करता है।

सबप्रथम, उनका सवधा उपयुक्त और सुदृढ तर्क था कि रेलों को भारत की वर्तमान विशिष्ट आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में देश के आर्थिक विकास में उनके यागदान के सदम में ही दर्शना चाहिए।<sup>65</sup>

द्वितीय, उनका मतव्य था कि परिवहन और उद्योग में उद्योग का महत्त्व प्राथमिक और परिवहन का महत्त्व गौण है क्योंकि किसी भी उपयुक्त रूप में देखें तो आर्थिक विकास का आधार उद्योगीकरण ही है। जी० वी० जोशी ने 1884 में लिखा औद्योगिक प्रगति अतत आवश्यक रूप में उत्पादन वृद्धि पर निभर है न कि अंतर्राष्ट्रीय विनिमय की सुविधाओं की वृद्धि पर। वस्तुतः उद्योगों का एक सामान्य समन्वय राष्ट्र की समृद्धि का जीवन रक्त है।<sup>66</sup> इसी तथ्य की सबल पुष्टि में बवई के नेटिव ओपीनियन ने 25 मई 1884 के अक में रेल प्रवर समिति की कांयवाही पर टिप्पणी करते हुए लिखा

हमारी विनम्र सम्मति में भारत में रेल प्रसार के विषय से सबधित वर्तमान समिति की अपेक्षा विभिन्न उद्योगों के प्रारंभ की योजना की परिकल्पना के लिए एक आयोग की स्थापना अपेक्षाकृत अधिक लाभदायक होगी। इस दिशा में विकास का अर्थ हमारे साधनों का समुचित रूप में विधास नहीं है।

जी० एस० अय्यर ने भी इस विषय पर बल देकर कहा

सरकारी राजस्व धन संपत्ति के उत्पादन के सवधन पर खर्च न होकर केवल सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जान के लिए खर्च किए जा रहे हैं। यह एक स्पष्ट बात है कि जो थोड़ी सी संपत्ति पहले से ही किद्यमान है उसको इधर-उधर करने की अपेक्षा नई संपत्ति के उत्पादन का लक्ष्य अधिक महत्त्वपूर्ण है।<sup>67</sup>

इसके अतिरिक्त रेलों को अपने आप में उपयोगिता देग की उत्पादन शक्ति पर निभर है।<sup>68</sup> अर्थात् राष्ट्रीय आर्थिकता और उद्योग द्वारा उनके उपयोग की क्षमता पर आश्रित है। जब तब रेलें राष्ट्रीय उद्योगों के अपेक्षाकृत अच्छे संगठन के लिए लाभप्रद अथ अधिक महत्त्वपूर्ण माधनों को साथ नहीं ले पाती तब तक वे अकेले उम दश की प्रबल शक्ति में योग नहीं दे सकती, जो अकेले ही उनकी व्यापक महत्ता की सुदृढ आधारशिला की व्यवस्था करता है।<sup>69</sup> जब और ज्यों ही देश का उद्योगीकरण हो जाएगा तब अधिकाधिक रेलें भी बनाई जा सकेंगी। परंतु इस समय जबकि दश वृत्तिप्रधान है, तब

रेलपथा का निमाण सबथा निरथक ही है।<sup>१०</sup> इसवे विपरीत यदि रेलो के साथ साथ भारत के उद्योग और व्यापार का विकास होना तो रेलो का विकास स्वस्थ और लाभप्रद भी होता और जन समयन का अधिकारी बनता।<sup>११</sup> उदाहरणार्थ 30 अप्रैल 1884 के अक मे सहचर ने लिखा

पहन स बन रेलो क लिए पर्याप्त मात्रा म यातायात को पाना आवश्यक है परंतु यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि देश के निजी उद्योग का विकास नहीं होना।

पहने इस देश म बपडे की मिलें लोहे की ढलाई के कारखाने और इस प्रकार अन्य औद्योगिक प्रयत्ना की स्थापना होने दीजिए, तब दखिए रेलों कच्चे माल और पक्के उत्पादना के बाह्य व्यवसाय को किस प्रकार लाभप्रद बनाती हैं।<sup>१२</sup>

परंतु पर्याप्त विश्वास के साथ आशा किए जान पर भी वास्तव म एसा कुछ न हुआ।<sup>१३</sup> भारतीयों ने सोचा कि रेलों अपन आप न तो उद्योग का जन्म दे सकती हैं और न ही देश की आर्थिकता के विकास का जन्म कर सकती हैं।<sup>१४</sup> इसके लिए तो कुछ और परिस्थितिया भी अपेक्षित थी। भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ न यह देखा कि उनका अनुभव अमरीका के अनुभव म सप्रथा भिन्न रहा है। वहा तो औद्योगिक क्रांति का जागे ले जान मे रेलें सहायक रही हैं।<sup>१५</sup> इसके विपरीत भारत म रेलो न औद्योगिक आंदोलन का उदासीन बनाने म भारत के प्राकृतिक संसाधनों के शोषण म तथा विदेशी व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहन देने मे महायत्ना दी है। वाणिज्य की शक्ति न औद्योगिक नहीं, केवल व्यावसायिक क्रांति का ही प्रवर्तन किया है।<sup>१६</sup> रेलो ने यहा तो सामान्य पथो पर स्वस्थ भौतिक प्रगति का अवरोध करके तथा राष्ट्रीय गतिविधि को उसके अपने ही तंत्र मे अस्तव्यस्त करके आधुनिक उद्योग के विकास मे बाधा पहुंचाई है।<sup>१७</sup>

इस सबका स्पष्ट अभिप्राय यह था कि द्रुत औद्योगिक विकास के बिना रेलो के विकास की चर्चा एक प्रकार से पागलपन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं थी अथवा जी० वी० जार्जी के शब्दों मे इस दश मे देश के आर्थिक साधनों के बाहर अमरीका की गति पर रेलो को जागे बनाने की सुस्पष्ट नीति यदि अपन माय अपेक्षाकृत अधिक महत्व के अन्य आर्थिक उपायों को नहीं अपनाती तो राष्ट्र की दरिद्रता के रूप मे ही उसका अंत होगा।<sup>१८</sup>

अन्तिम, भारतीय नेताओं ने बताया कि भारत के साधन अत्यंत सीमित हैं और उनसे अत्यंत निस्तत क्षेत्र मे काय नहीं किया जा सकता और क्षुद्र साधनों के कारण अनेक क्षेत्रों म म हमें चनाव करना है। भारतीय लोकतांत्रिकों के मन म सदेह का लेश भी नहीं था कि औद्योगिक पिछड़ापन भारतीय अर्थव्यवस्था का विषम पाप है और उद्योग को परिवर्धन पर प्रमुखता अवश्य ही मिलनी चाहिए।<sup>१९</sup> उन्होंने इसलिए सरकार से पिछवाले रेलों का दो जाने वाली राजकीय महायत्ना का अधिक उत्पादक प्रयास, उद्योग और निवेश की ओर दिशा परिवर्तन की माग की।<sup>२०</sup>

उन्होंने औद्योगिक आवश्यकताओं के साथ रेलो के सुसंगत समन्वयन के अतिरिक्त कुछ अन्य अभिमथानों का भी प्रस्तुत किया। वचाहृत थ कि रेलो के निमाण की गति तथा कायक्षेत्र के निरणय म उन अभिमथानों को समुचित महत्व दिया जाए। इस प्रकार

का निर्धारक और सीमक तत्व था भारतीय वित्त की विपन्न अवस्था और करगता पर पहल से ही भारी बोझ। व्यापक दृष्टि से उनका मतव्य था कि रेलों के निमाण में अपनाई जा रही द्रुतगति की दर के औचित्य को सिद्ध करने के लिए न तो भारत पर्याप्त धन सपना था, न उसके साधन पर्याप्त विस्तृत थे और न ही उसके वित्त पर्याप्त समृद्ध थे।<sup>81</sup> उनके विश्वासानुसार दूसरी विचारणीय बात यह है कि रेल निर्माण को प्रवानतया उपलब्ध स्वदेशी पूँजी पर ही निर्भर रखना चाहिए।<sup>82</sup> रेलों के विस्तार काय के लिए स्टलिंग ऋण में और अधिक वृद्धि किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे केवल भारत से धन की निवासी में ही वृद्धि होगी।<sup>83</sup>

भारतीय नेताओं के अनुसार वर्तमान स्थिति में शाचनीय तथा सतकता की अपेक्षा करने वाला एक अय तत्व यह था कि अधिकतर प्रारम्भिक रेलों की पटरियों के लिए भारत को अनुवधित और निश्चित एक शिलिंग दस पेंस के लिए एक रुपया विनिमय दर पर प्रतिभूत ब्याजों के भुगतान के लिए इंग्लैंड को रुपया भेजने में विनिमय पर होने वाला भारी घाटा था तथा रेलों पर लिए गए ऋणों पर ब्याज के पौडों में भुगतान के लिए राज्य रेलवे ने लंदन के वित्त बजार में उस समय अनुवध किया था जब पौडों के मुकाबले भारतीय रुपये की कीमत निरंतर घट रही थी।<sup>84</sup>

बहुत सारे भारतीयों का यह भी मत था कि नई रेल लाइनों की स्वीकृति से पूर्व यह सम्यक रूप से देखभाल कर निश्चित कर लेना चाहिए कि वे आर्थिक रूप से कदा तक लाभप्रद हो सकती हैं।<sup>85</sup> उनकी यह युक्तियुक्त धारणा थी कि बहुत सारे रेलपथ आर्थिक दृष्टि में लाभप्रद नहीं हैं। यदि यह सत्य नहीं है तो फिर ब्रिटिश पूँजीपति प्रतिभूति बिना पाए ही क्या नहीं इन रेलपथों के निमाण को हाथ में लेते ?<sup>86</sup>

कुछेक का तो यहाँ तक मत था कि रेलों की कितनी ही विशेषताएँ क्यों न हों आर्थिक राजनीतिक, सैनिक तथा अजाल सुरक्षा आदि उद्देश्यों के लिए आवश्यक जितने रेलपथ बनने में, पहले ही बन चुके हों। अब तो सरकार को अपना सारा ध्यान राष्ट्र के पुनर्निमाण के अत्याय क्षेत्रों की ओर देना चाहिए। नए रेलपथों के निमाण में तो तभी हाथ लगाना चाहिए जब उपर्युक्त सभी दूसरे पक्ष अनुकूल हों।<sup>87</sup>

भारतीय राष्ट्रवादी भारतीय वित्त की स्थिति, स्वदेशी पूँजी की अप्राप्तता, वर्तमान और निमाणधीन रेलों का लाभप्रद न होना, भारतीय उद्योग के साथ रेलों के सम्बन्ध की आवश्यकता और साथ ही विविध आर्थिक पक्षा और शक्तियों के बदलते महत्त्वों के कारण रेलपथों के कुछ विस्तार की अपरिहायता की सम्भ्र इन सभी पक्षा पर सामूहिक रूप से विचार करने के उपरांत 1884 के<sup>88</sup> पदचात यह अनुभव करने लगे कि यद्यपि रेलों के द्रुत विकास की जयवा उनके अधाधुध विकास की आवश्यकता तो नहीं है फिर भी आवश्यकता के अनुरूप उचित समय पर रेलें बनाई जा सकती हैं परंतु इस दिशा में सरकारी तौर पर जिस गति की बकालत की जाती है उसकी अपेक्षा अत्यधिक मद गति ही अपनाते की आवश्यकता है।<sup>89</sup> कइया न तो इसमें यह व्यत भी जोड़ी कि सरकार रेलपथों के और अधिक विस्तार का दायित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्षरूप से लोक वित्तों पर न डाले।<sup>90</sup> सभी भावी पथों का निर्माण विशुद्ध व्यावसायिक दृष्टि से हो

अर्थात् राज्य को स्वयं न तो किसी प्रकार में भागीदार बनना चाहिए और न ही राज्य के द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति दी जानी चाहिए। निजी कंपनियों का स्वयं ही खर्च उठाकर यह कार्य करना चाहिए।<sup>91</sup>

इस सदन में 1898 में फोर्लर जायोग के समक्ष अपना साम्य प्रस्तुत करने हुए और सी दत्त महोदय ने एन. जदमुत सुझाव दिया कि 'नई रेलों की स्वीकृति से पूरा लाभ प्रति निधियों से परामर्श कर लेना चाहिए। एक जय स्थल पर उन्हां जोर देकर कहा रेल नीति के संबंध में सरकार लोकोचिता की वनि चढ़ा रही है, इसका कारण यह है कि प्रभावशाली वर्गों के मुकाबले बचारी जनता को अपना मन अभिव्यक्त करने तथा उमर नवान का सांविधानिक अधिकार ही प्राप्त नहीं है।<sup>92</sup>

### संगठन का स्वरूप

भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने रेलों के निर्माण की गति के संबंध में विस्तृत विवेचना के अतिरिक्त रेलों के संगठन के स्वरूप पर भी ध्यान दिया, परंतु उन्होंने इस संबंध में समस्या के केवल एक पक्ष अर्थात् रेलों के निमाण और प्रबंध के लिए उपयुक्त अभिकरण की ओर ही ध्यान दिया। इस संबंध में यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि भारतीय नेता विनेपत 1884 के उपरांत, रेलों के द्रुत विस्तार के निरुद्ध थे, जो उनका सारा शोध इसी एक पक्ष पर केंद्रित रहा। फलतः रेल निमाण के अभाव पक्षा पर राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति बिरल तथा त्रिकोण ही रही। सभी प्रश्नों का उत्तर दे यह कहकर देते थे कि हम रेलों की कोई आवश्यकता नहीं।

लाड रिपन के वायसराय काल में उम समय भारतीय जनता की दृष्टि में रेल के निमाण के लिए प्रत्यक्ष राज्य अभिकरण के और निजी कंपनियों के सापेक्ष लाभ का प्रश्न सामयिक विवेचन का विषय बन गया, जब वायसराय के वित्त सदस्य इथेलिन बरिंग ने 1881 में निजी निमाण के पक्ष में सरकारी एकाधिकार के आशिक परित्याग, अर्थात् सरकारी सहायता के बिना जयवा किसी भी स्थिति में इस प्रकार की 'यूनितम सहायता की वकालत की। बाद में 1883 में भारत सरकार ने योजना बनाई कि उत्पादन के पथ निजी कंपनियों की पट्टे पर दलित जाए और सामाय मिद्धत के रूप में सरकार व्यावसायिक दृष्टि में जलाभप्रद हाने के कारण से अथवा किन्हीं जय कारणों में निजी कंपनियों द्वारा न किए जा सकने वाले रेलपथों का निर्माणकाय ही करे।<sup>93</sup> परवर्ती वर्षों में इस नीति पर व्यापक रूप से अमल किया गया और उत्तराधिकारी राज्यसचिवा गवर्नर जनरल तथा राबर्टसन जैसे रेल अधिकारियों द्वारा इसका अनुमोदन और प्रशसन किया गया।

दूसरी ओर रेलों के विनाश से संबंधित तथा सभी भारतीयों को समान रूप में प्रश्न या प्रतिभूति प्रयास भारत का पट्टे चने वाली हानि। उनकी दृष्टि में इस राष्ट्रीय वित्त पर असह्य भार पड़ता था, अतः भविष्य में इस जागी न रखने की प्रवृत्ति और जय रिहाय आवश्यकता थी।<sup>94</sup> भारतीयों के मत में इस प्रतिभूति का अत्यंत आपत्तिजनक पक्ष यह था कि इस कंपनी को अधिकारपूर्ण और परिणामहीन किन्तु स्वयं न लिए

प्राप्ताह्न मिलता था। कंपनी के पास मितव्ययी होने के लिए कोई प्रेरणा ही नहीं थी क्याकि वह जितना भी व्यय कर ले, सरकार उसपर प्रतिभूत व्याज राशि दन को प्रस्तुत थी। उल्लखनीय यह है कि यह उस समय था जबकि व्याज राशि में अधिक उपाजन की कोई समावना ही नहीं थी।<sup>95</sup> जुलाई 1881 में पूना की 'मावजनिक सभा' पत्रिका में अज्ञाननाम लेखक के प्रकाशित एक लेख, 'पार्लियामेटरी कमेटी आन इडियन पब्लिक वर्क' में जस्टिस रानाडे ने रेल प्रतिभूति के विरुद्ध भारतीय चिंतन का बड़े ही रोचक और संक्षिप्त रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया

व्याज की प्रतिभूति निर्धारित दर बहुत ऊंची होने के कारण (इंग्लड में पूजी पर मिलन वाले लाभ से बहुत ही ऊंची) यह पाया गया है कि कंपनीया रेलों के निर्माण में अथवा निर्माण के उपरांत उनके प्रबंध में पर्याप्त रूप से मितव्ययी नहीं हैं। उनका हित वस्तुतः इसी में था कि वे यथासंभव व्यय की राशि का जब ऊंचा रखें क्योंकि जितना अधिक धन वे लगा पाएंगी, उतनी अधिक ही प्रतिभूति व्याजराशि को पान की व अधिकारी होगी।<sup>96</sup>

जब एक बार रेलों की प्रतिभूति प्रथा को समाप्त कर दिया गया और यह तथ्य भी स्वीकार कर लिया गया कि कुछ नवीन रेलपथों का निर्माण अपरिहाय था, ता प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि निर्माण काय के लिए क्या विकल्प व्यवस्था अपनाई जाए। राष्ट्रवादी इन विषय में एकमत नहीं थे। एक वर्ग की मान्यता थी कि करदाताओं पर और अधिक भार न डालने की दृष्टि से सरकार को रेलपथों पर जन क्रांश का व्यय नहीं करना चाहिए तथा नए निर्माण का सारा क्षेत्र वास्तविक अप्रतिभूत निजी उद्यम पर छोड़ देना चाहिए।<sup>97</sup> दूसरा, और कदाचित अधिक मुत्तर तथा दूसरे पक्ष से भी प्रबलित वर्ग जिमके अंतगत जी० बी० जोशी तथा अन्य महानुभाव सम्मिलित थे। निजी स्वामित्व का विरोधी तथा सरकारी उद्यम का समर्थक था। दूसरे वर्ग के पक्षधरों द्वारा अपने समयन में प्रस्तुत कारणों की समीक्षा में पूर्व हम यहां यह बताना चाहेंगे कि प्रथम मत के पक्षधरों ने भी उही कारणों के आधार पर यह मांग की थी कि सरकार को उपयुक्त समय पर कंपनियों के साथ किए गए समझौतों और निर्धारित शर्तों के अनुरूप प्रतिभूत रेलों को सरीदने के अधिकार अपने हाथ में रखने चाहिए।<sup>98</sup> इसके अतिरिक्त वे सरकार द्वारा निर्मित अथवा अधिकृत रेलों के संचालन के लिए कंपनियों को पट्टे पर दिए जाने के विरुद्ध थे।<sup>99</sup>

राज्य रेलपद्धति के पक्षधर नताम्रा का विश्वास था कि इस समय वास्तविक चुनाव यथाथ निजी उद्यम तथा सरकारी उद्यम का न होकर सरकारी उद्यम और प्रतिभूत कंपनियों की पुरानी प्रथा का है और इन दोनों में सरकारी उद्यम निश्चित रूप से अधिक अच्छा और अधिक मितव्ययी था।<sup>100</sup> उनका तर्क था कि विदेशियों की निजी कंपनिया से देश के सामान्य हितों के संरक्षण के लिए पूर्ण दायित्व तथा उद्देश्य की समग्र एकता में काय करने की अपेक्षा ही नहीं की जा सकती क्योंकि कभी कभी तो लोकहिता के लिए निजी हितों की बलि ही चढानी पड़ती है।<sup>101</sup> उनकी मान्यता थी कि वित्तीय दृष्टि से प्रतिभूत रेलप्रथा की अपेक्षा राज्य रेलों से अधिक लाभ में क्याकि सरकार को अच्छी साख के कारण अधिक ऋण मिल सकता है। सरकार सदैव न्याज की कम दर पर ऋण लेने में समर्थ थी और

अतीत में कहीं भी सूद की दर इतनी ऊँची नहीं रही जितनी कि 5 प्रतिशत प्रतिमूल<sup>103</sup> इसके अतिरिक्त ऋण की गई पूँजी पर व्याज चुकाने के उपरांत राज्य रेल के अवशिष्ट लाभ भी देश में ही रहेंगे न कि निजी उद्यमियों के हाथ में पहुँकर विदेशों को भेजे जाएँगे।<sup>103</sup> 3 फरवरी 1884 के अंक में मराठा 1 तो सुभाष दिया कि राज्य ऋणा पर व्याज और 5 प्रतिशत प्रतिमूल व्याज के अंतर का उपयोग मूल ऋण को चुकाने में करने पर लाभकारी और व्याज राशि दाना से लक्ष्य में ही रखा जा सकता था।<sup>104</sup>

जी० बा० जोशी महादय के अनुसार राज्य रेल व्यवस्था केवल निषेधात्मक रूप में ही सही, राजनीतिक दृष्टि से लाभप्रद थी। यह भारतीयों के विरोधी मंगल विदेशी गिहित स्वार्थों के विकास का अवरोध करेगी<sup>105</sup> यद्यपि साप्ताहिक 'सहचर' ने अपन 30 अप्रैल 1884 के अंक में भारतीय रेलवे पर एक विस्तृत समीक्षात्मक लेख के अंत में इस दृष्टिकोण को अत्यंत जागरूक ढंग में प्रस्तुत किया

क्या इन तथ्यों की दृष्टि में यह उचित है कि असह्य रेलपथों का निमाण किया जाए और जनता का रेल कर्पणियों के हाथ में दास बनने के लिए विवश किया जाए? क्या सरकार भारत का दूसरा मित्र बनाना चाहती है? इसके बाद केवल सरकार को रेलों का निमाण करना चाहिए।<sup>106</sup>

इस वक्तव्य में भारतीय नेताओं की निजी उद्यम के विरोध में भीतरतम आपत्ति यह थी कि उद्यम चरित्र विदेशी था और वह इसके फलस्वरूप लाभ का नि्यात करता था। उनमें से बहुतों ने बार बार चले देकर कहा कि यदि विगुद्ध भारतीय कर्पणिया बनाई जाएँ तो निजी उद्यम का वांछनीय रूप से स्वागत होगा।<sup>107</sup> मध्यमवर्गीय इस पक्ष के नेताओं ने तथा प्रथम विचारधारा के समयक अनेकानेक नेताओं ने रेल निमाण के सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में भारतीय पूँजी और उद्यम के विनियोजन के पक्ष में अपना स्वर मुखरित किया।<sup>108</sup> उदाहरणार्थ मराठा 14 जनवरी 1883 के अंक में एक लेख प्रकाशित किया जिसमें मांग की गई थी कि अब सरकार की नीति भारत में स्वदेशी प्रवर्ध, स्वदेशी पूँजी, भंडार और श्रम साधनों से रेलों के निमाण की दिशा में चाहिए। 7 दिसंबर 1902 के अंक में पत्र ने मांग की कि यदि रेलों का निमाण अवश्य करना ही है तो वह यथासंभव भारतीय पूँजी से ही करना चाहिए। रेलों में स्वदेशी पूँजी के लगभग शून्य निवेश पर कुछ प्रवृत्त करत हुए समाचारपत्रों ने भारतीय जनता, विशेष रूप से पूँजीपतियों को रेलों के निमाण के लिए निजी कर्पणिया बालू करने के हेतु धन जुटाने से प्रवर्धित किया।<sup>109</sup> उन्हें सरकार पर भारतीय पूँजी का आवृष्टि करने का अभियोग लगात हुए उसमें भारतीय कर्पणियों के प्रति भारतीय पूँजी लगान के लिए विशेष व्यवहार करना का अनुरोध किया।<sup>110</sup> यह अत्यंत रोचक तथ्य है कि हिंदू ने जहाँ जहाँ 10 जनवरी 1887 के अंक में प्रतिभूति प्रथा को ध्वस्त बनात हुए उसमें निंदा की, वहाँ 3 जनवरी 1887 के अंक में भारतीय उद्यमियों के लिए प्रतिभूति की मांग करने में सकोच नहीं किया। कुछ नेताओं ने यह भी अनुमोदन किया कि विगुद्ध भारतीय पूँजी के सामर्थ्य के अनुरूप ही रेलपथों के निर्माण की गति को मंद बनाया चाहिए।<sup>111</sup>

कुछ दिनों बाद भारतीय नेताओं ने यह अनुभव किया कि सर्वोत्कृष्ट इच्छाओं के बावजूद

भारत में रेल निर्माण के लिए पर्याप्त पूंजीगत विशाल साधनों वाली निजी कंपनियों की स्थापना संभव नहीं थी, अतः उन्होंने राज्य एकाधिकार व्यवस्था का ही समर्थन किया।<sup>117</sup> अमृत बाजार पत्रिका ने अपने 5 मार्च 1885 के अंक में लिखा 'भारत जैसे देश में, जहाँ के लोग इतने अधिक निधन हैं, इतने अधिक अनुत्साही हैं कि वे अपनी पूंजी से रेलों का प्रबंध नहीं सभाल सकते, विदेशियों द्वारा देश को निधन बनाने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा है कि सरकार स्वयं व्यापारी की भूमिका निभाए तथा लाभ का अंजन करे।' सरकार द्वारा रेलों के निर्माण और संचालन में एक महत्वपूर्ण संभव आपत्ति यह थी कि उससे अत्यधिक केंद्रीकरण तथा अनियंत्रित अफसरशाही आ जाती है। इस बुराई का जी० वी० जोशी द्वारा सुझाया हुआ उपचार था रेल प्रबंध का विकेंद्रीकरण तथा विभिन्न प्रांतीय और स्थानीय अधिकारियों के हाथ में रेलों के प्रारंभ तथा प्रबंध के अधिकार सौंपना।<sup>118</sup> 'मराठा' ने 3 फरवरी 1884 के अंक में रेलों के संचालन के लिए लोक-समितियाँ और 'यासों' के संगठन का परामर्श दिया। 'हिंदुस्तान रिव्यू' और 'कायस्थ समाचार' पत्रों ने अपने-अपने मई 1903 के अंक में सुझाव दिया कि सरकारी और गैर-सरकारी विशेषज्ञों की एक संयुक्त समिति के रूप में रेल प्रबंध के लिए एक रेल 'यास' (रेलवे ट्रस्ट) बनाया जाना चाहिए।

### रेलें बनाम सिंचाई

इस समय भारतीय नेताओं के सिंचाई के प्रति दृष्टिकोण पर विचार कर लेना चाहिए। यद्यपि इस समय रेलों और सिंचाई का पारस्परिक संबंध स्पष्ट नहीं है परंतु विवक्षितता की अवधि में दोनों में अत्यंत घनिष्ठ संबंध था।<sup>119</sup> भारतीय नेताओं और सरकारी अधिकारियों दोनों ने रेलों और सिंचाई की परस्पर विरोधी तत्त्व के रूप में ग्रहण किया। दोनों ने भारत में पड़ने वाले अकालों की अत्यंत उपयोगी जीपधि के रूप में अपने-अपने पक्ष (रेल तथा सिंचाई) को प्रस्तुत किया तथा राज्य के सीमित वित्तीय साधनों के अपन पक्ष में विनिधान के लिए मुकाबला किया।

1902-03 के अंत तक छोटे-बड़े सिंचाई कार्यों पर सरकारी राजस्व का कुल व्यय लगभग 43 करोड़ रुपए था जबकि इसके विरुद्ध राज्य का और कंपनियों का रेटा पर प्रतिभूत कुल व्यय 30 जून 1905 तक 359 करोड़ रुपए था।<sup>120</sup> इस तथ्य पर भारतीय नेताओं ने उचित ध्यान दिया और इसकी आलोचना की फिर चाहे इस मस्य में राष्ट्रीय आंदोलन देर में शुरू हुआ था। परंतु उसने प्रचंड रूप 1897 के भयंकर अकाल की अवधि में और उसके पश्चात् ही धारण किया। आमतौर पर भारतीय नेताओं ने सिंचाई के मूल्य पर रेलों के प्रति अनुचित पक्षपात के लिए सरकार की भूमना की। उदात्त यह स्पष्ट घोषणा थी कि इने चहती के रूप में नैत हुए सिंचाई के माय मौतगी मा वाला बनाव किया जा रहा था। 1898 में आर० एम० सायानी ने वायसरॉय की विधान परिषद में यह प्रश्न उठाया और सिंचाई की कि जबकि रेलों पर सरकारी अनुग्रह के रूप में बहुत मंच हाता है, वहाँ अकालों में अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा देन वाली सिंचाई नहरों पर बहुत 75 लाख रुपए की अनुमति दी जाती है। दूसरे शब्दों में रेटा पर व्यय किए जान



वाली राशि का लगभग तेरहवा भाग प्रतिवर्ष सिंचाई पर खर्च किया जाता है।<sup>117</sup> इस विषय पर आर० सी० दत्त सरकार के तीव्रतम आलोचन थे। 1903 में उन्होंने लिखा कि जब हम रेलों से सिंचाई कायम के विषय की ओर आते हैं तो एक ओर हम मूलतः पूर्ण फिजूलखर्ची मितव्ययी हैं और दूसरी ओर उतनी ही मूल्यतापूर्ण कजूसी।<sup>118</sup> इसी प्रकार की समालोचना अथ अन्य समकालीन जनताओं और पत्रकारों ने भी की।<sup>119</sup>

सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीति के विरुद्ध भारतीय नेताओं का तब का निःस्वार्थ जनमन की दृष्टि से अधिक रेलों की अपेक्षा सिंचाई कायमों की ही अधिक उपयोगिता है। 'मराठा' ने अपन 17 फरवरी 1884 के अंक में बल देते हुए कहा कि जहाँ बाणिज्य मंदन का हित इसी में है कि वह रेलों के ऊपर ही अर्थात् रेलों के लिए मध्यम कर, वहाँ हमारा हित इसी में है कि हम रेलों के लिए मध्यम करें। केमर एंड हिंद ने 23 अगस्त 1903 के अंक में चालू एक सवा एक करोड़ रुपये की तुच्छ राशि के स्थान पर चार पांच करोड़ रुपये की राशि सिंचाई कायमों पर खर्च करने की बकालत करते हुए भारतीय दृष्टिकोण को इन गठनों में प्रखर अभिव्यक्ति दी।

निम्नोक्त यह तक प्रस्तुत किया जा सकता है कि नए रेल निर्माण पर भारत सरकार को प्रतिवर्ष पांच छ करोड़ की न्यूनतम राशि खर्च करनी पड़ती है और इस स्थिति में वह सिंचाई कायमों के लिए बहुत बड़ी राशि नहीं जुटा सकती। इस तक का स्वीकार करते हुए हमारा कथन यह है कि अत्र समय की मांग यह है कि रेलों के निर्माण की गति मंद स्तर पर लानी चाहिए अतः हमने वर्तमान भयंकर अकाल की अवधि में जो महंगा अनुभव प्राप्त किया है और अतः लावा मनुष्यों और कृषि पशुओं का जो भयंकर विनाश हुआ है, क्या सरकार इस सबको देखते हुए भी स्वार्थी बाणिज्य मंदन को प्रसन्न करने के लिए उन लावा स्वदेशी लोगों के हितों की जा आज भी पूरे पूरे साल अपेक्षागत भाजन पर जीवन निराह का विचार है अपेक्षा करते हुए रेल निर्माण के द्रुतविक्रम की नीति को अपनाएगी और सिंचाई की योजना की परिधि का संकुचित करेगी। जबकि यह निश्चित है कि उसने ही देश के सारे असुरक्षित क्षेत्रों में नातिनारी परिवर्तन लाया जा सकता है।<sup>120</sup>

कुछ भारतीय नेताओं ने अनुभव किया कि भारतीय कृषि की आवश्यकताओं और स्थिति की संभावनाओं के परिप्रेक्ष्य में सिंचाई की उपलब्ध सुविधाएँ अपर्याप्त थीं।<sup>1</sup> उन्होंने सिंचाई की बहुमुखी सुविधाएँ जुटाने के लिए ब्रिटिश पूँज शासकों और राजाओं की भरपूर प्रणाम की।<sup>2</sup> उन्होंने सिंचाई के द्रुत और व्यापक विकास की मांग की क्योंकि उनकी दृष्टि में इन सुविधाओं में ही भारत की व्यावहारिक मुक्ति निहित थी।<sup>3</sup>

भारतीय नेताओं ने रेलों की अपेक्षा सिंचाई को महत्व क्यों दिया? इसका कारण यह है कि अधिकांश भारतीयों की दृष्टि में रेलों की अपेक्षा सिंचाई अकालों को रोकने के लिए अधिक प्रभावशाली तथा विश्वमनीय उपचार था।<sup>20</sup> रेलें केवल उपकरण थीं और इस प्रकार वे जहाँ अकाल के अत्यंत घणित प्रभाव को मंद कर सकती थी वहाँ सिंचाई कृषि की जड़ तक जाती थी और इस प्रकार अकालों को रोक सकती थी। रेलें देश के विभिन्न भागों में व्यापक रूप से उपलब्ध मात्रा के समान वितरण के अधिक कुछ नहीं कर



अनुमति देना सरकार के प्रशासन का एक ही गवमुच शाचनीय पक्ष है।<sup>131</sup> सामान्यतः नरमपथी 'इन्दु प्रकाश' ने अपन 30 नवम्बर 1904 के अंक में लिखा भारत जैसे विद्युद्ध वृषिप्रधान देश में महत्व को अतिरिजित करने की सभा का ही दिखाई नहीं देती परन्तु दुःख तो यह है कि देश का प्रशासन आवश्यकता को गौरव ही नहीं देता। अगरेजी व्यापारियों को इस देश में मशीनें के विन्तार के लिए रेलें चाहिए और यह सरकार उनके लाभाध रेलें जुटा रही है।<sup>132</sup>

प्रारम्भ में भारतीय आन्दान का प्रशासन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, उसने इसे अनदेखा कर दिया।<sup>133</sup> उदाहरणार्थ 1901-2 के बजट भाषण में लार्ड बजट ने इस समस्या का विस्तृत विवरण करने के उपरांत यह निष्पन्न निष्कर्ष निकाला कि सिचाई से अवालो मुक्त सूबाप्रान्त जिलों की सुरक्षा अथवा वहाँ के विपिन लागों की सहायता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। वायसरॉय का तो इसके विपरीत यह तर्क बहना था कि इसमें तो समस्या के और अधिक विषय हा जाने की संभावना है क्योंकि उनकी मायता थी कि वस्तुतः मरस्थल के उपजाऊ वन के साथ ही जमदर भी उड़ जाती है और इस रूप में उपज बढ़ने के साथ साथ खाने वाले मुल भी वृद्ध ह। वृत्त मिलाकर उनका मत था कि सिचाई का क्षेत्र सीमित है क्योंकि 4,000 000 एकड़ भूमि से अधिक भूमि की भविष्य में सिचाई नहीं की जा सकती। उसने दृढ़तापूर्वक कहा कि मत्य यह है कि अनाल के विरुद्ध सरक्षण के रूप में जितना संभव था और जितना शीघ्रता से अपक्षित था उममें से बहुत सारा सिचाई काय पहले ही संपन्न किया जा चुका है। जनता द्वारा कभी कभी मर्मयित सिचाई कार्यों के सवधा अतिश्चित विस्तार की अब कोई संभावना ही नहीं है।<sup>134</sup> परन्तु ऊपर से अतिम नियम के रूप में दिग्माई देना वाली यह घोषणा स्थिर रूप में ले ली, सरकार अतः लोकमत का दबाव का अनुभव करने लगी। इसका स्पष्ट प्रमाण लार्ड बजट का जगले वष का बजट भाषण है जिसमें उन्होंने वकालत की 'अच्छी तरह बनते हुए घोड़े का चाबुक मारना ठीक नहीं है। इस मरकार की अपेक्षा जोई भी पहले की भारत सरकार सिचाई को प्रोत्साहन देने के महत्व को मवाधिक प्रधानता का रूप नहीं दे सकी।' उन्होंने आलोचना में अपनी इच्छा का पूर्ण सच्चाद पर विश्वास करने का अनुरोध किया।<sup>135</sup> अपनी इच्छाओं की मरचाई के प्रमाण में उमने सिचाई के प्रशन की सामूहिक समीक्षा और अतर्हित संभावनाओं की परीक्षा के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर दी। टी० ई० वाचा ने सत्य की स्वोक्ति में विनय के लिए सरकार की भत्सना का अवसर हाथ से नहीं जान दिया। 1901 में वाग्रस के सभापतीय अभिभाषण में उन्होंने अपना मत प्रकट करते हुए कहा 'यह तो स्पष्ट दृष्टिगाचर है कि सरकार प्रमुद्ध लावमान न गुनावन पिछड़ी रही है।'<sup>136</sup>

सिचाई आयोग ने जून 1903 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें उमने 20 वर्षों के भीतर 65 लाख एकड़ धरती पर सिचाई करने के लिए 44 करोड़ रुपया की अतिरिक्त राशि खर्च करने की सिफारिश की।<sup>137</sup> लार्ड बजट ने आयोग द्वारा प्रकल्पित वायव्य में मा स्वोचार करते हुए यह निष्पत्ती की 'यह मानवीय माधना और शक्तिता की चरम माभा का उदाहरण है और यह निती उरताह या सरकार की मरठित मक्ति का

प्रतीक है।<sup>139</sup> भारतीयों की आयोग के अनुमोदन के प्रति प्रतिश्रिया अनुकूल ही थी।<sup>139</sup> आलोचना का एवमात्र पक्ष यह था कि यह सब कुछ तुच्छ है। वस्तुतः आयोग का अत्यधिक ऊँची राशि और थोड़े समय में ही काय निपटाने के कायनाम का अनुमोदन करना चाहिए।<sup>140</sup>

## निष्कर्ष

रेलो के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण के गहरे विश्लेषण में यह तथ्य एक बार पुन स्पष्ट हो जाता है कि ममीक्षाधीन अवधि के भारतीय राष्ट्रीय नेताओं का आर्थिक चिंतन गहरा था। उन्होंने रेलों की भूमिका को अमूर्त रूप में देखकर समग्रत आर्थिक विकास के व्यापक मद्देन में ही देखा।

रेलो की वर्तमान नीति के अध्ययन से वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इस नीति का निर्धारण भारतीय जनता के हितों के सदर्भ में नहीं हुआ था। यह तो उल्टे भारतीय जनता की आवश्यकताओं की बहुत दूर तक उपेक्षा ही करती थी। वस्तुतः प्रमुख रूप से ब्रिटेन के आर्थिक और राजनीतिक हितों के परिप्रेक्ष्य में ही यह नीति निर्धारित की गई थी। उन्होंने यह भी देखा कि रेलें भारतीय अर्थव्यवस्था का औपनिवेशिक स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। वे पिछड़े देश में रेल विकास के और विस्तृत महा-नगरीय देश में उदीयमान वित्त शक्ति के सह-संबंध और उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली राजनीतिक जटिलताओं को भी उजागर करने में समर्थ सिद्ध हुए।

वे रेलों से औद्योगिक और कृषि संबंधी वृद्धि के रूप में परिलक्षित आर्थिक विकास यतिशील बनाते हुए राष्ट्रीय आर्थिक हितों की सेवा की अपेक्षा रखते थे। उनके मत में उपयुक्त रेल नीति वह है जो भारतीय उद्योग को उत्तम बनाए और उपयुक्त लोक काय नीति वह है जो सिंचाई और कृषि को प्राथमिकता दे।<sup>141</sup> उनकी इच्छा थी कि रेल नीति भारतीय वित्त साधनों तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को उचित महत्व दे।

अतः में यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारतीयों ने रेल नीति के स्वरूप को इस प्रकार लक्षित किया कि वह व्यापार की आवश्यकताओं को उद्योग की आवश्यकताओं के अधीन बनाए। इसका उद्देश्य भारतीय उद्योग को प्रोत्साहित करना ही न कि व्यापक आयात को उत्तम करना, अधिभ्रं खाद्यान्नों के उत्पादन का प्रोत्साहित करना ही न कि उनके व्यापक निर्यात का। इस प्रकार उनके मत की रेल नीति एक बार पुन विकासशील उस व्यापारी भूजी के हित की समर्थक नहीं थी, जिससे रेलों देश के अचला में पैर फँलाने और अधिभ्रं जमाने में सहायता प्राप्त कर रही थी और इस कारण जो निश्चित रूप से ही रेलों के द्रुतविकास की समर्थक बन रही थी। उदाहरणार्थ 1888 में बंगाल राष्ट्रीय वाणिज्य मदन ने वायसराय लाडलस डोन को भेजी शिकायत में देश और विदेश के व्यापार के हितों में रेलों और सहायक सड़कों के द्रुतविकास की वकालत की। इसमें पूर्व मदन ने रेल सम्मेलन को एक आवेदनपत्र भेजा था जिसमें उस समय प्रचलित रेल दरों के विशेषतः निर्यात के लिए निर्धारित वस्तुओं खाद्यान्न बीज और पट्टन आदि, पर रेल दरों के घटाने की वाञ्छनीयता पर बल दिया था।<sup>142</sup> इस प्रकार 1899 में लाडलस

का प्रस्तुत मानपत्र में सदन ने इस तथ्य की निंदा की कि भारत में केवल 21,000 मील लंबे रेलपथ हैं और इसके पत्रस्वरूप तब तक चल पाते हैं कि जिनके ही विस्तृत प्रदा है जिनका किसी भी वार्गजय केंद्र से मीघा मपत्र नहीं है। मागपत्र के अंत में यह लिखा गया था हम लोग, जो देश के व्यापार में गहरी रुचि रखते हैं, श्रीमान मन्त्रालय के रेल विकास के आश्वासन का अत्यधिक स्वागत करेंगे।<sup>113</sup> भारतीय नेताओं के रेलों के द्रुत विकास के विरोध में प्रस्तुत कारण और उद्देश्य तथा रेल विनाम की उनके मनातुकूल दिशा यदि वे विवेचन से यह सिद्ध हो जाता है कि व्यापारिक हितों की अपेक्षा औद्योगिक हित ही उनकी दृष्टि में अधिक महत्वपूर्ण थे।

### संदर्भ

- 1 यह भाग मध्य रूप से इंग्लिश थानर इनवन्वेंट इन एपामर (किनाम्ब्लिसिया 1940) हारम वन रेलवे पानिसा इन इंडिया (सन् 1897) जन्म पूर्वोद्धत दि इरीरियन गजेटियर आफ इंडिया एड III पूर्वोद्धत, एन मायाल दिवर्पमेंट आफ इंडियन रनवेज (बनकत्ता 1930) और आर० डी० तिवारी रेलवेज इन माडन इंडिया (वर्ष 1941) पर आधारित है
- 2 इस दबाव के कारण प्रकृति और सोमा तथा प्रयोग की विधिया विस्तार के साथ थानर द्वारा उनक पूर्वोद्धत ग्रय में निरूपित की गई हैं
- 3 वही प० 63
- 4 डब्ल्यू० डब्ल्यू० हटर दि मारक्विस् आफ डलहौजी (आवमफोड 1895) प० 192-4 जिन पूर्वोद्धत प० 212
- 5 अमरीका में कुछ रोजधो के निर्माण का व्यय भूमि के मूल्य को मिलाकर केवल 2000 स्टलिन पीड प्रति मील था बुनानन पूर्वोद्धत प० 183
- 6 जिनम में उद्धत पूर्वोद्धत प० 221 2 एक अन्य वित्त मदस्य रिटायड आनरेरी एम० लेइग ने 1861 में सरकारी तौर पर एक लेख में यही सवाल उठाया (उद्धत एच० एम० जगनिआनी रि रान आफ रि स्टेट इन प्राविजन आफ रेलवेज (सदन 1924) प० 931 राज्य सचिव को मार्च 1869 में प्रेषित अपनी टाक में भारत सरकार ने भी विशेष रूप से रोजधो के निर्माण के पथ की उग्र समालोचना की उद्धत वल पूर्वोद्धत प० 98
- 7 इरीरियन गजेटियर एड III प० 468
- 8 28 मार्च 1869 के सत्रपथ में भारत सरकार ने निर्देश किया कि इन समय भारतीय रेलों की योग्य थाप केवल तीन प्रतिशत है इनका परिणाम यह हो रहा है कि अवशिष्ट प्रतिशत व्याज का भुगतान भारत सरकार को ही करना पडा रहा है (उद्धत वल पूर्वोद्धत प० 97) 1858-9 से 1869-70 की अवधि में प्रतिशत मूल्य का राशि का कुल भार (आय से अतिरिक्त सरकार द्वारा देय) लगभग 140 लाख पीड था जबकि यह राशि 1868-9 में 650 लाख पीड थी (तिवारी पूर्वोद्धत प० 56)
- 9 वल में उद्धत पूर्वोद्धत प० 94
- 10 इन सब में सामान्य निर्धारित व्यवस्था यह था कि राज्य कोश पर रेलवे का सारा भार

राजत्व म प्रपन्न धर्मों क रूप मे अथवा रेलवे के श्रुती की सेवाओं के रूप म एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए यह सीमा सन्व दंडाई अवश्य जाती थी परंतु निर्धारित सीमा का पालन भी अनिवार्य किमा जाता था

- 11 ब्रिटिश व्यापारी और उद्योगपति भारतीय विदेश व्यापार के वतमान आयामों से असंतुष्ट थे और वे भारतीय मंडी की आंतरिक रूप म और पूरे तोर पर हृदयान के लिए तथा विशेष रूप से ब्रिटेन के लिए भारत से दूरतम प्रांतों से कच्चा मात लाने के लिए अपेक्षाकृत अच्छी परिवहन सुविधा क लिए चिन्ता रहे थे वस्तुतः भारत का समचित आर्थिक शापण पचापि प्राधुनिक सहायक सुविधाओं की माग करता था प्रतिभूत रेलवे म निवेश की सुरक्षित मानने वाले निवेशकों की ओर से भी नए सिरे से दबाव पड रहा था
- 12 धानर पूर्वोदित पृ० VIII
- 13 जैसम पूर्वोदित पृ० 227 इपीरियल गजेटियर (पृ० 414) के अनुसार भारत हस से बगमोल म प्रतिभूत रेलवे साइन के मुताबिक आग था और जनमध्या के हिताच से प्रतिभूत जापान से।
- 14 जोशी पूर्वोदित, पृ० 685 इडियन स्पेक्टटर ने 17 फरवरी 1884 के षक मे जोर जी० एम० अय्यर, ने 1898 में 'इडियन पालिटिकल' पृ० 182 में तथा 1903 म ई० ए० 267 मे इसी प्रकार के विचार प्रकट किए
- 15 दक्षिण बेल पूर्वोदित पृ० 244 5 और इपीरियल गजेटियर छद III प० 365
- 16 धानर म उदित, पूर्वोदित, पृ० 9
- 17 सान्याल पूर्वोदित, प० 146 म उदित चेतनी न 1894 मे अपनी 'इडियन पानिटो पुस्तक मे दावा किया कि रेलपथों क वतमान विकास म दुमिथा स भारत की रक्षा की है
- 18 आई० सी० पी० 1896 छद XXXV पृ० 345 और देखिए कजन स्पीचेज II प० 280
- 19 नोरोजी पाषर्दी, पृ० 193 एमज प० 122 3 132 एम० एन० बनर्जी स्पीचेज I पृ० 179  
सी० पी० ए० पृ० 270 इडियन स्पेक्टटर, 4 सित० (आर० एन० पी० बग 10 सित० 1881) 17 फरवरी 1884 मराठा, 24 फरवरी 2 माघ 1884 इदु प्रकाश 21 अप्रल 1884 सोय प्रकाश 16 जून (आर० एन० पी० बग० 21 जून 1884) हिंदू 9 जनवरी 1885 12 मई 1902. टल्क्यू० सी० बनर्जी सी० पी० ए० पृ० 4 जोशी पूर्वोदित प० 671, सानाद एजेन पृ० 87 बगबासी 5 मई (आर० एन० पी० बग० 12 मई 1894) वाचा स्पीचेज परिशिष्ट प० 22. जा० एम० अय्यर विलवी आयाग छद III प्रथम 1896 3 1898 4 इडियन पालिटिकल पृ० 182, 191 पर दत्त इग्लड एंड इडिया पृ० 130 स्पीचेज I प० 98 100 101 स्पीचेज II, पृ० 76 बगाली, 27 अप्रल 1901, एम० के पटेल, रिप० आई० एन० सी० 1902 पृ० 141
- 20 1853 मे हाऊम आफ नामस को ब्रिटिश इडिया एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत स्मारक म लोक कम की उपयोगी बनाने की व्यवस्था न करने वाले तथा देश क साधनों के विकास की तथा वाणिज्य और उत्पादनो म वृद्धि की ओर उपज मे उन्नति की संगणना न करने वाले 1833 क चाटर एक्ट की आलोचना की गई थी (मोलानाय छद राजा गिम्बर मित्र खड I प० 74 पर उदित) रामगोपाल घोष द्वारकानाय टयोर तथा बबई के व्यापारियों के प्रारंभिक रेलवे उद्यम को दिए गए प्रोत्साहन के लिए देखिए धानर पूर्वोदित प० 51 77 97 दादाभाई नोरोजी ने इहें भारत जैसे देश की उच्चत आवश्यकताओं म संचार का एक सस्ता साधन बनाया और कहा कि ये एक प्रकार सक्तीगनाशक औषधि हैं और इन्ही पर भारत की आर्थिक मुक्ति निर्भर

है उनका विश्वास था कि पिछले पचास वर्षों के प्रशासन में रेलपथों और नहरों का निर्माण ही एकमात्र अथवा प्रधान शुभ कार्य था इसलिये सरकार का दावा सही है और उस इसका भारी श्रेय मिलना ही चाहिए भारतीय जनता सचमुच धगरेज जनता के प्रति अपना कृतज्ञता पावित करती है (एसेज पृ० 123 126 और पृ० 103 106 108 128) तथा दक्षिण इंडियन स्पेक्टोर 4 सितंबर (आर० एन० पी० बग 10 सितंबर 1881) जामे जमशद 10 जनवरी (वही 15 जनवरी 1881), बाव थोनिक्ल 9 जनवरी (वही) और 20 मार्च (वही 27 मार्च 1881) और 16 दिस० (वही, 22 दिसंबर 1883) हिंदुस्ताना 2 मार्च (आर० एन० पी० एन०, 5 मार्च 1884) हिंदू 9 जनवरी 1885 मराठा ने 24 फरवरी 1884 व म म लिखा 'रेलवे के और अधिक प्रसार के बिना भारत के सदा विकासशील राष्ट्रों को पति म खड़े होने की आशा नहीं की जा सकती 1884 के वर्ष में यह समय बिखरता गिआई दता है इसका कारण बताया कि 1884 की प्रवर समिति के प्रतिवेदन और कायवाही पर विचार विमर्श का फल था अथवा भारतीय उद्योग रचि के उदय का परिणाम था जो इस समय व्यापार रचि पर प्रभुत्व पाने लगी थी

- 21 नौरोजी पावर्टी पृ० 193 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 701 और 671 बाबा स्पीचेज परिशिष्ट पृ० 22 जी० एस० अम्यर इंडियन पालिटिक्स पृ० 188 पर दत्त स्पाचेज II पृ० 44 रामगोपाल पूर्वोद्धत पृ० 145 पर उद्धत रानाडे एसेज पृ० 97 क्रमश
- 22 नमश आर० एन० पी० बग० 10 मई 1884 वही, 31 मई 1891 आर० एन० पी० बग 4 जुलाई 1903 और वही 3 दिसंबर 1904
- 23 जाशी पूर्वोद्धत पृ० 676-7 और पृ० 687
- 24 रानाडे एसेज पृ० 86 90 क्रमश
- 25 22 मई 1901 को मदुरा में मद्रास प्रांतीय परिषद में अभिभाषण स्टेटसमन 31 मई 1901 में उद्धत
- 26 जी० एस० अम्यर इंडियन पालिटिक्स पृ० 193 तथा देखिए उनको ई ए पृ० 262 271
- 27 इंडियन स्पेक्टोर, 19 अक्टूबर (आर० एन० पी० बग 25 अक्टू० 1884) हिंदू 23 जनवरी 1885 बगवासी 23 अप्रैल (आर० एन० पी० बग० 30 अप्रैल 1887) आयजनरियान, 1 मार्च (आर० एन० पी० एम० 31 मार्च 1895) दत्त इग्लड एंड इंडिया पृ० 81 स्वर्ण मित्रन 9 अगस्त (आर० एन० पी० एम० 15 अगस्त 1899) बंगाली 27 अप्रैल 1901 गोखले स्पीचेज पृ० 21 रिप० आई० एन० सी०—1904 पृ० 16९ बाबा सी० पी० ए०, पृ० 624 एम० के० पटेल रिप० आई० एन० सी०—1902 पृ० 141
- 28 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 687 8 और पृ० 675 684 693 और देखिए जी० एस० अम्यर इंडियन पालिटिक्स, पृ० 193
- 29 नेटिव आपीनियन 9 सितंबर (आर० एन० पी० बग 15 सित० 1883) शशिलेखा 1 अक्टूबर (आर० एन० पी० एम०, 15 अक्टूबर 1897)
- 30 जी० एम० अम्यर इंडियन पालिटिक्स 193
- 31 गोखले विषयी कमीशन खंड III प्रथम 18140-1 18155-60 बाबा स्पीचेज परिशिष्ट पृ० 22
- 32 नौरोजी पावर्टी पृ० 193-5 इंदु प्रकाश 13 दिसंबर (आर० एन० पी० बग 18 दिसंबर 1875) ए० बी० पी० 18 अगस्त 1881 मराठा 3 फरवरी 1884 7 दिसंबर 1902

- इंडियन स्पेक्टोर 17 फरवरी 1884, युनाइटेड इंडिया, 11 अगस्त (बी० ओ० आई 31 अगस्त 1884) जोशो पूर्वोदित, ए० 695, हिंदू 23 जनवरी 1885 29 अक्टूबर 1897 ए० ए० बनर्जी सी० पी० ए०, ए० 270, बगवासी 25 अप्रैल (आर० ए० पी० बग० 2 मई 1896), वापा स्पावेज, परिशिष्ट ए० 23 तिसव रामगोपाल पूर्वोदित ए० 145 पर उदित दत्त इगत एंड इंडिया, ए० 143 ई एच II, ए० 605, स्वदेशमित्र 30 अक्टू० (आर० ए० पी० ए० 30 नवंबर 1897), बैसरो 19 नवंबर (आर० ए० पी० बव 23 नवंबर 1901) मादवृत्त 29 जून (वही 4 जुलाई 1903), जी० ए० अय्यर विलबी आयोग, खड III प्रश्न 19564 इंडियन पार्लियामेंट ए० 190-2 पर, धोर ई ए, ए० 267 70
- 33 नोरोजी पावर्टी ए० 193-5 जी० ए० अय्यर ई ए ए० 268 270 इंडियन पार्लियामेंट ए० 190 पर
- 34 नोरोजी पावर्टी ए० 195 और देविए जी० ए० अय्यर ई ए ए० 268
- 35 जी० ए० अय्यर विलबी आयोग खड III प्रश्न 19636, 19640-1 19644 इंडियन पार्लियामेंट ए० 190 इसी तथ्य की पुष्टि म उन्होंने 1903 म धानर को उदित किया रेलवे उतम है सिवाई अच्छी है परतु धन की निचामी धार धारने और उसे लगातार विस्तृत बनाने की क्षतिपूर्ति के रूप में पहली अच्छी है और न ही दूसरी इस निचामी न भारत के हृदयकत को घुग लिया है और उसने जीवन रक्ष की प्रमुख आधारभूत औद्योगिक शक्ति को क्षीण कर लिया है (इस्यू० टी० धानर वेस्ट मिस्टर रिव्यू 1880 ई ए ए० 287 पर उदित)
- 36 बगवासी 23 अप्रैल (आर० ए० पी० बग०, 30 अप्रैल 1887) और 5 मई (वही 12 मई 1894) हितवादी 25 जुलाई (वही 1 अगस्त 1891), ए० बी० पी०, 20 सितंबर 1891 आयजनप्रियान, 1 माघ (आर० ए० पी० ए० 31 मार्च 1895), दैनिक औ समाचार चंद्रिका, 6 जनवरी (आर० ए० पी० बग०, 9 जनवरी 1897) बगाली, 27 अप्रैल 1901 नेटिव ओपीनियन 8 मई (आर० ए० पी० बव० 11 मई 1901) ए० ए० अय्यर रिप० आई० ए० सी० 1901 ए० 138 मोद वृत्त 29 जून (वही, 4 जुलाई 1903) यूरोपिय प्रकाशिका 18 मई (आर० ए० पी० ए०, 21 मई 1904) जी० ए० अय्यर ई ए ए० 110-11 276 बगवासी न 6 जुलाई 1889 के घन म रेलवे के विस्तार के समयकों को सालको ध्वेत मिट्ट बहुर उनकी भरसना की (आर० ए० पी० बग० 13 जुलाई 1889) इस तथ्य की पुष्टि म वाचा ने 1889 के अवाल आयोग के प्रतिवेदन से बडिका स० 536 को उदित किया जो इस प्रकार थी यह सही है कि रेलों सूखे के वर्षों में अवालप्रत होने को आशकावाले प्रदेशों में अनाज साती है परतु साथ ही अधिक उपज के वर्षों में उन प्रदेशों को अनाज के भंडार से वचित भी करती हैं (सी० पी० ए० ए० 577)
- 37 वजन स्पीचेज II ए० 277 9
- 38 जी० ए० अय्यर ई ए ए० 276 86 बगवासी 5 मई (आर० ए० पी० बग० 12 मई 1894) दैनिक औ समाचार चंद्रिका 6 जनवरी (वही 9 जनवरी 1897) बगाली 27 अप्रैल 1901 ए० के ए० अय्यर रिप० आई० ए० सी०—1901 ए० 138
- 39 जी० ए० अय्यर ई ए ए० 278
- 40 ए० ए० बनर्जी स्पीचेज I ए० 179 इसी म ए० 178 पर उदित कलकत्ता मे 2 माघ 1878 की जनसम्मेलन मे प्रस्तुत प्रस्ताव पार्लियामेंटरी कमेटी आन इंडियन पब्लिक वर्क्स



- जे० पी० एस० एस० जुलाई 1881 (स० 1 खंड IV), पृ० 8 रास्त शुपनार 5 जून (आर० एन० पी० वग 11 जून 1881) जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 218 687 ट्रिम्बून, 25 अप्रैल (बी० आ० आई० 15 मई 1884), नव विभाकर 24 मई (आर० एन० पी० वग० 29 मार्च 1884) दाका प्रकाश 30 मार्च बगवासी 29 मार्च (वही 5 अप्रैल 1884) बन्वान सजीवनी, 22 अप्रैल (वही 26 अप्रैल 1884) साम प्रकाश 26 अप्रैल (वही 3 मई 1884) भारत मिहिर, 13 मई (वही 24 मई 1884) दैनिक औ समाचार चंद्रिका 31 मई (वही, 6 जून 1891) लोकोपकारी 29 अगस्त (आर० एन० पी० एम० 15 सितंबर 1897) केमरी 19 नवंबर (आर० एन० पी० वग०, 23 नवंबर 1901) गाखले स्पीचज प० 1194 चिनबी बमोशन खंड III प्रश्न 18399, 18406 वाचा स्पीचज, परिशिष्ट पृ० 20 22 3 जी० एस० अय्यर ई ए, प० 578 9 दत्त ई एच I पृ० 212 और स्पीचज II पृ० 44 76-7 ई एच II प० 605 एन० के० एन० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1901 पृ० 138
- 41 वाचा सी० पी० ए० प० 580
- 42 जी० एस० अय्यर ई ए पृ० 270 1
- 43 जी० एस० अय्यर इंडियन पालिटिक्स पृ० 188
- 44 जी० एस० अय्यर ई० ए० प० 260
- 45 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 630-1 2 फरवरी 1889 के भक्त म बगवासी ने भी निर्देश किया कि ब्रिटिश न भी भारी निर्वातों के लिए रेल दरें घटा दी हैं
- 46 1916-18 के भारतीय उद्योग आयोग द्वारा यथा निर्दिष्ट दर नीति परवर्ती वर्षों में भारतीय राजनीति की ज्वलंत समस्या बन गई थी (देखिए, प्रतिवेदन अध्याय XIX) और अन्य असह्य अधिभूत विद्वानों तथा लेखकों की पुस्तकें परवर्ती वर्षों में जी० एस० अय्यर तथा जी० बी० जोशी द्वारा निर्दिष्ट पथ पर रेलों की दर नीति की समालोचना रेलवे पर लिखे जाने भारतीयों की सामान्य शक्ति बन गई
- 47 देखिए रेलवे सम्मेलन में 3 मितंबर 1888 को बंगाल राष्ट्रीय वाणिज्य सदन द्वारा अपन 1888 के प्रतिवेदन में प्रस्तुत स्मरण-पत्र
- 48 जोशी पूर्वोद्धत प० 688
- 49 वही, पृ० 689 और वही प० 801-02 जी० एस० अय्यर इंडियन पालिटिक्स प० 191 ई ए प० 266
- 50 जोशी पूर्वोद्धत प० 689 और जी० एस० अय्यर ई ए प० 265 और सहृदय 30 अप्रैल (आर० एन० पी० वग० 10 मई 1884) साथ ही जोशी और अय्यर ने निर्देश किया यह विन्धी राजनीतिक प्रभुत्व था जिसने ऋण ली हुई धनराशि से रेल-पथों का निर्माण किया ये हूँ अपने आप में रोग थे जबकि स्वतंत्र देशों में रेलें असह्य लाभों को जनक सिद्ध हो रही हैं जोशी पूर्वोद्धत प० 670-1 684 689 जी० एस० अय्यर इंडियन पालिटिक्स पृ० 189-90 और ई० ए० पृ० 261 268 270
- 51 जी० एम० अय्यर इंडियन पालिटिक्स प० 191 2 और ई ए, पृ० 262, 271 दत्त इल्लै एंड इंडिया पृ० 130 एन० के० एन० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1901 प० 138
- 52 इमना मुभाय वैरा आस्ट द्वारा उनका पुस्तक दि इकोनामिक डिवलपमेंट आफ इंडिया पृ० 14: में दिया गया है
- 53 दम प्रकार की आलाचना का अनेका उदाहरण मुझे बगवासी के 5 मई 1894 के निम्न अवतरण

म मिला है रेलों ने वण व्यवस्था को गहरा घक्का पहुँचाया है क्योंकि रेलों के हिस्सा म मभी वणों के लोगो को बचाने पर समान रूप से और समान स्तर पर बठाना पडता है (आर० एन० पी० बग०, 12 मई 1894)

- 54 उदाहरण 1883 म शादाभाई नौरोजी ने लिखा अतएव लोक बनों के मबध म वास्तविक महत्वपूर्ण प्रश्न उह रोजने की विधि सोचने का नटा प्रत्युत उनसे जनता के सामान्वित हान की विधि सोचने का है इंग्लैंड का एव सर्वाधिक महत्वपूर्ण और महान काय भारत म इन लोक बनों का विकास है परंतु साथ ही देघना यह भी है कि वे यहा क लोगो के लिए सामदायन हा हानिप्र न हों ऐसा न हो कि उनसे भारतीय दास बन जाए और दूसरे लोग उनको हृष्य जाए (पावर्टी पृ० 196)
- 55 जी० एम० अय्यर ई० ए० पृ० 272 और दत्त ई एच II, पृ० 174 और 545
- 56 राष्ट्रवादी अयशास्त्रिया के मत क लिए दक्षिण जोमी पूर्वोद्धत पृ० 674-6 684 687 8 693, जी० एस० अय्यर इंडियन पालिटिक्स प० 186 और ई० ए० प० 272 3 गांधल स्पीचेज पृ० 21 1157 1194 और विलवी बमीशन, खड III प्रश्न 18150 18407, 18410-14 पी० ए० धारनु आई० सी० पी० 1900 खड XXXIX पृ० 144 श्रीराम आई० सी० पी० 1904 खड XLIII पृ० 510 दत्त इंडियन पालिटिक्स प० 53 ई एच I प० 312 ई एच II, प० 174 357 546 स्पीचेज JI पृ० 37 44 60 77 फमिस एड सेंड एससमट इन इडिया (लदन 1900) (इसे आग निर्देश के लिए फमिस इन इडिया से सकेतिक किया जाएगा) पृ० 305 समाचारपत्रों के लिए देखिए नवविभाकर 25 जून (आर० एन० पी० बग०, 30 जून 1883) बगाली 3 मई 1884 रास्त गुफ्तार 2 माच (आर० एन० पी० बग 8 माच 1884) हिंदू, 18 अप्रल 1884 याय सुधा 7 मई (आर० एन पी० पी० एन० 12 मई 1884), नवविभाकर 21 अप्रैल बन्वान सजीवनी 22 अप्रल, साधारणी 20 अप्रल (आर० एन० पी० बग०, 26 अप्रैल 1884), समाचार चंद्रिका सोम प्रकाश 26 अप्रल (वही, 3 मई 1884), सहचर, 30 अप्रैल (वही 10 मई 1884) भारत मिहिर 24 मई (वही 31 मई 1884) 25 जनवरी बगबामी 9 अप्रल (वही 16 अप्रल 1887) रहबर, 25 जनवरी (आर० एन० पी० एन०, 30 जनवरी 1895) लोकोपकारी 29 अगस्त (आर० एन० पी० एम० 15 सितंबर 1897), शशिलेखा 26 अप्रल (वही 30 अप्रल 1898), जानुक्लन 13 मई (वही 13 जून 1903) कैसर ए हिंद 23 अगस्त (आर० एन० पी० बब० 29 अगस्त 1903) इंदर प्रकाश 30 नवंबर (वही 3 दिसंबर 1904) हली हितवादी 5 अप्रैल (आर० एन० पी० बग० 15 अप्रन 1905) भले ही स्थान का अभाव अधिक उदाहरणों को उद्धत करने की अनुमति मदे फिर भी यह दिखाने के लिए कि किस प्रबलता से इस दष्टिकोण का समर्थन किया गया था हम दो तीन उदाहरणों को प्रस्तुत करने के लोभ का तो सवरण नहीं कर पाते

जी० वी० जोशी

भारत मे न बवल धगरेजी राय की प्रत्युत धगरेजी वाणिज्य व्यवसाय को भी सुदढ करना साड डलहोजी का एक स्वप्न था और इस गहरी महत्वाकांक्षा के लिए भारत के स्थाई हिंदो का गीण रूप दे दिया गया था इंग्लड में उन्मुक्त व्यापार सिद्धात के समकानोन उदय ने और इस सिद्धात के अनुयायिया द्वारा लघ प्रमिद्धि ने चगुल मे फसाने वाली और निताल स्वाधपूण इस नीति के लिए आध्यात्मिक आधार का काय किया ब्रिटन राष्ट्र द्वारा भारत की कीमत लकाशापर

उत्पादना को पोषित करने और बढ़ाने के लिए उत्पन्न करने वाले कृषि सबधी बच्चे मान के परिमाण के निर्धारण की समता के सम्भ्रम ही आरी गई भारत को अपनी सारी शक्तियाँ बच्चे मान का निर्धारण बढ़ाने में ही लगानी पड़ी नहरो रेलों सहवा और मुघरे सचार साधनों को हर कीमत पर अधिवाधिव विवमित किया गया ताकि भारत से इन्ड को बच्चे मान के निर्धारण और इन्ड से बहा के पक्के उत्पादनो के भारत में आयात को मुविघाजनक बनाया जा सके सुलनात्मक रूप से इस सारी प्रक्रिया में भारत की अपनी जरूरता की ओर कोई ध्यान नहा दिया गया भारतीय साधनो का सयोजन ता सभी प्रकार के सहा में और बिसा भी त्याग के मूल्य पर पूरा करना ही था (पूर्वोद्धत पृ० 674-5)

जी० एस० अय्यर

ब्रिटिश पूजोपति और राजनीतिन के मुह से बेईमानी का स्वर ही निकलता है, यह स्मरणीय है कि रेलपथो के निर्माण का प्रत्येक मील अनेक भ्रगरेजा का इतना अधिक लाभ सर्वाधिन करा है कि प्रभावशाली व्यक्ति भारतीय अधिकारिया पर प्रतिवप नए काम को हाथ में सेन का निरतर दबाव डालने से कभी नही रुवते (ई० ए० प० 272 3)

गोपालकृष्ण गोखले

भारतीय लोग यह अनुभव करते हैं कि यह निर्माण काम प्रधान रूप से ब्रिटिश व्यापारीवय तथा धनिक समुदाय के हितो के लिए ही किया जा रहा है और यह हमारे ससाधनों के और अधिक शोषण में ही सहायक है (स्पीचेज प० 1194)

पी० ए० चारलू

रेलो का प्रयोजन वास्तविक रूप से उद्यम का वाणिज्य का उत्पादन का रेल सबधो का और महत्वाकांक्षी इजीनियरो का प्रयोजन है इन सबके प्रतिनिधि निश्चित रूप से इस सबध में अपना प्रनुध स्वर ऊचा करने में तथा अपनी मुसृष्ट सशक्न प्रतिभा का उपयोग करने में सगठित है (एल० सी० पी० 1900 खंड XXXIX, पृ० 144)

नवविभावर, 21 अप्रैल 1884

रेला की आवश्यकता ब्रिटिश व्यापारियो के लिए है भ्रगरेज व्यापारी ही इग्लंड के शासक हैं, ससद उनके नियक्षण में है मंत्री उनके सेवक हैं ब्रिटिश व्यापारियो के लिए अनुकूल और प्रसन्नतादायक नीति ही उस राष्ट्र की सर्वोत्तम नीति है (आर० एन० पी० बग० 26 प्रप्रैल 1884)

- 57 नवविभावर 1 अक्टूबर (आर० एन० पी० बग० 6 अक्टू० 1883) साधारणी 20 अप्रैल नवविभावर 21 अप्रैल (आर० एन० पा० बग 26 अप्रैल 1884) समय 12 मई (वही 17 मई 1884) भारत मिहिर 13 मद्र (वही 24 मद्र 1884) बंगाली 3 मद्र 1884 हिंदू 23 जनवरी 1884 बगदासी 9 अप्रैल (आर० एन० पा० बग० 16 अप्रैल 1887) जोशी पूर्वोद्धत प 670 675-6 689 जी० एम० अय्यर इंडियन पालिटिक्स प० 181 दत्त औ समाचार पत्रिका 21 अप्रैल (आर० एन० पी० बग० 24 अप्रैल 1897) दत्त इ एच II पृ० 174 546 और स्पीचेज I प० 98 इंदु प्रवाण 30 नवंबर (आर० एन० पी० बग

- 3 सितंबर 1904) बेनी हिजवादी 5 अप्रैल (आर० एन० पी० बंग 15 फरवरी 1905)
- 58 सहर 30 अप्रैल (आर० एन० पी० बंग 10 मई 1904) रामन 12 मई (बही, 17 मई 1904) बंगाली 3 मई 1894, माडदां परमन 15 जून (आर० एन० पी० बंग 21 जून 1904) बेनरी 9 सितंबर (बही 13 सितंबर 1900) जोशी पूर्वोद्धत पृ० 685 दैनिक औसमाचार चरित्रा 21 अप्रैल (आर० एन० पी० बंग 24 फरवरी 1907) जी० एम० अय्यर इंडियन पालिटिकल प० 181 दत्त स्पीचज I प० 98.
- 59 नवविभाकर, 21 अप्रैल (आर० एन० पी० बंग 26 फरवरी 1904) बंगाली 5 मई (बही 12 मई 1894) दैनिक औसमाचार चरित्रा 21 अप्रैल (बही 24 अप्रैल 1907) स्वयंमिन्न 30 अक्टू० (आर० एन० पी० एम० 30 नव० 1897) दत्त स्पीचज I पृ० 98 जी० एम० अय्यर इ० ए०, प० 263
- 60 समर, 12 मई (आर० एन० पी० बंग 17 मई 1904) बंगाली 9 अप्रैल (बही 16 अप्रैल 1887), केमरो, 9 सितंबर (आर० एन० पी० बंग 9 सितंबर 1900) दैनिक औसमाचार चरित्रा 21 अप्रैल (आर० एन० पी० बंग 24 अप्रैल 1907) जी० एम० अय्यर इंडियन पालिटिकल प० 181
- 61 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 674 और नवविभाकर 1 अक्टूबर (आर० एन० पी० बंग 6 अक्टूबर 1883)
- 62 जी० एम० अय्यर इंडियन पालिटिकल प० 181
- 63 जोशी पूर्वोद्धत प० 675 688 693 नवविभाकर 24 मार्च (आर० एन० पी० बंग 29 मार्च 1884) बंगाली 29 मार्च डाका प्रकाश 30 मार्च (बही 5 अप्रैल 1904) साधारणी, नवविभाकर 21 अप्रैल (बही 26 अप्रैल 1884) सोम प्रकाश, 26 अप्रैल (बही 3 मई 1884) मुनिगाबाद पत्रिका 30 अप्रैल (बही 10 मई 1884) रासल गुप्तार 25 मई (आर० एन० पी० बंग 31 मई 1884), रहमर 8 सितंबर (आर० एन० पी० एन०, 14 सितंबर 1902) नोकापारी 29 अगस्त (आर० एन० पी० एम० 15 सितंबर 1897) जी० एम० अय्यर इ० ए० पृ० 272 दत्त स्पीचज I पृ० 102 ई एच II, पृ० 174, गोपले स्पीचज, पृ० 1194 यह अत्यंत उत्सुकतावधक तथ्य है कि रेल आधिक्यता के बदायित्त अपने मुग के सर्वाधिक ममज्ञ विचारक हाइड क्लाव ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में यह लिखा रेलों के प्रवर्तन का सामाजिक तथ्य यह है कि हिन्दुस्तानी इनका निर्माण करें ताकि दम्भ के लोग इनके साथ का बड़ा धन पाने में इनसे समय हाँ सों उद्धत, जिनका म पूर्वोद्धत पृ० 226 और देखिए, मत पूर्वोद्धत प० 254 5
- 64 जोशी पूर्वोद्धत 675
- 65 जी० एम० अय्यर ने 1903 में लिखा थी रायटगा ने अपने सारे विस्तृत प्रतिवेदन में बहरी भी भारत की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में नहीं रखा वस्तुतः विदेशी ब्रिटिश भाषा के धर्मगत भारत की एक विशिष्ट अवस्था हो गई है और यह यह मांग करता है कि भारत की सामुद्रिकी समस्या के समाधान के लिए अन्य देशों के ज्ञान और अनुभव को उद्धत करने की कोई आवश्यकता नहीं प्रत्यंत अधिक सशक्त विरोधी हितों से निरंतर पिरी हुई उसकी अपनी आवश्यकताओं को समझने की आवश्यकता है (ई० ए० पृ० 266-67 और पृ० 261, 263) तथा देखिए एम० अय्यर इंडियन पालिटिकल पृ० 182 192 3 और वाद टिप्पणी 194 और आभ माद नौरोजी ने एक भिन्न रूप में ही सही, यही दृष्टिकोण व्यक्त किया सोच नहीं

वास्तविक समस्या उन्हें समाप्त करने की नहीं प्रस्तुत यह देखने की है कि उनसे दश व जन साधारण को पूरे लाभ वित्त प्रवार प्राप्त कराए जाए (पावर्टी प० 196)

- 66 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 696 और 676 क्रमश और भी सरकार विन्गी व्यापारियों को व्यापक व दफाया भगवाना के रूप में उपहार अर्पित करने के स्थान पर दस चार करोड़ की राशि को देश में ही औद्योगिक संगठन की स्थापना में अथवा स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहित कर देकर उनी दिशा में उसे प्रोत्साहन देने में अथवा यहां का जनता की ही जवाब में मौ गुना बढ़कर रूट के लिए देश के जयाय उपयोगी कार्यों में व्यय करती तो सचमुच यह बहुत ही अच्छा हाता (प० 688) और देखिए पृ० 671 689
- 67 जी० एस० अय्यर ६ ए प० 271 और इंडियन पानिटिक्म पृ० 182 188 डी० इ० बाबा ने भी राष्ट्रीय कायस के 1901 में हुए सत्रहवें अधिवेशन में मभापताय अभिभाषण में यह दावा किया यह अब स्वीकार कर लिया गया है कि रेने केवन एक स्था से दूसरे स्थान पर छायाणा के शीघ्र वितरण का साधन मात्र हैं परंतु ये दश की सपना में एक रुपये का भी वृद्धि नहीं करती उहाने इस बात की शिक्षायत की कि केंद्रीय अधिकारियों के इस भ्रम को तोड़ने में अनेक बप लग गए (सा पा ए प० 577) और देखिए रानाडे एजेज पृ० 88 और हिंदू 23 जून 1885
- 68 ए वानिंग कायस एज रिगाड स रेलवेज इन इंडिया (भारतीय रेलों का प्रति चेतावनी का स्वर) इडु प्रकाश 21 अप्रैल 1884
- 69 जोशी पूर्वोद्धत प० 671
- 70 सहचर 30 अप्रैल (आर० एन० पी० बग० 10 मई 1884) जी० एस० अय्यर ६० ए० पृ० 261
- 71 जी० वी० जोशी ने 1884 में लिखा यदि परिवहन की इन सुविधाओं का साथ साथ राज देश में विविध प्रकार के औद्योगिक जीवन के लिए समुचित आर्थिक स्थिति जुटाने की भी व्यवस्था करता केवन तभी परिवहन का लाभो को राष्ट्र का नाम लाया जा सकता था (पूर्वोद्धत प 696) और अरणो प 24 फरवरी (आर० एन० पी० बग 8 मार्च 1884) आयजन प्रियान 1 मार्च (आर० एन० पी० एम० 31 मार्च 1895) निस्तनपत्रिका 15 मई (वही 21 मई 1904)
- 72 आर० एन पी बग० 10 मई 1884
- 73 यहां तक कि 1873 में मात्र न भी भविष्यवाणी का थी जब एक बार लोहा और कोयलावाले विसा दश का संचलन में मशीनों प्रचलित हो गई तो उहे उनके निर्माण काय से हटाना सरल नहा जाना एक विशाल देश में भी रेल जाल कायम नहा रखा जा सकता जब तक कि रेल संचलन का लिए तात्कालिक और सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्पित औद्योगिक प्रक्रियाएं लागू नहीं की जाती और उनमें से रेलों से तात्कालिक रूप में न जुड़ी हुई औद्योगिक शाखाओं का मशीना के प्रयोग का विकास भी आवश्यक रूप से बाधनीय है अत रेल प्रणाली भारत में वास्तव में ही आधुनिक उद्योग को अग्रगति देने वाली होगी (आन क्लोनिवलिम पृ० 79) परंतु काय उस रूप में नहा हुआ 19वीं शताब्दी की अर्ध में रेलों का सारा निर्माण इंग्लैंड में बने सामान से ही किया गया रेलों अपने निर्माण काय के लिए अर्पित सामान को तैयार करने के लिए भारत में किसी सशक्त उद्योग को जन्म देने में अक्षम रही (जिन्म पूर्वोद्धत प० 227) अत एक सतक भारतीय विचारक ने यह भी अनुभव किया और रेलों के

विस्तार के सम्म में भारत में सोहा उद्योग को प्रोत्साहन न देने के लिए सरकार की जाली चना की नेटिव ओपीनियन ने अपने 20 दिसंबर 1885 के प्रवृत्त लिखा यह आश्चर्य का विषय है कि कोयला सेना में साहे का बड़ी बड़ी परतें मिली हैं हमारी सरकार इनका उपयोग पटरिया बनाने और पुना व शहतीर बनाने व बरान विदेशी बाजारों से उनकी खरीद कर रहा है विदेशी साहे पर घबरा का गइ धनराशि का यदि भारत में उपयोग किया जाता तो हम 7 बरबल ओपेराइत सस्ता और बढ़िया लोहे का उत्पादन कर सकते बल्कि नए उद्योग का प्रारंभ भी कर सकते थे क्या सरकार समस्या के हम पर ध्यान देगी और दूसरों को इस दिशा में पूजा लगाने को प्रेरित करने के लिए स्वयं पहल करेगी ?' समीक्षाधीन काल में राष्ट्रीय नेताओं की रेल मठारा के लिए सरकार द्वारा भारतीय फर्मों से खरीद जो उनसे अप्राप्यता की स्थिति में उनके उत्पादकों से खरीद की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण आर्थिक मांग थी (अध्याय 3 उपर) भारतीय इस्पात उद्योग की स्थापना 20वीं शताब्दी में की जा सकी जबकि रेलों के निर्माण का बहुत बड़ी काय पहले ही किया जा चुका था बरतुत भारतीय इस्पात उद्योग का उदय रेलों की तात्कालिक और सामयिक मागों की पूर्ति के सम्म में ही नहा हुआ था बुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि उद्योगीकरण की प्रक्रिया अत्यंत मरु थी और विदेशी पूजा के बठोर नियंत्रण में थी

74 दादाभाई नौरोजी ने उन लोग का आठ हाथा लिया जो यह कहते हैं कि क्योंकि रेलों ने नई मरी खोल दी है अतः देश के उत्पादन अवश्य बढ़ने चाहिए उहने यह दोहराया पदार्थों की माग धम की माग नहीं है और निवेश के लिए पूजा के अभाव में बड़ी मात्रा में उद्योगों का विस्तार नहीं किया जा सकता (पावर्टी प० 56)

75 जोशी ने निर्देश किया अमरीका में उन्मुक्त व्यापार नहीं है और सरक्षण नियम सर्वोच्च हैं वहा रेलें सरकारी प्रतिष्ठान नहीं वे निजी उद्यमों द्वारा अपने ही दायित्व पर बनाई गई हैं अमरीका में रेलें भौतिक समृद्धि का एक भाग हैं वहा सारे देश में कृषि उत्पादन वाणिज्य समृद्धि आदि अन्य पक्षों का भी साथ साथ और समुचित रूप से विकास किया जा रहा है दूसरी ओर हमारी स्थिति विचित्र रूप से अमरीका जसी नहीं है (वहा) रेलों के विकास का राष्ट्र की समृद्धि के तत्वों की सामाय वृद्धि के साथ कोई संबंध ही नहीं (पूर्वोद्धत पृ० 670-1)

76 उपर देखिए

77 जोशी पूर्वोद्धत प० 671 और 696

78 ए वानिंग वायस एज रिमांड स रेलवेज इन इंडिया (भारत में रेलों के संबध में चेतावनी का स्वर) इन्दु प्रकाश 20 अप्रैल 1884 और जोशी पूर्वोद्धत प० 671 क्रमश आर० सी० दत्त ने भी टिप्पणी की रेलों की व्यवस्था देश की तात्कालिक आवश्यकताओं से बही जागे है (ई एच II, प० 450)

79 हिंदू 23 जनवरी 1885 रानाडे एसेज प० 88 91 2 97 जोशी पूर्वोद्धत प० 671

80 उद्योग के लिए देखिए जोशी पूर्वोद्धत प० 688 याजवा परस्त 15 जून (आर० एन० पी० बब, 21 जून 1884) नेटिव ओपीनियन 20 दिसंबर 1885 रानाडे एसेज पृ 87 9 जी० एल० बय्यर ई ए, प० 264 272 रेलों के सिन्चार्ड से संबध की चर्चा आगे पथक रूप से की गई है इसी प्रकार गोखले ने 1897 में विलंबी आयोग के सामने घोषणा की हम उनके और रेल पथों की आवश्यकता नहीं हम तो इस समय पहले शिक्षा पर व्यय करना चाहते हैं और तदुपरान्त

रेलो पर प्राय एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं और इनसे अन्य दिशाएँ उपेक्षित हो रही हैं यह धीरे-धीरे है कि ये सभी रेलें मनुष्यवागी नहीं हैं परंतु प्रश्न यह है कि हमारे लिए कौन सा उपयोगिता भवेत्साकृत अधिक महत्व का है (विलबी आयोग, घट III प्रश्न 18409 और दक्षिण प्रश्न 18400)

- 81 एस० एन० बनर्जी स्पीचेज I प० 170-81 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 55, 671 इंडियन स्पेक्टर, 24 फरवरी 1884, नेटिव ओपोनियन 24 फरवरी 1884, इन्दु प्रकाश, 21 अप्रैल 1884, बंगाली 3 मई और 9 अगस्त 1884 ट्रिब्यून 1 माच (बी० ओ० आई० 15 माच 1884), बिहार हेराल्ड 22 और 29 अप्रैल (वही 15 मई 1884) भरगोप्य 24 फरवरी (आर० एन० पा० बग० 8 माच 1884) रास्त गुप्तार 2 माच (वही), बगवासी 29 माच और ठाका प्रकाश 30 माच (आर० एन० पी० बग०, 5 अप्रैल 1884) सहचर 23 अप्रैल (वही 3 मई 1884) भारत मित्र 13 मई (वही 24 मई 1884), हिंदू 6 अप्रैल 1889 जी० एस० अथर विलबी आयोग घट III प्रश्न 19609 और इंडियन पार्लियामेंट, पृ० 182 194 गोखले स्पीचेज प० 1194 और विलबी आयोग घट III प्रश्न 18399, 18406 दत्त इंडियन पार्लियामेंट 52 3 फर्मिस इन इंडिया प० 82, 305 और ई एच II प० 174 359-60 546 548 आर० सी० दत्त ने लिखा जब इंग्लैंड की जनता की प्रति व्यक्ति आय 42 पौंड बनना बले भारतीय जनता की प्रतिव्यक्ति आय 2 पौंड है तो हम यूरोप भ्रमण की वित्तासिता के मंत्र लेने की बात सोच ही कमे सकते हैं (ई एच II पृ० 548)
- 82 आग देखिए
- 83 इंडियन स्पेक्टर 2 माच 1884 इन्दु प्रकाश 21 अप्रैल 1884 ट्रिब्यून 25 अप्रैल (बी० ओ० आई० 15 मई 1884) युनाइटेड इंडिया 11 अगस्त (वही, 31 अगस्त 1884) हिंदू 29 अक्टूबर 1897 मराठा 7 दिसंबर 1902 दत्त फर्मिस इन इंडिया पृ० 305
- 84 इन्दु प्रकाश 21 अप्रैल 1884 हिंदू 18 अप्रैल 1884, बगवासी, 9 अप्रैल (आर० एन० पा० बग० 16 अप्रैल 1887) वाचा स्पीचेज परिशिष्ट प० 20 जी० एस० अथर इंडियन पार्लियामेंट पृ० 188 193 एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए पृ० 270 माचेस्टर गात्रियन के 5 नवंबर 1898 व घब म (इंडिया के 11 नवंबर 1898 के प्रक म) दत्त का पत्र रेल का दपमा भेजने में निम्न विनिमय दर के प्रभाव में भारत को होने वाले वास्तविक घाटे की समीक्षा के लिए देखिए बेल पूर्वोद्धत प० 243-4 चिपने पूर्वोद्धत पृ० 312 और सान्याल पूर्वोद्धत प० 44 120 1
- 85 एस० एन० बनर्जी स्पीचेज I प० 180 189 90 इंडियन स्पेक्टर 24 फरवरी 1884 इन्दु प्रकाश 21 अप्रैल 1884 इंडियन नेशन 21 अप्रैल (बी० ओ० आई० 15 मई 1884) बिहार हेराल्ड 22 अप्रैल और 29 अप्रैल (वही) जोशी पूर्वोद्धत प० 687 गोखले स्पीचेज प० 1194 दत्त स्पीचेज I प० 102 सामानी एल० सी० पी० 1898 खड XXXVII प 534
- 86 एन० एन० बनर्जी स्पीचेज I प० 190 ट्रिब्यून 22 माच (बी० ओ० आई० 15 अप्रैल 1884) इंडियन इको 25 अप्रैल (वही 15 मई 1884) बगवासी 9 अप्रैल (आर० एन० पी० बग० 16 अप्रैल 1887) गोखले स्पीचेज प० 1193-4 और विलबी आयोग घट III प्रश्न 18390
- 87 जागा पूर्वोद्धत प० 684 रानाडे एमेज पृ० 89 गोखल स्पीचेज प० 1194 जी० एन०

- अध्याय इंडियन पालिटिक्स, प० 182 उनका 1898 में मुद्रा आयोग के समक्ष साक्ष्य स्पीचेज I पृ० 98 100 ई एच II, प० 358 9 370, 546-8
- 88 जसा हम पहले दिखा चुके हैं इस वष तक इस सबध में राष्ट्रीय दृष्टिकोण विभक्त था 1884 में अथवा उसके उपरांत ही सभी प्रमुख राष्ट्रवादी समाचारपत्रा, हिंदू मराठा इंडियन स्पेक्टेटर ने अपना सारा ध्यान रेलों के प्रश्न पर ही केंद्रित किया
- 89 1884 के उपरांत रेलों के प्रति यह विशिष्ट दृष्टिकोण लगभग सभी राष्ट्रीय विचारों में झूट-प्रविष्ट हो गया था, अधिकारत यह स्पष्ट था पर कभी कभी स्पष्ट रूप भी ग्रहण कर लेता था, यह तथ्य पूर्वनिर्दिष्ट विवरण को देखने से स्वतः सिद्ध हो जाएगा इस दृष्टिकोण को स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए देखिए इंडियन स्पेक्टेटर, 17 फरवरी 1884 ट्रि-यून, 1 मार्च (बी० ओ० आई० 15 मार्च 1884) विहार हेराल्ड 22 और 29 अप्रैल (वही 15 मई 1884) बगदासी 29 मार्च और सोमप्रवाण, 30 मार्च (आर० एन० पी० बग० 5 अप्रैल 1884), नवविभाकर, 21 अप्रैल (वही, 26 अप्रैल 1884), सहचर, 30 अप्रैल (वही 10 मई 1884) बगदासी 9 और 23 अप्रैल (वही 16 और 30 अप्रैल 1884 क्रमशः) पसा अखबार 29 दिसंबर 1894 (आर० एन० पी० पी०, 5 जनवरी 1895) जाशी पूर्वोद्धत प० 684-5 वाचा विलबी आयोग खंड III प्रश्न 17503-04 17546 17613 17616-8 गोखले (वही, प्रश्न 18147 18392 जी० एस० अय्यर वही प्रश्न 18605 18623 6 18630 18963 19011 19560-1 19564 और इंडियन पालिटिक्स पृ० 181 2, पसा अखबार 5 अगस्त (आर० एन० पी० पी०, 28 अगस्त 1897) हिंदू 29 अक्टूबर 1897 सामाजी एल० सी० पी० 1898 खंड XXXVII प० 534 दत्त स्पीचेज I प० 101 2 स्पीचेज II प० 31 केसर ए हिंदू 23 अगस्त (आर० एन० पी० बव, 29 अगस्त 1903)
- 90 दत्त इंडियन पालिटिक्स प० 52 पीछे 81 पाद टिप्पणी में उद्धृत अनेक मतों में यह दृष्टिकोण भी स्पष्ट है
- 91 दत्त इंग्लैंड एंड इंडिया पृ० 143 स्पीचेज II पृ० 31 फर्गिस इन इंडिया, प० 82 305 और ई एच II, पृ० XVII 1778, 375 547 8 जी० एस० अय्यर ई एच प० 264 जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 687 8 श्रीराम एल० सी० पी० 1904 खंड XLIII प० 510
- 92 दत्त स्पीचेज I प० 102 और इंडियन पालिटिक्स प० 53 और देखिए दत्त इंडियन पालिटिक्स, प० 52 और ई एच II पृ० 174 177 358 1884 में जी० बी० जोशी ने शिकायत की कि प्रवर समिति ने विषय पर स्पष्ट दृष्टिकोण के लिए स्वदेशी अभियंताओं को गौरव नहीं दिया (पूर्वोद्धत प० 669) तथा जी० के० गोखले ने विलबी आयोग के समक्ष अपने साक्ष्य में इस बात पर बल दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अभी तक एक बार भी रेलों के विस्तार को बर्बाद नहीं की है (विलबी आयोग, खंड III प्रश्न 18415 6)
- 93 बल पूर्वोद्धत प० 31 और 37
- 94 एस० एन० बनर्जी स्पीचेज I पृ० 189 मराठा 3 फरवरी 1884 बंगाल पब्लिक ओपिनियन 24 अप्रैल (बी० ओ० आई० 15 मई 1884) भारत मिहिर 13 मई (आर० एन० पी० बग०, 24 मई 1884) सहचर 9 अप्रैल (वही 19 अप्रैल 1890) गुजरात दपण 23 मई (आर० एन० पी० बव 25 मई 1889) गोखले स्पीचेज पृ० 1193-4 जी० एस० अय्यर ई एच पृ० 264-5 दत्त में इस प्रथा को क्लृप्त बताया ई एच II प० 546
- 95 मोरोजी एलेज प० 108 09 जोशी पूर्वोद्धत प० 691 मराठा, 3 फरवरी 1884 बदवान



सजीवनी 22 अप्रैल सहचर 23 अप्रैल (आर० एन० पी० बग० 3 मई 1884) हिंदू, 10 अगस्त 1887 दत्त ने धानटन मसे और साठ सारेंस जसे ब्रिटिश अधिकारियों व बक्तव्यों को इसे प्रमाणित करने के लिए पुनरुद्ध किया और बहा रेलपथों के निर्माण में अपव्यय हुआ है यात्रियों के सुख की उपेक्षा की गई है यह कदाचित किसी भी देश व रेल उद्यम के इतिहास में अमृतपूर्व घटना है (ई एच II प० 353) और देखिए गोयल विलबी आयोग, खंड III प्रश्न 18392

- 96 1868 म ही दादाभाई नौरोजी ने इस प्रथा व संबंध में अपने विचार प्रकट किए थे 'मुझे समझ नहीं आता कि प्रतिभूति प्राप्त निजी उद्यम का क्या अर्थ है यह कसा उद्यम है जिसके खतरे और नार तो सरकार के दायित्व हैं और कंपनी केवल लाभ की ही भागीदार बने (जनरल आफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन खंड III 1869 स० 1 प० 13) उत्तर-पश्चिमी प्रांतों से निकलने वाली उच्च पत्रिका रहबर न प्रतिभूति रेलों को भारतीय बरदाताओं की बलि चढ़ाकर अंगरेज पूंजीपतियों को धनी बनाने का एक ढंग बताया 8 सितंबर (आर० एन० पी० एन०, 14 सितंबर 1892) और देखिए बगवासी, 9 अप्रैल (आर० एन० पी० बग० 16 अप्रैल 1887)
- 97 पाद रिप्ली 91 पीछे और इन्डियन स्पेक्टेटर 13 फरवरी (आर० एन० पी० बग० 19 फरवरी 1881) बर्दई समाचार 2 अप्रैल (वही 2 अप्रैल 1881) नवविभाकर 21 जुलाई (आर० एन० पी० बग० 26 जुलाई 1884) बंगाली 9 अगस्त 1884 हमारा विचार है कि इस स्थिति का वास्तविक कारण यह था कि उन्हें आशा थी कि प्रतिभूति के अभाव में निजी उद्यमों की सवजन विदित इनकारी से व्यवहार में नए रेलपथों का निर्माण हो ही नहीं पाएगा
- 98 गोयले स्पीचेज प० 1194 दत्त ई एच II प० 549 1886 में जोशी ने इस मांग का एक दूसरा विश्लेषण प्रस्तुत किया पूर्वोद्धत पृ० 107 11 और देखिए बाचा रिप० आई० एन० सी० 1898 प० 103
- 99 जा० एस० अय्यर ई ए प० 265 और एच० आर० मई 1903 प० 469
- 100 नौरोजी एसज प० 109 नौरोजी मसानी द्वारा पूर्वोद्धत पृ० 115-6 पर उद्धृत जोशी पूर्वोद्धत प० 108 688 693 इन्डियन स्पेक्टेटर 23 जन (आर० एन० पी० बग० 29 जनवरी 1881) रासल गुफ्तार 26 मार्च और बाबे त्रानिबन 26 मार्च (वही 1 अप्रैल 1882) नवविभाकर, 25 जून (आर० एन० पी० बग० 30 जून 1883) मराठा 3 फरवरी 2 मार्च और 20 जुलाई 1884 नेटिव आपीनियन 24 फरवरी 1884 सहचर 30 अप्रैल (आर० एन० पी० बग० 10 मई 1884) और 18 सितंबर (वही 28 सितंबर 1889) बंसरी 2 सितंबर (आर० एन० पी० बग० 6 सितंबर 1884) ए पी० पी० 5 मार्च 1885 एच आर मई 1903 प० 469
- 101 जांगो पूर्वोद्धत प० 693 और मराठा 20 जुलाई 1884 क्रमश और जी० एस० अय्यर ई ए, प० 263 265
- 102 जोशी पूर्वोद्धत प० 693 बंसरी 2 सितंबर (आर० एन० पी० बग० 6 सितंबर 1884)
- 103 जोशी पूर्वोद्धत प० 693 बंसरी पूर्वोद्धत स्थल रासल गुफ्तार 26 मार्च (आर० एन० पी० बग० 1 अप्रैल 1882) ए० बी० पी० 5 मार्च 1885 बाचा स्पीचेज परिशिष्ट प० 23 सहचर न ता 18 सितंबर 1889 के अर्थ में यथा तक सुभाव दिया कि रनों के राजस्व से कुछ एक लागू करों का हटाना अथवा कम करना संभव होगा (आर० एन० पी० बग० 28 सितंबर 1889) जा एम० अय्यर न राय द्वारा निजी कंपनियों को पट्टे पर देने की नीति व विरोध में यही तर्क प्रस्तुत किया (ई ए, प० 265)

- 104 जी० वी० जोशी ने 1886 में इस योजना का समर्थन किया जिसने अतद्युक्त वर्तमान प्रतिभूत राशियों को सरकारी खाते में सामान्य रेल ऋणा के रूप में बदलने और पुष्ट करने का सुझाव था उन्होंने साथ ही यह टिप्पणी की कि लाभों के बड़े बड़ भागा के अतिरिक्त प्रतिभूत कर्णियों की अपेक्षा एकमात्र सरकारी ऋण पत्रा को प्राथमिकता देने से ही हम प्रतिव्यय 816 000 पौंड का विशुद्ध लाभ हो सकता है (पूर्वोद्धत, पृ० 107 11)
- 105 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 693
- 106 आर० एन० पी० बग०, 10 मई 1884 उसी आधार पर जी० एस० अय्यर ने राज्य पथो पर निजी कर्णियों पर आपत्ति की 1903 में उन्होंने लिखा कि वे तो पहले ही पर्याप्त सशक्त हैं और प्रायः स्वदेशी जनता के विरुद्ध पढ़ने वाले विदेशी निहित स्वार्थों में और भी वृद्धि करेंगे (ई ए, पृ० 265)
- 107 रास्त गुप्तार 26 मार्च (आर० एन० पी० बब, 1 अप्रैल 1882) नवविभाकर, 25 जून (आर० एन० पी० बग०, 30 जून 1883), केसरी 2 सितंबर (आर० एन० पी० बब० 6 सितंबर 1884), मराठा, 20 जुलाई 1884 ए० वी० पी० 5 मार्च 1885
- 108 इडियन स्पेक्टेटर 4 सितंबर 1881 प्रत्येक स्थिति में यहूदी धनपतियों (सन्नेत राम चाइल्ड की ओर है) को लाने की अपेक्षा स्वयं भारतीयों को ही उपयोगी लोक कार्यों में प्रत्यक्ष रुचि लेनी चाहिए यहूदियों का तो एकमात्र उद्देश्य सट्टा बाजार के सेल-वेन के लाभों पर एकाधिकार करना है (आर० एन० पी० बब 10 सितंबर 1881) और रानाडे रिब्यू आफ फोरेटस श्री एसेज आन इडियन फाइनांस, (जे० पी० एस० एस०, खंड III सध्या 1 जुलाई 1880) प० 80 और पार्लियामेंटरी कमेटी आन इडियन पब्लिक बक्स ज० पी० एस० एस० खंड IV स० I (जुलाई 1881) पृ० 15 रास्त गुप्तार और गुजराती 11 सितंबर (वही, 17 सितंबर 1881) ए० वी० पी० 18 अगस्त 1881, आयजन प्रिया 1 मार्च (आर० एन० पी० एम० 31 मार्च 1895) जी० एस० अय्यर इडियन पार्लिटिवस प० 193 4 और ई ए प० 268 वाचा विलबी आयोग, खंड III, प्रश्न 17536-7 17546 गोखले वही प्रश्न 18147 पता अथवार 5 अगस्त (आर० एन० पी० पी० 28 अगस्त 1897)
- 109 इडियन स्पेक्टेटर, 5 अगस्त (आर० एन० पी० बब 11 अगस्त 1883), मराठा, 14 जनवरी 1883, हिंदू 10 सितंबर 1889 सहचर 3 अप्रैल (आर० एन० पी० बग० 13 अप्रैल 1895) भारत जीवन 30 मई (आर० एन० पी० एन० 8 जून 1898)
- 110 मराठा 14 जनवरी 1883 नवविभाकर 25 जून (आर० एन० पी० बग० 30 जून 1883), हिंदू 3 अगस्त 1887 और 20 सितंबर 1889 मराठा 7 दिसंबर 1902
- 111 सहचर 23 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 3 मई 1884) वाचा विलबी आयोग खंड III, प्रश्न 17546 जी० एस० अय्यर वही प्रश्न 19564-7 इडियन पार्लिटिवस पृ० 194
- 112 रास्त गुप्तार 26 मार्च और बाबे क्रानिकल 26 मार्च (आर० एन० पी० बब 1 अप्रैल 1882), केसरी 2 सितंबर (वही 6 सितंबर 1884) मराठा 20 जुलाई 10 अगस्त 1884
- 113 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 694 उन्होंने लोकहित के बड़े कार्यों का प्रबन्ध में लोगो को संबोधित करने की नीति की भी वकालत की (वही प० 826)
- 114 पृ० 270
- 115 तुलनीय 1901-02 के बजट भाषण में साह कजन ने कहा कि भारत में रेलों के साथ साथ हम सड़क सिंचाई के विषय पर भी विचार करते हैं (स्पीचेज II पृ० 281)

- 116 दि इपीरियल गजटियर आफ इंडिया (1908) खंड III पृ० 332 और 375-6
- 117 एल० सी० पी० 1898 खंड XXXVII पृ० 534
- 118 दत्त ई एच II, पृ० 550 तथा देखिए उनकी ई एच I, पृ० 312 ई एच II पृ० 360 362 स्पीचेज II पृ० 45 77 8
- 119 कसरी 9 सितंबर (आर० एन० पी० बव 13 मितंबर 1890) और 19 नव० (वही 23 नवंबर 1901) हिंदुस्तान 5 अक्टूबर (आर० एन० पी० एन० 13 अक्टू० 1897) पी० ए० चारल एल० सा० पी० 1900 खंड XXXIX पृ० 144 और एन० सी० पी० 1901 खंड XL पृ० 280 थोगम एल० सा० पी० 1904 खंड XLIII पृ० 510 वाचा सा० पी० ए०, पृ० 576 580 एस्० एम० पटल रिप० आई० एन० सी० 1902, पृ० 229 जा० एस्० अय्यर ई ए, पृ० 261 कसर ए हिंद और गुजराती 23 अगस्त (आर० एन० पी० बव 29 अगस्त 1903), डला हितवादी 15 अप्रैल (आर० एन० पी० बव०, 15 अप्रैल 1905)
- 120 वाचा स्पीचेज, पृ० 25 लगभग तथा वाचा विलंबी आयोग खंड III प्रश्न 17612-9
- 121 आर० एन० पी० बव० 29 अगस्त 1903 भारतीय मत को और विस्तार से जानने के लिए देखिए जामे जमशद 19 अगस्त (आर० एन० पी० बव, 26 अगस्त 1876) जोशी पूर्वोद्धत पृ० 678, नेटिव ओपीनियन 9 सितंबर (आर० एन० पी० बव 15 सितंबर 1883), इंडियन स्पेक्टेटर 27 दिसंबर 1891 नेटिव ओपीनियन, 10 जनवरी (आर० एन० पी० बव, 16 जन० 1892) लोकोपकारी 29 अगस्त (आर० एन० पी० एम०, 15 सितंबर 1897) हिंदू 29 अक्टूबर 1897 और 12 मई 1902 सायानी एल० सी० पी० 1898 खंड XXXVII पृ० 534 पसा अघवार 5 अगस्त (आर० एन० पी० पी० 28 अगस्त 1897) एन० वे० आर० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1901 पृ० 138-9 शशिलेखा 27 सितंबर और स्वदेशमित्र 1 अक्टूबर (आर० एन० पी० एन० 5 अक्टूबर 1901) जनानुकूलन 13 मई (वही 13 जून 1903) विस्तार पत्रिका 15 मई (वही 21 मई 1904) गुजराती 23 अगस्त (आर० एन० पी० बव 29 अगस्त 1903) दत्त ई एच II पृ० 178, 270 545 और स्पीचेज II पृ० 31 49 60
- 122 नेटिव ओपीनियन, 9 सित० (आर० एन० पी० बव 15 सित० 1883), जोशी पूर्वोद्धत पृ० 336 856 857 866-7 दत्त ई एच II पृ० 171 और स्पीचेज I पृ० 7
- 123 रानाडे पार्लियामेण्टरी कमेटी आफ इंडियन पब्लिक वकम जे० पी० पी० एम० जुलाई 1881 (खंड IV ख० 1) पृ० 11 नेटिव ओपीनियन 9 सितंबर (आर० एन० पी० बव 15 सित० 1883) इंदु प्रकाश 30 नवंबर (वही 30 दिसंबर 1904) दत्त स्पीचेज II पृ० 60-78
- 124 ए० बी० पी० 14 नवंबर 1901 और भी जोशी पूर्वोद्धत पृ० 336 वाचा स्पीचेज परिशिष्ट पृ० 25 और सी० पी० ए० पृ० 575 सायानी एन० सी० पी० 1897 खंड XXVVI पृ० 190 पी० ए० चारलू एल० सी० पी० 1900 खंड XXXIX पृ० 144 और एल० सी० पी० 1903 खंड XLII पृ० 144-5 दत्त फमिस इन इंडिया पृ० 82, स्पीचेज II पृ० 60-1 श्रीराम एल० सी० पी० 1904 खंड XLIII पृ० 510 बाबे त्रानिकल 27 मार्च (आर० एन० पी० बव 2 अप्रैल 1881) बाबे समाचार 9 सित० और साम्प्र वतमान 9 सित० (वही 10 सितंबर 1904) हिंदू 12 मई 1902
- 125 बाबे समाचार 28 जन० (आर० एन० पी० बव० 28 जन० 1882), जोशी पूर्वोद्धत पृ० 697 शशिलेखा 1 अक्टू० (आर० एन० पी० एम० 15 अक्टूबर 1897) स्वदेशमित्र

- 30 अक्टूबर (वही 30 नवंबर 1897), पी० ए० चार्ल्स एल० सी० पी० 1901 खट XL प० 280, एन० के० आर० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1901 प० 139 9 वाचा सी० पी० ए०, प० 576 7 दत्त ई एच II प० 178 366 7 श्रीर स्पीचेज II प० 40 60 78 सायानी एल० सी० पी० 1998, खट XXXVII प० 534
- 126 1898 मे जी० एल० अय्यर ने लिखा वे (रेलें) सपथा का उत्पादन नहा कर सकती, वे तो केवल उसवे वितरण म सहायक हो सकती हैं इसवे विपरीत सिचाई काय इस समय केवल एक फसल उगाने वाले किसान को दो फसलें उगाने के योग्य बना सकते हैं (इंडियन पालिटिक्स प० 182) 1901 म आर० सी० दत्त ने अगरेजा की एक सभा म कहा रेलें भारत क अन समरण म एक दाने तक की वद्धि नही करती जबकि सिचाई काय अन के उत्पादन की दुगना कर देते हैं फसला को बचाते हैं जोर अकाल रोकते हैं (स्पीचेज II प० 77) और भी इंडियन स्पेक्टेटर 27 दिसंबर 1891, वाचा स्पीचेज परिशिष्ट प० 25 तथा सी० पी० ए० पृ० 577, सायानी एल० सी० पी० 1897 खट XXXVI प० 189 हिंदू 12 मई 1902 दत्त ई एच II प० 174 360 इन्दु प्रकाश 30 नवंबर (आर० एन० पी० बब 3 दिसंबर 1904)
- 127 नेटिव ओपीनियन, 9 सितंबर (आर० एन० पी० बब० 15 सितंबर 1883) जोशी पूर्वोद्धत, प० 697 सायानी एल० सी० पी० 1898 खट XXXVII प० 534 कर्णाटक पत्रिका 17 अक्टूबर (आर० एन० पी० एम०, 31 अक्टू० 1898) वाचा सां० पी० ए० प० 578 580, गुजराती 23 अगस्त (आर० एन० पी० बब 29 अगस्त 1903) जी० एल० अय्यर ई ए, प० 267 दत्त ई एच II प० 173 4 हा यह अवश्य है कि यह एकमात्र कसौटी नहीं थी सिचाई कार्यों के अकालनिरोधक हाने के कारण अलाभप्रद होने पर भी उनका निर्माण करना ही चाहिए दक्षिण रानाडे पालियामेटरी कमेटी आन इंडियन पब्लिक बक्स जे० पी० एल० एल० जुलाई 1881 (खट IV स० 1) प० 26 और दत्त ई एच II प० 369 573 और स्पीचेज II प० 78 इस सबध मे यह भी उल्लेखनीय है कि कनिपय भारतीय लेखकों ने बडे परिमाण के लाभदायक सिचाई कार्यों की आलोचना की और उन्हान उनके स्थान पर छोटे पमाने के कम खर्चवाले कुओ और तालाबो जसे सिचाई कार्यों का समथन किया जोशी पूर्वोद्धत, प० 867 8, वाचा स्पीचेज परिशिष्ट, प 25 बगवासी 5 मई (आर० एन० पी० बब० 12 मई 1894)
- 128 रानाडे पालियामेटरी कमेटी आन इंडियन पब्लिक बक्स जे० पी० एल० एल० जुलाई 1881, पृ० 16 25 27, नेटिव ओपीनियन 9 सित० (आर० एन० पी० बब 15 सितंबर 1883), शशिलेखा 1 अक्टूबर (आर० एन० पी० एम० 15 अक्टूबर 1897) दत्त ई एच II प० 178 366-7
- 129 नेटिव ओपीनियन 9 सितंबर (आर० एन० पी० बब० 15 सितंबर 1883) सायानी एल० सी० पी० 1897 खट XXXVI, शशिलेखा, 1 अक्टूबर (आर० एन० पी० एम० 15 अक्टूबर 1897)
- 130 दत्त ई एच I पृ० 312 और ई एच II पृ० 545-6 और स्पीचेज II प० 31 60 77
- 131 आर० एन० पी० बब, 29 अगस्त 1903
- 132 वही 3 सितंबर 1904 और देखिए, पी० ए० चार्ल्स एल० सी० पी० 1900 खट XXXIX पृ० 144 श्रीराम एल० सी० पी० 1904 खट XLIII पृ० 510 केमरी 9 सितंबर (आर०

शन कर दिया गया। परन्तु ब्रिटिश व्यापारियों और कपास उत्पादकों के दबाव से गुल्फ सुधार और बटौती की प्रक्रिया विरोधपूर्ण सूती उत्पादन पर, शीघ्र ही अस्तित्व में आई (1861 में सूती गुच्छिया और घागा पर शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत और 1862 में घागा वन 3½ प्रतिशत कर दिया गया। 1862 में सूती टुकड़ों के सामान पर शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया। 1864 में सामान्य आयात शुल्क घटाकर 6½ प्रतिशत और 1875 में 5 प्रतिशत कर दिया गया। इन सारे वर्षों में आयात शुल्क विरुद्ध रूप से राजस्व के उद्देश्यों से ही धोपे गए। इनके पीछे सुरक्षा की इच्छा का लेश मात्र भी नहीं था।

इतने पर भी 1874 के आसपास कपास शुल्क, जो नियात शुल्क से प्राप्त होने वाली आय में मुनाबले कुल राजस्व का आधा भाग बनता था, लकाशायर के कपास उत्पादकों की कटु आलोचना का विषय बन गया। 1874 में माल्डेन के वाणिज्य सदन ने राज्य सचिव को एक विज्ञापन दिया, जिसमें शिकायत की गई थी कि कपास उत्पादन का मरुक्षित व्यापार भारत में भारत और ग्रेट ब्रिटेन दोनों के लिए अलाभप्रद बनता जा रहा था। उन्होंने साथ ही सूती उत्पादन पर आयात शुल्कों के हटाने की मांग की परन्तु नवंबर 1874 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने इस तरह का अस्वीकार कर दिया कि शुल्क सरक्षक थे। हाँ उक्त व्यापार के लक्ष्य का नए रुढ़िवादी भारत सचिव राड सेलिसवरी ने बड़ी प्रबलता के साथ समर्थन दिया और भारत सरकार में सूती सामान पर आयात शुल्क के हटाने की आवश्यकता पर बराबर और बार-बार बल दिया। उनमें जोर देकर कहा कि आर्थिक और राजनीतिक दोनों आधारों पर शुल्क का हटाना अत्यावश्यक था। उसने सबसे प्रथम यह तक प्रस्तुत किया कि सुरक्षण कर ग्रेट ब्रिटेन द्वारा स्वीकृत उक्त व्यापार की सामान्य नीति के विरुद्ध थे। दूसरे, वे भारत में निर्यात का प्रतिकूलित करके ब्रिटिश उत्पादकों को हानि पहुंचाते थे। तीसरे बरों की वृद्धि में भारतीयों के जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं वे उनके हितों के विरुद्ध हैं। अन्तिम वे पनपते भारतीय उद्योग के सच्चे हितों के विरुद्ध थे। उन्हीं के कारण वह वृत्तिम उन्नेजना के अंतर्गत कच्ची नीब पर विकसित हो रहा था। इन सबसे बढ़ चढ़कर उनमें टिप्पणी की कि राजनीतिक कारण भी कपास बरों के शीघ्र हटाने में समान रूप में जानापरक हैं। वास्तव में इस संघर्ष में उसके द्वारा प्रदर्शित सूक्ष्म चिंतन के कारण हम उसके मतव्य को मूल रूप में विस्तार से पुनर्दृष्ट करके बंधन का संवरण नहीं कर पाते

अंगरेजों के हाथ में निर्यात कर प्रथम भारतीयों के हाथ में जान की संभावना प्राप्त भारतीय व्यापार जहां अंगरेजों के लिए कटु भावनाओं को जन्म देगा वहीं भारतीयों के लिए अप्रत्याशित सुरक्षा की संभावना मिलने में उनमें तीव्र उत्सुकता उत्पन्न करेगा। अंगरेज उत्पादक बढ़ती हुई उत्कृष्टता के साथ अपने लिए हानि कारक बरों के हटाने के लिए दबाव डालेंगे और इसके लिए जितनी ही वे जल्दबाजी करेंगे, उतना ही अधिक भारतीयों का उसके महत्व का पता चलेगा। इस स्थिति में भी कुछ शांति अभियन्ता होंगे और भारतीयों के दावा की उपस्था करके अंगरेजी हितों को प्राथमिकता देने की नीति को इसका कारण माननेवाले

व्यक्तिया द्वारा और भी अधिक क्षोभ अभिव्यक्त किया जाएगा। यदि इस सबध मे कायवाही मे विलंब हुआ तो क्रोध की मात्रा व्यापक रूप मे उभर कर ऊपर आ जाएगी और यदि बहुत अधिक विलंब हुआ तो यह निश्चित रूप से एक गभीर सावजनिक खतरा बन जाएगा।<sup>4</sup>

जहा तक लाड सैलिसबरी का सबध था, उसने 31 मई 1876 के सप्रेषण मे इस सारे मतभेद को निष्कप रूप मे इस प्रकार सुलझाया। उसने समग्र प्रश्न की पुन परीक्षा करने के उपरांत घोषित किया कि भारतीय हितो की अनिवाय अपेक्षा इन करा को हटाने की है। भारतीयो के अनुसार ये कर सैद्धांतिक रूप से एकदम गलत, व्यावहारिक प्रभाव के रूप मे घातक तथा प्रवतन मे आत्मघाती है। कपास पर कर हटाने के विरुद्ध एकमात्र तक राजकोष पर पडने वाला हानिप्रद पभाव था। इस सबध मे उसका कथन था कि जहा भारत सरकार इस निर्देश को क्रियावित करने मे विवेक का परिचय दे, उसे भारतीय करदाता को प्रत्येक प्रकार के करो मे राहत देते समय इन करो के हटाने को ही प्राथमिकता देनी चाहिए।

भारत सरकार और वायसराय लाड नाथब्रुक ने राज्य सचिव के सुभाव को महत्व नही दिया और कपास करा को इस आधार पर हटाना अस्वीकार कर दिया कि वे व्यावहारिक रूप मे सरक्षक नही थे। परंतु विरोधियो का मुह बंद करने के लिए सरकार ने लंबे रेशोवाली रुई के आयात पर पांच प्रतिशत कर लगाने का निश्चय किया।

हा, कपास आयात करो का भाग्य उस समय पूरी तरह निश्चित हो गया जब 1875 मे लाड नाथब्रुक का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया और लाड लिटन को उसके स्थान पर वायसराय तथा जान स्ट्रुची को वित्त सदस्य नियुक्त किया गया। ये दोनो राज्य सचिव की इच्छाओ का पालन करने को अत्यंत उत्सुक थे।<sup>5</sup> उस समय (11 जुलाई 1877 मे) हाउस आफ कामन्स ने इस विषय का एक प्रस्ताव पारित किया कि भारत मे आयातित सूती उत्पादना पर इस समय लागू कर अपने स्वरूप मे सरक्षक होने के कारण सुदृढ वाणिज्य नीति के विरुद्ध है और ज्यो ही वित्तीय स्थिति अनुकूल हो त्यो ही यथाशीघ्र इन्हें हटा देना चाहिए।<sup>6</sup> हा, अफगान युद्ध, अकाला की प्रवृत्ति तथा चादी के अवमूल्यन से उत्पन्न वित्तीय कठिनाई ने लाड लिटन और उसके वित्त मंत्री के उत्साह को किसी सीमा तक दबा दिया। फिर भी 1878 मे कुछ अपेक्षाकृत मोटे प्रकार के सूती सामान पर करो मे और 1879 मे सिवाय 30 रेशोवाले सूत के, अन्य सभी प्रकार के सूती सामान पर कर हटा दिए गए। इसके उपरांत अवसर आया जब 1882 मे बजट मे 30 लाख पौंड का लाभ दिखाया गया और अधिकांश अन्य वस्तुओ पर करा के साथ कपास पर कर पूण रूप से हटा दिए गए। केवल नमक, शराब, तरल पदार्थो, शस्त्रो तथा गोला-बारूद आदि पर विशेष कर रहन दिए गए।

अगले बारह वर्षो तक भारत मे वास्तव मे किसी प्रकार के सीमा शून्य नही थे और वह किसी भी अन्य देश की अपेक्षा उन्मुक्त व्यापार के सिद्धांत को अधिक निकटता से अपना रहा था। यहा तक कि ब्रिटेन के पतन भी भारत के पतनो के समान स्वल्प नही थे। इसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप उत्पादित आयात मे वृद्धि हो

इन आयातों का मूल्य 1878-9 से 1881-2 में 18 प्रतिशत, 1878-9 से 1884-5 में 45 प्रतिशत बढ़ गया। इन वर्षों में मूल्यों में निरंतर ह्रास हो रहा था अतः इस प्रकार भारत के आयातों की परिमाणगत वृद्धि बहुत अधिक थी। निस्संदेह यह सब कुछ अन्य अन्तर्गतता और शक्तियों का भी परिणाम था परन्तु निर्विवाद रूप में आर्थिक रूप से यह आयातों के हटाने का फल ही था।<sup>7</sup>

## २ कपास आयातों के निवर्तन का राष्ट्रवादियों द्वारा विरोध

कपास आयातों के निवर्तन के आंदोलन के प्रारंभ से ही भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने एक मत से इतने अधिक रोप और उत्तेजना के साथ उनका विरोध किया कि आक्रमण के प्रमुख निशाने सर जान स्टुर्टी को बाद में वर्षों तक यह शिकायत बनी रही कि भारतीय लोकप्रिय धारणा राजकीय सुधारों के प्रश्न के संबंध में बाधक और नासमझ थी।<sup>8</sup>

1874 में जब माचेस्टर वाणिज्य सदन ने भारत में कपासों के हटाने की मांग की और राज्य सचिव ने इस मांग को भारत सरकार के पास भेजा तो बंगाल का 'सहचर' इसके विरुद्ध अत्यंत प्रचंडता से बरस पड़ा।<sup>9</sup> जनवरी 1875 में इसी प्रकार का विरोध ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बंबई शाखा ने किया।<sup>10</sup> समाचारपत्रों ने भी 1875 में लंबे रेशेवाली कपास पर 5 प्रतिशत कर लगाकर और सूती वस्त्रों पर आयात कर घटाकर कपास शुल्क के आलोचकों को चुप कराने की सरकारी नीति की तीखी आलोचना की।<sup>11</sup> अगले वर्ष लाड सैलिसवरी द्वारा माचेस्टर वाणिज्य सदन को 'कमश' कपास कर घटाने के आश्वासन की समाचारपत्रों ने निंदा की।<sup>12</sup>

मार्च 1875 में कुछ मोटे सूती वस्त्रों पर कर हटाने की बहुत सारे समाचारपत्रों ने उग्र नस्नना की।<sup>13</sup> और 1879 में सूती कपास के सभी प्रकार के सामान पर करों की हटाने का परिणाम समाचारपत्रों तथा लोक नेताओं द्वारा राष्ट्रव्यापी निंदा के रूप में ही दृष्टिगोचर हुआ।<sup>14</sup> क्रोध से जलते हुए सुरेद्रनाथ बैंजर्जी ने प्रश्न किया 'क्या अभी बलिदान की ओर आवश्यकता थी, क्या अभी देशवासियों के हितों का और अधिक प्रबल विनाश अपेक्षित था?'<sup>15</sup> इसी प्रकार सहचर ने 23 मार्च 1879 के अंक में कठोर भाषा में इस कृत्य के लिए लाड लिटन की निंदा की। उसमें लिखा 'वास्तव में हम लाड लिटन के चरित्र का जितना अधिक अध्ययन करते हैं, उतनी अधिक हम उसके प्रति घृणा उत्पन्न होती है।' पत्र में लाड लिटन की कर हटाने की कहानी को 'मानसिक दुर्बलता बताया और आश्चर्य प्रकट किया 'हमारी शोचनीय दशा के समय अपनी जाति के प्रति उसके द्वारा दिग्गम्य गणपति के उपाहरण को हम कभी नहीं भूल सकेंगे।'<sup>16</sup>

1880 में कपास पर अवगिष्ट वृद्ध करों के निवर्तन की बातचीत के समय भारतीय समाचारपत्र और जन-मस्थाएँ एक धारण पुनः भड़क उठीं। लाड हार्टिंगटन द्वारा भारतीय मजदूरों पर भाषण करते हुए की गई इस टिप्पणी ने आगे बढ़ी का काम किया कि कपासों के हटाने के लिए भारत सरकार पर दबाव डालने का कोई भी अवसर छोड़ा नहीं जाएगा और इसमें राष्ट्रवादियों का विरोध और तीखा हाँ उठा।<sup>17</sup> अंत में जब 1882 में

मेजर बेयरिंग ने कपास कर के निवन्तन की घोषणा की तो भारतीय लाकमत न एकमत से इस कायवाही स असहमति प्रकट की।<sup>19</sup> कुछ आलोचका ने तो अपेक्षाकृत बठोर भाषा में अपने को अभिव्यक्त किया। अमृत वाजार पत्रिका ने 6 अप्रैल 1882 क अक में लिखा जायात कर का निवन्तन एक् पाप है और हम फिर बार बार कहत ह कि इसे यायाचित सिद्ध करने की कोई भी चेष्टा अपन आपका घोर पातक के शिखर पर पहुचान की चेष्टा के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगी। फिर भी कुल मिलाकर बेयरिंग की कायवाही के विरुद्ध राष्ट्रीय समीक्षा अपेक्षाकृत हलकी ही थी। इसका आशिक कारण यह था कि इसकी पूव सूचना दी जा चुकी थी। उमका त्वचा विदारण किया जा चुका था और तार-तार करके उमकी आलोचना भी की जा चुकी थी और इसके अतिरिक्त यह किसी भी रूप म वस्तुत भारतीय कपडा उद्योग का प्रभावित ही नहीं करता था क्योंकि इसका सजध बढिया स्तर के सूती सामान से था और उस समय भारतीय मिलें उल्लेखनीय परिमाण म बढिया सूती सामान का उत्पादन ही नहीं कर रही थी। भारतीय सयत आक्रमण का एक अन्य प्रमुख कारण कटाचित लाड रिपन और मेजर बेयरिंग की भारतीय जनता में व्यापक लोकप्रियता और भारतीया की उन महानुभावो को राजनीतिक दृष्टि से परेशान न करने की उत्सुकता थी।<sup>0</sup>

कपास कर के निवन्तन का विरोध करते हुए भारतीय नेता गने अपन विरोधिया द्वारा प्रस्तुत इस प्रमुख आधार का कि ये कर भारतीय कपडा उद्योग को सरक्षण प्रदान करत ह खडन किया। एक ओर उनका कथन था कि कपास कर अपने स्वरूप म ही उद्याग के सवधा सरक्षक नहीं थे क्योंकि भारत अधिकाशत आयात किये जान वाले उत्कृष्ट कोटि के सूती वस्त्रा का उत्पादन ही नहीं करता था। भारतीय मिलें तो मोटे कपडे के उत्पादन में विरोप निपुण है और उस मोटे कपडे का जायात नहीं होता था। भारतीय मिला को मोटे कपडे के आयात की कुछ प्राकृतिक सुविधाए प्राप्त है, जिह कपास करो के निवन्तन से दुबल नहीं किया जा सकता।<sup>1</sup> दूसरी आर उनका सुदढ मत था कि विशुद्ध राजस्व के उद्देश्यो की दष्टि से करा की बडी आवश्यकता थी, वस्तुत भारतीय वित्तो के स्वरूप की दष्टि स तो ये कर आवश्यक ही थे। उसका तक था कि कपास करो के समान अदुखप्रद तथा हानिकारक अय कोई राजस्व का स्रोत ही नहीं था। भारत के वित्तो की स्थिति के निराशाजनक और अयवस्थित होने के कारण उनका भय था कि कपास करा के निवन्तन स हुए घाटे की पूर्ति जनता से और अयिक् ऋण लेने और धिनौन किस्म के बराधान उपाय से ही की जाएगी और वस्तुन की जा रही थी।<sup>2</sup> कुछ भारतीया ने टिप्पणी की कि नमक कर तथा अनुनक्ति करके अधिनियम ग्रथ में रहन पर कपास करा का हटाना सवधा अयायपूण था।<sup>2</sup> यह भी पर्याप्त आश्चयजनक है कि बहुत सारे भारतीय नेताजा न जिस सास में कपास करो के स्वरूप को असरक्षक माना था, उसी सास म उन करा के निवन्तन को भारतीय वस्त्र उद्योग पर हानिप्रद प्रभाव डालन वाला भी कह दिया। इस प्रकार से उ हानि निह्रिताथ द्वारा इन करा के सरक्षक स्वरूप का अमि-स्वीकार किया अयथा और किसी भी रूप में उनके निवन्तन स भारतीय उद्योग को वास्तव में होने वाली क्षति सिद्ध नहीं की जा सकती थी। कुठ ने तो खुले तीर पर मान



लिया कि आयात कर सरक्षक थे और उस रूप में सुरक्षा प्रदान करते थे। जैसा हम आगे के अध्याय में दिखाएंगे, लगभग सभी भारतीय नेताओं ने अध्ययन काल में उद्योगीकरण के उन्नयन के लिए सरक्षण के महत्व और उपयोग की क्वालता की।

### राजनीतिक अर्थ

प्रारम्भिक राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा सधप के हेतु लिए गए थोड़े से सावजनिक विषयों में एक था, कपास आयात करों के निवृत्तन का विरोध। वर्षों तक सगठित रूप से बुद्धिमत्ता पूर्वक तथा सतक होकर इसका अनुसरण किया गया परन्तु सधप का अन्तिम परिणाम उन्हें वृत्तित करने वाला ही निकला। पग-पग पर उनके दृष्टिकोण की उपेक्षा की गई, उस ठुकराया गया और अन्त में कपास आयात कर पूर्ण रूप से हटा लिए गए। इसका परिणाम शासकों के प्रति कटु प्रवृत्ति तथा शत्रुता की भावना के विकास और प्रसार के रूप में ही सामने आया। बहुत सारे उदीयमान भारतीय नेता शनैः शनैः शासकों की सद्भावना में सदेह करने लगे और समुचित राजनीतिक निरूपण निश्चालने लगे।

स्पष्ट रूप से देश के हितों के विरुद्ध दिखाई देने वाली नीति के प्रवृत्तन ने राष्ट्रवादिता को यह पूछने और इस मन इस प्रश्न का उत्तर ढूँढने पर विवश कर दिया कि यह नीति क्या लागू की जा रही है? उनके अनुसार सरकार की कर नीति का मुख्य आधार न तो भारतीय जनता का हितचिन्तन था और न ही उन्मुक्त व्यापार के सिद्धांत का वास्तविक परिपालन। वस्तुतः इस सबके विपरीत भारतीय बस्त्र उद्योग में द्रुतविकास से लकाशायर के उत्पादकों के हृदय में भडकती हुई ईर्ष्या ही इसका कारण थी। वे यह भी विश्वास करने लगे कि इंग्लड के दोना राजनीतिक दल लकाशायर में राजनीतिक समयन पाने के इच्छुक थे अन्त इंग्लड में दलगत राजनीति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें कपास करों के आंशिक अथवा पूर्ण रूप से हटाने के रूप में दक्षिणशाही लकाशायर के हितों के आगे भारतीयों के हितों की बलि चढानी पड रही थी।<sup>6</sup> उदाहरणार्थ, 15 दिसंबर 1875 को बोध सुधारक ने अपने, 'माचेस्टर के स्वार्थी व्यापारी और उनके कृतव्यवद्ध सेवक भारत राज्य सचिव' शीर्षक संपादकीय में यही दृष्टिकोण प्रकट किया।<sup>7</sup>

यहां तक कि जुलाई 1881 का जस्टिस रताडे को यह कहना पडा कि अनुदार राजनीतिज्ञों ने अपने कार्यालय में उन्मुक्त व्यापार के नाम पर भारत के हितों की बलि चढाई है और माचेस्टर को प्रसन्न करने के लिए 250 000 पौंड भारतीय राजस्व की रॉगि उतकी मवा में मोट की है।<sup>8</sup> इसी प्रकार 1880 में पटना की एक जन सभा में पूना सावजनिक सभा के राष्ट्रवादी अध्यक्ष राव वहादुर के० एल० नुलवर ने क्रुद्ध होकर टिप्पणी की

इस बात को समझने के लिए कि इंग्लड में बठकर भारत के भाग्य पर नियंत्रण रखने वाले अपनी नियुक्ति की अवधि को लवा करने के लिए तथा अपने काप की सुरक्षा के लिए किस प्रकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमें केवल इस बात पर विचार करना है कि माचेस्टर का अनुग्रह पाने के लिए ही अभी हाल ही

म कपास आयात करो से प्राप्त होने वाले हमारे राजस्व की बलि चढाई गई है।<sup>१</sup> बंगाली ने 11 मार्च 1882 के अंक में न केवल ग्रेडसन की उदारवादी सरकार की अवशिष्ट कपास आयात करो के हटाने की कायवाही की ही निंदा की, प्रत्युत उसके इस काय को करने के दभी ढग की भी भत्सना की। उसने लिखा करो को हटाने का िणय सवथा निराधार है, इसमें कपट और घनावट की गंध आती है। यह हमें रोष दिलाने वाली गलती को व्यापार उत्कृप बताने की बहानेवाजी है।

जहा ब्रिटिश प्रशासका ने भारतीयों के तर्कों की और उनके प्रचंड विरोध की उपेक्षा करना ही ठीक समझा<sup>२</sup>, वहा भारतीय नेता कपाम करो के निवतन पर लबी क्विच गई मुठभेड के राजनीतिक निहितार्थ की गहराई में उतरने लगे। इससे पूव उनके चितन का जो ढग था और बहुत सारे मामलो में आगामी वर्षों में भी जो चितन पद्धति उह अपनानी थी वह यह थी कि अब तक वे अपने सभी प्रकार के कुप्रशासनो का दायित्व भारत में स्थित अंग्रेज अधिकारिया के कंधो पर ढालते थे क्योकि भारतीय नेता इन अधिकारिया को सैतान समझकर उनसे घणा करते थे और यह मानते थे कि ये लोग अपने स्वाथ के कारण दयालु रानी, लाकतनीय ससद और स्वतंत्रता प्रेमी अगरेजो के उदार आन्देशो को लागू करने में असफल रहे है परंतु अब शीघ्र ही जनता को कपास करा पर मतभेद से मृत्यु ज्ञात हो गया कि इस विषय में नौकरशाही ने जहा 'यूनाधिक रूप से भारतीयों का पक्ष लिया था, वहा ब्रिटिश सरकार और ससद ने सैतान की भूमिका निभाई थी।<sup>३</sup> इसने बहुत सारे भारतीयों का इस विषय की परीक्षा करने और कदाचित प्रथम बार इस व्यापक स्तर पर अपने शासको की सद्भावना और भारत में ब्रिटिश शासन के वास्तविक लक्ष्य और प्रयोजन पर विचार करने को विवश कर दिया। इस चितन के फलस्वरूप वे इस दु खद निष्कप पर पहुंचे कि भारत पर अगरेजो के शासन का प्रधान उद्देश्य भारतीयों के हितों की अपेक्षा ब्रिटिश व्यापारिया और उत्पादको का हित-साधन ही था।

1875 में 'बेलगाव समाचार' ने अपना मत अभिव्यक्त किया कि राज्य सचिव द्वारा माचेस्टर वाणिज्य सदन को दिए गए आश्वासन कि अगरेजी वस्त्रों पर आयात कर हटा दिए जाएंगे, ब्रिटिश सरकार की मनोवृत्ति का ही एक प्रमाण है। सरकार जो भी काम करती है, ढोग तो भारत के हित का करती है पर वास्तव में वे सब होते शासक जाति के हित में ही हैं।<sup>४</sup> भोलानाथ चंद्र ममस्या का निर्भीक और विस्तृत विदग्धेपण करनेवाले कदाचित प्रथम भारतीय महानुभाव थे। उन्होंने 1876 में लिखत हुए प्रारंभ में ही यह स्वीकार किया कि इस सारे मतभेद में विचारणीय विषय, आयात कर, अपन आप में इतने अधिक महत्वपूर्ण नहीं थे, क्योकि सत्य यह है कि आयात कर भले ही हटा दिए जाए भारत का वस्त्र उद्योग तो फिर भी अपनी प्राकृतिक अनुकूल स्थितिवा के कारण फने फूलगा। राष्ट्र द्वारा विचारणीय विषय तो यह है कि ढग में उनके अपने हितों के अनुकूल शासन चलना है अथवा इंग्लड के हितों के अनुकूल। उह यह अत्यंत स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि भारतीयों ने जो महत्वाकांक्षाएं मजोर रखी थी कि अब उनके लिए सौभाग्य के मूय का उच्य होने वाला है, उसका उत्तर मवथा और पूणत नवारात्मक ही

1858 का बचन मंगलपणा ही सिद्ध हुआ था और यह विश्वास कि एक व्यापारी कंपनी के हाथ में राज के हाथ में प्रशासन के हस्तांतरण में प्रयामन की प्रकृति और उसमें उद्देश्य में परिवर्तन आ जाएगा, बालू की भीत पर टिका सिद्ध हुआ है। उन्होंने निम्न

सुधार और एक सुव्यवस्थित शासन और नई भूमि का के म्याग पर निश्चयात्मक रूप में पिछड़ापन ही मिला है। वही जाति की अपनी जाति के प्रति सत्यनुभूति दिखाई देती है। वही भारतीयों के हितों की अनुकूलता में इंग्लैंड के हितों की निरंतर स्पष्ट स्वीकृति है, वही लूट-खमाट और छोना भपटी की भावना है और भारत को 1776 में विद्यार्थी की अवस्था में रखने का जा सकल्प था, वही 1876 में भी विद्यमान है।<sup>33</sup>

भालासाथ चंद्र ने व्याख्यान दिया कि सचमुच लोगों को माचेस्टर की विजय में अमूल्य शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि इससे नग्न रूप में पता चलता है कि सारा भारत मिलाकर भी बपास की बत्ताई-चुनाई में माचेस्टर के समकक्ष नहीं है।<sup>34</sup> तीन वर्षों के उपरांत एस० एन० बनर्जी ने आन्कारिक रूप में देशवासियों के आगे प्रश्न उपस्थित करत हुए उनमें पूछा यदि हमारी अपनी सरकार होती तो क्या वह सरकार नोत्तम का हम प्रकार सबथा निरादर करती हुई और देशवासियों के हितों को पूर्ण उपेक्षा करती हुई ऐसा काम करने का साहम करती? इसी बठोर सत्य की अभिव्यक्ति मराठा ने 18 सितंबर 1881 के अक में निम्न टिप्पणी करते समय की कि भारत का स्थान साम्राज्य में समानता का न होकर एक विजित राष्ट्र का था। उसने इस बात पर विरोध बल दिया कि माचेस्टर के हितों के लिए भारत के हितों का बलिदान तो प्रत्येक विजित राष्ट्र द्वारा विजेता राष्ट्र को बिना शिकायत किए चुकाए जाने वाले दंड का ही रूप था। मराठा ने यह सबने किया कि वस्तुतः दुख का मूल कारण विदेशी शासकों का अमुक अथवा अमुक कृत्य न होकर देश की यथाथ मौलिक राजनीतिक स्थिति ही थी।

लाड रिपन ने 1882 में बपास करों का निवर्तन भारतीयों के सामान्य हित में हान के निश्चित मतों का पुन समायन किया। उसने साथ ही इस बात का भी दावा किया कि वह भारतीयों के लाभ के लिए भारत के हित में ही भारत पर शासन का बन्दूक है।<sup>35</sup> बंगाली न 11 मार्च 1882 में अक में तुरत उत्तर दिया 'भारत के लिए ही भारत पर शासन की चर्चा अपने आप में सुदूर हा सबती है परतु हमारे शासन यह नहीं भूल सकते कि वे अंगरेज हैं और उन्हें अवश्यमेव एक निश्चित परिमाण में प्रत्येक मूल्य पर अंगरेजों को लाभान्वित करने वाले मिठानों के अनुसार ही सरकार चलानी चाहिए। अमत बाजार पश्चात् न एक धार फिर अपन 6 अप्रैल 1882 के अक में भारत की राजनीतिक दायता को और ध्यान बाकृष्ट करत हुए उनका उपचार इस प्रकार में सुझाया 'ब्रिटेन यूरोप के अपन सर्वधी देशों को उन्मुक्त व्यापार का बरगान प्रदान नहीं कर सकते और अपन उपनिवेशों में भी यह उपास्ता नहीं दिखा सकते, क्योंकि वे अपन शासन आप हैं। परतु भारत एक असंगत देश है उसमें संपूर्ण दुःख और शक्तिहीन है।'<sup>36</sup> बरत वर्षों ने बालू बपास करों के निवर्तन की चर्चा करते हुए जार० सी० दत्त ने लिखा भारत में ब्रिटिश प्रशासन ने बरई के निम्न बपास उपाय को देखा में न देखकर उसमें प्रति

सतोप ही प्रकट किया परन्तु भारतीय प्रशासन के सबध में तो वे बेचारे ब्रिटिश व्यापारी और ब्रिटिश मतदाता के ही दाम थे।<sup>39</sup>

इस समालोचना का एक ममाहित तर्क यह था कि भारत सरकार को ब्रिटिश व्यापारियों के नियंत्रण में मुक्त कराया जाए ताकि भारत के अनुमूलन कर नीति अपनाई जा सके। महत्कर के 22 मार्च 1882 के अक्टू में निर्दिष्ट सरकारी वाप का नियंत्रित करने की शक्ति भारतीयों को हस्तांतरित करने की मांग भी बड़े ही स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत की गई।<sup>40</sup> चार वर्षों के उपरांत इसी पत्र में आग्रह किया कि यदि भारतीय आयात करों का पुनः लागू करना चाहते हैं तो उन्हें अग्रजों उपनिवेश, कनाडा और आस्ट्रेलिया द्वारा किए गए सघप के समान स्वशासन के लिए सघप का पथ ही अपनाना चाहिए। इसी प्रकार 17 जनवरी 1886 के अक्टू में मराठा ने घोर निराशा के साथ लिखा कि एक व्यापारी देश का विदेशी शासन में आयात करों के द्वारा बहाल होने की आशा हम कभी नहीं कर सकते।<sup>41</sup>

भारतीय नेताओं को इस समय अपने आप सूझा कि भारतीय उद्योग पर कपास करों के निवृत्तन से हानि होने का हानिप्रद प्रभाव को निष्प्रभावी बनाने का एक जय उपाय था, विदेशी कच्चा को न खरीद कर स्वदेशी को अपनाने के रूप में स्वेच्छा से अपने उद्योग को संरक्षण प्रदान करना। स्वदेशी का एक बहुत बड़ा गुण यह था कि राजनीतिक दमन की स्थिति में भी इसे अपनाया जा सकता था। हमें यहाँ स्वदेशी के प्रचार के राष्ट्रवादी प्रयत्नों की समीक्षा के लिए रकने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हम पहले ही इसी पुस्तक के तृतीय अध्याय में इसका विवेचन कर चुके हैं।

### आयात करों का पुनः आरोपण

1882 में आयात करों के पूर्ण निवृत्तन के समय लाड रिपन ने यह पवित्र जाणा प्रकट की कि अब इस वायवाही से भारत और इंग्लैंड की जनता में वर्षों से विद्यमान इस प्रश्न से संबंधित अप्रिय मतभेद समाप्त हो जाएंगे।<sup>42</sup> परन्तु भारत के पक्ष में बोलने का दावा करने वाले कामल न हो पाए और बाद में उन्हीं वर्षों तक, वस्तुतः तब तक जब तक कि राष्ट्रीय आंदोलन चलता रहा, कपास करों के निवृत्तन का राष्ट्रीय कटु समानाचन के प्रहार का प्रिय लक्ष्य बनाए ही रखा। ऊपर परीक्षित सभी पक्षों पर आग्रहपूर्वक कह चुकने के उपरांत राष्ट्रीय नेता दोहराते थे कपास करों का परित्याग 'राष्ट्रीय अध्याय का एक उदाहरण है, एक घटिया किस्म का विश्वासघात है, और भारतीय हिता का ब्रिटेन के हितों में अधीन करने का एक प्रमाण और उदाहरण है।'<sup>43</sup> इससे अतिरिक्त स्वल्पतम उत्तेजना के अवसर पर और प्रायः वित्तीय सत्र की प्रत्येक घड़ी में नमक कर तथा जाय कर जैसे अर्थ करों को उठाने के समय अथवा अकाल अनुदान को समाप्त करने और राज्य सरकारों की निर्दिष्ट राशि में कटौती करने जैसे लोकहित के खर्चों में छटनी के समय वे प्रायः इस सबके बदले कपास पर आयात कर पुनः लगाने की मांग प्रस्तुत करते थे।<sup>44</sup>

एक लंबे और कटु सघप के बाद भारतीयों को प्राप्त कर नीति सबधी विजय मिली

उत्पादन शुल्क लगा दिया गया। यह उत्पादन शुल्क, किसी भी देश के आर्थिक इतिहास में अविद्यमान चुगौकर, राजस्व के प्रयोजन में नहीं थोपा गया था प्रत्युत नए आयात करों से भारतीय उद्योग को किसी प्रकार से लकाशायर के हितों के विरुद्ध संरक्षण मिलने का सम्भावना के तत्व का निमूल करने के लिए ही थापा गया था। वास्तविकता यह है कि यह शुल्क लगाने से पूर्व स्वयं भारत सरकार इस कदम के औचित्य से सहमत नहीं थी। 1878 में सर जान स्ट्रेची ने सीमा शुल्क का 'महंगा, दुखदायी, और अमुकविधाजनक' और 'अधिकांश स्थितियों में भारत में अव्यावहारिक' होने के कारण अस्वीकार कर दिया था। यहाँ तक कि 1894 में वित्त मन्त्र जेम्स बस्टलेड ने भारत सचिव का भेजे संप्रण में इस तथ्य की ओर निर्देश किया, 94 प्रतिशत भारतीय उत्पादन तो माचेस्टर के उत्पादकों के साथ प्रतियोगिता की सीमा क्षेत्र के ही विलयुल बाहर हैं क्योंकि वे तो मोट स्तर के वस्त्र (24 नंबर और इससे अधिक ऊँचे) का उत्पादन करते हैं और माचेस्टर भारत के समान इस स्तर के वस्त्रों का सस्त में बेचने का दम नहीं कर सकता। उसने सलाह दी कि यदि यह दुखदायक शुल्क लगाना ही है तो इसे 24 न० के ऊपर के स्तर के सूती धागा पर लगाना चाहिए। परंतु राज्य सचिव का आदेश था जिससे विवेक हाकर सरकार को 20 नंबर से ऊँचे स्तर के सूत पर उत्पादन शुल्क लगाना पड़ा। इस प्रकार भारतीय मिला के कुछ उत्पादन का 20 प्रतिशत इस शुल्क के क्षेत्राधिकार में आ गया। कपास शुल्क वित्त पर भाषण करते हुए जेम्स बस्टलेड ने धमा प्रार्थना करते हुए स्वीकार किया कि सरकार ने अपनी ओर से इसकी विशेषताओं के आधार पर इसका अनुमोदन नहीं किया प्रत्युत राज्यसचिव से प्राप्त निर्देशों के कारण ही इसे लागू करना पड़ा है।<sup>6</sup>

जैसी आशा की जाती थी, भारतीय राष्ट्रवादीयों ने कपास के उत्पादकों पर आयात शुल्कों की बहानी का स्वागत ही किया और इसे लोकप्रिय इच्छा की स्वीकृति का संकेत बताया।<sup>62</sup> इस संबंध में हम दृष्टांत रूप में डी० ई० वाचा महोदय का उद्धृत करते हैं जिहान अनिस्वीकार करते हुए कहा 'सरकार ने सचमुच जनता की आवश्यकताओं को स्वर किया है और उदारतापूर्वक उसके सच्चे हितों की बकालत की है।'<sup>64</sup> इस प्रकार की प्रशंसा सामान्य नहीं थी और आयात शुल्क की अल्पता की आलाचना भी साथ साथ हानि लगी थी। उदाहरणार्थ मराठा ने 16 दिसंबर 1894 के अंक में सरकार की इस कार्यवाही के लिए उसका समर्थन करते हुए यह टिप्पणी जाड़ दी 'सरकार ने यह तभी किया है जब इस विषय में उसके लिए और कोई विकल्प नहीं रह गया और विचारविधान निश्चित ही था। इसका अतिरिक्त पत्र ने यह भी अनुभव किया कि शुल्क और अधिन ऊँचा जयान 10 अथवा 15 प्रतिशत होता। इसमें पृथक् भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने निभान रूप से कपास उत्पादन शुल्क की निंदा की। उनके अनुसार यह शुल्क अनुचित अशिष्ट तथा भारतीय जनता के हितों का विपरीत थे।'<sup>65</sup>

ब्रिटिश उत्पादक निश्चय ही 1894 के राजकर संबंधी प्रबंध से सतुष्ट नहीं थे। उनकी धारणा थी कि 20 नंबर से नीचे नंबरवान सूत को सीमाशुल्क में मिली छूट भारतीय वस्त्र उद्योग का संरक्षण जुटा रही थी। लकाशायर मोट कपड़े के उत्पादन में भारत के साथ प्रतियोगिता कर सकता था और करता था परंतु उमने मांग की कठिनाई

यह थी कि उत्पादित वस्तुओं पर लगे कर के भुक्ताने सूत पर उत्पादन शुल्क व्यवहार में अधिस्त हानका था और वर्मा में भारत के निर्याता को अनुचित रूप से समर्थन मिल रहा था।<sup>66</sup> अतः, फरवरी 1896 में भारत सरकार का राज्य सचिव के माध्यम से डाले गए दवाव के आगे भुक्ताना पड़ा और दान नए कानून बनाने पड़े जिनके अंतर्गत कपास के सूत पर आयात शुल्को तथा उत्पादन शुल्को का हटा दिया गया और साथ ही उसी समय बुने सामान पर आयात कर 5 प्रतिशत से घटाकर 3½ प्रतिशत कर दिए गए और उसी समय भारतीय मिलों द्वारा उत्पादित सभी प्रकार के बुने सामान पर 3½ प्रतिशत अनुरूप उत्पादन शुल्क घोषित किया गया। इस नए विधान का परिणाम यह निकला कि एक ओर आयातित सामान से मिलने वाली 51½ लाख रुपया की राशि अथवा 37 प्रतिशत राशि हाथ से निकल गई और दूसरी ओर भारतीय सामान पर करों में 300 प्रतिशत अथवा 11 लाख रुपयों की वृद्धि हो गई है।<sup>67</sup>

नाममात्र संरक्षण का हटाने के लिए मोटे कपड़े तक पर वीरधान की क्रिया न भारतीय लोकमत पर विस्फोटक प्रभाव डाला। भारतीय लोकमत ने भारतीय उद्योग और भारतीय जनता के हितों के बलिदान के विरुद्ध क्रोध में उफनते हुए तीखे प्रहार किए।<sup>68</sup> उदाहरणार्थ, 9 फरवरी 1896 के अंक में गरजते हुए मराठा न लिखा 'इस देश के प्रशासन के ईस्ट इंडिया कंपनी से महारानी महोदया के पास हस्तांतरित होने से पहले लकाशायर के पक्ष में दोबारा लगाए जाने वाले कपास शुल्क जैसे अति नीच और अयायपूर्ण पापकर्म करने का साहस किसी ने भी नहीं किया'। इसी प्रकार 'समय' ने 31 दिसंबर 1896 के अंक में तीखे प्रहार करते हुए लिखा 'इससे स्पष्ट दिखाई देता है कि अंगरेज किस प्रकार अपने स्वार्थों में अंधे हो गए हैं। अपने देशवासियों के हितों की उह इतनी चिंता है कि इसके लिए दूसरों के हितों को क्षति पहुंचाने में भी मकोच नहीं करते—वे तो छुरा निकाल कर दूसरों का गला काटने को तैयार हैं।'<sup>69</sup>

कपास पर लग उत्पादन शुल्क ने आगामी अनेक वर्षों तक राष्ट्रवादियों को उत्तेजित किए रखा। 1902 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तीखी भाषा में निवृद्ध एक प्रस्ताव में उत्पादन शुल्क की निंदा की और इसके निरसन की मांग की। यह प्रार्थना 1904 में दोहराई गई।<sup>70</sup> डी० ई० वाचा ने 1902 में प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए घोषणा की कि जब तक सरकार इस अनुचित शुल्क को हटा नहीं लेती, कांग्रेस इसके विरुद्ध आन्दोलन करती ही रहेगी।<sup>71</sup> आर० सी० दत्त ने अपने लेखा, पुस्तका और असह्य भाषणा में इस पर विस्तृत विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 'यह राज कर सबंधी अयाय के एक प्रमाण के तौर पर 1896 का अधिनियम आधुनिक काल में अपना उदाहरण आप ही था। उन्होंने आगे कहा अत्यंत सुसम्य सरकारें विदेशी सामान पर निषेधक शुल्क लगाकर गहउद्योगों की रक्षा करती हैं उन्मुक्त व्यापार की समग्रत और पूर्णत समयक सरकारें भी आयातित सामान पर राजस्व के प्रयोजन से साधारण सा सीमाशुल्क लगाती हुई अपने घरेलू उत्पादना पर शुल्क नहीं लगाती हैं। जी० के० खोसले ने लेजिस्लेटिव कौंसिल में अपने भाषणा में उत्पादन शुल्क के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा अनुभूत विशोभ को बार बार मुखरित किया।<sup>72</sup> एन० जी० चंद्रावरकर तथा

सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस के सभापति पद से उत्पादन शुल्क के निवृत्तन की मांग को उठाया<sup>74</sup> और समाचारपत्रों ने भी अपने कालमा में इस विषय को सजीव बनाए रखा।<sup>75</sup>

1894-6 के वित्तीय परिवर्तनों पर राष्ट्रवादियों का आक्रमण निम्नलिखित तर्कों पर आधारित था

भारतीय नृता निश्चित थे कि कपास पर लगे उत्पादन शुल्क भारत के औद्योगिक विकास को बिलंबित और प्रतिवधित करने वाले थे।<sup>76</sup> वे इस बात से विरोध रूप से भयभीत थे कि उत्पादन शुल्क भारतीय वस्त्र उद्योग के महीन प्रिस्म के सूत की कटाई के माग में बाधक बनेगा और इसी विशेष दिशा में इस उद्योग के अधिक विस्तार की संभावनाएँ थीं।<sup>77</sup> कुछ नेताओं ने यह आशंका भी प्रकट की कि उत्पादन शुल्क भारत के वस्त्र निर्यातों का बुरी तरह से झटका देगा और उसके फलस्वरूप जापान जैसे उनके प्रति द्वितीय एशियाई देशों का अपने उत्पादनों से भारत के उत्पादनों को प्रतियोगिता में पछाड़ने में समर्थ प्रमाण।<sup>78</sup> वस्तुतः यह भय निराधार था क्योंकि 1894 और 1896 दोनों अधिनियमों में नियान के लिए निर्धारित उत्पादनों पर शुल्क की पूरी छूट की व्यवस्था थी। इन नृताओं ने संभवतः या तो अधिनियमों की धाराओं को गलत समझा अथवा कदाचित्त उम्मा यह विश्वास था कि औद्योगिक उत्पादनक्षमता की सामान्य दुर्बलता तथा लाभ का ढाँचा परीक्षक रूप से विदेशी प्रतिद्वन्द्वियों में प्रतियोगिता में भारत की सामर्थ्य का प्रतिकूल रूप में ही प्रभावित करेगा।

भारतीय नृताओं ने 1896 के कपास उत्पादन शुल्क अधिनियम पर इस तक से और अधिक प्रहार किया कि इससे जनता के अपेक्षाकृत निधन बग को कठिनता का अनुभव होगा क्योंकि यह बग मोटा कपड़ा खरीदता है और उसपर अत्र कर लगा दिया गया है।<sup>79</sup> कुछ महानुभावों ने इस तथ्य को भी सामने रखा कि विदेशी वस्त्रों के आयात कर में जो 1½ प्रतिशत की छूट देस राज्य कर के साथ जाड़ दी गई है, उसका लाभ भारतीय जनता के अपेक्षाकृत धनी बग को ही होगा क्योंकि वे ही प्रधान रूप से विदेशी वस्त्रों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार उसका अर्थ यह हुआ कि धनिकों को भारमुक्त करने के लिए बचारा करावा पर कराधान कर लिया गया है।<sup>80</sup> बंगाली ने अपने 8 फरवरी 1896 के अत्र में पूछा सरकार की निधन जनता के प्रति वह सहानुभूति कहाँ बनी गई है जिसकी वह सोफी बचारती रही है ?<sup>81</sup>

उनका दूसरा तर्क यह था कि भारतीय उद्योग और जनता की समृद्धि पर इसके हानिप्रद प्रभाव के अतिरिक्त तथान्वित प्रयोजना की दृष्टि से भी यह उत्पादन शुल्क अनावश्यक, अत्र अत्रुजित था। इस तक के समय में उनकी सर्वप्रथम युक्ति यह थी कि स्पष्टतया वित्तीय उत्पादकता का इसको लागू करके कारणों में कोई स्थान नहीं क्योंकि इसकी बमूली में होने वाली आय उमूली पर हानि वात्रे व्यय के बराबर भी नहीं हो पाएगी। अत्र किन्हीं भी रूप में यह आय पर्याप्त नहीं कहला सकती। डी० ई० वाचा ने इस सत्र में एक रोत्रक तथ्य प्रस्तुत किया। उस समय सरकार का उत्पादन शुल्क के सत्र स 17 लाख रूपयों की बमूली हुई थी जो राजस्व का एक तुच्छ अत्र था जबकि उसने मिल मात्रिकों के लाभों को दुर्भाग्यप्रसन्न कर दिया था, यहा तक कि उनके 50 प्रतिशत

लाभ इस शुल्क से दुष्प्रभावित हो गए थे। अपने उपयुक्त वचन के उपपरिणाम में वाचा महादय ने कहा कि यह कहना बिलकुल गलत है कि मिलमालिक शुल्क से होने वाली हानि की उपभोक्ताओं से पूति कर सन्त थे अथवा कर रहे थे।<sup>87</sup> यह भी एक पर्याप्त राक्षक सत्य है कि इस विवाद में वाचा महादय ने इस कल्पना को जिम राष्ट्रवादियों ने इससे पूर्व स्पष्ट तक के रूप में प्रस्तुत किया था कि इस उत्पादन शुल्क के थोपने से उपभोक्ता पर ही सारा भार पड़ेगा—मानन से इनकार कर दिया।<sup>88</sup> द्वितीय, भारतीय नताआ न इम तक को भी ठुकरा दिया कि आयात कर के सरक्षी स्वरूप को अपक्षपाती बनाने के लिए तथा इस प्रकार भारत और ब्रिटेन में स्वतंत्र व्यापार को बनाए रखने के लिए उत्पादन शुल्क की अपेक्षा थी। उन्होंने पूर्ववत् दृढतापूर्वक कहा था कि आयात शुल्क स्थानीय उद्योग के लिए सभी व्यावहारिक दृष्टियों से किसी प्रकार का कोई सरक्षण नहीं जुटात क्योंकि भारतीय मंडी में भारत और ब्रिटेन के सूती उत्पादनो में प्रतियोगिता का क्षेत्र अत्यधिक ही सकीण था। ब्रिटेन भारत को थोटे से ही मोटे कपड़े का निर्यात करता था और इधर भारत उल्लेखनीय मात्रा में बढिया भूरे सामान का उत्पादन नहीं करता था जो भारत में ब्रिटेन के निर्यात का एक बहुत बड़ा भाग था।<sup>84</sup> इस तर के पथ पर बहुत सारे भारतीयों ने माग की कि यदि उत्पादन शुल्क अवश्य ही लगाना है तो उसे 20 नवर और उससे ऊंचे सूत पर न लगाकर 24 नवर और उममें ऊंचे सूत पर ही लगाना चाहिए।<sup>85</sup> इस सबध में फजल भाई विश्राम ने लेजिस्लेटिव कौंसिल में एक मसोधन प्रस्तुत किया जिसे उपस्थित सातो भारतीय सदस्या का समर्थन मिला।<sup>86</sup> बाद में जब ब्रिटिश उत्पादको ने शिकायत करत हुए और रियायतो की इस आधार पर चिल्लाहट की कि 20 नवर के नीचे के भारतीय सूत को दी गई छूट ने उमुक्त व्यापार के विरुद्ध युद्ध छेड रखा है तो भारतीय नेताओं ने उनकी मायता का बडी तीव्रता से निपथ किया।<sup>87</sup> कुछ ने तो यहा तक कि सुझाव दिया कि यदि भारत सरकार ब्रिटिश उत्पादको को प्रमन्न ही करना चाहती है तो उत्पादन शुल्क को बढाने के बदले 20 नवर तक के अगरेजी सूत को आयात कर से मुक्त कर दे।<sup>88</sup>

उत्पादन शुल्क के विरुद्ध राष्ट्रवादियों का प्रचंड विरोध और उसकी सावजनिक भत्सना प्रधान रूप से उसके दुष्परिणामो के विश्लेषण अथवा उसकी निरवकता के परिणाम से उत्पन्न नहीं थे, प्रत्युत उत्पादन शुल्क थोपने के मूल कारण का उनका सही ज्ञान तथा यह विश्वास ही इसका कारण था कि इस सदन में यह कर न गलत था, न अयथास्थान था और न ही मिथ्या विचारित साधन था, क्योंकि इस सबके विपरीत इसके प्रस्तावका का जागरूक प्रयोजन भारत के पनपते वस्त्र उद्योग को क्षति पहुंचाना था ताकि माचेस्टर के फिलस्तीनिया को सात्वना दी जा सके जो इस रूप में प्रतिद्वंद्वी के विकास को प्रतिबाधित करने की आशा रखत थे। 1894 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न इम तथ्य को बडी ही प्रखरता के साथ प्रस्तुत किया। उमने उत्पादन शुल्क को लकाशायर के हितो पर भारतीय हितो की बलि चढाना मानने के अपने दढ विश्वास को अभिलिखित किया।<sup>89</sup> बंगाली ने अपने 8 फरवरी 1896 के अंक में तीखे व्यग्यात्मक स्वर में टिप्पणी की 'भारतीय जनता तो भारत सरकार को सत्ता में नहीं रख सकती माचेस्टर कर सकता



है और करता है 'पहले मत्ता फिर फत्तव्य'।

और अधिक गहराई से विचार करने पर कुछ भारतीय नेता इस निष्पत्ति पर पहुँचे कि इस उत्पादन शुल्क के पीछे तो भारतीय औद्योगिक विकास को ब्रिटिश उद्योग का आवश्यकताओं और आदेशों के अधीन करने के मिद्दात और नीति काम कर रहे हैं। इस भावना का सशक्त अभिव्यक्ति देते हुए फिरोजशाह मेहता न कौंसिल चेंबर में घाणगा की वह मिद्दात और वह नीति यह है कि यदि वहाँ अगरेजी उत्पादनो के साथ भारतीय उत्पादना की प्रतियोगिता के सदेह का लेशमात्र भी दिखाई देता हो तो भारतीय उद्योग का उसके जनमने ही गला घोट दंता चाहिए।<sup>91</sup> अपने समय के वदाचित सर्वाधिक कोमल प्रकृति के लोक नेता एन० जी० चद्रावरकर भी 1900 के कांग्रेस अधिवेशन में अपने सभापतीय भाषण में यह टिप्पणी करने को विवश हो गए कि वतमान नीति में किसी भारतीय उद्योग को यूरोप की प्रतियोगिता में विवसित नहीं होने दिया जाणगा।<sup>92</sup> खासिम-उल अमदार न अपने 24 दिसंबर 1894 के अक में टिप्पणी की कि आज तक अगरेज भारतीय उद्योग को सहायता देने का फरेब करते आ रहे थे परंतु अब इस तथ्य ने उनके चेहरे का नकाब उतार दिया है और यह स्पष्ट हो गया है कि उनकी वास्तविक इच्छा इसके दमन की ही है।<sup>93</sup> मराठा ने 17 मार्च 1895 के अक में भारत में ब्रिटेन की मूल आर्थिक नीति के सबध में तो और अधिक ममघाती टिप्पणी की। उसने लिखा यह अबेली घटना यह प्रकट कर देती है कि इंग्लंड के मशीन उत्पादक की इच्छा है कि भारत कृषिप्रधान देश ही बना रहे जयवा हम भारतीय इंग्लंड के लिए सदा बच्चे माल के उत्पादक बने रहें और इंग्लंड सदैव हमारे लिए पक्के माल का निर्माता उत्पादक बना रहे।

### राजनीतिक प्रभाव

उत्पादक शुल्क और कर के प्रश्न के अध्ययन के आधार पर बहुत सारे विचारणीय भारतीय नेताओं ने भारत में ब्रिटिश राज्य के लाभप्रद चरित्र और वास्तव में तो उसके लक्ष्यों और प्रयत्नों का चुनौती दत्त हुए आर्थिक व्यापक अनुमान लगाए। वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय जागृतेन के इतिहास में कर सबधी दुष्घटना को प्राप्त महान ऐतिहासिक महत्व का प्रधान आधार नमम्या का यही पक्ष है। साथ ही भारत में राष्ट्रीय भावना को पानाने में कपास उत्पादन शुल्क तथा विभिन्न कर मन्गोधना ने जा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसमें राष्ट्रीय भावना विदेशी शासन के नैतिक आधार के प्रति सदेह पर ही केंद्रित हो गई जयवा दूसरे शासन में भारतीय जनता और उसके नेताओं के मन में इस शासन के नैतिक आधारों के विषय में ही शका उत्पन्न हो गयी।<sup>94</sup>

बहुसंख्यक भारतीयों ने 1894 और 1896 की अवधि में चुंगीकर तथा उत्पादन शुल्कों की कानूनी से यह प्रमुख परिणाम निवाला कि भारत का शासन भारतीयों के हित में न हारर मामायत ब्रिटिश जनता के और विरोधन ब्रिटिश व्यापारियों और उत्पादकों के हित में ही है। भारत की हितों का ब्रिटेन के हितों के साथ टकराव की स्थिति में भारतीयों को ही हानि उठानी पडेगी।<sup>95</sup> इस भावना का वेमरी के 28 फरवरी 1896 के अक में लिखे गए उद्देश्य ही कन्वैषन में इस प्रकार प्रकट किया भारत का निर्दिष्ट



द ताकि वह इस समय गुप्त रूप से प्रयुक्त की जाने वाली अथवा शक्ति का खुलकर काम में ना सकें।<sup>101</sup>

थोड़े से, विरल उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जिनमें स्वशासन तक की मांग की गई। उस संघ में यह नातिकारी विचार इस प्रकार प्रकट किया गया कि भारत तब तक राज करो के संवध में पाय प्राप्त नहीं कर सकता अथवा उद्योगीकरण की नीति का काय रूप नहीं दे सकता, जब तक कि वह ब्रिटेन के राजनीतिक नियंत्रण से मुक्ति नही पा लेता तथा आत्मशासित देश नहीं बन जाता। यह मत खुले तौर पर बगनिवासी ने अपन 9 फरवरी 1896 के अंक में इस प्रकार से प्रकट किया इंग्लैंड प्रधान रूप से एक उत्पात्क और व्यापारी देश है। जब तक इस देश पर अंगरेज लोगो का शासन है, तब तक भारत के संपूर्ण को व्यापार और उत्पादन में उनकी कृपा को सहन करना ही पड़ेगा।<sup>102</sup> 1896 के उत्पादन शुल्क और कर छूट की चर्चा करते हुए 1898 में आर० सी० दत्त ने उपयुक्त दृष्टिकोण से मिलते जुलते अपने विचार इस प्रकार प्रकट किए

जब तक भारत की जनता को सरकार की सहायता करने का, अपने राष्ट्रीय राजस्वों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने का सांविधानिक अधिकार मिल नहीं जाता तब तक भारतीय जनता का इंग्लैंड के ब्रिटिश मतदाताओं के आदेश से काम करने वाली भारत की वर्तमानवी सरकार द्वारा जानबूझकर और खुलामखुल्ला भारतीयों के हितों की वलि चढाने का अपमानित करने वाला दृश्य बार बार देखने का मिलगा।<sup>103</sup> उत्पादन शुल्क ने गोखले तक को इतना धुँध कर दिया कि उन्हें यह टिप्पणी करनी पड़ी कि इस गुत्त में यह स्पष्ट हो गया है कि जान स्टुअर्ट मिल न एक देश के लागा पर अन्य देश के लोगो की सरकार के संवध में जा रहा है बह सही है।<sup>104</sup>

परंतु देश की राजनीतिक मुक्ति का संघ्य अभी अविष्य के गम में ही निहित था। उस समय तो कायसूची में था, राष्ट्रीय भावनाओं को जगाना, इस प्रवृत्ति को पुष्ट करना तथा राजनीतिक जादोलन और संघर्ष के लिए भारतीय जनता को प्रशिक्षित करना। जसा कि हम पहले देख चुके हैं, इनमें में पक्वता, बुद्धिमत्ता और सफलता के साथ पहना काम ही संपन्न किया गया। दूसरा कायसूची के मामले में सारदार के चप्पे चप्पे में जान राष्ट्रीय भावना के प्रचार के साथ ही निष्पन्न हो गया। उस पीढ़ी के नेताओं में अत्यंत कुशल राजनीतिज्ञों में सबसे चतुर लाकनाय तिनक न इस संघर्ष में कर के विषय पर आदालत के महत्व को पूर्ण रूप से अभिस्वीकार किया। राष्ट्रीय एकता का आह्वान करने में उनमें रामाचरणपत्र मराठा ने अपन 9 फरवरी 1896 के अंक में लिखा

युवा भारत के कट्टर अंगरेज शत्रु सदैव मना पाड पाड कर चिन्तित रहें हैं कि भारत का भी एक राष्ट्र नहीं बन सकता। जाइए हम इस अयकर संकट की घड़ी में एक ही जाएं। आइए, हम सार भारतीय हिंदू, मुसलमान पारसी और भारत में रहने वाले अंगरेज एक सामान्य उद्देश्य बना लें। यह समय सदेह और संशोक का नहीं। राष्ट्रीय हित में सभी निजी मतभेद मुला देन चाहिए और मून निवासिया तथा जगल भारतीयों का समान शत्रु का सामना करने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए।<sup>105</sup> उत्पादन शुल्क की राष्ट्रीय प्रतिनियमा ब्रिटिश नीति के अय पत्रों के प्रति राष्ट्रीय प्रति-

क्रिया से अपने को उच्चतर स्तर की गुणात्मकता में पथक करती है। मत्स्य यह है कि राष्ट्रवादी नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में प्रथम बार ही आर्थिक अथवा उससे भिन्न कारणों से तीसरा वाय संपन्न किया। यद्यपि यह छोटे पैमाने पर और कदाचित् देश के केवल एक ही भाग अर्थात् जर्बई प्रेसीडेंसी में किया गया था यह कोरे आंदोलन के स्तर से उठकर वास्तविक वायवाही के क्षेत्र में पहुँच गया। इसी समय पर और कपास उत्पादन शुल्क के प्रश्न को लेकर विदेशी सामान का बहिष्कार उन्नेखनीय परिमाण में वाय रूप में परिणत होना दिखाई दिया।<sup>106</sup> विदेशी सामान के बहिष्कार की घोषणा राष्ट्रवादी नेताओं के एक वर्ग ने स्वदेशी उद्योग की सहायता के एकमात्र उपलब्ध साधन के रूप में की थी क्योंकि उनके अनुसार ब्रिटेन की 'वायप्रियता और दयालुता पर किसी प्रकार का विश्वास नहीं किया जा सकता था। देश के अनेक भागों में जनसभाएँ की गईं और उनमें स्वदेशी के प्रयाग की शपथ दिलाई गई। महाराष्ट्र में एक छोटे स्तर के स्वदेशी अभियान का सञ्चालन किया गया। राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से, छोटे स्तर पर विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का यह अभियान उत्पादन शुल्क के विरुद्ध किए गए राजनीतिक आंदोलन से कम महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि इसमें लोगों के स्वतः प्रत्यक्ष वायवाही करने का एक नया रूप उजागर हो गया। यह अपने दुश्मनों की निवृत्ति के लिए शासकों के आगे गिडगिडाने और उनकी कृपा पर निर्भर रहने के बदले अपनी सहायता प्राप्त ही करने की भावना का प्रतिनिधित्व करता था।<sup>107</sup> सरकार की शुल्क नीति से उत्पन्न होने वाली प्रारम्भिक स्वदेशी भावना ने भारतीयों में आत्मविश्वास की भावना का जन्म देने में, शहरी लोगों की बहुमर्यादा को राष्ट्रीय राजनीति के झुंडे के नीचे मगठिन होने में बीज डालने की भूमिका निभाई।

### 1899 के चीनी आयात शुल्क

भारतीय नेताओं को राजकारण की नीति का ध्याकुल करने वाला एक और पक्ष यूरोप से अनुग्रह के रूप में आने वाली चीनी पर उसी मात्रा में खोपा गया आयात शुल्क था। यह सचमुच एक जटिल विषय था और यह भारतीय नेताओं की आर्थिक पकड़ की गहराई आर्थिक राष्ट्रवाद की और राजनीतिक कौशल की कसौटी बन गया। समीक्षाधीन अवधि में यह आंदोलन भारतीय नेताओं के बीच गहरे मतभेद के कुछ कारणों में से एक था।

19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत चीनी का निर्यातक देश रहा था, किंतु इसके बाद जल्दी ही वह अधिकांश रूप में ब्रिटिश उपनिवेश मारिशस में बढ़िया चीनी आयात करने लगा। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक की अवधि में जर्मनी और जास्ट्रिया से चहा की सरकारी द्वारा अपनाई गई राज्य अनुग्रह निर्यात पद्धति के फलस्वरूप चुकदर चीनी के आयात में अपरिमित वृद्धि हो गई। सस्ती होने के कारण 1898 तक चुकदर चीनी के मारिशस के आयात पर और साथ साथ देश में उत्पादित चीनी पर छा जान का संकट उपस्थित हो गया। भारत सरकार ने इस प्रवाह को रोकने के लिए 20 मार्च 1899 को 1894 के भारतीय कर अधिनियम में संशोधन किया। इसने अतगत सरकार ने राज्य अनुग्रहों की मात्रा में अनुग्रह पोषित चीनी पर सम करने वाले आयात करों के आधान का

अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्मुक्त व्यापार की स्पष्ट स्वीकृति नीति से दिखाई देने वाले साहसिक परिवर्तन का प्रधान कारण सरकार ने यह बताया कि सरकार भारत के महान उद्योग और उस पर निर्भर करने की उपज के वृद्धि रूप से उत्तेजित प्रतियोगिता के ह्रास और अधिक क्षय तथा विनाश को रोकने को उत्सुक है। यह आरोप लगाया गया कि पहल ही बहुत अधिक क्षति हो चुकी है। भारत में रिफाइनरी व्यापार और अवाधत रूप से बढ़ती जा रही हैं और करने की उपज का क्षेत्र गिगटकर 13 प्रतिशत रह गया है। सरकार ने यह भी दावा किया कि अनुग्रह पोषित चीनी न केवल भारत में देश के आर्थिक कारखाना में उत्पादित और शोधित चीनी से प्रतियोगिता करती है प्रत्युत देश की अशोधित अथवा अधूरेपन से शोधित चीनी से भी प्रतियोगिता करती है।<sup>109</sup> इसके साथ ही सरकार ने इस तथ्य का मानने से एकदम इकारार दिया कि इसके पीछे मारिशस के किसानों और उत्पादकों के हितों की सुरक्षा जैसे शाही चिन्ता के किसी विषय में सरकार के इस निष्पक्ष पर पहुँचने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार ने यह मत प्रकट किया कि इसके विपरीत सत्य यह है कि भारतीय उद्योग के और भारतीय कृषि के हित ही समग्रतः पथ प्रदर्शक शक्ति रही है।<sup>109</sup>

यद्यपि लाड कजन ने अपने इस कदम के दश में प्रबलतम समयन का सुला दावा किया और सावजनिक रूप से घोषणा की कि केवल आयात व्यापारियाँ, बर्बई और कराची के यूरोपीय वाणिज्य सदनों द्वारा ही असहमति दिखाई गई है तथापि वास्तविकता कुछ और ही थी। भारतीय राष्ट्रीय नेता कभी भी, यहाँ तक कि प्रारम्भ में भी, इस समझने वाले आयात कर के समर्थन में एकमत नहीं थे। समय की गति के साथ तो राष्ट्रीय विरोध और बग पकड़ता गया। इसके अतिरिक्त जसाकि हम आगे देखेंगे, किसी भी स्थिति में भारतीय समर्थन बिना शत और सरकारी क्षेत्रों द्वारा यह पग उठाते हुए किए गए प्रचार की भावना के अनुरूप नहीं रहा।

भारत सरकार की कायबाही के समर्थक और आलोचक, कम से कम प्रारम्भ में तो बराबर संतुलित नहीं थे। अधिनियम के सशोधन के समय और उससे पूर्व समयका न आलोचना को पीछे छोड़ दिया था। समर्थकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वर जस्टिस एम० जी० रानाडे का था जिनका शब्द तब भी बहुत सारे भारतीयों की दृष्टि में आर्थिक मामलों में कानून की मी प्रामाणिकता लिए हुए था और जिनके विचार मई और जून 1899 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित तीन लेखों में अभिव्यक्त हुए थे।<sup>111</sup> दूसरे सत्रिय समर्थक थे पी० आनंद चारलू और जार० सी० दत्त। चारलू महादय ने इपीरियल लजिस्ट्रटिव कांसिल में अपने पद से सरकार का प्रबल और मुखर समर्थन दिया।<sup>112</sup> लगभग सभी राष्ट्रवादी समाचारपत्र, उदाहरणार्थ दि अमल बाजार पत्रिका दि बगाली मिहिंदू, मि मराठा, मि इंडु प्रकाश दि एडवोकेट और दि ट्रिब्यून समर्थक पक्ष में ही थे।<sup>113</sup> वस्तुतः सावजनिक रूप से अनुग्रह पोषित चुकंदर चीनी के विरुद्ध स्वर मुखरित करने वाला और सरकार में सरक्षक कायबाही की माग करने वाला दि अमल बाजार पत्रिका दश का प्रथम समाचारपत्र था।<sup>114</sup>

राष्ट्रवाणियों के एक छाट परतु मुखरित बग ने प्रबलता और कठोरता के साथ हम



मारिवास की चीनी, से रक्षा नहीं हो पाती।<sup>116</sup> गय ने लिखा आखिर हमारे लिए इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, यदि जमनी और आस्टिया के स्थान पर मारि इस चीनी भेजता है। वस्तुतः मारिशस ही हमारी आवश्यकता की बढ़िया चीनी का बहुत बड़ा भाग हमारे पास भेजता है और वही हमारी चीनी उद्योग की हत्या कर रहा है।<sup>117</sup> यदि सरकार इमानदारी से भारत के चीनी उद्योग के उद्धार और प्रोत्साहन की इच्छुक है तो उसे केवल मारिवास की चीनी पर ही प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए प्रत्युत उसके साथ ही साथ स्वदेशी उद्योग का भी सहायता और प्रोत्साहन देना चाहिए तथा गन्ने के उत्पादन में और चीनी उत्पादन के तरीके में सुधार के प्रयत्न करने चाहिए।<sup>118</sup>

चीनी गुल्फ लगान के पीछे सरकार के निहित आशय का मूल्यांकन करते समय अधिनाग समथका की प्रतिज्ञिया मई 1899 में इस विषय पर ब्लू बुक के प्रकाशन काल तक सरकार का पक्ष मही थी।<sup>119</sup> इस पुस्तक में प्रकाशित हाते ही लागू के गले के नीचे एक कट्टा सत्य उतारा। चीनी गुल्फ लगाने के समय बहुत सारे समाचारपत्रों और व्यक्तियों का विश्वास था कि यह शुरू भारत के हित में ही लगाया जा रहा है।<sup>120</sup> यहाँ तक कि एक प्रकार का हर्पोल्लास था कि भारत के उद्योग के पुनरुद्धार के लिए लाइ कर्जन के रूप में जायिव उद्धारक का अवतार हुआ है।<sup>121</sup> परंतु इस हृषातिरेक की स्थिति को महीन भी नहीं मनी रह सकी जब ब्लू बुक में आलोचकों के बुरे से बुरे सदेहों की पुष्टि कर दी।<sup>122</sup> इस पुस्तक ने समथका तक को यह मानने के लिए सहमत कर लिया कि यह गुल्फ एकाधिक रूप से अथवा सिद्धांत रूप से भारत के किमाना और उत्पादक के हितों की रक्षा के लिए नहीं लगाया गया था, प्रत्युत मारिशस और वेस्ट इंडीज के ही किमानों और उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के लिए था।<sup>123</sup> यहाँ तक कि जस्टिस रानाडे को यह टिप्पणी करनी पड़ी कि नीति में यह परिवर्तन वेस्ट इंडीज के चीनी उद्योग के विनाग के फलस्वरूप हुआ।<sup>124</sup> सरकार के इस पक्ष के अत्यधिक उत्साही समर्थक पी० आनंद चारलू को 1901 में यह स्वीकार करना पड़ा कि इस कानून का पारित करते समय जिस भय की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की गई थी कि यह अधिनियम कुछ उपनिवेशों के नाभों के लिए है वह भय सबका निरावार प्रतीत नहीं होता।<sup>125</sup> इसमें चीनी गुल्फ अधिनियम के बहुत सारे लोगों ने यह मानने को विवग कर दिया कि इसके प्रति उनका उत्साह मर पड़ गया है।<sup>126</sup> इतने पर भी वे इस अधिनियम की निंदा करने को तैयार न हुए। इस मंत्रण में वे आलापना में फिर अलग हो गए और उन्होंने यह कहना जारी रखा कि यह उपाय भारतीय चीनी उद्योग की कुछ समस्याओं के उपरांत अवश्य रखा करेगा अतः भारतीयों को इसके समर्थन में कतराना नहीं चाहिए।<sup>127</sup> और मारिशस के किमानों के साथ सामान्य उद्देश्य पर चलना चाहिए।<sup>128</sup> उनका कथन था कि यदि इस गुल्फ में भारतीय चीनी के प्रतिद्वंद्वियों में एक का हानि पहुँचती है तो यह भी एक विधेयक के नाभ ही है।<sup>129</sup> इसमें अतिशय इसमें भारतीय चीनी उद्योग को गाम देने का समय भी तो मिलेगा।<sup>130</sup>

भारतीय नेताओं का यह बग दूगर बग की इस मायता में समान रूप से गम्भिर था कि केवल मर करने जान कर के आधान में ही भारतीय चीनी उद्योग के और उत्पादन में सफलता नहीं मिलेगी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शीघ्रता





प्रयोग करने वाले निधन वगैरे पर इसका प्रभाव पड़ता था और इस पक्ष की अवहलना नहीं की जा सकती थी।<sup>159</sup>

मार्च 1894 में जब कोयला लौह धातुओं, रंगों, कच्चे औद्योगिक सामान तथा अन्य औद्योगिक मशरूमों पर कराधान की योजना वाले 'इंडियन टैरिफ बिल' को पेश किया गया तो भारतीय नेताओं ने पूर्वपेक्षा अधिक तीव्र प्रतिक्रिया प्रकट की। उन्होंने उद्योगों पर पराजय कराधान के माध्यम से औद्योगिक विकास को क्षति पहुंचाने की सरकारी नीति की जोरदार निंदा की।<sup>160</sup>

19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में चांदी की चढ़ाई एक छोटी सी मद थी जिसका भारत में इंग्लैंड को निर्यात किया जाता था। ब्रिटिश सरकार ने एक तो उसपर 30 से 35 प्रतिशत तक आयात शुल्क लगा दिया और दूसरे उसे बोम्बेन ठप्पा पद्धति का शिकार बना दिया।<sup>161</sup> 1882 के पदचालत भारतीय नेता इस राज्य कर के विरुद्ध तीव्र विरोध प्रकट करते रहे।<sup>162</sup> 1889 में यह विरोध उस समय अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चांदी की चढ़ाई पर शुल्क हटाने की तथा एक्टिव रूप से ठप्पा अख्तियार करने की पद्धति से मांग की।<sup>163</sup> इसका अभीष्ट प्रभाव पड़ा। कांग्रेस के इस अधिवेशन में भाग लेने वाले चार्ल्स ग्राइलाफ ने यह प्रश्न सदन में उठाया और 1890 में शुल्क हटा दिया गया।

भारतीय नेताओं ने इन छोटी छोटी बातों को भी इतना महत्व केवल इसलिए दिया ताकि ब्रिटिश के स्वतंत्र उद्योग के सिद्धान्त का खोखलापन दिखाया जा सके। इंग्लैंड में चांदी की चढ़ाई शुल्क हटाने की मांग करते हुए उन्होंने बार बार यह प्रश्न पूछा—जब भारत में 1882 में उम्मुक्त व्यापार के सिद्धान्त के पालन के वहान से रपास शुल्क हटाया गया था तो चांदी की चढ़ाई शुल्क अभी क्या बनाया रखा जा रहा है और इंग्लैंड भारत द्वारा निर्दिष्ट अच्छे उदाहरण का प्रत्यावतन क्या नहीं कर सकता? इंग्लैंड की शुल्क हटाने से दलबारी केवल भारत से सामग्री का स्वाथपरता और उनके दाह्ये व्यवहार को ही प्रकट करती है, यह उन्होंने घोषित किया।<sup>164</sup> 21 फरवरी 1884 के एक में ज्ञान प्रकाश ने लिखा—इसमें बढावर भद्दा मजाक और क्या हो सकता है कि इंग्लैंड उम्मुक्त व्यापार के प्रचार के मंत्र में इस बहावन का चरिताथ कर रहा है कि 'कोई दूसरे को तो फनसपा मिगाए और खुद बचनूफा जमी हक्के करे'।<sup>165</sup> इसी प्रकार अमृत बाजार पत्रिका ने 27 मई 1884 के अंक में ब्रह्म जोकर कहा—'इसे ब उम्मुक्त व्यापार कहते हैं हम तो इस धोखा ही कहते हैं कि उम्मुक्त व्यापार। मराठा न 3 जून 1888 के अंक में टिप्पणी थी कि 'इसके की उम्मुक्त व्यापार की नीति मयकारी और धावा घड़ी है—इंग्लैंड की सारी स्वाथपरता की नीति सगी हो गई है और व्यापार के संबंध में इंग्लैंड की व्यापारिक स्वतंत्रता की ऐसी बचनूफा माहित हुई है।'।

भारतीय नेताओं ने चांदी की चढ़ाई शुल्क हटाने के पक्ष में कुछ और तक भी प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि भारत में 'रपास रपास कर के विपरीत चांदी की चढ़ाई पर इंग्लैंड में रपास शुल्क भी विरुद्ध रूप में मरफन-भाषन के रूप में ही चलाया है इनमें होने वाली सार्पित आय कुछ हजार पाँडों की तुच्छ राशि ही है।'<sup>166</sup> उनका तर्क था कि इन करों के

हटने से भारतीय कारीगरी और व्यापार को सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त चादी की चट्टो के नियान से भारतीय चादी को निकासी की सुविधा उपलब्ध होगी और इससे भारत के रूपये पर दबाव को कम करने और उसके अवमूल्यन का रोकने में सहायता मिलेगी।<sup>108</sup>

### निष्कष

भारत सरकार द्वारा अपनाए गए विभिन्न कर साधना के प्रति भारतीय राष्ट्रीय नेतृत्व के दृष्टिकोण के उपर्युक्त अध्ययन के बाद कर नीति के चार प्रमुख तत्व स्पष्ट होते हैं प्रथम, अधाधुनिक नहीं, यह द्विवेकपूर्ण ढंग से भारतीय उद्योग को सरक्षण प्रदान करने की सुस्पष्ट नीति है। द्वितीय, भारतीय नेताओं के आधुनिक उद्योग के प्रति प्रबल और पूर्ण लगाव का यह एक अत्यन्त निदर्शन है। एक बार पुनः व्यापार के हितों की अपेक्षा उद्योग के हितों की प्राथमिकता दी गई। इसके साथ ही भारतीय नेताओं ने जानबूझकर विदेशी वस्तुओं और शोधित चीनी के उपभोक्ता मध्यमवर्गीय समाज के रूप में अपने हितों को देश के उद्योगीकरण के व्यापक हितों के अधीन ही कर दिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने भारतीय उपभोक्ता के हितों की अपेक्षा भारतीय उत्पादकों के हितों की अधिक महत्त्व दिया। यह रोचक तथ्य है कि जब कभी उनके विचार में भारतीय उद्योग पर कोई आच नहीं आती थी, जैसा कि पेट्रोलियम और किन्हीं किन्हीं के मत में चीनी के बारे में, तब भारतीय नेता निस्संकोच और अब्राहम रूप से उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा में अग्रसर होते थे। तृतीय, वे इस धारणा पर पूर्ण विश्वास करने लगे थे और इसी पर उन्होंने दृढतापूर्वक आचरण भी किया और इसी का प्रचार प्रसार भी किया कि भारत सरकार की कर नीति भारतीय उद्योग के विकास को क्षतिग्रस्त कर रही है। इसके पीछे विदेशी शासकों का उद्देश्य कदाचित् ब्रिटिश उत्पादकों के हितों की सुरक्षा करना है। भारत सरकार ब्रिटिश उद्योगों के उत्पादित माल की गत के लिए भारत में यथासंभव मंडी बनाए रखने के लिए कृतसंकल्प है और इसी के सदर्भ में भारत के ग्रामों की आर्थिक स्वायत्तता और स्वदेशी कलाकौशल का द्रुतगति से विनाश किया जा रहा है। चतुर्थ, सरकार की कर नीति ने राष्ट्रीय भावना को न केवल जगाया प्रत्युत राजनीतिक वास्तविकता को अधिक स्पष्टता से देखना भी सिखाया। इसने नेताओं को भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को फूँकने, उन्हें राजनीतिक शिक्षा देने तथा उनमें पनपती राष्ट्रीयता को सुदृढ करने, सारे देश के विभिन्न भागों के लोगों को झुट्टा होने यहाँ तक कि उन्हें राजनीतिक सघर्ष और आंदोलन की कला सिखाने का अवसर जुटाया। वस्तुतः समीक्षाधीन अवधि में करनीति उन विषयों में से एक थी, जिन्हें भारतीयों में सरकार विरोधी भावनाएँ तथा सघर्षपूर्ण राष्ट्रवाद को जगाने का श्रेय प्राप्त है।

## संदर्भ

- 1 संपूर्ण समीक्षाधीन अवधि में भारतीय कर नीति के इतिहास के लिए देखिए सी० जे० हेमिन्टन लि ट्रेड रिलेशंस बिटवीन इंग्लंड ऐंड इंडिया (1600-1806) (कलकत्ता 1919) प्रमथनाथ बनर्जी फिस्कल पार्लिसी इन इंडिया (कलकत्ता 1922) सी० एन० बकीस फाइनल डेवलपमेंट इन माइन इंडिया (बंबई 1924) अध्याय 15 और दत्त ई एच II
- 2 लि इंपीरियल गजटियर (1908) चार्ट IV प० 262
- 3 राज्य सचिव के संप्रण देविए (सेप्टेम्बर 1875) स० 6 15 जुलाई 1875 और उसका संप्रण (सेप्टेम्बर 1875) 11 नवंबर 1875 (स० 53) और 31 मई 1876 (स० 25)
- 4 राज्य सचिव की टाक 15 जुलाई 1875 पूर्वोक्त स्थल 11 नवंबर 1875 को अपनी टाक में उलने दोबारा बल देते हुए लिखा मूलतः सामान पर कर दो उत्पादक वर्गों को जिनपर ताक की संपन्नता और बल निर्भर है एव दूसरे के प्रतियोगिता ही नहीं बनाते प्रत्युत राजनीतिक विपत्तों भी बनाते हैं यदि इस वाय को स्थगित कर दिया जाए तो यह वर्तमान में प्रतियोगिता रत वर्गों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और कट्टर बने हितों में मतभेद का विषय बन जाएगा पूर्वोक्त स्थल
- 5 लिटन के दक्षिणोण के लिए देखिए लेडो बट्टो बेलफोर रि हिस्टरी आफ साउथ लिटल ऐंडमिनिस्ट्रेशन 1876 ट 1880 (सन 1899) पृ० 462 477 स्ट्रुची के लिए देखिए उसका 1877 का विज्ञापन वक्तव्य  
स्ट्रुची ने अपने दक्षिणोण को निम्नलिखित अधिक सुस्पष्ट शब्दा में इस प्रकार अभिव्यक्ति दी मैं इस सबंध में भारतीय और अंगरेजों के हितों में किमी प्रकार के मतभेद में विश्वास नहीं करता यदि ऐसा विषय जाता तो स्थिति भिन्न होती—मैं इस प्रकार की कल्पना में विश्वास नहीं रखता मैं हम मोचे पर एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि हम कहा जाता है कि भारत सरकार का कर्तव्य केवल भारत के हितों की रक्षा करना है और यदि इसमें लक्ष्मण्य के हितों को आपात पहुँचता है तो हमें इनमें कुछ केना देना नहीं परंतु जहां तक मरा सबंध है मैं इस सिद्धान्त को अस्वीकार करता हूँ भारत में अपने जीवन का अधिक समय व्यतीत करने से और भारत सरकार के सन्देश बनने का अर्थ यह नहीं कि अंगरेज ही नहीं रहा मावेस्टर के हित जिनपर मूल लोण मात्र सिक्कोटते हैं न केवल कपास के उद्योग से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध बुद्धिमान और महान योगों के हित हैं प्रत्युत साक्षात् अंगरेजों के भी हित हैं मूल यह कहने में कोई सन्देह नहीं कि जहां मानवता के नाते मैं आशा करता हूँ और अनुभव करता हूँ कि हम देश के प्रति मर कुछ कर्तव्य हैं वहां मैं यह भी अनुभव करता हूँ कि मेरी कल्पना में अपने देश के प्रति कर्तव्य से बड़बड़ कुछ भी नहीं तथा देखिए उनका 1878 और 1879 के वित्तीय भाषण
- 6 माइ गिन्सबरी ने भारत सरकार के पास प्रस्ताव भेजते हुए यह निर्णय किया कि 5 और मिले अर्थात् काय आरम्भ करने जा रही हैं तथा 1878 के अंत तक 1 231 284 प्रीमिया का भारत में नियोजन हो सकता (1878 के वित्तीय भाषण का परिशिष्ट 10)
- 7 जे० स्ट्रुची इंडिया (1903) पृ० 181 2 तथा बर्किंग फारनेचिव स्टेटमेंट्स 1883 कडिकाए 75-78 परिमन्त्र राय पूर्वोक्त पृ० 50 और जोगो पूर्वोक्त पृ० 628-9 हेमिन्टन ने विरोधी दक्षिणोण का प्रतिपादन किया कर के निवृत्त में न तो कपास के फसल सामान के आपात व्यापार को ही पतन की अपेक्षा अधिक इनपति मिली है और न ही भारत के हितों से बड़

कपास उद्योग के विस्तार में बिसी प्रकार की बाधा उपस्थित हुई है (पूर्वोद्धत, पृ० 247)

- 8 स्ट्रुची इंडिया (1903) प० 178
- 9 17 दिसंबर 1874 के घन म नेटिव ओपीनियन द्वारा पुनर्घटित ए० बी० पी० का एक विदेशी सस्करण, तथा देखिए आर० एन० पी० बग०, 2, 9 जनवरी 6 27 फरवरी 1875 में उद्धृत समाचारपत्र
- 10 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बंबई शाखा की प्रबंध समिति का 15 जनवरी 1875 का शासन, जर्नल आफ् द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन पृष्ठ IX 1875
- 11 देखिए आर० एन० पी० बग 14 21 28 अगस्त 4 11 सित० 1875, आर० एन० पी० बग० 14 21 28 अगस्त 1875 आर० एन० पी० एन० 28 अगस्त 1875 आर० एन० पी० एम० सितंबर अक्टूबर 1875
- 12 देखिए आर० एन० पी० बग 4 11 18, 25 मार्च 1 8 अप्रैल 1876 आर० एन० पी० बग० 18, 25 मार्च 15 22, 29 अप्रैल 1876 परवर्ती विरोध के लिए देखिए भोलानाथ चंद्र एम० एम० पृष्ठ V जनवरी-जून 1876 पृ० 3 58 63 याज्ञदा परस्त 1 अप्रैल बंबई समाचार 31 मार्च (आर० एन० पी० बग 7 अप्रैल 1877), इंदु प्रकाश 23 अप्रैल (वही 28 अप्रैल, 1877) एजुकेशन गजट 20 जुलाई (आर० एन० पी० बग० 28 जुलाई 1877) सट्टर 23 जुलाई (वही 4 अगस्त 1877)
- 13 देखिए आर० एन० पी० बग०, 23 30 मार्च 6 13 अप्रैल 1878 और देखिए आर० एन० पी० बग 11 18 जनवरी 8 15 22 फरवरी 1 15 मार्च 1879 आर० एन० पी० बग० 22 फरवरी 1 मार्च 1879 आर० एन० पी० एन० 22 फरवरी 1 मार्च 1879 ब्रह्म पब्लिक ओपीनियन 13 फरवरी 1879
- 14 देखिए आर० एन० पी० बग 22 29 मार्च 5 26 अप्रैल 10 मई 1879 आर० पी० एन० बग० 22 29 मार्च 5 12 अप्रैल 1879 आर० एन० पी० पी० एन० 5 12 अप्रैल 1979 3 मई 1879 को पार्लियामेंट के सामने भारत सरकार की कायदाही के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए एक जन सभा हुई इंदु प्रकाश 5 मई (आर० एन० पी० बग 10 मई 1879 इसी प्रकार की एक सभा का आयोजन कलकत्ता में 27 मार्च 1879 को किया गया इसमें लगभग 300 लोग सम्मिलित हुए (बागल पूर्वोद्धत प० 41) और देखिए एस० एन० बनर्जी स्पीच ] प० 201 03 के० टी० तलग सिलेक्ट राइटिंग एंड स्पीच (बंबई 1916) प० 185-6 लालमोहन घोष स्पीच आफ लालमोहन घोष आशुतोष बनर्जी द्वारा संपादित (कलकत्ता 1883 और 1884) भाग 1 प० 9
- 15 एस० एन० बनर्जी स्पीच ] प० 202
- 16 आर० एन० पी० बग० 5 अप्रैल 1879
- 17 भारत मिहिर 19 फरवरी (आर० एन० पी० बग० 28 फरवरी 1880), बंगाली 29 जनवरी 1881 ए० बी० पी० 24 फरवरी 1881 आर० एन० पी० बग० 1 8 15 जनवरी 19 फरवरी 5 मार्च 1881 में उल्लिखित समाचारपत्र आर० एन० पी० बग 29 जनवरी 5 26 फरवरी 1881 16 मई 1880 को पूना में पूना सांख्यिक सभा द्वारा आयोजित एक जनसभा ज० पी० एस० एस० खंड III सख्या 1 (जुलाई 1880) पृ० 9 (और देखिए पृ० 3)
- 18 मराठा 28 अगस्त 18 सितंबर 1881 नेटिव ओपीनियन 28 अगस्त 4 सितंबर 18 सितंबर 1881 और आर० एन० पी० बग 3 10 24 सितंबर 1881 और आर० एन० पी० बग०

- 24 31 दिसंबर 1881 में उल्लिखित समाचारपत्र
- 19 ए० बी० पी० 16 23 30 मार्च 6 अप्रैल 1882, बंगाली 11 मार्च 1882 मराठा, 26 मार्च 1882 नैटिव प्रोप्रीटियन, 12 मार्च 1882 आर० एन० पी० वॉ 11, 18 मार्च, 1 अप्रैल 1882 आर० एन० पी० वॉ 25 मार्च 1 अप्रैल 1882, आर० एन० पी० पी० एन० 22 29 मार्च 5 12 अप्रैल 1882 में उल्लिखित समाचारपत्र यहाँ तक कि परम प्रतापी महाराज जतींद्र मोहन टगोर ने चब्रर कांसिल की अपनी सीट से कपास आयात के निवृत्तन की निगा की (एन० सी० पी० 1882 खंड XXI प० 304)
- 20 यह शासन पहले ही दशौ भाषा प्रस कानून तथा स्वशासन के विस्तार की वापस ले चका है अपराध प्रतिष्ठा संहिता सुधार बिल दूर की कोड़ी था भारतीय नेताओं को अब भी किमा अय वस्तु का अपना अग्ररेजा में स उत्तरवादिया और उग्रवादियो पर दंड विम्वदास था
- 21 उदाहरणय देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बर्बई शाखा का स्मरणपत्र जनरल आफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन खंड IX (1875) प० 99 भोलानाथ चंद्र एम० एम० खंड V (जनवरी जून 1876) प० 51 58 9 आर० एन० पी० वॉ 22 29 मार्च, 12 26 अप्रैल, 3 मई 1879 में उल्लिखित समाचारपत्र तलग राइटिंज प० 186 एन० एम० घाप स्पीचेज खंड I प० 9 एस० एन० वनर्जी स्पीचेज I प० 202 वायसरायल्टी आफ लाइ लिटन ज० पी० एस० एस० खंड III स० 1 (जुलाई 1880) प० 68 9 मराठा 26 मार्च 1882 सर जान स्टूची ने निम्नलिखित आश्चर्योत्साहक परतु उदघाटक शब्दों में भारतीय दण्डिकाण को उलट रूप में हम प्रकार प्रस्तुत किया भारत में करो की सूची में शामिल अथवा शामिल किया जा सकने वाला प्रत्येक उत्पादन या तो भारत में उत्पादित होता है या किया जा सकता है अत यह मिथ है कि कपास आयात शुरूक वास्तव में अथवा सामर्थ्य से सरमर्क हैं (वित्तीय प्रतिवेदन 1878 बडिका 55)
- 22 उदाहरण के लिए देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बर्बई शाखा का अनुस्मारक पूर्वोक्त स्थल भोलानाथ चंद्र पूर्वोक्त स्थल तलग राइटिंज प० 185 एम० एन० वनर्जी स्पीचेज I, प० 200-02 वायसरायल्टी आफ लाइ लिटन पूर्वोक्त स्थल तथा बहुत सारे समाचारपत्र पीछ पाद टिप्पणी 13 14 में उद्धृत
- 23 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बर्बई शाखा का अनुस्मारक पूर्वोक्त स्थल सहचर 23 जुलाई (आर० एन० पी० वॉ 4 अगस्त 1877) एन० एम० घोष स्पीचेज भाग I प० 193 200-02 रानाडे ज० पी० एस० एन० खंड IV सख्या 1 (जुलाई 1881) प० 50 बहुत बयों में उपरान्त आर० सी० दल न व्यथित होकर कहा उस समय यह कर हटाए गए हैं जबकि दण्डिणी भारत अभी 1877 के मन्म अज्ञान से समत नहीं पाया जबकि उत्तरी भारत अभी 1877 के अकाल से सतप्त है जबकि भूराजस्वों में करो की अभी अभा बन्तारी को गई है जबकि विश्व करो की उगाही से बनाया गया अकाल बोमा कोप' अदृश्य हो गया है और जबकि अफगानिस्तान के ककट और विनाल घर्षों न बन्तानिक जिनामा का माग हा अवदद कर दिया है [ई एच II] प० 416)
- 24 बर्बई समाचार जाम जमान और अछार लीगलर 21 मार्च (आर० एन० पी० वॉ 23 मार्च 1878) इंडियन स्पेक्टर 28 अगस्त (वॉ 3 गिनबर 1881) बंगाली 11 मार्च 1882 इंडियन स्पेक्टर नैटिव प्रोप्रीटियन गुजरान मित्र 12 मार्च (आर० एन० पी० वॉ 18 मार्च 1882) वस्तुतः 1882 में जिनन भी समाचारपत्रों ने आयात करों के निवृत्तन पर टिप्पणा की हम तथ्य को प्रस्तुत किया

- 25 आर० एन० पी० बब 7, 21 28 अप्रैल 1877 और 22 29 मार्च 5 अप्रैल 1879 में उल्लिखित समाचारपत्र भारत मिहिंदर 29 मार्च (आर० एन० पी० बग० 5 अप्रैल 1879) हिंदी प्रयोग अर्पित (आर० एन० पी० पी० एन० 12 अप्रैल 1879) मिरात उल हिंद 15 फरवरी (वही, 19 फरवरी 1880) बदनान सजीवनी 3 जनवरी (आर० एन० पी० बग० 14 जनवरी 1882) सहचर 29 मार्च (वही, 8 अप्रैल 1882)
- 26 सहचर 17 दिसंबर ए० बी० पी० के विशेषी सस्वरण म बलगाव समाचार, 2 मार्च (आर० एन० पी० बब 6 मार्च 1875) आंध्रभाषासजीवनी तिथि रहित (आर० एन० पी० एम० सितंबर अक्टूबर 1875) सदाशुभ 23 अगस्त (आर० एन० पी० पी० एन० 28 अगस्त 1875) आर० एन० पी० बग० 2 9 जनवरी 6 27 फरवरी 13 मार्च 14 21 28 अगस्त 1875 और आर० एन० पी० बब, 14 21 28 अगस्त 4 11 सितंबर 1875 4 11 25 मार्च 1 8 अप्रैल 1876, आर० एन० पी० बग० 18 मार्च 15 22 अप्रैल 1876 21 28 जुलाई 4 18 अगस्त 1877 आर० एन० पी० बब 23 मार्च 1878 में उल्लिखित समाचारपत्र भोलानाथ चंद्र एम० एम० खंड V (जनवरी-जून 1876) पृ० 48 58-63, एल० एम० घोष जर्नल आफ इंडिया एसोसिएशन खंड III भाग 2 पृ० 65 और स्पीचज भाग 1 पृ० 9, एम० एन० बनर्जी स्पीचज I, पृ० 220 आर० एन० पी० बब 22 29 मार्च 5, 19 26 अप्रैल 1879 आर० एन० पी० बग० 22 फरवरी 22 29 मार्च, 5, 12 अप्रैल 1879 आर० एन० पी० पी० एन० 5 12 अप्रैल 1879 में उल्लिखित समाचारपत्र दि श्रान प्लेज एंड इटस वासिक्वेंसिज ज० पी० एस० एस०, खंड III सध्या 1 (जुलाई 1879) पृ० 44 वायसरॉयल्टा आफ लाड सिटन जे० पी० एस० एम० खंड III सध्या 1 (जुलाई 1880) पृ० 34 63 68 मिरात उल हिंद 15 फरवरी (आर० एन० पी० पी० एन० 19 फरवरी 1880), सहचर 20 दिसंबर 1880 (आर० एन० पी० बग० 1 जनवरी 1881) साधारणी 2 जनवरी (वही 8 जनवरी 1881) सुलभ समाचार, 8 जनवरी (वही 15 जनवरी 1881), आनंद बाजार पत्रिका 21 फरवरी (वही 5 मार्च 1881), केसरी 20 सितंबर (आर० एन० पी० बब 24 सितंबर 1881), मराठा 18 सितंबर 1881 26 मार्च 1882, ए० बी० पी० 16 मार्च 1882, आर० एन० पी० बब 18 25 मार्च 1 8 अप्रैल 1882, आर० एन० पी० बग० 24 31 सितंबर 1881, 7 जनवरी 25 मार्च 1 अप्रैल 1882, आर० एन० पी० पी० एन० 22 29 मार्च 1882 में उल्लिखित समाचारपत्र
- 27 आर० एन० पी० बब 25 दिसंबर 1875
- 28 रानाडे रिब्यू आफ मी टूड एंड इगलिश कामस अगस्तस मोडरिडियन द्वारा, जे० पी० एस० एल०, खंड IV सध्या 1, पृ० 50 यह समीक्षा अज्ञातनाम प्रकाशित हुई हमारे पास जी० ए० मानवर द्वारा जस्टिस रानाडे को इसका लेखक मानने का प्रमाण उपलब्ध है (मानकर पूर्वोद्धृत पृ० 214-5 खंड I)
- 29 जे० पी० एस० एल०, खंड III सध्या 1 (जुलाई 1880) पृ० 11
- 30 उनके दृष्टिकोण का सोदाहरण विमर्श जान स्ट्रुची की अगली टिप्पणी में किया गया है भारतीयों द्वारा ब्रिटिश सरकार पर लक्ष्यायन का पक्षपात करने का अभियोग मूखतापूर्ण आरोप है जिसका उत्तर देने की न अपेक्षा थी और न है (इंडिया 1903 पृ० 178) तथा देखिए स्ट्रुची फाइनेंसल स्टेटमेंस कठिका 77 यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उसी समय उच्च ब्रिटिश

अधिकारियों ने राष्ट्रीय आपत्तियों की सम्यक जानकारी तो प्राप्त की परंतु उन्हें स्थिति के परंपरागत रूप में लेते हुए टाल दिया

- 31 पुनर्नीय क्वील पूर्वोद्धृत पृ० 408-24
- 32 1 मार्च (आर० एन० पी० बंग 6 मार्च 1875) इसी प्रकार 23 अगस्त 1875 के अंक में सदाशिव को नये रेशवाली कपास पर आयाज कर लगाने पर विचार करते समय यह टिप्पणा करना को विवश होना पड़ा यह देखने के पश्चात् कौन इनकार करेगा कि हमारे शासकों को यह वास्तविक चिंता उत्तजित कर रही है कि भारत का एक बहुत बड़े उत्पादक देश के रूप में ही विकास हो ? (आर० एन० पी० पी० एन०, 28 अगस्त 1875) और देखिए साधारणी, 29 अगस्त (आर० एन० पी० बंग०, 11 सितंबर 1875)
- 33 भोलानाथ चंद्र एम० एम० खंड V (जनवरी जून 1876) पृ० 58 60 अतएव उन्होंने कहा कि स्वामिभक्ति के लिए युवराज के भारत पधारने का बोर्ड महत्व नहीं इंग्लैंड की शासिका महारानी का भारत की सम्राज्ञी की उपाधि ग्रहण करना व्यर्थ है वस्तुतः देवता नहीं प्रत्युत पिशाच ही सच्चे अर्थों में शासक शक्ति हैं माजिस्टर ही सच्चे अर्थों में भारत के भाग्य का निर्णायक है (वही पृ० 63)
- 34 वही पृ० 62 तथा देखिए साधारणी 23 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 29 मार्च 1879)
- 35 एम० एन० बर्नार्ड स्प्रीचेज I पृ० 202
- 36 एल० सी० पी० 1882 खंड XXI पृ० 328 9
- 37 और देखिए सहचर 29 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 8 अप्रैल 1882)
- 38 दल ई० एच० II पृ० 339
- 39 आर० एन० पी० बंग० 1 अप्रैल 1882 तथा समय 15 मार्च (वही 20 मार्च 1886)
- 40 सहचर 13 जन० (वही 23 जन० 1886)
- 41 एन० सी० पी० 1882 खंड XXI पृ० 328
- 42 उगाहरण के लिए देखिए बी० ओ० आई० 15 अप्रैल 1884 बंगाली 22 मार्च 1884 एल० ए० स्वामी नाथ अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1885 पृ० 69 वेसरी 24 जनवरी बाघ मुघावर 25 जनवरी (आर० एन० पी० बंग 28 जनवरी 1888) एल० ई० एच० II पृ० VIII, 120 339 41 401 02 411, 416 518 537 स्प्रीचेज II पृ० 126
- 43 उगाहरण के लिए देखिए आई० एन० सी० 1885 1887 और 1889 के प्रथम प्रस्ताव VI VI और III वेसरी 3 अप्रैल (आर० एन० पी० बंग 7 अप्रैल 1883) जे० यू० यात्रिका रिप० आई० एन० सी० 1885 पृ० 66 एम० ए० स्वामीनाथ अय्यर वही पृ० 69 बंगाली 9 जनवरी 1886 आर० एन० पी० बंग० 2 9 16 23 30 जनवरी 6 फरवरी 18 25 मितंबर 2 9 अक्तूबर 1886 आर० एन० पी० बंग, 18 सितंबर 1886 म उल्लिखित समाचार पत्र ट्रिब्यून 18 सितंबर, इंडियन स्पेक्टटर 19 मितंबर, बिहार हेराल्ड और इंडियन मिरर 21 मितंबर पीपुल्स मेंड 25 मितंबर नात्र प्रकाश 30 सितंबर (बी० ओ० आई० खंड IV सन्ध्या 10 अक्तूबर 1886) ट्रिब्यूनसंस्कारिका सन्ध्या 3 (आर० एन० पी० एम० अक्तूबर 1886) जोगी पूर्वोद्धृत पृ० 100-01 142 160 मांडनिक पूर्वोद्धृत पृ० 651 659-60 एम० एम० बर्नार्ड स्प्रीचेज III पृ० 8 मुह प्रथम सेन रिप० आई० एन० सी० 1887 पृ० 132, मराठा 29 जनवरी 1883 बंगाली 28 जनवरी 1883 ए० बी० पी० 26 जनवरी 1888 बी० ओ० आई० फरवरी और मार्च 1883 म उल्लिखित समाचारपत्र आर० एन० पी० बंग 28 जनवरी

- 4 फरवरी 1888 आर० एन० पी० बग०, 28 जनवरी 4 फरवरी 1888, आर० एन० पी० एम 31 जनवरी 29 फरवरी 1888 आर० एन० पी० पी० एन० 31 जनवरी 7 14 फरवरी 1888, नीरोजी सी० पी० ए०, पृ० 177 ज्ञान प्रकाश और सुधारक 19 फरवरी सुबोध पत्रिका, 18 फरवरी (आर० एन० पी० बब 24 फरवरी 1894)
- 44 भारत सरकार तो नए कर अधिनियम में मूल्य सामान को सम्मिलित करने के लिए अत्यंत उत्सुक दिखाई देती थी परंतु महारानी की सरकार के आदेश से उसे अपने निश्चय को रद्द करना पड़ा देखिए भारताय कर अधिनियम पर मार्च 1849 में वित्त सदस्य का भाषण, एल० सी० पी० 1894 खंड XXXIII और देखिए वकील पूर्वोद्धत पृ० 426 पी० बनर्जी फिस्वल्स पालिसी इन इटिया पृ० 89-90
- 45 देखिए एल० सी० पी० 1894 खंड LXXIII पृ० 155
- 46 पूना सावजनिक सभा का स्मरणपत्र दिनांक 6 मार्च 1894 जे० पी० एस० एस० खंड XVI स० 4 (अप्रैल 1894) इंडियन एसोसिएशन का स्मरणपत्र, दिनांक 8 मार्च 1894 रिपोर्ट आफ दि इंडियन एसोसिएशन फॉर 1892 3 टु 1895-6 बर्बई प्रेसीडेंसी एसोसिएशन द्वारा 2 मार्च 1894 को विरोध स्वरूप भेजा गया तार, पी० पी० (हाऊस आफ कामस), 1895 खंड 72 स० 202, बर्बई के 2 नवंबर 1894 को हुए सातवें प्रांतीय सम्मेलन में अध्यक्षीय अभिभाषण जे० पी० एस० एस० खंड XVII स० 3 (जनवरी 1895) पृ० 5 6 18 मार्च 1894 को पूना में हुए सम्मेलन में प्रस्तुत याचिका के लिए देखिए मराठा 18 मार्च 1894 20 मार्च 1894, को मद्रास में हुए सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के लिए देखिए मराठा, 25 मार्च 1894 कलकत्ता में 8 मार्च बर्बई में 14 मार्च, अमृतसर में 7 मार्च और लखनऊ में 9 मार्च 1894 को हुए जन-सम्मेलनों में पारित प्रस्तावों के लिए देखिए, पी० पी० (हाऊस आफ कामस) 1895 खंड 72 सख्या 202
- 47 ए० बी० पी० 3 मार्च 1894 मराठा, 4 मार्च 1894 बंगाली 10 17 मार्च 1894 इंदु प्रकाश 12 मार्च 1894 इंडियन स्पेक्टेटर 11 मार्च 1894 एडवोकेट 9 मार्च (आई० एस० बी० ओ० आई० 25 मार्च 1894) ट्रिब्यून 14 मार्च (वही 15 मार्च 1894) आर० एन० पी० बब, 10 मार्च आर० एन० पी० बग० 10 17, 31 मार्च 1894, आर० एन० पी० एम० 15, 31 मार्च 1894 आर० एन० पी० एन०, 14 21 28 मार्च 1894 आर० एन० पी० पी० 7 21 अगस्त 1894 में उल्लिखित समाचारपत्र
- 48 पूना सावजनिक सभा का स्मरणपत्र 1894 पूर्वोक्त स्थल इंडियन एसोसिएशन का स्मरणपत्र, पूर्वोक्त स्थल बर्बई प्रेसीडेंसी एसोसिएशन का विरोध पूर्वोक्त स्थल जी० आर० एम० चितनवीस एल० सी० पी० 1894 खंड XXXIII पृ० 157 रास बिहारी घोष स्पीचेज पृ० 151 2.
- 49 रास बिहारी घोष स्पीचेज पृ० 150 आगे चौदहवें अध्याय में राष्ट्रवादियों की तरफ नीति के इस पक्ष की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की गई है
- 50 पूना सावजनिक सभा का 1894 का स्मरणपत्र पूर्वोक्त स्थल तथा पीछे सदन 45 6 में उद्धृत लगभग सभी भारतीय नेता
- 51 आई० एस० बी० ओ० आई० 29 अप्रैल 1894
- 52 ज्ञान प्रकाश 5 मार्च (आर० एन० पी० बब, 10 मार्च 1894)
- 53 बहुत सारे राष्ट्रवादी नेताओं ने धीमे स्वर में और अप्रत्यक्ष ढंग से राजनीतिक धमकी भी दी और इन प्राथियों ने तो अपने पासको से राजनीतिक नतिवता की अपेक्षा करते हुए उन्हें महा



तक था। वही दे दी कि जब हम एक स महाराजा की आजादगी भारतभय जनता का बचपनी का एक एका महारा घटना समया त्रिमका क्षतिपूर्ति कथा हा हा नही मरणा (नियम, मरणा 18 माच 1894)

- 54 11 माच (आर० एन० पी० बग० 17 माच 1874)
- 55 आर० एन० पी० बग० 31 माच 1894 दमा प्रकार बगामी न 17 माच 1874 न एक म बचपनी की कि भारतीयों का एकदक न ज्ञाय स शिक्षाग दिय गया ?
- 56 आर० एन० पी० बग० 24 माच 1874
- 57 एल० गा० पी० गड XXXIII पृ० 46
- 58 बचपनी का पृ० 387 384
- 59 विनाय प्रतिभान 1874 बहिरा 55
- 60 बचपनी पूर्वोक्त पृ० 427 ) न उद्धत और दियत बचपनी एन० गा० पी०—1894 गड XXXIII पृ० 393 4
- 61 बचपनी पूर्वोक्त पृ० 427 429 शिमला—पूर्वोक्त पृ० 245-51
- 62 एल० गा० पी०—1874 गड XXXIII पृ० 381 2
- 63 मराठा 16 निसबर 1894 दहियत एके न 23 निसबर 1874 दहियत 24 निसबर 1894 ए० बी० पी० 22 निस० 1894 बगामी 22 निस० 1894 निस० 27 निस० 1894 कनर-ए दिस 16 निस० मुवाय प्रकार 19 निस० मुवाय पत्रिका 16 निस० दमा निस 20 निस० (आर० एन० पी० बग० 22 निस० 1894) स्वच्छमिजन 21 निस० 1894 दामिम उन जगवार 24 निस० 1894 तथा अन्य भारतभय समाचारपत्र (आर० एन० पी० एम० 15 जनवरी 1895) मन्म एड्ड 24 निस० 1894 (आई० एन० बी० ओ० आई० 13 जनवरी 1895) दिसनाना 26 निस० 1894 (आर० एन० पी० एन०, 2 जनवरी 1895) एम० एन० बनजी गा० पी० ए. प० 259 61 जागा पूर्वोक्त 191 2 केवल एक प्रधान समाचारपत्र एडवोकेट न बगाम पर आपात शुल्क न विरुद्ध हम आधार पर आपाति की कि हमसे हम प्रकार की वस्तुभा न दाम बड जाग्य और इसका परिणाम उन्मान्य का न सगता हो सकता है। हमने म्यान पर पत्र का मुभाव था कि मावेकर के उपरानी तन्मा से सबध जोचना चाहिए
- 64 वाचा निस० आई० एन० सी० 1894 पृ० 31
- 65 आई० एन० सी० 1894 का प्रस्ताव ] वाचा निस० आई० एन० सी०—1894 प० 31 2 मराठा 16 निसबर 1894 ए० बी० पी० 22 29 निसबर 1894 बगामी 22 निसबर 1894 निस० 27 निस० 1894 दहियत एकेटेटर 23 निसबर 1894 दह प्रकाश 24 31 निस 1894 आर० एन० पी० बग० 22 दिस० 1894 5 जनवरी 1895 आर० एन० पी० बग० 22 29 दिसबर 1894 5 12 जनवरी 1895 आर० एन० पी० एम० 15 जनवरी 1895 आर० एन० पी० एन० 9 16 23 जन० 1895 आर० एन० पी० 12 जनवरी 9 फरवरी 1895 म उल्लिखित समाचारपत्र यहाँ यह निश करना उचित है कि बहुत सारे भारतीय नताओ ने उस समय भी जब मीमा शुल्क के लगाने की सभाजनओ पर विचार किया जा रहा था इसका प्रबल विरोध किया था इस सबध मे दधिए, दहियत एकेटेटर 1 जुलाई 1894 दिसू 11 जुलाई 1894 गुजराती 1 जुलाई सुधारक 2 जुलाई (आर० एन० पी० बग० 7 जुलाई 1894) केमरी 24 जुलाई (वही 28 जुलाई 1894) दिसून 18 जुलाई एडवोकेट 20 जुलाई

- (आई० एन० बी० ओ० आई० 26 अगस्त 1894)
- 66 इंग्लिश यूरोजिन पृ० 252 3 दस ई एच II पृ० 539-40 बर्नोस यूरोजिन पृ० 430-2
- 67 बर्नोस यूरोजिन पृ० 431
- 68 मराठा, 2 जनवरी 9 फरवरी 1896 ए० बी० पी० 29 जा० 1896, बगाली 1 8 फरवरी 1896, हिंदू 27 जनवरी 1896 इंग्लिश गेनेरेटर 2 फरवरी 1896, नाम स्टड्ड 27 जनवरी इंडिया मगन 27 जनवरी (आई० एन० बी० ओ० आई० 15 मार्च 1896) एडवांसि 28 जनवरी ट्रिग्नू 29 जन० इंडियन मिस्टर 30 जनवरी (वही 22 मार्च 1896) बिहार हेराल्ड, 8 फरवरी (वही 5 अप्रैल 1896) आर० एन० पी० बब 25 जन० 1 फरवरी 1896, आर० एन० पी० बग० 1 8 15 फरवरी 1896 ए० एन० पी० एम० 15 29 फरवरी 1896. आर० एन० पी० एन० 5 12, 19 फरवरी 1896 आर० एन० पी० 8 15 22 फरवरी 1896 वं जलियन समाचारपत्र बर्नोस प्रोडेंसी एग्रेसिवा की ओर 27 जनवरी 1896 का भवा मदा तार इंडिया टारिफ एक् 1896 और वाटन इयूटा एक् 1896 व मासिक 1896 व वागमाल-नो 5078 (हाउस आफ वायग) पृ० 163 28 जनवरी 1896 व बर्नोस की एक जनगभा में पारित प्रस्ताव वही पृ० 166 29 जनवरी 1896 व अग्रज पुता सावर्जनिक तथा द्वारा प्रेषित तार वही पृ० 171 2 फरवरी 1896 व मगन व हर्द जनगभा द्वारा अभिप्रेत विरोध वही पृ० 192 7 फरवरी 1896 वी थोरसा जिला वरा बर्नोस व हर्द जनगभा द्वारा अभिप्रेत विरोध वही पृ० 193 विधान परिषद व बी० आर० गुप्तकुटे, पी आन द चारम् और मोहिनी मोहा राय व सरकारी प्रस्ताव व विरुद्ध भाषण (एन० सी० पी० 1896 यह  $\lambda \lambda \lambda V$  पृ० 67 7 78 87 92 95)
- 69 आर० एन० पी० बग० 8 फरवरी 1896
- 70 नमन प्रस्ताव  $\lambda V$  और प्रस्ताव VIII
- 71 रिप० आई० एन० सी०—1902 पृ० 143
- 72 दस ई एच II पृ० 543 और वही पृ० 597, 612 स्पीचर II पृ० 45-6 80 126-7
- 73 योगले स्वायत्त, पृ० 10, 41 2 और 77 अपने 1903 व बजट भाषण म उद्देशे आर० सी० दस वी प्रतिप्रतिन रिपया उद्देशे दुकतापूर्वक स्वीकार किया गृह उद्योग पर सरकारी बराधान की विदश प्रतिपादित व लाभ व। लाभ बनाने वाली ऐसा व्यवस्था किनी भी अन्य दश म समभव नही थी भल ही वही की सरकार विनास के बगार पर खरी हुई गिरने की स्थिति म हा क्यों न हो (वही, पृ० 42) और देखिए, श्रीराम—एन० सी० पी०—1903, घड VIII पृ० 104 5
- 74 सी० पी० ए०, नमन पृ० 527 और 696
- 75 उपाहरणाथ मराठा 10 मई 1896 नेटिव ऑपानियन, 1 अप्रैल बरवरी 31 मार्च (आर० एन० पी० बब 4 अप्रैल 1903) इंडियन पीपुल, 19 जनवरी 1905
- 76 आई० एन० सी० 1894 व प्रस्ताव I, हिंदू 11 जुलाई 1894 ट्रिग्नू, 18 जुलाई (आई० एन० बी० ओ० आई० 26 अगस्त 1894), बाधा रिप० आई० एन० सी० 1894 प० 32, मराठा 16 निस० 1894 ए० बी० पी०, 29 निस० 1894 हनु प्रकाश 24 निस० 1894, बगबाली 22 निसबर सजीवनी 22 निस०, दनिश औ समाचार चंद्रिका 24 निस० (आर० एन० पी० बग०, 29 निस० 1894) मद्रास स्टड्डे, 24 निस० 1894 ट्रिग्नू 26 दिसंबर 1894 (आई० एन० बी० ओ० आई० 13 जनवरी 1895) ज्ञान प्रकाश 27 निस० 1894 बिहार

- हेराल्ड 29 दिसंबर 1894 इंडियन मिरर 30 दिसंबर 1894 (वर्षी 20 जनवरी 1895)  
हिंदुस्तान 4 जनवरी (आर० एन० पी० एन० 9 जनवरी 1895), रजदर 8 जनवरी (वही  
16 जन० 1895) पना अग्रसार 26 जनवरी (आर० एन० पी० एन०, 9 फरवरी 1895),  
पी० ए० चारखू एन० पी० 1896 एड \\\ V प० 83-4 जोगा यूरोपत प० 91  
पार्लियामेण्ट, एडवोकेट 28 जनवरी (आई० एम० पी० ओ० आई० 22 मार्च 1896) समय  
31 जनवरी बंगलादेशी 1 फरवरी (आर० एन० पी० एन० 8 फरवरी 1896), कर्नाटक प्रचारिका  
3 फरवरी केरल परित्रा 8 फरवरी कागिभ उम अग्रसार 3 फरवरी (आर० एन० पी० एन०,  
15 फरवरी 1896) कुछ कर्तो क उग्रार आर० पी० एम० न युटि का विभागा मुम्बई क  
परिणामस्वरूप भारतीय वरत उद्योग का माग जागृत क परिणाम कर्तो क अग्रसार हा गया का  
(ई एच II प० 544) तथा दण्डि पही प० 1\ और उमका स्थापत्र II, प० 46 60  
127 1904 में घोषित ग भा द्वाभा प्रकार का मन अभिष्यार विद्या का दण्डि, स्थापत्र प० 77  
और "दिए धीराम एन० पी० पी० एड \\\ II प० 104-05 और इंडियन पत्र 19  
जनवरी 1905
- 77 वाचा रिप० आई० एन० पी० एन०—1894 प० 32 ए० पी० पी० 29 दिसंबर 1894 बंगला  
22 दिसंबर (आर० एन० पी० एन० 29 दिसंबर 1894) पान प्रचार 27 दिसंबर 1894  
विहार हेराल्ड 29 दिसंबर 1894 (आई० एम० पी० ओ० आई० 20 जनवरी 1895)
- 78 हिंदू 11 जुलाई 1894 टिम्पुन 18 जुलाई (आई० एम० पी० ओ० आई० 26 अगस्त 1894)  
वाचा रिप० आई० एन० पी० एन०—1894 प० 32 स्थापत्र प० 432 ए० एम० मुनासिपर वही  
प० 33 पना अग्रसार 26 जनवरी (आर० एन० पी० एन० 9 फरवरी 1895) पी० एन०  
आटे रिप० आई० एन० पी० एन०—1895 प० 160 पार मिहिर 3 फरवरी (आर० एन० पी०  
एन० 15 फरवरी 1896) दत्त स्थापत्र II प० 46 80 एम० एन० बनव्री पी० ए०  
प० 694
- 79 मराठा 26 जनवरी 1896 हिंदू 27 जन० 1896 इंडियन स्पेक्टर 26 जन० 1896  
बंगाली 1 फरवरी 1896 इंडियन नेशन 27 जनवरी एडवोकेट 28 जनवरी इंडियन मिरर  
30 जनवरी (आई० एम० पी० ओ० आई०, 22 मार्च 1896) विहार हेराल्ड 8 फरवरी  
(वही 5 अप्रैल 1896) 1 फरवरी को समाप्त होन काये सप्ताह क बर्द क प्राय सभी  
समाचारपत्र आर० एन० पी० एन० बर 1 फरवरी 1896 समय 31 जनवरी सजीवनी 1 फरवरी  
(आर० एन० पी० एन० 8 फरवरी 1896) कर्नाटक प्रचारिका 3 फरवरी और केरल परित्रा  
1 फरवरी (आर० एन० पी० एम० 15 फरवरी 1896) हिंदुस्तानी 29 जनवरी (आर०  
एन० पी० एन०, 5 फरवरी 1896) यूना सांस्कृतिक समा के अग्रसार का साद, पी० पी०  
(एच० आफ० पी०) सी 8078 आफ 1896 प० 171 बोरगाण जिला केर बर्द में हुई जन  
सभा द्वारा अभिव्यक्त विरोध वही प० 193 पी० ए० चारखू एन० पी० एन०—1896 एड  
XXXV प० 86 आई० एन० पी० एन०—1902 का प्रस्ताव XVI गोयल स्वाक्षेत्र प० 10 77
- 80 बंगाली 8 फरवरी 1896 समय 31 जनवरी सजीवनी 1 फरवरी दत्त 2 फरवरी (आर०  
एन० पी० एन० 8 फरवरी 1896) आर्यजनप्रियान 1 फर (आर० एन० पी० एम० 15  
फरवरी 1896) बर्द प्रेसोइसी एसोसिएशन के प्रधान का साद, पी० पी० (हाउस आफ  
कामस) 1896 सी 8078 प० 163 बर्द की जनसभा में पारित प्रस्ताव वही प० 166
- 81 वाचा रिप० आई० एन० पी० एन०—1894 प० 31 मराठा 16 दिसंबर 1894 दत्त की समाचार

- चंद्रिका, 19 निसबर (आर० एन० पी० बग० 22 दिसबर 1894) सजीवनी 22 दिसबर (वही, 29 दिसबर 1894 (आई० एस० बी० ओ० आई० 13 जनवरी 1895) ज्ञान प्रकाश 27 निस० 1804 बिहार हेराल्ड, 29 दिस० 1894 इंडियन मिरर 30 निस० 1894 (वही 20 जनवरी 1895) इस तथ्य पर विशेष बल नहीं दिया गया जसाकि वित्त सदस्य ने स्वयं सजिस्लटिव कौमिल में कहा 'हमने इससे मिलने वाले राजस्व के घतमान साधन के रूप में इसका प्रस्ताव नहीं किया है' (एल० सी० पी० 1894 खंड XXXIII प० 384) इसके अतिरिक्त भारतीय नेताओं को यह तथ्य स्वतः माक्षी के रूप में प्रतीत हुआ 1904 में वित्त सदस्य की इस टिप्पणी कि, आयात शुल्क से केवल 20% साधन रूपों के राजस्व को ही प्राप्ति होती है पर गोखले ने तिरस्कारस्पन्त कहा उत्तर दिया यदि मेरे माननीय मित्र सचमुच यह विश्वास करते हैं कि सीमा शुल्क इसलिए लगाए गए हैं कि इनसे राजस्व को आय होती है जिन्हें सरकार नहीं छोड़ सकती तो बदाचित्त भारत में अथवा इंग्लैंड में ऐसा सोचन जाने के अनेके व्यक्ति होंगे (स्पीचेज पृ० 78) तथा थाराम एल० सी० पी०—1903 खंड XLII पृ० 104-05
- 82 वाचा रिप० आई० एन० सी०—1902 पृ० 142 3
- 83 1904 में इस कल्पना को गोखले ने उस समय स्पष्ट अभिव्यक्ति दी जब उन्होंने दस्तापूर्वक स्वीकार किया कि अब इसमें कोई संदेह नहीं कि यह शुल्क वास्तव में ही उपभोक्ताओं द्वारा उपभोक्ताओं से अप्रिप्राय अधिकांश निघन समुदायों, द्वारा ही चुकाया जाता है (स्पीचेज पृ० 77) इससे पूर्व 1902 में उस समय के और भी अधिक सतक थे जब उन्होंने कहा था कि भारत का एक भाग घतत गरीबों के ऊपर ही पड़ता है (वही पृ० 10)
- 84 हिंदू 11 जुलाई 1894 ट्रिब्यून, 18 जुलाई (आई० एस० बी० ओ० आई० 26 अगस्त 1894) वाचा रिप० आई० एन० सी० 1894 पृ० 32 इंदु प्रकाश 31 दिसबर 1894 ट्रिब्यून 26 दिस० 1894 (आई० एस० बी० ओ० आई० 13 जन० 1895) ज्ञान प्रकाश 27 दिस० 1894 बिहार हेराल्ड 29 दिस० 1894, इंडियन मिरर 30 दिस० 1894 (वही 20 जन० 1895) वाचा स्पीचेज पृ० 430 और रिप० आई० एन० सी० 1895 पृ० 157 8 दत्त ई एच II पृ० 540 गोखले स्पीचेज पृ० 41 2
- 85 आई एन० सी०—1894 का प्रस्ताव I ए० एस० मधोलकर रिप० आई० एन० सी० 1894 पृ० 33 मराठा 16 निस० 1894 इंडियन स्केटेटर 30 दिस० 1894 हितवादी 28 निस० 1894 (आर० एन० पी० बग० 5 जनवरी 1895) केसर-ए हिंदू, 30 निसबर 1894 (आर० एन० पी० बग० 5 जनवरी 1895) ताज उल अखबार 5 जनवरी (आर० एन० पी० पी० 12 जनवरी 1895) पसा अखबार 26 जनवरी (वहाँ 9 फरवरी 1895)
- 86 एल० सी० पी० 1894 खंड XXXIII पृ० 402-03 420 450
- 87 आई० एन० सी० 1895 का प्रस्ताव XXI एन० एन० बनर्जी सी० पी० ए० पृ० 259 61 वाचा रिप० आई० एन० सी०—1895 पृ० 157 8 पी० ए० चारलू एल० सी० पी०—1896 खंड XXXV पृ० 80 82
- 88 वाचा रिप० आई० एन० सी०, 1895 पृ० 158 एन० एन० बनर्जी सी० पी० ए०, पृ० 295 पी० ए० चारलू पूर्वोक्त स्थल पृ० 80
- 89 उल्हासराय दैनिक औ समाचार चंद्रिका 5 फरवरी 1896 का श्रक में लिखा हमारे कुछ समकालीन इतने आशावादी हैं कि वे यह विश्वास सहज में ही कर लेते हैं कि यह विरोध भविष्य में फल लाएगा—अपनी सरकार को होंश में लाएगा वस्तुतः यह सोचना एक गलती

है कि अपना सरकार हाथ में लहा उम्मीद अपना अनुसर ब्रिटिश सरकार के पास इतनी अधिक अवसर (हाना) है कि यह उसे दूसरा को द गचना है वरु जानबूझकर संसदीयता का प्रयत्न करने के लिए भारत में प्रति बहा भारत अध्यापन कर रहा है परन्तु प्रश्न यह है कि सरकार कर हा क्या सक्ता है ? उम्मीद हा अध्यापन अनुसर संसदीयता का प्रयास ता कोई भा दन नहीं पर गचना (आर एन० पा० बण० 9 फरवरी 1896)

- 90 प्रस्ताव I तथा वाचा रिप० आई० एन० सी० 1894 पृ० 31 3 टी० ए० बालू एन० गा० पा० 1896 पृ० X\ \ V प० 81 मानवाय म्यान्ड पृ० 37 8 वाचा पूर्वोद्धत, प० 192 वाचन म्यान्ड पृ० 5 41 एन० एन० बन्धनों—गा० पा० ए० प० 674 दन ई एच II प० I\ 531 534 वाचन II, प० 121 वाच 65 और 68 मन्त्रों में उल्लिखित प्रायः सभी सम्पादन
- 91 पी० महता एसीजेस प० 390 इमी प्रारंभ बगवाणन अधिन 9 फरवरी 1896 के घर में किया भारतीयों का अब समझ जा गई है कि सरकार भारतीयों का उम उदात्त का विरोध करने का रक्ष है अध्यापन विरोध उन्नत हिता व भारतीयों का हिता व साथ टकराव का समाधान है के गणनापूर्वक संसद के अधिनियम भी नहीं देना (आर० एन० पा० बण० 15 फरवरी 1896)
- 92 गी० पी० ए० म प० 527
- 93 आर० एन० पा० एन० 15 जनवरी 1895 इमा प्रारंभ 30 मिनट 1874 के घर में अरगोन्स यह विचार प्रकट किया कि क्या अध्यापन शुल्क व अधिनियम का पारित करने सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि यह भारतीयों का विरोध और उनका समझ नहीं घटती (आर० एन० पा० बण० 5 जनवरी 1895) वस्तुतः अर्थ प्रम व बर्नई मन्त्रालय ने विद्या इस सप्ताह के अर्थ अर्थ भारतीयों सम्पादन ने कागज अर्थ विन व पाग होन पर बनना अस्वीकृति सरकार का भारत में औद्योगिक प्रवृत्ति के हिता व प्रति उम्मीदना स जमी अपने निज की महान और निराशा का प्रकट करने काता भावा प्रकट में की है (पृ०)
- 94 उम्मीदना 2 फरवरी 1896 के घर में एन० ने सरकार का चेतावना दी इम 9 फरवरी पारित के निरंतर अनुसरण से भारतीय जनता का ब्रिटिश शासन के 'याव और सन्ध्याई पर स विरोध उठने लगा है इमने पूर्व 1894 में रासबिहारी घोष शासकों को मजबूत कर चुके थे कि घनी कर के द्वारा छल-कपट करने से इनके की 'यावपूर्ण व्यवहार के लिए प्रतिनिधि, जो विना पी मुच पर एणीय और स्पर्धा योग्य है दाव पर है इन्के ने इनके दीपकाल में आज तक तीरो-तलवार से भी अधिक शक्ति को प्रभाव अपनी प्रजा पर दाता है जिसके कारण प्रजा इस विरोध साम्राज्य की बगवण है उस प्रभाव के विनष्ट होने का घनरा उत्पन्न हो गया है (स्पेशल, प० 152 3) केवल भारतीयों ने घाने की चेतावनी नहीं दी थी जनरल जी० बिस्मि ने भी बरगदर जोर दनर 1894 में अविष्यवाणी का था कि यदि समुचित पग उठाते में देर की गई तो भारत सरकार की सद्भावनाओं और चरित को एमी सति पट्टुकी क्रिके परिणाम भयकर हो सकत हैं और होय (पूर्वोद्धत पृ० 347) तथा देधिप पृ० 290 इसी प्रकार 1894 में बपास के अध्यापन पर शुल्क को छूट का विरोध करने वाले इन्डियन कौंसिल के छ सन्धियों में से एक सर ए० एरबुथनर ने अपने असहमति भाषण में चेतावनी दी ब्रिटिश राज्य व नाम से जाने जानि बाल जटिन मज के लिए यह निश्चित है कि भारत के हिता में और घट ब्रिटन के हितों में आवश्यक दृष्ट बघन हो ऐसा कोई पग नहीं उठाना चाहिए जिससे महिभामयो महाराणी की भारतीय प्रजा में अनोप उत्पन्न होना हा अध्यापन जिससे ब्रिटिश शासन पर उनके विरोध को

- धरका लगता हो ऐसा कोई भी पग राज्य के हित का विरोधी ही माना जाएगा (बकील पूर्वोद्धत, पृ० 427)
- 95 मूल याद में उद्धत लेखको के अतिरिक्त देखिए 'स्वदेशमित्रन, 21 दिसबर 1894 कर्णाटक प्रकाशिका 14 जनवरी 1895 (आर० एन० पी० एम० 15 जनवरी 1895) सजीवनी 22 दिस० (आर० एन० पी० बग० 29 दिस० 1894) बगाली 22 दिस० 1894 आर० एन० पी० एन०, 23 जनवरी 1895, ताज उल अखबार 5 जनवरी (आर० एन० पी० 12 जनवरी 1895), इंडियन स्पेक्टटर 26 जून 1896 समय 31 जनवरी, दक्षक, 2 फरवरी सजीवनी 1 फरवरी (आर० एन० पी० बग० 8 फरवरी 1896) बर्दई के लगभग सभी समाचारपत्र विशेषत नैटिव ओपीनियन 26 जनवरी इंदु प्रकाश 27 जनवरी और गुजराती 26 जनवरी (आर० एन० पी० बग, 1 फरवरी 1896), स्वदेशमित्रन 11 फरवरी (आर० एन० पी० एम० 29 फरवरी 1896), बगाली 8 फरवरी 1896 वाचा स्पीचेज, पृ० 431 दत्त स्पीचेज II पृ० 127 बांवे प्रेसीडेंसी एजोसिएशन का स्मरणपत्र पी० पी० (हाउस आफ बामस) 1896 सी 8078 पृ० 163 तथा वही पृ० 193
- 96 आर० एन० पी० बग 1 फरवरी 1896 दो सप्ताह बाद 11 फरवरी 1896 कं भ्रम म केसरी ने फिर लिखा गत सोमवार से पहले अनुचित कपास शुल्क स्वीकृत करके भारत सरकार ने सारे सप्ताह के सामने यह स्पष्ट कर लिया है कि वे इस दश के लोगों के हितों के लिए भारत पर शासन नहीं करते प्रत्युत इस शासन का उद्देश्य थोड़े से भ्रमरेज व्यापारियों के हितों की ही रक्षा करना है
- 97 एल० सी० पी०—1896 खंड XXXV पृ० 85
- 98 मालवीय स्पीचेज पृ० 34-5 तथा केसरी, 11 फरवरी (आर० एन० पी० बग 15 फरवरी 1896) दैनिक औ समाचार चंद्रिका (आर० एन० पी० बग० 8 फरवरी 1896) दत्त ई एच II पृ० 542 3
- 99 मालवीय स्पीचेज, पृ० 37 8
- 100 वही, पृ० 26 और वाचा रिप० आई० एन० सी० 1894 पृ० 33 दैनिक औ समाचार चंद्रिका ने 5 फरवरी 1896 के भ्रम म घोषणा की कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल लकाशायर का दास है और महा की सरकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल की दास है (आर० एन० पी० बग० 8 फरवरी 1896) अल्गोदय ने पहले ही 30 दिसबर 1894 के भ्रम म घोषणा की थी भावस्टर के उत्पादक ही हमारे असली शासक हैं और भारत राज्य सचिव का वचन हा असल में हमारे लिए बानून है (आर० एन० पी० बग 5 जनवरी 1895) इत परवर्ती दृष्टिकोण को भारत जीवन ने 10 फरवरी के भ्रम मे (आर० एन० पी० एन 12 फरवरी 1896) अखबार ए आम ने 14 फरवरी के भ्रम में (आर० एन० पी० पी 22 फरवरी 1896) और स्वदेशमित्रन ने 11 फरवरी के भ्रम म (आर० एन० पी० एम 29 फरवरी 1896) में प्रतिध्वनित किया
- 101 वाचा रिप० आई० एन० सी०—1894 पृ० 33 इंदु प्रकाश 31 दिसबर 1894 और सुबोध पत्रिका 30 दिसबर 1894 (आर० एन० पी० बग 5 जनवरी 1895)
- 102 आर० एन० पी० बग० 15 फरवरी 1896
- 103 दत्त इंडियन पालिटिकल पृ० 53 इसी प्रकार 3 फरवरी 1896 के भ्रम म कर्णाटक पत्रिका ने यह राय प्रकट की आवश्यकता यह है कि भारत में भारतीयों की ही सरकार हो लोगो की और अधिक विस्तृत कौंसिल को पाने की चेष्टा करनी चाहिए और साथ ही देखना चाहिए कि

वही पृ० 175

- 120 रानाड एनी कार प्राटबन पृ० 10 12 13
- 121 एन इडिया 11 मार्च 1899 ए० पी० 22 मार्च 1899, सिड् 18 मार्च 1899 इति  
 श्री समाचार पत्रिका 22 मार्च (आर० एन० पी० वग० 25 मार्च 1899) विभागी 24 मार्च  
 (वही 1 अप्रैल 1899) भारत जावन 27 मार्च (आर० एन० पी० एन०, 28 मार्च 1899)  
 सिड्मुना 14 अप्रैल (वही 19 अप्रैल 1899)
- 122 रानाड एनी कार प्राटबन पृ० 6
- 123 राय इडियन शहर इप्टोज पृ० 7 गुजरात 19 26 मार्च (आर० एन० पी० वग०  
 25 मार्च 1 अप्रैल 1899) प्रतिवागा 17 अप्रैल (आर० एन० पी० वग०, 22 अप्रैल 1899)
- 124 रानाडे एनी कार प्राटबन पृ० 3 ए० पी० 18 19 अप्रैल 1899 22 मार्च 1899 पी०  
 ए० चारनू एन० सी० पी० 1899 एड \\\VIII पृ० 176 समय 24 मार्च (आर०  
 एन० पी० वग० 1 अप्रैल 1899)
- 125 पी० ए० चारनू एन० सी० पी० 1899 एड \\\VIII पृ० 127 एन एन इति  
 31 मार्च 1899 सिड् 21 मार्च 1899 सिड्मुना 14 अप्रैल (आर० एन० पी० एन० 19 अप्रैल  
 1899) भारत जावन 1 मई (वही 3 मई 1899)
- 126 राय इडियन शहर इप्टोज पृ० 2-4 6-7 24 तथा गुजराती 19 मार्च (आर० एन० पी०  
 वग० 25 मार्च 1899) 14 मई (वही 20 मई 1899)
- 127 राय इडियन शहर इप्टोज पृ० 12
- 128 वही पृ० 22 3
- 129 1899 की पी० पी० (हाउस आफ कामन्स) एड-66 या 9287 अन्य वृत्त न इन समय का उद्  
 घाटन किया कि भारत सरकार न अपने सम्पत्ति म दक्षिणपूर्व स्वाकार विभा वि आयोजित  
 चीनी न सामाजिक दृष्टि से भारत के गंगा उत्पन्न का प्रभावित नहीं किया धन सरकार ने  
 चीनी पर मम करने वाले शुल्क को लगाने से इनकार कर दिया इनपर राज्य सचिव ने दो बार,  
 एक बार अपने 25 अगस्त 1898 के सम्पत्ति म और दूसरी बार 26 जनवरी 1899 के सम्पत्ति में  
 मारिशस के विस्तार से प्राप्त आवेदनपत्र भेजे जिनमें अनुष्टुट पोषित चीनी का विरुद्ध भारत में  
 सरकारी साधन वस्तुन की भाग की गई था साथ ही सचिव ने भारत सरकार पर बड़े शिष्ट हक  
 से दबाव डाला कि वह इस मांग को स्वीकार कर ले
- 130 ए० पी० 24 मार्च 1899 यह बहुत सीधे का दृष्टिकोण प्रतीत होता है यह दूसरी बात है  
 कि नेटिव प्रत के बहुत सारे सवादाताओं ने दुर्भाग्यवश इडियन प्रत का साप्ताहिक मार-रूपों  
 में इस दृष्टिकोण का उल्लेख को आवश्यक नहा समझा उनका मतव्य बदाचित यह था कि सर  
 कार की कायवाही के समय में ही उपयुक्त दृष्टिकोण समाविष्ट है सरकारी कायवाही के अथवा  
 विरोधी गुजराती ने अपने 14 मई 1899 का एक म भारतीय प्रेस म सरकारी इरादा का जिस  
 विश्वास का साथ वणन किया था उसका पूरा ही उल्लेख किया (आर० एन० पी० वग०  
 20 मई 1899) वाचा ने भी 1906 में इस धारणा पर अपने विचार प्रकृत किए (स्वीचेज  
 पृ० 173)
- 131 वाचा स्वीचेज पृ० 173 समय के 24 मार्च (आर० एन० पी० वग० अप्रैल 1899) का निम्न  
 लिखित अवतरण म यह भावना चित्रित है वाच वजन ने इस विल का पास करने के रूप में  
 भारतीय जनता का प्रति जो उच्चास्यता और सहानुभूति तथा इससे भी बड़कर कृतव्य परायणता

- का परिचय दिया है जगसे प्रत्येक भारतीय पर म उनके प्रति आदर की भावना दृढ़ होगी, और दक्षिण भारत जोनन 3 अप्रैल (आर० एन० पी० एन० 4 अप्रैल 1899)
132. गुजराती ने अपने 14 मई 1899 के पत्र में लिखा कि भारत सरकार और भारत मन्त्रि के बीच हुए सारे पत्र व्यवहार से स्पष्ट होता है कि कुमन चव्हरसेन (उपनिवेश राज्य मन्त्रि) ने अपने नवजी शस्त्रो से विजय प्राप्त की है और उसन सचमुच ही सारी भारतीय जनता क छोटे से बड़े तक सभी भ्यक्तिया को मूढ बनाया है (आर० एन० पी० वग 20 मई 1899)
133. ए० बी० पी०, 1 जून 1899 हिंदू 12 मई 1899 (हालांकि यह द्विविधायस्त था), ट्रिब्यून, 30 मई इंडियन मिरर 12 मई मद्रास स्टड्ड 11 मई (आई० एस० बी० ओ० आई० 21 मई 1899), सजीवनी, 11 मई (आर० एन० पी० वग० 20 मई 1899) सत्य विजय, 17 मई वेसरा 16 मई हितैष्ट 18 मई (आर० एन० पी० वग 20 मई 1899)
134. रानाडे प्लो फार प्रोटेक्शन, पृ० 2
135. एल० सी० पी०, 1901 खट XL पृ० 281 तथा दत्त ई एच II, पृ० 523
136. ए० बी० पी०, 20 मई 1899, इंडियन मिरर, 12 मई मद्रास स्टड्ड 11 मई (आई० एस० वा० आ० आई० 21 मई 1899)
137. ए० बी० पी० 20 मई और 1 जून 1899 हिंदू 21 मई 1899 मद्रास स्टड्ड 11 मई (आई० एस० बी० ओ० आई०, 21 मई 1899) एडवाकट 19 मई (वहा 28 मई 1899)
138. रानाडे प्लो फार प्रोटेक्शन पृ० 6
139. ए० बी० पी० 20 मई 1899
140. रानाडे प्लो फार प्रोटेक्शन पृ० 6
141. ए० बी० पी०, 20 मई 1899 सजीवनी, 11 मई (आर० एन० पी० वग० 20 मई 1899)
142. रानाडे प्लो फार प्रोटेक्शन पृ० 6
143. वही पृ० 17 21
144. देखिए आगे अध्याय 11
145. ज० एफ० फिनले एल० सी० पी० 1902 खट XLI प० 216 कजन स्पीचेज III पृ० 20, दत्त ई एच II, पृ० 523
146. लोवाट फ्रेजर पूर्वोद्धत प० 342 परिमल राय पूर्वोद्धत प० 84
147. कजन स्पीचेज III पृ० 5 तथा देखिए इपीरियल गजटियर आफ इंडिया (1908) खट III पृ० 288-90
148. पी० ए० चारलू एल० सी० पी० 1899 खट XXXVIII प० 134
149. वही पृ० 178 9 मराठा 26 मार्च 2 अप्रैल 1899 हिंदू 18 21 मार्च 12 मई 1899 वयाली 18 मार्च 1899 इंडियन मिरर 23 मार्च (आई० एस० बी० ओ० आई०, 2 अप्रैल 1899) सत्य विजय, 17 मई (आर० एन० पी० वग 20 मई 1899), वगबासी 25 मार्च 1 अप्रैल (आर० एन० पी० वग० 1 8 अप्रैल 1899) उडिया और नवसवाद 29 मार्च (वही 17 जून 1899) 21 अप्रैल 1902 के 'यू इंडिया में विपिनचंद्र पाल ने स्पष्टता स स्वीकार किया कि उन्होंने 1899 में यह जानते हुए कि यह चानी आयात शुल्क भारतीयों के हितों में न होकर ब्रिटिश पूंजीपतियों और मारिशस के हितों के लिए ही सुरक्षापरक है उसका समयन इसलिए किया था कि इसे मने एक नए सिद्धांत के रूप में देखा था, यह सवे-गले स्वतंत्र व्यापार के सिद्धांत में स्वस्थ निवतन था भारत सरकार के मन में भी इसे लागू करते समय यही भावना



काम कर रही थी जेम्स बेस्टमन ने घोषित किया था मैं अपनी राज कर्तव्य में एक मरणा नए अध्याय का उद्घाटन करने जा रहा हूँ (एस० गा० पी० 1899 ग्रंथ XXV VIII पृ० 124) इस विल का गमका करते हुए गांधी ब्रजन औद्योगिक का स रिटर्न का मीटिंग विव आवश्यकताओं के मन्त्र में मरणा गिद्धाति का शान्तिर ईग स पचाव करा हुए प्रत्य होने हैं (स्पीचज | पृ० 63-4)

- 150 रानाड का प्ला पार प्रोटक्टा में बी० जी० बाने की घूमिका पृ० IV और V
- 151 जे० एन० विन्से एम० गा० पी० 1902 ग्रंथ XLI पृ० 215-7 ब्रजन सावत्र III प० 12
- 152 ब्रजन एपीवेज III पृ० 6
- 153 ए० बी० पी० 25 26 अप्रैल 1902 यू इटिया 21 अप्रैल 12 जून 1902 मरणा 15 जून 1902 कसर ए हिं 1 जून बगरा 3 जून इंदु प्रयाग 2 जून (आर० एन० पी० बग 7 जून 1902) वायन आफ इटिया 21 जून 1902 प्रतिवाता 26 मई (आर० एन० पी० बग०, 31 मई 1902) हितवाता 30 मई (बहा 7 जून 1902) सजावता 12 जून इडियन मिरर 8 जून (बही 21 जून 1902) पावर ऐंड एडियन 1 जून (बी० ओ० आई० 28 जून 1902)
- 154 यू इटिया 12 जून 1902 कसर ए हिंद (आर० एन० पी० बग 14 जून 1902) प्रतिवाता 26 मई (आर एन० पी० बग० 31 मई 1902) हितवाता 30 मई (बहा 7 जून 1902)
- 155 14 जून (आर० एन० पी० बग० 21 जून 1902) डिम्पूर न भी 27 मई 1902 क घर म विन का विरोध करने स इनवार कर टिया (बी० ओ० आई०, 28 जून 1902)
- 156 मराठा 25 मई 8 जून 1902 ए० वा० पी० 21 अप्रैल 1902 बेगरा 3 जून इंदु प्रयाग 2 जन (आर० एन० पी० बग 7 जून 1902) गाव ही बेगता ने अपन पाठ्यां की पनापता दी वि 'माचेस्टर के लिए भारतीय चीनी उद्योग को पग बनान वाली सरकार से भारतीय उद्योग के प्रोत्साहन का आशा करना समुद्र क धारे पानी से पाना निवासन की चपटा करना है
- 157 यू इटिया 21 अप्रैल 1902 सजीवनी 12 जून (आर० एन० पी० बग० 21 जून 1902)
- 158 स्ट्रुची इटिया (1903) पृ० 182
- 159 बगाली 4 फरवरी 1888 इडियन मिरर 3 फरवरी गुजरात मिर 5 फरवरी इंदु प्रयाग 5 फरवरी (बी० ओ० आई० माच 1888) धांचे समाचार 11 फरवरी गुजरात ग्रंट 9 फरवरी रास्त गुफार 5 फरवरी तथा अय अनेक समाचारपत्र (आर० एन० पी० बग 11 फरवरी 1888) समय 3 फरवरी (आर० एन० पी० बग० 11 फरवरी 1888) हिंदुस्तान 12 फरवरी यत्पारा 9 फरवरी (आर० एन० पी० पी० एन० 14 फरवरी 1888) पूना सावजनिक समा का स्मरणपत्र दिनांक 6 माच 1894 जे० पी० एस० एन० ग्रंथ XVI स० 4 (अप्रैल 1894) प० 137 इडियन एनोसिएशन का स्मरणपत्र दिनांक 8 मार्च 1894 रिपोर्ट आफ इडियन एनोसिएशन फार 1892 3 टू 1895-6 प० 43 सुधाम स जिस्तटिव कौंसिल को बर्ब प्रसिद्धि की का विरोध पी० पी० (हाउस आफ कामस) 1895 परचा 202 इंदु प्रयाग 12 माच 1894 इडियन स्टेडेटर 11 माच 1894 कसर ए हिं 4 माच मान प्रकाश 5 माच सुधारक 5 माच गुजराती 4 माच (आर० एन० पी० बग 10 माच 1894) आजाद 9 माच (आर० एन० पी० एम० 14 माच 1894) कर्णटिक प्रकाशिका 12 मार्च (आर० एन० पी० एम० 15 माच 1894) स्वदेशमित्र 16 माच मनोरमा 19 माच केरल पत्रिका 17 माच, खासिम उन्न अचवार 15 माच (बही 31 माच 1894) जी० आर० एम० चितनवीस एन०





## मुद्रा और विनिमय

भारत में लोकमत निर्णायक उपायो को बनाने के लिए सवधा परिपक्व है और चादी के सिक्का की ढलाई पर रोक को सामान्यतया स्वीकृति ही मिलेगी।

—भारत सरकार का 1892 में सन्देश

इंग्लैंड के निधनों की वचतो को इस प्रकार प्रभावित करने वाले किसी सुभाव पर एक क्षण के लिए भी विचार नहीं किया जाएगा। यह अनुमान भी लगाया जा सकता है कि यदि ऐसी योजना यूरोप के इटली जैसे निधन देश में लागू की जाती तो वहाँ प्रायद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक जनता में विद्रोह भड़क उठता।

—भार ती ६९

समीक्षाधीन अवधि में भारत सरकार की अर्थनीति में मबधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण मत-भेद वाला विषय या 'मुद्रा परिवर्तन'। 1893 में चादी के सिक्को की टुकसाल बंद हान तथा सिक्को की खुली ढलाई करने पर यह विषय अस्तित्व में आया था। आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास में निदमतापूर्वक अनावश्यक रूप से मुद्रा और विनिमय को परम्परा मचढ़ कर दिया गया। वस्तुतः मुद्रा मन्धी परिवर्तन रूप में मुद्रापरक वाय सपन्न करने में किसी प्रकार की असफलता अपयोज्यता अथवा व्यथता से प्रभावित नहीं था, प्रत्युत इसका कारण पौड-मटलिग के सदम में उसने विनिमय मूल्य में आमा दृआ ह्रास था। भारत सरकार ने केवल इसी एक राय का उपचार करने की चेष्टा की, उसने देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था पर मुद्रा परिवर्तनो के मभावित प्रभावों की पूण रूप में उपक्षा ही कर दी।

मुद्रा अपने आप में मच्चमुच एक व्यापक विषय है, इतना अधिन व्यापक कि उसका समग्र विवेचन समभव ही नहीं। विनिमय भी एक विषय विषय है। सौभाग्य में हमारा सबध यहाँ इन दानो विषयो की समग्रता में नहीं है। हमारा सबध तो देश के विन्ग व्यापार, उद्योग वित्त और समाज बन्ध्याण पर भारतीय मुद्रा और विनिमय के परिवर्तन में उत्पन्न प्रभाव से है। यह प्रभाव ही भारत सरकार और राष्ट्रीय नेताओं के बीच मत-

## 240 भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास

नेटिव ओपीनियन 3 जून इन्डियन नेशन 4 जून, ट्रिम्बून, 6 जून मद्रास मैन, 11 जून (बं०  
जी० आर्द०, बुनार्द 1888) गुजरात द्यन, 21 अप्रैल, बिहार हेराल्ड, 27 अप्रैल पुरुषोत्तम  
28 अप्रैल ददु प्रकाश 29 अप्रैल, ट्रिम्बून 15 मई (बा० ओ० आर्द० जून 1889)

167 मराठा 23 जनवरी 1884, वाचा रिप० आर्द० एन० मा० 1889 पृ० 56

168 मराठा 13 जनवरी 1884 रिप० आर्द० एन० मा० 1889 पृ० 56. आर्द० एन० सी० 1889  
या प्रस्ताव VIII

## मुद्रा और विनिमय

भारत में लोकमत निर्णायक उपायों को अपनाने के लिए सवथा परिपक्व है और चादी के सिक्कों की ढलाई पर रोक को सामान्यतया स्वीकृति ही मिलेगी।

—भारत सरकार का 1892 में सप्रेषण

इंग्लड के निधनों की बचतों को इस प्रकार प्रभावित करने वाले किसी सुभाष पर एक क्षण के लिए भी विचार नहीं किया जाएगा। यह अनुमान भी लगाया जा सकता है कि यदि ऐसी योजना यूरोप के इटली जैसे निधन देश में लागू की जाती तो वहाँ प्रायद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक जनता में विद्रोह भडक उठता।

—आर सी दत्त

समीक्षाधीन अवधि में भारत सरकार की अर्थनीति से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण मत-भेद वाला विषय था 'मुद्रा परिवर्तन'। 1893 में चादी के सिक्कों की टक्काल बद होने तथा सिक्कों की खुली ढलाई करने पर यह विषय अस्तित्व में आया था। आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास में निश्चयतापूर्वक अनावश्यक रूप से मुद्रा और विनिमय को परस्पर संबद्ध कर दिया गया। वस्तुतः मुद्रा संबंधी परिवर्तन रूपों के मुद्रापरक बाय सपन करने में किसी प्रकार की असफलता अपयाप्तता अथवा व्यथता से प्रभावित नहीं था, प्रत्युत इसका कारण पौंड-स्टर्लिंग के सदम में उसके विनिमय मूल्य में आया हुआ ह्रास था। भारत सरकार ने केवल इसी एक राग का उपचार करने की चेष्टा की, उसने देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था पर मुद्रा परिवर्तनों से सभावित प्रभावों की पूर्ण रूप से उपेक्षा ही कर दी।

मुद्रा अपने आप में मधुमूत्र एक व्यापक विषय है, इतना अधिक व्यापक कि उसका समग्र विवेचन संभव ही नहीं। विनिमय भी एक विषय विषय है। सामान्य में हमारा समग्र यहाँ इन दोनों विषयों की समग्रता से नहीं है। हमारा संबंध तो देश के विदेश व्यापार, उद्योग, वित्त और समाज कल्याण पर भारतीय मुद्रा और विनिमय के परिवर्तन से उत्पन्न प्रभाव से है। यह प्रभाव ही भारत सरकार और राष्ट्रीय नेताओं के बीच मत-

भेद का विषय बन गया और इसी ही भारतीय समाज के नेताओं में प्रारंभ राष्ट्र मानना तथा विद्रोही प्रवृत्ति का जन्म दिया। पश्चात् इस अध्याय में हमारी चर्चा का विषय दो परस्पर संबंधित विषयों मुद्रा और विनिमय के इस विषय प्रभाव तब ही सीमित है।

### सरकारी मुद्रा नीति

19वीं शताब्दी के अन्तिम चरण की अवधि में भारत सरकार की मुद्रा नीति का उद्भव और विस्तृत विवेक 1893 की इन्डियन कॉर्पोरेशन बिलों के प्रतिवेदन में, 1898 की इन्डियन कॉर्पोरेशन बिलों के प्रतिवेदन में तथा इन विषयों पर निर्मित अन्य अनेक श्रेष्ठ प्रयासों में किया गया है। अतः यहाँ समीक्षाधीन अवधि में भारतीय मुद्रा और विनिमय के क्षेत्र में पश्चिम घटनाओं और परिवर्तनों का अत्यंत संक्षिप्त विवरण देना ही पर्याप्त होगा।

1835 के 17वें अधिनियम में अनुसार भारतीय मुद्रा का रजत मान पर रखा गया और 1870 के सिक्का दलार्ड अधिनियम के अनुसार गवर्नर को यह आदेश दिया गया कि विनिमय के निजी व्यापार में चांदी की धातु के विनिमय में ही रूपाय बनाए। इनमें भारतीय मुद्रा का स्वाभाविकता प्रदान की। दूसरे शब्दों में रुपये का मूल्य व्यापार में चांदी के मूल्य के सदृश ही और उसका विनिमय मूल्य स्वयं मान माने देना ही चांदी से उपलब्ध होने वाले स्वर्ण के सदृश ही निर्धारित किया जाता था। चांदी का मूल्य 1873 तक व्यापारिक रूप से स्थिर ही रहा जब तक कि अर्थव्यवस्था में रुपये का मूल्य भी 2 शिलिंग के आसपास ही स्थिर रहा। परन्तु 1873 में जब सारे विश्व में कुछ कारणों से, जिनमें सबसे अधिक भारत में नहीं, अतः उनकी पूर्ण चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, चांदी में प्राप्त होने वाले सान के मूल्य में ह्रास आना लगा तो स्थिति में भारी परिवर्तन का आना स्वाभाविक ही था। इसके फलस्वरूप जिस रूप में चांदी के विनिमय के लिए स्वतंत्रता सौंपा जाता था, स्वर्ण पर आधित मुद्राओं के सदृश में उम चांदी के रूप में मूल्य में ह्रास आने लगा। दूसरे शब्दों में स्वर्ण मान वाले देशों के साथ भारत का विनिमय (इंग्लैंड उम समय स्वर्ण मान वाला देश था) गिरने लगा। इस प्रकार जहाँ 1873 में भारतीय रूपय का मूल्य लगभग 2 शिलिंग था, वहाँ उसका विनिमय मूल्य 1893-94 में 14-54 पैसे रह गया।

भारतीय विनिमय के ऐतिहासिक पतन को अनेक कारणों से समझें प्रहार सहन करने पड़े। सबसे प्रथम भारतीय विदेश व्यापार विशेषतः आयात व्यापार को बुरी तरह से बाधित और पीड़ित करने के लिए इसकी भूमना की गई। विदेश व्यापार में सतत व्यापारियों ने अनुभव किया कि रुपये के स्टैबिलिटी मूल्य को लग रहे भयंकर भटके इंग्लैंड और भारत के व्यापार संबंधों पर विशेष हानिकारक प्रभाव डाल रहे थे। इसके अनिश्चितता उनकी शिवायत यह थी कि विनिमय की अनिश्चितता ने विदेश व्यापार को जोए और सट्टेबाजी का स्वरूप प्रदान कर दिया था। पतनशील विनिमय के विरुद्ध दूसरा अभियोग भारत सरकार द्वारा नियुक्त अगरेज सिविल और मिनिस्ट्री अपसर ने लगाया और बाद में उन्होंने उस अभियोग का सुदृढ़ता से उभारा। उनकी शिवायत यह थी कि उन्हें वेतन तो मिलता है रूपों में जबकि उन्हें अपने वेतन का एक बहुत बड़ा भाग अपने परिवार के पालन-पोषण के लिए बच्चा की शिक्षा के लिए स्टैबिलिटी के रूप में व्यय करना

होता है। इससे उहे अवाछित हानि होती है और क्लेशदायक आर्थिक क्षति उठानी पडती है। इसका कारण यह था कि उहे उसी सख्या मे विनिमय मे पौड लेने के लिए अपेक्षाकृत अधिक सख्या मे रुपये अपने घरों को भेजने पडते थे।<sup>3</sup> रुपये के स्टर्लिंग मूल्य मे गिरावट के साथ एक प्रधान पाप यह जुड गया कि इससे ब्रिटिश पूजी का भारत मे प्रवाह निरुत्साहित और मदगति हो गया। पूजी के व्याज और लाभ के साथ साथ रकम पूजी के स्वर्ण मूल्य के ह्रास अथवा कम से कम अनिश्चितता न इस प्रवाह को विलंबित कर दिया। यह घोषित किया गया कि ब्रिटिश पूजी के अतः प्रवाह पर इस प्रतिबन्ध ने, विशेष रूप से देश मे त्वरित आवश्यकता वाले प्रतिबन्ध ने रेलों के विस्तार मे बाधा पहुंचाई।<sup>4</sup>

गिरते विनिमय से सबधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपत्ति भारत सरकार की थी, जिसके वित्त सचमुच ही इसके कारण विपन्न हो गए थे। इस सबध मे भारत सरकार की स्थिति सवथा बिचिन थी। जहा सरकार राजस्व की वसूली चादी के रुपया मे करती थी, वहा उसे अपने गृह व्यय का इंग्लड मे भुगतान सोने मे करना पडता था। 1873-98 की अवधि मे चादी की स्वर्ण क्रय शक्ति अबाध रूप से घटती गई। भारत सरकार को अपने स्टर्लिंग दायित्व के भुगतान के लिए प्रतिवप अधिक से अधिक सख्या मे रुपये चुकाने पडे। अधिक शोचनीय बात यह हुई कि दायित्व और अधिक बढ़ते गए। इस प्रकार विनिमय से भयकर घाटा हुआ। दूसरे शब्दों मे भारत सरकार को किसी भी वप विशेष मे जितने रुपया का भुगतान करना पडा और विनिमय की दर के सुविधाजनक रूप से 2 शिलिंग प्रति रुपया रहने पर जितने रुपयों का भुगतान करना पडता, उन दोनों के मध्य का अंतर भारत सरकार को विनिमय से होने वाला घाटा ही था। उदाहरणार्थ, 1894-5 मे गृह प्रभारों के भुगतान के लिए 1577 करोड स्टर्लिंग पौड के बदले 289 करोड रुपये चुकाने पडे। यदि विनिमय दर 1872-3 वाली ही बनी रहती, तो स्टर्लिंग पौड की उमी राशि के विनिमय के लिए 166 करोड रुपये चुकाने पडते। इस प्रकार 123 करोड रुपये के अंतरवाली राशि को विनिमय से होने वाला घाटा ही कहा जाएगा। स्थिति की गभीरता का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि उस वप घाटे की रकम भारत सरकार द्वारा उगाहे गए कुल भू राजस्व के आधे भाग से भी अधिक थी।<sup>5</sup>

विनिमय मे गिरावट से 1875-98 की अवधि मे होने वाला घाटा 154 करोड रुपये के लगभग था। 1894 मे घाटे की राशि चरम शिखर पर पहुंच गई।<sup>6</sup> इस घाटे की पूर्ति के लिए सरकार को प्रतिवप छटनी तक का सहारा लेना पडा। प्रथम साधन तो अव्यावहारिक सिद्ध हुआ। वस्तुतः इस अवधि मे सरकार का खर्च उल्लेखनीय गति से बढ़ता गया। इस प्रकार से सरकार को व्यापक रूप से अलोकप्रिय साधनों अथवा करो, नमक कर, आय कर भू राजस्व मे वृद्धि का सहारा लेने पर विवश हाना पडा। परंतु भारत जैसे निधन कृषिप्रधान देश मे करो मे वृद्धि का क्षेत्र भी स्पष्ट रूप से सीमित था। किसानों पर किसी प्रकार के अनुचित करभार के साथ अत्यंत गभीर स्थिति का राजनीतिक खतरा भी जुडा हुआ था। विशेषतः इसका भय यह था कि इसे देश पर अधिकार जमाने वाले विदेशी शासन का दुष्परिणाम समझा जाएगा और माना जाएगा कि वह देश के बाहर बड़े हुए खर्च की पूर्ति के लिए ही यह सब कुछ कर रहा है।<sup>7</sup>



इसके अतिरिक्त विनिमय में अचानक उत्तार-चढ़ाव का परिणाम यह हुआ कि भारत सरकार को बहुत बड़ी सीमा में विनीय अतिस्थितता और कठिनाई का सामना करना पड़ा। उसका वित्तीय हिंसाचर और व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई और उसका बजट 'विनिमय की दृष्टि में एक जुगा मरीगा' सिद्ध हुआ।<sup>9</sup> इस प्रकार रुपये के स्वण मूल्य में गिरावट में लगभग शताब्दी के एक चरण (चतुर्थांश) तक भारतीय धातुकारों की नींद हरा गई। वे अत्यंत व्याकुल होकर बजट के अनुदान के लिए उपाय और माघन ढूँढने लगे। उनसे विचार में सरकार के सामने दो ही माग थे या तो वह विनिमय में गिरावट को राखे अथवा अनिश्चित करो का अनावश्यक माग प्रणय कर। उनकी निश्चित धारणा थी कि इन दो मागों को छोड़कर कोई अन्य माग नहीं था।<sup>10</sup>

निराश होकर भारत सरकार ने विनिमय में गिरावट रोकने के लिए उपयोगी माघना की खोज प्रारंभ की। वया तक यह अंतरराष्ट्रीय दा धातुओवाले इकरारनाम पर भारी आशा मजोए रही। भारत सरकार का विचार था कि यह सोन और चादी का सापण मूल्य निर्धारित करेगा परंतु जब इस इकरारनाम का उपमहाग हात हात मारी आघाए टूट गई, 1892 के धुमेलस सम्मेलन की अमपन्नता नवीनतम अमपन्नता थी—तब सरकार अपने मुद्रा मान को चादी के स्थान पर सोन पर आधारित करने की योजना पर विचार करने लगी। इस योजना का अपनाने के लिए व्यापारीवग न भी, जो वाणिज्य मंडल और नवनिर्मित भारतीय मुद्रा समिति के रूप में मगठित था, इस समय सरकार पर दवाव डाला।<sup>10</sup> सारे के सारे मुद्रा संबंधी प्रश्न का तथा भारत सरकार की योजना का उस समय लाड चामलर लाड हरशल की अध्यक्षता में बनी समिति को सौंप दिया गया। इस समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप भारत सरकार ने 26 जून 1893 का 1893 के अधिनियम सं० 8 को लागू किया, इससे अनुमार निजी खात में चादी के अप्रतिवाधित सिक्का को ढालन वाली टकमाल का बंद कर दिया। सरकार ने यह अधिसूचना जारी की जिससे अतगत रुपये का मूल्य 1 शिलिंग 4 पेंस निर्धारित किया गया और कहा गया कि इसी दर पर सरकारी करो के भुगतान के लिए जनता से सोने के सिक्के, चादी के सिक्के, पौंड और आधे पौंड लिए जाएंगे तथा विनिमय में रुपया अथवा नोटा की आपूर्ति की जाएगी। ये सारे उपाय देश में स्वण मान को अपरिहाय रूप में लागू करने के पथ में प्रथम पग ही थे।

1893 की नायवाही का मुख्य उद्देश्य रुपये की प्रचलित मात्रा को घटाकर उसके स्वण मूल्य को 1 शिलिंग 4 पेंस तक बढ़ाना था। इस प्रकार रुपया चादी से विच्छिन हो गया तथा उसमें निहित चाँदी के मूल्य से उसका मूल्य बढ गया। यह रुपय का प्राङ्गिक और यथाय स्थिति को छोड कर एक नकली और बडे मूल्यवाली स्थिति को ग्रहण करता था। इसका परिणाम यह निकला कि रुपये की क्रयशक्ति बढ गई अथवा दूसरे शब्दा में आतर्गिक मुद्रा के सवुचन के फलस्वरूप आतर्गिक कीमतें गिर गईं।

संक्रमण काल की अवधि, जिसमें रुपय का मूल्य और अधिक गिरता गया और 1894 में यह 4 शिलिंग 3 पेंस तक पहुच गया, वे पश्चान सरकार की मुद्रानीति को वाछित उद्देश्यों में सफलता मिली और रुपये का मूल्य धीरे धीरे बढने लगा। यहा तक कि जब 1898-9 की अवधि में चादी का मूल्य घट रहा था, रुपये का मूल्य 1 शिलिंग 4 पेंस के

लगभग था। इस समय भारत सरकार ने मोचा कि 1893 की नीति के तर्कों पर आधारित निष्पक्ष निकायने का उपयुक्त समय आ गया है। अतः सारे प्रश्न पर विचार के लिए उसने सर हेनरी फाउलर की अध्यक्षता में एक अद्य समिति की नियुक्ति की। समिति ने स्वर्ण मुद्रा के साथ स्वर्णमान की स्थापना की सिफारिश की तथा आवश्यक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अद्य अनेक उपाय सुभाए। फरवरी 1899 में (अधिनियम सं० XXII द्वारा) रुपये का मूल्य 1 शिलिंग 4 पेंस निर्दिष्ट किया गया और इस समय इसी दर पर अशरफी और आधी अशरफी के सिक्कों को भी बानूनी सिक्के की भाव्यता दे दी गई। अतः रुपया नाममात्र का सिक्का बन गया हालांकि यह असीमित सरकारी सिक्का बना रहा। भारतीय मुद्रा के क्षेत्र में इस परिवर्तन का हमारा कोई संबंध नहीं अतः हम इस विवरण को यहीं समाप्त करते हैं। इस संबंध में केवल दो रोचक बातों का उल्लेख आवश्यक समझते हैं। प्रथम, भारत में जो घयाय में छाया रहा, वह स्वर्ण मुद्रा के साथ स्वर्णमान नहीं था प्रत्युत उसे 'स्वर्ण विनिमय मान' ही कहा जाता है।<sup>11</sup> द्वितीय, भारत के वित्तीय इतिहास में विनिमय की स्थिरता के तथा लाभ बजट के नए युग का प्रारंभ होने लगा था परंतु यह न तो टक्काल बढ़ हान का परिणाम था और न रुपये की अत्यधिकता की सापेक्ष निवृत्ति का। वस्तुतः रुपये का टक्कन तो थोड़े ही समय के बाद उल्लेखनीय परिमाण में होने लगा था।<sup>12</sup> तभी तो जे० एम० बॉम ने टिप्पणी की कि सरकार उद्वेगजनक वेग से सिक्के बनाने में जुटी है।<sup>13</sup> और भारतीय नेता शीघ्र ही रुपये की बहुलता की शिकायत करने लगे हैं।<sup>14</sup> सत्य यह था कि रुपये का स्वर्ण मूल्य स्थिर बना रहा और यह सब एकांततः प्रशासनिक उपायों का परिणाम था और इन उपायों को सरकार ने किसी विवशता अथवा अनिवायता के कारण नहीं अपनाया था।<sup>15</sup>

### भारतीय नेतृत्व की प्रारंभिक प्रतिक्रिया

रुपये के निरंतर गिरते स्वर्णमूल्य से उत्पन्न समस्याओं के प्रति भारतीय राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया में निरंतरता नहीं थी और उसकी अभिव्यक्ति और मद्दगति से हुई। बहुत से राष्ट्रवादी नेताओं ने विनिमय में गिरावट की आलोचना की और इसे भारी दुर्भाग्य बताया, विशेषतः इसलिए क्योंकि विनिमय में होने वाले घाटे के फलस्वरूप नए कर लगाए गए थे।<sup>16</sup> यह बात अवश्य है कि बहुत सारे नेता तो बहुत समय तक इस प्रश्न की समग्र जटिलता को ही न समझ पाए और न ही उसका विस्तृत विश्लेषण कर पाए। हा, इस सामान्य तर्क के कुछ एक राष्ट्रवादी अपवाद भी थे।<sup>17</sup> परिवर्तन आलोचकों के दृष्टिकोण के साथ इन अपवाद वाले नेताओं के दृष्टिकोण को संक्षिप्त रूप से ही प्रस्तुत किया गया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये नेता अपने युग से आगे बढ़े हुए ही थे। परंतु प्रारंभिक वर्षों में, 1892 तक की इस विषय की गतिविधि को संक्षेप में कहना चाहें तो यही कहा जा सकता है कि अधिकांश भारतीय नेताओं की अत्यंत अस्पष्ट टिप्पणियां केवल निम्नलिखित सुझाव देने तक ही सीमित रही (क) यह प्रभारों में बंटौती,<sup>18</sup> (ख) स्वर्ण दायित्व का रजत दायित्व में रूपांतरण,<sup>19</sup> (ग) अंतर्राष्ट्रीय द्विघातु प्रणाली का अपनाना।<sup>20</sup> थोड़े से नेताओं ने तो यहाँ तक भी सुझाव दिया कि मोने की

मुद्रा जारी की जाए।<sup>1</sup> और निजी मटटराजों के लिए म्यन्त्र टक्का बढ़ कर दता चाहिए।” जस्टिस रागाडे 7 व्यावहारिक नीति की बकालत की और घोषणा की कि मुद्रा में हेरफेर का विरोध इतने विश्वासपात मानकर किया जाए ज्यार्नि इगमे चादी के मूल्य का ह्रास और विनिमय दर में वृद्धि होती है।<sup>2</sup>

### राष्ट्रवादिया द्वारा मुद्रा परिवर्तन का विरोध

1892 के आम पाम जत्र ब्रिटिश व्यापारिया और अधिकागिया न आदालतन जारी कर मुद्रा और विनियम के प्रदन को अपने समय का ज्वलत प्रदन बना लिया ता उसके मबध में भारतीय नेताओ की उत्सासीता भी जाती रही। भारतीय नेताओ ने इसके पूर मट्टर को स्वीकार किया। इसकी पुष्टि 1892 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पूव भारतीय राष्ट्रीयतावाद के मुख्य प्रवक्ता डी० ई० वाचा की उम विषय पर जिसे 'उनका अपना विषय कहा जा सकता है' निम्नाक्त मुद्द स्वीकृति में होती है 'हमारे जम विगिष्ट स्थितिवाले देश का निवट भविष्य में आधिया उद्धार पूररूप से मुद्रा प्रदन के तही समाधान में ही निहित है।'<sup>3</sup>

इस स्थिति में भारतीय नेताओ न रुपये के नीचे तथा घटते हुए स्वण मूल्य के बचाव और सघप का दृष्टिकोण ही अपनाया। यहा तब कि वे 1893 और 1899 क मुद्रा अधिनियम पारित हो जाने के बाद भी निम्न विनिमय की प्रणमा करत रहे और उसके लिए दवाव डालत रहू। वस्तुत मुद्रा प्रदन पर 1893 के मुद्रा अधिनियम अपना लिए जाने के पहले और बाद में वर्षों तब राष्ट्रीय नीति की उल्लेखनीय निरतरता के कारण इस पुस्तक में इस विषय का एव पृथक् विषय के रूप में ही एक ही स्थान पर समग्र विवेचन किया गया है।

राष्ट्रीय दृष्टिकोण का प्रारम्भिक पक्ष यह विश्वास था कि इस विषय का केंद्र विनिमय की स्थिरता न होकर सोने से विनियमित होने वाल रुपय का अनुपात था। भारतीय नेताओं का विचार था कि विनिमय की ऊंची दर की बकालत करने वाले विविध पक्ष अपने स्वार्थों के कारण ही ऐसा करते थे। सरकार विनिमय में गिरावट के फलस्वरूप स्टर्लिंग के भुगतान में होने वाले घाटे की उपेक्षा करना चाहती थी ताकि सरकारी कमचारी इगड में अपनी अधिकाधिक धनराशि भेज सकें और यूरोपीय सामान के आयातकर्ता आयात कर सकें, अथवा उन्हें भारतीय उत्पादनों में प्रतियागिता के लिए बाध्य किया जा रहा था और इस प्रकार उन्हें उपेक्षाकृत कम मात्रा में लाभ अजन करने के लिए विवश होना पड रहा था। इन्ही कारणों से ये लाग स्वाथपूण तथा निरथक आंदोलन चला रहे थे।<sup>4</sup> भारतीय नेताओ ने दृढ़तापूर्वक कहा कि देश के हितों के माय विदेशी व्यापारिया, विदेशी पूजी और विदेशी कमचारियों के हितों को न तो रखा जाना चाहिए और न ही रखा जा सकता है। भारत के मबध में यद्यपि इस देश की जाता के और इस देश की सरकार के हित परम्पर मबधित नहीं हैं परंतु संक्षेपत वाछनीय यह है कि भारतीय जनता के हितों को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए और इस प्रदन पर किसी भी प्रकार से विचार करत समय भारतीयों के हितों को ही प्रामाणिक कसौटी मानना चाहिए।<sup>5</sup> राष्ट्रवादी नेताओ

ने इसी सिद्धांत को व्यवहार में लाते हुए रुपये की वृत्रिम मूल्यवृद्धि करने के लिए रजत मान का परित्याग करके टक्कालो को बढ़ करने तथा स्वणमान को अपनाने के लिए इंडियन बैंसी एसोसिएशन द्वारा संचालित तथा भारत सरकार द्वारा उत्साहपूर्वक समर्थित आंदोलन का विरोध किया।<sup>7</sup> भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1892 के अधिवेशन में भी इस आंदोलन का शुरु भाषा में निबद्ध प्रस्ताव में विरोध किया गया।<sup>8</sup> मजेंदार दात यह है कि भारत में सरकारी अधिधारियों ने उपहास के रूप में अथवा जाने अनजाने रूप में मुद्रा प्रश्न पर राष्ट्रीय दृष्टिवाण की उपक्षा की और उसका गलत अर्थ निकाला। उन्होंने 21 जून 1892 को भारत राज्य मन्त्रि को यह प्रतिवेदित किया कि भारतीय जनमत निर्णित उपाय को स्वीकार करने की स्थिति में है और चांदी के सिक्के बनाने की समाप्ति को जनता सामान्यतः स्वीकार करेगी।<sup>9</sup>

सरकारी अधिधारियों का भारतीय जनमत सत्रधी मिथ्या ज्ञान उस समय उघड़ गया जब 1893 में भारतीय टक्काला के बढ़ होत ही राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने 'यूनाधिक रूप से एक स्वर से इस पग का विरोध किया और इसे भारतीय जनता के विशेषतः उत्पादक और श्रमक वर्ग के हितों के प्रतिकूल बताकर उसकी भत्सना की।<sup>10</sup> बाद में उसी वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार की बायबाही की निंदा करते हुए प्रस्ताव पाम किया।<sup>11</sup> प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए डी० ई० वाचा ने 1893 के बैंसी एक्ट की इन शब्दों में भत्सना की 'अधरे में गहरी छलांग' और 'एक भारी अक्षम्य भूल'।<sup>12</sup> जब सरकार ने रुपये का मूल्य 1 शिलिंग 4 पेंस निर्धारित करते हुए स्वणमान की व्यवस्था की योजना बनाई तो इने, '1893 के अपराध की 1898 में पुनरावृत्ति'<sup>13</sup> बताते हुए वाचा ने सरकार की भत्सना सावजनिक रूप से की।<sup>14</sup> दादाभाई नौराजी ने टक्काल बढ़ करने की निंदा इन शब्दों में की 'यह एक अवैध, असम्माननीय और निरवुश कृत्य है।' उन्होंने स्वणमान के परित्याग की माग की।<sup>15</sup> आर० सी० दत्त ने भी कृत्रिम रूप से रुपये के मूल्य बढ़ाने के सरकार के प्रयत्न की निंदा 'अप्रावृत्तिक', निराशाजनक और भयकर' कहकर की।<sup>16</sup> उन्होंने सरकार का स्वणमान लागू करने के विरुद्ध चेतावनी दी।<sup>17</sup> भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी एक बार फिर विनिमय से हुए घाटे की पूर्ति के लिए महंगी कीमत पर मुद्रा में तबदीली करने अथवा आंतरिक मुद्रा के समेटा जैसे कृत्रिम उपाय अपनाने के प्रति अपनी असहमति प्रकट की।<sup>18</sup> डी० ई० वाचा न पूर्ववत् बड़ी ही उग्रता से यह विचार प्रकट किया कि सामान्य रूप से सवसाधारण द्वारा तथा विशेष रूप से बकों और व्यापारीवर्ग द्वारा उस दिन से भोगे हुए जोर भोगे जा रहे दुखा के कारणरूप सभी आर्थिक बुराइयों की जड़ 1893 का बैंसी एक्ट है।<sup>19</sup> उल्टे नौराजी, दत्त तथा अन्य भारतीय नेताओं ने दबाव डाला कि टक्कालें खोल भी जाएं और रुपये को चांदी के धातु मूल्य तक नीचे जाने दिया जाए।<sup>20</sup> भारतीय नेताओं ने फाउलर कमेटी में भारतीय हितों के संरक्षक एक भी प्रतिनिधि को सम्मिलित न करने का बहुत ही बुरा माना।<sup>21</sup> इस कमेटी की सिफारिशों की तथा उनके फलस्वरूप प्रस्तुत 1899 के बैंसी एक्ट की भारतीय नेताओं ने पुनः आलोचना की परंतु अब की बार पहले जैसा उत्साह दृष्टिगोचर नहीं हुआ। इसका कारण कदाचित्त यह था कि इस समय तक मुद्रा प्राप्ति एक व्यवस्थित तथ्य



व्यापार विरोधी पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण के अनुरूप यह नकारने की थी कि वच्चे सामान के निर्यात को प्रोत्साहन देना एक अच्छी बात है।<sup>53</sup> इससे इस दृष्टिकोण को बल मिलता है कि भारतीय नेताओं को अवमूल्यित रुपये की रक्षा के लिए न तो मुख्य रूप से व्यापारीवर्ग के प्रति सहानुभूति थी और न ही विदेशी व्यापार में रुचि थी। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि किसान को रुपये के अवमूल्यन से अपने उत्पादनों से अधिक रूपयों के मिलने के रूप में कोई लाभ पहुंचा है। उन्होंने निर्देश किया कि वस्तुतः बहुत सारे कृषि उत्पादनों के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बहुत सारे उत्पादनों के मूल्य तो घट ही गए हैं।<sup>54</sup>

### भारतीय वित्त में विनिमय की भूमिका

मुद्रा परिवर्तन के विरुद्ध भारतीय नेताओं की आपत्ति का दूसरा आधार उनकी यह धारणा थी कि रुपये की स्वण मूल्य में गिरावट भारत सरकार की आर्थिक कठिनाइयों का मूल कारण नहीं। उन्होंने विनिमय से भारत के कोप को होने वाले घाटे को देखा ही नहीं, अपितु उसके प्रति चिंता भी प्रकट की क्योंकि आखिरकार इस घाटे का भार बेचारे भारतीय करदाता के कंधे पर ही तो पड़ना था। उन्होंने इसकी पूर्ण समाप्ति की इच्छा की।<sup>54</sup> उदाहरणार्थ 1886 में दादाभाई नौरोजी ने विनिमय से होने वाले घाटे को ब्रिटिश भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और भारतीय जनता पर दुःखद भार बताया। उन्होंने लिखा 'दुर्भाग्यवस्तु निधन भारतीय को गृह प्रभारों के लिए 14 करोड़ रुपये के मूल्य के उत्पादन को 7 शिलिंग प्रति रुपया की दर से बेचने के बदले 1 शिलिंग 4 पेंस की दर से बेचने से रुपये के विनिमय में आई गिरावट से हुए घाटे को पूरा करने के लिए 7 करोड़ रुपये के मूल्य का और उत्पादन बेचना पड़ता है।<sup>55</sup> भारतीय नेताओं और सरकार के मध्य सम्झौते का क्षेत्र इस जगह खत्म हो गया क्योंकि उनमें इस बुराई के लिए उत्तरदायी तत्वों और उनके उपचार की प्रवृत्ति के बारे में मतभेद था। भारतीय नेता यह मानने को तैयार नहीं थे कि यह विनिमय का घाटा रुपये के स्वण मूल्य में गिरावट का परिणाम है। उनका कथन था कि रोग का स्रोत कहीं अन्यत्र है। भारतीय नेताओं में मुद्रा प्रश्न के इस पक्ष में उल्लेखनीय एकता तथा सुसंगति थी। रोग की यथाथ प्रवृत्ति की पहचान और प्रयोज्य उपचार ने उनकी समग्र मुद्रानीति में विशिष्ट स्थिति बनाए रखी। रोग की पहचान को सार रूप में निम्न विधि से प्रस्तुत किया जा सकता है

इस सारी समस्या की जड़ विनिमय की दर न होकर भारत के इंग्लैंड के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबन्ध हैं। सरकार के विनिमय संबंधी घाटे के लिए निम्न विनिमय के बदले गृह प्रभार ही उत्तरदायी हैं। यदि भारत से इंग्लैंड में स्वण के रूप में अनिवाय धन न भेजा जाता तो रुपये के स्वण मूल्य में गिरावट में संभवतः भारत सरकार के वित्त अथवा भारत के लोग प्रभावित ही न होते। दूसरी ओर जब तक गृह प्रभार बने हुए हैं, केवल मुद्रा परिवर्तन से कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा।<sup>56</sup>

इस संबन्ध में अनेक भारतीय प्रवक्ताओं ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्लासिकी मोडर्न सिद्धांत पर दृढ़ विश्वास प्रकट किया जिसके अनुसार—मुद्रा पद्धति इस विधि से प्रवर्तित

वन चुवी थी।<sup>44</sup> फिर भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस परवर्ती अना वषों में इस प्रश्न का महत्त्व देती रही। अपने 17वें अधिवेशन में कांग्रेस ने नवनीत तौर पर रुपये की 30 प्रतिशत कीमत बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया।<sup>45</sup> 18वें अधिवेशन में पुनः इस प्रश्न का प्रस्ताव पारित किया गया।<sup>46</sup> अना जनता वर्षों तक रुपये की नफली मूल्यवर्द्धि और नाकहिता पर उमने दुष्प्रभाव की आलाचना करत रहे।<sup>47</sup>

भारत सरकार की मुद्रानीति की राष्ट्रवादी अस्वीकृति के तीन मुख्य आधार थे। 1. ह्यासी मुल रुपये का लाभकारी चरित्र 2. मुद्रा के सरकार अथवा जनता की आर्थिक कठिनाइया के मूल कारण हान के प्रमाण का अभाव, 3. जाता की आर्थिक स्थिति पर रुपये के बढ़ते मूल्य का हानिकारक प्रभाव। इन आधारों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है क्योंकि इनसे गभीरतापूर्वक अवधि में भारतीय राष्ट्रीय नेताओं के आर्थिक दृष्टिकोण संबंधी मौलिक सिद्धांतों पर भी प्रकार प्रकाश पड़ता है।

### निम्न विनिमय के लाभ

बहुत सारे भारतीय नेताओं का यह विश्वास था कि 1873 में भारत के व्यापार और उद्योग में जो प्रगति की है उसमें गिरत रुपये वाल रजत मान ने भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की सतापजाव रूप में पूर्ति की है और इस प्रकार भारत द्वारा अपनाया जा सकने वाला यह बदाचित्त सर्वोत्तम मुद्रा मान था।<sup>48</sup> उनके अनुसार निम्न विनिमय की मुख्य उपयोगिता थी विनिमय में गिरावट की सीमा तक अल्पधि में मंहने बन गए आयातों में भारतीय उत्पादना, विद्योपत सूती वस्त्रों को परोक्ष संरक्षण देने के रूप में प्रोत्साहन जुटाना। 'मराठा ने अपने 25 सितंबर 1892 के अंक में लिखा विनिमय कटौती सभी प्रकार के अंगरेजी सामान पर आयात शुल्क के रूप में काम करती है। यहां विनिमय में फिर वही काम किया है जो करने से सरकार निरंतर इनकार करती रही है।'<sup>49</sup> हिंदू तो 4 सितंबर 1889 के अंक में यह देख पाते में सफल हो गया कि निम्न विनिमय के कारण ही भारत इंग्लैंड के सूती वस्त्र उत्पादकों से चीन और जापान के बाजार हथियाने में सफल हो सका है।<sup>50</sup> पी० सी० राय ने इस स्थिति में एक और उपयोगिता देखी। उन्होंने कहा कि निम्न विनिमय ने अंगरेजी पूंजी के लिए भारत को एक अनाकंपक प्रदेश बनाकर भारतीय पूंजीपतियों के लिए उद्यम के अवसर उत्पन्न किए हैं।<sup>51</sup>

यह जाश्चयजनक तथ्य है कि राष्ट्रवादियों ने चांदी के रुपये के समर्थन में स्वीकृत तक को उसी समय आगे नहीं बढ़ाया। वह तक यह था कि विनिमय की निम्न दर विश्व के बाजारों में मूल्य को नीचे गिराकर निर्यात को प्रोत्साहन देती है। वास्तव में कुछ भारतीय नेताओं ने (आर० सी० दत्त को छोड़ कर जिन्होंने थोड़ी बहुत अस्पष्टता के साथ यह स्वीकार किया कि चांदी के अवमूल्यन से भारत के विदेश व्यापार को हानि की अपेक्षा लाभ ही पट्टा है<sup>52</sup>) संवया अस्वीकार कर दिया कि रुपये के अवमूल्यन ने भारतीय निर्यात को प्रोत्साहन दिया है।<sup>53</sup> जो भी हो, उनमें सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति, उनके विदेश

व्यापार विरोधी पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण के अनुरूप यह नकारने की थी कि वच्चे सामान के निर्यात को प्रोत्साहन देना एक अच्छी बात है।<sup>5</sup> इससे इस दृष्टिकोण को बल मिलता है कि भारतीय नेताओं को अवमूल्यित रुपये की रक्षा के लिए न तो मुख्य रूप से व्यापारीवर्ग के प्रति सहानुभूति थी और न ही विदेशी व्यापार में रूचि थी। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि किसान को रुपये के अवमूल्यन से जपन उत्पादनो से अधिक रूपयों के मिलने के रूप में कोई लाभ पहुंचा है। उन्होंने निर्देश किया कि वस्तुतः बहुत सारे कृषि उत्पादनो के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बहुत सारे उत्पादनो के मूल्य ता घट ही गए हैं।<sup>53</sup>

### भारतीय वित्त में विनिमय की भूमिका

मुद्रा परिवर्तन के विरुद्ध भारतीय नेताओं की आपत्ति का दूसरा आधार उनकी यह धारणा थी कि रुपये की स्वर्ण मूल्य में गिरावट भारत सरकार की आर्थिक कठिनाइयों का मूल कारण नहीं। उन्होंने विनिमय से भारत के कोष को हाने वाले घाटे का देखा ही नहीं, अपितु उसके प्रति चिंता भी प्रकट की क्योंकि आखिरकार इस घाटे का भार बचारे भारतीय करदाता के कंधे पर ही तो पड़ना था। उन्होंने इसकी पूर्ण समाप्ति की इच्छा की।<sup>54</sup> उदाहरणार्थ 1886 में दादाभाई नौरोजी ने विनिमय से होने वाले घाटे का ब्रिटिश भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और भारतीय जनता पर दुःखद भार बताया। उन्होंने लिखा 'दुर्भाग्यग्रस्त निधन भारतीय को गृह प्रभारों के लिए 14 करोड़ रुपये के मूल्य के उत्पादन को 7 शिलिंग प्रति रुपया की दर से बेचने के बदले 1 शिलिंग 4 पेंस की दर से बेचने से रुपये के विनिमय में आई गिरावट से हुए घाटे को पूरा करने के लिए 7 करोड़ रुपये के मूल्य का और उत्पादन बेचना पड़ता है।'<sup>55</sup> भारतीय नेताओं और सरकार के मध्य समझौते का क्षेत्र इस जगह खत्म हो गया क्योंकि उनमें इस घुसाई के लिए उत्तरदायी तत्वा और उनके उपचार की प्रकृति के बारे में मतभेद था। भारतीय नेता यह मानने को तैयार नहीं थे कि यह विनिमय का घाटा रुपये के स्वर्ण मूल्य में गिरावट का परिणाम है। उनका कथन था कि रोग का स्रोत कहीं अन्यत्र है। भारतीय नेताओं में मुद्रा प्रश्न के इस पक्ष में उल्लेखनीय एकता तथा सुसंगति थी। रोग की यथाथ प्रकृति की पहचान और प्रयोज्य उपचार ने उनकी समग्र मुद्रानीति में विशिष्ट स्थिति बनाए रखी। रोग की पहचान को सार रूप में निम्न विधि से प्रस्तुत किया जा सकता है

इस सारी समस्या की जड़ विनिमय की दर न होकर भारत के इंग्लड के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंध हैं। सरकार के विनिमय संबंधी घाटे के लिए निम्न विनिमय के बदले गृह प्रभार ही उत्तरदायी हैं। यदि भारत से इंग्लड में स्वर्ण के रूप में अनिवाय धन न भेजा जाता तो रुपये के स्वर्ण मूल्य में गिरावट से संभवतः भारत सरकार के वित्त अथवा भारत के लोग प्रभावित ही न होते। दूसरी ओर जब तक गृह प्रभार बने हुए हैं, केवल मुद्रा परिवर्तन से कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा।<sup>56</sup>

इस संबंध में अनेक भारतीय प्रवक्ताओं ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्लासिकी मौद्रिक सिद्धांत पर दृढ़ विश्वास प्रकट किया जिसके अनुसार—मुद्रा पद्धति इस विधि से प्रवर्तित



होती है कि विगी देग के भुगतान का सतुलन अपने आप ही मुख्य स्थिति की ओर चला जाता है।<sup>57</sup> उन्होंने आन्तिपूर्वक वन देकर कहा कि गृह प्रभारा के भुगतान में हानि का घाटे का छान कर विनिमय की गिरावट अपना आप में भारत के विशेष व्यापार को प्रभावित नहीं करेगी क्योंकि नीमना के उतार-तढाच द्वारा विदेश व्यापार विनिमय की अर धाजा व अनुरूप अपने आपका स्वतः ही व्यवस्थित कर लेगा।<sup>58</sup> कुछ अर भारतीय नेताओं ने भी निर्देश दिया कि एग लवे गमन ता निरतर विशेषा का अनिवाय भुगतान की आवश्यकता न सरकार ता विगी भी मूल्य पर पौड गरीदन के लिए विचा कर लिया है। उसी का अप्रतिहाय दुप्रभाव चादी के मूल्य में ढाग स उत्पन्न विनिमय की दुदगा है।<sup>59</sup> भारतीय रूप्ये के रजत मान न हटन पर इस ता का गृह वन मिला। 1899 में वाचा ने बर्ई के मिल मानिया का बताया कि विनिमय के विदेशों का कारण विदेशों में लिए जाने वाले भुगतान के फलस्वरूप भारत के विदेश व्यापार के सतुलन में आई अर वस्था है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अपना मत प्रकट किया आपकी मुद्रा सोने की हा अथवा चादी की रई की अथवा गेहू की, जब तक यह प्रभार बढ़ते और बढ़ते ही रहेंगे तब तक यह तथाकथित विनिमय कठिनता वनी ही रहेगी वस्तुतः समस्या तो गृहप्रभारों की ही है।<sup>60</sup> उन्होंने तथा उनके साथ जी० एम० अर्यर महोदय ने भी यह अनुभव किया कि 1872 तक और यहां ता कि उनके बाद भी इन गृहप्रभारों के दबाव पर ध्यान इन लिए नहीं गया क्योंकि दस अवधि में रेलों तथा अर प्रयाजनों के लिए बहुत बड़ी बड़ी रकमों के ऋण लिए गए हैं।<sup>61</sup>

राष्ट्रवादी नेताओं ने अपने उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर अधिकांशों के इस दृष्टिकोण की तीव्र भत्सना की कि विनिमय से होने वाला घाटा उनके नियंत्रण से बाहर था और इसका उपाय या तो करा में वृद्धि द्वारा इसे सहन करना था, अथवा रूप्ये का मूल्य बढ़ाकर इसे निष्फल करना था उनके अनुसार इसका एक अन्य उपाय भी था और उसका पता रोग की जांच पडताल से लग जाता है। प्रथम, उनका कथन था सरकार को विनिमय से होने वाले घाटे का मूल कारण यदि विनिमय में गिरावट नहीं तो स्पष्ट है कि सरकार द्वारा प्रस्तावित मुद्रा पद्धति सबधी परिवर्तन से स्थिति में कोई बहुत बड़ा सुधार होने वाला नहीं।<sup>62</sup> द्वितीय, क्योंकि मूल दोष गृह प्रभारों का ही है अतः इस रोग का प्रभावी इलाज भारत के स्टलिंग दायित्वों में निरतर वृद्धि करने वाली वर्तमान नीति में जामूल चूल परिवर्तन लाना ही है। अतएव प्रमुख एकमात्र स्वाभाविक और उपयुक्त उपचार है गृह प्रभारों की समाप्ति अथवा उनमें कटौती अथवा इन्फ्लेक्शन की संपत्ति की निकासी की समाप्ति या कटौती अथवा उनसे कम स्टलिंग के बड़े भाग का दायित्व रूप्ये की देनदारी में परिवर्तन ताकि उत्तनी रकम के बराबर भुगतान के लिए काफी कम रूप्ये देन पडें। यह भारतीय कोष भंडारों के लिए एक बहुत बड़ी मुक्ति होगी।<sup>63</sup> इस उद्देश्य की प्राप्ति के निश्चिततम उपायों में भारतीय नेताओं के विचार में एक था, देश का प्रशासन दग के संपूर्ण द्वारा ही पूर्ण योग्यता के साथ चलाया जाना, क्योंकि उस स्थिति में उनके वेतन और पेंशन राशि का भुगतान सोने में नहीं करना पडेगा।<sup>64</sup> दूसरा मुभाया हुआ उपाय यह था कि देश के भीतर ही सरकारी भंडारों के अपेक्षाकृत अधिक

बड़ी सख्या मे अश खरीदना ।<sup>65</sup> एक अय उपाय यह भी था कि इंग्लड भारत सरकार के इंग्लड मे होने वाले व्यय के उचित अश का भुगतान करे ।<sup>66</sup> वस्तुत बुछ नेताओ ने तो रूपय के मूल्य में ह्रास का और विनिमय मे घाटे का स्वागत ही किया क्योकि उहे आशा थी कि यह स्थिति धन की निकाामी की समस्या की ओर सरकार का और भारतीय जनता का ध्यान खीचेगी और जनता सरकार को सही पग उठान के लिए विवश कर देगी ।<sup>67</sup> बगाली ने 3 सितवर 1892 के अक मे इस दष्टिकोण का अत्यत स्पष्टता से विश्लेषण किया

यदि वतमान स्थिति और अधिक समय तक चलती रही तो इसके कारण भारतीयो के लिए अत्यत लाभप्रद परिवतन अवश्य होंगे । गृह प्रभारो को घटाना आवश्यक है और आवश्यकता की वस्तुओ को देश मे ही पाने वा प्रयत्न करना चाहिए । यदि भारतीय बाजार मे सरकार ही खरीदार बन जाए ता भारतीय व्यापार का कितना प्रवल प्रोत्साहन मिलेगा । (यह) भारतीय उद्योग को भी प्रोत्साहित करगा ।

इसके अतिरिक्त यह भी अनुभव किया गया कि विनिमय म गिरावट अगरेजो की बहुत बड़ी सख्या का अपने देश मे ही रहने और भारत मे हथियाई हुई नौकरियो को भारतीयो के लिए ही छोडने को बाध्य करेगी ।<sup>68</sup>

भारतीय नेताओ ने इस बात से इनकार किया कि रूपये की मूल्यवद्धि का प्रयो-जन बडे हुए कराधान और आर्थिक सकट से भारत का मुक्ति दिलाता है । उनका तर्क था कि यदि गृह प्रभारो मे भारी कटौती न भी की जाए और विनिमय से होने वाला घाटा भी चलता रहे तो भी इनकी पूर्ति बिना किसी प्रकार के एए कराधान के वतमान आर्थिक ससाधनो मे तथा उनमे होने वाली सामान्य बढोत्तरी से ही की जा सकती है ।<sup>69</sup> उनकी धारणा थी कि निस्सदेह विनिमय एक पीडाजनक तत्व है परतु इसे भारतीय वित्त का कृत्रिम समाधान नहीं मानना चाहिए । भारतीय वित्तो के असतुलन का दायित्व प्रमुख रूप से विनिमय के घाटे पर न देकर सरकार के सिविल और मिलिट्री के खर्चों के विषम विकास पर ही देना चाहिए, क्यकि इनके ही कारण भारत की स्टॉलिंग देनदारी मे बढोत्तरी होती है ।<sup>70</sup> अत स्थिति का सही उपचार मुद्रा पद्धति मे परिवतन न होकर खर्चों विशेषत मिलिट्री के खर्चों, मे कटौती करना है ।<sup>71</sup> डी० ई० वाचा ने तो विशेष रूप से दढतापूर्वक इस धारणा का समर्थन किया और आकडो की सहायता मे सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि 1884 85 से लेकर इस अवधि तक मिलिट्री के खर्चों न सारे नए कर हजम कर लिए हैं और यन् मिलिट्री के इन व्ययो मे कटौती कर दी जाए तो भारत विनिमय की बैसाखी के बिना ही अपने पाव पर खडा हाने योग्य बन जाएगा ।<sup>7</sup>

कुछ भारतीय नेताओ का एक अन्य सुभाष था कि यदि वतमान सभी स्थितिया को अपरिवतनीय ही मान लिया जाए तो भी विनिमय की कठिनता का सामना भारत मे उत्पादित न की जाने वाली अथवा भारत की बहुसख्या के काम मे न आन वाली अथवा देश के विकास से सबध न रखने वाली विदेशो से आयात की जाने वाली वस्तुओ पर थोडे से आयात शुल्क को लगा कर निया जा सकता है ।<sup>72</sup> यह विवरण कपास शुल्क के सवया अनुरूप था ।<sup>74</sup>





प्रत्येक स्थिति में भारतीय नेताओं ने इस बचन पर तीव्र आपत्ति की जिन्हें वे बद बचन से अथवा रुपये की मूल्यवृद्धि में सरकार भारतीय जनता को नए कराधान की आवश्यकता की समाप्ति के रूप में किसी प्रकार का कोई गुण दे सकती है। उनका विचार था कि यह तब आर्थिक तथ्यों के माध्यम से अनिश्चित और कुछ भी नहीं। मुद्रा में परिवर्तन में सम्भवतः किसी प्रकार की अभीष्ट मरिद्धि नहीं होगी। इसके विपरीत 1893 और 1898 के मुद्रा कानून में भारतीय जनता को रुपये के बड़े मूल्य की सीमा तक भारत पर अनिश्चित प्रवृत्ति वाले परोक्ष करा का और अधिक शिक्कार बनाया गया है<sup>75</sup> क्योंकि अज्ञान और भी वृद्धि रूप में बड़े हुए मूल्य वाले रूपों के रूप में उगाह जा रहे हैं।<sup>76</sup> दादाभाई नौरोजी ने 1898 में लिखा कि "भारत में बद बचन में और उसके साथ रुपये के इस समय 11 पैसों के लगभग यथायत्न स्वर्ण मूल्य को 16 पैसों के बराबर स्वर्ण मूल्य में बदलना भारतीय करानाओं पर कुल मिलाकर गुप्त रूप से करा में 45 प्रतिशत की वृद्धि का भार डालता है।"<sup>77</sup>

भारतीय नेताओं के मत में सरकार के मुद्रा संबंधी प्रश्न को हल करने के लिए उसकी चालाक राजनीतिक छल-कपट की नीति का पता चलता है जिसके तहत भोली भाली तथा भटकी हुई भारतीय जनता पर जो कर भारत में किसी प्रकार की प्रत्यक्ष वृद्धि से विमुक्त हो उठनी गुप्त तथा परोक्ष कराधान के द्वारा उद्देश्य की पूर्ति की गई है।<sup>78</sup> इसके विपरीत कई राष्ट्रवादी नेताओं ने तो करा में प्रत्यक्ष और परोक्ष वृद्धि रूप दोनों बुराईयों में प्रत्यक्ष वृद्धि को अपेक्षाकृत छोटी बुराई मानते हुए उसका ही समर्थन किया, क्योंकि उनके विचार में इससे बेचारे करदाता को देश के करा में प्रचलित रूप से अपार बढ़ोतरी के स्थापन पर केवल विनिमय में प्राकृतिक गिरावट से हुए घाटे की पूर्ति के लिए आवश्यक अतिरिक्त करा का ही भुगतान करना पड़ता है।<sup>79</sup>

बाद में जब 1901 के बाद लाभ का बजट आना प्रारंभ हो गया तो राष्ट्रवादी नेताओं ने एक बार फिर यह दावा किया कि वे लाभ 1893 और 1898 में घोषित हुए मुद्रा विधान के अंतर्गत परोक्ष कराधान के ही परिणाम हैं।<sup>80</sup> साथ ही उन्होंने अभिस्वीकार किया कि मुद्रा नीति से पीछे छटना व्यावहारिक राजनीति की सीमा के अंतर्गत दिखाई नहीं देता। नेताओं की मांग थी कि इन अज्ञेयों का उपयोग मुद्रा विधान के आघात से पीड़ित बेचारे करदाता को करा में छूट के रूप में ही करना चाहिए।<sup>81</sup> इस संबंध में जी० के० गोखले ने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा कि यदि

रुपये के विनिमय मूल्य में वृद्धि से देश के कराधान में किसी प्रकार की परोक्षवृद्धि की सम्भव सम्भावना को नकारा जा सकता है तब भारत सरकार के माग में कौन भी उपाय है कि वह रुपये का मूल्य और अधिक ऊंचा 1 शिलिंग 6 पैसों अथवा 1 शिलिंग 9 पैसों अथवा 2 शिलिंग नहीं कर देती? उस स्थिति में तो लाभ इस समय के लाभ से भी बड़ा बढ़कर होगा। जब लाइ जाज हैमल्टन यह मानते हैं कि इस वृद्धि से किसी भारतीय को कोई हानि नहीं हुई तो फिर सरकार इस आश्चर्यजनक सरल और भीषण उपाय में अपने मसाधनों में वृद्धि क्यों नहीं करती?<sup>82</sup>

कुछ अधिक सचेत राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार रुपये की मूल्यवृद्धि से देश द्वारा



यूरोपीय अथवा भारतीय सरकारी यमचारियों को बड़े हुए रूपों में वेतनों का भुगतान करना पड़ेगा। इसका अर्थ होगा कि कोटि कोटि मपदा उत्पादकों तथा भारत को ममूद बनाने वाले श्रमिकों के श्रम से अर्जित संपत्ति उनके हाथ से छीन कर भद्राया में हाथ में सौंपना।<sup>90</sup>

डी० ई० चाचा न एक अन्य परोक्ष परतु हानिप्रद प्रभाव की ओर ध्यान दिलाया भारत स्वयंमानवाले देशों के साथ नवारात्मक व्यापार-संतुलन रख सकता था क्योंकि चीन तथा अन्य रजत प्रयावना देशों के साथ उसका नवारात्मक व्यापार संतुलन था। नया मुद्रा अधिनियम दूर के पूर्वी देशों में भारत के नियान को घटाकर इंग्लैंड को भेजी जाने वाली रकम को भेजने का याम अधिक कठिन बना देगा।<sup>91</sup>

### रूपों की मूल्यवृद्धि के हानिप्रद प्रभाव

भारतीय नेताओं ने भारत सरकार के मुद्रा अधिनियम की व्यथता को सिद्ध करने के अतिरिक्त उससे द्वारा भारतीय जनता विशेषतः उत्पादक वर्ग के आर्थिक हितों को पहुँचाई जा रही वाम्त्विक अथवा मभावित निश्चित हानि की ओर ध्यान दिलाया।

सबप्रथम, उन्होंने दावा किया कि रूपों की मूल्यवृद्धि भारत के देशी उत्पादकों के प्रति पक्षपातपूर्ण रही है।<sup>92</sup> रूढ़ियों का तो मत था कि मुद्रा में परिवर्तन ने देश के विदेश व्यापार पर घातक प्रभाव डालकर देश पर व्यापारिक अनुपयोगिता थोप दी है।<sup>93</sup> व्यापार के सबंध में उनकी चिंता प्रायः दिखावटी ही थी। वास्तव में वे उद्योग से ही घनिष्ठ रूप से संबंधित थे। वे रूपों की मूल्य वृद्धि के कुल मिलाकर भारत के विदेश व्यापार पर अथवा महा तब कि नियान व्यापार की समग्रता पर उससे दुष्प्रभाव से वाम्त्विक ही चिंतित नहीं थे। उनसे श्लोक के भडकने का मुख्य कारण यह था कि भारत से चीन और जापान को किए जा रहे मूल्य के निर्यात का भविष्य दुःशास्त्रस्त हो गया था क्योंकि भारत की इन दाना देशों के उत्पादकों से प्रतियोगिता थी और इन दाना देशों ने या तो रजत मान अपनाए रखा था अथवा चांदी और सोने के बीच विनिमय का निम्न अनुपात बनाए रखा था। इससे फलस्वरूप इन देशों के उत्पादकों ने मूल्य के सदम में भारतीय उत्पादकों का पिछाड़ दिया।<sup>94</sup> संक्षेपतः भारतीय नेता व्यापक रूप से सूती वस्त्र उद्योग के भविष्य के प्रति ही अधिक चिंतित थे जिस पर उस समय तब पूर्वी व्यापार संशक्त रूप से छा गया था।<sup>95</sup> उन्होंने शीघ्र ही उच्च स्वर से आत्त क्रदन करते हुए कहना प्रारंभ कर दिया कि रूपों की मूल्यवृद्धि के फलस्वरूप भारतीय सूती वस्त्र उद्योग पगु और अस्तव्यस्त हो गया है।<sup>96</sup> उदाहरणार्थ, जी० के० गोखले ने 1902 में यह आरोप लगाया कि सरकार के मुद्रा कानून के फलस्वरूप भारत के सूती वस्त्र उद्योग में बड़े पैमाने पर भयंकर मंदी आई है।<sup>97</sup> और अम्बालाल शकरलाल देसाई ने 1904 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूचित किया कि पिछले कुछ वर्षों में चीन के साथ विनिमय में गिरावट (वृद्धि) के कारण बर्बई की बीस मिला का दिवाला पिट गया है।<sup>98</sup> इस संघर्ष में राष्ट्रीय दृष्टिकोण को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 18वें अधिवेशन में स्वयं एक सूती कपड़ा मिल के मालिक वी० डी० ठाररमी ने अत्यंत सरलता और संक्षेप से प्रस्तुत किया। उन्होंने दृढतापूर्वक कहा

‘वतमान में हुए मुद्रा परिवर्तन के कारण देश के वताई उद्योग को पिछले कई वर्षों से भयकर सकट की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है।’ उन्होंने अपनी धारणा को प्रबल करते हुए कहा ‘रूपय की मूल्यवृद्धि ने रजत प्रयोक्ता चीन के बाजार में हानि पहुँची है। इसके विपरीत जापानी इससे भारतीय उद्योग को चीन के बाजार में हानि पहुँची है। इसके विपरीत जापानी रजत उद्योग को जिसे किसी भी इस प्रकार की बाधा या शिकार नहीं होना पड़ा—परोक्ष रूप से लाभ ही पहुँचा है। फलतः जापान चीन की एक तिहाई से अधिक माग की पूर्ति करने में समर्थ हो गया है।’ उन्होंने दुःखित स्वर में कहा ‘मुझे इसमें कुछ भी विस्मय नहीं होगा, यदि एक दिन जापान सारे बाजार पर उसी प्रकार बज्रा जमा लेगा, जिस प्रकार कभी भारत का था।’ हमारे प्रतियोगियों का दूर पूर्व में 20 रुपये प्रति गाँठ का उपहार ही है, जिसने हमारे वताई वुनाई उद्योग को आर्थिक दृष्टि से विनाश के गगार पर लाकर खड़ा कर दिया है।<sup>109</sup>

राष्ट्रवादी दृष्टिकोण सही था अथवा नहीं इसकी जाच म न पड़ते हुए हम इतना ही बहना चाहेंगे कि व्यापार को सूत व्यापार की अत्यंत सकीण दृष्टि से देखने का उनका विशेषण ढग तथा चिंतन रुपये के अवमूल्यन से विदेश व्यापार को पहुँची हानि अथवा सरकारी मुद्रानीति से विदेश व्यापार को पहुँचे लाभ पर आधुत था। उसकी समीक्षा उसे सबथा अप्रासंगिक ही सिद्ध करती है। एक बार यह स्वीकार कर लेने पर, जसा उनके बहुत सारे समीक्षकों ने किया है कि रुपये की मूल्यवृद्धि से (भले ही कितना आर्थिक क्या न हूँ) भारत के चीन और जापान को होने वाले सूत के निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ा है<sup>100</sup> तो भारतीय पक्ष भारी हो जाता है। वस्तुतः भारतीय राष्ट्रवादी नेता स्वयं ही अपनी एकपक्षीय मान्यता पर कि सूती उद्योग में गिरावट एकातत मुद्रा परिवर्तन का परिणाम थी पुनर्विचार करने लगे। उदाहरणार्थ डी० ई० वाचा ने 1901 में स्वीकार किया कि गिरावट लाने में अयाय कारण जैसे उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि, अकुशल प्रबंध व्यवस्था, प्लेग, अकाल का भी थोड़ा बहुत योगदान है। उन्होंने पुनः इस बात को दोहराया कि सरकार की मुद्रा नीति के विरुद्ध शिकायत करने वालों द्वारा अतिरिजित रूप में प्रस्तुत हानियों की सीमा तक सम्भवतः न सही परंतु वह निश्चित रूप से हानिप्रद अवश्य रही है।<sup>101</sup>

भारतीय नेताओं ने वरुन उद्योग के संबध में प्रस्तुत आधारों के सदृश ही निम्न विनिमय की आवश्यकता रखने वाले चाय तथा अय बागान उद्योगों की भी उन्हीं आधारों पर वकालत की।<sup>102</sup> वे इन उद्योगों से संबधित सधप के प्रति विशेष उत्साही नहीं थे। उन्होंने कागडा की तराई में चाय बागान मालिक कॅप्टन ए० बैंनन जस कुछ अग्रज चाय बागान मालिकों का समर्थन पाने के लिए ही इस विषय को उठाया था।<sup>103</sup>

यह पर्याप्त रोचक तथ्य है कि मुद्रा समस्या के दोनों राष्ट्रवादी विशेषज्ञों, दादाभाई नौरोजी और डी० ई० वाचा, ने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि वह मुद्रा प्रश्न पर विचार करते समय विदेश व्यापार की आवश्यकताओं पर ही केवल ध्यान देती है और मुद्रा की बठोरता की अपेक्षा उसकी अधिकता चाहने वाले अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक व्यापार की आवश्यकताओं की अपेक्षा करती है।<sup>104</sup>



म रुपये की सुधरी स्थिति यह प्रमाणित नहीं करनी कि टक्मालो का बंद करना एक उचित नीति थी तथा न ही यह सिद्ध होना है कि रुपये की सुधरी विनिमय स्थिति में इस नीति का कोई योगदान है। वस्तुतः यह सुधार तो बाजार में कौमिल बिल को लौटा देने का और राज्य सचिव के निरंतर श्रुण लेन का परिणाम था। 1893 के अधिनियम व प्रावृत्तिक प्रवर्तन में ये बातें सबथा भिन्न थी।<sup>12</sup>

राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण का सर्वाधिक सुदृढ़ समयन दादाभाई नौरोजी का मिला। उनकी सफाई का मुख्य आधार देयन में ही सरल था। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि मूल्य गिरें या बढें, वास्तव में राष्ट्रीय दृष्टिकोण के लिए इसका कोई विशेष महत्व नहीं। उन्होंने निर्देग किया कि मूल्य के उतार-चढ़ाव तो बर्तमान तत्वा का सम्मिलित प्रभाव होना है अतः मूल्य व सदम में किसी एक तत्व का महत्व देना अथवा उसे उत्तरदायी ठहराना सत्रथा भ्रम है। मही आर्थिक विफलण के लिए टक्मालो के बंद होने के वास्तविक तथा पूण प्रभाव को अथ पक्षा से अलग करके उमयी अपनी ही ममप्रता में उसकी जांच करनी चाहिए। समस्या का इस ढंग से दखत हुए नौरोजी का निर्दिचत मत था कि इस मान्यता का कि रुपये के सोन और चादीगत मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप किसान को सरकार को राजस्व की अपेक्षावृत्त ऊंची रकम चुकानी पडती है वस्तुआ के वास्तविक यत्नचित मूल्य के सदम में एक नितात स्वतंत्र रूप था। यदि किन्ही अन्य तत्वों के प्रवर्तन से वस्तुओं के वास्तविक मूल्य में गिरावट नहीं आती तो इसका अर्थ केवल यह है कि मुद्रा परिवर्तन यदि न होता और अन्य तत्वा का प्रवर्तन जारी रहता तो वस्तुओं के मूल्य और अधिक बढ जाते तथा किसान को उसी मात्रा में लाभ होता। इस प्रकार सरकार ने टक्माना का बंद करन के वपटपूण उपाय द्वारा किसान को अर्थ लाभप्रद तत्वा व लाभ से वचित कर दिया है। उन्होंने अपनी इस चिंतन पद्धति को एक अन्य रूप में भी अभिव्यक्ति दी। उनके अनुसार पुराने रुपये और नए रुपये के रजतमूल्य में अंतर आ गया है, पुराने रुपये का मूल्य 184 ग्रैन चादी था और नए का मूल्य 269 ग्रैन हो गया है, इससे विशिष्ट बाजार में और विशिष्ट समय में वास्तविक मूल्य स्तर से सबथा भिन्न चादी के इन दा भिन्न परिमाणों से नियमित उपभोग वस्तुओं के मूल्य के मध्य एक अंतर तो सत्रा बना रहेगा और रुपये की मूल्य वृद्धि से किसी भी घडी में मूल्य में आन वाला अंतर किसान को होने वाला घाटा ही कहलाएगा।<sup>13</sup>

### राजनीतिक आशय

राष्ट्रवादियों के सद्धानिक दृष्टिकोण का कि भारत सरकार की मौद्रिक कठिनाइयों का मूल कारण यह प्रभार थे एक उपपरिणाम यह विद्वास था कि यदि भारत राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र होता तो मुद्रा समस्या उत्पन्न ही न होती।<sup>14</sup> अब, जब समस्या उत्पन्न हो गई है, इससे निपटने के लिए सरकार को भारतीय जनता और उसके प्रतिनिधियों से परामर्श करना चाहिए।<sup>15</sup>

जब राष्ट्रीय विराध के वावजूद 1893 में निजी तौर पर सिक्के डालने के लिए टक्माना बंद कर दी गई और बाद में भारत में स्वणमान को लागू करने की वायवाही की



रुपय की रियायती विनिमय दर पर 1000 पीड प्रति वष की अधिकतम सीमा तब अपना आधा वतन यूरोप को भेज सकता था। रून्ड को घन भेजा गया है अथवा नहीं, यह दखे जिना ही यह भत्ता द दिया जाता था।<sup>19</sup> रूस इन सरकारों अधिकारियों के वनन में वास्तविक वृद्धि हा गई। इस बड़े हुए घन की राशि 1893-98 की अवधि में लगभग 5 कराड रुपय थी। 1895-6 में जब यह अधिकतम सीमा तब पहुंच गई, तब यह रूम लगभग 1.33 कराड रुपय थी।<sup>20</sup>

जब ब्रिटिश अधिकारियों ने प्रारंभ में विनिमय क्षतिपूर्ति भत्ते की मांग रखी तो भारतीय नेताओं ने उसका तीव्र विरोध किया। बाद में जय सरकार ने इन मांग का स्वीकार कर लिया तो सरकार को इस कायवाही के विरुद्ध विरोध का तूपान उठ सडा हुआ जा बाद में वर्षों तक चलता रहा। इस भत्ते की निंदा करते समय राष्ट्रवादियों ने बड़ी ही बठोर और चुभती भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने यूरोपीय अधिकारियों के विरुद्ध घणा की भावना का भडकाया। इस कायवाही से उत्पन्न देशवागियों की घृणा के स्वरूप, परिमाण, यहां तब कि उनके स्तर को, अपनी नगमी के लिए विख्यात नेताओं द्वारा प्रदर्शित निर्भीकता का 'बैसर् हिंद' के 27 अगस्त 1893 के अंक की टिप्पणा के निम्नलिखित अवतरण में बड़े ही मुदर रूप से प्रदर्शित किया गया है

जब कभी निष्पक्ष इतिहास 19वीं शताब्दी के अंत की अवधि के ब्रिटिश प्रशासन के व्यवहार पर अनश्वर निणय को अभिलिखित करेगा तो उनके किसी भी भाग में विदेशी दासत्व की, प्राचीन अथवा आधुनिक काल के इतिहास में अनुपलब्ध, फिजूल-सर्ची के रूप में सहानुभूतिहीनता के लिए और सामनय की व्यवस्था हेतु इस महान देश के असहाय और वजवान लोगों पर बमरताड तथा निदयतापूर्ण बोझ डालने में बगती जाने वाली बहिसाब क्रूरता के लिए जति बठोर निंदा के अतिरिक्त और क्या होगा? हर्स्टिंग्स से लसडोन के दिनों तक भारत सरकार की वित्तीय भूला और निदय लट की एक दु खद और विशाल सूची रही है परंतु उनकी बुद्धि में कदाचित्त यह सूची न अधिक भारी होगी और न ही अधिक विस्तृत। उन्होंने पिछले अयायो और पिछली गलतियों के स्तर को वर्तमान के अपेक्षाकृत अधिक बड़े अयायो और गलतियों से पीछे धकेल दिया है। यह अमम्मानप्रद तथा असोभन काय लाड लसडोन के लिए ही सुरक्षित था और कौन कहगा कि उनमें निलज्जतापूर्ण घृष्टता और विवेकहीन उत्तरदायित्व में अपना काय नहीं किया। ऐसा अनुमान है कि इस माहम और उत्तरदायित्व के लिए तो उन्हें ब्रिटिश अभिजातवर्ग में उच्चतम पद पर प्रतिष्ठित करने के रूप में पुरस्ठृत ही किया जाएगा। लसडोन की उच्च पदवी में परमादरणीया महारानी की भारतीय प्रजा के लाया लोगों का बहुत ही अहित किया है। इसमें सदेह नहीं कि महारानी महोदया उसकी लाडलिंग को और अधिक उन्नत करेंगी और इसमें सदेह नहीं कि उसे ड्यूक के पद में अलङ्कृत करेंगी। मधोधि त मुद्रा अधिनियम तथा विनिमय क्षतिपूर्ति भत्ते के लेखक हीन के नाते उसके सम्मान असम्मान की कौन शिकायत करेगा। इस अधिनियम तथा भत्ते के द्वारा विदेशी बर-भन्धी दैत्यो के लिए भूखी भरतें भारतीय बरदाताओं के भूत्य पर गुलछरें उडाना

संभव हो गया है। इस प्रकार लाड लेंसडोन ने अपनी ग्रासन सन्ना का स्मरणीय बना दिया है। उसने लाड लिटन द्वारा प्रारंभ किए गए और लाड उपरिन् द्वारा जारी रखे गए भ्रवणनीय लालच के क्षेत्रीय तथा वित्तीय चक्र के प्रयत्न का पूरा वर दिया है। क्या यह कहने की आवश्यकता है कि देश के प्रशासन द्वारा गन्ती अन्याय लूट और छीना भ्रष्टी के दिन दहाड़े किए जाने वाले बायों पर हम प्राध स जन रहे हैं। हम यह देखने के दृष्टिकोण है कि इन गैरईसाई काम करने वाला के साथ न्याय हो। इस विषय पर और अधिष् कहने की हममें रिम्मत नहीं है। गंगा विन्दु नंगा लूटपाट का काम मवया अदृष्टपूर्व ही है। कोई जनता की घाड़ी गो नलाई करने वाली सरकार ऐम काम में शर्मिदा हो उठती। परंतु यह मानना प्रायद गमन नहीं कि ब्रिटिश सरकार ईसाई तथा ईमानदार सरकार है अतः उसे एम व आनद के लिए दूसरे को लूटन-भ्रमूटन का पूरा पूरा अधिचार प्राप्त है।<sup>120</sup>

अन्य समाचारपत्रों ने भी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया अभिव्यक्त की तथा विनिमय क्षतिपूर्ति भने की स्वीकृति को इन शब्दों में वर्णित किया 'लूट', 'दूर कृत्य', 'डावा'।<sup>121</sup> बनबारा की इण्डियन एसोसिएशन और पूना की मावजनिक सभा ने इस बायवाही के विरुद्ध भारत सरकार के पास विरोधपत्र भेजे।<sup>122</sup> 1893 में हुए अपने अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस भत्ते के विरुद्ध तीव्र विरोध अभिनितित किया।<sup>123</sup> पत्रत अगन 10 वर्षों तक कांग्रेस के बायप्रमा में, जारी भत्ते को समाप्त करने की माग के प्रस्ताव पास शा रह।<sup>124</sup> सरकार की इस बायवाही की निंदा में सभी मावजनिक नेता एगनुट श गए। उदाहरणार्थ सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इन बायवाही को एक पाप कृत्य और पाप में भी निरुद्ध कृत्य तथा 'परने दरजे का ल-जाजनक कृत्य' बतलाया। उन्होंने आक्षेप प्रकट करने हुए कहा कि गंगी बायवाही करने वाली सरकार का भी क्या मन्थ ईसाई तथा गंगी आरक्षण करने वाली सरकार कहा जा सकता है? <sup>125</sup> दादाभाई गोरोजीन इस बायवाही का विषय भारत में हस्त्यहीन, मनमाती और दूर हीना भ्रष्टी कहा और इन प्रादत्त के दुष्टार में भी मुग बनाया क्योंकि उमन गंग के अनुभार मांग का पीर मागा था परंतु यह सरकार तो भारतीयों का मून भी माप ही चुग रही है।<sup>126</sup>

भारतीय नेताओं ने विनिमय क्षतिपूर्ति भने के अत्याय का बर्गी तहरना और गंगी गंग के साथ हमति अनुभव किया कि भारत सरकार के बजट पर यह क्षतिपूर्ति भार उम गमन मादा गया था जब पत्र ही का जटिन कठिनाया में परमात भी नई पर-राजिया गंग चारा और मन्थ गंगी भी और दर पर गए करा के मगन का मन्थ उमगित श गया था जो गीमा मुन्थ का रूप में स्वीकृ ही माग आया।<sup>127</sup> बंगाल भार-तीव्र नताला का एका प्रतीय मुन्थ कि गंग कर विनिमय मुन्थवरा भने का शो प्रकण मन्थ और द कर मावारी अधिचारियों के स्थिति में उमगा जा रहा। भारतीय नेताओं के अत्याय का बायवाही मधमुष मुन्थ में गमन तक मन्थ रिना कर और इन पर भी मुग आजन गंग गंग का र मन्थ अधिरिण करा का भार उमन में मन्थ मन्थ मन्थ की बर्णन पर मन्थ का र उम मुन्थ अधिचारियों का मन्थ मन्थ करा का जो मुग मन्थ पर भी विचार कर मन्थ द।<sup>128</sup> 1893 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की

संबोधित करते हुए सुरेंद्रनाथ बँनर्जी ने इस समस्या का चित्रमय विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा 'उच्च वेतनभागी सरकारों अधिकारियों द्वारा सामायित प्रयुक्त मास-मदिरा जुटान के विषय अब अभावग्रस्त भारतीय को अपन गृह, चावल और नमक की मात्रा को परिमित करना पड़ेगा।<sup>109</sup> एक अन्य अत्यंत श्रद्धा समीक्षा नायबस्ट प्रॉक्स और अवध के जमी उल उलुम ने लिखा 'भारत तो इस अधिकारियों के लिए वेतन की कठिनता में जुटा पाता है जहां य हावू हमने भी अधिक कुछ और की मांग करते हैं।<sup>110</sup> A

राष्ट्रीय नेताओं का यह निश्चित मत था कि विनिमय क्षतिपूर्ति भत्ता न केवल भार रूप था प्रत्युत अनुचित और अनावश्यक भी था। उन्होंने चर्चा करते हुए सबसे प्रथम तो रुपये के स्वणमूल्य में गिरावट में भारत स्थित यूरोपीय अधिकारियों को वास्तव में कोई उल्लेखनीय क्षति नहीं पहुंची क्योंकि इंग्लैंड में भेजी जाने वाली रकम का घाटा वहां उच्च भोग वस्तुओं के स्वण मूल्य में गिरावट आ जाने में पूरा हो गया है अथवा दूसरे शब्दों में दादाभाई नौरोजी ने इस 1886 में इस प्रकार स्पष्ट किया 'यद्यपि यूरोपीय अधिकारियों का इंग्लैंड भेजे गए रुपये से पहले की अपक्षा थोड़ा साना मिलता है परंतु उस मोने की श्रयशक्ति पूर्वापेक्षा अधिक है।<sup>111</sup> द्वितीय, भारतीय नेताओं के अनुसार भारत स्थित सरकारी अधिकारियों के वेतन बहुत ही ऊंचे थे, विशेषतः इंग्लैंड और भारत के मध्य संचार माधनों और सुविधाओं में आए परिवर्तनों के मदद में तो विनिमय में आई गिरावट के प्राक्जुद व बहुत ही ऊंचे थे।<sup>112</sup> तृतीय, कमचारियों को यह स्थापित पाने का कोई अधिकार ही नहीं था क्योंकि वे तो केवल रुपये में ही वेतन पाने के लिए अनुबंधित थे। अतः विनिमय के अनुपात को बीच में घसीटना सबथा अनुपयुक्त है। जब रुपये का मूल्य अतीत में ऊंचा था और भविष्य में जिसके 2 प्रतिशत तक बढ़ जाने की संभावना थी, इन कमचारियों ने अनुबन्धित वेतन लेने में तो भूतबान में इनकार किया और न भविष्य में ही वे इनकार करेंगे।<sup>113</sup> इसके साथ ही गोखले महोदय ने टिप्पणी की 'सरकार रेल कंपनियों को अब भी 5 प्रतिशत की दर से सूद का भुगतान कर रही है जबकि अब वह 2½ प्रतिशत की दर में ऋण ले सकती है। उनका स्पष्ट कथा था 'यदि वर्तमान अनुबंधों को भारत के बजट के पक्ष में नहीं छोड़ा जा सकता तो उन्हें उसमें विपक्ष में क्यों छोड़ा जाए।<sup>114</sup>

भारतीय नेताओं का यह भी निश्चित मत था कि इस भत्ते के निणय में वस्तुतः सरकार 'व्याप्रीय तथा निष्पक्ष ही नहीं रह सकी है।<sup>115</sup> प्रथम, यह भत्ता वेतन के आधे भाग (चाहे विदेश भेजा गया हो अथवा नहीं) पर न दकर 'आस्तविक रूप से भेजी गई रकम पर ही देना चाहिए था। द्वितीय यह भत्ता केवल उही अधिकारियों को देना चाहिए था जिनके मेवा में आ जाने के उपरांत रुपये के मूल्य में गिरावट आई है न कि उन लोगों को जिन्होंने जानबूझकर रुपया में वेतन लेना स्वीकार किया है।<sup>116</sup> तृतीय भारत सरकार ने अपने मन्त्रियों को 'उनकी शिक्षा के लिए विदेशों में भ्रमण भेजने वाले भारतीय अधिकारियों को इस भत्ते के देने से इनकार करने पर निर्णय लेना चाहिए है।<sup>117</sup>

भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने इस सारे वाद से राजनीतिक परिणामों पर पहुंचने में

चूक नहीं की विशेषतः भारत में ब्रिटिश शासन के प्रयोजन को उतारने शीघ्र ही जान लिया। उन्होंने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि उसने भारतीय जनता के हितों के साथ खिलवाड़ किया है और उनकी रक्षा के स्वीकृत दायित्व को नहीं निभाया है।<sup>147</sup> उन्होंने शिकायत की कि जहाँ सरकार ने भारत की अत्यन्त अनिवाय आवश्यकताओं, सफाई, समाज सुधार और प्रशासनिक सुधार, को आर्थिक तर्कों के आधार पर पूरा नहीं किया है, वहाँ उसने विनिमय क्षतिपूर्ति भत्ते की स्वीकृति के रूप में भारतीय वित्तों पर अनुचित और अनावश्यक भार डालने में जरा भी सकोच नहीं किया।<sup>148</sup> 22 अगस्त 1893 में अमृत बाजार पत्रिका ने क्रोध होकर लिखा 'दिनों में लोगों की जान बचाने के लिए तो पैसा नहीं था, परन्तु भारतीय किसानों के भाग्य पर पहले में माटे हो रहे, भयंकर रूप से ऊँचे वेतनभोगी सरकारी कर्मचारियों को और अधिक मोटा करने के लिए पैसा है?' जी० के० गोखले ने भी इसी प्रकार की शिकायत की

जनता की शिक्षा पर नगण्य और शोचनीय सरकारी खर्चों में पिछले पाँच साल से इस आधार पर वृद्धि नहीं हुई कि सरकार के पास खर्च करने के लिए और अधिक पैसा है ही नहीं और इधर सरकार ने कलम की एक चोट से ही शिक्षा पर होने वाले सारे खर्च से भी अधिक बड़ी धनराशि यूरोपीय अधिकारियों को भेंट कर दी है।<sup>149</sup> भारतीय नेताओं ने इस बात की भी शिकायत की कि जहाँ उच्च वेतनभोगी ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन में परोक्ष वृद्धि हो गई है, वहाँ सरकारी कार्यालयों में कलक अथवा प्रबन्ध अधिकारियों के रूप में नियुक्त भारतीयों के वेतन में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई।<sup>150</sup>

इस सबने इस तथ्य की पुष्टि कर दी कि भारत पर एकात्मत इंग्लैंड के हितों की दृष्टि से शासन किया जा रहा था। वस्तुतः इस विषय पर चिन्तन में पर्याप्त सीमा तक कटुता उत्पन्न की। सामान्यतया आशावादी दादाभाई नौरोजी ने निराश होकर लिखा कि 'परन्तु, देखा यह गया है कि जब यूरोपीय हितों की बात सामने आती है तो कानून और दिल, दोनों हवा हो जाते हैं और वस्तुतः मान निरकुशता और शक्ति ही कानून और तब रह जाते हैं।'<sup>151</sup> मुरद्रनाथ बेनर्जी ने कटु व्यंग्य करते हुए टिप्पणी की

यह विनिमय प्रस्ताव एक मूर्तिमान सिद्धांत है जिसका भारत सरकार निरन्तर अनुसरण करती रही है। वह सिद्धांत क्या है? हम इस धरती के संपूत हैं हम इस धरती के दाम हैं—लकड़ी काटने वाले, पानी खींचने वाले सेवक हैं। हमारा अस्तित्व तो हम नौकरशाही रूपी भगवान की सेवा के लिए ही है।<sup>15</sup>

'गुजरात दपण' ने 31 अगस्त 1893 के अंक में अपने क्रोध और क्रोध को निम्नलिखित शब्दों में वाणी दी

हमारे देश की जनता के तथाकथित संरक्षकों की स्मृति में भी भगवान बचाए जिन्होंने इस देश के तीनों करोड़ लोगों को, जिनकी वे पैत्रिक स्नेह के साथ रक्षा का दावा करते हैं वास्तव में नरक में धकेल दिया है। जब हमें यह ध्यान आता है कि हमारा देश विनाश के गत में धकेला जा रहा है तो हमारे लिए समय संभव नहीं हो पाता। इस दश में बतखों की सेना में राजहंस इसलिए भेजे गए हैं कि इस देश के वासियों की रक्षा करें, उन्हें सुसम्भ बनाए, उन्हें सुधारें, उन पर शासन करें, उन पर पाव की ठोकर

मार्गे तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें मौन के घाट उतारें। भगवान, हम हमार इन टास्तो से बचाआ।<sup>153</sup>

बहुत सारे अन्य भारतीय नेताओं ने विनिमय धतिपूर्ति भत्ते द्वारा प्रदर्शित ब्रिटिश गानन की प्रवृत्ति तथा भारत में ब्रिटिश कमचारियों की भूमिका पर इसी प्रकार की तात्वी, आलोचनापरक टिप्पणियाँ की।<sup>154</sup>

## निष्पत्त

पूजगामी समीक्षा से यह निष्पत्त पुष्ट होता है कि भारतीय नेताओं ने रुपये के गिरत विनिमय के प्रति अपना दृष्टिकानन का निर्धारित करने में एक ओर स्पष्टत विनामगीन सूती वस्त्र उद्योग के और कृषका के हितों को प्राथमिकता दी और दूसरी ओर कुछ अन्य वर्गों और समुदाया के हितों की उपक्षा ही नहीं, उनका विरोध तक किया।

एक ऐसा समुदाय वेतनभोगी भारतीयों का था जिनमें अधिकांश सरकार द्वारा नियुक्त थे। इनमें अपथाकत उच्च वेतनभोगी वस्त्रे पैमाने पर आयातित सामान के उपभोगी थे, वे एक निश्चित आय ही प्राप्त करते थे टकमालों के बद होने के फलस्वरूप भारत में मूल्यों में आई गिरावट से यह वर्ग लाभ में था। राष्ट्रीय नेताओं द्वारा इनके हितों का विरोध प्रच्छन्न और मौन ही नहीं था प्रत्युत कभी कभी प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप भी ग्रहण करता था।<sup>155</sup> इसी प्रकार रुपये की मूल्यवृद्धि से श्रृणकर्ता साहूकार भी स्पष्टत लाभ में था। राष्ट्रीय नेताओं ने यहाँ भी मूल्यार के प्रति किसी प्रकार का पथापात न दिखाया प्रत्युत भारत सरकार की मुद्राभित्ति के विरुद्ध मूदखोर के मुद्रापरिवर्तन में लाभार्थित होने की संभावना का एक प्रमुख तर्क के रूप में ही प्रयोग किया। श्रृणकर्ताओं तथा वेतनभोगी कमचारियों पर पड़े कर्सेसी लैजिस्लेशन प्रभाव के प्रति राष्ट्रवादियों का दृष्टिकानन डी०ई० वाचा के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नवम अधिवेशन में किए गए भाषण के निम्न लिखित अवतरण में अपन संक्षिप्त रूप में इस प्रकार है कठोर धम करने वाले श्रमिका तथा करो के भार से लबे किसानों का डमलिए दरिद्र बनाया जा रहा है ताकि उनके मूल्य पर सरकारी कमचारी और मूदखार मोट हो सकें।<sup>156</sup> इसके अतिरिक्त उन्होंने दैनिक वेतनभोगी मजदूरों, जिनकी मजदूरी का मूल्यवृद्धि की दशा में पिछड़ जाना और लूमरी और मूल्यों में गिरावट जाने पर लाभ में आ जाना स्वाभाविक था—के हितों की भी उमी कारण से कोई चिंता नहीं की। यह भी कम आश्चर्यप्रद नहीं कि स्वयं भारतीय नेताओं ने एक भिन्न सदम में ही सही निधन श्रमिकों, कषका के और मूल्य के बीच मह मध्य को उच्च स्तर में स्वीकार किया और उस पर दृढ विश्वास प्रकट किया।<sup>157</sup> हा, मुद्रा सम-न्याओं पर विचार करते समय यह विषय उनकी मगणनाओं से छूट गया।<sup>158</sup>

मुद्रानीति के निर्धारण में राष्ट्रीय नेताओं द्वारा सर्वाधिक उपेक्षित और यहाँ तक कि विरोध का शिकार व्यापारी वर्ग विनोपत सामग्री के आयात व्यापार में सलग्न व्यापारी वर्ग था। निम्नलिखित तथ्या में इस कथन की सुस्पष्ट और समुचित पुष्टि हो जाती है

(क) प्रथम, त्रमाकि पहले निर्देश किया जा चुका है, भारतीय नेताओं ने दशा के लिए सही मुद्रानीति के प्रदन पर निणय लेते हुए विदेश व्यापार की समृद्धि को एक

विचारणीय विषय नहीं बनाया।<sup>159</sup>

(ए) द्वितीय, भारतीय नेताओं द्वारा अभिगसित मुद्रानीति विदेश व्यापार में सलग्न व्यापारियों के बहुत बड़े समुदाय तथा उनके प्रवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत भाग के विपरीत थी। उदाहरणार्थ, 1892 में बंगाल के राष्ट्रीय वाणिज्य मदन की पाचवीं वार्षिक बैठक में अध्यक्षीय भाषण करते हुए रायबहादुर धनपतिमिह ने निम्नलिखित चेतावनी दी 'वर्तमान विनिमय दर व्यापार पर घातक प्रहार है और यदि रजत मूल्य में वृद्धि के तत्काल उपाय न किए गए तो वह दिन दूर नहीं जब व्यापार का बड़ा गन्ना हो जाएगा और कलकत्ता की अनेक प्रतिष्ठित कपनिया बंद हान पर विवश हो जाएगी।<sup>160</sup> जब 1892 में इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने टकराल बंद करने और स्वणमान ग्रहण करने का प्रयत्न आंदोलन प्रारंभ किया तो भारतीय व्यापारियों का एक बहुत बड़ा समुदाय मंत्रिय समर्थक के रूप में इस आंदोलन में सम्मिलित हुआ गया।<sup>161</sup> जून 1892 में कराची के 77 प्रमुख व्यापारियों ने और अक्टूबर 1892 में बंबई के 674 व्यापारियों ने सरकार को मानपत्र दिया, जिसमें रुपये के मूल्य को स्थिर करने का अनुरोध किया गया था और इसके लिए तब यह दिया गया था कि रुपये के मूल्य में उतार-चढ़ाव में उनसे सुरक्षित व्यापार के 'याचोचिन लेन देना में विगुह रूप से अनिश्चितता और जुएवाजी की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है।<sup>162</sup> बंबई के अग्रणी व्यापारी तथा महाजन सर शापुरजी भन्सा ने टकमाला के बंद होने के उपाय की तथा रुपये के स्वणमान अपनाने की प्रयत्न बहाल की। उनके मतव्य का आधार था कि रुपये के गिरते मूल्य ने भारत के विदेश व्यापार का बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया है तथा विदेशी पूँजी के भारत में प्रवाह को बाधा पहुँचाई है।<sup>163</sup> इसी प्रकार 1898 में बंगाल के प्रतिष्ठित व्यापारी जयगाविंद लाल ने सरकार पर विनिमय की व्यावहारिक स्थिरता का प्राथमिकता देने के लिए दबाव डाला।<sup>164</sup>

(ग) अतः, कुछ भारतीय नेता तो विदेश व्यापार में सलग्न व्यापारियों (जिनमें से अधिकांश सभी प्रकार से विदेशी ही थे) के प्रति माचजनिक रूप से शत्रुता प्रकट करने लगे और उन्हें परामर्श देने लगे कि उन्हें अवसर के अनुकूल बदलना चाहिए, बड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं।<sup>165</sup> दादाभाई नौरोजी के निम्नलिखित आवेगपूर्ण शब्दों में इस विरोध की अभिव्यक्ति स्पष्ट है

सबसे ऊपर स्वण मुद्रा के लिए सधप करता हुआ व्यापारी बँठा हुआ है जो यह चाहता है कि किसानों की बलि चढ़ाकर उसे उसका व्यापारिक खतरो से बचाया जाए। व्यापार के लाभ तो इस व्यापारी की अपनी ही जेबों में जाएँ और व्यापारिक उथल-पुथल के खतरे के चारों किसान उठाएँ। गरीबी में जकड़ा किसान इन खाते पीते व्यापारियों को बचाएँ। भगवान, भारत की रक्षा करो।<sup>166</sup>

विदेश व्यापार में सलग्न व्यापारियों और उनकी माँगों के प्रति तथा सूती कपड़ा उत्पादकों के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण में एक राक्षक अंतर स्पष्ट रूप में मिलता है। भारतीय राष्ट्रीय नेताओं का मुद्रानीति के प्रति न केवल दृष्टिकोण ही प्रत्युत उस दृष्टिकोण के निर्धारक कारण भी बंबई के सूती वस्त्र मिलमालिकों द्वारा प्रस्तुत कारणों से मिलते जुलते हैं। यह तथ्य बंबई मिल ओनर्स एसोसिएशन के 1893, 1898, 1899, 1900 और 1901 के



का घटाण, दम रूप में कि सबसे प्रथम सरकार भारत में ही भंडारा की खरीद करे और अधिक से अधिक भारतीयों को ही सवाजा में नियुक्ति कर। कुल मिलाकर निम्न विनियम न गृह प्रभाग की गमम्या का उजागर किया। यह दावा रूपा में महंगा उपचार था और सामान्य स्थिति में इस अपमान का परामर्श ही न दिया जाता, परंतु भारतीय नेताओं ने न दाचित अनुभव किया कि भारत जस एक अमान्याय स्थितिवाले देश के लिए यही एकमात्र उपलब्ध उपचार था।

## संदर्भ

- 1 उदाहरणार्थ रूपसे भारतीय मुद्रा इतिहास के संपिण्ड विवरण के लिए निम्नलिखित पुया का आश्रय लिया है जे० एम० कामराजी दि इंडियन करसा गिस्टस 1875 1926 (मार्ग 1930), एच० एन० चावतानी स्टडीज इन इण्डिया करेसी एंड एक्मचेंज (बंबई 1931), सी० एन० बशीत तथा एस० के० मुराजन करसी एंड प्राइमस इन इंडिया (बंबई 1927) डा० के० मन्होला हिस्टरी ऑफ प्राइमस आफ इंडियन करसी—1835 1945 (साटोर, 1945 तनीय संस्करण) जे० एम० वास इण्डियन करसी एंड फाइनेस (लंदन 1913 1924 में पुन मुद्रित) परिमल राय पूर्वोद्धत
- 2 इंग्लंड और भारत के कुछ लोगों ने सोचा कि विनियम की गिरती दर 1873 के परवर्ती 20 वर्षों की अवधि में भारत के विदेश व्यापार के द्रुतविकास लगभग दुगना करने के लिए उत्तरदायी है परंतु इस धारणा पर किसी भी स्थिति में विश्वास न किया गया था और न ही विश्वास किया जाता है व्यापारी वर्ग को इस बात का यकान था कि गिरती विनियम दर का उसके व्यापार पर बियना प्रभाव पड़ रहा है तथा देखिए रिपोर्ट आफ दि इंडियन करेसी कमिटी—1893 कडिका 25 व और फार्नेशल स्टेटसमट—1886-87, कडिका 2 और 1891 2 (कडिका 36)
- 3 विभिन्न सवाजा नागरिक धर्मोपदेश नीतिना तथा स्थल सना में तय यूरोपीय अधिकारियों के सिस्टमडन द्वारा 31 जनवरी 1893 को गवर्नर जनरल तथा इंडियन करेसी कमिटी को प्रस्तुत प्रतिवेदन साम्य के विवरण तथा परिशिष्ट 1893 सी-7060 II अनुमानत 1 से एन्वोजर 39
- 4 भारत के तीन उत्तराधिकारी वायसरॉयों ने इस विषय पर बल दिया लसडोन स्पीचेज पड II प 621 एनथिन, स्पॉन्ज प० 489 कजन स्पोजेज खड II प० 276 तथा देखिए, रिपोर्ट आफ दि इंडियन करेसी कमिटी 1893 कडिका 28
- 5 इंपारियल गजटियर आफ इंडिया (1908) खड IV प० 195
- 6 बकीन और मुराजन पूर्वोद्धत प० 40
- 7 भारत राज्य सचिव का ध्यान को निष्ठा रखा पत्र दिनांक 26 जनवरी 1886 भारत राज्य सचिव की ओर से भारत सरकार को संप्रण के साथ मलम स० 6 फीनांक 28 जनवरी 1886 तथा देखिए, रिपोर्ट आफ दि इंडियन करेसी कमिटी 1893 कडिका 34
- 8 उदाहरणार्थ देखिए फाइनेशल स्टेटसमटस 1883-4 (कडिका 136), 1886-7 (कडिका 1, 2 123) और 1893-4 (कडिका 28 30 31)
- 9 लसडोन एल० सा० पी० 1893 खड XXXII प० 282 3
- 10 जी० ह्यू० फारेस्ट ऐडमिनेस्ट्रेशन आफ दि मारकिंग आफ लैसटोन एज वायसरॉय एंड गवर्नर

जनरल आफ इंडिया, 1888 1894 पृ० 35 6 इंडियन करसी एसोसिएशन के विस्तृत दृष्टिकोण के लिए देखिए, प्रोसीडिंग्स आफ दि पब्लिक मीटिंग आफ दि इंडियन करसा एसोसिएशन, 13 जुलाई 1892 और लसडोन स्पेचेज खंड II पृ० 518 20 भारतीय व्यापारियों की धारणा के लिए देखिए बंगाल नेशनल चंबर आफ कामर्स के पाचवे वार्षिक अधिवेशन में मडल के अध्यक्ष का भाषण ए० बी० पी० 29 मई 1892 और एस० बी० भारुचा स्पीचेज आन इंडियन इकोना-मिक्स (बंबई तिथिरहित) पृ० 2-9

- 11 सुवर्ण विनिमय मान का अस्तित्व दश में उस समय तक कहा जा सकता है जबकि उसका प्रचलन उल्लेखनीय परिमाण में न हो जब स्थानाय मुद्रा स्वर्ण में आवश्यक रूप से बदलने के योग्य न हो और जब केवल सरकार अथवा सामान्य बैंक ही विदेशों में रुपये के प्रेषण का व्यवस्था स्थानीय मुद्रा के सदृश मं साने के 'यूनतम निर्धारित मूल्य पर करत हा विदेशों में उल्लेखनीय परिमाण में सुरक्षित भंडार इन धन प्रेषणा की आवश्यक व्यवस्था करते हैं (केस पूर्वोद्धत पृ० 30-1)
- 12 प्रथम विश्वयुद्ध तक इन वर्षों में बड़े पैमाने पर टक्कर हुआ 1899 1902 1903 1904 1905 1906 1911 और 1912 इन वर्षों में टक्कर स्पष्ट का विशुद्ध परिमाण क्रमशः इस प्रकार था 169 करोड़ 111 करोड़ 78 करोड़ 169 करोड़ 234 करोड़ 157 करोड़ 124 करोड़ और 163 करोड़ (बकील और मुराजन-पूर्वोद्धत पृ० 408)
- 13 केस पूर्वोद्धत पृ० 133, उन्होंने व्यर्थपूर्वक कहा है (भारत सरकार) जपनी नीति इस प्रकार की बनात हैं जिसे इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक समुदाय न उसी बन्ती भूख के साथ मुद्रा का उपभोग किया जिस प्रकार कुछ समुदाय बीयर का उपभोग करते हैं — (पृ० 134)
- 14 उदाहरण के लिए देखिए 1908-09 के बजट पर गोखले का भाषण स्पीचज पृ 177 80
- 15 केस पूर्वोद्धत पृ० 6
- 16 एस० एन० बनर्जी स्पीचेज I पृ० 198 द्वादश प्रकाश 7 अगस्त (आर० एन० पी० बब 12 अगस्त 1876) बाबे समाचार 5 मई 1879 और 9 नवंबर 1880 (वही 10 मई 1879 और 13 नव 1880 क्रमशः) बंगाली 11 जून 1881 ब्रह्मा पब्लिक ओपीनियन 23 जून 1881, हिंदू 10 अप्रैल 1885 मराठा 23 मई 1886, रीम गेंड रपट 29 मई लिबरल 30 मई (बी० ओ० आई० जून 1886) इंडियन स्पेक्टेटर 18 जुलाई (वही अगस्त 1886), भारतवासी 23 जून (आर० एन० पी० बग० 30 जनवरी 1886), समय 8 मार्च (वही 13 मार्च 1886) साधारणी 4 अप्रैल (वही 10 अप्रैल 1886) सहचर 9 जून नवविभाकर 14 जून (वही 19 जून 1886) नौरोजी एसेज पृ० 374 हिंदुस्तान 22 जून (आर० एन० पी० पी० एन० 26 जून 1888) यह आश्चर्यजनक है कि जी० बी० जोशी चांदी के सोने का भ्रय करन मूल्य में गिरावट से असंतुष्ट नहों थे उनका विचार था कि शीघ्र ही मांग और पूर्ति का नियम सतुनन ला देगा और कदाचित चांदी के पक्ष में ऊंचे मूल्य की प्रवृत्ति ही ला देगा (पूर्वोद्धत पृ० 118 128 9)
- 17 बंगाली 11 जून 1881 ब्रह्मा पब्लिक ओपीनियन 23 जून 1881 नौरोजी एसेज पृ० 514-20 इंडियन स्पेक्टेटर 18 जुलाई (बी० ओ० आई० अगस्त 1886)
- 18 इंडियन स्पेक्टेटर 17 जनवरी (आर० एन० पी० बब 23 जनवरी 1886) मराठा 4 अप्रैल 1886 इंडियन स्पेक्टेटर 18 जुलाई (बी० ओ० आई० अगस्त 1886) हिंदू 8 11 15 जून 4 सितंबर 1886 अगस्त 1886 के 'वायन आफ इंडिया के अनुसार उस समय के भारतीय समाचारपत्र इन पर सामान्य रूप से एकांत थे

- 19 इंदु प्रकाश 7 अगस्त (आर० एन० पी० वग 12 अगस्त 1876), इंडियन स्पेक्टेटर 17 जनवरी (वही 23 जनवरी 1886) समय, 17 मार्च (आर० एन० पी० वग०, 22 मार्च 1884), इंडियन स्पेक्टेटर 18 जुलाई (वा० ओ० आई० अगस्त 1886) समय, 22 अक्टूबर (आर० एन० पी० वग० 23 अक्टू० 1886) जी० या० जागी इस सचप म गिर अपवाद रूप से उन्होंने म्पयो के श्रृण के स्थान पर स्टेलिग ऋण की नीचा पकडन का परामर्श दिया क्याकि स्मिग को व्याज दर कम थी उनका विश्वास था कि विनिमय की गिरावट के लिए अर्थात् उन सस्ते धन के लाभ को निष्प्रभावित करना लगभग असमय ही होगा (पूर्वोद्धत पृ० 118 128)
- 20 बाबे समाचार 3 सितंबर 1880 31 मार्च 1882 (आर० एन० पी० वग, 4 सितंबर 1890 1 अप्रैल 1882 तमश), बंगाली 11 जून 1881, ब्रह्मो पत्रिका ओपीनियन 23 जून 1881 नवविभाकर 5 अप्रैल (आर० एन० पी० वग० 10 अप्रैल 1886), सहचर, 9 जून (वही 19 जून 1886)
- 21 इंदु प्रकाश 7 अगस्त (आर० एन० पी० वग 12 अगस्त 1876) न्याय प्रकाश 6 सित० (वही 11 सित० 1880) नवविभाकर 12 अप्रैल (आर० एन० पी० वग० 22 मई 1896) हिंदुस्थान 22 जून (आर० एन० पी० वग० 22 जून 1888) सहचर, 8 अप्रैल (आर० एन० पी० वग० 18 अप्रैल 1891)
- 22 इंदु प्रकाश 7 अगस्त (आर० एन० पी० वग 12 अगस्त 1876) ब्रह्मो पत्रिका ओपीनियन, 23 जून 1881 मराठा 16 मार्च 1884
- 23 मिस्टर फोसे के एसेज जान इंडियन फाइनाम, जे० पी० एम० एम० खंड III सधन 1 (जुलाई 1880) प० 80
- 24 बाबा स्पीचेज, पृ० 375
- 25 बाबा स्पीचेज प० 379 मराठा 4 सितंबर 1892 पान प्रकाश 1 सितंबर हिन्दु 1 सित० (आर० एन० पी० वग 3 सितंबर 1892), गुजरात दपण 22 सितंबर (वही 24 सितंबर 1892) वत्तल पत्रिका 13 अक्टूबर (आर० एन० पी० एम० 15 अक्टूबर 1892) हिंदुस्तानी 22 जून (आर० एन० पी० एम० 29 जून 1892) रहबर 8 जुलाई (वही 27 जुलाई 1892)
- 26 एम० एच० वकील सि करेंसी प्रान्तम इन इंडिया ऐंड सर इविड वारवर, सि ऐंग्लो इंडियन ऐंड सि रूपी (वर्ग 1892) प० 2 (एक भारतीय नेत्रव द्वारा मुद्रा समस्या का कल्पित यह प्रथम विस्तृत समीक्षात्मक विश्लेषण था) मराठा 4 सितंबर 1892 गुजरात दपण 22 सितंबर (आर० एन० पी० वग 24 सित० 1892) आर० सी० दत्त इंडियन पालिटिक्स प० 51 2
- 27 मराठा 4 सितंबर 1892 12 मार्च 1893 ए० बी० पा० 31 जुलाई 1892 8 फरवरी 1893 बंगाली 4 फरवरी 1893 एम० एच० वकील पूर्वोद्धत प० 2 बाबा स्पीचेज प० 376-8 387 90 गीरोजी 1893 की करेंसी कमेटी में गीरोजी का वक्तव्य पावर्टी पृ० 560 तथा हाउस आफ कमन्स में दिया गया भाषण हसाड चतुथ भासा खंड IX बानध 655 7 बदवान सबी वनी 14 जून (आर० एन० पी० वग० 25 जून 1892) दैनिक ओ समाचार चंद्रिका 13 जुलाई (वही 16 जुलाई 1892), पान प्रकाश 1 सित० (आर० एन० पी० वग 3 सितंबर 1892) गुजरात दपण 22 सितंबर (वही 22 सितंबर 1892) बाब समाचार, 28 अक्टूबर (वही 29 अक्टूबर 1892) एम्बोचेट 10 जून (वा० ओ० आई० 19 जून 1892) वत्तल पत्रिका 13 अक्टूबर (आर० एन० पी० एम० 15 अक्टूबर 1892) हिंदुस्तानी 22 जून (आर० एन० पी० एम० 29 जून 1892) रहबर 8 जुलाई (वही 27 जुलाई 1892) बंगाली के 18 फरवरी

1893 के घब म प्रस्तुत इंडियन एगोसिएशन द्वारा 1892 म हाउस आफ कामस का दिया गया  
 ज्ञापन बगनिवासी 17 फरवरी (आर० एन० पी० बग० 25 फरवरी 1893) बगवासी, 18  
 25 फरवरी (वही 25 फरवरी 4 मार्च 1893) हिमालय 10 मार्च (आर० एन० पी० पी०  
 18 मार्च 1893) आफनाथ पजाब 29 मई (वही 10 जून 1899) यही दृष्टिकोण नौराजी  
 1896 म पहले हा अपने निबंधो म प्रस्तुत कर चुके हैं एसेज पृ० 518 और आग हिंदू ने भी  
 4 मित० 1889 के घब म यही विचार प्रकट किया था

28 प्रस्ताव IV

29 भारत सरकार का भारत राज्य सचिव को संप्रपण सख्या 160 तिथि 21 जून 1892 लाड  
 एलगिन द्वारा सरकारी मुद्रानीति के जनसमर्थन का पत्रा दावा भी बराबर झूठ आधारों पर  
 किया गया स्वीचज पृ० 51 और लाड वजन स्वीचज I, प० 118 हाल म परसीवल स्पीयर  
 ने भी यह गलत धारणा व्यक्त की कि (काप्रस के) वाणिज्य से संबंधित पश्चिमी भारतीय सदस्यों  
 ने रुपये के विनिमय मूल्य म गिरावट को रोक न पान के लिए सरकार की आलोचना की है  
 इंडिया, ए माइन हिस्टरी (एन आबर 1961 प० 312)

30 ए० बी० पी०, 29 जून, 5 6 जुलाई 1893 बगवासी 1 जुलाई 1893 मराठा 2 जुलाई 1893  
 हिंदु प्रकाश 3 जुलाई 1893 हिंदू 10 अगस्त 12 सितंबर 1893 गुजराती 2 जुलाई बाबे  
 समाचार 3 और 4 जुलाई क सरे हिंद 2 जुलाई 9 जुलाई 20 जुलाई (आर० एन० पी० बब  
 8 15 22 जुलाई 1893 क्रमश) आय जन प्रियान 8 जुलाई केरल पत्रिका 8 जुलाई (आर०  
 एन० पी० एम०, 15 जुलाई 1893) वलात पत्रिका 7 सित० (वही 15 सितंबर 1893)  
 हिंदुस्तानी 5 जुलाई (आर० एन० पी० एन० 11 जुलाई 1893) हितवादी 29 जून दैनिक  
 ओ समाचार चंद्रिका 2 5 जुलाई (आर० एन० पी० बग०, 8 जुलाई 1893) बगवासी  
 8 जुलाई वही 15 जुलाई 1893) हिमालय 14 जुलाई (आर० एन० पी० पी० 29 जुलाई  
 1893) कोहेनूर 29 जुलाई ताज जल अखबार 29 जुलाई (वही 12 अगस्त 1893) अपवाद  
 रूप केवल सहचर 28 जून (आर० एन० पी० बग० 8 जुलाई 1893) बग निवासी 7 जुलाई  
 (वही 15 जुलाई 1893) हिंदुस्तान 8 जुलाई (आर० एन० पी० एन०, 11 जुलाई 1893) के

31 आई० एन० सी० 1893 का प्रस्ताव XIV इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले और बदल म  
 स्वर्णमान को समर्थन देने वाले एकमात्र प्रतिनिधि हिंदुस्तान समाचारपत्र के मालिक राजा  
 रामपाल सिंह थ (रिप० आई० एन० सी० 1893 प० 133)

32 रिप० आई० एन० सी० 1893 पृ० 128 130 1

33 वाचा रिप० आई० एन० सी० 1898 प० 98

34 कसरे हिंद 8 मई इंडियन स्पेक्टेटर 8 मई ज्ञान प्रकाश 9 मई (आर० एन० पी० बब 14 मई  
 1898), कसरे हिंद 15 मई गुजराती 15 मई (वही 21 मई 1898) तोहफा ए हिंद 13 मार्च  
 (आर० एन० पी० एन० 23 मार्च 1898) हिन्दी प्रतीय मई और जून (वही 13 जुलाई 1898)  
 इसका अपवाद था—अखबार ए आम 24 जून (आर० एन० पी० पी० 9 जुलाई 1898)

35 नौराजी पावर्टी पृ० 532 545 और इंडिया 20 मई 1898 प० 317 और 8 जुलाई 1898  
 प० 11

36 आर० सी० दत्त का 1898 की बरेंसी कमेटी के समक्ष साक्ष्य दत्त स्पीचज I पृ० 93

37 वही प० 76 82 91 3 104 तथा इंडिया में 11 नव 1893 को पुन मुद्रित माचेम्टर गार्जियन  
 को लिखे उनके पत्र

- 13 फरवरी 1894 29 सित० 1898 मराठा 31 जुलाई, 9 अक्टू०, 4 सित० 1892, 12 मार्च 1893 बंगाली 4 फरवरी 1893, 28 जून 1898 हिंदू 10 अप्रैल 1885, 8, 15 जून 1886 22 अगस्त 1893 5 8 जुलाई 1895, इंडियन स्पेक्टर 18 जुलाई (बी० ओ० आई० अगस्त 1886) विहार द्वारा 18 फरवरी (वही 18 मार्च 1894) पंजाब अगस्त 6 जुलाई (आर० एन० पी० पी० 16 जुलाई 1898) एम० एन० बनर्जी न 1879 और 1881 म ही (यद्यपि थोड़ा अस्पष्ट रूप से) यह विशेषण प्रस्तुत किया था दखिण, एम० एन० बनर्जी स्पष्टित I पृ० 198 और बंगाली 11 जून 1891 अपने तक की पुष्टि में दादाभाई नौरोजी न 1873 में इंडिया करेंसी कमीटी को भेज गए प्रतिबन्धन में राज्य सचिव द्वारा 26 जनवरी 1886 को कोषागार को निवा पत्र उद्धृत किया यह कहने की आवश्यकता नहीं कि भारत सरकार को इंग्लैंड को स्वयं मुद्रा के रूप में जो अनिवाय भुगतान करने पड़ते हैं उनके फलस्वरूप ही रुपये के वित्तीय मूल्य में आई गिरावट से सरकारों वित्त प्रभावित हो रहे हैं (पावर्टी पृ० 543)
- 57 नाथन ए० मिटजलर, दि प्योरी आफ इन्टरनेशनल ट्रेड, ए गवर्न आफ वाइपररी इकोनॉमिक्स, हावर्ड एम० एलिस द्वारा संपादित (विनिपादन, 1948) पृ० 221
- 58 नौरोजी पावर्टी पृ० 529 531 554 55 एसेज, पृ० 512 516-7 और इंडिया 20 मई 1888, पृ० 317 ए० बी० पी०, 1 अप्रैल 1886 10 जुलाई 1892 हिंदू 11 जून 1889 5 जुलाई 1895 इस संबंध में अमल बाजार पत्रिका न 17 जुलाई 1892 व मंत्र में बना हुआ साधन-सुधार तथ्य प्रस्तुत किया उसने लिया रुपये के अवमूल्यन का परिणाम सामान्यतया निर्यात में बढ़ि हानी और उसके फलस्वरूप चांदी के आयात बढ़ जाते हुए का परिणाम यह होता कि भारत में चांदी के मूल्य और ऊंचे बढ़ जाते ताकि चांदी के मूल्य में भारत में और बाहर के देशों में समान रूप से अवमूल्यन हो जाता परंतु यहाँ यह आर्थिक तथ्य और श्रृंखला विच्छिन्न हो गई है इसका कारण यह है कि धन की शिफासी ने भारत के अतिरिक्त आयात को निगल लिया है और इसका परिणाम यह हुआ है कि भारत के निर्यात का मूल्य गिर गए हैं और इससे देश को हानि पहुँची है
- 59 एम० एन० बनर्जी स्पॉन्स I पृ० 198 ब्रह्मो पब्लिक ओपीनियन 23 जून 1881 वाचा स्पेशिज पृ० 381, ए० बी० पी० 8 फरवरी 1893
- 60 बवई मिल बोस एसोसिएशन 1898 की रपट पृ० 90
- 61 वाचा स्पेशिज पृ० 381 पी० एम० डब्ल्यू, ई ए, पृ० 357
- 62 नौरोजी एसेज पृ० 517 और पावर्टी पृ० 543-4, मराठा 31 जुलाई 1892 बंगाली 28 जून 1898 कसने हिंदू 15 मई (आर० एन० पी० बव, 21 मई 1898)
- 63 वाचा रिप० आई० एन० सी० 1898 पृ० 101 02 तथा नौरोजी एसेज, पृ० 516-7 और पावर्टी पृ० 545 6 576 बवई प्रसीडेंसी एसोसिएशन का स्मरणपत्र लिखि 27 अगस्त 1886 यूरोपीय स्वयं वाचा रिप० आई० एन० सी० 1892 पृ० 84 और रिप० आई० एन० सी०-1898 पृ० 101-04 दन स्पेशिज I पृ० 93 97 8 इंडिया, 11 नवंबर 4 सित० 1898 पृ० 262 ई एच II पृ० 582, 585 ब्रह्मो पब्लिक ओपीनियन, 23 जून 1881 मराठा 31 जुलाई 28 अगस्त 4 नितंबर और 9 अक्टू० 1892 तथा 12 मार्च 1893 ए० बी० पी 27 मार्च 1892 8 फरवरी 1893 13 फरवरी 10 मार्च 1894 29 सित० 1899 हिंदू 21 मई 1894 8 जुलाई 1895 इंडियन एसोसिएशन की हावस आफ वामम की मासिका 25 फरवरी 1893 के बंगाली में इंडियन स्पेक्टर 18 जुलाई (वा० ओ० आई०, अगस्त 1886 पृ० 392)

- हिंदुस्तानी, 22 जून (आर० एन० पी० एन०, 29 जून 1892) बिहार हेराल्ड, 18 फरवरी (बी० ओ० आई०, 18 मार्च 1894 पृ० 216), ज्ञान प्रकाश, 9 मई (आर० एन० पी० बब 14 मई 1898) कसरे हिंदू, 15 मई (वही 21 मई 1898)
- 64 दत्त स्पीचेज I प० 93 तथा नौरोजी पावर्टी प० 545 575 6 वाचा रिप० आई० एन० सी० 1898 प० 104 हिंदुस्तानी 24 अगस्त 1892, 8 फरवरी 1893 (आर० एन० पी० एन० 31 अगस्त 1892 15 फरवरी 1893 क्रमशः) 1893 में इंडियन एसोसिएशन की हाउस आफ कामस को याचिका 25 फरवरी 1893 के बंगाली में ए० बी० पी० 13 फरवरी 1894 पान प्रकाश 9 मई (आर० एन० पी० बब, 14 मई 1898) कसरे हिंदू 16 जुलाई (वही, 22 जुलाई 1899) दत्त, इंडिया, 11 नवंबर 1898 पृ० 262
- 65 ज्ञान प्रकाश 1 सितंबर हितेच्छु 1 सित० (आर० एन० पी० बब 3 सितंबर 1892), 1893 में इंडियन एसोसिएशन का हाउस आफ कामस को गान 25 फरवरी 1893 के बंगाली में, पान प्रकाश 9 मई (आर० एन० पी० बब 14 मई 1898) तोहफा ए हिंदू, 13 मार्च (आर० एन० पी० एन 23 मार्च 1898)
- 66 आई० एन० सी 1898 का प्रस्ताव XIII नौरोजी पावर्टी प० 575
- 67 अमृत बाजार पत्रिका में 17 जुलाई 1892 के अक म लिखा विनिमय की कठिनाई एक प्राकृतिक चेष्टा है भारत को प्राकृतिक स्वस्थ स्थिति में लाना भले ही कठिन हो यह संपत्ति को अप्राकृतिक निकासी के, प्रति विरोध है जिसका शिकार भारत को बनाया जा रहा है तथा देखिए ए० बी० पी० 1 अप्रैल 1886 हिंदुस्तानी, 24 अगस्त (आर० एन० पी० एन० 31 अगस्त 1892) बंगाली 4 फरवरी 1893 नौरोजी सी० पी० ए० पृ० 177
- 68 ए० बी० पी० 17 जुलाई 1892, बंगाली 3 सितंबर 1892
- 69 वाचा स्पीचेज परिशिष्ट प० 31 42 सी० पी० ए० प० 617 दत्त स्पीचेज I प० 71 5 103 ई एच II प० 578
- 70 ए० बी० पी० 9 अप्रैल 1893 15 मार्च 1894 कसरे हिंदू इंडियन स्पेक्टेटर 11 मार्च, इंदु प्रकाश 12 मार्च (आर० एन० पी० बब 17 मार्च 1894) पी० मेहता, स्पीचेज प 445 6 पावर्टी पृ० 281 2 एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए० प० 243 5 वाचा स्पीचेज परिशिष्ट प० 6 16-19 रिप० आई० एन० सी० 1892 पृ० 84 रिप० आई० एन० सी० 1898, प० 101-02 सी० पी० ए०, प० 617 नदी इंडियन पालिटिक्स पृ० 128 30 दत्त स्पीचेज I प० 103 ई एच II प० 583 तथा आई० एन० सी०-1895 का प्रस्ताव III
- 71 हितेच्छु 1 सित० (आर० एन० पी० बब 3 सित० 1892) इंडियन एसोसिएशन का हाउस आफ कामस को 1893 में प्रस्तुत याचिका बंगाली के 25 फरवरी 1893 के अक में प्रकाशित, ए० बी० पी० 9 अप्रैल 1893 29 सितंबर 1898 बंगाली 1 जुलाई 1893 बिहार हेराल्ड 18 फरवरी (बी० ओ० आई० 18 मार्च 1894) नौरोजी पावर्टी प० 539-40 544 दत्त स्पीचेज I प० 93, 103 104 कसरे हिंदू 15 मई 1898 16 जुलाई 1899 (आर० एन० पी० बब 21 मई 1898 22 जुलाई 1899 क्रमशः)
- 72 वाचा रिप० आई० एन० सी० 1898 प० 102-04 तथा रिप० आई० एन० सी० 1894 प० 132 3 स्पीचेज परिशिष्ट प० 9 31 41 43 सी० पी० ए०-पृ० 617
- 73 1893 में हाउस आफ कामस को इंडियन एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत याचिका, बंगाली के 25 फरवरी 1893 के अक में प्रकाशित

- 74 नौरोजी सी० पी० ए० पृ० 177
- 75 आई० एन० सी० 1893 का प्रस्ताव XIV तथा आई० एन० सी० 1901 का प्रस्ताव XVII
- 76 एम० एच० वकील पूर्वोद्धृत पृ० 4 19 मराठा, 9 अक्टूबर 1892 2 जुलाई 1893 कसरे हिंद 9 जुलाई (भार० एन० पी० बव, 15 जुलाई 1893), ए० बी० पी० 29 सितंबर 1898 वाचा स्पीचेज पृ० 389 90 सी० पी० ए०, पृ० 611, 614 पी० महता स्पीचेज पृ० 362 574-5 604 जी० एस० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1898 पृ० 106-07, एच० आर० जून 1901 पृ० 441, ई ए पृ० 120-1 रिप० आई० एन० सी० 1904, पृ० 175 दस स्पीचेज I, पृ० 70 76-7 ई एच II, पृ० 458 579 80 596 598 इंडिया, 11 नव० 1898 ज० ए० बाहिया पूर्वोद्धृत पृ० 95 129, गोडले स्पीचेज पृ० 14 75 77, बी० डी० ठाकरसी रिप० आई० एन० सी० 1902 पृ० 99, नेसरो 31 मार्च (भार० एन० पी० बव 4 अप्रैल 1903) वस्तुतः 1893 की मुद्रा समिति न इन तक की साक्षरता को स्वीकार किया था और निघा था हम यह मानकर चल रहे हैं कि वर्तमान अनुपात अपना दानपत्र कर का कुछ अंतर बना रहेगा ऐसा मानने के मुताबिक रुपये के मुद्रा का वर्तमान स्तर में एकदम से कोई परिवर्तन नहीं आया
- 77 नौरोजी पावर्टी 531 तथा वही, पृ० 529 533-6 545 561 2, इंडिया, 20 मई 1899 पृ० 317 और इंडिया 8 जुलाई 1898 पृ० 11
- 78 नौरोजी पावर्टी प० 535 537 543 557 8 ए० बी० पी० 29 सित० 1898 ज० ए० बाहिया, रिप० आई० एन० सी० 1901, प० 176 जी० एस० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1902 प० 100 और रिप० आई० एन० सी० 1904 पृ० 175, और ई ए पृ० 10 दस ई एच II पृ० 585-6 तुलनीय रिपोर्ट आफ़् रि इंडियन करेंसी कमिटी 1893 पृ० 112
- 79 नौरोजी पावर्टी पृ० 545 तथा एम० एच० वकील, पूर्वोद्धृत, प० 5-6, मराठा, 9 अक्टूबर 1892
- 80 वाचा सी० पी० ए० पृ० 610
- 81 आई० एन० सी० 1904 का प्रस्ताव VIII दस ई एच II प० 596 गोडले स्पीचेज प० 75 77 रिप० आई० एन० सी० 1904 प० 164-5 168, पी० महता स्पीचेज प० 604, जी० एस० अय्यर, ई ए, पृ० 41 3
- 82 गाखले, स्पीचेज, पृ० 76 1902 क कायस अधिवेशन में इसी प्रकार का प्रश्न सी० डी० ठाकरसी ने उठाया (रिप० आई० एन० सी० 1902 प० 99)
- 83 नौरोजी पावर्टी प० 530
- 84 एम० एच० वकील पूर्वोद्धृत पृ० 19 नौरोजी, पावर्टी प० 529 531 560-2 सी० पी० ए० प० 176, इंडिया, 20 मई 1898 पृ० 317 मराठा 4 सितंबर 9 अक्टू० 1892 वाचा, सी० पी० ए०, प० 610 स्पीचेज प० 382 जे० ए० बाहिया पूर्वोद्धृत पृ० 65 बी० डी० ठाकरसी रिप० आई० एन० सी० 1902 प० 99 जी० एस० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1904 पृ० 175
- 85 इंडियन करेंसी कमिटी मिनटम आफ़् एविडेन्स गेड एवेडिक्स 1893 सी 7060 II प्रश्न 2353-4
- 86 वही प्रश्न 2371
- 87 वही प्रश्न 2355-9
- 88 वही प्रश्न 2391

- 89 मराठा, 9 अक्टूबर 1892, एम० एच० वकील, पूर्वोद्धत, पृ० 4 नोरोजी पावर्टी, पृ० 536, दत्त स्पीचेज I पृ० 88 90 इडिया 11 नवंबर 1898, पृ० 262 ई एच II, पृ० 581
- 90 वाचा सी० पी० ए०, पृ० 614 मराठा, 9 अक्टूबर 1892 वाचा स्पीचेज पृ० 390 नोरोजी पावर्टी, पृ० 561 3, एम० एच० वकील, पूर्वोद्धत पृ० 4-7
- 91 वाचा रिप० आई० एन० सी० 1893 पृ० 131
- 92 आई० एन० सी० 1899 का प्रस्ताव IV तथा आई० एन० सी० 1893 और 1899 के प्रस्ताव क्रमशः XIV और XVII
- 93 1893 में इडियन एसोसिएशन द्वारा हाउस आफ कामस म प्रस्तुत याचिका बगाली के 18 फरवरी 1893 में प्रकाशित बगवासी 26 अगस्त (आर० एन० पी० बग०, 2 सितंबर 1893), इडियन स्पेक्टेटर 8 मई 1898 क सरे हिंद 15 मई (आर० एन० पी० बव, 21 मई 1898) आई० एन० सी० 1898 का प्रस्ताव XIII वाचा ने शिकायत की कि भारत का व्यापार भी सामान्यतः अस्त व्यस्त हो गया है (रिप० आई० एन० सी० 1893, पृ० 131)
- 94 बर्दई समाचार, 27 जून 3 4 जुलाई (आर० एन० पी० बव 1 जुलाई 8 जुलाई 1893), जामे जमशद 27 29 जून 1 जुलाई (वही 1 जुलाई 1893) कसरे हिंद, 2 जुलाई इंदु प्रकाश 3 जुलाई (वही 8 जुलाई 1893) गुजरात दपण 12 अक्टूबर (वहा, 14 अक्टूबर 1893) 1893 में इडियन एसोसिएशन द्वारा हाउस आफ कामस को प्रस्तुत याचिका, बगाली के 18 फरवरी 1893 के क्रम में प्रकाशित ए० पी० पी० 23 जुलाई 1893, मराठा 2 जुलाई 1893, हिंदुस्तानी, 5 जुलाई (आर० एन० पी० एन० 11 जुलाई 1893) दैनिक ओ समाचार चन्द्रिका 2 जुलाई (आर० एन० पी० बग० 8 जुलाई 1893) बगवासी 26 अगस्त (वही 2 सितंबर 1893), बगाली, 3 फरवरी 1894 28 जून 1898 वाचा रिप० आई० एन० सी० 1893 पृ० 130 सी० पी० ए० पृ० 612, राय, पावर्टी पृ० 11 जे० यू० याचिका प्रसिडेंशियल ऐंड्रैस ऐट दि सबथ प्राविशल काफेंस (सातवें प्रांतीय सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण) ज० पी० एस० एन० जनवरी 1895 (खंड VIII सं० 3) पृ० 5 दत्त स्पीचेज I, पृ० 91 जे० ए० वाडिया रिप० आई० एन० सी० 1901 पृ० 177
- 95 वाचा ने निर्देश किया कि भारतीय सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन के अधिनाश का उपभोग चीन और जापान द्वारा किया जाता है (रिप० आई० एन० सी० 1893 पृ० 130)
- 96 पी० महता स्पीचेज पृ० 362 बर्दई समाचार 4 जुलाई (आर० एन० पी० बव 8 जुलाई 1893) हिंदुस्तानी 5 जुलाई (आर० एन० पी० एन० 11 जुलाई 1893) बगाली 3 फरवरी 1894 28 जून 1898 राय पावर्टी पृ० 11, याचिका, अध्यक्षीय भाषण, पूर्वोक्त स्थल पृ० 4 वाचा रिप० आई० एन० सी० 1893 पृ० 130-1 रिप० आई० एन० सी० 1898 पृ० 98 सी० पी० ए०, पृ० 612-4
- 97 गोखले स्पीचेज पृ० 10 तथा देखिए पृ० 11
- 98 रिप० आई० एन० सी० 1904 पृ० 174
- 99 रिप० आई० एन० सी० 1902 पृ० 99 अहमदाबाद के एक अन्य मिल-अधिकर्ता सोराबजी कडाका ने उनका समर्थन करते हुए दृढ़तापूर्वक कहा कि मुद्रा कानून ने देश के कारखाना उद्योग को अशरणा हत्या की है (वही पृ० 101)
- 100 देखिए परिमल राय पूर्वोद्धत, पृष्ठ 177 208 राय तथा कुछ दूसरा जैसे एलगिन (स्पीचेज, पृ० 489 90) और कर्जन (स्पीचेज III पृ० 135) ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि



भारत का 80 प्रतिशत अथवा उससे भी अधिक व्यापार स्वयंमान वाले देशों के माप का और रुपये के स्वयंमान से स्थिर संबंध होने पर भारत का साथ पड़ना निश्चित था। जहाँ हफ्तों बार बार दोहरा चुके हैं भारतीय नेता ता गमप्र विश्व व्यापार की चिंता अथवा उसके संबंध ही नहीं रखते थे उन्होंने तो अपने दृष्टिकोण को एक सीमित क्षेत्र तक ही संकुचित कर लिया जिससे अनुसार उनके प्रयत्नों का प्रत्यक्ष संबंध देश के उद्योगीकरण से ही था

- 101 वाचा सी० पी० ए० पृ० 613-4 तथा दक्षिण मराठा, 12 जुलाई 1903
- 102 1893 मे इंडियन एसोसिएशन द्वारा हाउस आफ कामस को प्रस्तुत शासन बंगाली के 18 फरवरी 1893 के अधिनियम प्रकाशित बंगाली 3 फरवरी 1894, आई० एन० सी० 1901 का प्रस्ताव XVII वाचा सी० पी० ए० पृ० 612
- 103 कांग्रेस के आठवें अधिवेशन में कप्तान बनन ने मुद्रा प्रस्ताव का गमयन किया (रिप० आई० एन० सी० 1892 पृ० 64)
- 104 नौरोजी पाथरी, पृ० 562 वाचा रिप० आई० एन० सी० 1898 पृ० 100-01
- 105 मराठा, 4 सितंबर 1892 और 2 जुलाई 1893 इंडियन एसोसिएशन आफ वेस्टर्न इंडिया द्वारा 1892 में प्रस्तुत स्मरणपत्र पूर्वोक्त स्थल, बर्दई समाचार 27 जून (आर० एन० पी० बंग 1 जुलाई 1893) वाचा रिप० आई० एन० सी० 1898 पृ० 101-02 आर० पी० फरवरी रिप० आई० एन० सी० 1893 पृ० 132-3 नौरोजी इंडिया 20 मई 1898 पृ० 317, दत्त इंडिया 11 नवंबर 1898 पृ० 261 2 सा० पा० ए० पृ० 490, पी० ए० चारनू एन० सी० पी० 1898 खंड XXXIV पृ० 502-03 आई० एन० सी० 1899 और 1901 का प्रस्ताव IV और XVII नमक गोखले स्पीचेज पृ० 14-5 75 111 एन० एन० बनर्जी सी० पी० ए० पृ० 685 वी० डी० टाकरसी रिप० आई० एन० सी० 1902 पृ० 98 बंगाली 10 फरवरी 1903
- 106 1893 में इंडियन एसोसिएशन द्वारा हाउस आफ कामस को प्रस्तुत वाचिका बंगाली के 18 फरवरी 1893 का अधिनियम मराठा 2 जुलाई 1893 ए० बी० पी०, 5 6 जनवरी 1893 19 सितंबर 1898 हितवादी 29 जून दैनिक ओ समाचार चट्टिका, 5 जुलाई (आर० एन० पी० बंग० 8 जुलाई 1893), हिंदुस्तानी, 5 जुलाई (आर० एन० पी० एन० 11 जनवरी 1893) तोडूपा ए हिं 13 मार्च (वही, 23 मार्च 1898), हिंदी प्रतीक मई-जून (वही 13 जुलाई 1898) अधिगारे आम के 17, 24 अगस्त के अधिनियम एक पत्र (आर० एन० पी० पी०, 11 सितंबर 1897) पसा जखवार, 30 अप्रैल, 2 मई (वही 14 मई 1898), इंडियन स्पेकर 8 अक्टूबर (आर० एन० पी० बंग 14 अक्टूबर 1899), दत्त स्पीचेज I पृ० 85 8 इंडिया 11 नवंबर 1898 पृ० 261 इंडियन पालिटिक्स पृ० 52 सी० पी० ए० पृ० 490 हिंदू 12 जुलाई 1899 आई० एन० सी० 1899 का प्रस्ताव IV, वाचा सी० पी० ए०, पृ० 615 जी० एन० अथर सिं वायसगाय आन दि इकोनामिक क्लेसिफिकेशन आफ इंडिया एन० आर० जून 1901 पृ० 441 गोखले स्पीचेज पृ० 14 111 रिप० आई० एन० सी० 1904 पृ० 163-4 ए० एन० देसाई रिप० आई० एन० सी० 1904 पृ० 174
- 107 दत्त स्पीचेज I पृ० 86
- 108 गोखले स्पीचेज पृ० 14
- 109 ए० बी० पी० 19 मित० 1898 तथा वही, 6 जुलाई 1893 मराठा, 2 जुलाई 1893
- 110 स्पीचेज I पृ० 81 तथा इंडियन एसोसिएशन आफ वेस्टर्न इंडिया का स्मरणपत्र पूर्वोक्त

स्यल इंडियन एसोसिएशन द्वारा 1893 म हाउस आफ कामस को प्रस्तुत याचिका, बंगाली के 18 फरवरी 1893 के घब म प्रकाशित मराठा 12 मार्च 1893, हिंदू 28 जून 1893, 12 जुलाई 1899 ए० बी० पी०, 26 जुलाई 1893, नौरोजी पावर्टी, पृ० 531 2 दत्त स्पीचेज I पृ० 81 5, इंडिया 11 नवंबर 1898 पृ० 261 2 सी० पी० ए० पृ० 490 जी० एस० धम्मर रिप० आई० ए० सी० 1898 पृ० 107 एच० आर०, जून 1901 पृ० 441 आई० एन० सी० 1899 का प्रस्ताव IV वाचा स्पीचेज पृ० 390 रिप० आई० एन० सी० 1899 पृ० 60-1 सा० पी० ए० पृ० 614 गांगुले स्पीचेज पृ० 14 111 ए० एस० देसाई रिप० आई० एन० सी० 1904 पृ० 174

- 111 नौरोजी, एगज प० 520 इंडिया 20 मई 1898 पृ० 317, 8 जुलाई 1898 पृ० 11 1893 म इंडियन एसोसिएशन द्वारा हाउस आफ कामस को प्रस्तुत याचिका बंगाली के 18 फरवरी 1893 के घब में प्रकाशित मराठा 12 मार्च 2 जुलाई 1893 ए० बी० पी० 23 जुलाई 1893 19 29 नितंबर 1898 वगरे हिं 9 जुलाई (आर० एन० पी० बब० 15 जुलाई 1893), हिंदुस्तानी 5 जुलाई (आर० एन० पी० एन० 11 जुलाई 1893), बगवासी, 8 जुलाई (आर० एन० पी० बग० 15 जुलाई 1893) आर० पी० बरदीकर, रिप० आई० एन० सी० 1893 पृ० 132 3 दत्त, स्पीचेज I पृ० 77 9 85 बगवासी, 29 जनवरी (आर० एन० पी० बग० 5 फरवरी 1898) जी० एस० धम्मर रिप० आई० ए० सी० 1898 पृ० 107 हिंदू 12 जुलाई 1899 आई० ए० सी० 1899 का प्रस्ताव IV वाचा रिप० आई० एन० सी० 1899 पृ० 60 सी० पी० ए० प० 614 स्पीचेज, पृ० 389, गोयले स्पीचेज प० 14 75 111, वी० डी० ठाकरसा रिप० आई० एन० सी० 1904 पृ० 174
- 112 वाचा, स्पीचेज पृ० 389 1893 म इंडियन एसोसिएशन द्वारा हाउस आफ कामस को प्रस्तुत याचिका बंगाली के 18 फरवरी 1893 के घब में प्रकाशित ए० बी० पी०, 23 जुलाई 1893 हिंदुस्तानी 5 जुलाई (आर० एन० पी० एन० 11 जुलाई 1893) दत्त, स्पीचेज I पृ० 80 'इंडिया' 11 नवंबर 1898 पृ० 261 आई० एन० सी० 1899 का प्रस्ताव IV
- 113 बर्द ममाचार 27 जून (आर० एन० पी० बब० 1 जुलाई 1893) मराठा 2 जुलाई 1893, रहवर 8 जुलाई (आर० एन० पी० एन० 27 जुलाई 1892) हिंदुस्तानी 5 जुलाई (वही 11 जुलाई 1893) हिमालय 14 जुलाई (आर० एन० पी० पी० 29 जुलाई 1893) नौरोजी, पावर्टी प० 534 इंडिया 20 मई 1898 पृ० 317 हिंदी प्रदीप मई जून (आर० एन० पी० एन० 13 जुलाई 1898) वाचा रिप० आई० एन० सी० 1898 पृ० 101 हिंदू, 12 जुलाई 1899 बंगाली 19 फरवरी 1903
- 114 जी० एस० धम्मर, ई ए पृ० 121 तथा एम० एच० बकील पूर्वोद्धत, प० 67, वाचा स्पीचेज पृ० 390 रिप० आई० एन० सी० 1893 पृ० 130 रिप० आई० एन० सी० 1898 प० 101 रिप० आई० एन० सी० 1899 पृ० 56 हिंदुस्तानी 22 जून (आर० एन० पी० एन०, 29 जून 1892) 1893 म इंडियन एसोसिएशन द्वारा हाउस आफ कामस को प्रस्तुत याचिका, बंगाली के 25 फरवरी 1893 के घब में प्रकाशित ए० बी० पी० 29 जून 1893 मराठा 2 जुलाई 1893 आयजनप्रियन 8 जुलाई केरल पत्रिका 8 जुलाई (आर० एन० पी० एम०, 15 जुलाई 1893) नौरोजी पावर्टी पृ० 534 561 इंडिया 20 मई 1898, प० 317, जे० ए० वाडिया पूर्वोद्धत पृ० 96 दत्त स्पीचेज I पृ० 89 90
- 115 कसरे हिं 27 अगस्त (आर० एन० पी० बब०, 2 सितंबर 1893) तथा नौरोजी, पावर्टी

- पृ० 534 547, 561, बगवासा 8 जुलाई (आर० एन० पी० बग०, 15 जुलाई 1893), दन इंडियन पालिटिक्स प० 52 जा० एन० अम्पर, रिप० आई० एन० सी० 1898 प० 107 ई ए प० 120 वाचा, रिप० आई० एन० सा० 1899, प० 56 बगाली 19 फरवरी 1903
- 116 जा० एन० अम्पर ई ए प० 120 1 हिंदू, 12 जुलाई 1899 वाचा, रिप० आई० एन० सा० 1899 प० 58-9 बगाली, 19 फरवरी, 1903
- 117 वकील और मुराजिन पूर्वोद्धत, पृ० 321 3 और परिमल राय पूर्वोद्धत पृ० 203
- 118 दस स्पीचज I प० 79 80 89 90
- 119 गोखले स्पीचज पृ० 14 तथा पृ० 75 कुछ वर्षों के उपरान्त 1908 में गोखले ने इन समस्या पर विचार से विचार किया सब कहा जाए तो सरकार का मुद्रा कानून से रुपये का नक्ती बर्द्ध का परिणाम तभी निकलगा जब नए आधार पर वस्तुएं व्यवस्थित हो जाएगी तब देश में कीमतों में सामान्य गिरावट आएगी चांगे के सिक्के गढ़न वाला टकसाला के बंद हान का बचाव प्रथम कई वर्षों में उसका परिणाम अकालों का निरंतरता में अभाव की स्थिति की व्यापकता से और कर्नाचित जोड़े हुए रुपया के परिचलन से नकारात्मक हो गया है इसके अतिरिक्त सारे विश्व में उपभोग वस्तुओं के स्वर्ण मूल्य में वृद्धि की सामान्य प्रवृत्ति ने भी निम्नदेह भारत में मूल्यवृद्धि में सहायता दी है हमारे सिक्का विशेषज्ञ ने परीक्षा करके इस समस्या पर कुछ प्रकाश डाला है विशेषज्ञ मिस्टर हरोसन के अनुसार 1898 से पहले बने रुपये का मडार 130 करोड़ का लगभग का है इस दस वर्ष की अवधि में सरकार ने विगुण रुप से इस मडार में 100 करोड़ रुपये की वृद्धि की है मरा विचार है कि देश की मुद्रा के इन आकस्मिक प्रसार का परिणाम मूल्य में सामान्य वृद्धि ही है (स्पीचज, पृ० 177 9)
- 120 वाचा, सी० पी० ए , पृ० 615-6
- 121 यदि हम फौलर कमिशन द्वारा (भले ही) सचोचपूर्वक अभियन्त विरोधी मान्यता को देखें तो यह अकान्तप्रौढ़ता वस्तुतः विस्मयजनक ही लगती है देखिए इंडियन कॅम्पा कमटी 1893 का प्रतिबन्धन कठिना 58 बगाली द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोण को कालांतर में ज० एन० कॅम्पा न पुष्ट किया (पूर्वोद्धत पृ० 6) एक अन्य भारतीय सचय रणछोड सात छोटलाल न जो हालांकि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता नहीं थे (वह अहमदाबाद की एक मिल का स्वामी थे और बर्बई विधानपरिषद का सदस्य थे) 1894 में सरकार से अपने आप रुपये करने का अपील इस आधार पर की कि जब एक बार भारत रजतमान से हट गया तो रुपये मुद्रा का संकेत मात्र बनकर रह जाता है उस स्थिति में भारत और इंग्लैंड के बीच विनिमय दर की ऊंच नीच पर रुपये की अधिकता और अभाव का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता अतः इंग्लैंड के लिए भारत के व्यापार सद्गुण पर निर्भरता को दृष्टि से कोई चिंता की बात नहीं इसका विपरीत इन स्थितियों में रुपये की कमी उद्योगों और कृषि को और उसके फलस्वरूप देश में निर्मात को क्षति पहुँचाती हुई दरों के मूल्य को और भी नीचे की ओर ले जाएगी (लेटस थान कॅम्पा, बर्बई 1895)
- 122 नोरोजी पावर्टी पृ० 532-4 और इंडिया 8 जुलाई 1898 पृ० 10-11
- 123 नोरोजी सी० पी० ए० पृ० 177 पावर्टी पृ० 560 इंडियन कॅम्पा कमटी सान्ध की काय वाही और परिशिष्ट—1893 सी 7060 II प्रश्न 2346-7, बगाली 11 जून 1881 हिंदू 22 अगस्त 1893
- 124 आई० एन० सी० 1892 का प्रस्ताव IV, दस इंडियन पालिटिक्स, पृ० 51 2 स्पीचज I, पृ 91

- 125 1893 के मुद्रा अधिनियम के कानून बन जाने पर मराठा ने 2 जुलाई 1893 के प्रक म पुन बल पूर्वक कहा कि इस दश की जनता के हितों पर ध्यान दिए बिना ही बिल पास कर दिया गया है विश्व के विसा भी दश म मुग्ण सबधी यह द्रुत परिवर्तन और यह भा इतनी आसानी से लागू करना कदाचित असम्भव ही होता
- 126 दत्त, इंडियन पालिटिक्स पृ० 52 तथा देखिए उनवी स्पीचेज I, पृ० 86
- 127 नौरोजी पावर्टी पृ० 542 और 547
- 128 होम (पब्लिक) नव० 1893 प्राग 315 (ए) कडिका 1
- 129 फाइनेशियल स्टेटमट 1896 7 कडिका 104, वकील पूर्वोद्धत पृ० 33
- 130 आर० एन० पी० बब 2 सितंबर 1893
- 131 ए० बी० पी०, 22 अगस्त 1893 दिहू 25 अगस्त 1893, 18 अप्रैल 1894 16 जून 1899 बंगाली 18 नवंबर 1893 10 फरवरी 10 मार्च, 7 अप्रैल 1894, मराठा 27 अगस्त 1893 21 जनवरी 1894, इंडियन स्पेक्टेटर, 27 अगस्त 1893, द्दु प्रवाण 25 सितंबर 1893 आर० एन० पी० बब 2 सितंबर, 30 सित० 1893 म उद्धत समाचारपत्र आर० एन० पी० बग० 2 9 23 सितंबर 1893 तथा आर० एन० पी० एम० 15 सित० 1893 म उद्धत समाचारपत्र
- 132 रिपोट आफ दि इंडियन एमोसिएशन 1829 3 से 1895-6 प० 34 और ज० पी० एस० एस०, जनवरी 1894 (खड XVI स० 3) पृ० 60
- 133 आई० एन० सी० 1893 का प्रस्ताव XV
- 134 प्रस्ताव XVI (1894), XVI (1895) XI (1896) IV (1897), XX (1898) XIV (1899) X (1900), XIX (1901) XIX (1902) और XIII (1903)
- 135 रिप० आई० एन० सी० 1893 प० 133 5
- 136 नौरोजी स्पाचेज पृ० 344 और पृ० 143 462 सी० पी० ए० प० 176 देखिए ए० सी० मजूमदार रिप० आई० एन० सी० 1895 पृ० 143 जोशी, पूर्वोद्धत प० 200 219 वाचा, स्पीचेज-परिशिष्ट प० 17 31 गोखले स्पाचेज पृ० 1190 दत्त ई एच II, पृ० 578
- 137 आई० एन० सी० व 1893 और 1894 के प्रस्ताव क्रमशः XV और XVI 1893 म इंडियन एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत स्मरणपत्र पूर्वोक्त स्थल, पृ० 35 1893 मे पूना सावजनिक सभा द्वारा प्रस्तुत स्मरणपत्र, जे० पी० एस० एस० जनवरी 1894 (खड XVI स० 3) प० 60 इन्डियन स्पेक्टेटर, 27 अगस्त 1893 मराठा 27 अगस्त 1893 कसरे हिन् 2 जून (आर० एन० पी० बब 8 जून 1895) वाचा स्पीचेज परिशिष्ट पृ० 17 30 एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए० प० 262 701 02 ए० सी० मजूमदार रिप० आई० एन० सी० 1895 प० 140 1
- 138 जी० बी० जोशी पूर्वोद्धत प० 200 तथा देखिए वही प० 199 219 नौरोजी एसेज पृ० 517 स्पीचेज प० 144 मुजरात दपण 31 अगस्त (आर० एन० पी० बब 2 सितंबर 1893) पूना सावजनिक सभा द्वारा 1893 में प्रस्तुत स्मरणपत्र—पूर्वोक्त स्थल प० 63-4 ए० बी० पी० 22 अगस्त 1893 बंगाली 81 नवंबर 1893 स्वदेशमित्र 25 अगस्त आर० एन० पी० एम० 15 सितंबर 1893), वाचा रिप० आई० एन० सी० 1893 प 129 ए० सी० मजूमदार रिप० आई० एन० सी०—1895 प० 143 गोखले स्पीचेज प० 1190 जमी उल जनुम 28 मई

- (आर० एन० पी० एन० 2 जून 1897), जी० एम० अय्यर, विनवी आयोग, खंड III प्र० 19027
- 139 रिप० आई० एन० सी० 1893 पृ० 135 1895 में ब्रांस अधिवेशन में बंगाल से आए एक अन्य प्रतिनिधि पुरुष चंद्र राय ने भी इसी प्रकार के भाव प्रकट किए (रिप० आई० एन० सी०— 1895 पृ० 145)
- 139 A 28 मई 1897 (आर० एन० पी० एन० 2 जून 1897)
- 140 नौराजी एमज पृ० 516 एम० एच० बकौन, पूर्वोक्त पृ० 12, 31 2, मराठा, 25 सितंबर 1892 12 फरवरी 1893 गुजरात दण्ड 22 सितंबर (आर० एन० पी० एन० 24 सितंबर 1892) 1893 में प्रस्तुत इंडियन एसोसिएशन की याचिका, बंगाली के 25 फरवरी 1893 के अंत में प्रकाशित वाचा रिप० आई० एन० सी० 1893 पृ० 137 स्पीचज परिशिष्ट पृ० 11, 30 बरार हिंदू 2 जून (आर० एन० पी० एन० 8 जून 1895) एम० एच० बकौन (पृ० 32-6) कसरे हिंदू का विचार था कि यदि सावधानी से हिमायत लगाया जाए तो बर्नाबित सरकार अधिनारी लाभ में हो रहे हैं
- 141 गोखल, स्पाचज पृ० 1190 तथा जोगी पूर्वोक्त पृ० 219 ए० वा० पा०, 27 मार्च 1892 11 फरवरी और 22 अगस्त 1893 मराठा 25 सितंबर 1892, 1893 में इंडियन एसोसिएशन द्वारा हाउस आफ कामन्स की प्रस्तुत याचिका बंगाली के 25 फरवरी 1893 के अंत में प्रकाशित, पी० एम० एम० का स्मरणपत्र ज० पी० एम० एम० जनवरी 1894 (खंड XVI स० 3) पृ० 64, गुजरात दण्ड 31 अगस्त (आर० एन० पी० एन० 2 सितंबर 1893) हिंदुवादी 25 अगस्त (आर० एन० पी० एन० 2 सितंबर 1893) वाचा, रिप० आई० एन० सी० 1893 पृ० 130 स्पाचज परिशिष्ट पृ० 30 एम० एन० बनर्जी सी० पी० ए० पृ० 263, पी० सी० राय वही पृ० 145 ए० सी० मजूमदार रिप० आई० एन० सी० 1895 पृ० 141 जी० एम० अय्यर विलवा आयोग खंड III प्रथम 19027 जमी उल डनुम 28 मई (आर० एन० पी० एन० 2 जून 1893) अंगरेज अधिकारियों द्वारा अपनाए गए रथ से यह दृष्टिकोण कितना भिन्न था दूर अधिकारियों की दुष्प्रकृति के सजाव तथा सचिव रूप की निम्नलिखित में से किसी एक के द्वारा देखा जा सकता है जनरल बिमनी 1 1894 में अपना 'इंडियन पार्लिमेंट' (पृ० 336-9) में लिखा यदि मनुष्य केवल चावल पर जीवित रहता और सादा सा कपड़ा पहनता तो रुपये की गिरावट के घाटे को वह सह सकता था परिणाम यह है कि भारत के वनिष्ठ मित्रिणी अथवा मित्रिणी कर्मचारी का रूप में मनुष्य के गिरावट के फलस्वरूप निश्चिन्ता तथा अभाव का जीवन बिताना पड़ता है (पृ० 337 8) उसने चेतावनी दी कि यदि वनिभय का सुधारन के लिए कुछ नहीं किया जाता तो अंगरेज अधिकारों बहुत भारे प्रलोभनों का मोह में छोड़ पाएंगे
- 142 नौराजी एमज पृ० 517 स्पीचज पृ० 143 462 मराठा, 25 सितंबर 1892 इंडियन एसोसिएशन का स्मरणपत्र 29 सितंबर 1893 पूर्वोक्त दण्ड पृ० 34 एम० एन० बनर्जी रिप० आई० एन० सी० 1893 पृ० 134 एम० एंडू इन्डू परिशिष्ट पृ० 47 गोखले स्पीचज पृ० 1190 वाचा स्पीचज परिशिष्ट पृ० 30 जी० एम० अय्यर विनवी आयोग, खंड III प्रथम 18638
- 143 गोखल स्पीचज पृ० 1190
- 144 नाम प्रकाश 31 अगस्त (आर० एन० पी० एन० 2 सितंबर 1893), 29 सितंबर 1893 का

- इंडियन एसोसिएशन का शासन, पूर्वोक्त स्थल पृ० 37 1893 का पू० सा० स० का स्मरणपत्र, जे० पी० एस्० एम० जनवरी 1894 (घट XVI सं० 3) पृ० 65 बगाली 10 फरवरी 1894 नौरोजी, स्पीचेज पृ० 143 एस्० एन० बनर्जी रिप० आई० एन० सी० 1893 पृ० 134 सी० पी० ए० पृ० 262 और एस्० ऐंड डब्ल्यू परिशिष्ट पृ० 47 8 ए० सी० मजूमदार रिप० आई० एन० सी० 1895 प० 143 गोखले स्पीचेज पृ० 1192 हिंदू 27 मार्च 1899
- 145 गोखले स्पीचेज पृ० 1192 तथा एस्० एन० बनर्जी सी० पी० ए०, पृ० 262 एस्० ऐंड डब्ल्यू परिशिष्ट पृ० 48 ए० सी० मजूमदार रिप० आई० एन० सी० 1895 प० 143
- 146 इंडियन एसोसिएशन का शासन 29 सितंबर 1893 पूर्वोक्त स्थल, पृ० 37 नौरोजी स्पीचेज, पृ० 144, एस्० एन० बनर्जी एस्० ऐंड डब्ल्यू परिशिष्ट प० 47 8 दत्त इन्डिया प० 165
- 147 एम० एन० बनर्जी, रिप० आई० एन० सी० 1893 प० 134
- 148 इंडियन एसोसिएशन का शासन, 29 सितंबर 1893 पूर्वोक्त स्थल प० 35, बगाली 13 नव० 1893, हितवादी 25 अगस्त साम प्रकाश 28 अगस्त (आर० एन० पी० बग० 2 सितंबर 1893), सहचर 30 अगस्त (बही, 9 सित० 1893) समय 15 सितंबर (बही 25 सितंबर 1893) एस्० एन० बनर्जी रिप० आई० एन० सी० 1893 प० 135 एस्० ऐंड डब्ल्यू परिशिष्ट पृ० 48, ए० सी० मजूमदार रिप० आई० एन० सी० 1895 प०, 141 ए० सी० पी० नायडू, बही पृ० 143
- 149 स्पीचेज पृ० 1192
- 150 ज्ञान प्रकाश, 31 अगस्त (आर० एन० पी० बग० 2 सितंबर 1893) अद्यकारे आम, 30 सितंबर (आर० एन० पी० पी० 14 अक्टूबर 1893), एस्० एन० बनर्जी सी० पी० ए० प० 263, दत्त इन्डिया ऐंड इंडिया पृ० 165 और ई एच II प० 578
- 151 स्पीचेज, प० 462
- 152 उन्होंने आगे कहा बर्दई के महान व्यक्तियोग पंजाब के महान व्यक्तियोग उत्तरी भारत के महान व्यक्तियोग बंगाल के महान व्यक्तियोग ! आजो हम एकजुट हो जाए आजो हम मुन्द पग उठाए आजो हम निश्चय करें कि तब तक चैन नही लेंगे जब तब इन अयाध के देवा को भीधे रास्ते पर नहा ला देते और तब तक आराम से नहा बैठेंगे जब तक कि उनकी आखा से भ्रम के इस आवरण को हटा नही देने जिसे बनाए रखने की वे व्यथ चेष्टा करत हैं कि यह दग उनका है हमारा नहा (रिप० आई० एन० सी० 1893 प० 135)
- 153 आर० एन० पी० बग० 2 सितंबर 1893
- 154 ए० बी० पी० 22 अगस्त 1893 मराठा 27 अगस्त 1893 गुजराती 27 अगस्त, (आर० एन० पी० बग० 2 सितंबर 1893) बगाली 26 अगस्त (आर० एन० पी० बग० 2 सितंबर 1893) बगाली 18 नवंबर 1893 गोखले स्पीचेज पृ० 1192 जोशी पूर्वोक्त पृ० 200 दत्त इन्डिया ऐंड इंडिया, पृ० 165
- 155 नौरोजी पार्लमेंट पृ० 562, जे० ए० काडिया पूर्वोक्त, पृ० 96 दत्त स्पीचेज I प० 90 तथा देखिए पीछे पाद टिप्पणी 90
- 156 रिप० आई० एन० सी० 1893 पृ० 128
- 157 देखिए अध्याय 1 और अध्याय 4
- 158 स्वर्ण विनिमय के पक्षधर एस्० बी० मरूवा ने निम्न विनिमय के समयको की उनकी

लिए मत्स्यना की उद्दोने ध्यय करते हुए टिप्पणी की चरखा मिनो के ये दसाल रुपये को रजत मूल्य 6 पस तक लाने का इच्छा क्या करते हैं ? यह तो मजदूरी को टगना है क्या इन लोगों को सम्य प्राणी कहा जा सकता है, जो एक आर मजदूरी को लूटने पर धामादा हैं और दूसरी ओर किसानों के हिता की बवालत करते हैं (स्पीचज, आन इडियन इकोनामिक्स, प० 26)

- 159 बंगाल का सहचर एकमात्र अपवाद था जिसने स्वर्णमान का निरन्तर समयन किया और निम्न तथा घटते बढ़ते विनिमय का विरोध किया उसने व्यापारियों और विदेश व्यापार की सफलता का अपना सद्भावितक विषय बनाया उदाहरणाय देविए 15 जून 1892 का अंक (आर० एन० पी० चग०, 22 जुलाई 1892, 28 जून 1893 (वही, 8 जुलाई 1893), 21 फरवरी 1894 (वही 3 मार्च 1894) अखबारे आम 24 जून (आर० एन० पी० पी०, 9 जुलाई 1898)
- 160 ए० बी०पी० 29 मई 1892 दुर्भाग्यवश मुझे सादन की 1893 1894 की रपट प्राप्त नहीं हो सकी परंतु 1897 8 की रपट से सन् के चितन की प्रवृत्ति का दखा जा सकता है इस रपट में विनिमय का अनिश्चितता पर चिन्ता प्रकट की गई और बाजार में पर्याप्त धन की और इस विनिमय के अनुपात को सुनिश्चित करने की मांग की गई थी
- 161 पेपस रिसेटिंग टु चेंजम इन इडियन करेंसी सिस्टम (भारत सरकार, 1893), पृ० 60-4 84-90
- 162 वही प० 25 7 73 4 तथा देखिए वही, पृ० 89-90
- 163 एस० बी० अरुचा पूर्वोद्धत प० 2 9 11 5 22 32
- 164 एल० सी० पा० 1898 खड XXXVII प० 513
- 165 मराठा 25 सितंबर 1892 तथा बंगाली 19 फरवरी 1903
- 166 नीरोजी, पावर्टी प० 561 तथा पृ० 547 इडियन करेंसी कमेटी (1893) द्वारा जांच के समय भी उद्दोने इसी प्रकार के विचार प्रकट किए इडियन करेंसी कमेटी साक्ष्य की कायवाही तथा परिशिष्ट, सी 7060 II प्रबन्ध 2393-7 इसी प्रकार जे० ए० काटिया ने 1901 में स्पष्ट रूप में कहा कि वे किसानों के प्रति निरन्तर अत्याचार की अपेक्षा व्यापारियों पर पड़ने वाले अत्याही घाटे को ही ठीक समझेंगे (पूर्वोद्धत पृ० 126) तथा मराठा 4 सितंबर 1892
- 167 देखिए रिप० आई० एन० सी० 1901 1902 और 1904
- 168 1898 में करेंसी कमेटी का समस्त प्रश्न किए जाने पर आर० सी० दत्त को यह स्वीकार करने पर बाध्य होना पड़ा था देखिए दत्त स्पेचिज I पृ० 76-89
- 169 वकील और बोग पूर्वोद्धत प० 128 परिफल राय पूर्वोद्धत प० 179 193-4
- 170 स्टेटिस्टिकल ऐन्ड्रवट रिपोर्टिंग टु ब्रिटिश इडिया फ्राम 1891 92 टु 1900-01 सारणी 129 और 200 हमने 1895 6 वष को लिया है क्योंकि स्टेटिस्टिकल एन्ड्रवट में उपलब्ध होने वाली सांख्यिकी का यह प्रथम वष है
- 171 इडियन करेंसी कमेटी साक्ष्य का कायवाही और परिशिष्ट 1893 सी 7060 II परिशिष्ट II प० 244 और गाडगिल पूर्वोद्धत प० 71 2
- 172 चानी और रुपये के अवमूल्यन की अवधि में जहां पूव के दूर देशों में भारतीय सूती बस्त्रों के निर्यात कई गुना बढ़ गए, वहां इस्लाम के सूती बस्त्रों के निर्यात में कोई वृद्धि नहीं हुई (इडियन करेंसी कमेटी साक्ष्य की कायवाही और परिशिष्ट 1893 सी 7060 II परिशिष्ट II पृ० 244)

- 173 डी० बारबूर एल० सी० पी० 1893 खड XXXII प० 274 5 वेस्टलैंड, एल० सी० पी०  
1894 खड XXXIII पृ० 181
- 174 एल० सी० पी०, 1893 खड XXXII पृ० 27५
- 175 वही
- 176 दादाभाई नौरोजी ने इसे 'शासन की विदेशीयता' कहा (इंडियन बर्रोमी कमेटी साध्य की काय  
वाही और परिशिष्ट 1893 सी 706 II, प्रपन 2346)



## श्रम

इस पनपत उद्योग के दम तोड़ने की अपेक्षा इसके संचालक श्रमिकों की अपेक्षाएँ ऊँची मृत्यु दर ही हमें रूचिकर है। एक बार हमारे उत्पात्का का भली प्रकार व्यवस्थित हो जाने दीजिए, उसके उपरांत हम अपने श्रमिकों की सुरक्षा अपने आप कर लेंगे।

—अमृत बाजार पत्रिका 25 सितंबर, 1875

हम इन अभाग्य वर्गों की पिथनता, गदगी और निम्न स्थिति को देखने के इतन आदी हो गए हैं कि अब हमारा मन कठोर हो गया है। हमारी और हमारे शासकों की आत्मा उनकी दशा देखकर उद्धिग्न ही नहीं होती। वस्तुतः उनकी यह दुदशा शताब्दियों से राज्य और समाज के उच्च वर्गों द्वारा किए जा रहे उनके तिरस्कार और दमन का ही फल है।

—जी० सुब्रह्मण्य अम्बर

आधुनिक उद्योगों, खाना, परिवहन और वागान के विकास ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय समाज में औद्योगिक श्रमिकवर्ग के रूप में एक सचचा नवीन वर्ग को जन्म दिया। 1880-81 तक इसका आकार साधारण था। उस वर्ष सूती कपड़ा मिलों में 47,955 पटसन मिलों में 35,235 और कोयला खानों में 11,969 कमचारी कार्यरत थे। 1905-06 तक इस नए वर्ग का स्वतंत्र रूप में उल्लेखनीय विस्तार हो गया था। उस वर्ष सूती कपड़ा मिलों में 212,720, पटसन मिलों में 144,879 और कोयला खानों में 89,995 कमचारी नियुक्त थे। इस प्रकार अकेले यत्रशक्ति से मंचालित आधुनिक कारखानों में ही 700,000 कमचारी नियुक्त थे।<sup>1</sup>

आधुनिक औद्योगिकता और उसके साथ जुड़ी पूँजीपति व्यवस्था के आने के साथ ही वे मजदूरों को जहाँ-जहाँ पहुँचें जितने जितने अगरेज श्रमिकों की पीढ़ियाँ का जीवन विकृत किया था। आधुनिक उद्योगों में लगे हुए श्रमिकों पुरुष, स्त्री और बच्चा की प्रारंभिक पीढ़ियों को भी आधुनिक मनुष्य की मान, क्रूर तथा घृणित शोषण का शिकार बनना पड़ा था। भारत में फैक्टरी के जीवन का निवृष्टतम पक्ष यह था कि कमचारियों को कारखानों में बहुत अधिक घंटे काम करना पड़ना था क्योंकि कारखानों में काम करने के समय की कोई सीमा निर्दिष्ट नहीं थी। आरंभ में एक औसतन बारहमासी कारखानों में शीत ऋतु

म दिन भर अर्थात् 11½ घंटे प्रतिदिन अथवा 80½ घंटे प्रति सप्ताह काम होता था और ग्रीष्म ऋतु में 14 घंटे प्रतिदिन अथवा 98 घंटे प्रति सप्ताह काम चलता था। लगभग 1887 के बाद जब कारखानों में रिजली की रोशनी प्रचलित हो गई तो बेचारे कारीगरों के प्रतिदिन काम के घंटे बढ़कर विभिन्न इलाकों में 12½ से 16 के बीच हो गए। इस अवधि में सबसे अधिक दुष्प्रभावित बलकत्ता के पटसन कारखानों के बुनकर थे, जिन बेचारों को 15-16 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ता था।<sup>13</sup> इतने अधिक घंटे काम करने के अतिरिक्त बेचारे श्रमिकों को मिल में आने और वहां से घर जाने में ही दो-तीन घंटे लग जाते थे, इस तथ्य को ध्यान में रखने पर उन गरीबों की शारीरिक दुदशा का सही अनुमान लगाया जा सकता है।

एक अन्य बात यह है कि काम के इन लंबे घंटों की थकावट और वारियत को दूर करने के लिए अवकाश काल की कोई नियमित और उपयोगी प्रणाली नहीं थी। कुछ मिलमालिक अवकाश की व्यवस्था करते थे परंतु यह समय 15-30 मिनट का होने के कारण अवकाश अपर्याप्त होता था। अन्य कारखानों तो छुट्टी करते ही नहीं थे। वे तो यह आशा करते थे कि कम-चारी खाना खाते समय भी मशीनों की चौकसी करें।<sup>14</sup> नियमित विश्राम अथवा अवकाश के दिनों की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे वे बेचारे निरंतर कष्ट से निवृत्ति पा सकते। 1885 के यावे फैक्टरी लेबर कमीशन ने टिप्पणी की कि भारत के कारखानों में सारे बंधन ही जाने वाली छुट्टियाँ औसतन पंद्रह हैं जबकि इंग्लैंड में 10 अवकाश के अतिरिक्त 52 रविवारों की पूरी छुट्टी और 52 शनिवारों की आधी छुट्टी रहती है। इस प्रकार कुल मिलाकर वहां 88 दिनों का अवकाश रहता है।<sup>15</sup> इसका परिणाम यह हुआ कि श्रमिकों की शारीरिक शक्ति पूर्णतः क्षीण हो गई। वे बेचारे कभी-कभी मशीनों से हटते ही और अपने साधियों के कारखानों के दरवाजे से बाहर निकल पाने से पहले ही फस पर गहरी नींद सो जाते थे।<sup>16</sup>

इससे भी बदतर बात यह थी कि 1891 तक महिलाओं को भी पुरुषों के समान उतने ही लंबे घंटों तक काम करना पड़ता था जबकि उनके लिए काम के लिए 11 घंटे का अधिकतम समय निश्चित किया गया था। प्रारंभिक भारतीय कारखानों में काम करने वाले बच्चों के साथ भी कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। 1881 तक बच्चों को भी उतने अधिक घंटों तक काम करना पड़ता था जितने घंटे वयस्क व्यक्ति काम करते थे। इसका परिणाम यह होता था कि वे बेचारे थकावट से चूर-चूर हाकर मशीनों के बीच गिर जाते थे।<sup>17</sup> 1881 के फैक्टरी ऐक्ट ने बच्चों के लिए काम के घंटों की अधिकतम सीमा 9 घंटे प्रतिदिन निर्धारित की और बच्चों की 'यूनतम परिभाषा 7 और 12 बंधन के बीच की आयु से की। फिर भी बहुत सारे कारखानों में बच्चों के समान लंबे घंटों तक काम करते रहे।<sup>18</sup> 1891 के फैक्टरी ऐक्ट ने बच्चों के काम के घंटों में और अधिक कटौती करके उसकी अधिकतम सीमा 7 घंटे प्रतिदिन निश्चित की और बच्चों की 'यूनतम और अधिकतम आयु सीमा भी 7-12 के स्थान पर क्रमशः 9-14 तक बढ़ा दी। परंतु व्यवहार में इन दोनों प्रावधानों का प्रायः उल्लंघन किया जाता था।<sup>19</sup>

रई पीजन-दवाने जैसे छोटे और मौसमी कारखानों की स्थिति तो आरंभ से

हृदयद्रावरु तथा भयावह थी। 1885 के बापे कैक्टरी नेवर कमीशन ने निर्देश किया कि पानदेग के पिंजा और सपीडन गाय में अधिकांशतः स्त्रिया और बच्चे ही नगरे हुए थे और उनके काम के घंटे सामान्य रूप से सवेरे 4 अथवा 5 बजे से साय 7, 8 अथवा 9 बजे तक होते थे और जय काम का दबाव बढ जाता था तो उह 8 8 दिना तक निरतर दिन रात तक काम करते रहना पडता था जब तक कि उनके हाम थककर और स्वास्थ्य त्रिगड कर काम करन से इनकार नहीं कर दत थे।<sup>10</sup> यह तथ्य प्रस्तुत एक साक्ष्य के तबे अवतरण में उदघत है, जिसमें इन उद्योगों में प्रचलित स्थितियों का दुखद बणन किया गया है और साथ ही एक और भारी अभावा की दुखद कथा पर तथा दूसरी ओर कूर लोभवृत्ति पर प्रकाश डाला गया है।<sup>11</sup> एक गवाहने स्वीकार किया कि उमन अपनी आखों से देखा है कि ऊधती हुए मजदूर महिलाएं यत्र की तरह तिनोने यत्र में रई लिए जा रही हैं। एक मिनट व मजदूर मटिनाए छाती से चिपके बच्चे को स्तन चुसवाती हैं और दूसरे ही मिनट मशीन में रई डालने लगती हैं।<sup>1</sup>

यह स्थिति इस रूप में तो और भी अधिक असह्य थी, इतने अधिक अमानवीय और कमरतोड लवे घटा की मेहनत से मिलने वाली मजदूरी तुच्छ और किमी भी मानदंड से पूणत अपयाप्त थी। इम अवधि के अधिकांश वर्षों में बर्ई के कपडा कारखानों में काम करन वाले पुरुषों और स्त्रियों को मिलने वाला मासिक वेतन सात रुपये से बीस रुपये के बीच था।<sup>12</sup> रई पीजन और सपीडन करने वाले छोटे कारखानों में लगभग 18 घंटे के दैनिक श्रम का पारिश्रमिक 3 4 आन था।<sup>14</sup> इसके अतिरिक्त, और यह तथ्य समान रूप से मट्टनपूण है, उद्योगों के विकास के और श्रम की उत्पादकता वृद्धि के बावजूद श्रमिकों के दान्तविक बतन में कोई अंतर नहीं आया।<sup>15</sup> श्रमिका के वेतन में उस समय भी कोई वृद्धि नहीं की गई जब उद्योग अतिशय सपन्न स्थिति में थे, इतने अधिक सपन्न कि रई एक कारखाने में चार वर्षों में ही अपनी लागत पूजी चुकाने में समथ हो गए थे।<sup>16</sup>

भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने, सामान्य रूप से भारतीय जनता के दुभाग्य से द्रवित आधुनिक औद्योगिक पूजीवाद की बहुमुष्ठी बुराइयां क प्रति तथा समाज के नए पनपते इस बग के शोषण तथा वियम आधिक कष्टों के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाया? यह प्रश्न एक विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसके साथ ही विरोधी हित जुडे हुए हैं और वे दोनों आशिक रूप से भारतीय हाने के कारण राष्ट्रीय हैं। यह एक व्यापक परिमाण में निधनता का प्रत्यक्ष निदर्शन था जो पयाप्त सीमा तक स्वयं भारतीयों के ही एक बग की लोभ लालमा की उपज थी। उदीयमान राष्ट्रीय नेताओं की श्रम नीति के विस्तृत विरलेपण से पूर्व तीन महत्वपूर्ण तत्वों पर ध्यान देना आवश्यक है। प्रथम 19वीं शताब्दी के अंत तक भारतीय नेताओं की किसी स्वतंत्र श्रमनीति का विकास नहीं हुआ था, वह अधिकांशतः भारत सरकार द्वारा श्रमिकों की कायस्थितियों के नियमन अथवा सुधार के लिए किए गए प्रयत्नों की प्रतिक्रिया के रूप में ही प्रकट होती थी। द्वितीय, नेताओं के दृष्टिकोण के विनियमन के लिए कुछेक नेताओं में श्रम समस्याओं के प्रति विचार-अभिव्यक्ति का अभाव इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सीधी व खुली टिप्पणी। प्रतिम, अधिकांश रूप से आर्थिक अथवा पूणत भारतीय पूजीपतियों के स्वामित्ववाले आधुनिक



फुल्की हलचल स्वयं श्रमिक वर्ग में भी उभरती दिखाई दी। उदाहरणार्थ, राधकान्त राम ने, जो स्वयं एक श्रमिक था और डी० चमनलाल के अनुसार प्रथम श्रमिक नेता के रूप में उदित हुआ था, फक्टरी श्रमचारिया की एक बैठक का आयोजन किया तथा उसने 578 श्रमिकों द्वारा हस्ताक्षरित एक जापान सरकार को भेजा जिसमें काम के दिन 9 घंटे करना और सप्ताह में एक दिन के अवकाश की व्यवस्था की मांग की गई थी।<sup>15</sup> बाद में वागानो रामचंद्र फाकड ने 634 श्रमिकों द्वारा हस्ताक्षरित एक अन्य जापान प्रस्तुत किया था।<sup>16</sup>

भारत और इंग्लैंड में आंदोलन के फलस्वरूप और उसी समय भारत में पूंजीपति हितों द्वारा किए गए प्रबल विरोध का देखते हुए भारत सरकार ने 7 नवंबर 1879 को भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में एक नरम प्रवृत्ति का बिल प्रस्तुत किया। बिल सारे परिवर्तना द्वारा शक्ति क्षीण किए जाने के उपरान्त यह बिल 'इंडियन फक्टरी ऐक्ट—1881' के रूप में कानून बन गया। कानून का प्रमुख सबंध श्रमिक बच्चा की समस्या से था। इसके अनुसार बच्चों को श्रमिक रूप में रखने की 'यूनतम आयु सात वर्ष की निर्धारित की गई थी और 7-12 वर्ष के बच्चों को 9 घंटे प्रतिदिन से अधिक समय काय करने की अनुमति नहीं थी। उन्हे प्रतिदिन इन 9 घंटों से अलग एक घंटे का अवकाश देने की तथा महीने में चार दिनों के अवकाश देने की इस कानून में व्यवस्था थी। एक में खतराक मशीनों के लिए समुचित बाड़ा बनाने और संबंधित स्थानीय सरकार का दुधटाखा की शीघ्र ही रपट करने की भी व्यवस्था थी। ये सारी बातें केवल उन कारखानों पर लागू होती थी जो मशीनी शक्ति का प्रयोग करते थे, सौ अथवा इससे अधिक श्रमिकों को नियुक्त करते थे और वर्ष में चार महीनों से अधिक समय तक चालू रहते थे। नील के कारखानों काय और काफी वागानों को विनैय रूप से इस कानून की सीमा से बाहर रखा गया था।<sup>17</sup> इसके अतिरिक्त पुरुषों और महिलाओं के काम के घंटों का भी नियमित नहीं किया गया था।

इस प्रकार 1881 का इंडियन फॅक्टरी ऐक्ट सबंध प्रारंभिक और सभी व्यावहारिक श्रमियों से साधारण ही था। इस तथ्य को स्वयं सरकार ने जनेक मांदा में स्वीकार किया। स्थानापन सचिव न स्थायी सरकारों का एक परिषद जारी करते हुए लिखा इस ऐक्ट का बनाने समय मिलमालिका के, व्यापारिक मण्डलों के तथा अन्य समस्याओं के प्रतिनिधियों को बड़ी ही सावधानी से महत्व देते हुए उम्बदा ध्यान रखा गया है। इस उद्देश्य को लगातार ध्यान में रखकर इससे अधिक हलका कानून बनाना संभव ही नहीं था।<sup>18</sup>

फॅक्टरी कानून बनाने के लिए प्रारंभिक सघष के प्रति और उसने फलस्वरूप 1881 का इंडियन फॅक्टरी ऐक्ट बन जाने के प्रति राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया लगभग पूर्ण रूप से बर्बई प्राप्त तक ही सीमित थी। इसे अनुचित भी नहीं माना जा सकता क्योंकि इस विषय से जुड़ा सारा मतभेद प्रमुख रूप से बर्बई की कपडा मिला स ही संबंधित था तथा बुल मिलाकर कारखानों के श्रमचारियों की कार्यस्थिति में सुधार की दिशा में किए जा रहे प्रयत्नों की उपेक्षा करने वाला अथवा विरोधी था। उदाहरणार्थ यह उल्लेखनीय है कि बर्बई प्राप्त के अधिकांश राष्ट्रवादी नेता, दादाभाई गोरोजी, एम० जी० रावडे

के० टी० तेलग और फिरोजशाह मेहता, तथा अन्य प्राता के राष्ट्रीय नेताओं ने उस समय अस्तित्व में आ रहे निम्नस्तरीय श्रमिक वर्ग के सबंध में अपने विचार प्रकट नहीं किए। बंबई के अग्रणी जननेता श्री० एन० मालिक ने, जो 1875 के बावे फौकटरी कमीशन के एक सदस्य भी थे, श्रमिकों के हित में कानून बनाने के विरुद्ध बहुमत के साथ अपना मत दिया। यदि बंबई के 'भराठा' और 'इंदु प्रकाश' और बंगाल के 'बंगाली' और 'अमृत बाजार पत्रिका' संपादकीय टिप्पणियों को उनके निजी विचार माना जाए अथवा इस प्रकार की टिप्पणियों के अभाव को ही उनके विचार के रूप में देखा जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि इन पत्रों के ये संपादक क्रमशः बंबई के युवक नेता तिलक अग्रकर और चदावरकर तथा बंगाल के एस० एन० बैनर्जी तथा घोष बंधु, एस० के० घोष तथा मोतीलाल घोष, श्रमिकों के हितों के प्रति उदासीन ही नहीं थे अपितु विरोधी थे।

जहां तक भारतीय समाचारपत्रों का सबंध है, केवल थोड़े से ही, सही गिनती के तौर पर बंबई के केवल चार, समाचारपत्रों ने ही श्रमिक हितों का समर्थन किया। इन पत्रों ने 1874 के ब्रिटिश फौकटरी ऐक्ट के समानांतर इंडियन ऐक्ट बनाने की क्वालता की। 'अखबार सौदागर' ने 24 नवंबर 1874 के अंक में लिखा मिलमालिक निधन श्रमिकों की निधनता का दुरुपयोग करते हैं और उनसे निन्द्यतापूर्वक काम लेते हैं। श्रमिकों को सप्ताह में कम से कम एक दिन का अवकाश मिलना चाहिए और उनके काम के घटे प्रातः 7 बजे से साय 5½ बजे तक होने चाहिए।<sup>9</sup> 'लोकमित्र' ने 29 दिसंबर 1878 के अंक में मिलमालिकों की उसकी स्वायत्तता के लिए निंदा की और सरकार से श्रम के घटों में समुचित कटौती करने का अनुरोध किया।<sup>10</sup> रास्त गोपतार ने 29 दिसंबर 1878 के अंक में और 19 जनवरी के अंक में एस० एम० बंगाली के बिल के प्रारूप को पूरा समर्थन दिया।<sup>11</sup> इस पत्र ने 7 दिसंबर 1879 के तथा 7 नवंबर 1880 के अंक में, 7 नवंबर 1880 के इंडियन स्पेक्टेटोर के अंक और 22 मार्च 1881 के अखबार सौदागर के अंक के साथ सरकार द्वारा प्रस्तुत फौकटरी बिल का समर्थन किया।<sup>12</sup> परंतु दया और मानवता के भावों से ही द्रवित इन थोड़े से समाचारपत्रों में भी थोड़े समय के बाद शीघ्र इस क्षेत्र को छोड़ने की प्रवृत्ति दिखाई दी। 1879 में ही लोकमित्र लेबर कानून का विरोधी बन बैठा।<sup>13</sup> इंडियन स्पेक्टेटोर 7 नवंबर 1880 के अंक में पहले ही इन शब्दों में विरोध प्रकट कर चुका था 'वयस्क श्रम के मामले में अनुचित हस्तक्षेप मिला की आतंरिक आवश्यकता में अनुचित हस्तक्षेप।'<sup>14</sup> यहाँ तक कि अगले वर्ष सरकारी बिल का समर्थन करते करते यह पत्र विरोधी क्षेत्र में चला गया।<sup>15</sup> 'अखबार सौदागर' भी फौकटरी कानून के समर्थन में कभी कभी भटक जाता था।<sup>16</sup> केवल 'रास्त गोपतार' अतः तब श्रमिका के उद्देश्य के प्रति सच्चा और ईमानदार बना रहा।<sup>17</sup> बंगाल के केवल एक समाचारपत्र 'सोमप्रकाश' ने 1881 के फौकटरी ऐक्ट बनने का समर्थन किया।<sup>18</sup> सार्वजनिक मर्यादा में पूना सावजनिक सभा अकेला संगठन था, जिसने माप्ताहिन अवरोध लागू करने की तथा वयस्कों के काम के घट सीमित करने की बगानत की। यह दूमरी बात है कि इस सस्या ने भी 1879 के जिन के प्रारूप की उम्र समय आलाचना की।<sup>19</sup>

इसके विपरीत दूमरी ओर भारतीय समाचारपत्रों की प्रवृत्त बहुरस्य न रिसी

फैक्टरी कानून की आवश्यकता को बड़ी ही प्रचंडता से नकार दिया और कानून की पुस्तक में इस विषय पर अवाञ्छनीय किसी कानून को सम्मिलित करने की चेष्टा का चिल्लाकर विरोध किया तथा उसकी भत्सना की। 1875 में 'जामे जमर्गेद', बंबई समाचार' और 'अरणोदय' ने बाबे फैक्टरी रीमॉशन की नियुक्ति का इस आधार पर विरोध किया कि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी।<sup>40</sup> जून 1875 में बंगाली ने 1878 में फैक्टरी बिल का प्रारूप सामने रखा तो बंबई तथा अंग्र प्रान्त के राष्ट्रवादी समाचार पत्रों ने इस पत्र से असहमति प्रकट की।<sup>41</sup> ब्राह्म समाज के आतिथारी और मुधारक बग के प्रवक्ता बंगाल के 'ब्राह्म पब्लिक ओपीनियन' पत्र ने भी 27 फरवरी 1879 का यही दृष्टिकोण प्रकट किया कि कारखाना कमचारियों के लिए सरक्षक कानून की सवना ही कोई आवश्यकता नहीं है। अमृत बाजार पत्रिका ने अपन 16 मार्च 1880 के अंक में अपनी सामान्य उग्रता से बंगाली के प्रयासों को फिल्ली उड़ाई।

नवंबर 1879 में विधान परिषद में सरकारी फैक्टरी बिल के प्रस्तुत होने का, तब नुमार उस पर प्रवर समिति और परिषद के विचार विमर्श का और उसके फलस्वरूप 1881 में फैक्टरी ऐक्ट के कानूनी रूप बनाने का भारतीय प्रेम न चीख चिल्लाहट द्वारा अपनी जमहमति लिखार विरोध ही किया। चांदी के राष्ट्रवादी तथा समाजमुधार के समर्थक पत्रों 'दु प्रकाश' (22 मार्च 1880, 21 मार्च 1881 और 4 अगस्त 1884), 'गुजराती' (28 नवंबर 1880 और 27 मार्च 1881), 'इंडियन 'स्पेक्टेटर' (20 मार्च 1881) 'नटिव ओपीनियन' (27 मार्च और 19 जून 1881) और 'गान प्रकाश' (30 जून 1881) ने इसके प्रति विरोध प्रकट किया।<sup>42</sup> पूना सावजनिक सभा की सामान्य सभामें त्रमासिक पत्रिका ने, जो उस समय बंबई के देशभक्ता की अभिव्यक्ति का मंच बनी हुई थी, घोषणा की 'फैक्टरी अधिनियम को नियमित करने के लिए कानूनी कार्यवाही का लक्ष्यमात्र भी जोचित नहीं।<sup>43</sup> उस समय बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित 'मराठा' ने 13 मार्च 1881 के अंक में इस कानून के विरुद्ध प्रचंड विरोध प्रकट किया। बंगाल के दो अग्रणी राष्ट्रवादी समाचारपत्रों 'अमृत बाजार पत्रिका' और 'बंगाली', न ब्राह्म पब्लिक ओपीनियन के समान इस कानून की भत्सना की।<sup>44</sup> इलाहाबाद के 'हिंदी प्रदीप' ने भी इसी प्रकार के भाव प्रकट किए।<sup>45</sup> कुन मिलाकर बंबई और बंगाल के अत्याप्य जनस्य समाचारपत्र इस बिल और उसके अंतिम रूप 1881 के इंडियन फैक्टरी ऐक्ट, के विरुद्ध सामूहिक राग अलापन में उत्सुकतापूर्वक सम्मिलित हुए गए।<sup>46</sup>

उस समय के आलोचकों ने फैक्टरी कानून के विरुद्ध ऐसे ऐसे मजेदार और अनाड़े तक प्रस्तुत किए कि जो अपने निष्कर्ष में आज के पाठकों को सुनने में मस्तिष्कजली और घृणित नहीं तो भ्रू अक्षय प्रतीत होंगे। उदाहरणार्थ, फैक्टरी कानून की अनावश्यकता को सिद्ध करने के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत एक तर्क था स्वयं श्रमिकों की ओर से न तो कोई मांग पत्र की गई है और न ही उनकी आर से किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त है। इन आलाचना के अनुसार श्रमिक तो नितात स्वच्छता से ही लगे समय तक कार्य करने को सहमत हैं।<sup>47</sup> अमृत बाजार पत्रिका ने 12 नवंबर 1880 के अंक में इस दृष्टिकोण को गंभीर म इस प्रकार प्रस्तुत किया 'यदि श्रमिकों पर कारखाना में भारी क्षत्याचार





माता पिता पर भाररूप ही जाएंगे।<sup>56</sup> जहां तक बच्चों का संवर्धन था, इन आलोचकों के अनुसार इस ऐक्ट का निरुद्भूत परिणाम यह होगा कि बाल अपराधों की संख्या में तर्जनी से वृद्धि हो जाएगी क्योंकि फैक्टरी की नौकरी से हटाए हुए लड़के या तो भोग-मागन पर, या उधार-मागन पर या चोरी करने पर मजबूर हो जाएंगे।<sup>57</sup>

फैक्टरी कानून के विरुद्ध राष्ट्रवाद्या की प्रबलतम आपत्ति का आधार यह विद्वान् था कि यह कानून लकाशायर व कारखानों के मुकाबले भारत के पनपते सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन व्यय में वृद्धि और उसके फलस्वरूप उसकी प्रतियोगिक सामर्थ्य में ह्रास करके इस उद्योग के विकास को बाधित करेगा।<sup>58</sup> कुछ राष्ट्रवादियों ने तो इसे विनाश के दैत्य का दरजा दे डाला। 13 मार्च 1881 के अंक में 'मराठा' ने विलाप करते हुए लिखा 'भारत का शिशु उद्योग डूब गया है। कुछ एक भारतीय नेताओं ने तो खुले तौर पर दहता से यह स्वीकार किया कि औद्योगिक विकास की बड़ी भारी आवश्यकता दृष्टिगोचर करते हुए कारखानों के मजदूरों के हितों का अनिदान भी करना पड़े तो उसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, 'अमृत बाजार पत्रिका' ने 2 सितंबर 1875 के अंक में अपना मत प्रकट करते हुए लिखा 'इस पनपते उद्योग का गला घोटने की अपेक्षा कारखानों के कमचारियों की अपेक्षाकृत बड़ी हुई मृत्यु दर ही वाञ्छनीय है। जब एक बार हमारे उत्पादन व्यवस्थित हो जाएंगे तो हम इन श्रमिकों की सुरक्षा का उपाय भी ढूँढ लेंगे।'<sup>59</sup> इसका साथ-साथ यह भी कहा गया कि कमचारियों के दृष्टिकोण से भी यह कानून हानिप्रद है क्योंकि इसका परिणाम साने का अडा देने वाली मुर्गी का मारना होगा। सूती वस्त्र उद्योग के विकास पर लगी किसी भी प्रकार की पाबंदी का बदले में यह फल होगा कि स्वयं कमचारियों की आय के और उनकी आजीविका के साधन प्रभावित होंगे।<sup>60</sup>

कई एक भारतीय नेतृत्व ने शांतिपूर्वक चल रहे निजी औद्योगिक उद्यम में खतरे से भरे हुए राज्य के हस्तक्षेप की प्रवृत्ति पर आपत्ति की।<sup>61</sup> उनके अनुसार उपयुक्त ढंग यह था कि स्वामी और सेवकों के झगड़ों को आपसी मोहोद से ही सुलभने लिया जाए।<sup>62</sup> भारतीय नेताओं ने दहतापूर्वक कहा कि यदि सरकार किसी भी स्थिति में इस संवर्धन के कानून बनाने पर तुली हुई ही है तो यह कानून सारे ब्रिटिश भारत में लागू होना चाहिए ताकि बंबई प्रांत के भारतीयों के स्वामित्ववाले उद्योगों के विरुद्ध अयाय प्रांतों के अगरेजों के स्वामित्ववाले उद्योगों को किसी प्रकार का लाभ न पहुंच सके और दाना में किसी प्रकार का भेदभाव न हो।<sup>63</sup> इसी प्रकार यूरोपियों के स्वामित्ववाले चाय और काफी बागान नीचे के कारखानों तथा इंग्लैंड का बच्चे माल के निर्यात का संवर्धन करने पर भी आपत्ति की गई। यह भेदभाव उस स्थिति में और भी अधिक अरुचिकर था जबकि रईस पिजने घुनने वाले छोटे कारखानों में तथा चाय और नीले के क्षेत्र में काम करने वालों की स्थिति बंबई के आधुनिक कपड़ा मिलों की कमचारियों की स्थिति से अधिक विषम थी। पत्रक यह कहा गया कि 'जोकेवा पर तुली हुई सरकार को सहायता की अपेक्षा रखने वाले भारतीय उद्योगों की संवर्धन के साथ देखभाल करनी चाहिए।'<sup>64</sup>



असंतुष्ट थे ही, फिर यह एक लकाशायर के उत्पादका का भी संतुष्ट न कर पाया क्योंकि व भारत में बढ़ते हुए सूती वस्त्र उत्पादन तथा भारत में ब्रिटिश वस्त्र के निरंतर गिरते आयात के कारण घटता हुआ था।

1882 में बर्बई सरकार ने अंग्रेजी कारखाना के इस्पेक्टर मीडे किंग को बर्बई प्रांत में कारखाना की कार्यप्रणाली की जांच पड़ताल के लिए नियुक्त किया। उसने कारखाना में बहुत सारी गलत बातों को प्रचलित पाया और वर्तमान कानून का अपर्याप्त घोषित किया।<sup>69</sup> उसने स्थिति में सुधार के लिए कुछ सुझाव भी दिए। 23 मई 1884 को बर्बई सरकार ने सुझावों की व्यावहारिकता के अध्ययन के लिए और समस्त विषय पर पूर्ण विचार के लिए एक जांच आयोग की नियुक्ति की। आयुक्तों ने, जिनमें चार मिल मालिकों के प्रतिनिधि थे — मूल कानून में साधारण की सिफारिश की। उन्होंने निम्न लिखित व्यवस्थाएँ जोड़ने का सुझाव दिया — बच्चा के और स्त्रियों के काम के घंटे का अधिकतम सीमा प्रमश 9½ और 11½ घंटे निर्धारित हो। उन्हें महीने में चार दिनों का अवकाश मिले। बच्चा की न्यूनतम और अधिकतम आयु प्रमश 9 और 14 वर्षों तक बढ़ाई जाए।<sup>70</sup> भारत सरकार को आयोग का प्रतिवेदन कार्यवाही करने के लिए भेजा गया परंतु वह वर्तमान कानून में सामान्य संशोधन से महत्व नहीं थी अतः उसने उस समय इस संबंध में जागे और कोई भी कार्यवाही नहीं की।<sup>71</sup>

परंतु मामला यही रूक नहीं गया। एक बार फिर इंग्लैंड में एक तीव्र आन्दोलन उठ खड़ा हुआ जिसकी मांग थी कि भारत में कठोर इंग्लिश फबटरी कानून लागू किया जाए। संसद सदस्यों ने बार-बार हाउस आफ कामंस में और उसके बाहर इस विषय को दाहराया। वाणिज्य मंडल का यह तथ्य जानकर भारी निराशा हुई थी कि भारत में कपास कर हटाने पर भी भारत के सूती वस्त्र उद्योग के विकास में किसी प्रकार की बाई बाधा उपस्थित नहीं हुई। अतः उन्होंने राज्य सचिव से अनवरत रूप से मांग की और उसके बदले में राज्य सचिव ने भारत सरकार पर इस संबंध में कार्यवाही करने के लिए निरंतर दबाव डाला।

इस समय इस स्थिति में एक नया तत्व देखने में आया। इस समय जाय और अधिकार के ध्यान पर उपकार और मानवता की दुहाई दत्त हुए नितांत दृढ़ स्वर में श्रमिक धीरे धीरे स्वयं ही अपनी मांगें पेश करने लगे। इसके साथ ही इन मांगों का रूप सरकार से आगे आने और श्रमिकों की सहायता करने की विनीत विनितिया का था। मजदूरों द्वारा अथवा मजदूरों की ओर से संचालित आंदोलनों के प्रेरणा स्रोत एन० एम० लोखंडे थे। उन्होंने 1880 में 'दीन बंधु' नाम से एक 'एंग्लो मराठी साप्ताहिक पत्र' चलाया और कारखानों के कर्मचारियों के हितों को ही उस पत्र का उद्देश्य बना दिया।<sup>72</sup> उन्होंने 1884 में बर्बई के कपड़ा कारखानों के कर्मचारियों के दो सम्मेलनों का आयोजन किया जिनमें कर्मचारियों ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित मांगों के प्रस्ताव स्वीकार किए सभी कारखानों के कर्मचारियों के लिए रविवार का अवकाश रहना चाहिए। सभी कर्मचारियों के काम के घंटों की सीमा प्रातः 6½ बजे से सूर्यास्त तक रहनी चाहिए। साप्ताहिक को आधे घंटे के अवकाश की व्यवस्था रहनी चाहिए।<sup>73</sup> श्रम का उपाजित

चेतन आने नहीं की 15 तारीख को भिन्न जाना चाहिए। औद्योगिक दुष्टताओं की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। इन मांगों का 5:00 श्रमिका द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन में सम्मिलित किया गया था और उस ज्ञापन को उस समय अपने को श्रमिक संघ के अध्यक्ष होने का दावा करने वाले लोखंडे ने अक्टूबर 1894 में बंबई फँक्टरी आयोग का नेता था।<sup>18</sup> परवर्ती सत्र वर्षों में लोखंडे तथा अन्य महानुभाव सम्मेलन और जारनों के द्वारा श्रमिकों की मांगों पर कानून बनाने के लिए सरकार पर बराबर दबाव डालते रहे।<sup>19</sup> लोखंडे के प्रयास का भारत में प्रथम श्रम आंदोलन का प्रारम्भिक रूप मानना अनिश्चित होगा क्योंकि वास्तव में यह आंदोलन कदापि न था।<sup>20</sup> जैसा कि उनकी पत्रिका के शीर्षक के शब्दावली में ही घोषित है लोखंडे महोदय श्रमिकों के संगठन नहीं बने, बह तो केवल श्रमिकों के हिनेच्छु भिय थे।<sup>21</sup> इन लोखंडे का न तो कानिकारी नेता माना गया और न ही उन्हें किसी प्रकार सरकार द्वारा दंडित किया गया। जबकि नील उद्योग में सर्वप्रथम आंदोलन के आयोजकों तथा महापुरुषों का दंडित किया गया था उन्हें 1890 के फँक्टरी कमीशन का स्थानीय सदस्य नियुक्त कर दिया गया।

इन सबके में यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जब कभी भारत में फँक्टरी कानून जारी करने के लिए इंग्लैंड में आंदोलन छिड़ा भारतीय और ब्रिटिश उत्पादकों ने भारत में राज के हस्तक्षेप के विरुद्ध तत्काल प्रबल जवाबी आंदोलन छोड़ दिया। उनके द्वारा प्रस्थापित तर्क थे भारतीय श्रमिकों को किसी प्रकार के कानूनी संरक्षण की अपेक्षा नहीं। किसी भी प्रकार के नए कानून से देश के शिशु उद्योगों के क्षतिग्रस्त होने की ही संभावना है। अतः इस प्रकार के माजुक मामले में बाहरी लोगों को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं।<sup>22</sup>

उस ओर में एक दबाव और उस ओर से दूसरे दबाव से आहुल-व्याहुल भारत सरकार ने अतः 1881 के फँक्टरी ऐक्ट में संशोधन के लिए 31 जनवरी 1890 में लेजिस्लेटिव कांसिल में एक बिल पेश किया।<sup>23</sup> कमीशन की व्यवस्थाएँ इटियन फँक्टरी कानून को इंग्लिश फँक्टरी कानूनों के समकक्ष बनाने में पर्याप्त नहीं थी। इस अंतर ने एक बार पुनः इंग्लैंड के दबाव डालने वाले का जो असंतुष्ट कर दिया और वह अधिक मात्रा में प्रावधानों के लिए पुनः संघर्षरत हो गए।<sup>24</sup> मार्च 1890 में बर्लिन में हुए अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों के निष्पत्तियों में उनके आंदोलन को और प्रोत्साहन मिला।<sup>25</sup> फ्रान्स राज्य सचिव ने जिन्होंने पहले बिल के प्रारूप को स्वीकृति दी थी जब अपक्षत्रित अधिक कठोर पग उठाने के लिए और एक अन्य आयोग को नियुक्त करने के लिए दबाव डाला।<sup>26</sup> भारत सरकार ने बंबई बंगाल उत्तर पश्चिमी प्रांतों और अवध के कारणाना में नियुक्त श्रमिकों की स्थितियों की जांच पड़ताल के लिए अक्टूबर 1890 में एक अन्य आयोग की नियुक्ति की।

कमीशन की सिफारिशों इस प्रकार थी एक महिला श्रमिका के दैनिक कार्यालय की सीमा 11 घंटे निर्धारित की जाए। बच्चों के काम के समय की सीमा 11 घंटे प्रतिदिन कर दी जाए। सभी काम गारियों के लिए, इतने 11 घण्टों 11 घण्टों प्रतिदिन किया गया था, एक दिन के साप्ताहिक अवकाश की 11 11 11 11

उन रई पीजने धुनन बातने के कारगना म भी नही, जिनके बारे में उन्होंने दबी जवान से स्वीकार किया कि वहाँ काम कभी कभी बंद हो जाता था।<sup>100</sup>

राष्ट्रवादी नेताओं का यह बग तो विरोध रूप में ही व्यक्त पुरुष श्रमिका के काम बंद होने का सीमित करने के विरुद्ध था। इस बग ने यह मानने से ही इनकार कर दिया कि भारतीय श्रमिक काम से दूर हुए हैं अथवा उन्हें अधिक लंबे और बंद होने तक काम करना पड़ता है। इन नेताओं के अनुसार मजदूरी तीर पर जो दिखाई देता है, व्यवहार में वास्तविक सत्य वह नहीं है। मराठा ने 20 दिसंबर 1888 के अग्र में लिखा कि विचारणीय तथ्य यह है कि भारतीय श्रमिक का मजदूरी में काम करने का एक अपना दग है। थाप उस घटो लगातार काम पर लगाए रखिए फिर भी आपको यही देखने को मिलेगा कि वह जपन को काम में दवा अनुभव नहीं कर रहा। वह बीच बीच में काम छोड़कर बाहर जान और आराम करने का अवसर निम्न ही लेगा।<sup>101</sup> 18 जनवरी 1889 के 'सुलभ समाचार' और 'बुधदाह पत्र' के अनुसार तो भारतीय कारखाना के काम के घटे उत्पन्न विदेशी देश के अनुकूल हैं और विदेशी श्रमिकों की अपेक्षा अधिक बंद श्रम शील और सहनशील भारतीय श्रमिकों की प्रवृत्ति के भी सजथा अनुकूल हैं।<sup>102</sup> इसके अतिरिक्त जोर देकर यह कहा गया कि काम के अपेक्षाकृत थोड़े घटे स्वयं श्रमिका के ही हित में नहीं होंगे क्योंकि इसे ग्रहण करने का जय उनके वेतन को नीचे लाना होगा।<sup>103</sup>

एक दिन के साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था का बहुत ही कम विरोध हुआ। इसका प्रमुख कारण, जैसा कि पहले बना चुके हैं, यह था कि मालिक लोग पहले ही जून 1890 में इसे मान्यता दे चुके थे।<sup>104</sup>

महिला श्रमिकों की नियुक्ति मजदूरी व्यवस्था के विरुद्ध राष्ट्रवादियों को आपत्ति सचमुच अत्यंत आवश्यक नहीं थी। समाज सुधार, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह तथा एक आफ कानॉन बिल की आयु के प्रबल तथा उत्साही समर्थक 'इंद्र प्रकाश' ने इस सब में इस प्रकार अपना विचार प्रकट किया 'यह दुख की बात है कि सरकार ने भारतीय कारखाना में महिलाओं की नियुक्ति के मामले में हस्तक्षेप करना उपयुक्त समझा। नई व्यवस्था के अनुसार उन्हें रात को काम देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तथा अनुमत काम के 11 घंटों में उन्हें एक बहुत लंबे समय तक विश्राम के लिए अनिवार्य रूप से अवकाश की व्यवस्था की गई है।'<sup>105</sup> अधिक 'रिजर्व' मराठा भी इन समाज सुधारकों से पीछे नहीं रहा। उनमें अपना मत प्रकट करते हुए 7 दिसंबर 1890 को लिखा 'आयुक्तों ने अपने प्रतिबंध में यह नहीं भी नहीं लिखा कि काम के अप्रतिबंधित घंटों के कारण भारतीय कारखाना में काम करने वाली महिला श्रमिका के स्वास्थ्य को किसी प्रकार की हानि पहुँचती है अतः हमारे विचार में सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।' बाद में जब मार्च 1892 में यह समाचार मिला कि 'अप्रदाया' में महिला श्रमिका की छुट्टी की जा रही है तो राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने यह मांग की कि फक्टरी ऐक्ट को महिलाओं के काम के घंटों को सीमित करने वाली धारा को महिलाओं के हित की दृष्टि से स्थगित कर देना चाहिए।<sup>106</sup> परंतु उनमें से किसी एक भी समाचारपत्र ने महिला का इस स्थापित वायव्यही का करने में निवृत्त होने के लिए

उनकी आलोचना करने अथवा उन्हें सनाह देने के रूप में एक शब्द भी नहीं लिखा।

इसी प्रकार कारखानों में नियुक्त किए जाने वाले बच्चा की यूनानतम आयु बढ़ाने और उनके काम के घटे घटाने की व्यवस्था का भी विरोध इस आधार पर किया गया कि इसका परिणाम निधन श्रमिकों की पारिवारिक आय में कटौती होगा।<sup>107</sup> 'सुरभि ओ पताका' ने 10 अप्रैल 1891 के अंक में शांताबुल भाषा में लिखा कि इस व्यवस्था के पश्चात् स्वस्थ लड़की लड़के अपने विप्लवग माता पिता की सहायता नहीं कर पाएंगे।<sup>108</sup> एक बहूत पुराना तर्क, काम न करने वाले बच्चे अपराधी बन जाते हैं, भी इस समय पुनः दोहराया गया। भारत में समाज सुधार में अग्रणी हिंदू ने 16 सितंबर 1891 के अंक में लिखा 'हमारी बच्चों की आशाएँ, श्रमिक बच्चे, या तो अपने माता पिता की सहायता के लिए श्रमणाय में सन्तुष्ट रहेंगे, अथवा अपने खाली समय में पुलिस और जपराध शाखा के अधिकारियों के लिए नए नए आविष्कार करेंगे। कारखाने तो अविद्यालय में बच्चा को डम हानिप्रद भाग में बचाते हैं।'<sup>109</sup>

राष्ट्रवादी नेताओं के उस वक्त की यह निश्चित धारणा थी कि नए फक्टरी कानून का अंतिम परिणाम श्रमिकों की स्थिति में किसी प्रकार का सुधार नहीं होगा प्रत्युत इससे भारत के विकासशील क्षेत्र उद्योग का विनाश ही होगा।<sup>110</sup> यह भी एक मजे की बात है कि कांग्रेस के मंच सश्रमिक पक्ष की बात बचल एक बार उस समय उठाई गई जब 1895 में अपने अध्यक्षीय भाषण में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने काम के घंटों पर प्रतिबंध लगाने वाले और उत्पादन व्यय में वृद्धि करने वाले फक्टरी कानून के प्रयोग के विरोध चलावनी दी। उन्होंने यह भी निर्देश किया कि यहाँ तक कि इंग्लैंड के अतिरिक्त जापान भी वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत का प्रबल प्रतिद्वंद्वी है।<sup>111</sup> इसने अतिरिक्त राष्ट्रवादियों ने अनुभव किया कि यदि भारतीय उद्योग पशु हो गया तो इससे श्रमिक ही सबसे अधिक घाटे में रहेंगे क्योंकि वे बेकारे आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन खो बैठेंगे। 10 जनवरी 1900 के अंक में 'अमृत बाजार पत्रिका' ने इस दृष्टिकोण को सक्षिप्त रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया 'कृपापूर्वक, निरपेक्ष भाव से श्रमिकों के काम के घटे घटाने और उन्हें एक दिन का साप्ताहिक अवकाश देने की वकालत करने वाले परोपकारी लोग क्या मिला के बंद हो जाने पर इन श्रमिकों का अपनी जेब से पालन पोषण करेंगे?' भारत की आवश्यकता है अनाज की पर्याप्तता और उसके लिए भारतीय कुछ भी करेंगे। 16 घंटे प्रतिदिन काय करना भी अधिक नहीं है।<sup>11</sup>

1881 के फक्टरी कानून के समान ही 1891 में फक्टरी कानून के लिए आंदोलन की राष्ट्रवादियों द्वारा अस्वीकृति के पीछे उनका यह विश्वास काम कर रहा था कि यह सब कुचले हुए भारतीय श्रमिकों की शुभकामना की भावना से प्रेरित न होकर लकाशायर की अपने प्रतिद्वंद्वी भारत का गला घोटने की भावना से ही प्रेरित था।<sup>112</sup> बंगाली ने अपने 27 अप्रैल, 1889 के अंक में इस सचित्र रूप में प्रस्तुत करत हुए लिखा कि वस्तुतः लकाशायर के उत्पादक और परोपकारी लोग भारत के प्रति ठीक उसी प्रकार की हितकामना की भावना रखते हैं जैसी एक जंगली पशु में अपने शिकार के प्रति होती है। वस्तुतः श्रम कानून उस नीति की परंपरा में है जिसके अंतर्गत पहले ही बचाव पर

तक यह नहीं हा जाता, तब तक कानून की इस धारा को अग्न्याई रूप से स्थगित रखा जाए।<sup>134</sup>

भारतीय नताओं न पटल की ही तरह यह भय प्रकट किया कि खान कानून खान उद्योग के विरोधत भारतीयों के स्वामित्ववादी भाग के विकास को नुसतान पहुँचाएगा।<sup>135</sup> उन्होंने खुन नीर पर अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि इसकी सरचना इंग्लैंड के वायना उद्योग का सहायता के लिए की गई है।<sup>136</sup> मत्प यह है कि इस मामले में हम दाप के लिए काट ठोस आधार नहीं था।

### राष्ट्रवादी नीति का आधार

अब तक हमने श्रमिका व पक्ष म कानूनी इम्प्लैण्ट के सदम म भारतीय कारखाना और खान उद्योग म नियुक्त श्रमिका को बटनी समस्याओं के निमी न किता पक्ष पर स्पष्ट विचार प्रकट करने बाल भारतीय राष्ट्रीय नताओं व बटुत बडे का व विरोधी स्व की समीक्षा की है। इसके साथ ही हमने यह भी दसा है कि श्रमिका की साधारण मांग के प्रति भी बाडे न राष्ट्रवादिप्रो न ही अपना समथ प्रकट किया है। हमने यह देखा कि यह विरोध न तो प्रचड था और न ही व्यापक। लकानायर की भूमिका का उल्लेख जाने पर ही उग्रता और व्यापकता आ जाती थी। अथवा यह विरोध एक प्रकार से उल्लाहरहित ही था। इसी प्रकार श्रमिका की मांग के प्रति समयन भी टूट दिल से था और परिणाम-स्वरूप महत्वशून्य था। इन दोना तथ्या की पुष्टि भारत सरकार की गतिविधिया की मानिका व प्रति पक्षपातपूर्ण प्रवृत्ति में तथा भारत सरकार द्वारा लाए गए अथवा कानूनों की मालिका की दृष्टि म साधारण प्रवृत्ति से हा जाती है। बर्बई भिन्नमानिक मध के 1891 के वष के प्रतिबन्धन स इस मत्प का समयन होता है। 1891 के फक्टरी एक्ट का उद्भूत करते हुए प्रतिबन्धन म कहा गया है ये परिवन्धन मध के सदस्या द्वारा पहने स ही समाधिंत दृष्टिकोण के बाहर नहीं जात। अत बिल पर विचार विमग करते समय किसी प्रकार का मज्रुतापूर्ण दृष्टिकोण ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं।<sup>137</sup> मुभाए गए अथवा कानून का रूप दिण गए अधिकाग उपायो की मालिका द्वारा म्बीवृत्ति व तथ्य को समकालीन कई समाचारपत्रा न भी अनुभव किया।<sup>138</sup> 1885 के बाव फँक्टरी कमीशन के जाच परिणामा के 1890 के फँक्टरी कमीशन की सिफारिशा के और 1890 के फँक्टरी अधिनियम व मानिका द्वारा किए गए अधिहून समयन में हम हम निष्पक्ष पर पहुँचते हैं कि राष्ट्रवादिया द्वारा किया गया विरोध मालिकों के प्रति वफादारी का एक विचित्र रूप है।<sup>139</sup>

भारतीय नताओं द्वारा प्रस्ताविन अथवा वास्तविक श्रम कानून का जो समयन अथवा विरोध हुआ उमम बन्दर अधिव महत्वपूर्ण जान यह था कि कारखाना तथा खानों के कर्मचारियों के अत्यंत दमित वग के प्रति इन नताओं म सत्रिय मजानुमूनि का लगभग पूर्ण अभाव था। राष्ट्रवादी आर्थिक चिन्तन के समयक किसी भी महानुभाव न इस विषय में लगभग कुछ भी नहीं कहा। भारतीय राजनीति म न्यायमूर्ति के रूप में विख्यात तथा ममाजमुधारणा म अग्रगण्य रानाडे श्रमिक वा के पूरण मोन थे।<sup>140</sup> भारतीय





सबसे उहेनिर्दीय नहीं ठहराया जा सकता। उनकी इस उपेक्षा का कारण यह भी हो सकता है कि उन्होंने फैक्टरी कानून की प्रत्येक चेष्टा के पीछे या तो माचेस्टर का हाथ देखा, जो बहुत ही पुले तौर पर नजर नहीं आता था अथवा विदेशी प्रतियोगिता के खतरे का देखा। उन्होंने विकासशील श्रमिक वर्ग की वस्तुगत आवश्यकताओं और हितों का ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार वे औद्योगिक पूँजीपति वर्ग के मुस्त्रिया बन गए अथवा कम से कम उनके हाथ में खेलते रहे। इसके अतिरिक्त यहाँ तक कि औद्योगिकता की समस्या को भी उन्होंने पूर्णतः और ममग्रत मालिकों की आँख से ही देखा। भारतीय उद्योगों की प्रतियोगी स्थिति विदेशी प्रतियोगिता में मुद्यार का भारतीय मालिकों द्वारा कल्पना दृष्टि तथा अधिकांश भारतीय नेताओं द्वारा समर्थित उपाय था, उत्पादन व्यय को बनाए रखना और इसके लिए अपनाए जाने वाले साधन थे, थोड़ा वेतन और काम के लंबे घंटे आदि अथवा संक्षेप में श्रमिकों से कमरतोड़ काम लेना। वस्तुतः भारतीय नेताओं ने अनवहे और परोक्षरूप से लकाशायर के इस आरोप को स्वीकार ही कर लिया कि श्रमिकों का अत्यधिक शोषण भारतीय उद्योग का परोक्ष संरक्षण दे रहा था। भारतीय नेताओं को तब तो यह सूझा कि लाभान को घटाने में भारतीय उद्योग की प्रतियोगी स्थिति सुधर सकती है और न ही यह सूझा कि श्रमिकों को प्रात्माहन देना अथवा अन्य किसी इस प्रकार के उपायों को अपनाने से औद्योगिक उत्पादकता सुधर सकती है।<sup>114</sup> वस्तुतः इस अवधि में भारतीय श्रमिक की उत्पादकता में वृद्धि इतनी द्रुत थी और भारतीय कारखानों को होने वाले लाभ इतने ऊँचे थे<sup>115</sup> कि अगरेज प्रतिद्वन्द्वियों के साथ भारतीय उद्योग की प्रतियोगी स्थिति का थोड़ा भी सीमा में भी दुबल बनाए बिना ही श्रमिकों की स्थिति में आसानी से सुधार किया जा सकता था। परंतु कालावधि में तो भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने आधुनिक उद्योग के हितों के रूप में समग्रत पूँजीपतियों के हितों पर ही ध्यान दिया।

निस्संदेह हम यह नहीं कहना चाहते कि उस विशिष्ट ऐतिहासिक घड़ी में और तत्कालीन राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों में भारतीय नेता कोई ऐसा पग उठाते अथवा उहे उठाना चाहिए था जो भारतीय समाज के उभरते दो गण वर्गों के बीच बग संघर्ष पनपाता। अथ किसी प्रयोजन से न सही, राजनीतिक उद्देश्य से तो निश्चित ही देश की राजनीतिक और आर्थिक मुक्ति के मधर्ष के लिए सभीदेशवासियों को संगठित करना न केवल लाभप्रद प्रत्युत आवश्यक भी था। यह एक स्वतः सिद्ध सत्य है कि उस समय भारतीयों द्वारा अपनाया गया आंदोलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम था और किन्हीं भी अन्य आधारों पर वर्गों को विभाजित करना कल्पित वाछनीय नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे ही अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी ने इस मिद्धात की प्रस्थापना की कि कांग्रेस, सभी देशवासियों के समान रूप से प्रत्यक्ष हित के विषयों तक ही अपन को सीमित रखे और समाजसुधारों की व्यवस्था तथा अन्य वर्गीय प्रश्नों को वर्गीय समस्याओं के लिए छोड़ दे।<sup>116</sup> परंतु राष्ट्रीय संगठन के भीतर ही भीतर मतभेद, हितों में संघर्ष तथा यहाँ तक कि विवादा उठ सकते थे और उठे भी। उन विवादा का हटाने और सुलभाने में ही राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा किए गए प्रयत्न में उतका पक्षपात उभरा। मालिकों और श्रमिकों के

बीच विवाद खड़े होने पर राष्ट्रवादी नेताओं ने दोनों विवादाधीन दलों में आपसी लेन-देन के आधार पर दोनों में समझौते का कोर्ष भी मुस्खा नहीं बनाया। वे या तो मौन रहे जिसका अर्थ अपेक्षाकृत अधिक सशक्त पक्ष की स्थिति का स्वीकृति के रूप में समझना था अथवा उन्होंने व्यापक राष्ट्रीय हिता की वकालत की जिम्मा स्पष्ट अर्थ वारखाना और खाना के श्रमिकों के हितों की पूर्ण उपेक्षा था। औद्योगिक क्षेत्र में राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति अर्थात् भारतीय उद्योग के विकास और उसकी संपन्नता का दृष्टिकोण अपनाते के फलस्वरूप श्रमिक वर्ग के हितों की बलि चढ़ा दी गई। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारतीय नेताओं ने श्रमिक-हितों के विरुद्ध अन्याय विषय में अभिशाप माने जाने वाले ब्रिटिश पूँजीपतियों और नौकरशाही के साथ सामान्य उद्देश्य अपनाने में भी सकोच नहीं किया।

प्लेटेशन लेबर ऐंड दि इंग्लैंड एमिग्रेशन ऐक्ट, 1882

(1882 का वागान श्रम तथा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम)

जहाँ तक ब्रिटिश स्वामित्ववाले वागानों में नियुक्त भारतीय श्रमिकों का संबंध था, भारतीय राष्ट्रीय नेताओं का दृष्टिकोण ठीक विपरीत था। नेताओं की स्थिति में यह पूरी की पूरी तन्दीली चाय वागान में नियुक्त सामान्यतः असम कुली कहे जाने वाले हजारों श्रमिकों के कष्ट और जीवन के प्रति अपनाए गए उनके दृष्टिकोण में जितनी स्पष्ट है, उतनी अन्यत्र नहीं कहीं। वागान श्रमिकों की दुदशा की ओर भारतीय नेताओं ने हार्दिक सहानुभूति और पूरी तत्परता के साथ ध्यान दिया। उन्होंने क्रूर विदेशी पूँजीपतियों की भत्तना की। असुरक्षित और बेजवान श्रमिकों के दुभाग्य पर आसू बहाए और उत्सुकता-पूर्वक उनके मामले की वकालत की। इस मामले में उन्होंने राष्ट्रीय भावना का अच्छा प्रदर्शन किया तथा सामूहिक राष्ट्रीय अपमान के तथा क्षत विक्षत राष्ट्रीय गर्व के सुप्त भावों को जगाने के लिए तथा असह्य हृदयों में राष्ट्रीयता की ज्योति जगाने के लिए कुलियों द्वारा अनुभूत दुभाग्य और लज्जाजनक अवहेलनाओं का सही उपयोग किया। स्थिति में यह प्रत्यावतन पूरी सावधानी से उठाया गया पण था क्योंकि इस मामले में मालिक विदेशी थे। 1891 में कांग्रेस के सभापति पी० आनंद चारलू ने 1901 में लैंजिस्लेटिव कौंसिल में असम लेबर ऐंड इमिग्रेशन बिल पर अपने भाषण में इस दृष्टिकोण को बड़े ही विशद और सक्षिप्त रूप में इस प्रकार प्रकट किया है

यदि मालिक और नौकर एक ही राष्ट्र के आवश्यक अंग हों तो कदाचित्त इस प्रकार के कानून के लिए आग्रह की आवश्यकता नहीं क्योंकि इस प्रकार की स्थिति में भेद-भाव का अवकाश थोड़ा होता है और पारस्परिक भावतुल्य की भावना अपेक्षाकृत अधिक होती है। परंतु जहाँ इस प्रकार के पारस्परिक सदभाव का  $\times \times \times$  आदान प्रदान का वातावरण न हो, इतना ही नहीं प्रत्युत स्थिति तथा  $\sim \sim \sim$  वहाँ एकपक्षीय प्रमादजय अयायपूर्ण प्रवृत्तियों के विचारण के लिए तथा समझौते के लिए इस प्रकार के कानून की एक प्रकार से अनिवार्यता  $\sim \sim \sim$  जाती है।<sup>147</sup>

राष्ट्रीय नेताओं के निणय को प्रभावित करने वाला दूसरा तत्व यह था कि असम के चाय बागान में श्रमिक इकरारनामे द्वारा अनुबधित थे और चाय की स्थिति मजदूरी अहितकर थी।

चाय उद्योग का भारत में वास्तविक प्रारंभ 1851 में कहा जा सकता है। इससे उपरांत इसने तीव्र गति से विकास किया। हमारे अध्ययन की अवधि में अधिकांश चाय बागान असम में स्थित थे। 1903 में इस उद्योग में 479,000 स्क्वार्ड और 93,000 स्क्वार्ड श्रमिक कार्यरत थे।<sup>148</sup> असम की जनसंख्या विरल होने के कारण और चाय बागान के प्रायः निम्न पहाड़ी ढलानों पर अवस्थित होने के कारण बगान तथा अत्याय प्राना में अत्यधिक आवश्यकता के अनुरूप विपुल संख्या में लोगों को मगाना पड़ता था परंतु प्रति वर्ष हजारों श्रमिकों को अपने घरों से बहुत दूर अस्वस्थ वातावरणवाली तथा विविध रोगों से दूषित धरती पर लाना आर्थिक और अत्याय प्रलोभनों की व्यवस्था की अपेक्षा करता था और असम के चाय बागान के मालिक यह सब करने का प्रस्तुत नहीं थे। इसके बदले उन्होंने छल-कपट और जोर-जबरदस्ती का माग ग्रहण किया। उन्होंने सरकार को दंडनीय कानून पास करके इस अपवित्र पाप में उनकी सहायता और सेवा करने के लिए मना लिया।<sup>149</sup> बस यही से असम के चाय बागान श्रमिकों के दुखों और दुर्भाग्य की कहानी आरंभ होती है। उन्हें यह जानकर घोर दुःख हुआ कि विदेशी पूँजीपतियों द्वारा देश के आर्थिक विकास का परिणाम यह निकल रहा है कि उनकी जाजीविका के लिए साधनों की सृष्टि उन्हें परंपरागत ग्रामीण दरिद्रता की अवस्था से निकाल कर इकरारनामे से अनुबधित रूप में शोषण और दुर्भाग्य की स्थिति में डाल रही है।

बंगाल के 1863 के और 1865 1870 और 1873 में संशोधित 'टाइमपोट ऑफ नेटिव लेबरर ऐक्ट' (संख्या 3) की व्यवस्थाओं के अंतर्गत असम के चाय बागान के लिए श्रमिकों की भरती वर्षों तक अधिकारों के दायरे द्वारा की जाती रही। यद्यपि कानून में अनुबधित श्रमिकों के संरक्षण की अपेक्षा की गई थी क्योंकि इसमें लायसेंसधारी भरती की व्यवस्था थी परंतु 1865 में यथा संशोधित अधिनियम से वास्तव में मालिकों को ही लाभ पहुंचा। इसने श्रमिकों के न केवल काम छोड़ने प्रत्युत काम करने में सुस्ती का भी दंडनीय अपराध बना दिया और साथ ही साथ मालिकों को नियुक्तिवाले क्षेत्र के जिले की सीमाओं के अंतर्गत भगोड़े नौकरों को गिरफ्तार करने का अधिकार दिला। नौकरों को सीधे और नौकरों माग पर चलते रहने के लिए मालिकों के पहले से बने अधिनियम अर्थात् 1859 के अधिनियम संख्या XIII का भी उपयोग किया जिसके अनुसार काम करने के आदेशों पर अधिम रूप से श्रमिकों द्वारा अनुबधित माग काम करने से इनकार के लिए दंडित करना, <sup>150</sup> <sup>151</sup> <sup>152</sup> <sup>153</sup> <sup>154</sup> <sup>155</sup> <sup>156</sup> <sup>157</sup> <sup>158</sup> <sup>159</sup> <sup>160</sup> <sup>161</sup> <sup>162</sup> <sup>163</sup> <sup>164</sup> <sup>165</sup> <sup>166</sup> <sup>167</sup> <sup>168</sup> <sup>169</sup> <sup>170</sup> <sup>171</sup> <sup>172</sup> <sup>173</sup> <sup>174</sup> <sup>175</sup> <sup>176</sup> <sup>177</sup> <sup>178</sup> <sup>179</sup> <sup>180</sup> <sup>181</sup> <sup>182</sup> <sup>183</sup> <sup>184</sup> <sup>185</sup> <sup>186</sup> <sup>187</sup> <sup>188</sup> <sup>189</sup> <sup>190</sup> <sup>191</sup> <sup>192</sup> <sup>193</sup> <sup>194</sup> <sup>195</sup> <sup>196</sup> <sup>197</sup> <sup>198</sup> <sup>199</sup> <sup>200</sup> <sup>201</sup> <sup>202</sup> <sup>203</sup> <sup>204</sup> <sup>205</sup> <sup>206</sup> <sup>207</sup> <sup>208</sup> <sup>209</sup> <sup>210</sup> <sup>211</sup> <sup>212</sup> <sup>213</sup> <sup>214</sup> <sup>215</sup> <sup>216</sup> <sup>217</sup> <sup>218</sup> <sup>219</sup> <sup>220</sup> <sup>221</sup> <sup>222</sup> <sup>223</sup> <sup>224</sup> <sup>225</sup> <sup>226</sup> <sup>227</sup> <sup>228</sup> <sup>229</sup> <sup>230</sup> <sup>231</sup> <sup>232</sup> <sup>233</sup> <sup>234</sup> <sup>235</sup> <sup>236</sup> <sup>237</sup> <sup>238</sup> <sup>239</sup> <sup>240</sup> <sup>241</sup> <sup>242</sup> <sup>243</sup> <sup>244</sup> <sup>245</sup> <sup>246</sup> <sup>247</sup> <sup>248</sup> <sup>249</sup> <sup>250</sup> <sup>251</sup> <sup>252</sup> <sup>253</sup> <sup>254</sup> <sup>255</sup> <sup>256</sup> <sup>257</sup> <sup>258</sup> <sup>259</sup> <sup>260</sup> <sup>261</sup> <sup>262</sup> <sup>263</sup> <sup>264</sup> <sup>265</sup> <sup>266</sup> <sup>267</sup> <sup>268</sup> <sup>269</sup> <sup>270</sup> <sup>271</sup> <sup>272</sup> <sup>273</sup> <sup>274</sup> <sup>275</sup> <sup>276</sup> <sup>277</sup> <sup>278</sup> <sup>279</sup> <sup>280</sup> <sup>281</sup> <sup>282</sup> <sup>283</sup> <sup>284</sup> <sup>285</sup> <sup>286</sup> <sup>287</sup> <sup>288</sup> <sup>289</sup> <sup>290</sup> <sup>291</sup> <sup>292</sup> <sup>293</sup> <sup>294</sup> <sup>295</sup> <sup>296</sup> <sup>297</sup> <sup>298</sup> <sup>299</sup> <sup>300</sup> <sup>301</sup> <sup>302</sup> <sup>303</sup> <sup>304</sup> <sup>305</sup> <sup>306</sup> <sup>307</sup> <sup>308</sup> <sup>309</sup> <sup>310</sup> <sup>311</sup> <sup>312</sup> <sup>313</sup> <sup>314</sup> <sup>315</sup> <sup>316</sup> <sup>317</sup> <sup>318</sup> <sup>319</sup> <sup>320</sup> <sup>321</sup> <sup>322</sup> <sup>323</sup> <sup>324</sup> <sup>325</sup> <sup>326</sup> <sup>327</sup> <sup>328</sup> <sup>329</sup> <sup>330</sup> <sup>331</sup> <sup>332</sup> <sup>333</sup> <sup>334</sup> <sup>335</sup> <sup>336</sup> <sup>337</sup> <sup>338</sup> <sup>339</sup> <sup>340</sup> <sup>341</sup> <sup>342</sup> <sup>343</sup> <sup>344</sup> <sup>345</sup> <sup>346</sup> <sup>347</sup> <sup>348</sup> <sup>349</sup> <sup>350</sup> <sup>351</sup> <sup>352</sup> <sup>353</sup> <sup>354</sup> <sup>355</sup> <sup>356</sup> <sup>357</sup> <sup>358</sup> <sup>359</sup> <sup>360</sup> <sup>361</sup> <sup>362</sup> <sup>363</sup> <sup>364</sup> <sup>365</sup> <sup>366</sup> <sup>367</sup> <sup>368</sup> <sup>369</sup> <sup>370</sup> <sup>371</sup> <sup>372</sup> <sup>373</sup> <sup>374</sup> <sup>375</sup> <sup>376</sup> <sup>377</sup> <sup>378</sup> <sup>379</sup> <sup>380</sup> <sup>381</sup> <sup>382</sup> <sup>383</sup> <sup>384</sup> <sup>385</sup> <sup>386</sup> <sup>387</sup> <sup>388</sup> <sup>389</sup> <sup>390</sup> <sup>391</sup> <sup>392</sup> <sup>393</sup> <sup>394</sup> <sup>395</sup> <sup>396</sup> <sup>397</sup> <sup>398</sup> <sup>399</sup> <sup>400</sup> <sup>401</sup> <sup>402</sup> <sup>403</sup> <sup>404</sup> <sup>405</sup> <sup>406</sup> <sup>407</sup> <sup>408</sup> <sup>409</sup> <sup>410</sup> <sup>411</sup> <sup>412</sup> <sup>413</sup> <sup>414</sup> <sup>415</sup> <sup>416</sup> <sup>417</sup> <sup>418</sup> <sup>419</sup> <sup>420</sup> <sup>421</sup> <sup>422</sup> <sup>423</sup> <sup>424</sup> <sup>425</sup> <sup>426</sup> <sup>427</sup> <sup>428</sup> <sup>429</sup> <sup>430</sup> <sup>431</sup> <sup>432</sup> <sup>433</sup> <sup>434</sup> <sup>435</sup> <sup>436</sup> <sup>437</sup> <sup>438</sup> <sup>439</sup> <sup>440</sup> <sup>441</sup> <sup>442</sup> <sup>443</sup> <sup>444</sup> <sup>445</sup> <sup>446</sup> <sup>447</sup> <sup>448</sup> <sup>449</sup> <sup>450</sup> <sup>451</sup> <sup>452</sup> <sup>453</sup> <sup>454</sup> <sup>455</sup> <sup>456</sup> <sup>457</sup> <sup>458</sup> <sup>459</sup> <sup>460</sup> <sup>461</sup> <sup>462</sup> <sup>463</sup> <sup>464</sup> <sup>465</sup> <sup>466</sup> <sup>467</sup> <sup>468</sup> <sup>469</sup> <sup>470</sup> <sup>471</sup> <sup>472</sup> <sup>473</sup> <sup>474</sup> <sup>475</sup> <sup>476</sup> <sup>477</sup> <sup>478</sup> <sup>479</sup> <sup>480</sup> <sup>481</sup> <sup>482</sup> <sup>483</sup> <sup>484</sup> <sup>485</sup> <sup>486</sup> <sup>487</sup> <sup>488</sup> <sup>489</sup> <sup>490</sup> <sup>491</sup> <sup>492</sup> <sup>493</sup> <sup>494</sup> <sup>495</sup> <sup>496</sup> <sup>497</sup> <sup>498</sup> <sup>499</sup> <sup>500</sup> <sup>501</sup> <sup>502</sup> <sup>503</sup> <sup>504</sup> <sup>505</sup> <sup>506</sup> <sup>507</sup> <sup>508</sup> <sup>509</sup> <sup>510</sup> <sup>511</sup> <sup>512</sup> <sup>513</sup> <sup>514</sup> <sup>515</sup> <sup>516</sup> <sup>517</sup> <sup>518</sup> <sup>519</sup> <sup>520</sup> <sup>521</sup> <sup>522</sup> <sup>523</sup> <sup>524</sup> <sup>525</sup> <sup>526</sup> <sup>527</sup> <sup>528</sup> <sup>529</sup> <sup>530</sup> <sup>531</sup> <sup>532</sup> <sup>533</sup> <sup>534</sup> <sup>535</sup> <sup>536</sup> <sup>537</sup> <sup>538</sup> <sup>539</sup> <sup>540</sup> <sup>541</sup> <sup>542</sup> <sup>543</sup> <sup>544</sup> <sup>545</sup> <sup>546</sup> <sup>547</sup> <sup>548</sup> <sup>549</sup> <sup>550</sup> <sup>551</sup> <sup>552</sup> <sup>553</sup> <sup>554</sup> <sup>555</sup> <sup>556</sup> <sup>557</sup> <sup>558</sup> <sup>559</sup> <sup>560</sup> <sup>561</sup> <sup>562</sup> <sup>563</sup> <sup>564</sup> <sup>565</sup> <sup>566</sup> <sup>567</sup> <sup>568</sup> <sup>569</sup> <sup>570</sup> <sup>571</sup> <sup>572</sup> <sup>573</sup> <sup>574</sup> <sup>575</sup> <sup>576</sup> <sup>577</sup> <sup>578</sup> <sup>579</sup> <sup>580</sup> <sup>581</sup> <sup>582</sup> <sup>583</sup> <sup>584</sup> <sup>585</sup> <sup>586</sup> <sup>587</sup> <sup>588</sup> <sup>589</sup> <sup>590</sup> <sup>591</sup> <sup>592</sup> <sup>593</sup> <sup>594</sup> <sup>595</sup> <sup>596</sup> <sup>597</sup> <sup>598</sup> <sup>599</sup> <sup>600</sup> <sup>601</sup> <sup>602</sup> <sup>603</sup> <sup>604</sup> <sup>605</sup> <sup>606</sup> <sup>607</sup> <sup>608</sup> <sup>609</sup> <sup>610</sup> <sup>611</sup> <sup>612</sup> <sup>613</sup> <sup>614</sup> <sup>615</sup> <sup>616</sup> <sup>617</sup> <sup>618</sup> <sup>619</sup> <sup>620</sup> <sup>621</sup> <sup>622</sup> <sup>623</sup> <sup>624</sup> <sup>625</sup> <sup>626</sup> <sup>627</sup> <sup>628</sup> <sup>629</sup> <sup>630</sup> <sup>631</sup> <sup>632</sup> <sup>633</sup> <sup>634</sup> <sup>635</sup> <sup>636</sup> <sup>637</sup> <sup>638</sup> <sup>639</sup> <sup>640</sup> <sup>641</sup> <sup>642</sup> <sup>643</sup> <sup>644</sup> <sup>645</sup> <sup>646</sup> <sup>647</sup> <sup>648</sup> <sup>649</sup> <sup>650</sup> <sup>651</sup> <sup>652</sup> <sup>653</sup> <sup>654</sup> <sup>655</sup> <sup>656</sup> <sup>657</sup> <sup>658</sup> <sup>659</sup> <sup>660</sup> <sup>661</sup> <sup>662</sup> <sup>663</sup> <sup>664</sup> <sup>665</sup> <sup>666</sup> <sup>667</sup> <sup>668</sup> <sup>669</sup> <sup>670</sup> <sup>671</sup> <sup>672</sup> <sup>673</sup> <sup>674</sup> <sup>675</sup> <sup>676</sup> <sup>677</sup> <sup>678</sup> <sup>679</sup> <sup>680</sup> <sup>681</sup> <sup>682</sup> <sup>683</sup> <sup>684</sup> <sup>685</sup> <sup>686</sup> <sup>687</sup> <sup>688</sup> <sup>689</sup> <sup>690</sup> <sup>691</sup> <sup>692</sup> <sup>693</sup> <sup>694</sup> <sup>695</sup> <sup>696</sup> <sup>697</sup> <sup>698</sup> <sup>699</sup> <sup>700</sup> <sup>701</sup> <sup>702</sup> <sup>703</sup> <sup>704</sup> <sup>705</sup> <sup>706</sup> <sup>707</sup> <sup>708</sup> <sup>709</sup> <sup>710</sup> <sup>711</sup> <sup>712</sup> <sup>713</sup> <sup>714</sup> <sup>715</sup> <sup>716</sup> <sup>717</sup> <sup>718</sup> <sup>719</sup> <sup>720</sup> <sup>721</sup> <sup>722</sup> <sup>723</sup> <sup>724</sup> <sup>725</sup> <sup>726</sup> <sup>727</sup> <sup>728</sup> <sup>729</sup> <sup>730</sup> <sup>731</sup> <sup>732</sup> <sup>733</sup> <sup>734</sup> <sup>735</sup> <sup>736</sup> <sup>737</sup> <sup>738</sup> <sup>739</sup> <sup>740</sup> <sup>741</sup> <sup>742</sup> <sup>743</sup> <sup>744</sup> <sup>745</sup> <sup>746</sup> <sup>747</sup> <sup>748</sup> <sup>749</sup> <sup>750</sup> <sup>751</sup> <sup>752</sup> <sup>753</sup> <sup>754</sup> <sup>755</sup> <sup>756</sup> <sup>757</sup> <sup>758</sup> <sup>759</sup> <sup>760</sup> <sup>761</sup> <sup>762</sup> <sup>763</sup> <sup>764</sup> <sup>765</sup> <sup>766</sup> <sup>767</sup> <sup>768</sup> <sup>769</sup> <sup>770</sup> <sup>771</sup> <sup>772</sup> <sup>773</sup> <sup>774</sup> <sup>775</sup> <sup>776</sup> <sup>777</sup> <sup>778</sup> <sup>779</sup> <sup>780</sup> <sup>781</sup> <sup>782</sup> <sup>783</sup> <sup>784</sup> <sup>785</sup> <sup>786</sup> <sup>787</sup> <sup>788</sup> <sup>789</sup> <sup>790</sup> <sup>791</sup> <sup>792</sup> <sup>793</sup> <sup>794</sup> <sup>795</sup> <sup>796</sup> <sup>797</sup> <sup>798</sup> <sup>799</sup> <sup>800</sup> <sup>801</sup> <sup>802</sup> <sup>803</sup> <sup>804</sup> <sup>805</sup> <sup>806</sup> <sup>807</sup> <sup>808</sup> <sup>809</sup> <sup>810</sup> <sup>811</sup> <sup>812</sup> <sup>813</sup> <sup>814</sup> <sup>815</sup> <sup>816</sup> <sup>817</sup> <sup>818</sup> <sup>819</sup> <sup>820</sup> <sup>821</sup> <sup>822</sup> <sup>823</sup> <sup>824</sup> <sup>825</sup> <sup>826</sup> <sup>827</sup> <sup>828</sup> <sup>829</sup> <sup>830</sup> <sup>831</sup> <sup>832</sup> <sup>833</sup> <sup>834</sup> <sup>835</sup> <sup>836</sup> <sup>837</sup> <sup>838</sup> <sup>839</sup> <sup>840</sup> <sup>841</sup> <sup>842</sup> <sup>843</sup> <sup>844</sup> <sup>845</sup> <sup>846</sup> <sup>847</sup> <sup>848</sup> <sup>849</sup> <sup>850</sup> <sup>851</sup> <sup>852</sup> <sup>853</sup> <sup>854</sup> <sup>855</sup> <sup>856</sup> <sup>857</sup> <sup>858</sup> <sup>859</sup> <sup>860</sup> <sup>861</sup> <sup>862</sup> <sup>863</sup> <sup>864</sup> <sup>865</sup> <sup>866</sup> <sup>867</sup> <sup>868</sup> <sup>869</sup> <sup>870</sup> <sup>871</sup> <sup>872</sup> <sup>873</sup> <sup>874</sup> <sup>875</sup> <sup>876</sup> <sup>877</sup> <sup>878</sup> <sup>879</sup> <sup>880</sup> <sup>881</sup> <sup>882</sup> <sup>883</sup> <sup>884</sup> <sup>885</sup> <sup>886</sup> <sup>887</sup> <sup>888</sup> <sup>889</sup> <sup>890</sup> <sup>891</sup> <sup>892</sup> <sup>893</sup> <sup>894</sup> <sup>895</sup> <sup>896</sup> <sup>897</sup> <sup>898</sup> <sup>899</sup> <sup>900</sup> <sup>901</sup> <sup>902</sup> <sup>903</sup> <sup>904</sup> <sup>905</sup> <sup>906</sup> <sup>907</sup> <sup>908</sup> <sup>909</sup> <sup>910</sup> <sup>911</sup> <sup>912</sup> <sup>913</sup> <sup>914</sup> <sup>915</sup> <sup>916</sup> <sup>917</sup> <sup>918</sup> <sup>919</sup> <sup>920</sup> <sup>921</sup> <sup>922</sup> <sup>923</sup> <sup>924</sup> <sup>925</sup> <sup>926</sup> <sup>927</sup> <sup>928</sup> <sup>929</sup> <sup>930</sup> <sup>931</sup> <sup>932</sup> <sup>933</sup> <sup>934</sup> <sup>935</sup> <sup>936</sup> <sup>937</sup> <sup>938</sup> <sup>939</sup> <sup>940</sup> <sup>941</sup> <sup>942</sup> <sup>943</sup> <sup>944</sup> <sup>945</sup> <sup>946</sup> <sup>947</sup> <sup>948</sup> <sup>949</sup> <sup>950</sup> <sup>951</sup> <sup>952</sup> <sup>953</sup> <sup>954</sup> <sup>955</sup> <sup>956</sup> <sup>957</sup> <sup>958</sup> <sup>959</sup> <sup>960</sup> <sup>961</sup> <sup>962</sup> <sup>963</sup> <sup>964</sup> <sup>965</sup> <sup>966</sup> <sup>967</sup> <sup>968</sup> <sup>969</sup> <sup>970</sup> <sup>971</sup> <sup>972</sup> <sup>973</sup> <sup>974</sup> <sup>975</sup> <sup>976</sup> <sup>977</sup> <sup>978</sup> <sup>979</sup> <sup>980</sup> <sup>981</sup> <sup>982</sup> <sup>983</sup> <sup>984</sup> <sup>985</sup> <sup>986</sup> <sup>987</sup> <sup>988</sup> <sup>989</sup> <sup>990</sup> <sup>991</sup> <sup>992</sup> <sup>993</sup> <sup>994</sup> <sup>995</sup> <sup>996</sup> <sup>997</sup> <sup>998</sup> <sup>999</sup> <sup>1000</sup>

वानूना के अपर्याप्त मिद्ध हो जाने पर भारत सरकार ने 1881 में अखिल भारतीय स्तर पर सारे प्रदन की जाच के लिए एक आयोग नियुक्त किया। कमीशन ने प्रतिवेदन में कहा कि वतमान वानूना में श्रमिका की सुस्ती और वामचोरी को रोकने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि इन वानूना से अनुबध का पालन कराना ही कठिन हो रहा है और वागान के सरदारों ने श्रमिका की भरती पर अनावश्यक पात्रदिया लगा रखी है।<sup>150</sup> इन सिफारिशों के अनुसार ही 1882 का 'इनलड एमिग्रेशन एक्ट' पास किया गया जिसने पूर्ववर्ती सभी वानूना को पीछे छोड़ दिया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इसने 1859 के अधिनियम XIII का रद्द नहीं किया। 1882 में इस अधिनियम ने भरती करने वाले अभिवर्ताओं का वानूनी मान्यता द दी और अनुबध लेखन को अत्यंत सरल बना दिया। इसने प्रथम तीन वर्षों में पुरुषों और स्त्रियों का 'यूनितम मासिक वेतन क्रमशः 5 रुपये और 4 रुपये तथा चौथे और पाचवें वर्ष में क्रमशः 6 रुपये और 5 रुपये निर्धारित किया। इसमें मालिक का दहाधिकारी के निवास स्थान में पाच मील की सीमा के भीतर जहाँ मजिस्ट्रेट नहीं है, पकड़े गए अनुबधित भगाड़े कर्मचारी को गिरफ्तारी के आदेशपत्र के बिना ही गिरफ्तार करने का अधिकार देने की व्यवस्था थी।<sup>151</sup>

भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं विशेषतः बंगालियों ने असम के कुलिया की सचमुच शाचनीय स्थिति और सरकार के अनुबधित श्रम पद्धति को वानूनी मान्यता और समथन देने के प्रयास के विरुद्ध अपनी तीखी प्रतिक्रिया प्रकट की। इस पद्धति के दावों पर बंगाली आदि भाषाओं के समाचारपत्र पहले से ही, 1870 से लिखते आ रहे थे। इसके साथ ही असम के श्रमिका के साथ किए जाने वाले निदनीय व्यवहार की लोमहर्षक कहानियाँ लिखकर ये पत्र पाठकों के हृदय में सुप्त राष्ट्रीयता का जगा रहे थे।<sup>152</sup> लगभग 1880 के आसपास ब्रह्म समाज के साधारण प्रचारक रामकुमार विद्यारत्न ने 'कुली कहानी' नामक एक पुस्तक लिखी। इसमें असम के कुलिया की दयनीय दशा पर प्रकाश डाला गया था। पुस्तक शीघ्र ही लोकप्रिय बन गई।<sup>153</sup>

जब 1881 में इंडियन एमिग्रेशन बिल प्रस्तुत किया गया और 1882 में पारित किया गया, उस समय भारतीय समाचारपत्रों ने कुली को वागान मालिक का गुलाम बनाने के लिए तथा उसे पूणत मालिक की दया पर छोड़ने के लिए बड़े ही आवेशपूर्वक भत्सना की।<sup>154</sup> उदाहरण के लिए 17 दिसंबर 1881 के अंक में 'बंगाली' ने लिखा कि इस बिल के द्वारा मानवीय स्वतंत्रता के पवित्र अधिकार का उल्लंघन होता है। पत्र ने घोषणा की कि यह कानून अपनी मूल प्रवृत्ति में दास कानून कहा जा सकता है। ब्राह्मों पब्लिक ओपीनियन ने अपने 29 दिसंबर 1881 के अंक में अपना मत प्रकट करते हुए लिखा कि कुली की स्थिति बिल संपत्ति से किसी भी रूप में बेहतर नहीं है और यह कानून उनके प्रति ऐसा ही व्यवहार करता है। दूर प्रदेश बर्मा से 'इंडियन स्पेक्टेटर' ने इस कानून की निंदा करते हुए लिखा कि इस कानून में बंगाल के दुखी कुली को कानूनी तौर पर गुलाम बनाने से कम कुछ भी तो नहीं। इस पत्र ने टिप्पणी करते हुए लिखा 'आज तक कभी श्रम को पूणत पूजा की दयादृष्टि का अधीन नहीं बनाया गया।'<sup>155</sup> बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों की उदीयमान पीढ़ी के प्रवक्ता भारतीय सघ (इंडियन एसोसिएशन) ने भारत सरकार

को एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें बिल की कुछ धाराओं, विशेषतः धारा 170 और 172 की आलोचना की गई। ज्ञापन में अनुरोध किया गया कि इस प्रकार के विचार करने के बदले मांग और पूर्ति के सिद्धांत को काम चलाना दिया जाए।<sup>156</sup> अधिकांश आलोचकों ने यह भी आरोप लगाया कि यह कानून एकांततः बागान मालिकों के हितों के लिए और उनके दबाव में ही बनाया जा रहा है।<sup>155</sup>

अगले कुछ वर्षों में कानून के अमल में आने पर आलोचकों के गभीरतम भय तथा उनकी अत्यंत अधकारभय भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध हुईं। अगले दस वर्षों में राष्ट्रीय नेताओं ने इस कानून की निरंतर और तीखी आलोचना की तथा अमल के साथ बागान के श्रमिकों की दयनीय दशा पर देश भर में आसू बहाए। सारे देश भर में 'एमिग्रेशन एक्ट' की प्रसिद्धि 'दाम कानून' के रूप में ही हुई।<sup>155</sup> भारतीय समाचारपत्रों द्वारा प्रायः प्रकाशित प्रलाभन दान, गुप्त रूप में भागने, पीड़ा देने, बलात्कार और यहां तक कि हत्या करने आदि की लोमहर्षक कहानियां सुन सुनकर भारत के लोगों के और विशेषकर बंगाल के लोगों के हृदय बहुत ही व्याकुल हो गए थे।

चाय बागान के श्रमिकों के भाग्य में सदैव गहरी रुचि लेने वाली इंडियन एसोसिएशन ने 1886 में एक बार पुनः इस विषय को उठाया। उस समय इस संस्था ने अपने सहायक सचिव द्वारकानाथ गांगुली को मीके पर जाच पड़ताल के लिए प्रतिनियुक्त किया। गांगुली महादय ने 'बंगाली' और 'सजीवनी' के पृष्ठों में श्रमिकों की लगभग गुलामी की स्थिति और उन्हें सताने की गुप्त तथा मर्मांतक कथाओं के रूप में अपने अनुभवों का वर्णन किया।<sup>158</sup> यह संस्था असम के कुलियों की स्थिति की ओर ध्यान देने के लिए वायसरॉय से पहलवा 1886 में अनुरोध कर चुकी थी। अब संस्था ने अपने सहायक सचिव के अनुभवों और 'वायसरॉय' द्वारा दिए गए कितने ही निष्णयों को उद्धृत करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन 5 मई 1888 का भारत सरकार के पास भेजा।<sup>160</sup> परवर्ती वर्षों में एसोसिएशन इस मामले में रुचि लेती रही और भारत में तथा इंग्लैंड में संबंधित अधिकारियों के पास ज्ञापन भेजती रही।<sup>161</sup>

समय के साथ साथ असम के कुलियों के मामले का भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उठाया परंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि कांग्रेस में इस प्रश्न को उठाने के प्रारंभिक प्रयत्न निष्फल सिद्ध हुए। 1887 की मद्रास कांग्रेस में जब बंगाल के प्रतिनिधियों ने कांग्रेस के नेताओं से असम के कुलियों के प्रति अमानवीय व्यवहार को कानूनी मान्यता देने वाले एक्ट की निंदा करने का अनुरोध किया तो उनकी प्रार्थना का इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि किसी आदेश विरोध के किसी विषय पर अखिल भारतीय कांग्रेस में विचार विमर्श नहीं किया जा सकता।<sup>16</sup> अगले वर्ष इलाहाबाद के अधिवेशन में किया गया प्रयास पुनः निरर्थक सिद्ध हुआ।<sup>163</sup> परंतु यह लोकप्रिय भावना सारे ही देश में क्रमशः बड़ा ही व्यापक रूप ग्रहण करती जा रही थी अतः रूढ़िवादी कांग्रेसी नेताओं को देर सबर इसके आगे भ्रूण ही पड़ा। वायसरॉय ने 1896 में 'उत्प्रवास अधिनियम' हटाने की बकालत करते हुए इस विषय का एक प्रस्ताव पारित करके चाय बागान के श्रमिकों के साथ संबंध जोड़ लिया।<sup>164</sup> प्रस्ताव के प्रस्तावित जागेंद्रचंद्र घोष और समर्थक विपिनचंद्र पाल, दादा

ने चाय बागान म व्यापन लगभग गुलामी जैसी दुदशा की ओर प्रतिनिधिया का घ्यात आकृष्ट किया।<sup>165</sup> काप्रेस के आगामी चार अधिवेशना म प्रस्ताव के महत्व का दाहराया गया।<sup>166</sup>

इस अवधि मे 1887 के काप्रेस अधिवेशन म अपन अनुभवा से ही बृष्टित बगाल के नेताओ ने 25 अक्टूबर 1888 को प्रथम बगाल प्रातीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसका प्रमुख उद्देश्य घसम के कुलिया के प्रश्न पर उग्र विचार प्रवृत्त करना था। प्रातीय सम्मेलन अत्यंत सफल हुआ और मयोजकान इम वापिन आयोजन का रूप द दिया। इसने सदब घसम के कुलियो की ममम्याआ के प्रति उत्तरत और सत्रिय रुचि दिगार्द।<sup>167</sup>

आर० सी० दत्त ने अपनी पुस्तक 'इतानामिक हिस्ट्री आफ इन्डिया' के माध्यम म इस भारतीय चाय उद्योग पर अमिट कलक बनात हुए उमकी सामान्य निगा म अपना सराकन स्वर मुम्भरित किया तथा अध्यात्मता की इस प्रणाली का ममाप्त करने की माग की।<sup>168</sup>

हा, यह अवश्य है कि एमिग्रेशन एकत तथा चाय बागा म व्यापन मयकर कुयपहार्ग के विरुद्ध आदातन मे प्रमुख भूमिका राष्ट्रवादी प्रेम ने ही निभात। भारतीय समाचारपत्रो ने कुलिया के माय पूरी महानुभूति तथा ममान मुन्दता शिवात हुए वर्षों तक उनकी दुदशा के विरुद्ध अपनी प्रतिज्ञा मे अपने पान के आदकाग का पूरा प्रयाग करत हुए तथा अपने भोत्र जीर दु श का अभिव्यक्ति दन हुए विराय प्रकट किया। अष्टाष्टणाय, इंडियन एगामिग्नान ने 1888 म भारत सरकार को जो पानन दिया, एग भर म गभी समाचारपत्रा ने टमका पूरा रूप म ममयन किया।<sup>169</sup> टम मयध म यह राष्ट्रवादीय है कि इस विषय म विरोध रुचि देने वाले पत्र य, मुम्बैनान वैनर्जी द्वारा मपात्ति 'पगाथी' और कृष्णकुमार नित्र द्वारा मपात्ति 'मत्रीवनी'।<sup>170</sup>

राष्ट्रवादी समाचारपत्रा तथा नेम्का ने मर्नी जार मग्गिदन व्यवस्था का अपने प्रहार का विरोध करत बनाया। उन्होंने विन्सार म टम वान का विवरण प्रगुत किया कि किस प्रकार कानून का अन्वयन के वे अगिगित जार भाते भाते मनुष्या का मरुपुत्रक विवश किया जा रहा है और उनका उपकरण किया जा रहा है तथा किस प्रकार भुर्त जीर सिद्धानहीन मर्नी करने वाली द्वारा मर्नी आगार्थी जार मरुपुत्रक प्रतिपादी द्वारा उन्हें छनकर और फुनराकर उनकी मनुष्यता का अग्ररण किया जा रहा है।<sup>171</sup> राष्ट्रवादियों की चिकानत की दि एरुद जार उद कृरी चाय बाग म पहुँच जाना था मा माँ। इव लमय धिनीना व्यवहार करना था जार उम वरुत ही मयकर रूप म मनाया जाना था।<sup>172</sup> उन बलपुत्रक और मरुकाटनी टग मे दागा म गया जामा था और मरि यह धचाव का उपाय करता था जो अमे मिग्गिजार कर किया जाना था और मरुविधात व अंतगत उल टक रिना जाता था।<sup>173</sup> द्वारावानाथ मागृथी ने 1886 मे प्रतिबन्ध किया कि उन्होंने स्वयंसेवक मण्डल काठगियों में अन्वयन श्रमिकों का मरुवाननी टग म धर करके रखे हुए देखा है।<sup>174</sup> यह भी पाना कि चाय बागा मे शारीरिक मयत्राण एक मरुदन्त (पुगि है 117) भारतीय मरुनेताओं ने कुलियो के प्रति हृदनदायक इन्करीर की करत बगान किया।<sup>175</sup> राष्ट्रवादी समाचारपत्रों तथा मरु, १० के १० १० ११



चढ़ाकर इन लाभों की उपलब्धि वाछनीय नहीं थी।<sup>184</sup> अथ, अपेक्षाकृत अधिक उग्र तथा क्षुब्ध वग ने तो अनुभव किया कि इस प्रकार का आर्थिक विकास सवथा अवाछनीय है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे कुलियों का दासा के रूप में वचने की शोचनीय प्रथा को बनाए रखने के बदले चाय उद्योग का नष्ट-भ्रष्ट होना तथा जमम का जगली पशुओं का निवास बनना ही पसंद करेंगे।<sup>185</sup>

## उपाय

यह शोचनीय स्थिति अधिक समय तक नहीं चलन दी जा सकती थी यहा तक कि अथथा भी यह स्थिति एत लवे समय तक जारी नहीं रह सकती थी। 1887 में ही मजीवनी ने चेतावनी की घटी बजा दी

भारत के अगरेज शासकों! यह भयकर दमन बंद करो। अगरेज व्यापारियों!

घन के लोभ में मानव पर किए जा रहे अत्याचार की ओर में अपनी आंखें बंद मत करो। क्योंकि इस तरह की स्थिति का लवे समय तक चलत रहना असभव है। तुम्हारे जैसे अनेक शक्तिशाली राष्ट्रों को भगवान के चाय ने दबोचा और दबाया है। अपनी यह उमादी प्रवृत्ति को छोड़ दो क्योंकि तुम्हें निश्चित रूप से अपनी करनी का हिसाब देना पड़ेगा। इस देश से अपनी इस पैशाचिक प्रथा के प्रत्येक चिह्न को मिटाने की चेष्टा करो।<sup>186</sup>

भारतीय नेताओं ने इस सबध में सबप्रथम उपाय के रूप में इस बात पर बल दिया कि भारत सरकार कुलियों की वास्तविक स्थिति को, 1859 के श्रमिक अनुबंध भंग अधिनियम (वर्कमेंस ग्रीच आफ कार्ट्रैक्ट ऐक्ट) के प्रवतन के यातनाप्रद प्रभावों का, और 1882 के अतदेशीय उत्प्रवास अधिनियम (इनलड एमिग्रेशन ऐक्ट) के प्रवतन के दुष्परिणामों को अनुभव करे और इसने लिए उहान भारत सरकार पर जाच पडताल करने के लिए एक स्वतंत्र आयोग की नियुक्ति हेतु त्वाव डाला।<sup>187</sup> द्वितीय उनका सुभाव यह था कि शक्तिशाली और समृद्ध बागान मालिका के मुकाबले श्रमिक निरीह तथा असहाय हैं अत इस तथ्य को देखते हुए सरकार को स्वयं उह यातनाओं से मुक्ति दिलाने के उपाय करने चाहिए।<sup>188</sup> इस प्रकार का एक उपाय यह होना चाहिए कि अपने श्रमिका के साथ दुर्व्यवहार करने वाले चाय बागान के प्रबधकों को तत्काल और तदनु रूप समुचित दंड दिया जाए।<sup>189</sup> परंतु भारतीयों की सर्वाधिक सवमाय और लाकप्रिय माग दंडनीय कानूना के निवतन की<sup>190</sup> और स्वतंत्र उत्प्रवास को लागू करन की थी ताकि चाय बागान का भारत के बहुत बड़ श्रम बाजार से माग और पूति के सामाय सिद्धांत के आधार पर श्रमिक मिल सकें।<sup>191</sup>

भारतीय नेता सरकार से अमम के कुलिया को इस दुर्भाग्य से मुक्त करने की अनुनय विनय करते समय यह तथ्य नहीं भूले कि एक विदेशी सरकार द्वारा यूरोपीय बागान मालिकों के विरुद्ध कोई पग उठाए जान की सभावना नहीं थी।<sup>19</sup> इस विवेक एव सतकता के कारण ही असम कुलिया के प्रगाढ मित्र 'सजीवनी' ने अपनी सहायता आप ही करने का आह्वान किया। इस पत्र नं 14 अगस्त 1886 के सपादकीय में भारतीया की मर्दानगी को



बलात्कार और पुरुषों की हत्याओं की कहानियाँ जनता में प्रचारित कीं। उन्होंने कुलियाँ अथवा कुलियों के शुभचिंतकों द्वारा 'यायालयों में मालिकों के विरुद्ध मामला ले जान पर 'यायालयों द्वारा मालिकों के पक्ष में विशुद्ध रूप में और अधिकांशतः 'चाय का गला पाटन' की कहानियाँ भी प्रकाशित कीं।<sup>176</sup>

भारतीय नेताओं का तत्कालीन कथन था कि चाय बागों में मृत्यु की ऊँची दर सबसुख वहाँ की वास्तविक स्थिति का सूचक तत्व है।<sup>177</sup> उनकी एक शिकायत यह थी कि काम की स्थितियों और प्रवृत्ति के अरुचिकर होने पर भी चाय बागान के श्रमिकों का वेतन बहुत कम था।<sup>178</sup> उन्होंने घोषित किया कि दंडनीय कानून बनाने का मुख्य प्रयोजन वस्तुतः कुलियों का वेतन कम रखना और इन नीचे वेतन पर कुलियों को काम करने के लिए विवश करना था। यह निश्चित है कि मामलायत के इतने कम वेतन पर काम करने को प्रस्तुत नहीं होता। इस प्रकार दूसरे शब्दों में इस कानून का उद्देश्य कुलियों को ठगना था।<sup>179</sup> कुछ भारतीयों ने यह भी निर्देश किया कि भारत में अथवा असम में श्रमिकों की कमी वास्तविक समस्या नहीं थी। ऊँचे वेतन में आवश्यकता के अनुरूप श्रमिक उपलब्ध हो सकते थे।<sup>180</sup> राष्ट्रवादियों ने इस मान्यता का जोरदार खंडन किया कि भले भले श्रमिकों में काम में जी चुराने की जन्मजात प्रवृत्ति है। वह अपनी धरती पर मूला मर जाता है परंतु दूसरी धरती पर जाकर जीने के लिए भी कठोर श्रम नहीं करता। इस प्रवृत्ति पर बाढ़ पान के लिए ही दंडनीय कानूनों की अपेक्षा है। राष्ट्रवादियों के अनुसार सच यह था कि यूरोपीय उपनिवेशवादी भारतीयों से अपने दामा के रूप में काम लेना चाहते हैं और यदि भारतीय काम करना से इनकार करते हैं तो उन्हें सुस्त और किम्मा बहकर गालियाँ ली जाती हैं, उन्हें 'श्रम की मृत्यु' में अपरिचित बताया जाता है तथा अनेक साधनों के प्रयोग द्वारा उन्हें काम करने के लिए विवश किया जाता है।<sup>181</sup>

भारतीय नेताओं ने यह निश्चयपूर्वक कहा कि वस्तुतः असम में कुली श्रम की सारी पद्धति दासता के रूप में भिन्न नहीं थी क्योंकि वहाँ भारतीय कुली का जीवन प्राचीन काल के दासों अथवा आधुनिक काल के ह्वशी दासों के जीवन से किसी भी रूप में बेहतर नहीं था।<sup>182</sup> इस संबंध में बी० सी० पाल ने बताया कि 1880 के आसपास के वर्षों में बंगाल की शिक्षित जनता 'अबन टाम्स बैरिन' पुस्तक की किस प्रकार प्रशंसा करती थी और फिर तत्काल असम के चाय बागान के कुलियों को दंगा की तुलना अमेरिका के ह्विशिया की मुक्ति से पूर्व की दशा के साथ करती थी।<sup>183</sup> इसी लेखक ने वर्षोंपरांत 'न्यू इंडिया' के 26 अगस्त 1901 व अंश में लिखा 'दंडनीय श्रमपद्धति दासता का सशोधित तथा आधुनिक रूप है।'

विचारणीय यह है कि इस गुप्त समाधान के विकास से और उसके फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि से कुल मिलाकर देश को क्या लाभ हुआ तथा आजीविका और नौकरी के रूप में श्रमिकों को क्या प्राप्त हुआ? कुछ भारतीय लेखकों ने समस्या के इस पक्ष की ओर भी ध्यान दिया। उनमें से महाशय सयत लेखकों ने इन लाभों को खुले तौर पर स्वीकार करते हुए भी विचार प्रकट किया कि महाराष्ट्र की महान्या की दरिद्रता, अत्यंत निरीह और गवया अगहाय प्रजा के बहुत बड़े वर्ग के जीवन और स्वतंत्रता की बलि

चढाकर इन लाभो की उपलब्धि वाछनीय नही थी।<sup>134</sup> अय, अपेक्षाकृत अधिक उय तथा क्षुब्ध वग न तो अनुभव किया कि इस प्रकार का आर्थिक विकास सवथा अवाछनीय है। उहोंने स्पष्ट शब्दो मे कहा कि वे कुलिया का दासो के रूप मे बेचने की शोचनीय प्रथा का बनाए रखने के बदले चाय उद्योग का नष्ट भ्रष्ट होना तथा असम का जगली पशुआ का निवास बनना ही पसद करेंगे।<sup>135</sup>

## उपाय

यह शोचनीय स्थिति अधिक समय तक नही चलने दी जा सकती थी, यहा तक कि अयथा भी यह स्थिति एक लब समय तक जारी नही रह सकती थी। 1887 मे ही मजीवनी ने चेतावनी की घटी बजा दी

भारत के अगरेज शासका ! यह भयकर दमन बढ करो। अगरेज व्यापारियो ! धन के लोभ मे मानव पर किए जा रहे अत्याचार की ओर से अपनी आखें बन्द मत करो। क्याकि, इस तरह की स्थिति का लबे समय तक चलते रहना असभव है। तुम्हारे जैसे अनेक शक्तिशाली राष्ट्रो का भगवान के चाय न दयोचा और दबाया है। अपनी यह उमादी प्रकृति को छोड दो क्योंकि तुम्ह निश्चित रूप से अपनी करनी का हिसाब देना पडेगा। इस देश से अपनी इस पशाचिक प्रथा के प्रत्यक चिह्न को मिटाने की चेष्टा करो।<sup>136</sup>

भारतीय नेताओ ने इस सबध मे सवप्रथम उपाय के रूप मे इस बात पर बल दिया कि भारत सरकार कुलियो की वास्तविक स्थिति को, 1859 के श्रमिक अनुबध मग अधिनियम (कमसेस ब्रीच आफ काट्टेक्ट ऐक्ट) के प्रवतन के यातनाप्रद प्रभावो को, और 1882 के अतदेशीय उत्प्रवास अधिनियम (इनलड एमिग्रेशन ऐक्ट) के प्रवतन के दुष्परिणामो को अनुभव करे और इसके लिए उहोंने भारत सरकार पर जाच पडताल करने के लिए एक स्वतत्र आयाग की नियुक्ति हतु दबाव डाला।<sup>137</sup> द्वितीय, उनका सुभाव यह था कि शक्तिशाली और समद्व बागान मालिको के मुवाबले श्रमिक निरीह तथा अमहाय ह, अत इस तथ्य को देखते हुए सरकार को स्वय उह यातनाआ से मुक्ति दिलान के उपाय बन चाहिए।<sup>138</sup> इस प्रकार का एक उपाय यह होना चाहिए कि अपने श्रमिको के माय दुष्यवहार करने वाले चाय बागान के प्रबधनो को तत्काल और तदनु रूप समुचित दड दिया जाए।<sup>139</sup> परतु भारतीयो की सवाधिक सवमाय और लाकप्रिय माग दडनीय कानूना के निवतन की<sup>140</sup> और स्वतत्र उत्प्रवास को लागू करने की थी ताकि चाय बागान को भारत के बहुत बड श्रम बाजार से माग और पूर्ति के मामाय सिद्धात के आधार पर श्रमिक मिल सकें।<sup>141</sup>

भारतीय नेता सरकार से असम के कुलियो को इस दुर्भाग्य से मुक्त करने की अनुनय विनय करते समय यह तथ्य नही भूले कि एक विदेशी सरकार द्वारा यूरोपीय बागान मालिको के विरुद्ध कोई पग उठाए जाने की सभावना नही थी।<sup>142</sup> इस विवक एव सतकता के कारण ही असम कुलियो के प्रगाड मित्र 'सजीवनी ने अपनी सहायता आप ही करने का आह्वान किया। इस पत्र ने 14 अगस्त 1886 के सपादकीय म भारतीयो की मर्निगी को

ललकारते हुए लिखा कि यदि उनकी संपूर्ण शक्ति और साहम नष्ट नहीं हो गए तो उन्हें देश में क्रोध की ऐसी प्रचंड ज्वाला प्रज्वलित करनी चाहिए कि उमम कुली ऐक्ट जलकर राख हो जाए।<sup>193</sup> इस पत्र ने भारतीयों से कुलिया को अथवा कुली बनने के इच्छुका को कानूनी तथा अथ इस प्रकार की सहायता देने के लिए तथा मानिकों की गतिविधि पर निगरानी रखने के लिए एक समिति के गठन का अनुरोध किया।<sup>194</sup> इस पत्र के एक सवाददाता ने यह सुझाव दिया कि शिक्षित भारतीयों को चाय पीना बंद कर देना चाहिए क्योंकि यह चाय पीना गरीब प्रपीडित कुलियों का खून पीने के अनिर्वाक और कुछ नहीं।<sup>195</sup> आश्चर्यजनक न होना पर भी यह पर्याप्त रोचक तथ्य है कि उस समय भारत में किसी ने भी चाय बागान के श्रमिकों को श्रमिक संघ बनाने आदि के रूप में अपनी सहायता आप करने का सुझाव नहीं दिया। हा, कुलियों ने स्वयं ही आक्रमण और झगड़ फसाद के रूप में आत्मसहायता का माग जपनाया<sup>196</sup> परंतु राष्ट्रीय नेताओं से उन्हें समुचित दिशानिर्देशन नहीं मिला।

### असम श्रम और उत्प्रवास अधिनियम, 1901

भारतीयों द्वारा फिरतर आदालत तथा असम के उत्तर तथा साहमी मुख्य आयुक्त हैनरी काटन के सतत प्रयासों के फलस्वरूप जब भारत सरकार ने इस विषय पर नए कानून बनाने का निश्चय किया तो उस समय बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में चाय बागान के श्रमिकों का प्रश्न पुनः एक बार भारतीय राजनीति का प्रमुख विषय बन गया। 13 अक्टूबर 1899 को विधानपरिषद में असम श्रम और उत्प्रवास बिल लाया गया और 8 मार्च 1901 में इस कानून का रूप ले दिया गया। जहाँ एक ओर इस नए बिल ने चाहे बेमन से ही सही भरती की पद्धति को सुधारने का प्रयत्न किया<sup>197</sup> वहाँ दूसरी ओर जुल मिला कर पहले की तरह ही विषय दुर्व्यवहार चलते रहने में इसका प्रयोजन ही असफल हो गया था।<sup>198</sup> इसके एक प्रावधान ने, जो सारे अधिनियम के प्रयोजन और प्रभाव के अपक्षरत व्यापक सदर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं थी, मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर दी और राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बन गई। 1899 में अपने मूल रूप में प्रस्तावित बिल में 1882 के अधिनियम के अंतर्गत अनुवधिन श्रमिकों के निर्दिष्ट न्यूनतम वेतन में एक रुपया प्रति मास की वृद्धि की व्यवस्था की। बाद में इस व्यवस्था में प्रवर समिति ने इस प्रकार से सुधार किया कि प्रथम वर्ष में पुरुष श्रमिक और महिला श्रमिक का मासिक वेतन क्रमशः 5 और 4 रुपये, द्वितीय और तृतीय वर्ष में क्रमशः 5½ और 4½ रुपये और चतुर्थ वर्ष में क्रमशः 6 और 5 रुपये कर दिया गया। इस प्रकार प्रथम और चतुर्थ वर्ष में श्रमिकों के वेतन उतने ही बने रहें, जितने पहले के अधिनियम में निर्धारित थे।<sup>199</sup> यद्यपि राष्ट्रवादियों ने इस बिल को इसके मूल रूप में बागानमालिका के हितों की सुरक्षा में गढ़ा हुआ तथा बनपूर्वक श्रम को जारी रखने वाला एक साधन मात्र माना<sup>200</sup> और इस वेतनवृद्धि का बहुत थोड़ा माना तथापि इन असहाय प्राणियों को इस बिलवित चाय का एक अंश देने वाली इस धारा का समर्थन भी किया।<sup>201</sup>

गन्धार द्वारा चाय बागानमालिका की ओर से जे० बरिधम द्वारा अधिनियम की

वेतनवालीघाराओ के प्रवतन को दो वर्षों तक स्थगित रखने के सुझाव की सशोधन के रूप में स्वीकृति ने एक बार फिर आग में घी का काम किया।<sup>0</sup> वस्तुतः लाड कजन ने पहले ही विवाद में हस्तक्षेप करते हुए बागानमालिका को इस प्रकार की रियायत मागने का निमंत्रण प्रत्यक्ष रूप में दे दिया था।<sup>08</sup> असम के मुख्यायुक्त ने जब इम सशोधन का इस आधार पर विरोध किया कि इसमें तो कुलियों के लिए पहले ही अपयाप्त और अभी अभी विजित रियायत का कोई अर्थ ही नहीं रह पाएगा तो वायसराय ने इस लोकप्रिय मुख्यायुक्त की सावजनिक रूप से अवमानना और<sup>04</sup> भत्सना की। इस बात ने कोड में खजली का काम किया।<sup>05</sup> विदेशी बागानमालिका के सामने लाड कजन द्वारा हथियार डाल दिए जाने के विरुद्ध सारे भारतीय समाचारपत्र और लोकनता एकजुट होकर खड़े हो गए।<sup>06</sup> उन्होंने स्पष्ट देखा कि भारतीय लोगो के मूल्य पर यूरोपीय पूजीपतियों के हितों की सावधानी के साथ रक्षा करने का यह एक अर्थ निदनीय निदर्शन था।<sup>07</sup> बंगाली ने 10 मार्च 1891 के अंक में लिखा भारत में ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य यूरोपीय पूजीपतियों और व्यापारियों को लाभ पहुंचाना है चाहे इसके लिए 'याय और मानवता का गला ही क्यों न घोटना पड़े। राष्ट्रवादियों ने भारत सरकार की निंदा करते हुए कुलियों के हितों की वकालत करने में उनकी 'यायप्रियता तथा वीरता के लिए हेनरी वाटन की भरपूर प्रशंसा की।<sup>08</sup>

### मद्रास बागान श्रम अधिनियम, 1903

1903 में जब मद्रास सरकार ने 'मद्रास बागान श्रम अधिनियम' को बानून का रूप दिया तो राष्ट्रवादियों की विदेशी सरकार के विरुद्ध क्षोभ की और बागान श्रमिका के प्रति सहानुभूति की भावना एक बार फिर भड़क उठी। प्रमुख रूप से 1901 के 'असम श्रम और उत्प्रवास अधिनियम' पर आधुत मद्रास अधिनियम में भी भाग जाने वाला के लिए गिरफ्तारी और सजा की तथा अनुपस्थित रहने वालों और सुस्ती बरतने वाला अर्थात् काम से जी चुराने वालों के लिए अथदंड और जेल की व्यवस्था थी। भारतीय नेताओं ने असम अधिनियम के समान मद्रास अधिनियम को भी पैशाचिक, ईश्वरविराधी, अमानवीय, घृणित तथा अ-यायपूर्ण बताकर उसकी भत्सना की तथा कुलियों की स्वतंत्रता गण्ट करने के लिए और दक्षिणी क्षेत्र के बागान में दासता को बानूनी रूप देने के लिए उसकी आलोचना की।<sup>09</sup> उन्होंने सरकार पर बागानमालिका और विदेशी पूजीपतियों का सदा उपवृत्त करने को प्रस्तुत रहने के लिए उनके हाथ में एक म्विलौना बनने का आरोप लगाया।<sup>10</sup>

### व्यापक संवध

बागान श्रमिका की समस्याओं पर विचार विमर्श से उभरे कुछ संवधित व्यापक राज नीतिक तथा आर्थिक प्रश्नों पर भी कई भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने गहरा विचार किया और उन प्रश्नों तथा सरकार के बागानश्रमिका के प्रति दृष्टिकोण में व्यापक संवध सिद्ध करने का प्रयास किया। प्रथम, भारतीय नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय

भारतीय समाचारपत्र तथा विधानपरिषद के भारतीय सदस्यों के विरोध की अपेक्षा बरके वागानमालिकों के अनुकूल कानून बनाने की सरकार की तत्परता से यही निष्पत्ति निम्ना कि यह सरकार भारतीय लोकमत का कोई महत्व ही नहीं देती।<sup>11</sup> उन्होंने यह अनुभव किया कि सशोधित विधानपरिषद पूर्णतः अनुपयोगी सिद्ध हुई है और सरकार न भारतीय सदस्यों की इच्छाओं की अवहलना की है।<sup>12</sup> जी० एस० अय्यर को इस स्थिति में यह मत प्रकट करना पड़ा कि 'आज की भारतीय पद्धति से अधिक हास्यजनक कानूनी पद्धति कहीं भी पहले नहीं रही।'<sup>13</sup> वस्तुतः विदेशी शासकों की 'यायप्रियता तथा प्रगतिशीलता पर कामल जीर उदार चिन्तनवालों का विश्वास हिल गया। 'मद्रास वागान श्रम अधिनियम के कानून बनने पर लोगों के विश्वास भंग को 'कैसे हिंदू' न अपन 8 मार्च 1903 के जर्नल में सुंदर अभिव्यक्ति दी है

यदि ये निष्पक्ष विचारक हैं तो हम उनके लिए किसी बटु विज्ञापण का प्रयोग न करत हुए पूछत ह कि जिन बेजवान और बेमहारा लोगों के वे पिता के समान रक्षक बनते ह, उन्हें वे क्यों एक अत्यंत स्वार्थी बग के ही आदेश से दास बना देते हैं? इस बात से कौन इनकार करेगा कि न केवल ब्रिटिश नीतियों के प्रत्युत ब्रिटिश मदाचार के विनाश का भी यह एक अत्यंत सुदृढ़ प्रमाण है। निस्संदेह सारे विशाल ब्रिटिश राज्य में चारा और विनाश के अपसकून और नबेत दिखाई दे रहे हैं जा परिणाम में सुखद नहीं कहे जा सकते। भगवान ही ब्रिटिश राज्य को भावी विपत्तियों से बचाए।<sup>14</sup>

वेमरी ने भी 10 मार्च 1903 के अंक में इस समग्र समस्या को विश्वव्यापी पैमाने पर आर्थिक साम्राज्यवाद के विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया। यह लिखने के उपरांत कि आज के भयंकर प्रतियोगिता के युग में यूरोपीय राष्ट्र भौतिक समृद्धि के लिए कड़ा परिश्रम कर रहे हैं और सम्यता का बरदान लाने के वहाने अपने अधीनस्थ अविश्वसित राष्ट्रा के वस्तुगत और खनिज पदार्थगत साधनों का शोषण कर रहे हैं, इस पत्र ने शिकायत के स्वर में लिखा कि यूरोपीय व्यापार के उद्देश्य से अथवा उपनिवेश स्थापित करने के उद्देश्य से जहां कहीं भी जाते हैं, उन देशों की जनता को वे लोग दाम बनाकर ही उसमें काम लते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में काफ़िरो के प्रति और असम में चायवागान बुलिया के प्रति इनका व्यवहार इसका प्रत्यक्ष और स्पष्ट प्रमाण है। निष्कष रूप में इस पत्र ने इस विचारधारा पर दुःख प्रकट करत हुए लिखा कि मनुष्यों का एक बग तो घन से खेने और उसमें शोष बंधुओं को उस बग के एका आराम के लिए सटने पर विवश किया जाए।<sup>15</sup>

कुछ भारतीय नेता वागान श्रमिका की समस्या को श्रमिकों और पूंजीपतियों के बीच संघर्षों की व्यापक समस्या के अंग के रूप में देखने को प्रेरित हुए। उन नेताओं ने श्रमिकों का ही पक्ष लिया। उदाहरणार्थ, जी० एस० अय्यर का विचार था कि वस्तुतः भारत सरकार की वागान श्रमिका के प्रति नीति तथा तथ्य दम सत्य में निर्दिष्ट है कि बटु चाय उद्योग में केवल पूंजीपतियों के हितों का ही ध्यान है।<sup>16</sup> आर० गो० दत्त का भी अनुभव था कि भा



उपदेश किया और दूसरी ओर इसने केवल एक वष उपरांत ही असम कुलिया के वेतन में वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया।<sup>1</sup>

इस तरह के विरोधाभासपूर्ण रवियों का एक और नाटकीय उदाहरण 3 मार्च 1903 के हिंदू के सपादकीय में मिला। जैसा हम पहले दिखा चुके हैं, 'हिंदू' बागान मालिका के हितों में लाए जाने वाले सभी कानून का प्रबलतम निन्दक और विरोधी रहा है। उसने उन सभी कानून का 'दाम बनाने वाले कानून' कहकर उनकी भत्सना की। इस पत्र ने मद्रास प्लाटस मिल के विरुद्ध लगातार निंदा का स्वर मुखरित किया था। 3 मार्च 1903 के सपादकीय में भी उसने यही विरोध प्रकट किया। परंतु इसी सपादकीय में उसने आश्चर्यजनक ढंग में यह मांग प्रस्तुत की कि इस प्रकार का कानून श्रमिका को नियुक्त करने वाले उन सभी मालिका के लिए समान रूप से बनाना चाहिए 'जिन्हें श्रमिका को पान में ही न केवल कठिनाई का अनुभव होता है प्रत्युत उन्हें अनुभव को निभाने के लिए श्रमिका का विवश करने में कठिनाई का अनुभव होता है'। उसने धनुसार ऐसे कानून की दक्षिण भारत के भूमिपतियों को विशेष आवश्यकता है। ये भूमिपति तो 'पतल लेवर ला' (द्वितीय श्रम कानून) को अत्यंत लाभप्रद और उपयोगी पाएंगे। अपन तक की पुष्टि में 'हिंदू' ने राष्ट्रवाद के नाम पर आग्रह किया भारतीय कुलिया के सबंध में वर्गीय कानून की कोई आवश्यकता नहीं। यदि वे यूरेशियानों के दास बनाए जा सकते हैं तो उन्हें भारतीय जमींदारों के दाम बनाने में कोई अनौचित्य नहीं होना चाहिए। भारतीय कुलिया का एक वर्गविरोध का ही दास नहीं बनाना चाहिए। इस तक पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। 'हिंदू' द्वारा लिख्य रूप में प्रस्तुत मांग से उसकी अचेत विडम्बना का तथा इस प्रश्न के बारे में उसकी फाल्गुण पवित्रता का पता चलता है।

जिस प्रकार अनुचित रूप से पश्चिमी प्रदेशों में कुलियों का चाय बागानमालिका की दया पर उनके हाथों में सौंपन का उचित नहीं माना जा सकता, उसी प्रकार भारतीय जमींदारों के हाथों में दंडीय अपराध के अंतर्गत कुलिया को सांपने से इनकार करने का किसी प्रकार का वायसगत नहीं ठहराया जा सकता। हिंदू द्वारा इस प्रकार का व्यवहार अपनाना सबंधा अविश्वसनीय नहीं लगता क्योंकि इससे दो महीने बाद ही तमिऴ पत्रकारिता के जन्मदाता एक अथ राष्ट्रवादी समाचारपत्र 'भूवदेशमित्र' न इसी प्रकार की मांग पस की।

### जी० आई० पी० रेलवे सिगनलवालों की हड़ताल

भारतीयों में इतर स्वामित्व वाले उद्योगों में नियुक्त श्रमिका के प्रति भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के दृष्टिकोण की रोचक विडम्बना 1899 में हुई जी० आई० पी० की हड़ताल के मद्दम में दखने का मिलती है। जब रेल कर्मियों के प्रवर्धक मंडल में वतना में कटौती न करने, उनकी को व्यवस्थित रूप से काम के घंटे सीमित करने तथा नियमित अवकाश की व्यवस्था करने की मांगें अस्वीकृत कर दीं तो 1899 में ही मई के प्रथम सप्ताह में 800 सिगनल कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी।<sup>2</sup> समाचारपत्रों की सूचना के अनुसार हड़ताल न रेलवे को तुरी तरह में प्रभावित किया। आमतौर पर माल की आवाजाही





ने हड़तालियों से नौकरी छूट जाने पर भी डटे रहने का निरंतर अनुरोध किया और हड़ताल छाड़कर काम पर जाने वालों को गद्दार कहकर उनकी निंदा की।<sup>2</sup>

भारतीय समाचारपत्रों ने रेलवे के प्रबंधकमंडल द्वारा कमचारियों के प्रति किए जा रहे व्यवहार दृष्टिकोण तथा कामवाही आदि की तीव्र निंदा की।<sup>3</sup> उन्होंने सावजनिक उपयोगिता के विभाग में अनुशासन के तक को प्रबंधकों का वाकडल कहकर ठुकरा दिया तथा जनता को जो गृही असुविधा का सारा दायित्व प्रबंधकों पर डाल दिया।<sup>4</sup> उन्होंने रेल कंपनियों पर हड़तालियों की 'पायसगत शिकायतों' दूर करके तथा विवाद को निपटाने के लिए मध्यस्थ को सौंपने की हड़तालियों द्वारा पहले से ही मंजूरि प्राप्त बात मानकर हड़तालियों से समझौता करने के लिए दबाव जाला।<sup>5</sup>

राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने सरकार से विवाद में हस्तक्षेप करने और प्रबंधकमंडल को सिगनलमना की उचित मानें मानने के लिए विवश करने का अनुरोध किया।<sup>6</sup> उनका उपयुक्त तर्क यह था कि मानवता के दृष्टिकोण को छोड़ दिया जाए तो भी सरकार हस्तक्षेप करने के लिए कतव्यवद्ध है क्योंकि जी० आई० पी० रेलव प्रतिभूत सस्था है और इस प्रकार हड़ताल के कारण होने वाली हानि सरकार को आर अतत करदाता को ही भुगतनी पड़ेगी।<sup>7</sup> मराठा' न 28 मई 1899 के अंक में लिखा कि 'अपन ही लोगो का जिनके प्रति हमारी गहरी महानुभूति है, निराश और पराजित करने के लिए अपक्षिण दाम हमसे ही मागना कहा का न्याय है ? राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने यह भी लिखा कि सरकार का हड़ताल में हस्तक्षेप करना नैतिक अधिकार के साथ साथ कतव्य भी है क्योंकि रेलव जनोपयोगी सस्था है, इसमें किसी प्रकार की अव्यवस्था अथवा कुप्रबंध से न केवल व्यापार जन सुग और सुविधाओं का हानि पहुँचती है प्रत्युत यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है।<sup>8</sup> समाचारपत्रों ने यह अनुभव किया और देखा कि सरकार न केवल हस्तक्षेप करने से इनकार करती है अथवा तटस्थ रहती है प्रत्युत प्रबंधकों को समर्थन तथा गन्तिय सहायता भी दे रही है, सरकार के इस आचरण की समाचारपत्रों ने तीव्र भत्सना की।<sup>9</sup>

सिगनलरों के प्रति 'पापक सावजनिक सटानुभूति' शाब्दिक प्रस्थान तब सीमित न रहकर उससे आगे निरल गई। समाचारपत्रों ने जनता और जन सस्थाओं से हड़ताली सिगनलरों की महायत्ता के लिए पसे जुटा का अनुरोध किया।<sup>10</sup> बहुत स लोग अपने आप महायत्ता के लिए आगे आए। उनकी सहायताय कोष संग्रह के लिए बर्दई प्रात के विभिन्न क्षेत्रों अहमदाबाद, अमरावती, पुलिया और नागपुर में सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया गया।<sup>11</sup> बर्दई में 19 मई का गण्यमाय भारतीय नागरिका और प्रतिष्ठित व्यापारियों की एक बैठक फिरोजगह एम० मेहना के भवन में हुई, इसमें हड़तालियों के उपयोग के लिए एक कोष जारी कराना का सक्ल्प किया गया। तत्काल मौके पर 2500 रुपयों की राशि इकट्ठी हो गई और अगले ही दिन 2500 रु० और 'न का बचन दिया गया।<sup>12</sup> दम कोष के लिए बंगाल में मुर्देनाथ टगोर ने और बंगाली मासिक 'भारत की गणतिका मुभी घोषान ने भी धन इकट्ठा किया।<sup>13</sup> हड़ताल के अमपन होने तथा लगभग 700 सिगनलरों के हटाए जाने पर बर्दई में उनके लिए गन्त सावजनिक कोष

जारी किया गया जिसके वापाध्यक्षा में एक डी० ई० वाचा थे।<sup>44</sup> 'मराठा' ने अपने 16 जुलाई 1899 के अंक में इन प्रयत्नों का समर्थन तथा सराहना की। कलकत्ता के 'अमृत बाजार पत्रिका' ने अपने 4 जुलाई 1899 के अंक में जमींदारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों से नौकरों से बर्नास्त किए गए सिगनलरो को नौकरी देने का अनुरोध किया।<sup>45</sup>

भारतीय नेताओं के उग्र रूप से हड़ताल समर्थक दृष्टिकोण को समझने का कुजी संक्षेपत उनके राष्ट्रवाद में निहित है। हड़ताली सिगनलर भारतीय थे जबकि उन्हें नियुक्त करने वाली रेलवे कंपनी का स्वामित्व और प्रशासन अंगरेजों के हाथ में था, यही अकेला तथ्य दोनों के मध्य के विवाद को भारतीय राष्ट्रवाद के मुख्य प्रवाह की ओर तथा राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए पर्याप्त था। किन्हीं मामलों में तो विवाद के बारे में यह विशिष्ट जाकारी स्पष्ट करने का आयोजन किया गया तथा इस स्पष्ट अभिव्यक्ति दी गई। 'मराठा' ने शिकायत की कि रेल कंपनी सिगनलरो को जीवन निर्वाह के लिए उपयुक्त वेतन देने से इसलिए इन्कार कर रही है क्योंकि वे भारतीय हैं। उसने 21 मई 1899 के अंक में अपेक्षाकृत गहराई से लिखा

मनेजर ने बर्दाश्त यह अनुभव किया कि बाले गुलामा को खाली जीवित रहने के लिए अपेक्षित से अधिक की आवश्यकता नहीं और इतना उसे दे दिया जाएगा ताकि वह जीवित रहे और गोरों आदमी की सेवा का भार वहन करता रहे। भगवान हाग सौंपे समार को सम्य बनाने के काम को ही बेचारा गौरा आदमी निभा रहा है और इससे अतगत् अपनी चातुरी से उष्णकटिबंधीय देश का इस प्रकार शोषण कर रहा है कि सारे लाभों को वह स्वयं हड़प जाता है और खून पसीना बहाने वाले काले गुलाम के लिए अपने (मालिक के) लाभ की दृष्टि से चंद टुकड़े छोड़ देता है।

'अमृत बाजार पत्रिका' के भी विचार से इस सारे विवाद के पीछे जातीय भेदभाव की भावना काम कर रही थी। 22 जून 1899 के अंक में इस पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा 'बंबई सरकार अब इस अशांतिपूर्ण स्थिति से बच नहीं सकती है' कि उसने रेलवे कंपनी की सहायता की है और सिगनलरो का दमन किया है। इसका एकमात्र कारण यह है कि सिगनलर हिंदुस्तानी हैं जबकि कंपनी के प्रबंधक शासक जाति के हैं। 14 मई के अंक में 'गुजराती' ने और 16 मई के अंक में 'जामे जमशेद ने इस संबंध में स्मरण कराया कि दो वर्ष पूर्व जब इसी रेल कंपनी के यूरोपीय गाड़ों ने हड़ताल की थी, उस समय रेल कंपनी और सरकार दोनों ने संवधा भिन्न दृष्टिकोण अपनाया था और वस्तुतः उनकी मांगें मान ली गई थी।<sup>46</sup> 'मराठा' ने 16 जुलाई 1899 के अंक में निष्पक्ष रूप में लिखा कि वास्तव में सिगनलर राष्ट्रीय सम्मान के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि वे तो 'अपनी और अपने समाज की मान प्रतिष्ठा की रक्षा के उद्देश्य से ही प्रेरित हैं।'

भारतीय नेतृत्व का सिगनलरो की हड़ताल के प्रति दृष्टिकोण का राष्ट्रवादी अभि-प्रेरण एक भिन्न सदम में पता चलता है। 1897-98 में बंबई की कपडा मिलों में कितनी ही हड़तालें हुई थी।<sup>47</sup> प्रमुख राष्ट्रवादी समाचारपत्रों में से किसी ने भी उधर नहीं दिया था और न ही उनका समर्थन किया था। जिस 'अमृत बाजार पत्रिका' फाड़कर सिगनलरो की वेतनवृद्धि के लिए की गई हड़ताल का समर्थन किया था





कुछ महीनों के ही उपरांत बंबई की कपडा मिलों के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ती क विरुद्ध की गई हड़ताल का विरोध करने में सकोच नहीं किया। 10 जनवरी 1900 के अर्थ में इस पत्र ने बकालत करते हुए लिखा कि मालिक इसमें अधिक देने की सामर्थ्य ही नहीं रखते और उन्हें इस विषय में बाध्य करने की चेष्टा का अर्थ होगा भारतीय उद्योग को हानि पहुंचाना और इसका अंतिम परिणाम यह होगा कि अंत में श्रमिक का भी 'भूखो मरना पड़ेगा'।

### नए दृष्टिकोण का प्रारंभ

भारतीय श्रमिक वर्ग के उदय तथा श्रम और पूँजी में संघर्ष का धीरे धीरे उदय होने में भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के मन में इस नए वर्ग की सामाजिक भूमिका के संबंध में नए विचार तथा इसके अधिकारों और दायित्वों के प्रति नए दृष्टिकोण ने जन्म लेना प्रारंभ कर दिया। यहाँ यह बात भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि ये नए विचार कुछ ही भारतीय नेताओं तक सीमित थे। इन विचारों ने सभी का समान रूप से समान परिमाण में प्रभावित नहीं किया था। यह काफी आश्चर्यजनक है कि इस नए दृष्टिकोण का विवेचन सर्वप्रथम मार्च 1899 में बंबई मिल ओनर्स एसोसिएशन की बैठक में उस समय किया गया जब स्वयं एक मिल मालिक डी० ई० वाचा ने यह विचार प्रस्तुत किया कि बस्त्र उद्योग का उत्पादन व्यय दो तरीकों से घटाया जा सकता है प्रथम, प्रयोग की जाने वाली कच्ची कपास के स्तर को सुधार कर और द्वितीय, कर्मचारियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थिति सुधार कर। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि काम के लंबे घंटे, थोड़े वेतन तथा जनता के खाद्य पदार्थों पर करों ने सर्वव्यवहारिक विकास को पगुही बनाया है। दूसरी ओर काम के अपेक्षाकृत कम घंटे, अपेक्षाकृत ऊँचे वेतन, मस्त खाद्य पदार्थों की व्यवस्था और आवास सुविधा आदि ने निश्चित रूप से ही विकास को पुष्ट और सशक्त बनाया है।<sup>18</sup> वाचा महाशय ने अपनी इस सलाह को अप्रैल 1905 में फिर दोहराया और उन्होंने दस घंटों के पाय दिवस की बकालत की, उन्होंने मिलमालिकों को चेतावनी दी कि वे सोन का अटा देने वाली मुर्गी की हत्या करने की नीति पर चलने से और अपने लोभ नालच से वाज आग। उन्होंने चुनौती के स्वर में कहा कि श्रमिकों का प्रश्न भविष्य में मिलमालिकों के लिए एक जटिल समस्या का रूप ग्रहण करने जा रहा है। अतः मिलमालिकों की अपनी भलाई इसी में है कि श्रमिकों की ओर से सरकार अपना किसी अन्य पक्ष द्वारा हस्तक्षेप करने से पूर्व स्वयं के (मिलमालिक) ही इस समस्या को सुलभाना प्रारंभ कर दें।<sup>19</sup>

भारतीय रंगमंच पर उभरते हुए श्रमिक वर्ग के महत्त्व को उस समय पहचानने वाले बिपिनचंद्र पाल दूसरे नेता थे। दुर्भाग्यवश उनके इस श्रवण (1901-05) के अधिकांश लेख नष्ट हो गए हैं अथवा कम से कम मुझे तो उपलब्ध नहीं हो सके हैं। 1901 में उनके द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले साप्ताहिक पत्र 'यू इंडिया' की दो चार प्रतिष्ठा दस शताब्दी के सांख्यिक पुस्तकालयों में मिल पाई हैं। इनके अध्ययन से यह प्रकट हो जाता है कि पाल महोदय निश्चित रूप से श्रम समस्या पर प्रगतिशील



में वे बचारे अपनी दैनिक अनिवाय आवश्यकताओं के दास ही थे। उनके सामन तो ये ही विकल्प थे भूलो मरना अथवा किसी भी मूल्य पर अपने धर्म को बचना।<sup>54</sup> वस्तुतः प्रतियोगिता का अथवा पूर्ति और मांग का यह नियम सवथा क्रूर था, जिसके अंतर्गत धनी अधिक धनी और गरीब और अधिक गरीब बनता है। इस सिद्धांत ने ता भारतीय श्रमिक को विवशता की स्थिति पर ला खड़ा किया है।<sup>55</sup> फिर इस ताटस्थ्य सिद्धांत का विकल्प क्या था ? जी० एस० अय्यर की मांगता थी कि मालिकों के मन में अपने असहाय, दरिद्र कमचारियों के प्रति उदारता और दयालुता की सहज भावना को पनपाना चाहिए परंतु उन्हें जपन सुभाष की व्यापारहारिता में सदेह था क्योंकि इस प्रकार की भावना का विकास अनिश्चित तथा अनिर्णीत था और उसका प्रवर्तन सर्वोच्छील तथा अस्थिर था। इससे एक ही मांग शेष रहा। राज्य ही एकमात्र ऐसा अभिकरण था जो व्यंग्य उपहास के रूप में स्वतंत्र कह जाने वाले इस दुर्लभ बग को असीम और वस्तुतः असमान प्रतियोगिता से बचाने का दायित्व ले सकता है, निभा सकता है और जिसे यह दायित्व उठाना और निभाना ही चाहिए।<sup>56</sup>

जी० एस० अय्यर ने साथ ही साथ यह भी अनुभव किया कि मालिका द्वारा अपने अधिकार दबाए जाने के विरुद्ध अपनी रक्षा के लिए श्रमिकों को अवश्यमेव एकजुट होना चाहिए तथा अपने संगठन बनाने चाहिए।<sup>57</sup> इस समय यदि एक श्रमिक अपने मालिक के किसी दुर्व्यवहार के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में नौकरी छोड़ता है तो दूसरा श्रमिक कम वेतन पर ही काय करन का सहर्ष तैयार हो जाता है। श्रमिकों में एकता न हान के कारण 'ऐसा करने वाले श्रमिक को उसके समुदाय द्वारा किसी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जाता'। इसके विपरीत दूसरे देशों में श्रमिक वेतन का सामान्य स्तर से नीचे गिरता सहन ही नहीं कर सकते। इसके स्थान पर तो वे काम ही बदल देते हैं।<sup>58</sup> वस्तुतः उन्होंने अनुभव किया कि जब अंगरेज श्रमिका न संगठित होना सीखा, और 1824 में संगठित होने के अधिकार को प्राप्त कर लिया तभी उनकी प्रगति प्रारंभ हुई, पश्चिमी सभ्यता में श्रमिक बग को इतने सशक्त तत्व के रूप में प्रतिष्ठित करने का कारण मात्र उठावा संगठित होना है।<sup>59</sup> उन्होंने श्रमिकों को मध्य में संगठित होने और अपने अधिकारों के लिए मालिकों से सघप करने के लिए कहा।<sup>60</sup> उन्होंने जनता में भी इस बात की अपील की कि अपने को संगठित करने के काम में जनता मजदूरों को हर तरह की सहायता दे।<sup>61</sup>

जी० एस० अय्यर अपनी पूर्वनिर्दिष्ट महत्वपूर्ण पुस्तक 'मृषि श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन करने वाले प्रथम और एकमात्र राष्ट्रवादी अध्यासत्री थे। उन्होंने एक पूरे अध्याय में इसी विषय का विवेचन किया। मृषि श्रमिका की अत्यंत विषम दुर्गति पर विचार प्रकट करते हुए उन्होंने श्रमिका के हितों के लिए धातक जमींदारों के दबाव के आगे भ्रान्त के विरुद्ध सरकार का चेतावनी दी।<sup>62</sup>

श्रमिक समस्या के प्रति जागरूकता विज्ञान चाल दूरने भारतीय लेखक 'डॉन' के सहायक सतीशचंद्र मुखर्जी थे। इस विषय पर उनके विचार अगस्त 1898 के 'डॉन' में प्रकाशित तैसा, 'आसपकट्स आफ इवानामिन साइफ इन इंग्लैंड ऐंड इटिया' तथा 'डॉन'

के माच, अप्रैल, मई और जून 1100 के अको मे प्रकाशित, 'दि इंडियन इकोनामिक प्रॉब्लम' म देखे जा सकते हैं। पश्चिम की औद्योगिक प्रणाली की संचालन विधि की जानकारी मुकर्जी को अपने समकालीन किसी भी अय भारतीय की अपेक्षा अधिक अच्छी थी। इसके अतिरिक्त उनका दावा था कि वे विद्युद्ध रूप से प्रधानतया किसानो और श्रमिको की हितकामना से ही प्रेरित थे।<sup>66</sup> परतु उनके श्रमिक समस्या के विश्लेषण को एक अय कारण से भी महत्ता प्राप्त है। यह उन छोटे माटे बुजुआओ, बुद्धिजीवियो, व्यावसायिका, कलकों तथा कमचारियो के उदीयमान वर्गों की प्रथम सयुक्त छवि थी जो पूजीपतिया के विकासशील बग के विरुद्ध ता थे परतु वे अभी तक नए मजदूर बग के साथ अपने को जोट नही पाए थे। यह एक सयोग की बात नही है कि यह सवाल सव-प्रथम बगाल म उठा जहा शिक्षित कमचारिया और व्यावसायिका का बग उठ खडा हुआ था और स्वदशी पूजीपति बहुत कम थे।

मुकर्जी प्रस्तावना रूप म यह मान कर चले कि भारतीय आर्थिक ससाधना का पूरा पूरा विकास करना ही होगा।<sup>67</sup> परतु उनका तक था कि यही पयाप्त नही होगा। इस स्थिति म एक उपयुक्त प्रश्न उत्पन हुआ कि साधनो का विकास कौन करेगा और उन पर नियंत्रण कौन रखेगा।<sup>68</sup> ब्रिटिश उद्योगो के विकास के इतिहास का अध्ययन प्रस्तुत करत हुए उन्होंने कहा कि अब तक ता उद्योगीकरण के सारे लाभ पूजीपतियो को मिलते रह ह। आधुनिक उद्योग के आगमन और विकास की परिणामगत स्थिति यही रही है

श्रमिकबग जो पिठली कई शतादिया तक बडे बडे जमीदारो के आधिपत्य की बुराइया का शिकार रहता था वह अब समान रूप से अत्याचारी पूजीपतिया के हाथो मे पड गया है। यद्यपि वे कहने को (राजनीतिक दष्टि से) मुक्त हैं परतु वस्तुन आर्थिक दष्टि मे वे अपन पूजीपति मालिको के पूर्वपिक्षा अधिक ही अधीन हैं।<sup>69</sup>

मुकर्जी न फ्रेडरिक एंगल्स की प्रसिद्ध पुस्तक, 'बर्किंग क्लासेज इन इंगलड इन 1844' से तय्य उद्धृत करत हुए ब्रिटिश श्रमिको की दरिद्रता और निवृष्ट स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया।<sup>70</sup> उन्होंने मिद्ध किया कि आधुनिक कानून भी उन बुराइया को मिटाने म असफल रहा था क्योंकि उन बुराइयो की जड जिननी प्रतीत होती है उससे कही गहरी थी।<sup>71</sup> फलत यदि पश्चिम की औद्योगिक पद्धति को ही भारत म लागू किया गया है तो इसका एक और अनिवाय परिणाम है छोटे से अल्पमतीय सुगठित पूजीपतिबग का उदय, यह बग विदेशी हा अथवा स्वदेशी। इस बग की शक्ति और प्रभाव का अय जनता की सुख-समृद्धि म उन्नति कदापि नही।<sup>72</sup> दूसरी और श्रमिकबग एवमात्र मगोन बन-कर रह जाएगा। वे श्रमिक दूमरो के लिए कमरतोड काम करन वाले बन जाएगे। उनका आत्मसम्मान समाप्त हो जाएगा और वे असहाय बन जाएंग और उस स्थिति म अपन मालिको के अधीन हो जाएंग।<sup>73</sup> इस दुदशा से बचन के लिए श्रमिको का एकजुट होकर विगाल पैमाने पर श्रमिक सघो का संगठन करना पडेगा। उन्हें सुगठित पूजीपतीय शक्तियो के विरुद्ध श्रमिक कल्याण सघो की व्यवस्था के रूप म अपनी महायता आप



करने का माग ग्रहण करना होगा। यही माग उह 'गति और व्यवस्था' के लिए एक घमकी और सचमुच ही 'स्थायी रूप से राजनीतिक और सामाजिक खतरा' बना देगा।<sup>4</sup>

मुखर्जी ने अनुभव किया कि पूँजीपतीय औद्योगिकता का यह द्विमुखी परिणाम समाज को निश्चित रूप से एक गहरी विडमना में डाल देगा। श्रमसघा के अस्तित्व से जहा समाज की स्थिरता को खतरा मिद्ध होगा वहा इनका अभाव इससे भी भयकर खतरा उत्पन्न करेगा। भली प्रकार संगठित पूँजीपनिवग के अवाध विकास का अनिम परिणाम होगा, औद्योगिक अधदासता।<sup>5</sup> यह भयकर स्थिति लागो को खने और विश्लेषण करने के लिए विवश करेगी कि क्या इस स्थिति, जिमम निश्चित रूप से अचछाई को बुराई और बुराई को अचछाई में मिलाने वाली सभी दूषित विचारा और प्रवृत्तियो वाली संस्थाए शामिल ह के अतिरिक्त अय कोर्दे ऐसा उपाय नही है कि जिमम भारत की औद्योगिक समस्याओ का समाधान ढूढा जा सके।<sup>6</sup>

मुखर्जी द्वारा समस्या का मुभाया उपाय द्विमुखी था, प्रथम नैतिक तथा द्वितीय भौतिक। सारे आर्थिक जीवन को इस प्रकार पुनर्गठित करना चाहिए कि प्रतियोगिता का सिद्धांत नैतिक सिद्धांत पर आधारित हो जाए और वह नैतिकता की महत्ता स्वीकार करे।<sup>7</sup> आर्थिक समस्या को व्यापक नैतिक जीवन से संबद्ध रूप में ग्रहण करना चाहिए।<sup>7</sup> वस्तुतः समाज की इस नई व्यवस्था में भौतिक संपन्नता को प्रोत्साहन तो दिया जाएगा परंतु जनता इस भौतिक संपन्नता को अनिवायन प्रथम स्थान कदापि नहीं देगी। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक विकास ही उन्नति का स्वरूप बन जाएगा।<sup>8</sup> भौतिक स्तर पर आधुनिक पूँजीपतीय औद्योगिकता के दोषों का मयासभव निवारण प्रथमता स्वयं औद्योगिक संगठनों द्वारा ही किया जाएगा। इसके अतिरिक्त औद्योगिक पारिवारिक सघ के रूप में उपादन-प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी जिमका आधार यह होगा कि कर्मचारी, कारीगर और कृषक सब एक ही परिवार के अंग माने जाएंगे और समान लाभदा के अधिकारी होंगे। ये पारिवारिक सघ व्यवसाय मशीना और पूँजी की विपुल राशि की अपेक्षा रखने वाले बड़े पैमाने के पूँजीगत उद्यमों, इजीनियरी माजनाए, खानों, रासायनिक तथा धातु शोधन उद्योग, की स्थापना करेंगे। इन उद्योगों के सफल प्रबलन से व्यक्तिगत तथा सामूहिक मस्कृति के विकास में किसी प्रकार की बाधा के बदल नहीं यता ही मिलेगी।<sup>9</sup> मुखर्जी ने दावा किया कि आर्थिक संगठन की यह व्यक्तिनिष्ठ प्रणाली श्रमिकों के स्वाभिमानों और स्वतंत्र बग को जन्म देगी। इस प्रणाली के अंतर्गत श्रमिक व एक एक दिन के श्रम का विनाश महत्व होगा।<sup>10</sup> अपनी पद्धति के नैतिक और आर्थिक तत्वा का जाडत हुए मुखर्जी ने 1900 में प्रधान रूप से छोट पमात के उद्योगों के निर्जी गठन पर आधत सामूहिक समाज की मस्थापना की सिपारिश इन शब्दों में की मेरा विचार यह है कि राष्ट्रीय विमान का काय इस रूप में संपन्न किया जा सता है कि काय और गतिविधि के आध्यात्मिक, बुद्धिजीवी, मनिक व्यापारिक, तथा वनन भोगी सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों के समक्ष एक उच्च सांस्कृतिक जाण्य ह। समाजिक संगठन में सभी के लिए एक मवसम्मत निर्जी और सम्मानित स्थान हो। सभी इस प्रकार पारस्परिक ममजय और सहयोग से काय करें जिगत बिना किसी भेद

भाव के सारे भारतीय समाज की समान रूप से आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति हो।<sup>18</sup>

सदभ

- 1 वियोडोर मोरिसन दि इकोनामिक ट्रांजिशन इन इंडिया (लन्डन 1916) प० 174 75
- 2 रिपोर्ट आफ दि बाबे फक्टरी लेबर कमीशन आफ 1885 प० 5
- 3 आर० क० दास फक्टरी लैबर इन इंडिया (बर्लिन 1923) प० 56 बुकानन पूर्वोद्धत, प० 307 08 भारतीय कारखानों के काम के लंब घटाने के रुढ़िवादी समाचारपत्र टाइम्स आफ इंडिया को भी इतना उत्तेजित किया कि उसने अपने 16 सितंबर 1905 के अंक में इस दृष्टि की इन शान्ति में निंदा की मालिक श्रमिकों को सबेरे से शाम तक काम करने को विवश कर रहे हैं। नीचे मालिक अपने लाभों की अतृप्त तृष्णा के लिए बेचारे श्रमिकों का जीवन रक्त पी रहे हैं—अहमद मुश्तार की पुस्तक फक्टरी लेबर इन इंडिया मद्रास 1930 में प० 31 पर उद्धृत
- 4 बुकानन पूर्वोद्धत प० 312
- 5 रिपोर्ट आफ दि बाबे फक्टरी लेबर कमीशन आफ 1885 प० 8
- 6 फक्टरी इस्पेक्टर की रिपोर्ट—1888 बुकानन पूर्वोद्धत प० 310
- 7 मारक्सिस आफ सलिसबरी का बाबे सरकार को संप्रेषण ए० जी० क्लो इंडियन फक्टरी लजिस्लेशन ए हिस्टोरिकल सर्वे (कलकत्ता 1926) (इंडियन इंडस्ट्रीज और लेबर की एन रेडिया वार्ता स० 37) में उद्धृत प० 2
- 8 दास फक्टरी लेबर इन इंडिया प० 59
- 9 दास फक्टरी लेबर इन इंडिया, प० 59 60 बुकानन पूर्वोद्धत, प० 308 311 क्लो पूर्वोद्धत प० 29 30
- 10 रिपोर्ट, प० 10
- 11 वही प० 13
- 12 वही प० 12 तथा देखिए वही प० 11 3
- 13 दास फक्टरी लेबर इन इंडिया प० 139 बुकानन पूर्वोद्धत प० 329
- 14 रिपोर्ट आफ दि बाबे फक्टरी लेबर कमीशन आफ 1885 प० 12 3
- 15 बुकानन पूर्वोद्धत प० 332 और 349-51, दास फक्टरी लेबर इन इंडिया, प० 145 6 152 3 बाबिया और मर्चेंट न ए शाट हिस्टरी आफ लेबर कडीशस ऐंड दि एपायर (लेखक कुंजिस्की) (लन्डन 1942) से एक तालिका प्रस्तुत की है जिसमें यह दिखाया गया है कि 1880 1919 तक भारतीय कारखानों के श्रमिकों के वास्तविक वेतन में निरंतर गिरावट आई है। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रथम विश्वयुद्ध तक की अवधि में घन वेतनों में वृद्धि की प्रवृत्ति में पर्याप्त एकरूपता रही है इसके विपरीत दूसरी ओर वास्तविक वेतनों में ह्रास की प्रवृत्ति के दशन होते हैं (पूर्वोद्धत प० 372)
- 16 जम्स जोस फक्टरी इस्पेक्टर की रिपोर्ट क्लो पूर्वोद्धत प० 17
- 17 देखिए दास फक्टरी लजिस्लेशन इन इंडिया (बर्लिन 1923) प० 5-11

- 18 जे० सी० रिड ए हिस्टरी आफ फक्टरी लजिस्लेशन इन इंडिया (बलकला 1920) पृ० 45  
को पूर्वोद्धत प० 45
- 19 रिड पूर्वोद्धत प० 9 वला पूर्वोद्धत प० 4
- 20 दास फक्टरी लजिस्लेशन इन इंडिया प० 15, रिड पूर्वोद्धत प० 5
- 21 दास फक्टरी लजिस्लेशन इन इंडिया प० 16 सरकार ने इसके बदले एक अय स्थिति शून्य की कि स्वयं पीड़ितों द्वारा अपने आप अपना उनको प्रतिनिधिया द्वारा मिलमालिका द्वारा लिए गए किसी अत्याचार के विरुद्ध सरकार को कोई शिकायत ही नहीं मिला है। (मला द्वारा उद्धत पूर्वोद्धत प० 6)
- 22 दास फक्टरी लजिस्लेशन इन इंडिया, प० 18 20
- 23 वही, प० 16-7
- 24 उपाहरणाय इसका 15 जनवरी 1880 का एक दखिण (आर० एन० पा० बब०, 17 जनवरी 1880)
- 25 डी० चमालाल कुली (लाहौर 1932) घड II पृ० 78 जोर को पूर्वोद्धत, पृ० 9
- 26 वलो पूर्वोद्धत प० 11
- 27 1881 के ऐक्ट की संख्या, 15
- 28 किड—पूर्वोद्धत प० 21 पर उद्धत
- 29 आर० एन० पी० बब० 28 नवंबर 1874
- 30 वही, 4 जनवरी 1879
- 31 वही, 4 जनवरी 1879 तथा 25 जनवरी 1879 क्रमश
- 32 वही 13 दिसंबर 1879 13 नवंबर 1880 2 अप्रैल 1881 क्रमश
- 33 26 जनवरी (वही 1 फरवरी 1879) और 23 नवंबर (वही, 29 नवंबर 1879)
- 34 वही, 13 नवंबर 1880
- 35 वही 26 मार्च 1881
- 36 वही 22 नवंबर 1879
- 37 इसका कारण बदाचित यह तथ्य था कि एल० एल० बगाला उमने स्वामियों म एक थे
- 38 28 मार्च (आर० एन० पी० बब०, 2 अप्रैल 1881)
- 39 वलो पूर्वोद्धत पृ० 9
- 40 आर० एन० पा० बब० 27 मार्च 22 मई 2 अक्टूबर 1875 तथा देखिए ए० बी० पी० 2 सित० 1875 बा० बी० मजूमदार द्वारा पूर्वोद्धत पृ० 353 पर उद्धत
- 41 नैटिव ओपीनियन 29 दिसंबर 1878 19 जनवरी 1879 गुजरात मित्र 29 दिसंबर 1878 12 जनवरी 1879 जाम जमसद 8 जनवरी 1879, जलगांव समाचार 19 जनवरी 1879 बर्दई समाचार 23 जनवरी 1879 खानदेग व मव 13 जनवरी 1879, राजधान परस्व 26 जनवरी 1879 अरणादय 26 जनवरी 1879 लावमित्र 26 जनवरी 1879 और सत्य सन्न 15 फरवरी 1879 (देखिए आर० एन० पा० बब० सप्ताहान 4 11 18 और 25 जनवरी तथा 1 15 22 फरवरी 1879) 'बनास ग हिंदुस्तान 28 जून 1878 (आर० एन० पा० पा० एन० 4 जनवरी 1879) अद्यतरे आम 8 जनवरी (वही 11 जन० 1879) नसाये अमरा 30 जनवरी (वही 1 फरवरी 1879) भारत मिहिर 29 जनवरी (आर० एन० पा० बब० 8 फरवरी 1879) सहसर 10 मार्च (वही 15 मार्च 1879)

- 42 देखिए, आर० एन० पी० बब० के संबधित भ्रम
- 43 फक्टरी लजिस्लेशन इन इंडिया, जे० पी० एस०, जुलाई 1881 खंड IV स० 1, प० 39
- 44 17 मार्च 26 मार्च और 24 मार्च 1881 त्रमस
- 45 जनवरी (आर० एन० पी० पी० एन० 8 जनवरी 1880)
- 46 बंबई के लिए देखिए, जामे जमशेद, 28 नव० 1879 और 14 मार्च 1881, बंबई समाचार 8 दिसंबर 1879 और 22 दिस० 1880 हितेच्छु 11 दिस० 1879 सूर्यप्रकाश 13 दिस० 1879 और 19 मार्च 1881 शमशेर बहादुर 17 दिस० 1879, सूर्योदय, 29 नव० 1880 बाबे शानिकल, 14 मार्च 1881 राजदान परस्त 13 मार्च 1881 खानेश बभब 18 मार्च 1881 गुजरात मित्र 20 मार्च 1881, गंगा लहरी, 25 मार्च 1881 शुभमूचक 25 मार्च 1881 शिवाजी, 25 मार्च 1881 'याय प्रकाश 28 मार्च 1881 आर्यावित तथा नासिक वत्त 9 अप्रैल 1881 (देखिए आर० एन० पी० बब० के संबधित भ्रम) बंगाल के लिए देखिए सहचर 14 मार्च (आर० एन० पी० बग० 26 मार्च 1881) नवविभाकर 21 मार्च साधारणी 27 मार्च (वही 2 अप्रैल 1881), भारत मिहिर, 29 मार्च (वही 9 अप्रैल 1881) आनंद वाशार पत्रिका 4 अप्रैल (वही, 16 अप्रैल 1881)
- 47 नेटिव ओपीनियन 19 जनवरी (आर० एन० पी० बब० 25 जनवरी 1879) गंगा लहरी, 25 मार्च (वही, 2 अप्रैल 1881), बंगाली 26 मार्च 1881 और दि फक्टरी लजिस्लेशन इन इंडिया पूर्वोक्त स्थल पृ० 48-9 मजदार बात यह है कि यह तक उस समय बिना किसी हिचकिचाहट या परेशानी के तब पर रख दिया गया जब राष्ट्रवादी नेताओं ने बागान मजदूरों अथवा किसानों का मामला उठाया उस समय उन्होंने अचानक इन मूक प्राणियों की बाणी की भूमिका अपना ली
- 48 जामे जमशेद 25 मार्च (आर० एन० पी० बब०, 27 मार्च 1875) गुजराती 28 नवंबर (वही 4 दिस० 1880), सहचर 14 मार्च (आर० एन० पी० बग० 26 मार्च 1881) दि बाहो पब्लिक ओपीनियन ने 27 फरवरी 1879 के भ्रम में लिखा कमचारियों और मालिकों के आपसी संबंध पूणत स्वस्थ हैं। कमचारियों से कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध काम नहीं लिया जाता। उनके बतन निश्चित हैं और वे पूण उदारता के साथ तथा नियत समय पर दिए जाते हैं इससे लिए भगरेजी और देशी कारखाने सचमुच प्रशंसा के पात्र हैं। कतिपय अपवादों को छोड़कर सभी कारखाने प्रायः ऐसे स्थानों पर बनाए गए हैं जो स्वास्थ्य और स्वच्छता की दृष्टि से सबसे उपयुक्त हैं जब कोई कमचारी कारखाने में बीमार पड़ जाता है तो मालिक उसके स्वास्थ्य का भलीभांति देखभाल करते हैं
- 49 बंबई समाचार, 2 मई (आर० एन० पी० बब० 3 मई 1879) और 2 दिसंबर (वही 4 दिस० 1880) जामे जमशेद 28 नवंबर (वही 29 नव० 1879) सहचर 14 मार्च (आर० एन० पी० बग० 26 मार्च 1881)
- 50 फक्टरी लजिस्लेशन इन इंडिया, पूर्वोक्त स्थल पृ० 49
- 51 जामे जमशेद 17 मई (आर० एन० पी० बब० 22 मई 1875) फक्टरी लजिस्लेशन इन इंडिया, पूर्वोक्त स्थल पृ० 35-6 और 41, ए० बी० पी० 17 मार्च 1881
- 52 गुजरात मित्र 12 जन० (आर० एन० पी० बब० 18 जन० 1879) फक्टरी लजिस्लेशन इन इंडिया पूर्वोक्त स्थल पृ० 37-40 और 49 इनमें से परवर्ती में निम्नलिखित अवतरण प्रकाशित हुआ था 'इस कथन में कोई अतिरजना नहीं कि जहां तक नियमानुसार कारखानों में काम

- (वही 13 दिस० 1890) गुजराती 7 दिस० (वही), मराठा 14 दिसंबर 1890 समय, 17 दिसंबर (आर० एन० पा० वग० 20 दिसंबर 1890)
- 95 1890 व बिल और 1891 के ऐक्ट पर समाचारपत्रों की टिप्पणियों में कमी का एक अन्य कारण यह था कि समाचारपत्र पढ़ने ही एक आप कानसैट बिल (सहमति बिल) में व्यस्त थे
- 96 जामे जमशान् 8 मार्च (आर० एन० पी० वग० 4 मार्च 1891) तथा इंदु प्रकाश 11 अप्रैल 1891 मराठा 5 अप्रैल 1891 सुरभि ओ पताका 10 अप्रैल (आर० एन० पी० वग०, 18 अप्रैल 1891) सत्हर 9 सितंबर (तथा 19 सितंबर 1891)
- 97 मराठा 16 फरवरी 1890 और 5 अप्रैल 1891 सुरभि ओ पताका 13 फरवरी (आर० एन० पी० वग० 22 फरवरी 1890) दैनिक ओ समाचार चंद्रिका, 5 मार्च (वही 8 मार्च 1890) के० एल० नुनकर एल० मा० पी० 1891 छद्म \XX, प० 177 179
- 98 हिंदू न 10 दिसंबर 1890 के एक में अपेक्षाकृत और अधिक भाषा प्रकट की उसने संपादक ने यह कहते हुए कि— यमिका की स्थिति अच्छी है और व काफी प्रसन्न है लिखा कि उसने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि किस प्रकार उनका पारिधमिक बढ गए हैं किस अच्छी प्रकार से उनकी देखभाल का जाता है और कितना सुखद भविष्य उनके सामने है सत्हर, 11 मार्च (आर० एन० पी० वग० 21 मार्च 1891)
- 99 आर० एन० पी० वग० 17 मई 1890 तथा सत्हर 9 सितंबर (आर० एन० पी० वग०, 19 सितंबर 1891) यह द्रष्टव्य है कि मराठी प्रवक्ताओं ने भारत में निग्रहना की स्थिति को नकारने के लिए जाय और जायदकताओं की मापेक्षितता का तक पैत किया तो राष्ट्रवादी नेताओं ने इसे अवमानना, क्रूर तथा हृदयहीन बनाकर अस्वीकृत कर लिया अर्थात् 1
- 100 दास फरवरी त्रिजिज्ञान इन इडिया प० 90-] तथा हिंदुस्तान 1 जून (आर० एन० पी० एन० 5 जन 1889)
- 101 मराठा 3 जन 1884 गुजरात दपण 30 मई (आर० एन० पी० वग० 1 जून 1889) भारत जीवन 1 दिसंबर (आर० एन० पी० एन 9 दिस० 1890) दास के फरवरी त्रिजिज्ञान इन इडिया प० 90 पर उद्धृत के० एन० बहादुरजी, सत्हर 9 सितंबर (आर० एन० पी० वग०, 19 सितंबर 1891)
- 102 आर० एन० पी० वग० 26 जनवरी 1889
- 103 हिंदू 17 मई 1889 समय 28 दिसंबर 1888 (आर० एन० पी० वग० 5 जनवरी 1889) मुनष समाचार और बुशान् 18 जन (वही 26 जनवरी 1889) मराठा 14 दिस० 1890 समय 14 फरवरी (आर० एन० पा० वग० 22 फरवरी 1890) नेटिव ओपीनियन 6 फरवरी (आर० एन० पी० वग० 8 फरवरी 1890)
- 104 कतिपय समाचारपत्रों ने इस प्रस्ताव का भी विरोध किया परंतु केचन जून 1890 से एन तक ही दिये, समय 24 मई (आर० एन० पी० वग० 1 जन 1889), हिंदुस्तान 22 मई (आर० एन० पी० एन० 29 मई 1899) और 23 अप्रैल (वही 23 अप्रैल 1890) भारत जीवन 1 दिस० (वही 9 दिस० 1890) नेटिव ओपीनियन 6 फरवरी (आर० एन० पी० वग० 8 फरवरी 1890) इस सम्म में 22 फरवरी 1889 व मर्च में हिंदुस्तान ने इस तक की बात कहात हुए लिखा कि इस सम्म से विनमार्तिक अपने साथ के सप्तमास से बरित हो जाएय पर भी मन्त्रेतर बान है कि उन समय हिंदुस्तान का सम्मान बाई और नही सम्मानाहन माधवीय व और मार्तिक व राजा रामपालसिंह जो उन निर्वा कायण के मर्च के एक प्रवक्

साहसी ब्राह्मण के नेतृत्व में हिन्दुओं ने नान विरुद्ध (मन्नाम विधि रद्दित तृतीय संस्करण) काय 1 पृ० 146

- 105 6 अप्रैल 1891 इस बात का अर्थ उमे अत्यन्त भिन्ना चाहिए कि इस विपिन्न खबरे का प्रयोजन भी उगने उनी सपादकाय म स्पष्ट कर दिया है परन्तु अमिका के शिरो सञ्जन हटकर यह भूछता उगमूक हागा कि क्या सरकार पर पूजागिया इस प्रकार क मानून से जिनके उत्पादन उद्यम बुरी तरह म अग्न धरता हा गग हैं के शिरो की दग्गभाल का दावित्व नहा है स्पष्ट है कि इंदु प्रकाश के लिए उनीपमान औद्योगिक पूजावाद की गतिनया क विरोध की ओसा हिंदू चंद्रिकागिता की शीघ्र करते वाली गतिनयों का विरोध करना सरल ही था
106. मराठा 13 माघ 1892 संजीवनी 5 निसबर (आर० एन० पी० बग० 12 निसबर 1891) नटिव आपीनियन 10 माघ गुजरात दपण 10 मार्च बर्दई समाचार 7 माघ (आर० एन० पी० बब०, 12 माघ 1892) और एविए बगबाता 9 अप्रैल (आर० एन० पी० बग० 16 (अप्रैल 1892)
- 107 हिंदुमनान 23 अप्रैल (आर० एन० पी० एन० 28 अप्रैल 1890) भारत जावन 1 दिसबर (बही 9 निसबर 1890) मराठा 7 निस० 1890 हिंदू 16 नित० 1891
- 108 आर० एन० पी० बग० 18 अप्रैल 1891
- 109 और एविए बर्दई समाचार 4 निसबर (आर० एन० पी० बब० 6 निसबर 1890)
- 110 ए० बी० पी० 7 फरवरी 1889, हिंदू 17 मई 1889 बाहे नूर 28 मई (आर० एन० पी० पी० 8 जून 1889) समय 14 फरवरी (आर० एन० पी० बग०, 22 फरवरी 1890) भारत जीवन, 1 निसम्बर (आर० एन० पी० एन०) 9 दिसम्बर 1890) दैनिक ओ समाचार चंद्रिका 5 माघ (बही 8 माघ 1890) गुरभि ओ पताका 10 अप्रैल (बही 18 अप्रैल 1890) सहृषर, 9 सितंबर (बही 19 सितंबर 1891) इंदु प्रकाश 11 अप्रैल 1891
- 111 सी० बी० ए० पृ० 264-5 बनर्जी न बंगाल के विदेशी स्वामित्ववाले पटतन उद्योग को भी अपने सरक्षण में लिसा जा हु डी क प्रहार का शिकार पा
- 112 और देखिए मराठा 23 निसबर 1888 समय 28 दिसबर (आर० एन० पी० बग० 5 जनवरी 1889) गुरभि ओ पताका 10 अप्रैल (बही 18 अप्रैल 1891), गम खबारे हिंदू 21 माघ (आर० एन० पी० पी० 28 माघ 1891)
- 113 मराठा 23 निस० 1888 ए० बी० पी० 8 फरवरी 1889, हिंदू 14 और 17 मई 1889 और 10 दिस० 1890 गान प्रकाश 16 मई और ट्रिभ्यू 22 मई (बी० बी० आई० जून 1889) मुलम समाचार और कुशदाह 18 जनवरी (आर० एन० पी० बग० 26 जनवरी 1889), गुरभि ओ पताका 31 जनवरी (बही 9 फरवरी 1889) सहृषर 7 फरवरी (बही 16 फरवरी 1889) प्रतिहार 7 जून (बही, 15 जून 1889) हिंदी प्रदीप (आर० एन० पी० एन० 26 जून 1889) गुजरात दपण 30 मई और शिवाजी 24 मई (आर० एन० पी० बब० 1 जून 1889), कोदैनूर 28 मई (आर० एन० पी० पी० 8 जून 1889) सजीवनी 8 फरवरी (आर० एन० पी० बग० 15 फरवरी 1890) समय 14 फरवरी (बही 22 फरवरी 1890) दैनिक ओ समाचार चंद्रिका 5 मार्च (बही 8 माघ 1890) कासिम उल अखबार 10 फरवरी (आर० एन० पी० एम० 28 फरवरी 1890) भारत जीवन 1 दिस० (आर० एन० पी० एन० 9 निस० 1890) ट्रिभ्यू 11 माघ (आई० एम० बी० ओ० आई०, 29 माघ 1891 प० 257), नेटिव ओपीनियन 26 माघ (बही 19 अप्रैल 1891 प० 316) सहृषर 11 माघ (आर० एन० पी०

जाती रही। मेरा विचार है कि हम मिल अभिवर्तिका के लिए इस प्रश्न में (1891 का फरवरी ऐबट) शिवायत करने की कोई बात नहीं। इससे विपरीत हमें तो यह पता उठाने के लिए सरकार का प्रस्ताव करना चाहिए (वही, पृ० 211) तथा दक्षिण ज० एन० माका (एल० सा० पी० 1891 खंड XXX पृ० 162) भरे विचार में सरकार ने श्रुता और साथ ही साथ विवेक के साथ पद सजा है।

138 बर्दई समाचार 3 और 5 फरवरी (आर० एन० पी० बव 8 फरवरी 1890), मराठा 22 जून 1890 आम अमरोद 8 मार्च (आर० एन० पी० बव 14 मार्च 1891)

139 हिदा मुन्तावर मुहूर्द मुन्त और गयाह चुस्त का भाव ही यहाँ अधिक उपयुक्त है।

140 अपनी पुस्तक 'राजाह प्राफिट आफ़ निवरेटड इंडिया में डी० जी० बर्बे लिखते हैं कि राजाह राज्य के हस्तगत हो इस रूप में चाहत है कि जिससे औद्योगिक प्रगति का पथ इस रूप में नियमित हो जाए कि बाड़ी सी परिहाय बठिनाई न हो (पृ० 118) परंतु हम राजाह के भारतीय अर्थशास्त्र पर लिखे निबंधों में अथवा उनके अन्य विमा प्रसिद्ध निबंध में इस प्रकार का कोई उद्धरण ढूँढ पाने में असफल रहे हैं। दुर्भाग्यवश बर्बे ने सदा निर्वेग नहीं किया। दूसरा और बगतीय भवतोय दस्त का धारणा है। राजाह के समय लेखन में वर्गों के प्रति न्याय का भाव शकता के सबंध में चला लोका के हाथों में पूजा के केंद्रित हो जाने के दुस्प्रभाव के सबंध में श्रमिक सभा की आवश्यकता के सबंध में अथवा मिल मालिकों के विरुद्ध श्रमिकों के दिनों के सरसक प्रभावी उपायों के सबंध में किसी उद्धरण को ढूँढना निरर्थक चेष्टा ही है। 'द इकॉनॉमिक्स आफ़ राजाह इन इकोनॉमिक्स इंडियन जर्नल आफ़ इकोनॉमिक्स', जनवरी 1942 खंड LXII पृ० 3 पृ० 262-3

141 इनके विपरीत उर्हानि 1911 में 1911 के इंडियन फ़ैक्टरी बिल का व्यययता जिसमें कपन बार खाना में बयस्क श्रमिकों के काम के घंटों को प्रतिदिन बारह तक सीमित करने का विधान का के विरुद्ध मतदान किया।

142 सी० पी० ए० 264-5

143 राजाह एनेज पृ० 60

144 वाशिया और मर्बेट पूर्वोद्धत पृ० 373

145 1887 में फ़ैक्टरी इम्पेक्टर जन्म प्राप्त न स्पष्ट दी कि बर्दई वस्त्र उद्योग अत्यंत समृद्ध है और बर्दई कारखाना न चार वर्षों में ही अपनी लागत पूजा वापस चुकता कर दी है (कला पूर्वोद्धत पृ० 17 पर उद्धृत) 1905-06 में भारतीय वस्त्र उद्योग का औसत विग्राह लाभ 227 लाख रुपये था जबकि इन दो वर्षों में वेतन के रूप में वायिव भुगतान की राशि थी बवल 209 लाख रुपये एन० डी० महता 'द इंडियन काउन्ट टक्सटाइल इन्स्टी' (बर्दई 1953) पृ० 203

146 सा० पी० ए० पृ० 12

147 एन० पी० पी० 1901 खंड XL पृ० 132

148 इपीरियल गजेटियर आफ़ इंडिया (1908) खंड III पृ० 56-7

149 तुननाय बदन स्पेविज II पृ० 238-9 अंश में श्रम व्यवस्था अनिवायन इत्तारनामे के श्रम की दो जिसके अंतर्गत श्रमिकों की निश्चिन्ता वर्षों का अनुबंध करने का मत जाना होता था कि श्रमिक अनबंध की प्रति नशा करते थे तो सरकार दंड विधान के प्रवर्धन की योजना द्वारा श्रमिकों की गहायता करती थी। भारतीय परिस्थितियों में अंशवार इत्तारनामा पद्धति एक बार अंश में गृह्ये श्रमिकों की प्रकृत मानिका के अग्रान और उनकी दया पर निर्भर बना रता था।





की कि देश के किसी भी वानून में इससे अधिक बकर व्यवस्थापन मिलाया नमक नहीं' (वही पृ० 169)

- 166 1897 1898 1899 1900 और 1901 के प्रस्ताव क्रमशः IV, XX, XIV X तथा XIII
- 167 वागल पूर्वोद्धृत पृ० 105-07
- 168 खंड II पृ० 352 522 तथा दक्षिण इंग्लैंड इंडिया पृ० 131
- 169 बंगाली 12 मई 1888, बंगाल क समाचारपत्रों के लिए दक्षिण, आर० एन० पी० बंग०, 26 मई 2 9 16 और 23 जून 1888 वायस आफ इंडिया, जुलाई 1888 (खण्ड VI, सं० 7), रियल स्पेक्ट्रेटर 3 जून (वही) वाफतावे हिंद 15 जून (आर० एन० पी० पी०, 23 जून 1888), इपीगियन पेपर 23 जून (वही 7 जुलाई 1888)
- 170 विशेष रूप में देखिए उनके 1886 के मक जब प्रस ने बुनी अधिनियम के विरुद्ध एक सफल अभियान छेड़ दिया था सजीवनी के अक्तूबर नवंबर और दिसंबर में प्रकाशित मकाम में इस विषय पर सुंदर और प्रामाणिक लेखमाला उपलब्ध है
- 171 ए० बी० पी० 19 अगस्त 1886, सजावना 20 अगस्त (आर० एन० पी० बंग० 27 अगस्त 1887) 1888 का मेमोरियल आफ दि इंडियन एगोसिएशन वागल पूर्वोद्धृत परिशिष्ट ई पीछे 169 पार्सिप्यपी में उल्लिखित समाचारपत्र ए० बी० पी० 24 मई 1888 हिंदू 30 मई 1888 चंद्र प्रकाश 11 जून 1888 नेटिव ओपीनियन 3 जून 1888 ए० एम० श्रीमती रिप० आई० एन० सी० 1888 पृ० 160, रहबर 14 फरवरी (आर० एन० पी० एन० 18 फरवरी 1892) 1893 में इंडियन एगोसिएशन द्वारा राज्य सचिव को प्रस्तुत विरोधपत्र 1893 में 1895 6 तक के वर्षों की रिपोर्ट आफ दि इंडियन एगोसिएशन पृ० 82 जे० सी० पाप रिप० आई० एन० भी० 1896 पृ० 165 6 दत्त इंग्लैंड एंड इंडिया पृ० 131 और ई० एच० II पृ० 352 उदाहरणार्थ जे० सी० धोप ने 1896 में काफस क प्रतिनिधियों का वताया मीने परोब आदमी और ओरता को भीत से भी बदतर भाग्य से बचने के लिए जहाज से ब्रह्मपुत्र क घाटे पाना में छनाग मगाते देखा है उसी वापस के सामन आर० के० सरकार न विवरण देते हुए बहा धनदान और असावधान जनता पर एक फोज सी खुनी छोट नी गई है और में आपकी विश्वास मिला सकता है कि दस के दूरस्थ मत्त प्रशास में इनक अतीत क पठारियों के आतंक से भी बचन है रिप० आई० एन० सी० 1896 पृ० 165 और 170 क्रमशः
- 172 प्रभाती 4 जून (आर० एन० पी० बंग० 7 जून 1884) मन्वर 4 जून (वही 14 जून 1884) सजीवनी 22 नवंबर (वही 29 नव० 1884) पनाका 25 सित० और नवविभाकर 28 सित० (वही, 3 अक्तूबर 1885) दि रियाल आफ नेटिव प्रस फार बंगाल 1886 सोम प्रवाग 19 जुलाई और आनंद बाजार पत्रिका 19 जुलाई (वही 24 जुलाई 1886) सजीवनी, 7 अगस्त (वही 14 अगस्त 1886) भारत मित्त्र 19 अगस्त (वही 28 अगस्त 1886) अक्तूबर नवंबर और दिसंबर की सजावनी (वही अक्तू० नव० और दिस० 1886) ए० बी० पी० 19 अगस्त 1886 हिंदू 24 जून 1887 मराठा 12 फरवरी और 27 मई 1888 1888 का इंडियन एगोसिएशन का ज्ञापन पूर्वोक्त स्थल पीछे 169 की पार्सिप्यपी में उल्लिखित समाचारपत्र ए० बी० पी० 24 मई 1888 वायस आफ इंडिया जुलाई 1888 (खंड VI सं० 7) इंडियन स्पेक्ट्रेटर रिप्यूट 23 मई 1888 3 जून 1888 (वही) रहबर 14 फरवरी (आर० एन० पी० एन० 18 फरवरी 1892) बंगाली 4 फरवरी 1893 दत्त ई एच II पृ० 522 और दि 8 मार्च (आर० एन० पी० बंग० 14 मार्च 1903) जी० एम० बय्यर ई ए पृ० 185

- 173 ए० बी० पी० 24 मई 1888, इन्डियन एसोसिएशन का 1888 का नामन पूर्वोक्त स्थल दत्त इंग्लड ऐंड इडिया प० 131 ई एच II प० 352
- 174 बगल पूर्वोक्त प० 103 तथा इडियन एसोसिएशन का 1888 का नामन पूर्वोक्त स्थल
- 175 जे० सी० घोष ने 1896 मे वाप्रेस व अधिवेशन मे एकत्रित प्रतिनिधियों को एक घटना बताई जहा बड़ी सख्या म औरता और मरदा पर मामूहिक रूप से थोड बरसाए गए चीफ कमिश्नर की 1887 की श्रमिको के प्रसम म उत्प्रवास संबंधी रिपोर्ट को उद्धत करत हुए उत्तान एक घटना का विवरण दिया कि किस प्रकार भनेजर क घर के बराडे के एक खभे के साथ भित्रियों को बाध दिया गया उनके कपडे कमर तक उठा लिए गए और उनके गंगे चूतडा पर चमडे क चाबुक से पिटाई को गई (रिप० आई० एन० सी 1896 प० 167)
- 176 रिपोर्ट आन आ दि नेटिव प्रेस बगल 1886 सोम प्रकाश 19 जुलाई (आर० एन० पी० बग० 24 जुलाई 1886) ए० बी० पी० 24 मई और 19 जुलाई 1888 मराठा 12 फरवरी 27 मई 1888 ट्रिभून 23 मई (बी० ओ० आई० जुलाई 1888) इडियन एसोसिएशन का नामन पूर्वोक्त स्थल जे० सी० घोष रिप० आई० एन० सी० 1896 प० 167 दत्त ई एच II प० 352, कसरे हिंद, 8 माच (आर० एन० पी० बब 14 माच 1903)
- 177 इडियन एसोसिएशन 1888 का नामन पूर्वोक्त स्थल, ट्रिभून 23 मई (बी जा० आई० जलाई 1888), बगाली 4 फरवरी 1893 जे० सी० घोष रिप० आई० एन० सी० 1896 प० 167 जी० एस० अय्यर ई ए, प० 185 तुलनीय कजन स्पीचेज I प० 243 मसम मे स्वतंत्र श्रमिको की अपेक्षा अनुबधित श्रमिका की म्यू दूर भयकर रूप से ऊची थी
- 178 इडियन एसोसिएशन द्वारा 1893 म राज्य सचिव की प्रपित याचिका रिपोर्ट आफ दि इडियन एसोसिएशन फार 1892 3 टु 1895-6 प० 82 बगाली 21 जनवरी 1893 जे० सी० घोष रिप० आई० एन० सी० 1896 प० 167 सी० वाई० चितामणि इडिया ऐंड लाड कजन पूर्वोक्त स्थल प० 243 जी० एस० अय्यर ई ए, प० 180 5
- 179 जे० सी० घोष रिप० आई० एन० सी० 1896 प० 167 तथा बी० सी० पाल वही प० 168 बगाली 4 फरवरी 1893 हितवादी 23 माच (आर० एन० पी० बग० 31 माच 1900) इडियन एसोसिएशन ने 10 माच 1893 के नामन मे उलेख किया कि यन्त्र कुलिया का अस्वास्थ्य के लिए हानिकर बागा म काम करना पडता है जयवा यदि उह अपने धरो स बहुत दूर आना पडता है तो उह अपेक्षित त्याग के अनुरूप ही उपयुक्त वेतन मिलना चाहिए (रिपोर्ट आफ दि इडियन एसोसिएशन 1892 3 टु 1895-6 प० 22)
- 180 जे० सी० घोष रिप० आई० एन० सी० 1896 प० 167 हिनवादी 23 माच (आर० एन० पी० बग० 31 माच 1900) जी० एस० अय्यर ई ए प० 182.
- 181 कसरी 10 माच (आर० एन० पी० बब 14 माच 1903) और देखिए जे० सी० घोष रिप० आई० एन० सी० 1896 प० 165 जी० एस० अय्यर ई ए प० 181
- 182 सोम प्रकाश 19 जुलाई आनंद बाजार पत्रिका 19 जुलाई (आर० एन० पी० बग० 24 जुलाई 1886) ए बी० पी० 19 मई 1886 सजीवनी 20 अगस्त (आर० एन० पी० बग 27 अगस्त 1887) प्रतिवार 26 मई (वही 2 जून 1888) परिदशक 11 जून (वही 23 जून 1888) ए० बी० पी० 24 मई 1888 मराठा 27 मई 1888 हिंदू 30 मई 1888 1888 का इडियन एसोसिएशन का नामन पूर्वोक्त स्थल बी० सी० पाल रिप० आई० एन० सी० 1888 प० 159 बगाली 4 जून 1892 रिपोर्ट आफ दि इडियन एसोसिएशन 1892 3 टु 1895-6

को वि देश के किसी भी वानून में इससे अधिक बर व्यवस्था मिलना सम्भव नहीं (बहो, प० 169)

166 1897 1898 1899 1900 और 1901 के प्रस्ताव क्रम IV XX, XIV X तथा XIII  
167 वागल पूर्वोद्धत प० 105-07

168 खंड II प० 352 522 तथा दक्षिण इंग्लैंड इंडिया, प० 131

169 बंगाली 12 मई 1888, बंगाल के समाचारपत्रों के लिए देखिए, आर० एन० पी० वग० 26 मई, 2 9 16 और 23 जून 1888 वायस आफ इंडिया जुलाई 1888 (खंड VI स० 7) इंडियन स्पेक्टेटोर 3 जून (वही) आफतावे हिंद 15 जून (आर० एन० पी० पी० 23 जून 1888) इपीनियल पपर 23 जून (वही 7 जुलाई 1888)

170 विशेष रूप से देखिए उनके 1886 का प्रक जब प्रम ने कुला अधिनियम का विरुद्ध एक सपना अभियान छेद दिया था सजीवनी के अवतुवर नवंबर और निसंबर में प्रकाशित प्रका में इन विषय पर सुदर और प्रामाणिक लेखमाला उपलब्ध है

171 ए० बी० पी० 19 अगस्त 1886, सजीवनी 20 अगस्त (आर० एन० पी० वग०, 27 अगस्त 1887) 1888 का मेमोरियल आफ दि इंडियन एमोसिएशन वागल पूर्वोद्धत परिशिष्ट ई पीछे 169 पार्सिटिप्पणी में उल्लिखित समाचारपत्र प० वग० पी० 24 मई 1888 हिंदू 40 मई 1888 ददु प्रकाश 11 जून 1888 नटिव ओपीनियन 3 जून 1888 ए० एम० भीमजी रिप० आई० एन० सी० 1888 पृ० 160 रहबर 14 फरवरी (आर० एन० पी० एन० 18 फरवरी 1892) 1893 में इंडियन एमोसिएशन द्वारा राज्य सचिव को प्रस्तुत विरोधपत्र 1892 3 स 1895 6 तक के वर्षों की रिपोर्ट आफ दि इंडियन एमोसिएशन पृ० 82 जे० सी० थोप रिप० आई० एन० सी० 1896 पृ० 165 6 दत्त इंग्लैंड एंड इंडिया प० 131 और ई० एल० II प० 352 उदाहरणार्थ जे० सी० थोप ने 1896 में कांग्रेस के प्रतिनिधियों को बताया मैं नवीन आत्मी और औरता को मौन से भी बन्तर भाग्य से बचने के लिए जहाज से ब्रह्मपुत्र के पानी में छलांग लगाते दया है उसी कांग्रेस के सामने आर० के० सरकार न विवरण दे रहा अनजान और अभावधान जनता पर एक फौज की खुली छोड़ दी गई है और मैं विस्वास दिला सकता हूँ कि देश के दूरस्थ भूत प्रदेशों में इनके अतीत के पवारियों को भी बन्कर है रिप० आई० एन० सी० 1896 प० 165 और 170 क्रम

भाग में उत्प्रवासियों की धरती पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार लिया गया था दडनाय कानून न्यूनाधिक रूप से अपरिवर्तित ही रहा देखिए अधिनियम का अध्याय IX

- 198 दास हिस्टरी आफ इंडियन लैजिस्लेशन प० 23 और चमनलाल पूर्वोद्धृत खंड II, प० 67 चालू दुब्यवहारा के प्रति श्रमिकों के असंतोष की अभिव्यक्ति 1903 में बड़े पमाने पर असम के चाय बागाना में हुए उपद्रवों के रूप में हुई देखिए दास प्लाटेशन लेबर इन इंडिया प० 34
- 199 कजन स्पीचेज II प० 245
- 200 हिंदू 3 नवंबर 1899 ए० बी० पी० 26 28 फरवरी 1901 बंसरी 19 मार्च (आर० एन० पी० बव 23 मार्च 1901), हितवादा 15 मार्च (आर० एन० पी० बग० 23 मार्च 1901) बंगाली 19 मार्च 1901
- 201 सजीवनी 2 नव० (आर० एन० पी० बग० 11 नवंबर 1899) बगवासी 11 नव० (वही 18 नवंबर 1899) आर० एन० पी० बग० 9 मार्च 1901 में उल्लिखित बंगाल के समाचारपत्र सजीवनी 28 फरवरी हितवादी 1 मार्च इंडियन मिरर 1 2 मार्च 1901 (वही 9 मार्च 1901) बंगाली, 17, 22 24 फरवरी 1901 ए० बी० पी० 26 28 फरवरी 1901 हिंदू 13 मार्च 1901 मद्रास स्टड्ड 10 मार्च (आर० एन० पी० एम० 16 मार्च 1901), एडवोकेट, 1 मार्च (आर० एन० पी० एन०, 2 मार्च 1901) श्रीराम एल० सी० पी० 1901 खंड XL प० 86 पी० आनंद चारलु वही प० 131 2 जब क० बकिधम न परिपद म प्रथम तीन वर्षों में पुष्पा और स्त्रियों के बतन क्रमश 5 और 4 रुपये तथा चतुर्थ वर्ष म त्रमश 6 और 5 रुपये निर्धारित करने का सशोधन पेश किया तो परिपद के सभी भारतीय सदस्यों ने उसके विरुद्ध मतदान किया (वही प० 146)
- 202 एल० सी० पी० 1901 खंड XL प० 147
- 203 कजन स्पीचेज II, प० 236
- 204 वहां प० 246-7 तथा देखिए प० 234-5
- 205 एल० सी० पी० 1901 खंड XL प० 150
- 206 बंगाली 10 मार्च और 19 मार्च 1901 हिंदू 13 मार्च 1901, ए० बी० पी० 11 मार्च 1901 बंगाल के समाचारपत्रों के लिए देखिए आर० एन० पी० बग० 16 23 30 मार्च 1901 मद्रास स्टड्ड 10 मार्च और स्वदेशमित्र 11 मार्च (आर० एन० पी० एम० 16 मार्च 1901), इंदु प्रकाश 28 मार्च (आर० एन० पी० बव 30 मार्च 1901) नवघ टाइम्स 7 मार्च (आर० एन० पी० एन० 9 मार्च 1901) दत्त ई एच I प० XIV और ई एच II प० 522 आइ० एन सी० 1901 का प्रस्ताव XIII पी० आनंद चारलु श्रीराम तथा विविन कृष्ण बोम न सर हेनरी काटन के स्वर के साथ स्वर मित्राया और बकिधम के सशोधन क विरुद्ध मत लिया एल० सी० पी० 1901 खंड XL प० 158
- 207 मराठा 17 मार्च 1901 तथा इंडियन मिरर 10 मार्च प्रतिवासी 11 मार्च (आर० एन० पी० बग० 16 मार्च 1901) बगवासी 16 मार्च वसुमती 21 मार्च (वही 23 मार्च 1901) प्रभाती 20 मार्च (वही 30 मार्च 1901) दत्त ई एच I प० 14-15 ई एच II प० 352 और 522 दत्त ने एक अन्य उदाहरण देकर सरकार के भद्रूरा क प्रति और बंगाल मालिका के प्रति 'यवहार में अंतर दिखाया कि जब 1903 में बंगालमालिका ने उस निर्धारित चाय पर कर लगाने की मांग की जिसकी आय का उपयोग भारत में चाय की खपत पर होना था तब भारत

## 342 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास

- प० 227, जे० सी० घाय रिप० आई० एन० सी० 1896 प० 167 बेसरो, 19 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 23 मार्च 1901) कसरे हिंदू 8 मार्च (बहा 14 मार्च 1903), दत्त ई एच II प० 352
- 183 बी० सी० पाल मेमोरीज, खंड II प० 54
- 184 बंगाली, 11 मार्च 1893, ए० बी० पी०, 28 फरवरी 1901 दत्त ई एच II प० 351 2
- 185 सजीवनी 19 नवंबर (आर० एन० पी० बंग०, 26 नव० 1887) तथा ए० बी० पी०, 19 जूनार्द 1888
- 186 20 अगस्त (आर० एन० पी० बंग० 27 अगस्त 1887)
- 187 मई 1888 का इंडियन एसोसिएशन का नापन, पूर्वोक्त स्थल, बागल पूर्वोक्त प० 105-0० बी० सी० पाल रिप० आई० एन० सी० 1888, प० 158 162 ए० बी० पी० 19 अगस्त 1886 बंगाली 12 मई 1888 मराठा 27 मई 1888, हिंदू 30 मई 1888, नेटिव ओपियोनिपन 3 जून 1888 इंदु प्रकाश 11 जून 1888, वायस आफ इंडिया जुलाई 1888 (खंड VI स०7) डिप्लूट 23 मई और इंडियन स्पेक्टेटर 3 जून (बही) बागल क समाचारपत्रा के लिए दाल्प, आर० एन० पी० बंग० 26 मई 2 9 23 जून 1888 इंडियन एसोसिएशन का 1893 का स्थापन रिपोर्ट आफ दि इंडियन एसोसिएशन 1892 3 टु 1895 6 प० 83-8
- 188 सजीवनी 29 नवंबर (आर० एन० पी० बंग० 29 नव० 1884) मराठा 27 मई 1888, ए० बी० पी० 24 मई 1888
- 189 इंडियन एसोसिएशन का 1893 म दिया गया नापन पूर्वोक्त स्थल प० 23-7, बंगाली 11 मार्च 1893
- 190 हिंदू 30 मई 1888, बंगाली 5 दिसंबर 1891 इंडियन एसोसिएशन द्वारा 1893 म प्रस्तुत नापन रिपोर्ट आफ दि इंडियन एसोसिएशन 1892 3 टु 1895 6 प० 21 इंडियन एसोसिएशन द्वारा 1896 म प्रस्तुत नापन बही प० 92 बंगाली 6 जून और 15 अगस्त 1896 मई० एन० सी०, 1896 1897 1898 1899 1900 और 1901 के प्रस्ताव सख्या XV IV XA XIV X और XIII प्रकाश हिंदू 3 8 नव० 1899 यू इंडिया 26 अगस्त 1901 सी० वाइ० चिंतामणि इन्डिया एंड साइ बजत एच० आर० अगस्त 1901 प० 244 जे० सी० घोष रिप० आई० एन० सी० 1901 प० 166 दत्त ई एच II प० 352
- 191 दत्त ई एच II प० 352 तथा 1893 का इंडियन एसोसिएशन का नापन पूर्वोक्त स्थल प० 22 बंगनी 15 अगस्त 1896 हितवादी 23 मार्च (आर० एन० पी० बंग० 31 मार्च 1900) ए० बी० पी० 26 फरवरी 1901 हिंदू 13 मार्च 1901
- 192 सजीवनी 28 अगस्त (आर० एन० पी० बंग० 4 नितंबर 1886), भारत मिहिर 2 नितंबर (बही 11 नितंबर 1886), सी० वाई० चिंतामणि इंडिया एंड साइ बजत एच० आर० अगस्त 1901 प० 244 दत्त ई एच I प० XII ई एच II प० 352 522.
- 193 आर० एन० पी० बंग० 21 अगस्त 1886
- 194 28 अगस्त (बही 4 नितंबर 1886) तथा भारत मिहिर 2 नितंबर (बही 11 नितंबर 1886)
- 195 3 नितंबर (बही 10 नितंबर 1887)
- 196 सेविका दास प्लांटेशन सेक्टर इन इंडिया (कसबाता 1931) प० 34 94 5
- 197 अगस्त 1901 एन० सी०—1901 (1901 का एक्ट न० VI) अध्याय I VII निरूपण म धारा 3 सेविका त्रिगम स्थानीय सरकारों का किमी भी अथम त्रिगम म अथवा सेविका किमी

भाग में उत्प्रवासियों की धरती पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार दिया गया था दंडनीय वानून न्यूनाधिक रूप से अपरिवर्तित ही रहा देखिए अधिनियम का अध्याय IX

- 198 दास हिस्टरी आफ इंडियन लेबर लजिस्लेशन प० 23 और चमनलाल पूर्वोद्धत खंड II, प० 67 चालू दुब्यवहारा के प्रति श्रमिकों के असंतोष की अभिव्यक्ति 1903 में बड़े पमाने पर असम के चाय बागानों में हुए उपद्रवों के रूप में हुई देखिए दास प्लाटेशन लेबर इन इंडिया प० 34
- 199 कजन स्पीचेज II, प० 245
- 200 हिंदू 3 नवंबर 1899 ए० बी० पी०, 26 28 फरवरी 1901 नैसरी 19 माच (आर० एन० पी० बव 23 माच 1901) हितवादी 15 माच (आर० एन० पी० बग०, 23 माच 1901) बंगाली 19 माच 1901
- 201 सजीवना, 2 नव० (आर० एन० पी० बग० 11 नवंबर 1899) बगवासी 11 नव० (वही 18 नवंबर 1899), आर० एन० पी० बग० 9 माच 1901 में उल्लिखित बंगाल के समाचारपत्र सजीवनी 28 फरवरी हितवादी 1 माच इंडियन मिरर 1 2 माच 1901 (वही 9 माच 1901) बंगाली 17 22 24 फरवरी 1901 ए० बी० पी० 26 28 फरवरी 1901, हिंदू 13 माच 1901 मद्रास स्टड्ड 10 माच (आर० एन० पी० एम० 16 माच 1901), एडवोकेट 1 माच (आर० एन० पी० एन० 2 माच 1901) श्रीराम एत० सी० पी० 1901 खंड XL प० 86 पी० आनंद चारनू वही प० 131 2 जब क० बकिषम ने परिषद में प्रथम तीन वर्षों में पुरुषों और स्त्रियों के वेतन क्रमशः 5 और 4 रुपये तथा चतुर्थ वर्ष में क्रमशः 6 और 5 रुपये निर्धारित करने का सशोधन पेश किया तो परिषद के सभी भारतीय सदस्यों ने उमक विरुद्ध मतदान किया (वही प० 146)
- 202 एन० सी० पी० 1901 खंड XL प० 147
- 203 कजन स्पीचेज II प० 236
- 204 वहां प० 246-7 तथा देखिए प० 234-5
- 205 ग्ल० सा० पी० 1901 खंड XL प० 150
- 206 बंगाली 10 माच और 19 माच 1901 हिंदू 13 माच 1901, ए० बी० पी० 11 माच 1901 बंगाल के समाचारपत्रों के लिए देखिए आर० एन० पी० बग० 16 23 30 माच 1901 मद्रास स्टड्ड 10 माच और स्वदेशमित्र 11 माच (आर० एन० पी० एम० 16 माच 1901) इंदु प्रकाश 28 माच (आर० एन० पी० बव 30 माच 1901), अवध टाइम्स 7 माच (आर० एन० पी० एन० 9 माच 1901) दत्त ई एच I प० XIV और ई एच II प० 522 आई० एन० सी० 1901 का प्रस्ताव XIII पी० आनंद चारनू श्रीराम तथा विपिन कृष्ण दास ने सर हेनरी काटन के स्वर के साथ स्वर मिलाया और बकिषम के सशोधन के विरुद्ध मत दिया एन० सी० पी० 1901 खंड XL प० 158
- 207 मराठा 17 माच 1901 तथा इंडियन मिरर 10 माच प्रतिवासी 11 माच (आर० एन० पी० बग० 16 माच 1901) बगवासी 16 माच वसुमती 21 माच (वही 23 माच 1901) प्रभाती 20 माच (वही 30 माच 1901) दत्त ई एच I प० 14-15 ई एच II प० 352 और 522 दत्त ने एक अन्य उदाहरण देकर सरकार के मजदूरों के प्रति और बंगाल मालिकों के प्रति व्यवहार में अंतर दिखाया कि जब 1903 में बंगालमालिकों ने उस निर्धारित चाय पर कर लगाने की मांग की जिसकी आय का उपयोग भारत में चाय की खपत पर होना था तब भारत

## 344 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदभव और विकास

- सरकार ने अपने सम्मान को ताब पर रखकर इस मांग को स्वीकार कर लिया और सिद्ध कर दिया कि वह चाय वागानमालिका की चाय बेचने वाला एजेंट ही है (ई एच II पं० 522 3)
- 208 ए० वी० पी० 11 मार्च 1901 बंगाल के समाचारपत्रों के लिए देखिए आर० एन० पी० बंग० 16 23 30 मार्च 1901 केसरी, 19 मार्च (आर० एन० पी० बंग० 23 मार्च 1901) ज० सी० घोष रिप० आई० एन० सी० 1901 पं० 165
- 209 बंगाली 15 फरवरी 1903 हिंदू 28 फरवरी 2 3, मार्च 1903 इंडियन पीपुल 13 मार्च 1903 मुनाइटिड इंडिया 3 मार्च (वी० थो० आई० 21 मार्च 1903) इंडियन रिव्यू फरवरी 1903 आर० एन० पी० एम० 7 फरवरी 7 14 मार्च 1903 और आर० एन० पी० बंग० 14 मार्च 1903 में उल्लिखित मद्रास और बंबई के लगभग सभी महत्वपूर्ण समाचारपत्र जी० एस० अय्यर ई ए पं० 183 मद्रास विधान परिषद में मद्रास वागान श्रम बिल का अधिकांश भारतीय सदस्यों द्वारा तीव्र विरोध किया गया था देखिए प्रोसीडिंग्स आफ मद्रास लेजिस्लेटिव कांसिल 1902 खंड XXX पं० 21 1 6 और 1903 के लिए खंड XXXI पं० 93-7
- 210 बंगाली, 15 फरवरी 1903 हिंदू 3 मार्च 1903 इंडियन पीपुल 13 मार्च 1903 मुनाइटिड इंडिया 3 मार्च (वी० थो० आई० 21 मार्च 1903) स्वदेशमित्र, 5 फरवरी (आर० एन० पी० एम० 7 फरवरी 1903) कसरे हिंदू 8 मार्च (आर० एन० पी० बंग० 14 मार्च 1903)
- 211 सुधारक 9 मार्च (आर० एन० पी० बंग० 14 मार्च 1903) इनके बदले जी० एस० अय्यर ने अनुभव किया कि सरकार ने सावजनिक संगठन के रूप में एवमात्र वाणिज्य सदन और निजी व्यक्तियों के रूप में इस सदन के शीघ्र स्वयं प्रतिनिधियों से ही परामर्श किया था (ई ए पं० 184)
- 212 केसरी 10 मार्च सुधारक 9 मार्च (आर० एन० पी० बंग० 14 मार्च 1903) जी० एन० अय्यर ई ए पं० 183 5
- 213 जी० एम० अय्यर ई ए पं० 185
- 214 आर० एन० पी० बंग० 14 मार्च 1903
- 215 वही
- 216 जी० एम० अय्यर ई ए, पं० 180 और अवर सेक्टर प्रान्त में एच० आर०, अगस्त 1901 पं० 117 8
- 217 दत्त ई एच I पं० XIV XV पं० 352 522
- 218 14 मार्च (आर० एन० पी० बंग० 23 मार्च 1901)
- 219 रिप० आई० एन० सी० 1901 पं० 168
- 220 एन० सी० पी० 1901 खंड XL पं० 131 और 153
- 221 आई० एम० सी० 1901 का प्रस्ताव XIII और आई० एन० सी० 1900 का प्रस्ताव XXIV
- 222 25 मई (आर० एन० पी० एम० 30 मई 1903)
- 223 मराठा 7 21 मई 1899
- 224 मराठा 14 मई 1899 सुधारक 15 मई (आर० एन० पी० बंग० 20 मई 1899)
- 225 जहाँ तक हमारी जानकारी है भारत में श्रम आन्दोलन के इतिहास में अय्यर ने इस तथ्य का पूरा उपयोग का है यह आश्चर्य का विषय है कि वे इस हड़ताल में भाग नहीं लेते हमने पूर्ववर्ती इसी रेलवे के एंग्लो इंडियन गादों की हड़ताल का वर्णन किया जा चुका है परन्तु उस हड़ताल में भारतीय श्रमिकों का योगदान तो माना ही नहीं जा सकता क्योंकि 1899 में पूरा बंबई और कलकत्ता की चिननी ही श्रमिकों में हड़तालें हुए वे तात्कालिक तथा घमण्डित श्रमिक

स अधिक अधसगठित थी

- 26 केसरी 16 मई (आर० एन० पी० बब 20 मई 1899)
- 27 14 मई 1899 के कसरे हिन्दू ने यह स्पष्ट देखा था उसने यह निष्कर्ष किया कि यदि यह सफल हुआ तो यह श्रमिकों के लिए अनिष्टकारी उदाहरण सिद्ध होगा (आर० एन० पी० बब 20 मई 1899)
- 28 कसर हिंदू अपवाद था शीघ्रस्थ समझना में है, मराठा केसरी इंडियन स्पेक्टटर इंदु प्रकाश सुधारक नटिव ओपीनियन ज्ञान प्रकाश, सुबाध पत्रिका और मोद वत
- 29 मराठा 7 14 21 28 मई 4 जून 16 जुलाई 1899 बर्बई क समाचारपत्रों के लिए देखिए आर० एन० पी० बब 13, 20 मई 1899 ए० बी० पी०, 24 मई 1899 हितवादी 26 मई (आर० एन० पी० बब० 3 जून 1899) हिंदू 8 मई 1899 वत्तत पत्रिका 17 मई (आर० एन० पी० एम० 31 मई 1899) हिंदुस्तानी 17 मई (आर० एन० पी० एन० 31 मई 1899) जाम उल उलुम 7 जून अल्मोडा अखबार 10 जून हिंदुस्तानी 7 जून (वही 14 जून 1899) शहाना ए हिंदू 24 जून और 1 जुलाई (वही 5 जून 1899) अमृत बाजार पत्रिका न तो समस्या का सामाजिककरण तक कर दिया ये हड़तालें कुचले हुए लोगों के जीने का अधिकार मानने के प्रयत्न हैं जब वही जहा वही हड़ताल होती है समझ लीजिए कि वहा शिनायतों की इतनी अधिक प्रबलता और व्यापकता है कि उसने हड़तालियों को अपने अन्यायों के विरोध में खड़ा होने के लिए विवश कर लिया है (24 मई 1899)
- 30 केसरी 16 30 मई (आर० एन० पी० बब 27 मई 3 जून 1899) नेटिव ओपीनियन 25 मई (वही 27 मई 1899), ए० बी० पी० 2 जून 1899 हिंदुस्तानी 17 31 मई (आर० एन० पी० एन० 31 मई 7 जून 1899) मराठा 28 मई 1899
- 31 आर० एन० पी० एन० 14 जून 1899
- 32 केसरी 23 मई नेटिव ओपीनियन 25 मई (आर० एन० पी० बब०, 27 मई 1899) कसरी 30 मई (वही 3 जून 1899)
- 33 मराठा 7 14 21 मार 1899 नेटिव ओपीनियन 11 मई श्री सयाजी विजय 6 मई ज्ञान प्रकाश 11 मई (आर० एन० पी० बब० 13 मई 1899), इंदु प्रकाश 18 मई सुधारक 15 मई नेटिव ओपीनियन 18 मई, केसरी 16 मई गुजराती 14 मई (वही 20 मई 1899) नटिव ओपीनियन 25 मई (वही 27 मई 1899) पसा अखबार 17 जून (आर० एन० पी० पी० 1 जुलाई 1899) हिंदुस्तानी 17 मई (आर० एन० पी० एन० 31 मई 1899)
- 34 मराठा 21 मई 1899 केसरी, 16 मई (आर० एन० पी० बब 20 मई 1899)
- 35 मराठा 14 मई 1899 इंदु प्रकाश 18 मई इंडियन स्पेक्टटर 14 मई सुबाध पत्रिका 14 मई नेटिव ओपीनियन 18 मई गुजराती, 14 मई (आर० एन० पी० बब० 20 मई 1899) 14 मई 1899 के इंडियन स्पेक्टटर ने सारे मामले को मत्तीपूर्ण ढंग से इस प्रकार प्रस्तुत किया अर्थात् हो या बुरा हम अब इस देश में बड़ी बड़ी समस्याओं के रूप में श्रमिकों को सगठित करना है हम इस छोटे नहीं सबत श्रमिकों को सगठित करके यह मिट्ट बनना है कि उनमें रित्तनी शक्ति है हम और पूँजी के बीच शत्रुता की भावना के विकास को रोकना का उपाय यह है कि श्रमिकों और पूँजीपतियों को समय समय पर उठने वाले विवादों को निपटान के लिए साबनाप्र यात्राएँ बनाना चाहिए (वही)
- 36 मराठा, 7 मई 1899 सुधारक 15 मई केसरी 16 मई इंदु प्रकाश 18 मई जाम जमद



2. भारत में जायिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास

पाश्चात्य राष्ट्रवाद में जायिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास का अर्थ है कि उच्च प्रोद्योगिकी के उच्च जीवन को महल दे

2.1 दली पत्र 200 200

2.1 दली पत्र 200 200

2.1 दली पत्र 200 200

## कृषि I

जमीदारों के हितों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ कांग्रेस का आंदोलन (सरकार को विवश करने की नीति लिए हुए), खेतिहरों पर ही अधिकांशतया खर्च किए जाने वाले जमीदारों पर लगे करों की उनसे वसूली के परित्याग का पक्षधर है।

जे० डी० रीम

भारत की आत्मा रूप किसानों के ऊपर मड़राते हुए जड़ता और उदासीनता के बादलों को हटाने पर ही देश का उद्धार किया जा सकता है। हमें अवश्यमेव उन बादलों को हटाना होगा और उसके लिए हमें अपने आपको किसानों के साथ जोड़ना होगा और यह अनुभव करना होगा कि किसान हमारा हैं और हम किसानों के हैं।

बाल गंगाधर तिलक

कदाचित्त भूमि सबंधी समस्या 19वीं शताब्दी के समाप्ति काल में भारत के लिए मिरन्द बनने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या थी। खेतीबाड़ी भारतीयों का प्रमुख आर्थिक आधार थी। लगभग 80 प्रतिशत लोग अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर थे। 19वीं शताब्दी की अवधि में ब्रिटिश सर्वोच्चता के प्राथमिक प्रभाव के अतिसरत देश के निरंतर ग्रामीकरण ने भारतीयों की कृषि पर परंपरागत निर्भरता को, और अधिक बढ़ा दिया था। फलतः आर० सी० दत्त के शब्दों में स्थिति यह हो गई थी कि खेतीबाड़ी के फलने फूलने का अर्थ था भारतीयों की खुशहाली और फसलों के विगड़ जान का अर्थ था देश में अकाल की स्थिति।<sup>1</sup>

इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अत्यंत पिछड़ी हुई थी और यहाँ के खेतिहर बहुत गरीब थे। भारत में उस समय तक ज्ञात अकालों में सर्वाधिक भयंकर 1876-7 के भयंकर अकाल तथा 1896-1901 तक देश को अपनी जकड़ में रखने वाले भीषण अकालों में यह तथ्य नाटकीय ढंग से उजागर कर दिया। खेतिहरों की निराशापूर्ण स्थिति का एक जय मकेत 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पनपता असतोष था जिसकी अभिव्यक्ति बंगाल में 1873 के पद्मना दंगा में, 1875 में दक्षिण के खेतिहरों के दंगा में, बंबई में 1878-9 के फडके के विद्रोह में तथा 1894 में असम कृषि दंगों में देखने को मिली। भयंकर



यागदान 23 99 करोड था।<sup>7</sup> जसाकि ये अक् सूचित करते है इन वर्षों मे भूराजस्व की वसूली मे ऋमिक वद्धि हो रही थी।<sup>8</sup> इसके लिए सरकारी विश्लेषण यह था कि यह वद्धि 'मुख्य रूप से कृषि भूमि के विस्तार तथा मूल्यों मे वद्धि का परिणाम थी।'<sup>9</sup>

राष्ट्रवादी नेताओ ने भारतीय कृषि सबधी समस्त समस्याओ मे कर् निधारण पद्धति तथा भूराजस्व की मात्रा को सर्वाधिक महत्व दिया। उन्हाने भारत सरकार की भूराजस्व नीति का किमाना के दुर्भाग्य और दरिद्रता का तथा कृषि के पिछडेपन का मुख्य कारण घोषित किया। ममीक्षा मीन अवधि के प्रारंभ मे राष्ट्रवादियो द्वारा सरकारी नीति पर दोषारोपण की शुरुआत भारतीय कृषि समस्याओ पर 'जरनल आफ दि पूना सावनांक सभा' मे प्रकाशित जस्टिस रानाडे की लेखमाला न हुआ।<sup>10</sup> इस प्रकार 1879 मे एग्रेरियन प्रावनम ऐंड इटम सोल्यूशन' शीषक अपने लेख मे जस्टिस रानाडे न एक बटु सत्य का उल्लेख किया 'बर्ई राजस्व विभाग की कायवाहियो न देश को कगाल बना गिया ह'।<sup>11</sup> 1881 मे प्रकाशित अपने लेख 'लड ला रिफाम ऐंड ऐग्रीकल्चरल बक्स मे उद्दोन अपना मत अभिव्यक्त किया कि जब तक वर्तमान कर् निधारण पद्धति के अतगत भूराजस्व के दबाव को कम नहीं किया जाता, तब तक कृषि मे किमी भी प्रकार का सुधार सबधी प्रयत्न स्थाई लाभप्रद परिणाम उत्पन नहीं कर सकता। उन्हाने आराप लगात हुए कहा कि हमारी भौतिक समृद्धि के विकास के माग मे भूमि पर एकाधिकार तथा अपनी ही मरजी से भूमि के कर्ो मे वद्धि का अधिकार दानो मुख्य बाधाए है।'<sup>1</sup>

सरकार की भूराजस्व नीति के विरुद्ध अर्ध कई भारतीय नेताओ न भी यथासमय विचार प्रकट किए। 1891 मे नागपुर मे हुए अधिवेशन मे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न इस प्रसंग की चर्चा करते हुए निणयात्मक स्वर मे घोषणा की कि भूराजस्व प्रशासन की अविवेकपूर्ण पद्धति देश मे दरिद्रता और भुखमरी की व्यापकता के कई कारणो मे स एक था। इस सुधार के चलते दश की 90 प्रतिशत जनसख्या की जाजीविका का साधन कृषि का सुधार न केवल असभव हो गया है प्रत्युत उस कृषि का ऋमिक ह्रास भी निश्चित हो गया है।<sup>12</sup> 1888 से 1903 तक की अवधि मे एक भी वर्ष ऐसा नहीं बीता जबकि भूराजस्व प्रशासन के किसी न किसी पक्ष पर कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित न किया हो। बीसवीं शताब्दी के गुरु होते ही और दश के विनाशकारी अकालो के पजे मे फसत ही आर० सी० दत्त न राष्ट्रवातियो की भूमिकर सबधी आलोचना को एक तीव्र आंदोलन का रूप द गिया। अपनी लेखमाला और भाषणो के जो वाद मे आपन 'नेटम टु लाड वजन नामस छप, तथा भूमि राजस्व की ही व्यापक विवचना करने वाले, इकानामिक ट्रिस्टरी आफ इटिया ग्रंथ के (नो गडो मे) प्रकाशन के माध्यम से दत्त ने वार वार भूराजस्व प्रणाली पर कृषि को पनु बनान का भारतीयो को दरिद्र बनान का तथा अकाला के परिमाण और प्रभाव को गहरा करने का अभियाग लगाया।<sup>13</sup> दत्त को अपन इस धमयुद्ध मे जी० वी० जोगा मे मूल्बचान समर्थन मिला। जागी ने 1900 01 मे 'टाइम्स आफ इटिया मे ज नाम मे प्रकाशित पत्रमाला मे बर्ई के भूराजस्व प्रशासन पर चाट की।<sup>14</sup> गुजरात मे भूमिकर निधारण की प्रभावी निंदा करने वान गोकुलदास के० पारीख न भी दत्त को समर्थन गिया।<sup>15</sup> बटून सारे अर्ध लोक नेताओ तथा समाचारपत्रा न भूराजस्व प्रशासन को ही कृषि के ह्रास का

विनाशकारी अकानो तथा कृषक असतोप ने सरकार तथा भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं का ध्यान भारतीय किसानों की समस्याओं और निधनता की ओर खींचा।

भारतीय नेताओं के कृषि संबंधी विभिन्न पक्षों के प्रति दृष्टिकोण का, सरकार की कृषि संबंधी नीतियों का तथा खेतिहरों की दरिद्रता के कारणों का विवेचन निम्नलिखित पांच शोधकों के अंतर्गत किया गया है। 1 भूराजस्व अथवा कृषक और राज्य 2 कृषक और भूमिपति 3 कृषक और माहूवार 4 पूजावादी खेतीवादी 5 कृषि और उद्योग।

### भूराजस्व अथवा कृषक और राज्य

अनेकानेक ऐतिहासिक तत्वों के परिणामस्वरूप 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में भूमि की पट्टेदारी और भूराजस्व प्रणालियाँ का मिला जुला रूप विकसित हुआ। यहाँ मध्य में भी इन दोनों पद्धतियों की समीक्षा करना मभव नहीं अतः हमें यहाँ केवल अप्रतिभार संश्लेषण से ही असतोप करना पड़ेगा। निम्नदेह इनसे स्थिति का पूरा ज्ञान तो नही हो सकता, हाँ, उचित अनुमान अवश्य हो जाएगा। वंगाल में और उत्तरी मद्रास में जमींदारों ने स्थाई बंदोबस्त पद्धति के अंतर्गत धरती अपने कब्जे में कर रखी थी। इस पद्धति के अनुसार वे सरकार को स्थाई तौर पर निर्धारित राजस्व का भुगतान करते थे। उत्तरी भारत में जमींदारों अथवा ग्राम समुदायों ने धरती पर कब्जा कर रखा था और वे भूमि कर चुकाते थे। यह कर समय समय पर राजस्व के गए समझौतों के अनुसार बदला जाता था। बंबई और मद्रास में प्रचलित रयतवादी पद्धति के अंतर्गत धरती पर किसानों की जागीरों का ही कब्जा था जो सीधे राज्य सरकार का कर चुकाते थे। प्रत्येक पृथक ज्ञान पर पृथक पृथक तौर पर राजस्व कूता जाता था और प्रत्येक नए समझौते में इसे नियमित रूप में बदला जाता था।<sup>1</sup> ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में समय और स्थान के अनुसार राजस्व की मात्रा निर्धारण का सिद्धांत बदलता रहता था परंतु 19वीं शताब्दी के मध्य तक स्थाई बंदोबस्त में न आए देश के सभी भागों में 'यूनाधिक' रूप में, कम से कम निर्धारित रूप में ही, एकरूपता का आधार अपनाया गया। इसका सामान्य आधार अथवा सिद्धांत यह था कि जमींदारों और ग्राम समुदायों के कब्जा की जोना पर वास्तविक अथवा अनुमानित प्रतिपादित विराए का आधा भाग तथा रयतवादी में आधिक विराए का अथवा निवल (नेट) संपत्ति से प्राप्त अथवा निवल उत्पादन पूजा का आधा भाग<sup>2</sup> सरकार द्वारा भूराजस्व के रूप में वसूल किया जाएगा।<sup>3</sup> व्यवहार में इस सिद्धांत पर बटारना में अमल नहीं किया गया, चानू राजस्व का कूता जाना जारी रहने, धरती की उत्पादनता का तथा मीन जागीरों की सामान्य आर्थिक स्थिति और भूमि के अन्य मूल्य आदि अन्य तत्वों पर भी समुचित ध्यान दिया जाता रहा।<sup>4</sup> चानू करों में वृद्धि का आधार विगुड रूप में केवल उपज की ओर यह एक अनिश्चित ढंग था। इस वृद्धि के पीछे अन्य अन्य विचारणीय विषय भी जुड़े रहते थे।<sup>5</sup>

समीक्षाधीन अवधि में भूराजस्व संश्लेषण का अर्थ का मवाधिक संश्लेषण माघन था। 18<sup>01</sup> 2 में सरकार की कुल निश्चित राजस्व 46 86 कराह में म भूराजस्व की वसूली 19 67 कराह थी। 19 11-02 में सरकार की कुल वसूली 60 79 करोड़ में भूराजस्व का

यागदान 23 99 करोड था।<sup>7</sup> जैसाकि ये अक सूचित करत है, इन वर्षों में भूराजस्व की वसूली में क्रमिक वृद्धि हो रही थी।<sup>8</sup> इसके लिए सरकारी विश्लेषण यह था कि यह वृद्धि 'मुख्य रूप से कृषि भूमि के विस्तार तथा मूल्यों में वृद्धि का परिणाम' थी।<sup>9</sup>

राष्ट्रवादी नेताओं ने भारतीय कृषि संबंधी समस्याओं में कर निर्धारण पद्धति तथा भूराजस्व की मात्रा को सर्वाधिक महत्व दिया। उन्होंने भारत सरकार की भूराजस्व नीति को किसानों के दुर्भाग्य और दरिद्रता का तथा कृषि के पिछड़ेपन का मुख्य कारण धारित किया। ममीक्षाधीन अवधि के प्रारंभ में राष्ट्रवादियों द्वारा सरकारी नीति पर दोषारोपण की शुरुआत भारतीय कृषि समस्याओं पर 'जरतन आफ दि पूना सावर्जनिक सभा' में प्रकाशित जस्टिस रानाडे की लेखमाला से हुआ।<sup>10</sup> इस प्रकार 1879 में एंग्लो-इंडियन प्रॉब्लम ऐंड इट्स सोल्यूशन' शीपक अपने लेख में जस्टिस रानाडे ने एक बहुत सत्य का उल्लेख किया 'बंबई राजस्व विभाग की कायवाहिया न देश को कगल बना दिया है।'<sup>11</sup> 1881 में प्रकाशित अपने लेख 'लड ला रिफॉर्म ऐंड एग्रीकल्चरल बक्स' में उन्होंने अपना मत अभिव्यक्त किया कि जब तक वर्तमान कर निर्धारण पद्धति के अंतर्गत भूराजस्व के दबाव को कम नहीं किया जाता, तब तक कृषि में किसी भी प्रकार का सुधार संबंधी प्रयत्न स्थाई लाभप्रद परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकता। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी भौतिक समृद्धि के विकास के मांग में भूमि पर एकाधिकार तथा अपनी ही मरजी से भूमि के करो में वृद्धि का अधिकार दोनों मुख्य बाधाएँ हैं।<sup>12</sup>

सरकार की भूराजस्व नीति के विरुद्ध अग्र्य कई भारतीय नेताओं ने भी यथामय विचार प्रकट किए। 1891 में नागपुर में हुए अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस प्रसंग की चर्चा करते हुए निष्पात्तमक स्वर में घोषणा की कि भूराजस्व प्रशासन की अविवक्षणीय पद्धति देश में दरिद्रता और भुखमरी की व्यापकता के कई कारणों में से एक था। इस सुधार के चलते देश की 90 प्रतिशत जनसंख्या की आजीविका का साधन कृषि का सुधार न केवल अमभव हो गया है प्रत्युत उम कृषि का त्रमिक ह्रास भी निश्चित हो गया है।<sup>13</sup> 1888 से 1903 तक की अवधि में एक भी वष ऐमा नहीं घीता जबकि भूराजस्व प्रशासन के किसी न किसी पक्ष पर कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित न किया हो। बीसवीं शताब्दी के गुरुहोत ही और देश के विनाशकारी अकालों के पजे में फसत ही आर० सी० दत्त ने राष्ट्रवादिता की भूमिकर सबंधी आलोचना को एक तीव्र आंदोलन का रूप द दिया। अपनी लेखमाला और भाषणों के जो बाद में आपन नेटस टु लाड वजन, नाम से छप, तथा भूमि राजस्व की ही 'यापक विवेचना करने वाले, 'इकानामिक हिस्टरी आफ इंडिया', ग्रंथ के (दो खंडों में) प्रकाशन के माध्यम से दत्त ने बार बार भूराजस्व प्रणाली पर कृषि का पगु बनाने का, भारतीयों को दरिद्र बनाने का तथा अकालों के परिमाण और प्रभाव का गहरा करने का अभियोग लगाया।<sup>14</sup> दत्त को अपने इस धमयुद्ध में जी० बी० जोशी से मूल्यवान समर्थन मिला। जोशी ने 1900-01 में 'टाइम्स आफ इंडिया' में जो नाम में प्रकाशित पत्रमाला में बंबई के भूराजस्व प्रशासन पर चोट की।<sup>15</sup> गुजरात में भूमिकर निर्धारण की प्रभावी निंदा करने वाले गोकुलदास के० पारीख ने भी दत्त को समर्थन दिया।<sup>16</sup> बहुत सारे अग्र्य लोक नेताओं तथा समाचारपत्रों ने भूराजस्व प्रशासन को ही कृषि के ह्रास का

तथा कृषकों की दरिद्रता का मूल कारण ठहराया।<sup>17</sup> इस मन्वथ मे यहा यह उल्लेखनाय है कि यह आलोचना अधिकाशतया बर्बई, मद्रास और केंद्रीय प्राता की भूमिकर निगारण पद्धति तक ही सीमित थी। स्थाई बंदोबस्तवाले बगाल मे यह पद्धति स्पष्टतया गिनायत का कारण नही बन सकती थी। प्रमुपतया 'सहारनपुर कानूना' के लागू हान के बारा उत्तर पश्चिमी प्राता, जबध तथा पजाब म कर की मात्रा कुल मिलाकर सतोपप्रद समझा जाती थी।<sup>18</sup>

वस्तुतः भूराजस्व नीति उन विषयो मे से एक थी जिस पर राष्ट्रीय नेताओ का सारा का सारा बग और मानी की सारी विचारधारा सुदृढतापूर्वक सुगठित थी। भूराजस्व मन्वधी सरकारी नीति की राष्ट्रवादियो द्वारा समीक्षा का व्यापक ज्ञान आर० सी० दत्त के लेखा मे होता है। अतः हम इस अव्ययन म इसके कुछ पक्षा की परीक्षा करेंगे। इस मन्वथ म दश मे व्यापक परिमाण म हुई समीक्षा के विवरण को न देकर, हम यहा केवल राष्ट्रवादिया द्वाग की गई समीक्षा की संक्षिप्त रूपरेखा ही प्रस्तुत करेंगे।

### बुराइया

भारतीय नेताओ के अनुसार भारतीय भूराजस्व पद्धति का प्रथम बडा भारी दोष यह था कि कर निधारण अत्यंत कठोरतापूर्वक ऊंची दर पर था और इस हाने बाने प्रत्येक बंदो बस्त म खेतिहर के भुगतान की उच्चतम सामथ्य सीमा तक निरंतर ऊंचे तौर पर बगया जाना था। इस प्रकार यह राजस्व वास्तव म बहुत अधिक लगान के रूप म बदल जाता था तथा खेतिहर बग को निघन बनाना एक कुचल दता था।<sup>19</sup> बहुता का यह दावा था कि दश के प्रहुत भागा म भूराजस्व की वास्तविक माग आधे निबल किराए अथवा निबल उपज की अपक्षा बहुत ऊंची है। सरकार ने इसे अपनी माग की अंतिम सीमा के रूप म स्वीकार किया है और यह प्रायः सकल (ग्राम) उपज के बीस प्रतिशत से अधि बठता है।<sup>20</sup> बर्बई और मद्रास म अभी कभी कर निधारण की मात्रा इतनी ऊंची होती कि मार का मान आर्थिक तिराया इसी मे निपट जाता था।<sup>21</sup> इसके अतिरिक्त घटिया जमीना, केवल गुजारेवाली तथा अलाभप्रद जाता के सयध म सरकारी माग खेतिहर का बतन और उसकी पूजी के लाभ का ही हडप लेती थी। जस्टिस रानाडे न 1879 मे इस स्थिति का विरोधण इस प्रकार किया

सरार भूमिबान मभी खेता म जुनाई के दाम तथा किमान ब बतन इस सीमा तक पहुंच जात हैं कि सारी फमल म उनकी पूति ही मुश्किल मे हो पाती है। उम एमा धरती म बाई लाभ नही भिनना है। वह अपन मेन मे श्रम करन ब बदन बबन राटी नमा पाना है। अतः इस प्रकार ब खेता गर बाई आर्थिक तिराया नहीं हा सक्ता। सिमान बचारा जा भी नगात चुकाता है बट या ता ऋण लेकर चुकाता है अथवा किमी अय माधन म प्राप्त आय स चुकाता है। भूमि म प्राप्त आय म यह मन्व ही नही।"

इस भारी नगात का कभी कभी परिणाम यह निकलता है कि उम गल म स्थित नित्री गणत का समय द्वाग बरनपूर्वक अधिग्रहण कर लिया जाता है और बचारा किमान

वास्तव में राज्य का खेत जोतने वाला दास बन कर रह जाता है।<sup>3</sup>

राष्ट्रवादी नेताओं ने अपने मभी लेखों और भाषणों में आकडामहित प्रमाण उद्धृत किए। कई एक भारतीय नेताओं ने इस ओर भी निर्देश किया कि भुगतान न कर पाने वाले खेतिहरों पर लगान का भुगतान करने के लिए अनुचित और भारी दबाव डालना, धरती के लगान की उगाही के लिए बड़ी संख्या में उनके जातों का बिक जाना जोतों की मजदूरी में मस्ते दामों पर योजना व रेहन रचना आदि मामलों में धरती के लगान की ऊँची दर के ही मूल्य प्रमाण हैं।<sup>4</sup> इनके अतिरिक्त दंगल, मुखमरी और मौत की बढ़ती संख्या भी इसी तथ्य की पुष्टि करती है।<sup>5</sup> राष्ट्रवादियों ने सारे देश में धरती के निरंतर बढ़ते दामों तथा विरायों में निरंतर हा रही बढ़ती की लगान के निम्नस्तरीय होने का प्रमाण और परिणाम मानने में मवधा इकार कर दिया। इसके विपरीत उनका तर्क यह था कि यह तो दंग की बढ़ती जनसंख्या के उद्योगों में खपत न पाने से बंधारे खेतिहरों में धरती का पाने के लिए बढ़ती हुई प्रतियोगिता का तथा देश के बदन हुए ग्रामीकरण का ही दुष्प्रभाव था।<sup>6</sup> उन्होंने यह भी निर्देश किया कि 'पूजीनिवेश के निवायों की कमी से भी इस वृद्धि को समझने में सहायता ली जा सकती है।' वस्तुतः बंदोबस्त अधिकारियों के विरुद्ध निजी सुधारों पर करने लगान की सरकारी प्रतिभूति खेतिहरों द्वारा किए गए सुधारों को व्यवहार में करमुक्त नहीं करती। यह प्रायः या तो परोक्ष रूप से धरती के पुनर्वर्गीकरण के वेग में लिया जाता है अथवा सरकार द्वारा किए गए सुधारों से हुए सुधारों के बंधारे किसानों को बहनाया जाता है अथवा निजी सुधारों के फलस्वरूप तथा अशत प्राकृतिक अथवा अय कारणों से हुई आय को 'अनुपाजित आय' घोषित करके लिया जाता है।<sup>7</sup>

राष्ट्रवादी नेताओं के अनुसार धरती की लगान पद्धति का एक दूसरा महत्वपूर्ण दोष यह था कि 'आर्थिक' सहायता के फलस्वरूप सरकार की धरती से माग अनिश्चित और अपन प्रभाव में उतार चढ़ाववाली थी। इसके साथ ही बढ़ती की कोई निश्चित अथवा विनिश्चित नियम नहीं थे। यह लगान अनात, अस्पष्ट, अनिश्चित, भ्रामक और अवास्तविक, अस्थिर और अपर्याप्त आधारों पर बढ़ाया जा सकता था और बढ़ाया जाता था। किसान बेचारा इन आधारों को न तो समझता था और न ही समझ सकता था। राजस्व अधिकारियों का दोबारा बंदोबस्त के समय अपनी स्वच्छाचारी शक्ति का सोत्साह दुष्प्रयोग करने का अवसर मिल जाता था। मजदूरों का यह भी कि उन अधिकारियों पर किसी प्रकार का 'आर्थिक' अथवा विभागीय प्रतिबंध नहीं था।<sup>8</sup>

तृतीय भारतीय नेताओं ने भूराजस्व पद्धति की बंधोरता की भी निंदा की। उन्होंने घोषित किया कि धरती का लगान सरती के साथ, दृढ़तापूर्वक तथा कसकर वसूला जाता था। इसके उगाहने का दंग और समय असुविधाजनक, दुखदायक तथा भारतीय दृष्टि की परिस्थितियों के प्रतिकूल था।<sup>9</sup> उनका कथन था कि सरकार फसलों के बिगड़ जाने और अकालों की आर कोई ध्यान ही नहीं देती। इस प्रकार के प्राकृतिक संकट के समय में जब बेचारा किसान आर्थिक दृष्टि से भारी कष्ट भोग रहा होता है, उस समय भी उसे अपने हिस्से का सरकारी लगान चुकाने को कहा जाता है।<sup>10</sup>

कुछ भारतीयों ने विभिन्न प्रदेशों और वर्गों में भूमि लगान के साथ ५५



प्रश्न पर भी विचार किया और अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि विभिन्न प्रांतों में इन बांधों का रूप भिन्न भिन्न था। बंगाल का योगदान अपने हिस्से की तुलना में बड़ा कम था।<sup>12</sup> इसके अतिरिक्त समाज के अर्थ वर्गों की अपेक्षा किसानों को काफी अधिक भार उठाना पड़ता था।<sup>13</sup> कई नेताओं ने तो स्पष्ट अनुभव किया कि ब्रिटिश भारत में प्रचलित भूमि लगान पद्धति में जो भी दोष वर्तमान हैं, उनका कारण भारत सरकार द्वारा रिकार्डियन सिद्धांत में विश्वास और उसका अनुसरण करने में है और इसके माध्यम से धारणा काम कर रही थी कि भारत में राज्य ही वास्तविक रूप से भूमिपति अथवा स्वामी था। फलतः सरकारी भूराजस्व नीति के पीछे विद्यमान मान्यता पर प्रहार का अभियान चलाया। इस प्रहार का विवेचन 'इंडियन पार्लियामेंट इकोनमी' अध्याय में भी किया गया है। भारतीय नेताओं के अनुसार भूराजस्व पद्धति के कृषि पर पड़ने वाले घातक और क्षतिकारक प्रभाव निम्नलिखित थे

प्रथम, ऊँचे परिमाण में भूमि लगान किसानों की सभाविता बचत का एक बहुत बड़ा भाग हड़प कर ग्रामों का धनस्थ बना देता है, भूमि को धन निष्ठा से बर्चित कर देता है और सामान्य रूप से कृषि सबंधी सुधारों पर होने वाला खर्च रोक देता है।<sup>14</sup> द्वितीय, भारी लगान देहातों में साधनहीनता बढाकर जवालों की व्यापकता और विस्तार बढा देता है। किसान अच्छे वर्षों में बुरी फसलवाले वर्षों के लिए कुछ नहीं बचा पाता फलतः वह आमानी से अकाल और मृत्यु का शिकार बन जाता है। यह उनकी बचत शक्ति का अभाव ही था जो मूँचे को अकाल का रूप दे देती थी।<sup>15</sup> आजीविका वाली जोता पर तो भारी और उच्च लगान सामान्य वर्षों में भी भुलमरी की स्थिति ला देता है।<sup>16</sup> तृतीय लगानों में निरंतर मसाधन, अल्पकालीन बढोबस्त, लगान वृद्धि के अनिश्चित आधार प्रत्यक्ष व्ययों के भूभाग का न्याय मृत्याकन और उसके फलस्वरूप जोतने वाले के सुधार पर नग्न लगान लगाना आदि, ये सब किराया का आधार अनिश्चित बना देते हैं। अनिश्चित किराया के साथ जुड़े ऊँचे लगान, किसान के सारे बचत के तदय को, तथा उसकी घरना के स्वाई सुधार की तथा कृषि सबंधी उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति को ही नष्ट कर देते हैं। किराया की अमरुदक्षितता तथा लगानों में ऊँची बढोतरी किसानों को असमर्थता में डाल देते हैं कि यह कठोर श्रम कर कि आराम का जीवन बिताए, क्योंकि उसे तो यह भी विश्वास नहीं होता कि वह अपने कठोर श्रम का फल भी पाएगा कि नहीं। भूराजस्व पद्धति के साथ जुड़ी हुई यही अनुविधानिक स्थिति थी जिसने भारतीय किसानों को आलसी, फिजूलखर्च बना दिया था। देहातों में उद्यम और उरमाह की भावना का अभाव के लिए यही उत्तरदायी है। इसका परिणाम यह निकला है कि कृषि में गतिहीनता तथा ह्रास आ गया है और भारतीय ग्रामों में निधनता का साम्राज्य स्थापित हो गया है।<sup>17</sup> भारतीय नेताओं ने इस धारणा का बड़ी तीव्रता तथा उग्रता के साथ सहा किया कि भारतीय किसानों का शक्तिहीन, अक्षम तथा अदूरदर्शी स्वभाव और चरित्र ही उसकी आर्थिक बहिष्कारों के लिए उत्तरदायी था उसकी यथावधि चरित्रानुबिणेतताएँ तो काफी हद तक वस्तुतः भूराजस्व पद्धति का ही परिणाम थी अथवा भारतीय श्रमिकों की स्वभाव से ही मिली थी परिश्रमी तथा दूरदर्शी हैं।<sup>18</sup>

परिमाण और उसके साथ जुड़ी अनिश्चितता भूमि पर निजी पूँजी के निवेश को बाधित ही नहीं प्रत्युत असंभव बना देती है और इस प्रकार भूमि सुधारों को और पूँजीनिष्ठ कृषि के विकास को नकार देती है।<sup>39</sup> पंचम, सरकारी लगानों में वृद्धि बड़े बड़े जमींदारों और बड़ी बड़ी जोतों के मालिकों को किराया बढ़ाने का बहाना जुटा देती है और वे वास्तविक में भी बहुत अधिक किराया बढ़ा देते हैं जिसके फलस्वरूप वास्तविक जमीन जोतने वाला पर भारी बोझ पड़ता है।<sup>40</sup> आर० सी० दत्त ने बताया कि जहाँ जोतों पर लगान किराए के एक भाग के रूप में होता था वहाँ लगान कमचारी उन जमींदारों पर, जो सामान्यतया किराया बढ़ाने के प्रति उदार हो सकते थे, किराया बढ़ाने के लिए जोर देते थे ताकि सरकार अधिक लगान लगा सके।<sup>41</sup> छोटे कृषि उत्पादकों में ऊँचे परिमाण में किसी प्रकार की बढ़ोतरी न होने पर, लगान की ऊँची दर और उसके साथ सबद्ध भूमि लगान पद्धति की कठोरता तथा उग्रता धरती को बचाने के लिए इच्छुक और लगान की मांग की पूर्ति में असमर्थ वेचारे परेशान किसानों को निदयतापूर्वक साहूकार के झूठे पत्रों में डाल देती है, जहाँ एक बार फसा वह गरीब कभी मुक्त नहीं हो पाता।<sup>4</sup> भूमि के लगानों के संग्रह की कठोरता और अमुविधा से भी किसानों को अपनी उपज बचाने के लिए विवश होना पड़ता था और बाजार में एकदम उपज का तूफान सा आ जाता था जिससे टिंटा के विरुद्ध मूल्यों में नकली गिरावट आ जाती थी जो उन वेचारे किसानों के लिए हानिकारक थी।<sup>4</sup>

कुछ भारतीय नेताओं ने भूमि लगान की समस्या को उन की निकासी के साथ भी जोड़ा और कहा कि ऊँचे लगानों के दोष उस स्थिति में और भी तीव्र हो जाते हैं जब इन लगानों की राशि का भूमि को उपजाऊ बनाने में उपयोग न करके उसके बहुत बड़े भाग की दश से बाहर निकासी की जाती है।<sup>44</sup>

### उपचार

राष्ट्रवादियों द्वारा का गई भूराजस्व प्रशासन की आलाचना के उपयुक्त सक्षिप्त विश्लेषण में यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय नेताओं का विश्वास था कि कृषि सबधी सभी समस्याओं और दोषों की आधारभूत भूराजस्व पद्धति में उपयुक्त सुधार किए बिना किन्हीं भी समस्या का समाधान असंभव है। उनके इस दृष्टिकोण को जस्टिस रानाडे के शब्दों में निम्नलिखित रूप में सक्षिप्त रूप में रखा जा सकता है

उनकी (छेतिहरा की) एक ही मांग है कि उन्हें, सामाजिक स्तर पर अपने का बेहतर बनाने के निरर्थक सघष में उनकी शक्तियों को नष्ट करने वाले, उनकी योग्यताओं को अपगु करने वाले, अत्यंत कष्टदायक तथा असह्य भार रूप, लगानों के बर्दास्तों में मुक्त किया जाए। इस भारी दबाव को थोड़ा हलवा कीजिए, गतिविधि तथा लचीली शक्ति को भीतर से ही उमड़ने दीजिए, उनकी स्वतः ही भौतिक संपन्नता की ओर गति होगी और इससे उनके सार पुराने घाव भर जाएंगे।<sup>45</sup>

परंतु अब प्रश्न यह था कि इस भारी भार को हलवा बनाया किस प्रकार जाए? राष्ट्रवादियों का उत्तर यह था कि भारतीय भूराजस्व पद्धति के अनिवाद्य दायपूर्ण तत्व य थे कि एक ओर वास्तविकी असुरक्षित थी, दूसरी ओर लगानों की खाई बड़ी गहरी थी और

तीसरी ओर लगान वृद्धि अनिश्चित आधार लिए हुए थी। उपचार में केंद्रीय उपाय ही मरत थे कि वास्तविकी की सुरक्षित बनाया जाए ताकि भूमि जोतने वाले अपन का स्वतंत्र मालिक समझे ही नहीं, प्रत्युत यथाथ में वास्तविक और स्वतंत्र रूप में मानिक बन भी जाए। जैसा कि जस्टिस रानाडे ने बार बार बल दिया, भारत में तो सर्पित क जादू की ही आवश्यकता थी।<sup>46</sup> 1890 में इस विषय पर लिखत हुए जी० वी० जोगान इम दृष्टिकोण को स्पष्ट शब्दा में अभिव्यक्ति दी

स्वत्वाधिकार एक ऐसी प्रभावी और मानव का गतिशील बनाने वाली शक्ति है जिसे बिना भर में सुधारों को स्वतंत्र प्रेरणा और गति मिलती है। तयारपित बालमियो, परोपकारिया और मसार को मिथ्या मानने वाले वदातिया क इस देश में भी स्वत्वाधिकार का प्रभाव स्वतंत्र माय है। वस्तुतः मानव प्रकृति का और मानव श्रम का नियम भारत, फ्रांस अथवा नावें कही भी, बदला नहीं जा सकता। किसी भी व्यक्ति को आप एक काली चट्टान का ही सुरक्षित स्वामित्व द दीजिए वह उम पय रीली धरती को लहलहाते वाग में बदल देगा, जिमान की वतमान उपेक्षावति को बरलो का इनके अतिरिक्त अय कई समय साधन हमें दिखाई नहीं देता कि उमकी रक्ति उपायन करने के लिए उसकी जोत का उम सुरक्षित अधिकार दिया जाए तथा उम अपने श्रम का फल पाने का पूरा आश्वासन दिया जाए।<sup>47</sup>

भारतीय नताजा द्वारा सुभाए गए उपचारमूलक साधना का आर० सी० दत्त ने 1900 में लाड कवन का लिये अपने पाचवें और अंतिम आपन लेटर टु कजन में बड़ी सफाई क साथ सक्षिप्त रूप दिया।<sup>48</sup> उन्होंने लाड कजन के भूमि प्रस्ताव के द्वितीय प्रत्युत्तर सत्र रिप्लाई टु नाड कज स 'नड रिजाल्यूशन' में इसे तत्व रूप में इस प्रकार में प्रस्तुत किया एवं कृषिप्रधान देश की संपन्नता और प्रमन्नता व्यापक रूप से भूमि लगान पर कुछ स्पष्ट, निश्चित समझ आत वाली तथा ध्यावन्तारिक मामा लगान पर ही निर्भर करती है।<sup>49</sup> सवाधिन मट्टवपूण साधना का विवेचन निम्नलिखित रूप में है

भूमि लगान का भार इस स्तर तक कम किया जाना चाहिए जिससे किसान के पास आजीविका के लिए समुचित बचत रह जाए खराब मौसमों के लिए व्यवस्था सभ्य हो सके, तथा पजी के निवारा द्वारा भूमिसुधार किया जा सके। दोबारा बढोबस्त करत समय भी लगान वृद्धि पर इस प्रकार में एक मोमा निर्धारित करनी चाहिए जिससे किसान इन विन्याय के साथ स्वच्छापूवक सुधार कर सके कि उसे उमके श्रम और त्याग का फल जवय्य मिागा।<sup>50</sup> कुछ भारतीय नताजा का यह भी कर्न था कि भारत की अपनी स्थितिया में भूमि लगान का निर्धारण का उचित मानक आधार यह होगा कि निरन उपाय का जयना विराए में आय का, अथवा आर्थिक विराए का आधा भाग उगाहना श्या। समझ तब यह हमी कि दमना हिमात्र मही मही और दमान्तारी में किया जाए। इन आधार पर लगाया गया लगान होगा तो कष्टनायक और अमुविधात्राक ही परतु भारतमाय स्थिति में ही उचित माना जा सकता है।<sup>51</sup> भारत सरकार की भूमि लगान नीति के विरुद्ध युद्ध की तीव्रता में आर० सी० दत्त ने कृत्र 'उपायान' क 1/5 भाग क अधिन तम तब लगान मोमा निर्धारित करने का अनिश्चित मांग प्रस्तुत की।<sup>52</sup> मजेतर बाप द



पर उत्तेजित तिलक ने बालू 'अकाल सहायता बोर्ड' के अंतर्गत अपने अधिकार मांगने के लिए लोगों को सुशिक्षित और संगठित करने का बीड़ा उठाया। 'केमरी' पुस्तिकाओं, जन-सभाओं प्रचार और तब तो अभी अभी अपने नियंत्रण में आई 'पूना सावजनिक सभा' के अभिकरणों के माध्यम से तिलक दक्षिण के किसानों का यह समझाने में जुट गए कि अकाल की श्रवण में उनके दबाव और सहायता के लिए कानूनी व्यवस्था थी, सरकार उनके जीवन की रक्षा के लिए नैतिक रूप में बाध्य थी। सरकारी अधिकारी अकाल महिता के अंतर्गत उनकी सहायता के लिए बाध्य रहे थे। उस सहिता का पालन करने के लिए किसान भाई सरकारी अधिकारियों पर दृढ़तापूर्वक और उच्च स्वर से दबाव डालें, करा के भुगतान करने की स्थिति में न हों पर भुगतान करने से इनकार करने पर किसान भाई केवल कानूनी दृष्टि से बिल्कुल गाय पर हानि प्रत्युत वस्तुतः वे कानून पालन कराने में सहायक भी सिद्ध होंगे।<sup>64</sup> यह लगान मनाही आंदोलन के एक प्रारंभिक रूप में अलग कुछ न था।<sup>65</sup> तिलक के सरकार विरोधी न होने के दृढ़ कथना के बावजूद सरकार ने स्थिति को भली प्रकार समझ लिया था और उसी पूना सावजनिक सभा के अभिवर्तिका के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की सभा के विरुद्ध और अंत में स्वयं लावमान्य के विरुद्ध कठोर पा उठाया।<sup>66</sup> तिलक पर 1897 में राजद्रोह का अभियोग लगाकर उन्हें गिरफ्तार किए जाने और उन्हें 18 महीने कारावास का दंड दिए जाने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 1896 की शीत ऋतु में दक्षिण के किसानों में उसके आंदोलन की जातिवारी दक्षिण की दूरदर्शी ब्रिटिश अधिकारियों ने केवल भाग गए थे परंतु उसके प्रति सावधान भी हो गए थे। इसके मांग ही स्वयं तिलक ने भी अपने इस कार्य के गहरे राजनीतिक परिणाम निराले तथा उससे उपयुक्त सचक लिया। जब अथ राजनीतिक कार्यकताओं ने उनके नेतृत्व का अनुसरण किया और 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी अकालपीठिका की सहायता के लिए प्रभावी पण उठाने में पिछड़ गई तो लोकमान्य ने कांग्रेस की उसके निष्कर्षों के लिए भत्तना की तथा वेसरी के 12 जनवरी 1897 के अंक में लिखा

पिछले गारह वर्षों से हम गला फाड़फाड़कर इस इच्छा से चिन्ताते आ रहे हैं कि सरकार हमारी बात सुने परंतु अब तब सरकार के कान पर जो तक नहीं गयी जो हमारी आवाज नकारवान में तुम्ही की आवाज बनकर रह गई है। हमारे शासक हमारे बकबया पर विश्वास नहीं करते अथवा विश्वास न करने का दावा करते हैं। आइए, अब हम सुदृढ़ साविधानिक उपायों से सरकार को अपनी शिकायतें सुनने के लिए विवश कर दें। हम अशिक्षित ग्रामीणों को यथासंभव सर्वोत्तम राजनीतिक शिक्षा दें। उनके माय समता के स्तर पर व्यवहार करें। उन्हें उनके अधिकार बताएं तथा उन्हें सिखाएं कि साविधानिक तरीकों से वे अधिकार कैसे पाए जाते हैं। तभी, केवल तभी सरकार इस बात को समझेगी कि कांग्रेस के तिरस्कार का अर्थ भारत राष्ट्र का तिरस्कार है। तभी कांग्रेसी नेताओं के प्रयास सफल होंगे। इस महान अनुष्ठान के लिए योग्य और दृढ़ निश्चयवाले व्यक्तियों के एक विशाल दल की अपेक्षा है, जिनके लिए राजनीति अवकाश और मनोरंजन का साधन न होकर



प्रथा लाना चाहते थे। इस मायता को अंगीकार करते हुए उनमें से कितनों ने व्यक्ति अथवा अव्यक्त रूप से भारतीय नेताओं पर विरोधाधिकार संपन्न जमींदारों के प्रवक्ता होने तथा अधिभारहीन और कुचले हुए कृषकों के हितों की उपेक्षा ही नहीं प्रत्युत उनका विरोध करने का आराप लगाया। राजस्व के स्थाई वदोवस्त की निरंतर वकालत करने के कारण आर० सी० दत्त का नौ जमींदारों का पिटूटू होने की उपाधि दी गई। वस्तुतः आर० सी० दत्त तत्कालीन नताओं पर राजस्व के स्थाई वदोवस्त का मन्वय म लगाए गए आराप सब का निराधार थे। विषय के इस पक्ष का विस्तृत विवेचन अनुचित न होगा।

निस्संदेह इस भ्रम की जड़े बहुत पुरानी थी यद्यपि कि उस युग के भारतीय नेताओं के मन में भी यह भाति व्याप्त थी परन्तु परवर्ती कृषकों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्कालीन भारत सरकार की भूमि लगान नीति के सन्तुष 1902 में भारत सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव है। यह निश्चिन्त रूप से नहीं कहा जा सकता है कि कजन न प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करते समय जानबूझकर ऐसी विधि अपनाई जिससे वह सरकारी भूराजस्व नीति के ममीक्षकों के विरुद्ध भारतीयों के मन में भ्रम का बीज बोकर बहस में विजय प्राप्त कर सके। कुछ भी हो उसने पहले उस प्रसिद्ध प्रस्ताव में राजस्व के स्थाई वदोवस्त का वगाल के 1793 के स्थाई वदोवस्त के साथ जाड़ा और उसके पश्चात पराट्ट मुख हामर कहा कि भारत सरकार के वर्तमान विरोधियों, पूर्ववर्ती विचार परंपरा के प्रतिनिधियों ने इससे पहले ही सार भारतवर्ष में स्थाई वदोवस्त की वकालत की है।<sup>15</sup> उसने आगे चलकर यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि स्थाई वदोवस्त वगाल का अकाल में नहीं बचा सका है। यह विश्वास करने का भी कोई आधार नहीं कि वगाल का किमान भारत में अत्याय प्रथा के किसानों की अपेक्षा अधिक ममद है। स्थाई वदोवस्त होने के कारण जमींदार का किराएदार बना हुआ वगाल का किमान वास्तव में सुखी नहीं है अपितु विपरीत स्थिति यह है कि वह किराए में दबा पड़ा है वगाल है और दलित पीड़ित है। जमींदारी प्रथा के अभाव में उत्पन्न सहानुभूतिपूर्ण जनिकताओं द्वारा प्रदेश का प्रबंध मचालन, जमींदारों और किराएदारों के बीच विच्छिन्न सन्तुष और विचौतियों का बहुमुखी हम्नक्षेप जादि चुराया बढ़ती जा रही हैं। अतिम सत्य यह है कि यदि इन सबके बावजूद वगाल का किसान सुरक्षित और संपन्न है तो इसका कारण स्थाई वदोवस्त न हामर सरकार द्वारा उसकी रक्षा के लिए पारित काश्तकारी कानून हैं।<sup>16</sup> इस प्रकार कजन न डके की चोट पर कहा कि किसानों के हितों का ध्यान में रखते हुए सरकार किसी भी सम्य देश के लाभ आदेश के रूप में सहायक होने के अनुभव में दूय कृषि किराया पद्धति का प्रस्ताव का जानबूझकर समर्थन नहीं कर सकती।<sup>17</sup> वस, यही कथन का आधार बन गया। कजन न जानबूझकर अथवा अनजाने सरकार विरोधियों की स्थाई वदोवस्त की माग को बगाल में प्रचलित कृषि किराया पद्धति के साथ जोड़ दिया। उसने आनाचकों पर परोक्ष रूप से और बड़ी ही सफाई तथा चतुरता से जमींदार समर्थक होने का किला लगाने की भी चष्टा की। उसने जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों की स्थिति का सुधारण और सुरक्षित करने के सरकारी प्रयत्न में महवोग न देने के लिए उन नताओं पर ताने बस और उड़े आटे हाया लिया।<sup>8</sup>

इस सबध में कजन द्वारा प्रदर्शित मांग का परवर्ती अनेक लेखको न अनुसरण किया और समय बीतने के साथ भ्रमजाल और कसता गया। इसी नम में जे० डी० रीस न 1908 में लिखा कि जमींदारों के हिता के साथ घनिष्ठता से जुड़ा कांग्रेस का आदानन सरकार को उन करों की वमूली बद करने के लिए विवश करने पर तुला हुआ है जो सरकार बड़े बड़े जमींदारों से उगाहती है और बड़े पैमाने पर छोटे छोटे किसानों पर खच करती है।<sup>79</sup> भारत में कजन के प्रशासन के भाट जीवनीकार लोवेट फ्रेजर ने 1911 में अपने लेख में आर० सी० दत्त पर अभियोग लगात हुए लिखा कि वह प्रमुख रूप से समझ वग के हितों की ही देखभान कर रहे है। फ्रेजर ने राष्ट्रवादियों की गतिविधियों पर साफ तौर पर लिखा 'अखिल भारतीय राजनीतिन आंदोलन का एक विचित्र पहलू यह है कि अत्यंत दरिद्र वग का सरकार के सिवाय जय कोई प्रवक्ता और सरक्षक ही नहीं है।'<sup>80</sup> 1921 में प्रकाशित के० टी० शाह के सिक्स्टी इसस आफ इंडियन फाइनांस के निम्नलिखित अवतरण से फ्रेजर की राष्ट्रवादियों की स्थिति के प्रति गलत धारणा के अत्यंत भ्रष्ट रूप को देखा जा सकता है

यदि स्वर्गीय श्री आर० सी० दत्त के लेखों को इस सबध में गत शताब्दी के लोकमत का सूचक स्वीकार कर लिया जाए तो यह मानना पडेगा कि वगाल के स्थाई बनने बस्त को दूसरे प्राता में लागू करने का भारतीय लोगनेताओं की व्यापक स्वीकृति प्राप्त थी और इसका उद्देश्य अगरजी ढग के जमींदारों के हाथ में पूरे तौर पर जमीन का आधिपत्य सौपना था।<sup>81</sup>

अतीत में राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण के सबध में तीन अय प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्रियों, पी० जे० थामस, पी० एस० लोम्नाथन तथा वी० आर० मिश्र ने भी गलतफहमी पैदा की।<sup>82</sup> भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दो भारतीय इतिहासकारों, पनसी छाया घोष तथा वी० वी० मिश्र ने काफी हाल में और सभवत इसके लिए उनके पान कोई कारण न था इसी गलती को दुहराया है। डाक्टरेट की उपाधि के लिए लिखे अपने शान प्रबंध, 'दि डेवलपमेंट आफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1892-1909', में श्रीमती घोष न कांग्रेस की स्थाई वदोयन्त की मांग को वगाल टाइप के स्थाई वदोबस्त का विस्तार मान लिया है।<sup>83</sup> श्रीमती घोष ने तो यहा तक लिख डाला है कि 1899 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अविवेशन में अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए आर० सी० दत्त ने सरकार से भारत के दूसरे भागों में वगाल पद्धति का लागू करने की प्रायना की थी।<sup>84</sup> वी० वी० मिश्र अपने शान के ग्रथ 'दि इंडियन मिडल क्लासेज दयर ग्रोथ इन माडन टाइम्स' में लिखत है कि कांग्रेस न 1888 में सरकार पर दश के सभी भागों में वगाल के ढग के स्थाई वदोयन्त को जिसन काश्तकारों को बहुत दुख पहुंचाया था और इस प्रकार जो मंत्रणा जगुपयोगी था, यह हम पहले ही दिखा चुके है, लागू करने के लिए दवाव डाला था।<sup>85</sup> इस मुद्दे मायता की स्थापना पुस्तक के मिडल क्लास अपोजीशन टु टर्नेट राइटम' शीपक उप विभाग में की गई है। इसमें लेखक का तक है कि 1880 के वर्षों में लजिस्लटिव कॉमिशन के विस्तार के लिए सरकार की आनाकानी का एक कारण यह भय था कि उाका विस्तार और भारतीयकरण काश्तकारी में मुधार जंस प्रगतिवादी कानून का मांग में आढे आएगा।



भारत सरकार के मन में यह भय न केवल कौमिल के भारतीय सदस्यों की काइनकार विरोधी भूमिका से उत्पन्न हुआ प्रत्युत शिक्षित वर्गों के राजनीतिक संगठन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा उठाई गई मांगों की प्रवृत्ति से भी उत्पन्न हुआ।<sup>166</sup> हाल में एक अन्य लेखक परसिवल स्पीयर यह स्वीकार करते हुए भी कि पश्चिम तथा दक्षिण प्रदेशों के कांग्रेसी सदस्यों का जमींदारों से कोई विशेष मरोमर नहीं था दुःखानुभव कहते हैं कि बंगाली सदस्य सामान्यतया जमींदारों से संबंधित थे और उन्होंने सार भारत में स्थाई बलायुक्त लागू न करने से उत्पन्न अनेक बुराइयों के लिए सरकार को दायी ठहराया था।<sup>167</sup>

वास्तव में, समीक्षाधीन अवधि के प्रारंभ में उसकी समाप्ति तक भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के प्रबल बहुमत को जमीन पर स्थाई बदोवस्त की मरहारी मांग और बंगाल के स्थाई वदावस्त के बीच अंतर की स्पष्ट जानकारी थी। उन्होंने यथासंभव स्पष्ट तथा निव्याज भाषा में और बार बार इस तथ्य को उजागर किया कि स्थाई बदोवस्त की चर्चा का अर्थ देश के अग्र्य भागों में बंगाल पद्धति के दोहरान की मांग अथवा 1793 के जमींदारी लगान के विस्तार की मांग कदापि नहीं थी, इसका अभिप्राय केवल भूमि के लगान की मांग की निरंतरता को स्थिर करने की मांग थी। उन्हें यह ज्ञान था कि उन्हें गलत समझा जा सकता है और उनके मतव्य का गलत अर्थ निबाला जा सकता है अतः उन्होंने स्पष्ट रूप में यह कहने में कोई मन्कोच नहीं किया कि जमींदारी तथा रयतवादी पट्टे के सापेक्षिक गुण दोषों के संबंध में उनके निजी विचार कुछ भी क्या न हों परंतु स्थाई बदोवस्त की मांग करते समय उनका न पट्टेदारी प्रथा से कोई वास्ता था और न ही लगान वसूली में। उन्हें ता एवमान लगान की विविधता अथवा पट्टेदारी प्रथा के अंतर्गत करान के सिद्धांतों में ही प्रयोजन था।

स्थान की कमी के कारण यहां भारतीय नेताओं द्वारा इस संबंध में दिए गए सभी विश्लेषण सबका स्पष्ट तथा पूर्ण रूप से उद्धृत करना संभव नहीं अतः अध्ययनवाली की सारी जगहों में फँसे हुए कुछ उद्धरण नीचे पुनः उद्धृत किए जा रहे हैं। बंगाल के इस संबंध में सर्वाधिक उदनाम नेताओं के अवनरणा पर बल दिया गया है। 1879 में एक प्रमुख बंगाली नेता उल्लेखनीय है कि अपनी पीढ़ी के कदाचित्त सर्वप्रमुख नेता, लालमाहं चार ने लिखा

मैंने विचार में बंगाल में प्रचलित पद्धति के मशोधित रूप निरंतरतावाले वदायुक्त को सारे देश में व्यापक रूप देने में उद्वेग लेश के लिए अथ कोई वरदान नहीं हा सकता। हम तो चाहेंगे कि स्वयं कृपक वग अपने आप ही बदोवस्त की कायवादी करने कि यह नया प्रणाल के जमींदारों जैसे विरोधियों के द्वारा किया जाए। हम तो भारत में स्विटजरलंड तथा यूरोप महाद्वीप के अग्र भागों में प्रचलित पद्धति जसी ही कोई पद्धति चाहते हैं।<sup>168</sup>

1880 में जस्टिस रानाडे ने कहा 'भूमि द्वारा उत्पादित अनाज के अनुरूप निर्धारित स्थाई रयतवादी बदोवस्त इस कृषि समस्या का एकमात्र समाधान बन सकता है।<sup>169</sup> चार वर्षों के बाद उन्होंने यह अधिवृत्त घोषणा की

यहाँ हम यह कहना चाहेंगे कि समय समय पर इस पत्र में तथा अयाय पत्रों में प्रकाशित हमारे विचारों को प्रायः ग़रत ममभा गया है। हमने रैयतवाड़ी पट्टेदारों को नष्ट करने की मांग कभी नहीं की जयवा हमके साथ जमींदारी बदावस्त की व्यवस्था के लिए कभी नहीं सोचा रैयतवाड़ी प्रथा तो हम प्रात में चिरकाल में प्रचलित है और यह एतन्मात्र पद्धति है जो हमारे ग्रामीण समाज की लोकतंत्रीय व्यवस्था के सप्रथा अनुकूल है। हमने तो इस प्रात में किसानों की ज़ीतों पर लगान के स्थाई निर्धारण के लिए आंदोलन किया है।<sup>90</sup>

इस प्रकार ने स्थाई बंदोस्त की बरानत करते हुए 7 मार्च 1881 के अंक में दस्तावेज़ लिखा

भारत के इस प्रात के किसी भी जगह जमींदारी लागू करने की बकालत नहीं की और यदि इंदु प्राश न बगाल की कृषिसंप्रथी संपन्नता की जय जयवार की है तो इसका श्रेय बगाल में लगान के स्थाई निर्धारण का ही है परंतु इसका अर्थ यह बदापि नहीं कि हम जमींदारों द्वारा किसानों को अपदम्य करना चाहते हैं। हमारी न्यति को इस रूप में दखना इस सारे प्रदन को समझने में शाचनीय रूप से अपने अचानक का ही प्रदगन करना है।<sup>91</sup>

मराठा न 17 फरवरी 1884 के अंक में इस प्रदन पर जिस स्पष्टता और दो टूक निणयात्मकता के साथ प्रकाश डाला, वह सचमुच ही विरोध रूप से ध्यान देने योग्य तथा उल्लेखनीय है

यदि स्थाई बंदोस्त उचित है तो सरकार का कुछ त्याग अवश्य करना पड़ेगा। उसे विचौलिया अथवा जमींदारों पर निभरन रहकर किसानों के पास जाना होगा। सरकार उद्योग और शिल्प को प्रोत्साहन देने के बदले बंधारे किसानों को जमींदारों की दया पर ही निभर रहने को विवश कर रही है। बगाल की जमींदारी अयोग्यताओं की दृष्टि में खुदकास्त कृषि नहीं है। खुदकास्तवाली पद्धति ही स्थाई रैयतवाड़ी पद्धति होगी। यह वह पद्धति है जिसके लिए हम सघष करते रहें हैं।<sup>92</sup>

1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में स्थाई बंदोस्त के सबब में प्रस्तावित प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए शेख राजा हुसैन खां ने स्पष्ट उद्घोष किया कि वह सरकारी भाग की स्थिरता तथा निश्चितता चाहते हैं न कि आवश्यक रूप से बगाल में प्रचलित पद्धति जैसी किसी स्थाई बंदोस्त की पद्धति। उन्होंने बल देकर कहा कि सारे देश में जमीन की पट्टेदारी विविधता लिए हुए है, उसने अनुसार प्रत्येक स्थान पर स्थाई बंदोस्त का रूप भी भिन्न भिन्न होगा।<sup>93</sup> हिंदू ने भी 13 सितंबर 1889 के अंक में इस बात से इनकार किया कि राष्ट्रवाधियों की मांग जमींदारी पद्धति लागू करने की है। उसने दावा किया कि स्थाई बंदोस्त का कोई भी समझदार समभव इस पद्धति का पक्षधर कतई नहीं है। 2 जनवरी 1891 के अंक में तो हिंदू इस बार और भी अधिक स्पष्ट तथा सबल प्रवक्ता था

स्थाई बदावस्त की बकालत करने वाले आज के नेता जमींदारों के किसी बड़े जग

की मृष्टि नहीं करना चाहते। वे तो धरती की उपज में सरकार के भाग को उन लोगों द्वारा हड़प देना नहीं देखना चाहते जो न श्रम करते हैं और न बंट उठते हैं। व तो एए एसी पद्धति चाहते हैं जिसमें बगाल की पद्धति के दोषों का अभाव हो और इस प्रकार किसान को सभी लाभ प्राप्त हो।

अपने समय के बगाल के उच्चतम नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा संपादित 'गंगात्री' पत्र ने न केवल जोर देने वालों की मलाह से ही स्याई बंदोबस्त का समर्थन किया प्रत्युत उसने 1793 के उदाबस्त की निंदा भी की। उसने 28 जून 1890 को अपने एक में लिखा कि जमींदारी पट्टेदारी का परिणाम यह हुआ कि जमींदारों और अमली ऐतिहरा के बीच विचौलिया की एक लंबी शृंखला अस्तित्व में आ गई है। उसने घोषित किया

हम स्याई बंदोबस्त के सिद्धांत को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं, परंतु इस समय में हम यह कहना चाहते हैं कि देश के लिए यह परम सौभाग्य है कि यदि यह सीधा किसानों से लिया जाता। लाड बानवानिस द्वारा जमींदारों के परिश्रेय में इस विषय का देखना एक भारी और दुःखद गलती है। देश के किसी भाग में भी नए सिरे में इस समय 1793 के उदाबस्त के विचार की किसी भी योजना के विरुद्ध हम अवश्य अपना विरोध प्रकट करना चाहिए। धरती के बंदोबस्त का राज्य द्वारा अपनाया जाने वाला नहीं सिद्धांत यह होना चाहिए कि धरती को रखने वाले, जोतने वाले और सुधारने वाले श्रमिक को श्रम का फल पाने में किसी प्रकार की असुविधा, परेशानी तथा बर्चनी न हो और उस भूस्वामी के रूप में राज्य को केवल निश्चित और उचित किराए का ही भुगतान करना पड़े।<sup>94</sup>

1893 के अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में स्याई बंदोबस्त के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बाल गंगाधर तिलक ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह जमींदारों के लिए नहीं प्रत्युत किसानों के लिए ही बोल रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि इस प्रस्ताव में सरकारी लगान को अथवा बंदोबस्त के कूतन के विभी उपाय का कोई उल्लेख ही नहीं है। इसमें तो केवल भूमि लगान की मांग का नियमित और निश्चित कर को कहा गया है।<sup>95</sup> एक अन्य मराठी नेता पी० आर० नातु ने 1894 में कांग्रेस के अंगरेज अधिवेशन में इसी तथ्य को दोहराया तथा विदेशियों को यह भ्रात धारणा बनाने से बचने के लिए मावधान किया कि देश की बहुसंख्या स्याई बंदोबस्त के रूप में बगाल में प्रचलित पद्धति चाहती है।<sup>96</sup> 1901 में लिखी अपनी पुस्तिका, दि इंडियन फार्मिस में पी० सी० राय ने बगाल के जमींदारों की सभी प्रकार से भ्रमना करने के उपरांत मांग की कि अस्थायी स्याई बंदोबस्त भविष्य में सीधे राज्य और ऐतिहरा के बीच होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार के विचौलिया जमींदारों तात्कालिक दारों तथा मालगुजारे के बीच में नहीं लाना चाहिए। उन्होंने सरकार और जनता से अपील की कि वे दमन का ऐसा दुश्चक्र बंदोबस्त चलने दें जो बेचारे किसानों के लिए दबाव अथवा मृत्यु का फल बन जाए।<sup>97</sup> लाड बंजन द्वारा 1902 के प्रस्ताव में प्रस्तुत भारतीयों की मांग का गलत विवरण जो सुबह्याण्य अय्यर की आवा से छिप न सका। उन्होंने फरवरी 1892 में प्रकाशित अपने एक लघु लाड बंजन रिजाल्यूशन आन लड 'रैवेयू' में प्रखर स्वर में लिखा कि प्रस्ताव ने यह

अनुमान लगाने में गलती की है कि

भूराजस्व नीति के आलोचक स्थाई बंदोबस्त की मांग के रूप में जमींदारी पद्धति की भी मांग कर रहे हैं। श्री दत्त तथा दूसरा ने अपने को राज्य और किसान के बीच जमींदारा, त्रिचौलियों की सृष्टि की वकालत करने वाले समझे जाने के विरुद्ध बचाव की बार-बार चेष्टा की है। उनकी योजना थी स्थाई बंदोबस्त सीधे सरकार और किसान के बीच हो स्थाई बंदोबस्त के लिए जमींदार पद्धति कोई आवश्यक पक्ष नहीं और हमारा सुभाव है कि सीधा बंदोबस्त सरकार और किसानों के बीच होना चाहिए। दुख देनवाला यह जमींदारा का तत्व तो बतमान विवेचन के अंतर्गत आता ही नहीं।<sup>99</sup>

अंतिम रूप में हम यह दिखाना चाहते हैं कि आर० सी० दत्त इस तथ्य को निरंतर अपनी भाषा के सामने रखने वाले तथा भली प्रकार इस समझने वाले किन्हीं भी अन्य भारतीय नेताओं में किसी भी प्रकार पीछे नहीं थे कि बंगाल की जमींदाराना पट्टदारी में तथा भूमि लगान के स्थाई बंदोबस्त में बड़ा भारी अंतर था। 1874 में ही एक युवक अधिकारी के रूप में उन्होंने बंगाल के स्थाई बंदोबस्त पर सशक्त प्रहार किया और इसे कानवालिंस की अवरदस्त गलती कहा।<sup>100</sup> इसके साथ ही भी दशनीय है कि सरकारी अधिकारी के रूप में जमींदारा और उनके स्थाई बंदोबस्त के लिए स्थाई धना के कारण उन्हें जमींदारा से सदैव अपयश और निरन्वार ही मिला।<sup>100</sup>

इसमें सन्देह नहीं कि समय के बीतने के साथ साथ बंगाल के स्थाई बंदोबस्त के प्रति उनकी अरुचि नम पड़ती गई और यहां तक कि बाद में एक प्रकार से मर्यादित प्रशंसा के रूप में बदल गई, फिर भी उनके दिमाग में यह बात स्पष्ट थी कि देश के अन्य भागों में बंगाल पद्धति के विस्तार की चर्चा करना निरर्थक ही नहीं गलत भी था। इस प्रकार 1897 में उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक प्रदेश की विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार भूमि लगान के स्थाई बंदोबस्त के सिद्धांत का प्रयोग किया जाए तो उससे संबंधित सभी प्रश्न अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे।<sup>101</sup> 1899 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पी० सी० घोष ने देश के अन्य भागों में बंगाल पद्धति के विस्तार की मांग महसूस की, दत्त महादय ने इस मांग को आगे तो नहीं ही बढ़ाया साथ ही खुले तौर पर इस बात की घोषणा की कि वे भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित विभिन्न पद्धतियां, बंगाल की जमींदारी पद्धति, अवध की ताल्लुकदारी पद्धति उत्तर पश्चिम की महलवाड़ी पद्धति, मध्य भारत की मालगुजारी पद्धति और दक्षिण भारत की रयतवाड़ी पद्धति के गुणा का विवेचन ही नहीं करना चाहते। उन्होंने बड़ी ही सुस्पष्ट भाषा में जोर देकर कहा कि किसान किस पद्धति अथवा बंदोबस्त के अंतर्गत रह रहा है इसकी चिंता करना बेकार है। उन्हें केवल अपनी भूमि की उपज का उचित भाग मित्रों का विश्वास होना चाहिए इसी में उसकी रक्षा है और इसी में देश की रक्षा है।<sup>10</sup> लाड कजन का लिखे अपने चतुर्थ पत्र में उन्होंने इस मामले में अपनी स्थिति एकत्र साफ कर दी

देश के अन्धाय भागों में बंगाल पद्धति के विस्तार की मांग मैं इस समय नहीं करता। आपको लिखे अपने प्रथम तीन पत्रों में मैंने ऐसा कोई सुभाव नहीं किया।

प्रत्येक प्रांत में अपनी भूमि पद्धति है जिसके अंतर्गत वहां के लोग पीढ़िया से रहते आ रहे हैं। श्री ममहोदय। मैं तो केवल यह भाग ही है कि जिस भी पद्धति के अंतर्गत किसान रहता आ रहा है उसमें उसे सम्मर्पण प्रदान किया जाए।<sup>103</sup>

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय नेताओं ने और विरोध भागीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्थाई बंदोबस्त की मांग करते समय सदैव भूमि लगान के स्थाई बंदोबस्त शब्द का तथा भूमि पर सरकारी मांग की स्थिरता और स्थायित्व शब्द का ही प्रयोग किया। इस रूप में उन्होंने इस सबंध में मद्देह के लिए कोई अवधान ही नहीं छोड़ा कि उनकी वास्तविक रूढ़ि क्या थी।<sup>104</sup> इसी प्रकार अतीत में सरकारी क्षेत्रों में इस प्रश्न पर हुए विवाद के इतिहास में उनका व्यवहार 9 जुलाई 1862 और 24 मार्च 1865 में राज्य सचिव का संप्रेषित अपने पत्रों में उनके विशय उल्लेख और इन संप्रेषणों को पूरे तौर पर लागू करने में भागीयों के पूर्णतया सतुष्ट होने के उनसे उदघाप इस तथ्य को उजागर करते हैं कि स्थाई बंदोबस्त की मांग करते समय उनके मन में बंगाल की जमींदारी पट्टा पद्धति बंदोबस्त नहीं थी। इसके विपरीत व धरती पर सरकारी मांग को स्थाई रूप से सीमित करना चाहते थे।<sup>105</sup> यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारत की विभिन्न लगान पद्धतियों के विकास का ऐतिहासिक विश्लेषण करते हुए आर० सी० दत्त ने रैयतवादी पद्धति में न केवल पट्टेदारी अथवा किसानों के स्वत्वाधिकार में प्रत्युत भूमि के अस्थायी लगान निर्धारण के रूप में भी अनेक भयकर दाप देखे क्योंकि रैयतवादी पद्धति के व्यवस्थापक कामन मानने न रैयतवादी क्षेत्रों में लगान के स्थाई बंदोबस्त का समर्थन किया था, दत्त महोदय ने उसकी प्रशंसा की।<sup>106</sup>

स्थायी बंदोबस्त की मांग के संबंध में राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण के संबंध में यदि अन्य प्रमाण अपेक्षित है तो वह समझौते और यथाथवादिता की भावना से उनकी इस योजना की स्वीकृति और सहमति में देखे जा सकते हैं जिसके अंतर्गत इस व्यवस्था की मांग की गई कि लगान का एक स्थाई बंदोबस्त होगा जिसमें भूमि लगान को निरंतरता का रूप देते हुए निश्चित किया जाएगा परंतु उसमें मूल्यों में परिवर्तन की भीमा तक परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।<sup>107</sup> इस संबंध में राष्ट्रवादी नेताओं ने साह रिपन द्वारा सुभाषण गए समझौते का समर्थन किया।<sup>108</sup> अक्टूबर 1882 और मई 1883 के संप्रेषणों में यह कहा गया कि तब तक भूमि का कोई नया सर्वेक्षण नहीं किया जाएगा तथा लगान को ऊंचा नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि (क) जात का क्षेत्र बढ़ नहीं जाता, (ख) कीमतें बढ़ नहीं जाती, (ग) राज्य के बोय द्वारा किए गए सुधारों के फलस्वरूप उपज बढ़ नहीं जाती।<sup>109</sup> इसके अतिरिक्त इस आपत्ति को कि लगान के स्थाई बंदोबस्त से उन क्षेत्रों में जहाँ बड़े बड़े जोतने योग्य भूभाग जोते नहीं गए हैं, जमीन के मालिकों को अनुपातित आय की अपरिमित राशि मिलने लगी दूर करने के लिए भारतीय नेताओं ने अपनी सहमति प्रकट करते हुए यह मांग की कि सरकार अपनी इस मांग को अपने ही मापदंड में करने में ही पूर्णतया विश्वस्त क्षेत्रों तक ही सीमित रखे।<sup>110</sup> इन सब बातों पर विचार करने में यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि समाहित राष्ट्रवादी मांग के अंतर्गत भूमि लगान की राशि को मूल्यों के साथ जाड़ दिया जाए तो वास्तविक मांग में पट्टेदारी

पद्धति का तही प्रत्युत कर निर्धारण के सिद्धान्त का ही सबेते मिलता है ।

अब रोचक प्रश्न यह उठता है कि उपर्युक्त तथ्यों के सदम में जब राष्ट्रवादियों की स्थाई बदोबस्त की माग के सबध में स्थिति नितात स्पष्ट और निश्चित थी तब फिर यह मतिभ्रम कैसे उत्पन्न हो गया ? इसके उत्तर में हमारे इस कथन में कुछ हद तक सत्य है कि कम से कम आशिक रूप से ही रही, यह घपला जानबूझकर पदा किया गया था ताकि भूमि लगान पद्धति पर राष्ट्रवादियों के पहार को कोई श्रेय न मिल सके । राष्ट्रवादियों की स्थिति को जानबूझकर गन्त ढग में प्रस्तुत किया गया ताकि भारतीयों द्वारा उठाए गए प्रमुख विषयों पर स विशेषतया भूमि पर भारी लगान से इंग्लड और भारत की जनता का ध्यान हटाया जा सके । यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे एक भ्रष्ट तथा पाखंडपूर्ण प्रवृत्ति काम कर रही थी जिसके अतगत इंग्लड का संपूर्ण व्यवस्था, उपाधिकारी महानुभाव, वशानुगत लाड जायरिशवास्तकार की सहायता तथा रक्षा के किसी भी प्रयास का विरोध करने वाले तथा अपनी तीव्र प्रतिक्रिया प्रकट करने वाले आयरलड के बडे बडे भूमडला के स्वामी मालिक टोरी पार्टी के पथप्रदशा, इंग्लड में भूमि के राष्ट्रीयकरण के विरोधी तथा त्रिश्च में सर्वोच्च वनभागी सिविल सर्विस के सदस्य, सब के सब भारतीय किसान के उद्धारक बन गए और भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं पर जमींदारों के पिटठू हाने का आरोप लगाने लगे । वस्तुतः स्थिति थी यह विडवना भारतीयों से छिपी नहीं थी । आहरणाथ वजन के इस दृढ मत या रि स्थाई बदोबस्त किसी भी सम्य देश में सफन नहीं हुआ है, लडन परत हुए आर० सी० दत्त न 1902 में टिप्पणी की इंग्लड के व जमींदार जो 1798 के पिटग एक्ट के अतगत हुए स्थाई वन्देस्त के लाभो का उपभोग कर रहे हैं और उन्हें गोख द रू हैं, भारत आने पर यह शिक्षा ग्रहण करत है कि जो उनके त्रिण अच्छा है, वह भारतीयों के त्रिण अच्छा नहीं है ।<sup>110</sup> ए

हा यह अवश्य है कि यह व्यापक गलतफहमी कवन तथ्यों का गन्त ढग में प्रकट करने का ही परिणाम न थी । वस्तुतः कुछ भारतीय नेताओं की भूमि नीति का कुछ गन्त और लगान के स्थाई बदोबस्त पर तन प्रस्तुत करने का उनका ढग कुछ ढग प्रकार का अवश्य था कि उससे कभी कभार इस आर ध्यान दन धान को ध्राति अत्रयत जा सकती थी । प्रथम कभी कभी भारतीय नेताओं ने और विशेषतया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस परवर्ती कुछ वर्षों में अपनी माग प्रस्तुत करते हुए कवन 'स्थाई बदोबस्त' शब्द का प्रयोग किया । वे 'भूमि लगान शब्द जाडना भूत गए ।<sup>111</sup> वस्तुतः यह साग भाषागत भी भूत अथवा आलस्य के अतिरिक्त अन्य कोई विशेष मन्थ त्रिण थी और त्रिगन भी कांग्रेस के पूर्ववर्ती प्रस्तावों को और अनेकानेक राष्ट्रवादियों का ढग त्रिगन पर लम्बा और जनभाषणों का, जिनमें में कुछ को हम पहन ही ऊपर उद्धृत कर चुके हैं, ध्यान ग दना है वह इन शब्दों के छूट जान में भन्व नहीं सकता ।

द्वितीय, यह कन्वित्त सर्वाधिक मन्वपूर्ण था, भूमि लगान का स्थाई बदोबस्त बहुत म समयका ने विनोपन आर० सी० दत्त ने वगान का विगाना की स्थिति की विधि सीक्षा और वगान को ही स्थाई बदोबस्त की ध्यावगति उपनविषय है

के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि बंगाल के किसानों का अकाल से विरोध बर्बर नहीं पहुँचा, इसका कारण उनके अनुसार यह था कि स्थाई बंदोबस्त ने उन्हें इस योग्य बना दिया है कि वह अकालों के विरुद्ध उच्च स्तर पर आर्थिक प्रतिरोध अपना सके। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल का किसान देश के अग्र भाग के किसानों की अपेक्षा भौतिक साधना की दृष्टि से अधिक मजबूत है।<sup>11</sup> इस भावना को कभी कभी आर० सी० दत्त महोदय बहुत ही अतिरिक्त रूप दे देते थे और इस सीमा तक कह डालते थे कि म्यांई बंदोबस्त ने बंगाल की जनता को समृद्ध और सुखी बना दिया है।<sup>12</sup> दत्त बार बार यह भी घोषित करते रहे कि बंगाल के जमींदार उचित तथा न्यायसंगत किराया वसूल करते हैं और इस किराए की रकम कुल उपज के 1/5 भाग से अधिक नहीं होती।<sup>13</sup> बंगाल के तथा देश के अग्र भाग के बहुत सारे और नता भी थे जिन्होंने बंगाल के किसानों का जमींदारी की बुराई का पात्र बनाने वाले बंगाल के स्थाई बंदोबस्त को जायज माना। उदाहरणार्थ पी० सी० राय ने बंगाल बंदोबस्त की निम्न शब्दों में निंदा की

जनता के एक अत्यंत सीमित और रिपट स्वार्थी वर्ग जो जमींदार वर्ग कहलाता है वे सिवाय इस पद्धति के न तो राज्य का और न ही किसानों को कोई लाभ पहुँचाया है। बंगाल के किसान अत्यंत शोचनीय अवस्था में हैं और भारत के किसी भी प्रदेश के कृषि क्षेत्रों से बेहतर अवस्था में नहीं हैं। यदि बंगाल का किसान थोड़ा बहुत खाता पीता और समृद्ध दिखाई देता है तो इसमें जमींदारों का कोई भी महयोग नहीं, यह तो उसका अपना धर्म है। बंगाल का औसत जमींदार विशेषतः अपने बाय से अनुपस्थित रहने वाला, उतना ही क्रूर और अत्याचारी है जितना कि बर्मा, माहाराष्ट्र तथा महाजन आदि विभिन्न नामों वाले किसानों के शत्रु हृदयहीन हैं।<sup>14</sup>

यह यह उल्लेखनीय है कि आर० सी० दत्त ने स्वयं कभी इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की कि 1793 के स्थाई बंदोबस्त ने बंगाल के किसानों का समृद्ध बनाया है। उन्होंने तो सदैव उनके लाभों 1859 और 1885 के पट्टेदारी कानूनों के लाभों में जोड़ने की ओर ध्यान दिया। उनकी दृष्टि में 1793 का विनियम तथा 1859 और 1885 के कानून परम्पर महयोगी ही नहीं प्रत्युत एक ही पक्ष के दो पक्ष थे। कानूनों के इन दोनों वर्गों के सम्मिलित प्रवर्तन से ही बंगाल के किसानों की स्थिति सुधर सकी थी तथा भारत के अन्य प्रांतों के किसानों की अपेक्षा अच्छी बन सकी थी। जिस तरह उन्होंने 1793 के स्थाई बंदोबस्त की प्रणाली की उम्मीदों के साथ ही उम्मीदें रखीं, उन दिनों से और उसी उत्साह से उन्होंने 1859 और 1885 के अधिनियमों का स्वागत किया।<sup>15</sup> जब कन्नन ने 1902 के प्रस्ताव में अनुदारतापूर्वक उनपर तथा अन्य नेताओं पर अपने वास्तविकारों पर जमींदारों की मांग के सीमा निर्धारण की आवश्यकता पर समुचित ध्यान न देने का आरोप लगाया<sup>16</sup>, तो दत्त का आघात पहुँचा और उन्होंने मद्दुता के साथ कन्नन का उत्तर दिया कि उन्होंने सदैव इस अभिप्राय ही नहीं किया कि 'बंगाल के रट ऐक्ट' ने म्यांई बंदोबस्त द्वारा किए अर्द्धे काय को पूर्णता तक पहुँचाया है प्रत्युत 1885 के 'रट

एक्ट' की रूपरेखा तयार करने में भी पर्याप्त योगदान दिया है।<sup>118</sup> दत्त को इस समय वास्तव में यह भी कहना चाहिए था कि उन्होंने 1874 में ही जमींदारों और किसानों के बीच स्थाई बंदोबस्त के लिए दबाव डाला था, उह इस बात की भी वकालत करनी चाहिए थी कि विस्तृत सर्वेक्षण के उपरांत भुगतान किए जाने वाले किराए की दर सावधानी से निश्चित कर इसे सदा के लिए स्थिर घोषित कर दिया जाए।<sup>119</sup>

तृतीय, अधिकांश भारतीय नेताओं ने जमींदारी की पट्टेदारी के उन्मूलन की मांग नहीं की। उनकी दृष्टि में जहां तक किसानों के हितों का संबंध था, जमींदारी पट्टेदारी और रयतवाड़ी पट्टेदारी के बीच कोई अंतर न था। उनके इस उपेक्षा भाव का अर्थ जमींदारी के प्रति उनका अनुराग कदापि नहीं था अपितु उह यही विश्वास था कि जहां तक जमींदारी प्रथा के दोषों का संबंध था दोनों वास्तव में जमींदारी पद्धति के दो भिन्न भिन्न रूप थे—एक निजी जमींदारी का रूप था और दूसरा राजकीय जमींदारी का। जहां प्रथम में किराए का निर्धारण निजी स्वामी करते थे वहां दूसरे में सरकार आगे बढ़कर इस काम को संपन्न करती थी। व्यवहार में किसानों के लिए इन दोनों में चुनाव की कोई बात ही नहीं थी।<sup>120</sup> आर० सी० दत्त का इस विषय में कथन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने रयतवाड़ी पद्धति का संगठन किसानों को जमींदारी के चंगुल से बचाने के लिए नहीं, अपितु बिचौलियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभों को हथियाने और अपने राजस्व का अधिकतम बढ़ाने की इच्छा से ही किया है।<sup>121</sup> कंपनी जमींदारों के लाभों के प्रति ईर्ष्यालु रही है और किसानों के हितों के प्रति उत्सुक नहीं रही। इस पद्धति के अंतर्गत कंपनी का किसानों पर इतना अधिक बड़ा नियंत्रण हो गया है जितना किसी दासों के स्वामी का अपने दासों पर होता है, जो उनकी जीवन की आवश्यकता के लिए अपक्षित से अतिरिक्त और सब कुछ छीन लेता है।<sup>122</sup> कई नेताओं ने तो यह भी कहा कि जमींदारी प्रथा रयतवाड़ी प्रथा से दो बातों में तो बेहतर ही है। प्रथम जहां सरकार किसानों का धरती के अनुचित लगान बढ़ाने तथा अर्थ इस प्रकार के दूसरे दबावों से बचाने के लिए जमींदारों के विरुद्ध कानून बना सकती है और बनाती है, वहां भूराजस्व को बढ़ाने की अपनी शक्ति पर, तथा अन्य कई प्रकार से किसानों के साथ संबंधों को कटु बनाने की प्रक्रियाओं पर कानूनी जयवाज्य किसी प्रकार के प्रतिबंध लगान से इनकार करती है। यदि एक बार लगान का स्थाई बंदोबस्त स्वीकार कर लिया जाए तो जमींदारों अथवा अर्थ बढ़े बड़े मालिकों के किराया बढाने पर प्रतिबंध लगाकर किसानों तक इसके लाभों का विस्तार किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। वस्तुतः यह वाय तो सरकार अब भी सम्मानपूर्वक कर सकती है। जमींदारों को किराया बढ़ाने की अनुमति देने, प्रोत्साहन देने यहाँ तक कि कभी कभी विवश करने की वर्तमान नीति को छोड़कर उसके स्थान पर सरकार एक आदर्श प्रस्तुत कर सकती है।<sup>123</sup> कुछ भारतीय नेताओं के अनुसार रयतवाड़ी पट्टेदारी से जमींदारी को बेहतर बनाने वाला दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष निकासी का था। उनका तर्क था कि जमींदारी पद्धति में यदि किसानों को ऊँचा किराया देना पड़ता है तो इसमें एक अच्छाई तो है कि यह किराया भारतीय मालिकों को जाता है जो उस धन को भारत में ही खर्च करता है। इसके विपरीत विदेशी चरित्र



वाली सरकार को गिण जाने वाल किराए की देश के बाहर निकामी हा जाती है।<sup>14</sup>

चतुर्थ कृष्ण गन्तकर्मों इस तथ्य से भी उत्पन्न हुई कि कुछ भारतीय नेता इस बात से व्याकुल थे कि जिम ढग से अपनी प्रतिभा के उपयोग के अभाव में भारतीय लोगों का सारा सामाजिक जीवन समान रूप से निम्न स्तर पर पहुँच गया था, उस समय इन नेताओं ने उत्सुकता के साथ यह अनुभव किया कि जमींदार उस वक से सबध रखता है जिसे सामाजिक स्तर और बौद्धिक उत्थ के किसी रूप में बनाए रखने में सफलता मिली है अतः वह संपूर्ण भारतीय जनता को अधकारपूर्ण तथा गवाह अस्तित्व में पहुँचने से बचाने में सहायक और उद्धारक सिद्ध हो सकता है।<sup>15</sup> इसके अतिरिक्त भारतीय नेताओं के एक वग का यह भी विश्वास था कि लोगों को नेताओं और विचौलियों की आवश्यकता है और जमींदार अच्छे विचौलिए सिद्ध हो सकते हैं तथा वे ग्रामीण क्षेत्रों के प्राकृतिक नेता हैं।<sup>16</sup> इस सबध में अमृत बाजार पत्रिका द्वारा 20 जनवरी 1871 के अंक में 1793 के स्याई बंदोबस्त की रक्षा में प्रस्तुत लक्ष्यसपादनीय विश्लेषण का अध्ययन रोचक होगा। यह उद्धारण दशनीय है क्योंकि इसमें बंगाल के नेताओं के एक महत्वपूर्ण वग के और सम्भवतः भारत के ही राष्ट्रवादी नेताओं की वैचारिक प्रक्रिया की स्पष्ट दृष्टि देखने को मिलती है। यह बात और है कि इस उद्धारण का सत्रध अध्ययन-काल से दस वष पूर्व से है, फिर भी यह अवतरण ध्यान देने योग्य है।

यह सबविदित और विश्वसाय सत्य है कि वग के रूप में जमींदार देशवासियों के सद्ब्यवहार के पात्र नहीं। उनकी एक बहुत बड़ी मर्यादा अनुत्साहिया, निष्कर्ष, दुबलो, अन्यायियों, शोषकों और स्वाधियों की है। हम यह भी भली प्रकार जानते हैं कि वे ओद्येयन और धृतापूर्ण कार्यों से प्रतिवष बहुत बड़ी धनराशि, जिमपर वास्तव में किसानों का ही नैतिक अधिकार है, हथप जात है। हम यह भी जानते हैं कि इन जमींदारों ने कुछ के विनाश से ही लाखों किसानों को अधकारिता के बंधन में मुक्ति मिलेगी। हम यह सत्र जानते हैं और जमींदार की अपक्षा किसान से ही अधिक प्यार और उसका ही अधिक आदर करते हैं। इतने पर भी हम जमींदारों का समर्थन करते हैं। यह हमारी गुर आवश्यकता है। निस्संदह यह गुर है परंतु है हमारी आवश्यकता ही।

सपादनीय में आगे कहा गया है कि यह आवश्यकता का रूप में है, प्रथम, जनता के आंदोलन के लिए भारतीयों को पैसा चाहिए और वह पैसा केवल जमींदारों के पास है, व्यापारी तो पहले ही नष्ट हो चुके हैं। मद्रास में जहाँ जमींदार नहीं हैं, धन और दानियों के अभाव में वहाँ जन आंदोलन को गहरा धकरा लगा है। द्वितीय, जगरेजों ने पहले ही संपत्ति उत्पादन के सभी साधना, व्यापार, उद्योग तथा लोक नियुक्तियाँ को हथिया रखा है। भूमि ही बची हुई है। यदि जमींदारों को हटा लिया जाए तो सपदा के इस स्रोत पर भी अगरेज अधिकार जमा लेंगे और इससे किसानों का नाम की दृष्टि में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अतः जमींदारों को ही चलने देना चाहिए जो किसानों के धर्म के पत्र को हडपने के कारण गुरे अवश्य हैं परंतु यूरोपीयों से अधिक गुरे तो गही। सपादनीय में इस विषय का विस्तृत विवेचन इस प्रकार प्रस्तुत किया है

जमीदारों की कीमत पर किसान की समृद्धि ठीक उसी प्रकार सदैव उचित है जिस प्रकार किसानों और जमींदारों की कीमत पर यूरोपीयों की समृद्धि अनुचित परन्तु हम इस बात का कोई भरोसा नहीं कि सरकार किसानों के हित में ही बंदोबस्त को नष्ट करना चाहती है। इसके विपरीत हमें तो यह आशंका है कि धरती पर बढ़ाया हुआ लगान हमारा लाभ के लिए नहीं प्रत्युत अगरेज जाति के लाभ पर ही खर्च होगा।

सपादनीय ने इस साहसिक घोषणा के साथ यह निष्कर्ष निकाला 'पहले हम अपने देश के वित्त पर नियंत्रण करने दीजिए फिर हम दिल और दिमाग से बंदोबस्त का विरोध करेंगे परन्तु इस समय तो हम उसका समर्थन करने को ही विवश हैं।'

उपर्युक्त सभी तथ्यों से यह अधिक से अधिक सिद्ध होता है कि बहुत सारे भारतीय नेता जमींदारी और जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण के प्रश्न की उपेक्षा करना चाहते थे परन्तु इन पक्षों में यह तथ्य घुथलाया नहीं जा सकता कि स्थाई बंदोबस्त की मांग करते समय भारतीय नेता जमींदारी पट्टेदारी के लागू करने का पड्यत्र नहीं कर रहे थे।

## संदर्भ

- 1 दत्त स्पीचेज II, पृ० 90
- 2 दत्त ई एच II पृ० 97
- 3 सबल (प्रास) उपज के मूल्य तथा श्रमिकों के वेतन और लाभ की औसत दर पर कृषि में विनि योजित पूँजी के लाभ आदि की सगणना व उपरांत उत्पादन के अनुमानित व्यय का अंतर निवल (नेट) प्राप्ति अथवा उपज थी
- 4 दत्त ई एच II पृ० 98 इंपीरियल गजेटियर आफ इंडिया (1908) खंड IV, पृ० 217-9
- 5 इंपीरियल गजेटियर आफ इंडिया (1908) खंड IV पृ० 222-3
- 6 वित्त सदस्य ए० कोलविन द्वारा 1884 में सामान्य रूप से सरकार द्वारा करवर्द्धि के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांत का प्रस्तुत संक्षेप इस प्रकार से है पहला मूल्यांकन करते समय जमींदार अथवा किराएदार द्वारा किए गए सभी प्रकार के सुधारों पर छूट दी जाती थी दूसरा पहले से ही वर्गीकृत धरती के पुन वर्गीकरण की अथवा पुन मूल्यांकन की अनुमति जिसा भी रूप में नहीं दी जानी थी तीसरा चालू मूल्यों को ही सशोधन का आधार माना जाता था तथा किसी प्रकार का परिवर्तन केवल सावधानी से निर्धारित दो या तीन आधारों पर ही किया जाता था ये आधार थे, भारत सरकार जोत को स्थिर कर सकती थी नियंत्रित कर सकती थी तथा उसमें बढ़ोतरी कर सकती थी वर्द्धि का आधार राय द्वारा किए गए सुधारों से उपज में वर्द्धि और मूल्यों में वर्द्धि थी वित्त सदस्य (फाइनेंस मंत्री) ने इस बात का संकेत दिया कि नियम बढोर नहा ये और उनकी प्रयोगशीलता का विचार प्रत्येक मामले में पृथक पृथक रूप से ही सावधानी के साथ किया जाता था (फाइनेंश्ल स्टेटमेंट 1884-5 बडिवा 75) कुछ का कहना था कि वास्तविक कर निर्धारण तो और भी अधिक व्यावहारिक था देखिए बी एच० बोबन पावेल

- १० ग्राट एमाउट आफ दि लैंड रवेन्यू ऐंड इट्स ऐडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया (आकमफाह, 1894) पृ० 48
- 7 इपीरियल गजेटियर आफ इंडिया (1903) खंड IV, पृ० 201
- 8 1856-7 और 1901-2 की अवधि में भूराजस्व लगभग 58.6 प्रतिशत बढ़ गया दूसरी सगणना 1888-9 और 1905-6 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिए गए षको से की गई है
- 9 इपीरियल गजेटियर आफ इंडिया (1908) खंड IV पृ० 239, और देखिए स्टुची इंडिया (1903) पृ० 125
- 10 मनकर पूर्वोद्धत में इन लेखा के साथ रानाह का नाम जुड़ा हुआ है पृ० 213-6
- 11 जे० पी० एस० एस० जुलाई 1879 (खंड II, स० 1) पृ० 2 और देखिए पृ० 19-21
- 12 वही अक्टू० 1881 (खंड IV स० 2) पृ० 53 और देखिए वही, पृ० 55-57, 8, दि डवन एथीक्लचरिस्ट रिलीफ बिल, वही, अक्टूबर 1879 (खंड II, स० 2), दि ला आफ लंड सेल इन ब्रिटिश इंडिया वही अक्टूबर 1880 (खंड II स० 2) सट्टल प्रोविंशियल लैंड रवेन्यू ऐंड टनसी बिस्स, वही, अप्रैल 1881 (खंड II, स० 4) 'एग्जिप्टियन आफ सफ म इन एगिया वही अक्टूबर 1882 (खंड V, स० 2) प्रथियन नड लजिस्लेशन ऐंड दि बगान टनसी बिल वही, अक्टूबर 1883 (खंड VI स० 2) 'प्रपोज्ड रिफार्म इन दि रिस्टलमेंट आफ लंड एसेसमेंटस' वही जनवरी 1884 (खंड VI स० 3) और प्रोटस्ट ऐंड वाजिंस अगेंस्ट दि 'यू डिपाचर इन दि लंड एसेसमेंट पालिसी वही अप्रैल 1884 (खंड VI सख्या 4)
- 13 प्रस्ताव III
- 14 दत्त द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन की भूराजस्व नीति पर लगाए गए आरोपों के लिए विशेष रूप से देखिए ई एच I पृ० 79, 189-90 194 231 245, 362 372 3 और ओपेन लेटर्स टू लाड कजन (लाड कजन के नाम खुले पत्र 1900 में लिखित) (इसे आगे सदन के लिए 'ओपेन लेटर्स से संकेतित किया जाएगा), परवर्ती काल के लिए विशेष रूप से देखिए, दत्त 'ग्लोड ऐंड इंडिया पृ० 134 सी० पी० ए० पृ० 481-90, स्पेचेज I, पृ० 27-40 158-60 ओपेन लेटर्स स्पेचेज II पृ० 30 38, ई एच II, पृ० XIII फर्मिस ऐंड लंड एसेसमेंट इन इंडिया (सदन 1900), पृ० XI-XII
- 15 जोशी पूर्वोद्धत में पुन मुद्रित पृ० 392-574 उन्होंने इसी प्रकार के विचार 1884 में (पृ० 696) तथा 1890 में अपने निबंध 'दि इकोनामिक सिस्टम इन इंडिया—एथीक्लचर (देखिए विशेषतया पृ० 672 886 904-05) में भी इसी प्रकार के विचार प्रकट किए थे
- 16 देखिए नटसन ऐंड कगनी (मद्रास 1902) द्वारा प्रकाशित उनकी पुस्तक 'लैंड प्रान्जम इन इंडिया में एक लेख 'दि मावे लंड रवेन्यू सिस्टम' मई 1900 में बंबई में हुए प्रांतीय सम्मेलन में दिए गए उनके अद्ययापीय भाषण के उद्धरण, जो बंगाली के 22 मई 1900 के अंक में पुन मुद्रित हुए थे और दिल्ली पूर्वोद्धत पृ० 624-8 और रिप० आई० एन० सी०—1902 पृ० 81 एवं आग
- 17 पूना सामाजिक मन्ना के सचिव का पत्र जे० पी० एन० एस० जनवरी 1879 (खंड I सख्या 3) पृ० 37-43 बाबा रिप० आई० एन० सी० 1891 पृ० 22 सी० पी० ए० पृ० 561 574-5 'गम पावर्टी' पृ० 180-1 इंडियन फर्मिस पृ० 50, पी० मेहता स्पेचेज पृ० 607 जी वेंकटरमन रिप० आई० एन० सी० 1895 पृ० 131 ए० नदी इंडियन पालिटिक्स पृ० 130 जी० एस० अम्बर, दिल्ली कमीशन, खंड III प्रश्न 18716 रिप० आई० एन० सी० 1901, पृ० 87,

- चारहवें बवई प्रांतीय सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्ताव, मराठा 16 नव० 1902, गोयले, स्पीचेज, पृ० 80-82, 110-2 1017, एल० एम० घोष सी० पी० ए०, प० 743 757 एल० ए० जी० अय्यर, रिप० आई० एन० सी० 1903 पृ० 52 आर० एन० मधोलकर नि इकोनामिक कडीशन इन इंडिया एच० आर० अगस्त 1904 समाचारपत्रों में उदाहरण रूप में देखिए इंदु प्रवाश, 25 अक्टूबर (आर० एन० पी० बब० 30 अक्टूबर 1880), मराठा, 31 जुलाई 1881, 1 जनवरी 1882 ए० सी० पी० 5 अक्टूबर 1882 18 मार्च 1901 हिंदू 18 जनवरी 5 सितंबर 1884 4 जून 1900 इंडियन स्पेक्टेटर, 7 जनवरी (आर० एन० पी० बब० 13 जनवरी 1883), (इंडियन स्पेक्टेटर ने अपने 8 मार्च 1884 के भव में टिप्पणी की कि भूमि पुत्रों के साथ ब्रिटिश भारतीय अधिकारिया ने सभी प्रकार के सबर्धों में लुटरो की भूमिका ही निभाई है) स्वदेशमित्र, 27 जुलाई (आर० एन० पी० एम० अगस्त 1885) स्वदेशमित्र 13 नवंबर (वही 30 नवंबर 1889) हिंदुस्तान 3 मार्च (आर० एन० पी० एन० 10 मार्च 1891) बंगाली 13 फरवरी 1892, स्वदेशमित्र 17 मार्च, 28 अप्रैल 12 दिव० (आर० एन० पी० एम०, 31 मार्च 30 अप्रैल, 15 दिस० 1900 क्रमशः) केसरी 25 दिस० (आर० एन० पी० बब० 29 दिस० 1900) यू इंडिया 19 मई 1902
- 18 उदाहरण के लिए देखिए दत्त ओपेन लेटर्स, प० 71, 74-5
- 19 उदाहरण के लिए देखिए पूना सावजनिक सभा के सचिव का एक पत्र जे० पी० एस० एस० जनवरी 1879 (खंड III स० 1) प० 37 9 रानाडे एग्रियन प्रॉब्लम एंड इट्स सोल्यूशन जे० पी० एस० एस० जुलाई 1879 (खंड II, स० 1) प० 5 9 लड ला रिफॉर्म एंड ऐग्रीकल्चरल बक्स, जे० पी० एस० एस० अक्टूबर 1881 (खंड IV स० 2) पृ० 37 54 16 मई 1880 को पूना सावजनिक सभा द्वारा आयोजित पूना की एक सावजनिक सभा में स्वीकृत याचिका जे० पी० एस० एस०, जुलाई 1880 (खंड III स० 1) पृ० 5 'ए प्ली फार स्पॉलिएशन आफ इंडिया जे० पी० एस० एस० जनवरी 1885 (खंड VII स० 3) प० 7 15, तलग स्पीचेज, पृ० 16, आई० एन० सी० 1896 1897 1901, 1902 1903 और 1904 के प्रस्ताव क्रमशः XII IX, VIII(a) III III III राय पावर्टी, प० 180-1 184 9 जोशी पूर्वोद्धृत पृ० 334 392 536 (विशेष रूप से देखिए पृ० 452 3 457 61 466-81 494 5 508 10), 890-902 पी० मेहता स्पीचेज प० 450, ए० नदी इंडियन पोलिटिक्स प० 130-3 पी० पी० विल्लर्ड रिप० आई० एन० सी० 1892 पृ० 99 तिलक रिप० आई० एन० सी० 1895 पृ० 132 दत्त स्पीचेज I प० 21, 40 180 सी० पी० ए० प० 480-9 ओपेन लेटर्स प० 18 9 तथा पांच पत्र स्पीचेज II प० 30 57 179 80 ई० एच० I प० IX पाद टिप्पणी 370 ई० एच० II पृ० XIII 483 490 1 496 7 535 दसवें बवई प्रांतीय सम्मेलन में पारित प्रस्ताव (प्रस्तोता तिलक), मराठा 27 मई 1900 जी० के० पारिख 10वें बवई प्रांतीय सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण बंगाली 22 मई 1900 (तथा डिग्री पूर्वोद्धृत प० 624-8) प्रोसीडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बांग, 1901 खंड XXXIX प० 227 36 लड प्रॉब्लम इन इंडिया प० 124 34 रिप० आई० एन० सी० 1903 प० 59 वी० आर नाबियार, रिप० आई० एन० सी० 1900 पृ० 101 वाचा सी० पी० ए० पृ० 561 564, स्पीचेज प० 436 गोयले प्रोसीडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बांग, 1900 खंड XXXVIII वही प० 92 3 वही 1901 खंड XXXIX पृ० 244 स्पीचेज प० 80-2, 110 12 आर० एन० मधोलकर रिप० आई० एन० सी० 1901, पृ० 86-7,

## 374 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास

- जी० एस० अय्यर, वही प० 93 ई ए पृ० 48, बी० ए० छरे का लेखकें बर्से प्रांतीय सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण मराठा 26 अप्रैल 1903 एल० एम० पाय, सी० पी० ए०, पृ० 757-9 समाचारपत्रों के लिए दक्षिण उदाहरणों, इंदु प्रकाश, 25 अक्टू० और 29 नवंबर (आर० एन० पी० बब० 30 अक्टूबर और 4 दिस० 1880 कर्मण) मराठा, 1 जनवरी 1882 इण्डियन स्पेक्टेटर 7 जनवरी (आर० एन० पी० बब० 13 जनवरी 1883) हिंदू 18 जनवरी, 7 फरवरी 5 सितंबर 1884, 4 जून 1900 स्वदेशमित्र, 27 जुलाई (आर० एन० पी० एम०, अगस्त 1885) 13 नव० (वही 30 नव० 1889) स्वदेशमित्र, 8 मई शशिलेखा 15 मई (वही 31 मई 1896), तमिल प्रतिनिधि, 10 अक्टू० (वही 31 अक्टू० 1900), स्वदेशमित्र 12 दिस० (वही 15 दिस० 1900) 4 अगस्त के पत्र अखबार में महद्युक्त आत्म का पत्र (आर० एन० पी० पी० 18 अगस्त 1900), बसरी, 25 दिस० (आर० एन० पी० बब० 29 दिस० 1900), 12 मार्च (वही 16 मार्च 1901) ए० बी० पी० 17 23 जनवरी 18 मार्च 1901 न्यू इंडिया 19 मई 1902
- 20 रानाडे जे० पी० एस० एस० जुलाई 1877 (खंड II स० 1) प० 11 और अक्टूबर 1881 (खंड IV, स० 2) पृ० 55 एंजली फार स्मोलिशन आफ इंडिया बहा जनवरी 1885 (खंड VII, स० 3) प० 16 जारी पूर्वोद्धत प० 890-1 दस, सी० पी० ए० पृ० 488 फर्मिस इन इंडिया पृ० XI ओपेन लेटम प० 19 39 पाद लिपिणी 51 स्पीचेज II प० 73 179-80 ई० एच० II प० XIII 08 306 320 489 499 502 जी० एस० अय्यर ई० ए० प० 47 तथा आगे
- 21 दस स्पीचेज II पृ० 57 74 177 202 ई० एच० I प० X 169-70 ई० एच० II प० 98 334 492, 499 जी० एस० अय्यर ई० ए० प० 50-1
- 22 जे० पी० एस० एस० जुलाई 1879 (खंड II स० 1) प० 9 और देखिए रिपोर्ट आफ दि सबवेमेटी आफ पूना सावजनिक सभा (पूना 1873) प० 32 53, तिलक प्रोमीडिंग आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बांबे 1895 खंड XXXV III पृ० 91 ए० नयी इंडियन पब्लि टिकम प० 111 132 जोशी, पूर्वोद्धत प० 476, 479 80 497 499 500 गोखले प्रोसाइमिंग आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बांबे 1900 खंड XXVIII पृ० 94 जी० के० पारिख रीड प्राल्म इन इंडिया, प० 147 दस ई० एच० II पृ० 493 पाद लिपिणी, जी० एम० अय्यर ई० ए० पृ० 50 79 80 और देखिए ए० बी० पी०, 18 अक्टूबर 1900 और 12 फरवरी 1902, पी० पी० पिल्लई रिप० आई० एन० सी० 1903 प० 60 रानाडे ने भी कहा कि कि राजस्व अधिकारियों को इस लक्ष्य को ध्यान में रखन हुए तथा घोषणे बहुत छूट देने हुए चलना चाहिए कि धरती का निरंतर बढ़ती हुई आबादी का पालन-पोषण करना पड़ता है जे० पी० एस० एस० जुलाई 1879 (खंड II स० 1) पृ० 3
- 23 पूना सावजनिक सभा के सचिव का पत्र जे० पी० एस० एस० जनवरी 1879 (खंड I, स० 3) प० 37, रानाडे जे० पी० एस० एस०, अक्टूबर 1881 (खंड IV स० 2) प० 54 56-7 जारी, पूर्वोद्धत पृ० 347 869 904-05 बी० ए० छरे रिप० आई० एन० सी० 1893 प० 117 पी० महता स्पीचेज, प० 625-6 वाचा, सा० पा० ए० प० 568
- 24 रानाडे जे० पी० एस० एस० जुलाई 1879 (खंड II, स० 1) पृ० 7 8, राय फावर्टी पृ० 186-7 जी० के० पारिख नड प्राल्म इन इंडिया, प० 124 34 तथा टिपणी पूर्वोद्धत प० 625 दस स्पीचेज I पृ० 22 सर फिलिप मॉगिस मिन्टस आन दि स-सेक्ट आफ ए

- परमानेंट सेटलमट पार भगाल, बिहार ऐंड उड़ीसा बि ए प्रिफेस बाइ आर० सी० दत्त (कलकत्ता 1901) पृ० XII एल० एम० घोष सो० पी० ए० पृ० 758 760-1 पी० पी० पिल्लई, रिप० आई० एन० सी० 1903 पृ० 61
- 25 दत्त स्वाचज I प० 22 स्पीचेज II, प० 170 ए० बी० पी० 18 अक्टू० 1900 और 12 फरवरी 1902
- 26 तलग स्पीचेज प० 17, जोशी, पूर्वोद्धत पृ० 654, 658 900 जी० के० पारिख िगवी पूर्वोद्धत, प० 627 उद्धत, और रिप० आई० एन० सी० 1902 पृ० 82 गोपले, प्रोसीडिंग्स आफ दि नॉसिल आफ दि गवर्नर आफ बाब 1901, पृ० XXIX पृ० 244 और दखिए, डी० ए० खरे का तरहूँ बर्दई प्रांतीय सम्मेलन म अध्यक्षीय भाषण, मराठा 26 अप्रैल 1903
- 27 तेरहूँ बर्दई प्रांतीय सम्मेलन म डी० ए० खरे का अध्यक्षीय भाषण, मराठा, 26 अप्रैल 1903
- 28 माडलिब स्पीचेज पृ० 541 पूना सावजनिक सभा के सचिव क पत्र, जे० पा० एल० एस० जनवरी 1879 (पृ० I स० 3) और जुलाई 1886 (पृ० IX स० 1) पृ० 2 5, रानाड जे० पी० एल० एस० जुलाई 1879 (पृ० II, स० 1) प० 3 जनवरी 1884 (पृ० VI स० 3) पृ० 6 9 तलग स्पीचेज प० 10-1 जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 497, 902-04 मराठा 25 जुलाई 1886 पी० पी० पिल्लई रिप० आई० एन० सी० 1892 पृ० 117 जी० वेंकटरमन रिप० आई० एन० सी० 1895 पृ० 132 पी० मेहता स्पीचेज, पृ० 450 जी० क० पारिख डिगवी, पूर्वोद्धत प० 627 पर एन० एम० चरियार रिप० आई० एन० सी० 1903 पृ० 64 दत्त, ई० एच० II पृ० 465 7 50।
- 29 पूना सावजनिक सभा के सचिव का पत्र, जे० पी० एल० एस० जनवरी 1879 (पृ० I स० 3) पृ० 37, रानाडे जे० पी० एल० एस० जुलाई 1879 (पृ० II स० 1), पृ० 3 जनवरी 1884 (पृ० VI स० 3) पृ० 5 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 497, आर० एन० मधोलकर रिप० आई० एन० सी० 1890 प० 48 9 पी० मेहता पूर्वोद्धत पृ० 606 दत्त ओपेन लेटर्स प० 47 52, स्पीचेज II पृ० 39 186 198 ई० एच० II प० IX XI 152 169 171 370 पाद टिप्पणी 380 382 ई० एच० II, प० XII XIII 335 491 2 499 505 515-6 जी० क० पारिख डिगवी पूर्वोद्धत पृ० 626 8 पर रिप० आई० एन० सा० 1903 पृ० 56 7 वाचा सी० पा० ए० पृ० 564 आर० एन० मधोलकर दि इकोनामिक कमीशन आफ इंडिया एच० आर० अगस्त 1904 पृ० 259
- 30 रानाडे जे० पी० एल० एस० जुलाई 1879 (पृ० II, स० 1) पृ० 9 नेटिव आपीनियन 7 नवंबर (आर० एन० पी० बब०, 13 नवंबर 1880) सुजोय पत्रिका 14 नव० खानदेश बभब 12 नव० लोकमित्र 14 नव० (वही 20 नव० 1880) ज्ञान प्रकाश 13 दिस० (वही 18 दिस० 1880) सूर्योदय 20 दिस० कल्पतरु 19 दिस० (वही 25 दिसंबर 1880) नव विभाकर 6 नवंबर (आर० एन० पी० बग०, 11 नव० 1882) इंडियन स्पेक्टेटर 7 जन० (आर० एन० पी० बब० 13 जन० 1883) अखबारे आम 12 दिस० (आर० एन० पी० पी० एन० 19 दिस० 1883) हिंदू 5 सित० 1884 वाचा रिप० आई० एन० सी० 1891 प० 22 तथा सी० पी० ए०, पृ० 561 पी० पी० पिल्लई रिप० आई० एन० सी० 1892 पृ० 98 100 पी० मेहता स्पीचेज प० 394-5 451 575 6 622 आर० एम० सयानी सी० पी० ए० पृ० 364 आर० एन० मधोलकर इंडियन पालिटिकल प० 39 एन० जी० चदावरकर सा० पी० ए० प० 509 10 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 453 जी० एल० अम्बर रिप० आई० एन० सी०

- 1901 पृ० 92 3, ५० ए० प० 52 4, राम इंडियन फौमिस प० 58 यू इंडिया, 19 मई 1907 डी० ए० घरे का 13व बर्बई प्रांतीय सम्मानन म अध्यक्षीय भाषण मराठा, 26 अप्रैल 1903 एल० एम० पाप सी० पा० ए० प० 759 दत्त ई० एच० ]] प० 487
- 31 16 मई 1880 का पूना म हुई मावजनिक् सभा म स्वीकृत याचिका ज० पी० एम० एम०, जुलाई 1880 (खड III, स० 1), प० 56 पी० मेहता स्पीचेज प० 575 674 जोशी पूर्वोद्धत प० 404-05 408-10, 415 418 508 10, गोपल प्रोसीडिन्स आफ दि कौमिल आफ दि गवर्नर आफ बाय 1900 खड XXXVIII प० 88 92 जीर स्पीचेज, प० 6 जी० व० पारिख प्रोसीडिन्स आफ दि कौमिल आफ दि गवर्नर आफ बाय 1900 खड XXXVIII प० 118 और आग, वही 1901 खड XXXIX, प० 236 7 आर० एन० मधोलकर रिप० आई० एन० सी० 1901, प० 87 जी० एन० अय्यर, ई० ए० पृ० 52, एन० एम० घोष, सी० पी० ए०, पृ० 760
- 32 इंडियन स्पेक्टटर, 11 और 18 सितंबर (आर० एन० पी० बब० 17 और 24 नितंबर 1881) जोशी, पूर्वोद्धत, प० 466
- 33 रानाडे ज० पी० एन० एम०, अक्टूबर 1891 (खड IV, स० 2) पृ० 57 नौराजी स्पीचेज प० 177 जी० एन० अय्यर ई० ए०, प० 80 और आग अध्याय 11
- 34 रानाडे जे० पी० एम० एन० जुलाई 1879 (खड II स० 1), प० 19 और वही अक्टूबर 1881 (खड IV स० 2) पृ० 56-7 राय पावर्टी प० 180-4 187 8 जी० एन० अय्यर विलवा आयोग खड III प्रश्न 18737 जी० व० पारिख विलवा पूर्वोद्धत पृ० 628 पर दत्त इंग्लंड ऐंड इंडिया, पृ० 69, ई० एच० I प० XI स्पीचेज II प० 75
- 35 पी० मेहता स्पाचेज प० 607 दत्त, स्पीचेज I प० 22 37 40 180 सी० पी० ए० मे प० 490 1 485 487 ओपन लटस, पृ० 18 9 स्पीचेज II प० 57 ई० एच० I प० XI 94 171, केसरा, 25 दिस० (आर० एन० पी० बब० 29 लि० 1900) आर० एन० मधोलकर रिप० आई० एन० सी० 1904 पृ० 259
- 36 जोशी पूर्वोद्धत, प० 480 497 जी० एन० अय्यर ई० ए० पृ० 50
- 37 पूना सावजनिक् सभा क सचिव का पत्र जे० पी० एन० एन० जनवरी 1879 (खड I स० 3) पृ० 43 रानाडे, जे० पी० एन० एन०, जनवरी 1884 (खड I स० 3) प० 5-6 हुसन खान रिप० आई० एन० सी० 1888, पृ० 176 एम० एन० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1889 प० 50 इद्रु प्रकाश 28 जुलाई 1890 आर० एन० मधोलकर रिप० आई० एन० सी० 1890 पृ० 48 ज० राम वही पृ० 52 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 696 7, 824 969-71 886 तथा आगे 894 904-05 डा० ए० घरे, रिप० आई० एन० सी० 1893 पृ० 117, एन० जी० चंदावरकर, सी० पी० ए० प० 521 2 जा० एन० अय्यर विलवा आयोग खड I प्रश्न 18737, दत्त ओपन लटस प० 52, स्पीचेज II प० 30 39 41 75 105 184 186, 188 198 लड प्रान्तस आफ इंडिया प० 17 8, ई० एच० I पृ० XI 94 171 ई० एच० II पृ० XII, 467 501 516
- 38 रानाडे ज० पी० एन० एन० अक्टू० 1881 (खड IV, स० 2) पृ० 55 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 347, 453 870-1 904-05 अघकारे आम 21 जुलाई (आर० एन० पी० पी० 30 जुलाई 1898) एन० जी० चंदावरकर सी० पी० ए०, पृ० 521 दत्त सी० पी० ए०, पृ० 478 480 स्पीचेज II, पृ० 91 तथा आग ई० एच० II पृ० XIII

- 39 रानाड जे० पी० एस० एस० जुलाई 1879 (खंड II सं० 2) पृ० 48, 57 ज्ञान प्रकाश 8 फरवरी (आर० एन० पी० बब०, 10 फरवरी 1883), बी० एन० सेन रिप० आई० एन० सी० 1889 पृ० 49, जे० एन० बोस, रिप० आई० एन० सी० 1890 पृ० 50 आई० एन० सी० 1891 और 92 के प्रस्ताव क्रमशः III और IX डी० ए० खरे रिप० आई० एन० सी० 1893 पृ० 117 आर० एन० मधोलकर इंडियन पालिटिक्स पृ० 45 स्वदेशमित्र 17 मार्च (आर० एन० पी० एम० 31 मार्च 1900) एल० ए० जी० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1903 पृ० 55 रानाडे ने 1879 में ही निर्देश किया था कि कृपि में इस समय जितनी भी पूजा नियोजित है वह सारा की सारी व्ययवित्त तथा अनुत्पादक उद्देश्य लिए हुए है अतः उसकी प्रवृत्ति सूदखोर पूजा की है न कि निवेश पूजा की जे० पी० एस० एस० जुलाई 1879 (खंड II सं० 1) पृ० 16-7
- 40 बंगाली 21 अक्टूबर 1882, जी० एस० खरपड रिप० आई० एन० सी० 1893 पृ० 118
- 41 दत्त, ई० एच० II पृ० 269, 306, 463 480-3
- 42 इंदु प्रकाश, 25 अक्टूबर (आर० एन० पी० बब०, 30 अक्टू० 1880) सुबाघ पत्रिका, 14 नव० (वही, 20 नव० 1880), इंदु प्रकाश 5 सित० (वही 10 सित० 1881) सि वायसरायल्टी आफ लांड लिटन जे० पी० एस० एस० जुलाई 1880 (खंड III सं० 1) पृ० 61 रानाड, जे० पी० एस० एस० जन० 1881 (खंड III सं० 3) पृ० 18 और अक्टू० 1881 (खंड IV सं० 2) पृ० 37 अखबारों आम 12 दिस० (आर० एन० पी० पी० 19 दिसंबर 1883) हिंदू 18 जन० 1884 पी० पी० पिब्लई रिप० आई० एन० सी० 1892 पृ० 98 पी० महता, स्पीचेज पृ० 450 575 605, 622 आई० एन० सी० 1895 का प्रस्ताव X आर० एन० मधोलकर, इंडियन पालिटिक्स पृ० 39 ए० नदा इंडियन पालिटिक्स पृ० 131 2 दत्त सी० पी० ए० पृ० 480 स्पीचेज II पृ० 57 8 193-4 ई० एच० II पृ० 487 516 जी० के० पारिख का दसव बंबई प्रांतीय सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण बंगाली 22 मई 1900 दसवें बंबई प्रांतीय सम्मेलन में तिलक द्वारा प्रस्तुत और सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्ताव मराठा 27 मई 1900, राय इंडियन फॉर्मिस पृ० 50 58 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 410 414 421 426 435 गोखले, स्पाचज पृ० 82 1017 वाचा सी० पी० ए० पृ० 561 2 585 यू इंडिया, 19 मई 1902 तथा देखिए अध्याय 10 आगे
- 43 गोपले प्रोसीडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बांग 1901 खंड XXXIX पृ० 247 जी० एम० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1901 पृ० 92 3 दत्त ई० एच० II पृ० 487 तथा देखिए अध्याय 4 का 72 सभ्या की पारंप्रिपणी
- 44 देखिए आगे अध्याय 12 और 13
- 45 जे० पी० एस० एस० अक्टूबर 1881 (खंड IV सं० 2) पृ० 58 और देखिए रानाड जे० पी० एस० एस० जनवरी 1884 (खंड VI सं० 3) पृ० 4 वाचा सी० पी० ए० पृ० 574 5
- 46 रानाडे, जे० पी० एस० एस० अक्टू० 1881 (खंड IV, सं० 2) पृ० 57 एसेज पृ० 256-7
- 47 जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 870 और देखिए पृ० 347
- 48 दत्त ओपेन लेटर्स पृ० 79-80 तथा देखिए वही पृ० 81 3 फॉर्मिस इन इंडिया, पृ० XIV XVI
- 49 उन्होंने तो जोर देकर कहा था कि भारत में भूमि समस्या का कभी समाधान नहीं हो पाएगा और भारत धन से तब तक नहीं बढेगा जब तक यह नहीं किया जाता





- एच० II, प० 485 495 501, 595 612, एल० ए० जी० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1903 प० 55
- 56 तेलग स्पीचेज पृ० 4 6-7 20 रानाडे, जे० पा० एस० एस० जनवरी 1884 (खड VI स० 3), पृ० 8 11 और वहा, अप्रल 1884 (खड VI स० 4) पृ० 48 9 मराठा, 30 माच 1884 25 जुलाई 1886 ज्ञान प्रकाश, 3 अप्रल इंदु प्रकाश 31 माच (आर० एन० पी० बब 5 अप्रल 1884) इंडियन स्पेक्टेटर, 20 अप्रल (वही 26 अप्रल 1884) इंदु प्रकाश 12 जुलाई (वही, 17 जुलाई 1886), पूना सावजनिक सभा के सचिवा क पत्र दिनांक 4 जून 1884 जे० पी० एस० एस० जुलाई 1886 (खड IX, स० 1), प० 3 5 6 जाशी पूर्वोद्धत प० 824 दत्त, ई० एच० II प० 465 7
- 57 एल० एम० घोष स्पीचेज, पृ० 28, एस० एस० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1889 पृ० 50, आई० एन० सी० 1894 1896 1898 1901 और 1903 के प्रस्ताव क्रमश II (बी) XVII VI III और III, जोशी, पूर्वोद्धत पृ० 497 दत्त ओपेन लेटस प० 53 65 6 79 83 एस० एन० बनर्जी, सी० पी० ए० पृ० 698 9
- 58 वी० महता स्पीचेज पृ० 395 622-4 दत्त ओपेन लेटस प० 49 51 54 80 फर्मिस इन इंडिया पृ० XVI स्पीचेज II प० 12 41 ई० एच० II पृ० 467 9 612 आई० एन० सी० 1902 1903 और 1904 को प्रस्ताव क्रमश III III (ए) III (बी), डी० ए० खरे का तरहूँ बबई प्रांतीय सम्मेलन मे अध्यक्षीय भाषण मराठा, 26 अप्रल 1903
- 59 आई० एन० सी० 1895 का प्रस्ताव स० X एन० जी० चदावरकर सी० पी० ए० पृ० 520
- 60 गोखले प्रोसीडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बाबे 1901, खड XXXIX पृ० 247, जो० एम० अय्यर, रिप० आई० एन० सी० 1901 पृ० 93 और ई० ए० पृ० 54-5
- 61 1876 77 और 1896-1901 क अकाला के दौरान भारतवष म सावदेशिक स्तर पर माग उठाई गई और देखिए रानाडे जे० पी० एस० एस० अक्टूबर 1879 खड II स० 2) प० 66 पी० पा० विल्लई रिप० आई० एन० सी० 1892 प० 99 100 मराठा 17 जन० 1897 जी० के० पारिख प्रोसीडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बाबे 1900 खड XXXVIII प० 118 और आगे जोशी पूर्वोद्धत, प० 404 413 4 420 511 555 8 हिंदू० 18 अगस्त 1902 दत्त स्पाचेज II प० 59 जी० एस० अय्यर ई० ए० पृ० 55 7 गोखले स्पीचेज प० 82 3
- 62 रानाडे जे० पी० एस० एस० जुलाई 1879 (खड II स० 1) पृ० 10 13-4 और अप्रल 1884 (खड II स० 4) पृ० 55, बबई समाचार 22 नव० (आर० एन० पी० बब 27 नव० 1880) पूना सावजनिक सभा द्वारा प्रस्तुत स्मरणपत्र जे० पी० एस० एस० जुलाई 1881 खड IV स० 1) प० 9 ए० वी० पी० 26 जून 1884 और 19 जून 1892 मराठा का एक स्तम्भ लेखक 7 फरवरी 1892 राम इंडियन फर्मिस प० 58 दत्त ई० एच० II पृ० 493 पाद टिप्पणी आर० एम सयानी एल० सी० पी० 1897 खड XXXVI पृ० 191
- 63 रानाडे जे० पी० एस० एम० जुलाई 1879 (खड II स० 1) प० 13-4 दत्त ई० एच० II प० 493 पादटिप्पणी
- 64 केमरी 15 और दिस० (आर० एन० पी० बब 19 और 26 दिस० 1896) आर० एन० पी० बब 2 9 16 23 और 30 जनवरी और 6 13 और 27 फरवरी 1897 मे यथाप्रतिवेदित विभिन्न समाचारपत्रो मे प्रकाशित रिपोट मराठा 3 10 17 जनवरी 1897 रामगोपाल

- 50 नीरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 173, 176, रानाडे, जे० पी० एम० एम०, अक्टू० 1879 (घट II सं० 2) पृ० 66 जन० 1881 (घट III सं० 3), पृ० 17 और अक्टू० 1881 (घट IV, सं० 2) पृ० 42 45 6, एल० एम० घोष, स्पीचेज, प० 28 मराठा 31 जुलाई 1881, स्वदेशमित्र 8 मई शिलेपा, 15 मई (भार० एन० पी० एम०, 31 मई 1896), आई० एन० गां०, 1890 और 1902 के प्रस्ताव नमश XIII तथा III, जी० एम० अम्बर विलवे आयाग घट 3, प्रश 18643 4 दस स्पीचेज I पृ० 23 26 37 40 सी० पी० ए० प० 486 ओपेन लेटर्स, पृ० 53 स्पीचेज II पृ० 17 8, 41, 59 97 200, 202, ई० एच० II प० 528, 606-07 स्वदेशमित्र 17 माघ (भार० एन० पी० एम० 31 माघ 1900), ए० वी० वा० 21 अप्रैल 4 जून, 18 अक्टू० 1900 जोमा, पूर्वोदय, पृ० 364-5 457 497, 513 एम० एम० मानवीय रिप० आई० एन० सी० 1900 पृ० 98 वाचा सी० पी० ए० पृ० 601 एम० एन० वनजी गां० पी० ए० पृ० 691, 698 699 आरह्वे बवई प्रांतीय सम्मेलन का प्रस्ताव मराठा 16 नव० 1902, तेरह्वे बवई प्रांतीय सम्मेलन में तिलक का भाषण मराठा, 10 मई 1903, एर० ए० जी० अम्बर, रिप० आई० एन० सी० 1903 पृ० 52 3, गोखले स्पीचेज, पृ० 77 80 83, 112 तथा देविए आगे पाद टिप्पणी 55-58
- 51 रानाडे, जे० पी० एम० एम० अप्रैल 1884 (घट VI सं० 4) पृ० 55 और देविए रानाडे वही जुलाई 1879 (घट II सं० 1) प० 11 3, दस ओपेन लेटर्स, पृ० 41 2, 53 65 89, 82 3, पवित्र दन दृष्टिया, पृ० XVI स्पीचेज II पृ० 18, 75 104 177 8 201 ई० एच० I प० 396 ई० एच० II पृ० X, XII 471 485 495 501-02 597 612 मराठा, 3 मई 1903
- 52 दस सी० पी० ए० पृ० 482 3, आपन लेटर्स पृ० 41 2, 53, 65 79, 82-3 बाद में आर० सी० दस न विरोध प्रकट करत हुए कहा कि उन्होंने सबल उपज के 1/5 भाग को दर पर लगान की अधिकतम सीमा किमी अकली जाल पर न बढ़ाने का प्रस्ताव किया था न कि धरती क लगान का सामान्य मानक का रूप में थोड़े प्रस्ताव रखा था अधिकतम लगान पर इस प्रकार की रोक की आवश्यकता उस समय उत्पन्न हुई जब राजस्व अधिकारियों द्वारा उपज के आधे भाग पर सगटिन लगान कभी कभी कुल उपज के 1/5 भाग से अधिक बढता था और कभी कभी तो सबल उपज के 1/3 से भी बढ़ जाता था आपन लेटर्स पृ० 39 पाद टिप्पणी 42 पाद टिप्पणी 53 पाद टिप्पणी 65 पाद टिप्पणी, स्पीचेज II पृ० 178 9, ई० एच० II पृ० 512 3 यह समझ है कि दस दस दस से अपनी उस गतरी पर परदा डालने की चेष्टा कर रहे थे जो मतभंग की तीव्रता में उनसे हा गई था और कजन ने राष्ट्रवादियों की समालोचना को नकारने के लिए जिमका वही बुद्धिमत्ता में उपयोग किया था
- 53 ए० पी० एम० एम० एम० जुलाई 1879 (घट II सं० 1) पृ० 13
- 54 जोमा पूर्वोदय पृ० 490-1
- 55 एल० एम० घोष स्पीचेज पृ० 28 आई० एन० सी० 1895, 1896 और 1901 और 1903 के प्रस्ताव नमश XIV XIII, III और III ए० ए० - - - - - की ओर सं० 9, नवंबर 1895 को साइ एलगिन के स्वागत में किया गया जनवरी 1896 (घट XVIII सं० 3) प० 11, सी० शकरजु 389 - स्पीचेज I पृ० 40 181 ओपेन लेटर्स पृ० 48 9 स्पी 186-7 190 198 202 सह आयाग आफ दृष्टिया

- एच० II, पृ० 485 495, 501 595 612 एल० ए० जी० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1903 पृ० 55
- 56 तेलग स्पीचज पृ० 4 6-7 20 रानाड जे० पा० एस० एम० जनवरी 1884 (खड VI स० 3), पृ० 8 11 और वही, अप्रैल 1884 (खड VI स० 4) पृ० 48 9 मराठा 30 मार्च 1884 25 जुलाई 1886 ज्ञान प्रकाश, 3 अप्रैल इंदु प्रकाश 31 मार्च (आर० एन० पी० बब 5 अप्रैल 1884), इंडियन स्पेक्टेटर 20 अप्रैल (वही, 26 अप्रैल 1884) इंदु प्रकाश 12 जुलाई (वही 17 जुलाई 1886), पूना सार्वजनिक सभा के सचिवा के पत्र दिनांक 4 जून 1884 जे० पी० एस० एस०, जुलाई 1886 (खड IX, स० 1), पृ० 3, 5-6 जाशी पूर्वोदित पृ० 824 दत्त, ई० एच० II पृ० 465 7
- 57 एल० एम० घोष स्पाचेज पृ० 28 एम० एस० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1889 पृ० 50 आई० एन० सी० 1894 1896 1898, 1901 और 1903 के प्रस्ताव क्रमशः II (बी) XVII VI, III और III, जोशी पूर्वोदित पृ० 497 त्त ओपेन लेटर्स पृ० 53 65-6 79 83, एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए० पृ० 698-9
- 58 बी० महता स्पीचेज पृ० 395 622-4 दत्त ओपेन लेटर्स पृ० 49 51 54 80 फर्मिस इन इंडिया पृ० XVI स्पीचेज II पृ० 12 41 ई० एच० II पृ० 467 9 612 आई० एन० सी० 1902 1903 और 1904 के प्रस्ताव क्रमशः III III (ए) III (बी), डी० ए० घरे का तरहें बर्दे प्रांतीय सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण, मराठा, 26 अप्रैल 1903
- 59 आई० एन० सी० 1895 का प्रस्ताव स० X एन० जी० चंदावरकर सी० पी० ए० पृ० 520
- 60 गोधले प्रोसीडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बांबे 1901 खड XXXIX पृ० 247 जी० एम० अय्यर, रिप० आई० एन० सी० 1901 पृ० 93 और ई० ए० पृ० 54-5
- 61 1876-77 और 1896-1901 के अकाला के दौरान भारतवर्ष में सावर्जनिक स्तर पर मांग उठाई गई और देखिए रानाड जे० पी० एस० एस० अक्टूबर 1879 खड II स० 2) पृ० 66 पी० पी० पिल्लई रिप० आई० एन० सी० 1892 पृ० 99 100 मराठा 17 जन० 1897 जी० के० पारिख प्रोसीडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बांबे 1900 खड XXXVIII पृ० 118 और आगे जोशी पूर्वोदित पृ० 404 413 4 420 511, 555 8 हिंदू० 18 अगस्त 1902 दत्त स्पाचेज II पृ० 59 जी० एस० अय्यर ई० ए० पृ० 55 7 गोखल स्पीचेज पृ० 82 3
- 62 रानाडे जे० पी० एस० एस० जुलाई 1879 (खड II स० 1) पृ० 10 13-4 और अप्रैल 1884 (खड II स० 4) पृ० 55, बर्दे समाचार 22 नव० (आर० एन० पी० बब, 27 नव० 1880) पूना सार्वजनिक सभा द्वारा प्रस्तुत स्मरणपत्र जे० पी० एस० एस० जुलाई 1881 खड IV स० 1) पृ० 9 ए० बी० पी० 26 जून 1884 और 19 जून 1892 मराठा का एक स्वतंत्र लेखक, 7 फरवरी 1892 राय इंडियन फर्मिस पृ० 58 दत्त ई० एच० II, पृ० 493 पाद टिप्पणी आर० एम० समानी एल० सी० पी० 1897 खड XXXVI पृ० 191
- 63 रानाड जे० पी० एस० एस० जुलाई 1879 (खड II स० 1) पृ० 13-4 दत्त ई० एच० II पृ० 493 पाद टिप्पणी
- 64 केमरी 15 और दिस० (आर० एन० पी० बब 19 और 26 दिस 1896) आर० एन० पी० बंब 2 9 16 23 और 30 जनवरी और 6 13 और 27 फरवरी 1897 मय्याप्रतिवेदित विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट, मराठा 3 10 17 जनवरी 1897, रामगोपाल

- 50 नीरोजी स्पेचेज, परिशिष्ट, पृ० 173, 176 रानाडे, जे० पी० एस० एस०, बन्नु० (खंड II स० 2) पृ० 66 जन० 1881 (खंड III स० 3), प० 17 और अक्तू० 18 IV, स० 2) प० 42, 45 6, एल० एम० घोष, स्पेचेज, प० 28 मराठा, 31 जुलाइ स्वदेशमित्रन 8 मई, शशिलेखा, 15 मई (आर० एन० पी० एम० 31 मई 1896), आ सी०, 1890 और 1902 के प्रस्ताव क्रमशः XIII तथा III, जो० एस० अरु० आयोग खंड 3, प्रश्न 18643-4 दत्त स्पेचेज I प० 23 26 37 40 सी० पी० ए० ओपेन लेटर्स, प० 53, स्पेचेज II पृ० 17 8 41 59 87 200 202 ई० एच० J 606-07 स्वदेशमित्रन 17 मार्च (आर० एन० पी० एम० 31 मार्च 1900), ए 21 अप्रैल, 4 जून 18 अक्तू० 1900 जोशी, पूर्वोद्धृत पृ० 364-5 457 497 एम० मालवीय रिप० आई० एन० सी० 1900 प० 98 वाचा सी० पी० एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए० प० 691 698 699 वारहूँ बबई प्राता प्रस्ताव मराठा 16 नव० 1902 तेरहूँ बबई प्रातीय सम्मेलन में तिलक का 10 मई 1903 एल० ए० जी० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1903 प स्पेचेज प० 77, 80 83 112 तथा देखिए आगे पाद टिप्पणी 55 58
- 51 रानाडे जे० पी० एस० एस० अप्रैल 1884 ( (खंड VI, स० 4) पृ० 55 वीं वही जुलाई 1879 (खंड II स० 1) प० 113 दत्त ओपेन लेटर्स प० 89 82 3, फॉर्मिस इन इंडिया प० XVI स्पेचेज II पृ० 18 75, 10 एच० I प० 396 ई० एच० II प० X, XII 471, 485 495 501-02 3 मई 1903

- 1893 प० 114 और रिप० आई० एन० सी० 1895 प० 133 जोशी पूर्वोद्धत प० 362  
 3, 811 824 5 एम० आर० सयानी एल० सी० पी०—1897 खड XXXVI स० 191  
 और सी० पी० ए० प० 365 जी० आर० एम० चिननवीस, एल० सी० पी० 1898 खड  
 X XVII प० 481 पी० ए० चारलू, वही प० 502 और एल० सी० पी० 1900 खड  
 XXXIX प० 146, पी० मेहता स्पीचेज प० 606-07 एम० एम० मालवीय रिप० आई०  
 एन० सी० 1899 प० 91 3 और रिप० आई० एन० सी० 1900 प० 99 एस० एन० बनर्जी  
 रिप० आई० एन० सी० 1900 प० 75 6 गोखले स्पीचेज प० 24 5 112 जी० एस० अय्यर  
 एच० आर० फरवरी 1902 प० 149 51, बारहवें और तेरहवें बर्षों प्रांतीय सम्मेलनों के  
 प्रस्ताव, मराठा 16 नवंबर 1902 और मई 1903 क्रमशः
- 73 भूराजस्व के स्याई निर्धारण की मांग आर० सी० दत्त के भूमि समस्या पर लिखे गए लगभग  
 सभी लेखों में उपलब्ध है उन्नाहरणाय देखिए इंग्लड एंड इंडिया प० 51 133 5 फर्मिस इन  
 इंडिया, प० XII स्पीचेज I प० 15 24 158 180 1 इ० एच० II प० X XI
- 74 ज्ञान प्रकाश 6 फरवरी (आर० एन० पी० बब, 8 फरवरी 1879) अरुणोदय, 27 अप्रैल (वही  
 3 मई 1879) शिवाजी 8 अगस्त (वही 16 अगस्त 1879), सुबाघ पत्रिका 1 अगस्त (वही  
 7 अगस्त 1880) इंदु प्रकाश 7 मार्च (वही 12 मार्च 1881), अरुणोदय 30 अक्टूबर (वही  
 5 नवंबर 1889, 24 मार्च 1900 3 फरवरी 1901 ज्ञान प्रकाश, 8 फरवरी (आर० एन० पी०  
 बब, 10 फरवरी, 1883) सोमप्रकाश 8 जनवरी (आर० एन० पी० बग० 13  
 जनवरी 1883), नेटिव ओपीनियन, 1 अप्रैल 1883, हिंदू 27 फरवरी 1884, 13 सित० 1889  
 2 जून० 1891 नसीमे आगरा, 23 अग० (आर० एन० पी० पी० एन० अगस्त 1884)  
 स्वदेशमित्र, 27 जुलाई (आर० एन० पी० एम० अगस्त 1885) बंगाली 28 जून 1890  
 इंदु प्रकाश 28 जून 1890 हिंदुस्तान 3 मार्च (आर० एन० पी० एन० 10 मार्च  
 1891) हिंदुस्तानी 7 अक्तू० (आर० एन० पी० एन० 15 अक्तू० 1891) हिंदुस्तानी,  
 8 नवंबर (वही 15 नवंबर 1893) विकटोरिया पेपर, 25 अक्तू० (आर० एन० पी० पी०  
 4 नवंबर 1893, पसा अखबार 13 अक्तू० (वही, 20 अक्तू० 1894) केरल पत्रिका 26  
 जनवरी (आर० एन० पी० एम०, 31 जन० 1895), सियालकोट पेपर 8 अक्तू० पसा अखबार  
 7 अक्तू० (आर० एन० पी० पी० 28 अक्तू० 1899) स्वदेशमित्र 18 मार्च और 21 अगस्त  
 (आर० एन० पी० एम० 31 मार्च और 31 अगस्त 1900 क्रमशः)
- 75 सड रवेयू पालिसी आफ दि गवर्नमेंट आफ इंडिया (कलकत्ता, 1902) कडिका 5
- 76 वही कडिका 5 और 6
- 77 वही कडिका 6
- 78 वही कडिका 9
- 79 रीस पूर्वोद्धत प० 63 यह वाकी आवश्यकतक है कि एच० और तो रीस ने लगान के स्याई  
 बदोबस्त सबंधी बार्सेस के आंदोलन की जमींदार समर्थक नाम दे डाला दूसरी ओर जमी प्रस्ताव  
 के तीन ही पन्नों के उपरान्त प्रत्येक जमींदार के निजी स्वामित्व के स्याई बदोबस्त की बर्णनात  
 प्रारम्भ कर दी रीस की मायता थी कि यह स्याई बदोबस्त बंगाल के स्याई बर्नोबस्त से भिन्न  
 होगा (वही प० 66-9) इससे स्पष्ट है कि उसे यह मालूम था कि स्याई बर्नोबस्त शब्द के  
 विपरीत रूप से दो भिन्न अर्थ हो सकते थे
- 80 सोवेट फ्रेजर पूर्वोद्धत प० 154 5

पूर्वोद्धत, पृ० 122-30 तहमकर, पूर्वोद्धत, पृ० 69-73 प्रधान और भागवत पूर्वोद्धत पृ० 100-03 सोस भटोरियस फार ए हिस्टरी आफ दि प्रोडम मूवमेट इन इंडिया, (बर्बर्), खंड II पृ IX 196-638

- 65 उदाहरणाय 15 निसबर 1896 क प्रक के केसरी का लेख 'अतिशयत किमान को यह पढ़ान की आवश्यकता है कि उसके अधिभार क्या हैं और उन्हें वह किस प्रकार प्राप्त कर सकता है' उद्धान यह घोषणा की कि नेताओं का यह कतब्य है कि वे किसान जनता को समभाए कि यदि उनकी फसल घराब हो गई है तो उन्हें लगान चुकाने की आवश्यकता नहा है (आर० एन० पी० वस०, 19 दिस० 1896), उन्होंने इसी प्रकार म लिखा 'यदि सोप गोली की परवाहन करने अपन अधिकारों के लिए लड़न का दड निश्चय कर लें तो नेतागण उनका मुद्ध में साथ दन के लिए कतयरद हाग (प्रधान तथा भागवत पूर्वोद्धत पृ० 102) तथा देखिए रामगोपाल, पूर्वोद्धत पृ० 125-6 और तहमकर पूर्वोद्धत, पृ० 71
- 66 रामगोपाल पूर्वोद्धत, पृ० 126-9
- 67 वही उद्धत पृ० 129-30
- 68 तहमकर—पूर्वोद्धत पृ० 63 पर उद्धत
- 69 जे० पी० एम० एम०, जुलाई 1879 (खंड II स० 1) पृ० 14-20 और अक्टू० 1881 (खंड IV स० II), पृ० 54-8 एस० पृ० 256-7 रिप० आई० एन० सी० 1887 पृ० 143 इस प्रकार 1881 मे स्पाई कर निर्धारण की बवालत करते हुए कहा 'सरकार के पास अवशिष्ट एकमात्र विवरण जिसके साथ सभी उपकरणों का सुधार महत्वहीन हो जाना है' की अनुपस्थिति में अन्य उपचारों के प्रभाव की चर्चा करते हुए उन्होंने शोकाकुन होकर कहा 'भारी लगानों की वस्तु की आसान सुविधाओं ने इसे विस्मृति की नीद में मुना लिया है और वे यह मानने लगे हैं कि रोटी के टुकड़ के लिए परेशान लाधा किसान बघानिक वानुनों के रूप में पत्थर के टुकड़ों के उपहार से समुद्ध हो जाएंगे वस्तु गहरे पावों को और गहुरा करने वाली पद्धति में नव जीवन रक्त और शक्ति का संचार किए बिना किराया की मसही खाई को पाटने वाले कानूनों से बाइ लाभ नन्हीं होगा जे० पी० एम० एन० अक्टूबर (खंड IV, स० 2) पृ० 54 और 57 क्रमश
- 70 प्रस्ताव VII 1888 में प्रस्ताव पारित करने क प्रयत्न की असफलता के लिए देखिए, रिप० आई० एन० सी० 1898 पृ० 163-4 174-8
- 71 1890 का प्रस्ताव VI 1891 का III 1892 का IX, 1893 का X और XI 1894 का II 1896 का XIII 1897 का VII 1898 का VI 1900 का XXIII, 1901 का III 1902 का III 1903 का III और 1904 का III
- 72 एल० एम० घाप स्पीचेज पृ० 5 पूना सावजनिक सभा के सचिव का पत्र जे० पी० एम० एस० जनवरी 1879 (खंड I स० 3) पृ० 43-16 मई 1880 को पूना में हुई एक सावजनिक सभा में स्वीकृत 'याचिका जे० पी० एम० एस० जुलाई 1880 (खंड III स० 1) पृ० 8-9 पूना सार्व जनिक सभा का स्मरणपत्र दिनांक 2 मार्च 1881 जे० पी० एन० एम० जुलाई 1881 (खंड IV स० 1) पृ० 8-9 शंघ राजा हुसैन खां मुशी शंघ हुसैन खां और राजा रामपालसिंह आई० एन० सी० 1889 पृ० 175-6, बी० एन० घेन रिप० आई० एन० सी० 1889 पृ० 48-9 एम० मुब्रह्मण अय्यर वही पृ० 50-1 आर० एन० मयानकर, रिप० आई० एन० सी० 1890 पृ० 49 और इंडियन पालिटिकल पृ० 45-6 बी० जी० सिलक रिप० आई० एन० सी०

- 1893 प० 114 और रिप० आई० एन० सी० 1895 प० 133, जाणा पूर्वोद्धत प० 362  
 3 811, 824 5, एम० नार० सयानी, एल० सी० पी०—1897 खड XXVI स० 191  
 और सी० पी० ए० प० 365 जी० आर० एम० चितनवीस एल० सी० पी० 1898 खड  
 X XVII प० 481 पा० ए० चारलू वही प० 502 और एल० सी० पी० 1900 खड  
 XXXIX प० 146, पी० मेहता, स्पीचेज, प० 60-07, एम० एम० मालवीय रिप० आई०  
 एन० सी० 1899 प० 91 3 और रिप० आई० एन० सी० 1900 प० 99 एस० एन० बनर्जी  
 रिप० आई० एन० सी० 1900 प० 75 6 गोखले स्पीचेज प० 24 5 112 जी० एस० अय्यर  
 एच० आर०, फरवरी 1902 प० 149 51, बारहव और तेरहवें बर्षों प्रातीय सम्मेलना के  
 प्रस्ताव, मराठा 16 नवंबर 1902 और मई 1903 क्रमश
- 73 भूराजस्व के स्थाई निर्धारण की माग आर० सी० दत्त के भूमि समस्या पर लिखे गए लगभग  
 सभी लेखों में उपलब्ध है उदाहरणार्थ देखिए इंग्लैंड एंड इंडिया प० 51 133 5 फर्मिस इन  
 इंडिया प० XII स्पीचेज I प० 15 24 158 180-1 इ० एच० II प० X XI
- 74 ज्ञान प्रकाश 6 फरवरी (आर० एन० पी० बब 8 फरवरी 1879) अरणोदय 27 अप्रैल (वही  
 3 मई 1879) शिवाजी 8 अगस्त (वही 16 अगस्त 1879) सुबोध पत्रिका, 1 अगस्त (वही  
 7 अगस्त 1880), इंदु प्रकाश 7 मार्च (वही 12 मार्च 1881) अरणोदय 30 अक्टूबर (वही  
 5 नवंबर 1889, 24 मार्च 1900, 3 फरवरी 1901 ज्ञान प्रकाश 8 फरवरी (आर० एन० पी०  
 बब 10 फरवरी 1883) सोमप्रकाश 8 जनवरी (आर० एन० पी० बग 13  
 जनवरी 1883) नेटिव ओपीनियन, 1 अप्रैल 1883 हिंदू, 27 फरवरी 1884 13 सित० 1889  
 2 जून० 1891 नसीम आगरा, 23 अग० (आर० एन० पी० पी० एन० अगस्त 1884)  
 स्वदेशमित्र, 27 जुलाई (आर० एन० पी० एम० अगस्त 1885), बंगाली 28 जून 1890  
 इंदु प्रकाश 28 जून 1890 हिंदुस्तान 3 मार्च (आर० एन० पी० एन० 10 मार्च  
 1891) हिंदुस्तानी 7 अक्तू० (आर० एन० पा० एन० 15 अक्तू० 1891) हिंदुस्तानी,  
 8 नवंबर (वही 15 नवंबर 1893) विक्टोरिया पेपर 25 अक्तू० (आर० एन० पी० पी०  
 4 नवंबर 1893 पसा अखबार 13 अक्तू० (वही 20 अक्तू० 1894) केरल पत्रिका, 26  
 जनवरी (आर० एन० पी० एम० 31 जन० 1895), सियालकोट पेपर 8 अक्तू० पसा अखबार  
 7 अक्तू० (आर० एन० पी० पी० 28 अक्तू० 1899), स्वदेशमित्र 18 मार्च और 21 अगस्त  
 (आर० एन० पी० एम० 31 मार्च और 31 अगस्त 1900 क्रमश )
- 75 लड रवेपू पालिसी आफ दि गवर्नमेंट आफ इंडिया (क्लकत्ता 1902) कठिका 5  
 76 वही कठिका 5 और 6  
 77 वही, कठिका 6  
 78 वही कठिका 9
- 79 रीस पूर्वोद्धत प० 63 यह काफा आश्चर्यजनक है कि एच और तो रीस ने लगान के स्थाई  
 बंदोबस्त सबंधी कागस के अधोलन को जर्मीदार समयक नाम दे ढाला दूसरी ओर उमो प्रस्ताव  
 के तीन ही पन्नों के उपरान्त प्रत्येक जमादार के निजी स्वामित्व के स्थाई बन्दोबस्त की बगलत  
 प्रारम्भ कर दा रीस की मान्यता थी कि यह स्थाई बन्दोबस्त बगल के स्थाई बंदोबस्त से भिन्न  
 होगा (वही प० 66-9) इससे स्पष्ट है कि उसे यह मानूम था कि स्थाई बन्दोबस्त शब्द के  
 विपरीत रूप से दो भिन्न अर्थ हो सकते थे
- 80 लोवेट क्षेत्र पूर्वोद्धत प० 154 5



- 81 शाह मिन्मटी इपस आफ इंडियन फर्मिस, पृ० 196 और देखिए, पृ० 200
- 82 थामस पूर्वोद्धृत पृ० 123, लोकनाथन, दि इकोनामिक्स आफ गोखले', इंडियन जर्नल आफ इकोनामिक्स जनवरी 1842, खंड XXII स० 3 पृ० 228, बी० आर० मिथ सैंड रेवेन्यू पालिसी इन दि यूनाइटेड प्राविसेज (बनारस 1942) पृ 37 39 हा लोकनाथन ने गोखले को स्पाई बदोबस्त का समर्थन करने के दोष से मुक्त कर दिया
- 83 पी० सी० घोष 'दि डेवलपमेंट आफ इंडियन नेशनल काप्रेस 1892 1909 (कलकत्ता, 1960) पृ० 41 3
- 84 वही पृ० 44 यह एक भारी धारण्य का विषय है जसाकि बाद में लिखा जाएगा, भाषण में कोई ऐसा अवतरण ही न था, जिसको इस ढंग से व्याख्या की जा सके
- 85 बी० बी० मिथ्रा दि इंडियन मिडिल क्लासेज—देयर प्रोप इन माहन टाइम्स (सन् 1961), पृ० 350 यह भी एक सयोग है कि जिस वय यह प्रस्ताव भन्ने ही मिथ्रा के अधिप्राय के अनुकूल नहीं पारित हुआ, वह वय 1888 न होकर 1889 या 1888 में तो यह मामला कांग्रेस की विभिन्न स्पाई समितिया के सदस्या के पास उनकी राय जानने के लिए ही भजा गया था (देखिए प्रस्ताव XIV)
- 86 वही पृ० 349 50
- 87 पी० स्पीयर इटिया ए माहन हिस्टरी (ए० एन० एन० आबर यू० एस० ए० 1961) पृ० 312 इसी प्रकार एच० एल० सिंह लिखते हैं जहां तक भूमिधारी वर्गों का संबंध है कांग्रेस की नीति अधिकांशत उनके पक्ष में थी कांग्रेस स्पाई बदोबस्त के विस्तार की समझ में जो किसानों और जमादारों के लिए बहुत अधिक और रयन तथा राय के लिए बहुत ही कम उपयोगी था कांग्रेस की इस नीति का लेखा जोखा करते हुए साइ एलमिन ने सत्य को ही उजागर किया कि वगान के जमादार बड़े ही शक्तिशाली थे और उस प्रांत के लेखका और वक्ताओं के साथ उनके व्यापारिक संबंध थे प्रान्तस एंड पालिसीज आफ दि ब्रिटिश इन इंडिया 1885 1898 (बर्दई 1963) पृ० 217
- 88 एन० एम० घोष रीपोजेक्ट पृ० 5
- 89 रानाडे एसेज पृ० 327
- 90 जे० पी० एस० एम० जनवरी 1874 (खंड VI स० 3) पृ० 19 20
- 91 आर० एन० पी० बब०, 12 मार्च 1881
- 92 और देखिए मरान 22 अगस्त 1886 और बंगाल पब्लिक ओपीरियन (बी० ओ० आई०, 31 जनवरी 1884)
- 93 रिप० आई० एन० सी 1888 पृ० 175 1889 के कांग्रेस के अधिवेशन में स्पाई बदोबस्त के प्रस्ताव का प्रस्तोता बी० एन० मेन ने इस पण पर बल दिया था रिप० आई० एन० सी० 1889 पृ० 48-9) इसी प्रकार 1890 के कांग्रेस के अधिवेशन में जानकानाथ बोस ने विश्वास लिखा कि सारे बर्दई और मद्रास में हुए विमाना के स्वत्वाधिकार वाला स्पाई बदोबस्त ही देखा चाहते हैं (रिप आई० एन० सी० 1890 पृ० 51 2)
- 94 और देखें एम० एन० ब्रनर्जी रिप० आई० एन० सी० 1900 पृ० 75-6
- 95 रिप० आई० एन० सी० 1893 पृ० 14 उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि सरकार देश के विभिन्न भागों में प्रचलित स्थिति के अनुकूल जमादारों अथवा शर्मों के मानिक अथवा किसानों के साथ बातचीत कर सकती है

- 96 रिप० आइ० एन० सी० 1894 प० 38 और देखिए पी० मेहुता, स्पाचज, प० 606-07, पी० ए० चार्ल्स एल० सी० पी० 1900 खड XXXIX प० 147
- 97 राय इंडियन फर्मिस प० 56-7
- 98 एच० आर० फरवरी 1902, प० 149-51 और देखिए गोखले स्पीचेज प 24
- 99 दत्त पीजटरी इन बंगाल (कलकत्ता 1874) प० 46 और आग
- 100 बगवासी 10 अगस्त (आर० एन० पी० बब०, 17 अगस्त 1895)
- 101 दत्त इंग्लिश ऐंड इंडिया प० 134
- 102 सी० पी० ए० प० 486 पी० सी० घोष को गुमराह करने वाली बात बदाचित आर० सी० दत्त को भारत के दूसरे भाग म बंगाल प्रशासन के विस्तार की माग थी परंतु दत्त विस्तार की माग कर रहे थे न कि जमींदारी पट्टेदारी की वह उस पद्धति की माग कर रहे थे जिसमें कुल उपज का 1/6 भाग ही किराए के रूप में चुकाना होता है उनके भाषण का पूरा वाक्य इस प्रकार है बंगाल नियम का भारत के दूसरे भागों में विस्तार का लिए दूसरे प्रांतों में कुल उपज के 1/6 भाग को किसान से वसूल किए जाने वाले धरती के किराए की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए तब देखिए कि अकाम को रोकने की समस्या कसे सुलभती है (वही प० 481)
- 103 दत्त ओपेन लेटर्स प० 65 और देखिए वही प० 74 स्पीचेज II प० 178 ई० एच० II प० XI
- 104 उदाहरणाय देखिए पूना सावजनिक सभा के सचिव का पत्र जे० पी० एस० एल० जनवरी 1879 (खड I स० 3) प० 43 रानाडे जे० पी० एस० एल० जुलाई 1879 (खड II स० 1) प० 16 एसज प० 256 16 मई 1880 की पूना की जन सभा में स्वीकृत याचिका जे० पी० एस० एल० जलाई 1880 (खड III स० 1) प० 9 ज्ञान प्रकाश 8 फरवरी (आर० एन० पी० बब० 10 फरवरी 1883 आई० एन० सी०—1888 1889 1890 1891 1892 1893 1895 1897 और 1900 के प्रस्ताव क्रमश XIV VII VI III IX X, XIV VII और XXIII बी० एन० सेन रिप० आई० एन० सी० 1889 प० 48 जोशी पूर्वोद्धत प० 361 811 854-5 आर० एन० मधोलकर इंडियन पालिटिक्स प० 45-6 पी० ए० चार्ल्स एल० सी० पी० 1898 खड XXXVII प० 502 और वही, 1900 खड XXXIX प० 146 सी० शंकरन नायर सी० पी० ए० प० 384-5 दत्त इंग्लिश ऐंड इंडिया, प० 51 134-5 स्पीचेज II प० 168 गोखले स्पीचेज प० 24
- 105 रानाडे जे० पी० एस० एल० जुलाई 1879 (खड II स० 1) प० 14-15 16 मई 1880 को पूना में हुई जन सभा में स्वीकृत याचिका जे० पी० एस० एल० जुलाई 1880 (खड III स० 3) प० 9 रिप० आई० एन० सी० 1889 प० 48-9 आई० एन० सी० 1889 1893 1894 1898 1902 1903 और 1904 के प्रस्ताव VI XI II III III, और VI (बी) क्रमश जोशी पूर्वोद्धत प० 364 811 दत्त इंग्लिश ऐंड इंडिया प० 91 2 स्पीचेज I प० 19-20 स्पीचेज II प० 40-1 172 3 फर्मिस इन इंडिया प० XII ई एच II प० XXI 273-291 आर० एन० मधोलकर इंडियन पालिटिक्स प० 45 6 गोखले, स्पीचेज प० 25
- 106 दत्त ई० एच० I प० 123 5 135-40 152, 168 और देखिए, दत्त इंग्लिश ऐंड इंडिया प० 49-50 ओपेन लेटर्स प० 31 ई० एच० II प० 77-8 दत्त ने एलिफिस्टन व रयतबाड़ी पद्धति के प्रबन समर्थक होने पर भी ग्राम समुदाय और ग्राम पंचायत आदि के बचाने की चेष्टा के लिए उसकी प्रशंसा की (ई० एच० I प० 352-65)
- 107 16 मई 1880 को पूना में हुई जन सभा में स्वीकृत याचिका जे० पी० एस० एल०

- (खंड III सं० 1), पृ० 89 रामाडे, एजेज, प० 327, जे० पी० एम० एम०, अक्टूबर 1881 (खंड IV सं० 2) प० 56, वहाँ जनवरी 1884 (खंड VI सं० 3) प० 21 वहाँ, अप्रैल 1884 (खंड VI सं० 4) प० 55, शंख राजा हुसन खा रिप० आई० एन० सी० 1888 प० 175 आर० एन० मधोलकर, रिप० एन० सी० 1890 पृ० 49 के० जी० देशपांडे, रिप० आई० एन० सी० 1891 पृ० 33 आई० एन० सी० 1899 का प्रस्ताव II (बी) पी० ए० चार्ल्स एल० सी० पी० 1900 खंड XXXIX प० 146 पा० महता, स्पीचज प० 607 दत्त स्पीचज I प० 181 82 ओपेन लेटम प० 48 66 79, फर्मिस इन इंडिया पृ० XV, स्पीचज II पृ० 187 8 ई० एच० II पृ० 514, गोखले, प्रासीडिंग आफ दि कॉमिल आफ दि गवर्नर आफ बावे 190 खंड XXXIV प० 245 एल० ए० जी० अम्यर रिप० आई० एन० सी० 1903 प० 56
- 108 दत्त ई० एच० II पृ० 503-04 एल० गोयान, दि वामसरायल्टी आफ लाड रिपन (लंदन, 1953) प० 189
- 109 पनाह जे० पी० एम० एम०, जनवरी 1884 (खंड VI सं० 3) प० 4-11, साधारणी, 23 नव०, सजीवनी, 22 नव० समाचार चंद्रिका 24 नव० (आर० एन० पी० बग० 29 नव० 1884), प्रामवत प्रकाशिका, 29 नव० (वहाँ, 6 दिस० 1884), प्रतिकार 12 दिस० (वही 20 दिस० 1884), आई० एन० सी० 1893, 1894 1898 और 1899 का प्रस्ताव क्रमशः XI II, VI और II (बी) आर० एन० मधोलकर रिप० आई० एन० सी० 1896 पृ० 159, रिप० आई० एन० सी० 1901 प० 87 पी० मेहता स्पीचज पृ० 607, दत्त, स्पीचज I प० 158-60, आगन लेटम, प० 35, 41 53-4, 79, फर्मिस इन इंडिया प० XIII, XV, स्पीचज II पृ० 9, ई० एच० I प० XI XII 503 504
- 110 आई० एन० सी० 1889 1890 1902 1903 और 1904 के प्रस्ताव क्रमशः VII, VI, III और III (बी) दत्त, स्पीचज I प० 181 2 ई० एच० पृ० 184, गोखले, स्पीचज, प० 24, आर० एन० मधोलकर रिप० आई० एन० सी० 1901 पृ० 87
- 110-ए दत्त स्पीचज II प० 173 तथा देविए, गोखले, स्पीचज पृ० 25
- 111 आई० एन० सी० 1896 1901 1902 1903 और 1904 के प्रस्ताव क्रमशः XIII III III, III और III
- 112 रामाडे, जे० पी० एम० एम० जुलाई 1879 (खंड II सं० 1) पृ० 17 8 इदु प्रकाश, 10 मार्च (आर० एन० पी० बब०, 15 मार्च 1879), तिवाजी 8 अगस्त (वही 16 अगस्त 1879), इदु प्रकाश 7 मार्च (वही, 12 मार्च 1881) पूना सांख्यिक समत का स्मरणपत्र जे० पी० एम० एम०, जुलाई 1881 (खंड IV सं० 1), प० 8, ए० बी० पी०, 5 अक्टूबर 1882 28 नव० 1889 27 मार्च 1900 बी० एन० सेन, रिप० आई० एन० सी० 1889 पृ० 48 जे० एन० बोस रिप० आई० एन० सी० 1890 पृ० 51 ए० नदी इंडियन पालिटिकल पृ० 33-4 मासवीय रिप० आई० एन० सी० 1900 प० 99 दत्त इग्लैंड ऐंड इंडिया, पृ० 13 134 स्पीचज I पृ० 15-18 180-1, सी० पा० ए०, पृ० 481 ओपेन लेटम पृ० 59 60 64-5 स्पीचज II पृ० 45 40 169 ई० एच० I, पृ० 94-6, ई० एच० II पृ० X 461, 509 और जे० एन० गुप्ता श्री साइफ़ ऐंड बक आफ आर० सी० दत्त (लंदन 1911) पुस्तक पृ० 333-4 पर उद्धृत एम० एन० बनर्जी सी० पी० ए०, पृ० 698 एल० एम० घोष सा० पी० ए०, पृ० 759

- 3 दत्त फ्रांसिस मिनिटस पृ० IV तथा दक्षिण स्पीचेज I, पृ० 18 आपन लेटस प० 64 ई० एच II पृ० 94 5
- 4 दत्त, सी० पी० ए०, पृ० 484 आपन लेटस, पृ० 22 61-4 फर्मिंग इन इंडिया प० IX 106-07 ई० एच० II, 461 इस सबध म दत्त के विवेचन म स्पष्ट गलती यह है कि वह यह दखने म चुब गए कि बंगाल म वास्तविक किसानो और जमींदारो के मध्य विचोलिए ये जमींदार के पास तो वादिक किसान की ओर से 1/5 भाग से अधिक नही पहुचता था जबकि वास्तव मे किसान बेचारे को शायद अपनी कुल उपज के प्रतिशत का बहुत बडा भाग देना पडता था और सचमुच ही यह सब कुछ रयतवादी म भी हो रहा था
- 5 राय इंडियन फर्मिस, प० 55-6 और देखिए एस० एन० वनर्जी स्पीचेज II 12 3, इंडियन सेक्टरेटर 25 सितंबर (आर० एन० पी० बव० 1 अक्टूबर 1881) ग्रामवत्त प्रकाशिका 16 फरवरी (आर० एन० पी० बग० 1 माघ 1884) मराठा 17 फरवरी 1884 बंगाली 28 जून 1890 और आगे देखिए बंगाल रट बिल की धारा जसा पहले निर्देश किया जा चुका है, एक नवयुवक के रूप मे दत्त ने स्वयं 1874 म अमहाय किसानो का दमन करने और उह दरिद्र बनाने की जमींदारो को अनुमति देन वाले 1793 के स्थाई बंदोबस्त की निंदा की थी देखिए, 'पीजटरी आफ बंगाल', पृ० X 46 और आगे 1888 म जी० बी० जोशी ने बंगाल मे ऊंचे किराए सागू होन की निंदा लगातार की थी पूर्वोद्धत, पृ० 884
- 6 दत्त इंग्लड ऐंड इंडिया, पृ० 90-1, 116 स्पीचेज I पृ० 15 6 180 इंडियन पालिटिक्स, पृ० 55 सा० पी० ए० प० 481 ओपेन लेटस, प० 18 9 59 61 65 78 फ्रांसिस मिनिटस पृ० VII VIII स्पीचेज II, प० 4 5 170 ई० एच० II, प० 263 4 437, 460-1
- 7 लड रवेयू पालिमी आफ गवर्नमट आफ इंडिया 1902 कडिका 9
- 8 दत्त स्पीचेज II पृ० 170
- 9 दत्त पीजटरी आफ बंगाल पृ० 83 इस कायवाही के नतिक उद्देश्य की चर्चा दत्त ने निम्न लिखित रूप म प्रस्तुत की है और फिर यह जमींदार है कौन ? वही जो किराया बढ़ाने के लिए किसान को परेशान करता है ? वही जो स्वयं महलो के शहर म अपने आरामदेह घर मे चुपचाप बठा रहता है और उसके मजदूर प्रात से साय तक खेतो मे धम करते हैं और रात भर जागते रहते हैं वे जठ की तपती दुपहरी मे सावन के बरसते पानी और पीप की सफ्त कपाने वाली सर्दी म खुले आसमान के नीचे काम करते हैं वे जमीन जोतते हैं और फसल काटते हैं पीधे लगाते हैं और फल बीनते हैं उह इसलिये परेशान किया जाता है कि वे अपने अथक धम के फल के भाग पर निरंतर बढ़ती माग को पूरा करन से इनकार करते हैं जमींदारो के पास किसानो को तग करने की शक्ति कहा से आती है ? क्या एक निवन्धमे आदमी को किसी मेहनती गरीब को परेशान करने का नतिक अधिकार प्राप्त है ? इस काय का समथन करने वाली आचारसंहिता सचमुच ही विचित्र होगी (पृ० 87)
- 0 उनके देष्टिकोण का तक अधिकांशतया असदिग्ध था हा यह कभी कभी स्पष्ट रूप से प्रकट किया जाता था प्रमाण रूप मे देखिए सी० जे० ओ० डोनिल की समीक्षा दि रुइन आफ इन्डियन प्राविस जे० पी० एस० एच०, जनवरी 1881 (खंड III स० 3) प० 38 इडु प्रकाश, 7 माघ (आर० एन० पी० बव० 12 माघ 1881) हिंदू 14 अप्रैल 1884 जोशी पूर्वोद्धत 885 दत्त इंग्लड ऐंड इंडिया प० 130 ए बी० पी० 28 जुलाई 1904
- 1 दत्त ई० एच I पृ० 128, 232 3 190, 362, 365 दत्त ने कपनी के एक डायरेक्टर हेनरी

सेंट जान टवकर की पुस्तक मे निम्नलिखित अवतरण को उद्धृत किया इस न ही छुपाया जा सकता है और न ही नकारा जा सकता है कि इस रयतवादी पद्धति का उद्देश्य किराए के रूप मे मिलने वाले सरकारी राजस्व की अधिकाधिक प्राप्ति है

- 122 वही प० 362
- 123 रानाडे एसेज, प० 29 30 327 सी० जे० आ० डानिल की समीक्षा रुदन आफ इंडियन प्रॉविंस' ज० पी० एस० एस०, जाबरी 1881 (खंड III स० 3) एस० एस० अम्यर रिप० आई० एन० सी० 1886, प० 62 एच० ए० रहीम रिप० आई० एन० सी० 1890, प० 55 जी० सी० सिंह रिप० आई० एन० सी० 1893 प० 115-6 केरल पत्रिका 26 जनवरी (आर० एन० पी० एम०, 31 जनवरी 1895) मालवीय स्पीचेज प० 266-8, दत्त ह्यलड एंड इंडिया, प० 13 स्पीचेज I, प० 15 सी० पी० ए० प० 482 ओपेन लेटस प० 59, 74-6 78, और देखिए पीछे 40-1 पाद टिप्पणी उदाहरणाम आर० मा० दत्त ने विभिन्न प्रांतों के किराया कानूनों को पूरा समयत दिया और किमारों की सुरक्षा के लिए इससे भी कोई बड़ा माघन अपनाने की वकालत की देखिए फरवरी 1899 को अवधि म पायनियर को लिखे पत्र तथा 14 सित० 1900 को ऐंटनी मकडानन को लिखा पत्र, जे० एन० गुप्ता पूर्वोद्धत प० 349 पर स्पीचेज II प० 178 और ई० एच० II प० 268 71 458-60 467
- 124 एस० एन० बनर्जी स्पीचेज II, प० 10-11 हिंदू 14 अप्रैल 1884 ए० बी० पी०, 22 नवंबर 1883 3 फरवरी 1901 दत्त, ई० एच० I, प० 96 133 और ज० एन० गुप्ता पूर्वोद्धत प० 334 पर, और देखिए ए० बी० पी० 25 जन० 1902 यहा यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रवादियो ने सरकारी सख को बड़ा ही सफाई से मोड़ दिया कि जमादारी पद्धति क अतगत जहां किराए का लाभ खून चूसने वाले जमादारवग को मिलता है वहा रयतवादी म यह खून चूसने वाली सस्था सरकार है
- 125 रानाडे, एसेज प० 287 290 दत्त ई० एच० I प० 131 2 ई० एच० II प० 43
- 126 रानाडे जे० पी० एस० एस० जुलाई 1879 (खंड II स० 1) प० 2 17 18 एसेज प० 239-42 पूना सावजनिक सभा का स्मरणपत्र जे० पी० एस० एस० जुलाई 1881 (खंड IV स० 1) प० 9 ब्रह्मो पत्रिका ओपीनियन 28 अक्टूबर 1880 ए० बी० पी० 22 नवंबर 1883 मराठा 27 जुलाई 1890 इंदु प्रकाश 28 जुलाई 1890 बी० एन० सन रिप० आई० एन० सी० 1890 प० 50 ए० बी० पी० 20 फरवरी 1899 दत्त ई० एच० I प० 132 दत्त ई० एच० II प० 52 58 86 88-9 264 267 दत्त ने अपने ग्रंथ 'इकोनामिक हिस्टरी आफ इंडिया क द्वितीय खंड मे टिप्पणी की कि भ्राम समुदायों और बिचौलिया जमींदारों के अभाव म पंजाब में व्यापारी सराफा और रकम उधार देने वाले आदि के रूप मे एक नया वर्ग अस्तित्त्व में आ गया है जो किसी भी देश के मुलीनपन्न का निदृष्टतम रूप है (ई० एच० II प० 89-90)

## कृषि II

जमींदारों को इस स्थिति में रखना चाहिए कि वे वास्तुकारों का दमन न कर सकें। साथ ही वास्तुकारों को भी भूस्वामियों का अपमानित और तिरस्कृत करने के लिए प्राप्ताहित नहीं करना चाहिए। सामाजिक शिष्टाचार का निर्वाह इस रूप में हो कि भूमिपति वास्तुकार से प्रेम करें और वास्तुकार भूमिपतियों का आदर करें।  
अमृत बाजार पत्रिका, 8 जनवरी 1885

समाज के एक वर्ग को कठोर श्रम और दासता के बंधन में जकड़ने वाली तथा दूसरे वर्ग को गैरश्रमिक श्रम से सबंधा छूट, सुख चैन और पूर्ण अवकाश की सुविधा जुटाने वाली प्रवृत्तियों के प्रमुख कारण कुछ भी क्यों न रहे हों 'परंतु अब यह नितांत स्पष्ट है कि आधुनिक सम्यता की प्रवृत्तियाँ तथा समता की पनपती भावना इन दोनों वर्गों में असमान और अयोग्यपूर्ण सबंधों को दीर्घकाल तक बने नहीं रहने देंगी। देर सवेर समाज की पुनर्व्यवस्था होना निश्चित है, और अच्छा यही है कि हम बिना किसी प्रहार की शिवायत किए और बुडबुडाए उस समय के स्वागत के लिए तैयार रहे।'।

मराठा 21 अक्टूबर, 1893

यदि अंगरेजों के दमन को चिंगारी की सजा दी जाए तो राजाओं और जमींदारों के दमन को शोले की सजा देनी पड़ेगी।

बगनिवासी, 30 अक्टूबर, 1891

### किसान और जमींदार

भूमि जोतने वाले की उपज पर केवल कर कमचारी का ही अधिकार नहीं था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी मद्रास, मध्य भारत के प्रांतों में, उत्तरी पश्चिमी प्रांत तथा अवध और बंबई तथा पंजाब के छोटे से भागों के जमींदारी क्षेत्रों में भूमि जोतने वाला वास्तुकार था जो जमींदार को किराया चुकाता था, उससे ही जमींदार सरकार को लगान का भुगतान करता था। इसके साथ ही साथ इन सभी इलाकों में किराया लेने वाले

जमींदार और किराया चुकाने वाले तथा असल में ही जमीन जोतने वाले किसानों के बीच बिचौलियों की संख्या निरंतर कई गुना बढ़ती जा रही थी। इधर रयतवाड़ी इलाका में भी धीरे धीरे सुदकास्त की प्रणाली विच्छिन्न तथा विलुप्त होती जा रही थी। मानिक किसान धीरे धीरे अपनी धरती ऋणदाता, व्यापारी तथा व्यवसायी बग के हाथों बेचते जा रहे थे। व्यापारी लोग भूमि के मालिक तो बन जाते थे पर धरती जोतते नहीं थे। वे उन पुराने किसान मालिकों को धरती पर बन तो रहन देते थे परंतु अब उनकी स्थिति दरिद्र व अमहाय किराएदार किसान की हो जाती थी। दश के देहाता में निरंतर बढ़ते हुए किरायों तथा धरती को खाली करने की घटनाओं ने विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर दी थी और किसी न किसी रूप में किसानों और जमींदारों के पारस्परिक संबंधों के प्रश्न को देश की एक महत्वपूर्ण आर्थिक तथा राजनीतिक समस्या बना दिया था। अतः सरकार किराए के बमरतोड़ भार से दबे किसानों को कुछ राहत देने के लिए तथा विभिन्न प्रांतों में नास्तकारी और किराए संबंधी कानूनों की श्रृंखला बनाने के लिए विवश हो गई। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने रयतवाड़ी इलाकों में मनमर्जी पर रखे कास्तकारों की समस्या की पूर्ण रूप से ही उपेक्षा कर दी।

यह काफी आश्चर्यजनक बात है कि इस प्रश्न पर राष्ट्रवादी नेताओं की नीति न केवल अनिश्चित थी प्रत्युत इस पर उन्होंने विशेष ध्यान भी नहीं दिया। इन नेताओं ने न तो किसान और जमींदार के बीच के प्रश्न को प्रमुख आर्थिक समस्या माना और न ही किसानों के लक्ष्य को सामान्य राजनीतिक आंदोलन से जोड़ा। राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा किसानों की समस्याओं की उपेक्षा के परिमाण को इस तथ्य में नापा जा सकता है समीक्षाधीन अवधि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उनके संबंध में वास्तव में ही कुछ भी नहीं कहा परंतु उस समय देश के सामने आने वाली आर्थिक यथार्थताओं ने उत्तरोत्तर भूमने वाले, राजनीति में सनिय और सजीव भाग लेने वाले नेताओं से ता इन समस्याओं से आलस मुदने की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। इन नेताओं ने इन समस्याओं को दो रूप में लिया सामान्य और विशिष्ट। सामान्य रूप के अंतर्गत इन नेताओं ने किसानों का अस्पष्ट रूप से ही पक्ष लेते हुए छिटपुट टिप्पणियाँ की तथा सामान्य उपचार सुभाएँ और विशिष्ट रूप के अंतर्गत उन्होंने सरकार द्वारा पारित विभिन्न नास्तकारी और किराया संबंधी अधिनियमों पर अपने मत प्रकट किए। यहाँ उन्हें रोग विशेष के लिए निश्चित उपचार सुभाएँ या अथवा अपना स्पष्ट मत प्रकट करना था। अतः उन्हें पहले तो ही किसानों अथवा जमींदारों के समर्थक के रूप में आना पड़ा।

सामान्य रूप के अंतर्गत राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने जमींदारी इलाका में किसानों के प्रति मानवीय चिंता प्रकट की तथा जमींदारों द्वारा किसानों के सामान्य दमन बमरतोड़ किराया की बमूली और किसानों की बदसली के प्रति विरोध प्रकट किया। यह विरोध कभी कभी तोखी भाषा में भी होता था। उदाहरणार्थ, शक्तिशाली जमींदारों द्वारा किसानों के दमन की आलोचना करते हुए बंगाली में अपने 9 अक्टूबर 1882 के अंक में लिखा किसी भी प्रकार का अत्याचार निन्दनीय है। अत्याचारी भन ही गोरा हो अथवा शक्तिशाली आत्मी दमन करने वाला भन ही भारत में जमा और पना हो अथवा दूर

पश्चिम से आया हो, सवया और समान रूप से घृणा का पात्र है।<sup>3</sup> दस हजार व्यक्तियों के खून पीसने की बर्माई पर एक व्यक्ति को जीवन की सभी सुख सुविधाएँ तथा विलासिताएँ जुटाने वाली लगान सग्रह पद्धति को अमात्य ठहराते हुए 'सोम प्रकाश' ने 24 जुलाई, 1882 के अंक में व्यंग्यपूर्वक पूछा 'एक के श्रम का दूसरे द्वारा लाभ उठवाया जाना और गुलछरों उड़ाना कहा का 'याय है ?' उसने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया कि 'समय की गति के साथ जमींदार उत्तरोत्तर जितना अधिक शक्तिशाली हुआ है, किसान उत्तरोत्तर उतना ही अधिक दीन हीन हुआ है।'<sup>4</sup> 14 जून, 1884 के अंक में 'बगबासी' ने गांव के जमींदार को सभी प्रकार के बानूनों का उत्लघन करने वाला तथा बगाल का सबसे बड़ा उत्पाती बताया।<sup>5</sup> 'बगनिवासी' ने 30 अक्टूबर, 1891 में जमींदारों, उनके गुमास्तों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा किसानों के अमानवीय और अकथनीय दमन की निंदा करते हुए एक लंबा और अध्रूण सपादकीय प्रकाशित किया। उसने इस संबंध में शिक्षित लोगों की अवमण्यता तथा उपेक्षा वृत्ति की आलोचना करते हुए लिखा

यदि हमारे अपने ही देशवासी (जमींदार और उनके दलाल) साधारण सा अधिकार पाकर इतना भारी अत्याचार और दमन कर सकते हैं तो असीम शक्तियों से संपन्न विदेशी जिलाधीश के अत्याचार के विरुद्ध चीखा चिल्लाहट करना कहा तक उचित है ? यदि अंगरेजों द्वारा किए गए दमन को चिंता ही कहा जाए तो इन जमींदारों और राजाओं द्वारा किए जा रहे दमन को धधकते हुए शोले की सजा दी जानी चाहिए।<sup>6</sup>

उत्तरी पश्चिमी प्रांत और अवध में उत्तरी भारत के कांग्रेस के मुस्लिम समर्थकों में अपनी सज्जाद हुमन द्वारा सपादित प्रमुख हास्य व्यंग्य प्रधान पत्र 'जबध पत्र' के 18 जनवरी 1894 के अंक में एक काटून प्रकाशित हुआ। इसमें अधनगे बदन और नंगे परा दो किसान एक जमींदार को पालकी में उठाए हुए चित्रित किए गए थे। बड़ी तोड़वाले जमींदार न चमकीले गहने और 'स्टार आफ इंडिया का तमगा पहन रहा था। कार्टून का शीर्षक था 'अकाल का कारण'। उन दोनों में एक किसान दूसरे साथी से कह रहा था 'भाई इसका बोझ तो हमारा दम तोड़ देगा, क्यों न इस पाजी को फेंक दिया जाए ?'<sup>7</sup> मालाबार से निकलने वाली, के० पी० कुरुणाकर मेनन द्वारा सपादित, 'केरल पत्रिका' ने अपने 21 मार्च 1896 के अंक में बार बार होने वाले मोपला बलवों के लिए, जमींदारों द्वारा किए गए असहनीय दमन से उत्पन्न गरीबी को उत्तरदायी बताया और अत्याचारी जमींदारों को सभी वर्गों और समुदायों के किसानों का समान रूप से क्रूरतापूर्वक दमन करने वाला घोषित किया।<sup>8</sup> 4 जुलाई 1896 के अंक में 'केरल पत्रिका' ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि उसने जमींदारों का दमन न रोकता तो न केवल मोपलों के बलवें नहीं रुक पाएंगे प्रत्युत नायर लोग भी विद्रोह पर उतर आएंगे।<sup>9</sup>

कुछ एक भारतीय जननेताओं ने 1870 के आसपास जमींदारी प्रथा की निंदा की। जमींदारों पर सशक्त प्रहार बकिमचंद्र चटर्जी ने अपने बगदशन के अंतगत समय' लेख में किया।<sup>10</sup> युवक नेता आर० सी० दत्त ने चटर्जी महादय का अनुसरण किया।<sup>11</sup> 17 फरवरी 1884 को 'मराठा' ने अपने एक लंबे लेख में जमींदारी पद्धति पर तीखा प्रहार





समयन किया तथा काश्नकारी अधिकारो को और अधिक सुदृढ बनाने के पक्ष में प्रबल तक दिए।<sup>17</sup> जोशी ने अधिकारियो में बर्बई के नितान असुरक्षित उपकाश्नकारोवाले रयतवाडी इलाके में भी कानूनी सरक्षण के विस्तार का अनुरोध किया।<sup>18</sup>

यह स्वाभाविक ही था कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान जमींदारी प्रणाली के उमूलन की व्यापक माग तो नहीं की गई परंतु यह कम महत्वपूर्ण नहीं कि यह माग क्यों उठाई गई। इस प्रकार 2 अक्टूबर 1881 के अक में इंडियन स्पेक्टेटर ने सरकार से सारी जमींदारी खरीदने और फिर सीधे किसानों से समझौता करने का अनुरोध किया।<sup>19</sup> 24 जुलाई 1882 के अक में 'साम प्रकाश' ने सरकार को रूस सरकार के आदर्श उदाहरण का अनुकरण करने का उपदेश दिया और कहा कि सरकार जमींदारी प्रथा समाप्त कर दे। जमींदारों को बीस वर्षों में हाने वाले लाभ के बराबर का धन उसकी जमीन के मूल्य के रूप में देकर उनका स्वामित्व समाप्त कर दिया जाए। यह धन आधा सरकार जुटाए और आधे की व्यवस्था किसान करें।<sup>20</sup> कभी कभी भारतीय नेता माग के प्रति टालमटोल काम लेते थे और जमींदारी प्रणाली को एक सिद्ध तथ्य मानकर जमींदार और पट्टेदार के मध्य स्याई समझौते की क्वालत करत थे।<sup>1</sup>

12 जून, 1880 के अक में बंगाली न बंगाल के स्याई बदोवस्त की एक और मजेदार आलोचना प्रस्तुत की। बंगाली पत्र न दृढ स्वर में कहा कि बंगाल में औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधिया का नितान अभाव है। जमींदारी ही वहा पूजी के निश्चित लाभप्रद निवेश का एकमात्र अवशिष्ट साधन है। यही कारण है कि पूजी निवेश की प्रवृत्ति उद्योग की अपेक्षा जमींदारी की ओर हो रही है। दो वर्ष पश्चात 28 जनवरी 1882 के अक में बंगाली ने अपनी आलोचना दोहराते हुए अपना मत प्रकट किया कि जमींदारी पद्धति का प्रवृत्तन बंगाल और बर्बई के औद्योगिक और व्यापारिक स्तर का उल्लेखनीय अंतर स्पष्ट करता है।

इनके विपरीत सामान्य आधार पर जमींदारों अथवा अथ बड़े बड़े भूखंडों के स्वामियों के हिता के भारतीय नेताओं द्वारा समयन के उदाहरण बहुत ही कम थे। बंगाल में 'बंगाली' ने पट्टेदारों के समयन की अपनी पहली नीति स हटते हुए 19 मार्च 1887 के अक में सरकार से पूर्वी बंगाल में किसान सगठना का तोड़ने के उपाय करने का और किसानों को उचित किराये के भुगतान की अनिवार्यता से परिचित कराने का अनु रोध किया। 20 फरवरी 1899 के अक में अमृत बाजार पत्रिका ने भी दावा किया कि अगरेजी राज्य की अकालो, कृषि सबधित लागो के विप्लवों तथा अनेक अन्यान्य बुराइयों में सुरक्षा जमींदारों के अधिकारों और सुविधाओं को बनाए रखने पर ही निर्भर है न कि उनके विनाश में। एक वर्ष पश्चात इसी पत्रिका ने अपने 12 जनवरी 1900 के अक में सरकार से अनुरोध किया कि वह या तो जमींदारों के प्रति अपनी कठोरता की नीति में मद्दुता लाए या उन्हें किसानों से किराया वसूल करने की सुविधाएं जुटाए। 'केसरी' ने 18 अक्टूबर 1881 के अक में शिकायत की कि देश के दूसरे भाग में, बर्बई के सतारा तथा अथ दूसरे जिलों में किसानों से जमीन के निधारण लगाना की वसूली करने में इमामदारों को सफल बनाने के लिए अधिकारियों ने उनकी आवश्यक तथा अपक्षित

किया। जैसा कि हम जागे विवेचन करेंगे, बंगाल किराया बिल पर मतभेद के समय अनेक भारतीय मस्थाआ और राष्ट्रवादी नताआ न किसान समर्थक दृष्टिकोण अपनाया। बाद में पश्वीशचन्द्र राय ने अपने लो लेखा, 1895 में प्रकाशित 'पावर्टी प्राब्लम्स इन इंडिया' और 1901 में प्रकाशित 'दि काजेज आफ इंडियन फार्मिंग में जमींदारी प्रणाली और जमींदारों के दमन को ही योग्य की दरिद्रता के लिए उत्तरदायी माना।' जी०वी० जोशी ने जमींदारी की विस्तृत आलोचना की। उन्होंने 1890 में प्रकाशित अपने निबंध 'इकोनामिक सिच्युएशन इन इंडिया' में जमींदारी और रयतबा... क्षेत्रों की बुराइयों की तफसील में आलोचना की। उन्होंने लिखा कि सारे देश... आगे धरती को किराए पर देने की घटनाएँ बढ़ रही हैं। विचो... रखे काश्तकारों की सरया कई गुना बढ़ गई है। एक ओर जनसं... और गैरकृषि उद्योग में बराबर ह्रास हान से किसानों में घ... और प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न हो गई है और इस स्थिति... जमींदारों ने किसानों को गगनचुंबी किराया देने के लिए बा... किराया और काश्तकारी की असुरक्षा का दुष्परिणाम यह है... जोतने वाले किसान का धरती को सुधारने का निश्चयान... है।<sup>12</sup> जोशी जी के निबंध का संक्षेप इस प्रकार है



किया। जैसा कि हम आगे विवेचन करेंगे, बंगाल किराया बिल पर मतभेद के समय अनेक भारतीय सस्थाओं और राष्ट्रवादी नेताओं ने किसान समर्थक दृष्टिकोण अपनाया। बाद में पृथ्वीचन्द्र राय ने अपने दो लेखों, 1895 में प्रकाशित 'पावर्टी प्राब्लम्स इन इंडिया' और 1901 में प्रकाशित 'दि वाजेज आफ इंडियन फार्मिस में जमींदारी प्रणाली और जमींदारों के दमन को ही लोगों की दरिद्रता के लिए उत्तरदायी माना।<sup>12</sup> जी०वी० जोशी ने जमींदारी की विस्तृत आलोचना की। उन्होंने 1890 में प्रकाशित अपने निबंध 'इकोनामिक सिच्युएशन इन इंडिया' में जमींदारी और रंपतवाड़ी दोनों क्षेत्रों की बुराियों की तफसील से आलोचना की। उन्होंने लिखा कि सारे देश में काश्तकार द्वारा आगे धरती को किराए पर देने की घटनाएँ बढ़ रही हैं। त्रिचौलियों और मनमरजी ने रखे काश्तकारों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। एक ओर जनसंख्या की वृद्धि और दूसरी ओर गैरकृषि उद्योग में बराबर ह्रास होने से किसानों में धरती के पान के लिए हौठ और प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न हो गई है और इस स्थिति का दुष्परिणाम यह निकला है कि जमींदारों ने किसानों को गंगारुबी किराया देने के लिए बाध्य कर दिया है। इन ऊँचे किरायों और काश्तकारों की असुरक्षा का दुष्परिणाम यह निकला है कि असली हल जोतने वाले किसान का धरती को सुधारने का निश्चयात्मक उस्ताह ही नष्ट हो गया है।<sup>13</sup> जोशी जी के निबंध का संक्षेप इस प्रकार है

किसानों की स्थिति यह है कि वह कितनी भी समझदारी से काम कर ले, कृषि उद्योग अथवा उपज से उसे कुछ मिलता मिलाता नहीं है और यदि वह अपने काम की उपेक्षा करता है तो उसका कुछ बिगड़ता नहीं। उसे किसी प्रकार की कोई आशा नहीं है। अपना कर्जे की कुछ एकड़ धरती को बचाने के लिए वह भूखे मरने की वजाय मुहमाया ऊँचा किराया चुकाता है। अपनी सहायता आप करने का उद्देश्य ही इस स्थिति का अंग नहीं और न ही इस स्थिति में स्वतः बटार धर्म की प्रेरणा की अपेक्षा की जा सकती है।<sup>14</sup>

1894 में प्रकाशित अपने निबंध 'नाटम आन एग्रीकल्चर इन बांगे' में जोशी ने जमींदारी और स्वैच्छिक काश्तकारी के विकास पर विस्तृत विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कुछ पूर्वक कहा कि आर्थिक रूप में उपकाश्तकारी के व्यापक व्यवहार के कारण और आर्थिक रूप से श्रृंखला प्रस्तता से मुक्ति न मिलने के फलस्वरूप बर्बरता के प्रति काश्तकारी अधिकार अथवा काश्तकारी कानून नाम की कोई वस्तु ही नहीं रह गई है। इस प्रकार काश्तकारी अधिकारों तथा अग्रिन्स काश्तकारों की बेदखली अथवा किराया बर्द्ध के विरुद्ध संरक्षण की कोई व्यवस्था ही नहीं है।<sup>15</sup>

बहुत दूरे भारतीय नेताओं ने काश्तकारों को संरक्षण देने के निश्चयात्मक उपाय भी सुझाए। इनमें सर्वाधिक लोकप्रिय उपाय या किराया में अनुचित बर्द्ध के, भारी लगानों के, बेदखली के तथा काश्तकारों के अधिकारों के हनन के विरुद्ध काश्तकारों को कानूनी संरक्षण प्रदान करना तथा कर्जों के अन्याय अधिकारों का विस्तृत तथा सुदृढ़ रूप देना।<sup>16</sup> यह एक वाक्य तथ्य है कि सरकार द्वारा अपनाए गए काश्तकारी कानून का जी०वी० जोशी, आर० सी० दत्त तथा जस्टिस रानाडे तीनों मुख्य अध्यापकों ने

समयन किया तथा काश्नकारी अधिकारो को और अधिक सुदृढ बनाने के पक्ष म प्रवल तक लिए।<sup>17</sup> जोशी ने अधिकारियो मे बर्बई के नितात असुरक्षित उपकाश्तकारोवाले रयतवाडी इलाके मे भी कानूनी सरक्षण के विस्तार का अनुरोध किया।<sup>18</sup>

यह स्वाभाविक ही था कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान जमींदारी प्रणाली के उमूलन की व्यापक माग तो नहीं की गई परंतु यह कम महत्वपूर्ण नहीं कि यह माग क्यों उठाई गई। इस प्रकार 2 अक्टूबर 1881 के अक मे इंडियन स्पेक्टेटर ने सरकार से सारी जमींदारी खरीदने और फिर सीधे किसानो से समझौता करने का अनुरोध किया।<sup>19</sup> 24 जुलाई 1882 के अक म 'सोम प्रकाश' ने सरकार को रूस सरकार के आदश उदाहरण का अनुकरण करने का उपदेश दिया और कहा कि सरकार जमींदारी प्रथा समाप्त कर दे। जमींदारा को बीस वर्षों मे होने वाले लाभ के बराबर का धन उसकी जमीन के मूल्य के रूप म देकर उनका स्वामित्व समाप्त कर दिया जाए। यह धन आधा सरकार जुटाए और आधे की व्यवस्था किसान करे।<sup>0</sup> कभी कभी भारतीय नेता माग के प्रति टालमटाल काम लेते थे और जमींदारी प्रणाली को एक सिद्ध तथ्य मानकर जमींदार और पट्टेदार के मध्य स्याई समझौते की बकालत करते थे।<sup>1</sup>

12 जून, 1880 के अक मे बंगाली ने बंगाल के स्याई बदोवस्त की एक और मजेदार आलोचना प्रस्तुत की। बंगाली पत्र ने दृढ स्वर मे कहा कि बंगाल म औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियो का नितात अभाव है। जमींदारी ही वहा पूजी के निश्चित लाभप्रद निवेश का एकमात्र अवशिष्ट साधन है। यही कारण है कि पूजी निवेश की प्रवृत्ति उद्योग की प्रपेक्षा जमींदारी की ओर हो रही है। दो वर्ष पश्चात 28 जनवरी 1882 के अक म बंगाली ने अपनी आलोचना दाहराते हुए अपना मन प्रकट किया कि जमींदारी पद्धति का प्रवृत्तन बंगाल और बर्बई के औद्योगिक और व्यापारिक स्तर का उल्लेखनीय अंतर स्पष्ट करता है।

इसके विपरीत सामाय आधार पर जमींदारा अथवा अथ वडे वडे भूखंडा के स्वामियो के हिता के भारतीय नताआ द्वारा समयन के उदाहरण बहुत ही कम थे। बंगाल मे 'बंगाली' ने पट्टेदारा के समयन की अपनी पहली नीति स हटत हुए 19 मार्च 1887 के अक मे सरकार से पूर्वी बंगाल मे किसान सगठना का तोडने के उपाय करने का और किसानो को उचित किरायो के भुगतान की अनिवायता से परिचित करान का अनु रोध किया। 20 फरवरी 1899 के अक म अमृत वाजार पत्रिका ने भी दावा किया कि अगरेजी राज्य की अवालो, कृषि सबधित लागो के विप्लवा तथा अन्क अयाय बुराड्या से सुरक्षा जमींदारो के अधिकारा और सुविधा का बनाए रखन पर ही निभर है न कि उनके विनाश मे। एक वर्ष पश्चात इमी पत्रिका न अपने 12 जनवरी 1900 के अक मे सरकार मे अनुरोध किया कि वह या तो जमींदारा के प्रति अपनी कठोरता की नीति म मृदुता जाए या उन्हें किसानो से किरायो वसूल करने की सुविधाए जुटाए। बेमरी ने 18 अक्टूबर 1881 के अक मे शिवायत की कि देग क दूमर भाग म, बर्बई के सतारा तथा अथ दूसरे जिनो म किसानो म जमीन के निर्धारण रगानो की वसूली करने मे इमामदारो को सफल बनान के लिए अधिकारियो ने उनकी आवश्यक तथा अपधित

सहायता नहीं की।<sup>3</sup> 27 जुलाई 1890 के अक मे 'मराठा' ने विलाप करते हुए लिखा कि देश में जमींदारों और भूस्वामियों की दुदशा के उदाहरण बहुत जा रहे हैं। उसने सरकार की भ्रमश जमींदारों के अधिकारों के उन्मूलन की प्रवृत्ति की शिक्षाएत की। उसने जमींदारों को और कुछ नहीं तो अपने को जीवित रखने के लिए परस्पर समर्थित होने का परामर्श दिया। उसने दक्षिण के जमींदारों को तो विशेष रूप से ही अपना एक संध बनाने की सलाह दी। 9 दिसंबर 1900 के अक मे इस पत्र ने सरकार से लगान वसूली में इनामदारों की सहायता करने का अनुरोध किया। यहाँ इस बात को दोहराना अनुचित न होगा कि जमींदारों की सस्या और उनके अधिकारों की रक्षा की प्रवृत्ति व पीछे यह भावना काम कर रही थी कि दलित भारतीय जनता का सहज नेतृत्व यही जमींदार वर्ग ही कर सकता था।<sup>4</sup>

जैसा हम पहले ही निर्देश कर चुके हैं कि जमींदार और किसानों के संबंध पर राष्ट्रवादियों के मामूली विचार अत्यंत मृदु हैं। वस्तुतः राष्ट्रवादी नेताओं ने किसानों समर्थक अथवा जमींदारों समर्थक प्रवृत्ति दिखाने के बजाय कृषिक्षेत्र से संबंधित इस पक्ष की ओर विशेष रुचि नहीं दिखाई। सरकार द्वारा 1880-1905 की अवधि में स्वीकृत काश्तकारी कानून के प्रति उनके दृष्टिकोण के अध्ययन से भी इस तथ्य की पुष्टि हा जाती है। 1885 के बंगाल काश्तकारी कानून को छोड़कर इन नेताओं ने किसी भी अन्य काश्तकारी कानून में कोई गहरी या पर्याप्त रुचि नहीं दिखाई।

### 1885 का बंगाल टेनेसी ऐक्ट

1793 के स्याई बंदोबस्त ने किसानों को जमींदारों की दया पर ही छोड़ दिया था। 60 वर्षों से भी ऊपर समय बीत जाने के बाद सरकार का बंगाल के किसानों की दुदशा की ओर ध्यान गया। 1859 के लगान के अधिनियम (अधिनियम संख्या 10) के अनुसार 12 वर्षों से ऊपर एक ही भूभाग के पट्टेदार किसानों को मौसमी हक मिला गया। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था थी कि इसके अंतर्गत निर्धारित विशिष्ट और उचित आधारों को छोड़कर अथवा किसी भी रूप में लगान नहीं बढ़ाया जा सकता था। यह अधिनियम तथा 1869 का संशोधित अधिनियम जमींदारों और किसानों के मध्य पनपते तनाव को दूर न कर सके। जमींदारों ने किसानों को निवालन, लगान में बराबर परिवर्तन करते रहने, बलपूर्वक उन्हें तंग करने, अवध रूप में उनकी बुर्की बनाने और उन्हें बदमाश बनाने आदि गम्भीर तरीके जारी रखे। उन्होंने किसी न किसी तरीके से किसानों को मौसमी हक पान से वंचित करने में तथा लगान बढ़ाने में सफलता पाने के भाग निवाल ही लिए। एक ओर जमींदारों पूष्वन घूतता करते रहे और दूसरी ओर यह शिक्षाएत करते रहे कि 1859 और 1869 के कानूनों के अंतर्गत उनके लिए बालू लगान की वसूली अत्यंत कठिन हो गई है यहाँ तक कि संयथा उपयुक्त कारणों से भी लगान में वृद्धि तो लगभग अमभव हा ही गई है।<sup>5</sup> फरवरी 1872 में बंगाल में कृषकों और जमींदारों के बीच अनवरत मध्य हुए और जमींदारों विरोधी विप्पनव हुए। एसा लगने लगा कि स्थिति किसी समय भी नियंत्रण से बाहर हो सकती है।<sup>6</sup> विहार में







विरोधी थे जिममे किसानो को मीरूसी हऊ देने की तथा धरती को हस्तांतरित करने की शक्ति प्रदान करने की व्यवस्था हो और लगान बढाने तथा रिमानो को बदरान करने के अधिकारो पर नियन्त्रण की व्यवस्था हो। उनका दावा था कि इस प्रकार का कोई कानून बनाना उनके स्वत्वाधिकारों पर छापा मारना, उनके योग्य सम्मान और निहित अधिकारों का घूमिल करना तथा 1793 की संधि का उल्लंघन करना होगा। उनकी यह भी धारणा थी कि अधिकारियो द्वारा विचारित कानून का रूप स्वयं रिमानो के लिए हानिप्रद सिद्ध होगा क्योंकि इसका परिणाम निरर्थक मुजद्दमेराजी तथा उप-पट्टेदारी होगा।

दूसरी ओर इंडियन एसोसिएशन, बंगाल के युवा राष्ट्रवादियो के उनीयमान नेता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने तथा बंगाल के बहुसंख्यक राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने रिमानो के समर्थन का पक्ष लिया। उन्होंने किसानों और जमींदारों के मध्य के मझो में सरकार के हस्तक्षेप करने के अधिकार को गंवाया चित ठहराया। रिमानो के पक्ष में इस प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता को स्वीकार किया तथा यह मानते हुए भी कि यह रिमानो के हस्तक्षेप से अधिक साधक नहीं है, 1880-1883 की अवधि में वे कृषि गण सभा की वास्तविकी विला के प्रारूप का सामान्य स्वीकृति दी और इन रिमानो के विरुद्ध जमींदारों द्वारा किए जा रहे मुकदमों का विरोध किया।<sup>29</sup> बंगाल के राष्ट्रवादी नेताओं का अपक्ष-वृत्त अधिक युवा और अधिक प्रगतिशील युग तो सरकारी कानूनों के प्रति कारे समर्थन को प्रकट करने से आगे बढ़ गया। उनमें से बहूता ने यही ही प्रवृत्तता के साथ रिमानो के उद्देश्य का अनुमोदन किया और बंगाल के गिगित नागा, राजनीतिक सम्प्रदाय और नेताओं ने किसानों के हितों को वाणी देन तथा जमींदारों द्वारा गंवाये गये रिमानो के विरोध करने का अनुरोध किया। उदाहरणार्थ, 18 अक्टूबर 1880 को अजमेर बंगाली न लिखा

हमार अपने सगठन है जो एग के नाचार रिमानो के हितो की गणमान तथा सुरक्षा का दम भरते हैं। हम तो समझ ही नहीं आता कि आज के गणतन्त्रवादी के व्यापार तथा वनव्यपात्रन का अपक्षवृत्त कोई और श्रेष्ठ अवसर अगव पत्राग यों में कभी आएगा नी कि नहीं। सचमुच ही समझ आ गया है कि यह गणतन्त्र जरीय रूप योगिता का प्रमाण है तथा अपने अस्तित्व का अधिकार सिद्ध करें। बंगाल की बरग वृषक जगत देन के साथ निरीह लोग एतना भी ता नहीं जाना कि उनका पारो आर हा क्या रहा है। यह उनके मित्रों का काम है कि वे उनकी भावनाओं को अभिव्यक्ति दें उनकी अनुमति करें तथा उनकी आर ग काम करें। आर बर और घोष प्रकाश का समर्थन अव भीत गया है। अब ता एत व्यक्तियों की आशाकता है जो हृदय में उगाती हो रिमानो के प्रति एतरी गलतनुमति एतना है और एतरे भाव्य को गयारा को उतुक्त है। एत व्यक्ति एक रिमानो हृदय रिमानो एतना है रिमानो के समर्थन में जनसभाएं करें और उतरे एतना एतना तो का आरक्षण करें। अभावकल्प भेदहीवागी रिमानो की गरा करत काग एतना एतना एतना देन की गरा ही बगना है।<sup>30</sup>

जाने वाले लगान की राशि का उसकी कुल उपज के 5/16 भाग से अधिक का न होना। (4) गैरमौरूमी किसान के जोत में हटाए जाने पर उसे मुआवजे का हक होना, तथा (5) लगान के मुकदमों की सरल और सक्षिप्त सुनवाई के साथ उनके शीघ्र निपटारे की व्यवस्था के रूप में जमींदारों की प्रमुख शिकायत को दूर करना। इसके अतिरिक्त अन्ततः के माध्यम से फसल की गिनी और कुर्की की व्यवस्था की गई। इन सभी महत्वपूर्ण धाराओं के लागू होने की निश्चितता के लिए दीवानी अदालतों के तथा बायकारी अधिकारों के हस्तक्षेप की भी इस बिल में व्यवस्था थी।<sup>32</sup>

1883 के काश्तकारी बिल पर जमींदारों ने तीखे प्रहार किए। इस प्रहार से घबराकर सरकार ने जमींदारों को शांत और सतुष्ट करने वाले परिवर्तनों के सुभाव के लिए प्रवर समिति नियुक्त की। इस समिति में जमींदारों के दो महत्वपूर्ण प्रवक्ता फ्रिंस्तोदास पाल (उनकी मृत्यु के बाद उनके स्थान पर प्यारेमोहन मुखर्जी को रखा गया) तथा महाराजा दरमगा सम्मिलित थे।<sup>33</sup> इस समिति ने बिल का इस रूप में सशोधन किया कि उसका कृषक समर्थक आधार ही नामशेष हो गया। सशोधित बिल ने मार्च 1885 में कानून का रूप ले लिया। 1885 के काश्तकारी कानून में मौरूसी हक की प्राप्ति को सङ्कुचित बना दिया गया। अब इस अधिकार को केवल उसी गांव में धरती जोतने तक सीमित कर लिया गया। पहले के 1883 के बिल में निहित 'उभी जागीर में' धारा को छोड़ दिया गया। 1883 के ही बिल द्वारा किसान को हस्तांतरण करने की दी गई पूर्ण शक्ति को भी इस बिल ने छीन लिया। मौरूसी और गैरमौरूसी किसानों पर लगान बढ़ाने की सीमाएं भी हटा दी गईं। गैरमौरूसी किसानों को वेदबल करने पर क्षतिपूर्ति की व्यवस्था वाली धारा को भी इस बिल से हटा दिया गया। इस प्रकार 1883 के बिल की किसानों का लाभ पहुंचाने की सभावनावाली तीनों धाराओं को तो छोड़ ही दिया गया और मौरूसी अधिकार प्राप्ति से संबंधित धारा को हलका बना दिया गया। विरोधी दिशा में बिल का एकमात्र सशोधन इस रूप में था कि मौरूसी हक वाले किसान के लगान की वृद्धि का घटा दिया गया था। यह वृद्धि बचहरी के बाहर आपसी अनुबंध द्वारा 6 जान प्रति रुपये के बदले दो आने प्रति रूपया कर दी गई थी। 1885 का काश्तकारी अधिनियम मौरूसी किसानों के अधीनस्थ मुजारों को कोई सरक्षण नहीं दे सका था।<sup>34</sup> अधिनियम के प्रशंसकों का दावा था कि यद्यपि इसमें जमींदारों को सुविधाएं जुटाने की व्यवस्था है तथापि जिस ढंग से अधिनियम का अंतिम रूप में निर्धारित किया गया है, उसमें किसान के अधिकारों को, अधिष्ठान भूमि पर उसके स्वामित्व का, एकपक्षीय स्वत्वापहरण के विरुद्ध उसके हितों की सुरक्षा को वास्तविक रूप में सुदृढ़ता प्रदान की गई है।<sup>35</sup> उनकी राय में इस अधिनियम की निर्दोषता का सर्वोत्तम प्रमाण सैद्धांतिक रूप से इससे सबद्ध सभी प्रमुख वर्गों द्वारा शांतिपूर्वक इसकी स्वीकृति थी।<sup>36</sup> दूसरे के विचार में 1883 में प्लारेंस नाइटिंगेल द्वारा अभिव्यक्त भय, कि जमींदार अपने वर्ग को सुविधाएं पहुंचाने वाले बिल पास करा लें और किसानों का मिलन वाली सुविधाएं छीन ली जाएगी, 37 गल्प सिद्ध हुआ है।<sup>38</sup>

जमी आग की जाती थी जमींदार किसी भी ऐसे काश्तकारी कानून के पूर्णतः



वस्तुतः बंगाली ने तो 3 जनवरी 1880 के अंक में किसानों का एक अंग होने का दावा किया। इंडियन एसोसिएशन ने आगे बढ़कर किसानों की आप्रशयकताओं और शिकायतों के प्रवक्ता के रूप में कार्य करने के पवित्र वनव्य के निर्वाह की प्रतिज्ञा की।<sup>41</sup> इंडियन एसोसिएशन तथा अय कतिपय महानुभावा, द्वारिकानाथ गागुली, वृष्णकुमार मिश्र और रगलाल मुखर्जी आदि ने व्यक्तिगत रूप से किसानों को अपनी मांगों के लिए अपने आप आंदोलन करा के लिए संगठित करने का बीड़ा उठाया। संगठन के अधिकारी तथा अय किसानों से सहानुभूति रखने वाले बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में गए और उन्होंने 1880, 1881 और 1885 में असह्य किसान प्रदर्शनों तथा किसान जनसभाओं का आयोजन किया। कुछ सभाओं में तो दस से बीस हजार तक किसान सम्मिलित हुए और इन सभाओं में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, आनन्दमोहन बासु तथा द्वारिकानाथ गागुली जैसे वक्ताओं ने भाषण दिए।<sup>42</sup> अनेक स्थानों पर लगान सघों तथा किसान सघों की स्थापना की गई।<sup>43</sup> वस्तुतः इंडियन एसोसिएशन ने इन सघों का उपयोग देहातो में अपनी शाखाओं के जाल बिछाने और राजनीतिक गतिविधि का विस्तार करने के लिए ही किया।<sup>44</sup>

1883 के बंगाल टर्नेसी बिल को देश के अय भागों के गण्यमाय नेताओं का भी समयन प्राप्त हुआ। विशेषतः वाल गगाधर तिलक अथवा जी० जी० आगरकर द्वारा बिल के समयन में निखित तथा 1883 में मराठा में प्रकाशित सपादकीय लेख सचमुच विस्तृत रूप से उद्धृत करने योग्य हैं क्योंकि इनसे राष्ट्रीय नेताओं के उच्च पदाधिकारियों के वृषि सन्धी प्रातिकारी दृष्टिकोण के प्रारम्भिक लक्षण देखने को मिलते हैं। 14 अक्टूबर 1883 के अंक के सपादकीय में गहरी राजनीतिक दूरदर्शिता तथा मानवता के प्रति छानकत प्रेम के महान माधन के रूप में बिल की प्रशंसा करते हुए घोषित किया कि भौतिक सुख सुविधाओं के समान वितरण का यह एक छोटा सा प्रारम्भ है जो प्रगतिशील सप्ताह में एक न एक दिन अवश्य पूरा होगा। सरकार से अपने मायसगत कार्य पर सुदृढ़ वन रहन का अनुरोध करते हुए सपादकीय में सलाह दी कि इस श्रेष्ठ कार्य के विरुद्ध निहित स्वार्थी बग चिन्लाएंग परन्तु दूरदर्शितापूर्ण राजनीतिज्ञता इसी में है कि शक्ति, संपत्ति और सरक्षकता के हाथ में जाने वाले लोगों द्वारा अपनाए गए धमकी भरे व्यवहार की उपेक्षा की जाए, उनके आग भुका न जाए। सपादकीय में यह निर्देश किया गया कि यदि जमींदारों के पाम मण्टि के प्रारम्भ काल में स्वत्वाधिकार होत तो भी समय की गति के साथ उनमें सशोधन करना ही पड़ता। इसके अतिरिक्त सरकार जमींदारों के निहित हितों को प्रनाए रखन के लिए तब तक बाध्य है जब तक वे लाभहित का माग में आड़े नहीं आत। जब समाज का माग के लिए सनरा उपस्थित होता है तब अधिकारों में सशोधन एक तत्वाज्जा वन जाता है। जब उपयुक्त समय आ जाए, परिस्थितियां अनुकूल हों तब परिवर्तन का समाज में अपना माग आप ही बनाएगा तथा समाज पर अपने का वनपूर्वक ही घोषणा, भन ही समाज का कुछ सरस्य उसे न चाह। जमींदारों द्वारा उठाई गई आप तिया का उत्तर मराठा ने 21 अक्टूबर 1883 के अंक के सपादकीय में दिया। जमींदारों की इस घोषणा का कि वास्तविकी कानून के लिए अभी उपयुक्त समय नहीं आया है, उत्तर दत्त हुए सपादकीय ने टिप्पणी की कि प्रत्यक्ष और तात्कालिक शक्तिप्रम्न व्यक्ति कभी

यह स्वीकार नहीं करेंगे कि उनके अधिकारो को छीनने का उपनुरत समग्र आधा है अथवा कमी आएगा। सारे विश्व में खेतिहरो के दुर्भाग्य पर रदा करते हुए सपाशीम में रोसक ने लिखा

प्रमुख कारण कुछ भी हा, चाहे खेत में बरीयता हा अथवा तापता में बरीयता हो, इसने समाज के एक वग पर कमरतोड बठोर भ्रम और दासता पाद की है तथा दूसरे वग को पूण आराम तथा शारीरिक श्रम से मुक्ति का बरदा दे रिता है परंतु अत्र यह पूण रूप से नितात स्पष्ट हो गया है कि आधुनिक सभ्यता तथा समता की पनपती भावना इन दोनो वगों के मध्य असमाज और अत्यायपूर्ण संबंधो को तब समय तक बने नहीं रहने देगी। समाज की पुाठ्यंयस्था के दिना का देर सभर आना निश्चित है। अच्छा हो कि हम बुडबुडो अथवा शिशुका शिवात में स्वयं बसने उस दिन के स्वागत के लिए ही अपने आप को तयार कर ल।

लेखक ने घोषणा की कि यदि उम पर छाड दिया जाए तो वह अधिक सीतासरी सामन प्रस्तुत कर सकता है जिसके अनुसार जमीनार तिसाना का स्थाई धंदो तत बने का तिस हो जाएगा। 18 नवबर 1883 के अत्र में 'गराठा' ने पत्र अत्युच्च नैमित्यता का उर अपनाया और घोषणा की कि त्रिल सवधी सास गतगद में विपय में तिसारणीय विपय यह है कि क्या हम सुस्त, आलसी और गुफतगारा का एक सारा नये धनाय बनना आरते हैं जो दूसरे आदमिया के श्रम के फल का सा शरार जाण, भूगरी। श्रम के बीनन भन पर गुलछरें उडाए परंतु इस बात की शरा भी तिसा न करे कि वे शोभिक, निगरी श्रम पर वह पलता है, सर्वो में छिटुर कर तया साध गदापी में अनासभ गुन भयन है। 6 नव बरी 1884 के अरु में टमने त्रमीदार्ग का अनायगी विन हुए तिसा, 'तमीदार्ग के पास पसा है और उस पैम के फलस्वरुप तिसा पास प्रगत और शोभन है, इसने तिसारीय पुसरी आर किसान निस्सदृ निरत, दुखय और धवाक है, परंतु तिसान मीत श्रम श्रम में शरी बना रहेगा यदि जमादार समय पर नहीं बनते ता तब मगी गी तिसा मक महन मीत मा भटका उन्हें अवसर तगता और शर भरता त्रमीदार्ग का विनद्वैत यु तिसा सारा देगा।" 'इंडियन स्पेक्ट्रेटर' ने भी वान 29 माई 1883 के ध्वन में विन मर शरी सवारा







1881 और 1883 के काश्तकारी बिला का विरोध किया। कई मामला मे यह विरोध खुले तौर पर ही किया गया।<sup>51</sup> 'अमत वाजार पत्रिका' और उसके बंगाली प्रतिरूप आनंद वाजार पत्रिका' न सामान्यतया विरोधी दृष्टिकोण अपनाया परंतु उनके विरोध के आधार भिन्न थे। उन्होंने पितृवादी तक प्रस्तुत किया जो परिणाम मे जमींदारो के पक्ष मे जाता था। उदाहरणार्थ उनका एक तर्क था कि किसी प्रकार के कानूनी हस्तक्षेप से जमींदारो और किसानो के मध्य मंत्री और सौहार्द के संबंधो का धक्का पहुंचेगा। 'अमत वाजार पत्रिका' न अपन 8 जनवरी 1885 के अंक मे बड़े सफेद और हिचकिचाहट के साथ इस तर्क को इस प्रकार प्रस्तुत किया

जमींदार और किसान से संबंधित विषय पर हमारा निष्ठात पक्ष यह है कि किसानो के जोत संबंधी अधिकारो की स्पष्ट और सतोपप्रद परिभाषागत व्याख्या की जानी चाहिए ताकि उहे छीना भ्रष्टी के प्रयासो के विरुद्ध बचाया जा सके परंतु इसके साथ ही दोना को परस्पर सामाजिक सद्भाव और सहानुभूति से बाधने वाले तथा समय की बसीटी पर खरे सिद्ध हुए बंधनो को निममतापूर्वक टूटने नही दना चाहिए। मक्षेप मे जमींदारो को इस स्थिति मे रखा जाए कि वे किसानो सता न सके परंतु इसके साथ ही किसानो को भी जमींदारो को नकारने के लिए और सामाजिक परंपराओ मे उनके महत्व को अस्वीकार करा वे लिए प्रोत्साहित नही करना चाहिए। जमींदार अपना हित किसान से स्नेह करने मे और किसान अपना हित जमींदार का आदर करने मे अनुभव करें।<sup>52</sup>

कभी कभी तो उन्होंने यह अनुभव किया कि बंगाल के जमींदारो पर प्रहार एक प्रकार से देश मे एकमात्र अवशिष्ट सपन और नतुत्व प्रदान करने वाले वग पर ही आश्रमण था।<sup>53</sup> परंतु उनके विरोध का प्रमुख आधार उनका यह विश्वास था कि प्रस्तावित उपायो मे जमींदार और किसान के बीच के विचौलिया, मध्यवर्ती किसान तथा मालिक, के हितो की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई थी।<sup>54</sup>

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जब जमींदारो न अलबर्ट बिल के विरुद्ध विपला जादोलन चलाने वाले बंगाल के अगरेजो मे अपने पक्ष मे समर्थन की माग की ता अमृत वाजार पत्रिका तब ने तथा अन्य जमींदार समर्थक राष्ट्रवादी पत्रो ने जमींदार विरोधी पत्रो का साथ दिया और जमींदारो को इस वापवादी की निंदा करते हुए उमे देश के प्रति विश्वासघात, बचन भंग टुच्छापन तथा मिलजुब व्यवहार बताया।<sup>55</sup>

राष्ट्रवादी ममाचारपत्रो और तत्कालीन नेताओं द्वारा प्रस्तावित काश्तकारी बिल के पक्ष अथवा विपक्ष मे प्रस्तुत तर्कों की भिन्नता का आधार उनको सहानुभूति के मात्र जमींदार, विचौलिया अथवा किंगो की भिन्नता थी।

जमींदार समर्थक राष्ट्रवादी ममाचारपत्रो न मौजूगी अधिवारा व विस्तार मंत्री व्यवस्था<sup>56</sup> का मौजूगी हक के हस्तांतरण की व्यवस्था का<sup>57</sup> लगान की वृद्धि पर प्रतिबंध लगान की व्यवस्था का<sup>58</sup> तथा घरमौजूगी किसानो का बेदखल करने पर उट्ट क्षतिपूर्ति देन की व्यवस्था<sup>59</sup> का विरोध किया। उन्होंने माग की कि यदि लगान पर मौजो ही लगानो है ता उगको अपनाहुट अधिखुम ऊनी मौजो निर्धारित करनी चाहिए।<sup>60</sup>



1881 और 1883 के कास्तकारी पिला का विरोध किया। कई मामलों में यह विरोध खुले तौर पर ही किया गया।<sup>51</sup> 'अमृत बाजार पत्रिका' और उसके बंगाली प्रतिरूप आनंद बाजार पत्रिका' ने सामान्यतया विरोधी दृष्टिकोण अपनाया परंतु उनके विरोध के आधार भिन्न थे। उन्होंने पितवादी तक प्रस्तुत किया जो परिणाम में जमींदारों के पक्ष में जाता था। उदाहरणार्थ उनका एक तर्क था कि किसी प्रकार के कानूनी हस्तक्षेप से जमींदारों और किसानों के मध्य मैत्री और सौहार्द के संबंधों का धक्का पहुंचेगा। 'अमृत बाजार पत्रिका' ने अपन 8 जनवरी 1885 के अंक में बड़े सकोच और हिचकिचाहट के साथ इस तर्क को इस प्रकार प्रस्तुत किया

जमींदार और किसान से संबंधित विषय पर हमारा सिद्धांत पक्ष यह है कि किसानों के जोत संबंधी अधिकारों की स्पष्ट और सतोपप्रद परिभाषागत व्याख्या की जानी चाहिए ताकि उन्हें छीना भपटी के प्रयासों के विरुद्ध बचाया जा सके परंतु इसके साथ ही दोनों को परस्पर सामाजिक सदभाव और सहानुभूति से बांधने वाले तथा समय की कसौटी पर खरे सिद्ध हुए बंधनों को निममतापूर्वक टूटने नहीं देना चाहिए। मक्षप में जमींदारों का इस स्थिति में रखा जाए कि वे किसानों से सत्ता न सकें परंतु इसके साथ ही किसानों को भी जमींदारों को तकारन के लिए और सामाजिक परंपराओं में उनके महत्व को अस्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। जमींदार अपना हित किसान से स्नेह करने में और किसान अपना हित जमींदार का जादर बन में अनुभव करें।<sup>52</sup>

कभी कभी तो उन्होंने यह अनुभव किया कि बंगाल के जमींदारों पर प्रहार एक प्रकार से देश में एवमात्र अवशिष्ट संपन और नेतृत्व प्रदान करने वाले वर्ग पर ही आश्रय था।<sup>53</sup> परंतु उनके विरोध का प्रमुख आधार उनका यह विश्वास था कि प्रस्तावित उपायों में जमींदारों और किसानों के बीच के विचौलिया, मध्यवर्ती किसान तथा मालिक, के हितों की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई थी।<sup>54</sup>

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जब जमींदारों ने अलबट पिल के विरुद्ध विपला आंदोलन चलाने वाले बंगाल के अंगरेजों से अपने पक्ष में समयन की मांग की तो अमृत बाजार पत्रिका तब ने तथा अन्य जमींदार समर्थक राष्ट्रवादी पत्रों ने जमींदार विरोधी पत्रों का साथ दिया और जमींदारों की इस धारणाओं की निंदा करते हुए उन्हें देश के प्रति विश्वासघात, वचन भंग, टुट्टापन तथा निलज्ज व्यवहार बताया।<sup>55</sup>

राष्ट्रवादी समाचारपत्रों और तत्कालीन नेताओं द्वारा प्रस्तावित कास्तकारी विधियों के पक्ष अथवा विपक्ष में प्रस्तुत तर्कों की भिन्नता का आधार उनकी सहानुभूति के पात्र जमींदार, विचौलिया अथवा किसान की भिन्नता थी।

जमींदार समर्थक राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने मोरिसी अधिवारों के विस्तार संबंधी व्यवस्था<sup>56</sup> का मोरिसी हक के हस्तांतरण की व्यवस्था का<sup>57</sup> उपाय की वृद्धि पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था का<sup>58</sup> तथा गैरमोरिसी किसानों को बेल्मन करों पर उन्हें क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था<sup>59</sup> का विरोध किया। उन्होंने मांग की कि यदि लगान पर भीमा हीानी है तो उनकी अपेक्षाओं अधिकतम ऊंची भीमा निर्धारित करनी चाहिए।<sup>60</sup>

राष्ट्रवादी समाचारपत्रों के एक समूह ने सोच समझकर ही तालुकेदारों : जैसे बिचौलियों के हितों की बकालत की। उदाहरणार्थ, 'अमृत बाजार पत्रिका आम बिचौलियों के हितों का समर्थन किया तथा उन्हें बंगाली समाज का आग्रह भविष्य बताया।<sup>60</sup> ए आनंद बाजार पत्रिका का तर्क था कि सरकार जो अधिकार सभी किसानों को देना चाहती है, यदि वे अधिकार बिचौलियों को दे तो उनका अधिक अच्छा उपयोग ही सकता है क्योंकि ये बिचौलिय पट्टेदार उल्लंघन रूप से उन सभी दोषों से मुक्त हैं जो किसानों और जमींदारों में प्रायः पाए जाते हैं। लोग जमींदारों से अपेक्षाकृत अच्छे हैं और वे जमींदारों और किसानों की अपेक्षा अधिक प्रत्यक्ष और गहरी रुचि लेते हैं। ये एक साधारण किसान की अपेक्षा अधिक और सुशिक्षित हैं अतः भूमि सुधार और वैज्ञानिक साधनों के उपयोग में अधिक सक्षम साय ही, ये लोग जमींदारों के दमन का रोकने में भी पर्याप्त समर्थ और शक्ति संपन्न इसके अतिरिक्त ये किसानों से अपना प्रत्यक्ष संबंध भी बनाए रखते हैं। इन्होंने के साथ संबंध के लिए चंपरासिया, नायबा और दिवानो आदि के माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती।<sup>61</sup> जब एक बार इस समाचारपत्र का यह विश्वास हा गया कि यह बिचौलिय पट्टेदारों के विरुद्ध जाता है तो उसने 1883 के वास्तविकारी बिल का समर्थन किया।<sup>62</sup> इस पत्र ने यह भी देखा कि ये बिचौलिय सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से बंगाल के एक महत्वपूर्ण वर्ग से संबंधित थे। बहुत से मध्यवर्गीय बंगाली, छात्र, क्लक, डाक तथा पुलिस अधिकारी, इसी बिचौलिय वर्ग से संबंध रखते थे और स्वशासन के आंदोलन का आधार था।<sup>63</sup> बंगाली ने 17 मार्च 1883 के अग्रणी समाज की रीट की हड़डी बने इन बिचौलियों के हितों की सुरक्षा करने और उन्हें दमन करने का समर्थन किया। इस पत्र ने इस समर्थन के साथ यह भी सचेत किया कि नायब वास्तविकारी बिल द्वारा पहले ही किया जा चुका है। बंगवासी, नवविभाकर, मिहिर, तथा साधारणी आदि ने भी बिचौलियों को अधिकार देने के पक्ष का समर्थन किया।<sup>64</sup>

किसानों के पक्ष के समर्थक भारतीय नेताओं ने वास्तविकारी बिल की वास्तविक अधिकारों को विस्तृत करने वाली धाराओं का अनुमोदन किया, इन अधिकारों का सुदृढ़ बनाने की बकालत की तथा किसानों के हितों के विरोधी दिशाई देने वाले तत्काल आलोचना की। प्रथम, उन्होंने व्यापक और स्थाई आधार पर मौरूसी हक देने वाली धाराओं का अनुमोदन किया।<sup>65</sup> उन्होंने इस दिशा में और अधिक बड़ी सुविधाओं की मांग की।<sup>66</sup> द्वितीय, उन्होंने मौरूसी हक को हस्तांतरित किया जा सकने वाला बनाने तथा उत्तराधिकार का रूप देने का पूरा पूरा समर्थन किया।<sup>67</sup> तृतीय, उन्होंने जमींदारों के अधिकारों के विस्तार पर प्रस्तावित प्रतिबंध का स्वागत किया।<sup>68</sup> बड़िया का तो विचार कि प्रतिबंध वाछनीय रूप में नहीं हैं और अधिकतम निर्धारित सीमा भी बहुत ऊंची कुछ ने मांग की कि जब भूमि के सुधार में जमींदारों का कोई योगदान ही नहीं उम्मेद लगाने बढ़ाने की अनुमति क्या दी जाए।<sup>69</sup> कुछ ने तो जमींदारों और किसानों के मध्य स्थाई रूप से लगानों के निर्धारण की मांग की।<sup>70</sup> चतुर्थ, मौरूसी हक वाले बिचौलियों

को जमींदारों द्वारा बेदखल करने पर किसानों को जमींदारों द्वारा क्षतिपूर्ति की प्रस्तावित व्यवस्था का भी उन नेताओं ने अनुमोदन किया।<sup>17</sup> कुछ नेताओं ने यह प्रस्ताव किया कि जमीनों के लगान और इसकी वृद्धि के संबंध में मौजूदगी और गैरमौजूदगी हकवाले किसानों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए।<sup>18</sup> पंचम, किसानों से लगान के आसान तरीकों में वसूली की सुविधाएँ जमींदारों को प्रदान की जानी चाहिए।<sup>19</sup> जमींदारों को फसल की कृषि का अधिकार दिए रखने का यह अभिप्राय होगा कि वे किसानों का दमन करत रहेंगे।<sup>20</sup>

राष्ट्रवादी नेताओं के इस वक्तव्य 1883 के टेनेसी बिल के एक विशिष्ट पक्ष के प्रति कि इससे उपकाशकारी के प्रसार के निवारण में कोई सहपत्ता नहीं मिलती है तथा इससे मौजूदगी हक प्राप्त किसानों के अधीनस्थ वास्तविकारों के हितों की सुरक्षा नहीं मिलती है, ऐसा तीखा आलोचनात्मक और लगभग आधुनिक दृष्टिकोण अपनाया कि बंगाल के ग्रामों में कालांतर में घटित घटनाओं के सदम में इस आलोचना को एक अतिरिक्त ऐतिहासिक महत्व प्राप्त हो गया है।<sup>21</sup> अतः उसकी हम थोड़ी सी विस्तृत चर्चा नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं

इन नेताओं ने निर्रक्षित किया कि 1883 के बिल के विभिन्न प्रावधानों, मौजूदगी हक को व्यापक बनाने, मौजूदगी हक को हस्तांतरण का विषय बनाने तथा किसानों को जमीनों की आगे लगान पर देने का अधिकार देने का परिणाम यह निकलेगा कि विचौलिया वगैरे बड़े पमानों पर उभर कर अस्तित्व में आ जाएंगे जो जमींदारों की अपेक्षा किसानों का अधिक दमन करेंगे और उनमें बहुत ऊँचे लगान वसूल करेंगे। इस प्रकार असली धरती जातने वाला की बहुत बड़ी संख्या तो अधिकारहीन और सवया असहाय तथा अधीनस्थ किसान बनकर रह जाएगी।<sup>22</sup> इस सबका कारण उनके विचार में यह था कि इस बिल में न तो धरती के असली जोतने वालों के समुचित संरक्षण की कोई व्यवस्था थी और न ही किसान शब्द का उपयुक्त विश्लेषण किया गया था। अतः उनकी मांग थी कि इस नए वक्तव्य के विकास को अवश्यमेव रोकना चाहिए। परंतु यह वाय कौन हो? इस सदम में यह उत्तेजनीय है कि जमींदारों मौजूदगी हक के हस्तांतरण के विरुद्ध इस आधार पर थे कि उनके अनुसार इसको परिणामस्वरूप जमीन मूदतौर विचौलिया के हाथों में पड़ जाएगी। नेताओं के जिन वक्तव्यों का हम यहाँ विश्लेषण कर रहे हैं वह विचौलिया के विरुद्ध इसलिए था कि यह वक्तव्य जमींदारों के नहीं प्रत्युत किसानों के हितों के प्रतिकूल था। अतः उन्होंने जमींदारों द्वारा अपनाई गई स्थिति का मानन से इनकार कर दिया और इसके विपरीत मौजूदगी हक के हस्तांतरण का इस आधार पर समर्थन किया कि इसमें किसानों की सहायता मिलती। इसके साथ ही इसके परिणामस्वरूप विचौलिया के विकास की संभावना को निरूल करने तथा उपराज्यकारी का निरूलकहित करने के लिए उन्होंने कुछ अन्य उपचार भी सुझाए जो किसानों के अनुकूल और जमींदारों, विचौलिया तथा मूदतौरों के प्रतिकूल थे। मवाधिक व्यापक लोकप्रिय उपचार था कि मौजूदगी हक असली जोतने वालों को मिलना चाहिए। तब के लिए जमीन के स्वामी नहीं। इसके साथ ही उनका कथन था कि जब कभी जिनके समय के लिए मौजूदगी

हक प्राप्त किसान अपनी मांगी धरती को अथवा उसके कुछ भाग को लगान पर षडाता है, उतनी अवधि के लिए उसे अपने मौरूसी हक से वचित कर देना चाहिए और उसके बदले असली जोतने वाले उपकास्तकार को ही यह अधिकार मिल जाना चाहिए।<sup>17</sup> 10 नवंबर 1883 के अक म सजीवनी ने और 12 नवंबर 1883 के अक मे नवविभाकर ने उपकास्तकारी पर काबूनी प्रतिवध लगाने की माग की।<sup>18</sup> नवविभाकर ने बडी ही बुद्धिमत्तापूर्वक स्वय हल जोतनेवाले किसान की परिभाषा निम्नलिखित रूप मे की, 'क्या यह कानून बनाना ठीक नही होगा कि जो स्वय अपने हाथा अथवा नौकरो के माध्यम से हल नही जोतता, जोत के हानि-लाभो का प्रत्यक्ष रूप से भागीदार नही बनता, किसान कहलान का हकदार नही है और इसके फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति मौरूसी हक प्राप्त नही कर सकता।' 13 मार्च 1883 के अक मे 'बगाली' ने जमीन की जोता की सीमा निधारित करन वाले आज के प्रस्ताव क महत्व का पूवाभास करते हुए सिफारिश की कि किसी भी कास्तकार को समुचित आर नियमित रूप से जातने के लिए अपेक्षित साधना की उपलब्ध पयाप्तता से अधिक धरती रखने की अनुमति नही देनी चाहिए। अतिम कुछ वृषक समथक समाचारपत्रो न प्रस्ताव रखा कि मौरूसी हकदार किमान द्वारा और गरमौरूसी हकदार किसान द्वारा चुवाए जाने वाले लगान का अतर इतना थोडा हो कि कोई भी मौरूसी हकदार किसान अपनी धरती को किराए, पट्टे पर देने मे किसी प्रकार के लाभ की प्राप्ति की सभावना ही न देवे।<sup>19</sup>

1884 की प्रवर समिति और भारत सरकार द्वारा 1883 के कास्तकारी बिल के तीन प्रमुख मिद्दातो, पट्टे की स्थिरता, यायसगत लगान तथा स्वतंत्र रूप मे बित्री का अधिकार म कतर-योट किए जाते ही किसानसमथक राष्ट्रवादी नेताओ न इन परिवतनो के विरुद्ध रापपूण आदालन शुरू कर दिया। उन्होने किसानो के हिता के साथ विश्वासघात करने के लिए और जमीदारो के हिता के अनुरूप बिल मे सशोधन करने के लिए विशेषत मौरूसी हक प्राप्त करने सबधी, हस्तांतरण करने सबधी धाराओ को पानी मे डालन तथा लगान वृद्धि को सीमित करन वाली और वेदखली की हालत म क्षतिपूर्ति करन वाली व्यवस्थाओ को छोडने के लिए सरकार की आलोचना की।<sup>20</sup> कुछ लोगो का विरोध तो इस सीमा तक पहुंच गया कि व सशोधित बिल को स्थगित करन की ही माग करने लग क्योकि उनका विचार था कि किसानो के दृष्टिकोण से यह बिल न केवल असतोपजनक प्रत्युत उनके हिता के प्रतिकूल भी था।<sup>21</sup> अत म किसानो के पक्षधर जो इस बिल के आलोचक थे, केवल इसी विश्वास से इसना समथन करने लग कि कुछ भी न होने मे ता कुछ होना अच्छा है।<sup>22</sup> इसके अतिरिक्त बट्टा ने यह अवश्य अनुभव किया होगा जैसा 'साधारणी' ने अपने 5 जुलाई 1885 के अक म लिखा 'यद्यपि कास्तकारी अधिनियम सतोपप्रद नही है तथापि इसवे अतर्गत प्रमुख मिद्दात वृषको के अनुकूल हैं अत यह अधिनियम इस रूप म किसानो के अजाय हिता तथा अधिकारो के आदोलन के लिए आधारशिला का फाय करेगा।<sup>23</sup> यहा यह उल्लेखनीय है जो सभवन आश्चर्यजनक ही है कि वस्तुत हमारे अध्ययन के अगत अवधि से सबधित 1885 के परिवर्ती बीस वर्षो की अवधि में बगाल मे इस सबध म कई आदोलन नही हुआ। साथ ही यह निष्प

निवालना भी विलकुल सही होगा कि भारत सरकार बंगाल और बिहार के जमींदारों के आगे उनके द्वाग डाले गए दबाव के कारण झुकी न कि इस कारण कि किसानों के पक्ष में अपेक्षित समथन तथा बगान के उभरते बहुसंख्यक राष्ट्रवादी नेताओं के विरोध का अभाव था। वस्तुतः राष्ट्रवादियों का एक वर्ग सरकारी अधिकारियों की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील और अधिक दृग्दर्शी था। जब बहुत सारे सरकारी अधिकारी उपकास्तकारी को देहाती बेरोजगारों का एक सुरक्षित सहारा अथवा अधिन से अधिक एक अपरिहाय रोग मानते थे, इन नेताओं ने उपकास्तकारी को रोकने के लिए और मजदूर किमाना के हितों की सुरक्षा के लिए आदानन किया।<sup>85</sup>

### पट्टेदारी सबधी कानून, 1880 1905

1881 के उत्तर-पश्चिमी प्रांतीय लगान अधिनियम (नाथ-वेस्टन प्राविंसज रेंट ऐक्ट) पर राष्ट्रवादियों की कोई भी टिप्पणी उपलब्ध नहीं।<sup>86</sup> 'जरनल आफ दि पूना साव-जनिक सभा' में अप्रैल 1881 में बिना नाम स प्रकाशित एक लेख में 1883 में कानून का रूप ग्रहण करने वाले मध्य प्रदेशीय प्रांता के कास्तकारी बिल की तीखी आलोचना की गई।<sup>87</sup> लेखक ने बिल की उन व्यवस्थाओं पर आपत्ति की जिनके अंतगत मालगुजारों के लगान बढ़ाने की शक्तियों को सीमित किया गया था, बिनापत सरकार अपने राजस्व की मांग पर इस प्रकार की कोई सीमा लगान के पक्ष में नहीं थी लगान बसूली में किसानों को कष्ट देने पर तथा उन्हें बेदखल करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। लेखक ने उन व्यवस्थाओं की भी निंदा की जिनका सबध गरमोहसी किमान को बेदखल करने पर भूमिसुधार की क्षतिपूर्ति करना था तथा मौहसी हकों को व्यापक रूप देना था।<sup>88</sup> लेखक ने सैद्धांतिक रूप में यह मान लिया था कि जमींदारों और किसानों के सबध त्रिमी चाहेंगे एजेंसी द्वारा नियमित नहीं किए जा सकत, इन्हें तो किसी प्रतिबोधिता पर छोड़ देना पड़ेगा।<sup>89</sup> 'यायमुधा' ने भी जमींदारों के दृष्टिकोण से सट्टल प्राविंसज टेनेंस बिल की आलोचना की।<sup>90</sup> दूसरी ओर बंगाली ने बिल का समथन तो किया परन्तु यह अनुभव किया कि किसानों के हितों की सुरक्षा की दिशा में बिल पर्याप्त नहीं है।<sup>91</sup> जब सरकार ने बाद में 1883 के सी० पी० टनेंसी ऐक्ट को थोड़ा और अधिक किमाना के अनुकूल बनाने की इच्छा से उसमें परिवर्तन का प्रयत्न किया तो 'मराठा' ने अपन 29 सितंबर 1889 के अंक में जमींदारों के हितों के साथ खिलवाड करने का सरकार की नीति के प्रति विरोध किया।

राष्ट्रवादी नेताओं ने 1886 के अबध रेंट ऐक्ट पर तथा पञ्जाब कास्तकारी अधिनियम पर अपन विचार प्रकट नहीं किए।

1885 के बंगाल टेनेंसी ऐक्ट में संशोधन का बिल 1897 में पेश किया गया और 1898 में पारित किया गया। इससे उल्लेखनीय रूप से ही बंगाल में नाममात्र का मनभेद उभरा। 'डाका प्रफा' और 'बंगबानी' ने इस बिल का प्रति जमींदार समर्थक दृष्टिकोण अपनाया तो 'बंगाली' और 'हिन्दुवादी' किमान समर्थक ही बन रहे।<sup>92</sup> बंगाल विधान परिषद में सुरेंद्रनाथ बँनर्जी और मालीधरण बँनर्जी ने अपन विचार में किमानों के हितों





होने पर अधिनियम की आलोचना की।<sup>105</sup>

1898 और 1904 की अवधि में बंबई सरकार ने रत्नगिरि जिले में खेतों और उनके किसानों के मध्य के संबंधों के जटिल प्रश्न पर कानून बनाने का एक प्रयास किया। इस संबंध में उत्पन्न मतभेद की स्थिति में बंबई के राष्ट्रवादी नेताओं ने निश्चित रूप से खात समझक दृष्टिकोण ही अपनाया।<sup>106</sup>

### किसानों का साहूकार

ग्रामीण भारत की तीसरी मुसीबत थी गांव के साहूकार अथवा कज देने वाले बनिए। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में ग्रामीण कजदारी इतनी तेजी से बढ़ गई कि वह ग्रामीण क्षेत्रों की विपन्नतम समस्या बन गई। ग्रामीण ऋणदाता साहूकारों द्वारा बसूली जाने वाली, आसमान को छूने वाली व्याज की दर ने दो प्रमुख रोगों को जन्म दिया। व्याज के भुगतान किसानों की आय का बहुत बड़ा भाग हड़प जाते थे और किरानों की प्रायः ही ऋण की वापसी में असमर्थता के फलस्वरूप बड़े पैमाने पर किसानों की भूमि हल न चलाने वाले ऋणदाता साहूकारों के हाथ में चली जाती थी। इस प्रकार पुराना किसान साहूकार की मरजी पर पट्टदार बन गया था और इसका अवश्यभावी परिणाम यह निकला कि कृषि और कृषक दोनों की हालत पहले से अधिक विगड़ गई।<sup>107</sup>

ग्रामीण कजदारी की समस्या के प्रति भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं का रवैया प्रायः कुछ जटिल, बहुमुखी और उभयपक्षी और कभी कभी विपरीत था। जहाँ ब्रिटिश भारतीय प्रशासकों ने साहूकार और उनके व्याज की उंची दरों को किसानों की निधनता और कजदारी के प्रमुख कारणों में से एक माना,<sup>108</sup> वहाँ भारतीय नेताओं का निश्वास था कि ऋणदाता साहूकार खेतिहरों की गरीबी और ऋणग्रस्तता का प्रमुख कारण न होकर गौण कारण ही था। इस संबंध में उनकी आशा यह थी कि साहूकारों को ही इस अपराध का प्रमुख और एकमात्र कारण बनाना किसानों की गरीबी और ऋणग्रस्तता के वास्तविक और मूल कारणों से ध्यान हटाने जैसा था।<sup>109</sup> उनकी धारणा थी कि इस प्रश्न को इस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए कि किसानों को साहूकारों के पास आना ही क्या पड़ता है? साहूकारों के पास क्या उधार लेने के लिए जाना किसानों के लिए कोई अथवा फायदे की बात तो है नहीं।<sup>110</sup>

उनके अनुसार ग्रामीण ऋणग्रस्तता में चिंता करने वाली यदि वे प्रमुख कारणों में एक भारतीय किसानों की निधनता भी थी। भारतीय किसानों का अपनी घरती में पर्याप्त आजीविका नहीं मिल पाती थी फलतः वह अपने और अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए, विनिम्न तनी के अलावा, व्याज की बहुत ऊंची दरों पर ऋण लेना बाध्य था। इस प्रकार किसानों के पास का भी विकल्प था, या तो बर भूवा मर या साहूकारों की मरण में जान।<sup>111</sup> उनके विचार में ऋणग्रस्तता का दूसरा कारण था, उगावों को उंची दरों के साथ साथ निश्चित तथा बठोर भूराजस्वपद्धति। उन्होंने घोषित किया कि अधिकांशतया किसान मरदारों के उगावों का भुगतान करने के लिए ही ऋण लेते थे। 'अमन वाजार पत्रिका' ने 12 जून 1884 के अंक में लिखा: 'सून नूनन वाला ऋणग्रस्ता साहूकार मरचारी भूराजस्व

पद्धति की ही उपज है। साहूकार का जन्म ही इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार लगान से दबे किसान को सन्नत के समय में भी लगानों में किसी प्रकार की राहत नहीं देती थी।<sup>11</sup> कुछ भारतीय नेताओं ने तो ग्रामीण कजदारी का सारा दोष जटिल और अत्यंत विस्तृत कानून प्रणाली पर डाला जो व्यवहार में साहूकार की सहायता करती थी और उसे किसान से उसकी भूमि का कब्जा हथियाने में प्रोत्साहित करती थी और इस प्रकार साहूकारी की सारी बुराइयों को तीव्रता प्रदान करती थी।<sup>12</sup> बहुत सारे नेताओं ने इस सरकारी धारणा का जोरदार और दृढ़ता से खंडन किया कि किसान विवाह, मृत्यु तथा अथवा इस प्रकार के सामाजिक और धार्मिक समारोहों के लिए अनावश्यक रूप से ऋण लेता है अथवा दूसरे शब्दों में किसान की ऋणग्रस्तता का कारण उसकी फिजूलखर्ची है।<sup>13</sup>

इस प्रकार राष्ट्रवादियों द्वारा ग्रामीण कजदारी के विश्लेषित कारणों के पीछे उनका यह विश्वास था कि यह ब्रिटिश प्रशासनिक पद्धति की ही देन है और ऋणदाता साहूकार तो ब्रिटिश अधिनीतियों का एक उपकरणमात्र है। इस विश्वास को 'विही मामला म अत्यंत स्पष्ट भाषा में अभिव्यक्त भी किया गया। उदाहरणार्थ 'अमृत बाजार पत्रिका' न 2 जनवरी 1901 के अंक में दृढ़तापूर्वक कहा कि इस देश में कम से कम मारवाड़ी उद्यमी तो ब्रिटिश शासन की ही उपज थे। 'केसरी' ने 18 फरवरी 1902 के अंक में टिप्पणी की

निस्मदेह ऋणदाता साहूकारों की संख्या ब्रिटिश शासन के अंतर्गत बढ़ी है परंतु इसका कारण ब्रिटिश शासन द्वारा स्वदेशी उद्योगों की हत्या है। जब राष्ट्रीय उद्योग नामशेष हो गए हैं, जब प्रतिवर्ष 45 करोड़ रुपया की इंग्लैंड को निकासी कर दी जाती है तब यह क्या आश्चर्य का विषय है कि भारतीय जनता के विभिन्न वर्गों द्वारा एक दूसरे को खाने के सिवाय उनके लिए और कोई बहत्पिच माग ही नहीं रह गया है। ब्रिटिश सरकार न केवल यह परिवर्तन लाई है अपितु उसने कानूनी साधनों से इसे निरंतर बनाए रखने का प्रयत्न भी किया है।<sup>14</sup>

बहुत सारे राष्ट्रवादी नेताओं ने किसान की दरिद्रता के प्रमुख कारण देहाती कजदारी तथा साहूकार का मानन की सरकारी धारणा से असहमत होते हुए भी साहूकारी से उत्पन्न बुराइयों को तत्परतापूर्वक स्वीकार किया, ग्राम के साहूकारों द्वारा बसूले जाने वाले ऊंची दर के ब्याज की निंदा की तथा किसान को लूटने के लिए बनिए द्वारा अपनाए जाने वाले अवैध और घृणित हथकड़ों की भत्सना की तथा साहूकारी को महत्वपूर्ण मानते हुए भी उसे किसानों की गरीबी का एक गौण कारण ही घोषित किया। उन्होंने प्रायः 'खून चूमने वाले' के रूप में विख्यात और ज्ञात साहूकार के पंजा से किसान को बचाने की माग की।<sup>15</sup> उदाहरणार्थ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1899 के अधिवेशन में पंजाब के प्रतिनिधि लाला मुरलीधर ने कज देने वाले साहूकार का रखाचित्र निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया

साहूकार मनुष्य और पशु का विचित्र समन्वित रूप है। जो लाम आत्मा के पुनर्जन्म तथा पुनः शरीर धारण करने के सिद्धांत में विश्वास करत हैं, वे मेरी इस धारणा से एकदम सहमत होंगे कि साहूकार के पास शेर के पंजे हैं, लोमड़ी का दिमाग है और

वक्रे का दिल है। वह पैसे को हड़पने वाला, घृणित जोक है, मैं तो कहूँगा कि यह वह व्यक्ति है जो गरीब खेतिहर का खून चूसता है।<sup>117</sup>

कुछ भारतीयों ने कृषि भूमि के गैर खेतिहर वर्गों के पास हस्तांतरण होने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता प्रकट की तथा उसकी निंदा की।<sup>118</sup>

इसके साथ ही साथ सार भारतीय नेताओं ने यह अनुभव किया कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में तथा ऋण लेने के वैकल्पिक साधनों के अभाव की स्थिति में साहूकार ग्रामीण भारत की आर्थिक आवश्यकता था, क्योंकि उसके बिना किसानों के लिए कृषि कार्यों का संचालन लगान की मांग का शीघ्रता से भुगतान आर्थिक कठिनाई के समय अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण करना कठिन हो जाएगा। जत उनका विचार था कि साहूकार को दवाना नहीं चाहिए प्रत्युत उसे सुधारना चाहिए और उस पर नियंत्रण रखना चाहिए।<sup>119</sup> निम्नलिखित उस समय की परिस्थितियों में यह चिंतन द्वारा अपने में साधक तथा सुदृढ़ थी।<sup>120</sup> नेताओं में से कुछ लोग इस तब को बहुत आगे न गए और कभी कभी साहूकारों और उनके हितों की रक्षा के लिए खुले आम बोलने लगे।<sup>121</sup>

साहूकारों के साथ किसानों के संबंधों के प्रति भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के दृष्टिकोण को बदाचिंत समय समय पर साहूकारों के शोषण तथा अपदस्थ करने का प्रयत्न से किसानों को बचाने के लिए और इन प्रयत्नों के परिणाम में ब्रिटिश शासन की राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता के लिए उत्पन्न होने वाले खतरों को बचाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के प्रति अपनाए गए उनके दृष्टिकोण के सदृश ही भली प्रकार समझा जा सकता है।

### दक्षिण के खेतिहरों की सहायता का 1879 का अधिनियम (डकन ऐग्रीकल्चरिस्ट्स रिलीफ ऐक्ट)

अधिनियमों द्वारा उठाया गया साहूकार विरोधी प्रथम महत्वपूर्ण चरण 1879 का दक्षिण के कृषिों की सहायता का अधिनियम था। इसका उद्देश्य 1875 के गंभीर उपद्रवों के रूप में दक्षिण वरई के खेतिहरों द्वारा अभियुक्त असंतोष को दूर करना था। यह कार्य साहूकारों को दवाने, साहूकारों की गत और कष्टपूर्ण प्रवृत्तियों को रोकने, वानूनी पायवाही का मरन रूप देने तथा ग्रामीण ऋणों को नीचे लाने से किया जा सकता था। दक्षिण के चार जिलों में लागू किए गए अधिनियम के अंतर्गत न्यायालयों को यह अधिकार दिया गया कि वे प्रतिनापनों की भावना को देखें, ऋण के इतिहास और माय्यता की जांच करें, अनुचित व्याज दरों की वसूली की अनुमति न देते हुए समुचित आधार पर वास्तव में नौ देय ऋण गति निर्धारित करें। यह अधिनियम बजारों की घटती या बिक्रम से प्रभावित था जब तक कि किसान न जमीन देने का ही विद्विक्त रूप में निमित्त इकारनामान कर रखा हो। इतने पर भी कुछ विशेष परिस्थितियों में यह अधिनियम में निम्नलिखित को धरती लौटवाने की व्यवस्था भी थी। अधिनियम में ग्राम रजिस्ट्रारों की नियुक्ति की व्यवस्था थी जिससे आगे ऋण संबंधों में भी प्रतिनापनों का पजीकरण करना पड़ता था और ऋण की रकम अधिक होने पर बजारों का विचारना पापित

वरन का प्राथनापत्र देना होता था। इस अधिनियम के अतगत ऋण चुकता न करने पर जेल के दंड को हटा दिया गया था तथा ऋण परामशदाता की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1882 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और कजदारों को रेंट रखी गई धरती को छुड़वाने की चिंता किए बिना ही हिसाब के लिए कानून की शरण लेने की शक्ति दी गई।

इस अधिनियम को जस्टिस रानाडे, पूना सावजनिक सभा तथा बवई के कई समाचारपत्रों ने सत्रिय समर्थन दिया।<sup>1</sup> रानाडे ने अपने दृष्टिकोण को निम्न शब्दों में संक्षिप्त रूप दिया

इस अधिनियम का समग्र औचित्य इसी एक तथ्य में निहित है कि साधारण कानून विवालिये और अशिक्षित किसान में तथा सपान और चालाक साहूकार में बुद्धि और सुविधाओं की समानता के सिद्धांत को लेकर चलता है जबकि वस्तुतः इस समानता का किसी भी रूप में अस्तित्व ही नहीं है नकली कानून द्वारा समानता की धारणा पूर्ण रूप से ही कल्पनामूलक है और इसका बहुत ही दुरुपयोग होता रहा है। अपेक्षाकृत दुबल वर्ग के संरक्षण की दृष्टि से पुरानी रूढ़िवादी स्वदेशी परंपराओं की ओर लौट कर इस बुराई के उन्मूलन का समय आ गया है।<sup>2</sup>

रानाडे ने अक्टूबर 1879 में 'जरनल आफ दि पूना सावजनिक सभा' में प्रकाशित अपने लेख, 'दकन ऐग्रीकलचरिस्ट बिल' में बिल की लगभग सभी महत्वपूर्ण धाराओं का समर्थन किया।

बवई के बहुत मारे राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने प्रमुख रूप से इस आधार पर बिल को अस्वीकृत कर दिया कि यह अनिच्छापूर्वक किया गया प्रयास है अतः यह किसानों की सुरक्षा में सफल नहीं होगा। यह साहूकारों के रूप में गौण बुराई का तो उपचार करता है परन्तु कठोर और दकियानूसी लगान पद्धति के रूप में प्राथमिक बुराई को छूटा तक नहीं। इसका परिणाम यह होगा कि किसानों के दायित्व तो यथापूर्व बने रहेंगे परन्तु उनकी ऋण लेने की साख जाती रहगी अतः उसकी ओर दुःशा हागी।<sup>3</sup> अधिनियम के आलोचकों के मन में बर्दाचित्त वही विश्वास काम कर रहा था जिसे 3 फरवरी 1884 के एक म. मराठा ने खुले तौर पर प्रकट किया। यह एक ऐसा साधन है जिसे दुर्भाग्य के वास्तविक आधार को छिपाने के लिए अपनाया गया है। सरकार द्वारा अपने उत्तरदायित्व को साहूकारों के कंधों पर फेंकने की दिशा में किए जा रहे प्रयत्नों का यह एक रूप है।<sup>4</sup> यहां तक कि अधिनियम का खुलकर समर्थन करने वाले रानाडे ने यह बात जोड़ दी कि यह बिल किसानों को राहत पहुंचाने में तभी सहायक सिद्ध हो सकता है जब इस कल्पना से काम लिया जाए कि भूराजस्व नीति को उदार बनाया जाएगा बिल की सफलता के लिए यह एकमात्र शर्त है।<sup>5</sup> उन्होंने आगे दृढ़तापूर्वक लिखा 'नहीं तो यह कानून कोई भी उल्लेखनीय और स्थाई लाभ नहीं पहुंचा सकेगा और संभव यह भी है कि वर्तमान स्थिति का ही और अधिक विषम बना देगा क्योंकि किसानों के बंधों को बढ़ा देकर भूमि लगानों को चुकाने के लिए किसी न किसी तरह रुपया जुटाना पड़ेगा।<sup>6</sup> थोड़े से भारतीय नेताओं ने अधिनियम का विरोध भी किया। उनके विचार

में यह साहूकार के हितों की पूर्ण उपेक्षा करता था और परिणामस्वरूप पूरी तरह बरबाद कर रहा था।<sup>17</sup>

### धरती के सङ्ग्रहण पर प्रतिबन्ध

1879 के उपरांत शताब्दी के अंत तक सरकार ने देहाती कजदारी के बढ़ते खतरे के विरुद्ध कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। परंतु धरती के किसानों के हाथ से निकल कर गर खेतिहर वर्गों के हाथ में जाने की गति इतनी अधिक बढ़ गई कि अधिकारी घबड़ा उठ। तब सरकार पहले से अपनाए गए प्रयत्नों की अपेक्षा और अधिक वेगवान और प्रभावी उपचार करने को विवश हो गई। इस सबंध में वर्षों तक सरकारी चिंतन इस धारणा के चारों ओर घूमना रहा कि किसानों के हाथों से धरती के खेतिहर वर्गों के पास जान के प्रमुख कारण थे, सरकारी भाग की अत्यधिक कमलता। सरकारी कर नीति अधिक लगान का एक भाग लेने के बाद बहुत बड़े अनुपातित अवशिष्ट भाग को भूस्वामियों के हाथ में छोड़ देती थी और इससे खून चूसने वाले लगान वसूलने वाले वर्ग के बने रहने में सहायता मिलती थी। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा भूस्वामियों को धरती बेचने अथवा रेंट रखने के रूप में धरती का हस्तांतरित करने की अवाधित शक्ति दी गई थी। भारतीय किसानों की फिजूलखर्ची की आत्त थी। वह एक ओर अपनी इस प्रकृति के कारण और दूसरी ओर भूमि के सङ्ग्रहण की शक्ति से संपन्न होने के कारण अधिकतम रकम उधार लेता था।<sup>18</sup> अतः यह विश्वास बनाया गया कि जितना ऊँचा कराधान होगा, किसानों के लिए वह उतना ही अधिक फायदेमंद होगा। यदि ब्रिटिश प्रशासन ने राजनीतिक दृष्टि से अपने प्रस्ताव को लागू करना असंभव अनुभव न किया होता तो अवश्य ही उताने खेतिहर जमींदारों को लाभरहित बनाने के लिए भूमि लगान में वृद्धि के प्रस्ताव को रखने की उत्सुकता अवश्य दिखाई होती।<sup>19</sup> अधिकारियों द्वारा विस्फुट रूप में अवशिष्ट दूसरा उपाय था, अबुद्धिमान और अदूरदर्शी किसानों के लिए घातक सिद्ध हो रहे भूमि हस्तान्तरण के उपहार रूप अधिकार का उनके हाथों से छीन लेना, धरती बेचने की उसकी शक्ति पर प्रतिबन्ध लगाना तथा इस प्रकार उसकी मालकी को सीमित करत हुए बड़े पैमाने पर कृषि लेने की उसकी शक्ति और प्रलोभन का दूर करना।<sup>20</sup>

नई नीति का प्रथम प्रमुख साकार रूप 1900 का पञ्जाब एलिनशन एक्ट था। अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकारी किसानों द्वारा डिप्टी कमिश्नरों की स्वीकृति के बिना और परिभाषित खेतिहरों के विवाय किमी अथवा स्थाई रूप से भूमि के स्वामित्व परिवर्तन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। गरखेतिहरों का भूमि के स्वामित्व की कई रूपों में अस्थाई स्वीकृति अधिनियम वीम बंध की अवधि के लिए निश्चित की गई। इस अवधि के उपरांत, बिना किमी प्रकार की बाधा के धरती मूल स्वामी के अधिकार में मानी जाने की व्यवस्था की गई तथा किमी आयेगा अथवा आगति के परिपालन के लिए कृषि भूमि को न बने जा सकने की व्यवस्था की गई।<sup>21</sup> इसमें स्पष्ट है कि यह अधिनियम किसानों का चानू कृषिप्रवृत्तता से मुक्त करने के लिए नहीं बल्कि पञ्जाब में कृषि वर्ग के एक बाहरी व्यक्ति के रूप में सरकार द्वारा किए जा रहे संपत्तिहरण से और इस

रूप से शायद निरंतर बढ़ रहे राजनीतिक एतरे के रोग से बचाने के लिए तथा भविष्य में उस न बढ़ने देने के लिए बनाया गया था।<sup>13</sup> यही कारण है कि भूमि के खेतिहर वर्गों में हस्तांतरण की पूरी इजाजत थी और वास्तव में भूमि में सत्रमण की पूर्णरूप से रोकने की जगह इन कम किया गया और नियमित बनाया गया। हा यह आशा अवश्य की गई थी कि इस सन्मान की थोड़ी सी आवश्यकता होत ही साहूकार के पास भागे जाने की प्रवृत्ति और सामर्थ्य पर परोक्ष रूप से दबाव अवश्य पड़ेगा।

इस दिशा में उठाया गया अगला महत्वपूर्ण कदम 1901 में ब्रिटेन में लड रैंवेयू अमंडमट एक्ट (भूराजस्व ससोधन अधिनियम) को कानून का रूप देना था। इसमें सरकार का भूमि लगान का नुगतान न करन के अपराध में सरकार द्वारा जन किए गए खाली भूखंडों और खेता के तथा हस्तांतरण के अधिनार से रहित नए प्रकार के जोतों के बंदोबस्त करने की शक्ति दी गई थी। इसके अनिश्चित अधिनियम में कलक्टर द्वारा यथानिर्दिष्ट अवधि के लिए तथा यथानिर्दिष्ट शर्तों पर जन्म धरती देने की भी व्यवस्था थी।<sup>133</sup> इस अधिनियम में सामर्थ्य देने की व्यवस्था थी बाध्यता की नहीं थी तथा जन धरती को अमत्रमणीय बनाने की व्यवस्था थी। अतः ऐसा कहा जा सकता है कि इस अधिनियम का क्षत्र पजाब के क्षेत्र की अपेक्षा बहुत ही सकीण था इसके अतिरिक्त पजाब अधिनियम की अपेक्षा यह अधिनियम दो रूपा में बंठोर था प्रथम इसके अंतगत जितनी भी धरती आती थी, यह अधिनियम उस पर प्रतिबन्ध ही नहीं लगाता था प्रत्युत रहने, बिनी आदि किसी भी रूप में धरती के हस्तांतरण पर पूर्ण निषेध लगाता था। द्वितीय, यह सरकार को सर्वोक्षित जोतों पर स्याई मीहसी हक देने के बदले जब्त किए गए खंडा का थोड़े समय के पट्टे पर देने का अधिकार देता था।

धरती के निजी स्वामित्व परिवर्तन की शक्ति को प्रतिबन्धित करने की चेष्टाओं के प्रति राष्ट्रवादियों का दृष्टिकोण ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कारणों और निवारण के उपायों के संघर्ष में त्रिदिश अधिकांश और भारतीय नेताओं के बीच मतभेदों का उजागर करता है। इन मतभेदों को देखते हुए यह स्वाभाविक ही था कि राष्ट्रवादी नेताओं ने इस अधिनियम का उसके जन्म काल से लेकर सरकार द्वारा उसे स्वीकृति देने के समय तक विरोध किया।<sup>134</sup>

पजाब के बाहर पजाब भूमि सत्रमण बिल का था तो विरोध हुआ और या उसे समर्थन नहीं मिला।<sup>135</sup> पजाब में भी राष्ट्रवादी पदाधिकारियों में इस बिल में मतभेद उत्पन्न कर दिया।<sup>136</sup> इसने बहुत सारे भारतीय राष्ट्रवादियों का अजीब स्थिति में डाल दिया। उदाहरणार्थ पजाब प्रांत के राष्ट्रवादी पत्रों में उर्दू भाषा के मुखपत्र 'अखबार आम' न आरंभ में बड़ी ही सकोच की सी स्थिति अपनाई और अपनी प्रतिक्रिया समयका और विरोधियों दोनों के विचारों को प्रकाशित करने के रूप में प्रकट की। लगभग एक वर्ष तक बीच में लुडकते रहने के उपरांत आखिरकार उसने अपने 7 अगस्त 1900 और 27 अक्टूबर 1900 के अंकों में बिल का विरोध किया।<sup>137</sup> परंतु दो ही सप्ताहों के उपरांत उसने अपना हल बदल दिया और उसने 10 नवंबर 1900 के अंक में

विश्वास के साथ भविष्यवाणी की कि यह अधिनियम सफल होगा और इसके सबध में उठाई गई सभी आपत्तियाँ असंगत हैं।<sup>139</sup> किसी भी रूप में पंजाब के भीतर अथवा बाहर पंजाब एलिनेशन बिल का कठोर रोपपूर्ण अथवा दीर्घकालीन विरोध नहीं हुआ।

दूसरी ओर 'बंबई भूराजस्व सशोधन बिल' में बंबई प्रदेश की जनता में व्यापक रोप की नहर दौड़ गई। प्रदेश के सभी भागों में विरोध समाए हुए तथा बंबई प्रेजीडेंसी एग्रीकल्चरल, पूना सांख्यिक सभा तथा दक्षिण सभा ने इसके विरुद्ध ज्ञापन भेजे।<sup>140</sup> प्रमुख राष्ट्रवादी समाचारपत्र इस बिल की निंदा के लिए कटिबद्ध हो गए,<sup>141</sup> और प्रमुख लोकनता हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गए।<sup>142</sup> बंबई लैजिस्लेटिव कौंसिल के कुछ भारतीय सदस्य, पी० एम० मेहता, जी० के० गोखले जी० के० पारिख, बालचंद्र कृष्ण और डी० ए० खरे ने बिल को जल्दबाजी में कानून का रूप देने के विरुद्ध अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए कौंसिल से बहिष्मन का अभूतपूर्व कदम उठाया, यह भारतीय विधान परिषदों के इतिहास में कदाचित्त प्रथम उदाहरण था।<sup>143</sup>

भूमिस्वामित्व परिवर्तन विरोधी कानून के विरुद्ध राष्ट्रवादियों के विरोध का आधार यह विश्वास था कि भले ही यह कानून किसानों को साहूकारों द्वारा किए जाने वाले स्वामित्वहरण से बचाने के उच्चतम उद्देश्य को लेकर बनाया गया है परंतु इससे व्यवहार में कोई लाभ तो होगा नहीं उल्टे यह किसानों के हितों के विरुद्ध ही जा सकता है। प्रथम उनकी धारणा थी कि स्वामित्व परिवर्तन पर लगे प्रतिबंधों से किसानों की साख जड़मूल से नष्ट न होकर भी क्षीण अवश्य हो जाएगी। क्योंकि किसानों को वृत्ति सबंधी गतिविधियों के संचालन के लिए, सरकारी भागा के मुकामान के लिए और अभाव के दिनों में परिवार के भरण-पोषण के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ती ही रहती है इस कानून का परिणाम यह होगा कि या तो वह ऋण ले ही नहीं पाएगा अथवा उसे इनके लिए बहुत ऊँची ब्याज दर देनी पड़ेगी।<sup>144</sup> उनका यह भी दावा था कि इन प्रकार के प्रतिबंधों का अनिवाय परिणाम यह होगा कि भूमि का मूल्य घट जाएगा।<sup>145</sup> उनकी यह भी धारणा थी कि ये प्रतिबंध किसानों के स्वामित्व के अधिकारों के क्षेत्र में घुसपैठ हैं। धीरे धीरे ये प्रतिबंध किसानों को वास्तव में ही राज्य का दास बना देंगे।<sup>146</sup> भारतीय जनता ने विरोध रूप से बंबई भूराजस्व सशोधन बिल पर प्रहार करते हुए अपनी इस आत्माबता का उग्र स्वर रखा। उनसे अनुमान करने की गई धरती पर समुचित समझी जाने वाली शर्तों पर और समुचित समझी जाने वाली शर्तों के लिए सदायस के सरकार को अधिकार न होने वाली व्यवस्थाएँ न बल निमान से स्वामित्व का अधिकार छीनने का उद्देश्य लिए हुए हैं प्रत्युत उमरे म्याई मोरमी हन और निरनर जानन का हन भी छीननी हैं। इस प्रकार जनता ने दो व्यवस्थाओं का राजनीय जमीनदारी अथवा भूमि के राष्ट्रीयकरण के मिद्वान की लागू करने का एक गुप्त पद्धत बताया।<sup>147</sup> कुछ ने तो भविष्यवाणी की कि जल्द ही विमान का गन्ध है इन श्रावितकारी व्यवस्थाओं में विपरीत परिणाम ही प्राप्त होगा। बचारा निमान अपन पूरा स्वामित्व के अधिकार का बचाने के लिए साहूकार पर और अधिक निभर रंगा





अधिकार के स्रोत की खोज करते हुए उन्होंने निर्देश किया कि कठोर वित्तीय पद्धति लागू करने पर भारत सरकार के लिए किसान को भूमि बेचने अथवा रेहन रखने के रूप में स्वामित्व में परिवर्तन का अधिकार अनुपूरक पग के रूप में ही देना पड़ा अथवा लगान की द्रुत वसूली संभव ही न हो पाती। स्वामित्व परिवर्तन के अधिकार में किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाना सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न करना होगा और उसके साथ वित्तीय पद्धति में जिसके सदम में इन अधिकारों का देना एक अनिवाय आवश्यकता बन गई थी, प्रभावी सहायन करना ही नहीं प्रत्युत उसे खत्म करना होगा।<sup>155</sup>

वहुत सारे भारतीय नेता इस तथ्य से सहमत थे कि स्वामित्व परिवर्तन, निषेधक कानूनी उपायों की वास्तविक प्रभावात्मकता के सदम में दृष्टिगाचर परिणाम के अनुरूप सिद्ध नहीं हो रहा था क्योंकि यह उपाय ग्रामीण ऋणग्रस्तता के सतही पक्ष से ही संबध रखता था। यह उपाय अधिक से अधिक राग के प्रभाव को कम ही कर सकता था परंतु वास्तविक समस्या का न तो यह विश्लेषण कर पाता था और न ही समाधान।<sup>156</sup>

### वैकल्पिक उपचार

ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्या के प्रति भारतीय नेताओं का मूल दृष्टिकोण यह था कि अपक्षाकृत अधिक असदिग्ध उपायों के रूप में केवल साहूकार विराधी उपायों पर ही अधिक बल नहीं देना चाहिए प्रत्युत देवना यह चाहिए कि वे कौन से कारण हैं जिनसे विवश होकर किसान को साहूकार और ऋणदाता के चंगुल में फसना पड़ता है। ग्रामीण ऋण के अपक्षाकृत अच्छे अभिवरण (एजेंसिया) खोलने से ही किसान को साहूकार से छुटकारा मिलना संभव है। 'मराठा' ने इस दृष्टिकोण को अपने 8 अक्टूबर 1899 के अंक में स्पष्ट रूप से इस प्रकार व्यक्त किया

जब तक रुपया ऋण लेने की आवश्यकता बनी रहेगी, खेतिहर और ऋणदाता साहूकार एक दूसरे के निकट आते ही रहेंगे और भूस्वामित्व परिवर्तन निषेधक कानूनों के पवित्र उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। वस्तुतः सरकार जितना कर सकती है उम उतना अवश्य करना चाहिए। या तो वह ऋणग्रस्तता के वास्तविक कारण लगान में कुछ कटौती करके ऋणग्रस्तता को, आंशिक रूप में ही सही, कुछ कम करे अथवा किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा उन्हें सौतान और दूर प्राइमट ऋणदाता साहूकारों को पंजा से छुड़ाने के लिए स्वयं ऋणदाता के रूप में कार्य करे।<sup>157</sup>

इसी प्रकार गोपालकृष्ण गोखले ने बयई भूमिगत सशोधन मिल पर भाषण करते समय सरकार को चुनौती दी कि वह एक छाटा सा इनाम छाट ले। वह के किसानों के मांग ऋण साहूकारों से लेकर अपन हाथ में कर ले और किसानों की साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि बंध चानू करे और फिर किसानों में भूमिस्वामित्व परिवर्तन का अधिकार छीन। उन्होंने दुःखापूरक कहा कि समस्या को मनी ढंग में सुलभान या यही एनमात्र मनी उपाय होगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि हमारे बहुत सारे श्रमिकों को सरकार की दम नीति का समर्थन करेंगे। उन्होंने अनुभव किया कि मूल समस्या यह है



पूर्वाघ म बहा के किसानो की दशा में सफलतापूर्वक सुधार किया है। उन्होंने निर्देश किया कि भारतीय काश्तकारी कानून के अंतर्गत किसान और जमींदार दोनों का कृषि सचवा की पुरानी व्यवस्था के बंधनो में बंधा रहना जारी रहेगा। इस प्रकार का कानून तो वतबधो और अधिकारो की वतमान जटिलताओ में वृद्धि करने का काम ही करेगा, जमींदार वग को केवल लगान के रूप में अनुग्रह राशि (पेंशन) खाने वाला बनाने के और किसान को जमीन के पूण स्वत्ववाधिकारी के रूप में राज्य की ओर अधिक में अधिक देखने के लिए विवश करेगा। दोनों को अपनी स्थिति को सही प्रकार से समझने में कोई सहायता नहीं मिलेगी। एक वग के हित में वतमान अधिकारो को सतही तौर पर दुहा जा रहा है, हालांकि इसे शीघ्र सुधार' व 'जातिकारी' सुधार का नाम दिया जा रहा है। इस प्रकार की नीति का परिणाम यह होगा कि भगडालू भागीदारा में भूमि पर स्वामित्व और हितो का पूर्ववत पथक और विभाजित रूप बचा रहेगा और किसी भी प्रकार का वास्तविक सुधार नहीं हो पाएगा।<sup>167</sup> इसी प्रकार किसान को वजदार साहूकार की लूट से बचाने के लिए भूमि सन्नमण को अवैध बनाने के प्रस्ताव पर संपत्ति करते हुए रानाडे ने अपना मत प्रकट किया वास्तविक संपत्ति के इच्छित तथा अनिच्छित सभी प्रकार के हस्तांतरणो पर प्रतिबंध लगाने से स्थिति में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होगा। इससे तो बचल वतमान गरीबी की जड़ें मजबूत होगी और वतमान अमहाय अवस्था और अधिक विषम बन जाएगी।<sup>168</sup>

रानाडे ने चालू भूमि सचवो के स्थान पर निजी और स्वतंत्र संपत्ति के आधार पर नए भूमि सचव स्थापित करने का आह्वान किया।<sup>169</sup> सरक्षित पट्टेदारी के स्थान पर उन्होंने किसान का स्वतंत्र तथा उन्मुक्त बनाने का सुझाव दिया ताकि उसमें निजी अस्तित्व की स्थापना हो सके। इस प्रकार का स्वतंत्र किसान दबाया नहीं जा सकेगा, वह स्वामित्व के पूण अधिकार का उपभोग करेगा। संपत्ति के जादू से सम्मोहित वह अपनी धरती पर कठोर श्रम करेगा।<sup>170</sup> इसके साथ ही उनका यह विश्वास था कि छोटे छोटे किसानों में बटी हुई कृषि, भारतीय परिस्थितियों में न तो स्याई और प्रगतिशील बन सकेगी और न ही सभी वर्गों की सर्वोत्तम शक्तिया का सदुपयोग या उन्नत तकनीक और लोक कर्मों का समुचित उपयोग कर सकेगी। उन्होंने लिखा कि जमीन जोतन वाला का जमीन स पूणत अनभाव एक राष्ट्रीय रोग है और सारे देश में छोटे छोटे किसानों के स्तर का बहुत नीचे गिरना भी किसी रूप में कम गंभीर राग नहीं।<sup>171</sup> उन्होंने दृष्टापूर्वक कहा कृषि के समुचित और मतुलित विकास के लिए बड़े पैमाने के पूंजीनिष्ठ किसानों का होना आवश्यक है। ऐम संपन्न किसान भारतीय जमींदारों के समान नहीं प्रत्युत बस्तानवी जमींदारों तथा जमन जमींदारों के आदम पर धरती के पूरे तौर पर मालिक होंगे। 1879 में उन्होंने आशा प्रकट की कि एक बार धरती को कृषि में प्रतिबद्ध स मुक्त कीजिए समझकर और मिनव्ययी वग धरती पर अधिकार करने में सफल हो ही जाएंगे। मारण्य में जमींदारों का एक ऐसा वग अस्तित्व में आ जाएगा, जिसका उद्देश्य धरती के अधिगण माध्याग और सरकार द्वारा निमित्त नोन कार्यों का उपयोग करना होगा।<sup>172</sup> थोड़ा अ न उन्होंने य रीतर टिप्पणिया की

भारत जैसे पुराने और पिछड़े हुए सभी देशों में शक्ति के सभी तत्वों पर एकाधिकार करने वाला एक अल्पसंख्यक वर्ग सदैव मिलता है। सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में इस वर्ग के लोग सदैव अग्रणी रहते हैं। इस वर्ग के लोगों के पास प्रतिभा, संपत्ति, मितव्ययी प्रवृत्ति, ज्ञान और सयोजनशक्ति होती है जबकि बहुसंख्यक वर्ग के लोग अधिक्षित, अदूरदर्शी, बेसमर्थ, फिजूलखर्च और साधनहीन होते हैं, इन दोनों वर्गों में किसी भी राजनीतिक चातुरी से संतुलन नहीं रखा जा सकता। प्रतिभा और संपत्ति के प्रति शक्ति का आकर्षण निश्चित है। अतः कगाली में फसे किसानों को भूमि का स्वामी बनाए रखने के लिए सघन करना सर्वथा निरर्थक है। यह तो धरती और पूँजी के स्वाभाविक ऐक्य को भंग करना है।<sup>173</sup>

1883 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम की समीक्षा करते हुए रानाडे ने खमार भूमि अथवा जमींदारों के निजी अधिकार की भूमि को बम करना और किसानों के अधीनस्थ धरती में बढोतरी करने की प्रवृत्ति की आलोचना की।<sup>174</sup> उन्होंने इस विल की व्यवस्थाओं का प्रशा की भूमि कानून व्यवस्थाओं से अंतर दिखाने हुए प्रशा के कानून की इस आधार पर प्रशंसा की कि उसमें पुराने जमींदारों को अपनी भूसंपत्ति के एक भाग को अपने अर्द्धित अधिकार में ही बड़े पैमाने के पूँजीनिष्ठ खेतों में बदलने की अनुमति थी।<sup>175</sup> इसी प्रकार सरकार की नीति की आलोचना के अभाव कारणों के साथ एक महत्वपूर्ण कारण उनका यह विश्वास था कि इससे बड़े पैमाने की पूँजीनिष्ठ कृषि के विकास में खावट पदा होती है।<sup>176</sup> इसी प्रकार उनके भूमि के हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिरोध लगाने के विरोध का प्रमुख आधार उनका यह भय था कि इन प्रतिबंधों से देश की भूमिगत संपत्ति के केंद्रित होने की अपरिहार्य प्रवृत्ति रुक जाएगी।<sup>177</sup>

अतएव रानाडे ने भारत में कृषि सबंधीय भावी विकास को साथ साथ जीवित करने वाले दो कृषि सबंधित वर्गों को जन्म देकर उन पर आधारित करने की बकालत की (क) व्यापक क्षुद्र कृषक वर्ग, जो राज्य के अथवा जमींदारों के किसी भी प्रकार के भार से पूर्णतया मुक्त होगा। उसे स्थाई और निम्न दर पर निर्धारित भूराजस्व की प्रतिभूमि प्राप्त होगी और उसके लिए कृषि बका के द्वारा सस्ती दर और आमान शर्तों पर ऋण की व्यवस्था होगी। (ख) पूँजीपति किसानों का बड़ा वर्ग जो किसी भी वास्तविक कानून से अप्रभावित होगा अर्थात् उसके पास धरती का पूर्ण और एकांत स्वत्वाधिकार होगा। यह वर्ग इस स्थिति में होगा कि अपक्षित पूँजी का निवेश तथा अधुनातन वित्तीय कृषि सबंधी तकनीक का उपयोग कर सके। प्रशा में इस सबंध में उन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य में प्रचलित जमींदार और किसान दोनों वर्गों के संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकारवाली स्वामित्व पद्धति के अनुकरण और स्वीकरण की अपील की।<sup>178</sup> उन्होंने बताया कि प्रशा में 1860 में 15 प्रतिशत भूमि पर राज्य अथवा चक्र का अधिकार था 44 प्रतिशत पर बड़े बड़े जमींदारों का अधिकार था, 35 प्रतिशत पर किसानों का स्वत्वाधिकार था और 5 प्रतिशत पर छोटे छोटे मालिकों का अधिकार था। इस प्रकार समय के स्वर में उन्होंने कहा कि बड़ा भूमि समृद्ध जमींदार और भारमुक्त निधन में बराबर बड़ी हुई है। गामती अधिदास ने बड़ा भारमुक्त स्वत्वाधिकारी का और जमींदारों से अलग संपत्ति का

अबाध स्वामी का रूप ले लिया है।<sup>117</sup> प्रशा के आदर्श को भारत पर लागू करते हुए जस्टिस रानाडे इस निष्कर्ष पर पहुँचे

यदि इस देश को अपनी शक्ति और समृद्धि के आधार के रूप में स्वाभिमानी व रवतत्र भूधरो की गहरी आवश्यकता है तो भूमि पर स्वामित्व प्राप्त व्यक्तियों के प्रकाश और नेतृत्व की भी आवश्यकता किन्नी प्रकार कम महत्वपूर्ण नहीं। ऊपर के दस हजार लोगों द्वारा बड़े बड़े भूभागोंवाली जागीरों पर अधिकार करना और बड़ी सरया में छोटे छोटे खेतिहर किसानों द्वारा छोटे छोटे भूभागों पर अधिकार रखना, इस प्रकार बड़े और छोटे खेतों पर खेती । दश की उन्नति और स्थिरता की प्राप्ति के लिए ग्रामीण समाज की यह मिश्रित रचना एक आवश्यकता है।<sup>118</sup>

रानाडे ने पूँजीनिष्ठ किसान और जमींदार वर्ग के अस्तित्व में आने के माध्यमों और उपायों पर भी विचार किया। उन्होंने जाशा प्रकट की कि कुछ एक मितव्ययी स्वतंत्र किसान धीरे धीरे अपनी स्थिति में विस्तार करेंगे और अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में आ जाएंगे।<sup>119</sup> उन्होंने यह आशा भी प्रकट की कि धनी वर्ग के बहुत सारे लोग भूमि की ओर आकृष्ट होंगे, वेपरवाह और निष्कर्म किसानों से भूमि सरीदगे तथा इस प्रकार पूँजीपति जमींदार की भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ेंगे।<sup>120</sup> स्पष्टतया यह उपचार रैयनवाड़ी इलाके पर ही लागू होगा। बंगाल के जमींदारी क्षेत्र के संवर्धन में रानाडे ने प्रशा के भूमि सुधारों का अनुकरण का सुझाव दिया। उनका इस संवर्धन में सर्वप्रथम सुझाव यह था कि बृषि में संवर्धित क्षेत्रों में सभी प्रकार के सुधार समाज के विभिन्न वर्गों के आर्थिक संबंधों पर विसा प्रभाव की हिमक गडबड आने बिना अथवा त्रास का भूतका अनुभव किए बिना तथा असंवर्धित क्षेत्रों को जम दिए बिना ही किए जाने चाहिए।<sup>121</sup> बंगाल कास्टकारी कानून के प्रति उनके विरोध के कारणों में उनकी एक यह आशंका थी कि इस विल का अनिवाय परिणाम वर्ग संघर्ष होगा।<sup>122</sup> वह जमींदारों के वर्तमान अधिकारों के एकतरफा छीन जाने के भी विरुद्ध थे और बंगाल विल में उनके अनुसार यह भावना निहित थी।<sup>123</sup> इसके साथ ही उनकी यह भी मान्यता थी कि छीन गए अधिकारों की क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए।<sup>124</sup> इस संवर्धन में रानाडे की अपनी योजना किसानों और जमींदारों दोनों को धरती के स्वामित्व का समान अधिकार देकर दानों में सौहार्द और सीमनम्य की भावना उत्पन्न करता था। उनका प्रस्ताव था कि किसान को भूमि का पूरा स्वत्वाधिकार दे देना चाहिए परंतु केवल उत्तम ही भाग का, जितना उसकी पट्टेदारी के अंतर्गत आता है। नया स्वामित्व का खरीदने के मूल्य के रूप में उन अवशिष्ट धरती पर जमाखार के रूप में अपना सभी दाव छोड़ने हंग। इस प्रकार उसकी पट्टेदारीवाले भूभाग पर उसका पूरा स्वत्वाधिकार होगा और शेष भाग पर जमींदार का पूरा स्वामित्व ही जाएगा। यदि जमींदार का फिर भी कुछ बचावा निरालना है तो उसकी पूर्ति किसान कुछ एन वर्षों तक निराला प्रभाग के नए मुगतन द्वारा करेगा।<sup>125</sup> संक्षेप में जमींदारी अधिारों को खोलने के लिए जमींदारों का क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए तथा उन पट्टेदारी के अंतर्गत भूमि का कुछ भाग अपनी तान के लिए रखने का अधिकार मिलना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत निष्क्रिय लगान बगुन जाने जमींदार सालाना पूँजी निवारा उद्यमी किसान



कि कृषि की प्रगति देश के उद्योगों के साथ और द्रुतविकास के साथ बड़ी घनिष्टता में संबंधित है। जब तक देश के ग्रामीणों की प्रवृत्ति को शीघ्रता से रोका नहीं जाता दश की कृषि समस्या के समाधान की दिशा में किया जाने वाला कोई प्रयास सफल नहीं हो सकता।

इस दृष्टिकोण के प्रारंभिक प्रस्तावक के रूप में रानाडे ने 1881 में एक प्रस्तुत किया कि भारतीय कृषि में व्याप्त रोग का मूल कारण राजनीतिक पद्धति के गहरे प्रतस्तल में निहित है अतः बाहरी उपचार अथवा चमड़ी पर मरहम पट्टी करने का कोई लाभ नहीं होगा। स्थिति के उपचार के लिए किसी भी अन्य वस्तु से बचकर अपेक्षित यह है कि कृषि पर राज्य के भार को कम किया जाए और श्रम, उद्योग और फलतः पूँजी के लिए नए मांग खोलकर धरती पर आबादी का भार घटाया जाए।<sup>19</sup> बाद में 1892 में रानाडे ने 'भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था' पर दिए गए अपने भाषण में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि कृषि पर सदा के लिए निरंतर रहने वाले देश का निधन रहना तथा अपेक्षाकृत और अधिक निधन बनते जाना निश्चित है क्योंकि कृषि तो ह्रासमान प्रतिफल नियम (ला आफ डिमिनिशिंग रिटर्न) की अवाञ्छनीय स्थिति के अंतर्गत संचालित होती है और भारत में तो वर्षों की अनिश्चितता का एक और दुर्गुण इसके माध्यम में जुड़ा है।<sup>20</sup> 'मराठा' ने 1881-84 की अवधि में अपनी संपादकीय माला में कृषि प्रगति और औद्योगिक प्रगति के घनिष्ठ रूप से अयो-याश्रित होने पर बार-बार जोर दिया। उदाहरणार्थ, 4 सितंबर 1881 के अंक में उसने लिखा

कृषि संबंधी श्रम बाजार में कृषक श्रमिकों का आधिक्य है और जब तक यह आधिक्य कृषि से हटाया नहीं जाता और वही दूसरे स्थान पर खपाया नहीं जाता तब तक कृषकों की दीन हीन दशा में सुधार के लिए उपचार रूप में किए गए किसी भी प्रयास का उत्तम, लाभप्रद और स्थाई परिणाम नहीं निकलेगा। कृषि और मशीनी उद्योग का विकास साथ-साथ ही होना चाहिए।

इसी प्रकार अपने 12 फरवरी 1882 के अंक में उसने एक प्रस्तुत किया 'वेबल यानून' से, वेबल से कहा कि किसानों को स्थाई रूप में काश्तकारी के अधिकार देने से किसानों की हानत में तब तक कोई सुधार नहीं होगा, जब तक कि देश में विविध उद्योगों की स्थापना नहीं की जाती क्योंकि एकमात्र कृषि पर निर्भर रहने वाला देश कभी संपन्न नहीं रह सकता।<sup>21</sup> नेटिव ओपीनियन में भी अपने 25 मई 1884 के अंक में इस तर्क को दोहराया।

1895 में पी० सी० राय ने रानाडे के विचारों में सहमति प्रकट करते हुए घोषणा की कि कृषिसमाधान देश-दस्तकारी और हस्तशिल्पियों के देश की अपेक्षा गंदव विच्छन्न रहगा। देश की आर्थिक कठिनाई का सर्वोत्तम समाधान मूलतः भारतीय उद्योगों का पुनर्जागरण तथा पश्चिम के आधुनिक उद्योगों का अपनाना है। इसमें कृषि में श्रम का आधिक्य कम होगा और देश संपन्न बनगा।<sup>22</sup>

जी० पी० जोशी ने जमीन पाने की अवस्था और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के लिए कृषि पर बहुत भार को उत्तरदायी ठहराया। उनके अनुसार इस प्रतिस्पर्धा का दुष्परि-

पाम यह हुआ है कि धरती के लगान गगनचुम्बी हो गए हैं, धरती को छोटे छोटे टुकड़ा में बाटना पडा है और किसान की धरती मुधारने की आकांक्षा क्षीण हुई है।<sup>196</sup> इसके अतिरिक्त कृषि पर जनसंख्या के बढ़ते भार न बेवारी बढाई है और लाखों को जबरदस्ती निष्काम बना दिया है अथवा दूसरे शब्दों में इसने दश की आर्थिक शक्ति को बिनाशात्मक रूप से बेकार कर दिया है। उनकी सगपना के अनुसार जाधी से अधिक ग्रामीण जनता वास्तव में उपयुक्त काम के अभाव का शिकार थी।<sup>197</sup> अतएव उहान फालतू और बेकार जनसंख्या को समुचित काम जुटाने के लिए अटृपीय उद्योगों के विकास की सिफारिश की। उहाने अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि श्रम के नए अवसरों को जुटाने के रूप में वर्तमान अस्वस्थ और असामान्य दवाव में किसान जितना ही अधिक मुक्त होगा उतनी ही अधिक उमरी पायस्थिति भाररहित होगी और सफलता के अधिक अच्छे अवसर उम उपलब्ध होंगे।<sup>198</sup> उहान इस बात पर भी बल दिया कि जब तक भारत एकमात्र कृषि उद्योग पर निर्भर है, हमारी आर्थिक कठिनाइया का मूल अछता ही रहगा।<sup>199</sup> तिलक के केसरी ने 18 जून 1901 तथा 11 नवंबर 1902 के अंकों में इन दोनों धारणाओं की पुष्टि की।<sup>200</sup>

जी० मुग्रहाण्य अय्यर ने भी 1903 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'सम इकोनामिक आमपैक्टन आफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया' में इसी विचारधारा का असंदिग्ध अभिव्यक्ति दी। रूस के वित्तमंत्री एम० डी० वित्ते के इस बयान से सहमति प्रकट करते हुए कि जब तक कोई भी देश विपुल रूप से कृषिप्रधान देश बना रहेगा, तब तक वह समय समय पर आने वाले अकालों और सामान्य दरिद्रतापरक अभावों से मुक्ति नहीं पा सकेगा, अय्यर ने आराप लगाया कि इस सबंध में भारत की स्थिति रूस से भी बदतर है। यहाँ की 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और शेष मजदूरी अथवा छोटे छोटे अनुत्पादक घटकों पर आश्रित है। उहोंने लिखा कि जब तक देश की आर्थिक दशा की इस गभीर अव्यवस्था का उपचार नहीं किया जाता तब तक हजारों वर्षों की अवधि में भी न यहाँ का किसान सपन बन पाएगा और न ही दूसरे वर्ग समृद्धि प्राप्त कर सकेंगे। निर्धनता की इस चरम सीमा का निराकरण कभी नहीं हो पाएगा। अतएव देश का उद्योगीकरण देश की संपन्नता की अनिवार्य शर्त है।<sup>201</sup>

## संदर्भ

- 1 एकमात्र अपवाद 1899 का था और वह भी पंजाब लैंड एलियेशन बिल पर प्रस्ताव के रूप में कांग्रेस ने और बाता के साथ इस बात की भी सिफारिश की कि 'निजी किराया बसूली वाले जमींदारों के मामले में अनुचित रूप से किराये में बढ़ोतरी रोकने की कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए (प्रस्ताव II बी) जमींदारी पर कांग्रेस की चुप्पी को ए० ओ० ह्यूम की पुस्तिका 'डिस्ट्रिक्ट्स ऑन ऐग्रीकल्चरल रिफॉर्म इन इंडिया' में की गई टिप्पणियों तीर्थी भत्सनाभा पूणत, किराया बसूली करने वाले बेवार बिक्रीलिए आदि के संबंध में देखिए उनकी पुस्तिका



## 420 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास

आन एग्रीकल्चरल रिफॉर्म इन इंडिया (कलकत्ता 1889 पृ० 3)

- 2 सोम प्रकाश 14 जून (आर० एन० पी० पृ०, 19 जून 1880), नवविभावर 12 जुलाई (वही 17 जुलाई 1880) बदवान सजीवनी 9 नवंबर (वही 20 नवंबर 1880), भारत बंधु, 26 नव० (आर० एन० पी० पृ० एन० 2 दिसंबर 1880), साधारणी 15 मई (आर० एन० पी० पृ०, 21 मई 1881) केरल मित्रन, 30 अप्रैल (आर० एन० पी० पी० एम०, मई 1881), हिंदी प्रतीक अगस्त (आर० एन० पी० पी० एन० 3 सितंबर 1881) इंडियन म्येकट्टर 25 सितंबर (आर० एन० पी० पृ० ब० 1 अक्तू० 1881) परिष्कार, 1 जनवरी (आर० एन० पी० पृ० पृ० 14 जनवरी 1882) मंग प्रकाश 26 जून वही 1 जुलाई 1882, उत्कल दीपिका 15 जुलाई (वही 22 जुलाई 1882) प्रयाग समाचार 11 दिसंबर म प्रकाशित लेख (आर० एन० पी० पृ० एन०, 14 दिस० 1882) साधारणी 7 जनवरी (आर० एन० पी० पृ० पृ० 13 जनवरी 1883) समय 28 मई (वही 2 जुलाई 1883) सहचर 18 जुलाई (वही 28 जुलाई 1883), ग्रामवत प्रकाशिका 22 मार्च (वही 5 अप्रैल 1884) समय 29 दिसंबर 1884 (वही 3 जनवरी 1885) सहचर 6 मई (वही 16 मई 1885), सुरभि ओ पताका 9 दिस० (वही 18 दिसंबर 1886) सजीवनी 14 जनवरी (वही 21 जनवरी 1892) प्रहृति 21 जनवरी (वही 28 जनवरी 1892) मनोवनी 11 फरवरी (वही, 18 फरवरी 1892), चगनिवामा 25 अक्तू० (वही 2 नवंबर 1895) चार मित्रिन 27 अप्रैल (वही 9 मई 1896) केरल पत्रिका 16 नव० और केरल सचारी 20 नवंबर (आर० एन० पी० एम० 30 नव० 1895) केरल चंद्रिका 20 मार्च (वही 31 मार्च 1896) केरल सचारी 1 जुलाई (वही 15 जून 1896) हिंदुस्तान 25 अगस्त (आर० एन० पी० एन० 31 अगस्त 1898) और आन उल्लिखित समाचारपत्र और देखिए मराठा, 17 फरवरी 1884
- 3 बंगाली 23 जनवरी 1892 भी देखें
- 4 आर० एन० पी० पृ० 29 जून 1882
- 5 वही 21 जन 1884
- 6 वही 7 नवंबर 1891
- 7 आर० एन० पी० एम० 24 जनवरी 1874
- 8 आर० एन० पी० एम० 31 मार्च 1896 तथा देखिए केरल पत्रिका 1 अगस्त 12 और 26 दिसंबर (वही 15 अगस्त 31 सितंबर 1896)
- 9 वही 15 जुलाई 1896
- 10 इन पात्रों का इत बंगाल पृ० 210-23
- 11 वही पृ० 46 और आन
- 12 गंग पावटी पृ० 179-200 इंडियन फाइनेंसियर पृ० 39-40 55 57
- 13 जोशी पूर्वोक्त पृ० 870-94 900 01 904-05
- 14 वही पृ० 834
- 15 वही पृ० 351 2 तथा पृ० 412
- 16 एन० एम० अथर गंगार गेड राष्ट्रिय पृ० 250 4 मंग प्रकाश 14 जून (आर० एन० पी० पृ० पृ०, 19 जून 1880) साधारणी 23 जन० (वही 29 जनवरी 1881) मंग प्रकाश 14 अगस्त (वही 19 अगस्त 1882) चित्रचतनगुहा 5 मार्च (आर० एन० पी० एन० पी० एन० 15 मार्च 1883) एन० एन० पत्रिका एवावर II पृ० 17 केरल पत्रिका निबिर्दिष्ट

- (आर० एन० पी० एम० मार्च 1886) एच० ए० रहीम, रिप० आई० एन० सी० 1890 प० 55  
 बगनिवासी 25 अक्टूबर (आर० एन० पी० बग०, 2 नवंबर 1895) बेरल पत्रिका 16 नवंबर  
 और 14 दिसंबर (आर० एन० पी० एम० 30 नवंबर और 31 दिसंबर 1895) बरल पत्रिका  
 4 जुलाई और 1 अगस्त (वही 15 जुलाई और 15 अगस्त 1896) हिंदुस्तान 25 अगस्त  
 (आर० एन० पी० एन० 31 अगस्त 1898) राय पावर्टी प० 217 273 मालवीय स्पार्चज  
 प० 266-8 रिप० आई० एन० सी० 1900 प० 98 आई० एन० सी० 1899 का प्रस्ताव  
 II (बी०)
- 17 रानाडे एसज प० 30 1 327 जोशी पूर्वोद्धत प० 878 84 दत्त पीछ अध्याय 9 म पाट  
 टिप्पणी 116 तथा सी० पी० ए० प० 482 ओपन लेटस प० 18 74 8 मे तथा जे० एन०  
 गुप्ता पूर्वोद्धत प० 349
- 18 जोशी पूर्वोद्धत प० 365 6
- 19 आर० एन० पी० बब० 8 अक्टूबर 1881
- 20 आर० एन० पी० बग० 29 जुलाई 1882 तथा देखिए सोम प्रकाश 27 नवंबर (वही 2 दिसंबर  
 1882)
- 21 बगाली 19 फरवरी 1881 सोम प्रकाश 14 जून (आर० एन० पी० बग० 19 जून 1880)  
 सोम प्रकाश 27 नवंबर (वही 2 दिस० 1882) भारत मिहिर 22 जनवरी (वही 2 फरवरी  
 1884) तथा देखिए आगे पाद टिप्पणी 71 यहा यह उल्लेखनाय है कि किरायेदारा के स्थाई  
 बंदोबस्त की माग को सवप्रथम 1831 म राजा राममोहन राय न हा मुखरित किया था जमिन  
 मेन नोटस आन बगाल रिन्मा (कलकत्ता द्वितीय संस्करण 1957) प० 12 बी० बा० मजूमदार  
 पूर्वोद्धत प० 67 9 सोम प्रकाश ने अपने 24 जुलाई 1882 के अंक में अपन दृष्टिकोण क समथन  
 म राममोहन राय का मत उद्धत किया था (आर० एन० पी० बब० 29 जुलाई 1882)
- 22 आर० एन० पी० बग० 26 मार्च 1887 बगवासी 16 दिसंबर (वही 23 दिस० 1893)
- 23 आर० एन० पी० बब०, 22 अक्टूबर 1881
- 24 विशेष रूप से देखिए मराठा 27 जुलाई 1890 और ए बी० पी० 20 फरवरी 1899
- 25 हम समथ म राष्ट्रवाणी विचारधारा की शून्यता का उपन ध कारण कदाचित यह हा सकता है कि  
 विभिन्न प्रांतो के स्वदेशी पत्रा के सजायदाताओं ने हम सवध म उपलिन प्रतिवेदन हा न भज हो  
 यहा हम तथ्य की ओर हम जवयय निर्देश करना चाहंग कि हमन जितने भी राष्ट्रवाणी पत्रा  
 और पत्रिकाओं का उनकी मूल भाषा म तथा साथ ही साथ राष्ट्रवाणिया के लखा जीर भाषणा  
 का अध्ययन किया है उनसे हम इस परिणाम पर हा पहुंचे हैं कि ये सब तत्कालीन राष्ट्रवादी  
 नेताओं की इस विषय म वधारिक गहराई और रचि क अभाव के ही परिभाषक हैं साथ ही  
 यह निष्कप निदानना भी गनत और अनचिन न हागा कि यदि सजायदाताओं ने व्यापक तथा  
 प्रबन दृष्टिकोण के सवाद भज होते तो विषय की गभीरता का देखते हुए पत्र-पत्रिकाओं द्वारा  
 उनकी उपेक्षा कदापि समथ न होता
- 26 सी ई० बकनड बगाल अडर की रेफिटनेट गवर्नर (बकत्ता 1901) खड II प० 705  
 812 3 इलवट एल० सी० पी० 1883 खड XVII प० 77 8 स्ट्रुचा इडिया (1903)  
 प 4.4 जमींदारो द्वारा किसानो के दमन के लिए सरकारी रिपो के अवतरण दखिा जिहें  
 पावती चरण राय न अपन प्रव रि रट कवश्चन इन बगाल (कलकत्ता 1883) प० 122 और  
 आग म पुनरुद्धत किया है

422 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास

- 27 बकनेड पूर्वोद्धत खंड I, पृ० 544-8, खंड II पृ० 631-2, 636-3.
- 28 वही, खंड II पृ० 702, स्ट्रुची इंडिया (1903) पृ० 425-6
- 29 बकनेड पूर्वोद्धत, खंड II पृ० 704-05 813
- 30 इनवट एल० सी० पी० 1883 खंड XXII पृ० 80-3
- 31 वही पृष्ठ 84-8
- 32 वही पृष्ठ 100-126
- 33 बकनेड पूर्वोद्धत खंड II पृष्ठ 809
- 33 A वही पृष्ठ 811 2 और 1885 का अधिनियम VIII
- 34 दक्षिण 1885 के अधिनियम की धारा-49
- 35 लामल लाइफ आफ दि मोरनिंग आफ डपरिन ऐंड एवा (सदन 1905), खंड II पृ० 80
- 36 बकनेड पूर्वोद्धत खंड II पृ० 816
- 37 जर्नेल आफ ईस्ट इंडिया एगोसिएशन खंड XV सफ्या 3 1883 पृ० 191
- 38 जे० एन० गुप्ता पूर्वोद्धत पृ० 101-03 पर आर० सी० दत्त और ए० पी० मडडोलन
- 39 27 जून 1881 को इंडियन एगोसिएशन द्वारा प्रेषित प्रापन वागल पूर्वोद्धत परिशिष्ट पृ० I, II XIV पर 1879-80 का इंडियन एगोसिएशन का प्रतिवेदन ब्राह्मो पब्लिश ओपीनियन क 25 अगस्त 1881 के अरु म उद्धृत इंडियन एगोसिएशन का 29 अक्तूबर 1883 का विज्ञापन इंडियन एगोसिएशन का 1883 का प्रतिवेदन पृ० 15 और आगे एम० एन० बनर्जी स्पीचर II 6-11 ब्राह्मो पब्लिश ओपीनियन 28 अक्तूबर 9 16 फिब्रवर 1890 19 मई 16 जून 18 अगस्त 1881 बंगाली 24 जुलाई 14 21 अगस्त 4 सित० 9 अक्तू, 13 नव० 11 18 सित० 1880, 8 15, 29 जनवरी 3 फरवरी 17, 24 31 मार्च 7 अप्रैल 1 नवंबर 1884 समालोचक 27 फरवरी (आर० एन० पी० बग० 6 मार्च 1880) सोम प्रकाश 9 अगस्त (वही 14 अगस्त 1880) साधारणी 15 अगस्त (वही, 21 अगस्त 1880) नव विचारक 10 जनवरी (वही 22 जन० 1881) परिष्कार 6 फर० (वही 19 फरवरी 1881) साधारणी, 13 मार्च (वही 26 मार्च 1881) सुपावर 14 मई (वही 21 मई 1881) अणुवासी 11 नवंबर (वही 18 नवंबर 1882) साधारणी 24 सित० (वही 30 सित० 1882) इंडियन मिटर 31 मार्च (सी० ओ० आर्द०, अप्रैल 1883), इंडो पब्लिश ओपीनियन 9 16 23 अप्रैल (वही मई 1883) और 5, 21 जुलाई (वही जुलाई 1883) बंगवासी 7 जुलाई भारत मित्र 17 जुलाई प्रतिनिधि 12 जुलाई साधारणी 24 जून, प्रामथ प्रकाशिका 14 जुलाई संशोधनी 7 जुलाई (वही जुलाई 1883), माहम 23 जुलाई मध्यप्रारु (वही 30 अगस्त 1883), सहायर 28 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 31 मार्च अणु 31 मार्च प्रमती 3 अप्रैल (वही, 7 अप्रैल 15 जून 1883) संशोधनी, 11 अगस्त बंगवासी 25 अगस्त सित०, साधार 14 सितंबर (वही 22 सित० प्रकाशिका नव० 1883) प्रामथ प्रकाशिका, 10 नव 7 सित० प्रका 4 सित० 22 सित०

- 10 अप्रैल (वही 30 अप्रैल 1884), सजीवनी 16 फरवरी (आर० एन० पी० बग० 23 फरवरी 1884), ग्रामवत प्रकाशिका 16 फरवरी प्रतिकार, 22 फरवरी (वही 1 मार्च 1884)
- 40 इमी प्रकार इस पत्र ने 19 फरवरी 1881 के अंक में दृढ़तापूर्वक लिखा राष्ट्र का गठन किससे होता है ? क्या ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के कुछ सौ सदस्यों से ? अथवा मुफसिल में मिलने वाले कुछ हजार जमींदारों से ? अथवा सबको हजारों कलकत्तावासियों से ? राष्ट्र तो भाषणों में निवास करता है वस्तुतः बंगाल की यह गूणी कृषक जनता ही है जिससे वास्तव में राष्ट्र का गठन होता है इसी प्रकार अन्य सबल भाष्यताओं के लिए देखिए बंगाली, 14 अगस्त 13 नवंबर 1880 15 जनवरी 1881 ब्राह्मो पत्रिका ओपीनियन 9 दिसंबर 1880 25 अगस्त 1881 ए० एन० वनर्जी स्पीचेज II प० 13 20 साधारणी 15 जुलाई (आर० एन० पी० बग०, 28 जुलाई 1883), सजीवनी 11 अगस्त (वही 25 अगस्त 1883) बंगाल पत्रिका ओपीनियन 20 दिसंबर 1883 (वी० ओ० आई० 15 जनवरी 1884)
- 41 इंडियन एसोसिएशन का 1879-80 का वार्षिक विवरण 25 अगस्त 1881 के ब्राह्मो पत्रिका ओपीनियन में उद्धृत किमानों के प्रतिनिधि होने की हैसियत से ही एसोसिएशन ने बंगाल सरकार को 27 जून 1881 को किरायेदारी कानून पर एक ज्ञापन भेजा बंगाल पूर्वोद्घत परिशिष्ट ए में उद्धृत और दूसरा ज्ञापन 29 अक्टूबर 1883 को भेजा (इंडियन एसोसिएशन का 1883 का वार्षिक विवरण) प० 15 और आग
- 42 बंगाल पूर्वोद्घत प० 50 53-4 70-1 90 और परिशिष्ट प० 1 बंगाली 8 जनवरी 5 12 फरवरी 2 अप्रैल 14 28 मई 1881 ब्राह्मो पत्रिका ओपीनियन 20 जनवरी 10 फरवरी 1881 इंडियन एसोसिएशन का पाचवा वार्षिक विवरण 4 मार्च 1882 के बंगाली में उद्धृत, ए० बी० पी० 25 जून 1885
- 43 बंगाल पूर्वोद्घत, प० 53 54, 71, ए० बी० पी० 25 जून 1885
- 44 बंगाल पूर्वोद्घत, प० 72 3 78 इंडियन एसोसिएशन के 1885 में पाचवें वार्षिक विवरण में इस संदर्भ में कहा गया इस समय एसोसिएशन बड़ी सक्रियता से ग्राम सभों के निर्माण में जुटी हुई है शक्ति के प्रदर्शन के लिए आयोजित किए जाने वाले राजनीतिक प्रदर्शनों की सफलता के लिए लोगों की विपुल सहायता के सभों की बड़ी भारी आवश्यकता है यह तथ्य जब हमारे सामने आता है कि हमारा आंदोलन थोड़ा सा शिक्षित बानुओं तक सीमित है तो हमारे मन में बड़ी ही बसक पैदा होती है एसोसिएशन ने इस बसक अथवा बलक को मिटाने का सक्ल्य कर लिया है (उसी में उद्धृत, प० 90) तथा देखिए बंगाली, 4 मार्च 1882
- 45 और देखिए मराठा 10 अप्रैल 7 सितंबर 1884
- 46 वी० ओ० आई० मार्च 1883 और आर० एन० पी० बग० 31 मार्च 1883 इंडियन स्पेक्टेटर 24 जुलाई (आर० एन० पी० बग० 30 जुलाई 1883) और 1 अप्रैल तथा 1 जुलाई (वी० ओ० आई० अप्रैल और जुलाई 1883) भी देखें
- 47 नेटिव ओपीनियन ने बाद में अपनी स्थिति बदल ली और बिल का विरोध करना प्रारंभ कर दिया देखिए उसका दिनांक 11 नवंबर 1883 का अंक
- 48 बाबे त्रानिकल 25 फरवरी (वी० ओ० आई० मार्च 1883) ट्रिब्यून 7 अप्रैल (वही अप्रैल 1883) रास्त गोफतार, 4 नवंबर (वही नव० 1883) जामेजमगेद 20 दिसंबर 1883 बाबे त्रानिकल 30 दिसंबर 1883 गुजराती समाचार 1 जनवरी (वही 15 जनवरी 1884) बैसरी 16 मार्च (वही मार्च 1885)

- 4) रानाड एजेज प० 275 7
- 50 न्त स्याचज II प० 170 तथा चे० एन० गुप्ता पूर्वोद्धत प० 50 9९ 103
- 51 उपाध्याय भागन मिहिर 17 अगस्त दावा प्रकाश, 22 अगस्त (आर० एन० पा० बग० 28 जगन् 1880) भारत मित्र 14 सित० (वही 25 सित० 1880), विहार वध 9 16 23 सित० (वही 2 अक्टूबर 1880) साम प्रकाश 3 जनवरी (वही 8 जनवरी 1881) दावा प्रकाश 16 जनवरी (वही 22 जनवरी 1881) विहार हुराड 13 मार्च (वा० आ० आ०, मार्च 18८3) इण्डियन प्रानिबल 21 28 मई डिसेंबर 3 10 17 जून (वही जून 1883) चार वल 2 9 जुलाई (वही जुलाई 1883) उत्कल दीपिका 30 सितंबर 1892 (आर० एन० पा० बग० 20 जनवरी 1883) उत्कल दपण 21 जनवरी (वही 10 फरवरी 1883) चार वल 5 फरवरी (वही 17 फरवरी 18८3) साम प्रकाश 27 जगन् (वही 1 सितंबर 1883) 10 सितंबर (वही 22 सितंबर 1883) दावा प्रकाश 11 नवंबर (वही 17 नवंबर 1883), इण्डियन प्रानिबल 22 29 सितंबर 1884 (बी० ओ० आर्० जनवरी 188५) नवविभावर 9 मार्च (आर० एन० पा० बग० 14 मार्च 1885) बी० एन० माडरिज स्पेसिज प० 636 7 640-1 645
- 52 बी० आ० आर्० जनवरी 1885 तथा देविण ए० बी० पा० 3 मार्च 18८0 7 दिसंबर 1882 19 मार्च 1885 आनंद बाजार पत्रिका 23 अगस्त (आर० एन० पी० बग० 4 सित० 1880) 12 फरवरी (वही 17 फरवरी 1883) तथा ऐशिया इन्विचन मुद्रा 26 मार्च (आर० एन० पा० पी० एन० ५ अप्रैल 1883) एन एड उपाध्याय है वि 1883 के पत्रकारी टर्नेमा बिल पर रानाड के प्रहार का एक एन आधार था रानाड की आशंका यह थी कि इस बिल में एक वग व दूसरे वग के बीच हस्तगत की सरकार को अधिक शक्ति प्राप्त है जिसका उपयोग वह वग-वग का जम देन और बलान में कर सकता है (एतज प० 276) तथा देविण प० 283-4
- 53 ए० आ० पा 22 नवंबर 1883 आनंद बाजार पत्रिका 20 जून (आर० एन० पा० बग० 5 जुलाई 1883) और 21 जनार (वही 26 जनार 1883) इण्डियन मित्रात्री 8 फरवरी (बी० आ० आर् 15 फरवरी 1884)
- 54 ए० बी० पी० 10 मार्च 1881 21 मार्च 1884 19 मार्च 188५ आनंद बाजार पत्रिका 14 मार्च (आर० एन० पी० बग० 26 मार्च 1881) निपिरिन्नि (वा० ओ० आ० फरवरी 1893) तथा साग 61 3 पा० इण्डिया में उद्भव
- 55 ए० बी० पा० 2१ 29 नवंबर 1883 आनंद पत्रिका जारी नियत 29 नव० 6 11 सित० (बी० आ० आर्० सित० 1९९3) बगानी 24 नव० 15 सितंबर 1883 समय 26 नवंबर आनंद बाजार पत्रिका 26 नवंबर (आर० एन० पी० बग० 1 सित० 1893) नवविभावर 3 सितंबर (वही 8 सितंबर 1893) भारत मित्र 11 सित० (वही 22 सित० 1893) इण्डियन स्टार 2 सितंबर डिसेंबर 25 नवंबर इण्डियन रिबर 27 नवंबर 1० सितंबर इण्डियन इका 27 नव० भारत मित्र 27 नव० नवविभावर 26 नवंबर (बी० आ० आर्० सितंबर 1833) मगड और वजरागो मित्र 23 सितंबर 1893 (वही 15 जनवर 18९4)
- 56 10 अगस्त नवविभावर में एक महासभा (आर० एन० पा० बग० 4 सित० 13 0) भारत मित्र 21 सित 18९0 (वही 1 जन० 1931) विहार हुराड 27 मार्च 3 अप्रैल (वा० ओ० आर्० अप्रैल 1893) इण्डियन प्रानिबल, 7 मई 1९९3) इण्डियन प्रानिबल 21 जन० 4 फर० इण्डियन स्टार 29 जन० 1894) आनंद बाजार पत्रिका 7 सित० (आर० एन० पा० 1884)

- 57 डाका प्रकाश 16 जनवरी (आर० एन० पी० बग० 22 जनवरी 1881), विहार हेराल्ड, 12 और 19 फरवरी (बी० ओ० आर्द० 29 फरवरी 1884)
- 58 बिहार बंधु 9 16 23 सितंबर (आर० एन० पी० बग० 2 अक्टूबर 1880) हिंदू रजिना 8 दिना० डाका प्रकाश 12 सित० (वही, 18 दिसंबर 1880), भारत मिहिर 21 दिसंबर 1880 (वही 1 जनवरी 1881) सोम प्रकाश 9 मार्च (वही 14 मार्च 1885)
- 59 30 अगस्त के नवविभाकर का एच सबादाता (आर० एन० पी० बग० 4 सितंबर 1880), भारत मिहिर, 7 सितंबर (वही 18 सितंबर 1880) उत्पल दीपिका, 23 जून (वही 7 जुलाई 1883), बिहार हेराल्ड 8 15 अप्रैल (बी० ओ० आर्द० 30 अप्रैल 1884) साधारणी 7 दिसंबर (आर० एन० पी० बग० 13 दिसंबर 1884)
- 60 बिहार हेराल्ड 27 मार्च 3 अप्रैल (बी० ओ० आर्द० अप्रैल 1883) इंडियन फ्रानिक्ल 30 जुलाई (वही अगस्त 1883) बिहार हेराल्ड 11 18 मार्च (वही 31 मार्च 1884)
- 60-ग ए० बी० पी० 3 और 10 मार्च 1881 21 28 फरवरी और 6 नवंबर 1884 तथा 19 मार्च 1885 उमने अपने 3 मार्च 1881 के अक्ष म यह भी निश्चय किया कि वस्तुतः बंगाल के गावों का विचौलिया बाबू था जिमने परीक्षा पास कर रखी थी और जो लिखना पता और घर जाता था
- 61 आनंद बाजार पत्रिका 12 19 26 फरवरी (आर० एन० पी० बग० 17 24 फरवरी 3 मार्च 1883 और बी० ओ० आर्द० फरवरी 1883) और 23 जुलाई (बी० ओ० आर्द० अगस्त 1883)
- 62 आनंद बाजार पत्रिका 5 19 नवंबर (आर० एन० पी० बग० 10, 24 नवंबर 1883) 10 मार्च 18 अगस्त 22 सितंबर (वही 15 मार्च 23 अगस्त 27 सितंबर 1884) 3 अगस्त (वही 8 अगस्त 1885)
- 63 आनंद बाजार पत्रिका 26 फरवरी (आर० एन० पी० बग० 3 मार्च 1883) 10 मार्च 18 अगस्त (वही 15 मार्च 18 अगस्त 1884) तथा ऐन्ड्रिए नवनिभाकर 17 नवंबर (वही 22 नवंबर 1884)
- 64 बंगाली 17 नवंबर (आर० एन० पी० बग० 24 नवंबर 1882) भारत मिहिर 20 नवंबर 11 दिसंबर (वही 1 22 दिसंबर 1883) नवविभाकर 25 फरवरी 7 तब० (वही 1 मार्च 22 नवंबर 1884) साधारणी 25 मई (वही 31 मई 1884)
- 65 बंगाली 24 जुलाई 18 दिसंबर 18९0 8 जनवरी 1881 24 31 मार्च 7 अप्रैल 1883 22 29 नवंबर 1884 इंडियन एग्रीकल्चर का 27 जून 1881 का नामन पूर्वोक्त स्थान इन्डियन एग्रीकल्चर का 29 अक्टूबर 1883 का नामन पूर्वोक्त स्थान साधारणी 24 सित० (आर० एन० पी० बग० 30 दिस० 1882) मराठा 15 अप्रैल 1883 इन्डियन मिरर 31 मार्च (बी० ओ० आर्द० अप्रैल 1883) इंडियन नेशन 22 अक्टूबर (वही नव० 1883) समय 10 सितंबर (आर० एन० पी० बग० 22 सितंबर 1883) सत्यावनी 10 नवंबर (वही 17 नव० 1883) इंडियन नेशन 7 जनवरी (बी० ओ० आर्द० 31 जनवरी 1884) ग्रामवत प्रकाशिका 16 फरवरी (आर० एन० पी० बग० 1 मार्च 1884) मजबूतना 3 मई (वही 10 मई 1884) एम० एन० बनर्जी स्पेसिज II प० 15
- 66 बंगाली 15 जनवरी 1881 इंडियन एग्रीकल्चर का 27 जून 1881 का नामन पूर्वोक्त स्थान इंडियन एग्रीकल्चर के तत्वावधान म बिलिंगटन स्वयंवर बलनत्ता म हुई पट्टेदारों म सम्मेलन की बायबाही बंगाली 2 अप्रैल 1881

- 111 इंदु प्रकाश, 4 अगस्त (आर० एन० पी० ब०, 9 अगस्त 1879), मराठा, 10 अगस्त 1881, रानाडे 'लेड सा रिफाम ऐंड एग्रीकल्चरल बक्स जे० पी० एस० एस०, अक्टूबर 1881 (खंड IV सख्या 2), प० 39-40, जोशी पूर्वोद्धत, प० 350 356, 515 521 2 ए०बी० पी० 20 मार्च 1892 22 नव० 1898, राय पावटी पृ० 222 नदी इंडियन पालिटिक्स पृ० 116 118, सियालकोट पेपर, 16 नवंबर (आर० एन० पी० बी०, 25 नव० 1899), दत्त सी० पी० ए० प० 478 बंगाली 21 अगस्त 1901, एन० सी० केलकर एच० आर०, सितंबर-अक्तूबर 1901 पृ० 243, जी० एस० अय्यर ई० ए० पृ० 13 16 बेमरी 18 फरवरी (आर० एन० पी० ब०, 22 फरवरी 1902)
- 112 और देविण ज्ञान प्रकाश 5 सितंबर द्रोघ मुधाकर 28 अगस्त (आर० एन० पी० ब०, 7 सित० 1878), ज्ञान प्रकाश 30 सित० (वही 5 अक्टू० 1878) इंदु प्रकाश 4 11 अगस्त (वही 9 16 अगस्त 1879), इंदु प्रकाश 25 अक्टू० (वही, 30 अक्टूबर 1880), इंदु प्रकाश 5 सित० (वही 10 सित० 1881), रानाडे दि इवन एग्रीकल्चरिस्ट्स विल, जे० पी० एस० एस० अक्टू० 1879 (खंड II स० 2) पृ० 46 7 'लेड सा रिफाम एंड एग्रीकल्चरल बक्स पूर्वोद्धत स्यल प० 37 55 और बेलाक पूर्वोद्धत पृ० 27, मराठा 24 सितंबर 1882 इंडियन स्केटेटर 8 अक्टूबर (आर० एन० पी० ब० 14 अक्टूबर 1882) ए० बी० पी० 26 जून 1884 20 मार्च 1892 22 नवंबर 1898, 1 2 जनवरी 1901 रूबरे हिंदू 3 जुलाई (आर० एन० पी० बी० 15 जुलाई 1893) जोशी पूर्वोद्धत प० 348-9 357 408 410 414 421 426 435 443-4 448 50 515 522 पी० महता पूर्वोद्धत प० 394 5 450 575 655 मालवीय पूर्वोद्धत प० 305 06 312-3 आई० एन० सी० 1895 का प्रस्ताव A, आर० एन० मुधोलकर रिप० आई० एन० सी० 1895 प० 111 आर० पी० बर्गंडकर वही प० 112, नदी इंडियन पालिटिक्स, प० 131 2, गोखले स्पीचर, पृ० 1016-7 जी० एस० अय्यर विलवा वमीशन खंड III अगस्त 1902 4 रिप० आर० एन० सी०, 1900 प० 29 और ई० ए० प० 13 16 7 अक्टूबर आर० एन० एन० 6 जनवरी (आर० एन० पी० बी० 14 जनवरी 1899) पत्रिका समाचार 18 मार्च (वही 25 मार्च 1899) दान अक्टूबर 1899 पृ० 67 निसंबर 1899 प० 136 दत्त सी० पी० ए० प० 480, स्पीचर II प० 194 ई० एच० II पृ० 331, जी० बी० पारिख बर्गंड व दगवें प्रांतीय सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण बंगाली 22 मई 1900, सी० आई० चिंतामणि इंडिया ऐंड साइ ब्रजन पूर्वोद्धत स्यल पृ० 341 2 बंगाली 21 अगस्त 1901 मद्रास स्टेट्स 2 अगस्त (आर० एन० पी० एम० 10 अगस्त 1901), रिभ्यू आफ् फायनंस पत्रिका द पीपल टेंड बार' एच० आर० अगस्त 1904 प० 196 और देविण पीठ अगस्त 9 और आर० मुनि स्वामित्व परिवर्तन' भाग I
- 113 एन० एम० घोष स्पीचर प० 88 रानाडे दि इवन एग्रीकल्चरिस्ट्स विल पूर्वोद्धत स्यल पृ० 50-1 'लेड सा रिफाम ऐंड एग्रीकल्चरल बक्स पूर्वोद्धत स्यल पृ० 44 पुना मासिक पत्रिका 6 सितंबर 1879 का विरोधक ख० पी० एम० एम० जनवरी 1890 (खंड II स० 3) प० 106 मजिबनी 6 अगस्त (आर० एन० पी० ब० 13 अगस्त 1898) दान अक्टूबर 1899 पृ० 67 निसंबर 1899 प० 136 7 गोखले स्पीचर पृ० 1016 दत्त स्पीचर I प० 13-4 27 रिभ्यू आफ् फायनंस—पत्रिका द पीपल टेंड बार' एच० आर० अगस्त 1904 पृ० 197
- 114 उमाहरनाथ देविण रानाडे दि इवन एग्रीकल्चरिस्ट्स विल पूर्वोद्धत स्यल, पृ० 45 'लेड

रिफाम एंड एग्रीकल्चरल बस' पूर्वोक्त स्थल पृ० 55, जोशी पूर्वोक्त पृ० 346 7, 443 4  
515 517 519 536, मेहता स्पीचेज पृ० 663 4 810 मालवीय स्पीचेज पृ० 308, आर०  
एन० म्घोलकर रिप० आई० एन० सी० 1895 पृ० 111, नदी इंडियन पालिटिक्स पृ० 117  
जी० एम० अम्पर ई० ए०, पृ० 13 6, दत्त ओपेन लेटर्स प० 78 स्पीचेज I पृ० 27 तथा  
देविण पोछे अष्टमाय 9 और आय पाठ टिप्पणी सख्या 152

115 आर० एन० पी० बब 22 फरवरी 1902

116 उदाहरणार्थ देविण ज्ञान प्रकाश 30 सितंबर (आर० एन० पी० बब 5 अक्टूबर 1878), एल०  
एम० घोष स्पीचेज, पृ० 88 आनंद बाजार पत्रिका 7 सितंबर (आर० एन० पी० बग० 18  
सितंबर 1880) इंदु प्रकाश 25 अक्टू० (आर० एन० पी० बब 30 अक्टूबर 1880) भारत  
बधू 26 नवंबर (आर० एन० पी० पी० एन० 2 दिस० 1880) रानाडे मिस्टर वेडरबन एंड  
हिज त्रिटिग्न आन ए परमानेंट सटलमेट पार दि इवन जे० पी० एस० एस० जनवरी 1881  
(घट III सं० 3) पृ० 17, 'नद सा रिफाम एंड एग्रीकल्चरल बस' पूर्वोक्त स्थल, पृ० 41  
50 मराठा 1 जनवरी, 12 19 फरवरी 1882 बंगाली 2 दिस० 1882 भारत मिहिर 28  
नवंबर (आर० एन० पी० बग० 9 दिस० 1882) भारत मिहिर 28 नवंबर (आर० एन०  
पी० बग०, 9 दिसंबर 1882), भारत मित्र 22 नवंबर (वही 1 दिसंबर 1883) ए० बी० पी०  
12 26 जून 1884 सजीवनी 19 अप्रैल (आर० एन० पी० बग० 26 अप्रैल 1884) हिंदू  
पत्रिका 30 अप्रैल (वही, 10 मई 1884) हिंदू 29 दिसंबर 1884 राजा रामपाल सिंह  
रिप० आई० एन० सी० 1886 पृ० 65 6 बोहेनूर 13 15 17 अगस्त रावी 14 अगस्त  
आफताबे पंजाब, 16 अगस्त (आर० एन० पी० पी० 24 अगस्त 1889) हितवादी 25 जुलाई  
'आर० एन० पी० बग 1 अगस्त 1891) बगनिवासी 28 अगस्त (वही 5 सितंबर 1891)  
बंगाली 23 जनवरी 1892, हिंदुस्तान 26 अप्रैल (आर० एन० पी० एन० 28 अप्रैल 1892)  
ताज उल अखबार 4 फरवरी (आर० एन० पी० पी० 18 फरवरी 1893), रहवरे हिंद 13  
जुलाई (वही 22 जुलाई 1893) अखबारे आम 13 अक्टूबर (वही 21 अक्टूबर 1894),  
रहवरे हिंद 14 मार्च 20 जून (वही 23 मार्च और 6 जुलाई 1895) अखबारे आम 18  
जुलाई (वही 27 जुलाई 1895) गमखबारे हिंद 20 जुलाई (वही, 3 अगस्त 1895)  
जाशी पूर्वोक्त पृ० 350 61 407-08 411 3 447 8 राम पावटी, पृ० 220  
सहृषर 13 मार्च सजीवनी 16 मार्च (आर० एन० पी० बग० 23 मार्च 1895), आर० एन०  
म्घोलकर रिप० आई० एन० सी० 1896 पृ० 15 तिलक रामगोपाल पूर्वोक्त पृ० 145  
सजीवनी, 19 मार्च 6 13 27 अगस्त (आर० एन० पी० बग० 26 मार्च 13 20 अगस्त  
3 सितंबर 1898) आर० एम सयानी एल० सी० पी० 1898 खड XXXVII प० 524,  
पोइनेक्स 5 अक्टूबर गुरुजी 6 अक्टूबर (आर० एन० पी० बब० 6 अक्टूबर 1898), ताज  
उल अखबार 21 जनवरी (आर० एन० पी० पी० 4 फरवरी 1899) पसा अखबार 1  
फरवरी (वही 18 फरवरी 1899) सियालकोट पेपर 8 अक्टू० (वही 28 अक्टूबर 1898)  
अल्मोडा अखबार 1 अप्रैल (आर० एन० पी० एन० 12 अप्रैल 1899) मराठा 8 अक्टूबर  
1899 काचा स्पीचेज प० 436 दत्त स्पीचेज I प० 14 तंज वहादुर सधू एच आर०  
नवंबर 1900 पृ० 36 प्रोसीडिंस आफ् दि फ्रंट नाथ अरकोट डिस्ट्रिक्ट काफिस हेल्ड आन 21  
22 जुलाई 1900 पृ० 9 एन० जी० चदावरकर सी० पी० ए० पृ० 517 नमरो के 12  
फरवरी 12 मार्च के सबाददाता (आर० एन० पी० बब 16 फरवरी 16 मार्च 1901) विक्ट



दूतन 4 मई (आर० एन० पी० एम० 4 मई 1901) इडियन मिरर, 28 सित० (आर० एन० पी० बग० 5 जनू० 1901) यू इडिया 25 नव० 1901 सी० वाई० चित्तामणि इडिया ऐंड साइ बज्जन पूर्वोक्त स्थल प० 341, पी० मेट्टा स्पीचेज प० 625, एम० आर० आर० अप्पर रिप० आई० एन० सा० 1903 प० 142, सा० सी० घोष वही, प० 144, गोवत म्पाचेज प० 111 329 1034 मालवीम स्पीचेज, प० 30

117 रिप० आई० एन० सी० 1899 प० 44

118 रानाडे एमेज प० 293 4, जोशी, पूर्वोक्त प० 419-20 439 447 8 519 21 आर० एन० मधोलकर रिप० आई० एन० सी० 1895 प० 108 09, नदी इडियन पालिटिक्स, प० 116 7 एम० एन० बनर्जी मा० पा० ए० प० 698, बगाली 13 फरवरी 1892 सजीवनी 13 जगस्त (आर० एन० पी० बग 20 अगस्त 1898), इडियन स्पेक्टेटर 11 दिसंबर 1898, पसा अखबार 1 फरवरी (आर० एन० पी० पी० 18 फरवरी 1899) सियालकोट 5पर 8 जनूबर (वही, 28 जनूबर 1899), इंदु प्रकाश 9 जनूबर (आर० एन० पी० बब० 14 जनूबर 1899)

119 रानाड रिड्जन ऐग्रीकल्चरिस्ट्स विल पूर्वोक्त स्थल प० 49 50 आनंद बाजार पत्रिका 7 मितबर (आर० एन० पी० बग० 18 सितंबर 1880) शान प्रकाश 25 मित० (आर० एन० पा० बब, 30 मितबर 1882), इडियन स्पेक्टटर 8 मयतूबर 26 नवंबर (वही 14 अतू० 2 मित० 1882) ए० बा० पी०, 25 जनवरी, 1 फरवरी 1883 20 मार्च 1892 22 नवंबर 1898 इडियन स्पेक्टटर 29 जून (आर० एन० पी० बब 5 जुलाई 1884) जाशी पूर्वोक्त प० 343 एन० जा० चन्नावरर सा० पा० ए० पू० 517 प्रधान और भागवत पूर्वोक्त म नितर प० 133 पी० मत्ता स्पाचेज प० 656-7 जी० ब० पारिष प्रोसीडिंग आफ दि कौंसिल आफ गिवनर आफ बाब 1901 पृष्ठ XXXIX प० 314, डा० ए० एर वही प० 325-6 वाचा सी० पी० ए०, प० 582 जी० एत० अम्बर ई० ए० प० 156

120 तुलनीय गाइडिन पूर्वोक्त प० 97 तथा बज्जन स्पीचेज II प० 29 सी० एम० रिवाज एन० सी० पी० 1899 पृष्ठ XXXVIII प० 325 6 जा० हेमिन्गन इडियन डिबेट 3 फरवरी 1901 लगभग 113

121 मराठा 6 मार्च 1881 7 मई 1882, अष्टवारे आम 6 नवंबर (आर० एन० पा० पा० 17 नवंबर 1894) और 6 जनवरी (वही 14 जा० 1899) विक्टोरिया पार 17 जुलाई (वही 5 अगस्त 1899) भारत मित्र 22 जनवरी (आर० एन० पी० बग० 27 जनवरी 1900), ए० बी० पी० 1 जनवरी 1901, बंगरा 18 फरवरी (आर० एन० पा० बब 22 फरवरी 1902)

122 रानाड रिड्जन एग्रीकल्चरिस्ट्स विल 30 पी० एम० एम० जनूबर 18, 9 (पृष्ठ II म० 2) (यह सद्य मूल रूप में सद्य ब नाम ब रिना प्रकाशित हुआ था और मनकर ब जनूगार इन जस्टिस रानाड न हू लिगा था सद्य में लगे गान्य है त्रिगम इन सद्य म मनकर का विचार अगणित रूप से सद्य मित्र हुआ है) गुता गान्यनिग एन० एन० 6 मितबर 1879 का विरालयन जे० पा० एम० एम० जनवरी 1890 (पृष्ठ II म० 1) का सद्य गुताग और सी० मित्र) आर० एन० ए० " 16 जनवरी 1879), (पृष्ठ 16 अगस्त 1879) जाम बम, 23 अगस्त 1879

123 रानाडे अड सा रि

पृष्ठ

- 124 इंदु प्रकाश 22 जुलाई (आर० एन० पी० वब 27 जुलाई 1878) चान प्रकाश, 30 सितंबर (वही 5 अक्टूबर 1878) गुजरात मित्र 29 दिसंबर 1878 (वही 4 जनवरी 1879) अरुणोत्पल 27 जुलाई (वही 2 अगस्त 1879) इंदु प्रकाश 4 अगस्त (वही 9 अगस्त 1879) नटिव गार्पिनियन 10 अगस्त (वही 16 अगस्त 1879) इंदु प्रकाश 29 नवंबर (वही, 4 दिसंबर 1880), सुबोध पत्रिका, 5 दिसंबर (वही 11 दिसंबर 1880) मराठा 3 अप्रैल 1881 3 फरवरी 1884 इंदु प्रकाश 3 अप्रैल (आर० एन० पी० वब 8 अप्रैल 1882) शिवाजी 22 सितंबर (आर० एन० पी० वब 30 सितंबर 1882) इंडियन स्पेक्टर 8 अक्टूबर (वही 14 अक्टूबर 1882), मराठा 15 अक्टूबर 1882, जनवरी 1883 व धा० जा० जाई० म उद्धत समाचारपत्र
- 125 दि इवन एग्नीकल्चरिस्टस एकट पूर्वोक्त स्थल प० 44
- 126 एसेज प० 327 और रि सड ला रिफाम ऐंड एग्नीकल्चरल बक्स पूर्वोक्त स्थल प० 42 45 6 49 53 पूना सावजनिक सभा का 6 सितंबर 1879 का विरोधपत्र पूर्वोक्त स्थल प० 110 11 परवर्ती वर्षों में बहुत सारे भारतीयों ने इस प्रकार का भय प्रकट किया तथा निर्देश किया कि बिल सादृकार और कजदारा में भगडा पदा करन के लिए बनाया गया है और इसका परिणाम बहुत सारे मामलों में किसानों की धरती के मयाय रूप में ही साहूकारों के हाथों में चले जान के रूप में हुआ है अतः उन्होंने अधिक उदार राजस्व नीति की जोर किसान के ऋण के लिए वकल्पिक साधन की व्यवस्था का वकानत की नेटिव बोपीनिधन 23 सितंबर 1888, मराठा 4 अक्टूबर 1891 केसारे हिंद 28 अक्टूबर (वही 24 अक्टूबर 1891) गुजरात दपण 29 नवंबर (वही 5 दिसंबर 1891) जाशी पूर्वोद्धत पृ० 355 359-60 वी० आर० नातू रिप० आई० एन० सी० 1894 प० 38 इंदु प्रकाश 7 मई (आर० एन० पी० वब 12 मई 1891) इंडियन स्पेक्टर 13 मई (वही 19 मई 1894), एन० जी० चंदावरकर सी० पी० ए० प० 509 10 517 8 पी० मेहुता स्पीचेज प० 304-05
- 127 मराठा 5 जून 1881 24 सितंबर 1882 4 अक्टूबर 1891 इंदु प्रकाश 21 सितंबर 1891 प्रकाशक 4 जनवरी कास 4 जनवरी (आर० एन० पी० वब 12 जनवरी 1901)
- 128 प्रमाण के रूप में देखिए भारत सरकार का 3 जनवरी 1894 का भारत सचिव का संपरण होम (पब्लिक) प्रोसीडिंग्स जनवरी 1894 प्रोग स 186 (ए) कठिका 28 ज० मोटी प्रोमोनिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बावे 1900 खड XXXVIII पृ० 141 और वही 1901 खड XXXIX पृ० 179 84 आज हैमिल्टन इंडियन डिबेटस 3 फरवरी 1901 लगभग 111 5 खड रेविन्यू पालिसी आफ दि गवर्नमेंट आफ इंडिया 1902 कठिका 29 एरिक स्टोम दि इंग्लिश यूटिलिटेरियस ऐंड इंडिया (आक्सफोर्ड 1959) प० 138 39 रोस पूर्वोद्धत पृ० 319
- 129 ज० मोटी प्रोसीडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बावे 1900 खड XXXVIII पृ 141 आज हैमिल्टन इंडियन डिबेटस 3 फरवरी 1901 लगभग 111 2 एम० एम० पावन का 10 जनवरी 1902 को फवियन सोसायटी में भाषण स्टेटसामन 6 फरवरी 1902
- 130 इन दक्खिण के विभाग के इतिहास के लिए देखिए सी० एम० रिवाज एल० सी पी० 1899 खड XXXVIII पृ० 318 20 1857 और 1880 में सरकारों शत्रु में इस विषय पर मतभेद के लिए देखिए रामाडे एसेज पृ० 294-324
- 131 1900 का अधिनियम LIII

- 132 सी० एम० रिवाज पूर्वोक्त स्थल, प० 325-7, वजन, स्पीचेज I प० 124-5 स्पीचेज II प० 28-9-34
- 133 1901 का वरई अधिनियम IV ज० एम० मॉटी प्रोसीडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ इंडिया 1901 पृष्ठ XXXIX प० 186, जोशी, पूर्वोक्त प० 532-539-545
- 134 रानाड, लड ना रिफार्म ऐंड एंग्रिकल्चरन बक्स पूर्वोक्त स्थल प० 32 एमेज प० 325-7 आई० एम० सी० 1895 का प्रस्ताव X 9 नव० 1895 को पूरा सावजनिक सभा द्वारा लाइ एलमिन को सहायन जे० पी० एल० एम०, जनवरी 1896 (पृष्ठ XVIII स० 3) प० 11 दल सी० पी० ए० प० 478 और स्पीचेज II प० 16
- 135 आई० एम० सी० 1899 का प्रस्ताव II इंडियन स्पेक्टेटर 8 अक्टूबर इतु प्रकाश 9 अक्टूबर (आर० एम० पी० बख 14 अक्टू० 1899) हिंदुस्तानी, 20 सितंबर (आर० एम० पी० एन०, 26 सितंबर 1899) इंडियन स्पेक्टेटर जुलाई 1900 केशरी 30 अक्टूबर (आर० एम० पी० बख 3 नव० 1900) बंगाली 8 नवंबर 1900 7 अक्टूबर के अथ म हिंदू ने तथा 8 नवंबर 1899 के अथ म मराठा न विल का निम्न ता नना की परतु उम निरथक घोषित किया
- 136 विल के समर्थन के लिए दक्षिण सिविल एंड मिलिट्री यूज 4 अक्टू० (आर० एम० पी० पी०, 21 अक्टू० 1899), पला अधिवार 4 नवंबर (वही 18 नवंबर 1899), रफीके हिंदू 18 नव० (वही 25 नवंबर 1899) रफीके हिंदू 3 मार्च 28 अप्रैल 9 जून 8 सितंबर 3 नवंबर (वही नमक 10 मार्च, 5 मई 30 जून 15 सितंबर 17 नवंबर 1900) गमहवारे हिंदू 27 जनवरी (वही 3 फरवरी 1900) विरोधियों के लिए देविए टिप्पण 7 अक्टू० (आई० एम० पी० पी० 22 अक्टूबर 1899) वरान 31 जुलाई (आर० एम० पी० पी० 12 अगस्त 1899) मियाजवाट पपर 8 अक्टूबर (वही 28 अक्टूबर 1899) विकारिया पेपर 4 नवंबर (वही 18 नवंबर 1899) पत्राज समाचार 18 नवंबर (वही 25 नवंबर 1899) दोस्त हिंदू, 2 मार्च विकारिया पेपर 5 मार्च (वही 10 मार्च 1900) मियाजवाट पपर 8 अप्रैल (वही 14 अप्रैल 1900) पब्लिश गजट, 24 अक्टूबर (वही 3 नवंबर 1900) पत्राज के दो भाषणी नाराजा मुरवाधर और कन्हैयालाल ने कायम अधिवेशन म विल का विरोध किया देविए रिप० आई० एम० पी० 1899 प० 45-7
- 137 आर० एम० पी० पी० नमक 18 अगस्त और 3 नवंबर 1900
- 138 वना 24 नवंबर 1900 इमी प्रकार 22 अगस्त 1900 के अथ म विकारिया पेपर म अपनी मिच्छी म्मिनि म पत्राज पया और सहायन विल का समर्थन करने तथा आर० एम० पी० पी० 8 सित० 1900
- 139 हायवड पूर्वोक्त प० 71 एच० मानी पूर्वोक्त पृष्ठ 1 प० 424
- 140 मराठा 30 जून 7 14 जुलाई 1901 हिंदू 31 जुलाई 1901 ए० बी० पी० 26 अगस्त 1901 आर० एम० पी० बख 1 8 22 जून 1901 म प्रतिबन्धित समाचारपत्र तथा दक्षिण अगस्त अगस्त और सितंबर 1901 के आर० एम० पी० बख
- 141 जोशी पूर्वोक्त प० 439-44, 512-54 पी० मन्ना स्पीचेज प० 641-6 651-712 गानन स्थावर प० 1017-48 जा० क० पाठ्य प्रामादिकम आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ इंडिया 1901 पृष्ठ XXXIX प० 191-5 312-71 रा० ए० ए० वरे वना प० 319-28 प्रस्ताव और समाचार पूर्वोक्त म नियम प 132-3 काथा म० पी० ए० प० 169-70 एम० पी० बखन नि रोटि सैड लिविन्गेन इन बाक एच० आर०, सितंबर-अक्टूबर 1901 प० 242

और आग तथा देखिए दत्त स्पीचेज II पृ० 136 138 और हर्नड म दहन बाल भारताभा के सम्मेलन की ओर स दादाभाई नौरोजी द्वार० सी० दत्त और व० हरनामसिंह द्वारा इस्ताम्बरित पापा दत्त, स्पीचेज II पृ० 141 9 म पुन उद्धत

- 142 प्रोसार्डिगा आफ नि बॉमिन आफ नि गवर्नर आफ बावे 1901 छह XXXIX प० 367 8
- 143 पूना सावजनिक सभा का 6 सितंबर 1879 का विरोधपत्र पूर्वोक्त स्थल प० 110 आर० एन० मुधोकर, रिप० आई० एन० सी० 1895 पृ० 110 रहबर 1 माच (आर० एन० पी० एन० 10 माच 1897) आई० एन० गी० 1899 का प्रस्ताव II इंडियन स्पेक्टेटर 8 अक्टूबर इंदु प्रकाश 9 अक्टू० (आर० एन० पी० वच 14 अक्टूबर 1899) पना अक्टूबर 1 फरवरी (आर० एन० पी० पी०, 18 फरवरी 1899) बकील 31 जुला (वही 12 अगस्त 1899) विक्टोरिया पेपर 4 नवंबर (वही 18 नवंबर 1899) सियामकोट पेपर 16 नवंबर (वही 25 नवंबर 1899) इंडियन एनोमिशन की साहौर की उपसमिति का प्रतिवेदन, रफिबे हिं, 25 नवंबर म पुन उद्धत (वही 9 दिसंबर 1899) बेमरी 30 अक्टूबर (आर० एन० पी० वच 3 नवंबर 1900) भाषा पूर्वोद्धत प० 444 515 544 गोयल स्पीचेज प० 1032 3 पी० मत्ता स्वाचत्र प० 674 686 जी० बे० पारिष पूर्वोद्धत प० 192 3 ही० ए० वर पूर्वोक्त स्थन प 325 सी० का० चित्तमणि इंडिया ऐं साह राजन एच० आर० मई 1901 प० 340-1 मराठा 14 जुलाई 1901 बहमदाबाद टाइम्स व सरे दि 26 मई गजरातो 26 मई (आर० एन० पी० वच 1 जून 1901) इंदु प्रकाश 20 जून (वही 22 जून 1901) मातवाय स्पीचेज प० 310, 317
- 144 रहबर 1 माच (आर० एन० पी० एन० 10 माच 1897) विक्टोरिया पेपर 4 नवंबर (आर० एन० पी० पी० 18 नवंबर 1899) पत्र समाचार 18 नवंबर सियामकोट पेपर 16 नवंबर (वही 25 नवंबर 1899) इंडियन एनोमिशन साहौर की उपसमिति का प्रतिवेदन पूर्वोक्त स्थल सात हिंद 2 माच (आर० एन० पी० पी० 10 माच 1900) दत्त सी० पी० ए०, पृ० 477 आयेन टेटर पृ० 78 स्पीचेज II पृ० 36 ई० एच० II पृ० 471 487 494 फसलकर रिप० आई० एन० सी० 1899 प० 47 भाषी पूर्वोद्धत प० 444 मातवीय स्पीचेज पृ० 317
- 145 रानाठ एंड सा रिफाम एंड ऐग्रीकल्चरल बैंक पूर्वोक्त स्थल प० 32 3 पूना सावजनिक सभा का साह एनगिन को सत्रोघन 9 नवंबर 1895 पूर्वोक्त स्थन प० 11 आर० एन० मधोलकर रिप० आई० एन० सी० 1899 पृ० 109-10 मधोलकर रिप० आई० एन० सी० 1899 पृ० 45
- 146 भाषी पूर्वोद्धत प० 444 513, 515 522 530-1 पी० मत्ता स्पीचेज प० 643-4 654 658 9 650-5 692 3 697 702 704 गोयले स्पीचेज पृ० 1018 9 1038 9 बाबा सी० पी० ए० प० 569-70 बेसरी 4 18 जून (आर० एन० पी० वच 8 22 जून 1901)
- 147 भाषी पूर्वोद्धत प० 531 543, पी० मेहता स्पीचेज प० 675 711 गोयल स्वाचत्र प० 1037
- 148 रानाठ, एसेज प० 325-7 जे० एन० गप्ता पूर्वोद्धत म दत्त प० 168, इंडियन स्पेक्टेटर 8 जुलाई 1900 जी० व० पारिष पूर्वोक्त स्थन प० 316
- 149 विक्टोरिया पेपर 4 नवंबर (आर० एन० पी० पी० 18 नव० 1899) बकील 20 नव (वही, 2 दिस० 1899) इंडियन एनोमिशन साहौर की उपसमिति का प्रतिवेदन पूर्वोक्त स्थन

बन्देसाल, रिप० आइ० एन० सी० 1899, प० 46 एन० सी० कलवर, दि रीसेंट लड लेनिस्तेशन इन बाय, पूर्वोक्त स्थल, प० 247 दूसरी ओर मोखले ने शिकायत की कि बर्दे लजिस्लेशन के तथाकथित शिकार इससे किनी भी रूप में बुरी तरह से प्रभावित नहा हो (स्पीचज प० 1010 1037 S)

- 150 उदाहरणार्थ जिरोजशाह मेहता ने यह निर्णय करने के उपरांत कि अंगरेज अधिकारी देशी व्यक्तियों के साथ संपर्क बनाता है यह सहानुभूतिपूर्ण होने पर भी अवेला पड़ जाना है जिन्नामु होने पर भी अनमिन रहता है और जीवनप्रयत्न अजनबी और विदेशी ही बना रहता है दडगापूर्वक रूप कि मैं और मेरे साथी ही यह कहने का दावा कर सकते हैं कि हम किसानों के विचारों और भावों को यत्नित रूप से और सही तौर पर जानते तथा उनकी जानकारी का अनुभव रखते हैं हम ही उनके जीवन के दृग् उनकी इच्छाओं और आशाओं का उनके स्वभाव उनके पूर्वग्रहों और रुचियों आदि का जानते और समझते हैं अतः कृपको के विचारों को ठीक ढंग से प्रस्तुत करने का और उनका प्रतिनिधित्व करने के सही अधिकारी हम ही हैं न कि इर द्वीप में रहने वाले अंगरेज और कृषक जनता से दूर तथा अलग अलग अंगरेज अधिकारी (स्पीचेज प० 6,0) तथा देखिए बने प० 640 1 652, 703 मोखले स्पीचेज प० 1029 30
- 151 एन० सी० कलकर रि रीसेंट लड लेनिस्लेशन इन बाय' पूर्वोक्त स्थल प० 244 तथा आर० एन० मगावर रिप० आइ० एन० सा० 1895 प० 111 मगटा 8 अक्टूबर 1899 30 जून 7 जुलाई 1901 हिंदू 7 अक्टूबर 1899, इदु प्रकाश 9 अक्टू० (आर० एन० पी० बब 14 अक्टू० 1899) इंडियन स्पेक्टेटर 28 अक्टू० 1900 जोशी पूर्वोक्त प० 443 447 512 5 पी० मेहता स्पीचेज प० 304 दत्त स्पीचेज II प० 135 6 मी० वाई० चिन्तामणि इंडिया एंड गाड कान पूर्वोक्त स्थल प० 340-2, गुजराता 2 जून (आर० एन० पी० बब, 8 जून 190 ) बगानी 21 अगस्त 1901 मालवीय स्पीचज प० 313 4
- 152 चोगा पूर्वोक्त प० 448 515 22 544 पा० मेहता स्पीचेज प० 63-4 676 7 जी० के० पारिय पूर्वोक्त स्थल प० 193 318 मालवीय स्पीचज प० 308 तथा दिये पीछ पास्टिण्णो सं० 114
- 153 उदाहरणार्थ जो० एस० अय्यर ने लिपिणी की यदि सरकार यह समझती है कि लगान इनका बम है कि हमसे आमीण ऋणप्रस्तुता जग विलक्षण और भारी रोग को बढ़ावा मिलता है तो सरकार के लिए रास्ता खोजना है वह लगान में इतनी अधिक वृद्धि की घोषणा कर दे कि विमान बहार का अपनी धनी से आजाविका हो न मिल सके और उस दृग् प्रकार सजा के लिए ऋण खोजना से मुक्ति मिल जाए सरकार भविष्य में और अधिक नरमा बनाने के लिए जता लाट बचन करने रहे हैं अपने को बचनवद्ध क्या करती है ? (ई० ए० प० 13-4) आर० सी० एस न सरकार पर पुगनी परास का जमाना की प्रवृत्तियों को दोहराने का आरोप लगाना विरामपरा का इतना गुना सि ब दूर दूर हा रं गरीब आत्मी बं स बनर हो जात' (स्पीचज II प० 194-5) तथा पी० मन्ना स्पाज प० 656-7
- 154 ए० ए० आर मित्र पर पुता माधवनिन सभा का 6 गितंबर 1877 का जिरोपयज पूर्वोक्त स्थल प० 110 आर० पी० बरदिवर रिप० आइ० एन० मा० 1895 प० 112 3 मगटा 8 अक्टू० 1899 हिंदू 7 अक्टूबर 1899 पैमा अक्टूबर 7 अक्टूबर (आर० एन० पी० पा० 28 अक्टूबर 1899) गियायकोट देवर 16 नवंबर 1 गिग० (वही 25 नवंबर, 9 प० 1899) पाग हिं 2 मार्च (वही 10 मार्च 1900) मग्गापर रिप० आइ० एन० सी० 1899 प० 45 जोशी

पूर्वोद्धत, पृ० 440 443-4, 450 गोप्रले स्पीचेज, पृ० 1019 मी० वाई० चिंतामणि इन्दिया  
 एंड लाड बज्जन् पूर्वोक्त स्थल पृ० 341 2 मराठा 30 जून 7 जुलाई 1901 इन्द्र प्रकाश,  
 20 जून (आर० एन० पी० बव 22 जून 1901) एन० मी० बेन्जर सि रोमेंस एंड लेजिस्लेशन  
 इन बांबे, पूर्वोक्त स्थल पृ० 243-4, मालवाय स्पीचेज पृ० 305-06 312-4

155 सरकार द्वारा भूमि का अधिकार न पाने पर भा विमान सरकारगी नक्का माग की पूर्ति आमानी  
 से कर सकता है, इसका अनुमान अथवा ज्ञान होने पर सरकार उसे स्वामित्व का अधिकार न द  
 यह एक बात है तथा किसान द्वारा प्राप्त भूमि का स्वतंत्र व्यापार का अधिकार का अपना अर्द्धि  
 मणा हठधर्मिता और पित्रुलघर्षों आदि के कारण दुष्प्रयोग करने पर सरकार द्वारा उस अधिकार  
 का छीना जाना दूसरी बात है दूसरी स्थिति में सरकार का पण पापसगत हो जाता है

156 बर्दे भूराजस्व बिल पर अपने भाषण में गमीणा का इन रूप का स्पष्ट अभिव्यक्ति गणपलकृष्ण  
 गोप्रले ने की उन्होंने यह पापणा की कि यदि बिल वास्तव में साहूकारों के बुरा तरह शिकार  
 करने हुए विमानों को बिग्री प्रकार की राहत दे सकता है तो मैं यह कहना चाहुंगा कि इन उपाय  
 के विरुद्ध कितना भी कुछ कथो न कहा गया हो उससे उन विमानों के पक्ष में तो यह ताम ही पहु  
 चाएगा उन्होंने अपना यह दृढ़ मत अभिव्यक्त किया यह कहना असभव है कि बिल का प्रकार  
 से कुछ भी कर सकता है (स्पीचेज पृ० 102) तथा देखिए वही पृ० 25 1022-4 1036-40  
 दत्त सी० पी० ए० पृ० 460 ओपेन सेटस पृ० 78, एन० जी० चणवरकर सी० पी० ए०,  
 पृ० 519 20 हिंदू 7 अक्टूबर 1899 मियालकोट पेपर 16 सितंबर (आर० एन० पी० पा०  
 6 अक्टूबर 1900) मुस्लीमर रिप० आई० एन० सा० 1899 पृ० 45 जोशा पूर्वोद्धत  
 पृ० 444 512 514 5 530 541 2 544 मी० वाई० चिंतामणि इन्दिया एंड लाड बज्जन्  
 पूर्वोक्त स्थल पृ० 340-1 मराठा 14 जुलाई 1901 कंगरे हिंदू 26 मई गुजराती 26 मई  
 (आर० एन० पी० बव 1 जून 1901), बगला 21 अगस्त 1901 तथा देखिए पा० महता,  
 स्पीचेज पृ० 672.

157 और देखिए मराठा 30 जून 1901

158 गोखले स्पीचेज, पृ० 1039-40

159 और देखिए, वही पृ० 25 1017 रानाडे लड ला रिफाम एंड एग्रीकल्चरल बक्स पूर्वोक्त  
 स्थल पृ० 48 57 एसेज पृ० 256-7 एन० आ० चदावरकर सी० पी० ए० पृ० 520

160 रानाडे लड ला रिफाम एंड एग्रीकल्चरल बक्स पूर्वोक्त स्थल पृ० 42 तथा देखिए मराठा  
 4 सित० 1881 1 जनवरी 12 फरवरी 1882 25 मर्च 1884 25 जनवरी 1885 प्रकाशक,  
 8 जनवरी बल, 4 जन० (आर० एन० पी० बव 12 जनवरी 1901) कसरी 18 जून (वही  
 22 जून 1901) 10 17 नवंबर (वही 14 21 नवंबर 1903), जी० एत० ज्यर ई० ए०  
 पृ० 65-6

161 प्रमाण का रूप में देखिए पुना सावजनिक सभा का 6 सितंबर 1879 का विरोधपत्र पूर्वोक्त स्थल,  
 पृ० 105-06 110-1 रानाडे दि डकन एग्रीकल्चरिस्ट बिल पूर्वोक्त स्थल पृ० 49 मिस्टर  
 बडरबन एंड हिज व्रिटिस आन ए परमानेंट सटलमेट फार दि डकन पूर्वोक्त स्थल पृ० 17  
 लड ला रिफाम एंड एग्रीकल्चरल बक्स पूर्वोक्त स्थल पृ० 42 46 53-7 एसेज पृ० 256-7  
 मराठा 1 जनवरी 1882 इन्द्र प्रकाश और ज्ञान प्रकाश तिथिरहित (बी० आ० जाई० जनवरी  
 1883) जोशी पूर्वोद्धत पृ० 355-60 आई० एन० सी० 1895 का प्रस्ताव X आर एन०  
 मघोलकर रिप० आई० एन० सी० 1895 पृ० 111 पी० मेहता स्पीचेज पृ० 395 673-4

दत्त सी० पी० ए० प० 490 और आगे स्पीचेज II पृ० 135-6 ई० एच० II प० 495 एन० पी० चंदावरकर, सी० पी० ए०, पृ० 520, ए० बी० पी०, 22 नवंबर 1898, सी० बार्ड० चिंतामणि, 'इंडिया एंड लाड कर्जन' पूर्वोक्त स्थल, पृ० 340-2, मासवीय स्पीचेज, प० 31-4 तुलनीय म्यूहर मक्जी छूट की बार्ड० पद्धति ऋणप्रस्तुता को न तो समाप्त करेगी और न ही धन क रूप में बढ़ाएगी भूमिलगान को समाप्त कर देने का भी अपेक्षित प्रभाव रहा पंडा (प्रासोडिग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बांबे खंड XXXIX प० 353)

- 162 एल० एम० घोष स्पीचेज प० 88 सोम प्रकाश 31 अक्टूबर (आर० एन० पी० बग०, 5 नवंबर 1881) भारत बधु 26 नव० (आर० एन० पी० पी० एन० 2 जून 1880), 29 अप्रैल (वही 3 मई 1882) बंगाली 10 सित० 1881, 2 दिस० 1882 मासिक पूर्वोक्त प० 131 9 रानाडे सेंट ला रिफार्म एंड ऐग्रीकल्चरल बस पूर्वोक्त और एन० प० 40 65 256 नटिव ओपीनियन 19 नव० (आर० एन० पी० बग० 25 नव० 1882) सोम प्रकाश 20 नव० (आर० एन० पी० बग० 25 नव० 1882) भारत मित्र 79 नव० सुलम समाचार 2 जून (वही 9 दिस० 1882) बंगाली, 16 दिस० (वही 23 जून 1882), भारत मित्र 22 नव० (वही 1 जून 1883) इंडियन मिरर बार्ड० पत्रिक ओपीनियन दि हेराल्ड (बिहार) इंडियन स्पेक्टेटर नटिव ओपीनियन मराठा समी तिविरहित (बी० ओ० आई० जनवरी 1893) इंडियन मिरर 2 अगस्त, वीकल फ्रेंड 4 11, 18 अगस्त, ट्रिब्यून 11 अगस्त इंडियन स्पेक्टेटर 12 अगस्त इंडियन इन्फो 14 अगस्त इंडु प्रकाश 6 अगस्त (बी० आ० आई० अगस्त 1883), मजरीचना 19 अप्रैल (आर० एन० पी० बग० 26 अप्रैल 1884) पामवत प्रकाशिका 26 अप्रैल (वही, 3 मई 1884), आनंद बाजार पत्रिका 5 मई (वही 10 मई 1884) मन्थर 7 मई नवविभाकर 12 मई (वही 17 मई 1884) बंगवासी 16 अगस्त (वही 23 अगस्त 1884) बर्दे समाचार 26 अप्रैल (आर० एन० पी० बग० 26 अप्रैल 1884) पान प्रकाश 15 मई (वही 17 मई 1884) इंडियन स्पेक्टेटर, 29 जून (वही 5 जुलाई 1884) हिंदू 29 जून 1884 3 फरवरी 1888 मराठा 25 जनवरी 1885 पंजाबी अथवार 9 फरवरी (आर० एन० पी० पी०, 16 फरवरी 1887) हिन्दुस्तान 10 जून (आर० एन० पी० एन०, 16 दिस० 1890) बगनिवानी 29 अगस्त (आर० एन० पी० बग० 5 जून 1891) गुजरात पत्र 29 नवंबर (आर० एन० पी० बग० 5 जून 1891) आई० एन० सी० 1891 1896 1901 और 1902 व प्रस्ताव III XIII III और III वमश एम० मुन्शियार रिप० आर्० एन० सी० 1891 पृ० 36-7 हिन्दुस्तान 26 अप्रैल (आर० एन० पी० एन० 28 अप्रैल 1892) जागी पूर्वोक्त पृ० 359 366 राय पावर्टी प० 222 5 रोजीवनी 26 अक्टूबर (आर० एन० पी० बग० 2 नव० 1895) विद्यार्थिन वेग 9 फरवरी (आर० एन० पी० पी० 16 फरवरी 1895) आर० एन० मयांतर रिप० आर्० एन० सी० 1896 प० 158 एन स्पीचेज I पृ 14 आर० एन० मयांतर एन० सी० पी० 1897 खंड XXXVI प० 191 एन० एम० एम० (आर० एन० पी० एन० 10 मेष 1897) पमा अथवार 23 जुलाई (आर० एन० पी० पी० 10 अक्टूबर 1897) अथवार आय 25 अक्टूबर (वही 6 अक्टूबर 1897) अथवार अथवार 1 अक्टूबर (आर० एन० पी० एन० 12 अक्टूबर 1897) तात्र उल अथवार 21 अक्टूबर (आर० एन० पी० पी० 4 फरवरी 1897) विद्यार्थिन वेग 4 फरवरी (वही 18 फरवरी 1897) बरीन 3 अक्टूबर (वही 29 अक्टूबर 1897) नवान एप एम० एन० आर्० एन० पी० 1897

- पृ० 49 जी० के० पारिषद, 22 मई 1900 के बगाली मे उद्वन तेज बहादुर सप्रू एच० आर० नवंबर 1900 प० 36, रफीके हिंद 16 जून (आर० एन० पी० पी० 7 जुलाई 1900) सियाल काट पपर 16 सित० (वही 6 अक्टूबर 1900), अखबारे आम 10 नवंबर (24 नवंबर 1900) जी० एस० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1900 पृ० 29 चित्तौड म 21 22 जुलाई 1900 को हुए प्रथम अरोटा सम्मेलन की कायवाही प० 9 पी० महता स्पीचेज प० 673 वाचा सी० पी० ए० प० 580-4 बी० के० बोस एल० सी० पी० 1901 खड XL प० 266 8 ए० वा० पी० 1 जन० 25 सित० 1901 हिंदू 23 मार्च 1901 बगाली 28 नवंबर 1901 यू इटिया 2 दिसंबर 1901 सी० वाई० चित्तमणि इडिया एंड लाड कजन पूर्वोक्त स्थल प० 341 इन्डियन डेली मेल, 24 नव० हिंदुस्तानी 27 नव० (आर० एन० पी० एम० 30 नवंबर 1901) इंदु प्रकाश, 2 दिसंबर क सरे हिंद 1 दिसंबर मुघारक 2 सित० (आर० एन० पी० वब 7 दिस० 1901) मराठा 16 नवंबर 1902 श्रीराम एल० सी० पी० 1903 खड XLII प० 103
- 163 ए० वा० पी० 28 29 अक्टू० 1903 बगाली 28 अक्टू० 1903 मराठा 8 नव० 1903 आर० एन० पी० वग० 14 21 नवंबर 1903 आर० एन० पी० वब 31 अक्टू० 7 14 नवंबर 1903 आर० एन० पी० एम० 7 21 नव० 1903 मे उल्लिखित सभी समाचारपत्र एडवोकेट 1 नव० (आर० एन० पी० यू० पी० 7 नव० 1903) ट्रिब्यून 21 अक्टू० (आर० एन० पी० पी० 31 अक्टूबर 1903) पसा अक्टूबर 8 नव० (वही 14 नवंबर 1903) आई० एन० सी० 1903 का प्रस्ताव XII गोयले स्पाचेज प० 329 30 ए० मुखोपाध्याय और श्रीराम एन० सी० पी० 1904 खड XLIII क्रमश प० 389 और 401-02
- 164 राना एसेज प० 61, 63 जोशी पूर्वोक्त प० 359 60 366 हिंदू 29 दिस० 1884 नवविभाकर 12 मई (आर० एन० पी० वग० 17 मई 1884) सहचर 14 मई (वही 24 मई 1884) एस० मुत्तलियर रिप० आई० एन० सी० 1891 प० 37 राय पावर्टी प० 224 इंदु प्रकाश 2 दिस० (आर० एन० पी० वब 7 दिन० 1901) गायल स्पीचेज प० 332 3 मराठा 8 नव० 1903 एच० आर० मार्च 1904 प० 302-03
- 165 रानाड ग्लड ला रिफारम एंड ऐग्रीकलचरल बक्स पूर्वोक्त स्थल प० 49 51 एसेज प० 256 जाशी पूर्वोक्त प० 367 गोयले स्पीचेज प 25 112 331 2
- 166 रानाड क एल विषय पर विचार 1879 83 की अवधि म प्रकाशित पूना सांजनिक् सभा क अरनन म लिख चार सखा म प्रकट हुए थे देखिए दि ऐग्रियन प्रालम एंड एटस सोयूशन ज० पी० एस० एस० जुलाई 1879 (खड II स० 1) रि ला आफ लड सेल इन ब्रिटिश इडिया (1880) एसेज म लड ला रिफारम एंड ऐग्रीकलचरल बक्स जे० पी० एस० एस० अक्टू० 1881 (खड IV स० 2) और प्रशियन गड नेजिस्लेशन एंड दि बगाल टर्नेसी बिल (1883) एसेज म
- 167 रानाडे एमज प० 275 81 283 288 9 यहा यह उल्लेखनीय है कि उ हाने बगाल म वतमान बुराईया का हटाने के लिए उपाय क रूप म कानूनी साधन की महत्ता की स्वीकार किया था
- 168 वही प 326
- 169 इस प्रकार बगाल के सबध म उहोने निखा रयतवाडी भूमि पढ़ने ही अधिकारा की जटिलता को सीमित करने की कल्पना करती है जबकि सभी बधानिक उपायों का प्रवृत्ति यथासभव जोता को अधिक से अधिक जिरायती अधवा खाम बनाने की होनी चाहिए कानूना का रूप एसा होना चाहिए कि उनक अंतगत भूमि का स्वामी सभी प्रकार के लाभ का तो भागी बन औ



दत्त सी० पी० ए०, प० 480 और आगे स्पाचेज II प० 135-6, ई० एच० II प० 495, एन० पी० चण्णवरकर सी० पी० ए०, प० 520, ए० बी० पी०, 22 नवंबर 1898 सी० बार्ड चित्तामणि इंडिया ऐंड लाइ वजन प्रोवोकल स्थल, पृ० 340-2, मालवीय, स्पीचेज प० 313-4 तुलनीय म्यूचर मक्की छूट की कोई पद्धति ऋणप्रस्तता को न तो समाप्त करेगी और न ही धन के रूप में बनाएगी भूमिलगान को समाप्त कर देने का भी अपेक्षित प्रभाव नहीं प्यंग (प्रोसीडिंग्स आफ दि कौमिल आफ दि गवर्नर आफ बांबे, बख XXXIX प० 393)

- 162 एल० एम० घोष स्पीचेज प० 68 सोम प्रकाश, 31 अक्टूबर (आर० एन० पी० बग० 5 नवंबर 1881) भारत बंधु, 26 नव० (आर० एन० पी० पी० एन० 2 जून 1880), 28 अप्रैल (वही 3 मई 1882), बंगाली 10 मित० 1881, 2 दिस० 1882, मासिक प्रौद्योग प० 131 8 रानाडे, लड ला रिफार्म ऐंड एग्रीकल्चरल बस प्रोवोकल और एंडर प० 40 65 256 नटिव ओपीनियन 19 नव० (आर० एन० पी० बग० 25 नव० 1891) सोम प्रकाश 20 नव० (आर० एन० पी० बग०, 25 नव० 1882) भारत मित्र, 75 नव० मुनभ समाचार 2 जून० (वही 9 दिस० 1882) बंगबासी, 16 दिस० (वही 23 जून० 1882) भारत मित्र 22 नव० (वही 1 जून० 1883) इंडियन मिरर बंगला पत्रिका ओपीनियन दि हेराल्ड (बिहार) इंडियन स्पेक्टेटर, नटिव ओपीनियन मराठा स्पी तिपिरहित (बी० ओ० बार्ड० जनवरी 1893), इंडियन मिरर, 2 अगस्त पीपुल्स फ्रेंड 4 11 18 अगस्त ट्रिब्यून 11 अगस्त इंडियन स्पेक्टेटर 12 अगस्त इंडियन इका 14 अगस्त ए प्रकाश 6 अगस्त (बी० ओ० बार्ड० अगस्त 1883) सजीवना, 19 अप्रैल (आर० एन० पी० बग० 26 अप्रैल 1884) ग्रामवत प्रकाशिका 26 अप्रैल (वही 3 मई 1884), दान्ता दावार पत्रिका 5 मई (वही 10 मई 1884), महत्तर 7 मई नवविभाकर 12 मई (वही 17 मई 1884) बंगबासी 16 अगस्त (वही, 23 अगस्त 1884) बर्कई समाचार, 26 अप्रैल (आर० एन० पी० बग० 26 अप्रैल 1884) पान प्रकाश, 15 मई (वही 17 मई 1884) इंडियन स्पेक्टेटर 29 जून (वही 5 जुलाई 1884) हिंदू 29 जून 1884 3 फरवरी 1888, मराठा 25 जनवरी 1885 पत्राकी अग्रवार 9 फरवरी (आर० एन० पी० पी०, 16 फरवरी 1889) ट्रिब्यून 10 जून० (आर० एन० पी० एन० 16 दिस० 1890), बंगबिवासी 28 अगस्त (आर० एन० पी० बग० 5 मित० 1891) गुजरात दण 29 नवंबर (आर० एन० पी० बग० 5 जून० 1891) आर० एन० पी० 1891 1896 1901 और 1902 व प्रस्ताव III VIII III और III प्रकाश, एम० मूलियार रिप० आर० एन० पी० 1891 पृ० 36-7 ट्रिब्यून 26 अप्रैल (आर० एन० पी० एन० 28 अप्रैल 1892) जोशी प्रोवोकल पृ० 399 1/6 राय पावर्टी प० 222 5 रत्नापना 26 अक्टूबर (आर० एन० पी० बग० 2 नव० 1895) विचारविचार देवर 9 फरवरी (आर० एन० पी० पी० 16 फरवरी 1895) आर० एन० मणोनगर रिप० आर० एन० पी० 1896 प० 158 दत्त स्पीचेज I पृ० 14 आर० एन० मराठा एन० सी० पी० 1897 बख XXXVI प० 191 नवंबर 1 माघ (आर० एन० पी० एन० 10 माघ 1897) पना अग्रवार 23 जनवरी (आर० एन० पी० पी० 10 जनवरी 1898) अग्रवार आम 25 जनवरी (वही 6 अगस्त 1899) अलोप अग्रवार 1 अप्रैल (आर० एन० पी० एन० 12 अप्रैल 1899) तात्र उग्र अग्रवार 21 जून० (आर० एन० पी० पी० 4 फरवरी 1899) विचारविचार देवर 4 फरवरी (वही 19 फरवरी 1899) वरिण 3 अप्रैल (वही 23 अप्रैल 1899) नवाब एन० एम० रिप० आर० एन० पी० 1899

- पृ० 49 जी० ब० पार्लिय 22 मई 1900 व बगाती म उदक तेज बहादुर सयू एच० आर० नवंबर 1900 प० 36, रफीके हिंद 16 जून (आर० एन० पी० पा० 7 जलाई 1900) सियाल बाट पेपर 16 गिन० (वही 6 अक्टूबर 1900) अग्रवारे आम 10 नवंबर (24 नवंबर 1900) जा० एग० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1900 प० 29 पित्तोड म 21 22 जलाई 1900 की हूण प्रथम अराठा सम्मेलन की वापवादां, पृ० 9 पी० महता, स्पीचेज पृ० 673 बाबा सा० पी० ए० पृ० 580-4 बी० बे० बाग एल० सी० पा० 1901 घट XL पृ० 266-8 ए० बा० पी० 1 जन०, 25 सित० 1901 हिंदू 23 मार्च 1901 बगाला 28 नवंबर 1901 'यू इन्डिया 2 नवंबर 1901 मी० आई० बिनामणि इंडिया ऐंड साइ कजन पूर्वोक्त स्थल प० 341 इंडियन इली मेस 24 नव० हिंदुस्ताना 27 नव० (आर० एन० पी० एम०, 30 नवंबर 1901), इंडु प्रमाण, 2 नवंबर कंठरे हिंद 1 नवंबर मुघाब 2 नव० (आर० एन० पी० बब, 7 दिस० 1901) मराठा 16 नवंबर 1902 धीराम एन० सी० पा० 1901 घट XLII प० 103
- 163 ए० बी० पा० 28 29 अक्टू० 1903 बगाली 29 अक्टू० 1903 मराठा 8 नव० 1903 आर० एन० पी० बब० 14 21 नवंबर 1903 आर० एन पी० बब 31 अक्टू० 7 14 नवंबर 1903 आर० एन० पी० एम० 7 21 नव० 1903 म उल्लिखित सभी समाचारपत्र एडवोकेट 1 नव० (आर० एन० पी० यू० पी० 7 नव० 1903) ट्रिब्यून 21 अक्टू० (आर० एन० पी० पी० 31 अक्टूबर 1903), पता अग्रवार 8 नव० (वही 14 नवंबर 1903) आई० एन० सी० 1903 का प्रस्ताव XII गोयन एगवज प० 329 30 ए० मुद्रोपाश्र्याय और धीराम एच० गा० पा० 1904 घट XLIII नमरा प० 389 और 401-02
- 164 रानाड एगज पृ० 61, 63 जोगी पूर्वोक्त, पृ० 359 60 366 हिंदू 29 नव० 1884 नवविभाजर 12 मई (आर० एन० पी० बग० 17 मई 1884) सत्वर 14 मई (वही 24 मई 1884) एग० मुगलियर रिप० आई० एन० सी० 1891 प० 37 राय पावर्नी प० 224, इंडु प्रमाण 2 नव० (आर० एन० पा० बब 7 दिस० 1901) गाउले स्पीचेज प० 332 3 मराठा 8 नव० 1903 एच० आर० माच 1904 प० 302-03
- 165 रानाड लड सा रिफाम ऐंड एग्रीकल्चरल बसम पूर्वोक्त स्थल प० 49 51 एसन प० 256 जागा पूर्वोक्त प० 367 गायल स्पीचेज प० 25 112 331 2
- 166 रानाड व इल विषय पर विचार 1879 83 की अबाध म प्रकाशित पुता सावजनिक सभा व जरनल म लिये चार सत्रा म प्रकट हूण ये देखिए दि लेग्रियन प्राप्तम ऐंड इतल सोयूगन ज० पी० एम० एल० जुलाई 1879 (घट II स० 1) रि ना आफ लड सल इन इतिहा इडिया (1880) एसन म लड सा रिफाम एंड एग्रीकल्चरल बसम जे० पी० एम० एस अक्टू० 1881 (घट IV, स० 2) और प्रशियन लड सजिस्केला एंड दि बगाल टनेसा बिल' (1883) एमेज म
- 167 रानाड एसन प० 275-81 283 288-9 यहा यह उल्लेखनीय है कि उद्धान बगाल म वामान बुगइया का हटाने के लिए उपाय क रूप म कानूना साधन का महत्ता की स्वीकार किया था
- 168 वहा प० 326
- 169 इस प्रकार बगाल के सबध म उन्हीने निष्ठा रयतवादी भूमि यद्ने ही अधिवारी की जटिलता को सामित करने की कल्पना करती है जबकि सभी अधािनिक उपायो की प्रकृति यथासभव जोतो की अधिक स अधिज जिरामती अधवा याम बनान की हाना चाहिए कानूना का रूप एसा होना चाहिए कि उनके अंतगत भूमि का स्वामो सभी प्रकार के लाभ का तो भागी बन और हानिया

#### 440 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदभव और विकास

सं उभवा वाइ मवध न हा (वही, प० 278)

- 170 वनो प० 257 264, 287 289 तथा लड ला रिफाम ऐंड एथीक्त्वचरम वकस पूर्वोक्त स्थल, प० 56-7
- 171 एमेज प० 287 तथा रेखिए एप्ररियन प्रावलम ऐंड इन्स सात्पूजन पूर्वोक्त स्थल प० 17
- 172 रि एप्ररियन प्रावलम ऐंड इन्स सात्पूजन पूर्वोक्त स्थल प० 17 उहो आगे कहा समझ वगैरे को न्य समय भूमि में किया प्रकार की कोई रचि नहीं है । उह धरती से कोई पद मिल सकता है । प्रतिष्ठा और न ही वे जमींदारों के रूप में काम कर सकते हैं । इन प्रकार के संपत्ति वगैरे की अनुपस्थिति वृष्टि के सर्वोत्तम विधान का अवरोध कर देता है
- 173 वही प० 18 तथा दखिए वहा प० 10-1 13 14 19 और एमेज प० 325 7
- 174 एमेज प० 277 8
- 175 वही प० 267 70 273 5
- 176 रि एप्ररियन प्रावलम ऐंड इन्स सात्पूजन पूर्वोक्त स्थल प० 16-7
- 177 एमेज प० 326-7 उन्मुने यह भी किताब इन समय देश सङ्गम की अवस्था में है यह वर्तमान अध्यात्मो और पितृमत्तात्मक स्थितियाँ सङ्गूर रहा है वह इस समय अधिक व्यवस्थित और व्यवसायपरक स्थिति का अभाव जा रहा है प्रवाह के विरुद्ध जाना वाला अथवा प्रवाह को अवरुद्ध करने वाला कोई आर्थिक कानून वर्तमान परिस्थितियों में सफल नहीं हो सकता सभी प्रकार का — भूमिगत अथवा पश्चात्तक संपत्ति का स्वामित्व वगैरे अङ्गुली और अन्य हस्तगत साधनों का समाप्ति और उनका सही रूप में उपयोग करना में अल्पकालीन व सफल होना ही है । यह है कि अपरिचित हस्तान्तरण को सरकारी नियमित रूप में दृष्टिगत करके कठिनाई दूर हो जाए (वहा प० 325-6) यह भी उल्लेखनीय है कि राजाह का यह मतभेद कि साहूकार भूमि का कच्चा प्याज की ऊँची दर वसूलन के लिए सत्ता था न कि वृष्टि व्यवसाय में उल्लाहपूर्वक प्रथम होने के लिए सत्ता व सभासत्ता था (एड ला रिफाम ऐंड एथीक्त्वचरम वकस पूर्वोक्त स्थल प० 39)
- 178 एमेज प० 264 269 9 276 राजाह ने बंगाल के जमींदारों का अरजी याचना के रूप में उल्लाह मानने में कोई गलती नहीं की परवर्ती भारतीय सङ्घना ने आमतौर पर यह रूप में की है इंग्लैंड और उत्तरी देशों में 19वीं सदी में बंगाल का और 19वीं सदी में पूर्वोक्त में मुद्रा में पूरा प्रजा की स्थिति वास्तव में ही एक समय था क्योंकि बंगाल के जमींदारों और प्रजा के आन्दोलन के कारण राजाह ने निरन्तरम सङ्घना पर इंग्लैंड सङ्घना के कारण ही उन्मुने प्रजा की सत्ता का साक्ष्यता के साथ अध्ययन किया था तथा उन्मुने बंगाल के साथ (वहा प० 251)
- 179 वनो प० 272-4
- 180 वनो प० 287 तथा दखिए प० 290
- 181 रि एप्ररियन प्रावलम ऐंड इन्स सात्पूजन पूर्वोक्त स्थल प० 17
- 182 वनो और एमेज प० 325-7
- 183 एमेज प० 274 5

- 185 उन्होंने आरोप लगाया कि वतमान प्रस्ताव केवल एक बग के लाभ के लिए दूसरे बग के अधिकारों को छीनता है इस बचल समाजवादी अथवा साम्यवादी मिथ्याता पर ही 'यावत्सगत' माना जा सकता है (वही प० 287) तथा देखिए प० 279 80 283 289 291
- 186 वही प० 280
- 187 वही प० 284
- 188 वही प० 285-6
- 189 वही प० 286-7
- 190 नगीमे आगरा, 23 अगस्त (आर० एन० पी० एन० 25 अगस्त 1884) ज० एन० वास रिप० आई० एन० सा० 1890 प० 52 आइ० एन० सा०—1891 और 1892 व प्रस्ताव III और IX हिंदुस्तानी 8 नवंबर (आर० एन० पी० एन० 15 नवंबर 1893) विभूत्तरजनी 25 नवंबर (आर० एन० पी० एन० 15 अगस्त 1896) दत्त स्पीचर I पृ० 161 सा० शंकरन नायर पी० पी० ए० पृ० 385, स्वप्नामिन्न 17 मार्च (आर० एन० पी० एन० 31 मार्च 1900)
- 191 रिप० आई० एन० सा० 1890 पृ० 53 उन्होंने यह सवाल उठाया क्या यह अच्छा नहीं होगा कि भूमि के मुद्दारे में कुछ भी बाग द गवन में अक्षय निष्पन्न किसानों का जोना का स्वामी बनाने की अपेक्षा अधिक किसानों को दिया जाए ? क्या यह स्वयं उनके अपने लिए धरती के लिए तथा देश के लिए बहुत नया होगा ?
- 191ए टान, अप्रैल 1900 पृ० 268
- 192 लक्ष्मी रिफार्म ऐंड एग्जिक्शंस बिल पूर्वोक्त स्थान प० 42 अपनी सामान्य गहरी पकड़ के अनुष्ण रानादे ने सत्र के दूसरे पक्ष पर भा विचार किया 'इसमें सन्देह नहीं कि कृषि अनुसंधानों को दी गई प्रेरणाएँ धन में अपने आप दूसरे उद्योगों को संप्रतिष्ठ करेगी और परिणाम में देश के साधनों का एक रूप में पूजा पण्यीय विकास होगा जिसका कि हम समय पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता । (वही प० 53)
- 193 रानादे एंग्ल पृ० 25 6 तथा देखिए प० 207
- 194 तथा देखिए मराठा 23 जनवरी 13 फरवरी 17 जून 1881 1 जनवरी 1882 25 मई 1884
- 195 राम पावर्टी प० 97 8
- 196 जोशी पूर्वोक्त, प० 350 353 870 2
- 197 वही पृ० 849 851 2
- 198 वही प० 368 तथा देखिए प० 852 3
- 199 वही प० 642
- 200 आर० एन० पी० बब, नमन 22 जून 1901 और 15 नवंबर 1902 तथा देखिए केसरी 10 17 नव० (आर० एन० पी० बब 14, 21 नव० 1903), आरट्टेके बब प्रतीय सम्मेलन का प्रस्ताव मराठा, 16 नवंबर 1902
- 201 जो० एन० अय्यर ई० ए० पृ० 64-6

## लोकवित्त I

सम्य प्रशासतावाला कोई एमा देग नहीं जहा पर इतना हनवा कराधान हा ।

—जान स्टुषी

हा बुछ वस्तुए अभी एमी बची हैं जिन पर कर लगाया जा सकता है तानि अंगरेजा का विजय अभियान पूरा हा सके । एमी अवशिष्ट वस्तुओं म उत्तमगीय १ भारतीय लोग की चमकी और उनका वायुमंडल । — बेगरी 31 जनवरी 1888

आरक्षिय सरकार द्वारा प्रणामित प्रत्येक रूप म नियमा की अपेक्षा घनिव। पर की अर्थिक मात्रा म कर उगाना उचित समझा जाता है क्योंकि यह धनी का ही पुत्रिम संगठन म, आर्थिक जगजता की स्थापना स देना तार आदि म आभाषित हाता है परंतु जिन देग का प्रणामन उच्च वर्गों के लागो व ही हाय म हा, क्या क्या व अपन जाप पर रर मापा की मयता करेंग ? — स्वर्णमित्र 18 फरवरी 1888

समीक्षाधीन अवधि म भारत सरकार की औद्योगिक और शुकर पद्धति परधी नीतिया तथा विनायी समझ्या व उपरांत भारतीय राष्ट्रीय नेताओं की प्राधानि का प्रवर्धन करन वाला ताब का उगरी विना नीति । दस अवधि म भारतीय वित्त व निषासन रूप से तानिया म अंगरेजी एमी गवृत्ता के वना के पारम्पर्य गणत पर रूप के आसना की आगना ग मतिर द्यया म भारत वनातरी, गनी व रचना मूय म अयगत ताव ग दून विनास पर गान बाता द्यया तथा दू मनी तावा व पारम्पर्य द्यया म विनास द्वारा वना की बहावरी का एक जयि-राता का रूप ताना । यत्रि कुछ रूप वर्गों म भारतीय वित्त साम्य वना का वरु प्रगुत करन म मयत हा ताव तदति कुत मियाकर य वय आर्थिक जगजुता कष्ट तथा वरा द्वारा द्यय व। तानि प्रान्त वना व प्रदता व। अमयता व ही वय व। दू वम हैरा ती की बाव गरी वि वर प्रति वय मनी विना साम्य पृथक पृथक रूप म भारत के विना की दुर्गा का राता रात रर तथा वि वय वनी



प्रत्येक एक महत्वपूर्ण अधिनियम की जिसे उन्होंने जनता पर नए कर थोपने का, अनावश्यक, निरर्थक तथा आल्याणकारी व्यय का तथा भारत और ब्रिटेन के संबंधों में अत्याय का उदाहरण समझा, परीक्षा की, रिदा की तथा उमड़े विरुद्ध लाकप्रिय जादोलन चलाया। प्रत्येक इस प्रकार के उदाहरण में उन्होंने भारत में ब्रिटिश राज्य की प्रकृति और उद्देश्या के मध्य में समुचित निष्पन्न निम्नलिखित की चेष्टा की।

### कराधान

भारत सरकार के कुल राजस्व 1880 में 74.3 करोड़ के मुकाबले 1993 में 90.6 करोड़ और 1904 में 172.2 करोड़ तक पहुंच गए।<sup>10</sup> परंतु जहां तक आय बाता के साथ राज्य रकमों की कुल रकम बसूली, सिचाई योजनाओं की बसूली तथा आय रला के खाता की विपुल बसूली का सम्मिलित करने का संबंध था, य अर्क विवृत रूप लिए हुए थे। इनके अतिरिक्त खातों के एका में परिवर्तन जैसे कुछ और तत्वों में भी वर्षों तक वित्तीय आगामी की तुलनात्मकता का विवृत किया था।<sup>11</sup>

नागा पर राजस्व भारत के मध्य में ब्रिटिश अधिकारियों और भारतीय नताओं द्वारा परस्पर विरोधी मत प्रकट किए गए। बहुत सारे ब्रिटिश लगवों और अधिकारियों ने सार सरकारी राजस्व का कराधान के परिमाणारूप देयन पर प्रारंभिक आपत्ति की।<sup>12</sup> उदाहरणार्थ उनमें से उदात्त जू यह मिद्ध करने की चेष्टा की कि भूमि पर नगान सरकारी विराया था कर नहीं।<sup>13</sup> इसी प्रकार उन्होंने अपनी स मितन जाने राजस्व का नी नागा पर लगन बाता कर मानन में इत्वार कर दिया।<sup>14</sup> दूसरी ओर भारतीय लगवों ने सरकारी राजस्व के स्रोतरूप लगभग सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं का कर योग्य रूप में वर्गीकरण किया। उदाहरणार्थ दागाभाई नौराजी ने कर की परिभाषा एक प्रकार में की दाग की कुल वार्षिक आय में से देग की सरकार अपन प्रशासना और सावजनिक श्रृण आदि के लिए जा ररन लेती है, यह कर है।<sup>15</sup> गद के वतमान स्वीकृत अध को ध्यान में रगन हुए भारतीय नताओं द्वारा विदायित परिभाषा का अगगाहन अधिन सती गाना उचित है।

ब्रिटिश प्रशासक प्रायः इस बात को स्तनापूरर वस्तु यह कि भारत पर बना इनके कर नगान गए हैं और सराधिक गभावता यही है कि यह विव भर में गवायित रकमों को चुकाया जाता है। प्रमाण के रूप में भूतपूर विव गस्य जा म्द्र तान बडे विवाम के साथ यह दावा किया कि विव में गस्य प्रशासन बाता बाद भी देग तारा के गमात इनके कर चुकाया जाता है।<sup>16</sup> बजरा नी ग्गी प्रकार की स्थिति के प्रति पूरा विवस्य था। जी० के० गानन की इस धारणा का कि सरकारी भारतीय जाता का वस्तु पुरी तरर में अधिन कर रहे हैं नकारा इस बजरा ने 1902 में विर सरागपुग स्वर में टिप्पणी की कि गन्तानीय गस्य का रिनी भूरीतीय गग में गन के लिए नेत्र किया जाण ता मुझे आता है कि य सरस्व पद्धति के मामला में परिचित विषाग के साथ ही नीय गग देग में गने के लिए वादग सौट आणग।<sup>17</sup>

ब्रिटिश विचारियों का इस संबंध में दुइ मत यह था कि कराधान की व्यावहारिक





प्रकार 1880 में रानाडे ने टिप्पणी की कि 'कराधान में और अधिक बढ़ि करना राजनीतिक पालन का परिचय देना होगा।'<sup>9</sup> 'अमृत बाजार पत्रिका' ने मत प्रकट किया कि एक सीमा होती है जिसके आगे कराधान असंभव सा हो जाता है और यह सिद्ध करने के उचित प्रमाण उपलब्ध हैं कि भारत उस सीमा तक पहुँच चुका है। उसने 27 अगस्त 1885 के अंक में चेतावनी देते हुए लिखा 'जब विवेकशून्य धार्मिक सीमा का अनिश्चयन करते हैं तो वे विद्रोह को निमग्न करते हैं। यदि लोग विद्रोह करने में अत्यंत अक्षम हैं तो प्रगति स्वयं ही हस्तगत करती है तथा अपने रोप का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती है। भारत में इस सीमा का अतिक्रमण हुआ है, इसका प्रमाण लगातार अनायास रूप में देखा जा सकता है।' यहाँ तक कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में भी कराधान पर बहुत तीव्र आलोचनाएँ हुईं। दादाभाई नौरोजी ने 'गामको' पर आरोप लगाया कि वह इस प्रकार ऊँचे और ऊँचे कर लगाए जा रहे हैं, जग निचुड़े हुए मत्तरे को और निचोड़ने की चेष्टा की जा रही है। इस प्रकार 'गामको' जनता के कष्टों और दुखों में बढ़ि कर रहे हैं।<sup>10</sup> इसके माघ ही तिलक ने कमरी ने अपन 31 जनवरी 1888 के अंक में टिप्पणी की 'भारत में कोई भी वस्तु कराधान से मुक्त नहीं, यहाँ तक कि वस्त्रों के पत्तों तक का कराधान का विषय उठाया गया है।' व्यंग्यपूर्ण प्रहार करने हुए वेसरी ने सुभाव दिया 'हा अभी भी कुछ एक वस्तुएँ बची हैं, जिन पर कर लगाया जा सकता है ताकि अन्न का विजय अभियान पूरा हो जाए। इन अवशिष्ट वस्तुओं में उन्नीसवीं है, भारतीय नागा की कमरी और उनका धामुष्ण।'<sup>11</sup> 9 फरवरी 1899 में मत्प्रभित्र ने चेतावनी दी कि सरकार का यह उद्देश्य अपने ध्यान में 'भली प्रकार धारण कर लेनी चाहिए कि मुम्मा दिनांक तक पर एक निरीह माघ की 'गामी' को फाटकर टुकड़े टुकड़े कर सकती है अथवा स्वतः दुह जा सकने वाले दूध का लालक उपयोग खाता यदि माघ के माना में फिर दूध को लालक की चेष्टा करता है तो उस मान को बर्बाद करने की मार मानी है।' उग्रभण विनाशकारी स्वर में उग्र धमकी देते हुए लिखा 'भामी की रानी, विजय उन मुक्त विमताओं द्वारा, 'गामी' का, तात्या टांग और जमाय शब्द और मादा यद्यपि दृष्टिगत के पात्र बन गए हैं तथापि उन्नीसवीं तकवार जात की विचार में मामल धूम रहा है तथा हमारी धीरता का प्रमाण देना रहे।'<sup>12</sup> 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में सरकार के तत्पर में मत्प्रभित्र और प्रभावित थे कि विनी की 'गाम' कराधान को मत्न करने की दृष्टि 'गाम' तत्प्रभित्र का बुरी है।<sup>13</sup> वर्षान्तर 'गामी' प्रकार की विराधी भावनाएँ और 'गामी' प्रकार के मत बढ़ते गए राष्ट्रवादी भावना द्वारा प्रकट किए जाते रहे।<sup>14</sup>

भारतीय नागाओं की एक 'गाम' विचारणा यह थी कि 'गाम' में कराधान करना ऊँचा और भारी हो नहीं है प्रत्युत विचारणा भी जा रहा है।<sup>15</sup> उन्नीसवीं जी० धी० जाती में 1896 में 'गाम' उठाया कि 'गाम' तथा 'गाम' ध्यायानि 'गाम' का विचारण 'गाम' पर भी 'गाम' कराधान का भार 1893-4 और 1895-6 की अवधि में 35 प्रतिशत बढ़ा है।<sup>16</sup>

भारत में कराधान की भारी उच्च प्रमाणाँ करना के लिए भी भारतीय नागाओं ने

अर्थात् सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपनाई गई विधि के समान आकड़ों को ही कमीटी बनाया परन्तु इस कमीटी का निर्धारण उहान अपन ढंग से ही किया। उन्होंने यह स्वीकार किया कि स्वतंत्र रूप से प्रति व्यक्ति कराधान की राशि कम थी परन्तु उनका तब यह था कि प्रति व्यक्ति आय को देखे बिना ही प्रति व्यक्ति में लिए जाने के स्वतंत्र आकड़ों में कराधान के परिमाण का निर्णय नहीं किया जा सकता। इस संबंध में यहाँ प्रति व्यक्ति कराधान की राशि नहीं प्रत्युत इससे सबद्ध प्रतिव्यक्ति आय के अनुपात को दमना अधिक महत्वपूर्ण था। यदि भारत में कराधान नीचा था तो राष्ट्रीय आय उससे भी अधिक नीची थी। भारतीय नेताओं का कथन था कि इस मद में देखे जाने वाले पर भारत में कराधान सचमुच ही अत्यंत भारी और दवाने वाला सिद्ध होता है। दादाभाई नौरोजी इस तत्त्व के मुख्य निर्माता थे। उन्होंने 1871 में पूर्वी भारत के वित्तों के लिए नियुक्त प्रवरसमिति को प्रस्तुत अपने प्रतिवदन में इस तत्त्व का प्रयोग किया था। उन्होंने इस तथ्य को वाणी दी कि इंग्लैंड में प्रतिव्यक्ति कराधान का परिमाण लगभग 8 प्रतिशत है जबकि भारत में यह 16 प्रतिशत के लगभग है।<sup>37</sup> उन्होंने तथा अन्य भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए सारियकी प्रमाणा का वर्षों तक उपयोग किया। इस मंत्र में यह उल्लेखनीय है कि उनके जको की गणना में प्रतिशत में भिन्नता आ जाती थी।<sup>38</sup>

कुछ भारतीय नेताओं ने अनुभव किया कि आय के साथ कराधान का यह औसत भी धोके के भारीपन को सही रूप में और यथोचित ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाता। उनका कथन था कि कुल मिलाकर कराधान का जनता की भुगतान की क्षमता के साथ संबंधित करना चाहिए। एक निधन व्यक्ति से उसकी आय के एक निश्चित अनुपात को कर के रूप में लेना एक बात थी और एक धनी व्यक्ति से उसकी आय के उसी अनुपात को कर के रूप में लेना संभवता भिन्न बात थी क्योंकि इससे निधन व्यक्ति के लिए तो जीवनस्तर बनाए रखने में उस और अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। चिंतन की इस रूपरेखा की स्पष्ट और निश्चित अभिव्यक्ति दादाभाई नौरोजी के लेखों में देखने का मित्र। उन्होंने राष्ट्रवादियों की स्थिति में प्रतीत होने वाले विरोधाभास के समाधान के लिए इस चिंतन पद्धति का प्रयोग इस प्रकार से किया कि भले ही यह मान लिया जाए कि प्रति व्यक्ति कराधान नीचा है फिर भी वह भारतीय लोगों के लिए कमरतोड़ है। उन्होंने पूर्वी भारत के वित्तों से संबंधित प्रवरसमिति का भेजे गए अपने प्रतिवदन में इस तथ्य का सम्यक विश्लेषण इस प्रकार से किया

इस तथ्य को भली प्रकार ध्यान में रखना चाहिए कि एक हाथी के लिए एक टन वजन भी भारी नहीं परन्तु बच्चे को कुछ एक किलो भार ही कुचलने के लिए काफी है। कराधान के प्रतिशत से आसानी के साथ भार उठा सकने अथवा उस भार से कुचले जाने को नहीं मापा जा सकता प्रत्युत इस मापन के लिए उपयुक्त आधार है भुगतान के लिए आय के साधनों की प्रचुरता अथवा वृच्छता। आय के मापन की प्रचुरता की स्थिति में भारी प्रतिशत के करों का सुविधा से भुगतान किया जा सकता है और आय के साधनों की सीमितता की स्थिति में यह भार कठिनाई से ही सहन

हो पाना है जयवा थाडा-बहुत क्लेश उत्पन्न करता है परंतु आय के साधनों की अपर्याप्तता की स्थिति में तो यह भार अत्यधिक कष्टदायक हो जाता है।<sup>39</sup>

उत्तम अपन इस मूत्रमूढ मिथान को 'पावर्टी आफ इंडिया' लेख में दोहराया और वार्म में अपन जमम्य भाषणा जादि में इनका विस्तृत विवेचन किया।<sup>40</sup> 1896 में जलित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आर० एम० राम्मानी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में दादाभाई के तर्क का दोहराया।<sup>41</sup>

दादाभाई ने जब इस चिन्तनपद्धति का भारत पर प्रयोग किया तो उन्हें यह घोषणा करनी पड़ी कि भारत में कराधान का भार इंग्लैंड के कराधान के भार में दुगुना ही नहीं अपितु दुगुनायक भी है क्योंकि यह गरीबों में लिया जा रहा था।<sup>42</sup> इसी प्रकार आर० एम० राम्मानी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारत के सत्रय में आय पर करों की औसत 16 प्रतिशत है और यद्यपि इंग्लैंड के मध्यम प्रचलित अनुपात के मुकाबलें देश का वेधत 24 गुना ऊँचा है तथापि वास्तव में यह परिमाण में उल्लेखनीय रूप से अत्यधिक भारी है और इस प्रकार सूचना अनुपात की अपेक्षा भारत इंग्लैंड से वास्तव में ही बड़ी अधिक दुरी स्थिति में है।<sup>43</sup> वे० टी० तैलम मदनमाहन मानवीय, गाणानृष्ण गोखल, आर० गी० दत्त तथा वित्त ही जय जाता जा न भी इसी ढंग में देश की निधनता और कराधान भार में महत्प्रयत्न जाय।<sup>44</sup> 1896 में जी० धी० जाशी ने सत्रया ठास मिथान प्रस्तुत किया कि जब तक कुल राष्ट्रीय उत्पादन में विकास नहीं होता तबतमान कराधान में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हानी चाहिए। इस संबंध में उक्त दादाभाई का दावा किया कि कराधान बढ रहा है जबकि राष्ट्रीय उत्पादन का ह्रास हो रहा है।<sup>45</sup> दादाभाई तैराजी और मदनमाहन मानवीय ने भी घाटे भिन्न शब्दों में इसी तर्क का दोहराया। उत्तम जोर देकर इस तथ्य का स्मरण किया कि भारतीय अपेक्षाकृत ऊँचे कर देना भी प्रगतितापूर्वक उद्योग ह्रास, परंतु शत यह है कि इनका मध्य प्रवृत्ती राष्ट्रिय आय के साथ होता गच्छे।<sup>46</sup>

जय मन्तव्य के समर्थन के लिए भारतीय नेताओं ने इस संबंध में अग्रज अधिकाधिक के वक्तव्य प्रस्तुत किए जिसमें स्पष्ट गया था कि भारत सरकार ने सरकारों में भारत पर किसी प्रकार के कराधान का अवकाश हा नहीं छोटा है। अब स्थिति यह है कि भारत में आर्थिक और राजनीतिक मरुत काण दिना किसी प्रकार का जय कराधान किया ही नहीं जा सकता।<sup>47</sup>

यह मन्तव्य नाम के प्रकट पत्र लिए जाते जय ता राष्ट्रियों के जय मन्तव्य के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया कि भारतीय जनता में जावपन्नता अथवा वास्तविकता में अधिक कर उठेंगे गच्छे।<sup>48</sup> 1902 में आचार्य बरतु जयता का जय जय जय का वेंद्रीय नियम वास्तविक गाणानृष्ण गाणानृष्ण जय घाणित जय जय भारत सरकार की लिए लिए पर घाण प्रण करण आर । किया कि य जय अरु जय रूप म और स्पष्ट रूप में यत् मिथान जय है कि रूप के जय की स्थिति और रूप जय जय की प्रण प्रण का भी व्यावहारिक मध्य जय है। जय की वावपन्नता जय कि व्यावहारिक ढंग में बड़े ऊँचे परिणाम में जनता पर भारी जय का जय निघाणित किया

गया है और उसे बनाए रखा जा रहा है। इस प्रकार एक ओर विपन्न राष्ट्र और दूसरी ओर भरपूर कोश के प्रत्यक्ष विरोध का सुविधापूर्वक विश्लेषण किया जा सकता है।<sup>14</sup>

राष्ट्रवादी नेताओं में से कुछ अर्थशास्त्रियों ने भी लोगों के विभिन्न वर्गों में कराधान के वितरण के प्रश्न पर विचार किया। 1880 के प्रारंभ में भारत सरकार के वित्त विभाग द्वारा कराधान के परिमाण के संबंध में विहित विस्तृत जाच-पड़ताल के निष्कर्ष के रूप में यह परिणाम सामने आया था कि भारत में कराधान का प्रमुख भार प्रधान रूप से अपेक्षाकृत अधिक निधन वर्गों पर ही पड़ता है।<sup>15</sup> राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों ने इस परिणाम के साथ पूर्ण सहमति प्रकट की और कराधान पद्धति की उसके प्रतिगामी चरित्र के लिए आलोचना की। उनके अनुसार कराधान पद्धति का प्रतिगामी चरित्र यह था कि इसकी प्रवृत्ति घनिष्टता की अपेक्षा निधन पर अधिक भार डालने की थी। 1871 में दादाभाई नौरोजी ने जनता के अन्याय वर्गों की अपेक्षा किसानों से अधिक कर ँठने के लिए सरकार को आड़े हाथों लेते हुए व्यंग्यपूर्वक पूछा 'या इसका कारण यह है कि समृद्ध वर्ग आंदोलन का आश्रय ले सकता है और सरकार को अपनी बात मानने के लिए विवश कर सकता है जबकि गरीब मजदूर और खेतिहर यह सब कुछ नहीं कर सकते। क्या इसी कारण से यह उचित समझा गया है कि अन्याय वर्गों की अपेक्षा इस वर्ग को निचोड़ना आसान है?' श्री ० श्री ० जोशी ने 'अप्रैल 1888 में अपने निबंध 'दि वर्मा डेफिनिट ऐंड दि एनहेंसमेंट आफ साल्ट ड्यूटीज' में इस प्रश्न को विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने 'सपन जमींदारों और उसके घनिष्ठ मित्रों तथा चायशागान के स्वाधिकाओं को छूट देने वाली और निधन पर भार डालने वाली कर नीति अपनाते के लिए वित्त सदस्य की भर्त्सना की।<sup>16</sup> उन्होंने कराधान पद्धति की विषमता पर दुःख प्रकट करते हुए कहा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इस पद्धति के अंतर्गत ब्रिटिश प्रशासन ब्रिटिश 'याय और ब्रिटिश शांति से अधिकाधिक लाभान्वित होने वाले सपन व्यक्ति तो कम टैक्स देते हैं जबकि साधु, कम उपार्जन करने वाले निधन लोग अधिकतम कर चुकते हैं। उन्होंने यह भी निर्देश किया कि कराधान के भार की विषमता एक वर्ग और दूसरे वर्ग के मध्य ही नहीं प्रत्युत 'गरीबों में विभिन्न वर्गों के बीच और देहातो की साधारण जनता के बीच विद्यमान है।<sup>17</sup> इस संबंध में भावी कायदाही के लिए उन्होंने पत्रप्रदक्षक के रूप में सरकार का सलाह दी कि सर्वप्रथम वह सावजनिक कराधान के वितरण की विषमताओं के संशोधन और निवारण को अपने प्राथमिक वनव्य के रूप में स्वीकार करें।<sup>18</sup> उससे पूर्व 1886 में उन्होंने कराधान के निम्न सिद्धांत का उल्लेख किया था

सभी वित्तीय विचार विमर्शों में व्यावहारिक वित्त विशेषण के लिए विचारणीय प्रश्न यह नहीं है कि सामान्य जनसंख्या पर कराधान का कुल बोझ भारी है अथवा हलका यह तो व्यावहारिक राजनीति का एक तत्व है। अर्थशास्त्री के लिए तो विचारणीय यह है कि सार्वजनिक भार को एक साथ लेते हुए यह देखना है कि उसका विभाजन ममान रूप से और निष्पक्ष रूप से हुआ है अथवा नहीं (और) यह देखना है कि उसका भार सभी वर्गों पर न्यायसंगत और निष्पक्ष रूप से उनकी भुगतान क्षमता के अनुरूप पड़ता है अथवा नहीं?<sup>19</sup>

नमक कर में वृद्धि के बदले आय कर में बढ़ोतरी की वकालत करते हुए सुरहाण्य अय्यर के स्वामित्ववाले तथा उनके द्वारा संपादित 'स्वदेश मित्र' ने अपने 18 फरवरी 1888 के अंक में जाशी जी के विचारों को इस प्रकार दोहराया

एक 'यायसगत सरकार द्वारा प्रशासित प्रत्येक देश में निधनों की अपेक्षा धनिकों पर ही अधिक परिमाण में कराधान करना उचित समझा जाएगा क्योंकि धनी लोग ही लाभान्वित होते हैं परंतु यदि किसी देश की सरकार ही उच्च वर्ग के लोगों के हाथ में है तो क्या वे अपने आप पर कराधान की मूलता करेंगे।<sup>6</sup>

'स्वदेशमित्र' ने अपने 25 फरवरी 1888 वाले अंक में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि केवल वही सरकार 'यायसप्रिय' सरकार कही जा सकती है जो निधन वर्गों को टट्टी से मुक्ति दिलाती है तथा उच्च और मध्यवर्ग पर कराधान द्वारा अपने राजस्व की वसूली करती है।<sup>7</sup> इसी प्रकार 18 मार्च 1888 को पूना साधजनिक सभा के तत्वावधान में अपने आपन में गिंकायत की कि इस देश का निधन वर्ग पहले से ही भारी बरों के बोझ से दबा हुआ है जबकि उच्च वर्ग के तथा अधिक समृद्ध लोग तुलनात्मक रूप में छूट और राहत का आनंद भोग रहे हैं।<sup>8</sup> पृथ्वीश चंद्र राय भी कराधान के असमान परिमाण की आलोचना करने में पर्याप्त उग्र थे और उन्होंने इस अपमानजनक बड़ा बलक बताया। नमक कर, आय कर तथा भूमि लगान का विस्तृत विवरण करने के उपरांत वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अतंतु दुर्व्यवस्थित वित्तों का गारा भार देश के निधनों का ही उठाना पड़ता है।<sup>9</sup> बाद में 1903 में अपने वज्रत भाषण में गांधी ने भी यही मत प्रकट किया कि कराधान में प्रभावित किसी प्रकार की राहत अपमानजनक निधन वर्गों को ही मिलनी चाहिए क्योंकि अपने साधनों की अपेक्षा वे ही राजस्व में वाछनीय से बहुत अधिक भुगतान का योगदान करते हैं।<sup>10</sup>

यह एक पर्याप्त राख्य है कि इस काफी कुछ प्राथमिकी दृष्टिकोण का अपने समय के अग्रणी भारतीय उद्योगपति जे० एन० टाटा का प्रबल समर्थन मिला उन्होंने 1895 में 'लंदन डेली ट्रािब्यूनल' का भेजे जपान पत्र में लिखा मैं मदद इस मत का समर्थक रहा हूँ कि भारत में निधनों पर कराधान का वास्तविक ही भारी है और अच्छे मान पीत वर्ग के समृद्ध लोगों पर यह भार अत्यंत हीनवा है। जिन लोगों का अपना जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकारों की गहायता की अपेक्षा रहती है उनके लिए कुछ भी खुशागी नहीं पत्ता, जिन्हें सरकारों के अभाव में किसी हानि की आशंका नहीं रहती वर्गों का तत्काल दनकारी के भुगतान के लिए अपने भ्रातृत्व की बलि पड़ानी पड़ती है।<sup>11</sup>

इस विचारधारा को राष्ट्रवादी विचारों के मनी वर्गों द्वारा मिल गए दानों में भी वर्गों में नमक कर और आय कर के प्रति भारतीय राष्ट्रवादी विचारों का समर्थन के समर्थन में किया गया है कि बहुत गार भारतीय राष्ट्रवादी विचारों की पुष्टि की कि यदि भारतीय लोगों पर कराधान करना ही है तो

घनिष्ठ पर कर लगान चाहिए, निधन पर नहीं।<sup>65</sup>

कराधान के कारण हुआ अन्याय

भारतीयों के विचार में अत्यधिक कराधान भारत की घोर निधनता के ही नहीं यहाँ तक कि प्रायः निरन्तर पढ़ने वाले अवालाक भी तात्कालिक और प्रमुख कारणों में से एक था। इस संबंध में राष्ट्रीय विचारधारा को दादाभाई नौरोजी ने 1880 में भारतीय असास आयोग के प्रतिवेदन में निहित कुछ विवरणों पर पापन में स्वर दिया गया। उन्होंने दुःखनापूर्वक कहा कि भारी कराधान लासों की भूमि और मीनों के लिए उत्तरदायी था।<sup>66</sup> भारत के असंगत राष्ट्रवादी जननता तथा पत्रकार यहाँ तक इस दृष्टिकोण का दाहरात रहे।<sup>67</sup> अतः 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अपने एक मौलिक सिद्धांत के रूप में अपना लिया। उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि हाल के अवालाक का कारण भारतीयों की घोर दरिद्रता थी और दरिद्रता लाने के अन्याय कारणों में प्रमुख थे अत्यधिक कराधान तथा ऊँच लगान।<sup>68</sup>

इसमें भी अधिक रोचक तथ्य यह है कि कुछ भारतीय नेताओं ने और सर्वोपरि जी० वी० जादी ने उपयुक्त तब के अतिरिक्त भारतीय उद्योग और भारतीय उद्यम की दृष्टि से भी ऊँचे कराधान की निंदा करते हुए अपनी सूक्ष्म बुद्धि का परिचय दिया। उन्होंने घोषणा की कि ऊँचे कराधान पूँजी निर्माण की प्रश्रिया को बाधित करते थे और इस रूप में देश के आर्थिक विकास को यदि पूँजित असंभव नहीं तो बर्धन अवश्य बना रहे थे।

1888 में जी० वी० जोशी ने प्रथम इस बात पर जोर दिया कि राज्य द्वारा लगाए गए भारी कर मजदूरी की बढ़ती और मजदूरी कोष के विकास में बड़े पमाने पर हस्तक्षेप करते थे।<sup>69</sup> बाद में 1890 में उन्होंने अपने एक विस्तृत लेख 'इकोनामिक सिच्युएशन इन इंडिया' में इस तथ्य को उजागर किया कि भारत में औद्योगिक श्रमिक का पीडित करने वाला एक बेशर्त पूँजी की अपर्याप्तता थी जो अन्याय विषयों के साथ इस तथ्य का परिणाम थी कि भारतीयों की कुल आय में प्रथम तो बचता का अवकाश ही कम रहता है और फिर हमारी कुल अर्जित आयों पर भारी कर लगाकर उन्हें और भी क्षीण कर दिया जाता है। उन्होंने सगणना की कि कुल राष्ट्रीय बचता (कुल उत्पादन में से लोगों के जीवन निवाह पर होने वाले व्यय को घटा कर) की राशि प्रतिवर्ष 90 करोड़ रुपये थी, जिसमें से सरकार 50 करोड़ रुपये करो के रूप में ले लेती थी। इस प्रकार राष्ट्रीय वार्षिक बचतों का आधे से अधिक भाग 'यूनाधिक रूप से अधिकांशतः अनुत्पादक व्ययों की पूर्ति के लिए सरकारी कोष में चला जाता था। इससे स्पष्ट है कि हमारी औद्योगिक प्रगति का पीछे की ओर धकेलने वाला इससे अधिक बड़ा आर्थिक रोग और क्या हो सकता है?'<sup>70</sup> गापालकृष्ण गोखले ने 1902 में अपने प्रथम बजट भाषण में इन भावनाओं को प्रतिध्वनित किया। गोखले ने अपना मत प्रकट करते हुए कहा 'भारतीय वित्तों पर कराधान का स्तर इतना अधिक निम्न होना चाहिए कि उससे राष्ट्रीय उद्योग की अबाधित गतिविधि और विकास के लिए यथासंभव अवकाश मिल सके।'<sup>71</sup>

तथ्यात्मक रूप से बहुत सारे भारतीय नेताओं ने भारत की विशिष्ट आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों से संबंधित सैद्धांतिक नियम के स्तर पर निम्न कराधान की मांग उठाई। यह मांग 'अमृत बाजार पत्रिका' के 7 फरवरी 1871 के अंक में बड़ी स्पष्टता से अभिव्यक्त की गई। उसमें इस सरल कथन को निम्नलिखित रूप से अभिव्यक्ति दी गई

लोगों पर कराधान स्वयं लोगों द्वारा लगाया ही नहीं जाता और उनका साम्राज्य के वित्तों पर कोई नियंत्रण भी नहीं है।<sup>16</sup> उनकी चीखोपुकार कराधान में कटौती के लिए हो सकती है न कि वृद्धि के लिए। हमारी विनम्र सम्मति में ससदविहीन जनता के लिए कराधान में कटौती के लिए निरंतर और सुदृढ़ मांग करते रहना ही एकमात्र बुद्धिमत्तापूर्ण नीति है।

1886 में जी० वी० जोशी ने बल देकर घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन की विशिष्ट स्थितियों के कारण राष्ट्र की भौतिक और नैतिक प्रगति के लिए सरकारी बोझों का यथासंभव हलका होना आवश्यक है।<sup>16</sup> जब 1898 के उपरांत भारतीय बजटों में निरंतर वृद्धि होनी प्रारंभ हो गई, बहुत सारे भारतीय नेताओं ने बरो में छूट की मांग की।<sup>17</sup> 1902 में सुरेंद्रनाथ बँनर्जी ने टिप्पणी की कि जब देश के सामान्य करणात्मक मूल्यों मरते किसान हो तो देश के शासकों का उन प्रजाजनों का कराधान में छूट देना सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व बन जाता है।<sup>18</sup> 1905-06 के बजट पर भाषण करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्न कराधान के मामले को अत्यंत स्पष्टता के साथ इस प्रकार प्रस्तुत किया

सभी देशों में यह वित्त का सर्वसाधारण नियम है कि सरकारी बरो का भार यथासंभव हलका होना चाहिए। यदि संपन्न यूरोपीय देशों में यह स्थिति है तो भारत में इसकी और अधिक जरूरत है क्योंकि यहाँ राजस्व की वसूली निधन और अमहाय जनता से की जाती है तथा उस राजस्व के अपेक्षाकृत बड़े भाग का मुगलान जीण शीण एवं नितांत अभावग्रस्त कृषक वर्ग द्वारा लिया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ भारत में मामूली की विशिष्ट स्थितियों के कारण सरकारी व्ययों के एक बहुत बड़ा भाग का जनता की नैतिक तथा भौतिक उत्थिति में अनावश्यक प्रयत्न अथवा दूर गंभव कार्यो पर व्यय करना पड़ता है।<sup>17</sup>

### भारतीय दृष्टिकोण के कुछ पक्ष

देश पर अधिक कर भार हटाने के विचार की आवश्यकता में वृद्धि के लिए कई तथ्य उभर दायी थे। सी० एन० बरोन के अनुसार 1871-1901 की अवधि में कराधान का परिमाण राष्ट्रीय आय की ओसत का 8.9 प्रतिशत के बीच था।<sup>19</sup> द्वितीय, आवश्यकता में उपर कराधान अथवा कराधान का ऊंचा स्तर विनामगीय देश की प्रवृत्ति आर्थिक दृष्टि में निरर्थक रूप के लिए अधिक में भी हुआ परन्तु कठिनता उत्पन्न करता था। क्योंकि यह विमानों द्वारा अथवा दूसरे माध्यमों में निम्न मध्य वर्गों के सभी तथ्यों में बलपूर्वक संप्रतिद्वेषण था। यह धारणा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की अवधि में स्वयं प्रमाण के

रूप में सामने आ गई। तृतीय, वर्तमान कराधान के स्तर के समथक तत्व के रूप में देशा नुराग अथवा सामाजिक जागरूकता की भावना नहीं थी। इसके विपरीत, जैसा हम बाद में स्पष्ट रूप से दिखाएंगे, भारतीय नेताओं के मन में यह भय था कि भारत सरकार की विदेशी प्रवृत्ति के कारण प्रशासन की यूनतम आवश्यकताओं से किसी प्रकार का अधिक राजस्व शाही उद्देश्यों की पूर्ति में लाया जाएगा। चतुर्थ, भारतीय नेताओं ने भूमि और नमक पर करों के तथा शराब पर उत्पादन शुल्क के माध्यम से सरकार के भारतीय राजस्वों के उगाहने पर आपत्ति की। अन्तिम, भारतीय नेताओं ने कराधान के स्तर और उसके उपयोग के ढंग को सहसंबंधित कर दिया। उन वर्षों में भारत सरकार अतन्त राज्यों के कार्यों में अहस्तक्षेप के सिद्धांत की सकीण परिधि में काम कर रही थी और किसी बड़े पैमाने के विकास को सक्रियता से नहीं ले रही थी।

### राजस्व के स्रोत

अब हम भारत सरकार के राजस्व के तत्कालीन मुख्य स्रोतों, भूमि लगान, नमक कर, अफीम और उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, और आयकर के प्रति भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के दृष्टिकोण का विवेचन करेंगे।<sup>74</sup> वर्तमान भूमि लगान के परिमाण और उसमें किसी प्रकार की वृद्धि के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रवादी, नेताओं की तीव्रतम आलोचना तथा चुने हुए कुछ उत्पादनों पर आयात कर लगाकर कोश जुटाने की उन नेताओं द्वारा की गई जारदार वकालत का विस्तृत विवेचन पूर्ववर्ती अध्यायों में किया जा चुका है। अगले पष्ठों में आय कर, नमक कर, अफीम कर तथा उत्पादन शुल्क के संबंध में उनके विचार प्रस्तुत करते हुए उनका विश्लेषण किया गया है।

### आय कर<sup>75</sup>

हमारे अध्ययन के अंतर्गत अवधि के प्रारंभ में ही अर्थात् 1880 में लाइसेंस कर के रूप में प्रसिद्ध आय कर का एक सशोधित रूप भारत में लगाया जाता था। इस दिशा में सव-प्रथम प्रारंभ 1860 में किया गया, जब प्रथम वित्त सदस्य जेम्स विल्सन ने व्यापार, कृषि, व्यवसाय, सरकारी तथा गरसरकारी नौकरी से 200 रुपये प्रति वर्ष से अधिक आय पर कर लगा दिया। इस कर में निरन्तर परिवर्तन किए जाते रहे हैं और अन्त में 1865 में इसका परित्याग कर दिया गया, साथ में यह घोषणा की गई कि इसे देश के एक बहुत बड़े सुरक्षित कोष का काम करना था।<sup>76</sup> उस वर्ष के उपरांत व्यक्तिगत आय पर कर लगाने के मामले को कई बार अपनाया गया और कई बार छोड़ा गया। अन्ततः उसे कुछ विभिन्न रूपों में फिर ग्रहण किया गया।

1878 में भारत सरकार ने अन्तिम रूप से तब तक नियमित रूप ले चुके अकालों के मुकाबले के लिए लक्ष्मी अवधि की बीमा निधि योजना के रूप में समुचित राजकीय व्यवस्था का दृढ़ निश्चय किया। इस निधि के लिए रकम अर्जान भूराजस्व और ११ पर उपकर लगाने से और अशत व्यवसायी और व्यापारी वर्गों तथा दस्तकारों पर कर लगाने से उगाही जानी थी। इस कार्य के लिए कोई केंद्रीय कानून नहीं।



प्रातीय उपाया की ही इस विषय में सहायता ली गई। लाइसेंस कर वस्तुतः सीमित आय कर था और इसका निर्धारण प्रायः लगभग आय के अनुसार वर्गीकरण के आधार पर होता था।<sup>77</sup> कृषि, व्यवसाय तथा वेतनो से तथा इनके अतिरिक्त प्रतिभूतियों से प्राप्त होने वाली आय को इस कर की क्षेत्र सीमा के बाहर रखा गया था। इस कर का परिमाण और प्रकृति सब प्रातो में समान नहीं थी। उत्तर पश्चिमी प्रातो और अवध में तथा मद्रास में कर योग्य 'यूनतम आय की राशि 200 रुपये थी जबकि बंगाल, बंबई और पंजाब में यह राशि 100 रुपये थी। कर का परिमाण भी विभिन्न वर्गों (जिनके अंतर्गत करदाता विभक्त किए गए थे) के अनुसार भी भिन्न था परंतु यह किसी भी रूप में करदाता के कुल लाभ के दो प्रतिशत से अधिक अथवा 500 रुपये से अधिक नहीं था। 1879-80 में सरकार ने व्यवसायी और वेतनभोगी वर्गों तक इस कर के विस्तार की असफल चेष्टा की। 1880 में कर में छूट की सीमा 500 ₹० तक बढ़ा दी गई। इस समय कर में प्राप्त होने वाली राशि 5 लाख पौंड में ऊपर थी और करदाता व्यक्ति 228,447 थे।<sup>78</sup>

भारतीय नताओं ने लाइसेंस कर लगाने के समय ही सामान्य रूप से उसका विरोध किया<sup>79</sup> और परवर्ती वर्षों में उसे हटाने की मांग करते रहे।<sup>80</sup> यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने प्रमुख रूप से लाइसेंस कर लगाने के पीछे निहित सिद्धान्त पर प्रहार नहीं किया। उन्होंने इस लगाने के ढंग पर आपत्ति की, जो उनके अनुसार अमान्य और अन्यायपूर्ण था। इस कर के विरुद्ध उनकी मूलप्रथम आपत्ति यह थी कि यह आय के बहुत ही निम्न स्तर तक आक्रमण करता था, अतः निधनों की बहुत बड़ी मर्यादा इनमें दुष्प्रभावित होती थी। कुछ का तो यह भी विचार था कि करा का वास्तविक निधनों पर अत्यधिक भारी था, जबकि समझदारी इससे अपेक्षाकृत रूप में मुक्त था। उदाहरणार्थ, 14 जनवरी 1878 के अंक में 'इंडु प्रकाश' ने इस कर की 'आपाचितता पर प्रधानतम स्वर में पूछा कि यह कर्ता का 'आय है कि यह बड़े बड़े और प्रभावशाली व्यक्तियों, व्यापारियों तथा वाणिज्य में नये व्यक्तियों, जिनमें अधिकांश यूरोपीय हैं की जेबों का तो हल्के रूप में प्रभावित करता है जबकि छोटे छोटे व्यापारियों और दलालों पर जिनमें अधिकांश भारतीय हैं, पर भारी बोझ डालता है।'<sup>81</sup> इसी प्रकार 'इंडियन स्पेक्टेटर' ने 23 अक्टूबर 1881 के अंक में इस कर को घणघणकर राक्षस बनाया जा आधा भीरु और आधा गुंडा था। समृद्धतम और अच्छी सरकार के सर्वोत्तम लाभों का आनंद उठाने वालों के पास में तो यह दुःखकर निबल जाता था और छोटे छोटे व्यापारियों का मूल मूल्य था।<sup>82</sup> राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने इस ओर भी संकेत किया कि निधन लागू कर निर्धारण और समाहरण से संबंधित छोटे छोटे अधिकाारियों के दुष्प्रभावों की प्रकृति में ही बुझे तट्टे दुग्गी थे।<sup>83</sup> अतएव कुछ समाचारपत्रों ने कर सीमा बढाने की मांग की।<sup>84</sup> यह पर्याप्त रोचक तथ्य है कि 17 जनवरी 1880 के अंक में बंगाली ने बड़ी तीव्रता से कर की अधिकतम सीमा निर्धारित करने पर आपत्ति की क्योंकि हमारे उन वर्गों पर व्यापारियों के प्रति जितने हम प्रकार के निर्णय अपेक्षाकृत परंपरा की बराबर आयोजना की गयी थी और जो अधिकांश यूरोपीय ही थे विभिन्न परंपरागत व्यवहार हुआ था। यह यह उल्लेखनीय है कि भारतीय समाचारपत्र इन मांगों में इतना निधनों की तीव्र भावना



पेशना से वसूल की गई। 1902-03 में वरदाताओं की संख्या बढ़कर लगभग 5,31,000 हो गई और लगभग 21 करोड़ रुपये की राशि इकट्ठी हुई।<sup>92</sup>

आय कर के प्रति राष्ट्रवादी नेताओं के दृष्टिकोण में सामान्यतया मतभेद ही था। यदि समय की पर्याप्त लंबी अवधि के सदृश में देखा जाए तो यह मतभेद और भी स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ जाता है। वस्तुतः कुछ भारतीय नेताओं ने विभिन्न कालों में भिन्न-भिन्न यहाँ तक कि परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया।

1880 में आय कर लगाने के प्रस्ताव का और 1886 में वास्तविक रूप में इस कर के आरोपण का राष्ट्रवादी पत्रों और नेताओं ने बड़े पैमाने पर विरोध किया।<sup>93</sup> यह विरोध स्वयं कर की प्रकृति के विरुद्ध उसे यूरोपीयों और समृद्ध तथा प्रभावशाली भारतीयों का डर है। इतना नहीं था क्योंकि अतिरिक्त करों के किसी भी प्रस्ताव पर राष्ट्रवादियों में विश्वास का अभाव था और यह उस समय राष्ट्रवादी नेताओं के लिए एक प्रकार में स्थायी अभिशाप था, राष्ट्रवादियों का विरोध उस आवश्यकता की अस्वीकृति के प्रति था जिसके अंतर्गत यह कर लगाया गया था। उदाहरण के रूप में भारतीय समाचारपत्रों द्वारा अपनाई गई स्थिति की समीक्षा करते हुए 'वायस आफ इंडिया' के संपादक ने राष्ट्रवादियों के मतव्यं को इसी रूप में ग्रहण किया।<sup>94</sup> इसके अतिरिक्त 1882 से पहले तक तो बहुत सारे भारतीय राष्ट्रवादियों का यह आशंका थी कि आय कर लगाने में बजट में बचत हो सकती है और इन बचतों को सरकार आयात कर हटाने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकती है।<sup>95</sup> 1882 के उपरांत जब सचमुच आयात कर हटा दिया गया तो भारतीय नेताओं ने इस आधार पर आय कर का विरोध किया कि राजस्व वसूली का अपेक्षाकृत अच्छा साधन आयात करों का पुनः लगाना होगा।<sup>96</sup> थोड़े से भारतीयों ने इस कर से प्राप्त राजस्व को सरकार द्वारा तंजी से बढ़ते सैनिक व्ययों की पूर्ति के लिए प्रयोग करने का संदेह भी किया। ये व्यय भारतीयों के लिए कर्ज और कष्ट का कारण बने हुए थे।<sup>97</sup> अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आय कर विरोधियों के शीघ्र ही नतीजा यह निकल कर पड़ा कि एक पक्ष, व्यवसायी और वेतनभागी वर्गों को इसके सीमा क्षेत्र में लाने का समर्थन किया।<sup>98</sup>

इतना सच जानने के बावजूद यह जान लाना भी आवश्यक है कि जब आय कर के कुछ विरोधियों ने भारत के लिए प्रत्यक्ष कर के बजाय अगुणयुक्त होने की घोषणा की<sup>99</sup> अर्थात् उन्हें ने कुछ नये आय कर लगाने के स्थान पर आम जन के विस्तार और उच्च वृद्धि की वकालत की।<sup>100</sup> ता उस समय उन्होंने यह संस्था स्पष्ट कर दिया कि उनका विरोध किसी भी रूप में सामान्य सार्वजनिक कामना में उनका प्रेरित नहीं था जितना अनुचित बंधन तथा निहित स्वार्थपूर्ण विचारों के विरोध भी रूप में माना जा सकता है।<sup>101</sup> आधुनिक पर्याप्त स्पष्टबक्ता सिद्धांतों का है उन्होंने 1886 में आय कर विरोध (इसमें टैक्स विरोध 1886) पर भाषण करते हुए सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया कि उच्च वर्गों का नाइसंसार कर के स्थान पर आय कर के आगमन रम्य दास द्वारा ऐक्ट का अनुवर्तन जाता रहा है।<sup>102</sup>

आय कर के इस विरोध के अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जिसकी भारतीय

आय कर के इतिहास लेखको ने 'यूनाधिक रूप से लगभग उपेक्षा ही की है, यह था कि आय कर लगाने का विरोध करने के बदले राष्ट्रवादी नेताओं में अधिक सशक्त वर्ग ने कर लगाने के पक्ष, कर लगाने के समय और कर लग चुकने के बाद एक प्रकार से उसका प्रायः सक्रिय और प्रबल तथा कि-ही कि-ही मामलों में अनिच्छा तथा अनुत्साहपूर्ण समर्थन ही किया।

'अमृत बाजार पत्रिका' ने 1870 के बाद से आय कर का सक्रिय समर्थन किया।<sup>102</sup> बहुत सारे राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने 1880 में आय कर को वेतनभागी तथा व्यवसायी वर्गों पर लागू करने के जान स्ट्रैची के प्रयास का स्वागत और समर्थन किया।<sup>103</sup> भारत में रहने वाले अंगरेजों के विरोध के कारण जब स्ट्रैची के प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा तो 'अमृत बाजार पत्रिका' ने ताँखे व्यंग्य बाण बरसाए। 5 मार्च 1880 के अंक में इस पत्र ने भारतीय जालोचकों के आय कर हटाने के प्रयास का आड़े हाथों लेते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की

अब वेतनभोगिया और व्यवसायी वर्गों पर लगा कर हटा लिया गया है। एक निपट मूल्य को भी यह समझने में देर नहीं लगेगी कि सर स्ट्रैची के आय कर को लगाने के क्षेत्र में विस्तार की घोषणा के विरुद्ध की गई चितलाहट कितनी निरर्थक और निराधार थी। प्रत्येक समाज में कुछ गंधे अवश्य होते हैं, यदि वे न हों तो भला अपनी पीठ पर घावी के कपडों का बोझा कौन उठाएगा? परंतु इन गंधों को घोंघी के कपडों का भार उठाने पर ही लगाए रखना चाहिए। इन्हें राजनीतिक संस्थाओं का नेतृत्व अथवा नाबजर्निक पत्रों का संपादकत्व नहीं सभालने देना चाहिए।

परवर्ती वर्षों में 'हिंदू', 'इंदु प्रकाश' और 'इंडियन स्पेक्टटर' जैसे अग्रणी राष्ट्रवादी समाचारपत्रों की बहुसंख्या ने चालू लाइसेंस करके स्थान पर आय कर लगाने का अनुरोध किया।<sup>104</sup> अतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1885 में अपने प्रथम अधिवेशन में अयाय वस्तुओं के साथ फिलहाल इस कर से मुक्त सरकारी और गैरसरकारी वर्गों के समुदाय पर इस कर के विस्तार के अनुरोध का प्रस्ताव पारित किया।<sup>105</sup> 1886 में जब अतः आय कर लगाया गया तब 'अमृत बाजार पत्रिका', 'हिंदू', 'मराठा' तथा अन्य अनेक राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने उसका समर्थन किया।<sup>106</sup>

1886 के उपरांत राष्ट्रवादी क्षेत्रों में आय कर को और अधिक व्यापक तथा और अधिक विस्तृत लोकप्रियता मिलने लगी, विशेष रूप से यह इस तथ्य से सिद्ध है कि यह माना जाने लगा कि इसके हटाने का परिणाम अयाय करों को लगाना होगा। यह तथ्य इस दृष्टिकोण को भी सिद्ध करता है कि कुछ भारतीय नेताओं का पूर्ववर्ती विरोध वस्तुतः अपने आप में आय कर का विरोध न होकर किसी प्रकार के नए कराधान का ही विरोध था। जब एक बार यह प्रमाणित हो गया कि नए करों का लगाया अपरिहार्य है तो राष्ट्रवादी नेताओं ने एक स्वर से आय कर हटाने की मांग का विरोध किया तथा किसी भी प्रकार के अयाय कर लगाने की अपेक्षा इस कराधान का ही पक्ष लिया। भारतीय कांग्रेस के 1887 के तृतीय अधिवेशन में यह तथ्य उस समय नाटकीय जब एक प्रतिनिधि श्री० आर० चक्रवर्ती आयकर ने छोटे प्रस्ताव में

आय कर हटान की मांग पेश की, तत्काल नहीं' 'नहीं' 'सशोधन वापस ला' की ऊंची ऊंची आवाजें आईं, यह कहा गया कि हम अपने आपको कराधान से मुक्त नहीं करना चाहते हम इस कर के 'पक्षधर' हैं। 'बैठ जाइए' 'बकवास बंद कीजिए'। चक्रवर्ती आयकर को अपना मसौदा वापस लेने पर विवश होना पड़ा।<sup>107</sup> कांग्रेस के अगल अधिवेशन (1888) में मदनमोहन मालवीय ने घोषणा की कि कांग्रेस धनिकों अथवा उन लोगों पर जो कर चुकान में समर्थ हैं, आय कर लगाने की वाछनीयता से सहमति प्रकट करती है और उसकी पुष्टि करती है।<sup>108</sup>

1902 में सी० आई० चित्तामणि ने तहरवा प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कर हटान व आंदोलन की बड़ी जारदार निंदा की<sup>109</sup>, साथ ही उस वर्ष के कांग्रेस अध्यक्ष एस० एन० बैनर्जी की भी कर हटान की मांग के प्रति सहानुभूति नहीं थी।<sup>110</sup> भारत के अर्थ सावजनिक नताशा में मेदाभाई गौरीजी ने वायसरॉय की कौंसिल के सदस्य एस० एम० मन्नावारी का 26 अप्रैल 1889 को लिखे पत्र द्वारा आय कर के विरुद्ध नमक कर के पक्ष में मत देने के लिए उनकी निंदा की।<sup>111</sup> आर० सी० दत्त ने अपनी पुस्तक 'इकानामिक डिस्ट्री आफ इंडिया' में आय कर के 'यायसगत और उचित होने के कारण उसकी प्रशंसा की।<sup>112</sup> 1888 में जी० वी० जाशी नमक कर में वृद्धि के बदले आय कर में वृद्धि और विस्तार के पक्ष में जोरदार तर्क प्रस्तुत किया।<sup>113</sup> 'इंडियन एमोसिऐशन' ने भी 1894 में इसी प्रकार की मांग प्रस्तुत की।<sup>114</sup>

मसाचारपत्रों में अमृत बाजार पत्रिका' ने तो आय कर के पक्ष में जिहाद जारी रखा।<sup>115</sup> इस पत्र ने 18 अप्रैल 1893 के अपने अंक में इस कर के परिमाण में वृद्धि की मांग की। 28 दिसंबर 1887 के अपने अंक में हिंदू ने मांग की कि आय कर का भारताय कराधान का म्याई खोत बना देना चाहिए।<sup>116</sup> 15 दिसंबर 1890 के अपने अंक में मुधारक ने घोषणा की कि कर को हटाने की मांग असंदिग्ध रूप से स्वाधपूण ही होगी।<sup>117</sup> 'सजीवनी' में 10 मार्च 1894 के अंक में आय कर में वृद्धि की बकालत की। उमका आधार यह था कि वर्तमान दर में वास्तव में धनिकों को छूट मिलती थी।<sup>118</sup> 'बगानी' ने भी 4 नवंबर 1902 के अंक में कर हटाने पर आपत्ति की। 29 मई 1904 के अंक में 'मराठा' ने बजट में बचा होने पर भी इस कर के बने रहने की इच्छा प्रकट की और सुभाव दिया कि इस कर में हानि वाली आय का 'पाम बना देना चाहिए और उग आय का शिक्षा विधेयत औद्योगिक शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। बहुत सारे अर्थ समाचारपत्र आय कर हटाने के विरुद्ध बर्षों तक यही स्थिति अपनाए रहे और कई मामलों में तो इनके क्षेत्र विस्तार की गिरत बकालत करते रहे।<sup>119</sup> विधेयत 1888 में नमक कर में वृद्धि के समय बहुत अधिक मस्या में मसाचारपत्रों ने इसका बन्द आय कर में वृद्धि की बकालत की।<sup>120</sup>

1886 के उगगत आय कर के पक्ष में उल्लेखनीय विचारधारा के प्रकट प्रकृत के विरुद्ध वेचन मुटटा भर भारतीय मसाचारपत्रों और नताशा में ही उग वर्ष के ~~प्रकाशित~~ की मांग की। ~~इस~~ तक ~~यह~~ निश्चित रूप में जान पाए हैं। 'मसाचारपत्र' (बगान में निरन्तर बकालत) और 11 फरवरी 1891

का सहकर, 'नाथ वेस्ट प्राविसेज' तथा अवध से प्रकाशित होने वाला 'भारत जीवन' ही इस कर को हटाने की माग कर रहे थे।<sup>1</sup> राजनीतिक नेताओं में जी० आर० चित्तनवीस, महाराजा दरभंगा और आशुतोष मुखर्जी ही, जिनकी उच्च स्तर के राष्ट्रीय नेताओं में गिनती नहीं होती थी। कर का विरोध करने वाला थे।<sup>1</sup>

जहाँ तक आय कर लगाने के ढंग का संबंध है, कुछ भारतीय नेताओं ने भू से ही जमींदारों और भूमिपतियों को इस कर से मुक्त करने की आलोचना की। 17 जनवरी 1880 को 'बंगाली' ने इसी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हुए जमींदारों द्वारा पहले से ही सड़क शुल्क और लोकिकम शुल्क चुकाए जाने के कारण उन्हें इस कर से मुक्ति देने के औचित्य की धारणा का खंडन किया। उस पत्र ने अपना मत प्रकट करते हुए लिखा कि ये कर वस्तुतः परोक्ष रूप से किसानों द्वारा ही चुकाए जाते हैं। 7, 9, और 12 जनवरी 1886 के अंकों में 'हिंदू' ने, 25 फरवरी 1886 के अंक में 'इंडियन नेशन' ने और 18 जनवरी 1886 के अंक में 'गुजरात मित्र' ने जमींदारों को 1885 के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखने की आलोचना की।<sup>2</sup> 1888 में जी० वी० जोशी ने, ताल्लुकदारों और बागान मालिकों तक आय कर के क्षेत्र विस्तार के पक्ष में विस्तृत विवेचन किया।<sup>3</sup> 9 जनवरी 1890 के अंक में 'हिंदू' ने और 18 फरवरी 1894 के अंक में 'कैसेरे हिंदू'<sup>4</sup> ने भी इसी प्रकार की माग करते हुए तक प्रस्तुत किए।

थोड़े से भारतीय नेताओं ने भारतीय आय कर में नियमित वृद्धि के नितांत अभाव की भी चर्चा की। इस कर की दृष्टि से 2000 रुपये से ऊपर की सभी प्रकार की वार्षिक आयों को इकट्ठे वर्गीकृत करने पर आपत्ति करते हुए हिंदू न दूतापूर्वक लिखा कि 'त्रिमिक' कराधान का सिद्धांत विश्व के अन्य किसी भी देश के समान ही भारत में भी सही तौर पर लागू है। अपना मत प्रकट करते हुए उसने लिखा कि उच्च वेतनभोगियों के लिए 2½ प्रतिशत कर की दर बहुत ही नीची दर है।<sup>5</sup> इंडियन एसोसिएशन ने 8 मार्च 1894 के ज्ञापन में सुझाव दिया कि जीवन की उपभोग सामग्री पर परोक्ष ढंग से कराधान के बदले आय कर की दर त्रिमिक रूप से बढ़ा देनी चाहिए। अपेक्षाकृत उच्च वेतन पर अपेक्षाकृत ऊँचा करारोपण करना चाहिए।<sup>6</sup> बहुत सारे और भारतीय नेताओं ने सुझाव स्थित रूप से त्रिमिक आय कर के लगाने की माग की।<sup>7</sup>

इस समय राष्ट्रवादी नेताओं के विशाल बहुमत द्वारा आय कर के समयन के अथवा कम से कम उसके अधिकार क्षेत्र के वेतनभोगी और व्यवसायी वर्गों तक विस्तार के आधारों का सक्षिप्त विवेचन कदाचित्त अनुचित न होगा। इन आधारों में प्रथम और कदाचित्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण यह समझ थी कि आय कर ही एक ऐसा अवेला महत्वपूर्ण कर है जिसके द्वारा भारत में रहने वाले यूरोपीय, भले ही वे सरकारी अधिकारी हों, निजी व्यवसाय संस्थानों के कर्मचारी हों या व्यवसाय वर्ग के लोग हों अथवा व्यापारी हों, भारत सरकार के शासन-संचालन के व्यय में अपना भाग का योगदान कर सकते हैं।<sup>8</sup> 'अमृत बाजार पत्रिका' ने इसी भावना की अभिव्यक्ति निम्नलिखित शब्दों में की। आय कर भारत में रहने वाले गत प्रतिगत यूरोपीयों की जेबा को

है जबकि इससे हजार भारतीयों में केवल एक व्यक्ति की जेब ही प्रभावित होती है।<sup>130</sup> कुछ समाचारपत्रों ने तो यह दृढ़ मत अभिव्यक्त किया कि आय कर का विरोध करना यूरोपिया के हाथों खेलना है।<sup>131</sup> राष्ट्रवादियों द्वारा आय कर को समयन देने का दूसरा कारण था कराधान में सामाजिक न्याय और समता की भावना। इस अत्यंत प्रजातंत्रीय दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति कि-ही कि-ही मामलों में तो सवथा स्पष्ट रूप में की गई। उदाहरणार्थ, 17 जनवरी 1880 के अंक में 'बंगाली' ने बल देकर कहा कि यदि भारत सरकार अपने खर्चों में कटौती न करके उन खर्चों की पूर्ति के लिए नए कर लगाने पर ही सुली टूट है तो अच्छा, बहुत ही अच्छा यह होगा कि यह कर निधना पर थोपने की अपेक्षा उन लागों पर लगाए जाए जो उनका भार सहन कर सकते हैं।<sup>132</sup> 5 मार्च 1880 के अंक में तो अमृत बाजार पत्रिका ने और भी अधिक दृढ़ता के साथ लिखा 'इस समय हमारे सामने विचारणीय प्रश्न यह नहीं है कि प्रत्यक्ष कर भारत के अनुकूल है अथवा नहीं? इस समय तो विचारणीय यह है कि हमारे समाज के अपेक्षाकृत संपन्न सदस्यों को इस भार में अपने समुचित भाग का योगदान करना चाहिए अथवा नहीं? यदि उन्हें अपना योगदान करना है तो प्रत्यक्ष कराधान के अतिरिक्त उन तक पहुंचने का और कोई माग ही नहीं।' अगले वर्ष 'पत्रिका' ने आय कर लगाने का औचित्य की एक धार फिर बकायत की तथा इस कर के द्वारा लोगों को अत्यधिक असुविधा और कष्ट मिलने और इस कारण इससे लाभ के निरसूल हो जान के तक के औचित्य का मानन से इनकार कर दिया। उसने अपने 29 दिसंबर 1881 के अंक में लिखा 'सर्वप्रथम, सत्य तो यह है कि जब बीम बराब लोगो को नमन कर, भूमि लगान और मुद्राक गुन्' आदि के भुगतान में होन जाने कष्ट की निश्चित रूप से ही कोई चिन्ता नहीं की जाती तो फिर इस दंग में समृद्ध वर्ग के दो लाख लोगो को होन वाली साधारण सी असुविधा की चिन्ता ही क्यों करता है?'<sup>133</sup> 19 दिसंबर 1884 के अंक में 'हिंदू' ने भी विरोध किया 'निधन लोगो को घनिष्ठा पर कर लगाने पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं। निधनों को तो उलट अपने पर नमन कर, उत्पादन शुल्क और मुद्राक गुन् आदि लगाने के विरुद्ध विवायन करनी चाहिए।' <sup>134</sup> 1888 में जी० वी० जे० भी इसी दृष्टिकोण को बड़ी स्पष्टता और प्रबलता के साथ अभिव्यक्ति दी। 1886 में आय कर लगाया जा अनुमोदन करने हुए उन्ने यहा तक कहा कि 1886 के आय कर अधिनियम का अन्तगत्त उच्च तथा उच्च मध्यम वर्गों पर डाला गया भार निर्धन वर्गों पर डाला गए भार का मुकाबल निम्नी भी परिमाण में स्वर में पर्याप्त, उचित अथवा अनुष्ण नहीं है। इसका विपरीत सत्य तो यह है कि कराधान का नए उपाय में जोर कराधान में समाज तथा समुचित अनुजन सिद्ध नहीं होता। 1886 के कराधान के उपायों आज भी सिद्धि का बीज है कि संपन्न वर्ग का कर गाने परिमाण में चुकाना है जबकि जनता को अपना उचित भाग की क्षमता अधिनियमों का भुगतान करना पटना है।<sup>135</sup>

हां, आय कर के समयकों में अंगव हर परत का अनुमान नहीं किया। निर्धन वर्ग में इन स्वीकार कराने हुए भी जिस दंग में कर लगाया जा रहा था, उसी मायापना की। उनके अंगुहार तथा सम्मानपूर्वक सम्मेलनों का विचार करना याद कर





इनके वेतनभोगी वर्ग के साथ घनिष्ठ पारिवारिक संबंध थे फिर भी उनमें से बहुत बड़ी संख्या में नेताओं ने इस तरह का समर्थन ही नहीं किया प्रत्युत जाय कर लगाने की बजाय लत तक की। यहाँ तक कि इस तरह का अपने उस रूप में विरोध करने वाले नेताओं की बहुत बड़ी संख्या ने इसका समर्थन ही नहीं किया प्रत्युत इसकी अधिकार सीमा का वेतनभोगी वर्गों तथा व्यवसायी वर्गों तक विस्तार करने की भाग की। इस प्रकार शिक्षित मध्यवर्गीय वर्गों को किसी प्रकार के प्रत्यक्ष कराधान की अधिकार सीमा के अंतर्गत लाने की वाछनीयता के बारे में राष्ट्रवादी नेताओं में प्रायः यथासंभव व्यापक एकरमता थी। जब एक बार आय कर अस्तित्व में आ गया तो परवर्ती वर्षों में दृग हटाने के लिए इसके विरुद्ध कोई एक भी महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी स्वर सुनने को नहीं मिला।

इस सदन में यह अत्यंत सावधानी के साथ उन्नेत्तनीय है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकांश शीपम्य नेता तथा अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी समाचारपत्रों, 'अमृत बाजार पत्रिका', 'हिंदू', 'मराठा', 'बंगाली', 'हिन्दवादी', 'सजीवनी', 'इंदु प्रकाश', 'इण्डियन स्पेक्टोर तथा 'स्वदेशमित्र' के स्वामी तथा संपादक निरिच्छत रूप से आय कर के निर्धारण क्षेत्र के अंतर्गत आते थे और अथवा प्रत्यक्ष करों के बंधन से अथवा यहाँ तक कि अधिकांशतः पराक्ष करों के बंधन से संवत्सा मुक्त थे।<sup>117</sup> इतने पर भी वे अपने आप को अपने पर कर लगाने के लिए समर्पित करने के लिए और इस रूप में आत्महत्या के कष्ट का भुगतान के लिए सहमत थे ताकि भारत सरकार के विदेशी कमचारियों पर कराधान किया जा सके। भारतीय राष्ट्रीय नेताओं का यह दृष्टिकोण एक आर राष्ट्रिय भावनाओं के तथा देश पर विदेशी शासन के विरुद्ध शत्रुता की भावनाओं के उभरते तूफान का चोन्क है और दूसरी ओर उम समय के राष्ट्रीय नेताओं द्वारा सामान्य राष्ट्रीय हिता के समर्थन निजी स्वार्थों को गौण बनाने की प्रवृत्ति का सूचक है।<sup>118</sup>

राष्ट्रवादी नेताओं ने जनता के वेतन उसी वर्ग के हिता की इस मामले में दृग्भाल की जिम्मेदार की वापिस आय एक हजार रुपय प्रति वर्ष तक की अथवा दूसरे शब्दों में निम्न दुबानदारा तथा निम्नवेतनभोगी सरकारी कमचारियों के हिता की बरालत की। इन संबंध में यह अवश्य उन्नेत्तनीय है कि भारतीय नेताओं द्वारा आय कर की हूट सीमा का बंधन की बरालत केवल सामाजिक न्याय और समता के आधार पर ही उपयुक्त नहीं थी प्रत्युत आठ छोट दुबानदारा और निम्न सरकारी सरकारी कमचारियों को राष्ट्रीय पक्ष में लाने की यह एक समी दृष्टिया में संवत्सा उपयुक्त राजनीतिक युक्ति भी थी। यहाँ तक कि इस मामले में नेताओं ने आय कर की हूट सीमा बढ़ाने की अपेक्षा नकार कर और भूमि लगान घटाने के लिए अपेक्षाकृत बड़े संघर्ष किया। मत्स्य यह है भारतीय नेताओं ने करों में राष्ट्रवाद के मामले में संवत्सा बरालत हुए और समर्थन किसी भी योजना की विचारित करते हुए ऊपर से कोई प्राथमिकताओं का ध्या रना।<sup>119</sup> यहाँ तक कि उन्नेत्तनीय है कि सामान्य में भारतीय नेताओं ने आय कर के मामले में दृग्भाल की हूटान के लिए निरन्तर बंधन तथा ध्यान्तन कर रहे यद्यपि ध्यान्तिया और जमीनरा के हिता का वापिस रूप में प्रतिनिधित्व नहीं किया।<sup>120</sup>

## नमक कर

1880 से 1905 की अवधि में नमक कर भारत सरकार की आय का एक दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत था। नमक पर कराधान की पद्धति एक प्रांत से दूसरे प्रांत में भिन्न भिन्न रूप लिए हुए थी। बर्मा में इसे उत्पादन शुल्क का रूप प्राप्त था बंगाल में प्रधान रूप से आयातित नमक पर सीमा शुल्क लगता था<sup>151</sup> और मद्रास, उत्तरी भारत तथा पंजाब में सरकार द्वारा एकाधिकार के रूप में स्वतः उत्पादित नमक पर कर सरकार द्वारा वस्तुओं के निर्धारित मूल्य में सम्मिलित रहता था।

1878-79 तक नमक कर की दर भी एक प्रांत से दूसरे प्रांत में व्यापक रूप से भिन्न थी।<sup>152</sup> कलकत्ता अंतर्देशीय सीमा शुल्क रेखा समाप्त करने के उपरांत जब नमक कर की दर में लगभग एकरूपता लाई गई तो उत्तरी भारत में उसे समानांतर रूप देने के लिए उसकी दर घटाकर 3 रुपये प्रति मन के स्थान पर 2र० 8 आन प्रति मन कर दी गई, बंगाल में भी यह दर घटाकर 3 र० 4 आने के बदले 2 र० 14 आने प्रति मन कर दी गई। मद्रास और बर्मा में यह दर बढ़ाकर 1 र० 13 आने के स्थान पर 2 र० 8 आन कर दी गई। यह सुधारकारी एकीकरण सरकार के लिए लाभ प्रद सिद्ध हुआ। 1875 77 से 1879 81 में नमक कर के राजस्व की राशि लगभग दस लाख पौड बढ़ गई।<sup>153</sup> परंतु लोग न इस वृद्धि के पूरे परिमाण को अनुभव नहीं किया क्योंकि उस समय परिवहन सुविधाओं के समकालीन विस्तार के कारण बाजार में नमक के मूल्यों में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आ गई थी।

1858 से पहले भी प्रमुख भारतीयों ने नमक कर की आलोचना की थी।<sup>154</sup> 1882 तक भारतीय नेता नमक कर में कटौती और उसे हटाने तक की मांग करते रहे। नमक कर के समाप्ति के प्रति 1859 में प्रारंभ हुई और उसके फलस्वरूप बर्मा प्रांत में कर की दर बढ़कर काफी ऊंची हो गई। अतः स्वाभाविक रूप से ही उस प्रदेश में कर के विरुद्ध तथा कर में वृद्धि के विरुद्ध आलाचना का स्वर अत्यंत मुखर था।<sup>155</sup> उदाहरणार्थ, 1880 में दादाभाई नौरोजी ने नमक कर को ब्रिटिश नाम पर एक कलकत्ता बताया।<sup>156</sup>

इस समय हम इस तथ्य की ओर भी ध्यान देना होगा कि भारतीय नेताओं के एक अन्य बग न भले ही वह अल्पसंख्यक था, नमक कर का समर्थन किया। यह बहुत स्वाभाविक था कि यह बग प्रधान रूप से बंगाल में ही था जहां नमक कर में परिवर्तन नीचे की ओर जा रहे थे और जहां जमींदार सदब किसानों के हितों के मूल्य पर अपने हितों की रक्षा के प्रति चिंतित थे। बंगाल में नमक कर के पक्षधर दो प्रारंभिक प्रतिनिधि थे, राजा दिगंबर मिश्र और त्रिम्बोदास पाल।<sup>157</sup> इससे भी अधिक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि 'अमृत बाजार पत्रिका' ने भी सड़क शुल्क जस आयाय करो में वृद्धि के बदले नमक कर में वृद्धि की कबालत की।<sup>158</sup> इस अप्रत्याशित स्थिति अपनाने के लिए पत्र के संपादक द्वारा निर्दिष्ट कारण यह था कि बंगाल में नमक कर प्रधान रूप से नमक पर आयात शुल्क था। यह नमक लिवरपूल और चेन्नौर से लाया जाता था अतः इस कर में वृद्धि का सारा भार विदेशियों पर ही पड़ने की संभावना थी।<sup>159</sup>

1882 में भारत सरकार ने नमक कर में कटौती की। बर्मा अथवा पंजाब के सिंधु

पार के जिलों को छोड़कर सारे देश में यह कर दो रुपये प्रति मन कर दिया गया। इस कदम के प्रति राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया मिश्रित थी। मराठा और बंबई के बहुत सारे अर्थ पत्रों ने और बंगाल के कुछ पत्रों ने इसका स्वागत किया और सरकार से इसे और अधिक घटाने का ही अनुरोध किया।<sup>160</sup> दूसरी ओर 'अमृत बाजार पत्रिका' और बंगाल तथा उत्तरी भारत के कितने ही दूसरे पत्रों ने अनुभव किया कि इस कदम का स्वागत नहीं किया जा सकता क्योंकि वस्तुतः लोगों ने नमक कर का कभी दुखप्रद नहीं माना। इसके बदले तो लाइसेंस कर के भुगतान में राहत देनी चाहिए थी।<sup>161</sup>

1882 और 1888 की मध्यावधि में नमक कर के विरुद्ध अनेक राष्ट्रीय स्वर मुखरित हुए। उदाहरणार्थ नमक कर विरोधी आंदोलन के संचालन में अग्रदूत होने का श्रेय प्राप्त करने वाले जी० वी० जोशी ने इन्हीं वर्षों की अवधि में नमक कर के विरुद्ध अपना मधुप जारी किया था। 1886 में प्रकाशित अपने एक लेख 'वेज ऐंड मीज आफ मीटिंग दि ऐंडीशियनन आर्मी एकम्पेंडीचर' में उन्होंने नमक कर का और जनजीवन तथा लोकप्रियता पर उसके प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने नमक कर में किसी भी प्रकार की वृद्धि का अत्यंत प्रखरता के साथ विरोध किया तथा किन्हीं क्षेत्रों में इस कर का मुरखित राजस्व मानने की नीति को घातक प्रवृत्ति बताने हुए उसकी तीव्र निंदा की। उन्होंने नमक कर का दण्ड मंथना कराने का एक अंग बनाए रखने की भर्त्सना की।<sup>162</sup> 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम अधिवेशन में ही एम० ए० स्वामिनाथन अय्यर तथा वी० एम० पंतुलु ने नमक कर में किसी प्रकार की वृद्धि के प्रयत्न की निन्दा की तथा कांग्रेस और जनता में इस प्रकार की किसी भी अवांछनीय घटना के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने का अनुरोध किया।<sup>163</sup> इन वर्षों की अवधि में कुछ एक अप्रगण्य समाचारपत्रों ने भी नमक कर घटाने अथवा उम समाप्त करने की वकालत की।<sup>164</sup> दूसरी ओर 1886 में कुछ समाचारपत्रों ने आय कर लगाने के बदले नमक कर में वृद्धि की वकालत की।<sup>165</sup>

1888 तक ऊपरी बंधों पर विजय और उसके संयोजन के उत्तर-पश्चिमी सीमा में सैनिक बाधवाहों का तथा विनिमय में हानि वाली निरंतर गिरावट के पनस्वरूप भारत सरकार की आर्थिक स्थिति एक बार फिर गहवद हो गई थी और एक बार फिर नए करा का लगाना अनिवार्य हो गया। इस सबके परिणामस्वरूप तत्कालीन वित्त मन्त्र जेम्स ब्रिस्टल ने 19 जनवरी 1888 के अपने एक बाधवाहों आयोग द्वारा नमक पर 2 रुपये प्रति मन कर के स्थान पर उम कर का हार्ड रूप प्रति मन कर देना पड़ा।<sup>166</sup> 1902 में नमक कर में कुल आय 9। करोड़ रुपये हुई जबकि 1888 में इस कर में हानि वाली आय की राशि 76 करोड़ रुपये थी।<sup>167</sup>

नमक कर में वृद्धि का भारत में जनता, राज और विरोध की भावना, तीव्र रूप में उत्पन्न कर दी। मराठा, हिंदू, बंगाली और यह। तक कि 'अमृत बाजार पत्रिका' के साथ साथ ही बहूत सार अर्थपत्रों राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने उड़ी ही तीव्र और निरंतर भावों में इस पण की वृद्धि का भर्त्सना की।<sup>168</sup> कुछ समाचारपत्रों के विरोध

का ढग तो विद्रोह की सीमा को छूता सा लगने लगा। उदाहरणार्थ, बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित केसरी ने अपने 31 जनवरी 1888 के अंक में टिप्पणी करते हुए लिखा

विश्व के किसी मूभाग में भारत के समान दुभाग्यग्रस्त लोग नहीं रहते। यदि विश्व के किसी भी देश के किसी व्यक्ति को उसके पापों के लिए दंड देना हो तो उसे भारत में भेज दीजिए। हमें यह सब भारत सरकार के नमक कर विषयक नवीन आदेश के सदम में ही सोचने को विवश होना पड़ रहा है। वस्तुतः इस प्रकार का अमानवीय पग केवल वही उठा सकता है जिसे भारतीय जनता की सवथा अभावग्रस्त और दीन हीन दशा की चिंता ही न हो। इस समय तो उन लोगों की ही बच जा रही है जो यह मानते हैं कि तलवार के बल पर अंगरेजों ने भारत को जीता है और तलवार के बल पर उन्हें इसे अपने अधीन बनाए रखना चाहिए। बिल्ली स्वभावतः बिनम्र और भीरु होती है परंतु जब उसे आवश्यकता में अधिक दबाया जाना है तो वही पलटकर इस प्रकार से भ्रष्ट होती है कि उसका प्रहार असह्य हो जाता है। इस समय यही संभव स्थिति हिंदू की है। यहाँ यह स्मरणीय है कि इस समय अंगरेज लोगों पर थोड़ा सा भी कर भार डालने में सकोच करने वाली सरकार के लिए भारत पर अपना स्थाई प्रभुत्व खोने की आशंका हो सकती है।<sup>169</sup>

‘बोध समाचार’ ने अपने 25 जनवरी 1888 के अंक में चेतावनी दते हुए लिखा कि वर्तमान बड़ोतरी गहरी खाई के घसते बगार के अतिरिक्त और कुछ नहीं और इसे लागू करना जनता के रिसते घावा को हरा करना है, इसमें जनसाधारण की शांति और सतोष भंग हान की निश्चित आशंका निहित है।<sup>170</sup> महाराष्ट्र मित्र ने अपने 8 मार्च 1888 के अंक में अनाय वस्तुओं के साथ नमक कर में वृद्धि के विरुद्ध लोगों को भड़काते हुए एक हिंदू और एक अंगरेज के बीच एक वातालाप प्रकाशित किया जिसमें हिंदू लाड डफरिन का बसाई की उपमा देता है। अंगरेज जब हिंदू के इस व्यवहार पर आपत्ति प्रकट करता है तो वह उत्तर में स्पष्ट शब्दों में कहता है ‘क्या नमक कर में वृद्धि जीवन रक्त चूसना नहीं?’<sup>171</sup> इसी प्रकार बंगाल के पत्र ‘प्रजाबधु’ ने अपने 27 जनवरी 1888 के अंक में आश्चर्य प्रकट करते हुए लिखा ‘सचमुच भारतीयों के लिए वह घड़ी अभिशाप रूप की थी, जब लाड डफरिन ने भारत भूमि पर पाव रखा।’<sup>172</sup>

नमक कर में बड़ोतरी ने एक बार फिर जी० वी० जाशी को 1888 में सरकार की नमक कर नीति पर घातक प्रहार करने का उत्तेजित किया।<sup>173</sup> अतः इस प्रश्न को 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने हाथ में लिया और नमक कर वृद्धि के पग को अनाय ठहराते हुए उसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित तथा अभिलिखित किया।<sup>174</sup> यह एक पर्याप्त रोचक तथ्य है कि कांग्रेस ने यह प्रस्ताव अपनी ही स्थाई समिति की इच्छाओं के विरुद्ध पारित किया। स्थाई समिति इस प्रस्ताव का पहले ही इस आधार पर विरोध कर चुकी थी कि एक बार जब वृद्धि कर ही दी गई है तो उसके तुरंत उपरांत उसे हटाने की मांग करना सवथा निरर्थक है।<sup>175</sup> अतः इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि रत्नगिरि जिले

के दा साधारण सदस्यों द्वारा प्रस्तुत तथा समर्थित प्रस्ताव पर कांग्रेस के किसी भी मुख्य नेता ने कोई भी ब्यक्तिय नहीं दिया।<sup>176</sup>

इस प्रश्न पर राष्ट्रवादी समझमत्त मत को छिन्न भिन्न करते हुए थोड़े मन्वर सरकारी पक्ष के समर्थन में भी मुत्तारित हुए।<sup>177</sup> यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पहल में ही विराधी राज्य के चतुर्थ स्तम्भ के रूप में मायना प्राप्त 'अमृत बाजार पत्रिका' और 'ट्रिब्यून' जैसे अधिकांश समाचारपत्रों के नाम इस समय इस प्रश्न पर राष्ट्रीय भावना के मुख्य स्त्रात में पुनः सम्मिलित होकर उमःसमुक्त स्वर से वाणी दनवाला की मूची व अतगत नहीं था।

राष्ट्रीय नेताओं द्वारा परवर्ती वर्षों में नमक कर की तीव्र निंदा और उसमें कटौती की निरन्तर माग जारी रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सन्ध में राष्ट्रीय भावना का सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व किया और एक के बाद दूसरे वर्ष निरन्तर इस कर में तात्कालिक कटौती की माग के प्रस्ताव पारित करते रही।<sup>178</sup> बहुत मार प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं ने इसी पक्ष का अनुसरण किया।<sup>179</sup> जी० वी० जोशी के राजनीतिक सिष्य गोपालकृष्ण गोखले ने अपना राजनीतिक विषय में नमक कर के प्रश्न को अपनी रुचि का विषय बनाया तथा अपने गुरु के साथ ही 'राजनीतिक' मंच तथा विधानसभा के सदन में आग बढाया।<sup>180</sup> इसी प्रकार अधिकांश राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने इस कर के विरुद्ध वर्षों तक अविच्छिन्न रूप में आंदोलन चलाए रखा।<sup>181</sup> इस मन्ध में आर० टी० रसडन नामक एक अंगरेज व्यापारी द्वारा 'मराठा' के संपादक का लिखे और मराठा के ही 21 जुलाई 1889 के एक में प्रकाशित पत्र का विवरण भी एक पर्याप्त रोचक तथ्य प्रस्तुत करता है। यद्यपि स्पष्टतः इसमें व्यक्तिगत मत का ही प्रकाशन था तथापि इसके प्रकाशन का अर्थ निश्चित रूप से इसके संपादक तिलक के मत के थोड़ा बहुत अनुकूल हाना था। इसके प्रकाशन से संपादक जेल जाने में बाल बाल बचा।<sup>182</sup> पत्र लेखक रसडन ने भारतीय नेताओं का अनाज बानून विरोधी आंदोलन के समानुद्भव नमक कर के विरुद्ध आंदोलन चलाने की सलाह दी। उन्होंने भारतीयों से अनुरोध किया कि वे सरकार को बतलाए कि अबाल से बहुत बड़ी सन्ध में होने वाली मृत्यु तो नमक कर से हाने वाली हत्या ही है। यह सारी बायबाही घणाजनक, लज्जाजनक तथा कलकपूण है। हम इस कर का वापस लेने का अनुरोध करते हैं। यदि तुम इस कर को नहीं हटाओ तो हम प्रयत्न करेंगे और स्थिति को इस प्रकार से असह्य और विषम बना दें कि तुम चाहो अथवा न चाहो पर तुम्हें इस कर को क्षीघ्रता से हटाना ही पड़ेगा। महात्मा गांधी द्वारा लगभग चालीस वर्ष बाद अपनाए गए पक्ष का निर्देश करते हुए उसने भारतीय नेताओं का सलाह दी कि वे अपने लोगों को समझाए कि वे स्वयं नमक तयार करें ताकि उन्हें नमक कर देना ही न पड़े और आप नेतागण उनकी आवश्यकता के समय उन्हें सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए कोष की व्यवस्था करके उन्हें इस दिशा में प्रोत्साहन दें सवत हैं।'

बाद में शताब्दी के बदलते बदलते जब बजटों में बचत होने लगी तो भारतीय नेताओं ने इन बचतों का निम्नलिखित रूप में उपयोग करने और सबप्रथम नमक कर में कटौती करने के लिए संध किया।<sup>183</sup> मिलमालिक संध को सन्धधित करते हुए

डॉ० ई० वाचा ने तो यहाँ तक कहा कि कपास पर सीमा शुल्क हटाने से भी पहले नमक कर में कटौती करनी चाहिए।<sup>184</sup>

अतः 1903 में 8 आने प्रति मन की दर से नमक कर में कटौती की घोषणा की गई। जैसी कि आशा की जाती थी, भारतीय नेताओं ने इस घोषणा का सद्प स्वागत किया। हा, उम समय उन्होंने कर की इस दर को और नीचा करने की माग पेश कर दी।<sup>185</sup> परवर्ती महीनों और वर्षों में यह माग दोहराई गई<sup>186</sup> और जब 1905 में सरकार ने आठ आने प्रति मन की दर से और अधिक राहत देने की स्वीकृति दी तो भारतीयों ने अपनी प्रतिक्रिया सरकार को बघाई देने के साथ साथ इस कर में और अधिक कटौती करने की माग के रूप में प्रकट की।<sup>187</sup>

यह उल्लेखनीय है कि जहाँ एक ओर भारतीय नेताओं का शक्तिसंपन्न तथा प्रभुत्व-प्राप्त वर्ग नमक कर के विरुद्ध सघष कर रहा था, वहाँ दूसरी ओर एक छोटा सा अल्पमन प्रमुख रूप से 'अमृत बाजार पत्रिका' के नेतृत्व में नमक कर के बदले आय कर में अथवा अयाय करों में राहत देने के पक्ष में अपने विचार प्रकट कर रहा था।<sup>188</sup> जसा हम पहले ही दिखा चुके हैं, थोड़े से अंतराल के लिए 1888 में 'अमृत बाजार पत्रिका' ने अपनी स्थिति बदली थी और नमक कर में वृद्धि का विरोध किया था, परंतु 1888 के उपरांत उसने एक बार पुनः अपनी पूर्ववर्ती स्थिति अपना ली।<sup>189</sup>

### नमक कर पर राष्ट्रवादियों के प्रहार के कारण

राष्ट्रवादियों ने नमक कर पर अपने आक्रमण के लिए बौद्धिक कारण प्रस्तुत किए? उन्होंने सैद्धांतिक आपत्ति उठानी प्रारंभ की। उनकी घोषणा के अनुसार उत्तम राजस्व और न्यायपूर्ण कराधान का यह नियम है कि जीवन की प्रधान आवश्यकता की वस्तु नमक निस्संदेह जीवन की एक प्रमुख आवश्यकता थी पर कराधान और वह भी इस जसाधारण परिमाण में नहीं होना चाहिए।<sup>190</sup> इसके उपरांत उन्होंने प्रशामका की इस धारणा के आगे प्रश्नचिह्न लगाया कि यद्यपि इस कर से समृद्ध राजस्व की प्राप्ति होती है तथापि इसका भार लोगो को दुःखप्रद प्रतीत नहीं होता क्योंकि यह जनसंख्या के विशाल भाग में बँटा हुआ है।<sup>191</sup> उनका कथन था कि इसके परिमाण को अमृत रूप में नहीं नापना चाहिए प्रत्युत भारतीय जनता की निपट दरिद्रता के सदम में और उस प्रसंग में ही उसे देखना चाहिए। यदि लोगो की आय के अत्यंत निम्न स्तर को देखा जाए तो कुछ आने प्रति व्यक्ति कर भी वास्तव में ही स्पष्ट रूप से उनकी कमर तोड़ने वाला सिद्ध होगा। इस दिशा में तक देते हुए जी० वी० जोशी ने टिप्पणी की कि यदि अयाय बातों के साथ अपेक्षाकृत निधन वर्गों की स्थिति में निरंतर उत्तरोत्तर सुधार हुआ होता जिससे उनके पास उनके जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकाधिक सुविधा तथा अवकाश प्राप्त होता तो यह नमक कर इतना अधिक दुःखद न होता।<sup>192</sup> 1888 में इलाहाबाद कांग्रेस में नमक कर प्रस्ताव को पेश करने वाले एन० वी० ब्रूकेन अपनी मान्यता को सचित्र रूप में प्रस्तुत करते हुए लिखा इस देश में लाख लाख ऐसे लोग हैं कि जिनके लिए इन अनिरीक्षित आठ आने का अर्थ है वर्ष में आठ दिन बिना भोजन किए व्यतीत

करना और विधेयत उन लोगों के लिए जिन्हें पहले ही 24 घंटों में कठिनाताएँ एक मिनट का पाना मिल पाता है।<sup>192</sup> कुछ राष्ट्रवादियों ने तो नमक कर के परिमाण का गणित रूप में सगणना करने इम तब का बट्ट-बट्ट कर समर्थन देना चाहा। उदाहरणार्थ, 1890 में प्रिंसल केनडी ने सगणना की कि पाँच व्यक्तियों के परिवार की पाँच रुपये प्रति मास की आय पर नमक कर 6 पैसे प्रति रुपये की दर से पड़ता था जबकि निम्न स्तर पर आय कर की दर चार पैसे प्रति रुपये प्रति व्यक्ति पड़ती थी।<sup>193</sup> इसी प्रकार डी० ई० वाचा ने उम्मीद सगणना की कि यदि प्रति व्यक्ति आय को 2 पौंड भी मान लिया जाए तो नमक कर प्रति व्यक्ति आय का 1 प्रतिशत था।<sup>194</sup>

राष्ट्रवादियों के नमक कर विरोध का प्रधान आधार उसका दापपूर्ण स्वल्प था जिसका उद्भव इम तब्य से हुआ था कि यह कर देश के निधनों में अत्यन्त निधना को, जो न तो किसी प्रकार के कर का भुगतान करे म समर्थ के और न ही कितरी आय कठिनाता में भी तन और प्राण एक साथ रख पान में समर्थ थी, बहुता की ता आय जीवन निवाह के ही उपयुक्त नहीं थी,<sup>195</sup> अत्यन्त भारीपन, दबाव तथा क्रूरतापूर्वक प्रभावित करता था।<sup>196</sup> यही मुख्य कारण था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बार बार इस टैक्स में बड़ोतरी का विरोध किया। इस सदन में थोड़े में भारतीय नेताओं ने राजस्व की असमानता और नमक कर की प्रतिगामी प्रकृति का भी उल्लेख किया। 1871 में इसी प्रमुख आधार पर दादाभाई नौरोजी ने नमक कर के विरुद्ध आपत्ति की। 'सिलेक्ट कमेटी आन ईस्ट इंडिया फाइनांस' का प्रस्तुत अपना प्रतिवेदन में दादाभाई ने निर्देश किया कि नमक कर के भार का परिमाण जितना अधिक गरीबों पर पड़ता था, अन्य धार्मिक वर्गों द्वारा भुगतान किए जाने वाले राजस्व के भाग का परिमाण उनका अधिक नहीं था। निधन कुनिया, श्रमिका और किसानों पर नमक कर का भार उनकी साधारण 20 गिलिंग वार्षिक आय का चार प्रतिशत था, यह बताने के उपरान्त उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा 'बीस गिलिंग प्रतिवर्ष बसाने वाले निधन व्यक्ति के लिए चार प्रतिशत कर भी अपेक्षाकृत धनी वर्गों की आय पर दस अथवा बीस प्रतिशत कर की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है।'<sup>197</sup> इसी प्रकार 1880 में 'जरनल आफ पूना सावजनिक सभा प्रकाशित 'फाइनांस आफ इंडिया अंडर लाड लिटन' के अज्ञाननामा लेखक ने लिखा यह कर अपने परिमाण में धनिता और निधनों को समान रूप से प्रभावित करता है किन्तु उनके साधनों के अनुरूप उन्हें प्रभावित नहीं करता। यही एक प्रबलतम कारण है कि इसे बराबर नीची दर पर ही रखा जाए जिसमें यह निधन जनता के लिए दुपद सिद्ध न हो।<sup>198</sup> इसी प्रकार की भावनाएँ अन्य नेताओं ने भी प्रकट की।<sup>199</sup> हा जी० धी० जोशी ने अवश्य ही इस दृष्टिकोण को 1886 में अत्यन्त स्पष्टता तथा निव्याजता के साथ अपने लेख में प्रस्तुत किया। उनका तर्क था कि रूप के भुगतान में समानता एक प्रकार की भूठी समानता है। यह सच्ची समानता अर्थात् 'बलिदान की समानता' नहीं है।<sup>200</sup> दो वर्षों के उपरान्त 1888 में उन्होंने यह दिखाने का प्रयत्न किया कि नमक कर में बढि लोक बरा के निधनों और धनिकों में वितरण की विषमता को और गहरा करती है।<sup>201</sup>

भारतीय नेताओं द्वारा अपनाई गई दूसरी कसौटी नमक कर का नमक की खपत पर





भूमा मरते निधना का रान चूसन वाली कर पद्धति, वित्तनी ही महत्वपूर्व आवश्यकता से प्रेरित क्या न हो, मक्या निदनीय तथा स्पष्टतया तिरस्करणीय है। का भी राजस्व वानून, राजनीति अथव्यवस्था का योर्द भी सिद्धात इग प्रवार का दूर कर पद्धति लागू करने की म्वीगति गही देता। वित्तनी ही बढी अपरिहाय आवश्यकता क्या न हा ? राजस्व मकधी सबटवाली स्थिति वित्तनी ही विपम और अमह्य क्यों न हा ? जनमाधारण के कष्टा की इग प्रवार की निमम उपगा को वित्ती भी रूप म यायाचित नही टाराया जा सनना।

इस कथन के उपगत आरोप और निरागा ने पूण लेखक ने अपना अतिम निणय दत हुए लिगा परतु दुग ता यह है कि हमारा वित्तीय प्रशासन सामान्य मानवीयता की दुवलता से परिचित ही नहीं, उमे मकधील दरिद्रता म विसी प्रवार ती महानुभूति ही नहीं।<sup>9</sup>

1868 के उपरात नमक कर विराधी आदालन म महत्वपूर्ण भूमिा निभाा वान दूसर प्रमुख नेता थे गाफानकृष्ण गागन। उन्हाने जोशी का अनुकरण ही नहीं किया प्रत्युत गभी महत्वपूर्ण स्थितिया म उहाने जोशी द्वारा प्रस्तुत तर्कों के साथ साथ उनके ही द्वारा उदधृत साख्यिकी सगणनाआ का टाहराया। इस णिा मे उनना महत्वपूर्ण यागदान यह था कि उहान जोशी के काय का लानप्रिय बनाया।<sup>10</sup>

नमक कर के विरुद्ध राष्ट्रवाणिया का दूसरा आरोप यह था कि इममे नमक जसी आवश्यक उपभोग्य वस्तु की पर्याप्त मात्रा म अनुपलब्धि के कारण पनुआ और भूमि का नमक से वचित करके वृषि का हानि पहुंचान ती प्रवृत्ति निहित थी।<sup>11</sup> इसके अतिरिक्त जी० बी० जोशी और गोपालकृष्ण गासते न नमक कर की इस रूप म भी निदा की कि नमक उद्योग पर कर एक औद्योगिक कर था कयाकि इसके परिणामस्वरूप एकाधिकार पद्धति को बढावा मिलता था अत इमस भारत की विशेषतया आवश्यक और सशक्त आर्थिक प्रगति बुरी तरह से प्रभावित होती थी।<sup>1</sup> इसके साथ ही साथ उहाने यह भी आरोप लगाया कि नमक कर लगान के फनस्वरूप अस्तित्व मे आने वाले वतिपय विभिन्न तत्व जैम कि नमक पर सरकार का एकाधिकार, विभिन्न प्रातो मे नमक कर का समा नीकरण और कर की ऊची दरें आदि भारत के विभिन्न प्राता मे विन्नेपतया बगाल म एक फनत फूलते स्थानीय उद्योग को प्रतिबाधित और विनष्ट करने म तथा स्वदेशी उत्पादन को बाजार से निकाल फेंकने म उत्तरदायी सिद्ध हुए हैं।<sup>12</sup> जी० बी० जोशी न तो इम सीमा तक आरोप लगाया कि बगान मे उद्योगो का सामूहिक ह्रास सभी देशी उद्योगो को विदेशियो का हस्तांतरित करने की कर नीति की एक चातुरीपूर्ण रणनीति है।<sup>14</sup> उहाने यह आशका भी प्रकट की कि एकाधिकार की मध्यवर्ती स्थिति अपनाए बिना ही कपटपूर्ण ढग म बगाल की ही घातक नीति बबई मे भी अपनाई जाने लगी है।<sup>15</sup>

कराधान के वैकल्पिक साधन

बहुत मार भारतीय नेताआ ने धीमे स्वर मे या खुले रूप म यह अभिस्वीकार किया कि बजट के घाटे ने सचमुच ही सरकार को इतनी ऊची दर पर नमक कर बनाए रखने के



यदि परम श्रेष्ठ वायसराय महोदय माचेस्टर में जाने वाले मूती सामान पर आयात कर लगाने का निश्चय करते तो इससे माचेस्टर के व्यापारियों में व्यावृत्तता फल जाती क्या कपानु ब्रिटिश सरकार ससद के चुनाव के समय उपयोगी महायना देने वाला के प्रति कृतघ्न हो सकती थी? यदि आय कर में वृद्धि की जाती तो उमरा भारत अधिकांशतया उच्च यूरोपीय अधिभारिया और यूरोपीय व्यापारिया पर पड़ता। विनिमय की दर पहले से ही ऊंची होने के कारण यह भार उनकी कमर तोड़ने वाला होता और इससे व विद्रोह के लिए उठ गये होते। क्या लाड डफरिन जसा समझदार व्यक्ति इस प्रकार के विराधी तत्वा को उभार कर अपन उखन नाम को कलङ्गित करेगा? संक्षेप में लाड डफरिन ने इन दोनों विकल्पा को अस्वीकार कर तथा नमक कर में वृद्धि व अवशिष्ट उपाय को अपना कर अपनी प्रतिभा का ही परिचय दिया है। लाड डफरिन का यह भली भाँति बात है कि भारत की निहत्थी और कफादार जनता जब तक भी बँठ जीवित है, किसी माग के प्रति इनकार के स्वर का उच्चारण नहीं करगी। भारतीयों का सगठनात्मक रूप में सुगठन होने की भी तो आवश्यकता नहीं क्योंकि सरकार ने कपापूर्वक उनकी सुरक्षा का दायित्व लिया हुआ है।<sup>5</sup>

इसी प्रकार इंडियन स्पेक्टेटर' ने अपने 22 जनवरी 1888 के अंक में लिखा अथवा वदाचित्त सरकार लोकमत से भयभीत है क्योंकि यह निश्चित है कि धार्मिक वर्गों पर लगे करों में किसी प्रकार की वृद्धि के परिणामस्वरूप पचीस करोड़ लोगों के प्रतिनिधियों के विरोध के रूप में सरकार का बुरा समय देखना पड़ता, जबकि बीस करोड़ लोगों के मुँह में जवान ही नहीं जिससे नमक कर में वृद्धि के विरुद्ध उनके द्वारा किए जाने वाले किसी प्रकार के विरोध की संभावना हो। सरकार की श्राय भावना के प्रति कुछ न कहा जा जाए, इतना तो निश्चित है कि भारत सरकार इस पीढ़ी में काफी समझदार है।<sup>6</sup>

22 जनवरी 1888 के 'मराठा' 25 जनवरी 1888 के 'हिंदू', 26 जनवरी 1888 के अमल ग्राजार पत्रिका, 28 जनवरी 1888 के 'बंगाली' ने तथा 4 फरवरी 1888 के 'सतीवनी' ने इसी स्वर में अपना मत प्रकट किया।<sup>7</sup> जी० बी० जोशी ने इस विषय में सरकार की श्रायवाही के पीछे निहित कारणों का समान भावना से उल्लेख किया।<sup>8</sup> 18 मार्च 1888 के मराठा ने तो यहाँ तक दावा किया कि नमक कर सजुडा विचारणीय प्रश्न वस्तुतः यह है कि भारत देश भारतीयों के लिए है अथवा जौरी के लिए?<sup>9</sup>

### राजनीतिक सीख

वृद्धत मार राष्ट्रवादी समीक्षकों ने विधान परिषद के दो नामजद सदस्यों, प्यार मोहन मुखर्जी और दिनशा पेटिट के 1888 में नमक कर में वृद्धि को समर्थन देने के व्यवहार की तीव्र भत्सना की।<sup>10</sup> उन्होंने इसे राष्ट्रवादियों की इस धारणा के प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया कि वर्तमान विधान परिषदें भारतीय लोकमत को त सही रूप में प्रतिबिंबित करती हैं और न कर सकती हैं और न ही यह देश के जनसाधारण के हितों की रक्षा कर सकती

हैं। अतः इन विधानपरिपदों में लोकप्रिय तत्वा को सम्मिलित करके इनका सुधार करना चाहिए।<sup>30</sup> इस निष्कर्ष का जी० वी० जोशी न जचला ममयन दिया। उन्होंने टिप्पणी करते हुए लिखा कि 'नमक कर में वृद्धि सबसे चर्चा विधान परिपद के लिए अपमानजनक है। और देशी सदस्यों के लिए तो यह और भी अधिक अपमानजनक है। इस मसल पर बढ़कर तो व्यवस्था के लिए ही यह सर्वाधिक अपमानजनक है।' "इसी प्रकार कांग्रेस के 1890 के अधिवेशन में मदनमोहन मालवीय ने कहा 'हम इस बात पर सतोप कर देंगे कि विधान परिपद में कोई गैरसरकारी सदस्य न हो परंतु हमारे लिए इस बात पर सतोप करना संभव नहीं कि ऐसे लोग गैरसरकारी सदस्य हैं जिनका जनता के साथ किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं जो जनता की वास्तविक स्थिति में सवधा अनजान हैं तथा जनता के प्रति अनिवार्यतया वाञ्छनीय महानुभूति न दिखाकर उनके प्रति विश्वासघात करते हैं।' उन्होंने पी० एम० मुर्जो और दिनशा पट्टि को निजी आय का उपभोग करने वाले और ऊँचे वेतन पानेवाले अत्यंत सम्मानीय मज्जन बनाते हुए आलंकारिक भाषा में पूछा 'मज्जना, क्या आपको विश्वास है कि विधानपरिपद के चुनाव में यदि जनता के मत के लिए कोई अवकाश हो तो क्या जनता इन लोगों का सदस्य के रूप में भी कभी चुनेगी?' शानाआ की आर से नहीं नहीं कभी नहीं की तुमुल ध्वनि के मध्य उन्होंने पुनः पूछा कि और यदि किसी भी प्रकार की गलती से ये लोग एक बार विधानपरिपद के सदस्य नियुक्त हो भी गए तो क्या अगले चुनाव में उन्हें अपमान और घणा के साथ ठूकरा नहीं दिया जाएगा।<sup>32</sup>

### निष्कर्ष

नमक कर के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने नमक कर में कटौती और उस कर को समाप्त करने की मांग का राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय नीति के रूप में ही अपनाया था। वस्तुतः इस मांग का नेताओं ने चालू वित्त नीति की निंदा और उसकी व्यावहारिकता के आगे प्रश्नचिह्न लगाने के लिए उपयोग किया। इसके साथ ही साथ इस मामले में राष्ट्रवादी नेताओं ने देश की निधन जनता के हितों का सही रूप में और तत्परतापूर्वक अभिव्यक्ति दी और इसके द्वारा उठाने उभरते हुए राष्ट्रीय आंदोलन में निधन जनता का साथ लेकर चलने का प्रयास किया। वस्तुतः इस प्रयास में निधनों का साथ लेकर चलने के तथ्य को भारतीय नेताओं ने अत्यंत स्पष्टतापूर्वक समझ लिया था। 1890 में राष्ट्रीय कांग्रेस के छठे अधिवेशन में नमक कर में कटौती की मांग के प्रस्ताव को पार करत हुए प्रिंगले बेनेडी ने प्रतिनिधियों का निम्नलिखित अवतरण में इस प्रकार सलाह किया

प्रतिनिधि मित्रा ! क्या आप उन लोगों के बयान का जो आप पर यह शपथ लगाते हैं कि आपका मामला निजी स्वाध में प्ररित है और आपका आन्दोलन मात्र कृष्ण वण के 'मुद्रो की गौर वण के धाह्यणा के प्रति घणा का अगरेजा के प्रति घणा के रूप में परिवर्तित करने के अनिरिक्त और कुछ भी नत्ता यह कहकर गलत मिद कर गवों कि यदि गुलामी का यह जुआ और सिमी रूप में कम दुसरापी नती बनाया जा

सकता तो हम पूर ही कर लगाइए, धनिया पर कर लगाइए परतु कृपा करवे निधना को तो क्षमा कर दीजिए ।<sup>33</sup>

इसी प्रकार 1892 में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि जी० एस० खपटे ने नमक कर पर प्रस्ताव को दरिद्र नारायण की कांग्रेस से विनय के रूप में वर्णित किया ।<sup>34</sup>

इसके विपरीत राष्ट्रीय नेताओं ने इस मामले में देश के धनिया के हितों की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं की अथवा धनिया वर्गों के प्रवक्ता के रूप में वे भी इसी विद्वान स कि इससे धनिया पर लगे आय कर जैम जयाय करा की समाप्ति में सहायता मिलगी नमक कर को बनाए रखने तथा उसमें वृद्धि करने का समय ही करते ।<sup>35</sup> राष्ट्रवादियों की स्थिति और धनिया वर्गों के हितों के बीच अंतर को स्पष्ट रूप में तभी देखा जा सकता है यदि जमींदारों, बड़े बड़े व्यापारियों और गैरसरकारी अगरेजों के समकालीन प्रवक्ताओं द्वारा अपनाए गए और सावजनिक रूप से अभिव्यक्त कर समर्थक दृष्टिकोण के सदर्भ में राष्ट्रवादी नेताओं के दृष्टिकोण का देखा जाए । 1882 में कलकत्ता के व्यापारियों के प्रवक्ता दुगाचरण लाहा ने इपीरियल विधानपरिषद में नमक कर में कटौती की विचाराधीन नीति को भावनात्मक बताकर इसका विरोध किया । उन्होंने सुभाव दिया कि इससे अच्छा तो यह होता कि इसके बदले सरकार देश की परिस्थितियों के अनुकूल न बैठने वाले प्रत्यक्ष करों को हटा ही देती ।<sup>36</sup> विधानपरिषद में बंगाल के जमींदारों के प्रतिनिधि महाराजा जीतेंद्र माहन टैगोर ने लाहा के मत का पूरा पूरा समर्थन किया ।<sup>37</sup> इसी प्रकार बंगाल के जमींदारों के एक अन्य प्रवक्ता प्यारेमोहन मुक्जी न बर्द के व्यापारियों के प्रवक्ता दिनशा पेटिट तथा भारत में रहने वाले ब्रिटिश सरकारी कर्मचारियों और व्यापारियों के अनेक प्रवक्ताओं ने 1888 में नमक कर में की गई वृद्धि का पूरा पूरा समर्थन किया ।<sup>38</sup> 1887 के बंगाल राष्ट्रीय याणिज्य सदन की समिति के प्रतिवेदन में यह दावा किया गया कि जाय कर की वर्तमान दर को दुगना करने की अपेक्षा नमक कर में वृद्धि कम जापत्तिजनक थी ।<sup>39</sup> सदन के 1889 के अध्यक्ष और सचिव ने तो पूरी शक्ति और दृष्टता के साथ नमक कर में किसी प्रकार की कटौती का विरोध किया ।<sup>40</sup>

### उत्पाद राजस्व

राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत तथा एक अर्थ परीक्षक कर उत्पादना पर उत्पादन शुल्क के रूप में तथा मालक द्रव्या शराव, भाग घतूरा और अफीम, बेचने के लिए लाइसेंस फीस के रूप में लगाया गया करता था । इस सार्धन स होने वाली कुल आय 1860-1 में 1 18 करोड़ रुपये से 1880 01 में 3 19 करोड़ तथा 1902 03 में 6 64 करोड़ रुपये हो गई ।<sup>41</sup> हमने यहां देशी अथवा कच्ची शराव से प्राप्त होने वाले राजस्व के उभर पक्ष विशेष का ही यहां विवेचन प्रस्तुत किया है जो इस मद स होने वाली आय का प्रमुख भाग था ।<sup>42</sup> देशी शराव पर शुल्क पद्धति दश के भिन्न भिन्न कालों में है । इन पद्धतियों का माटे तीर पर परस्पर दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है (1) केंद्रीय शराव कारखाना पद्धति इसके अंतगत उत्पादित तथा बिन्नी के लिए अनुनप्त प्रत्यक्ष गलन

शराब पर एक निश्चित शुल्क लगाया जाता था, (2) ठेका बिक्री पद्धति, इसके अतगत उत्पादित मात्रा पर शुल्क न लगाकर कुल उत्पादन पर शुल्क लगाया जाता था और उसका भुगतान एक मुश्त नीलामी के आधार पर किया जाता था। स्पष्ट है केंद्रीय पद्धति की अपेक्षा ठेका बिक्री पद्धति में शराब की खपत पर सरकारी नियंत्रण का अवकाश काफी कम था।<sup>43</sup> 1890 के वर्षों में शराब की 'यूनतम खपत से अधिकतम राजस्व की उगाही भारत सरकार की एक नीति थी। इसका अर्थ था शुल्क को दर का बढ़ाना तथा शराब की बिक्री के स्थानों को इस सीमा तक प्रतिबन्धित करना कि उसकी खपत 'यूनतम हो जाए। इसके साथ ही साथ गैरकानूनी शराब के उत्पादन को भी सीमित कर दिया गया।<sup>44</sup> कम से कम 1890 के पश्चात् तो क्रमशः नीलामी पद्धति को हटाते जाना और केंद्रीय शराब कारखाना पद्धति का विस्तार करना सरकार की निश्चित निर्धारित और और घोषित नीति बन गई।'<sup>4</sup>

भारतीय नेताओं ने मादक द्रव्यों की खपत और उन पर कराधान के प्रश्न को बहुत अधिक महत्व दिया। भारतीय नता कुल मिलानर मदिरा के प्रयोग के विरुद्ध थे और देश में मदिरापान की प्रवृत्ति के प्रसार के विरोधी थे। उनके विचार में मदिरापान की प्रवृत्ति एक घातक दोष तथा भयंकर उत्पात था जो नैतिकता को घबसा करे वाला एक प्रकार का पापमय कृत्य था, आर्थिक दृष्टि से देश को दरिद्र और शारीरिक दृष्टि से दुर्बल बनाने वाला था।<sup>45</sup> कुछ नेताओं का तो यहाँ तक विश्वास था कि मदिरापान की प्रवृत्ति के विकास से श्रमिकों की कार्यक्षमता घट जाने में औद्योगिक प्रगति दुष्प्रभावित होगी।<sup>47</sup>

मदिरा की खपत में वृद्धि की निंदा करते समय भारतीय नेताओं ने यहाँ एक बार फिर 'पहली खपत सरकार के मुँह पर मारी। उन्होंने सरकार पर यह आरोप लगाया कि वह और उसकी आधिकारी नीति ही मदिरापान की प्रवृत्ति के प्रसार के लिए पूरी तरह उत्तरदायी थी। उन्होंने अधिकतम उत्पादन शुल्क की बसूली के लिए जानबूझकर अथवा अनजाने मदिरापान की प्रवृत्ति का प्रोत्साहित करने के लिए अथवा तत्परता के साथ उसे निरत्साहित करने में असफल रहने के लिए सरकार की तीव्र भत्सना की।"<sup>48</sup> 1880 के वर्षों में बंगाल में तो सरकारी उत्पादन शुल्क नीति की आलाचना अत्यन्त उग्र तथा निरन्तर थी क्योंकि वहाँ उस प्रांत में ठेका पद्धति प्रचलित थी जिस पर मदिरा को सस्ता करने का आरोप लगाया जा रहा था।<sup>49</sup>

भारतीय नेताओं ने यह भी दोष लगाया कि एक ओर तो सरकार सांख्यिक रूप से तथा सिद्धांत रूप से मदिरापान की प्रवृत्ति को निरत्साहित करने का दावा करती है परन्तु दूसरी ओर व्यावहारिक रूप में उसकी नीति का प्रभाव सवथा विपरीत रूप में पड़ रहा है।<sup>50</sup> प्रशासन द्वारा उत्पादन शुल्क की बसूली में वृद्धि करने वाले सरकारी अधिकारियों की मुक्तकंठ से प्रशंसा करने, उन्हें उन्नति देने तथा इस बसूली में वृद्धि न कर पाने वाले अधिकारियों की निंदा करने की नीति अपनाने का वास्तविक परिणाम यह दरतन में आया है कि सरकारी कमचारी मदिरा की खपत का बढ़ाकर उत्पादन शुल्क की बसूली में वृद्धि करने के प्रति और उत्साही बन गए हैं।<sup>51</sup> यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस

विषय में सरकारी पक्ष के प्रवक्ता भी राष्ट्रवादियों के आरोप का प्रत्याहार करने में तथा उत्पादन राजस्व में वृद्धि का कारण उत्पादन गुल्म की ऊँची दर और उस पर अपक्षाकृत अधिक नियंत्रण को मिट्टी करने में कम उत्साही तथा कम तत्पर थे। यह पर्याप्त रोचक तथ्य है कि कुछ एक अर्थात् मदरों में सरकारी अधिकारियों ने परोक्ष रूप में मदिरा की खपत में वृद्धि का स्वीकारता किया परन्तु इस सरकार ने जनता की बढ़ती संपन्नता के संकेत के रूप में ही प्रस्तुत किया।<sup>53</sup> राष्ट्रवादों ने नतीजा न प्रश्न के समग्र रूप में अनुरूप ही सरकारी मामला का सदन किया और उसके विपरीत यह धारणा प्रस्तुत की कि मदिरापान न पियकरडों और उनके परिवारों में दुभाग्य, विनाश और दरिद्रता का आधिपत्य स्थापित कर दिया है।<sup>54</sup>

राष्ट्रवादी नेताओं का इस तथ्य के प्रति निश्चित मत था कि मदिरापान के व्यसन के विरुद्ध संघर्ष करने में शिक्षा एक अत्यंत मद प्रभाववाला शस्त्र था। इस व्यसन के प्रसार का तत्काल कम करने के लिए प्रशासकीय उपाय ही उपयोगी सिद्ध हो सकते थे।<sup>55</sup> अतः उन्होंने मदिरापान के विरुद्ध लाकप्रिय आंदोलन छेड़ने की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपना सारा ध्यान और सारे प्रयास सरकार से जनता के नैतिक व्यवहार की श्रेष्ठता के आदर्श के समक्ष राजस्व के दृष्टिकोण को गौण बनाने और इस प्रकार मदिरापान की प्रवृत्ति को निरस्तारहित करने की नीति को अपनाने के लिए अनुरोध और विवश करने पर ही केंद्रित किया।<sup>56</sup> उन नेताओं द्वारा सुझाए गए लगभग सभी प्रशासकीय उपायों का उद्देश्य मधुशालाओं और मदिरा बित्री की दुकानों की संख्या घटा कर मदिरा की महंगा और मदिरा की प्राप्ति को दुर्लभ तथा कष्टसाध्य बनाना था। नतीजा द्वारा प्रचारित उपायों में जिस उपाय को सर्वाधिक व्यापक लोकप्रियता मिली, वह था स्थानीय लोकमत। उन्होंने मांग की कि किसी भी स्थान पर नई मदिराशाला अथवा नई मदिरा बित्री दुकान को खोलने के प्रश्न को निणय के लिए प्रत्यक्ष रूप से अथवा स्थानीय नगरपालिका जैसी संस्थाओं के माध्यम से अभिव्यक्त लोकमत को निर्णायक तत्व के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए।<sup>57</sup> एक अर्थात् लोकप्रिय मांग जो अधिकांशतः बंगाल तक ही सीमित रह गई वह थी ठेका प्रथा की समाप्ति।<sup>58</sup> जब 1889-90 की अवधि में बंगाल के अधिकांश भागों में ठेका पद्धति समाप्त कर दी गई, स्वयं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया।<sup>59</sup> राष्ट्रवादियों ने मदिरा पर आयात कर और उत्पादन शुल्क बढ़ाने का समर्थन किया।<sup>60</sup> कुछ ने तो सरकार से मदिरा बित्री केंद्र बंद करने, मदिरा की परचून बित्री की दुकानों को लाइसेंस देने में कठोरता बरतने जैसे विगुद्ध प्रशासनिक पग उठाने का अनुरोध किया।<sup>61</sup> यह भी कम आश्चर्यजनक नहीं कि राष्ट्रवादी नेताओं में इन सभी उपायों की कबालत करते हुए नशाबंदी को कोई विशेष महत्त्व नहीं दिया। संभवतः उनके विचार में यह उपाय व्यावहारिकता तथा संभावना के क्षेत्र में बाहर था।<sup>6</sup>

मदिरा से संबद्ध उत्पादन गुल्म से प्राप्त होने वाले राजस्व के प्रति राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण से उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका दृष्टिकोण और उसके पीछे प्रेरणा विगुद्ध राष्ट्रीय ही थी। भले ही मदिरा उत्पादन गुल्म राजस्व का एक

फलता फूलता साधन था और इसका भुगतान केवल मदिरा के वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा ही किया जाना था जिससे देश की सामान्य जनता पर अतिरिक्त कर लगाने की आवश्यकता नहीं थी फिर भी राष्ट्रवादी नेताओं ने सर्वसाधारण की हितकामना की दृष्टि से इसे देखा और इस रूप में उसकी निंदा करने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं किया। इस संबंध में राष्ट्रवादियों की नीति के इस पक्ष को एक और दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। मदिरा को अपेक्षाकृत अधिक महंगा करने की राष्ट्रीय नीति अपनाएँ पर एक ओर मदिरा का सेवन करने वाले भारतीय नेताओं का भी घाटे में रहना स्पष्ट था, दूसरी ओर मदिरा की पूर्ति में बटौती का स्वाभाविक परिणाम उत्पादन शुल्क में ह्रास था और यह मदिरापान न करने वालों के हित के सर्वथा विरुद्ध था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस मामले में वित्तीय विषयों में भी भारतीय राष्ट्रवादियों ने निःस्वायत्तरता और परोपकारिता का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया।

विचाराधीन प्रश्न से संबंधित का अर्थ तत्त्व भी यहाँ उल्लेखनीय है, प्रथम, कालांतर में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में एक प्रबल राजनीतिक शस्त्र के रूप में प्रयुक्त मदिरा विरोधी मधुप के इस रूप में प्रयोग करने की प्रवृत्ति का इस समय तक अभाव था। उच्च भारतीय नेताओं में यह भावना अवश्य उभरने लगी थी कि मदिरा विरोधी आंदोलन का जनता का राजनीतिक कार्यों का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। 17 अप्रैल 1905 में एंग्लो इंडियन टेंपरेंस एसोसिएशन के अधिवेशन में बोलत हुए दादाभाई नौरोजी ने कहा

भारत में इन लोगों की संख्या की 300 लाखों थी और इसका अर्थ था कि नीचे से ऊपर तक के सभी वर्गों, धर्मों और स्थितियों के लोग परस्पर संगठित होने, एक दूसरे के प्रति भ्रातृभाव अपनाने तथा एक महान उद्देश्य के लिए कार्य करने का पाठ सीख रहे थे। यह संस्था भारत में मदिरापान के व्यसन को निम्न करने के लिए ही प्रयास शुरू करने नहीं जा रही थी, प्रत्युत समान रूप से ही महत्वपूर्ण परस्पर संगठित होने के उच्च विचारों को अपनाने के लिए भी जनसाधारण को प्रशिक्षित करने जा रही थी। यह सच प्रवृत्ति इन लोगों के लिए सचमुच अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।<sup>63</sup>

द्वितीय, विदेशी सरकार के मदिरापान के प्रसार के लिए दापी घोषित करने की प्रवृत्ति ने भारतीय उत्पादन शुल्क नीति को एक राष्ट्रीय रंग दिया।

अफीम में प्राप्त होने वाला राजस्व

अफीम भारत सरकार के राजस्व का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत था। 1884 तक यह बजट की द्वितीय और 1884 के उपरांत तृतीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण और लाभप्रद मद थी। इसकी वसूली में वष प्रतिवष बड़े ही भयंकर रूप से उतार चढ़ाव आता रहता था और इसके फलस्वरूप भारतीय वित्त को निश्चित रकम की वसूली में सदैव अस्थिरता और अनिश्चितता रहती थी। उदाहरणार्थ, 1880-81 में अफीम से प्राप्त होने वाली विगुद्ध रकम 8.45 करोड़ थी, 1890-91 में 5.70 करोड़ और 1900-91 में 4.97 करोड़ थी



जबकि 1897-8 में यह 2 70 करोड़ की निम्न सीमा को पार कर गई।<sup>64</sup> अफीम राजस्व की वसूली बंगाल अफीम के निर्यात से जिसका उत्पादन बंगाल सरकार के अधिकार के अंतर्गत विहार, उत्तर-पश्चिम प्रांत और अवध के राज्य एकाधिकार व्यवस्था के अंतर्गत होता था तथा बंबई में मालवा अफीम पर भारी निर्यात शुल्क के समूह से होती थी। निर्यातित अफीम का अधिकांश चीन को भेजा जाता था और उसका एक भाग उत्पादन और राजस्व पद्धति के अंतर्गत भारत में बेचा जाता था जिसकी वित्री से प्राप्त आय उत्पादन कर के खाते में जमा की जाती थी। अफीम से प्राप्त होने वाला उत्पादन शुल्क 1870-1871 में 36 लाख था जो धीरे-धीरे बढ़कर 1900-01 में 103 लाख हो गया।<sup>65</sup>

सारी 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और अनेकानेक लोक मस्थाओं ने नैतिकता और मानवीयता के आधारों पर चीन के साथ ब्रिटेन के अफीम के व्यापार की कटु आलोचना की। 1888 में अफीम व्यापार निरोध संधि (सोसाइटी फॉर दि संप्रेशन ऑफ दि ओपियम ट्रेड) की स्थापना के रूप में अफीम व्यापार के, सरकार द्वारा उसे दिए जा रहे संरक्षण के तथा उसके अनयन के विरुद्ध एक सुनियोजित आंदोलन प्रारंभ हुआ।<sup>66</sup> इस आंदोलन के फलस्वरूप 10 अप्रैल 1891 को हाउस ऑफ कॉमंस ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें इस बात को दृढ़तापूर्वक स्वीकार किया गया कि भारत में अफीम से वसूल किया जाने वाला लगान अनैतिक था। इसके साथ ही भारत सरकार पर दबाव डाला गया था कि उचित रूप में औपनिवेशिक रूप में प्रयोग में आने वाली मादक का छोड़ कर उसे पोस्त की खेती और अफीम की वित्री के लिए लाइसेंस देना बंद कर देना चाहिए। 1893 में इस प्रश्न को उसके समग्र रूप में देखने और उसकी छानबीन करने के लिए एक राजकीय आयोग (रायल कमीशन) नियुक्त किया गया। कमीशन ने 1895 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और यथास्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न करने की मलाहट दी।<sup>67</sup> इन सभी वर्षों में भारत सरकार ने अफीम के व्यापार का निषिद्ध और प्रतिबंधित करने के किसी भी प्रस्ताव का तीव्र प्रतिवाद किया। भारत सरकार का प्रमुख तर्क यह था कि इस प्रकार के पगों से वित्तीय तथा राजनीतिक स्थितियों के दुष्प्रभावित होने की आशंका थी।<sup>68</sup>

अफीम व्यापार और उससे प्राप्त हान वाले राजस्व के प्रति भारतीय नेताओं के दृष्टिकोण का अध्ययन रोचक है। उनके सामने एक ऐसी स्थिति आ गई थी जहां उन्हें दो बातों में से एक का चुनाव करना था प्रथम, अपना राष्ट्रीय हित, जो अनेक अर्थ मामलों में उनका पक्ष प्रदर्शक तत्व बना रहा था, द्वितीय मानवीयता और परांपकार की भावना, जिसके आधार पर वे प्रायः ब्रिटिश सरकार से आर्थिक तथा राजनीतिक रियायतें देने के लिए निवेदन करते आ रहे थे।

अफीम कर के नैतिक पक्ष के संबंध में अधिकांश राष्ट्रीय नेताओं ने सरकारी स्थिति के प्रतिकूल पक्ष ही ग्रहण किया। उनका यह पक्ष इस लगान के विरोधी आलाचक्र अंगरेजों की स्थिति के ही अधिक निकट था क्योंकि इन नेताओं ने खुद तौर पर घोषित किया कि अफीम का व्यापार और उससे उगाया जान वाला कर दाना सबका अनैतिक हान के कारण अत्यंत निंदनीय थे। 1870 में ही केशवचंद्र सेन ने हजारों दरिद्र चीनियों के हत्याने

अयायपूर्ण अफीम व्यापार को हटाने की माग की।<sup>69</sup> 1880 म दादाभाई नौरोजी ने बड़े शोभपूर्ण स्वर म घोषणा की कि अफीम व्यापार इंग्लड के मस्तक पर कलक का टीका है और भारत के लिए इसमे भागीदार होना अभिशाप रूप है।<sup>70</sup> उसी तीव्र स्वर मे 7 अगस्त 1881 के अक मे 'मराठा' ने 40 करोड मानवो को विप देन के अभिशाप को भारतीय जनता के मत्थे मढने के विरुद्ध विरोध प्रकट किया।<sup>1</sup>

दादाभाई नौरोजी और रमेश चद्र दत्त अफीम से प्राप्त राजस्व की प्रवृत्ति के सबध मे सरकारी दृष्टिकोण से असहमत थे। सरकारी दृष्टिकोण यह था कि अफीम लगान का भुगतान भारतीय जनता द्वारा नहीं प्रत्युत चीनी उपभाक्ताओ द्वारा ही किया जाता है।<sup>2</sup> नौरोजी और दत्त का विपरीत मत यह था कि वस्तुत यह भारतीय जनता पर एक गुप्त कर है क्योंकि यदि अफीम व्यापार पर सरकार का एकाधिकार न हाता तो अफीम कर के रूप म सरकार को होने वाले सारे के सारे लाभ भारतीय जनता को उपलब्ध होते।<sup>3</sup>

अफीम व्यापार के प्रमुख प्रश्न अफीम व्यापार को खत्म करन पर भारतीय नेताओ मे मतभेद उत्पन हो गए। जहा अधिकाश नेताओ ने इस प्रवार का पक्ष ग्रहण किया जो भारत सरकार की नीति से बहुत कुछ मिलता जुलता था वहा उल्लेखनीय सरया म नेताओ ने मानवीय आधारो पर अफीम व्यापार को त्यागने का भी पक्ष ग्रहण किया। प्रथम पक्षवाला का तर्क था कि बोरी भावना को आधार बना कर अफीम कर की वलि चढान की बात कहना युक्तिसंगत नहीं लगता क्योंकि अफीम से प्राप्त होने वाली राशि भारतीय वित्त का एक उल्लेखनीय अंश है और उस छोडने का अर्थ होगा उसके स्थान पर जय नए कर लगाना। अत उहोने उस समय इंग्लड मे चलाए जा रहे अफीम विराधी आन्दोलन की तीव्र आलोचना की।<sup>4</sup> इस प्रवार 'अमृत बाजार पत्रिका' न अपन 9 जुलाई 1880 के अक म टिप्पणी करते हुए लिखा 'नैतिकता के दृष्टिकोण से राजस्व के इतन अच्छे स्रोत को छोडकर उसकी पूर्ति के लिए नए करा को लगाने के रूप म पहले ही निधन तथा अभावग्रस्त जनता के जीवन रक्त को निचोडना हमारी विनम्र नैतिक सम्मति म ऊचे स्तर की अनतिकता होगी।'<sup>5</sup> सधपशील साधारण ब्रह्म समाज का उच्च नैतिक मुखपत्र 'ब्राह्मण पब्लिक ओपीनियन' ने 15 जुलाई 1880 के अक मे अफीम लगान के सबध म आदश नैतिक दृष्टिकोण अपनाने के रूप मे भारतीय अव्यवस्था को अस्त व्यस्त करने के विरुद्ध चेत्तावनी दी।<sup>6</sup> यहा तक कि भारत मे सामाजिक सुधारो के लिए सतत यत्नशील तथा प्रचंड प्रवक्ता 'इंडियन स्पेक्टेटर' ने अपने 12 मार्च 1882 क अक मे इंग्लड के अफीम विरोधी आदोलन करने वालो को अच्छी भावनाओ से प्रेरित परंतु अज्ञानी कट्टर लोगो का शक्तिशाली बग बताया।<sup>7</sup> एक अय सुधारक पत्र हिंदू ने अपने 3 जुलाई 1881 के अक मे घोषणा की कि वह अफीम राजस्व का हटाने की माग का केवल इस शत पर समथन कर सकता है कि इंग्लड के कर्दाता इससे भारत सरकार को हाने वाली क्षति की पूर्ति करने का वचन दें।<sup>278</sup>

बहुत सारे भारतीय नेताओ ने अगरेजो के अफीम विरोधी प्रयास को दूसरे लोगो के मूल्य पर लोकोपकार के दभ का रूप देते हुए उस पर तीखे व्यग्य प्रहार किए। उनका सुभाव था कि यदि ब्रिटिश लोग चीनियो के कल्याण के प्रति सचमुच ही उत्सुक थे

उह अपनी सरकार पर भारत सरकार को अफीम राजस्व के खोने से होने वाली क्षति-पूर्ति के लिए दबाव डालना चाहिए।<sup>9</sup> यह भी पर्याप्त राक्षस तथ्य है कि ब्रिटेन के अफीम विरोधी आंदोलन के जिन अग्रणियों की ईमानदारी के आगे प्रदर्शित लगाया गया और जिन्हें मुख्य तथा बट्टर की उपाधियां प्रिभूषित किया गया, उनमें भारत समर्थक, राष्ट्रीय कांग्रेस के उस्ताही पथधर, समद मदम्य ड्यू एस० वेन और सैमुअल स्मिथ जैसे लोग भी सम्मिलित थे।

भारतीय नेताओं के इस बग ने अफीम व्यापार को प्रतिबंधित करने के विरोधी अपने पक्ष के समर्थन में कुछ और रोचक तथ्य भी पेश किए। प्रथम उक्त निश्चित मत था कि चीन के दोषों में सुधार के कार्य को हाथ में लेने से पहले अधिकारियों और सुधारकों का यह नैतिक दायित्व है कि वे भारत में मदिरापान के दुष्प्रसन्न के विरुद्ध संघर्ष करें क्योंकि मदिरापान अफीम फूंकने की अपथा किसी भी रूप में कम हानिप्रद नहीं था।<sup>10</sup> द्वितीय, कुछ की तो यह मायता थी कि अफीम निषेध के त्याग से संबंधित भारत सरकार का कोई भी पक्ष सवथा निष्फल सिद्ध होगा क्योंकि अभाव की खाई की पूर्ति प्रशा, तुर्की और संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा अथवा अपने देश में अफीम की खेती के विस्तार तथा अफीम के उत्पादन में वृद्धि करके स्वयं चीनिया द्वारा अत्यंत तत्परता और शीघ्रता से की जाएगी। इस प्रकार लोभित का उद्देश्य तो अपूर्ण तथा अप्राप्त ही रहगा। हा इसमें भाग्यीयों को निश्चय ही आय के एक बढ़िया स्रोत से हाथ धोना पड़ेगा।<sup>11</sup> यह आश्चर्यजनक तथा उत्सुकतावधक है कि समाचारपत्रों ने यह तक प्रस्तुत नहीं किया कि अफीम व्यापार को निषिद्ध करने से इस व्यापार में सलग्न भारतीय व्यापारी बहुत बुरी तरह प्रभावित होंगे। इसके विपरीत अफीम विरोधी पत्रिका 'सजीवनी' ने अपने 23 दिसंबर 1893 के अंक में व्यापारियों पर अफीम व्यापार के समर्थन का अभियोग लगाते हुए लिखा कि उनका ऐसा करना स्वाभाविक था क्योंकि इससे उह बहुत बड़ा लाभ जो था।<sup>12</sup> अफीम विरोधी आंदोलन के विरोधी गण्टवादियों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के पीछे व्यापारिक प्रेरणा का अभाव तथा राजस्व प्रेरणा की प्रमूता से यही सिद्ध होता है कि 'राष्ट्रवादी नेताओं' इस बग की इस नीति के निर्माण के पीछे व्यापारियों के हित की किसी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी।

मानवीयता के आधार पर अफीम उत्पादन को प्रतिबंधित और अफीम व्यापार का कानूनी रूप से निषिद्ध करने के समर्थक भारतीय नेताओं के दूसरे बग न इस कायदाही से राजस्व का होने वाली क्षति की पूर्ति व्यापारिक कटौती द्वारा करने का सुझाव दिया। इस संवध में मराठा, 'हिंदू', सोम पकाश' और 'आनंद बाजार पत्रिका' जसी बहुत सी पत्र-पत्रिकाओं की स्थिति समय विनोय पर सपादकीय लिखने वाले किसी भी महानुभाव की व्यक्तित्व प्रवृत्ति के अनुरूप परिवर्तित रूप लेने वाली और इस प्रकार अस्थिर तथा डाबा-डोत रही है। 'आनंद बाजार पत्रिका' ने अपने 20 जुलाई 1880 के अंक में राष्ट्रवादियों की अफीम विरोधी भावनाओं की बड़ी ही स्पष्टता तथा प्रचलता के साथ निम्नलिखित अवतरण में इस प्रकार में वाणी दी है

क्याकि चीन को अपनी मांग की सतुष्टि के लिए कही न कही स अफीम का आयात



हित को ध्यान में रखते हुए अफीम व्यापार को निषिद्ध करके नए करों की मभावना को आसवा प्रकट की। इस सबंध में यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार भारतीय नताओ ने 1877 से 1882 तक सीमा शुल्क का हटाने के लिए व्यापक और समुक्त विरोधी आंदोलन चलाया था, अफीम व्यापार में अपक्षाकृत अधिक विस्तृत वित्तीय सभावनाएँ निहित होने पर भी इन नेताओं ने इस व्यापार के विरुद्ध संचालित ब्रिटिश आन्दोलन के विरुद्ध उसी प्रकार के किसी व्यापक और समुक्त विरोध का आयोजन नहीं किया।<sup>1</sup> इसका विश्लेषण कदाचित इस तथ्य से हो जाता है कि अफीम राजस्व के मामले में सभावित हानि केवल वित्तीय थी, उससे किसी प्रकार से औद्योगिक हित प्रभावित नहीं होते थे जबकि बपास सीमा शुल्क से वित्तीय हानि के साथ साथ औद्योगिक हितों को हानि पहुँचती थी। अतः स्पष्टतः भारतीय नताओं का यह मतव्य था कि वित्तीय हानि के प्रति विरोध प्रकट करके उसे भले ही सहन कर लिया जाए चाहे इससे वित्त को सतोप न मिले और न ही सिद्धांतों के पालन की प्रसन्नता मिले, परंतु औद्योगिक हानि को तो किसी भी रूप में सहन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके परिणाम दूरगामी होते हैं और इससे राष्ट्रीय हितों को वास्तविक और व्यापक क्षति पहुँचती है।

## संदर्भ

- 1 इंपारियल गजेटियर ऑफ इंडिया (1908) खंड IV पृ० 165-9 वाले पूर्वोद्धृत पृ० 12-6, पृ० जे० थामस ग्रोय ऑफ फेडरल फाइनांस इन इंडिया (मद्रास 1939) पृ० 239-54
- 2 चिसनो पूर्वोद्धृत पृ० 339
- 3 कृत्वा 82
- 4 16 अगस्त 1901 हुआड (चौधरी सिरीज) खंड XCIX लगभग 1208 इसी प्रकार 1899 में कजन ने घोषणा की कि बुरी हालत में भी बजट में 4½ करोड़ लाभ की उपस्थिति यह दिखाती है कि भारतीय वित्तों में केवल सहन शक्ति ही नहीं प्रत्युत उनमें अदभूत सामर्थ्य का स्रोत भी अंतर्हित है (स्पीचेज I पृ० 76) तथा देखिए जी० हैमिल्टन हुआड (चौधरी सिरीज) 4 सितंबर 1895, खंड XXXVI लगभग 1702-05
- 5 रिप० आर्ड० एन० सी 1898 पृ० 131
- 6 एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए० पृ० 242 तथा देखिए उनकी स्पीचेज III पृ० 12 जान फ्राइट के उसी अवतरण को उद्धृत करते हुए पी० सी० राय ने 1895 में दावा किया कि फ्राइट की कसौटी पर तो भारत पर ब्रिटेन का शासन स्वतः विनिश्चित स्वतः कलंकित तथा स्वतः लाष्टिन सिद्ध होता है (पावर्टी पृ० 276-7)
- 7 वही पूर्वोद्धृत पृ० 207
- 8 वही पृ० 279-30 जानी ने इस सुभाव को भी अस्वीकार कर दिया कि भारतीय वित्तों की प्रवृत्ति धर्मों में समतुलन लाने की है अतः भारतीय वित्तों को स्वस्थ कहा जा सकता है जोशी के अनुसार यह समतुलन वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक न होकर देश की सरकार की निरकुश प्रवृत्ति

का ही सूचक है यह केवल प्रशासन की पूर शक्ति का ही प्रदर्शन है व्यावहारिक रूप से अनुत्तरदायी और स्वेच्छाकारी विभाग की विवेकहीन नीति को ताज के ध्वज निर्धारित करने की अनुमति दी जा रही है इस प्रकार से व्यवस्थित व्ययों से जनता पर कराधान का स्तर निश्चित किया जा रहा है, जिसका वस्तुतः जनता की कर भुगतान की क्षमता से किसी भी प्रकार का कोई सामान्य संबंध नहीं (वही पृ० 207)

- 9 गोखले स्पीचेज पृ० 21
- 10 वकील, पूर्वोद्धत पृ० 607-08 भारत सरकार का विशुद्ध राजस्व 1881 2 म 46-86 करोड़ रुपये और 1904-05 में 65 17 करोड़ रुपये था (इंपीरियल गजटियर आफ इंडिया, 1908 खंड IV पृ० 201)
- 11 विसनी पूर्वोद्धत पृ० 326 8 दत्त, ई० एच० II पृ० 37 43, वकील, पूर्वोद्धत पृ० 85 91 और ग्रामस पूर्वोद्धत पृ० 120
- 12 उदाहरण देखा, रिपोर्ट आफ दि इंडियन फेमिन कमीशन, 1880 खंड II पृ० 82 फाउलर हसाड (चौथी सिरीज) 15 अगस्त 1894 खंड XXVJII लगभग 1140 और स्ट्रुजी इंडिया (1903) पृ० 120-1
- 13 अध्याय 14 में लैंड रवेयू के मतगत इंडियन पोलिटिकल इकोनमी मन्थनी ग्रन्थ देखिए
- 14 आगे ओपीएम रवेयू पर अनुभाग देखिए
- 15 नीरोजी, पावर्टी पृ० 60 उन्होंने साथ में यह भी कहा 'आप इस रकम को कर राजस्व कहें अथवा अपनी रुचि का कोई अन्य नाम दें सरकार इसे विसी भी रूप में अथवा विसी भी शैली में ग्रहण करें इतना तो निश्चित है कि यह रकम सरकार के लिए देश की आय से ही ली जाती है इस तथ्य को तो नहा बदला जा सकता है भारत के संबंध में सरकार यह रकम भूमि लगान के रूप में लेती है अर्थात् कर के रूप में अथवा विसी भी अन्य रूप में इससे कोई भ्रतर नहीं पड़ता तथ्य यह है कि सरकार देश की कुल आय में से अपने लिए इतना अधिक राजस्व ले लेती है जो अन्यथा जनता के पास ही रहता (वही) उन्होंने अपने इस मत को दोहराने हुए थोड़ा समय के उपरान्त और अधिक सशक्त अभिव्यक्ति दी 'राजस्व के इस भाग को राजस्व कर किराया भ्रशदान बरदान अमिशाप अथवा भ्रगरेजी शब्दकोश की बणमाला के ए से जड़ तक अन्तर पर अन्य किसी नाम से पुकारिए सीधे सी सच्चाई तो यह है कि देश को अपनी आय से सरकार को उसने प्रयोजनों के लिए एक निश्चित भाग देना ही पड़ता है यह भाग न तो आकाश में बरसता है और न ही देश की सरकार द्वारा किसी जादू से उत्पन्न किया जाता है (वही पृ० 220) तथा देखिए, नीरोजी स्पीचेज पृ० 316 परिशिष्ट पृ० 40 और आग वाचा सी० पी० ए० पृ० 539 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 223
- 16 स्ट्रुजी इंडिया (1894) पृ० 395 तथा देखिए विसनी पूर्वोद्धत पृ० 347
- 17 ग्रन्थ स्पीचेज खंड II पृ० 452 तथा वही खंड III पृ० 146
- 18 ग्रामस पूर्वोद्धत पृ० 77 पर
- 19 नीरोजी की पावर्टी पृ० 58 पर उद्धृत 1880 के अकाल आयोग की समझना के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति पर 4 किलो का कर भार था (रिपोर्ट आफ दि इंडियन फेमिन कमीशन 1880 भाग II पृ० 93)
- 20 हमाड (चौथी सिरीज) 15 अगस्त 1894 खंड XXVIII लगभग 1140 विस ग्रामस एडवर्ड ता के अनुसार 1904 में कर भार का परिमाण केवल 1.42 प्रति व्यक्ति था (एल० सी० पी०

- 1904) खंड XLIII पृ० 534) स्ट्रेची इटिया (1903) पृ० 120 भी देखिए
- 21 देखिए पीछे अध्याय I
- 22 चिमनी पूर्वोद्धत पृ० 328 तथा पृ० 331
- 23 कजन स्पीचेज खंड III पृ० 148 तथा जी० हैमिल्टन, इंडियन डिबेट्स, 3 फरवरी 1902 लगभग 106 ला पाइनांसल स्टमट, 1903 कठिवा 35
- 24 स्ट्रेची इटिया (1903) पृ० 119 वस्टलड, एल० ती० पी० 1895 खंड XXXIV पृ० 436
- 25 उदाहरणार्थ मुर्देनाथ बनर्जी ने 1895 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भाषण करते हुए व्यंग्यात्मक टिप्पणी की यहाँ तक कि प्रेम के क्षेत्र में भी कोई अपेक्षाकृत सदर मूर्ति सामने नहीं आती किंतु ज्या ही छानबीन करने वाली सच नाइट का प्रकाश उस पर डाला जाता है सारा धमजाल तत्काल लुप्त हो जाता है (ती० पी० ए० में पृ० 702)
- 26 हिंदू पामनियर, विमानविहारी मजुमदार की हिस्टरी आफ पोसिटिवल घाट फाम राममाइल टू दयान (1882-4) खंड I (बलकत्ता, 1934) पृ० 91 पर उद्धृत
- 27 दत्त ई० एच० II पृ० 385 पर उद्धृत और देखिए नोरोजी स्पीचेज परिशिष्ट डी०
- 28 एल० एन० बनर्जी स्पीचेज I पृ० 203
- 29 रिव्यू आफ फासेटस थी एसेज आन इंडियन पाइनांस जे० पी० एल० एल० खंड III सख्या 1 (जुलाई 1880) पृ० 80 हमारे पास जी० ए० मनेकर का कथन प्रमाण रूप में उपलब्ध है जिनके अनुसार यह समीक्षा जस्टिस रानाडे द्वारा लिखी गई थी (मनकर पूर्वोद्धत पृ० 214)
- 30 नोरोजी स्पीचेज पृ० 116
- 31 आर० एन० पी० बब 4 फरवरी 1888 उसी मनोदशा में लिखते हुए हिंदी प्रदीप ने 1 जनवरी 1879 के अंक में टिप्पणी की हमारी सरकार के पवित्र चरण असहिष्णु रूप से अत्यंत धमिलारी हैं जहाँ जहाँ पड़ते हैं वह धरती और वहाँ की घटिया से घटिया वस्तु राजस्व का बहुमूल्य स्रोत बन जाती है (आर० एन० पी० पी० एम० 11 जनवरी 1879)
- 32 आर० एन० पी० बब 11 फरवरी 1888 अपने 5 मार्च 1888 के अंक में इसी पत्र में व्यंग्यात्मक ढंग से सरकार को ब्रजट का घाटा पूरा करने के लिए लोगों को लूटने और हवा मेला विबाह तथा वेश्यागमन पर बर लगान का सलाह दी (आर० एन० पी० बब 10 मार्च 1888)
- 33 सी० पी० ए० पृ० 354 पर तथा देखिए पृ० 351 और 367 दो वष उपरालत सयाणी ने चेतावनी दी कि वर्तमान करो में वृद्धि करना अथवा और नए करारोपण करना राजनीतिक धरने का विषय बन जाएगा क्योंकि भारतीय जनता में और अधिक करो में भ्रुगतान की सामर्थ्य नहीं है (एल० सी० पी० 1898 खंड XXVII पृ० 531)
- 34 उदाहरण के लिए देखिए इंडियन स्पेक्टेटर 24 अक्टूबर (आर० एन० पी० बब 30 अक्टूबर 1890) रिव्यू आफ दि इंडियन साल्ट टक्स पृ० पी० एल० जुलाई 1881 खंड IV सख्या 1) पृ० 60 नवविभाकर 7 जनवरी (आर० एन० पी० बब 12 जनवरी 1884) सजीवनी 6 मार्च साधारणी 7 मार्च (वही 13 मार्च 1886) महाराष्ट्र मित्र 9 सित० (आर० एन० पी० बब 18 सितंबर 1885) एम वा० मुंबारायड रिप० आई० एन० सी० 1885 पृ० 70 मानवीय स्पीचेज पृ० 220-1 281 हिंदू 29 अगस्त 1887 बंगाली 3 सितंबर 1887 इंडियन स्पेक्टेटर 28 अगस्त 11 सितंबर नान प्रकाश 29 अगस्त इंडियन यूनियन 31 अगस्त बिहार ट्राइल और इंडियन प्राविचल 3 सितंबर सुबोध पत्रिका 4 सितंबर इंदु प्रकाश 5 सितंबर इंडियन नेशन 5 सितंबर तथा अन्य अनेक भारतीय समाचारपत्र (बी ओ० आई० अक्टूबर

- 1887), भोष मुधावर, 25 जनवरी (आर० एन० पी० बब 28 जनवरी 1888), मराठा 22 जनवरी 1888 हितवाणी, 22 माघ (आर० एन० पी० बग० 20 माघ 1895) बगवासी 20 अप्रैल (बहो, 27 अप्रैल 1895) राय पावर्टी प० 260 तिलक प्रोमोग्निस् आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बाबे 1895 खड XXXIII प० 90-1 पी० महता स्पीचेज प० 447 8, जी० वी० जोशी, पूर्वोद्धत, प० 203 228 9 ट्रिब्यून 16 जनवरी (आर० एन० पी० पी० 25 जनवरी 1902) एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए० प० 259 700 गोखले स्पीचेज प० 6-7, 21 परिशिष्ट, प० 1169 और 1178 नौरोजी स्पीचेज परिशिष्ट प० 51, ननी, इंडियन पालिटिक्स प० 120 एन० एम० घोष सी० पी० ए० प० 747 756 दत्त ई० एच० II प० 559 603
- 35 राय पावर्टी प० 256-8, जोशा, पूर्वोद्धत प० 221 6 पी० महता स्पीचेज प० 448 मयानी, सी० पी० ए० प० 348 वाचा सी० पी० ए०, प० 611 एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए०, प० 700, जी० एस० अम्बर बिलवी कमीशन खड III प्रश्न 18965 और ई० ए० प० 38-40 मालवीय, स्पीचेज, प० 219 291 दत्त इन्सट एंड इंडिया प० 141 2 ई० एच० II प० 383-4 गोखले, स्पीचेज, प० 6
- 36 जोशी पूर्वोद्धत प० 223
- 37 नौरोजी स्पीचेज परिशिष्ट प० 182
- 38 नौरोजी, स्पीचेज प० 141 156 7 189, 292 4 592 परिशिष्ट प० 38 एसाज प० 374 पावर्टी, प० 60-1 221 इंडियन स्पेक्टेटर 24 जून (आर० एन० पी० बब 30 जून 1883) तेलग सेलेक्टेड राइटिन्ज एंड स्पीचेज (बबई 1885) (इस आग सदभ के लिए स्पाचेज स सवेतित किया जाएगा) प० 222 एस० एन० बनर्जी स्पीचेज II प० 143 और सी० पी० ए० प० 703 राय पावर्टी प० 259 मयानी सी० पी० ए० प० 347 8 नदी इंडियन पालिटिक्स प० 110 एल० एम० घोष सी० पी० ए० प० 756 दत्त ई० एच० II प० 603-04 ए० मुखर्जी एल० सी० पी० 1904 खड \LIII प० 423-4 तथा देखिए पी० महता स्पीचेज प० 447 8 451 2, मालवीय स्पीचेज प० 276 279 80 291 2 नान प्रवाण 2 अप्रैल (आर० एन० पी० बब 4 अप्रैल 1903)
- 39 नौरोजी स्पीचेज परिशिष्ट प० 183
- 40 उदाहरणाय नौरोजी पावर्टी प० 60-1, 221 2 और स्पीचेज प० 156 और 293-4
- 41 सी० पी० ए० प० 348
- 42 नौरोजी स्पीचेज प० 157 भारत के व्ययो पर उन्होंने बिलवी आयोग को बताया कि किसानों पर कराधान मात्र इस दृष्टि से दुखदायक है कि यह दुखदायक बन जाता है (स्पीचेज परिशिष्ट प० 51) तथा पावर्टी प० 221 2
- 43 सी० पी० ए० प० 348
- 44 तेलग स्पीचेज प० 223 मालवीय स्पीचेज प० 30-1, गोखले स्पीचेज प० 15 21 दत्त ई० एच० II प० 572 राय पावर्टी प० 258 9 वाचा स्पीचेज परिशिष्ट प 32 विणम्भरनाथ एल० सी० पी० 1897 खड \XXVI प० 182, ए० मुखर्जी एल० सी० पी० XLIII प० 424
- 45 जोशी पूर्वोद्धत प० 226 तथा देखिए मालवीय स्पीचेज प० 219 और 291
- 46 नौरोजी, स्पीचेज प० 116 316 361 609 परिशिष्ट प० 21 मालवीय स्पीचेज प० 219



- और 291 तथा देखिए, तिलक प्रोसीडिन्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बावे 1895 खड XXXIII प० 91, दत्त स्पीचेज II प० 83-4 गुजराती, 22 माच (आर० एन० पी० बव 28 माच 1903)
- 47 नौराजी पावटी प० 61 स्पीचेज प० 131 528 राय, पावटी प० 260-1, मासवीय स्पीचज प० 221 नदी इंडियन पालिटिक्स प० 120, दत्त, ई० एच० II प० 377, जी० एस० अम्बर ई० ए० प० 10
- 48 जी० एस० अम्बर ई० ए० प० 45 तथा पी० मेहता स्पीचेज प० 574-5 604
- 49 गोखले स्पीचेज, प० 1 2 8 9 तथा प० 6 7, 21 71 74 और 101 तथा देखिए गोखले रिप० आई० एन० सी० 1904 प० 170 और आगे, वाचा, सी० सी० ए० प० 610-1 एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए० प० 700, आर्० एन० सी० 1904 का प्रस्ताव VIII
- 50 रिक्स थापसन एल० सी० पी० 1882 खड XVI प० 313 4 1880 के भारतीय अकाल आयोग के अनुसार कराधान का भार पयव पयक वर्गों पर प्रति व्यक्ति भिन्न भिन्न था भूमि स सर्वाधिक जमींदार वर्गों पर यह भार 273 पौंड, कृषक श्रमिकों पर 085 पौंड व्यापारियों और अधिकारियों पर 164 पौंड और हस्तशिल्पियों पर 1 पौंड था इस सगणना के उद्देश्य के लिए आयोग को अपनी इच्छाओं के नितात प्रतिबूल भूमि लगान को समग्र कराधान मे सम्मिलित करना पडा (रिपोर्ट आफ दि इंडियन फमीन फमीशन 1880 खड II प० 93)
- 51 नौराजी स्पीचेज परिशिष्ट प० 177
- 52 जाशी पूर्वोद्धत प० 152 तथा देखिए, प० 89 100 142
- 53 वही प० 164
- 54 वही प० 185 तथा प० 165
- 55 वहा प० 91 और देखिए प० 100 149
- 56 आर० एन० पी० एम० 29 फरवरी 1888
- 57 वही
- 58 जे० पी० एस० एस० जनवरी-अप्रैल 1888 (खड X सख्या 3-4) प० 21 इसी प्रकार 4 फरवरी 1888 के सजीवनी ने निर्देश किया कि इस देश मे धनिक वर्ग पर केवल उपयुक्त एवं पर्याप्त कर नहीं लगा जानी ही बात नहीं बल्कि बात यह है कि वह उतना कर भी नही देता जितना निधन वर्ग देता है (आर० एन० पी० बग० 11 फरवरी 1888)
- 59 राय पावटी प० 261 और 274 बाद मे 1901 मे उन्होंने सिफारिश की कि गरीबों पर कराधान भार को अवश्य कम करना चाहिए भले ही इसके लिए उन करो को भारी खाते-मीठे लोगों व वर्गों पर ही क्या न ढालना पडे (इंडियन पमिस प० 67)
- 60 गोखले स्पीचेज प० 40 तथा देखिए गोखले प्रोसीडिन्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बावे 1900 खड XXXVIII प० 94 साम प्रकाश 24 जुलाई (आर० एन० पी० बग 29 जुलाई 1882) एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए० प० 704 दत्त इम्पड ऐंड इंडिया प० 163 कसरी 31 माच (आर० एन० पी० बव 4 अप्रैल 1903)
- 61 राय पावटी प० 274 5 पर उद्धत
- 62 प्रमाण के रूप मे देखिए, जाशी पूर्वोद्धत प० 100 140-2 161 6
- 63 नौराजी पावटी प० 222
- 64 उदाहरण जाशी पूर्वोद्धत प० 185 221 228 राय पावटी प० 241 जी० एस० अम्बर

- विलवी कमोशन, खंड III प्रश्न 18646, मालवीय स्पीचेज पृ० 250-2 281 दत्त इंग्लड  
 ऐंड इंडिया, पृ० 133, स्पीचेज I पृ० 27 आर० एन० मधोलकर रिप० आई० एन० सी०  
 1901 पृ० 83 ज्ञान प्रकाश, 16 जनवरी (आर० एन० पी० दब 18 जनवरी 1879), बोध  
 सुधाकर 22 जनवरी (वही, 29 जनवरी 1879) नवविभाकर 7 जनवरी (आर० एन० पी०  
 बग० 12 जनवरी 1884), सजीवनी 18 जुलाई (वही 25 जुलाई 1885) साधारणी 7 माच  
 सजीवनी, 6 माच (वही 13 माच 1886) हितवादी, 13 जुलाई (वही 21 जुलाई 1900)  
 जा० एस० अम्बर, रिप० आई० एन० सी० 1900 पृ० 29 ए० बी० पी० 18 माच 1901  
 एडवोकेट 2 फरवरी (आर० एन० पी० एन० 4 फरवरी 1905)
- 65 प्रस्ताव XII इस प्रकार का एक प्रस्ताव लगभग इसी भाषा में काग्रेस ने निम्नांकित वर्षों में  
 पारित किया, देखिए 1897 का प्रस्ताव IX, 1901 का प्रस्ताव VIII 1902 का प्रस्ताव III  
 और 1904 का प्रस्ताव III
- 66 जोशी पूर्वोद्धृत पृ० 185
- 67 वही पृ० 793 5 तथा पृ० 824, 1136 यथा यह उल्लेखनीय है कि जोशी ने अपनी उद्योग की  
 परिभाषा के अंतर्गत कृषि को भी शामिल किया था
- 68 गोखले स्पीचेज पृ० 13 तथा देखिए एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए० पृ० 710
- 69 जोशी पूर्वोद्धृत पृ० 1
- 70 जी० एस० अय्यर ई० ए०, पृ० 42 3 गोखले स्पीचेज पृ० 4 15 21 73 दत्त ई० एच० II  
 पृ० 559 596-7 एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए०, पृ० 691 700-02 आई० एन० सी०  
 1904 का प्रस्ताव VIII
- 71 सी० पी० ए० पृ० 700 पर
- 72 गोखले स्पीचेज पृ० 101
- 73 वकील पूर्वोद्धृत पृ० 533 निश्चय ही यह कामचलाऊ तथ्यमिता था फिर भी मेरे विचार  
 में विचाराधीन विषय के लिए यह उपयुक्त और पर्याप्त था हमारे पास बहुत सारे उच्च  
 सरकारी प्रवक्ताओं की मायताएँ प्रमाण रूप में उपलब्ध हैं कि किसी भी अय्य वराधान की  
 सहन करने की भारत की क्षमता पूर्ण रूप से छिन भिन्न हो चुकी थी प्रमाण रूप में देखिए  
 एलगिन स्पीचेज पृ० 490
- 74 1880 में भूमि राजस्व से 21 करोड़ नमक कर से 71 करोड़ अफीम शुल्क से 104 करोड़  
 उत्पादन शुल्क से 31 करोड़ सीमा शुल्क से 25 करोड़ और आय कर (लाइसंस कर) से 5  
 करोड़ रुपया की वसूली हुई 1904 में इन करों से प्राप्त होने वाली राशि क्रमशः 283 करोड़  
 79 करोड़ 90 करोड़ 79 करोड़ 64 करोड़ और 18 करोड़ रुपये थी (पी० जे० ग्रामम  
 पूर्वोद्धृत पृ० 408)
- 75 नाइमेंस कर और आयकर के संक्षिप्त इतिहास के लिए देखिए जे० पी० नियोगी दि  
 इवाल्प्युशन आफ दि इंडियन इनकम टक्स (लन्दन 1929) प्रमथनाथ बनर्जी ए हिस्टरी आफ  
 इंडियन टक्सेशन (कनकता 1930) और पी० के० आर० बी० राव टक्सेशन आफ इनकम  
 इन इंडिया (कलकत्ता 1931)
- 76 वित्त सन्स चार्ल्स ड्रिविलियन पी० बनर्जी इंडियन टक्सेशन पृ० 94 पर उद्धृत
- 77 जान स्ट्रुची और रिचाड स्ट्रुची दि फाइनांस ऐंड पब्लिक वक्स आफ इंडिया पृ० 197
- 78 पी० बनर्जी इन्डियन टक्सेशन पृ० 72

- 79 आर० एन० पी० बव 12, 19 26 जनवरी, 2 फरवरी 1878 आर० एन० पी० बग०, 12 19 26 जनवरी 2 फरवरी, 2 23 मार्च 1878, आर० एन० पी० एम० अप्रैल 1878 आर० एन० पी० पी० एन० 19 26 जनवरी, 2, 9 16 23 फरवरी 9 16 मार्च 6 अप्रैल 1878 एल० एम० घोष स्पीचेज, प० 6
- 80 उदाहरण के रूप में देखिए ब्राह्मो पब्लिक आपोिनियन 1, 8 जनवरी 1880, बंगाली 4 जून 1880 नवविभाकर 1 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 6 मार्च 1880) विवेकवादिनी, स० 12 (आर० एन० पी० एम० मार्च 1880) धर्म समाचार 11 दिस० (आर० एन० पी० बव 11 दिसम्बर 1880) रास्त गुप्तार, 27 मार्च, जामे जमशेद, 1 अप्रैल (वहाँ 2 अप्रैल 1881) इंडियन स्पेक्टेटर 3 अप्रैल (वहाँ 9 अप्रैल 1881) नटिव आपोिनियन 17 अप्रैल (वहाँ 23 अप्रैल 1881) इंडियन स्पेक्टेटर नेटिव ओपीनियन 12 मार्च (वहाँ 18 मार्च 1882) ए० बी० पी० 16 मार्च 1882 अखबार आम 12 अप्रैल (आर० एन० पी० पी० एन० 19 अप्रैल 1882) रहूवरे हिंदू 24 अप्रैल (वहाँ 26 अप्रैल 1882) भारत मिहिर 14 मार्च सहचर 15 मार्च (आर० एन० पी० बग० 25 मार्च 1882) द्रविडवातमणि, 2 अप्रैल (आर० एन० पी० एम० अप्रैल 1883) इंडियन स्पेक्टेटर 16 मार्च (बी०ओ०आई०, 31 मार्च 1884) बंगाली 22 मार्च 1884
- 81 आर० एन० पी० बव 19 जनवरी 1878
- 82 वही 29 अक्टूबर 1881 और देखिए बोध सुधानर 9 जनवरी (आर० एन० पी० बव 12 जनवरी 1878) रास्त गुप्तार 13 जनवरी (वही 19 जनवरी 1878) कवि वचन सुधा 21 जनवरी (आर० एन० पी० पी० एन० 26 जनवरी 1878) आपताबे पंजाब 21 फरवरी (वही 23 फरवरी 1878) ए० बी० पी० 10 जनवरी (आर० एन० पी० बग० 10 जनवरी 1878) भारत मिहिर 17 जनवरी सोम प्रकाश 21 जनवरी (वही 26 जनवरी 1878) साधारणी 20 जनवरी (वही 2 फरवरी 1878) सुनेशासिमामनी 1 मई (आर० एन० पी० एम०, मई 1878) विवेकवादिनी स० 12 (वही मार्च 1880) आनंद बाजार पत्रिका 13 अप्रैल (आर० एन० पी० बग० 24 अप्रैल 1880) सोम प्रकाश 7 जून (आर० एन० पी० बग० 12 जून 1880) एल० एम० घोष स्पीचेज प० 6 16 मई 1880 को पूना की सावजनिक सभा में स्वीकृत पापन, ज० पी० एम० एस० जुलाई 1880 (घट III स० 1) प० 4
- 83 जुलाई से दिसंबर 1878 तक के महीने का आर० एन० पी० बव ए० बी० पी० 21 फरवरी प्रतिवार 22 फरवरी (आर० एन० पी० बग० 2 मार्च 1878) वष 1879 में बर्बई बंगाल पंजाब और उत्तर पश्चिम प्रांता तथा अखंड और मद्रास के नेटिव प्रस के प्रतिवेदन ब्राह्मो पब्लिक आपोिनियन 8 जनवरी 1880 बंगाली 4 दिस० 1880 आनंद बाजार पत्रिका 13 अप्रैल (आर० एन० पी० बग० 24 अप्रैल 1880) सोम प्रकाश 7 जून (वही 12 जून 1880) नवविभाकर 21 जून (वही, 26 जून 1880) इंडियन स्पेक्टेटर 23 अक्टू (आर० एन० पी० बव 29 अक्टूबर 1881)
- 84 सहचर 14 जनवरी (आर० एन० पी० बग०, 26 जनवरी 1878) बनारस अखबार 17 जनवरी (आर० एन० पी० पी० एन० 26 जनवरी 1878) आपताबे पंजाब 21 फरवरी (वही 23 फरवरी 1878) ए० बी० पी० 2 जनवरी 1880 बंगाली 17 जनवरी 1 80 हिंदू दिनपिपी 21 फरवरी (आर० एन० पी० बग० 28 फरवरी 1880) नवविभाकर 1 मार्च (वही 6 मार्च 1880) साधारणी 7 मार्च (वही 13 मार्च 1880) भारत मिहिर 9 मार्च (वही 20 मार्च

1880), इंडियन स्पेक्टेट 7 माच (आर० ए० पी० ब० 12 माच 1881)

- 85 ज० पी० नियोगी दि इयाल्गुशन आफ् दि इंडियन इनराम टनम प० 100-03
- 86 वही पृ० 101
- 87 मास मटोरियन पार ए रिस्टरी आफ् दि प्रीडम मूवमट इन इन्डिया गृह I 1818 95 (वर्ग 1957) प० 29-40
- 88 इडु प्रकाश 14 जनवरी रास्त गुप्तार 13 जनवरी (आर० एन० पी० ब० 19 जनवरी 1878) जामे जमशे 24 जनवरी (वही 26 जनवरी 1878) सफीरे बागाना 6 फरवरी घ्राफतावे पत्राव 21 फरवरी (आर० एन० पी० ब० 23 फरवरी 1878) सोम प्रकाश 7 जनवरी (आर० एन० पी० ब० 12 जनवरी 1878) वकीले हिंजुलान 5 अप्रल (आर० एन० पी० ब० 13 अप्रैल 1878) गुप्तानिमानो 1 अप्रल (आर० एन० पी० ब० 13 अप्रैल 1878), साधारणी 16 माच (आर० एन० पी० ब० 13 माच 1878) एल० एम० घोष स्पीचेज प० 6 19 नए वर के अधिवार दास स सरकारी वमचारिया और व्यवसाय मे लग हुए लोगो को बाहर रखने सबको प्रावधान को भसना करने के लिए मद्रास मे एक जनसभा हुई शम्भ उल अणवार 18 माच (आर० एन० पी० ब० 18 माच 1878)
- 89 बगाला 17 जनवरी 6 माच 1880 ए० बी० पी० 2 जनवरी 1880 ब्राह्मो पत्रिक जोपीनियन 8 जनवरी 1880, आर० एन० पी० ब० 4 मितवर 1880 मे प्रतिवेदित समाचारपत्र हिंदू हितपिणी 21 जनवरी (आर० एन० पी० ब० 28 फरवरी 1880) नवविभावर 1 माच (आर० एन० पी० ब० 6 माच 1880), साधारणी 7 माच (वही 13 माच 1880) भारत मिहिर 9 माच (वही 20 माच 1880) सहचर 15 माच (वही 27 माच 1880) इन्डियन स्पेक्टेट 6 माच 3 अप्रैल (आर० एन० पी० ब० 12 माच 9 अप्रैल 1881) नेटिव ओपी नियन, 17 अप्रैल (वही 23 अप्रैल 1881) सुबाघ पत्रिका 19 फरवरी (वही 25 फरवरी 1882) मराठा 30 अप्रैल 1882 नेटिव ओपीनियन 16 अगस्त (आर० एन० पी० ब० 22 अगस्त 1885) इंडियन स्पेक्टेट 23 अगस्त (वही 29 अगस्त 1885) ज० यू० यासिक रिप० आई० एन० सा० 1885 प० 67 और इन्डिया आफ् एन० सी० 1885 का प्रस्ताव VI
- 90 जे० पी० एस० एस० जुनाई 1880 (खंड III सख्या 17) प० 4
- 91 देघिए 2 जनवरी 1880 को अमत बाजार पत्रिका और 19 दिसबर 1884 का हिंदू तथा दधिए ए० बी० पी० 3 जनवरी घामवत प्रकाशिका 5 जनवरी (आर० एन० पी० ब० 12 जनवरी 1878) हिंदू हितपिणी 12 जनवरी (वही 26 जनवरी 1878) भारत मिहिर 21 फरवरी (वही 2 माच 1878) और साधारणा 16 माच (आर० एन० पी० ब० 23 माच 1878) और इंडियन स्पेक्टेट 23 अक्टूबर (आर० एन० पी० ब० 19 अक्टूबर 1881) 10 जनवरी 1878 के अमत बाजार पत्रिका ने पिपिणी की जि सरकार न आय कर नहा लगाया है क्योंकि उसे यूरोपियो और समझ तथा प्रभावशाली भारतीयो का डर है
- 92 बी० व० आर० बी राव टैक्समन आफ् इनकम प० 292 तथा पी० बनर्जी इंडियन टैक्समन प 127 ए कालविन एल० सी० पी० 1886 खंड XXV प० 21 और जामे
- 93 ब्राह्मो पत्रिक ओपीनियन 8 जनवरी 1880 22 दिसबर 1881 बगाली 24 म्मि० 1881 रास्त गुप्तार गुजरात मित्र थावे धानिकन और अरुणादय 11 दिस सुद प्रकाश 10 म्मि० याय प्रकाश 12 दिस० वासिदे मुबई 16 दिस (आर० एन० पी० ब० 17 दिसबर 1881) बवई समाचार जामे जमशे 20 म्मि० (वही 24 दिस० 1881) सहचर 28 दिस० 1881

(आर० एन० पी० बग० 7 जनवरी 1882) परिश्रमक 1 जनवरी (वही 14 जनवरी 1882) नसीमे आगरा 30 निसवर 1881 (आर० एन० पी० वी० एन०, 10 जनवरी 1892), सोम प्रकाश 5 अक्टूबर सुरभि औ पताका 7 अक्टूबर (आर० एन० पी० बग० 10 अक्टू० 1885), सहृषर 7 अक्टू० भारत मिहिर 8 अक्टू० सजीवनी, 10 अक्टू० (वही, 17 अक्टू० 1885), वायस आफ इडिया जनवरी 1886, इडियन मिरर 7 9, 15 जनवरी ट्रिभ्यून 9 जनवरी व्हिार हेराल्ड 19 जनवरी इडियन नेशन 11 जनवरी इडियन इवा 11 जनवरी (बी० ओ० आई० जनवरी 1886) हिंदुस्तानी 8 जन० अण्वारे ग्राम 9 जन० (बी० ओ० आई० जन० 1886) बगाली 9 16 23 जन० 1886 इडियन एमोसिएशन व सेनेटरी का भारत सरकार को पत्र बगाली 23 जनवरी 1886 बाबे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन का भारत सरकार को विरोधपत्र रिपोट आफ बाब प्रेसीडेंसी एसोसिएशन 1885 6 प० 205-08 बवई समाचार और जाम जमशेद, 5 जनवरी (आर० एन० पी० बग० 9 जनवरी 1886) इदु प्रकाश 11 जनवरी 10 जनवरी के गुजराती गुजरात मित्र रास्त गुप्तार और यज्ञा परस्त हितेच्छु 14 जनवरी पंडित 15 जन० (वही 16 जन० 1886) सुरभि औ पताका भारत मिहिर 31 दिस० 1885 भरी 1 जन० नव मेदिनी 3 जन० दाका प्रकाश 3 जन० सोम प्रकाश और नवविभाकर 4 जन (आर० एन० पी० बग० 9 जनवरी 1886) सहृषर 6 जनवरी सजीवनी 9 जन० (वही 16 जनवरी 1886) उत्सव दीपिका 16 जनवरी (वही 30 जन० 1886) कर्णाटक प्रकाशिका तिथिरहित हिंदू जनभूपयी तिथिरहित केरल मित्रन तिथिरहित शम्स जल अण्वार 8 फरवरी (आर० एन० पी० एम० फरवरी 1886) माडलिक स्पीचेज प० 660 एत० एन० बनर्जी स्पीचेज III प० 1-9

- 94 वायस आफ इडिया जन० 1886 तथा देखिए इडियन मिरर 7 9 15 जनवरी इडियन इको 11 जनवरी (बी० ओ० आई० जन० 1886) बगाली 9 16 जन० 1887, 1886 मे बवई प्रेसीडेंसी एसोसिएशन का भारत सरकार को विरोधपत्र पूर्वोक्त स्थल इडियन स्पेक्टेटर 10 जन० (आर० एन० पी० बग० 16 जन० 1886) आर एन० पी० बग० 16 जनवरी से 6 फरवरी 1886 एत० एन० बनर्जी स्पीचेज III प० 3-4
- 95 रास्त गुप्तार गुजराती गुजरात मित्र और अरुणोदय 11 दिस० इदु प्रकाश 12 निस० (आर० एन० पी० बग० 17 दिस० 1881) बवई समाचार और जाम जमशेद 20 निस० (वही 24 निसवर 1881)
- 96 सहृषर 7 अक्टूबर सजीवनी 10 अक्टू० (आर० एन० पी० बग० 17 अक्टू० 1885), सुरभि औ पताका 31 दिस० 1885 नवविभाकर 4 जनवरी (वही 9 जन० 1887) भारत मित्र 7 जनवरी उचिन वक्ता 8 जनवरी बगवासी 9 जनवरी (वही 16 जनवरी 1886) सहृषर 13 जन० भारत मिहिर 14 जन (वही 23 जनवरी 1886) सोम प्रकाश 1 फरवरी (वही 6 फर 1886) बाब प्रेसीडेंसी एसोसिएशन का 1886 म भारत सरकार को ज्ञापन, पूर्वोक्त स्थल माडलिक स्पीचेज प० 651 60 एम० एन० बनर्जी स्पीचेज III प० 8
- 97 जनवरी 1886 क वायस आफ इडिया मे भारतीय समाचार पत्रों की राय का सार-संग्रह 1886 म बाबे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन का ज्ञापन पूर्वोक्त स्थल एत० एन० बनर्जी स्पीचेज III प० 8
- 98 ब्राह्मो पत्रिका ओपीनियन 8 जनवरी 1880 बगाली 9 16 जन० 1886 भारत सरकार को इडियन एमोसिएशन के सेनेटरी का पत्र बगाली 23 जनवरी 1886 म ट्रिभ्यून 9 जन (बी० ओ० आई० जन० 1886) जनवरी 1886 के वास्तु आफ इडिया म भारतीय समाचारपत्रों के

- दण्डिकोण का सार सक्षप, 1886 मे बाबे प्रेसीडन्सी एसोसिएशन के सञ्चाली का भारत सरकार को शापन पूर्वोक्त स्थल, सहचर 30 दिसबर 1885 सुरभि ओ पताका, 31 दिस० 1885 (आर० एन० पी० बग०, 9 जन० 1886) सजीवनी, 9 जनवरी (वही 16 जन० 1886)
- 99 बाह्यो पत्रिक ओपीनियन 8 जनवरी 1880 22 दिस० 1881 पूना सावजनिक सभा 1881 का शापन ज० पी० ए० ए०, खड IV, स० 1 (जुलाई 1891) प० 15 सहचर 7 अक्टूबर (आर० एन० पी० बग०, 17 अक्तू० 1885) ट्रिब्यून 6 फर० (बी० ओ० आई० फरवरी 1886) मासिक स्पेसिज, प० 665
- 100 पूना सावजनिक सभा का 1881 का शापन पूर्वोक्त स्थल नवविभाकर, 4 जन० (आर० एन० पी० बग० 9 जनवरी 1886) सहचर 6 जनवरी (वही 16 जनवरी 1886) सोम प्रकाश 1 फरवरी (वही 6 फरवरी 1886)
- 101 मासिक स्पेसिज, प० 661
- 102 1870 और 1872 के लिए देखिए बी० बी० मजूमदार पूर्वोक्त, प० 382 3 तथा ए० बी० पी० 7 फरवरी 1871
- 103 ए० बी० पी० 2 जनवरी 1880 बंगाली 17 जनवरी 1880, आनंद बाजार पत्रिका, 30 दिस० 1879 नवविभाकर 5 जनवरी (आर० एन० पी० बग० 10 जन० 1880) नवविभाकर 1 माच (आर० एन० पी० बग०, 6 माच 1880) साधारणी 7 माच (वही 13 माच 1880), भारत मिहिर 9 माच (वही 20 माच 1880) सहचर 15 माच (वही 27 माच 1880) तथा देखिए पीछे पादटिप्पणिया 89 90
- 104 हिंदू 19 दिस० 1884 इंदु प्रकाश 3 माच 1884 इंडियन स्पेक्टेटर, 23 अक्टूबर (आर० एन० पी० बग० 29 अक्तू० 1881) 18 दिस० (आर० एन० पी० बग० 24 दिस० 1881) 9 माच 1884 सुबोध पत्रिका 11 दिस० (आर० एन० पी० बग० 17 दिस० 1881) नवविभाकर 19 दिस० (आर० एन० पी० बग० 24 दिस० 1881) आनंद बाजार पत्रिका 26 दिस० 1881 (आर० एन० पी० बग० 7 जनवरी 1882) साधारणी 15 जन० (वही 21 जन० 1882) प्रभाती 7 अप्रैल (वही 7 अप्रैल 1883) स्वदेशमित्र 11 दिस० (आर० एन० पी० एम० दिस० 1884) दैनिक 23 दिस० (आर० एन० पी० बग० 28 दिस० 1885) 1880 से पूव इस प्रकार की माग के लिए देखिए पीछे पादटिप्पणी स० 91
- 105 प्रस्ताव VI बाद म जब सरकार ने दोबारा कर लगान का निणय किया तो गवर्नर जनरल ने वाप्रस क इस प्रस्ताव को भारतीयों के प्रगतिशील बग म मत के रूप म लेत हुए अपने पग की स्वीकृति के तौर पर उद्धत किया (एल० सी० पा० 1886 खड XXV प० 27)
- 106 ए० बी० पी० 14 28 जन 4 11 फरवरी 1886 हिंदू 7 9 15 जनवरी 1886 (बी० ओ० आई० जनवरी 1886) मराठा, 17 जनवरी 1886 (मराठा ने आय कर को कराधान पद्धति के स्याई पग बनाए जाने का विरोध किया) इंदु प्रकाश, 25 जनवरी 1886 सुबाध पत्रिका 24 जन० (आर० एन० पी० बग० 30 जन० 1886) शिवाजी 29 जन० (वही 6 फरवरी 1886) दैनिक 30 दिस० 1885 (आर० एन० पी० बग० 2 जनवरी, 1886) भारतवासी 9 जन० साधारणी 10 जनवरी (वही 16 जनवरी 1886) आनंद बाजार पत्रिका 18 जन० (वही 23 30 जन० 1886) सुरभि ओ पताका 28 जन० (वही 6 फरवरी 1886) आफताब पजाब 13 जनवरी (बी० ओ० आई० जनवरी 1886) इन पत्रों म कुछ न इसम पहले यहा तक कि कुछ ही दिन पहले आय कर का विरोध किया था इसी मूची म प्रदर्शित बंगाल क प्रमुख समाचारपत्रों की व्यापक सख्या को देखत हुए 1886 म बंगाल क रिदुम्तानी भाषाई

समाचारपत्रों के प्रतिवेदन में की गई इस स्वीकृति पर आश्चर्य होता है कि आनन्द बाबू पत्रिका को छोड़कर किसी एक भी स्वदेशी भाषाई पत्र ने आय कर का पक्ष लेते हुए उदात्त समर्थन नहीं किया होम (पब्लिक) माच 1888 प्राग, 404 (ए) कटिका, 56

- 107 रिप० आई० एन० सी० 1837 पृ० 135
- 108 मालवीय स्पीचज पृ० 505
- 109 रिप० आई० एन० सी० 1902 पृ० 133
- 110 सी० पी० ए० प० 704
- 111 मसानी पूर्वोद्धत प० 318 पर
- 112 दत्त ई० एच० II प० 165 समान रूप से ही महत्वपूर्ण यह तथ्य है कि राष्ट्र की आय को दुष्प्रभावित करने वाले करा को लौटाने की मांग के समय उनसे द्वारा उल्लिखित कर के भूमि लगान भूमि लगान पर उपकर नमक कर बपास उत्पादन शुल्क उनसे द्वारा हटाए जाने के लिए उल्लिखित किए गए करों में आय कर सम्मिलित नहीं था देखिए ई० एच० II प० 596-7 इसी प्रकार 1904 के बजट पर उनसे भाषण बी० के० बोस और श्रीराम न आय कर जारी रखने के पक्ष में ही भाषण दिया (एल० सी० पी० 1904 खंड XLIII प० 432 और 503 क्रमशः)
- 113 जोशी पूर्वोद्धत प० 141, 161 6 190
- 114 पापन, दिनांक 8 माच 1894 रिपोर्ट आफ दि इंडियन एसोसिएशन 1892 3 से 1895 6 पृ० 43 तथा देखिए पूना सावजनिक सभा का शापन, दिनांक 23 दिस० 1890 जे० पी० एन० एन० जन० 1891 (खंड XIII त० 3) प० 80
- 115 20 सित० 1891 7 8 माच 1894 23 अक्टूबर 1902
- 116 और देखिए, हिंदू 8 अप्रैल 1889 28 मई 1890 3 दिसंबर 1890
- 117 आर० एन० पी० वग 20 सित 1890
- 118 आर० एन० पा० वग० 17 माच 1894 तथा सजीवनी 30 अगस्त (आर० एन० पी० वग० 6 सित० 1890)
- 119 तिरगा निशान 13 अप्रैल (आर० एन० पी० एम०, 30 अप्रैल 1889) इंदु प्रकाश 8 सित० (आर० एन० पी० वग 13 दिस० 1890) नेटिव ओपीनियन 14 दिस० (वही 20 दिस० 1890) मराठा 14 दिस० 1890 वगवासी 30 अगस्त (आर० एन० पा० वग० 6 सित० 1890), हिंदुस्तानी 21 जनवरी (आर० एन० पी० एन० 27 जन० 1891), कसरे हिंद 18 फरवरी (आर० एन० पी० वग 24 फरवरी 1894) स्वदेशमित्र 5 अप्रैल (आर० एन० पी० एम 15 अप्रैल 1899) जमी उन्नत उलूम 7 नव० (आर० एन० पी० एन० 13 नव० 1900) अथवा समाचार 7 नव० (वही 8 नव० 1902) हितवादी 31 अक्टूबर (आर० एन० पी० वग० 8 नवंबर 1902) स्वदेशमित्र 8 अप्रैल (आर० एन० पी० एम०, 9 अप्रैल 1904)
- 120 देखिए आगे उक्त कर संबंधी भाग
- 121 आर० एन० पी० वग० 15 नव० 1890 वही, 21 फरवरी 1891 और आर० एन० पा० एन० 25 नवंबर 1890 क्रमशः
- 122 जो० आर० विननवीस एल० सी० पी० 1894 खंड XXXIII प 246 महाराजा आफ दरमगा एल० सी० पा० 1897 खंड XXXVI प० 210 आशुतोष मुखर्जी एन० सी० पी० 1904 खंड XLIII प० 416 20





- 135 जोशी, पूर्वोद्धत पृ० 164 6 तथा नवविभाकर 5 जन० (आर० एन० पी० बग०, 10 जनवरी 1880), सुबोध पत्रिका 11 दिस० (आर० एन० पी० बग०, 17 दिस० 1881), अवधारे आर 21 जनवरी (आर० एन० पी० पी० एन० 31 जन० 1882) इंदु प्रकाश, 8 मार्च 1884 इंडियन स्पेक्टेटर 9 मार्च 1884 स्वदेशमित्र 11 दिस० (आर० एन० पी० एम० दिस० 1884), दैनिक 23 नवंबर (आर० एन० पी० बग०, 28 नवंबर 1885) मराठा 17 जन० 1886 भारतवासी 9 जनवरी साधारणी 10 जनवरी (वही 16 जनवरी 1886) सुरभि ओ पताका 28 जन० (वही, 30 जन० 1886), रिप० आई० एन० सी० 1887 पृ० 135 तिरगा निशान 13 अप्रैल (आर० एन० पी० एम० 30 अप्रैल 1889), सुधारक, 15 दिस० (आर० एन० पी० बग० 20 दिस० 1890), पूना सावजनिक सभा का 23 दिसंबर 1896 का पापन ज० पी० एस० एस० जनवरी 1891 (खंड XIII सं० 3), पृ० 80 हिंदुस्तानी 21 जनवरी (आर० एन० पी० एन०, 27 जन० 1891), आफताबे पनाब 2 नवंबर (आर० एन० पी० पी० 14 नवंबर 1891) सजीवनी, 10 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 17 मार्च 1894), स्वदेशमित्र 5 अप्रैल (आर० एन० पी० एम० 15 अप्रैल 1899), उमी उल उलम 7 नवंबर आर० एन० पी० एन०, 13 नवंबर 1900) अवध समाचार, 7 नवंबर (वही 9 नवंबर 1902) हितवाणी, 31 अक्टूबर बंगाली, 4 नव० (आर० एन० पी० बग० 8 नवंबर 1902) स्वदेशमित्र, 8 अप्रैल (आर० एन० पी० एम० 9 अप्रैल 1904)
- 136 नवविभाकर 26 जनवरी (आर० एन० पी० बग० 31 जनवरी 1880) ए० बी० पी० 29 दिस० 1881) इंडियन स्पेक्टेटर 18 दिस० (आर० एन० पी० बग०, 24 दिस० 1881) और 9 मार्च 1884 सजीवनी 10 अक्टू० सोम प्रकाश 12 अक्टू० (आर० एन० पी० बग० 17 अक्टूबर 1885)
- 137 प्रस्ताव सख्या VI
- 138 ए० बी० पी० 28 जनवरी 11 फरवरी 1886 बंगाली 9, 23 जनवरी 1886 दैनिक 30 दिस० 1885 (आर० एन० पी० बग० 2 जनवरी 1886) बंगवासी 9 जनवरी (वही, 16 जन० 1886) दैनिक और आगद बाजार पत्रिका, 11 जनवरी (वही) सहृदय 13 जन० भारत मिहिर 14 जन० सजीवनी और भारतवासी 16 जनवरी साधारणी 17 जनवरी (वही 23 जनवरी, 1886), सुरभि ओ पताका 28 जनवरी (वही 6 फरवरी 1886) एस० एन० वनर्जी स्पीचेज III पृ० 4 इंडियन एसोसिएशन का शापन बंगाली के 23 जन० 1886 के प्रकृ म प्रकाशित, बाबे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन का शापन रिपो० आफ बाबे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन 1885 6 प० 206-07
- 139 प्रस्ताव सख्या VI
- 140 मालवीय स्पीचेज, प० 504
- 141 1888 का प्रस्ताव VIII 1889 का प्रस्ताव III (जी) 1890 का प्रस्ताव II (जी) 1891 का प्रस्ताव IV 1892 का प्रस्ताव V (बी), 1893 का प्रस्ताव III (बी) 1894 का प्रस्ताव XVI (बी) 1895 का प्रस्ताव XXII (ए) 1896 का प्रस्ताव XIII 1898 का प्रस्ताव XX (जी) 1899 का प्रस्ताव XIV (III डी) 1900 का प्रस्ताव X (III डी) 1901 का प्रस्ताव III तथा XIX (I ए)
- 142 उद्धारणाय हिंदू 8 अप्रैल 1889 बंगवामी सजीवनी 30 मितंबर (आर० एन० पी० बग० 6 मिन० 1890) नेटिव ओपीनियन 14 दिसंबर (आर० एन० पी० बग० 20 दिस० 1890) हिंदुस्तानी 21 जनवरी (आर० एन० पी० एन० 27 जनवरी 1891) ए० बी० पी० 20

सितंबर 1891 आपताने पजाब 2 नवंबर (आर० एन० पी० पी० 14 नवंबर 1891) हिंदू  
4 अप्रैल 1894 30 नवंबर 1895 स्वदेशमित्र 5 अप्रैल (आर० एन० पी० एम 15 अप्रैल  
1899) जमी उल उलूम, 7 नवंबर (आर० एन० पी० एन०, 13 नवंबर 1900) अवध  
समाचार 7 नवंबर (वही 8 नवंबर 1902) ए० बी० पी० 12 मार्च 1902 हितवादी 31  
अक्तूबर (आर० एन० पी० वग० 8 नव० 1902)

143 जी० पी० सेन रिप० आई० एन० सी० 1887 प० 131 2 जे० सी० घोष वही पृ० 133,  
मालवीय, स्पीचेज, प० 505-08 राय पावर्टी प० 267 71 जी० आर० एम० चितनवीस  
एन० सी० पी० 1894 खड XXVIII प० 246 पी० ए० चारलू एल० सी० पी० 1896  
खड XXXV प० 285 जी० आर० एम० चितनवीस एल० सी० पी० 1899 खड  
XXXVIII प० 234 पी० ए० चारलू वही प० 243 गोखले स्पीचेज प० 10 पी० ए०  
चारलू, एल० सी० पी० 1902 खड XLI प० 119 श्रीराम, वही प० 142 3 एस० एन०  
बनर्जी सी० पी० ए०, पृ० 704 सी० आई० चिंतामणि रिप० आई० एन० सी० 1902  
प० 133

144 रिपायत की घोषणा करते हुए वित्त सदस्य सर एडवर्ड ला ने टिप्पणी की जहा तक आय कर  
मे छूट की सीमा को बढ़ाने की बात है हमारा विश्वास है कि हजार रुपये से कम रकम पर  
कर का भुगतान अधिकांशतः साधारण व्यापारियों व्यापारिक संस्थानों तथा सरकारी कार्यालयों  
के क्लर्कों और पेंशनभोगियों द्वारा किया जाता है जो आय के अपन निम्न तथा साधारण  
साधनों के कारण इस कर को असाधारण भार के रूप में हा ग्रहण करते हैं इस अतिरिक्त  
हमारे विचार म कर निर्धारकों की जाच सखी अनुचित वायदावाही का शिकार भी अधिकांशतः  
इस निम्न वर्ग को होना पड़ता है ये कर निर्धारक कभी कभी जाच क समय अयामपूर्ण ढंग से  
बहुत ऊंचे कर निर्धारित कर देते हैं (फाइनेशनल स्टेटमट 1903-04 कडिवा 39)

145 गोखले स्पीचेज प० 38 श्रीराम बी० वे० बास०, पी० आन० चारलू एन० सी० पी० 1903  
खंड XLI पृ० 100 126-7, 140-2 प्रमत्त हिंदू, 18 मार्च 1903 ए० बी० पी० 19 23  
मार्च 1903 बगानी 21 मार्च 1903, 28 मार्च 4 11 अप्रैल 1903 वे० बी० ओ० आई० म  
28 मार्च के आर० एन० पी० वग० मे 28 मार्च 4 11 अप्रैल 1903 के आर० एन० पी०  
वग० म 4 11 22 अप्रैल 1903 म आर० एन० पी० पी० म 28 मार्च 4 11 अप्रैल 1903  
आर० एन० पी० यू० पी० म तथा 21 मार्च 1903 क आर० एन० पी० एम० म उल्लिखित  
पत्र-पत्रिकाएँ आई० एन० सी० 1903 का प्रस्ताव सं० VIII

146 प्रमाण रूप मे लेखिए गोखले स्पीचेज प० 77 और आई० एन० सी० 1903 का प्रस्ताव  
सं० VIII

147 राष्ट्रीय दृष्टिकोण के इस पक्ष पर अमल बाजार पत्रिका के संपादक मानिक ने 23 अक्तूबर 1902  
को सावजनिक रूप से वक्त दिया उन्होंने निर्देश किया कि वह आय कर का तब भा समर्थन कर  
रहे हैं जबकि उन्हें इस कर के कारण एक बहुत बड़ी रकम का भुगतान करना पड़गा

148 अत भारतीय नेताओं की बड़ी संख्या वित्त सन्स्य ए० बालविन की 1886 में उच्च वर्गों पर इस  
निदापरक टिप्पणी से बंध गई कि ये साग जनता पर कराधान का भार बढ़ाने के लिए ता  
उत्सुक हैं परंतु अपनी उंगली भी छुआना नहीं चाहते फलतः य वग विगपन व्यापारों और  
व्यवसायी लोग जिम सरकार की छत्रछाया म फलते-फूलते हैं उन सरकार क समर्थन क निष्प  
कर के रूप म उसके प्रति अपना कोई भी योगदान नही दन बालविन न अपन मित्रों सगण्ड  
का कररहित उल्लेखनीय शाय अजन करने के लिए मजाक उड़ाया तथा उनम जनता क भार म

- उनके समुपयुक्त भाग की उगाही द्वारा उच्च तथा मध्यवर्ग को कर से बचन व इस 'वचन' से मुक्त करने का वचन दिया (एल० सी० पी० 1886 खड 25 पृ० 11 और 18) जमा हूम किया चुके हैं, भारतीय पत्रकार तथा अन्धाय राष्ट्रीय नेता इस वाय में सरकार की सहायता करने के लिए आध स भी अधिक माग तक आग बढ़ने को सहमत व वस्तुतः जसा कि नमकर वाले अगले भाग में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, सरकार ने ही इस सघ्न में इनकार का खया अपनाया जो वष बाद सरकार ने इस राह पर आगे बढ़ना अस्वीकार कर दिया भारतीय नेताओं के पास इस इनकार की तीव्र आलोचना का माग ही बचा था तुलनीय हफरिन मिनिस्टर एक्कोजर टु डिस्पच (पॉ ट्रक)आफ गवर्मेंट आफ इंडिया सन्धा 68 दिनांक 6 नवंबर 1888
- 149 उदाहरण के रूप में 8 अप्रैल 1889 के अख म हिंदू ने निर्देश किया कि निम्न मध्य वर्ग का सालना 500-1000 उपाजन करने वाला व्यक्ति आय कर चुवाने की अच्छी स्थिति में था उस व्यक्ति की अपेक्षा जा देकारा नमक कर का भुगतान करता है पत्र ने इस आधार पर माग था कि प्रत्याशित राहत देने के किसा भी प्रश्न पर इन दोनों में निधन व्यक्ति को प्रायमिवता मिलनी चाहिए और दधि एल० एन बनर्जी सी० पी० ए० पृ० 703-04 और पी० ए० चारनू एल० सी० पी० 1902 खड XLI, पृ० 119 कराधान में किसी प्रकार की राहत आय कर की अपेक्षा नमक कर और भूमि लगान के भार को हलका करने के दृष्टिकोण के लिए देखिए ए० बी० पा० 4 फरवरी 1886 मराठा 14 दिस० 1890, सजीवनी 30 अगस्त (आर० एन० पी० वग०, 6 सित० 1890) पूना सावजनिक सभा का 23 दिन० 1890 को प्रथि पापन, ज० पी० एल० एल० जनवरी 1891 (खड XIII स० 3) पृ० 80 मराठा 29 मई 1904
- 150 1882 में शीरियल सजिस्ट्रिडव कौंसिल में कलकत्ता के 'यापारिया के प्रतिनिधि दुगाचरण लाहा और बगाल के जमादारा के प्रतिनिधि जीतेन्द्र मोहन टगोर ने नमक कर में कटौती का विरोध किया उन्होंने इसके बदले लाइसेंस कर को हटाने की सिफारिश की (एल० सी० पी० 1882 खड XXI पृ० 290-1 304) 1889 में दुर्गाचरण लाहा ने नमक कर में कटौती का विरोध किया और उसके बदले आय कर समाप्त करने का सुभाव दिया उनके अनुसार आय कर समाप्त करने से जनता को ठोस और वास्तविक राहत मिलेगी तथा लोग इसका सचमुच ही स्वागत करेंगे (एन० सी० पी० 1889 खड XXVIII पृ० 141) 1890 में बगाल के राष्ट्रीय वाणिज्य सदन (बगाल नेशनल चंबर आफ कामर्स) ने सरकार के पास आय कर समाप्त करने के लिए पापन भेजा (चंबर का 1890 की रिपोर्ट पृ० 23)
- 151 बगाल और असम को उनकी जखूरत का सारा नमक इंग्लैंड और यूरोप से मिलता था इसका प्रमुख कारण यह था कि दक्षी नमक उद्योग आयातित नमक की प्रतियोगिता नहा कर सकता था यह आयातित नमक वस्तुतः विदेशा पोना में पात के भार का सतुलित करने के लिए तादा जाना था स्थानीय नमक पर घोर आयातित नमक पर शुल्क लगान के उपरांत दाना का मत्प बराबर हो जाता था (पी० बनर्जी इन्डियन टक्सेशन पृ० 280-6 वकील पूर्वोद्धत पृ० 457 8)
- 152 1859 में यह दरें निम्नलिखित रूप में थीं  
बगान में 2 रु० 8 आने प्रति मन मद्रास में 14 आने प्रति मन बर्बई में 12 आने और उत्तरा भारत में 2 रुपय प्रति मन (पी० बनर्जी इन्डियन टक्सेशन पृ० 278)
- 153 जान और रिचाड स्ट्रुधी पूर्वोद्धत पृ० 219-32
- 154 उदाहरण के रूप में दधि ए० पी० बनर्जी इन्डियन टक्सेशन पृ० 277 बी० वा० मजूमदार पूर्वोद्धत पृ० 204 484 5 दस इ० एच० II पृ० 150-1

- 155 प्रमाण के रूप में देखिए नोरोजी स्पीचेज, परिशिष्ट पृ० 178 एसेज पृ० 107 नेटिव ओपी नियम 18 अगस्त (आर० एन० पी० बग, 24 अगस्त 1872) सत्य शोधक 5 सितंबर जगनमित्र 6 सित०, ज्ञान प्रकाश 16 सित० (वही, 18 सितंबर 1875) बर्दे समाचार 21 सित० (वही, 25 सितंबर 1875), शुभमूचक 22 जनवरी और रास्त गुप्तार 14 जनवरी (वही 20 जनवरी 1877) सूद प्रकाश 5 जनवरी, गुजरात मित्र 6 जनवरी जाम जमशद 10 जन० (वही, 12 जनवरी 1878), इंदु प्रकाश 14 जनवरी रास्त गुप्तार 13 जन० (वही 19 जनवरी 1878), नेटिव ओपीनियम, 20 जन० (वही 26 जन० 1878) बावे त्रानिकल 14 मार्च जामे जमशद 17 मार्च (वही 20 मार्च 1880), दि पाइनासेज आफ इंडिया थ्रदर लाड लिटन ज० पी० एस० एस० अप्रैल 1880 (खंड II सं० 4) पृ० 30, प्रोसीडिंग्स आफ दि सभा ज० पी० एस० एस० जुलाई 1880 (खंड III सं० 1), पृ० 3 दि वायसरायल्टी आफ लाड लिटन वही पृ० 63, भारत मिहिर, 27 जुलाई (आर० एन० पी० बग० 7 अगस्त 1880), मराठा 15 मई 1881 'दि इंडियन साल्ट टक्स, ए बुक रिब्यू जे० पी० एस० एस०, जुलाई 1881 (खंड IV सं० 1) पृ० 59-61, इंडियन स्पेक्टेटर, 14 अगस्त (आर० एन० पी० बग 20 अगस्त 1881) वसरी, 23 अगस्त (वही, 3 सितंबर 1881), इंडियन स्पेक्टेटर और रास्त गुप्तार 29 जनवरी (वही 4 फरवरी 1882), हिंदी प्रदीप जनवरी 1879 (आर० एन० पी० पी० एन०, 11 जनवरी 1879)
- 156 नोरोजी पावर्टी पृ० 215
- 157 वी० वी० मजूमदार पूर्वोद्धत पृ० 314 और 317
- 158 1877 में पत्रिका द्वारा अपनाई स्थिति के लिए देखिए वही पृ० 383 1881 में उसका रवये के लिए देखिए 30 जून 1881 का उसका भाव और देखिए नवविभाकर 26 जनवरी (आर० एन० पी० बग० 31 जनवरी 1880), आनंद बाजार पत्रिका 11 जुलाई (वही, 23 जुलाई 1881)
- 159 ए० वी० पी० 30 जून 1881 तथा आनंद बाजार पत्रिका 11 जुलाई 1881 पूर्वोक्त स्थल
- 160 मराठा 2 अप्रैल 1882 बर्दे समाचार और जामे जमशद 10 मार्च (आर० एन० पी० बग, 11 मार्च 1882) अरुणोत्थ नेटिव ओपीनियम रास्त गुप्तार और इंडियन स्पेक्टेटर 12 मार्च (वही 18 मार्च 1882) सोम प्रकाश 13 मार्च (आर० एन० पी० बग 18 मार्च 1882) सुलभ समाचार और वगवासी 18 मार्च (वही 25 मार्च 1882) साधारणी 19 मार्च (वही 1 अप्रैल 1882)
- 161 ए० वी० पी० 16 मार्च 1882 भारत मिहिर 14 मार्च सत्कर 15 मार्च नवविभाकर 20 मार्च (आर० एन० पी० बग० 25 मार्च 1882) चाम्बल और आनंद बाजार पत्रिका 20 मार्च बिहार बंधु 30 मार्च (वही 1 अप्रैल 1882) परिदशक 26 मार्च (वही 8 अप्रैल 1882) अखबारे आम 12 अप्रैल (आर० एन० पी० पी० एन० 19 अप्रैल 1882) रहवरे हिंद 24 अप्रैल (वही 26 अप्रैल 1882)
- 162 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 89 100 तथा देखिए पृ० 3
- 163 रिप० आई० एन० सी० 1885 पृ० 69 और 73
- 164 मराठा 25 जन० 22 मार्च 1885 शिवाजी 23 जनवरी जामे जमशद 29 जनवरी (आर० एन० पी० बग 31 जन० 1885) नेटिव ओपीनियम और इंडियन स्पेक्टेटर 22 मार्च (वही 28 मार्च 1885) हिंदू 3 अप्रैल 1885 स्वदेशमित्र 18 जनवरी (आर० एन० पी० एम जनवरी 1886) वगवासी 2 और 23 जनवरी (आर० एन० पी० बग० 9 और 30 जनवरी

- 165 देखिए पाठ पाठटिप्पणी सत्या, 100 उदाहरणार्थ ट्रिब्यून 1 मई (बी० ओ० आई०, मई 1886)
- 166 एल० सी० पी० 1888 खंड XXVII, पृ० 20
- 167 धामन पूर्वोद्धृत पृ० 498
- 168 मराठा 22 और 29 जनवरी 1888 हिंदू 25 जन० 1888, बंगाली, 28 जन० 1888 ए० बी० पी० 26 जन० 1888, नेटिव प्रेम बर्बई के रिपोटर ने 28 जनवरी और 4 फरवरी 1888 को समाप्त होने वाले सप्ताहा की रिपोर्टों में लिखा कि इस सप्ताह का लगभग सभी समाचारपत्रों ने नमक कर में वृद्धि के संबंध में यूनायिक् रूप में रोष प्रकट किया है और देखिए आर० एन० पी० बर 11 फरवरी 1888 सजीवनी, 21 जनवरी नवविभावर, साधारणी 23 जन० (आर० एन० पी० बर०, 28 जन० 1888) सुरभि आ पताका 26 जनवरी प्रियदधु और समय, 27 जनवरी बगबासी 28 जन० दाका प्रकाश 29 जन० (वही 4 फरवरी 1888), हिंदू रजिना 1 फरवरी जगतबासी 2 फरवरी प्रतिवार 3 फरवरी (वही, 11 फरवरी 1888) आर० एन० पी० एम० 31 जन० 15 29 फरवरी 1888 में उल्लिखित लगभग सभी समाचारपत्रों कोहेनूर, 28 जनवरी (आर० एन० पी० एन०, 31 जन० 1888), हिंदुस्तान 1, 2, 3 फरवरी, पत्रावी अखबार 4 फरवरी सुबोध सिंधु 1 फर० (वही 7 फरवरी 1888), अवध अखबार, 10 फरवरी (वही 14 फरवरी 1888) वायस आफ इंडिया के कार्यालय में प्राप्त समाचारपत्रों द्वारा अभियुक्त मन को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए उसने सप्ताह में लिखा कि अधिकांश नमक कर में वृद्धि के प्रति तीव्र विरोध प्रकट किया है बी० ओ० आई०, फरवरी 1888 नेटिव बोपी नियम 22 जनवरी इंडियन नेशन 23 जनवरी इंडियन यूनिफन 25 जन० पीपुल्स फ्रंट, 28 जन० (बी० ओ० आई० फरवरी 1888) बिहार हेराल्ड और ट्रिब्यून 11 फरवरी (वही माच 1888)
- 169 आर० एन० पी० बर 4 फरवरी 1888
- 170 वही 28 फरवरी 1888 इसी प्रकार महु स्वर वाले इंदु प्रकाश ने अपने 30 जनवरी 1888 के एक में चेतावनी देते हुए लिखा कहा जाता है कि जस लाड डलहौजी ने अधिवहन नीति अपना कर लाड बेनिग के लिए विद्रोह से जूझने का वातावरण तयार किया था उसी प्रकार लाड डफरिन भी भारतीय जनता पर विभिन्न करों की वृद्धि द्वारा अपने उत्तराधिकारी के लिए बना चिन बसा ही वातावरण तयार कर रहे हैं (आर० एन० पी० बर, 4 फरवरी 1888)
- 171 आर० एन० पी० बर 17 माच 1888
- 172 आर० एन० पी० बर० 4 फरवरी 1888 बर्बई के सत्य घोषक ने अपने 25 जनवरी 1888 के एक में टिप्पणी की कि इस प्रकार का अल्पम्य भुन करके लाड डफरिन ने भारतीय जनता की दृष्टि में अपने को घणा का पात बना लिया है (आर० एन० पी० बर, 28 जनवरी 1888) 22 जनवरी के एक में गुजरात मिस्र में ध्ययपूर्वक लिखा कि लाड डफरिन हम देश से बर्नाम होकर ही जाएगा भारतीय लोग उनकी अवहेलना करेंगे और भगवान ने प्रायना करें कि उन्हें शोधातिशात्र इस व्यक्ति से छुटकारा मिले ! (वही)
- 173 जोशी पूर्वोद्धृत पृ० 137 90 सरकार की नीति के अन्वय में असंतुष्ट उद्दिष्टों को घोरता की अन्वय और राज्य मन्त्रि आते जाते रहते हैं उनकी नीति भी बलबुली के समान दणभर के लिए दीप्त रहकर अन्त में सत्ता के लिए विनीत हो जाएगा परंतु कराडो दुधी और बेशप्रस्त भारतीयों का मन नहीं हो पाएगा सांविधानिक रूप से उन्हें बोलने का अधिकार प्राप्त नहीं परंतु उनमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अपने पर किए गए अन्याय और अत्याचार को चुपचाप महन

- कर ले' (वही प० 140)
- 174 प्रस्ताव सं० XV
- 175 रिप० आई० एन० सी० 1888 पृ० 179
- 176 वही प० 179 80
- 177 इंडियन मिरर 22 फरवरी (बी० ओ० आई० फरवरी 1888) सोम प्रकाश, 23 जनवरी (आर० एन० पी० बग० 28 जन० 1888), वन्दान सजीवनी 24 जनवरी सहचर, 25 जन० (वही, 4 फरवरी 1888)
- 178 1899 का प्रस्ताव III (i) 1890 का प्रस्ताव V, 1891 का प्रस्ताव VI (ए) 1892 का V (ए) 1893 का VII (ए), 1894 का XVI (ए) 1895 का XIX 1896 का VIII, 1897 का IV 1898 का XX 1899 का XIII 1900 का X 1901 का XIX 1902 का XII पूना सावजनिक सभा का 23 दिस० 1890 का नापन जे० पी० एस० एस० जनवरी 1891 (खड XIII सं० 3) प० 79 80 विभिन्न प्रांतीय कांग्रेसों ने भा अपने वार्षिक अधिवेशनों में इस प्रश्न पर विचार किया
- 179 नौरोजी, सी० पी० ए० पृ० 177 स्पेचेज प० 142 (उन्होंने नमक कर को किसी सभ्य देश में प्रचलित राजस्व पद्धतिया में सर्वाधिक क्रूर बताया) वाचा रिप० आई० एन० सी० 1890 प० 37 9 रिप० आई० एन० सी० 1895 पृ० 158 एस० एन० बनर्जी स्पेचेज III प० 160 एस० एंड टर्ग्यु० प० 312 रिपोर्ट आफ दि बंगाल नेशनल चंबर आफ कामर्स 1888 प० 34 राय पावर्टी पृ० 266-7, पी० ए० चारलू एल० सी० पी० 1896 खड XXXV प 84 2०5, जी० बी० जोशी पूर्वोद्धत प० 191 202 1136 जी० आर० एम० चितनधीस एल० सी० पी० 1899 खड XXXVIII प० 234, पी० ए० चारलू वही प० 243 और एल० सी० पी० 1902 खड XLI पृ० 118
- 80 उदाहरण के रूप में देखिए आई० एन० सी० 1890 प० 39 और रिप० आई० एन० सी० 1895 पृ० 151
- 81 उदाहरण के रूप में बंगाली 9 मार्च 1889 ओनामी अखबार 7 फरवरी (आर० एन० पी० पी 9 फरवरी 1889) कोहीनूर 5 मार्च (वही 9 मार्च 1889) मराठा 14 दिस० 1890 23 जन० 1891 हिंदू 10 जन० 1891 बंगाली 28 मार्च 1891 आर० एन० पी० बब 28 मार्च और 4 अप्रैल 1891 पसा अखबार 1 अप्रैल (आर० एन० पी० पी० 18 अप्रैल 1891) अखबारे आम 16 अप्रैल (वही 25 अप्रैल 1891)
- 82 रामगोपाल पूर्वोद्धत प० 45 47
- 83 स्वदेशमित्र 16 अप्रैल (आर० एन० पी० एम० 4 दिस० 1900) बंगाली 16 अक्टूबर 1901 भारत जीवन 17 फरवरी (आर० एन० पी० यू० पी० 22 फर० 1902) मोखले स्पेचेज प० 10 3 पी० ए० चारलू एन० सी० पी० 1902 खड XLI पृ० 118 9 हितवासी 4 अप्रैल (आर० एन० पी० बग० 12 अप्रैल 1902) आई० एन० सी० 1902 का प्रस्ताव XIII स्वदेशमित्र 17 जन० (आर० एन० पी० एम० 17 जनवरी 1903) 1902 की कांग्रेस में अध्यक्षीय भाषण करते हुए एस० एन० बनर्जी ने घोषणा की कि यदि करो म राहत दनी ही है तो विचारणीय तथ्य यह है कि कटौती के लिए किस कर को प्राथमिकता दनी चाहिए मुझे यह कहने में कोई सकोच नहीं कि नमक कर में ही सबसे प्रथम कटौती की जानी चाहिए (सी० ए० प० 703)

- 184 वाचा स्पीचेज, पृ० 434
- 185 आई० एन० सी० 1903 का प्रस्ताव VIII गोखले, स्पीचेज पृ० 38 40-1, श्रीराम तथा पी० ए० चारलू एल० सी० पी० 1903 खंड XLII पृ० 99 100 और 140-2, मराठा 22 मार्च 1903, हिंदू 18 मार्च 1903, बंगाली, 19 21, 25 मार्च 1903, कायस आफ इंडिया, 21 मार्च 1903 मद्रास स्टेट्स, 18 मार्च (बी० ओ० आई०, 28 मार्च 1903), इंदु प्रकाश, 19 मार्च, इंडियन मिरर, 20 मार्च, इंडियन सोशल रिफार्मर, 22 मार्च (वही, 4 अप्रैल 1903), एडवोकेट और यू इंडिया 26 मार्च (वही 11 अप्रैल 1903), आर० एन० पी० बंग, 21 28 मार्च 4 अप्रैल 1903 आर० एन० पी० बंग० 28 मार्च, 4 अप्रैल 1903 आर० एन० पी० एन०, 21 28 मार्च 1903, आर० एन० पी० यू० पी०, 28 मार्च 4 11 अप्रैल 1903, आर० एन० पी० पी० 28 मार्च 4 11, 25 अप्रैल 1903 में उल्लिखित समाचारपत्र
- 186 उदाहरण के रूप में हिंदू 18 नव० 1903 हिंदुस्तान रिव्यू और कायस समाचार, सितंबर 1902 गोखले स्पाइज पृ० 77 9 आई० एन० सी० 1904 का प्रस्ताव VIII (बी)
- 187 आई० एन० सी० 1905 का प्रस्ताव VII गोखले स्पीचेज पृ० 93 5 मराठा 26 मार्च 1905 बंगाली 28 मार्च 1905 आर० एन० पी० बंग 25 मार्च 1, 8 अप्रैल 1905, आर० एन० पी० बंग०, 1 8 अप्रैल 1905 आर० एन० पी० एम० 1 8 अप्रैल 1905 में उल्लिखित समाचारपत्र सिटीज 3 अप्रैल (आर० एन० पी० यू० पी० 8 अप्रैल 1905)
- 188 डॉ० पी० सर्वाधिकारी रिप० आई० एन० सी० 1890 पृ० 43 4 उन्होंने नमक कर में कटौती को मद्रास और बंबई की (बंगल) मांग बताते हुए उसकी आलोचना की दैनिक औ समाचार चंद्रिका 20 फरवरी (आर० एन० पी० बंग० 24 फरवरी 1894)
- 189 ए० बी० पी० 4 एम० 1902 12 जन० 23 24 मार्च 1903 27 मार्च 1905 उसके द्वारा प्रस्तुत नवीं म एक यह था कि नमक कर में किसी भी प्रकार की कटौती का लाभ निकपूल और बेगार के एक व्यापारियों को ही मिलेगा
- 190 नौगोजा पावर्टी पृ० 213-6 दि इंडियन सास्ट टकस जे० पी० एस० एस०, जुलाई 1881 (खंड IV म० 1) पृ० 59 61 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 91 नवंबर 24 जनवरी (आर० एन० पी० बंग 28 जनवरी 1888) मजावनी 28 जनवरी (आर० एन० पी० बंग० 4 फरवरी 1888), हिंदुस्तान, 1 2 3 फरवरी सुबोध सिंधु 1 फरवरी पंजाबी अखबार 4 फरवरी (आर० एन० पी० पी० एम० 7 फरवरी 1888) एस० एन० बनर्जी स्पीचेज III, पृ० 161 और सी० पी० ए० पृ० 703 वाचा रिप० आई० एन० सी० 1890 पृ० 38 पता अपवाद 1 अप्रैल (आर० एन० पी० पी०, 18 अप्रैल 1891) टाय पावर्टी पृ० 261 2 गोखले स्पीचेज पृ० 13 94 1890 के कायस अधिवेशन में इसी आपत्ति को चित्रात्मक भाषा में प्रकट करते हुए पत्रा के लाला मुरलीधर ने नमक कर का भूख और प्यास पर मानव जीवन पर बर् बताना (रिप० आई० एन० सी० 1890 पृ० 42)
- 191 प्रमाण के रूप में देखिए, ड्यूक आफ आरगिल का 21 जनवरी 1869 का सप्रथम जान स्टुवी तथा रिचार्ड स्ट्रुवा पूर्वोद्धत पृ० 222 3 पर नितन एन० सी० पी० 1878 खंड XVII पृ० 99 100 वेस्टने एल भी० पी० 1888 खंड XXVII पृ० 20
- 192 शशी पूर्वोद्धत पृ० 184 5
- 193 रिप० आई० एन० सी० 1888 पृ० 179 1890 के कायस अधिवेशन में यही तथ्य प्रस्तुत करते हुए मोहन चटर्जी ने आश्चर्यचकित होकर कहा 'जब उच्च पद प्रतिष्ठित और विलासिता की

गोद म लोटते हुए महानुभाव कहते हैं अरे गरीब आत्मी इसे महसूस नहीं करेगा ता हम यह बहुत दुःखदायी, बहुत निरुत्साहित करने वाला तथा बहुत हृदयद्रावक लगता है वस्तुन हमारे पास इस भूखता, नग्नता तथा स्वाधपरता को सही रूप में परिभाषित करने के लिए शान ही नहीं (रिप० आई० एन० सी०, 1890 प० 46) इसी प्रकार की अन्य टिप्पणिया के लिए देखिए, जोशी, पूर्वोद्धत प० 186 7 नोरोजी स्पीचेज परिशिष्ट प० 64 मालवीय स्पीचेज प० 30 1 राय पावर्टी प० 265 हिंदू 18 नवंबर 1903

- 194 रिप० आई० एन० सी० 1890 प० 36
- 195 वही प० 37 तथा देखिए वाचा को सी० एल० पारिख पूर्वोद्धत प० 345 पर
196. नोरोजी स्पीचेज परिशिष्ट प० 178 एल० ए० स्वामिनाथ अग्र्यर रिप० आई० एन० सी० 1885 प० 69 बर्बई व नागरिकों के द्वारा दिनांक 18 माघ 1888 को प्रस्तुत सावजनिक पापन, जे० पी० एस० एस० जन अप्रिल 1888 (खंड X स० 3-4) प० 18 बगानी 28 जन० 1888 इंडियन स्पेक्टेटर नेटिव ओपीनियन, 22 जन० इंडियन नेशन 23 जन० इंडियन यूनिन 25 जनवरी पोपुल्स फ्रड, 28 जन० (वी० ओ० आई० फरवरी 1888) बिहार हेराड ट्रिभ्यून 11 फरवरी (वही माघ 1888) स्वदेशमित्र 28 जन० (आर० एन० पी० एम० 31 जन० 1888) एन० पी० बरसे रिप० आई० एन० सी० 1888 प० 179 एल० एन० बनर्जी और एम० तथा ड्यू० प० 312 वादा रिप० आई० एन० सी० 1890 प० 37 और स्पीचेज प० 434 जी० एस० अग्र्यर बिलबी वमीशन खंड III प्रश्न 18762 मालवीय स्पीचेज प० 30-1 राय, पावर्टी प० 265 6 पी० ए० चारलू एल० सी० पी० 1902 खंड XLI प० 118 हिंदू 18 नवंबर 1903 नमक कर में वृद्धि से प्रभावित भारतीय जनता के दुर्भाग्य का सजाव चित्र खींचते हुए जी० के गोखले ने 1890 में घोषणा की कि इस वृद्धि ने अकाल की सीमा पर जीवन निर्वाह करने वाले निधन तथा अभावग्रस्त लोगों के भयंकर वृष्ट विषम दुःख गहन बाधा-ज और भारी कठिनाइयों को और अधिक बना दिया है जी० वी० जोशी ने इस विषय पर अपने विस्तृत लेख में इस तथ्य को सही प्रकार उजागर किया गोखले रिप० आई० एन० सी० 1890 प० 40 आई० एन० सी० 1895 की रिपोर्ट प० 150-1, स्पीचेज प० 11 95 जोशी, पूर्वोद्धत प० 83 105 137 90 191 202 विनाय रूप से देखिए प० 3 92 140 149 167, 185 7 195 1136
- 197 1888 का प्रस्ताव IV, 1895 का प्रस्ताव XIX 1896 का प्रस्ताव VIII 1897 का प्रस्ताव IV 1898 का प्रस्ताव XX (11 बी), 1899 का प्रस्ताव XIV (11 बी) 1900 का प्रस्ताव X (11 बी) 1901 का प्रस्ताव XIX (11 बी)
- 198 नोरोजी स्पीचेज परिशिष्ट प० 178
- 199 जे० पी० एस० एस० अप्रिल 1880 (खंड II स० 4) प० 30
- 200 सजीवनी 28 जन० (आर० एन० पी० अग० 4 फरवरी 1888) पूना में पारित प्रस्ताव ज० पी० एस० एस० जन० अप्रिल 1888 (खंड X स० 3-4) प० 31 जे० मुनाजियार रिप० आई० एन० सी० 1890 प० 46 गोखले स्पीचेज प० 40
- 201 जोशी पूर्वोद्धत प० 91
- 202 वही प० 185 तथा देखिए प० 149 प० 188
- 203 आरगिन के इयूज का 1869 का संप्रपण जान स्टुडी और रिचाड स्टुडी ए. ई. पर पाठनाशन स्टेटमेंट 1877 दूगरी और दो भगवूत वित्त मन्थ्य ई० बरिय ।



अपना यह सुविचारित मत प्रकट कर चुके थे कि नमक कर में किसी प्रकार की वृद्धि का परिणाम निम्नो पर भार में वृद्धि और नमक की खपत में कटौती होगी (एल० सी० पी०, 1882 खंड XXI पृ० 321-3 और एल० सा० पी० 1886, खंड XXVI पृ० 9-10)

204 एल० सी० पी० 1888 खंड XXVII पृ० 20

205 सत्य शोधक 5 सित० जगन्मित्र 6 सित०, पान प्रकाश 16 सित० (आर० एन० पी० बव, 18 सित० 1875) बंगला 23 अगस्त (वही, 3 सित० 1881), इंडियन स्पेक्टर 22 जन०, वेसल 24 जन०, शुभ सूचक 20 जन० (आर० एन० पी० बव, 28 जन० 1888), बंगाली और सजावती 28 जन० (आर० एन० पी० बव०, 4 फरवरी 1888), पंजाबी अखबार, 4 फरवरी मुबोध सिन्धु 1 फर० हिंदुस्तान 1 2 3 फर० (आर० एन० पी० पी० एन० 7 फर० 1888) पूना में सांघजनिक सभा द्वारा 18 मार्च 1888 को स्वीकृत जापन ० पी० एल० एल० जन अप्रैल 1888 (खंड X स० 3-4) प० 26-27 बाबा, रिप० आई० एन० सी० 1890 प० 37 और सी० एल० पारिध पूर्वोद्धत प० 382 पी० बनेडो रिप० आई० एन० सी०, 1890 प० 36 बंगाली 28 मार्च 1891 पंजा अखबार 1 अप्रैल (आर० एन० पी० पी०, 18 अप्रैल 1891) अखबारे आम 16 अप्रैल (वही 25 अप्रैल 1891) राम पावटी प० 264-5 ए० डी० उपाध्याय रिप० आई० एन० सी०, 1895 प० 151, 1902 की काग्रस का प्रस्ताव स० XIII इस विषय पर लोकप्रिय भावना के प्रदर्शनाय कुछ एवं अवतरण नाचे प्रस्तुत किए जा रहे हैं 1890 की काग्रस में पी० बनेडो ने दुर्घटित होकर कहा 'नमक की सस्ते दाम पर उपलब्धि न हो पान के कारण इस विशाल भारत देश के लाखों-करोड़ों पुरुषों स्त्रियों और बच्चा की इन दिनों आयु घट गई है उनका शरीर क्षीण हो गया है शारीरिक दुबलता के साथ साथ उनके मानसिक और नैतिक स्तर के विकास भी सुविधाओं में धूमिल पड़ गई है' (पूर्वोद्धत), 1895 की काग्रस में ए० डी० उपाध्याय ने शोक प्रकट करते हुए कहा 'आखिर हमन क्या बौन सा भयंकर अपराध किया है कि जिसके फलस्वरूप हमें यहाँ तक पर्याप्त नमक की अनपारिध का अवांछनीय दंड दिया जा रहा है (पूर्वोद्धत) अपने 31 जन० 1898 के प्रक० में तिलक के वेंसरी 7 लिखा 'बायसराय महोदय की अथवा विभिन्न अन्य महानुभाव की सलाह पर वित्त सदस्य न नमक की पूर्ति को घटाकर उचित हो पग उठाया है उसने अपने एक ही तीर से दो शिकार मार हैं एक ओर तो राजस्व की उगाही कर ली गई है और दूसरी ओर शासन के विरुद्ध अपन वैसा द्वारा निरपेक्ष उद्वेलक मचाने वाला को क्षीणकाय बना दिया है (आर० एन० पी० बव 4 फरवरी 1888)

206 जोशी पूर्वोद्धत प० 169-83

207 वही, प० 184

208 वही प० 187-8

209 वही प० 195-8

210 गांधी रिप० आई० एन० सा० 1890 प० 40 रिप० आई० एन० सी० 1895 प० 150 1 स्याचज प० 13 31 39-41 79

211 रि० 3 अप्रैल 1885 जाभा पूर्वोद्धत प० 90 824 इंडियन स्पेक्टर 22 जनवरी (आर० ए० पी० बव 28 जनवरी 1888) इंडियन नेशन 23 जनवरी (बी० ओ० आई० फरवरी 1888) हिंदू 25 जनवरी 1888 बाबा रिप० आई० एन० सा० 1890 प० 37 राम पावटी प० 263-4, साज उल्लेखवार 27 फरवरी 1890 (आर० एन० पी० पी०, 10 जन० 1891)

- 212 जागी पूर्वोद्धत, प० 92
- 213 वही, प० 93 9, 178 9 गोखले स्पीचज, प० 79 80
- 214 जोशी पूर्वोद्धत प० 97
- 215 वही प० 98 शुभसूचक न अपने 22 जनवरी के भ्रम म और रास्तगुप्तार न अपन 14 जनवरी के भ्रम मे इस प्रकार की आशकाए प्रकट की थी (आर० एन० पी० बब 20 जनवरी 1877)
- 216 जोशी पूर्वोद्धत प० 100 142 स्वदेशमित्रन 18 जनवरी (आर० एन० पी०, जनवरी 1886), पीछे पार्लियमन्ती सख्या 168 म निर्दिष्ट लगभग सभा समाचारपत्र आई० एन० सी० 1889 का प्रस्ताव सख्या III (1) नोरोजी सी० पी० ए० प० 177 8
- 217 जोशी पूर्वोद्धत प० 166 190, मराठा 22 जन० 1888 ए० बी० पी०, 26 जन० 1888 28 जनवरी 1888 को समाप्त होने वाले सप्ताह के बर्दे के लगभग सभी मगाचारपत्र रिपोटर का सार सक्षेप (आर० एन० पी० बब 28 जन० 1888) ट्रि-यूत 11 फरवरी (बी० आ० आई०, माच 1888) सजवनी 28 जनवरी (आर० एन० पी० बग० 4 फरवरी 1888) स्वदेशमित्रन 28 जन० 25 फर० (आर० एन० पी० एम० 31 जनवरी 29 फरवरी 1888), अमत बोधिनी 2 फरवरी (वही 15 फर० 1888) हिंदुस्तान 1 2 3 फरवरी सुबोध सिध 1 फरवरी (आर० एन० पी० पी० एन०, 7 फरवरी 1888)
- 218 जोशी पूर्वोद्धत प० 141 2 161 165 6 190 कसर हिन्दू 22 जन० (आर० एन० पी० पी० बब 28 जन० 1888)
- 219 एन० बी० बरवे रिप० आई० एन० सी० 1888 प० 179 इदु प्रकाश 30 जनवरी (आर० एन० पी० बब 4 फरवरी 1888), स्वदेशमित्रन 18 फरवरी (आर० एन० पी० एम० 29 फरवरी 1888) गोखले रिप० आई० एन० सी० 1890 प० 39-40, शशिलेखा 27 दिस० (आर० एन० पी० एम० 31 दिस० 1895)
- 220 पूना निवासियो द्वारा 18 माच 1888 को एक सावजनिक सभा मे स्वीकृत ज्ञापन ज० पी० एस० एस० जनवरी अप्रैल 1888 (खड X स० 3-4) प 17 जोशी पूर्वोद्धत प० 141, 189 तथा दधिए भागे अध्याय XII
- 221 रिपोटर का सार सक्षेप आर० एन० पी० बब 28 जनवरी 1888 कसरी 31 जन० (आर० एन० पी० बब 4 फरवरी 1888)
- 222 जोशी पूर्वोद्धत प० 199
- 223 गोखले स्पीचज प० 39
- 224 वही प० 79
- 225 आर० एन० पी० बब 28 जन० 1888
- 226 आर० एन० पी० बब 28 जनवरी 1888
- 227 आर० एन० पी० बग० 11 फरवरी 1888
- 228 जोशी पूर्वोद्धत प० 139
- 229 मुजर्जी और पेन्टि द्वारा नमत कर के समथन व लिए दधिए एन० सा० पा० 1888 खड XXVII प० 24 और 31 मुजर्जी ने घोषणा की कि माघ हा साथ यह एक नया साधन है जिनमे सवसाधारण को सामान्य सनोप मिल गया और जा दश व निप्रनतम व्यक्ति को जेव का भी उल्लेखनीय रूप से प्रभावित नहीं करेगा उनका कायबाही की आलोचना व लिए दधिए 9 फरवरी 1888 का गुजरात गजट जिसने निघा 'भूरता की यह परावाया है तुम क्या

जानो कि तुम किस तरह अधीन जनता का छून चूस रहे हो (आर० एन० पी० बव, 11 फरवरी 1888), 5 फरवरी 1888 के 'राज्यमन्त्र' ने भी एन० मुवर्जी को 'आद्रगर लाह इफरि' के सबेतेो पर नाचने वाली बठपुतली की सजा देत हुए टिप्पणी की कि मुवर्जी महोदय का स्वाप घणास्पद है और यह उसका देशद्रोही होने का प्रमाण है (आर० एन० पी० बव 11 फरवरी 1888) शान प्रकाश, 9 फरवरी, श्री शिवाजी 10 फरवरी और बर्दई व बहुत सारे अन्य समाचारपत्र (आर० एन० पी० बव०, 11 फरवरी 1888) वत पर 9 फरवरी, सुबोध सिध 8 फर० (आर० एन० पी० पी० एन० 14 फरवरी, 1888) जानी पूर्वोद्धत प० 143-4, 1867 स्वदशमित्रन, 18 फरवरी (आर० एन० पी० एम०, 29 फरवरी 1888) इत्यु० सी० बनर्जी का लेख बंगाली 25 अगस्त 1888 का घब म, मसानी पूर्वोद्धत प० 318 पर नौरोजी का कथन बाचा रिप० आई० एन० सी०, 1890 प० 38 मानवीय स्पीचेज, प० 278 30 एस० एन० बनर्जी एस० एंड इत्यु० प० 312 इसके बहुत समय पश्चात 1897 म जमा उन जलम ने अपने 28 मई के धक् म घटना का स्मरण करात हुए अपना रोप निम्नलिखित शर्तों म प्रवट किया 'नमक कर के मामले मे महामहिम की अपेक्षा पदविधों के भूध भारतीय ही वास्तव म अधिक दोषी हैं' एसा लगता है कि यह घोषेबाजी उह मात्के दूध का साथ घट्टी में पिलाई गई है वे देशद्रोही हैं बगल म एक राजा हैं जिन्हने नमक कर का जोरदार समपन किया है ऐसे लोग जिस भी देश म उत्पन हुए हैं और रहते हैं उस देश के ओर मानवता के नाम पर कलक रूप हैं, ऐसे लोगो को ता समुद्र मे फेंक देना चाहिए जब तक ऐसे घोषबाज इस देश मे जीते हैं देश कभी समद नही हो सक्ता (आर० एन० पी० एन० 2 जून 1897)

230 बर्दई के नटिव प्रेस के सवाददाता ने अपनी साप्ताहिक टिप्पणी म लिखा कि रास्त गुप्तार ओर सप्ताह का अन्य अनेक समाचारपत्र विधानसभाआ के वतमान दोषपूर्ण गठन की एक बार फिर शिवायत कर रहे हैं और उ हे वास्तविक रूप म अधिक लोक प्रतिनिधित्व का रूप देन की माग कर रहे हैं (आर० एन० पी० बव 11 फरवरी 1888) मराठा 18 फरवरी 1888 स्वदेश मित्रन 19 फरवरी (आर० एन० पी० एम० 29 फरवरी 1888) हिंदुस्तान 1 2 3 फरवरी (आर० एन० पी० एन० 7 फरवरी 1888) एस० एन० बनर्जी एस० एंड इत्यु० प० 311 2 स्पाचेज III प 137 161 बाचा रिप० आई० एन० सा० 1890 प० 38 लाला मुरलीधर वही प० 42

231 जोशी पूर्वोद्धत प० 144

232 मानवीय स्पीचेज प० 26-7 और 30-1

233 रिप० आई० एन० सी०, 1890 प० 36

234 रिप० आई० एन० सी० 1892 प० 67 और गोखले स्पीचेज प० 79 और जोशी पूर्वोद्धत प० 200

235 सी० पी० जान स्टुधी इडिया (1903) प० 165-6 जिन लोगो पर यह कर लगा है उन लोगो की बहुमस्या तो इस करके अस्तित्व तक से परिचित नही जनता तो शात ओर अप्रभावित रहती है अपनी आवाज गुना सक्ने बाल केबन अत्यसक्षयक सपनन बग ही उन बातो का जिनका उनके अपन जीवन पर कोई विभाव प्रभाव नही पडता, गला फाडकर समपन करत रहत है स्टुधी द्वारा स्थिति का अध्ययन या तो सबका सहा है परतु बवन एक बात गलन है जिनका उत्पन्न उगन नही किया उस समय भारतीय नेता भा अपनी आवाज गुना सक्न म समय का ओर उभने नमक कर का विरोध हा नही किया प्रस्थान उसने विरुद्ध बहुत हा उचा स्वर

- उठामा इस प्रकार उन्होंने भूख जनता की भावनाओं को बाधो दीं
- 236 एल० सी० पी०, 1882 खट XXI पृ० 290-1 1889 में उसने नम्र कर में किसी प्रकार की बढ़ती के अपने विरोध को दोहरामा और एक बार फिर उसने आय कर में राहत देने की यकालत की (एल० सी० पी० 1889 खट XXVII पृ० 141)
- 237 एल० सी० पी०, 1882 खट XXI पृ० 303-04
- 238 एल० सी० पी० 1888 खट XXVII पृ० 24 और आगे
- 239 रिपोर्ट आफ दि बंगाल नेशनल चैंबर आफ कामस, 1887 पृ० 23-4 तथा दखिए टिड्ड पट्टियाट 23 जनवरी (सी० ओ० आई०, फरवरी 1888)
- 240 रिपोर्ट आफ दि बंगाल नेशनल चैंबर आफ कामस 1889 पृ० 3-4 34 5
- 241 इपीरियल गजटियर आफ इंडिया (1908) खट IV, पृ० 276
242. कुल 664 बरौड राजस्व में से 4 86 बरौड मंदिरा पर उत्पादन शुल्क से ही समूल हुआ (वहा)
- 243 यह मामले में बठिनाई नहा होनी चाहिए कि नीलामी पद्धति का सबसे बड़ा दोष यह था कि इससे मन्त्रि के मूल्य में भारी बढ़ती की सम्भावना थी एकाधिकार का एकमात्र उद्देश्य यथा-संभव अधिकतम लाभ कमाना था बहुत सारे मामलों में यह पाया गया कि थोड़ी मात्रा में ऊंची कीमतवाली मन्त्रि का बिर्षी की अपेक्षा बड़ी मात्रा में थोड़ी कीमतवाली मंदिरा की बिर्षी से अधिकतम लाभ की सुरक्षित प्राप्ति हुई (बकील, पूर्वोद्धत प० 470)
- 244 पी० बनर्जी इंडियन टर्म्समन पृ० 482 5
- 245 बकील पूर्वोद्धत पृ० 477
- 246 उदाहरणार्थ मराठा 18 फरवरी 1883 29 सितंबर 1885 बंगाली 9 अप्रैल 19 अप्रैल 1887, इंडियन एगोसिएशन का बंगाल सरकार को प्रतिवेदन निका 15 नवंबर 1887 बंगाल पूर्वोद्धत, परिशिष्ट डी० एल० एन० बनर्जी ए नेशन इन मन्निंग, पृ० 93 7 दादाभाई नोरोजी के दृष्टिकोण के लिए दखिए मसानी पूर्वोद्धत प० 363 365 आई० एन० सी० 1888 का प्रस्ताव VII आई० एन० सी०, 1900 का प्रस्ताव XV पी० मेहता स्पीचज, प० 565 मातवीय स्पीचज, पृ० 381, मुरलीधर रिप० आई० एन० सी० 1890 पृ० 32 जी० गी० मित्रा रिप० आई० एन० सी० 1899 प० 77 9 गोखले स्पीचज प० 16 84 मंदिरापान की प्रवृत्ति के प्रति प्रारम्भिक भारतीय समालोचना के लिए देखिए इंडियन एगोसिएशन 1852 बी० बी० मजूमदार पूर्वोद्धत प० 486 पर और नेशनल सेन, साइफ एंड बकम पी० एस० बसु द्वारा संपादित (कलकत्ता 1940) पृ० 209 10
- 247 आई० एन० सी० 1900 का प्रस्ताव XV एम० एन० चौधरी रिप० आई० एन० सी० 1900 प० 86
- 248 लोकनेताओं और सस्थाओं के लिए दखिए इंडियन एगोसिएशन द्वारा बंगाल सरकार को 15 नवंबर 1887 को प्रस्तुत आपन पूर्वोक्त स्पल, आई० एन० सी० 1888 का प्रस्ताव VII और आई० एन० सी० 1900 का प्रस्ताव XV निरंक के मत को रामगोपाल ने उद्धृत किया है पूर्वोद्धत पृ० 72 3 217 तिलक प्रोसीडिंगज फ्राफ दि कौंसिल आफ दि बाब 1895 खट XXX प० 91 2 पी० मेहता स्पीचज प० 564 5 एस० एन० बनर्जी ए नेशन इन मेनिंग प० 381 मातवीय स्पीचज पृ० 381 गोखले प्रोमीडिंगज आफ दि कौंसिल आफ बाब 1901, खट XXXIV, पृ० 249 स्पीचज प० 16 83 4 वाचा रिप० आई० एन० सी० प० 140 और रिप० आई० एन० सी० 1890 पृ० 31, जी० सी० मित्रा, रिप० आई

सी० 1899 पृ० 77 9 समाचारपत्रों के लिए देखिए समाचार चंद्रिका, 8 अप्रैल (आर० एन० पी० वग० 17 अप्रैल 1880), सुलभ समाचार, 30 अक्टूबर (वही 6 नवंबर 1880) सोम प्रकाश 6 दिसंबर (वही, 11 दिस० 1880), ए० बी० पी० 24 नव० 1881 22 नव० 1883 और 2 अप्रैल 1885, मंगल मजदूरी, स० 4 (आर० एन० पी० एम० फरवरी 1882), साम प्रकाश 3 अप्रैल (आर० एन० पी० वग०, 8 अप्रैल 1882), सोम प्रकाश 3 अप्रैल (वही 5 मई 1883) भारत मिहिर 1 मई (वही 12 मई 1883) धगवासी 27 अक्टूबर (वही 3 नवंबर 1883) सगोधिनी 7 नवंबर, (वही 17 नव० 1883) परिदर्शन 11 नवंबर (वही 24 नवंबर 1883) मराठा, 17 मई और 29 सितंबर 1885 बंगाल के सभी पत्र-पत्रिकाओं ने इंडियन एसोसिएशन द्वारा 15 नवंबर 1887 को प्रस्तुत पापन का समयन किया देखिए आर० एन० पी० वग० नवंबर दिसंबर 1887, सजीवनी 7 14 अप्रैल (आर० एन० पी० वग०, 14 और 21 अप्रैल 1888) आर० एन० पी० वग० 22 मार्च 1890 25 अप्रैल 1891 में उल्लिखित सभी समाचारपत्र हिंदुस्तान, 17 और 18 जुलाई (आर० एन० पी० एन० 24 जुलाई 1889) भारत जीवन 1 जुलाई (वही 9 जुलाई 1895) स्वदेशमित्र 13 मार्च (आर० एन० पी० एम० 15 मार्च 1889) इंडियन पीपुल 26 मई (आर० एन० पी० यू० पी० 4 जन 1904) स्वदेशमित्र 2 दिस० (आर० एन० पी० एम०, 3 दिस० 1904) राष्ट्रवाणियों की कभी कभी अभिव्यक्त होने वाली हार्दिक भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति लाला मुरलाधर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1890 के अधिवेशन के सदस्य को संबोधित मापन के निम्न अवतरण में इस प्रकार से हुई है जहां पूर्व ने पश्चिम की गणित ज्योतिष तथा अन्य विज्ञानों की शिक्षा दी है वहां प्रतिदान में पश्चिम ने पूर्व को मुक्ति के बदले मदिरा के रूप में नरक-यातना दी है यहां तक कि हमारे मुस्लिम शासक भी मस्जिदों से घणा करते थे और मदिरा से प्राप्त आय को अभिशाप मानते थे यह ईसाई शासकों को ही समर्पित है कि वे इस प्यार करे उत्तम हो इस चूम चाटें और इसमें लाखा-कराडों पाँच धन कमाए क्या ऐसे मनुष्य भी सत्कार में हैं जो ईश्वर और परलोक पर विश्वास करने का ढाग तो रचते हैं परंतु ईश्वर द्वारा उनके अधीन किए लोगों के प्रति क्रूरता निदयता तथा योजनाबद्ध निममता का व्यवहार करते हैं? इस प्रकार ये लोग उस परमगिता के प्रति प्रत्येक प्रकार के पापमय और घणित आचरण करते हैं (रिप० आई० एन सी० 1890 प० 32 3)

249 248 की पाठटिप्पणी में उद्धृत प्रसंगों के अतिरिक्त उदाहरण देखिए आर० एन० पी० वग० 17 अप्रैल 30 अक्टू०, 27 नवंबर 1880 26 फरवरी 12 मार्च 16 25 जुलाई 1 अक्टू०, 26 नवंबर, 10 17 दिस० 1881 18 25 फरवरी 18 मार्च 15 जुलाई 1882 27 अक्टू० 10 17 नवंबर 1883 इंडियन मिरेर 20 नव० बंगाल पत्रिका ओपीनियन 13 दिस० (बी० ओ० आई० दिस० 1883) बंगाली 10 नवंबर 1883 9 अप्रैल और 19 नवंबर 1887 सजीवनी 30 अप्रैल (आर० एन० पी० वग० 7 मई 1887) बंगाल की प्रथम प्रांतीय परिषद का प्रस्ताव, 3 नव० 1888 के बंगाली में उद्धृत

250 1898 में पी० मेहता ने टिप्पणी की कि उत्पादन (एक्सचेंज) विभाग उस प्रकार के उदाहरण का अनुकरण कर रहा है कि जा यह कहता है कि वह अच्छे सिद्धांतों और आर्थिकों के प्रचार के लिए तो प्रतिबद्ध है परंतु उन सिद्धांतों पर आचरण करने के लिए किसी भी रूप में विवश नहीं है (एपीजे प 564) तथा दक्षिण, तिलक प्रोमीडिज आफ रि कौगिल आफ रि गवर्नर आफ बांग 1895 पृष्ठ XXX पृ० 92

- 251 ए० बी० पी०, 22 नवंबर 1883, वाचा रिप० आई० एन० सी०, 1888 प० 140 दैनिक औ समाचार चंद्रिका, 10 माच सहचर 12 माच (आर० एन० पी० बग० 22 माच 1890) जी० सी० मित्रा रिप० आई० एन० सी० 1899 प० 78-9 तथा देखिए केशवचंद्र सेन पूर्वोद्धत, प० 210
- 252 फाइनाणल स्टेटसमेट 1888 9 कडिका 65 तथा भारत सरकार का संप्रपण सख्या 166 25 जून 1887 उसी में उद्धत फाइनाणल स्टेटसमेट 1891 2 कडिका 38 1903 में लिखते हुए जान स्ट्रुची ने बल देकर कहा 1880 के पश्चात लगभग सभी ओर मदिरा की दुकाना की सख्या में और मदिरा की खपत में कमी हुई है इसे सामान्य रूप से लखा जा सकता है इंडिया (1903) प० 170
- 253 फाइनाणल स्टेटसमेट 1884-5 कडिका 37, फाइनाणल स्टेटसमेट, 1889 90 कडिका 22 फाइनाणल स्टेटसमेट 1891 2 कडिका 38 एडवड ला एन० सी० पी० 1901 खड XL प० 309 फाइनाणल स्टेटसमेट 1902-03 कडिका 91
- 254 जी० सी० मित्रा रिप० आई० एन० सी० 1899 प० 70 रामगोपात्र पूर्वोद्धत प० 217 पर तिलक गोखले स्पीचेज, प० 16 मालवीय स्पीचेज प० 380
- 255 1904 में डा० के० गोखले ने कहा था शिक्षा एक उपयोगी उपचार हो सकता है परंतु उसने प्रवृत्तन की प्रक्रिया का मद होना अनिवाय है मरे विचार में स्थानीय लोकमत को इस मन्ध में बधानिक भायता दी जानी चाहिए (स्पीचेज प 85)
- 256 आई० एन० सी० 1888 का प्रस्ताव VII 1889 का प्रस्ताव IV 1890 का प्रस्ताव IV 1891 का प्रस्ताव VI (सी) 1892 का प्रस्ताव V (सी) 1893 का प्रस्ताव III (सी) 1894 का XVI (सी), 1895 का प्रस्ताव XXII (बी) 1896 का प्रस्ताव XI (ए) 1897 का प्रस्ताव IV (ए) 1898 का प्रस्ताव XX (ए) 1800 का प्रस्ताव XV रानाडे एडमिनिस्ट्रटिव रिफार्मस इन बावे प्रेजीडेंसी केलाक पूर्वोद्धत प० 45 पर मराठा 18 फरवरी 1883 हिंदू 15 जुलाई 1885, बी० एन० मासिक, स्पीचेज प० 579 वाचा रिप० आई० एन० सी० 1888 प० 140 और रिप० आई० एन० सी० 1890 प० 31 प्रधान एंड भागवत पूर्वोद्धत प० 90 पर तिलक गोखले स्पीचेज प० 83 5
- 257 ए० बी० पी० 24 नव० 1881, नेटिव ओपानियन 26 अगस्त (बी० ओ आई० सित० 1883 स० 9 खड 1) नवंबर 18 नवंबर बगाल पत्रिक ओपानियन 13 दिस० (वहा दिसंबर 1883 सख्या 12 खड I), बगवासी, 21 मई नवविभाकर साधारणी 23 मई (आर० एन० पी० बग० 28 मई 1887) इंडियन एनोसिएशन का 15 नवंबर 1887 का नापन पूर्वोद्धत स्थल बगाली 5 और 19 नव० 1887 प्रथम प्रांतीय सम्मेलन का प्रस्ताव बगाली के 3 नवंबर 1888 के मन्ध में उद्धत ए० बी० पी० 21 फरवरी 1889 आई० एन० सी० का 1890-1900 के प्रस्ताव पीछे 256 सख्या पान्टिप्पणा में उद्धत रामगोपात्र पूर्वोद्धत प० 72 3 पर तिलक हिंदू 27 नव० 1890 वाचा रिप० आई० एन० सी० 1890 प० 31 एन० एन० बर्नार्डी सी० पी० ए० प० 290 गोपने स्पीचेज प० 84 5
- 258 देखिए पीछे पादटिप्पणा स० 249 में प्रस्तुत मन्ध
- 259 आई० एन० सी० 1890 का प्रस्ताव स० IV
- 260 केलाक पूर्वोद्धत प० 45 पर रानाडे का दृष्टिकोण सोम प्रकाश 13 फरवरी (आर० एन० पी० बग० 18 फरवरी 1882) मराठा, 18 फरवरी 1883 समय 26 जन० (आर० एन० पी०

- वग० 31 जन० 1885), बगवासी 30 अप्रैल (वही 7 मई 1887) आई० एन० सी०, 1890 का प्रस्ताव IV विलक प्रोसीडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बाव 1896 छड XXXIV प० 117 आई० एन० सी० 1990 का प्रस्ताव XV
- 261 आई० एन० सी० 1899 का प्रस्ताव IX तथा समाचार चंद्रिका, 8 अप्रैल (आर० एन० पा० वग० 17 अप्रैल 1880), सुलभ समाचार, 30 अक्टू० (वही 6 नवंबर 1880) मोडर्निक, (स्पीचेज प० 584 मराठा 18 फर० 1883, समय, 26 जनवरी (आर० एन० पा० वग० 31 जन० 1885) आई० एन० सी० 1890 का प्रस्ताव स० IV विलक, प्रोसीडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ गवर्नर आफ बाव 1895 छड XXXII प० 92, गणले वही 1901 छड XXXIX प० 249 इस संबंध में गोखले ने एक रोचक तथ्य का निवृण किया कि जब तक शराब मिलने की संभावना में बढ़ती नहीं की जाती तब तक मन्दिर जमे पत्थरों के मूल्यों में वृद्धि का अर्थ दरिद्र उपभोक्ता की जड़ की हटका करना ही होगा तिनका महोत्प ने सा यह तब कह डाला कि यदि लोग अपने पियबबड ही हैं तो फिर मन्दिर के मूल्यों में वृद्धि करने में कोई तुक नहीं
- 262 हमारे अध्ययन का नवी अवधि में 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह माग बेमन से उस समय प्रस्तुत की जबकि उसने सरकार से अमरीका के प्रमुख मन्दिर कानून जत उपाया को अपनाते का अनुरोध किया परंतु उसी सात में उसने स्थानीय लोकमत और मन्दिर पर अतिरिक्त बराधान की भी बकालत की (प्रस्ताव XV)
- 263 मसानी पूर्वोद्धत प० 366 1891 में नितात परहेज (मन्दिरापान न करने) करने वाले भारतीय धात भाव वाले मय (इंडियन ब्रदरहुड आफ टोटल ऐक्स्टनस) का उद्घाटन करते हुए दादाभाई नौरोजी ने सुविचारित रूप से कहा था इसका एक अय महत्वपूर्ण तत्व यह है कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे मिलने में समय हुए हैं तथा सभी समुदायों को समान रूप से पुष्पभाषित करने वाले महान प्रश्न पर सुविचारित कायवाही करने का प्रस्तुत हुए हैं वही प० 365 6 तथा दधि एम० एन० बेनर्वा ए नेशन इन मेकिंग प० 94-07
- 264 इपीरियल गजटियर आफ इंडिया (1908) छड IV प० 275 और वकील पूर्वोद्धत, प० 603
- 265 इपीरियल गजटियर आफ इंडिया (1908) छड IV, प० 275
- 266 वकील पूर्वोद्धत प० 492
- 267 इपीरियल गजटियर आफ इंडिया (1908) प० 245 6 अफीम के हातिप्रद प्रभाव के संबंध में बमीशन की राय थी कि भारत में अफीम के मयत प्रयोग को उसी रूप में सेना जिन रूप में इंग्लड में मन्दिर के मयत प्रयोग का लिया जाता है अफीम हातिप्रद है, हातिरहित है और यहाँ तक कि अफीम लाभप्रद भी है यह सब उस परिस्थिति और उल विवेक पर निभर है जिसके धतगत इसका उपयोग किया जाता है (वही प० 246)
- 268 ई० बेरिंग फाइनांशल स्टेटमट 1882 बडिका 146-73 1893 में इविड बारबर का अफीम के लिए निपुक्त शाही बमीशन के समथ साय बकाल पूर्वोद्धत प० 49 पर तथा देविए चिसनी पूर्वोद्धत प० 328 30 जान स्ट्रेची इंडिया (1903) प० 154
- 269 कभवचन सेन पूर्वोद्धत, प० 210
- 270 नौरोजी पावर्टी प० 215 तथा दधि वही प० 201 स्पीचेज प० 142 तथा 192 3 मसानी पूर्वोद्धत प० 316 दादाभाई नौरोजी का था अफीम ब्यापार के संबंध में बहुत उपा नतिप धादन था जब उन्होंने 1855 में ब्यापारिक सस्थाओं के साथ ब्यापारिक गठबंधन किया तो

- उन्होंने उसी समय यह शत रख दी थी कि वे अपनी के व्यापार से होने वाले लाभ के भागीदार नहीं बनेंगे बाद में उन्होंने सचमुच ही अपनी तथा मदिरा से अर्जित लाभ में से अपना भाग लेने से इनकार कर दिया (नोरोजी, स्पीचेज पृ० 192 और मसानी पूर्वोद्धत पृ० 74)
- 271 और देखिए, रास्त गुफ्तार 12 जून (आर० एन० पी० बव 18 जून 1870), नेटिव ओपीनियन (वही 24 अगस्त 1872) बंगाली 3 जुलाई 1880 12 मार्च 1882 ब्राह्मो पत्रिका ओपीनियन, 26 मई 1881, हिंदू 5 दिस० 1884, मराठा 22 मार्च 1885 ए० बी० पी० 20 मई 1886, 16 फरवरी 1888, आद्य प्रकाशिका स० 19 (आर० ए० पी० एम० मई 1886) बगनिवासी 17 अप्रैल (आर० एन० पी० बग० 25 अप्रैल 1881) सजीवनी 26 अगस्त (वही 2 सित० 1893)
- 272 रिपॉट आफ दि इंडियन फमिन कमिशन 1880 भाग II पृ० 89 पी० बनर्जी इंडियन टक्सेशन, पृ० 314 तथा पीछे पादटिप्पणी स० 268 में उद्धृत अधिकारीगण
- 273 नोरोजी स्पीचेज, परिशिष्ट पृ० 41 तथा मसानी पूर्वोद्धत पृ० 316 दत्त ई० एच० II पृ० 155 इसक दूसरी ओर जी० बी० जोशी ने अभिस्वीकार किया कि अपनी लगान का भुगतान विदेशी उपभोक्ताओं द्वारा ही किया जाता है (पूर्वोद्धत पृ० 222)
- 274 बर्दई समाचार 29 जून (आर० एन० पी० बव 3 जुलाई 1875) जाम जमशद 19 फरवरी (वही, 22 फरवरी 1879), बर्दई समाचार 3 मई (वही 8 मई 1881) बाव त्रानिकल 8 मई (वही 14 मई 1881) आर्यावत 4 जून और शिवाजी 3 जून (वही 11 जून 1881) बंगाली 3 जुलाई 1880 भवविभाकर 29 मार्च (आर० एन० पी० बग० 3 अप्रैल 1880) नेटिव ओपीनियन 19 जून 25 दिस० 1881 मराठा 16 अप्रैल 1882 सुबोध पत्रिका, 22 जून (आर० एन० पी० बव 28 जून 1882), केसरी 2 मई (वही 6 मई 1882) नेटिव ओपीनियन रास्त गुफ्तार और बावे त्रानिकल 7 मई (वही 13 मई 1882) सहचर 25 जनवरी (आर० एन० पी० बग० 4 फरवरी 1882) समय 4 जून (वही 9 जून 1882) माघारपी 11 मई और नवविभाकर, 12 मई (वही 17 मई 1884), समाचार चंद्रिका 16 मई (वही 24 मई 1884), आनंद बाजार पत्रिका 2 जून (वही 7 जून 1884) मराठा 22 मार्च 1885 गुनरात दण 12 मई (आर० एन० पी० बव 18 मई 1889), नेटिव ओपीनियन 7 मई (वही 9 मई 1891), पूना वभव 6 सितंबर (वही 12 सित० 1891) मान प्रकाश 17 नव० (वही 19 नवंबर 1892) आफतावे पंजाब 27 अप्रैल और ताज उल अखबार 25 अप्रैल (आर० एन० पी० पी० 9 मई 1891) अखबारे आम 18 अगस्त (वही 29 अगस्त 1891) हिंदुस्तान 8 मई (आर० एन० पी० एन० 15 मई 1889) 'यामसिधु 22 अप्रैल (वही 30 अप्रैल 1891), सुबाध सिध 29 अप्रैल (वही 7 मई 1891), बंगाली 18 अप्रैल 1891, सहचर 15 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 25 अप्रैल 1891), बाका प्रकाश 26 अप्रैल और सुरभि औ पनाबा 17 अप्रैल (वही 2 मई 1891), सोम प्रकाश 8 जून (वही 13 जून 1891), हिंदू जनभूषणी 18 मई (आर० एन० पी० एम० 31 मई 1889) वनात पत्रिका 14 जून तथा मंगल के अच पत्रों की स्वीकृति (वही 15 दिस० 1893) ताज उल अखबार 5 अगस्त (आर० एन० पी० पी० 19 अगस्त 1893), कोटेनूर 9 सितंबर (वही 23 सित० 1893) दास्त हिंदू 13 अक्टूबर (वही 21 अक्टूबर 1893) पैसा अखबार 8 जून (वही, 16 जून 1893) विहार हराख 18 मई (आई० एल० बी० ओ० आई० 9 जून 1895) फोर्निक्स 8 मई (आर० एन० पी० बव 18 मई 1895, इंडियन स्पेक्टटर 12 मई 1895) कर्णाटक प्रकाशिका 30 अगस्त (आर०



एन० पी० एम०, 31 अगस्त 1897)

- 275 अफीम विरोधी आंदोलनकारी अग्रजों और लोकोपकारियों पर चोट करते हुए पत्रिका ने अपने 20 मई 1886 के प्रक म ब्यंगपूर्ण भाषा में लिखा वे भूल जाते हैं कि इंग्लैंड जैसे आक्रमणकारी और विजता देश को किसी देश को विप लने जसी साधारण सी घटना पर बड़बड़ाना नहीं चाहिए इतना तो असंदिग्ध रूप से तथ्य है कि अफीम की अपेक्षा चाहा और सिक्का किसी भी देश को अधिक शोभता और अधिक निश्चितता से विनष्ट करने वाला साधन है इसका साथ ही पत्र ने अपना मत प्रकट करते हुए लिखा अफीम राजस्व की दृष्टि पूर्ति के लिए भारतीयों पर कर लगान के लिए भारत सरकार को कहना चाहिए कि यह इस प्रकार का कृत्य होगा कि जहर देने के स्थान पर सरकार लूट का घधा अपनाने पर विवश होगी और देखिए ए० बी० पी०, 16 फरवरी 1888 और 17 अप्रैल 1891
- 276 ब्राह्मो पब्लिक ओपीनियन ने अपने 26 मई 1881 के प्रक म और अधिक दृढ़तापूर्वक लिखा कि भले ही अफीम लगान के जमाव में भी बजट में किसी प्रकार का असंतुलन न आने पाए फिर भी भारत जसा निधन देश अफीम राजस्व को हटाने का सामर्थ्य नहीं रखता
- 277 आर० एन० पी० बंग 18 मार्च 1882 मराठा ने अपने 22 मार्च 1885 के प्रक म में इन आंदोलनकारियों को 'अतिरिक्त प्रेष्ठ आदेशवादियों के सामाजिक संगठन की सना दी
- 278 हिंदू ने अपने 11 मई 1895 के प्रक म में और आगे लिखा अफीम एक भारी बुराई हो सकती है परंतु राष्ट्रीय दिवालियापन उससे बड़ी बुराई है
- 279 ए० बी० पी०, 9 जुलाई 1880 और 20 जुलाई 1886 ब्राह्मो पब्लिक ओपीनियन 15 जुलाई 1880, आनंद बाजार पत्रिका 2 जून (आर० एन० पी० बंग० 7 जून 1884) हिंदू 26 जनवरी 1885 9 दिसंबर 1890 3 जुलाई 1893 बंगाली 18 अप्रैल 1891
- 280 कलाक पूर्वोद्धत प० 45 पर तिलक, ए० बी० पी०, 9 जुलाई 1880 16 फरवरी 1888 ब्राह्मो पत्रिका ओपीनियन 15 जुलाई 1880 नेटिव ओपीनियन 19 जून 1881, मराठा 17 जुलाई 1881 23 अप्रैल 1882 22 मार्च 1885 दि इंडियन साल्ट टक्स ज० पी० एस० एस० खंड IV स० 1 जुलाई 1881 प० 61 बंसरी 2 मई (आर० एन० पी० बंग० 6 मई 1882), गान्धारणी 11 मई और नवविभाकर 12 मई (आर० एन० पी० बंग०, 17 मई 1884) समाचार चंद्रिका 16 मई (वही 24 मई 1884), सहचर 15 अप्रैल (आर० एन० पी० बंग० 25 अप्रैल 1891) सोम प्रकाश 8 जून (वही 13 जून 1891), सुलभ दैनिक 15 दिस० (वही 23 दिसंबर 1893) रहबरे हिंदू 28 सितंबर (आर० एन० पी० पी० 14 अक्टू० 1893) अखबारे आम, 31 अक्टू० (वही 4 नवंबर 1893) वतात पत्रिका 14 दिसंबर तथा अन्य पत्र पत्रिकाएँ (आर० एन० पी० एम० 15 दिस० 1893)
- 281 नवविभाकर 29 मार्च (आर० एन० पी० बंग० 8 अप्रैल 1880) नेटिव ओपीनियन 19 जून 1881 मराठा 16 अप्रैल 1882 और 7 दिस० 1893 बंसरी 2 मई (आर० एन० पी० बंग० 6 मई 1882) ममय 4 जून (आर० एन० पी० बंग० 9 जून 1882) गान्धारणी 11 मई (वही 17 मई 1884) टिडुस्तान 8 मई (आर० एन० पी० एन० 15 मई 1889)
- 282 आर० एन० पी० बंग० 30 दिस० 1893
- 283 आर० एन० पी० बंग० 31 जुलाई 1880 मराठा ने अपने 7 अगस्त 1881 के प्रक म टिप्पणी की निरसादेह चीन के साथ अफीम व्यापार बंद कर देना से भारतीय विज्ञान में चौड़ी धारें पड़ जाएगी परंतु 40 करोड़ लोगों को विप देने के आरोप सिर पर सेने की अनेका हम धारें की

करने के लिए अथ अधिक उपाय सोचना तथा विभिन्न विभागों के खर्चों में कटौती करना ही अधिक उपाय है' यों ही समय के उद्धार 12 मार्च 1832 के अधि में मराठा न मत् प्रकट करते हुए लिखा अफोम व्यापार जस गहित काय का निषिद्ध करो जसे नतिव और लाभप्र साधन म अपने रुपये के उपयोग मे किसी भी भारतीय को शिक्वा शिक्वायन नहा हागी इगी प्रकार सजीवनी ने 26 अगस्त 1893 के अधि म दावा किया 'पाप पूण व्यापार से अजित राजस्व से कोई भी सरकार फनती फूलती नही रह सकती यायप्रिय भगवान द्वारा सभी पापी अवश्य दंडित किए जाएंगे अत सरकार के लिए उचित यही है कि वह इस पापमय व्यापार को छोड दें (आर० एन० पी० वग० 2 सितंबर 1893) और देखिए सोम प्रकाश 19 जुलाई (आर० एन० पी० वग० 24 जुलाई 1880) इंडियन स्पेन्टर 7 अगस्त (आर० एन० पी० वग० 13 अगस्त 1881), हिंदू 5 सित० 1884 और 14 अप्रैल 1891 नौरोजी पावर्टो प० 215 स्पीचेज पृ० 196 और मसानी पूर्वोद्धत प० 359 362 पर हिंदुस्तानी 15 अप्रैल (आर० एन० पी० एन० 21 अप्रैल 1891) इंडियन मिगर् 15 अप्रैल और एडवोकेट 17 अप्रैल (आई० एस० बी० ओ० आई० 3 मई 1891), दि ऐंटी आपियम एलायंस मुवमट' ज० पी० एस० एस०, छठ XIV स० 2 अक्टूबर 1891 प० 6 16 अलात पत्रिका 16 अप्रैल (आर० एन० पी० एम० 30 अप्रैल 1891), रहवरे हिंद 16 और 20 अप्रैल (आर० एन० पी० पा० 25 अप्रैल 1891) बगनिवासी 17 अप्रैल और सजीवनी 18 अप्रैल (आर० एन० पी० वग०, 25 अप्रैल 1891) समय 24 अप्रैल (वहा 2 मई 1891)

नौरोजी स्पीचेज प० 194

नौरोजी पावर्टो पृ० 215

नौरोजी स्पीचेज प० 192 6

सीमा शुल्क से होने वाली शुद्ध आय 1875 6 म 2 5 करोड रुपये 1877 8 म 2 4 करोड रुपये 1882 3 म यह घटकर 1 1 करोड रुपये रह गई इसका अर्थ हुआ कि कर नीति म सुधार के पांच वर्षों म 1 4 करोड रुपये घट गई 1882 और 1893 की अवधि के बीच इसकी निम्नतम प्राप्ति 1884 5 म 0.8 करोड रुपये थी इस प्रकार कर नीति स सुधार के फनस्वरूप सीमा शुल्क म किसी भी एक अवले वष म होने वाली अधिकतम हानि दो करोड रुपये से कम की था जसम राजस्व स 1875 1898 के बीच म होने वाली शुद्ध आय 6 1 करोड रुपये था दक्षिण अफ्रीका पूर्वोद्धत, पृ० 596 और 603

## लोकवित्त II

सरकारी और गैरसरकारी दृष्टिकोणों में प्रमुख मतभेद का विषय है व्यय की दिशाएँ ।

बालगगाधर तिलक

भयकर बढ़ते सैनिक व्यय जैसा कोई भी अन्य विषय भारत देश का बुरी तरह से झकझोरने वाला नहीं ।

डॉ ई वावा

### व्यय

भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने कराधान के परिमाण तथा कर निर्धारण की पद्धति की जाच पटताल के साथ साथ उसके उपयोग पर भी विस्तृत विचार किया क्योंकि उनके विचार में करो से प्राप्त कुल रकम के समान कराधान के उद्देश्य और उनके वितरण का प्रश्न भी किसी रूप में कम विचारणीय तथा कम महत्वपूर्ण नहीं था । उन्होंने इस तथ्य को पूर्ण रूप में स्वीकार किया कि कर राजस्व के लोकहित में व्यय होने वाले रूप में अथवा करदाताओं को परोक्ष रूप से कर राजस्व लौटाए जाने के सम्भावित रूप में तथा कर राजस्व के अनुत्पादक निरर्थक और व्यर्थ के कार्यों में उपयोग किए जाने वाले रूप में बड़ा भारी अंतर था । इस कमीटी के आधार बनाने पर भारतीय नेता इस निष्पत्ति पर पहुँचे कि भारत सरकार की व्यय नीति अमतोपप्रद ही नहीं थी, प्रत्युत सवमाधारण के हितों के लिए क्षतिकारक भी थी । प्रथम, उन्होंने इस तथ्य को बड़े ही गंभीर रूप में लिया कि भारत के राजस्व का एक बहुत बड़ा भाग देग के भीतर खर्च न होकर दश के बाहर खर्च होता है इस प्रकार दश से राजस्व की निकासी हो रही है । उन्होंने निर्देश किया कि इस मस्य में भारत की स्थिति ब्रिटेन जैसे स्वतंत्र देग से जहाँ भले ही भारी कर लगाए गए हैं तथा भिन्न थी ।<sup>1</sup> इस विषय का विस्तृत विवेचन हमने निम्न अध्याय में किया है । यहाँ तो हम इतना संकेत करना है कि कुछ भारतीय नेताओं ने लोकवित्त की कुल बमूली की अपेक्षा व्यय की व्यावहारिक प्रमाणा के प्रति अधिक ध्यान दिया । इस प्रकार 1800 में दादाभाई नौरोजी ने अपना मत प्रकट करते हुए लिखा

‘इस समय वास्तविक प्रश्न, सभी प्रश्ना से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं कि 60,00,00 00 पौड या 100,000,000 पौड कैसे प्राप्त किए जाए। हो सकता है कि यह विषय भी आवश्यक हो परंतु अधिक आवश्यक और अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जनता से उगाही रकम जनता को किस प्रकार लौटाई जाए। 1887 में लिखे अपने एक पत्र में वह और भी अधिक सुस्पष्ट और मुखर थे भारत में कराधान की बुराई उसका परिमाण नहीं, यहाँ तक कि अक्षर के समय वसूल किए जाने वाले भूमि लगान जितना इस समय वसूल किए जाने पर भी उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजस्व के एक भाग की देश से निकासी ही दुर्भाग्यपूर्ण बुराई है।’<sup>3</sup> ‘अमृत बाजार पत्रिका’ ने भी अपने 22 फरवरी 1900 के अंक में इसी प्रकार की धारणा प्रकट की

यदि करो द्वारा उगाही धनराशि इस देश में व्यय की जाती है तो इस देश के वासी ऊँचे कराधान और उनके भुगतान से भी अपना को व्यथित अनुभव नहीं करेंगे परंतु यदि 25 करोड़ रुपये के मूल्य का इस देश का उत्पादन प्रतिवष इंग्लैंड को ही भेजना है जिसके बदले में इस देश को कोई लाभ नहीं मिलना है तो इस देश के वासी उनके कराधान का भुगतान करने में भी अपने को दरिद्र और असमर्थ अनुभव करेंगे।<sup>4</sup>

द्वितीय, भारतीय नेताओं ने देखा कि सरकारी खर्च की प्रकृति फिजूलखर्ची वाली है और उनका वितरण देश की आर्थिकता और जनता की परिस्थितियों और सच्ची आवश्यकताओं के अनुकूल और उनसे संबंधित नहीं है। उनका विश्वास था कि इनका और अधिक लाभप्रद तथा साध्य उपयोग किया जा सकता था। यूँ तो उनका यह निष्कर्ष सामान्यतया भारतीय वित्तों के व्यय की आलाचना ही करता था परंतु कभी कभी विशेषतः इन नेताओं में अर्थशास्त्र के पंडितों द्वारा इसे भली प्रकार पकड़ा और अपने विश्लेषण का आधार बनाया गया। इस प्रकार ‘अमृत बाजार पत्रिका’ ने अपने 30 मार्च 1882 के अंक में यह मत प्रकट किया कि देश की वित्त व्यवस्था की किसी भी रूप में जांच करने पर प्रथम प्रश्न यह उभर कर सामने आता है कि उगाही गई धनराशि में से कितनी इस देश पर खर्च की गई है और कितनी यो ही बरबाद की जा रही है? इस पत्रिका की दृष्टि में इसका उपयुक्त उपचार था, करो की राशि का उपयोग निश्चित रूप से केवल उन्हीं के लिए किया जाना चाहिए जिनसे वह वसूल की गई है। इस बात को स्वीकार करते हुए कि अंगरेजी शासन को कायम रखने का व्यय दायित्व भारत पर है, पत्रिका ने भारतीय वित्तों का सभी पक्षों, चेशायर माचेस्टर लंदन, मिल्ल सॉविस, मिलिट्री सॉविस, नौकरी करने वाले तथा साहमियों की इच्छापूर्ति के लिए प्रयोग किए जाने का अथवा इंग्लैंड के युद्ध अभियानों, आनमणा और दुष्कर्मों में सहायता देने के लिए प्रयोग किए जाने का विरोध किया। फिरोजशाह मेहता ने 1883 में देश भर में निर्मित सड़कें, पुलों, दवाखानों स्कूलों और पुस्तकालयों की उपयोगिता का स्वीकार करते हुए भी यह पूछा कि मालिक प्रश्न यह है कि क्या इन सुधारों में ससाधनों का व्यय आवश्यकता से अधिक तथा गलत दिशा में नहीं हुआ है? क्या इन ससाधनों का और अधिक साध्य तथा और अधिक लाभप्रद उपयोग नहीं किया जा सकता था? क्या देश की

वास्तविक आवश्यकताओं की जानकारी से इतनी भारी गलतियाँ सुधारी नहीं जा सकती थी।<sup>6</sup> 1895 में ववई विधान परिषद में अपने प्रथम वजट भाषण में वाल गगाधर तिलक ने यह सिद्धांत निघारित किया कि वजट के मूल्यांकन की वास्तविक कसौटी यह हानी चाहिए कि पिछले 25 वर्षों में राजस्व में कितनी वृद्धि हुई है और प्राप्त की भौतिक मपनता के लिए उस राशि का कितना अंश समर्पित किया गया है।<sup>6</sup> 1896 के अपने निबन्ध 'दि प्रजेंट फाइनाणियल पोजीशन में' 1883-4 के वर्षों से भारतीय खर्चों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने के उपरांत जी० वी० जोशी ने अपना मत प्रकट किया कि यदि देश का इतना भारी अतिरिक्त धन देश के आंतरिक विकास और प्रगति के उद्देश्यों पर खर्च किया जाना तो देश के लाखों करोड़ों लोग सतोष और जानद का उपभोग करते।<sup>7</sup> दादाभाई नौरोजी ने 21 मार्च 1896 को विलबी कमीशन का लिखे अपने पत्र में इस स्थिति का अत्यंत सुस्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।<sup>8</sup>

विलबी कमीशन के समक्ष जी० अपने प्रसिद्ध वजट भाषणों में सुस्पष्ट सद्धातिक रूप में राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने और उसके आधार पर भारतीय वित्तों के विश्लेषण करने का सारा दायित्व अकेले गोपालकृष्ण गोखले ने निभाया। 1897 में विलबी कमीशन के समक्ष तक करते हुए उन्होंने कहा कि खर्चों में वृद्धि, राष्ट्रीय वित्त के एक पक्ष के रूप में कोई विशेष गंभीर आपत्तिजनक नहीं। उन्होंने लोकवित्तों का मिद्धात निर्धारित करते हुए कहा 'इस संबंध में सभी कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि जिस क्षेत्र में व्यय में वृद्धि हुई है उसके उद्देश्य का स्वरूप क्या है? और लोकवित्तों के उस दिशा में किए गए खर्चों का परिणाम क्या निकला है?' उन्होंने यह स्वीकार किया कि पिछली बहुत सी दशाब्दियों में यूरोपीय देशों के व्ययों में वृद्धि हो रही है परंतु उनका कथन था कि वह वृद्धि भारत के खर्चों में हो रही वृद्धि से मौलिक रूप से बहुत भिन्न है। जहां उन देशों के बड़े खर्चों में उन देशों की सुरक्षा और शक्ति में वृद्धि की है, उन देशवासियों के ज्ञान और संपन्नता में वृद्धि की है वहां स्वेच्छाचारी शासन के प्रबंधों, दोषग्रस्त बंधानिक नियंत्रण के तथा विदेशी शासन के अतिनिहित दोषों के अंतर्गत भारत के निरंतर बढ़ते खर्चों में भारत में केवल हमारे ससाधन के निरंतर शापण में वृद्धि करने में सहायता की है, हमारा भौतिक प्रगति को अवरुद्ध किया है, हमारी प्राकृतिक सुरक्षा को दुबल क्षीण किया है तथा हम पर अपरिभाषित तथा अनिश्चित वित्तीय दायित्वों का बोझ लाद दिया है।<sup>9</sup> भारत के सावजनिक खर्चों तथा अन्य देशों के सावजनिक खर्चों में बीच एक अन्य मौलिक अंतर यह था कि जहां अन्य देशों में सावजनिक व्यय करणताओं के हितों में किया जाता है, वहां इस देश में दूसरों के हितों का पर्याप्त महत्त्व दिया जाता है और कभी कभी तो उन हितों को भारतीय हितों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार के उत्तराहरण के रूप में यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारतीय वित्तों को ब्रिटिश सर्वोच्चता के हितों का स्याई दावा की पूर्ति करनी पडती है। उह ब्रिटिश प्रभुत्व के पूर्व में विस्तार के हितों की देखभाल और भारत में निश्चिंत और मिलिट्री सवा में सलमन सूरापिया के हितों की सुरक्षा करनी पडती है। इसमें साथ ही गाय ब्रिटिश वाणिज्य व्यापारी तथा धनिक वर्गों के हित भारतीय सरकारों के हितों पर हावी हो जाते हैं।<sup>10</sup>

कराधान के प्रश्न के समान भारतीय नेता प्रायः यह तर्क करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचते थे कि भारत की निधनता और भारतीयों की वर भुगतान की अक्षमता के सदभ में सरकारी खर्चें भारत जैसे निधन देश के सगाधना और शक्ति व बाहर थे। मदनमोहन मालवीय ने 1889 में घोषणा की कि भारत की दरिद्रता के सदभ में खर्चों में वृद्धि न केवल अनुचित तथा अत्यायपूर्ण थी प्रत्युत निश्चित रूप में पाप वम भी थी। उन्होंने यह तो माना कि सरकारी खर्चों में वृद्धि अपने आप में कोई बुराई नहीं यह वृद्धि ता वस्तुतः स्वागत योग्य होती है परंतु यह तब होता है जबकि उमका परिणाम जनता की धन मपत्ति में वृद्धि के रूप में गामन आए। जैम कि इगलड में था परंतु इस दश का दुर्भाग्य तो यह है कि सरकारी खर्चें तो निरंतर वृद्धि जा रहे हैं जत्रकि दगावासिया की दशा दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है।<sup>11</sup> इसी तर्क का आधार बनाते हुए 1894 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दृढ़तापूर्वक कहा 'वित्तीय खर्चों की जाच पडताल स तब तक कोई परिणाम नहीं निरखेगा, जब तक उसमें भारतीयों की चाल वित्तीय मार का सहन करने की शक्ति की जाच पडताल का काय सम्मिलित न किया जाए।'<sup>12</sup> 1895-6 की इपी रियन लनिस्मटिव कौमिल में अपन भाषण में फिराजगह महता न भी इस दृष्टिकोण का विस्तृत विवचन किया। उन्होंने निर्देश किया कि व्यया की आवश्यकता ता एक तुलनात्मक गणना है। खर्चों की किसी भी विधिगत मद के लिए वित्तनी ही अधिन आवश्यकता क्या न हो, इस आवश्यकता की पूर्ति करते समय व्यय के नश्य और दिगाको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अतत करो का भार निधन किसानों का ही उठाना पडता है। इस कथन के उपरान अपन दृढ़ विश्वास का व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यदि समाज की वगूली केवल इमी ढग से ही की जानी है तो जिम खर्चों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए राजस्व वसूल किया जाना है अपन आप में भने ही विनना उपयुक्त, उचित तथा निर्विवाद सिद्ध क्या न कर दे उसका भुगतान देश के मसाधनों और शक्ति की सीमा के बाहर हं।<sup>1</sup>

पिछने बहुत सारे वर्षों की अवधि में उदत सरकारी खर्चों को सबथा अनुचित नितात हानिप्रद, यहा तक कि भारत की निधनता के लिए उत्तरदायी कारणों में से एक मानते हुए भारतीय नेताओं ने व्यापक स्तर पर सरकारी खर्चों में कटौती का समथन किया और उसके लिए आंदोलन किया। उन नेताओं ने यह घोषित किया कि भारत के आर्थिक तथा वित्तीय दोषों की निवृत्ति के लिए खर्चों में कटौती एक आवश्यक उपचार था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बडे हुए सैनिक व्ययों की पूर्ति के लिए अपन पहले ही अधिवेशन में अथ सावजनिक व्ययों में कटौती करने का सुझाव दिया।<sup>13</sup> कांग्रेस ने अपने 1887 के तताय अधिवेशन में वित्तीय कठिनाइयाँ पर काबू पाने के लिए खर्च में कटौती का सुझाव एक बार पुन दिया।<sup>14</sup> 1891 में कांग्रेस ने घोषणा की कि अनुचित रूप में बडे हुए सैनिक और नागरिक सेवाओं के खर्चें भारत की दरिद्रता के महत्वपूर्ण कारणों में से एक थे और सरकारी खर्चों में कटौती भारत की दरिद्रता के निवारण के माधनों में एक थी।<sup>15</sup> 1891 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकारी खर्चों और दरिद्रता व अकालों में सहस्रवध का तथा सरकारी खर्चों में कटौती को बार बार 1892, 1896, 1897, 1899, 1901 और 1904 में दोहराया।

1894, 1895 और 1897 में कांग्रेस ने अपने दृढ़ मत को पुनः बलपूर्वक दोहराया कि दशके दुर्दशाग्रस्त वित्तों में मुधार का एकमात्र उपचार सरकारी खर्चों में कटौती है।<sup>17</sup> 1885 में बनकत्ता में हुए अधिवेशन में राष्ट्रीय सम्मेलन ने सरकारी खर्चों में कटौती के लिए इसी प्रकार के सशक्त तक प्रस्तुत किए।<sup>18</sup> 'पूना सावजनिक सभा ने,' 'वावे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन'<sup>19</sup> 'मद्रास महाजन सभा'<sup>20</sup> A ने सरकारी खर्चों में कटौती के लिए 1886 में इस सत्र में सरकार को विस्तृत ज्ञापन दिए। जी० वी० जोशी ने अपने 1886-7 में प्रकाशित लेख 'ए नोट आन रिटेंचमेंट' में,<sup>21</sup> गोपालकृष्ण गोखले और टी० ई० वाचा न विलबी कमीशन के समक्ष प्रस्तुत अपने साक्ष्यों<sup>22</sup> में तथा रमेशचंद्र दत्त ने 1898 में इसी मांग को मुखरित किया।

यहां यह जानना कम रोचक नहीं होगा कि दादाभाई नौरोजी ने खर्चों में कटौती के सबंध में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। इसका कारण यह बताया जा सकता है कि उन्होंने भारत की निधनता के निवारण के लिए संपत्ति का उत्पादन बढ़ाने पर ही सारा बल दिया। उनका विश्वास था कि यदि राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाया जा सके तो भारत किसी भी व्यय की पूर्ति में समर्थ हो जाएगा।<sup>23</sup> अतः उन्होंने ऊंचे खर्चों का घटाने की आवश्यकता पर बल न देकर धन की निकासी को रोकने की आवश्यकता पर ही सारा बल दिया। यहां तक कि बड़े पैमाने पर यूरोपीयों को नौकरी देने की आलोचना भी उन्होंने इसी आधार पर की कि इससे दश से धन की निकासी होती है, न कि इस आधार पर कि इससे प्रशामन महंगा हो जाता है।

इस प्रकार सरकारी खर्चों के वर्तमान ऊंचे स्तर के बटु आलोचक तथा इन खर्चों में कटौती के प्रबल समर्थक होने के नाते राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकारी खर्चों के वास्तविक विकास की जांच के लिए तथा इन व्ययों का सीमित करने के ठोस तथा व्यावहारिक उपाय सुझाने के लिए सारी समस्या की छानबीन आरंभ की। व इस तथ्य से सहमत थे कि सरकारी खर्चों की ऊंची दर के कारण अनिवाय नहीं है अतः उनका उपचार किया जा सकता है।<sup>24</sup>

सरकारी खर्चों के सबंध में राष्ट्रीय नेताओं के दृष्टिकोण का एक अर्थ उल्लेखनीय तथ्य यह है कि उन्होंने इनके विवरण के प्रति कोई विशेष रूचि नहीं दिखाई। उनका मुख्य उद्देश्य व्यय मबधी भूत नीतियों तक ही सीमित था। इस प्रकार उदाहरण के रूप में 1895 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह मत अभिव्यक्त किया कि 'व्यय आयोग (एकम-पेंटीचर कमीशन)' की जांच पड़ताल का तब तक कोई उपयोग नहीं होगा जब तक कि इन व्ययों को नियमित करने वाली नीति की रूपरेखा की जांच-पड़ताल न की जाए।<sup>25</sup> इसी प्रकार दादाभाई नौरोजी ने त्रिलोकी कमीशन को बताया कि वे विभागीय खर्चों के विवरण की जानकारी के प्रति बोर्ड उत्सुकता नहीं रखते क्योंकि व्यय के समग्र प्रशासन का स्वाभाविक आधार पर स्थापित किए बिना इस प्रकार की जांच-पड़ताल केवल रोग के लक्षणों को दबाना मात्र होगा इंग्लैंड को दूर करना नहीं। उन्होंने कहा कि आवश्यकता तो इस बात की है कि उन सिद्धांतों की चर्चा की जाए जिनके अनुसार व्यय के स्तर टांच का संचालन होता है।<sup>26</sup> उन्होंने यह भी अनुभव किया कि गैर सरकारी लोग न

तो व्ययों के विवरण को समीक्षा कर सकते हैं और न ही व्ययों के सही आंकड़ा का गहरा अध्ययन कर सकते हैं क्योंकि इनके लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध ही नहीं होती। उन्होंने टिप्पणी की कि वस्तुतः उह तो यह भी नहीं मालूम कि व्यय के विवरण सम्बन्धित चीजों में प्रश्न पूछें? अतः य वेबन नीतियों की सामान्य स्वरूपों की आलोचना कर सकते हैं।”

### सैनिक व्यय

1880 से 1905 तक की अवधि में भारतीय बजट में खर्चों का सबसे बड़ा भाग सेना पर होने वाले खर्चों का था। 1881-2 में सेना पर जोर मना से सम्बन्धित व्ययों पर होने वाले सामान्य खर्चों की कुल वृद्धि राशि 17.88 करोड़ थी जो भारत सरकार के कुल व्यय का लगभग 41.9 प्रतिशत था। 1885 के पश्चात् प्रमुखतया वर्मा युद्ध, उत्तर-पश्चिम में रूस के आगे बढ़ने की आगवा समय समय पर सेना के सुधार और आधुनिकीकरण के लिए उठाए गए गए और इस मद में खर्च में किए जाने वाले भूतान में हुई विनिमय की हानि आदि कारणों से यह राशि और भी अधिक बढ़ने लगी। समीक्षाधीन अवधि में सेना पर होने वाले व्ययों में निरंतर और नमिक वृद्धि का इन कारणों से देखा जा सकता है। 1886-7 में यह राशि 19.41 करोड़ अथवा बजट के कुल युद्ध खर्चों का लगभग 42.4 प्रतिशत थी। 1891-92 में 22.57 करोड़ अथवा लगभग 45.4 प्रतिशत, 1901-02 में 23.55 करोड़ अथवा लगभग 45.2 प्रतिशत तथा 1904-05 में 30.2 करोड़ अथवा कुल युद्ध खर्चों का 51.9 प्रतिशत थी।<sup>2</sup> इसके अतिरिक्त भारत को रायल नेवी (शाही नौसेना) को देना की सामान्य जलयुग सुरक्षा का शक्ति निभान के लिए आर्थिक सहायता देनी पड़ती थी जिसकी राशि विविधता लिए रहती थी। 1869 में जहां यह राशि 70,000 पाउंड थी वहां 1900 में 1,00,000 पाउंड हो गई। इसके साथ ही भारत सरकार को स्थानीय रायल इंडिया मैरीन वा खर्च भी उठाना पड़ता था।<sup>3</sup> इसके अतिरिक्त युद्ध, विशेष अभियान तथा विशिष्ट सुरक्षा कार्य पर होने वाले विशिष्ट प्रकार के व्यय भारत भी सहन करने पड़ते थे। 1876-7 और 1902-03 में सैनिक प्रशिक्षण पर 22.2 करोड़ रुपये और विशिष्ट सुरक्षा कार्यों पर 4.5 करोड़ रुपये खर्च हुए।<sup>4</sup>

भारतीय नेताओं ने सेना पर होने वाले खर्चों पर प्रबल प्रहार किए तथा इस विषय पर एकमत होकर निरंतर और नियमित रूप से अभियान चलाए रखा। वस्तुतः हमारे अध्ययन के अनुरूप संपूर्ण अवधि में सेना संबंधी व्यय राष्ट्रीय आंदोलन के आक्रमण का सबसे प्रमुख लक्ष्य रहा है। यद्यपि इन नेताओं ने सेना संबंधी व्यय और उसके सभी पक्षों, धनराशि के साथ साथ उद्देश्य और उसके उपयोग किए जाने के ढंग आदि की तीव्र आलोचना की तथापि उनका ध्यान प्रमुख रूप से इस प्रश्न के प्राथमिक पक्ष पर ही रहा। उदाहरणार्थ, कुछ आर्थिक प्रश्नों से संबद्ध पक्षाधीन छोड़कर इन नेताओं ने सगठन कार्यक्षमता की समस्याओं तथा सशक्त नीति की 'यूनाधिक' रूप की। इस प्रवृत्ति का एकमात्र अपवाद सेना के भारतीयकरण की इच्छा थी। संक्षेप में भारतीय नेताओं ने यह घोषणा की कि भारत के वित्तों



प्रधान कारण तथा ऊँचे कराधान के अस्तित्व का कारण मिलिट्री के ऊँचे और निरंतर बढ़ते हुए व्यय ही थे। उनकी यह निश्चित धारणा थी कि जय तक अनावश्यक सना सवधी खर्चें इन्हीं प्रकार बढ़ते जाएंग अथवा इतने ऊँचे बने रहेंगे तब तक भारतीय वित्त में सुधार की कोई संभावना नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने पहले ही अधिवेशन से सैनिक व्यय में वृद्धि के प्रति विरोध प्रकट किया।<sup>30</sup> 1889 में कांग्रेस ने देश में सना सवधी व्ययों में वृद्धि की निरंतरता के ध्यान पर उसमें कटौती की आवश्यकता पर बल दिया।<sup>31</sup> 1891 में उसने अपना यह दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि देश की धार दरिद्रता का कारण वर्तमान सैनिक और नागरिक प्रशासन पर होने वाली फिजूलखर्ची है। इसमें भी सैनिक प्रशासन की फिजूलखर्ची विशेष चिंतनीय है।<sup>32</sup> परवर्ती वर्षों में कांग्रेस सेना के खर्चों में कटौती करना और उस कटौती को बनाए रखने की निरंतर और बार बार माग करती रही। राष्ट्रवादियों की जय सस्थाए भी समय समय पर इस प्रश्न का उठाने लगीं। 1885 में 'ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन', कलकत्ता की 'इंडियन एसोसिएशन', 'बावे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन', पूना सावजनिक सभा, मद्रास की 'महाजन सभा', कराची की सिंध सभा तथा सूरत की 'प्रजा हितवधक सभा' ने संयुक्त रूप से अगरेज मतदाताओं से 'भारत की अपील' शीर्षक से इंग्लैंड में इश्तहारों की एक सामान्य माला निकाली और उसका वितरण किया।<sup>33</sup> इश्तहार नंबर-9 का शीर्षक था '20 वर्षों में भारत के सैनिक व्ययों में 21 प्रतिशत की वृद्धि।' इसका अर्थ था कि जो सैनिक व्यय 1857 में 11 463 000 पौंड पर पहुंच गया था, वही 1884 में और अधिक बढ़कर 16,975 550 पौंड हो गया है, इसे आसानी से घटाकर 14 लाख पौंड किया जा सकता था।<sup>34</sup>

बहुत सारे प्रमुख राष्ट्रवादी लोकनेताओं ने सैनिक खर्चों की विस्तार से और तीक्ष्ण मन के साथ चर्चा की। डी० ई० वाचा निश्चित रूप से इस प्रश्न पर प्रमुख राष्ट्रवादी प्रवक्ता थे। इस विषय पर दिए गए उनके भाषणा और लिखे गए लेखों को यदि एक स्थान पर इकट्ठा किया जाए तो एक काफी बड़ा ग्रंथ तैयार हो जाएगा। 1885 में उन्होंने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित करते हुए 1871 में सेना पर किए जा रहे खर्चों में वृद्धि की समीक्षा की तथा इस घोर पातक के लिए सरकार को भत्सना की।<sup>35</sup> 1891 के कांग्रेस के अधिवेशन में एक अय विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने दबतापूर्वक कहा कि इस समय सेना के खर्चों में वृद्धि के प्रश्न के समान दुष्प्रभावक अय कोई प्रश्न नहीं। सेना पर हानि वाले व्ययों में वृद्धि तो देशवासियों की धर्मता को साए जा रही है।<sup>36</sup> उन्होंने अपने इसी दृष्टिकोण को परवर्ती वर्षों में बार बार दोहराया।<sup>37</sup> जी० बी० जोशी ने प्रथम अपने 1886 में प्रकाशित निबंधों 'ए नोट आन रिट्रिचमेंट और 'दि नैटिव इंडियन आर्मी' में देश के वित्तों पर बढ़ते हुए सैन्य व्ययों के घातक प्रभाव की जांच की।<sup>38</sup> उन्होंने 1886 में प्रकाशित अपने लेख 'दि प्रेजेंट फाइनांसियल पोजीशन' में विस्तृत सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर अपना आरोप दोहराया।<sup>39</sup> अर्थविज्ञ संघ व्ययों के विरुद्ध अभियान चलाए रखने वाले गापालशुष्ण गान्धे एक दूसरे राष्ट्रवादी नेता थे।<sup>40</sup> अनेक अय राष्ट्रवादी जननेताओं ने भी सरकार जादा खर्चों के साथ बढ़ते सैनिक व्ययों के विरुद्ध भाषण दिए तथा लेख लिखे।<sup>41</sup> इसी प्रकार

राष्ट्रवादी पत्र पत्रिकाओं ने भी सैन्य व्यय के विरुद्ध बराबर जोरदार आवाज उठाई और इन व्यय में कटौती की मांग के लिए दवाव डाला।<sup>4</sup>

भारतीय नेताओं ने मिलिट्री के खर्चों की आलोचना के लिए केवल उन खर्चों के विस्तृत आकार को ही अपना आधार नहीं बनाया प्रत्युत भारतीय संसदों की गूढ़ता पर विचार करते हुए उनके औचित्य को भी समीक्षा का आधार बनाया। उन्होंने इस सिद्धान्त पर बल दिया कि देश की सुरक्षा और सना संबंधी आवश्यकताओं को मिलिट्री के खर्चों के उपयुक्त आकार के निर्धारण की एकमात्र कमीटी मानकर देश की उन खर्चों का सहन करना ही क्षमता को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए।<sup>43</sup> अतएव उनका तर्क था कि इस समय देश में सैन्य सेनाओं पर जितना व्यय कर रहा है, वह उसकी सहनशक्ति के बाहर है।<sup>44</sup> कुछ लोगों ने तो यह तथ्य प्रतिपादित किया कि सैन्य खर्चों का इससे बढ़कर अधिक निम्नरीय पक्ष क्या हो सकता है कि भारत जैसा निम्नरीय देश अपने वाणिज्य राजस्व का जितना बड़ा भाग सना पर खर्च कर रहा है, उतना ता ब्रिटेन और जर्मनी ही सैन्य का मिलाकर विश्व के अपेक्षाकृत अधिक विकसित, अधिक संपन्न और सैनिक तानाशाह देश भी नहीं कर रहे।<sup>45</sup> उन्होंने यह तथ्य भी प्रस्तुत किया कि सैनिक खर्चों भारत के मारे विरुद्ध भूराजस्व को हजम कर जात हैं। उन्होंने इस तथ्य का प्रयोग इस महंग सैन्य सेनाओं के सैन्यतंत्र को भारत द्वारा बहन करने में उसकी अक्षमता के प्रमाण के रूप में किया।<sup>46</sup> भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सातवें अधिवेशन में डी० ई० वाचा ने टिप्पणी की कि 'दरिद्र विमानों का खून चूसा जा रहा है ताकि सैनिक बरभाक्का मजे उठा सकें, स्टार और मडल प्राप्त कर सकें।'<sup>47</sup>

भारतीय नेताओं के अनुसार भारत की आर्थिक क्षमता के बाहर सैन्य खर्चों का प्रत्यक्ष तथा वृद्धांतित निरूपित दुष्परिणाम यह हो रहा था कि सरकार एक ओर तो सना पर पानी की तरह खर्च बहा रही थी और दूसरी ओर राष्ट्र निर्माता विभागों पर बहुत कम खर्च कर रही थी। इस प्रकार देश की स्वस्थ आंतरिक प्रगति और आर्थिक विकास को धक्का लग रहा था। समस्या के इस तथ्य को प्रायः ही प्रबलता के साथ प्रस्तुत किया गया। उदाहरणार्थ, डी० ई० वाचा ने 1891 में चिंतित होकर आश्चर्य प्रकट किया यदि भारत का 54 करोड़ का बड़ा भारी अनावश्यक, सामान्य से अतिरिक्त और फालतू खर्च 5 वर्षों में बचाया गया होता तो भारत न जाने कितना सुखी सतुष्ट, कितना संपन्न तथा कितना उन्नत हो गया होता।<sup>48</sup> दस वर्षों के उपरांत उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा 'जनता के कल्याण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, देश के सभी जाति-सुधारों के मांग में प्रधान बाधा मिलिट्री के खर्च हैं।'<sup>49</sup> इसी प्रकार तिलक के केसरी ने अपने 15 अप्रैल 1902 के अंक में अपना मत प्रकट करते हुए लिखा 'धरेंद्र प्रशासन के मामलों में जनता के हितों का प्रति सरकार की उपेक्षा कर्त्तव्य का वास्तविक कारण भारत के बढ़ते हुए मिलिट्री के खर्च ही हैं।'<sup>50</sup> जी० के० गोपाल ने 1903 में इस तथ्य पर कि 1885-1898 की अवधि में सरकार द्वारा जनता से अतिरिक्त राजस्व के रूप में इकट्ठी की गई 120 करोड़ रुपये की धनराशि में से लगभग 80 करोड़ रुपये सेना द्वारा हर्ष लिया गया है। विनाश धनराशि में से सावजनिक शिक्षा के भाग में आधे करोड़ रुपये से भी

आई है शोक प्रकट करते हुए दृढ़तापूर्वक कहा कि जज हमारे राजस्व निरंतर बढ़त हुए मेना के उद्देश्यों की पूर्ति की ओर ही उ मुख किए जा रहे हैं तब राज्य द्वारा निजी बड परिणाम पर जनता की भौतिक समृद्धि तथा नैतिक प्रगति से सम्बंधित किसी सुदृढ जोर स्वाई प्रयाग की सभावना के लिए अवकाश ही नहीं।<sup>51</sup>

### ऊँचा सैन्य व्यय तथा सुभाए गए उपाय

भारतीय नेताओं ने अनुभव किया कि ऊँचे सैन्य व्ययों की वारी निंदा करना ही काफी नहीं है क्योंकि सरकारी अधिकारी इस तथ्य से तो इनकार ही नहीं करते कि ये खर्च उँचे हैं। उनका तब तो यह रहता है कि ये खर्च अनिवार्य हैं और भारत साम्राज्य की सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए इनमें किसी प्रकार की कटौती सम्भव नहीं। उदाहरणार्थ 1894-5 के विनीय विवरण पर हुए विवाद में जनरल त्रिवरणी ने सैन्य व्ययों के जालोचनों को उत्तर देते हुए कहा था

मैं निंदा प्रस्ताव देखे हैं मैं आरोप पत्र देने है मैं जोरदार वक्तव्य सुन हूँ, मैंने भारत सरकार से सजा घटाने की अपीलें भी देखी हैं, परंतु किसी व्यक्ति ने भी इस सम्बन्ध में कोई एक भी तर्क प्रस्तुत नहीं किया कि किस प्रकार उचित मात्रा में सैन्य व्ययों में कटौती की जा सकती है।

इस प्रकार लाड बजा के वायमराय काल में सैन्य व्यय उत्तरोत्तर बढ़ते बढ़ते आसमान पर पहुँच गए इनके बावजूद उसने 1901 में घोषणा की

मुझे इस तक से जरा भी क्षोभ नहीं पहुँचा कि सेना पर किया जाने वाला सैन्य व्यय निरर्थक है और इस धन का अधिक अच्छा उपयोग दस के आर्थिक विभाग की योजनाओं पर खर्च करके किया जा सकता है। मैं बड़ी प्रसन्नता से सारे राजस्व को ही विकास योजनाओं पर खर्च करने को प्रस्तुत हूँ परंतु मैं यह स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसा दुस्माहम नहीं कर सकता। देश को सुरक्षित रखने के लिए सना की आवश्यकता है और भारत को सुरक्षित नहीं माना जा सकता।<sup>52</sup>

इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय नेता सैन्य व्यय में वृद्धि के लिए उत्तरदायी तत्वों की जाँच पड़ताल करने और तन्मुरूप उपायों का सुझाने के लिए विवश हो गए। परंतु इस महत्त्व का ह्रास में लेकर भी इन नेताओं ने इस प्रश्न के व्यापक नीति सम्बंधी पक्षों के अध्ययन तब ही अपने का सीमित रखा। उन्होंने न तो कोई व्यावहारिक सुझाव दिए और न ही सरकारी पक्ष द्वारा पक्ष किए गए अपेक्षित तत्त्वों की प्रशासनिक विवरणों का अध्ययन किया।<sup>53</sup> इस दृष्टिकोण का स्पष्ट जोर युक्तियुक्त प्रतिपादन श्री ० ई० वाचा ने 1895 में उक्त समय किया, जब उन्होंने यह टिप्पणी की कि अधिकारी लोग सना के खर्चों के जानाचार्जों से रचनात्मक सुझावों की माँग तो इस प्रकार कर रहे हैं जैसे कि माना इन आलोचकों के पास सार्वभूमिक तथा विभिन्न विवरण उपलब्ध हैं और इनकी माँगता में उनके लिए सुझाव भेजना सम्भव है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की स्थिति में उस समय रचनात्मक पहल जान वाले सुझावों का भेजना सम्भव ही नहीं है। रचनात्मक प्रस्ताव दस किए जज हम अपेक्षित मामलों ही नहीं दी जानी तो हम बेचन समीक्षा ही कर सकते



हुई। यह घटना इस तथ्य का प्रमाणित करती है कि सेना में कटौती बड़ी आमानी से की जा सकती है।<sup>61</sup> सेना की अधिकता की व्यथना के उप सिद्धांत के रूप में नेताओं ने यह दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि जब कभी सेना की संख्या तथा उसकी क्षमता में सुधार के लिए कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी है, उन कदमों का अंतिम निष्पत्ति सुरक्षा से संचित विषयों के संदर्भ में नहीं हुआ है। सामान्य रूप से ब्रिटेन के शाही हिंदी की सुरक्षा और उत्तयन के विचारों को महत्व दिया जाता रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने 1903 और 1904 के अधिवेशनों में इस विचारधारा को बड़ी स्पष्टता तथा प्रबलता के साथ प्रतिपादित किया।<sup>62</sup> 1896 में विलीयम बर्मीन्गहम को भेजे अपने एक संप्रेषण में दादाभाई नौरोजी ने असाधारण प्रखरता तथा कटुता के साथ इस तथ्य को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया

वाम्भव में सारी यूरोपीय (अर्थात् भारतीय) सेना ब्रिटिश सेना का अविभाज्य अंग है। ब्रिटिश सेना द्वारा भारत को एक श्रेष्ठ प्रशिक्षण क्षेत्र के रूप में सम्मत्ता जाता है और उसी रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसी भी मूल्य पर अंगरेजों के नाभ, सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए तथा उनके देशवासियों के लिए आश्रित स्थल के रूप में एक ब्रिटिश साम्राज्य तथा यूरोपीय सम्मान की सुरक्षा की दृष्टि से ही भारत का उपयोग किया जाता है। भारतीय लोगों के साथ दारुणाकार व्यवहार किया जाता है। उन्हें मालिकों की चर्म उत्तति के लिए सारे खर्चों के भुगतान के सब गौरव का अनुभव करने का तो मिलता है परंतु सारे मामले में जरा सी भी जबान खोलने की अनुमति नहीं मिलती।<sup>63</sup>

इसी प्रकार गोखले ने अपना निश्चित मत अभिव्यक्त किया कि ब्रिटिश नीति एशियाई साम्राज्यों को हृदयपने की तथा यूरोपीय शक्तियों की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए भारतीय समाजों का प्रयोग करने की ही रही है।<sup>64</sup> बहुत सारे अन्य भारतीयों ने भी इसी उग्रता से खेप लिखे तथा भाषण किए।<sup>65</sup>

भारतीय नेताओं ने मांग की कि भारत की प्राकृतिक सीमाओं के बाहर के सब उद्देश्यों के लिए भारतीय साम्राज्य सेनाओं का उपयोग तथा ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सत्ता के लिए भारतीय राजस्वों का व्यय नहीं किया जाना चाहिए।<sup>66</sup> उन्होंने कहा कि शाही उद्देश्यों के लिए निश्चित भारतीय सेना के भाग विशेष के भरण पोषण का, भारत में स्थित सुरक्षित ब्रिटिश सेना का और शाही युद्धों में प्रयुक्त भारतीय सेना के व्यय का सारा भार ब्रिटिश सरकार को वहन करना चाहिए। ध्यानपूर्वक देखने से यह मन सबंध उपयुक्त तथा सम्यक्चित ही होगा।<sup>67</sup> जब ब्रिटिश सरकार ने 1903 में भारतीय नवतारा द्वारा अनुमोदित सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए दक्षिणी अफ्रीका में नियुक्त ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी के भरण-पोषण के व्यय के कुछ भाग का भुगतान भारतीय राजस्व में करने की योजना की घोषणा की तब उसे सुनकर भारतीय नेता तिलमिला उठे। उन्होंने बहुत दूरस्थ प्रदेश दक्षिणी अफ्रीका में गति स्थापित करने के लिए किए जा रहे सबके भारत का भारत के ऊपर उत्तयन की चेष्टा का एक घटनापूर्ण और निम्ननीय योजना घोषित की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि साम्राज्य के उद्देश्यों के लिए भारतीय धन को खर्च

करने का यह एक दूसरा उदाहरण था। उन्होंने अपनी भावनाएँ प्रायः तीखी और कठोर भाषा में ही अभिव्यक्त की। उदाहरण के रूप में 'एडवोकेट' ने अपने 23 जुलाई 1903 के अंक में लिखा था। भारतीयों की छाती से मांस के एक और बड़े टुकड़े को काटने के लिए मि० ब्रोडरिक ने अपना छुरा तेज कर लिया है।<sup>68</sup> 'इंडियन सोशल रिफार्मर' ने 19 जुलाई 1903 के अंक में भारत को लूटने की नीति के विरुद्ध विरोध प्रकट करते हुए भारतीय लोक नेताओं से कहा कि वे उस आदेश की सीधी सादी शब्दावली में इस घणित याजना की निंदा करें।<sup>69</sup> दादा भाई नौरोजी ने स्पष्ट शब्दों में प्लेटो के समान दार्शनिक भाषा में लंदन की सभा में उपस्थित लोगों से पूछा 'वे कान से कारण है और वे कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिन्होंने हमारे शासकों के मन को इतना अधिक कलुषित कर दिया है कि उन्हें ऐसा नीच और घृणित मुझाव देना पड़ा है?'<sup>70</sup>

भारतीय नेताओं ने यूँ तो अपना साँग ध्यान प्रायः सैन्य व्यय के नीतिपरक पहलुओं की सामान्य समीक्षा तक ही सीमित रखा। कुछ नेताओं ने अवश्य 1890 की अवधि में अग्रिम सीमा नीति के अपनाने के फलस्वरूप सैन्य व्यय में वृद्धि होने से पूर्व ही सैन्य-संगठन के पक्षों को विशेष रूप से आलोचना और सहायन का आधार बनाया।

सामान्यतः अधिकांश भारतीय नेताओं की आलाचाना में केवल अस्पष्ट और थोड़े से नेताओं की अभिव्यक्ति में सुस्पष्ट प्रस्तुत किया गया। पहला आक्षेप यह था कि भारतीय सेना जहाँ एक ओर अधिक खर्चीली है वहाँ दूसरी ओर अपेक्षित रूप से कुशल नहीं है।<sup>71</sup>

बहुत सारे भारतीय नेताओं ने यह सिद्ध करने के लिए तथ्य तथा आकड़े प्रस्तुत किए कि भारत में सेना का प्रति सैनिक मूल्य सारे विश्व से ही उच्चतम था। उन्होंने आकड़ा से सिद्ध किया कि यूरोप में जर्मनी के कुशलतम सैन्यतंत्र से भी भारतीय सेना का व्यय अधिक ऊँचा था। यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में हुए व्यय से भी यह व्यय अधिक ऊँचा था।<sup>72</sup> उन नेताओं के विचार में भारतीय सेना के महंगेपन के लिए कई तत्व उत्तरदाई थे। उनका कहना था कि 1859 की एकीकरण योजना, अल्प कालीन सेना पद्धति इंग्लैंड में भर्ती और प्रशिक्षण प्रणाली, इंग्लैंड और भारत के मध्य ब्रिटिश सेनाओं के परिवहन की पद्धति, अनुपयोगी सेवाओं का विकास तथा ब्रिटिश सैनिकों को पेंशन देने जैसी बातों ने भारत पर व्यय का गलत और अनावश्यक रूप से ज्यादा वित्तीय भार डाल दिया है इसलिए इन खर्चों को समाप्त करने की अवस्था उनमें कटौती करने की आवश्यकता है।<sup>73</sup> 1897 में विलीवली कमिशन के समक्ष अपना सामान्य प्रस्तुत करते हुए जी० के० गोखले ने भारतीय स्टाफ का पम्प सिस्टम पर बटु प्रहार किए। गोखले ने ब्रह्मता से टिप्पणी की कि सना में उन्नति की पद्धति सेनाओं की आवश्यकता के सम्म में नियमित नदों की गई प्रत्युत अफमरों के हितों को दखते हुए ही उभरा नियमन किया गया है। इसका अर्थ तो यह निकला कि सेना अधिकारियों के लिए ही अधिकारी सेना के लिए नहीं है। वास्तव में उनके धन का निष्पत्त यह था कि सना के अधिकारियों को उनके सेवा काल में तथा सेवा निवृत्ति के उपरान्त आवश्यकता में बहुत अधिक धन दिया जाता है।<sup>74</sup>

एकाध भारतीय नेताओं का तो यहाँ तब विश्वास था कि भारत स्थित ब्रिटिश सैनिकों के वेतन और भत्ते आदि एकदम अपव्यय थे। उदाहरणार्थ 'इंडियन स्पेक्टेटर' ने अपने 15 अगस्त 1860 के अंक में यह निदर्श किया कि यूरोप में किसी एक सैनिक पर लागू जाने व्यय की तुलना में भारत स्थित ब्रिटिश सैनिक पर व्यय पाँच गुना अधिक आता है। पत्र न टिप्पणी करते हुए लिखा

छगर्द की छुरी का चलाना तिलात आवश्यक हो गया है। निश्चित रूप से ही हम यह नहीं चाहते कि हमारे सिपाही बिनासिता का जीवन बिनाएँ। हम यह तो किसी भी रूप में नहीं देखना चाहते कि बोर ब्रिटिश सैनिक घटिया वस्त्र पहनें और घटिया भोजन खाएँ परंतु तागो की आशंका यह है कि वे यदि आवश्यकता से अधिक बढ़िया वस्त्र नहीं पहनाते तो भोजन अवश्य आवश्यकता से अधिक बढ़िया खाते ह। हमारा भी विश्वास है कि स्वदेशी सेना का मिलने वाला कुछ राशन की तुलना में ब्रिटिश सैनिक अत्यंत खिलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं।<sup>15</sup>

जब इंग्लैंड में हुई वतन वृद्धि के समाप्त भारत में ब्रिटिश सैनिकों के वेतन में भी 1902 में वृद्धि की गई तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके साथ-साथ जगज्जय नेताओं ने इस पत्र के विरुद्ध अपना अत्यंत सशक्त विरोध प्रकट किया।<sup>16</sup> यहाँ उल्लेखनीय है कि उस समय कुछ ने तो भारतीय सैनिकों के वेतन में वृद्धि की वजालत की और जब भारत सरकार ने 1895 में भारतीय सैनिकों का वेतन 7 रुपये से बढ़ा कर 9 रु० माह कर दिया तो उनमें से बहुत सारे नेताओं ने हफ्ता-पत्र समाचार के रूप में इस पत्र का स्वागत किया।<sup>17</sup>

कुछ भारतीय नेताओं द्वारा वचन का सुभाषा गया दूसरा उपाय था पत्रक अध्यायीय कर्मात्ता की समाप्ति, क्योंकि उनके वक्तव्य के अनुसार केंद्रीय शाही नियंत्रण के कारण सैनिकों के वेतन का मापकता निस्सार तथा नामशेष हो गई थी। उस समय तो उन्हें बनाए रखने का एकाग्र उद्देश्य बिना जाय के ही अधिकारियों का वेतन जुटाया था।<sup>18</sup> भारतीय नेताओं ने लाड निचनर की 1904 की सेना के पुनर्बिभाजन और पुनर्गठन की योजना का भी विरोध किया क्योंकि उसके साथ अतिरिक्त खर्च जुड़े हुए थे। उन्होंने माग की कि इस योजना का भार भारतीय राजकाय पर नहीं डालना चाहिए।<sup>19</sup>

साथ-साथ के प्रश्न पर निचनर का मतभेद<sup>20</sup> के प्रति भारतीय नेताओं द्वारा अपनाए गए दुर्निष्पेक्ष से यह अत्यंत स्पष्ट हो जाता है कि वे लोग जिस भीमा तब साथ व्यय में वचन के लिए कृत-मन्त्र थे। इस मतभेद का जिस पर कानून न स्वयं अपने वायव्य पद के भविष्य तक की दाय पर लगा दिया था, पता चलता कि 1905 में उस समय कानून, जब कानून द्वारा बनाए गए यूनीवर्सिटी एक्ट कलकत्ता प्रिविचालय में उमरो द्वारा लिए गए शीघ्रता भाषण तथा प्रयास के लिए गए विभाजन के कारण राष्ट्रवादी कानून के प्रश्न विरोधी बन गए थे। उन नेताओं के लिए अपनी धना के पात्र, जितने विरुद्ध ने प्रकट मण्य करत आरंभ थे, के विरोधी निचनर का समर्थन करना सहज और मानवीय दृष्ट्य ही था। परंतु उनके द्वारा कर्जन का किया गया विरोध निम्नी ध्वजिगत कारण से प्रेरित नहीं था प्रत्युत उनका मूल आधार राष्ट्रीयतावादी ही था,

अत उन्होंने प्रधान सेनापति की शक्तियों में वृद्धि द्वारा सैन्यव्यय में वृद्धि की सभावना की आशका से विचनरे और भारत सचिव के विरुद्ध सदैव कजन के पक्ष का समर्थन किया। हा, यह बात दूसरी है कि इन लोगो का यह समर्थन उत्साह शून्य था और कभी कभी तो उसका स्वर भी मद रहता था।<sup>85</sup>

बुद्ध भारतीय नेताओं के मत में भारत में सेना के ऊंचे खर्चों के लिए उत्तर-दायी एक अर्थ तत्व था, भारतीय सेना में महंगी ब्रिटिश सैनिक टुकडियों का अधिक अनुपात। इस कारण से तथा बहुत सारे अयाय कारणों से इन नेताओं ने सेना के भारतीयकरण की माग की।<sup>85</sup> हा, थोड़े-बहुत नेताओं ने यह अवश्य स्वीकार किया कि भारत सरकार की विदेशी प्रकृति के कारण उसके लिए भारत में एक निश्चित सख्या में ब्रिटिश सैनिकों का रखना एक प्रकार से अनिवार्य सा हो गया है परंतु उनका सुभाव यह था कि उन सैनिकों की सरया इतनी बडी नही होनी चाहिए, जितनी कि उस समय थी।<sup>85</sup> इसके अतिरिक्त बहुतो का तो यह भी तक था कि ब्रिटिश सैनिक टुकडियों की आवश्यकता विदेशी शासन को बनाए रखने के लिए है। अत उनका सारा खर्चा ब्रिटिश वित्तों को ही उठाना चाहिए। यदि सारा नही तो कम से कम भारत के माय इस खर्च का भागीदार ता बनना चाहिए।<sup>85</sup> उन्होंने भारतीय सैनिकों का अधिकारी बनने का अवसर देने से इनकार की भी आलोचना की तथा अनुभव किया कि यह अयाय आधारों के अतिरिक्त वित्तीय आधार की दृष्टि से आपत्तिजनक है क्योंकि ब्रिटिश अधिकारों भारतीय अधिकारियों की अपेक्षा अधिक महंग पडते थे। अत उन्होंने भारतीयों के लिए सेना की सवा म उच्च पदों के द्वार खोलने का अनुरोध किया।<sup>86</sup> यहा यह उल्लेखनीय है कि इस माग को उठाने के पीछे वित्तीय आधार बदाचित्त अपेक्षाकृत गौण कारणों में से एक था।

जी० वी० जोशी और जी० के० गोखले ने भी भारतीय सेना में किसी भी प्रकार की वालटियर पद्धति 'राष्ट्रीय देशरक्षक' सेना तथा रिजर्व सेना के अभाव में स्याइ सेना को युद्ध के लिए निरंतर तैयार रखने की नीति की आलाचना की। उनका कथन था कि इससे अयाय दुबलताओं के साथ दश में तपुसता की प्रवृत्ति पनपती है और दश के वित्तों का व्यर्थ दुरुपयोग होता है जिसके फलस्वरूप करदाता को अपन भुगतान के अनुरूप प्रतिदान नही मिल पाता है। उनका कथन था कि किसी देश की क्षमता का आधार सकटकाल में सैनिकों की सख्या में वृद्धि कर सकना होता है। जहा अर्थ देगों ने अपनी शांति काल की सेना में अल्पकालिक मूचना से ही अनेक समयों में अपक्षित वृद्धि कर ली है, वहा भारत एक भी बटालियन के विन्तार की सामर्थ्य नही रखता अकगणना की दृष्टि से खर्चों में वृद्धि के रूप में सेना में वृद्धि दिखा देना दूसरी बात है। इससे भारतीय पद्धति अकुशल और विनाशात्मक रूप से अपव्ययी तथा महंगी बन जाती है। दूसरी ओर उनका सुभाव यह था कि रिजर्व सेना की पद्धति को अपनाते में एक ता सरकार सेना की सख्या में बढती कर सकेगी और दूसरे इससे वित्तों का राहत मिलगी। उन्हेम नोय यह है कि इस सबका कुन मिलाकर देश की सशस्त्र सेनाओं की क्षमता पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नही पडेगा बल्कि उनसे इससे उमकी क्षमता में वृद्धि ही होगी।<sup>87</sup>

भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा इस दिशा में प्रस्तावित दूसरा पक्ष था, 111



पद्धति की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1886 में ही इस साधन को अपनाने की वकालत की थी और इसके उपरांत लगभग प्रतिवष उसने इस मांग को दोहराना जारी रखा।<sup>88</sup> इस मांग का प्रत्यक्ष प्रयोजन देश की सुरक्षा क्षमता में वृद्धि करना था परंतु इन पस्तावों पर बकनव्य देने वाले प्रायः ही इसके वित्तीय लाभों का ही गुणगान करने लग जाते थे।<sup>89</sup>

भारतीय राष्ट्रीय नेताओं का विश्वास था कि किसी भी अथ नत्व की अपेक्षा सीमावर्ती अभियान और उन अभियानों के लिए की जाने वाली तैयारियाँ ही सेना को बड़ी भारी सन्ध्या में बनाए रखने के तथा दुःसंप्रद व भारस्वरूप सैन्य व्यय के लिए उत्तरदायी तत्व थे। क्योंकि इन अभियानों का सबंध सरकार की सीमा नीति से था अतः भारतीय नेताओं ने इस नीति की विस्तृत रूप से भर्त्सना की तथा इस नीति को छोड़ने के लिए सरकार पर दबाव डाला।<sup>90</sup> इसके अतिरिक्त इन नेताओं ने मांग की कि यदि सरकार के लिए अग्रगामी सीमा नीति को छोड़ना संभव नहीं तो इंग्लैंड को या तो सारे का सारा अथवा उल्लेखनीय परिमाण में सन्धियों का भार उठाना चाहिए क्योंकि यह नीति प्रधानतया इंग्लैंड के सामाजिक लक्ष्य व हितों के लिए अपनाई गई है तथा इंग्लैंड ही इनसे प्रमुख रूप में लाभान्वित होता है।<sup>91</sup>

हम ऊपर हम बात का विवेचन कर चुके हैं कि किस प्रकार राष्ट्रवादियों ने यह मांग पनप की कि भारत के विदेशी युद्धों में भाग लेने के सारे अथवा आंशिक व्यय का, भारत स्थित ब्रिटिश सेना के भरण पोषण के व्यय के भाग का भारत की आवश्यकता से बड़ा चढ़ कर शाही उद्देश्यों के लिए हुए सैन्य व्यय का, सीमावर्ती अभियानों में हुए व्यय का तथा सामान्य रूप से इस प्रकार की अग्रगामी नीति के अपनाने से होने वाले व्यय का भार ब्रिटेन का उठाना चाहिए। अपने युग के कुछ प्रमुख नेता तो एक पक्ष और आगे बढ़कर यहाँ तक कहने लगे कि भारत के सामान्य सैनिक व्यय में ब्रिटिश कोष का अपना योगदान देना चाहिए। यह मांग इस अपील के साथ जुड़ी हुई थी कि भारत के समग्र प्रशासकीय व्यय में इंग्लैंड का अंशदान करना चाहिए।

इस विचित्र मांग के पीछे विद्यमान तर्क हम मांग से भी अधिक राक्षस हूँ तथा भारत में ब्रिटिश राज्य के उद्देश्यों के सबंध में राष्ट्रवादी नेताओं की गहरी जानकारी पर बहुत प्रकाश डालते हैं। निष्पक्ष रूप से राष्ट्रवादियों का तर्क यह था कि अंग्रेज भारत की सुरक्षा में इतनी अधिक रक्ति रसते हैं जितनी कि भारत स्वयं क्याकि अंगरेजों को भारत पर शासन करने से महत्वपूर्ण आर्थिक तथा राजनैतिक लाभ प्राप्त होता है। इस तर्क का प्रायः ही पलायन मुस्पष्ट तथा सुदृढ़ भाषा में प्रस्तुत किया गया है। 1893 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादाभाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया

ब्रिटेन के इतने गहरा व्यापक और महान हितों के साथ साथ महत्ता और महत्त्व अतिवायत पूर्वोक्त साम्राज्य पर निर्भर है और हमारे साथ अविच्छिन्न रूप में गठबंध है। क्या यह उचित है कि हमें सैन्य व्यय तथा बाह्यनीति के ब्रिटेन की इतनी महत्ता तथा प्रतिष्ठा और ममृष्टि का भार मूल्य दरिद्र भारतीय जनता की गदन पर नान



भावना न केवल हमारे शासकों को देश पर शासन करने को प्रोत्साहित करती है प्रत्युत निकृष्टतम सबटवालीन स्थिति का उपयुक्त और प्रभावी सामना करने के लिए सदैव नैतिक दृष्टि से उद्यत रहने की प्रेरणा भी देती है।<sup>96</sup> 'अमृत बाजार पत्रिका' ने भी अपने 6 सितंबर 1894 के अंक में इसी भावना का प्रतिबिम्बित करत हुए लिखा, भारतीय सेना के खर्चों में वृद्धि का कारण शासकों के मन में जनता के प्रति अविश्वास-भावना है। इसमें पूर्व पत्रिका ने अपने 3 सितंबर 1885 के अंक में यह मत प्रकट किया था कि भारतीयों के प्रति ब्रिटेन के इस अविश्वास को मध्य एशिया में रूस की गतिविधियों के प्रति ब्रिटेन के दृष्टिकोण के मदद में समझा जा सकता है। इस पत्रिका ने दावा किया कि अंग्रेज रूसिया से भयभीत नहीं हैं प्रत्युत उन्हीं इस बात का भय है कि रूसियों के पहुंचते ही इस देश के वासी ही उनके विरुद्ध नहीं जाए। अतः उनकी इच्छा रूसियों को भारत की सीमा में हजारों मील दूर रखने की है। 1897 में कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में श्री० शंकरन नैयर ने तथा 1903 में अपने वज्र-भाषण में श्री० के० गाखले ने भी इसी प्रकार की आलाचना अपनी सामान्य मूढ अभिव्यक्ति के माध्यम की।<sup>97</sup> विन्स्टी कमीशन के समक्ष जिरह के प्रश्नों का उत्तर देते हुए इस दृष्टिकोण को तीखी और मुस्पष्ट अभिव्यक्ति देने का श्रेय दादाभाई नौरोजी को है। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि भारतीय सेना में दो भारतीय सैनिकों की तुलना में एक ब्रिटिश सैनिक रखने का अनुपात इस भय का परिणाम है कि भारतीय सैनिकों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उनमें निरापराध रूप से पूछा गया कि क्या यह भय सैनिकों से है? उनका उत्तर था 'मेरा अभिप्राय भारतीय सैनिकों से है। ब्रिटिश सरकार का भारतीय सैनिकों से ही भय है।' अगले प्रश्न का उत्तर देते हुए वे पुनः अपने मुख्य विषय की ओर लौट आए और बाल यंत्रि आप यह मानते हैं कि यूरोपीय सैनिकों की एक निश्चित संख्या का होना आवश्यक है तो इसका कारण यह आशय है कि भारतीय सेना उपयुक्त ढंग से बांध नहीं करती।<sup>98</sup>

अविश्वास और भागी संघर्षों की नीति के एक विकल्प के रूप में इन नेताओं ने एक नई नीति अपना देने की बकालत की जिसके अंतर्गत देश की सुरक्षा को राष्ट्रीय आधार दिया जाए। भारतीय लोगों पर विश्वास तथा भरोसा किया जाए और भारतीयों को संपन्न तथा सतुष्ट बनाया जाए।<sup>99</sup> इसी प्रकार बहुतों का सुभाव था कि रूसी आक्रमण के विरुद्ध बचाव के लिए मङ्गी अग्रगामी सीमा सुरक्षा नीति अपनाने की अपेक्षा जनता की रक्षादारी तथा विश्वास का पाना अधिक बहुर और अधिक उपयोगी बकालत नीति है। उनमें अनुमान वास्तविक सीमा तो बफादार जनता का हृदय है और विन्स्टी आक्रमण न सुरक्षा का सर्वोत्तम उपाय आर्थिक सुधार और जाति का संतोष है।<sup>100</sup>

### अर्थनैतिक व्यय

भारतीय राष्ट्रवादों ने सामान्य व्यय के समान अर्थनैतिक व्यय के प्रति दृढ़ता अधिक बढ़ा और उग्र नहीं था। हा, वस्तु मार तथा नुकसान अर्थनैतिक व्यय में वृद्धि की जानेवाला अर्थनैतिक व्यय, परंतु उग्र अर्थनैतिक व्यय के विरोध में पाई जाने वाली तीव्रता और उग्रता का

प्रायः अभाव ही था। इस सबध में उनकी प्रज्ञान आलोचना यह थी कि विधेयत भारत जैसे निधन देश के लिए यहाँ का प्रशासन बहुत अधिक महंगा था। 1897 में इस दृष्टिकोण का संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हुए डी० ई० वाचा न लिखा 'एशियाई निधनता' लिए रहने वाले भारत जैसे एशियाई देश में पश्चिमी ढंग का प्रशासन चलाना वित्तीय-राजनीतिगत के प्रतिकूल ही है।<sup>101</sup>

भारतीय नेताओं के अनुसार प्रशासन के महंगपन का प्रधान कारण प्रशासन के उच्च पदा के लिए ऊँचे वेतन का ढाँचा है। वास्तव में असैनिक प्रशासन के विरुद्ध उनकी कदाचित्त यही अकेली महत्वपूर्ण शिकायत थी। स्वभावतः असैनिक प्रशासन के व्यय में कटौती के सुभाव इस पक्ष विशेष तक ही सीमित थे।

भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा असैनिक खर्चों में कटौती के लिए सुभाए गए उपायों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय था, सभी प्रशासनिक सेवाओं नगर, रेलवे, इंजीनियरी, मेडिकल डाक तार, पुलिस, लोक-कर्म, सीमा शुल्क आदि के वरीय पदा का और विशेषतः महान इंडियन सिविल सर्विस का भारतीयकरण इस सेवा पर व्यावहारिक दृष्टि से ब्रिटिश नागरिकों का एकाधिकार था और इसमें प्रायः स्पृहणीय वेतन पैगान और भत्ते आदि की व्यवस्था थी। यह विषय अपने आप में इतना अधिक विस्तृत है कि इस ग्रंथ में इसे समेटा नहीं जा सकता और साथ ही यह विषय हमारे अध्ययन क्षेत्र की सीमा से भी बाहर है। इसके अतिरिक्त यह राष्ट्रवादियों की मांगों में से एक है, जिन 1858-1905 की मध्यावधि में पनपत राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के अध्ययन में गलत रूप से बढ़ा-चढ़ाकर पक्ष किया गया है। फिर भी, 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण की अवधि में इस मांग के राष्ट्रवादी आंदोलन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण, व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त तथा समर्थित आधारफलक होने के कारण हम यहाँ इसका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण के लिए भारतीय नेताओं ने सुझाव दिया कि सवा में भारतीयों की वृद्धि जैसे प्रत्यक्ष पगों को उठाने के अतिरिक्त, आई० सी० एस० तथा जूनियर सेवाओं की भारत और इंग्लैंड में साथ-साथ ही परीक्षा की व्यवस्था करने तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आयु सीमा में वृद्धि करने जैसे कुछ एक परास्य प्रशासनिक पगों को भी उठाना चाहिए।

राष्ट्रीय नेताओं ने सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण की मांग सामाजिक और नैतिक लाभों के अनेक और विविध आधारों पर की। वे आचार थे, राजनैतिक जीवित्य, धर्म तथा विशुद्धता, 1858 में की गई 'प्रतिष्ठा' की पूर्ण प्रशासनिक क्षमता तथा प्रज्ञान में वृद्धि।<sup>102</sup> हमारा मकसद इस विषय में केवल आर्थिक आधारों से है और इन्हीं आधारों के प्रायः पूर्वापेक्षा सर्वाधिक व्यापक प्रमुखता तथा महत्ता प्राप्त होने का विश्वास किया जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रवादियों की प्रशासनिक विभागों में यूरोपियों के प्रभुत्व से संबंधित आर्थिक-आलोचना दोधारी थी। एक ओर तो उन्होंने यूरोपियों की समस्या में अधिकता पर यह आरोप लगाया कि इससे देश की सर्पत्ति की निकामी हानी है क्योंकि यूरोपीय अधिकारियों द्वारा विपुल राशि में प्राप्त किए जाने वाले वेतन और पेंशनों का निर्यात कर दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि देश का दृष्टिगत

का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर उनका अभियोग यह था कि यूरोपियों का ऊँचे स्तर पर दी जाने वाली वेतन राशि से सरकार के लिए आर्थिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। यहाँ विवेचन के लिए हमें पुनः एक बार इस प्रश्न के इन दोनों पक्षों को पथक करना है। हम यहाँ केवल व्यय पक्ष का ही विवेचन करेंगे, धन की निकासी के पक्ष का हमें अगले अध्याय 'डेन' में ही विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय नेताओं में इन दोनों पक्षों के सबंध में अपने आप श्रम विभाजन हाँ गया था। उदाहरणार्थ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी माँग को सुदृढ़ आधार देते हुए न्याय, राजनैतिक औचित्य, प्रशासनिक कुशलता तथा 1858 के शासनपत्र में निहित व्यवस्थाओं को अपनाने की अपील की। दादा भाई नौरोजी, वाचा, दत्त तथा कुछ अन्य महानुभावों ने धन की निकासी पर अधिक बल दिया। 'अमृत बाजार पत्रिका', 'हिंदू', 'केसरी', 'मराठा', जी० वी० जोशी तथा अन्य बहुत सारे राष्ट्रवादी नेताओं ने मितव्ययी प्रशासन के प्रश्न पर बल दिया। इस प्रकार ये तीनों बग़ अपने-तकों को सवधापथक रूप में ही प्रस्तुत नहीं करते थे प्रत्युत बहुत बार वे तीनों प्रकार के तर्कों को मिला-जुलाकर भी उपस्थित करते थे।

भारतीय नेताओं द्वारा प्रस्तुत वित्तीय तर्क सार रूप में इस प्रकार थे। यूरोपीय ऊँची दर पर वेतन पाते हैं और बढ़ाचित उँचे ऊँचा वेतन मिलते रहना निश्चित ही है। अतः उच्च पदाँ पर विदेशियों की व्यापकता भारतीय प्रशासन के महंगपन का महत्वपूर्ण कारण है। इसके विपरीत दूसरी ओर क्योंकि भारतीय अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूप से कम वेतन पर नियुक्त किए जा सकते हैं अतः यूरोपीय अधिकारियों के स्थान पर भारतीयों को नियुक्त करके प्रशासनिक खर्चों का उल्लेखनीय रूप से नीचे लाया जा सकता है।<sup>163</sup> इस सद्बन्ध में आर्थिक पक्ष को कभी कभी नैतिक तथा राजनैतिक पक्षों से अलग करते हुए उस पर बल दिया जाता था। उदाहरणार्थ, अमृत बाजार पत्रिका ने 18 नवंबर 1886 के अपने अंक में सरपन के साथ, यह खरापन इस पत्रिका की अनेक महत्वपूर्ण तथा विविष्ट विशेषताओं में से एक उल्लेखनीय विशेषता उस समय थी, जब यह दादा भाई, शिशिर कुमार तथा मोतीलाल घाँप द्वारा संपादित किया जाता था, टिप्पणी की

ऊँचे वेतन वाले सभी पदों से भारतीयों को दूर रखने की सरकारी कायदा की अनैतिकता पर सरकार से ध्यान करना अथवा भारतीयों को बिना किसी प्रकार के राजनैतिक अधिकार दिए अधीनस्थ प्रजा बनाए रखने और इस प्रकार उनमें अमनोप पनपाने की राजनैतिक गलती करने की बात सरकार से करना भ्रम के आग वीन बजाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। अतः तुच्छ बातों की ओर ध्यान देने की अपेक्षा हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आर्थिक विषय पर ही डटा रहना चाहिए। (बल दिया गया)।

भारतीय नेताओं में अद्यत्तास्थिति में भी समस्या के मान्यनी विस्तरेण का प्रयत्न किया। 17 मई 1892 के सार्वजनिक विवरण का आधार बनाते हुए उन्होंने सगणता की कि 1000 रु० अथवा उससे अधिक प्रतिमाँ वेतन अथवा पेंशन पाने वाले यूरोपीयों का प्रतिव्यय दो

जाने वाली धनराशि 14½ करोड़ रुपये बैठती है, जो भारत सरकार के कुन शुद्ध राजस्व का 30 प्रतिशत है।<sup>104</sup>

सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण के पक्ष में प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत तर्कों के पीछे यह धारणा काम कर रही थी कि जब कभी एक भारतीय प्रशासनिक सेवा में किसी यूरोपीय का स्थान ग्रहण करता है तो उसे अपेक्षाकृत निम्न वेतन दिया जाना चाहिए। वस्तुतः राष्ट्रवादी मतव्य का आधार यह पूर्वानुमान ही था, परंतु यह एक पर्याप्त रोचक आश्चर्य है कि जिस निरंतरता के साथ इस मतव्य को ग्रहण किया गया, उस मतव्य के तथा उस मतव्य के प्रतिपादन के तुलनात्मक अध्ययन में यह स्पष्ट हो जाना है कि इसका खूबे आम प्रतिपादन अथवा प्रचार विरल ही हुआ। उसमें सबथा विपरीत कुछ भारतीय नेताओं ने जातीय समानता के तर्क को आधार बना कर यहां तक मांग करनी प्रारंभ कर दी कि प्रशासनिक स्थानों की प्रवृत्ति और उनके साथ जुड़े उत्तरदायित्वा के सदभ म ही वेतनों और सुविधाओं के निर्धारण का उचित पथ अपनाना चाहिए, न कि उन पदा पर आरुढ व्यक्ति विशेषों की राष्ट्रियता को किसी भी रूप में आगर बनाना चाहिए। उठाने यह भी मांग की कि भारतीय असैनिक सेवारत भारतीय व्यक्तियों को यूरोपीय व्यक्तियों के समान ही वेतन समान अवकाश तथा समापेशन आदि देकर इन सेवा की गरिमा और प्रतिष्ठा को बचाए रखना चाहिए। उदाहरणार्थ 'ब्रह्मो पब्लिक ओपीनियन' ने अपने 11 सितंबर 1879 के अंक में अगरेज असैनिक प्रशासकों को मिलने वाले वेतन अवकाश और पेंशन इंडियन सिविल सर्विस में नियुक्त कमचारियों को देने की मांग करते हुए एक नई जाति प्रथा चलाने का विरोध किया। पत्रिका के अनुसार यह प्रथा भारतीय प्रशासकों में हीन भावना की सृष्टि करेगी। इसी प्रकार सिविल सर्विस का वानूनी रूप देने की लिटन की याज्ञना के विरुद्ध प्रतिवाद तथा उसे निवारण की चेष्टा करते हुए बंगाली ने अपने 10 जनवरी 1880 के अंक में टिप्पणी की

भारतीय प्रशासनिक कमचारी तो एक ऐसा विचित्र जंतु है जिस यूरोपीय कमचारियों के लिए मोहक सम्मान, भविष्य तथा वेतना आदि से कुछ लेना देना ही नहीं। अपने यूरोपीय साथी की अपेक्षा वेतन, पेंशन, यश पदवी आदि की दिशा में तो उसकी स्थिति नितांत भिन्न है, परंतु समार में कोई भी सम्मानित और स्वतंत्रता प्रेमी व्यक्ति इस प्रकार के असम्मानित पद के प्रति आरुष्ट नहीं हागा और न ही इस प्रकार के स्थान को ग्रहण करने का तालक करेगा।

1886 में लोच सेवा आयोग को अपने प्रत्युत्तरों में वी० एन० माडलिन, फिरोजशाह मेहता और वी० जी० तिलक ने समान कार्य के लिए समान वेतन सिद्धांत की वपालन की।<sup>105</sup> इसके उपरांत 1898 में कांग्रेस के महापति ए० एम० बोमन और जी० के० गोखले ने वेतना के संबंध में भारतीय और यूरोपीयों में किसी भी प्रकार का भेदभाव चरतन पर तीव्र आपत्ति की।<sup>106</sup> दूसरी आर अमत बाजार पत्रिका 'हिंदू', 'स्वदामित्र', 'बेमरी', तथा अन्य अनेक ने खुबे आम तथा दडनापूर्वक भारतीयों का कम वेतन देने की चरतन की। उनका तर्क था कि इस प्रकार के त्याग के बिना आर्थिक आधार पर प्रशासन के भारतीयकरण का राष्ट्रवादिता का मारा मामना ही व्यव सिद्ध हो जाएगा। 17

सदभ में 'अमत बाजार पत्रिका' द्वारा अपनाई गई स्थिति का स्वयं उसी के शत्रु में अध्ययन अपने आप में पर्याप्त रोचक है। इस पत्रिका ने नवंबर दिसंबर 1886 की अवधि में प्रकाशित संपादकीय लेखमाला में भारतीयों को यह सुभाव स्वीकार करने की सलाह दत्त हुए लिखा कि जो प्रत्याशी भारत में हुई प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होते हैं, उन्हें नियमित वेतन का 2/3 भाग ग्रहण करने को प्रस्तुत होना चाहिए। अपने 18 नवंबर 1886 के अंक में इस पत्रिका ने लिखा यदि हम यूरोपीय लोगों के साथ समान वेतन पाने के लिए झगड़ते हैं तो इस अवधि में सरकार द्वारा सेवाओं के भारतीयकरण के उद्देश्य को ही हम समाप्त कर देते हैं। इस समय प्रश्न सही अथवा गलत के बीच चुनाव का नहीं। प्रत्युत हम 'भारतीयकरण' लेना है अथवा नहीं इसके बीच चुनाव का है। अपने 9 और 16 दिसंबर के अंकों में इस तक को सशक्त वाणी में प्रस्तुत करते हुए इस पत्रिका ने आगे बतकर लिखा सत्य यह है कि यदि भारतीय अपेक्षाकृत कम वेतन लेकर क्षमता तथा कार्यक्षमता का प्रदर्शन करेंगे तो इससे परोक्ष रूप से सरकार पर प्रशासनिक अधिकारियों के वेतनों में कमी करने का दबाव पड़ेगा। कम वेतन पाने वाले भारतीय कम-चारिया को सम्मान और लोक प्रतिष्ठा से हाथ धोना पड़ेगा, इस आपत्ति का उत्तर दत्त हुए पत्रिका ने जो लिखा वह एक जोर तो अवाल प्रौढ विचार है, और दूसरी जोर संपादक के मन में व्यापक रूप से उदार प्रजातांत्रिक विचारों के गहरी जड़ पकड़े होने का प्रमाण है। पत्रिका ने लिखा

हम यह अपन मन में भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि अधिकारियों में सम्मान की प्रवृत्ति के जन्मदाता देश के विदेशी शासक हैं। कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक नहीं कि अधिकारियों को इतना अधिक अनुचित रूप से आदर-सम्मान दिया जाए, जितना कि भारत में दिया जाता है। सरकार ने यह सब जानबूझकर इसलिए किया है ताकि ये अधिकारी जनता की पहुँच के बाहर हो जाए। निरंकुश सरकार का अपन कम-चारिया को जनता पर निरंकुश शासन के लिए निरंकुश शक्तियाँ देनी ही हानी हैं। हम प्रजाजनों के मान सम्मान तथा स्वतंत्र चरित्र की बलि चढ़ाकर अधिकारियों को ऊपर उठाना ही सरकार की नीति है। सरकारी कम-चारियों के लिए सम्मान प्राप्ति की बात करना स्पष्टतः देग-द्रोह है। हमें अपनी सारी शक्तियाँ कम-चारिया को नीचे लाने में और जनता का थोड़ा ऊपर उठाने में खर्च करनी चाहिए।

इसी प्रकार 'हिंदू' ने अपने 15 जुलाई 1886 के अंक में यह आगावादी दृष्टि व्यक्त किया कि गिणित भारतीय भाड़े के टटटू यूरोपीय द्वारा माग गए वेतन की अपेक्षा धाँदे वेतन पर ही अपन देग तथा अपने देग-गमिया के लिए काम करना स्वीकार कर लेंगे। उसने भारतीयों से त्रिदशिया के समान वेतन पाने की आरम्भत्या जैसी माग का छोटन का अनुरोध किया।<sup>107</sup> 25 मई 1887 के अंक में एम पत्र ने फिर लिखा कि अगरेजों का मिलने वाले जिन वेतनों को धन का अपव्यय कहकर हम उनकी निन्दा करने आ रहे हैं उन्हीं वेतनों की देग-गमिया द्वारा अपन लिए माग करना विवकल्य है, देगानुराग विरोधी दृश्य है।<sup>108</sup> दूरी प्रकार 1886 के नोन मवा आयोग के समक्ष अपन माग्य में

अनेक राष्ट्रवादी नेताओं ने या तो कहा कि भारतीयों को यूरोपीयों को मिलने वाले वेतनों से कम वेतन मिलना चाहिए<sup>109</sup>, या उन्होंने एक मिला जुला सुझाव रखा कि एक हजार प्रतिमास के वेतन तक तो यूरोपीयों और भारतीयों के वेतन में समानता रहनी चाहिए। इस राशि से ऊपर के वेतनों में भारतीयों को कम मिलना चाहिए।<sup>110</sup> 1898 में विलबी कमीशन के समक्ष अपना साक्ष्य देते सुर्द्रेनाथ बनर्जी ने कदाचित् जपान साथी मित्रों के कटु प्रहारों से बचने के लिए इस दृष्टिकोण को स्पष्ट कहने की अपेक्षा उसे मृदु भाषा में प्रस्तुत किया। 'जहाँ कहीं किसी पद के लिए योग्य भारतीय उपलब्ध है वहाँ उसकी नियुक्ति अवश्य ही करनी चाहिए', इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि यदि किसी पद के लिए अपेक्षित योग्यताओं के मूल्य का स्थानीय बाजारी मूल्य के समक्ष में परीक्षण किया जाए और तदनुसार वेतन का निर्धारण किया जाए तो इसमें सरकारी खर्च में उल्लेखनीय बचत हो सकती है।<sup>111</sup> इसी प्रकार विलबी कमीशन के समक्ष अपने साक्ष्य में दादाभाई नौरोजी ने अभियोग स्वीकार किया कि भारत का प्रशासन भारतीयों के हाथ में होना चाहिए और उन भारतीयों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि योग्यता के स्तर के वहाँ बन रहने पर स्वयं सरकार के अपने ही तख्तीने के अनुसार कम से कम 1/3 भाग की सरकारी खर्च में बचत होगी।<sup>112</sup>

सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण के सिवाय भारतीय नेताओं ने उल्लेखनीय परिमाण में सरकारी खर्चों में कटौती करने के लिए कोई अन्य ठोस सुझाव नहीं दिया। उन्होंने असैनिक प्रशासन के खर्चों में कटौती के लिए प्रायः अस्पष्ट और सामान्य मांग प्रस्तुत करने तक ही अपने को सीमित रखा। उनके द्वारा कटौती के लिए सुझाए गए उपायों में अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण कुछ उपाय जो 1880 की अवधि में ही सुझाए गए थे, निम्नलिखित हैं

उनके मत में उच्च सरकारी अधिकारियों को दिए जा रहे वेतनों में कटौती करके प्रशासनिक व्ययों में वास्तविक बचत की जा सकती है। उन्होंने घोषणा की कि इकरारनामे के अंतर्गत असैनिक प्रशासन के अधिकारियों जिनमें अधिकांश यूरोपीय हैं तथा अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों, उदाहरणार्थ, गवर्नर जनरल, प्रांतों के गवर्नर, भारत सरकार के तथा आयुक्तों के सचिवों के वेतन पेंशन तथा भत्ते गगनचुम्बी हैं, इनमें कटौती करने से सरकारी वित्तों को भारी लाभ हो सकता है और इस कटौती से इन वेतन भोगियों को भी कोई असुविधा नहीं होगी क्योंकि अतीत में इन लोगों के ऊँचे वेतनों के लिए जिस देश निर्वासन तथा कष्टमय जीवन को याचकगत बताया जाता था और आज इंग्लैंड और भारत में यातायात साधनों के विवास के फलस्वरूप तथा भारत में निवास की स्थितियों में सुधार आ जान के फलस्वरूप पहले की परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं।<sup>113</sup>

भारतीय नेताओं ने इसके अतिरिक्त यह भी अनुभव किया कि कुछ ऊँचे प्रशासनिक स्थान जैसे कि राजस्व बोर्ड, राजस्व आयोग का स्थान तथा कुछ मध्य-स्तरीय अधिकारियों के स्थान निरर्थक ही नहीं प्रत्युत बिना काम के वेतन का भुगतान करने वाले थे,



अतः उनकी मांग थी कि इन स्थानों को समाप्त कर देना चाहिए।<sup>111</sup> उनमें से बहुतों ने तो इंग्लैंड में 'इंडिया कॉमिन्स' (भारत परिपद) को ही समाप्त करने की मांग की। उनकी इस मांग के पीछे अत्यंत कुछ कारणों के साथ-साथ परिपद का आर्थिक दृष्टि से महत्त्व तथा उपयोगिता की दृष्टि से सबका निरर्थक होना था।<sup>112</sup>

इसके साथ-साथ कुछ राष्ट्रवादियों ने बटौती के नाम पर निचले स्तर के निम्न वतन वाले स्थानों को समाप्त करने की अथवा उन स्थानों के वेतना में बटौती करने की सरकारी प्रवृत्ति का विरोध किया।<sup>113</sup> उनमें से बहुतों ने तो काफी आगे बढ़कर सरकार से कभी-कभी उसी जाश खरोश के साथ, जिस जोश खरोश के साथ वे ऊंचे वेतना में बटौती की बहाल कर रहे थे, बहुत कम वेतन वाले अधीनस्थ प्रशासनिक तथा पुलिस-कर्मचारियों के वेतना में वृद्धि की बहाल कर दी। इस प्रकार उदाहरण के रूप में, 1895 में कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में सुरेंद्रनाथ बेंगर्जी ने विनिमय क्षतिपूर्ति भत्ते की आलाचना करते हुए सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले क्लर्कों और चपडसिया की वतन वृद्धि के लिए तर्क प्रस्तुत किया। उन्होंने शिकायत की कि बेचारे अभावग्रस्त सरकारी कर्मचारी अपने वतन में बड़ी कठिनाई ही जीवन निर्वाह कर पाते हैं। विवश होकर जीविका जुटाने के लिए उन्हें गलत तरीके अपनाए पड़ते हैं। वे बहुत सालों से वही वेतन प्राप्त कर रहे हैं।<sup>114</sup>

सरकारी सचों में बटौती का राष्ट्रवादी क्षेत्र में व्यापक रूप से लाभप्रियता प्राप्त एक अत्यंत उपाय केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों का प्रतिवचन गर्भों के महीनों में प्रायः अप्रैल से अक्टूबर तक पंचम प्रदक्षिण में जाना तथा बहाल से वापस लौटना था। यद्यपि इस उपाय का अपना-आप फलस्वरूप रियासतों के रूप में होने वाली बचत विशेष उल्लेखनीय नहीं थी तथापि इस उपाय का पर्याप्त लाभप्रियता प्राप्त हुई। वस्तुतः भारतीयों ने इस मांग को मनवाने के लिए दो बार छोट मोट आंदोलन किए। प्रथम, 1886-7 की अवधि में भारत सरकार द्वारा वित्त समिति की नियुक्ति ने भारतीय राजनीति में व्यापक रूप से बटौती का एक सजीव विषय बना दिया और पुनः जब भयंकर अराल ने देश को अपनी लपट में ले लिया। उन्होंने विविध आर्थिक, राजनैतिक तथा प्रशासनिक आधारों पर सरकारों के पंचमगमा की निंदा की।<sup>115</sup> यहाँ हम केवल उनकी आर्थिक आपत्तियों से प्रयोजन है और वे थी, प्रतिवचन पंचम प्रदक्षिण में अल्पकालीन पड़ाव की विलासिता के लिए भारी और निरर्थक धन की व्यवस्था करनी पड़ती है और भारत को निम्न देशों के लिए यह सब जुटाना कठिन कार्य ही है।<sup>116</sup> इस तथ्य का कभी-कभी तो और अधिक प्रबलता में प्रस्तुत किया गया। उदाहरणार्थ, त्रिहार हारम्ब' ने अपने 20 जुलाई 1886 के अन्त में टिप्पणियों की कि पहाड़ों पर सरकारी अधिकारियों का जीवन मात्र प्रमत्तता और मीजा का जीवन है। इस पर होने वाले भारी खर्च की पूर्ति बचारे करदाताओं में जीवन रखने को चुम्बक ही की जाती है।<sup>117</sup> बुद्धिमान भारतीय नेनाआ ने इस व्यवस्था के तानिक दृष्टि में अमंगल होने की भी चर्चा की। उनमें अनुमान प्रिटिश अधिकारियों का इस अनुमान तथा आश्चर्यचकितता के सम्बन्ध में ही ऊँच वेतन लिए जाते हैं कि इन बचारे का भंडाना की सम्पत्ति गर्भों में काम करना पड़ता है। फिर गर्भियों के महीनों में उन्हें पंचम प्रदक्षिण में जाना पड़ेगा



नागरिकों को विपुल परिमाण में नौकरी के अवसर जुट पाते हैं, अतः ब्रिटिश सरकार को इस सर्वोच्चता का मूल्य चुकाने के लिए और भारत सरकार के साधारण, सामान्य व्ययों के एक भाग का भुगतान करने के लिए महमत हाना ही चाहिए।<sup>133</sup>

सैन्य व्यय में यागदान करने के अतिरिक्त कुछ एक भारतीय नेताओं ने इस मंत्र में दो महत्वपूर्ण तथा उपयोगी सुझाव रखे। प्रथम, भारत में मशीन प्रसार की मनाजा में नियुक्त यूरोपियों पर होने वाले व्यय का ब्रिटेन को अगदान ही नहीं प्रत्युत सार के भारतीय व्यय का ही भुगतान करना चाहिए क्योंकि भारत सरकार ने किसी भी रूप में स्पष्टतया और अनिवाद्यतया भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता का सुरक्षित बनाए रखने के लिए ही इन्की नियुक्ति की है।<sup>134</sup> द्वितीय, ब्रिटेन का भारत सरकार के गृह प्रभारों के तथा इंग्लैंड में हुए भारत सरकार के व्ययों के यागोचिन भाग का योगदान करना चाहिए।<sup>135</sup>

ब्रिटेन के भारतीय व्ययों में योगदान करने को सहमत होने का एक परोक्ष सभावित लाभ भारतीय नेताओं की दूर दृष्टि के अनुसार यह था कि इसमें ब्रिटेन की मदद और वहाँ की जनता भारतीय वित्तों के प्रति अधिक गहरी रुचि और अधिक समीक्षापरक दृष्टि अपनाएगी क्योंकि इससे उनकी अपनी जेब ही प्रभावित होगी।<sup>136</sup>

विलयी कमीशन ने 1900 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। यह कमीशन खुल मिलाकर ब्रिटेन और भारत के मध्य प्रचलित वित्तीय संवधा से सतुष्ट था। अतः उनमें ब्रिटिश बाप में से भारतीय कोष को साधारण सी ही राहत देने की सिफारिश की। दादाभाई नौरोजी, विलियम विन्स्टन तथा डब्ल्यू० एस० वॉन, जो कमीशन के सदस्य भी थे, कमीशन के बहुमत में असहमत थे तथा उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने वाला अपना अल्पमतीय प्रतिवेदन पृथक् रूप से ही प्रस्तुत किया।<sup>137</sup> भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जहाँ विलयी कमीशन द्वारा प्रतिपात ब्रिटिश अगदान का कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार कर लिया, वहाँ बहुत गारे अन्य सदस्यों ने कमीशन के निष्कर्षों के प्रति असंतोष प्रकट किया।<sup>138</sup> उनका विचार था कि यह यागदान थोड़ी असुविधाजनक प्रकृति का है और इसे भारत के प्रति बिना गये याग की एक छाटी सी किस्त ही समझना चाहिए। दूसरी ओर उन्होंने अल्पमतीय प्रतिवेदन का बड़े ही उत्साह के साथ स्वागत किया।<sup>139</sup>

### कुशल क्षेम व्यय

यद्यपि भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने भले ही सरकारी व्यय में कटौती के लिए निरंतर आन्दोलन किया तथापि वे सिद्धांत रूप में मशीन प्रसार के व्यय में वृद्धि के विरुद्ध नहीं थे। दूसरे शब्दों में उनका दृष्टिकोण किसी भी रूप में मंत्र प्रकार में पराधान के पूनव तथा व्ययों के पूनव करने के विरुद्ध तब सीमित नहीं था। इसके मवया विपरीत जहाँ उन्होंने सेना अर्थात् प्रशासन तथा रेलों पर होने वाले व्ययों को अनावश्यक, निरर्थक तथा अत्यधिक महंग मानते हुए उच्च कटौती के लिए आन्दोलन किया वहाँ उच्च गण्य की विनाशपरक तथा क्षेप-कल्याणकारक मानी जान वाली गतिविधियाँ अथवा निःप्राय विनाशकारी तथा तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था औद्योगिक तथा कृषि-मन्त्री जनित

कृषि बको का विकास, सफाई और सावजनिक स्वास्थ्य, लोकप्रिय तथा कुशल पुलिस-प्रणाली तथा न्याय प्रशासन के लिए व्ययों में वृद्धि, का न केवल स्वागत किया प्रत्युत उसके लिए अनुरोध किया और दबाव तक डाला। वास्तव में भारतीय नेताओं द्वारा बचतों की वाञ्छित दिशाओं के अध्ययन के उपरांत तथा उनके द्वारा बचतों की अवाञ्छित दिशाओं की समीक्षा के उपरांत यह रोचक तथ्य सिद्ध हो जाता है कि सरकारी खर्चों के समुचित वितरण और उसके क्षेत्र की समस्या के संबन्ध में राष्ट्रवादियों की समझ सचमुच ही प्रशंसनीय थी।

सामाजिककरण के स्तर पर राष्ट्रवादी नेताओं ने देश की सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक प्रगति को द्रुतगामी बनाने के लिए सरकारी वित्तों के उपयोग की संभावनाओं को पूरे रूप से स्वीकार किया। उन्होंने इस संबन्ध में कहा कि राज्य की पुनर्संरचना के प्रयोजनों के लिए किए जा रहे व्ययों के मुकाबले भारत सरकार द्वारा जनता के प्रत्यक्ष हितों के अथवा उनके नैतिक और भौतिक विकास के कार्यों पर वास्तव में किए जाने वाले खर्च की राशि साधारण तथा तुच्छ थी। अतः उन्होंने मांग की कि सरकार का इस दिशा में अधिक खर्च करना चाहिए और जब कभी कटौती की छुरी चलानी पड़े तो उसका उपयोग राज्य के अनावश्यक खर्चों में कटौती के लिए किया जाना चाहिए, आवश्यक खर्चों के लिए उसका प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। 1886-7 के आर्थिक सत्र से उभरने के लिए कटौती के उपायों की एक सूची प्रस्तुत करते हुए जी० बी० जाशी ने आवश्यक तथा उपयोगी खर्चों को समाप्त न करने की सरकार का चेतावनी भी क्योंकि इसका अनिवाय दुष्परिणाम देश के विकास का अवरुद्ध अथवा पराङ्मुख होना था। उन्होंने बचत के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिस भी क्षेत्र में बचत की योजना बनाई जाए वहां यह अवश्य देखना चाहिए कि उसमें स्थाई तथा उपयोगी रूप से कुशलता तथा प्रगति पर किसी प्रकार से बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ता।<sup>110</sup> बाद में 1888 में उन्होंने इंडियन पोलिटिकल ऐसोसिएशन और लेखकों पर लगाए जा रहे इस अभियोग में उनका बचाव किया कि वे वास्तव में ही उपयोगी और आवश्यक खर्चों में भी कटौती चाहते हैं और दावा किया कि वे तो उलटे तकनीकी शिक्षा न्याय प्रशासन पर खर्चों आदि में वृद्धि की मांग करते आ रहे हैं। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि लोकमत के ध्यायवाता निरंतर लंबे समय से जिस बात पर दबाव डालते आ रहे हैं, वह इस प्रकार है

सरकार को उन खर्चों में कटौती करनी चाहिए जिन्हें अनुभव और विषय न जाता के धन का निरर्थक अनावश्यक और धूलतापूर्ण अप्रयय सिद्ध कर दिया है। गिनता सिता वाले बड़े बड़े भवन बनवाना पवनीय प्रदर्शन में पशय टाया, गमा। योग्यता वाले जयवा अधिक योग्यता वाले भारतीय प्रत्यागियों का मुलभ।।।। पर नी न। यूरोपीय लागो को नियुक्त करना मवथा निरर्थक प्रयय \*। गमा म अनावश्यक तरी करना तथा गृह प्रमारों में अनुरित यदि कर्मा अताप्रयक के वैज्ञानिक ससोधन पर, दूसर म मी गीमा म यनिक विज्ञान

शिक्षा की कि मेना और नगर प्रशासन के अत्यधिक ऊँचे व्यय की एक बहुत बड़ी सुराई यह थी कि शिक्षा और पुलिस सुधार जैसे अत्यंत आवश्यक प्रयाजनों के लिए भी अपेक्षित राशि सुलभ नहीं हो पाती थी।<sup>141</sup> 1895 में बंबई के बजट पर जपन मंत्रिमंडल भाषण में ही वी० जी० तिलक ने सरकार का लताडते हुए कहा कि 1870 से सरकार ने 54 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व इकट्ठा करने पर भी राज्य के भौतिक विकास पर कठिनाता से कुछ लाख रुपये ही खर्च किए हैं। उन्होंने निर्देश किया कि जहाँ देश को औद्योगिक, तकनीकी अथवा उदार शिक्षा, ग्रामों में सफाई, सड़कों और नहरों आदि लोकोपयोगी कार्यों के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी<sup>142</sup> उस दिशा में खर्च न करके अतिरिक्त राजस्व की उगाही राशि को विविध प्रशासकीय विभागों पर अनावश्यक रूप से खर्च कर दिया गया है। 1896 के बजट पर बोलते हुए उन्होंने विशेष रूप से सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर खींचा कि सरकारी और गैरसरकारी क्षेत्रों के दृष्टिकोण में मतभेद का प्रमुख विषय खर्चों की दिशाएँ हैं<sup>143</sup> इसी प्रकार 1897 में विल्वी कमीशन के सामने अपना साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए डी० ई० वाचा ने सुस्पष्ट रूप से यह सिफारिश की कि उत्पादक प्रकृति के असैनिक व्यय अपनी पर्याप्त मात्रा में सदैव वांछनीय रहे हैं। इस कथन के उपरान्त उन्होंने उत्पादक प्रकृति के व्यय का अत्यंत वृत्तान्तिक ढंग से विश्लेषण प्रस्तुत किया। करदाता को बदले में शिक्षा, यापूरा अधिक बुशल प्रशासन, ग्राम तथा नगरों की अपेक्षावृत्त अधिक अच्छी सफाई, लोकहित के अथ दूसरे कार्यों—जिनमें प्रातः के ससाधनों और जनता की समृद्धि में योगदान मिलता है—जिस व्यय से हो पाते हैं, वह 'उत्पादक प्रकृति का व्यय' है।<sup>144</sup>

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जो वर्षों से सामान्य तथा तकनीकी शिक्षा के लिए, यापूरा प्रशासन की व्यवस्था आदि के लिए बजट में अधिक व्यय की मांग करती आ रही थी, 1897 में अपनी मांगों को अधिक व्यवस्थित रूप दिया तथा सरकार से अनुरोध किया कि सेना तथा अथ इस प्रकार की मूढ़ों में होने वाले अनुत्पादक खर्चों को घटाकर बची राशि के बड़े भाग का जनता की प्रगति और सुख समृद्धि के उत्थान में सदुपयोग करा जाए।<sup>145</sup> अतः हमें वी० जी० वी० गांधी के विचारों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सिफारिशें कीं कि व्यय में वृद्धि पुलिस सेना में सुधार, विदेशों में औद्योगिक शिक्षा के लिए राजकीय छात्रवृत्तियों की व्यवस्था, पूसा में कृषि महाविद्यालय की स्थापना और सहकारी ऋण-समितियों की प्रस्तावित सरकारी उपायों का पूरा समर्थन किया तथा 1904 के बजट-भाषण में उन्होंने यह निर्देश किया कि इन उपायों तथा इन जैसे लोकहित कारक उपायों के लिए विपुल धनराशि अपेक्षित है। हमें साथ उनका यह भी दृढ़ मत था कि लाभ बन्धनों के इन कार्यों पर बने हुए व्ययों की न केवल गिनती ही नहीं की जायगी प्रत्युत देश भर में उनके प्रति ईमानदारी में गताप और कृतज्ञता की भावना अभिव्यक्त की जायगी।<sup>146</sup>

इस समय में दो नूतने वर्षों में कुछ अपने-ताने बन्धनों के विभागों पर भारत सरकार द्वारा खर्च की गई राशियों का अध्ययन भी पर्याप्त समय होगा।<sup>147</sup>

	1885	1898
शिक्षा	1 4 कराड	1 37 करोड
विज्ञान विभाग	40 करोड	45 करोड
डाक्टरी और जन स्वास्थ्य	69 "	1 53 "
कानून और न्याय	2 77 ,	3 43 "
सिचाई	79 "	2 "
		(वास्तविक राजस्व)
पुलिस	2 5 ,	3 8 "

लोकहित के किसी भी अन्वय क्षेत्र की अपेक्षा भारतीय नेता शिक्षा को सर्वाधिक महत्व देते हुए उसके लिए पर्याप्त वित्त की व्यवस्था चाहते थे। इसका कारण उनका यह सुप्रसिद्ध सिद्धांत था कि आधुनिक शिक्षा राष्ट्रीयतावाद को पुनर्जन्म देने के प्रमुख कारणों में सबसे पहला है। इस विश्वास को स्वयं वर्षों से सरकारी प्रवक्ता पनपाते तथा विकसित करते आ रहे थे। सर्वप्रथम राष्ट्रवादी नेताओं ने शिक्षा पर सामान्य रूप से तथा उच्च शिक्षा पर विशेष रूप से खर्चों में बटौती के प्रयासों का विरोध किया।<sup>149</sup> यहाँ यह देखा भी उचित होगा कि उच्च शिक्षा पर किसी प्रकार के भी प्रतिबंध अथवा उस पर होने वाले व्यय में किसी प्रकार की बटौती के प्रबलतम मुख्य विरोधी किरोजशाह मेहता ने सरकार द्वारा भारत में उच्च शिक्षा के प्रसार में किसी प्रकार की बाधा के प्रयास को नव शिक्षित भारतीयों के प्रति शासकों का ईर्ष्याभाव बताया। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा, प्रजाजनों को शासकों के स्तर पर उन्नत करने की बात करना अपने में बड़ा मोहक लगता है परन्तु जब प्रजा सरकार पर दबाव डालने लगती है, मानव स्वभाव की सहज दुर्बलता के कारण उस समय प्रबल प्रवृत्ति यह होती है कि प्रजा को पीछे धकेल दिया जाए।<sup>150</sup> इसी प्रकार वर्षों तक और लगभग निरंतर ही भारतीय नेता शिक्षा पर सरकारी खर्च में व्यापक वृद्धि के लिए दबाव डालते रहे। उदाहरणार्थ, यह एक ऐसी मांग थी कि जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1888 से आगे धार्मिक मांग का रूप दे दिया था।<sup>151</sup> 1893 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में निधन छात्रों की फीस में रियायत अथवा माफी देने की मांग की।<sup>152</sup> इसी प्रकार 1895 में उसने शिक्षा संस्थाओं में फीस बढ़ाने के राज्य द्वारा पूर्णतः अथवा अंशतः समर्थित प्रस्ताव का विरोध किया।<sup>153</sup> 1904 में कांग्रेस ने नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की दिशा में सरकार द्वारा पथ प्रदर्शन करने की प्रातिविकारी मांग की।<sup>154</sup> बहुत सारे दूसरे राष्ट्रवादी नेताओं ने शिक्षा के लिए अधिक धनराशि निर्धारित करने की मांग की तथा साथ ही साथ अर्थ देना द्वारा शिक्षा पर किए जाने वाले व्ययों के मुकाबले तथा स्वयं भारत सरकार द्वारा बनाए गए पर किए जाने वाले व्ययों के मुकाबले भारत में शिक्षा पर होने वाले व्यय की तुच्छ राशि की आलोचना की।<sup>155</sup>

शिक्षा को और विनोदना प्राथमिक शिक्षा को अथवा जन साधारण को शिक्षित करने के लक्ष्य को अपने सारे जीवन का लक्ष्य बनाने वाले जी० वे० गांधी के विचारों का सक्षिप्त विवेचन अनुचित न होगा। उन्होंने अपने सावजनिक जीवन के प्रारंभ में ही

इस उद्देश्य को अपनाया और 1891 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में शिक्षा के लिए निर्धारित ससाधना की स्वल्पता के लिए निंदा और शिकायत की। उन्होंने निरर्द्ध किया कि यूरोप के सर्वाधिक पिछड़े देश में भी शिक्षा पर किए जाने वाली व्यय की राशि उन देशों के सरकारी राजस्वों का 65 प्रतिशत है जबकि भारत में शिक्षा पर व्यय की जाने वाली राशि का अनुपात केवल एक प्रतिशत है। भारत में वास्तव में ही शिक्षा पर व्यय होने वाली राशि 20 वर्ष पूर्व खर्च होने वाली राशि से भी कम थी, जबकि उसका अनुपात 1/4 प्रतिशत था।<sup>156</sup> 1897 में विलनी कमीशन के समक्ष उन्होंने शिक्षा पर व्यय की तुलना का भारतीय व्यय के मस्तक पर एक बड़ा भारी क्लक बताया और कहा ग्रेट ब्रिटेन में शिक्षा पर व्यय के मुकाबले भारत में शिक्षा पर हो रहे व्यय की तुलना करने पर सरकार द्वारा पवित्र ऋण की उपेक्षा करने के लिए जितने भी अधिक बंधन शर्तों का प्रयोग किया जाए, थोड़ा ही है। ब्रिटेन और भारत में शिक्षा पर किए गए व्यय के अंतर को दिखाते हुए उन्होंने टिप्पणी की कि सगे बेटों और सौतेले बेटों के प्रति व्यवहार में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। उन्होंने देश में प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं के नितांत अभाव के लिए प्रशासन को विशेष रूप से ही आड़े हाथों लिया।<sup>157</sup> 1901 में अपने बजट भाषण में बार्नेलेजिस्लेटिव कांसिल में उन्होंने अपने विचारों का दृढ़तापूर्वक दोहराया।<sup>158</sup> इंपीरियल लेजिस्लेटिव कांसिल में अपने प्रसिद्ध वार्षिक बजट भाषणा में गोखले ने शिक्षा के सामान्य रूप में और प्राथमिक शिक्षा के विशेष रूप से प्रसार का निरंतर तथा सशक्त शब्दों में समर्थन किया। इस प्रकार 25 वर्षों तक सवसाधारण की शिक्षा की योजना के लिए कालत भारत रहने के उपरांत 1903 में उन्होंने कहा 'दंग की तात्कालिक और अनिवार्य आवश्यकता है, सबसे प्रथम जनता के लिए प्राथमिक विद्यालय। शिक्षा के प्रसार के प्रति अपने अत्यधिक उत्साह के कारण वे स्वयं अपनी मायताओं के तथा अवशिष्ट अभाव्य नताओं के प्रशासन के और अधिक विकेंद्रीकरण के विश्वास में भी विपरीत चले गए। उन्होंने भाग की कि शिक्षा का राज्य के विषयों की सूची में हटाकर केंद्रीय विषय बना देना चाहिए ताकि देश का सर्वोच्च सरकार जिम्मेदार और जितना ध्यान मय सवाओं तथा रचनात्मक प्रसार जस अपनी सूची के विषयों पर देती है, उतना ही महत्व और ध्यान देश की जनता की शिक्षा पर दे सके। वस्तुतः शिक्षा के लिए गोपनीय के मन में इतना अनुराग था कि उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा समर्थित एक अर्थ मित्रता का भी अतिशय प्रयोग किया। उन्होंने भारतीय विद्यालयों में योग्य अध्येताओं को अध्यापक बनने के लिए आकृष्ट करने के लिए उन्हें ऊंचे ऊंचे वेतन देने की कालत की।<sup>159</sup> इस सवध में उनके द्वारा निरिच्छित सुस्पष्ट उपयोगी प्रस्ताव यह था कि जय कभी बजट में बजत हो उसका उपयोग देश के शैक्षणिक तथा औद्योगिक शिक्षा के सवद्धन में करना चाहिए।<sup>160</sup>

यह यह उल्लेखनीय है कि प्राथमिक और तृतीय की शिक्षा के रूप का प्राप्त करने की शिक्षा में जहां भारतीय नेता सरकार में बलुन आगे बढ़ गए, वहां उन्होंने सरकार द्वारा उत्तर ऊंची शिक्षा के प्रसार का वाधित करने की शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा का एक सगा के रूप में उपयोग करने पर आपत्ति की। उमरा कथन का देश की राजनिति,

सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए उच्च शिक्षा की भी समान रूप से आवश्यकता थी और मत्व तो यह कि उमके बिना शिक्षा के अथ दोना क्षेत्रो मे भी किमी प्रकार की प्रगति नही की जा सकनी ।<sup>161</sup>

भारतीय नता गिन्ता के अतिरिक्त दशके औद्योगीकरण,<sup>162</sup> सिंचाई<sup>163</sup> कृषि विकास, ग्रामीण ऋणग्रन्तता मे सुवित के लिए वृषि बका की स्थापना<sup>164</sup> स्वास्थ्य तथा सफाई-सुविधाआ,<sup>165</sup> तथा प्रशासन स 'यायाधिवरण का पृथक् करन<sup>166</sup> तथा पुलिस पद्धति मे सुधार करने<sup>167</sup> जम प्रशासनिक सुधारों के लिए भी सरकारी बजट म से अधिक धन के निर्धारण के इच्छुक थे ।

सरकारी अधिकारियों ने एक ही साथ दो परस्पर विरोधी मागो व्ययो और कराधान मे कटौती करन तथा अपनी प्रिय लोक कल्याणपरक योजनाआ पर व्ययो का बढान, के निण प्राय ही राष्ट्रवाणी नताओ को फटवारा । उदाहरण के रूप म 1894 मे वित्त सदस्य जेम्स वेस्टलड न लाहौर मे प्रिममिस के भ्रवमर पर इकटठे हुए राजनीति म रचि रखन बान भारतीय सम्य महानुभावा ( भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ) के मामले पर व्यय्य आक्षेप करत हुए पूछा 'क्या हम आप ही सिताएगे कि भारत पर किम प्रकार शासन करें ? उन पर बरसते हुए उसने कहा कि वे एक ही साथ एक मद मे लर्चों मे भारी कटौती करन और दूसरी मद म लर्चों मे वृद्धि करने की अपनी सलाह और बुद्धि-मत्ता का अपने पाम ही रखें ।<sup>168</sup>

राष्ट्रवाणी नताआ द्वारा इस आलोचना का प्रत्युत्तर सीधा सादा परतु निरुत्तर करने वाला था । आवश्यकता से अत्यधिन बडे हुए सँ य व्ययो और प्रशासनिक व्यय म कटौती करने से एक साथ ही कराधान मे कमी और लोकहित के व्ययो म वद्धि की जा सकती है । इस प्रकार वेस्टलड की फटवार का उमी तीखी और व्यग्यपूण वाणी मे उत्तर देते हुए फिरोजशाह मेहता ने इस तथ्य को मानने से इनकार कर दिया कि भारतीय नता इस प्रकार के सुझाव देन मे सवथा तकबुद्धि रहित और विवेकहीन थे हालाकि वे विश्व की विशिष्टतम सेवा के सदस्या का मुकाबला तो नही कर सकते थे । इसके उपरांत उहाने दढतापूर्वक कहा कि यह समझना कठिन नही कि यदि सही दिशा म बचत की जाए तो राजस्व मे कमी करना तथा अथ दिशा मे व्यय को बनाना सभव है । उहाने करावान और व्यया के सवध मे राष्ट्रवादिया की समग्र स्थिति को सक्षेप मे इस प्रकार प्रन्तुत किया

यदि आप स'य व्यय म उचित कटौती कर सकें यदि आप व्ययसाध्य, महगे जभियानो को न अपनाने की नीति पर स्थिर रह सकें, यदि आप विपुल सेना और घरलू तब्वमीना म सतुलन ला सकें, यदि आप वेतनो और पेंशनो के जटिल तथा कमरताड भार को हलका करने के व्यावहारिक उपाय अपना सकें तो यह अनुमान सवथा निमूल और काल्पनिक नही होगा कि 'याय व्यवस्था मे सुधार लाया जा सकता है पुनिस को अधिक सुदढ बनाया जा सकता है, शिक्षा की अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्थित और सुदढ पद्धति का अपनाया जा सकता है, देश म लोक कल्याणकारी बायों और रेल पथो का जाल बिछाया जा सकता है, सफाई के व्यापक साधन अपनाए जा



हैं ठाक तार को अपेक्षाकृत सस्ता बनाया जा सकता है, इतने पर भी थोड़ी आय वाला को कर भार में राहत दी जा सकती है, धरती पर लगान की दर कम करके किसानों का सुख चैन की सास लेने का अवसर जुटाया जा सकता है और नमक कर में भी कटौती की जा सकती है।<sup>169</sup>

ए० एम० बोस ने<sup>170</sup> 1898 में और जी० वे० गोखले ने 1902 तथा 1905 में<sup>171</sup> इसी तक को दोहराया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण तथा चिंतन का आधार-भूत तत्व यही था कि बढ़ते हुए सैन्य व्यय ही देश के अर्थ सभी प्रकार के आंतरिक सुधारों के मांग की प्रधान बाधा थे।

कुछ भारतीय नेताओं ने तो एक कदम और आगे बढ़कर यहाँ तक कह डाला कि यदि वर्तमान करो की आय के पूंजापेक्षा अधिक बड़े और व्यापक भाग को आंतरिक सुधारों के उद्देश्यों के लिए खर्च किया जाए तो कराधान के चालू परिणाम का भी सहन किया जा सकता है।<sup>172</sup> विशिष्ट दूरदर्शी तथा प्रतिभाशाली जी० पी० जाशी महान्याय ने तो उत्पादक प्रयोजना के लिए विशेष रूप से लगाए गए अतिरिक्त कराधान तक का समर्थन देने का वचन दिया। इस प्रकार उन्होंने भारतीयों से औद्योगिक प्रयासों के प्रोत्साहन के उद्देश्य से विशेष रूप से लगे नए करा का भार सह्य उठाने का अनुरोध किया।<sup>173</sup> इसी प्रकार उन्होंने 1893 में व्यापक परिमाण में कृषि शिक्षा के कार्यक्रम को अपनाए की वकालत की भले ही इसके लिए विशेष कराधान द्वारा धन की व्यवस्था क्या न करनी पड़े।<sup>174</sup> जी० वे० गोखले ने भी विलची कमीशन के मसल कुछ कुछ इसी प्रकार का सुझाव रखते हुए कहा कि प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए स्थानीय समस्याओं का विशेष ध्यान लगाने का अधिकार दिया जाना चाहिए।<sup>175</sup> जी० सुब्रह्मण्य जय्यर ने भी कमीशन को सूचित किया कि शिक्षा के प्रसार के लिए वे करा में वृद्धि करने के भी समर्थक हैं।<sup>176</sup>

### सरकारी वाश पर लोकप्रिय भारतीय नियंत्रण

भारत सरकार की वित्तीय नीति की समीक्षा करते समय भारतीय नेता बठारत। पूवक तथा अनिवाय रूप से इस परिणाम पर पहुँचे कि सरकारी वित्त पर भारतीयों के नियंत्रण की लोकप्रिय मांग मजबूत उचित है। उनके विचार में यदि भारत में कराधान कमरतोड़ स्थिति में उच्च और अधिक रह और व्यय निरन्तर तथा अनवश्यक हाता हम सारी स्थिति के लिए स्पष्टतया उत्तरदायी कारणों में एक वर्तमान में वित्त पर नियंत्रण रखने वाला मजबूत तंत्र है जो सत्तापजनक रूप से अपने कर्तव्य का निवाह करने में अक्षम रहा है। 1892 में पूव भारत की इपीरियर लजिस्त्रेटिव कौंसिल का यन्त्र ही बजट में सिमी प्रचार का कोई सबंध नहीं था। 1892 के इंडियन कौंसिल अधिनियम के अधीन कौंसिल में बजट का विश्लेषण प्रस्तुत करना होता था। सदस्यों का उम्र पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार अवश्य था परन्तु उच्च उम्र पर सिमी प्रसार के प्रस्ताव रखने का अधिकार कौंसिल में मनदान करने का कोई अधिकार नहीं था। भारतीय वित्त पर सर्वोच्च नियंत्रण ब्रिटिश समद का था। भारत सरकार समद में विद्यमान भारत राज्य सचिव का माध्यम में ब्रिटिश समद के प्रति ही उत्तरदायी थी।<sup>177</sup>

राष्ट्रवादी नेताओं ने वित्त नियंत्रण के प्रवर्धित तंत्र को सवया लोपपूर्ण घातित किया। उनका कथन था कि यह तंत्र सरकार के कायपालक अंगों की व्ययपरत और करघानपरत प्रवृत्तियाँ पर प्रभावी नियंत्रण रखने में असफल निम्न हुआ है। यह तंत्र कमरतोड़ करघान को रोकने में और दश के ससाधना के निरयक, व्यय, अनुचित तथा अनुपयोगी खर्चों को रोकने में नितात असफल रहा है, इसी प्रकार जी० के० गोवने ने विलवी कमीशन के समक्ष अपने माक्ष्य में निर्देश किया कि भारतीय वित्त की प्रत्य व्यवस्था में भारतीय हिता पर भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता के हितों को एशिया में ब्रिटिश विस्तार को, ब्रिटिश की नागरिक और सैन्य सेवाओं को तथा ब्रिटिश वाणिज्य और पूँजी को प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने टिप्पणी करत हुए कहा

भारतीय कर-न्याताओं के हितों को इन अन्य हितों के गौण बनाने की व्यापक चेष्टा से और भी अधिक आवश्यक हा जाता है कि भारतीय वित्तों के न्यायाचित तथा मितव्ययी प्रशासन के लिए सर्वधानिक नियंत्रण तंत्र द्वारा उनकी सुरक्षा की पदाप्त व्यवस्था की जानी उचित है। मुझे तो यह आशका है कि हमारे देश के समान और किसी भी देश में वित्तों की सुरक्षा की ऐसी भ्रातिपूर्ण व्यवस्था नहीं है।<sup>179</sup>

भारतीय नेताओं ने दृढतापूर्वक यह मत प्रकट किया कि वर्तमान संविधान व अतगत भारतीय कर दाताओं के हितों की सर्वोच्च संरक्षक ब्रिटिश समद समुचित रूप से और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वाह करन में असफल रही है। सत्र के अंतिम समय में खाली बचों के सामने भारत के बजट को पेश किया जाता है और बिना किसी गभीर विवाद, चिंतन और छानबीन के कुछ थके माद सदस्यों द्वारा इस पारित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त दलीय स्थिति के कारण भारत मन्त्रि का सुरक्षित और निश्चित बहुमत का विश्वास रहता है।<sup>179</sup> भारतीय नेताओं की शिकायत थी कि भारत में भी किसी प्रकार के आर्थिक नियंत्रण और सतुलन की व्यवस्था का अभाव था, इसका बदले स्वतः निर्मित अपव्यय पद्धति ही प्रचलित थी। भारत सरकार के वित्त विभाग का छोड़कर लगभग और सभी विभाग पूणत खर्च करन वाले विभाग हैं।<sup>180</sup> स्पीरियन सैजिस्ट्रेटिव कौंसिल का इस संबंध में अस्तित्व अवश्य है परंतु वित्तीय मामला में वह सवधा अशक्त है। इसके सदस्य केवल भाषण दे सकते हैं व किसी भी रूप में सरकार की निंदा नहीं कर सकते, यहा तक कि सरकार के प्रस्तावा में अपनी असहमति तक प्रकट नहीं कर सकते। फलतः बजट पर हुए विवाद या तो निर्जीव होत हैं या अधिक स अधिक पांडित्यपूर्ण हाते हैं।<sup>181</sup>

राष्ट्रवादी नेताओं के अनुसार वित्तीय नियंत्रण के चारू तंत्र के अमतापप्रद चरित्र का मूल कारण इस तंत्र में लोकप्रिय भारतीय तंत्र का नितात अभाव था। अतः 1891 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दृढतापूर्वक कहा कि भारतीय सांगा की बन्ती दरिद्रता व अन्याय कारणों में एक मूल और व्यापक कारण, भारतीयों के अपने ही देश व वित्त पर नियंत्रण से तथा उनके प्रशासन में समुचित योगदान में उन्हें सवधा पथक रगता था।<sup>182</sup> इसी प्रकार 1901 में कांग्रेस के सभापतीय भाषण में डॉ० ई० वाचा नथन दवर : यह दश का दुर्भाग्य है कि देश के व्ययों और करघान पर देनवागिया का यानन

अधिकार ही नहीं आया था वे यह दिखा देते कि किस प्रकार 'यूनतम राजस्व से अधिकतम वृत्त और कुशलता उपलब्ध की जा सकती है।' 1853 आर० सी० दत्त ने अपने ग्रन्थ— 'इकोनामिक हिस्ट्री आफ इंडिया इन दी विक्टोरियन एज'—में अपने लाकवित्तों के तथा विलबी कमीशन की कायवाहिया के परीक्षण का निष्कर्ष इस शिवायत रूप में निकाला—भारतीय प्रशासन में इस लोकप्रिय भारतीय तत्व की अनुपस्थिति में सभी कायरत प्रभाव विशुद्ध रूप में भारतीय हिता से सबधा असंबद्ध प्रयाजना के लिए भारतीय राजस्व की बलि चढाकर खर्चों में वृद्धि और कराधानों में वृद्धि के लिए ही निरंतर काय करते रहे हैं और करते रहेंगे। 1854

राग निदान में उपचार भी निहित था। इंग्लैंड में नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ बनाने में मद्रास में मुभाए गए उपचारों में महत्वपूर्ण—डीले डाले समदीय नियंत्रण का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव यूनान की आवश्यकता थी। इस संबंध में भारतीयों की सर्वाधिक मांग दस की वित्तीय स्थिति की जांच पड़ताल करने तथा तत्संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत कराने के लिए प्रतिवर्ष हाऊस आफ कामन्स की एक प्रकर समिति नियुक्त करने की थी। 185 दूसरा प्रस्ताव भारतीय मामलों की समय-समय पर समदीय जांच पड़ताल करने की 1858 से पूर्व की पद्धति को पुनर्जीवन करना था। 1856 इनके अतिरिक्त 1897 में जी० के० गोखले ने मुभाव दिया कि भारतीय मत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत के प्रांतों का सदन में सीधा प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। 185 इस सदन में एक अन्य राष्ट्रवादी प्रस्ताव यह था कि प्रांतीय तथा इपीरियल लजिस्लेटिव कौंसिलों द्वारा निर्वाचित योग्य भारतीयों का पर्याप्त संख्या में भारत सचिव की कौंसिल में प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहिए। 1899

ये मारे के सारे उपचार अपनी प्रवृत्ति में केवल उपशामक ही थे। वित्तीय रोग के उपचार के लिए भारतीय नेताओं ने एक और अधिक महत्वपूर्ण मांग पैदा की। उनका कथन था कि सरकार का पक्ष को प्रत्यक्ष रूप में भारतीयों के प्रभावी नियंत्रण के अंतर्गत लाया जाए। वित्त की मुख्यस्थिति रूप देने का राजस्व की वसूली में वृद्धि का और जनता के हित में तथा जनता की इच्छाओं के अनुकूल वित्तों के व्यय का यह एकमात्र सुनिश्चित उपाय था। यह मांग प्रायः सामान्य रूप में पैदा की जाती थी जबकि हमने पूर्णतः श्राविकारी रूप लिया। इस प्रकार प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वाधिकार करत हुए दादाभाई नौरोजी ने जारी रखे हुए बहस कराधान के साथ प्रतिनिधित्व व्यवस्था मिलना चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि हमारा प्रथम सुधार यह हो कि हम स्वयं अपने पर कराधान करने की शक्ति मिले। 189

दूसरी प्रकार अपने 16 मिनटों 1886 के अर्थ में 'अमृत बाजार पत्रिका' ने माहमपूरक यह मांग की कि देश के लागा को अपने लिए बानून बनाने की, अपने करा के निधारण करने की तथा अपने वित्तों का व्यवस्थित करने की अनुमति अवश्यमान मिलनी चाहिए। पत्रिका ने वही स्पष्टता में किन्ना भारत के लिए यह एक प्रकार का गुरु प्रमाण है और केवल इसी से भारत स्वार्थी रूप से इंग्लैंड में सतर्कता से सतर्कता है। जुलाई 1902 में 'हिन्दुस्तान रिट्यू' ने और 'वायम्प समाचार' ने भी इसी प्रकार की स्पष्टता की मांग अपनाई। अधिकार आत्मविश्वास पूर्ण स्वर में की। 190 अन्य अर्थ में भारतीय उदाहरण



परिपदा द्वारा किए गए किसी भी निणय को रद्द करने की विशिष्ट और अंतिम शक्ति का इंग्लड के हाथ में होना, को भी सहप स्वीकार कर लिया।<sup>99</sup> यह पर्याप्त आश्चयजनक ही है कि जी० वे० गाखले न विलवी वमीशन के समक्ष इस सीमा तक अभिस्वीकार किया कि नीति सबधी बडे बडे प्रश्ना पर विचार विमश तथा उन पर निणय ठीक प्रकार स इंग्लड म ही हा सकता है।<sup>100</sup> इस प्रकार भारतीय नेताआ ने अपनी शक्तिमत्ता से दूर-गामी प्रभाव वाली माग को नपुमक बना दिया और साथ ही साथ स्पष्ट शब्दों म यह कहत हुए उम दबाव क ढग का रूप दे दिया कि उनके द्वारा सुझाए गए सुधारा का प्रधान प्रभाव यह नहीं हागा कि भारत में ब्रिटिश कायपालिका के अधिकार खडित अथवा दुबल पड जाएग। इसका प्रभाव तो पूण रूप मे मात्र नैतिक हागा, क्योंकि जब वमी गैर सरकारी सदस्य सरकार के विरुद्ध अथवा पक्ष में मतदान करेंग तो ब्रिटिश जनता को और अधिकारिया का भारत के लोकमत की सही स्थिति का सच्चा रूप देखन का मिल जाएगा।<sup>101</sup> इन नताआ की सरकारी वित्त पर वैधानिक नियन्त्रणा के अपने ही तर्कों म सकोच शीलता बदाचित् आशिक रूप स तो कडवी गोली को चीनी म लपेट कर प्रस्तुत करन की भावना से प्रेरित थी परंतु मुख्य रूप से एक एक पग आग बढने के विरुद्ध की उपज थी।

## सदर्भ

- 1 उल्हाहरपाथ देविए नौराजी, पावर्टी प० 59 222-4 और स्पीचेज, प० 331 157 220 294 316 593 परिशिष्ट पृ० 39 43 50-1 181 भोलानाथ चद्र एम० एम० छद् II (1873) प० 92 मालवाय स्पीचेज, प० 248 राय पृ० पावर्टी 251 2 259-60 278 दत्त ई० एच० I प० XIX III ई० एच० II प० XIX 613 स्पीचेज II पृ० 21 61 2 गोखले स्पीचेज पृ० 15 एल० एम० घोष सी० पी० ए०, प० 759
- 2 नौराजी पावर्टी पृ० 200
- 3 ममाना पूर्वोद्धत पृ० 316 और देविए नौराजी पावर्टी पृ० 223-4 और स्पीचेज, पृ० 142, 316 परिशिष्ट पृ० 18 20 41 50 52
- 4 और देविए ए० बी० पी० 18 जून 1885 24 दिस० 1896 1 जून 1900 इंडियन स्पेक्ट्र 5 जुलाई 1885 राय पावर्टी पृ० 251 3 ए० नदी इंडियन पालिटिक्स पृ० 126 दत्त पमित इन इंडिया पृ० 100-01 ई० एच० I पृ० XII वाषा सा० पी० ए० पृ० 605
- 5 पा० मरुता स्पेचज पृ० 152 तथा देविए पृ० 350 451 456-8
- 6 प्रागीडिग्न आफ् डि नैमिन्ड आफ् डि एक्नर आफ् बांबे 1895 छद् XXXIII प० 90
- 7 जोनी पूर्वोद्धत प० 220 तथा देविए पृ० 199 200
- 8 नौराजी स्पेचेज प० 361 और देविए जी० सी० अम्बर विलवी वमानन छद् III प्रश्न 18567 18917 18963 19048 न्यू इंडिया 18 निसर 1902
- 9 गोखले स्पीचेज प० 1168-9
- 10 बही प० 1156-7 तथा देविए पृ० 1159

- 11 मालवीय स्पीचेज पृ० 219 तथा देखिए पृ० 276-81, 291
- 11 ए प्रस्ताव मध्या V तथा देखिए मालवीय स्पीचेज पृ० 279 नोराजी स्पीचेज पृ० 124-49
- 12 पी० मेहता स्पीचेज पृ० 447 52 इडियन स्पेक्टेटर ने तो इसमें भी पूव 1883 में अपने 24 जून के अंक में सरकार को सुभाव दिया था कि सरकार को जनावश्यक रूप से बजट को संतुलित करने अर्थात् पहले आवश्यक खर्चों के लिए संकल्प कर लेना तथा पुनः उन खर्चों को पूर्ति के लिए आवश्यक वित्तीय साधनों की खोज करने की चेष्टा छोड़ देनी चाहिए बजट को संतुलित करने का एकमात्र उपयुक्त ढंग यह है कि प्रथम हिसाब-खाते के साथ साथ बराधान का समीक्षा करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि कौन सा कर निधनों को किसी प्रकार का बिगाड़ बट्टे लिए बिना सुविधा से उगाहा जा सकता है फिर उसके अनुरूप खर्चों की व्यवस्था करनी चाहिए (आर० एन० पी० बज 30 जून 1883) दश के यथा और समाधान में सह संवध की व्यवस्था की मांग करने वाले अय नेता एस० एन० बनर्जी स्पीचेज III पृ० 13
- गोखले स्पीचेज पृ० 1169 वाचा स्पीचेज परिशिष्ट पृ० 32 एन० पी० चदावरकर सी० पी० ए० प 528 9 तथा आर० डी० नागरकर रिप० आ० एन० सी० 1894 पृ० 78 9 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 207-08
- 13 प्रस्ताव स० VI
- 14 प्रस्ताव स० VI
- 15 प्रस्ताव सत्या III
- 16 प्रस्ताव सत्या IX, XII IX XIII VIII और III क्रमशः
- 17 प्रस्ताव सत्या XIV III (11) क्रमशः
- 18 बगाली 2 जनवरी 1886 तथा देखिए बागल पूर्वोद्धत पृ० 86
- 19 जे पी० एस० एन० अकनू 1886 और जन० 1887 (खंड IX सत्या 2 और 3) तथा बाबे प्रजीडमी एसोसिएशन का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन क्रमशः 1885 86 पूना सायजनिज समा ने इस तक को दोहराते हुए बड़े प्रबल तथा सशक्त ढंग से एक अय ज्ञापन 6 मार्च 1894 को प्रस्तुत किया जे० पी० एस० एन० अप्रैल 1894 (खंड XVI सत्या 4)
- 19 ए रिपोर् आफ दि फाइनान्स कमिटी 1886 खंड II पृ० 452
- 20 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 1 82 तथा पृ० 140 1 189 90 201 222 824 6
- 21 गोखले स्पीचेज पृ० 1169 और आगे वाचा स्पीचेज परिशिष्ट पृ० 9 और आगे तथा 31 2
- 22 दत्त स्पीचेज I पृ० 26, 36-7 इंग्लैंड एंड इंडिया, पृ० IX 137, 141 2 144-5 फॉर्मिड इन इंडिया पृ० XIV, XVI XVII ई० एच० II पृ० 612 और देखिए एस० एन० बनर्जी स्पीचेज III पृ० 13 जे० यू० यासिव एन० ए० स्वामिनाथ अम्बर, बी० एन० पतुनु गुरु रिप० आई० एन० सी० 1885 पृ० 65 72 पी० मेहता स्पीचेज पृ० 443 50 मालवीय स्पीचेज पृ० 219 21 248 52 276-81 285-302 पी० ए० चारलू एन० सी० पी० 1896 खंड XXV पृ० 286 आर० एम० सयानी सी० पी० ए० पृ० 309 351 2 एन० जी० चन्नावरकर सी० पी० ए० पृ० 527 भारतीय समाचारपत्रों ने प्रत्येक उपलब्ध अवसर पर विवक्षित नए कर लगाने के अवसर पर बढ़त सरकारी खर्चों की आलोचना की तथा उन खर्चों में बढौती का समर्थन किया
- 23 नोरोजी स्पीचेज पृ० 147 361 परिशिष्ट पृ० 16-8 2९ 48 और देखिए पावर्गी
- 24 उदाहरण के लिए जी० बी० जोशी द्वारा 1886-7 में किया गया बचतभ्य स्थिति

के वतमान खर्चों के प्रमुख कारण नीति सबधी गलतियों की तरह या तो दूर किए जा सकते हैं या निरीक्षण की कठिनाइयों के कारण इनकी व्यावहारिक शक्ति कम होती जा रही है (पूर्वोद्धृत प० 10) इस सबब में राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण और सरकारी दृष्टिकोण के अंतर का समझना दिलचस्प होगा उदाहरणार्थ जान स्ट्रुची के कथन को देखिए 'यह सत्य है कि अनुसरदायी लोगों के लिए यह दावा करना सरल है कि सरकारी खर्चों में बचत करने की बड़ पमाने पर सभावनाएँ हैं परंतु में निर्भीकता के साथ चुनौती देता हूँ कि प्रशासनिक आवश्यकताओं की वास्तविक जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह सिद्ध करना आसान नहीं होगा कि नागरिक सेवा के लिए जितनी राशि खर्च की जा रही है उससे बड़ी अधिक की आवश्यकता है (फाइनांशल स्टेटमट 1878) ई० बेरिंग ने 1883-4 में फाइनांशल स्टेटमट में अपनी राय प्रकट करत हुए लिखा भारत के वित्तों के लिए खतरा पदा करने वाले सभी खतरे, जिनमें युद्ध का खतरा भी शामिल है ऐसे कारणों से नियंत्रित हैं जिन पर भारत सरकार का कोई नियंत्रण नहीं (कड़िका 121) इसी प्रकार एल्गिन स 1894 में घोषणा की कि भारत सरकार के वित्तों का दुःशा का लिए उत्तरग्या कारणों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं (स्पीचर्क प० 50)

25 प्रस्ताव स० II

26 नौरोजी स्पीचेज परिशिष्ट, प० 6 22 3 वही प० 361, 379 परिशिष्ट प० 26-30, जी० एस० बय्यर रिप० आई० एन० सी० 1894 प० 76 बी० एन० सन० रिप० आई० एन० 1895 प० 61 इसी तथ्य को प्रस्तुत करत हुए जे० मुदालियर ने कहा कि भारतीयों को हिंसात्मक विताम ठीक रखने की ब्रिटिश क्षमता पर पूरा भरोसा है (वही प० 62)

27 वही परिशिष्ट प० 22 28 तथा बाबा विलबी समीक्षण खट III 17316

28 इंपीरियल गजटियर आफ इंडिया (1908) खट IV प० 202 मैंने गजटियर में दी गई तालिका से ही प्रतिशत की समझना की है अर्को के अर्थ आकड़ निम्नलिखित लेखकों के निम्नलिखित ग्रन्थों में दिए गए हैं सी० एन० वकील फाइनांशल डिवलपमेंट आफ माडर्न इंडिया प० 547 8, ए० टी० शाह सिवसटी ईयस आफ इंडियन फाइनांस प० 72 3 और पा ज० थामस दि ग्रोथ आफ इंडरल फार्मास इन इंडिया, प० 502

28-ए इंपीरियल गजटियर आफ इंडिया (1908) खट IV प० 382 3

29 वही प० 187

30 आई० एन० सी० 1885 का प्रस्ताव L वक्ताओं ने एच बी० एस० पार्थुनु गुरु ने भाषोद्वायक घोषणा की कि यदि रूस का आक्रमण की आशंका से ही सना सबधी ध्यय बढ़ाया जाना है तो इसके फलस्वरूप कराधान में वृद्धि करना होगा बड़े हुए करों को चुकाने में देश दरिद्र हो जाएगा किसानों की भूमि छोड़नी पड़ेगी और सरकार को उनमें पक्ष का अनुसरण करते हुए भारत देश छोड़ना पड़ेगा यह तो रूस का आक्रमण की अपेक्षा बन्तर ही होगा अतः यह औपधि रोग से बन्तर ही है (रिप० आई० एन० सी०, 1885 प० 73)

31 1890 का प्रस्ताव सन्ध्या III (एफ) तथा प्रस्ताव II (एफ)

32 प्रस्ताव स० III

33 इनके उपररत नाम 'इंडियन एक्स्पेंडिचर' का नाम से सम्बन्धित किया जाएगा

34 तथा दसिण 26 जनवरी 1896 को बड़े हुए दिव्यदा खर्चों पर भारत में अधिक की या गया बोध प्रजाहोगी एगोसिपणन का भाषन 1885-6 का भाव प्रजाहोगी एगोसिपणन का प्रथम वार्षिक





समाचार 1 अप्रैल और कनरे हिंद, 26 मार्च (आर० एन० पी० ब०, 1 अप्रैल 1993) बगदासी 8 अप्रैल (आर० एन० पी० ब०, 15 अप्रैल 1893), प्रतिकार 21 अप्रैल (वही 29 अप्रैल 1893) पसा अघवार 26 जनवरी (आर० एन० पी० पी०, 9 फरवरी (895) ए० बी० पी० 3 अप्रैल 1885 27 अप्रैल 1902 इंदु प्रकाश, 25 मार्च (आर० एन० पी० ब० 30 मार्च 1895), अवध टाइम्स 5 अप्रैल (आर० एन० पी० एन० 13 अप्रैल 1901), भारत जावन 17 फरवरी (वही 22 फरवरी 1902) ट्रिब्यून 16 जनवरी (आर० एन० पी० पी० 25 जनवरी 1902) मराठा, 13 अप्रैल 1902 बेसरी 15 अप्रैल (आर० एन० पी० ब० 19 अप्रैल 1902) बेसरी 21 जुलाई (वही 25 जुलाई 1903), हितवादी, 3 अप्रैल (आर० एन० पी० ब० 11 अप्रैल 1903), गुजराती 17 अप्रैल (आर० एन० पी० ब० 2, अप्रैल 1904) इंडियन एडवांकेट 18 अगस्त (आर० एन० पी० पी० 27 अगस्त 1904) स्वतंत्रमित्र 9 मई और प्रपंच तारकी 13 मई द्रविडवाचस्पति 11 मई (आर० एन० पी० एम० 13 मई 1905) इंदु प्रकाश 23 मार्च कनरे हिंद 26 मार्च गुजराती 26 मार्च (आर० एन० पी० ब० 25 मार्च 1905) इंडियन सोशल रिफार्मर 26 मार्च आरियन रिब्यू 29 मार्च बल 31 मार्च (वही 1 अप्रैल 1905)

43 वन मारे राष्ट्रवादी नेताओं की धारणा में जबकि यह स्वतंत्र मित्र तथा प्रवृत्ति था जो वं गोष्ठी में उसे सुस्पष्ट वाणी में जिस प्रकार लाठ सलिसद्वारी में स्वयं एक बार निर्देश किया था भाग्य क्षमता का निर्धारण प्रत्येक देश के दो तत्वों के समस्त विचार व सद्म में ही करना चाहिए प्रथम देश की सुरक्षा सबंधी आवश्यकताएँ तथा द्वितीय इस उद्देश्य के लिए उस देश द्वारा सुविधापूर्वक चलाए जा सकने वाले साधन (स्पीचज प० 43)

44 ए० बी० पी०, 13 अगस्त 15 अक्टूबर 1885, हिंदू 20 अगस्त 24 सितंबर 8 अक्टूबर 1885 मराठा 11 अक्टू० 1885 इंडियन स्पेक्टटर 27 सित०, 4 अक्टू० इंदु प्रकाश 28 सित० 12 अक्टू० मुंबोध पत्रिका 23 सित०, इंडियन मिरर 4 6 10 अक्टूबर इंडियन नेशन, 5 अक्टू० नेशन ऑफ़ियन 11 18 अक्टू० स्वतंत्रमित्र 28 सित० सजावनी 3 अक्टू०, हिंदुस्तान 11 अक्टूबर गुजराती 29 सितंबर कनरे हिंदू 11 अक्टू० (बी० अ० आई० अक्टूबर 1885) एडवांकेट 23 अक्टू० मिथ टाइम्स 24 अक्टूबर ट्रिब्यून 31 अक्टू० बिगर हंगल 3 नवंबर (वही नवंबर 1885) समाचार चित्रिका 4 जनवरी (आर० एन० पी० ब० 9 जन० 1886) हिंदू, 13 फरवरी 1890 एम० एन० अनर्जी स्पीचज III प० 143 एम० एडव० परिसिस्ट प० 26 ए० बी० पी० 5 अप्रैल 1895 पी० मन्ता स्पीचज प० 452 राय पावर्टी प० 304 एम० इंग्लैंड गैट्ट इंडिया प० 136 अवध टाइम्स 5 अप्रैल (आर० एन० पी० एम० 13 अप्रैल 1901) वाचा स्पीचज प० 397 बी० ए० अमर रिप० आई० एम० सी० 1903 प० 121, मासिक मंगल, प० 45 104 आई० एम० सी० 1904 का प्रस्ताव XII

45 ए० बी० पी० 13 अगस्त 1885 राय पावर्टी प० 286-7 मासिक स्पीचज प० 44 1180 चित्रकारी 3 अक्टू० (आर० एन० पी० ब० 11 अप्रैल 1902) 1886 प० बी० बी० आता ने कहा की प्रस्तुत करने हुए यह प्रमाणित किया कि विमल पारिभाषिक दृष्टि में दलित पर भाव स्पष्ट होता है कि भाग का छोड़कर बिना व अर्थ दिया भा दल का मुक्तता में भारत में आनी गता पर अधिपत्य किया है (पूर्वोक्त प० 253) इंडियन समाचार पत्र इंडियन एरन्स 1885 में भारत के मामले को एक समय दूसरे देश में पेश किया जब उम्मे

यह तुलनात्मक तथ्य प्रस्तुत किया कि इंग्लैंड में सेना पर होने वाला ऋण राष्ट्रीय आय का 2.16 प्रतिशत था जबकि भारत में इस ऋण का अनुपात 4.25 प्रतिशत बढ़ता था (इंडियन लाफलटस स० 11 पूर्वोद्धृत)

- 46 इंडियन लाफलटस स० 9 पूर्वोद्धृत वाग्ना रिप आई० एन० सी० प० 60 तथा सी० पी० ए० प० 619 पी० मेहता स्पीचेज प० 449 गोखले स्पीचेज प० 44 105 कसरी 21 जुलाई (आर एन० पी० वब 25 जुलाई 1903)
- 47 रिप० आई० एन० सी०, 1891 प० 25
- 48 वही
- 49 सी० पी० ए०, प० 619 पर
- 50 आर० एन० पी० वब 19 अप्रैल 1902 दूसरी जोर इसने अप्रैल 31 माघ 1903 के अक म टिप्पणी की कि यदि देश को समग्रतः सुरक्षित रखना है तो उसका आंतरिक विकास करना आवश्यक है (आर० एन० पी० वब 4 अप्रैल 1903)
- 51 गोखले स्पीचेज प० 43-4 इसी प्रकार 1892 के भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में एच० सी० मित्रा ने करुण अभिव्यक्ति करते हुए कहा शस्त्र लेखनी की हत्या कर रहा है सैनिक बंदरता बला और संस्कृति को नष्ट कर जा रही है (रिप० आई० एन० सी० 1892 प० 96) देखिए बाबे प्रेजीडेंसी एसोसिएशन का 27 जनवरी का नापन पूर्वोक्त स्थान पी० मेहता स्पीचेज प० 334 5 350 457 8 मालवीय स्पाचेज प० 295 जी०एस०अग्यर विनवी कमांडर खड III प्रश्न 18963 आर० एम० सयानी एल० सी० पी० 1898 खड XXXVII प० 527 ए० एम० बोस सी० पी० ए० प० 425 7 हिंदू 26 अप्रैल 1902 गोखले स्पीचेज प० 26 28 109 सी० वार्ड० चिंतामणि इंडियन मिलिट्री एसोसिएशन एच० आर० फरवरी 1903 प 233 हितवादी 3 अप्रैल (आर एन० पी० वब० 11 अप्रैल 1903) आइ एन० सा० 1903 का प्रस्ताव VII
- 52 एल० सी० पी० 1894 खड XXXIII प० 273
- 53 कर्जन स्पीचज II प० 266 एक वष पूव उसने कहा था भारत में साम्राज्य के राजनीतिज्ञ क दा वक्तव्य है प्रथम यथासंभव दस क लाख करोड़ों लोगों को अधिकाधिक सतुष्ट प्रसन्न और समृद्ध बनाना द्वितीय दशकामियों को तथा उनकी संपत्ति को सुरक्षित बनाना हम एक वक्तव्य की उपेक्षा करके दूसरे वक्तव्य के पालन का और नहीं बल सकते (स्पीचज I प 325) तथा देखिए स्पाचेज III प० 404
- 54 उगाहरण के रूप में जनरल ब्रेकनवरी ने अपने पूर्वोद्धृत भाषण में घोषित किया भारत सरकार मित यमिता का दिशा में दिए गए किसी भी व्यावहारिक मुद्दे का स्वागत करती है और गंगा स्वागत करेगी (एन० सी० पी० 1894 घट XX\III प० 274)
- 55 वाचा रिप आई० एन० सी० 1895 प० 73
- 56 इंपीरियल गजटियर आफ इंडिया (1908) खड IV प० 187
- 57 इस विषय में विस्तृत अध्ययन के लिए देखिए मरा लेख इंडियन नेशनलिस्ट्स गेंड फारन वारम गेंड एक्सपोजिशन 1878 99 हिस्टोरिकल स्टडीज स० 1 इतिहास विभाग की विश्वविद्यालय
- 58 इंपीरियल गजटियर आफ इंडिया (1908) खड IV प० 348 9
- 59 आई० एन० सी० का 1885 का प्रस्ताव V वाचा रिप० आई० एन० सी० 1885 प०

- जागी पूर्वोक्त पृ० 254 ए० बी० पी०, 13 अगस्त, 15 अक्तू० 1885, हिंदू, 20 अगस्त 24 सित० 8 अक्तूबर नवंबर 1885 मराठा, 11 अक्तू० 1885 अक्तू०-नवंबर 1885 के बी० ओ० आई० में उद्धृत पत्र आर० एन० पी० बंग० 22 अगस्त, 5, 26 सित० 7 नवंबर 1885 9 जनवरी 1886 में उल्लिखित पत्र-पत्रिकाएँ, बाबे प्रेसीडेंसा एसासिएशन का 27 जनवरी 1886 को प्रस्तुत स्मरणपत्र रिपोर्ट आफ दि बाव प्रसीडेंसी एशोसिएशन 1835-6 पृ० 209, 214 5, मद्रास महाजन समा का लाइ डफरिन्स को सर्वोद्योग पत्र, मराठा, 7 मार्च 1886 पूना सावजनिक समा द्वारा 30 सितंबर 1886 को प्रस्तुत विरोधपत्र जे० पी० एस० एस० अक्तूबर 1886 और जनवरी 1887 ) खंड IX सफ्याए, 2 3)
- 60 आई० एन० सी० का 1891 का प्रस्ताव सं० III, वाचा, रिप० आई० एन० सी०, 1891 पृ० 23-6 राय पावर्टी पृ० 304-06 जोशी, पूर्वोक्त पृ० 141, 201 वाचा स्पीचज परिशिष्ट पृ० 9 10 गोखले स्पीचज, पृ० 1183, 1205 सी० शंकरन नायर, सी० पी० ए०, पृ० 336 बंसरी 3 अप्रैल (आर० एन० पी० बंग 7 अप्रैल 1900), वाचा, सी० पी० ए०, पृ० 617 गोखले स्पीचज पृ० 26-7 हिंदू 4 अप्रैल (बी० ओ० आई० 26 अप्रैल 1902), एच० आर०, अगस्त (आर० एन० पी० एन०, 4 अक्तूबर 1901) एच० एन० बनर्जी सी० पी० ए० पृ० 706 सी० आई० चित्तागणि इंडियन मिलिट्री एसोसिएशन एच० आर० मार्च 1903 पृ० 227 एत० एम० घाय० सी० पी० ए० पृ० 764 दत्त ई० एच० II पृ० XVII
- 61 बगाली 23 मई 1896 ए० बी० पी० 27 मई 1896 हिंदू 27 मई (आई० एस० बी० ओ० आई० 12 जुलाई 1896) आई० एन० सी०, 1899 1901 1902 1903 और 1904 के प्रस्ताव सफ्या 3 10 7 7 (वा) और 12 (सी) प्रमश बी० एन० बसु रिप० आई० एन० सा०, 1899 पृ० 53 बगाली 29 जन 1900 दत्त स्पीचज II पृ० 85 एच० एस० दीप्ति रिप० आई० एन० सी०, 1901 पृ० 154, गोखले (स्पीचज पृ० 27, पी० ए० चारलू एल० सी० पी० 1902 खंड XLI पृ० 114 5 श्रीराम बरी पृ० 148 एम० एन० बनर्जी सा० पी० ए०, पृ० 706 बी० एन० सेन रिप० आई० एन० सी० 1902 पृ० 105 ए० बी० पी० 15 मार्च 1903, वाचा स्पाचज पृ० 400 श्रीराम एन० सी० पी०, 1903 खंड XLII पृ० 105, एल० एम० घाय० सी० पी० ए० पृ० 764 बी० एन० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1903 पृ० 121
- 62 प्रस्ताव सं० VII (ए) तथा प्रस्ताव सं० XII (सी) प्रमश
- 63 नौराजी, स्पीचज पृ० 352 और दयिण पृ० 250 340-1 और ममानो पूर्वोक्त, 434 5
- 64 गोयने स्पीचज पृ० 106-07 और पंचिए पृ० 21 26-7 1156 1205
- 65 राय पावर्टी पृ० 287 293 305-06 हिंदू 24 सित० और 8 अक्तू० 1885 मराठा, 11 अक्तू० 1885 अक्तू०-नवंबर 1885 के बी० ओ० आई० में उल्लिखित पत्र-पत्रिकाएँ पूना साव जनिक समा द्वारा 30 सितंबर 1886 को प्रस्तुत विरोधपत्र पूर्वोक्त स्थान वाचा रिप० आई० एन० सा० 1891 पृ० 29 तथा पी० ए० पृ० 607 618 स्पाचज पृ० 396 पत्र इलेक्ट्रॉनिक इंडिया पृ० 110 137 सी० पी० ए० पृ० 490 स्पीचज II पृ० 45 85 ई० एच० II पृ० 566-7 श्रीराम एन० सी० पी० 1902 खंड XLI पृ० 148 और बहा 1903 खंड XLII पृ० 106 एच० आर० अगस्त (आर० एन० पी० एन० 4 अक्तू० 1902) एम० एन० बनर्जी सी० पी० ए० पृ० 706 709 वा० एन० सेन रिप० आई० एन० सी० 1902 पृ० 105 ए० बी० ए० 22 सितंबर 1903 एन० एम० घाय० रिप० आई० एन० सी०, 1903 पृ० 119



- स्पोचेज परिशिष्ट पं० 16 जोशी पूर्वोद्धत, पं० 253, राय पावर्टी, पं० 285 गोखल स्पोचेज पं० 1183 ए० भीमजी रिप० आई० एन० सी० 1891 पं० 40
- 73 1859 की एकाकरण याज्ञना की आलोचना के लिए देखिए पूना सावजनिक सभा ए स्टेटमट आफ इंडियन ब्वरचस जे० पी० एस० एस०, जुलाई 1881 (खंड IV सं० 1) पं० 10 वाचा रिप० आई० एन० सी० 1885 पं० 53 6 रिप० आई० एन० सी० 1891 पं० 23 रिप० आई० एन० सी० 1895 पं० 71, रिप० आई० एन० सी० 1897 पं० 29 स्पोचेज पं० 395, एन० एन० वैनर्जी सी० पी० ए० पं० 245, गाखे स्पोचेज पं० 1184 सी० वा० चिन्तामणि, इंडियन मिलिट्री एक्सपेंडीचर एच० जार० फरवरी 1903 पं० 120 आई० एन० सी० 1903 का प्रस्ताव VII (डी) अन्य पक्षों के लिए देखिए रानाडे रिप्यू आफ फासेटस थी एसज जान इंडियन फाइनान्स पूर्वोद्धत स्थल पं० 80 इंडियन स्पेक्टेटर-11 मई (आर० एन० पी०) वग 17 मई 1884) वाचा रिप० आई० एन० सी०, 1885 पं० 57 60 इंडियन लीफनटस सं० 9 पं० 6 7 जोशी पूर्वोद्धत पं० 156 आई० एन० सी० 1891 का प्रस्ताव III, गाखल स्पोचेज पं० 992 5 1184 नोरोजी, स्पोचेज पं० 160 352 बगवासा 20 अप्रैल (आर० एन० पी०) वग०, 27 अप्रैल 1895)
- 74 गाखले स्पोचेज पं० 1186 7 1880 में ही जस्टिस रानाडे ने स्टाक ब्राम्स सिस्टम समाप्त करने का मांग का धी देखिए उनका रिप्यू आफ फासेटस थी एसज आन इंडियन फाइनान्स पूर्वोद्धत स्थल पं० 80 भारतीय सैनिक अधिकारियों को मिलान वाले भारी वेतन की आलोचना भी इंडियन लीफनटस सं० 9 पं० 6 पर वा गई है
- 75 जार० एन० पी० वग 21 अगस्त 1880 और इंडियन स्पेक्टेटर 20 अगस्त (वर्षी 26 अगस्त 1882) इंडियन लीफनटस सं० 11 पं० 2 म्यन्शमिन्न 17 अगस्त (जार० एन० पी०) एम० अगस्त 1885) ए० वा० पी० 16 सित० 1886 ए० भीमजी रिप० आई० एन० सी० 1888 पं० 133-4
- 76 आई० एन० सी० 1902 और 1903 के प्रस्ताव सं० VII और VII (सी) ए० वा० पा० 29 अप्रैल 1902 सिं० 24 माघ 15 अप्रैल 9 जुलाई 1902 मराठा 6 जनार् 1902 गुजराती 6 जुलाई मन्ग स्टेट 8 जुलाई नरिब ओपानिमन 9 जुलाई इंडियन नेशन 21 जनार् (पी० आ० वा० 2 अगस्त 1902) बसरा 8 जनार् (आर० एन० पी०) वग 12 जुलाई 1902) आध्र प्रवासिक 16 अप्रैल (आर० एन० पी०) एम० 19 अप्रैल 1902) म्यन्शमिन्न 16 जुलाई (वर्षी 26 जनार् 1902) निजाम उन मत्व, 24 माघ (आर० एन० पी०) एन० 29 माघ 1902) एम० ए० वार्जी सी० पी० ए० पं० 706 वाचा स्पोचेज पं० 397 ए० वा० पी० 20 और 23 अगस्त 1903 बगवासा 22 अगस्त (आर० एन० पी०) वग० 29 अगस्त 1903) एम० वाफ इंडिया 18 जनार् वन 17 जुलाई (आर० एन० पी०) वग 18 जुलाई 1903) बसरी 21 जुलाई (वर्षी 25 जुलाई 1903) अन्नाबाय म जगभा, प्रजावध 16 अगस्त (वर्षी 22 अगस्त 1903) (वर्षी वर्गोज रावक मत्व है कि प्रजावधु न विवायन थी कि नगर म प्रमथ घनी मन् मभा म बिचकुन जनुस्थित ध) इंडियन पीपुल और धरध ममाधार 7 अगस्त (आर० एन० पी०) वग 15 अगस्त 1903) ए० एम० पाप भी पी० ए० पं० 763 अगवार आम 16 जुलाई (आर० एन० पी०) पी० 25 जनार् 1903)
- 77 जोशी पूर्वोद्धत पं० 239 241 252 मुबोधेय पत्रिका 16 मक्कर आम जनार् 2- नवंबर

(आर० एन० पी० बव, 22 नव० 1894), एडवोरेट 29 जनवरी (आर० एन० पी० यू० पी०, 4 फर० 1905)

- 78 राय पावटी व० 285 मराठा 24 मार्च 1895, जी० आर० एम० चिनननाग, एत० सा० पी० 1895 घट XXXIV पृ० 400, बगवासी 29 मार्च (आर० एन० पी० बग० 6 अप्रैल 1895), सहचर, 10 अप्रैल (बही, 20 अप्रैल 1895) अग्रवारे आम 28 मार्च (आर० एन पी० पी० 6 अप्रैल 1895) शुभ भूवक, 12 अप्रैल (आर० एन० पी० बव, 20 अप्रैल 1895)
- 79 इंदु प्रकाश 28 मई (आर० एन० पी० बव, 2 जून 1883) एम० वा० गुप्तरावदु रिप० आद० एन० सी० 1885 पृ० 72, दिदू 24 जून 1885, स्वामिनारा 17 अगस्त (आर० एन० पी० एम० अगस्त 1885), टिमून, 18 मिन० (बी० ओ० आई० अक्टू० 1886) जागी पूर्वोदत पृ० 6-8 एन० जी० चणवरकर, सी० पा० ए० पृ० 529, दाया एताज, परिनिष्ट प० 15 यहा मह उल्लेखनाय है कि 1893 म पदक प्रमाहेगा साता वा सामान्य कर निया गया था
- 80 आई० एन० सा० 1904 प्रस्ताव XII (वा) क मर हिं 25 मिन० (आर० एन० पी० बव 31 मिन० 1904) इन्डियन सोशल 28 अगस्त (आर० एन० पी० यू० पी० 3 मिन० 1904) एडवाइज 29 जनवरी (बही 4 फरवरी 1905) गाथल स्पीडज पृ० 102-4 इंदु प्रकाश 23 मार्च बमरहिं और गुजराती 26 मार्च (आर० एन० पी० बव 25 मार्च 1905) इन्डियन सोशल रिफॉर्मर 26 मार्च ओरियंटल रिभ्यू 29 मार्च बस 31 मार्च (बग 1 अप्रैल 1905) स्वामिनारा 9 मई प्रपच तारकी 13 मई इविशवर्तमणि 11 मई (आर० एन० पी० एम० 13 मई 1905)
- 81 नथिण उवर प्रकर पूर्वोदत प० 415-53
- 82 ए० बी० पी० 15 मई 1905 मराठा, 25 जून 1905, एच० आर० जुलाई 1905 पृ० 80-1 आर० एन० पी० बव 1, 8 जुलाई 1905 म आर० एन० पी० एम० 1 15 जुलाई 1905 मे आर० एन० पी० बग 1 8 15 जुलाई 1905 म तथा आर० एन० पी० यू० पी० 1 8 जुलाई 1905 म उन्निष्ठित एत एतिका

- प्रस्तावों में आर्थिक तर्कों का स्पष्ट प्रतिपादन तो नहीं है परंतु जिन लोगों ने इन प्रस्तावों को प्रस्तुत किया और जिन महानुभावों ने इन पर वक्तव्य लिए उन्होंने आर्थिक तर्क एवं युक्तियों अथवा पक्ष का भी देखा है ए० एम० भीमजी रिप० आई० एन० सी०, 1888 प० 134 और तिलक रिप० आई० एन० सी० 1891 प० 389 और देखा है इंडियन स्पेक्टेटर, 22 जनवरी (आर० एन० पी० वब 28 जन०, 1882), मराठा 14 फरवरी 1886 हिंदुस्तान 7 अक्टू० (आर० एन० पी० एन० 8 अक्टू० 1891) गोखले स्वीचज पृ० 1185, 1187 8, बेसरी, 17 जनवरी (आर० एन० पी० वब 21 जनवरी 1899)
- 87 जोशी पूर्वोद्धत, प० 156 242 246-7 253-4, गोखले स्वीचज प० 46 8 90-1 1183-5 और देखा है, राजा रामपाल मिह रिप० आई० एन० सी० 1886 प० 93 यह दृष्टि भी मजिस्ट्रेट हागा कि यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में ही राजा राममोहन राय ने देश के प्रशासनिक ढाँचा में क्रांति के उपाय के रूप में स्थाई सेना के एक बहुत बड़ा भाग में लिए नगर रक्षक दल की स्थापना की वकालत की थी उन्होंने कहा था कि मानव का दुःख देने वाले भूमि राजस्व आदि में वृद्धि करने का किसी भी प्रकार का दंग की अपेक्षा इससे होने वाली वचन में अधिक उपयोगी लाभ हागा (बी० बी० मजूमदार पूर्वोद्धत पृ० 70)
- 88 1886 का प्रस्ताव स० XII 1887 का प्रस्ताव स० V तथा 1888 का प्रस्ताव स० VI तथा निम्नलिखित
- 89 रामपालमिह रिप० आई० एन० सी० 1886 प० 93 एम० वाहिद अली रिप० आई० एन० सी० 1888 पृ० 133 तिलक, रिप० आई० एन० सी० 1891 प० 389 गोखले, स्वीचज प० 489 इस दृष्टि से कि इस भाग की इस्तेमाल निमित्त भारतीयों को अथवा दगातियों को धकेलने के लिए एक और प्रयास की तरह न किया जाए गोखले ने प्रस्ताव रखा कि सरकार प्रयोग के लिए निम्नलिखित धन का तथा किसी विशिष्ट जाति के निम्नलिखित वग का चुनाव कर सकती है (वहाँ) तथा देखा है वही प० 90-1 जोशी पूर्वोद्धत प० 78 252, हिंदू 20 अप्रैल 1885
- 90 इस विषय के विस्तृत विवेचन के लिए देखा है मरा लेख इंडियन नेशनलिज्म ऐंड फारन वारर एंड एक्सपोर्टिडिज्म 1878 9 प्रकाशित हिस्टोरिकल स्टडी, पृ० 1
- 91 आई० एन० सी० के 1892 1895 1897 और 1898 के प्रस्ताव क्रमशः VII VIII I II III और VII, पी० मरुता स्वीचज प० 452 3 राय पावर्टी प० 299-300 आजाद 17 मई (आर० एन० पी० एन० 25 मई 1895) एम० एन० बनर्जी सा० पी० ए० पृ० 255 एम० तेंड० डब्ल्यू० परिशिष्ट पृ० 48 डी० जी० उपाध्ये रिप० आई० एन० सी० 1895 प० 101 पी० ए० चारनू एन० सी० पी० 1896 घट XXXV पृ० 286, नारायणी स्वीचज पृ० 344-6 349 50 परिशिष्ट प० 79 93 तथा आगे बाबा स्वीचज, परिशिष्ट पृ० 33 रिप० आई० एन० सी० 1897 प० 32 गायने स्वीचज प० 1206 07 जा० एम० अय्यर, बिलबी बमोजन पृ० III प्रश्न 19800 हिंदू 26 अगस्त 1897 गिवाज उल अगस्त 12 जन० (आर० एन० पी० एन० 19 जन० 1897) हिंदुस्तानी 13 अक्टू०, 22 नो० (वही, 20 अक्टू० 29 नो० 1897) मन्चर, 22 नो० 1897 (आर० एन० पी० वब 1 जन० 1898) सत्रावली 12 फरवरी (वहाँ 19 फरवरी 1898) जा० आर० एम० चिन्तनवाग एम० गा० पी० 1898 घट XXXVII पृ० 496 आर० एम० गयाना वनी प० 525-7 बगाम्पो 26 मार्च 1898 मुरवा 26 फर० रायमहा 1 मार्च, मन्चर रि० 27 फर० (आर०

- एन० पी० बब, 5 मय 1898) दत्त इग्लंड ऐंड इंडिया पूर्वोद्धत 110 1 स्पीचेज I पृ० 34 5  
 41 ए० एम० बोस सी० पी० ए प० 421 पी० ए० चार्ल्स एल० सी० पी० 1902 खड  
 XLI पृ० 116 एच० ए० यादविया रिप० आई० एम० सी० 1904 प० 203 एल० एम०  
 पोप सी० पी० ए०, पृ० 765 केसरी 7 फरवरी (आर० एन० पी० बब 11 फरवरी 1903)  
 92 सी० पी० ए० प० 168 तथा देखिए, नौरोजी स्पीचेज परिशिष्ट प० 75 6 78 90  
 93 मसानी पूर्वोद्धत प० 456 पर  
 94 राय, पावर्टी पृ० 299 इगो प्रकार 1898 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ने पूछा  
 'क्या इग्लैंड को यह पक्का विश्वास है कि यदि भारत की सुरक्षा नष्ट हो गई और भारत ब्रिटिश  
 साम्राज्य से छिन गया तो गढ़ प्रभारों के रूप में पात मूल्यवान विषयो के रूप में इग्लैंड को  
 मिलने वाले साध्या करोड़ों रुपया का हानि से इग्लैंड की प्रतिष्ठा को उसने गौरव को उसने  
 ध्यापार को, उसक विनियोजन को उसकी पूंजी को तथा उसकी जनता को किसी प्रकार की  
 बोझ हानि नहीं उठानी पड़ती ? (ए० एम० बोस सी० पी० ए० पृ० 420) और देखिए हिंदू  
 20 अगस्त 1885 13 फरवरी 1890 सुरमि 1 सित० (आर० एन० पी० बब० 5 सित०  
 1885) पताका, 18 सित० (बही 26 सित० 1885) तिरगा निगान 1 सितवर (आर०  
 एन० पा० एम० 15 सित० 1888) ए० बी० पी० 5 अग्रज 1895 27 मई 1896 आर०  
 एम० सयानी एल० सी० पी० 1898 खड XXXVII पृ० 527 एम० एन० बनर्जी एम०  
 ऐंड० डब्ल्यू० परिशिष्ट प० 26 48 दिसवी कमिशन खड III प्रश्न 19435 सी० पी० ए०  
 प० 708 केसरी 10 जून (आर० एन० पी० बब 14 जून 1902), दत्त इग्लंड ऐंड इंडिया,  
 पृ० 140-1, 145 166 ई० एच० II पृ० 567, गोखले, स्पीचेज पृ० 28 105 1208  
 95 आर० एन० पी० बब, 29 अगस्त 1903  
 96 राय पावर्टी प० 296  
 97 सी० शवरन नायर सी० पी० ए०, पृ० 387, गोखले स्पीचेज पृ० 48  
 98 नौरोजी स्पीचेज परिशिष्ट पृ० 75-6 तुलनीय एच० एल० सिंह पूर्वोद्धत प० 165 8 206  
 99 आई० एन० सी० 1891 का प्रस्ताव IV, तिलक रिप० आई० एन० सी० 1891 प० 38 9  
 एम० ए० एस० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1885 पृ० 68 जोशी पूर्वोद्धत प० 156 252  
 नौरोजी स्पीचेज परिशिष्ट पृ० 75 राय पावर्टी प० 297, बाबा स्पीचेज परिशिष्ट पृ० 16  
 गोखले स्पीचेज पृ० 48-9 90-1  
 100 नौरोजी पावर्टी पृ० 216 सी० पी० ए० पृ० 165 6 स्पीचेज प० 658 9 664 एल० एन०  
 बनर्जी, स्पीचेज I पृ० 192 एल० ऐंड डब्ल्यू० प० 422 और सी० पी० ए० प० 250, ए०  
 बी० पी० 3 सितवर 1885 और 19 जुलाई 1891 बगाली 4 जून 1887 10 अक्टू० 1897  
 और 1 जुलाई 1903 केसरी 14 सितवर (आर० एन० पी० बब 18 सित० 1897) ए०  
 एम० बोस सी० पी० ए० पृ० 403 पी० ए० चार्ल्स एल० सी० पी० 1902 खड XLI  
 प० 115 6 अमृत बाजार पत्रिका ने अपने 1 मई 1884 के अंक में इस दृष्टिकोण का विपरीत  
 ढंग से प्रयोग किया उनमें लिखा 'यही कारण है कि भारतीय जनता रूसी सेना के भारतीय  
 सीमाओं की ओर आग बढ़ आने पर असौम्य सतों अनुभव करती है क्योंकि उसका विश्वास है  
 कि रूसी जितना ही भारत की सीमा के अधिक निकट आएंगे उतना ही उसके मालिक उसका  
 अधिक आदर-सम्मान करेंगे'  
 101 इंडिया जुलाई 1897 प० 202 और उदाहरणाय देखिए ए० बी० पी० 21 मई 1885 31 मई



1888 27 जगस्त 1886 को ब्यया की बटौती पर बावे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत पापन सेंकड एनुअल रिपोर्ट आफ दि बाब प्रेसीडेंसी एसोसिएशन 1886-7, 30 सितंबर 1886 का पूना सावजनिक सभा द्वारा प्रस्तुत विरोधपत्र, जे० पी० एस० एम० अक्टू० 1886 और जनवरी 1887 (खंड IX स० 2 और 3) जोगी, पूर्वोद्धत, प० 824 5 आई० एन० सा० 1891 और 1904 के प्रस्ताव स० III (बी) और III त्रमश, पी० मेहता, स्पीचेज, प० 456 मालवाय स्पीचज प० 250 281 बाचा, स्पीचेज परिशिष्ट, प० 9 31 2 सी० पी० ए०, प० 607-8 ए० नदी, इन्डियन पालिटिक्स प० 127, 'दि इवोनामिक सिच्युएशन इन इडिया डान, अक्टू० 1899 (खंड IV स० 3) प० 65

102 नतिक और सामाजिक लाभो के लिए हम थोडा से ही उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं दिये जा० व० गोखल स्पीचज, प० 188 इंडियन पीपुल्स राइट यामत बाजार पत्रिका ने अपन 23 निसंबर 1886 के अफ म अपना दड मत प्रकट करते हुए लिखा कि भारत व लोगों का दावा है कि भारताय प्रशासन व सभी स्थाना पर हा उनका ही अधिकार है उनके इस दावे का आधार यह है कि इन सभी स्थाना का व्यय भार भारतीय मसाधना द्वारा उठाया जाता है अत भारत के नागरिक होने के नाते इन स्थाना को व अपना ही संपत्ति समझत हैं इसी प्रकार 1904 म राष्ट्रीय कांग्रेस म प्रस्ताव स० I का पक्ष करत हुए सुर्देनाय बनर्जी न तब उपस्थित किया कि विचारणीय तत्व यह है कि यद्यपि दश हमारा है, धन हमारा है भारी जनसंख्या हमारी है फिर भी हमारे भाग्य म ऊंची नियुक्तिया का बचल 14 स 17 प्रतिशत भाग हा उपनय है एसा क्यों ? (रिप० आई० एन० सी० 1904 प० 64) सेवाभा व भारतीयकरण का प्रचार राजनीतिक दृष्टि से इस रूप म किया गया कि यदि शान्त भारतीय लोगो को लाभप्रद नियुक्तिया न दी गईं तो वे राजनीतिक दृष्टि से असंतोष अनुभव करेंगे उदाहरण के लिए दिये गोरोगी एसेज प० 38 पावर्टी प० 205, स्पीचज, प० 507 माबलिक, स्पाचज, प० 701 ए० बी० पी० 9 जनवरी 1880 गोखल स्पीचज प० 68-9

103 आई० एन० सा० 1801 1897 1902 1903 और 1904 के प्रस्ताव संख्या III III (ii) XV II (गो) और I (बी) त्रमश नौराजा पावर्टी, प० 124 184 639 स्पीचज प० 284 6 परिशिष्ट प० 5 एम० ए० बनर्जी स्पीचज I प० 191 सी० पी० ए० प० 2, 0 एम० टेंक डब्ल्यू० परिशिष्ट प० 26 8 32 44 47 16 मई 1880 का पूना की जनगणना म स्वीकृत विरोधपत्र जे० पी० एम० एम० जुलाई 1880 (खंड III स० 1) प० 7 रानाडे रिप्यू आफ पारवेटन थो एसेज डान इन्डियन काइनाम जे० पी० एम० एम० जुलाई 1880 (खंड III स० 1) प० 80 पूना सावजनिक सभा द्वारा 2 मार्च 1881 को प्रस्तुत शायन जे० पी० एम० एम० जनार् 1881 (खंड IV स० 1) प० 12 जोगी, पूर्वोद्धत प० 5 6 49 155 बाब प्रेसीडेंसी एसोसिएशन का 27 अगस्त 1886 को प्रस्तुत स्मरणपत्र गवर्नर जनरल रिपोर्ट आफ डि बाब प्रेसीडेंसी एसोसिएशन मन्गल मन्गजन सभा का स्मरणपत्र रिपोर्ट आफ दि काइनाम कमिटी (जनवरी 1887) खंड II प० 452 3 रानाडे मेमोरेंडम शाय इन्डियन की खंड I प० 398 मातवीय स्पीचेज प० 290 299-301 518 वायने स्पीचज प० 28 63-4 1187-9 बाचा स्पीचज परिशिष्ट प० 26-7 29 31 2 गो० पी० ए० प० 609 दग ई० एच० I प० 413 ई० एच० II प० XV II सी० पी० ए० प० 491 जी० एम० एम्पर ई० ए० प० 100 विपरी कमिशन खंड III प्रश्न 18-64 एम० ए० स्वामिनाथ प्रम्पर, रिप० आई० एन० सी० 1895 प० 68 माया मन्गजन रिप० आई० एन० सा० 1891

प० 15 जी० ए० पाटिल रिप० आई० एन० सी० 1902 पृ० 139 नवविभावर 14 जून (आर० एन० पी० बग० 19 जून 1880) अद्ययाय 23 जन० (आर० एन० पा० बग० 29 जन० 1881) बरुन, 31 दिग०, गियाजी 29 निम० 1882 (वही 7 जन 1883) इडियन गवर्नर 25 फरवरी और 24 जून (वही माच और 30 जून 1883 प्रमग) मराठा 3 जून 9 मिनवर 1883 अहमोडा अद्यवार 9 जलाई (आर० एन० पा० पा० एन 14 जुलाई 1883) उधिन बरना 15 माच (आर० एन० पी० बग० 22 माच 1884) नवविभावर 1 मिन० (वही 6 मिन० 1884) पताका 10 जलाई (वही 18 जुलाई 1885) नटिव मापारियन 19 अप्रल (आर० एन० पा० बग० 25 अप्रल 1885) इदु प्रकाश 25 मई (वही 30 मई 1885) ए० बा० पी० 21 मई 1885 18 नवबर 9 और 16 निम० 1886 बगाना 16 जन० 1886 14 फरवरी 1886 इडियन स्पेक्टर 27 जून और 14 नव० 1886 मराठा 20 जून हिंदू 15 जलाई (बी० ओ० आई० जुलाई 1886) भारतीय प्रस व विचार का गणान्याय गार-नाय बी० ओ० आई० जुलाई 1886 बेसरी 31 जन० (आर० एन० पी० बग० 4 फरवरी 1888) अद्यवारे आम 21 अप्रल (आर० एन० पी० पी० 28 अप्रल 1888) ए० बा० पी०, 31 मई 1888 और 3 माच और 24 मई 1894 विक्टोरिया पेपर 30 नव० (आर० एन० पी० पी० 12 निम० 1891) आयजनप्रियन 8 अप्रल (आर० एन० पी० एम० 30 अप्रल 1893) जानोन्यम 1 मई (वही 15 मई 1893) बगवामी 20 अप्रल (आर० एन० पा० बग० 27 अप्रल 1895) बगुमती 5 मई (वही 14 मई 1898) बेसरी 31 माच (आर० एन० पी० बग० 4 अप्रल 1903), इडियन पीपुल 18 अगस्त (आर० एन० पी० यू० पा० 27 अगस्त 1904)

104 भिन्न भिन्न लागू का जोड़ भिन्न भिन्न था और यह स्वाभाविक ही था क्योंकि उन सबन भारतीय राष्ट्रीय काग्रत के 1892 के अधिवेशन में मन्मोहन मालवाय द्वारा जटाए गए अनुमानित और मिलते जुलते आवडों पर ही हिसाब लगाया था (स्पीचेज प 515 6) तथा दिये नौराजी स्पीचेज पृ० 134 (उनकी प्रवचणना 20 करोड़ रुपये बटती थी) परिशिष्ट प० 6 89 90 वाचा सी० पी० ए० पृ० 607 दन ई० एच० I पृ० 427 की पादटिप्पणी स्वाचज I प० 178 गायने स्पीचेज, पृ० 1187 8 समन्वय लेखा जात्रा के लिए दक्षिण इंदारियल गजटियर आफ इडिया (1909) खड IV प० 201

105 भाइलिक स्पीचेज पृ० 186-7 पी० महता स्पीचेज पृ० 225 अन्य भारतीय मताओं के लिए दक्षिण प्रातोडिगस आफ पब्लिक सर्विस कमाशन (कलकत्ता 1887 खड I भाग III पृ० 18 20 45 6 खड II भाग II पृ० 23 खड III भाग III पृ० 5 खड IV भाग II पृ० 102 325 (तिलक) खड V भाग II पृ० 288 393 खड VI भाग II पृ० 36 240 273 428 442 494 504 भाग II पृ० 32 71 86

106 ए० एम० बोस सी० पी० ए० पृ० 407 गोखले स्पीचेज पृ 68

107 बी० ओ० आई० जुलाई 1886

108 और देखिए रास्त गुप्तार 29 जून शुभ सूचक 13 जून (आर० एन० पी० बग० 5 जुलाई 1879) एन० ए० स्वामिनाथ अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1885 प 68 इडियन स्पेक्टर और मराठा 20 जून (बी० ओ० आई० जुलाई 1886) स्वदेशमित्रन तिथिरहित (आर० एन० पी० एम० फरवरी 1887) बेसरी 31 जनवरी (आर० एन० पी० बग० 4 फरवरी 1888) आयजनप्रियन 8 अप्रल (आर० एन० पी० एम० 30 अप्रल 1893) ए० बी० पी० 24 मई

1894, वसुमती 5 मई (आर० एन० पी० बग० 14 मई 1898), जी० एस० अय्यर, ई० ए०, पृ० 100 दत्त स्पीचेज I पृ० 94

109 प्रोसीडिंग्स आफ पब्लिक सर्विस कमिशन (1887) खंड II भाग III पृ० 41 खंड III भाग III पृ० 7, खंड IV भाग III पृ० 147 खंड IV भाग II पृ० 214 खंड VI भाग II पृ० 386 भाग III पृ० 93

110 बही, खंड IV भाग II पृ० 130 (नोरोजी) पृ० 145 (रानाडे), खंड V भाग II पृ० 230 खंड VI भाग II पृ० 74

111 एस० एन० बनर्जी एस० एंड डब्ल्यू० परिशिष्ट पृ० 47 तथा देखिए एस० एन० बनर्जी, विलवी कमिशन, खंड III प्रश्न 19419

112 नोरोजी स्पाचेज परिशिष्ट 5 इसके अतिरिक्त परिशिष्ट 11 31 2 37 भी

113 ए० बी० पी० 27 फरवरी 1880 रानाडे, रिब्यू आफ फासेटस वी एसेज आन इण्डियन फाइनांस जे० पी० एम० एम० जुलाई 1880 (खंड III स० 1) पृ० 80 जलवा तूर 1 माघ (आर० एन० पी० पी० एन, 4 माघ 1880), भारत मिहिर 3 अगस्त (आर० एन० पी० बग 14 अगस्त 1880) जे० पी० एस० एस० जुलाई 1881 (खंड IV स० 1) पृ० 10, बगाली 29 अक्टू० 1881 बकुल, 31 दिस० 1882, शिवाजी 29 दिस० 1882 (आर० एन० पी० बग 6 जन० 1885) भारत मिहिर, 5 जून (आर० एन० पी० बग० 9 जून 1883, सुरभि 2 जून (बही, 7 जून 1884) नवविभावर 1 सित० (बही, 6 सित० 1884), तत्व-विवेचनी 4 मई (आर० एन० पी० एम० मई 1884), बगाली, 19 जुलाई 1884, प्रजावध 6 फर० (आर० एन० पी० बग 14 फरवरी 1885), पताका, 11 सित० (बही 19 सित० 1885) नेटिव ओपीनियन 19 अप्रैल आर० एन० पी० बग 25 अप्रैल 1885 इंदु प्रवाश 25 मई बही 30 मई 1885 स्वदेशमित्रन 17 अगस्त (आर० एन० पी० एम० अगस्त 1885) वी० राघवाचारी रिप० आई० एन० सी०, 1885 पृ० 44 5, ज० यू० यात्रिक बही पृ० 65 एम० ए० एम अय्यर बही पृ० 68 एम० एन० बनर्जी स्पीचेज III पृ० 15-6 195 मछल, 14 फर० और 18 जुलाई 1886 सिध टाइम्स 10 जून बगाली 3 जुलाई (बी० जी० आई० जुलाई 1886) सजीवनी 9 जन० सोम प्रवाश 11 जनवरी (आर० एन० पी० बग० 16 जन० 1886) भारत मिहिर 14 जन० (बही, 23 जन० 1886) सार सुधानिधि, 15 माघ उचित बचना 13 माघ सोम प्रवाश और समाचार पत्रिका 15 माघ (बही 20 माघ 1886) बगवासी 6 नव० (बी० 13 नव० 1886) रिपोर्ट आफ् दि प्रसीडेंटी एमासिगमन 1886 7, पृ० 44-6 54 30 सितंबर 1886 का पूना सावजनिक सभा का ज्ञापन जे० पी० एम० एम० अक्टू० 1886 जनवरी 1887 (खंड IX स० 2 3) पृ० 6 मंगल मंगलन सभा तथा अन्य स्थानीय सावजनिक सभाओं का ज्ञापन रिपोर्ट आफ् दि फाइनांस कमिटी 1886 खंड II पृ० 453 स्वदेशमित्रन निधिरिडित (आर० एन० पी० एम० फरवरी 1887) एम० एम० अय्यर और जी० एम० अय्यर प्रोसीडिंग्स आफ् दि पब्लिक सर्विस कमिशन 1887 खंड V भाग II पृ० 214 और 288 प्रथम ए० बी० पी० 16 सित० 1886 द्रिध्या 18 सितंबर और विचार फराह 21 सित० (बी० आ० आई० अक्टू० 1886) टिडू 25 मई 1887 आर० एन० पी० बग 29 जनवरी 1888 स उन्निपिन पत्र पत्रिकाए नेमरी 31 जनवरी (आर० एन० पी० बग 4 फरवरी 1888) आज्ञा 3 फरवरी (आर० एन० पी० एन० 7 फरवरी 1888) इन्डियन 18 अगस्त (बही 21 अगस्त 1889) निरमा विमान 5 अक्टू० (आर० एन० पी० एम० 31 अक्टू० 1889) नोरोजी स्पीचेज पृ० 144 397 परिशिष्ट पृ० 32 3 अक्टू० 18

- हि० 26 फर० (आर० एन० पी० पी० 3 माच 1894) राय पावटीं पृ० 306 308 10 318 एम० के नायर रिप० आई० एन० सी० 1895 प० 74 विषभर नाथ एल० मी० पी० 1897 खड XXXVI प० 185 और वही 1898 खड XXXVII प० 518 9 वस्तुत उच्च वेतनो मे कटौती की माग एक पुरानी माग ही थी क्योंकि 1852 म सवप्रथम ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के तथा बंगाल प्रेसाडेंसी के मूल विवासियो की एसोसिएशन के गणन म यह माग की गई थी (बी० बी० मजूमदार पूर्वोद्धत प० 482 पर)
- 114 डक्न स्टार 12 सित० (आर० एन० पी० वव, 18 सित० 1880) ज० पी० एस० एस० जलाई 1881 (खड IV स० 1) पृ० 10 जोशी, पूर्वोद्धत, प० 3 7 64 69 75 7 82 मराठा 25 फरवरी 1883 इडु प्रकाश 26 माच 28 मई (आर० एन० पी० वव 31 माच 2 जून 1883) जे० यू० याज्ञिक रिप० आई० एन० सी० 1885 प० 65, एस० ए० ज्यूर वही पृ० 68 हिंदू 24 जून 1885 इंडियन प्रम ओपीनियम वा सपाकीय सार सक्षप बी० ओ० आई० जुलाई 1886 मराठा 17 जून 1886 मराठा 20 जून इंडियन मिरर 22 जून 3 जुलाई बंगाली 3 जुलाई (बी० ओ० आई० जुलाई 1886) 27 अगस्त 1886 का वावे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन द्वारा खर्चों पर प्रस्तुत गणन पूर्वोक्त स्थल 30 सितंबर 1886 को पूना सावजनिक सभा का विरोधपत्र पूर्वोक्त स्थल, पृ० 7, 10 मद्रास महाजन सभा तथा अय जनक स्थानीय सावजनिक सस्थाओ द्वारा प्रस्तुत गणन रिपोर्ट आफ दि फाइनास कमेटी 1886 खड II प० 450 452 54 459 65 471 84 रानाडे मेमारडम आफ डिसेंट (अस्थीकृति मे गणन) वही खड 1 प० 395 6 398 403 04 गोखले स्वीडज प० 1197 9 और देखिए तिलाक प्रोसाडिम आफ दि कौमिल आफ दि गवर्नर आफ दि वावे 1895 खड XXXIII पृ० 91
- 115 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने प्रथम अधिवेशन मे ही इस माग को उठाया और उसके पश्चात वर्षों तक यह माग दोहराती तो रही परंतु उसने इसके पक्ष मे किसी प्रकार के आर्थिक कारण उपस्थित नहीं किए कांग्रेस के लिए देखिए 1885 1894 1896 1897 और 1898 के प्रस्ताव सख्या II IV XI (जी) IV (एफ) और XX (एफ) क्रमश एस० मुनासियर रिप० आई० एन० सी० 1885 प० 27 8 स्वदेशमित्र 17 अगस्त (आर० एन० पी० एम० अगस्त 1885) तिरया निशान 14 जुलाई (आर० ए० पी० एम 15 जुलाई 1888) स्वदेशमित्र 21 जुलाई (वही) 31 जलाई 1888) स्वदेशमित्र 6 जून (वही) 15 जून 1900)
- 116 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन म भाषण करते हुए जे० यू० याज्ञिक ने इस तथ्य की जालोचना की कि ग्राम विभाग अग्र्यता द्वारा खर्चों म कटौती के लिए बना यह योजना विघात होता है अथवा उसका पालन इधर उधर किसी कंत्र को नीकरी स हटाने के रूप म अथवा किसी सरकारी सस्थान के प्यास कर्मचारियों को पाना पिलान वादे विसा नीकर को अथवा 8 10 द० मासिक वेतन पाने वाले किसी कपरासी को नीकरी स हटाकर किया जाता है इसके पश्चात उन्होंने अपना मत प्रकट किया कि इस प्रकार की आमू पोछने वाली नाति अपमाने से निश्चित रूप से किसी प्रकार के सतोपग्रद परिणाम की आशा नहीं का जा सकता (रिप० आई० एन० सी० 1885 प० 65) जनवा तर 1 माच (आर० एन० पी० पी० एन 4 माच 1880) ए० बी० पी० 21 मई 1885 सोम प्रकाश और आनंद बाजार पत्रिका 1 जून (आर० एन० पी० वय० 6 जून 1885) रटवरे रि० 1 जून (आर० एन० पी० पा० 15 जून 1889) सजावनी 21 सितंबर (आर० एन० पी० वय 28 सितंबर 1889) निरया निशान 5 अक्टूबर (आर० एन० पी० एम० 31 अक्टूबर 1889) रटवरे हि० 26 फरवरी (आर० एन० पी० पी०

- 3 मार्च 1894), सजीवनी, 20 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 27 अप्रैल 1895), बमुमती 5 मई (वही 14 मई 1898)
- 117 ए० एन० बनर्जी सा० पी० ए०, प० 263-4 और स्वदेशाभिमान 15 अप्रैल (आर० एन० पी० एम० अप्रैल 1878), आई० एन० सी० के 1891, 1892 1893 1894 1901 और 1902 के प्रस्ताव प्रस्ताव सख्या VII (सी) V (ई) III (ई) XVI (ई) VII और X, अखदारे आम 20 अगस्त (आर० एन० पी० पी०, 7 सितंबर 1895) सहृदय 10 अप्रैल (आर० एन० पी० बग 20 अप्रैल 1895) बगाली 11 अप्रैल 1896 ए० एन० बनर्जी ए० एन० एंड ड्यू० परिशिष्ट पृ० 25 जी० ए० अम्यर, विल्वी कमीशन, खंड III प्रश्न 18963 19710 19719 20 19735 19761 हिंदुस्तानी, 14 जुलाई (आर० एन० पी० एन० 20 जुलाई 1898), ए० एम० बोस सी० पी० ए० प० 426 गोत्रले स्पीचेज, प० 95 1200, विक्टोरिया पेपर 8 जुलाई (आर० एन० पी० पी० 19 जुलाई 1902) और दक्षिण नोरोजी स्पीचज परिशिष्ट प० 15
- 118 1886 में ए० एन० बनर्जी ने इन वारणा को बड़े ही सुंदर ढंग से सजिप्त रूप में प्रस्तुत किया है देखिए (स्पीचेज III प० 10-20)
- 119 ए० बी० पी० 19 नवंबर 1880 इंडियन स्पेक्टेटर 24 अक्टूबर (आर० एन० पी० बब, 30 अक्टू० 1880) बगाला 19 मार्च 1881 12 मार्च 1882 मराठा 27 मार्च 1881 सोम प्रकाश 17 जनवरी (आर० एन० पी० बग० 22 जन० 1881), दाना प्रकाश 20 फरवरी (वही 26 फर० 1881) बम्बान सजीवनी 22 मार्च (वही 2 अप्रैल 1881), साधारण 13 मर्च (वही 10 नव० 1881) चाखवार्ता 6 मार्च (वही मार्च 1882) सोम प्रकाश 27 मार्च (वही 1 अप्रैल 1882) बदवान सजीवनी 2 मई (वही 13 मई 1882), अनोडा अखबार 7 मई (आर० एन० पी० पी० एन० 10 मई 1883), हिंदुस्तान 28 मार्च (वही 2 अप्रैल 1884) बगाली, 15 मार्च और 21 जून 1884 आर० एन० पी० बग० 31 मई 21 28 जून 5 12 19 जुलाई 1884 बी० ओ० आई० 30 जून 15 31 जुलाई 1884 जून छुट्टी 1886 तथा आर० एन० पी० बग० 2 9 16 23 30 जनवरी, 3 10 24 जुलाई 1886 म उन्निधिन पत्र-पत्रिकाए शफीव हिं 22 मई (आर० एन० पी० पी० 31 मई 1886) गम्बारे हिं 26 जून (वही 5 जुलाई 1886) बगाली 10 जून 1885 बी० ए० पोटुनु गुड रिप० आई० एन० सा० 1885 पृ० 72. बगाली 3 अप्रैल, 17 जुलाई 1886, मराठा 17 अक्टूबर 1886 ए० एन० बनर्जी स्पीचेज III, पृ० 6 12 4 बाब प्रसोद्धा एनोसिएशन द्वारा 27 अगस्त 1886 को प्रस्तुत पापन पूर्वोक्त स्थल मरठ एनोसिएशन और मद्रास मद्राजन तथा म स्मरण-पत्र रिपोर्ट आफ् रि फाइनान्स कमेटी 1886 पृ० 452 3 हिंदू 2 मई 1887 बगवाना 26 फर (आर० एन० पी० बग० 5 मार्च 1887) रास्न गुफ्तार 2 अप्रैल (आर० एन० पी० बब 27 अप्रैल 1887) मुन्तान उन अखबार 15 दिग० (आर० एन० पा० एम० 15 दिग० 1887), जागा पूर्वोक्त पृ० 155 हिंदू, 22 जून 1888 1 जून 1891 3 फरवरी 1892, 31 जुलाई 1893 2 अप्रैल 1894 हिंदुस्तान 5 फरवरी (आर० एन० पी० एन०, 10 फर० 1889) समय 10 मार्च सजीवनी 11 मार्च (आर० एन० पी० बग० 18 मार्च 1893) धाम धार्मी 20 मार्च सहृदय 22 मार्च (वही 1 अप्रैल 1883) हिंदुस्तान 5 अप्रैल (आर० एन० पी० बब० 11 अप्रैल 1876) भाषा स्पीचज परिशिष्ट 26 ए० बी० पा० 27, 28 फरवरी 1877 मराठा 14 मार्च 1897 सजीवनी 13 फरवरी (आर० एन० पी० बग०, 20 फरवरी 1897),

- 24 माच के उडिया और नवसवाद (वही, 15 मई 1897) यद्रास स्टडड, 11 मा एस० पी० आ० आई० 21 माच 1897) पात प्रकाश, 11 माच सत्य नि वाडियावाड टाइम्स 10 माच (आर० एन० पी० बव 13 माच 1897) श्री सत्य 17 माच, इंडियन ट्रेड, 21 माच (वही 27 माच 1897) आजाद 5 माच हिंदुस्ता (वही 10 माच 1897) अजमले हिंद 3 माच रफी उल अखबार 5 अप्रल (वही 1897), कर्णिक प्रकाशिका 8 माच (आर० एन० पी० एम० 15 माच 1897) 16 माच (वही 31 माच 1897) स्वदेशमित्र 1 अप्रल (वही 15 अप्रल 1897) 30 सित० (वही 15 अक्टू० 1898) स्वदेशमित्र 14 अप्रल (वही 30 अप्रल 1899) हितवादी 3 माच (आर० एन० पी० बग० 11 माच 1899) (वही 30 अप्रल 1899) 3 माच (आर० एन० पी० बग०, 11 माच 1899) आंध्र प्रकाशिका 10 माच (आर० एम० 15 माच 1900) दत्त इंग्लिश एंड इंडिया प० 165
- 120 पी० ओ० आई० जुलाई 1886
- 121 बंधान सजीवनी, 17 जून सहचर 18 जून समय, 23 जून (आर० एन० पी० बग 1884) अमर पत्र 29 जुलाई (आर० एन० पी० पी० एन० 4 अगस्त 1884) 1 जुलाई (वा० ओ० आई० 31 जुलाई 1884) एस० एन० बनर्जी स्प्रीचेज III प०
- 122 नोगोजी एसेज प० 170 पावर्टी प० 142 210 सी० पी० ए० प० 173 4 अ सी० 1885 का प्रस्ताव सख्या VI जोशी पूर्वोद्धत प० 102-05 111 2 131 5 व मई (आर० एन० पी० बव 4 जून 1898) दत्त ई० एच० II प० XVII 612
- 123 जोशी पूर्वोद्धत प० 55 61 27 अगस्त 1886 का बाब प्रसीदेंसी एन्तोमिपणन प० पूर्वोक्त स्थल राम पावर्टी प० 311 8 गोखले स्पीचज प० 1202
- 124 विशेषतया देखिए नोरोजी पावर्टी प० 149 150 और आगे उहृति एम तथ्य को प्रस्तुत किया कि व्यावहारिकतया इंग्लैंड और भारत के बीच वित्तीय संबंध इन प्रकार के प्रकार के मालिक और नौकर के बीच होते हैं (स्प्रीचेज प० 163 337 342 प० 78 93 सी० पी० ए० प० 168)
- 125 प्रस्ताव V अन्व जय भारतीय नेताओं ने दोना दंगों के बाब खर्चों के समुचित वि भाग का पूरा समायन किया उद्धरणों के लिए देखिए आय इन मांग के विस्तृत वि मवधित विवरण उगाहरण के रूप म देखिए आर० एम० सायानी मा० पी० ए० प० आई० एम० पी० ओ० आई० मई जून जुलाई म उल्लिखित पत्र-परिवारण गोखले नोरोजी एस० एन० बनर्जी और एम० अय्यर क विनवी कमीशन क समय मार फामिल इन इंडिया प० XX और ई० एच० II प० 213
- 126 गोखले स्पाचेज प० 120-107 वाचा, प० 394-5 नोरोजी स्पीचेज प० 343 पावर्टी एम० एन० बनर्जी सी० पी० ए० प० 253-4 268-9 पा० मेन्ना स्पीचेज प० 361 स्पीचेज II प० 46 ए० बी० पी०, 4 जून 1883
- 127 देखिए पीछे

- 130 ए० वा० पी० 24 जून 15 सित० 1895, आर० एन० पी० बब 22, 29 जून 1895 में, आर० एन० पी० बग० 29 जून 6 जुलाई 1895 में, आर० एन० पी० एन०, 4 जून 2 9 16, 23 30 जुलाई 1895 में आर० एन० पी० एम०, 30 जून 15, 31 जुलाई 1895 में उल्लिखित पत्र पत्रिकाएँ, ए० एन० बनर्जी सी० पी० ए० पृ० 256, नौरोजी स्पीचेज पृ० 351, रय पावर्टी पृ० 338
- 131 ए० बी० पा० 11 जुलाई 1902 हिंदू 18 जुलाई 1902 आर० एन० पी० बब 26 जुलाई 23 अगस्त 1902 आर० एन० पी० एम०, 19 26 जुलाई 1902 आर० एन० पी० पी० एन० 19 26 जुलाई 9 16 23 अगस्त 1902 आर० एन० पी० बग०, 19 26 जुलाई 1902 और आर० एन० पी० पी०, 2 अगस्त 1902 में उल्लिखित पत्र-पत्रिकाएँ
- 132 श्रुतवाणी 30 अक्टू० (आर० एन० पी० बग० 7 नव० 1903), इंडियन पीपुल 6 नव० (आर० एन० पी० यू० पी० 7 नव० 1903), एडवाकेट 13 दिस०, (वही, 19 दिस० 1903)
- 33 नौरोजी पावर्टी पृ० 142 मी० पी० ए० 167 8 171 स्पीचेज, पृ० 146 151 5 158 162 3, 299 330-6 380 परिशिष्ट पृ० 78 9, गोखले स्पीचेज पृ० 1208, पी० ए० चारलू, एल० सा० पी० 1897 खंड XXXVI पृ० 231, जी० एल० ज्यूर विलबी कमीशन खंड III प्रश्न 19800 दत्त ई० एच० पृ० 409 ई० एच० II पृ० XVI XVII 60 613 इस संवत्स में दत्त नेताओं ने अपने शासकों का स्मरण कराया कि भारतीय साम्राज्य को पान में इन्होंने अपना जार स ता एक पाई भी खर्च नहीं 1857 के विद्रोह को कुचलने के उर्षों को मिलाकर भारतीय साम्राज्य का विजित करने के सारे खर्चों का भार भारतीय जनता ने ही उठाया है नौरोजी पावर्टी, पृ० IX 210 मी० पी० ए० पृ० 170, स्पीचेज पृ० 222 351 परिशिष्ट पृ० 78 गायन स्पीचेज, पृ० 1207, दत्त ई० एच० पृ० 399 406 409 स्पीचेज II पृ० 46
- 134 नौरोजी पावर्टी पृ० 142 657 सा० पा० ए० पृ० 167 8 स्पीचेज पृ० 146 150 158 9 337-40 परिशिष्ट पृ० 5 23 43-4 75 79 89 90 बाबा, स्पीचेज पृ० 400 परिशिष्ट पृ० 33 सा० पी० ए० पृ० 618 ए० एन० बनर्जी विलबी कमीशन खंड III प्रश्न 19419 जा० एम० ज्यूर वहा, प्रश्न 19800
- 135 इंडियन स्पेक्टर 25 फरवरी (आर० एन० पी० बब, 3 मार्च 1883), ए० एन० बनर्जी सा० पा० ए० पृ० 254-5 नौरोजी स्पीचेज पृ० 340 परिशिष्ट पृ० 79, बाबा स्पीचेज परिशिष्ट पृ० 33 आई० एन० सा० 1898 का प्रस्ताव XIII (बी) दत्त ई० एच II पृ० XVI XVII 215 613
- 136 ए० एन० बनर्जी मी० पा० ए०, पृ० 256-7 एच० ए० बाइपा रि० आई० एन० सी० 1895 पृ० 91 मी० फ्रान्क नायर सी० पा० ए०, पृ० 386 दत्त स्पीचेज I पृ० 35 बाबा, मी० पी० ए०, पृ० 618 9 स्पीचेज पृ० 400
- 137 पादाल रिपोर्ट ऑफ रि० रायन कमीशन ऑन दि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रि० एक्वॉटांचर ऑफ इंडिया (खंड IV) (हाउस ऑफ कामन्स) 1900 खंड 29 पृ० संलग्न 131
- 138 1900 का प्रस्ताव XI
- 139 बाबा सा० पा० ए० पृ० 618 स्पीचेज पृ० 398 400-01 ए० एन० बनर्जी सी० पी० ए० पृ० 708 ई० एच० II पृ० 557 559 बगामा 24 अक्टूबर 1900 मराठा और कैंगरे दि० 6 मई (आर० एन० पी० बब 12 मई 1900) श्रुतवाणी 25 अक्टूबर (आर० एन० पी० ए०

1 मई 1900) स्वदशमिजन 16 अप्रैल (आर० एन० पी० एन० 30 अप्रैल 1900)

- 140 जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 1 2
- 141 वही, पृ० 154-5
- 142 पी० मेहता स्वीचेज पृ० 456-7
- 143 प्रोग्रेसिव्ग आफ् बौगिज आफ् दि गवर्नर आफ् बांब 1895 छट XXXIII प० 90-1
- 144 वही 1896 छट XXXIV पृ० 119 और दधिए इगी अध्याय क पृ० 2 और 3
- 145 बाबा स्पीचज परिशिष्ट, पृ० 31
- 146 प्रस्ताव III (ii) इगी प्रचार 1904 में बांधतान मागकी कि जवतक बजट का बचना म करदाताओ को राहत दवर मरवार क अपने छचों को बड़ा के प्रलोभन का आशवा को समाप्त किया जाए सरकार का धाहिए कि अपने बजट की बचना क एब भाग को जनता को लाभान्वित करा यासे नत वक्षानिक कृपि सभया तथा औद्योगिक शिक्षा डान्दरी राहत का सुविधाआ म बद्धि बायो में गच करे तथा अवशिष्ट राशि का स्थानीय तथा नगर प्रशासन मडना को अत्यावश्यक रूप से अर्पित सफाई गुणार तथा दूरस्थ प्रस्था म मचार साधना क विकास बायो को हाय म सने क लिए सहायता देवे म गच करे (प्रस्ताव VIII सी)
- 147 गागने स्पीचज पृ० 92 और दधिए पृ० 109 नाक कल्याण के छचों म बद्धि की वकालत करन बात कुछ और नेता पे नौरोजी स्पीचज परिशिष्ट पृ० 25 एस० एन० धनर्जी एम० ऐंड डब्ल्यू०, परिशिष्ट प० 22 5 जो० एन० डब्ल्यूर विलवी कमीशन छट III प्रचन 19002
- 148 कचीन पूर्वोद्धत पृ० 158-67 555 6 566
- 149 आई० एन० सी० 1891 1892 1893 और 1894 के प्रस्ताव सध्या VIII XII XV और XX क्रमक क० टी० तनग मिनिट टु दि रिपोट आफ् दि इंडिया एजुकेशन कमीशन 1883 पृ० 607 और रिप० आई० एन० सी 1888 पृ० 152 रानाड मेमोरेंडम आफ् सिंटेड रिपोट आफ् दि पाइनात कमिटी, 1886 छट पृ० 411 ए० बी० पी० 21 मई 1885 26 जुलाई 1888 सटवर 2 सित०, मुरभि 8 सितवर (आर० एन० पी० बग० 12 सित० 1885) धारु चार्ता 7 सित० पताका 11 सित० (वही 19 सित० 1885) सोमप्रकाश 28 सित० (वही 3 अक्टू० 1885) मुरभि औ पताका 10 जून (वही 19 जून 1886) 1888 के भारत सरकार के शिक्षा बिल पर बगाल और ब्रहई के समाचारपत्रो मे टिप्पणिया विभिन्न पत्रो और जुलाई अगस्त 1888 क नटिव प्रेसो मे क्रमक उद्धत एच० सी० मिला रिप० आई० एन० सी० 1891 पृ० 49 पी० महता, स्पीचेज पृ० 331 5 339 55 502-04 508 बी० एन० सोल रिप० आई० एन० सी 1892 पृ० 87 8 डब्ल्यू सी० बनर्जी, सी० पी० ए० प० 130 गोखले स्पीचज प० 56-7 1193
- 150 पी० मन्ता स्पीचज पृ० 334 एब अय अवसर पर उहाने कहा कि भारत म उच्च शिक्षा के अनेक विरोधी स कहा भारत मे प्रत्येक महाविद्यालय को विपले नाग सेन की जगह मानते हैं और इतीलिए चाहते हैं कि जितने कम विद्यालय हो उतना ही अच्छा है (वही प० 348)
- 151 आई एन सी० 1888 का प्रस्ताव सध्या IX और आग
- 152 प्रस्ताव सध्या XII और देखिए तैलग मिनिट टु दि रिपोट आफ् इन्डियन एजुकेशन कमीशन 1883 पृ० 614
- 153 प्रस्ताव सध्या XX 1903 के शिक्षा मुधारो पर आपत्ति करते हुए 1903 म काप्रस के अध्यक्ष लाल मोहन घोष ने घोषणा की हम अपने देश के अपेक्षाकृत निधन छात्रा के माग म कठिनाइया



उत्पन्न करना नहीं चाहते हम अपने दरिद्र देश में एटन और आक्सफोर्ड के स्तर की आभिजात्य (टाइट-वाटवाली) शिक्षापद्धति का प्रस्तावन और प्रचलन नहीं चाहते' (सी०पी०ए०, पृ० 777) और देखिए—तलय पूर्वोक्त स्थल प० 606 08

- 154 प्रस्ताव सं० 11 इसी के साथ अपने तृतीय प्रस्ताव में कांग्रेस ने देश की दरिद्रता के निवारण के उपाय के रूप में शिक्षा के प्रसार का समर्थन किया लाल मोहन घोष ने अपने अध्यक्ष भाषण में जनता की निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए जोरदार तर्क दिए (सी०पी०ए० प० 777 9) और देखिए जी० एस० अय्यर विलची कमीशन खंड III प्रश्न 19685
- 155 जोशी पूर्वोद्धत, प० 222 826 1076, 1086-7 1090 और आगे तलय रिप० आई० एन० सी० 1888 प० 152 जी० एस० अय्यर वही प० 153-4, एच० सी० मित्रा रिप० आई० एन० सी० 1891, प० 49-50 बी० एन० सील रिप० आई० एन० सी० 1892 पृ० 87 95 एच० सी० मित्रा वही, प० 95-6 एस० एन० बनर्जी, सी० पी० ए० प० 290-1, एस० एंड डब्ल्यू० परिशिष्ट प० 22-4 वाचा, स्पीचिंग पारशिष्ट, प० 28 9 सी० पी० ए० प० 584, 619 मालवीय स्पीचिंग, प० 295, 359-68, पी० मेहता स्पीचिंग प० 352 3 457 9 बी० जी० निलक प्रोमोडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बांब 1896 खंड XXXIV प० 115 9 एल० एम० घाय, सी० पी० ए०, प० 777 9 समाचारपत्रा के मत के लिए देखिए द्दु प्रकाश 26 मार्च (आर० एन० पी० बंब 31 मार्च 1883) नव विभावर 1 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 6 मार्च 1886) हितवादी 24 दिस० 1898 (आर० एन० पी० बंग० 1 जन० 1899) स्वदेशमित्र 15 सित० (आर० एन० पी० एम० 20 मित० 1902) केसरी 31 मार्च (आर० एन० पी० बंब 4 अप्रैल 1903) इस संबंध में एक विचित्र टिप्पणी 20 मितवर 1896 कसर हिंद की थी उसने यह निर्देश किया कि 1896-7 के लिए गिना पर 6 319 000 रुपये बजट के खर्च का तक्षमीना था तथा मन्त्रि से वसूल होने वाला उत्पन्न शुल्क 5 करोड़ रुपये था उसने टिप्पणी की कि वे भारत को पिचकड़ बनाने के लिए अत्यधिक उत्सुक हैं परंतु मान के प्रकाश के व्यापक प्रसार के प्रति सतथा उत्साह है उनके पास 'आवकारी शुल्क' के 1/11 भाग से अधिक खर्च करने के लिए हृदय ही नहीं है (हिंदूर 100 में 23 व्यक्तियों के खर्च तब सोचें मर्ने ब्रिटिश शासन के 150 वर्ष के बाद भी देश में गण्यता का यह बना गुनर प्रगार है आर० एन० पी० बंब 26 सित० 1896) तकनीकी गिना के लिए देखें अध्याय 2
- 156 रिप० आइ० एन० सी० 1891 पृ० 51
- 157 गोपने स्पीचिंग पृ० 192 3 1200 -
- 158 प्राथमिक गिना के लिए बजट के अंगेगाहन अधिका बड़े भाग की व्यवस्था तथा बर्बर सरकार से प्रांतीय राजस्व के एक निश्चित घन के गिना के लिए निर्धारण करने की बकायत करा हुआ गायन ने प्राथमिक गिना के सामा का विस्तार यत्न किया और कदा गिना का अर्थ है सामा की बन्गण्या का बुद्धिमत्ता का स्तर प्रगन करना गुनिगिन थम के प्रति अंगेगाहन अधिका दक्षि और उत्तम उलान करता उचित और अनुचित में विवेक का अंगेगाहन अधिका यान्या उलान करता (प्रोमोडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बांब 1901 पृ० \XXIX प० 250-1)
- 159 गोपने एनाबर पृ० 59-62 तथा देखिए, प० 25-6 43-4 95-6.
- 160 बंग पृ० 61

- 161 लनंग मिनिट दु दि रिपोर्ट ऑफ दि इन्डियन एन्ड्रवेमन कमिशन, 1883 पृ० 609 घणाली 17 अप्रैल 1896 मराठा 1 घणस्त 1886, भारतीय सामान्यता के विचारों का सम्पात्कीय गार-मशर, बी० ओ० आई० अगस्त 1886, इन्डिया नगन, 2 अगस्त इन्डियन मिस्टर 8 अगस्त ट्रिम्पून 14 घणस्त बिहार हेराल्ड 17 अगस्त (बी० आ० आई० अगस्त 1880) भारत मिहिर 8 अप्रैल नवविभाकर 12 अप्रैल (आर० ए० पी० बग० 17 अप्रैल 1886) भारत मिहिर 15 अप्रैल सट्टर 14 अप्रैल (वही 24 अप्रैल 1886) साधारणी और बाका प्रकाश, 25 अप्रैल (वही 1 मई 1896) गुरभि ओ पनाबा 12 मई (वही 22 मई 1886) भारतवासी 14 मिन० नवविभाकर साधारणी 6 मिन० (वही 11 मिन० 1886) डब्ल्यू० सी० बनर्जी गा० पी० ए०, पृ० 130 पी० मत्ता स्पीचेज पृ० 334 349-51 506-08 एच० सी० मित्रा रि० आई० एन० सी० 1891 पृ० 49-50 बी० एन० भील रि० आई० एन० सी० 1892 पृ० 87 90 एच० सी० मित्रा वही पृ० 96 एम० एन० बनर्जी सी० पी० ए० पृ० 291 2 बाबा गी० पी० ए० पृ० 628
- 162 देविण अध्याय III
- 163 देविण अध्याय V
- 164 देविण अध्याय X
- 165 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 64 नवविभाकर 1 मार्च (आर० एन० पी० बग० 6 मार्च 1886) पीछे पाण्डिणपो सख्या 143 और 145 मातमीय, स्पाचेज पृ० 368 76 आई० एन० सी० 1904 का प्रस्ताव VII (गा)
- 166 आई० एन० सी० 1886 1887 1888 1892 1894 1901 और 1904 के प्रस्ताव नमन XI III III XII IV और XIII, पा० मेहता स्पीचेज पृ० 457 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 154 222 ए० एम० बोग गी० पी० ए० पृ० 447 8 बाबा सी० पी० ए० पृ० 619 एम० एम० बनर्जी सी० पी० ए० पृ० 717 8
- 167 आशा पूर्वोद्धत पृ० 222 पी० महता स्पीचेज पृ० 457 ए० एम० बोग सी० पी० ए० पृ० 450-2 बाबा सी० पी० ए० पृ० 619 एम० एन० बनर्जी सी० पी० ए० पृ० 719-21 विश्वभरनाय एम० गी० पी० 1897 घड XXXVI पृ० 183 गोखले स्पीचेज पृ० 91 2 95 इमका निम्न पढ़ने ही पीछे किया जा चबा है कि भारतीय नेताओं ने पुनिस व्यवस्था में योग्यता और ईमानदारी बढ़ाने के लिए निम्न वेतनभोगी पुनिस कमचारियों के वेतन में बढि की बबालत की
- 168 एन० सी० पी० 1894 घड XXXIII पृ० 306 इसी प्रकार एक अन्य वित्त सदस्य ई० ला ने लिपिणी की आदरणीय श्री गोखले एक ऐसे वग से संबधित हैं जो खजाने के द्वार पर आकर दाँ दोँ की स्ट नगाता है परतु वह बड हुण धर्रें ही नहीं चाहता प्रत्युत वतमान चानू करा की भी समाप्त करवाना चाहता है (एल० सी० पी० 1904 घड XLIII पृ० 539 और देविण वजन स्पीचेज II पृ० 464
- 169 नौरोजी स्पीचेज पृ० 319-20 दत्त ई० एच० I पृ० 308 9 406-9 ई० एच० II पृ० XV XVI 215 20 373 5, 604 भारतीय नेताओं ने अन्य मन्त्रों में भी इस ओर सबेत् किया था कि भारतीय रक्त और रसे के मूल्य पर साम्राज्य हुयियाया गया था नौरोजी पावर्टी पृ० 567 640 स्पीचेज पृ० 221 2 गोखले स्पीचेज पृ० 120 दत्त ई० एच० I पृ० 399
- 170 ए० एम० बोस सी० पी० ए० पृ० 427 448

- 171 गोखले स्पीचेज, पृ० 26 8 तथा 109 प्रमश, और देखिए डी० ई० वाचा, रिप० आई० एन० सी० 1891 प० 25, इंडियन एडवोकेट 18 अगस्त (आर० एन० पी० यू० पी० 27 अगस्त 1904)
- 172 वी० जी० तिलक प्रासाडिम्स आफ दि वी० सिल आफ दि गवर्नर आफ बाव 1895 छद्म XXIII, प० 91 गोखले स्पीचेज प० 61, आइ० एन० सी० 1904 का प्रस्ताव VIII गोखले रिप० आई० एन० सी० 1904 प० 169 मराठा न अपन 29 मई 1904 क अक्ष मे आय कर समाप्त करन का विरोध किया उसन इसक बदले यह प्रस्ताव किया कि इसकी आय के लिए एक यास बना दिया जाए जो इस रकम को शिक्षा पर खर्च करे इससे पूर्व अपन बाजार पत्रिका ने अपने 3 अगस्त 1900 क अक्ष म लिखा कि धरती पर लगे ऊंचे लगाना को भी यदि इपि सुधारो सफाई और ग्रामीण शिक्षा आदि पर खर्च किया जाता, तो हम इन लगानो को उपयोमी मान लेते
- 173 जागी पूर्वोद्धत प० 751
- 174 वही प० 1038
- 175 गोखले स्पीचेज प० 1200
- 176 विलवो कमीशन खड III प्रश्न 19686
- 177 सी० एन० वकील पूर्वोद्धत अध्याय 1
- 178 गोखले स्पाचज पृ० 1156-7 और देखिए वही प० 21 1159 60, नीराजी सी० पी० ए० प० 155 6 स्पीचेज पृ० 300, जागी पूर्वोद्धत प० 203 207, 220-1 229-30 एम० एन० वनर्जी एम० एंड डब्ल्यू० परिशिष्ट प० 2 3 वाचा स्पीचेज परिशिष्ट प० 3-4 सा० पी० ए० प० 620 जी० एम० अम्बर विनवी कमीशन, खड III प्रश्न 18559 मालवाय स्पाचज प० 287 90 सी० चकरन नायर सा० पी० ए० पृ० 385 एत ई० एच० प० \V और ई० एम० II प० 386-7
- 179 आई० एन० सी० 1889 और 1890 क प्रस्ताव प्रमश IX और III पी० महुता सी० पी० ए० प० 90 नीराजी स्पीचेज प० 107 8 सी० पी० ए० प० 156 मालवाय स्पीचेज प० 17 20 46 216-7 गोखले स्पीचेज प० 1158 1160-1 एम० एन० वनर्जी एम० एंड डब्ल्यू० परिशिष्ट प० 3 जी० एम० अम्बर रिप० आई० एन० सी० 1894 प० 77 विनवी कमीशन पृ० III प्रश्न 18559 18765 18769 एच० एन० एत, रिप० आई० एन० सी० 1897 प० 44
- 180 गोखले स्पीचेज प० 1161 मालवाय स्पाचज प० 287, एत ई० एच० I पृ० \V ई० एच० II प० XVIII 360
- 181 उपनिर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क 20वें अधिवेशन म सी० व० अम्बर न दावा किया कि 1892 म कौमिन म बजट पर विचार विमर्श करन का सर्व शक्ति वास्तव म जारी बचवास और निरी घाटा या क्याकि हम कौमिन म किए गए भाषणा का सरकार का नाति और प्रशासन पर बाई भी प्रभाव नही पड़ना या उच्छान आय शिपणा करत हुए बना बजट पट्टन स हा तमार पड़ना है उक्त मभा पत्र पुनर्निर्धारित रट्टा है और कौमिन के अनिश्चित मन्मथा को बचन अपना मत प्रकट करना जाना है और हमक लिए पत्रम स हा विषय गए निश्चया का पड़ना सर होना है (रिप० आई० एन० सी० 1904 प० 181) और देखिए नीराजी सी० पी० ए० प० 154 5 स्पाचज पृ० 245 पावर्टी प० 637 8 एम० एन० वनर्जी सा० पी० ए० पृ० 231 एम० एंड डब्ल्यू० परिशिष्ट प० 3 आर० एम० मयाता सी० पी० ए० प० 367

गोष्वने, स्पीचेज, प० 1158, 1161 वाचा स्पीचेज, परिशिष्ट, प० 3 मालवीय स्पीचज प० 50

182 प्रस्ताव III

183 सी० पी० ए०, पृ० 620

184 प० 601 उहनि यह भी सिवायत की कि ब्रिटन का प्रत्येक हित और ब्रिटिश जनता का प्रत्येक बग भारत सरकार पर दबाव डाल सकता है परंतु भारत की जनता अपनी ही सरकार पर कोई दबाव नहा डाल सकती है (प० 598) तथा देखिए उनकी ई०एच० I प० XV ई० एच० 2 प० 387 स्पीचज I पृ० 41, नोरोजी स्पीचज पृ० 108 131 222 245 300 356 पावर्डी प० 638 9 सी० पी० ए० प० 172 3 जोशी पूर्वोद्धत प० 220 गोखल स्पीचज पृ० 8 1156 1158 9 1161 1169, मालवीय स्पीचज प० 287 आर० एम० सयानी सी० पी० ए० पृ० 357

185 नोरोजी स्पीचज प० 108 आई० एन० सी० 1885 1886 और 1897 के प्रस्ताव क्रमशः III IV और III (1) गोखले स्पीचज प० 1162 वाचा स्पीचज परिशिष्ट प० 5 एम० एन० बनर्जी एस० ऐंड डर्यूं परिशिष्ट प० 3 6 जी० एस० अय्यर विनवी कमीशन खंड III प्रश्न 18767 18834 18847

186 एस० एन० बनर्जी एस० ऐंड डर्यूं परिशिष्ट प० 5 6

187 गोखले स्पीचेज पृ० 1164 1904 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस माग को 'वापक सदम मे रोहराया प्रस्ताव IX (ए) तथा देखिए इंदु प्रकाश 4 जून (आर० एन० पी० बज० 9 जून 1883)

188 वाचा स्पीचेज परिशिष्ट प० 34 एस० एन० बनर्जी एम० एंड डर्यूं परिशिष्ट प० 5 6 जा० एस० अय्यर बिलवी कमीशन खंड III प्रश्न 18767 आई० एन० सी० 1897 का प्रस्ताव सख्या III (1) आर० सी० दत्त ने 1903 में विना किसी निर्धारित सिद्धांत के इस माग को उठाया (ई० एच० II प० 600) तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 'वापक प्रशासनिक मुधारों के सदम में इस माग को उठाया (प्रस्ताव स० IX) और देखिए दत्त स्पीचेज 1 प० 98

189 नोरोजी स्पीचेज प० 105 भारतीय नेताओं की उदीयमान पीढ़ी के प्रथम वास्तविक अखिल भारतीय सम्मेलन के महान ऐतिहासिक महत्व के प्रति सम्यक रूपेण जागरूक दालभाई नोरोजी ने भावी राष्ट्रवादी प्रयास के लिए एक नक्ष्य निश्चित किया मैं यहाँ यह कह सकता हूँ कि भारत की इस प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रधान कार्य जनता की उच्चतम और प्रतिम आवाजाओं को स्पष्ट रूप से और साहसपूर्वक प्रकाशित करना है हमें तत्काल अपनी आवाजाओं की प्राप्ति में सफलता मिलती है अथवा नहीं यह एक दूसरी बात है परंतु हमारे शानका को यह ज्ञात होना चाहिए कि हमारी उच्चतम आवाजाएँ कौन सी हैं यदि हम स्पष्ट शब्दों में यह कहते हैं कि हम स्वाई समिति को सामान्य नियंत्रण क्षमता प्राप्त हान के भ्रतगत इच्छा से भारत को हस्तांतरित वास्तविक सरकार लेना चाहते हैं और इसके साथ साथ हम यह चाहते हैं कि हम पर बराधान का अधिकार हमारी प्रतिनिधि परिषदों को हाना चाहिए हम चला दना चाहिए कि हमारा भ्रत लक्ष्य क्या है? (इस पर बत दिया गया) (वही प० 109) और देखिए वही प० 222 300 परिशिष्ट प० 10 108 और आगे बाद में 1897 में डॉ० ई० वाचा की लिखित पत्र मसानी पूर्वोद्धत प 379 पर

190 आर० एन० पी० डू० पी० 23 अगस्त 1902 हलड में राजपौशी के अवसर पर उपस्थित

अतिथिया पर हुए खर्च की दनपारी भारत पर डालने की तीव्र निंदा करते हुए और इस तथ्य पर शोक प्रकट करते हुए बड़ा ही खोरता तथा साहस के साथ उन्होंने घोषित किया 'निधन भारत देश एक बहुत कठिन समय से गुजर रहा है भारतीयों की दशा तब तक ऐसी बनी रहेगी जब तक इस देश के संपूत अपने अधिकारों के लिए डट नहीं जाते तथा उन अधिकारों की प्राप्ति के लिए उपनिवेशियों की तरह धीरता तथा साहस का परिचय न दें अन्यथा ब्रिटिश सरकार के हाथों वित्तीय मामलों में उदारता की कौन कहे 'याय तथा औचित्य की भी आशा नष्ट की जा सकती

- 191 उदाहरणार्थ दक्षिण सहचर 26 जनवरी (आर० एन० पी० बग० 7 फरवरी 1880) सर्जीवनी, 9 जून (वही 16 जून 1883) नवविभाकर 29 मार्च (वही 3 अप्रैल 1886), मद्रास मद्राज सभा का ज्ञापन रिपोर्ट आफ दि फाइनाल कमेटी 1886 खंड II पृ० 453 मालवीय स्पीचेज पृ० 7 एमिनेंट इंडियन, पृ० 29 पर डब्ल्यू० सी० बनर्जी, मराठा 1 अप्रैल 1894 गुजराती 24 मार्च (आर० एन० पी० बग 30 मार्च 1895) जनोपकारी 16 जून (आर० एन० पी० एम० 30 जून 1896) हिंदुस्तान, 28 दिस० (आर० एन० पी० एन० 29 दिस० 1897) दत्त इंडियन पालिटिकल पृ० 51 फिनिस इन इंडिया पृ० XX ई० एच० I पृ० 408 और ई० एच० II पृ० XVII XVIII 380-1 387 599 601 एन० एन० बनर्जी स्पीचेज III पृ० 136 145 159 सी० पी० ए० पृ० 710-1, बंगाली, 22 जुलाई 1903
- 192 उदाहरणार्थ मुर्रेनाथ बनर्जी न 1895 के कांग्रेस के अपने अध्यक्षीय भाषण में बड़े निरुत्थन शर्तों में कहा कि बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं यह आधुनिक सभ्य सरकार का तात्विक सिद्धांत है कांग्रेस ने सरकार से प्रशासन में इस सिद्धांत को अपनाया की बात नहीं बही है उन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधियों को यह निर्देश किया कि राजनीति एक व्यावहारिक बात है हमें बड़े सिद्धांतों की बातें करने से काम नहीं चल सकता (सी० पी० ए० पृ० 236-7)
- 193 प्रस्ताव सं० III
- 194 प्रस्ताव सं० IV
- 195 प्रस्ताव सं० II I और II और III प्रथम
- 196 उदाहरणार्थ 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संबोधित करते हुए मदनमोहन मालवीय ने तब किया हम आपसे 'याय और औचित्य' के नाम पर अपने बजट पर धाड़ बढ़ाने नियंत्रण का अनमति की प्रायना करते हैं 'कौमिल में लाए जाने पर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से हम पर कुछ करने की स्थिति में रहने के लिए हम आपसे अनुमति विनय करते हैं (स्पाचर, पृ० 20) और दक्षिण, इंडियन स्पेक्टर 6 मार्च इंदु प्रकाश 7 मार्च (आर० एन० पी० बग 12 मार्च 1881) नटिव आगानियन 13 मार्च (वही 19 मार्च 1881), एम० एन० बनर्जी स्पाचर III पृ० 9 26 34 38 मोराजा स्पाचर पृ० 109-10 साम प्रकाश 24 जन० (आर० एन० पी० बग० 29 जन० 1887)
- 197 एम० एन० बनर्जी सी० पी० ए० पृ० 236 और एम० ई० डब्ल्यू० परिशिष्ट 4-6 आर० एम० सपानी सी० पी० ए० पृ० 369 बाधा स्पीचर परिशिष्ट पृ० 3-5 जा० एम० ब्रह्म विन्दा कमीशन रट III प्रश्न 18765 18767 18873 4 आई० एन० गा० 1877 का प्रस्ताव III (1) सा० ब्रह्म नारायण सी० पी० ए० पृ० 386 मानवाय स्पाचर पृ० 222 3 आई० एन० गा० 1904 का प्रस्ताव I \
- 198 एम० एन० बनर्जी सी० पी० ए० पृ० 236-7 एम० ई० डब्ल्यू० परिशिष्ट पृ० 4-5 आर०

- एम० सयानी सी० पी० ए०, प० 369 गोखले स्पीचेज प० 1161 वाचा स्पीचेज परिशिष्ट, प० 4, सी० शंकरल नायर सी० पी० ए० प० 386 एच० एन० दत्त रिप० आई० एन० सी०, 1897 प० 44 मालवीय, स्पीचज प० 293
- 199 एस० एन० बेनर्जी सी० पी० ए० प० 237 एस० ऐं डब्ल्यू० परिशिष्ट पृष्ठ 5 जी० एस० ज्ययर विलबी बमोशन खड III प्रश्न 18767 18875 आई० एन० सा० 1904 वा प्रस्ताव स० JX तथा देखिए, नीरोजी स्पीचेज प० 106
- 200 गोखले स्पीचज प० 1161
- 201 वही एस० एन० बेनर्जी, एस० ऐं डब्ल्यू० परिशिष्ट प० 5 मालवीय स्पीचज प० 293-4 एच० एन० दत्त, रिप० आई० एन० सी० 1897 प० 44

## निकासी

ब्रिटिश शासन की लाकोपकारी प्रवृत्ति की चर्चा तो केवल कल्पित कहानी के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इस शासन की सही प्रवृत्ति तो देशवासियों का स्वतंत्र चूसना है।

अपनी सरकार के बिना भारतीय वर्तमान आर्थिक निकासी से मुक्ति नहीं पा सकते। किसी भी प्रकार के कोई भी सामक उपाय उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकते। प्रशासनिक तंत्र में किसी प्रकार के यांत्रिक हर फेर अथवा सुधार से न तो भारतीयों को कोई लाभ ही सकता है और न ही होगा।

दादाभाई नौरोजी

भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के मत में भारत की दरिद्रता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारणों में एक था—भारत में इंग्लैंड को संपत्ति देने वाला निवासी। नेताओं के एक वर्ग के अनुसार तो यह निवासी भारत के सभी आर्थिक दोषों का प्रधान आधारभूत कारण है। वस्तुतः हमारे अध्ययन काल की अवधि में राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रमुख आधार 'निकासी सिद्धांत' अथवा यह विश्वास था कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति अथवा कुल वार्षिक उत्पादन का एक भाग इंग्लैंड का निर्यातित किया जा रहा है जिसके बदले में भारत को कोई समुचित आर्थिक अथवा भौतिक लाभ नहीं मिलता। अथवा दूसरे शब्दों में भारत का पराजय रूप में ब्रिटिश राष्ट्र का विराज दान के लिए बाध्य किया जा रहा है। धीरे-धीरे कुछ वर्षों के उपरान्त देश में जनता के खिलाफ निर्याती सिद्धांत न इतनी अधिक व्यापक प्रशिक्षण और प्रभाव जमा लिया कि विना ही ब्रिटिश प्रवृत्तियों और नीतियों का यह सिद्ध करना के लिए प्रयत्न प्रयास करने का बाध्य होना पड़ा कि यह नारी की सारी कल्पना आर्थिकता की दृष्टि से निराधार तथा भ्रान्तिमूलक है।

निर्याती सिद्धांत के समुदाय प्रमुख आचार्य दादाभाई नौरोजी थे। उन्होंने अपना सर्वोच्च जीवन-काल की सारी ही अवधि में विरत सर्वज्ञ के साथ सार्वभौमिक प्रयत्न किए गए थे। इस सिद्धांत की उत्पत्ति का मुख्य कारण की चेष्टा का यह है कि निकासी न ही परंतु इसमें विश्वास रखा और इसका प्रसार करता जाना की संस्था समर्थनी थी। दादा

भाई नौरोजी ने 1867 में अपनी मायता की वाणी दी और उसके उपरांत यह धीरे धीरे व्यापकता और समयान प्राप्त करती गई। उनके ग्रंथो—‘पावर्टी ऐंड आनज़िटिश क्ल इन् इंडिया’ डिग्वी के ग्रंथ—‘प्राम्परस ब्रिटिश इंडिया’ और दत्त के ग्रंथ—‘इकोनामिक हिस्टरी आफ इंडिया’ के दो खंडों के प्रकाशित होने पर तो यह मायता प्रचारक अपने चरम शिखर पर पहुँच गई तथा उसे राष्ट्रवादियों और लोम्नेताओं में व्यापक मान्यता ही मिल गई। इस ग्रंथ में हम अपने अध्ययन के अंतगत अवधि में राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा प्रचारित तथा माय ‘निवासी सिद्धांत’ के विस्तृत विश्लेषण को प्रस्तुत करने के लिए प्रमुख रूप से दादा भाई नौरोजी के भाषणों और लेखों को ही विश्वस्त आधार बनाने चनेगे।

मवप्रथम, 2 मई 1867 को लंदन में हुई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक बैठक के समक्ष पढ़े गए अपने एक लेख— इंग्लंडस डेट टु इंडिया<sup>1</sup>—में इस धारणा को प्रस्तुत किया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में उस देश की संपदा को उस देश से छीन रहा है। भारत में वसूल किए गए कुल राजस्व का लगभग चौथाई भाग देश से बाहर चला जाता है, तथा इंग्लंड के ससाधनों से जुड़ जाता है। इसके फलस्वरूप भारत का रक्त निरंतर निचोड़ा जा रहा है। बर्बई के दो प्रमुख समाचारपत्रों—‘नेटिव ओपी नियन’ और ‘रास्त गोफतार—को उन्होंने यह दिखाने के लिए उद्धृत किया कि शिक्षित भारतीयों की उदीयमान पीढ़ी उनके विचारों की समर्थक है।<sup>2</sup> इसके साथ ही देश में व्याप्त आर्थिक दुर्दशाओं के उपचार के रूप में उन्होंने सुझाव दिया कि कम में कम इंग्लंड की जनता के लिए जो करना उचित है, वह यह है कि वह भारत से छीनी गई संपत्ति भारत का वापस लौटा दें ताकि भारत अपने ससाधनों का विकास कर सके।<sup>3</sup> दादा भाई नौरोजी ने 1870 और 1872 में लंदन की कलासमिति के समक्ष तमश पढ़े गए दो लेखों—‘दि वाटस ऐं मीस आफ इंडिया’<sup>4</sup> तथा ‘आन दि कामम जाफ इंडिया’<sup>5</sup>—में भारत से भौतिक और नैतिक धन की निकासी सत्रधी अपने दृष्टिकोण को फिर से लोहा राया। हा, इस सिद्धांत के साथ कालांतर में जुड़े क्रांतिकारी आशय तथा मौलिक चिंतन का इन लेखों में अभाव ही था, इस समय धन निकासी के आर्थिक परिणामों की निष्ठा करत समय दादा भाई नौरोजी निकासी के लिए भारत और इंग्लंड के बीच राजनतिक सबंध के महत्व के उत्तरदायी हान में विश्वास रखते थे। उन्होंने अभिस्वीकार किया कि यदि इंग्लंड ने भारत को अपने अधीन नया रूप ही देना है तो भारत को उसका मूल्य चुकाने के लिए प्रस्तुत हो ही जाना चाहिए।<sup>6</sup> उन्होंने इंग्लंड को अवश्य यह परामश दिया कि वह भारत के साथ ‘यायोचित ढंग से आर्थिक सबंधों को स्थापित करने की चेष्टा करे’<sup>7</sup> तथा देश के उत्पादन को बढ़ाने की चेष्टा करे ताकि देश दरिद्रता के अभिशाप का भागे बिना ही ब्रिटिश शासन के मूल्य का भुगतान कर सके तथा देश से धन की निवासी का भार उठा सके।<sup>8</sup>

1871 में अपने द्वारा सगणित लगभग 120 करोड़ पाँड प्रतिवष की देण में निकासी के प्रति अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा—‘मैं इसे एक निवारण के रूप में नहीं कह रहा हूँ। आपको भारत में की गई निवासी का प्रतिदान तो मिलना ही चाहिए परंतु प्रश्न तो यह है कि हमारे पास भुगतान के साधन तो होने चाहिए।’<sup>9</sup> उन्होंने धारणा



## निकासी

ब्रिटिश शासन की लाकापकारी प्रवृत्ति की चर्चा ता केवण कल्पित कहानी के अति-रिक्त और कुछ नहीं। इस शासन की सही प्रवृत्ति तो देशवासियों का रक्त चूसना है।

अपनी सरकार के बिना भारतीय वर्तमान आर्थिक निकासी से मुक्ति नहीं पा सकत किसी भी प्रकार के कोई भी सामक उपाय उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकते। प्रशासनिक तंत्र में किसी प्रकार के यांत्रिक हल फेर अथवा सुधार से न तो भारतीयों को कोई लाभ हा सकता है और न ही होगा। दादाभाई नौरोजी

भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के मत में भारत की दरिद्रता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारणों में एक था—भारत में इंग्लैंड का संपत्ति की निकासी। नेताओं के एक वर्ग के अनुसार तो यह निकासी भारत के सभी आर्थिक दोषों का प्रधान आधारभूत कारण है। वस्तुतः हमारे अध्ययन काल की अवधि में राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रमुख आधार 'निकासी मित्रता' अथवा यह विश्वास था कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति अथवा कुल वार्षिक उत्पादन का एक भाग इंग्लैंड का निर्यातित किया जा रहा है जिसके बन्ने में भारत का बाह्य समुचित आर्थिक अथवा भौतिक लाभ नहीं मिलता। अथवा दूसरे शब्दों में भारत का पराग रूप से ब्रिटिश राष्ट्र का गिरावट देने के लिए वाध्य किया जा रहा है। धीरे धीरे कुछ वर्षों के उपरान्त देश में जनता के हितों में निकासी मित्रता न इतनी अधिक व्यापक प्रासंगिकता और प्रभाव जमा किया कि कितने ही ब्रिटिश प्रवक्ताओं और नेतृत्वों को यह मित्रता करने के लिए प्रयत्न प्रयास करना बाध्य होना पड़ा कि यह मारी की सारी कल्पना आर्थिकता की दृष्टि में निराधार तथा भातिमूलक है।

निकासी मित्रता के समकालीन प्रमुख आचार्य दादाभाई नौरोजी थे। उन्होंने अपने नब्बे सायजनिज जीवन-काल की मारी ही अवधि में विरल संकल्प के साथ रात दिन इंग्लैंड निर्यात करवा किया। देश मित्रता की उत्तमना का मुस्पष्ट करने की चष्टता धारण करने की नाओं में भी परंतु इंग्लैंड विचारण रखत और इंग्लैंड प्रसार करने वालों की मध्यमम तक थी। दादा



को कि वस्तुतः यह तो इंग्लैंड का ही कर्तव्य है कि वह हमें एक ऐसी सरकार दे, अपनी शक्ति और साख के सभी लाभ हमें दे ताकि हम बिना भूखे मरे अथवा अकाल का शिकार बने ब्रिटिश शासन का मूल्य चुका सकें।<sup>12</sup> उन्होंने एक बार फिर देश के उत्पादन में वृद्धि के लिए बड़े परिमाण में विदेशी पूँजी के विनियोग की सिफारिश की। इस प्रकार उन्होंने 1870 में ब्रिटेन से अनुरोध किया कि वह विदेशी शासन के दरिद्रता वधक प्रभावा को दूर करने के लिए बड़े परिमाण में विदेशी पूँजी का आयात करे।<sup>13</sup> उन्होंने आशा की कि यदि समुचित परिमाण में विदेशी पूँजी का भारत देश में आयात किया गया और उसका यथोचित रूप से विनियोग भी किया गया तो शीघ्र ही वर्तमान विनीय कठिनाइयाँ और असंतोष दूर हो जाएंगे।<sup>13</sup>

1871 में 'सिलैक्ट कमेटी ऑन ईस्ट इंडिया फाइनांस' को दिए अपने प्रतिवेदन में दादा भाई नौरोजी ने एक बार फिर स्वीकार किया कि धन की निकासी विदेशी शासन का ही एक प्राकृतिक आर्थिक परिणाम था।<sup>14</sup> उन्होंने ब्रिटिश राजनेताओं से वष प्रतिवष करोड़ों पाउंड के भारत से इंग्लैंड को निकासी के भार को समुचित रूप से हल्का करने के तथा भारतीय लोगों की धन की निकासी के न्यायोचित भाग के भुगतान की समुचित और आवश्यक परिमाण तक, क्षमता बढ़ाने के उपायों को दृढ़ करने का अनुरोध किया।<sup>15</sup>

1873 तक जब दादा भाई नौरोजी ने 'भारत की दरिद्रता' पर अपने प्रसिद्ध लेख का प्रथम प्रारूप तैयार किया, तो उस समय तक धन की निकासी पर उनके विचार अपेक्षाकृत अधिक सुप्रसिद्ध रूप से ज्ञात सघनशीलता का रूप ग्रहण करने लगे थे। 1876 तक निवामी-सिद्धांत में उनके मन में सुस्पष्ट रूप ग्रहण कर लिया और उसे उन्होंने उसकी समग्रता में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बर्बई शाखा के समक्ष पढ़े अपने लेख—'पावर्टी आफ इन्डिया' के सशाधित प्रारूप में अभिव्यक्त किया। इस सिद्धांत के दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत आर्थिक और राजनतिक पक्षों के विस्तृत विस्तरेषण को तो हम अगले पन्ना में पेश करेंगे। यहाँ केवल इतना ही निर्देश करना चाहते हैं कि उन्होंने अपने लेख का निष्कर्ष इन जोरदार शब्दों में निकाला

ब्रिटिश शासन की भारत के हितों की उपेक्षा करने की और भारतीयों को इंग्लैंड के हित में दास वर्तित्त से परिश्रम करने बाते बनाए रखने की अस्वाभाविक नीति के फलस्वरूप सारा शासन गलत, अस्वाभाविक आत्महत्या के गढ़ में धसता हुआ चला जा रहा है। उन्होंने इस कथन के साथ ही चेतावनी दी कि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जब तक प्रकृति के ये नियम अचल हैं, तब तक प्रत्येक उल्लंघन के लिए दण्ड का याय उगी प्रकार निश्चित रूप से जुड़ा हुआ है जिस प्रकार दिन के पश्चात् रात के आने का हम निश्चित रूप से जुड़ा हुआ है।<sup>16</sup>

इस समय से दादा भाई नौरोजी ने अपने निकासी सिद्धांत के प्रचार के लिए तथा निकासी के विरुद्ध प्रचंड और प्रबल सघन चलाने के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। उनके विचार में निकासी भारत में ब्रिटिश शासन का प्रधान आधारभूत दोष था। अपने

१२ ॥ मे ब्रिटिश समाचार पत्रों को लिखे पत्रों में, पत्र पत्रिकाओं में लिखे लेखों में, १३ ॥ के साथ किए गए पत्र-व्यवहार में, सरकारी आयोगों, समितियों और निजी



भाषण में उन्होंने घोषणा की कि भारत से हो रही निकामी का उदाहरण आज तक विश्व के किसी भी अन्य देश में दूढ़ने से भी नहीं मिलता। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि यदि इंग्लैंड को प्रतिव्यय स्वयं अपने राजस्व का आधा भाग खर्च करने के लिए जमनी, फ्रांस अथवा रूस को भेजना पड़ना तो इंग्लैंड में वर्षों पूर्व अकाल पड़ गया होता।<sup>3</sup>

अपने ग्रन्थ—'इकोनामिक हिस्ट्री आफ इंडिया' के प्रथम खंड की भूमिका में उन्होंने निष्पातमरु स्वर में लिखा—शुद्ध राजस्व का आधा भाग प्रतिव्यय भारत में बाहर निष्कामित कर दिया जाता है। उन्होंने शोक विह्वल होकर कहा—सचमुच ही भारत का उपजाऊपन, हमारे देश का ही संपन्न और भाग्यशाली बना रहा है। 'पुस्तक के परबर्ती भाग में उन्होंने निकासी के माधे निम्नलिखित पाप का भङ्गते हुए लिखा—'देश के साधनों की सीमा से उड़कर इतनी उड़ी आर्थिक निकामी विश्व के किसी समद्वतम देश को दरिद्र बना सकती है। इसमें भारत को विश्व के इतिहास में अभूतपूर्व और अश्रुतपूर्व रूप से निरंतर और व्यापक रूप से पड़ने वाले घातक अकालों का देश बना दिया है।<sup>4</sup> इसी प्रकार ग्रन्थ के दूसरे खंड की भूमिका में उन्होंने इंग्लैंड की आलोचना करते हुए लिखा कि इंग्लैंड जसा विश्व का समद्वतम देश विश्व के दरिद्रतम देश भारत से व्यापक योगदान को वसूलत की नीचता पर उतर आया है। उन्होंने जोर देकर दृढ़ स्वर में कहा कि इस योगदान के लिए भारतीयों को निरंतर अज्ञान रूप से अपने जीवन रक्त को निर्यात करना पड़ता है।<sup>5</sup>

जी० वी० नाशी, पी० सी० राय, मदन माहन मालवीय, डी० ई० वाचा, जी० के० गोखल, सी० सुब्रह्मण्य ऐयर और और सुरेंद्रनाथ बनर्जी सहित अन्य बहुत सारे भारतीय नेता भी निकासी के प्रश्न में संबंधित आंदोलन में सम्मिलित हो गए।

राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में अमृत बाजार पत्रिका निकासी सिद्धांत का प्रबलतम समर्थक था। 28 जुलाई 1870 में ही इस पत्रिका ने निकासी का भारत की दरिद्रता का कारण घोषित किया और कालांतर में वर्षों तक अपने इस सुदृढ़ मत का दोहराया। उदाहरणार्थ 14 अगस्त 1881 के अंक में इस पत्रिका ने शिवायत की कि भारत अनेक विभिन्न ढंगों से तथा अनेक दशा द्वारा इस प्रकार चूसा जा रहा है कि वे स्वयं अपने आप भी एक दूसरे की गतिविधियाँ और कायवाहियाँ से परिचित नहीं। वे यह भी नहीं जानते कि इस शून्य क्रिया के परिणामस्वरूप उनका योगी किस अत्यंत विषम तथा शाचनीय दशा में पड़ चुका है। 2 मार्च 1896 के अंक में इस पत्रिका ने अपने कथन का इस प्रकार दोहराया—इस लगातार निकासी के फलस्वरूप भारत दरिद्रता का शिकार हो गया है और इंग्लैंड संपन्न देश बन गया है। यह व्यवस्था भारत को संपत्ति की स्थिति में और भारतीयों को पशुओं की स्थिति में लाकर उनका अवमूल्यन करती है।<sup>6</sup> अधिकांश अन्य प्रमुख भारतीय पत्रों ने भी निर्धारित रूप से इस सन्ध में अपने विचार प्रकट किए तथा भारत से संपत्ति की निकासी की निंदा की।<sup>7</sup>

कितने ही वर्षों तक मोच विचार करने के उपरांत अथवा कल्पित सन्ध के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 में कलकत्ता में हुए अपने अधिवेशन में औपचारिक रूप से निकासी सिद्धांत को स्वीकार करते हुए यह मत व्यक्त किया कि वर्षों से निरंतर



के रूप में भारत को दी जाने वाली परतु न दी गई एक अर्थ विपुल राशि को लिया और इसमें निकासी का अपक्षावृत्त अधिक सही अनुमान लगाया।<sup>37</sup> उनके इस दृष्टिकोण के दा आधार थे। प्रथम, उनका अनुमान था कि ब्रिटेन और कई दूसरे देशों में निर्यात पर आयात की अधिकता इस तथ्य का मिद्ध करती है कि पूजा के सौदा तथा भारत में धन की निकासी पर होने वाले व्ययों को पथक कर देने पर भी निर्यातों से लाभ होता था।<sup>38</sup> यह तक वस्तुतः सवथा कोरी कल्पना ही था। इसका अर्थ यह हुआ कि आयातों और निर्यातों के मूल्यों के अंतर द्वारा निर्दिष्ट राशि की अपेक्षा वास्तव में ही निकासी की राशि अपने परिमाण में बहुत अधिक है। इस तक की प्रामाणिकता स्पष्ट रूप से दादा भाई की इस धारणा पर आधत है कि भारतीय निर्यातों का निर्यात पत्तन पर धापित मूल्य लागत मूल्य रहता था न कि बिक्रेता के लाभ के साथ बिक्री का मूल्य रहता था तथा भारतीय आयातों में ब्रिटिश निर्यातकार के लाभ पहले ही सम्मिलित रहते थे।<sup>39</sup> अस्तु निकासी की राशि के इस विकृत अनुमान का किसी भी मामले में बहुत सारे अर्थ नेताओं ने कोई उल्लेख नहीं किया। निकासी के विषय से सबधित बहत्तों ने तो व्यापार के निर्यात—सतुलन की सीधी सादी सगणनाओं तक ही अपने को सीमित रखा। यहा तक कि स्वयं दादा भाई नौरोजी भी भारत के वित्तीय ाय के मामले को पेश करते हुए कभी कभी निर्यातों पर होने वाले लाभों की गणना को छोड़ने के लिए सहमत हो जाते थे।<sup>40</sup>

बहुत सारे भारतीय नेताओं ने निकासी की सही राशि की सगणना की चेष्टा की। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा सगणना की विभिन्न विधियाँ अपनाए जाने के कारण प्रति व्यक्ति तथा प्रतिव्यय आयातों और निर्यातों की खाई निरन्तर चौड़ी होती जाने में प्रतिव्यय निकासी सबधी आकड़े भिन्न भिन्न रूप में ही सामने आने लगे। उदीयमान राष्ट्रीय नता बग ने इन आकड़ों को अपने हाथ में लिया तथा जन सपक के प्रत्येक उपलब्ध माध्यम के द्वारा देश के कोने कोने में इनका प्रचार प्रसार करते हुए इन्हें लोकप्रिय बनाया। जब जनता के सामने देश की संपत्ति की निकासी के सुस्पष्ट आकड़े आए तो स्पष्टतः जनता के मन में इस प्रश्न पर राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता न प्रबलता तथा विश्वसनीयता का रूप ले लिया। अतः इस सबध में कुछ एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा जो अर्थशास्त्री भी थे की गई सगणनाओं का अध्ययन रोचक ही होगा।<sup>41</sup>

दादा भाई की निकासी सबधी सगणनाएँ अत्यधिक जटिल थीं। इसका कारण यह था कि सभी प्रकार की सभय आपत्तियों का सामना करने के लिए तथा आलोचना को सतुष्ट करने के लिए वे अपनी सगणना के आधारों को ही निरन्तर बल्लत रहे। 1867 में उनके द्वारा निकासी की सगणित राशि 80 लाख पौड थी।<sup>42</sup> 1870 में उनके आकड़े बढ़ कर 1 करोड बीस लाख पौड हो गए।<sup>43</sup> 1876 में प्रकाशित पावर्टी आफ इंडिया में उन्होंने घोषणा की कि रेल पथों के ब्याज को निकाल कर 1835 से लेकर निकासी की औसतन वार्षिक राशि इस प्रकार से थी।<sup>44</sup>

वर्ष	वार्षिक औसत (पौंड में)
1835-1839	5,347,000
1840-1844	5,930,000
1845-1849	7,760,000
1850-1854	7,458,000
1855-1859	7,730,000
1860-1864	17,300,000
* 1865-1869	24,600,000
1870-1872	27,400,000

1893 में उन्होंने गिनती की कि निवासी की राशि 25 करोड़ रुपये प्रति वर्ष से अधिक घटनी है।<sup>45</sup> 1897 में उनके आंकड़े 1883-92 की अवधि में लगभग 359 करोड़ रुपये थे, परन्तु सरकारी ऋण पर वसूल किए जाने वाली रकम को निवासी न मानने के समर्थकों को मत्तुष्ट करने के लिए उन्होंने प्रभारों की राशि को निवासी की सीमा से अलग कर दिया और फिर भी देखा कि इन दस वर्षों में निवासी की राशि लगभग 288 करोड़ थी, जिसमें अनुमानित 118 करोड़ रुपये की राशि विदेश व्यापार के लाभों से अर्जित आय थी। दादा भाई द्वारा सगणित अल्पतम राशि थी 241 करोड़ रुपये अथवा 24 करोड़ रुपये की वार्षिक निवासी।<sup>46</sup> अतः 1905 में उन्होंने घोषणा की कि लगभग 3 करोड़ 40 लाख पौंड का अथवा 51.5 करोड़ रुपये के मूल्य के सामान की प्रति वर्ष देश में निवासी हो रही है।<sup>47</sup>

जी० बी० जोशी के अनुसार 1834-1888 तक लगभग 66 करोड़ पौंड की देश से निवासी हो चुकी थी। उन्होंने यह भी निर्देश किया कि यह निवासी प्रति वर्ष बढ़ रही है और 1888 तक कुल 25 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष तक पहुँच गई है।<sup>48</sup> 1901 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति पद से भाषण करते हुए डी० ई० वाचा ने निवासी की राशि 30 से 40 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष बताई।<sup>49</sup> कांग्रेस के अगले ही अधिवेशन में एस० एन० चैत्रजो ने 19वीं शताब्दी के पिछले तीस वर्षों में निवासी की औसत राशि 3 करोड़ पौंड सगणित की।<sup>50</sup> आर० सी० दत्त का अनुमान कम था। उनके अनुसार बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में निवासी की राशि लगभग 2 करोड़ पौंड प्रतिवर्ष थी।<sup>51</sup> पृथ्वीचन्द्र राय द्वारा 1901 में सगणित निवासी की अत्यधिक राशि 6 से 7 करोड़ पौंड प्रतिवर्ष थी।<sup>52</sup>

अपनी मायता के अनुसार लोगों को यह समझाने के लिए कि निवासी की राशि मचमुच ही परिणाम में विपुल है, बटुत सारे भारतीय नेताओं ने सरकारी राजस्व के अनुपात के सगणन की पद्धति को अपनाया। इस प्रकार उदाहरण के रूप में आर० सी० दत्त ने बार बार इस ओर निर्देश किया कि भारत के कुल राजस्व का लगभग आधा भाग विदेशों को निष्कासित हो जाता है।<sup>53</sup> असल में, जसा कि हम इस ग्रन्थ के एक अध्याय में पहले ही दिखा चुके हैं कि भारत सरकार की वित्त नीति की राष्ट्रवादियों द्वारा की गई



महत्वपूर्ण आलोचना यही थी कि देश में वसूल किए गए राजस्व के एक विपुल भाग का देश के बाहर व्यय किया जा रहा है।<sup>51</sup>

### निकासी का उद्भव

भारतीय नेताओं के अनुसार व्यापार सतूलन में अधिशेष निकासी का रूप लेता था। परंतु कौन से तत्व निकासी को जन्म देने के आधारभूत कारण थे? यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 1858 के उपरांत ही निकासी के विद्वेषण के समय यह प्रश्न प्रमुख रूप से उपस्थित हुआ। यद्यपि कंपनी के शासन काल में विशेषतया 1833 से पहले की अवधि में हुई संपत्ति की निकासी की राशि की तो प्रायः गणना की गई और उसकी निंदा भी की गई तथापि इन नेताओं ने इन वर्षों की मध्यावधि में हुई निकासी के विद्वेषण की आवश्यकता को अनुभव नहीं किया।<sup>52</sup> इसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी दो कारण थे—प्रथम, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का निवेश, इसके भागीदारों को लाभों का भुगतान, इसके सरकारी ऋण तथा खुली लूट की प्रक्रिया के माध्यम से इसके अधिकारियों द्वारा निजी संपत्ति का सचय आदि भारत से शुल्क वसूलने अथवा संपत्ति लौटाने के अत्यंत स्पष्ट और महत्वपूर्ण तत्व थे। इन शुल्कों के परिमाण और इनकी आर्थिक महत्ता पर भले ही मतभेद हों, परंतु इनकी सत्ता निर्विवाद थी। द्वितीय, भारतीय नेता अगणित उच्च सरकारी और गैरसरकारी अगरेजा के अधिकृत वकनव्यों को उद्धृत करने और उनकी विस्तृत परीक्षा करने के चक्कर में बिना पड़े ही निकासी के तथ्य को सिद्ध कर सकते थे।<sup>53</sup> वस्तुतः निकासी और उसके दुष्परिणामों के संबंध में भारत से सहानुभूति रखने वाले अगरेजा की संख्या इतनी बढ़ी थी कि आर० सी० दत्त महोदय को आश्चर्यचकित होकर यह कहना पड़ा—कोई एक निदक यह टिप्पणी कर सकता है कि भारत की ओर से तो इंग्लंड को संपत्ति प्रवाहित होती है और वहाँ के लोग भारतीयों को कौरी सहानुभूति और खेदों के रूप में बदला चुकाते हैं।<sup>54</sup> इसके अतिरिक्त भारतीयों को भूतकाल की इतनी अधिक चिंता नहीं थी, जितनी कि भविष्य की। भविष्य के सुरक्षित हो जाने पर ताबूत को भूलने तक के लिए सहमत थे।<sup>55</sup>

1858 के पश्चात् अथवा यहाँ तक कि 1833 के पश्चात् निकासी का प्रश्न जटिल और विवादास्पद बन गया था क्योंकि न तो भारत द्वारा उस समय इंग्लंड का किसी प्रकार का शुल्क दिया जा रहा था और न ही भारत के अधिशेष राजस्व को इंग्लंड के बोझ में डाला जा रहा था। जहाँ निकासी के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के लिए यह दिग्गम आवश्यक हो गया कि किस प्रकार भारत ब्रिटेन के पृथक् पृथक् नागरिकों के भुगतानों के रूप में तथा वह भी विभिन्न मार्गों से ब्रिटेन का 'पराश्र' शुल्क चुका रहा था।<sup>56</sup> उन्हें यह भी सिद्ध करना पड़ा कि इस परीक्षा निकासी का कारण पूणतया भारत पर ब्रिटेन का राजनितिक तथा आर्थिक प्रभुत्व था।

भारतीय नेताओं के अनुसार निकासी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व असैनिक सवाम, मेनाम तथा रेलवे में नियुक्त अंग्रेज कर्मचारियों, अंग्रेज वकीलों तथा अंग्रेज डाक्टरों आदि द्वारा अपनी बचता आय और बचत के एक बहुत बड़े भाग का इंग्लैंड में भेजना

या तथा भारत सरकार द्वारा अंग्रेज सरकारी कर्मचारियों की पेशगी तथा अवकाश-  
 चालीन भत्तों का इंग्लैंड में ही भुगतान करना था। दूसरे शब्दों में आर्थिक रूप से  
 भारतीय प्रशासन में, सेना में तथा रेलवे में यूरोपियों की असामान्य नियुक्ति का ही  
 परिणाम निवासी था।<sup>60</sup> इस सदन में यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कभी कभी तो दादा  
 भाई नौरोजी ने निवासी के उदगम के संबंध में यहाँ ही मकीण दृष्टिकोण अपनाया।  
 उन्होंने विशेषतया विवादात्त सलग होने पर निवासी के सारे ही रोग का दायित्व  
 भारतीय प्रशासन में अंग्रेजों की अत्यधिक नियुक्ति पर डाला।<sup>61</sup> कभी कभी तो उनकी  
 यह मकीण मनोवृत्ति मूलतः की सीमा पर पहुँच जाती थी। उदाहरण के रूप में  
 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए  
 उन्होंने अपना मत प्रकट किया कि भारत की जनता की इस विषम परिस्थिति और चरम  
 दीनता का एकमात्र कारण देश की सरकार में विदेशी कर्मचारियों की असामान्य नियुक्ति  
 है। इसी के फलस्वरूप देश का भौतिक हानि हो रही है और देश की संपत्ति की निवासी  
 ही रहती है। उन्होंने उस समय चेतावनी देते हुए कहा—देश के लिए यह जीवन और  
 मृत्यु का प्रश्न है। आप केवल इसी एक घुराई को हटा दीजिए, भारत प्रत्येक रूप में  
 सौभाग्यशाली बन जाएगा।<sup>62</sup> दादा भाई नौरोजी द्वारा इस संबोधित दृष्टिकोण को  
 अपनाने का परिणाम यह निकला कि उनके निदोषों को निवासी सिद्धांत के लोखलेपन  
 को मिट्टी करने के लिए केवल उनके वक्तव्य को ही विवेकशून्य प्रमाणित करने की  
 आवश्यकता रह गई। वदाचित् इससे भी अधिक दुर्भाग्यजनक बात यह है कि दादा भाई  
 के इस हास्यप्रद विश्लेषण ने बहुत सारे विचारकों को निवासी पर स्वयं उनके तथा अथ  
 राष्ट्रवादियों के विचारों की वास्तविक गहराई व जटिलता को समझने में पथभ्रष्ट ही  
 किया। दादा भाई नौरोजी के निवासी पर तक के इस अधिकारपूर्ण पक्ष की व्याख्या  
 किसी सीमा तक निम्नलिखित तीन पहलुओं से की जा सकती है (1) दादा भाई नौरोजी  
 स्वभाव से उग्रवादी थे। (2) 1870 तक सरकारी विदेशी पंजी विपुल परिमाण में नहीं  
 थी और उससे काफी समय बाद तक निजी विदेशी पूँजी की मात्रा भी उल्लेखनीय नहीं  
 थी। उस समय भारतीयों के विश्लेषण के अनुसार यूरोपीयों की नियुक्ति निश्चित रूप  
 से ही निवासी का सर्वाधिक विस्तृत स्रोत थी। (3) 1860 की अवधि तक दादा भाई  
 नौरोजी विदेशी पूँजी के विरुद्ध नहीं थे<sup>63</sup> और यहाँ तक कि उन्होंने तथा अथ भारतीय  
 नेताओं ने इससे बाद भी कई वर्षों तक विदेशी पूँजी के प्रयोग का अत्यंत सुदृढता तथा  
 प्रबलता के साथ विरोध नहीं किया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बाद में जब विदेशी पूँजी  
 भारत में संपत्ति की इंग्लैंड का निवासी का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई तो दादा भाई नौरोजी  
 ने निवासी के इस स्रोत के विरुद्ध ऊँचे स्तर में उसकी निंदा करना प्रारंभ कर दिया।<sup>64</sup>

भारतीय नेताओं के अनुसार भारत में धन की निवासी का एक अथ प्रधान और  
 आधारभूत स्रोत भारत सरकार के गृह प्रभार अथवा भारत सरकार की ओर से भारत  
 सचिव द्वारा इंग्लैंड में किया गया खर्च था। गृह प्रभारों के अंतर्गत भारत के सरकारी  
 ऋणों और प्रतिभूत रेल पथों के ब्याज का भुगतान भारत को सभरित सत्य तथा  
 अयाय नडारों का मूल्य, भारत सचिवालय में भारत सचिव के कर्मचारियों पर होना

वाले खर्चों तथा भारत सरकार के यूरोपीय कर्मचारियों को पेंशनो और भत्ता जो मिलाकर भारत के खात से इंग्लैंड में भुगतान किए गए सैनिक व असैनिक व्यय आदि सम्मिलित थे।<sup>65</sup> गृह प्रभारों के इनमें स प्रत्येक अंग का कभी कभी भारतीय नेताओं ने पृथक पृथक विमर्श किया तथा निवासी के ख़ाते के रूप में इसकी निंदा की।<sup>66</sup>

भारतीय नेताओं के अनुसार निवासी का तीसरा प्रमुख ख़ाते भारत में व्यापार और उद्योग में निवेशित निजी विदेशी पूंजी पर होने वाले लाभ थे।<sup>67</sup>

### निवासी के आर्थिक प्रभाव

जसाकि हम पूर्व निर्देश कर चुके हैं तथा जैसाकि आधुनिक इतिहास के छात्रों को सम्भव रूप से ज्ञात है, निवासी के साथ जुड़ा उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण दुष्परिणाम देश की धीरे-धीरे दरिद्रता थी। हा प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के इस सबंध में दृष्टिकोण थोड़ा-बहुत भिन्न रूप अवश्य लिए हुए थे। उदाहरणार्थ, दादा भाई नौरोजी ने निवासी को देश के सभी लोगों, दुःखी और दरिद्रता का वास्तविक, प्रधान और यहाँ तक कि एक मात्र मूल कारण धारित किया, तथा अत्याचारणों को केवल भ्रामक बताया।<sup>68</sup> उन्होंने 1880 में बड़ी प्रबलता के साथ एक प्रस्तुत करते हुए कहा —

यह आर्थिक नियमों की तूर प्रतिया नहीं है प्रत्युत यह तो ब्रिटिश नीति की विवेक-गुण्य और तूर वायदाही है। यह भारत की धन संपत्ति को ही भारत में हड़पने का कर तृप्त है और इसमें भी बढकर देश से इंग्लैंड को संपत्ति की क्रूर निवासी है। संक्षेपत यह भारत का रक्त चूसने के रूप में दुःखद ढंग में आर्थिक नियमों को विवृत करना और इसके फलस्वरूप भारत का विनष्ट करने का निरम प्रयास है।<sup>69</sup>

इस सबंध में दादा भाई के दृष्टिकोण को अपनाते वाले केवल थोड़े से ही और राष्ट्रवादी नेता थे। उन थोड़े में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे — अमृत बाजार पत्रिका के संपादक गण।<sup>70</sup> इन नेताओं में अधिकतर ने ही इस धारणा से कि भारतीय जनता को दरिद्र बनाने में निवासी की महत्वपूर्ण ही नहीं बदाचित्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, सहमति के रूप में अपने विचार प्रकट करके ही सत्ताप कर लिया।<sup>71</sup> भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी निवासी को केवल भारत की दरिद्रता के कारणों में से एक बताया।<sup>72</sup> यहाँ इस तथ्य का उल्लेख करना अनुचित न होगा कि बहुत सारे भारतीय नेताओं ने निवासी के सापेक्षिक महत्व के प्रश्न पर तथा दरिद्रता के लिए उत्तरदायी अन्याय विविध पक्षों पर विचार ही नहीं किया। जब उन्होंने निवासी पर विचार विमर्श किया तो उन्होंने इसकी प्रबलता का निंदा की और जब उन्होंने अपने विश्वासानुसार भारत की दरिद्रता के लिए उत्तरदायी किसी दूसरे पक्ष पर विचार विमर्श किया तो उन्होंने पहले जैसी ही प्रबलता से उसकी निंदा की।

सामों को बदाचित्त यह सम्भव रूप से ज्ञात नहीं है कि राष्ट्रवादी नेताओं की निवासी का देश को दरिद्र बनाने वाली मानने की अवस्था उन्हीं देश के लिए आर्थिक दृष्टि से विघ्नक तथा दुर्भाग्यजनक कारण मानने की धारणा के पीछे कौन-सा आर्थिक तर्क काम कर रहा था। इस दृष्टि से इस सबंध में ध्यान देने योग्य तत्व यह है कि भारतीय

नेताआन निवासी को केवल संपत्ति की हानि के रूप में ही नहीं लिया प्रत्युत उसे पूँजी की हानि भी माना। उनके द्वारा प्रतिपादित निवासी सिद्धांत केवल धन के अथवा सामग्री के नियान के सकुचित विचार क्षेत्र तक सीमित नहीं था प्रत्युत वह व्यापक आर्थिक कारणों तथा विचारों पर ही आधारित था।

संपत्ति की प्रत्यक्ष हानि की अथवा राष्ट्रीय उत्पाद के एक भाग के स्थूल रूप से स्थानांतरण होने की अथवा लोगों की आजीविका के साधनों में वास्तविक कमी होने की धारणा तो निवासी की परिभाषा में निहित थी। राष्ट्रवादी नेताओं में बहुत सारे अथ शास्त्रियों ने व्यापक रूप में निवासी के रूप और अर्थ को जिस प्रकार समझा तथा स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूप से जिस प्रकार उसका प्रचार प्रसार किया, वह यह था कि इस निवासी का देश की अर्थव्यवस्था पर भले ही अर्थ कोई दुष्प्रभाव न पड़ता हो फिर भी इससे राष्ट्रीय उत्पादन में होने वाली कमी ही अपना आप में इतना विशाल दोष है कि इस एक भारी रोग बहा जा सकता है।<sup>72</sup>

कुछ एक भारतीय नेता इस तथ्य का भी समझन में सफल हो गए कि विन्शा में राष्ट्रीय संपत्ति के स्थानांतरण से देश की आय पर और देश के भीतर राजगार पर उसका घातक प्रभाव ही पड़ता है। उन्होंने इस तथ्य की ओर निर्देश किया कि निवासी का अर्थ राष्ट्रीय आय के कुछ निश्चित भाग का देश के बाहर विदेशों में खर्च करना मात्र ही नहीं प्रत्युत देश के भीतर ही उसके खर्च किए जाने पर उसमें आय और राजगार में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि में कमी है। इस प्रकार 1903 में आर० सी० दत्त ने टिप्पणी की कि

जब देश में उगाह करों को देश में ही खर्च किया जाता है तो धन देश की जनता में परिचालित होता है, व्यापार, उद्योग और कृषि को परिपुष्ट करता है तथा किसी एक न एक रूप में समासाधारण के पास पहुंच जाता है परंतु जब देश में वसूल किए गए करों का देश के बाहर प्रेषित कर दिया जाता है तो देश का वह धन देश के लिए सत्ता के लिए ही नष्ट हो जाता है। वह न तो देश के व्यापार अथवा उद्योगों को संपन्न बनाता है और न ही किसी रूप में देश के जनसाधारण के हाथ में पहुंचता है।<sup>4</sup>

आर० सी० दत्त सहित कुछ एक भारतीय नेताओं ने जाज विंगेट की निम्नलिखित सुप्रसिद्ध टिप्पणियों को उद्धृत करते हुए देश के करों के देश के बाहर विन्शा में खर्च किए जाने पर उसके देश की आर्थिकता पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से संबंधित तथ्यों को सिद्ध किया

किसी देश से वसूल किए गए करों को उसी देश में खर्च करने तथा एक देश से वसूल किए गए करों को दूसरे देश में खर्च करने में प्रभाव की दृष्टि से एक महान अंतर है। प्रथम स्थिति में जनता से वसूल किए गए करों का विशाल भाग सरकारी भवनों में लगे लोगों को ही वापस मिल जाता है। उन लोगों द्वारा पाया गया धन खर्च किए जाने पर फिर श्रमिक वर्गों के पास पहुंच जाता है। परंतु वह स्थिति सदा और पूणतया भिन्न होती है जबकि किसी देश में उगाह करों को उस देश में नहीं

खर्चा जाता। इस स्थिति में उस देश को भारी और वास्तविक हानि हाती है और वरारापित दश में निकाला गया धन पूणतया नष्ट हो जाता है। जहाँ तक राष्ट्रीय उत्पाद पर इसके प्रभावा का संबध है, सारे का सारा धन समुद्र में फेंका गया ही समझना चाहिए।<sup>5</sup>

इस तथ्य के आधार पर भी भारतीय नतावा ने भारत के पुराने स्वच्छाचारी शासकों और ब्रिटिश शासकों के बीच अंतर का स्पष्ट किया। इस प्रकार 1902 में सुरेंद्रनाथ वैनर्जी ने टिप्पणी करते हुए लिखा पुराने विजेताओं ने विजित देश को शीघ्र ही अपना देश बना लिया था तथा देश की जनता से छीनी गई संपत्ति शीघ्र देश के लोगों के पास लौट आई थी। इस प्रकार उन्होंने यह उद्योग के स्त्रातो को प्रोत्साहित किया तथा देश की जनता की भौतिक संपन्नता में योगदान दिया।<sup>6</sup> अपने 'इकोनामिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया' ग्रंथ के प्रथम खंड की मूमिका में आर० सी० दत्त ने भी इस विषय पर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में प्रकाश डाला। एक भारतीय कवि के शब्दों में जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी के जल को सुखाकर भाप के रूप में ग्रहण करता है और फिर उसी जल को धरती का हारा-भरा करने के लिए वर्षा के रूप में उसे वापस लौटा देता है उसी प्रकार दश शासकों को देश के करो-करो उगाहकर देश की संपन्नता के लिए खच करने के रूप में उन करा-बादे-वासियों को लौटा देना चाहिए। परंतु भारत के उगाह गए कर भारत का संपन्न न बना कर किसी अन्य देश की ही संपन्नता में वृद्धि करते हैं—दशका विरोध करते हुए उन्होंने निश्चित स्वर में कहा कि ऐसा तो अफगान और मुगल शासकों के निवृत्ततम शासन काल में भी नहीं हुआ। दूसरी ओर उन्होंने दावा किया कि उन्होंने जो चकाचौध उत्पन्न करने वाले महल और स्मारक बनवाए तथा साथ ही साथ जिन विलासी कार्यों में वे प्रवृत्त हुए उन्होंने भारत के उत्पादकों और शरीरों को प्रोत्साहन और संपोषण दिया। उन्होंने इस प्रकार अपना निश्चित मत अभिव्यक्त करते हुए कहा—बुद्धिमान शासकों के तथा मूल शासकों के अंगीन शासन काल में एक बात समझ रही है कि करो-करो में वसूल किया गया धन जनता के पास ही लौट आया है और उसने देश के व्यापार और उद्योगों को संपुष्ट बनाया है।<sup>7</sup>

यहां यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रवादियों की इस भाव—वसूल किए गए कर जनता को ही वापस लौटा देने चाहिए ताकि उनकी जड़ें भारी हो सकें।<sup>8</sup> अथवा उनके व्यापार और उद्योग समृद्ध बन सकें—के पीछे करा को देश ही के भीतर खच करने से देश की गौण आय पर उमड़े पड़ने वाले प्रभाव के संबध में राष्ट्रवादियों की जातवारी का परिचय प्राप्त होता है।<sup>9</sup>

सादा भाई नौराजी ने निक्की की परिभाषा को और अधिक विस्तृत रूप दिया तथा विदेशियों द्वारा अपने बतना और जायों के भारत में खच दिए जाने वाले भाग के विरुद्ध भी शिवायत की। इस शिवायत के संबध में उनका दावा था कि विदेशियों द्वारा किया गया उपभोग भी आर्थिक रूप में भारतीय मामश्रिया और मवाआ की हानि ही थी क्योंकि जयया ये वस्तुएं उपभोग के लिए भारतीयों का ही मुत्रभ हाती।<sup>10</sup>

भारतीय उताआ में अथगाश्रिया न अवश्य निक्की से हानि बानी संपत्ति की हानि



प्रगति के लिए अपक्षिण जीवन रत्न की व्यवस्था के लिए देश की पूँजी को बचाना अत्यावश्यक है और उसका एक मात्र उपाय भारतीयों की सेवाओं में नियुक्ति है।<sup>84</sup> इसी प्रकार 1887 में एम० ई० ग्रांट डफ को लिखे अपने प्रत्युत्तर में दादा भाई ने शिकायत की कि वर्तमान नीति के अंतर्गत ब्रिटिश भारत अपनी तुच्छ आय से निरंतर निकासी के कारण अपनी किसी प्रकार की पूँजी को रख पाने की स्थिति से वंचित किया जा रहा है।<sup>85</sup> 12 फरवरी 1895 को 'हाउस आफ कॉमन्स' में दिए गए अपने भाषण में उन्होंने घोषित किया—निकासी के फलस्वरूप देश से पूँजी हटा दी गई है और देशवासियों को पूँजी को बढ़ाने से वंचित कर दिया गया है। वस्तुतः इससे इंग्लैंड को अनिवायत लाभ पहुँचा है और ब्रिटिश भारतीयों के साधन इस तरह लटखड़ा गए हैं कि वे किसी भी रूप में अपने साधनों को पुनर्जीवन नहीं दे सकते। अतः उनके लिए दरिद्रता का अभावग्रस्त जीवन जीने के सिवाय अन्य कोई चारा ही नहीं।<sup>86</sup> विलबी कमीशन के सामने जिरह के दौरान दादा भाई ने निकासी से भारत की पूँजी को होने वाली हानि की ओर कमीशन का ध्यान दिलाने की पूरी पूरी चेष्टा की तथा अपने आलाचकों को बीच में ही पर डबते हुए उन्होंने कहा कि भारतीयों को उपयुक्त विराज देने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है परंतु यह विराज इस परिणाम में होना चाहिए कि जिससे भारत के पूँजी निर्माण को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे।<sup>8</sup>

दादा भाई नौरोजी ने विलबी कमीशन के अध्यक्ष के साथ जो लड़ा चौड़ा घाद-विवाद किया उसमें उन्होंने प्रबली ही सुस्पष्ट भाषा और नाटकीय शैली से निकासी के प्रश्न को प्रभावशाली ढंग से ही पूँजी निमाण तथा आय प्रजनन के साथ जोड़ दिया। इस विषय में दादा भाई नौरोजी ने भारत जैसे अविकसित देश में निवेश वृद्धि और आय वृद्धि के पारस्परिक संबंध में बड़ी ही सुव्यवस्थित तथा अकाल प्रौढ़ सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया। आइए, हम उनके तर्कों को उसके मूल रूप<sup>87</sup> में सिलसिलेवार समझें।

दादा भाई ने अपने साक्ष्य के प्रारंभिक भाग में प्रतिपादित किया कि देश की कुशल और प्रगतिशील सरकार के लिए भारत का 6400 लाख रुपये राजस्व नितान्त अपयाप्त पड़ रहा है और यह राशि इतनी कम, सरकार की उस अस्वाभाविक प्रणाली के कारण है जो लोगों को दरिद्र बना रही है तथा उन्हें सरकार को अधिक भुगतान करने में नितान्त असमर्थ बना रही है। उन्होंने अपना मत पकड़ करते हुए कहा कि विदेशी मत्ता द्वारा रचित चूसे जान के स्थान पर यदि भारतीयों को अपने साधनों को भारत में ही रखने दिया जाए तो भारतीय आवश्यकता पट्टे पर कपड़े के रूप में ही 20 000 लाख रुपया का भुगतान कर सकते हैं। लाड बिनबी दादा भाई के इस मत-य से सहमत नहीं थे, तभी उन्होंने पूछा कि म्यन्त्र सत्ता के अधीनस्थ विण जान पर एक निधन दंग 2 र० 12 आन (3 गिलिंग 8 पस) प्रति व्यक्ति कर के स्थान पर उससे बड़ा कर 1 पौंड 6 शिलिंग 6 पस प्रति व्यक्ति कर का भुगतान किस प्रकार कर सकता है? दादा भाई का स्पष्ट उत्तर था कि अपने लाभों का अपने ही पाम रखने की अनुमति प्राप्त होने पर आज का निधन देना बल धनी बन जाएगा। यह तर्क विलबी की समझ में न आया अथवा वह समझना ही नहीं चाहता था अतः उसने पूछा कि क्या नौरोजी दादा भाई यूरोपीय विपाटिया और राजकीय

प्रशासकों पर सच किए जा रहे 2000 लाख रुपये पर आपत्ति करने हैं और यहाँ तक कि यदि यह रकम भारतीयों का लौटा दी जाए तो भी इससे दो रुपये के स्तर से बढ़कर 1 पौंड 6 शिलिंग 6 पैसे प्रति व्यक्ति के स्तर तक अर्थात् 6400 लाख रुपये से बढ़कर 30 000 लाख रुपये प्रति वर्ष तक कर वृद्धि में सहायता कम मिल सकती है ? दादा भाई द्वारा इस प्रश्न का दिया गया उत्तर इस तथ्य का उद्घाटन करता है कि उनकी दृष्टि में निकासी का अर्थ केवल संपत्ति का स्थानांतरण नहीं था। उनका उत्तर था कि देश से खींचा जाने वाला धन यदि बचा लिया जाए तो उससे आर्थिक प्रभाव ये होंगे कि इस देश समृद्ध हो जाएगा। दूसरे शब्दों में देश का लाभ केवल 2000 लाख रुपये की वास्तविक बचतों तक ही सीमित नहीं रह पाएगा। विलबी इस पर भी सतुष्ट नहीं था और उसने और अधिक कुरेदा—परंतु आप इसे (भारत को) इस रकम (2000 लाख रुपये) से बढ़कर तो समृद्ध नहीं बना सकते ? दादा भाई का प्रत्युत्तर था—यदि यह रकम देश में ही रहने दी जाए तो आर्थिक दृष्टि में वर्तमान की अपेक्षा यह अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी प्रभाव ही डालेगी। इसका अर्थ केवल 2000 लाख रुपये की बचत ही नहीं होगी प्रत्युत यह पुनः उत्पादनों की, देश में पूँजी को बनाने की दिशा में बचत होगी, परंतु यहाँ विचारणीय है कि दादा भाई ने पूँजी की बढ़ोतरी को एक बुद्धिवादी की भाँति वाली कहानी की तरह यात्रिक रूप में नहीं देखा जिससे पसा चक्रवर्ती ब्याज (या नफा) की महायता से हर साल बढ़ता जाए। भले ही उनके वास्तविक जानड़े और सगणनाएँ अस्पष्ट और कभी कभी निराधार भी हों परंतु इतना निश्चित है कि वे निवेशित आर्थिक विनास की जड़ को ही पकड़ नहीं रहे थे तथा आर्थिक विकास के आधुनिक सिद्धांतों का पूर्व सूचित ही नहीं कर रहे थे प्रत्युत निवेशगुणन की धारणा की भी कदाचित्त भविष्यवाणी कर रहे थे। इस पर जब विलबी ने विरोध प्रकट किया—कि यहाँ भारत में रखा गए 2000 लाख रुपये में भारत को केवल निश्चित राशि ब्याज की ही ता प्रप्ति होगी। दादा भाई ने एकदम मूढ़ तोड़ उत्तर दिया—ब्याज ही केवल सब कुछ नहीं है, इससे तो देश के माधनों का विकास होगा जिससे आज की अपेक्षा देश की पाँच गुणा अधिक समृद्धि हो सकती है। वस्तुतः भारतीयों के रक्त के रूप में भारत की पूँजी देश से बाहर ले जाई जाती है उसे देश में ही रहने दिया जाए और भारत के अपने माधनों का रूप लेने दिया जाए तो देश इन्हीं से पर्याप्त संपन्न बन जाएगा। यह पूँजी देश के रक्त समान है। विलबी ने फिर भी ठीक से समझने का ढाँग रचा<sup>99</sup> और टिप्पणी की—मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि भारत इतना संपन्न देश है कि 2000 लाख रुपये यदि यहाँ लगाए जाए तो वह एक वर्ष के भीतर ही 20000 लाख से 30000 लाख रुपये अर्जित कर सकता है। दादा भाई ने तत्काल यह उत्तर देकर विलबी की टिप्पणी को नाकारा कर दिया कि उनके द्वारा पूर्व सूचित परिणाम का अर्थ यह नहीं कि यह सब एक ही वर्ष में हो जाएगा। उनके कथन का अभिप्राय तो केवल इतना था कि यदि निकासी को रोक दिया जाए तो भारत आवश्यक करा का भुगतान यथासमय करने की स्थिति में आ जाएगा। कर 20000 लाख रुपये हो अथवा 30,000 लाख रुपये। इस वाद विवाद के विलबी ने दो तीन बार पुनः यह प्रयास किया कि दादा भाई यह स्वीकार



2000 लाख रुपये की छोटी सी रकम भारत के साधना को एक बड़े परिमाण में मफन बना सकती है—यह धारणा नितांत निर्मूल तथा मिथ्या कल्पित है परन्तु दादा भाई तो अपन कथन पर डटे रह ।

जी० बी० जाशी ने भी निकासी की पूँजी की क्षति माना और इस क्षेत्र में भी उन्होंने राष्ट्रवादी चिन्तन का एक नया धरातल प्रदान किया । उनका सुभाव था कि निकासी को वार्षिक कुल राष्ट्रीय उत्पादन के एक अंश के रूप में नहीं लेना चाहिए भले ही यह भाग चाहे जितना ऊँचा और भारी क्यों न हो, प्रत्युत इसे तो वार्षिक शुद्ध वाय क्लम अधिशेष अथवा बचत का एक भाग समझना चाहिए । इस प्रकार 1884 में अपने लेख—'दी इकोनामिक रिजल्ट ऑफ फ्री ट्रेड ऐंड रेलवे ऐकमॉशन'—में उन्होंने सगणता की कि 1882 में आयात पर निर्यात की अधिकता 23 करोड़ रुपये थी । भारत का कुल वार्षिक उत्पादन 350 करोड़ था और कुल उत्पादन 12 प्रतिशत पर सर्वाधिक अनुकूल दर से लाभ की राशि 40 करोड़ थी । अतएव राष्ट्रीय ससाजना पर निवानी का भाग राष्ट्रीय उत्पादन के लाभों का पचास प्रतिशत से अधिक था ।<sup>90</sup> छ वष पश्चात् जपान लेख—'दि इकोनामिक सिन्थ्युएशन इन इंडिया' में जाशी जी ने निम्नलिखित शब्दों में अपनी उक्त धारणा का सीधी तकसम्मत् अभिव्यक्ति दी

निकासी का पूरा माप दश की कुल वार्षिक आय के साथ उसका अनुपात नहीं है यह अनुपात तो लगभग 6 प्रतिशत है । उसका वास्तविक माप देश के प्रशासन के संचालन पर होने वाले वार्षिक आवश्यक व्ययों को निकाल कर शुद्ध आय का अनुपात है और यह अनुपात लगभग एक तिहाई भाग है । शुद्ध राष्ट्रीय आय में पूरे एक तिहाई भाग का विदेशी दायित्वा के निभाने के लिए दश के बाहर चले जाना और बदले में देश को किसी प्रकार का आर्थिक लाभ न पहुँचना सचमुच ही दश की भारी क्षति है और यही भारत में लघ पूँजी संचय का कारण है ।<sup>91</sup>

डी० ई० वाचा और जी० एस० पेयर सहित कितने ही अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने वार्षिक निकासी के सबंध में इसी प्रकार के विचार प्रकट किए । उन्होंने भी देश से पूँजी के बाहर ले जाने का देश की उल्लेखनीय और तात्विक क्षति बताया ।<sup>92</sup>

द्वितीय कुछ एक भारतीय नेताओं का यह निश्चित मत था कि निकासी से उत्पन्न होने वाली पूँजी की कमी का परिणाम यह निकलता है कि इससे भारत की आर्थिक मुक्ति का आधारभूत औद्योगिक विकास प्रतिरूधित हो जाता है । वस्तुतः उनका यह अनुभव था कि भारत में आधुनिक उद्योग की मदगति का प्रमुख दायित्व निवानी पर ही था । इस प्रकार दादा भाई नौरोजी ने अपने लेख—'दि पावर्टी आफ इंडिया में तब प्रस्तुत किया कि यद्यपि बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण भारत की एक अत्यंत अप्रतिहाय आवश्यकता थी परन्तु व्यवहार में उद्योग उपलब्ध पूँजी की कमी के कारण सीमित था और यहाँ उन्हें न जान स्टुअर्ट मिल के इस मतव्य को उद्धृत किया—

उत्पादक श्रम को समयान्तर और नियोजन देने वाला तत्त्व निर्देशित पूँजी है न कि श्रम के उत्पादन के बिना उसके पूर्ण होन पर धेनाआ की किसी प्रकार की भाग ।' और भारत के अभाव में पीटिन है जिसका एक कारण तो यह है कि इसका अधिशेष उत्पादन

स्वल्प है और इससे भी बढ़कर बात यह है कि इसके दैनिक पुन उत्पादन का आवश्यकताओं की और यहा तक कि अधिशेष की निकासी कर दी जाती है। इसलिए देश अपनी संपदा की वृद्धि के लिए उद्योग का उपयोग ही नहीं कर पाता और इसके फलस्वरूप देश की दरिद्रता का उत्तरोत्तर विस्तार अवाधित रूप से होता जा रहा है।<sup>93</sup> 1881, में अपनी इस तक प्रणाली की उन्होंने व्यग्यात्मक रूप से टिप्पणी की—जबकि अंग्रेज लोग भारत की मूल पूजा का ही अपहरण कर रहे हैं तो फिर वे इस बात पर आश्चर्य क्यों प्रकट कर रहे हैं कि भारत में उद्योगों की स्थापना नहीं हो सकती।<sup>94</sup> इसी प्रकार विल्वी कमीशन के सामने जिरह में उन्होंने इस आरोप का खंडन किया कि भारतीयों की उद्योगों में पूजा निवेश करने में असहमति ही भारत के औद्योगिक विकास के अभाव का प्रधान कारण है। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि तथ्य यह है कि भारतीयों के पास उपलब्ध पूजा पर्याप्त नहीं है। इससे भारत अपने ही लाभ के लिए अपने ही साधनों से अपने साधनों का स्वतंत्र विकास नहीं कर सकता। यदि प्रतिवचन भारत को पूजा से वंचित न किया जाए तो वह निश्चित ही अपने साधनों का विकास करने में समर्थ हो जाएगा।<sup>95</sup> बाद में 1900 में दिए गए अपने भाषण में दादा भाई ने घोषणा की कि यहा तक कि भारत के पुराने उद्योगों की क्षति का आंशिक दायित्व निकासी पर है। ग्रेट ब्रिटेन ने भारतीयों का जीवन रक्त चूस लिया है और वे अब अपने उद्योगों के संचालन की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि इसके लिए उनके पास साधन ही नहीं हैं।<sup>96</sup>

जी० वी० जोशी ने यह मत भी प्रकट किया कि भारत में औद्योगिक प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कायरेत पूजा की अपर्याप्तता का कारण बड़े पैमाने पर पूजा के संप्रदाय का अभाव था और यह अशत भारत से ब्रिटेन को पूजा की निकासी का परिणाम था। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि कोई भी देश इस निकासी को सहन करत हुए अपने औद्योगिक क्षेत्र को प्रगतिशील नहीं बना सकता।<sup>97</sup> इसी प्रकार श्री० ई० वाचा ने भी अनुभव किया कि भारत तब तक नए उद्योगों की स्थापना के सन्ध में साच तक नहीं सकता, जब तक कि वह पूजा की निकासी के अभिशाप से मुक्त नहीं हो जाता क्योंकि पैसा पस को खींचता है और भारत के उद्योग घनाभाव से पीड़ित है। उन्होंने अपने मतव्य की सत्यता के प्रमाण के रूप में जापान की उल्लेखनीय औद्योगिक प्रगति को उद्धृत किया जहा दम तांडन वाली प्रक्रियाएँ संपत्ति के राष्ट्रीय अधिशेष का वार्षिक जपहरण नहीं किया जा रहा था।<sup>98</sup> विल्वी कमीशन द्वारा जी० वे० गोखले से जिरह के दौरान दादा भाई नौराजी और गोखले के मध्य हुए प्रश्नोत्तरों में निकासी और औद्योगीकरण के अभाव के मध्यवर्ती संबंध के विषय में राष्ट्रवादी स्थिति को अत्यंत ही स्पष्ट भाषा में अभिव्यक्ति दी गई। गोखले से यह प्रश्न किया गया कि भारतीय नए उद्योगों की स्थापना क्यों नहीं करत ?

(दादा भाई) इसका क्या कारण है कि भारतीय इन उद्योगों का जोस कि चाय उद्योग का अथवा इनमें से किसी और उद्योग को अथवा इनमें किसी उद्योग का हाथ में नहीं ले सके जबकि विदेशी आए और उन्होंने इन पर बन्ना जमा लिया। क्या इसका कारण यह नहीं है कि हमारे देश की पूजा देश में बाहर ले जाई जा रही है ?

(गोखले) हा, यही कारण है।

(दादा भाई) क्या यह सभी रोगों का मूल कारण नहीं है ?

(गोखले) हा, सभी रोगों की जड़ यही है।<sup>99</sup>

कुछ एक भारतीय नेताओं ने थोड़ा और आगे बढ़कर यह निर्देश भी किया कि जहाँ निकासी भारत की पूँजी की क्षति का एक स्रोत है वहाँ अतीत में यह इंग्लैंड के पूँजी संग्रह का एक स्रोत सिद्ध हुई है और उसने देश के साधनों को सफल बनाया है तथा देश के द्रुत औद्योगीकरण में सहायता प्रदान की है।<sup>100</sup>

इस सब में यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दादा भाई नैरोजी तथा उपर्युक्त अयाय नेता कुल मिलाकर इस तथ्य से अपरिचित ही थे कि उनके द्वारा परिभाषित राष्ट्रीय अधिशेष अपने आप से औद्योगिक पूँजी का रूप ग्रहण नहीं कर सकता, उससे इस रूप में परिवर्तित होने के लिए तो दो अडचनों को हटाना होगा प्रथम, उन्होंने इस तथ्य की उपेक्षा की कि बचत करने वाले वर्गों के अनाप शनाप खर्चों के कारण राष्ट्रीय पूँजी का भीतर ही भीतर ह्रास होता जा रहा है। इसके साथ, बचत करने वाले वर्गों की प्रवृत्ति या तो संपत्ति के संग्रह की है अथवा, औद्योगिक, अनुत्पादक क्षेत्रों में धन के निवेश करने की है। दादा भाई ने समस्या के इस पक्ष पर ध्यान अवश्य दिया परन्तु चलता सा। उन्होंने विलबी कमीशन के समक्ष अपने साक्ष्य में भारत की रियासतों के कुछ एक शासकों की धन संग्रह की प्रवृत्ति की आलोचना की। इसी प्रकार जसाकि हम ऊपर निर्देश कर चुके हैं, जी० बी० जादी ने सरकार की भारतीय जनता से सरकारी ऋण उगाहन की प्रवृत्ति की निंदा की क्योंकि उनके अनुसार ये ऋण देश में निवेश की जाने वाली पूँजी का देश से अपहरण करते हैं। इसी प्रकार 'बंगाली' ने 25 दिसंबर 1880 के अंक में तथा 28 जनवरी 1882 के अंक में बंगाल की जमींदारी पद्धति की इसलिए आलोचना की कि इससे बंगाल की उपलब्ध पूँजी का व्यापार और उद्योग के क्षेत्र से हटाकर भूमि में उसका निवेश किया जा रहा है। परन्तु साधारणतया भारतीय नेताओं के इस चर्चा ने पूँजी निर्माण के इस पहलू की प्रायः उपेक्षा ही की। द्वितीय इन नेताओं ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान नहीं दिया कि अधिशेष का औद्योगिक पूँजी के रूप में लाने से पूर्व तकनीक, पूँजी संगठन, उद्यम कौशल आदि सबंधित समस्याओं का निपटारा भी आवश्यक है। वस्तुतः जैसा कि हम द्वितीय और तृतीय अध्याय में अयाय सदस्यों में देख चुके हैं कि बहुत सारे नेताओं ने इन समस्याओं पर ध्यान अवश्य दिया परन्तु निकासी के सबंध में उन नेताओं ने इन समस्याओं का गौण स्थान ही दिया। विशेषतः दादा भाई नैरोजी ने तो इन्हें तुच्छ मानते हुए इनकी पूर्ण उपेक्षा की। उनका कदाचित् यह विश्वास था कि निकासी का रोकना और उससे पूँजी का निर्माण करना ही प्रधान लक्ष्य था, और इस लक्ष्य की सिद्धि हो जाने के उपरांत ही अयाय समस्याओं का सामना करना उचित है।

दादा भाई नैरोजी द्वारा निकासी के विरुद्ध लगाया गया एक अन्य आरोप यह था कि इससे विदेशी पूँजी का देश में घुसना और देश का शापण करने की सुविधा उपलब्ध होती थी। उनके अनुसार सुविधा जुटाने का यह कार्य दो रूपों में होता था, प्रथम, निकासी भारत के अंदर पूँजी ही के संग्रह में बाधा पड़ाने और इस प्रकार स आंतरिक पूँजी को



की मांग का प्रस्ताव पेश करते हुए उन्होंने दावा किया कि वस्तुतः यह निकासी पर पहले के ही प्रस्तुत प्रस्ताव का पूरक है। उन्होंने कहा कि दादा भाई नौराजी जहाँ भारतीय राजस्व के एक बहुत बड़े भाग की प्रतिवध निकासी के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं, मैं स्वयं भी यही दिखाने को उत्सुक हूँ कि राजस्व के एक बहुत बड़े भाग की वसूली देश के दरिद्रों में दरिद्रतम लोगों, भारत के किमानों, से ही की जाती है। उन्होंने स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि इसमें प्रकट होता है कि हम दोनों (मैं और दादा भाई) दो भिन्न भिन्न प्रश्नों पर विचार नहीं कर रहे हैं प्रत्युत एक ही प्रश्न के दो पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा कि हम दो विभिन्न सुधारों की मांग नहीं कर रहे हैं। हम तो केवल बाहरी और भीतरी दृष्टि से सुधार की आवश्यकता को दिखाते हुए उम्मीद एक सुधार की मांग कर रहे हैं। उन्होंने दृढ़ स्वर में अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि आर्थिक निकासी तब तक कम नहीं होगी जब तक भूमि लगान कम नहीं होगा, और भूमि लगान तब तक कम नहीं होगा, जब तक धन की निकासी नहीं घटाई जाती।<sup>106</sup> इसी प्रकार 'अमृत बाजार पत्रिका' ने 1 अक्टूबर 1900 के अंक में मत प्रकट किया कि भूमि पर ऊँचे लगान एक भारी रोग है और यह अकाल के प्रमुख कारण निकासी का फल है।

डी० ई० वाचा ने 1886 में निकासी के ऋषि पर पड़ने वाले प्रभाव के एक अर्थ पक्ष को उजागर किया। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि निकासी ऋषि को सभी प्रकार की उत्पादक पूँजी से वंचित कर रही है। उन्होंने बल देकर कहा कि जब तक सारी जनता के सभी लाभों की निकासी की जा रही है, तब तक धरती की उत्पादकता में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की जा सकती। क्योंकि यह वृद्धि तभी संभव है जब धरती पर सबन पूँजी का व्यवस्थित स्थिति में निश्चित रूप से थोड़ी मात्रा में और कुल मिलाकर बड़ी मात्रा में किया जाए।<sup>107</sup>

बहुत सारे भारतीय नेता यह देखने में भी सफल हो गए कि संपत्ति के एकपक्षीय स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली प्रत्यक्ष हानि के अतिरिक्त निकासी भारत के विदेशों के साथ व्यापार संबंधों को बिगाड़ने के रूप में एक दूसरा आघात भी कर रही थी क्योंकि निकासी के साथ विनिमय अधिशेष अनिवाय रूप से जुड़ा तत्व था और यह भारत के निर्यात की एक अनिवाय विशेषता बन गई थी। भारत के लिए दो ही मांग थी या तो वह निर्यात करे या नष्ट हो जाए। फलतः भारत को विदेशी क्रेताओं का अपना मात खरीदने को प्रलोभित करने के लिए अपने मान की कीमत घटानी पड़ती थी। दूसरे गण्टों में निकासी के फलस्वरूप जिन शर्तों पर भारत आयात के बन्ने निर्यात करता था वह इनके मर्यादा अनुकूल नहीं थी।<sup>108</sup>

यहाँ यह एक उल्लेखनीय रोचक तथ्य है कि राष्ट्रवादियों को निकासी की जालोचना में कुछ विविध महापुरुषों का समर्थन प्राप्त हुआ। आदम स्मिथ ने वन्य आर्थिक नशा में भारत के प्रारंभिक ब्रिटिश शासकों को भारत के लुटेरे डाकू बताया।<sup>109</sup> इसी प्रकार वान माक्स ने भी निकासी के लिए लगभग उही गण्टों का प्रयोग किया, जिनका दादा भाई नौराजी प्रयोग किया करते थे। 1857 में माक्स ने लिखा



में, केवल 1857 के विद्रोह के कुछ एक वर्षों को छोड़कर और वह भी 250 लाख डालर के साधारण परिमाण तक, यह देश विशुद्ध रूप से पूँजी का निर्यातक ही रहा है।

### निकासी में कटौती

निकासी सिद्धांत के कुछ एक समयको का तो विश्वास था कि जब तक निकासी जारी है भारत का आर्थिक पुनर्निर्माण कभी संभव ही नहीं और यदि भारत को निकासी से एक बार मुक्ति मिल जाए तो और सत्र कुछ अपने प्राकृतिक रूप में ही स्वतः ठीक हो जाएगा।<sup>110</sup> कुछ एक अग्र नेताओं ने थोड़ा कम कठोर दृष्टिकोण अपनाया और उन्होंने भारत की दरिद्रता और अकाल को निर्मूल करने के लिए अन्य बातों के साथ साथ निकासी में कटौती का भी एक आवश्यक शत माना।<sup>111</sup>

इस सबंध में दो अग्र बातें भी विचारणीय हैं। प्रथम, जैसा कि हम पहले दिखा चुके हैं दादा भाई तक इस तथ्य से परिचित थे कि विदेशी शासन के आवश्यक उपकरण के रूप में थोड़ी बहुत निकासी का बना रहना तो सवधा अनिवाय ही है। विदेशी शासन को उखाड़ फेंके बिना तो इसे सवधा निर्मूल किया ही नहीं जा सकता और हमारे अध्ययन के अंतगत अवधि के दौरान सामान्यतया भारत से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने की कल्पना ही दादा भाई के मस्तिष्क में नहीं थी।<sup>112</sup> द्वितीय, दादा भाई और आर० सी० दत्त न ब्रिटिश जनता को यह समझाने की पूरी चेष्टा की कि निकासी में कटौती में स्वयं उन्हें असीम लाभ पहुंचेगा क्योंकि इससे उनका भारत को निर्यात कई गुना बढ़ जाएगा।<sup>113</sup> दादा भाई ने अपने लेख में सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमारे अध्ययन के अंतगत अवधि के दौरान ब्रिटिश जनता के विभिन्न वर्गों में उत्पन्न हो रहे तीखे राजनैतिक मतभेदों का लाभ उठाने में भी किसी प्रकार का सकोच नहीं किया। उन्होंने पहले 1893 में और फिर 1896 में ब्रिटन के श्रमिक वर्ग से अपील करते हुए यह अभियोग लगाया कि उच्च वर्ग के थोड़े से लोग ही हैं जो इस समय भारत से सभी प्रकार के लाभ उठा रहे हैं जबकि दूसरी ओर यदि निकासी समाप्त कर दी जाए तो भारत ब्रिटिश के सामान एक इतनी बड़ी भारी मण्डी बन जाएगा कि ब्रिटन को अपने श्रमिकों की बकारी का शब्द ही नहीं सुनना पड़ेगा।<sup>114</sup>

निकासी में कटौती कैसे की जा सकती है? इस सबंध में राष्ट्रवादियों का उत्तर बड़ा ही सीधा सादा था। निकासी के कारणों का हटा दीजिए। निकासी के कारणों की पहले ही विस्तृत समीक्षा की जा चुकी है अतः राष्ट्रवादियों द्वारा सुझाए गए उपायों के विस्तृत विवेचन की कोई आवश्यकता नहीं। हम यहां केवल राष्ट्रवादियों द्वारा सुझाए गए उपचारों का मात्र उल्लेख ही करेंगे।

इन उपचारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था नगर तथा सैनिक सेवाओं का भारतीयकरण और इसके फलस्वरूप इन सेवाओं में यूरोपीय तत्वों की समुचित परिमाण में कटौती।<sup>115</sup> इस सबंध में यहां यह उल्लेखनीय है कि जैसा कि हम पहले दिखा चुके हैं दादा भाई नौरोजी ने प्रायः ही सकीण आधार देते हुए यह सुझाव दिया कि भारतीयकरण की इस राग की एकमात्र औषधि है। इसमें निकासी सिद्धांत एक प्रकार के फूहड़ और

उपहासाम्पद बनकर रह गया। यह स्थिति उस समय और भी अधिक विवृत रूप धारण कर गई जब उन्होंने यह धारणा प्रकट की कि असनिक सेवाओं की एक साथ इंग्लड और भारत में परीक्षा तथा अप्रतिश्रुत और गौण सेवाओं की 'यायोचित प्रतियोगिता दस का मपन बनाने की पर्याप्त आवश्यक शर्तें हैं।<sup>116</sup>

द्वितीय, भारतीय नेताओं ने गृहप्रभारों में कटौती की मांग की।<sup>117</sup> इस पग की कालत कभी कभी तो निकासी से इसे सबधित किए बिना ही की गई। गृह प्रभारों को अनेक रूपों में घटाया जा सकता है। भारतीय नेताओं में सर्वाधिक लोकप्रिय उपाय था ब्रिटेन द्वारा इस भार के एक बड़े भाग को वहन करने में भागीदार बनना।<sup>118</sup> कुछ एक नेताओं ने यह सुझाव भी दिया कि इंग्लड में लिए गए सरकारी ऋणों पर भारत द्वारा देय ब्याज के भुगतान के और स्वयं सरकारी ऋणों के भार को हटाकर<sup>119</sup> इन ऋणों के लिए गृही प्रतिभूति जुटा करके ब्याज की दर में कटौती करके<sup>120</sup> सरकारी ऋण इंग्लड में लेने के बड़े भार में ही लेकर<sup>121</sup> रेलपथ निर्माण की गति का कम करत हुए रेलवे ऋणों के भार को कम करके,<sup>122</sup> भारत के सरकारी भंडारों के लिए स्वयं सरकारी भंडारों के लिए स्वयं भारत में ही सामान की खरीदारी करके,<sup>123</sup> अनावश्यक आयात का रोकने के लिए भारतीय उद्योग को उन्नत करके<sup>124</sup> निजी विदेशी पूँजी के बहत जायात के प्रवाह को रोककर<sup>125</sup> गृह प्रभारों का घटाया जा सकता है। भारतीय नेताओं द्वारा निकासी को रोकने के लिए सुझाया गया महत्वपूर्ण उपचार था—इंग्लड और भारत में गृह प्रभारों का 'यायोचित विभाजन।<sup>126</sup>

निकासी सिद्धांत में विश्वास न रखने वाले कुछ भारतीय

यह एक व्यापक मायना है कि भारतीय राष्ट्रवादियों में एक ऐसा वर्ग भी विद्यमान था जो निकासी सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता था। इस वर्ग का नेतृत्व रानाडे के हाथ में था और वे निकासी के रूप में प्रसिद्ध धन के निर्यात को भारत की दरिद्रता के लिए उत्तरदायी कारण नहीं मानते थे।<sup>127</sup> इस धारणा का आधार, 1890 में पूना में प्रथम उद्योग सम्मेलन में उनके द्वारा दिए गए उद्घाटन भाषण के लिखित रूप का एक अवतरण है। इस भाषण में रानाडे ने घोषणा की थी कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यह साचत हैं कि जब तक हम इंग्लड को ऊँचे खिगज देने को विवश रहना पड़ेगा, जिसका जय लगभग 20 करोड़ रुपये के अधिशेष निर्यात से हाथ घोना है तब तक हम पतन के गत में गिर पड़े रहेंगे और किसी प्रकार भी अपना उद्धार आप नहीं कर सकेंगे। यह न ता किन्ना रूप में उपयुक्त है और न ही यह वीराचित स्थिति है। उद्दान निर्देश किया कि इस निरामी का एक भाग तो भारत में निवेगित अथवा भारत के लिए ऋण में ली गई विदेशी पूँजी पर ब्याज की राशि है और हमें इस विषय में शिकायत करने के बने घयवाद करना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा ऋणदाता है, जो ब्याज की इतनी नीची दर पर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। एक अन्य भाग भारत का सभरण किए गए भंडारों का मूल्य की राशि का है जिस भंडार के अनुरूप सामान का हम भारत में उत्पादन नहीं करते। अवशिष्ट भाग प्रशासन और सना पर व्यया का तथा पेंना का भुगतान का है।



यद्यपि इस अवधि में अवश्य शिकायत की जा सकती है कि यह सारा आवश्यक खर्च नहीं है। रानाडे ने अपने श्रोताओं को सलाह दी कि वे खिराज के प्रश्न के निरर्थक विवाद में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग अथवा अपव्यय न करें। उन्हें इस प्रश्न को राजनीतिज्ञों पर ही छोड़ देना चाहिए।<sup>13</sup>

हमारे विचार में यह अवतरण सचमुच यह सिद्ध नहीं करता कि रानाडे इस बात में विश्वास नहीं करते थे कि भारत से संपत्ति की निर्याती ढा रही है अथवा यह आर्थिक दृष्टि में हानिकारक है। जैसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है, रानाडे 1872 के प्रारंभ में निकासी मित्रता का भारत में प्रचार करने वाले प्रथम व्यक्ति थे और औद्योगिक सम्मेलन में दिए गए उनके इस भाषण के मुश्किल में ही दो वर्षों के उपरांत 'भारतीय राजनीतिक आर्थिकता' विषय पर दिए गए इसमें भी अधिक महत्वपूर्ण भाषण में भारत से संपत्ति और प्रतिभा की निकासी के लिए उत्तरदायी विदेशी शासन की निंदा की।<sup>14</sup> इसके अतिरिक्त ऊपर उद्धृत अवतरण में भी उन्होंने भारतीयों को आधुनिक उद्योगों की वृद्धि के लिए प्रात्साहित करने के उद्देश्य विशेष से बुलाए गए औद्योगिक सम्मेलन का विरोध निकासी के प्रश्न का उठान के आधार पर किया न कि राजनीतिज्ञों का इस प्रश्न पर विचार न करने की सलाह दी। वस्तुतः 1881 में पूना सावजनिक सभा में जिसके अन्तर्गत और सर्वोच्च उस समय रानाडे ही थे, कुछ विषय प्रस्तुत किए जिन पर भारतीय विशेष रूप से ध्यान दे और इन विषयों में एक विषय था—आयातों की अपेक्षा निर्यातों की अधिकता के माध्यम से निकासी का प्रश्न तथा उस निर्यातों को रोकने के उपाय।<sup>15</sup> इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, जिसके पूर्व के पीछे रानाडे महत्वपूर्ण और अग्रणी नेता थे और जिन्होंने प्रस्तावों के प्रारंभ तैयार करने में उनकी भूमिका विशेष महत्वपूर्ण थी, घोषणा की कि निकासी भारत की दरिद्रता का महत्वपूर्ण कारण है।<sup>16</sup> इन बातों में भी प्रचंड और अधिक महत्वपूर्ण प्रमाणस्वरूप तथ्य यह है कि आर्थिक मामलों में उनके दोना निवृत्त सहयोगी और शिष्य—जी० बी० जागी और जी० क० गोखले ने इस दृष्टिकोण की पुष्टि की कि निकासी न औद्योगिक विकास को प्रतिबन्धित किया है और देश की जनता को दरिद्र बनाया है।<sup>17</sup> हा, यह कहना तो अवश्य ही गलत होगा कि जागी और गोखले के विचार रानाडे के विचारों पर लुप्त अनुमान गलत नहीं होगा कि जागी ने इस विचार का समर्थन नहीं किया होगा, जो उनके गुरु के मित्रता के मूल रूप में ही विरुद्ध था।

इस कथा में इतना जहर मलय है कि रानाडे तथा मित्र ही और भारतीय निकासी सिद्धान्त के विरुद्ध थे। रानाडे जागी और गोखले और भारतीय नताजा में कदाचित् बहुत सार अर्थ निकासी मित्रता को भारतीय राजनीति का अथवा राष्ट्रवादी प्रचार और आन्दोलन का प्रधान विषय नहीं बनाना चाहते थे। इसके अनिश्चित के इस प्रश्न का कुछ समय के लिए आशा में आश्रित भी करना चाहते थे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है जमा कि हम पहले दिखा चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और भारतीय नताजा का बहुमत, वास्तव में दानाभाद नोरोजी 'अमल बाजार पत्रिका' और कुछ अन्य लोगों को छोड़कर लगभग सभी भारतीय नताजा के विचार में देश को दरिद्रता के गढ़ में

धकेलने वाले मुख्य कारणों में निकासी भी केवल एक कारण ही था।

### निकासी सिद्धांत के आलोचक

राष्ट्रवादी नेताओं की आर्थिक नीतियों के वैज्ञानिक दृष्टि में खरेपन का निणय देना तथा उनकी नीतियों का विश्लेषण करने के लिए तथा उन्हें सही सिद्ध करने के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों की समीक्षा करना कदाचित् हमारे ग्रंथ के लिए उपयुक्त नहीं होगा। निकासी के राष्ट्रवादी विरोधियों के सबब में भी हमारा यही मत है। परन्तु इसके साथ ही निकासी सिद्धांत पर भारत में सरकारी और गैरसरकारी प्रवक्ताओं द्वारा सलाहकारों द्वारा तथा भारत में ब्रिटिश राज्य के रक्षकों द्वारा 1880-1905 की अवधि में और उसके उपरांत जिस उग्रता के साथ प्रहार किए गए, उसका उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है। इसके अतिरिक्त सरकारी पक्ष के अर्थशास्त्रियों और लेखकों की यह भी कल्पना थी कि राष्ट्रवादियों द्वारा निकासी पर किया जा रहा प्रहार उनकी पूर्ण मूल्यता और राष्ट्रवादी उतावला के पूर्वाग्रह से नहीं तो उनकी आर्थिक अज्ञानता और मर्यादित आर्थिक प्रश्नों की उपयुक्त जानकारी के अभाव में अवश्य उत्पन्न हुआ। इस मद्देन में हम निकासी सिद्धांत पर ब्रिटिश प्रहार के प्रमुख तर्कों और राष्ट्रवादियों द्वारा दिए गए उत्तरों की समीक्षा करेंगे, जिनमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि निकासी के राष्ट्रवादी आलोचक आर्थिक वास्तविकताओं से अनभिज्ञ नहीं थे। उन्होंने अपने विरुद्ध वाद में लगाए जाने वाले आरोपों को पढ़ने से ही भाप लिया था कि कदाचित् यह कहा जा सकता है कि उनमें समीक्षकों ने इस विषय के प्रति पूर्ण गंभीरता नहीं ली और न ही किसी सूक्ष्म चिंतन का परिचय दिया। वे अपने निकासीवाद के स्वरूप निर्धारण में भते ही सही रहें हैं। अथवा गलत, परन्तु इतना निश्चित है कि आर्थिक मामलों में वे अनाड़ी नहीं और निकासी के प्रति उनका दृष्टिकोण देश की स्थिति के विस्तृत, पूर्ण और अतः सवधित तथा समन्वित आर्थिक विश्लेषण का ही एक अंग था। निकासी सिद्धांत का तुरंत ब्रिटिश द्वारा खडन थियोडोर मोरिसन के प्रत्युत्तर पर ग्रंथ, 'दी इकोनामिक ट्रांजिशन इन इंडिया' में किया गया। यह ग्रंथ 1911 में प्रकाशित हुआ और कदाचित् यह सर्वाधिक विस्तृत और आलोचकों के दृष्टिकोण का सर्वोत्तम विश्लेषण था।<sup>123</sup> आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास में एल० सी० ए० नोल्म और वीरा एस्टे ने निकासी सिद्धांत की मोरिसन द्वारा आलोचना की व्यापक रूपरेखा को ही ग्रहण किया।<sup>124</sup> यह एक पर्याप्त रोचक तथ्य है कि निकासीवाद के समर्थक और विरोधी एक बात पर पूर्ण रूप से सहमत थे कि भारत को अपने निर्यातों के भाग के बन्ने कुछ आर्थिक तुल्य मूल्य की प्राप्ति नहीं होती। उसी प्रकार जान स्टैची ने 1878 के वित्तीय विवरण में टिप्पणी की कि इंग्लैंड के माध्य भारत के सबब और उस सबब के वित्तीय परिणाम भारत को प्रतिवर्ष लगभग 200 लाख पाँड का उत्पादन बदले में बिना किसी प्रकार के प्रत्यक्ष रूप से व्यापारिक दृष्टि में मुख्य मूल्य की सामग्री के प्राप्त किए ही यूरोप को भोजन को विवश होना पड़ता है। आयातों पर निर्यातों की इस अधिकता को ही अर्थशास्त्री अपनी भाषा में विराज का नाम देते हैं।<sup>125</sup> और मोरिसन ने 'निकासी का इस प्रकार परिभाषित किया कि भारत में सामग्री अथवा

धन व निर्यातों की वह धनराशि जिसके बदले भारत को उस वष उस धन राशि के तुल्य मूल्य का किसी प्रकार का सामान प्राप्त नहीं हुआ निर्याती है।<sup>136</sup> इस प्रकार निकासीवाद के आलोचकों और समर्थकों के मध्य मतभेद का आधार एकतरफा निर्यात अधिशेष के नहीं आर्थिक शब्दाथ उद्गम और परिणाम के संघर्ष में अपनी अपनी समझ है। निकासी सिद्धांत पर प्रहार का रूप इस प्रकार था —

प्रथम, यह कहा गया कि भारतीय आवश्यक वस्तुतया का हिसाब न करके प्रायः निर्याती को बढ़ा चढ़ाकर पेश करत हैं। वे इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं देते कि निर्यात अधिशेष का एक भाग तो अदृश्य आयातों, जैसे कि जहाजरानी सेवाएँ, आयातों और निर्यातों पर लगने वाला बीमा शुल्क तथा भारतीय छात्रों और पर्यटकों द्वारा विदेशों में किए गए खर्चों आदि के खाते में चला जाता है।<sup>137</sup> पूँजी खाते के बाय व्यापार भी आयातों और निर्यातों को सापेक्ष महत्त्व देने की झूठी प्रवृत्ति लिए हुए हैं क्योंकि पूँजी के आयात वास्तविक निर्यात अधिशेष का घटा देते हैं और पूँजी के बायभी भुगतान इन्हें अतिरिक्त रूप दे देते हैं।<sup>138</sup> अन्तिम, निर्यात अधिशेष की गणना करने समय सोन और चाँदी के भारी आयातों की भी गिनती करनी चाहिए।<sup>139</sup> मारिगन ने गणना की कि वार्षिक निकासी—जिसका अर्थ उसके अनुसार सोने और चाँदी के साथ व्यापार तथा पूँजी के आयातों को मिलाकर विस्तृत निर्यात अवशेष था—की राशि 210 लाख पाँट थी।<sup>140</sup>

द्वितीय, आलोचकों का रुथन था कि भारत अतिरिक्त निर्यातों के बन्ने पर्याप्त आर्थिक तुल्य मूल्य की सामग्री प्राप्त करता है। निकासी का सबसे बड़ा भाग ऋण लिए हुए धन पर व्याज की राशि का था ये ऋण भारत के आर्थिक विनाश और मरणात्मकता के सूचक थे न कि दरिद्रता के। विदेशी पूँजी की सहायता से रत्ना का निर्माण किया गया है, मिर्चाई का विकसित किया गया है तथा बागान और दूसरे औद्योगिक साहस के कार्य प्रारंभ तथा विरामित किए गए हैं जिनसे भारत लाभ अर्जित कर रहा है। इस लाभ का ही एक छोटा सा भाग व्याज के रूप में देश के बाहर भेजा जाता है। इसके साथ साथ इन लाभों के अर्जन से अतिरिक्त यह उद्योग प्रत्यक्ष जयवा परीक्षा रूप में देश की राष्ट्रीय जायम बँडि करत हैं। यदि सारा लाभ ही देश से बाहर भेज दिए जाते तो भी विराए और धन का राशि का भुगतान तो इस देश को ही प्राप्त होगा।<sup>141</sup> अब भारतीयों को अपने पूँजीगत साधनों की कमी का पूरा करने के लिए विदेशी निवेशकों का आभारी होना चाहिए।<sup>142</sup> भारत का प्राप्त लाभों को और अधिक बढ़ा चढ़ा कर इस प्रकार चित्रित किया गया कि भारत का रण्ड के साथ राजनितिक संबंधों का यह लाभ होना है कि रण्ड उम बिरद्व की तबल सस्ती बाजार में ऋण तंत्र की सुविधा जुटाना है। यदि भारत में निवेश के लिए पर्याप्त पूँजी के उपलब्ध होना की कल्पना कर भी ली जाए तो उम ऋण रूप में वेना अपेक्षाकृत अधिक महंगा पड़ेगा।<sup>143</sup> मारिगन ने घोषणा की कि वास्तव में भारत का सरकारी ऋण जिस प्रकार मन्त्री दर पर मिलत हैं, उमसे तो राजनीतिक निर्याती<sup>144</sup> की बात स्वतः ही जानी है और निर्यात रूप में यह कहना ही पड़ना है कि भारत प्रिंटिंग राज्य में अपने संघर्षों के कारण आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहा है।<sup>145</sup> इस संघर्ष में भारत की स्थिति की तुलना—यू० एम० ए०, रूस आस्ट्रिया, और जापान जस जयाम देना



थे—इंग्लड अथवा भारत म की गई सेवाआ का मुगतान, जहाजरानी, बीमा और बक प्रभाग । भारतीय ने इन सेवाआ पर विचार ही नहीं किया प्रत्युत इह प्राय ही अपनी शिकायत का प्रमुख आधार भी बनाया । बक, बीमा व्यापार और भारत के भीतर ही नटवर्ती जहाजरानी स्पष्टतया भारत में विदेशी व्यापार और उद्यम क ही अग वे और भारत में विदेशी पूजी के निवेश के इन लाभ को राष्ट्रवादियों ने अपनी जाच पडतात का विषय बनाया था । जहा तत्र आलोचको के इस बयन का सप्रथ था कि निर्याता की अधिकता का एक भाग तो आयाता और निर्यातो पर होने वाले जहाजी खर्च और बीमा की देनदारी का रूप था, दादा भाई ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया परंतु माय ही यह निर्देश किया कि निर्याता और आयाता के मूल्य की समणना करने का सरकारी ढग यह था कि निर्यातो की वतमान अधिकता के ही अतगत पहले से ही इन किराया आदि का विधान किया जा चुका है । यह कमे हुआ—इसका विश्लेषण उहोने निम्नलिखित ढग से किया—भारतीय आयातो का मूल्य सरकारी खातो में भारतीय पत्तना पर प्रचलित मूल्य के रूप में ही आता गया अत उस मूल्य में तो भाडे का व्यय और बीमा की दत्तारी स्वत सम्मिलित हो गए और दूसरी ओर निर्यातो का मूल्य भारतीय पत्तना पर प्रचलित मूल्य के रूप में ही बूना गया, अत उनम भाडे और बीमा का व्यय—जो उसके मूल्य में सम्मिलित किया जाता था और जिमका मुगतान आयात के पत्तन पर किया जाना था—का अलग रखा गया । अत उनके द्वारा सगणित निकासी इस विशिष्ट वप्रता में मुक्त थी ।<sup>1</sup> सत्य तो यह है कि वे इसके भी आगे बढ गए तथा उहोने अपना मत प्रकट किया कि यदि निर्यातो के मूल्य में मालभाटे और बीमे की रकम को जाड दिया जाए तो निकासी अपनी सगणना में भी अधिक बढे के रूप में सामन आएगी ।<sup>155</sup> आलोचका के इस प्रमुख तर्क का कि निकासी का वास्तविक सबध तो पूजीगत सेवाआ तथा व्यक्तिगत सेवाआ के मुगतान से है, राष्ट्रवादियों द्वारा दिया गया उत्तर उपयोगिता तथा अनि वायता के मौलिक सुद्ध तथा परिपक्व आधार को लिए हुए था । उनका बयन था कि यदि किसी सेवा विशेष की वास्तव में ही उपयोगिता और आवश्यकता है और उस विश्व में अपना रख करके ही पाया जा सकता है तो इस रूप में तो निकासी को सहन करना अनुचित नहीं कहा जा सकता परंतु इसके सबधा विपरीत यदि सेवा निरर्थक ह अथवा उपयोगी होन पर भी स्वयं भारत में उपलब्ध की जा सकती है तो उम पर अपना रख करन के रूप में निकासी अवश्यमेव आपत्तिजनक है ।

इस धारणा का कि निकासी के प्रमुख भाग का सबध उत्पादक सरकारी क्रणा पर व्याज और निजी विद्वंती पूजीपति उद्यमियों के लाभों में ही भारत के आर्थिक विकास और संपन्नता के सूत्र है राष्ट्रवादियों ने कई तरह से उत्तर दिया । उहाने निर्देश किया कि अर्धवत् तो विदेशी पूजी आवश्यक ही नहीं थी । इसका जाब दायता तो तब पनी है जबकि दश के शायद इस दश की पूजी की निकासी करत रह है आर कर रह है । इस निकासी के न हान पर तो भारत रतपथ आदि के लिए मंत्र ही पूजी जुटा पाना और साधारणतया अपनी पूजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करन में वास्तव में ही मग्य हाता । अत विदेशी पूजी न भारतीय पूजी का स्थान ग्रहण किया

है उसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की। यदि विदेशी पूजा का देशी पूजा की वृद्धि में वास्तविक योगदान रहता तो उसका श्रवण स्वगत किया जाता। इसके अतिरिक्त भारत में आयातित पूजा वास्तव में भारत की अपनी ही पहले निर्यात की गई पूजा थी। जत भारत में वास्तविक रूप में विदेशी पूजा का निवेश किया ही नहीं गया है।<sup>156</sup>

दूसरे भारतीय नेताओं का यह निश्चित मत था कि विदेशी पूजा वास्तव में उत्तनी लाभकारी कदापि नहीं थी जितना इसने समर्थक कहते थे। रेलों की वृद्धि बरदान नहीं है और उह देश की आवश्यकता से अधिक तीव्र गति से आगे धकेला जा रहा है।<sup>157</sup> रेलों के निर्माण के लिए उठाए गए सरकारी ऋण स्पष्टतया न तो लाभप्रद है और न ही आवश्यक। निजी विदेशी पूजा केवल व्याज को ही इस देश में बाहर नहीं खींच ल जाती प्रत्युत उद्यम के सभी प्रकार के लाभ भी हट्टप जाती है और इसमें देश पूजा के पुनर्निवेश के गौण लाभों से भी वंचित रह जाता है।<sup>158</sup> इसके अतिरिक्त रेलगाड़ियों में 19वीं शताब्दी के अंत तक किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिखाया।<sup>159</sup> वेतन आदि के रूप में देश को कुछ लाभ अवश्य हुआ परंतु इन वेतनों का भी एक अंश विदेशियों को प्राप्त हुआ और यह भी निवासी का ही एक रूप है।<sup>160</sup> इससे भी बढकर उल्लेखनीय सत्य यह है कि विदेशी उद्यमों में काय की शोचनीय स्थिति का आर पारिश्रमिक के रूप में मिलने वाली रकम की तुच्छता को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि इनसे भारत को होने वाला लाभ मामूली ही है।<sup>161</sup>

भारतीय नेताओं ने और अधिक तक प्रस्तुत किए। उनका कथन था कि औद्योगिक क्षेत्र में एकाधिकार जमाने की प्रवृत्ति के कारण विदेशी पूजा स्वदेशी पूजा के उपयोगी विनियोजन का निरुत्साहित और वंचित कर रही थी, उसके माग में बाधा बन रही थी इस रूप में वह देश के लिए हानिकारक थी।<sup>162</sup> जोर कुल मिलाकर विदेशी पूजा का उद्देश्य भारत को विकसित और संपन्न बनाना नहीं था प्रत्युत उसका दोहन, शोषण और अपहरण करना था।<sup>163</sup>

इस प्रकार इस धारणा का कि भारत को सस्ते व्याज की दर पर ऋण उपलब्ध होने से उसे लाभ पहुंचता है उत्तर यह था कि अतः तो ऋणों की सवधा ही कोई आवश्यकता नहीं। दूसरे, उनका उपयुक्त ढंग से प्रयोग ही नहीं किया जाता। वस्तुतः वे ऋण कुछ और न होकर भारत से निष्कामित भारत की ही पूजा थे अतः उनकी सस्ती दर पर उपलब्धि का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके अलावा यदि ऊंची दर पर ही सही देश में देशवासियों से ही ऋण लिया जाता तो भुगतान देग में रहता और देश के साधनों को फलीभूत बनाता, जबकि नीची दर के विदेशी ऋण विकामी का ही कारण बनते हैं।

भारतीय नेताओं ने भारत की तुलना कुछ समय निर्यात अधिशेष रखने वाले अमेरिका से करने को सवधा अनुचित बताया। इस तथ्य के अलावा कि अमेरिका आम तौर पर ऋण ली गई पूजा पर केवल व्याज का ही भुगतान करता है और उद्यम के मागे लाभ देग के भीतर अपने पाम ही रखता है।<sup>164</sup> भारत के निर्यात अधिशेष जोर अमेरिका के निर्यात अधिशेष के बीच एक अर्थ बहुत बड़ा जोर चानाने वाला अंतर था। अमेरिका इस समय अपने निर्यात अधिशेषों के द्वारा बाहरी देशों के लिए गए ऋणों का भुगतान



है उसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की। यदि विदेशी पूजा का देशी पूजा की वृद्धि में वास्तविक योगदान रहता तो उसका अवश्य स्वागत किया जाता। इसके अतिरिक्त भारत में जायातित पूजा वास्तव में भारत की अपनी ही पहचान निर्यात की गई पूजा थी। अतः भारत में वास्तविक रूप में विदेशी पूजा का निवेश किया ही नहीं गया है।<sup>156</sup>

दूसरे भारतीय नेताओं का यह निश्चित मत था कि विदेशी पूजा वास्तव में उत्तरी लाभकारी कदापि नहीं थी जितना इसने समयक वहत थे। रेलों भी शुद्ध वरदान नहीं हैं और वह देश की आवश्यकता से अधिक तीव्र गति में आगे धकेला जा रहा है।<sup>157</sup> रेलों के निर्माण के लिए उठाए गए सरकारी ऋण स्पष्टतया न तो लाभप्रद हैं और न ही आवश्यक। निजी विदेशी पूजा केवल व्याज को ही इस देश में बाहर नहीं खींच लानी प्रत्युत उद्यम के सभी प्रकार के लाभ भी हड़प जाती है और इसमें देश की पुनर्निवेश के गौण लाभों से भी वंचित रह जाता है।<sup>158</sup> इसके अतिरिक्त रेलगाड़ियाँ न 19वीं शताब्दी के अंत तक किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिखाया।<sup>159</sup> वेतन आदि के रूप में देश को कुछ लाभ अवश्य हुआ परंतु इन वतनों का भी एक अज्ञ विदेशियों को प्राप्त हुआ और यह भी निकासी का ही एक रूप है।<sup>160</sup> इसमें भी वक्तर उल्लेखनीय सत्य यह है कि विदेशी उद्यमों में काय की शांति की स्थिति को आर पारिथमिक के रूप में मिलने वाली रकम की तुच्छता को दखते हुए यही कहा जा सकता है कि इनसे भारत को होने वाला लाभ मामूली ही है।<sup>161</sup>

भारतीय नेताओं ने और अधिक तर्क प्रस्तुत किए। उनका कथन था कि औद्योगिक क्षेत्र में एकाधिकार जमाने की प्रवृत्ति के कारण विदेशी पूजा स्वदेशी पूजा के उपयोगी विनियोजन का निरस्तहित और वंचित कर रही थी, उसके मांग में बाधा बन रही थी, इस रूप में वह देश के लिए हानिकारक थी।<sup>162</sup> और कुल मिलाकर विदेशी पूजा का उद्देश्य भारत को विकसित और संपन्न बनाना नहीं था प्रत्युत उसका दोहन, शोषण और अपहरण करना था।<sup>163</sup>

इस प्रकार इस धारणा का कि भारत का सस्ते व्याज की दर पर ऋण उपलब्ध होने में उस लाभ पहुंचता है, उत्तर यह था कि अब तो ऋणों की सवथा ही कोई आवश्यकता नहीं। दूसरे, उनका उपयुक्त ढंग से प्रयोग ही नहीं किया जाता। वस्तुतः वे ऋण कुछ और न होकर भारत से निष्पासित भारत की ही पूजा थे, जत उनकी मन्ती दर पर उपलब्ध का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके अलावा यदि ऊंची दर पर ही सही दश में दशवासिया में ही ऋण लिया जाता तो भुगतान देश में रहता और देश के साधनों को फलीभूत बनाता जबकि नीची दर के विदेशी ऋण निकासी का ही कारण बनते हैं।

भारतीय नेताओं ने भारत की तुलना कुछ समय नियात अधिशेष रखने वाले अमेरिका में करने को सवथा अनुचित बताया। इस तथ्य के अलावा कि अमेरिका आमतौर पर ऋण ली गई पूजा पर केवल व्याज का ही भुगतान करता है और उद्यम के मार लाभ देश के भीतर अपने पास ही रखता है।<sup>164</sup> भारत ने नियात अधिशेष और अमेरिका का निर्यात अधिशेष के बीच एक अर्थ बहुत बड़ा और चीजान वाला अंतर था। अमेरिका इस समय अपने नियात अधिशेषों के द्वारा बाहरी देशों के लिए गए ऋणों का भुगतान



कर रहा है जिसका अर्थ यह है कि अतीत में यह निर्यात अधिरोप बना देना था। इसके निर्यात अधिरोप हमकी आस्पृशित समूहियों से संबंधित है। परंतु भारत का मामला विलुक्त अलग-थलग था। वह पिछले ऋणों का भुगतान नहीं कर रहा है क्योंकि भारत के निर्यात अधिरोपों की मर्यादा ही केवल तब की जाती है, जब उनमें आयात पूंजी आयातों में सम्मिलित कर दी जाती है। इस प्रकार जहां तक भुगतान चिट्ठे का संबंध है ऋण में ली गई धनराशि का भुगतान तो उसी समय स्वयं निर्यातों के साथ ही कर दिया जाता है। इस प्रकार एक ओर तो भारत के पास अतीत में कोई आयात अधिरोप नहीं था। 1857 के विद्रोह के पश्चात् कुछ एक वर्षों तक ही तो उनका परिमाण तुच्छ था। दूसरी ओर भारत में निर्यात अधिरोपों में भविष्य के लिए हम दूसरे दशक पर निर्यात प्रचार की दायदारी प्रदान नहीं की। इसलिए कालांतर में आयात अधिरोप हमकी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं कर पाएंगे। फलतः भारत का निर्यात अधिरोप एक एकी विविध प्रक्रिया है—जिसकी पूंजी के साथ व्यापार का तात्पर्य कोई अतीत है और जो ही कोई भविष्य। यह तो पदा होत ही हम ताड़ों की ही स्थिति है।<sup>165</sup>

इस सब सबों के साथ-साथ निर्यातों में प्रस्तावित प्रायः ही निर्यातों से संबंधी अपनी मर्यादाओं से उत्पादन मर्यादाओं के लागत मूल्य को शामिल करने पर सहमत था।<sup>166</sup> इस संबंध में यद्यपि यह भी उल्लेखनीय है कि उपयोगिता का आधार मानते हुए इन नताओं ने उद्योग ली गई पूंजी के संपन्न किए गए सिंचाई कार्य के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। इसी प्रकार कुछ एक नताओं ने तो देश के उत्पादन मर्यादाओं के विकास के लिए विदेशों से ऋण लेने का समर्थन किया।<sup>167</sup>

भारतीय नताओं ने एक अर्थ तथ्य की ओर संकेत करते हुए कहा कि भारतीय सरकारी ऋण का एक भाग पूणतया राजनैतिक प्रवृत्ति का हान के कारण निरवयव, अनावश्यक और अपने स्वरूप में अनुत्पादक है तथा इसका बदले में तुल्य मूल्य का कुछ भी प्राप्त नहीं होता है।<sup>168</sup> 1858 में लगभग 690 लाख पौंड तक पहुंचे साधारण सरकारी ऋणों के उदगम की सृष्टि करते हुए भारतीय नता इस परिणाम पर पहुंचे कि इसका अस्तित्व में लाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसने अपने शासन काल में ब्रिटिश द्वारा भारत में जीतने के लिए किए गए युद्धों के खर्चों की पूर्ति के लिए तथा भारत को कंपनी के लाभों का भुगतान करने के लिए इस रोग की मृष्टि की है। इसके साथ इसमें कंपनी द्वारा ताज का भारत में प्रशासन के हस्तांतरण के मूल्य के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों का क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाने वाली धनराशि तथा 1857 के विद्रोह का बुचलन में लंबे की गई धनराशि भी जोड़ दी गई है। इस प्रकार 1858 के बहुत बाद भी भारत विदेशी शक्ति द्वारा विजित होने का मूल्य चुकाता आ रहा है।<sup>169</sup> भारत और इंग्लैंड के अनुचित वित्तीय संबंधों के उदाहरण हैं—1878 के अफगान युद्ध का, मिस्त्री युद्ध का, 1890 के बर्मा युद्ध तथा सोमात युद्ध का स्वयं भारत ने मध्ये महना। ताज द्वारा भारत का प्रशासन सभालने के उपरांत साधारण सरकारी ऋणों का भार उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया।<sup>170</sup> अतः राष्ट्रवादी भारतीय नेताओं की दृष्टि से लगभग 1000 लाख पौंड भारतीय सरकारी ऋण का एक बहुत बड़ा भाग स्पष्टतया व्यापार ऋण नहीं है। इसलिए

नतिक दृष्टि से वह भारत का दायित्व नहीं। इसका व्याज स्पष्टतया धन की निकासी है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दादा भाई कभी कभी ऋण के इस अर्थ के प्रति भी उदारता बरतने की महमत हो जाया करते थे।<sup>171</sup>

जहाँ तक भंडारों का संबंध था वे पहले से ही आयातों में सम्मिलित थे<sup>172</sup> और इसके अतिरिक्त वे निकासी प्रकृति के ही थे, क्योंकि मूलतः वे इस रूप में अनावश्यक थे क्योंकि उनका उत्पादन देश में किया जा सकता था<sup>173</sup> परंतु फिर भी इन भंडारों के भुगतान के प्रति भारतीयों का दृष्टिकोण उदार था।<sup>174</sup>

निकासी के विरोधी भारतीय नता निकासी के जिस एक भाग को किसी भी स्थिति में धमा करने के लिए सवथा तैयार नहीं था, वह था भारत सरकार द्वारा यूरोपीय कम-चारियों पर किया जाने वाला व्यय। उनके विचार में सवाजों के लिए किया जाने वाला भुगतान निकासी की जड़ था। स्पष्ट है कि भारत का निकासी के इस भाग के बदले में तुल्य मूल्य का कुछ भी तो प्राप्त नहीं होना। दूसरी ओर भारतीय नता यह मानने का तैयार नहीं थे कि गैर आर्थिक सेवाओं के द्वारा इस मद की निकासी की क्षति पूर्ति हो जाती है।<sup>175</sup> वस्तुतः ये सेवाएँ आवश्यक ही नहीं थीं। सत्य तो यह है कि देश को इन सेवाओं की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि स्वयं भारतीयों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक योग्यता और अधिक सस्तेपन के साथ ये सेवाएँ की जा सकती हैं।<sup>176</sup> जत इन सेवाओं के लिए किया जाने वाला भुगतान अनिवाय रूप से थोपा गया है और वास्तव में निकासी का ही एक निश्चित रूप है। यह भी एक राक्षक तथ्य है कि भारतीय नताओं ने भारतीय कारखानों में विदेशी तकनीकशास्त्र की नियुक्ति<sup>177</sup> पर कोई आपत्ति नहीं ली अथवा भारतीय विश्वविद्यालयों में योग्य अध्यापकों की नियुक्ति का भी विरोध नहीं किया।<sup>178</sup> इन नेताओं ने विदेशों में भारतीय छात्रों की शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि के लिए सन्निय मधुप किया।<sup>179</sup> इन दानों में होने वाली निकासी को आवश्यक और उपयोगी माना गया। दूसरे, राष्ट्रवादियों का कथन था कि भारत सरकार द्वारा सैनिक और अनैतिक प्रशासन पर किए जाने वाले व्यय का एक बहुत बड़ा भाग भारत के हित को दृष्टि में रखकर नहीं किया जा रहा था प्रत्युत इसका उद्देश्य ब्रिटिश और उसके नागरिकों के हितों को सुरक्षित करना था।<sup>180</sup> जत कानून और व्यवस्था के नाम पर भी किया गया व्यय स्पष्ट रूप से धन की निकासी था। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौराजी न सरकारी अधिकारियों को भारत की सुरक्षा के दावे को चुनौती देते हुए प्रश्न किया कि भारत समुचित रूप से सुरक्षित कहा है जबकि स्वयं अंग्रेजों को इस लूटन की सुनी छूट मिली हुई है।<sup>181</sup>

कुछ एक भारतीय नेताओं ने यह भी टिप्पणी की कि यूरोपीय कमचारियों को दिए जाने वाले भुगतान को गैर आर्थिक पहलू से कितना ही योग्यसंगत सिद्ध करने का प्रयास क्या न किया जाए, आर्थिक दृष्टि से तो वह निश्चित रूप से ही धन की निकासी था।<sup>182</sup> दादा भाई न इस संबंध में व्यंग्य प्रहार करते हुए ब्रिटिश जनता से प्रश्न किया कि क्या वे उपयोगी सवा कं तक पर अपन प्रशासन के उच्च पदों पर और प्रमुख स्थानों पर फ्रांसीसी युवकों जैसे विदेशियों को आरूढ़ होने की अनुमति देंगे? <sup>183</sup> उन्होंने इन बातों का भी

लिये अपन पत्र में उन्होंने बार बार और जोर देते हुए लिखा हमारे लिए निवासी एक व्यापारिक मामला नहीं है। यह विन्नी मत्ता द्वारा भारत में स्थापना के सचों के अस्वाभाविक प्रशासन और अस्वाभाविक प्रवृत्तियों का परिणाम है।<sup>197</sup> उन्होंने दृढ़तापूर्वक लिखा कि जहाँ तक इंग्लैंड में प्रभारों की देयता का संबंध है, वहाँ भारत की स्थिति भी प्रकार की सहमति के बिना, अत्याचार के द्वारा बलपूर्वक ही लिए जा रहे हैं।<sup>198</sup> इस प्रश्न के समग्र राजनीति पक्ष में उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। और उन्होंने लिखा कि लाइव बवाल न ठीक ही फरमाया है कि कंधा पर रखे जाने सभी प्रकार के जुआ में अजनबियों का जुआ सवाधिक भारी होता है।<sup>199</sup> बाद में 1897 में विलबी कमीशन के समक्ष जिरह के दौरान उन्होंने यह टिप्पणी की भारत में ब्रिटिश राज्य का स्वार्थी और अव्यक्त दोष भारत की आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक निवासी है। इसे समुद्र पार के विन्नी गमन में पृथक् किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि यह प्रशासन इस मुद्दे सिद्धांत पर विश्वास ही नहीं रखता कि भारतीयों को अपन देश की सेवा में समुचित भाग और उनके अपन ही सचों में उन्हें कुछ कहने का अधिकार मिलना चाहिए। इस टिप्पणी के साथ उन्होंने बड़ी ही गुस्से भाषा में निवासी के राजनीतिक कारणों की ओर इंगारा किया।<sup>200</sup> निवासी सिद्धांत के अध्ययन में निबलन करने निष्कर्षों में भारत में ब्रिटिश राज्य का स्वरूप व प्रयोजनों के विषय में दादा भाई के विचार व दृष्टिकोण को धीरे धीरे गहरा कर दिया। अब निवासी पर विचार करते समय सामान्य रूप से ब्रिटिश राज्य को देखी परदान बतलाने वाले दादा भाई एक दूसरी भाषा में ही बोलने लगे। धीरे धीरे और लगभग अपनी इच्छाओं के विरुद्ध व यह अनुभव ही नहीं करने लग पत्थर सावजनिक रूप से घोषित करने लग कि ब्रिटिश राज्य को उपयोगी दयानु और लोभितकारी मानना मात्र एक भ्रम था। जैसाकि इसी अध्याय के प्रारंभिक भाग में हम निर्देश कर चुके हैं दादा भाई के अनुसार, भारत में औद्योगिक विकास के अभाव का और भारतीयों की दरिद्रता का सारे का सारा ही दायित्व निवासी पर है और यह निवासी शासन की दूषित नीति का ही परिणाम है। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि निवासी को समझ रखकर सोचने पर ब्रिटिश राज्य के अर्थ बलिपत लाभ, याय और व्यवस्था, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा विदेशी आक्रमण में बचाव तथा अवाल से बचाव की भारतीय जनता के लिए कोई उपयोगिता थी। 1880 में उन्होंने अवाल से बचाव के लिए उठाए गए पणों पर अपना मत प्रकट करते हुए कहा भारत के शासक अपने लिए इस संबंध में किसी प्रकार का श्रेय लेने का कोई दावा नहीं कर सकते क्योंकि वस्तुतः इन अवाल के लिए वे ही प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। वे ही तो भारत की संपदा की निवासी कर रहे हैं जो परिणाम में भारतीयों के द्वार पर दुर्भाग्य भुलमरी और ताखा मौतें लाती है।<sup>201</sup> न ही भारत ब्रिटिश शासन द्वारा बाहरी आक्रमण के विरुद्ध जुटाई गई सुरक्षा से किसी भी प्रकार से लाभान्वित होता है, क्योंकि अंग्रेज लोग भारत के प्रवेश द्वार पर तो सतरी बनकर खड़े हैं और सारे विश्व को चुनौती देते हैं कि वे भारत की सभी बाहरी आक्रमणकारियों से रक्षा कर रहे हैं और करेंगे परंतु जिस खजाने की रक्षा का वे दम भरते हैं और दरवाजे में उसी खजाने को चुपचाप ले जा रहे

हैं।<sup>19</sup> स्थिति की वास्तविकता यह है कि देश की रक्षा करना तो दूर रहा, अंग्रेजी शासन तो विदेशी आक्रमण को स्थाई रूप दे रहा है उसे बढ़ा रहा है, दिन प्रतिदिन उसकी सभावना में वृद्धि कर रहा है। इसके साथ ही अंग्रेजी शासन देश को समग्रतः परतु धीरे धीरे विनाश के गड्ढे में धकेल रहा है।<sup>193</sup> वस्तुतः अंग्रेज निवृत्ततम आक्रमणकारी था और भारत को इससे बुरे दुर्भाग्य का सामना कभी नहीं करना पड़ा।<sup>194</sup> जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लाभा के संबन्ध में दादा भाई ने निम्नलिखित टिप्पणी की

यह एक मिथ्या धारणा है कि भारत में देशवासियों को जीवन और संपत्ति की सुरक्षा प्राप्त है। वास्तविकता यह है कि सुरक्षा नाम की कोई वस्तु ही नहीं। एक रूप में जीवन और संपत्ति की सुरक्षा उपलब्ध है और वह इस प्रकार में है कि लोग किसी प्रकार की हिंसा से, आपसी मार पीट से तथा देशी निरकुश शासकों के भय से सुरक्षित हैं। यह जीवन और संपत्ति की निस्मदेह वास्तविक सुरक्षा है और भारत इसके लिए कृतज्ञता प्रकट करने से इनकार नहीं करता, परतु इंग्लैंड के स्वयं अपने पजे से उसे संपत्ति की किसी प्रकार की सुरक्षा संवधा ही प्राप्त नहीं है। पलत जीवन की सुरक्षा भी प्राप्त नहीं। भारत की संपत्ति सुरक्षित नहीं। जा सुरक्षित और पूणत सुरक्षित है, वह है, इंग्लैंड, वह पूण रूप से और समग्र रूप से रक्षित और सुरक्षित है तथा वह अपनी यह सुरक्षा बनाए रखना चाहता है ताकि वह वर्तमान दर पर 30,000,000 से 40,000,000 पौंड की संपत्ति प्रतिवर्ष भारत से ले जा सके और इसे हजम कर सके। इसलिए मैं यह कहने का साहस कर सकता हूँ कि भारत को संपत्ति और जीवन की सुरक्षा प्राप्त नहीं है। इतना ही नहीं, उस तो ज्ञान और बुद्धि की सुरक्षा भी प्राप्त नहीं है। भारत में ताबा करोडों लोगों के लिए तो जीवन का केवल यही अर्थ है आधे पेट खाना नमीब होना, अथवा भूखी मरना अथवा दुर्भिक्ष का सामना करना अथवा रोगों से जूझना।<sup>195</sup>

बानून और व्यवस्था के संबन्ध में 1876 में दादा भाई ने लिखा

एक भारतीय कहावत है कि 'किसी की पीठ पर भले ही लात मारी परतु किसी के पेट पर कभी लात नहीं मारनी चाहिए। देशी निरकुश शासन में लागू अपन उत्पादना को सुरक्षित रख सकते थे और उनका उपभाग कर सकते थे। यह दूसरी बात है कि इसके पीछे उन्हें कभी कभी हिंसा का सामना भी करना पड़ता था। ब्रिटिश निरकुश शासन में लोगों को शांति तो प्राप्त है हिंसा का अस्तित्व नहीं है परतु उनका कोष शांतिपूर्वक, अनदेखे रूप से और चालाकी के साथ लूटा जा रहा है। अब भारतीय बानून और व्यवस्था के अतगत शांतिपूर्वक भूखा मरता है और शांतिपूर्वक ही मृत्यु का ग्रास बनता है।<sup>196</sup>

उहोंने इसके साथ आगे कहा मैं नहीं कह सकता कि अंग्रेजों की ऐसी स्थिति के कारण क्या प्रतिक्रिया होगी।

निकासी सिद्धांत में भारत में ब्रिटिश राज्य की प्रवृत्ति और उसके स्वरूप को समझने की दिशा में उन पर गहरा प्रभाव डाला। इस प्रकार उन्होंने अपने निबंध, 'दो पावर्गों आफ इंडिया के लगभग निष्कर्ष के रूप में ही निष्ठा निबामी के कारण नाराही शासन

चक्र एक गन्त, अप्रावृत्ति और आत्मघाती स्थिति में घूम रहा है।<sup>19</sup> 12 फरवरी 1895 को हाऊस ऑफ़ कॉमन्स में लिए गए अपने भाषण में उन्होंने पाषण्डा की निम्नलिखित भारत वास्तव में ब्रिटिश भारत ही था, भारत का भारत नहीं।<sup>20</sup> उन्होंने और आगे रहा एक प्रकार में ता विपुलसम्यक् भारतीयों की स्थिति स्थिति राज्या व तासा की स्थिति में भी रहता है। ताग मानिना की भूमि पर और मानिना के साधना में काम करता है। मालिक उनके क्षेत्र श्रम का ही लाभ उठाते हैं। इसके विपरीत भारतीय अपनी ही धरती पर जीर अपना हा साधना में काम करता है। इनके पर भी उन्हें अपने लाभ विदली मानिना का मोक्ष इन पाते हैं।<sup>21</sup> इसी प्रकार 31 जनवरी 1897 को लार्ड किलग्रेव ने विना अपने एक पत्र में दादा भाई नवराज की, व (ब्रिटिश नागरिक) को मित्र नागरिक कहते हैं उन्हें अपने समकालीन का अव्यवस्थितता का रूप देना चाहिए। इस समय ता मय की वजाय यह एक निरा नूट और नई मजाक है। इस समय ता ताता का ताता दाग और स्वामी का ही है।<sup>22</sup> दादाभाई ने अपने आशय प्रति यह गा कि उपरांत के नाम पर ब्रिटिश न गोपण का यह क्या भ्रमजनक फंता रखा है। 'यह ता शाषण ब्रिटिश राज्य द्वारा इस ढंग से किया जा रहा है कि दान में न किसी प्रकार का स्वातंत्र्य रूप में सामन आता है। किसी प्रकार में जीवन तथा मरणा का धर्म पट्टा नहीं जाती है, जिसमें कि मरणा इस नूट का दल पाए और इस पर काप उठे।'<sup>23</sup> उन्होंने दादा स्वर में कहा, भारतीय लोगों के इस चालू अत्याय और दुभाग्यपूर्ण प्रयागन के अंतगत ब्रिटिश राज्य भारत का उपकारी होना का दाग करता है। मय यह है कि ब्रिटिश राज्य भारत का हित करना ता दूर रहा उसका मून ही चूम रहा है।<sup>24</sup> 1904 तक दादाभाई भारत में ब्रिटिश राज्य के वषण्डा प्रमग में बटु और बठोर गंगा का ही प्रयाग करने योग्य थे। अगस्त 1904 में हुए अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में दिए गए अपने भाषण में दादाभाई ने ब्रिटिश राज्य को 'असम्यक् वतनाया। उनके द्वारा प्रयुक्त वास्तविक गन्त

असम्यक्ता गन्त का क्या अभिप्राय है? क्या इसका अर्थ यह है कि यदि एक शूर व्यक्ति किसी दुबल व्यक्ति की पिटाई करता है और उसे लूट लेता है तो उसका यह दूषित काम असम्यक्ता है? यही बात राष्ट्र पर ही लागू होती है और इसी ढंग का प्रयोग ब्रिटेन भारत के प्रति कर रहा है। इसका अर्थ अवश्य ही हीना चाहिए। पशु शक्ति का साम्राज्य असम्यक्ता ही है।<sup>25</sup>

निकासी सिद्धांत ने एक अन्य रूप में भी दादा भाई के चिंतन का गहरापन दिया। धीरे धीरे उन्होंने राष्ट्रवादियों की इस परंपरागत धारणा पर अविश्वास करना प्रारंभ कर दिया कि भारत में जो कुछ भी गन्त काम हीना है उसका सारा दोष भारत में रहने वाले स्वार्थी और भारतीय अधिकारियों का अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करने का विवश करने वाले अंग्रेज अधिकारियों का है। विनवी कमीशन के समक्ष जिरह में उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की बुरी कार्य प्रवृत्ति का नहीं प्रत्युत सरकार की गंदी पद्धति अथवा मशीनरी को ही निकासी के लिए उत्तरदायी ठहराया। इस प्रकार उन्होंने कहा

मेरा सामान्य प्रहार सरकारी अधिकारियों पर नहीं, प्रत्युत उस बुरी व्यवस्था



ब्रिटिश साम्राज्य को अपनी भारत के अतीत के पागलों के साथ तुलना न करने के लिए सख्तपन किया। उन्होंने घोषणा की कि यदि ब्रिटिश अपने आपका उच्च ज्ञान और श्रेष्ठ गम्यता के अनुपात में पर्याप्त श्रेष्ठ मिश्रण नहीं करते और यदि भारत उनके अधीन व्यापक प्रगति और समृद्धि प्राप्त नहीं करता, तो भारत में उनके टिके रहना मनाई औचित्य नहीं। इसके अतिरिक्त पिछली निवासी को दुभाग्य मानकर भेजे ही भूना किया जाय और क्षमा कर लिया जाए परन्तु एक बार मामला माफ हो जाने पर भविष्य में की जान वाली इस प्रकार की निवासी का ता सीधी मादी भाषा में इकती और विध्वंस ही कहा जाएगा।<sup>9</sup> 1896 में उन्होंने टिप्पणी की कि यद्यपि भारतीयों का अब भी ब्रिटिश ज्ञान के स्वल्प अंत वरण में पचना विद्वान है परन्तु वनमान व्यवस्था का परिणाम भारतीयों का इस निष्पक्ष पर पहुँचा दगा कि भारतीयों के सामान्य अपन वनमान प्रणामका ग पिड छुड़ा के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है।<sup>10</sup> और फिर यदि निवासी जारी रही तो ब्रिटिश शासन भी एक विद्वशी निचोड़न वाली प्रूर शक्ति बना रहेगा जिस के फलस्वरूप जनना यूरोपीय शासना से मुक्त हान को उत्पन्न रहगी।<sup>11</sup> 'असतोप के वारण' पर नाड विन्नी को लिखे अपन पत्र में, ब्रिटिश राज्य के प्रति वफादारी के महान उद्घाषक, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में यह घोषणा करने का महत्त्व किया था कि हम बहादुरी से यह घोषणा करनी चाहिए कि हम पूर्ण रूप में ब्रिटिश राज्य के प्रति वफादार हैं।<sup>12</sup> उसी व्यक्ति ने पूर्वापक्षा अधिव स्पष्ट वाणी में गजना की, क्या किसी भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लिए यह सोचना संभव है कि कोई एक देश दूसरे देश का अपने अधीन कर ले और फिर उनमें वफादारी और स्नेह की भाँगा करे? यह मानना मानव प्रकृति के विरुद्ध है। ऐसा नहीं आज तक कभी हुआ है और नहीं भी होगा।<sup>13</sup> 1900 तक वफादार दादा भाई के मन में वदचित आत रूप से ही राजद्रोह की भावनाएँ घर करने लगी थी। उसी वर्ष उन्होंने शासना को एक और चेतावनी दी, भारतीय आज तक ब्रिटिश द्वारा किए जा रहे शोषण का सहन करते जा रहे हैं और यह विश्वास करना एक भूल ही होगी कि उनकी वफादारी डिंग नहीं सबनी और जिस रूप में आज है उसी रूप में सदा के लिए बनी रहगी।<sup>14</sup> भारतीय लाग अब स्थिति की वास्तविकता को समझ लगे हैं और यदि उनकी दशा को सुधारने के लिए कोई पग न उठाया गया तो हा सक्ता है कि वे शक्ति को नष्ट करने के लिए शक्ति का प्रयोग करने का प्रलोभित हो उठें।<sup>15</sup> यह तो थोड़े समय की ही बात थी, जबकि दादा भाई इस निष्पक्ष पर पहुँचे, यदि निवासी को रोकना है तो भारत को अवश्य ही राजनैतिक दृष्टि से स्वतंत्र होना पड़ेगा। दादा भाई के दिल और दिमाग की ताजगी, जिन्दादिली और वीरता के लिए उनका अभिनंदन ही करना पड़ेगा कि उन्होंने 79 वर्ष की पक्की आयु में जबकि धमनियाँ में रक्त प्रवाह गिथिल पड जाता है ब्रिटिश के भारत पर शासन की अंतिम प्रकृति के संबध में अपने पूर्व विश्वास से हटकर स्व शासन की गुणात्मक छलाग लगाई।<sup>16</sup> 1904 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में, जिसने भारत के राष्ट्रवादी क्षेत्रों में विन्नेपत उदारपथी क्षेत्रों में यथाथ में ही हलचल मचा दी, निवासी पर दिए गए अपने प्रसिद्ध भाषण में दादा भाई ने अपनी राजनैतिक मान्यता को निम्न-

निश्चित रूप से मुस्पष्ट भाषा में अभिव्यक्ति दी

इसका एकमात्र उपाय भारतीयों को स्वशासन देना है। भारत के प्रति अंग्रेज ब्रिटिश उपनिवेशों के समान ही व्यवहार अपेक्षित है। भारतीयों के इंग्लैंड के साथ सबंध अवश्य जुड़े रहे परंतु उन्हें दास बनने पर धोर आपत्ति है। वे अपने पर अपना ही शासन चाहते हैं तथा विश्व के अन्धकार देशों के साथ प्रगति में भागीदार बनना चाहते हैं।<sup>16</sup>

उनकी इस घोषणा का समाजवादी सम्मेलन के आतिथ्यकारी वातावरण से उत्तेजित मन की एकाएक और जलज्वारी में निवाली गई भडसा नहीं कहा जा सकता। उन्होंने इस कथन के एक ही वष उपरांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन को दिए गए अपने संदेश में विशेष निर्देश करते हुए मुस्पष्ट रूप से अपना दृढमत इस प्रकार से प्रकट किया

स्वशासन के बिना भारतीय शालू निकासी और उसके फलस्वरूप प्राप्त होने वाली घोर दरिद्रता दुर्भाग्य और विनाश से बची छुटकारा नहीं पा सकते। किसी प्रकार के बंसी भी तसल्ली देने वाले उपाय क्यो न किए जाए प्रशासननत्र में किसी प्रकार की बंसी भी नहीं बदल अथवा इधर-उधर की हर फेर क्या न की जाए, इनसे न तो कोई लाभ हो सकता है और न ही सबथा कोई लाभ होगा। स्वयं सरकार और स्वयं प्रजा ही निवासी को बंद कर सकती है। भारत के दुर्भाग्य और व्यथाओं की निवृत्ति के स्वशासन ही एकमात्र उपचार है।<sup>17</sup>

यहां यह स्मरणीय है कि ये दावा भाई ही थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक बलवत्ता अधिवेशन में दिए गए अपने भाषण में राष्ट्रीय आंदोलन के भावी लक्ष्य का निर्देश करते हुए यह घोषणा की थी कि भारतीय जनता की सभी राजनतिक मांगों को जिसे एक ही शब्द में समेटा जा सकता है वह है, स्वशासन अथवा स्वराज्य जैसा स्वराज्य इंग्लैंड में है अथवा दूसरे दूसरे उपनिवेशों में है।<sup>18</sup>

दादा भाई के इस अतिवादी दृष्टिकोण, निवासी भारत के दुर्भाग्य का एक महत्वपूर्ण कारण है वे राजनतिक महत्व को भली प्रकार समझने के लिए उनकी राजनतिक महत्ता के तथा भारत की दरिद्रता के कारण मान गए अथवा तत्वा, आधुनिक औद्योगिक शक्ति का अभाव अथवा अल्पधिक भूमि लगान अथवा ऊंचे करारधान अथवा राजनतिक अधिकारों की अनुपस्थिति, से तुलना अपेक्षित है। इनकी तुलना से पूर्व दो बातों का ध्यान रखना अत्यावश्यक है क्योंकि उनकी उपेक्षा का अर्थ उपयुक्त परिप्रेक्ष्य से हाथ धोना होगा। प्रथम, अपने अंतिम विश्लेषण में स्वयं दादा भाई ने भी भारत में उद्योग के अभाव को ही भारत की दरिद्रता का कारण बताया। अंतर बचल यह है कि उन्होंने इस अभाव के कारण के रूप में निकासी को ही उत्तरदायी बताया। द्वितीय, भल ही इस 'निघनता का औद्योगिक सिद्धांत' नाम दिया जाए, ताकि विश्लेषण से तो हर हालत में ही यही आतिथ्यकारी राष्ट्रवादी, राजनतिक अनुमान निष्कर्ष के रूप में उभर कर सामने आता है कि ब्रिटिश भारत की सरकार ब्रिटिश व्यापार और ब्रिटिश उद्योग के हितों की रक्षा में ही तत्पर है तथा भारतीय उद्योग और व्यापार अपनी पूणता में तब तक नहीं जा



मार्त जब तक कि प्रमुख रूप से भाग्यीय उद्योग के हिता की ही देखभाल के उद्देश्य को लेकर उनका चान्दा अपना ही राजनीति प्रमुख स्थापित नहीं होता। परन्तु 19वां शताब्दी के परवर्ती काल के और 20वीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल के बहुत मारे उद्योगिक नवाचारों तथा बाल गंगाधर तिलक, लाल्लू प्रसाद शर्मा और वी० सी० पात्रन भारतीय उद्योग के विकास पर उच्च प्रतिबन्ध का हटाया के लिए प्रयत्न सफल किया। इसी प्रकार नूतन नवाचारों के अन्तर्गत और ऊँचे पराध्याय के सिद्धांत से भी समय-समय पर प्राविशिकी राजनीति मार्गें उठी। इस प्रयत्न में इन सब की तथा हम यथास्थान पहले ही कर चुके हैं।

विशेषी तथा भारत की अर्थिक सिद्धांतों के राजनीति परिणामों के बीच मुख्य अंतर इस तथ्य में निहित था कि किसी भीमा तथा और कभी-कभी अर्थिकता के अन्तर्गत सिद्धांत विद्वानों का मत ही महत्त्व के परन्तु निशानी सिद्धांत के वार में यह नहीं कहा जा सकता।

उदाहरण के रूप में उद्योग के सिद्धांत का ही लीजिए, इस क्षेत्र में जहाँ भारत और ब्रिटेन के औद्योगिक हिता में संघर्ष के कारण बहुत मारे मतभेद उत्पन्न हुए और उद्योगिकता भी बढ़ी, वहाँ इस उद्योग के अन्तर्गत उद्योगिकता के दुर्भावनाओं को दूर करने की दिशा में कुछ उपाय नीतिवादी देने लगे — प्रथम, औद्योगिक सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार भारत में ब्रिटेन राज्य भारत के औद्योगिकीकरण के मार्ग में दुर्घटन बाधा नहीं था। वनमात्र अधिकांश और राजनीतिक परिस्थितियों में भी कुछ न कुछ औद्योगिक विकास संभव था। अतएव औद्योगिक संघर्ष को स्वराज्य आन्दोलन के माध्यम से जाड़न की गई स्वाभाविक जयवा पूरा आवश्यक्ता नहीं थी। उदाहरण के रूप में जस्टिस रानाडे द्वारा राज्य सहायता पर बल देने के बावजूद भारतीय उद्योग के विकास के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता पूरा रूप से आवश्यक नहीं थी।<sup>19</sup>

द्वितीय कभी कभी इन बातों में मार मारले को और भी अधिकांश जटिल बना दिया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार प्रायः ही उद्योगीकरण के पक्ष में बोलती रहती थी और कभी कभी तो स्वयं भारतीयों द्वारा प्रदर्शित उल्हास ही अपेक्षा कथनी के रूप में भी औद्योगिक विकास के लिए अधिकांश उल्हास दिवानी थी।<sup>20</sup> इनके अतिरिक्त भारत सरकार ने उद्योग के विकास के लिए 1905 में वाणिज्य और उद्योग संवर्धन एव प्रथम शाही विभाग की स्थापना और उसे सर्वोच्च महत्त्व देने के रूप में साधारण और नगण्य होने पर भी कुछ न कुछ पग तथा उठाए ही थे।<sup>21</sup> किसी भी रूप में क्या न हो यह आशावादी दृष्टि कोण सदैव बना रहा कि पराध्याय और मजदूरी तकनीकी शिक्षा और राज्य सहायता आदि से संबंधित सरकारी नीति में भारतीयों की इच्छानुरूप ही परिवर्तन किया जा सकता है। जसाकि 1918 के उपरांत भारतीय उद्योग आयोग की सिफारिशों के उपरांत एक सीमित परिमाण में हुआ भी। जब एक बार सरकार अपनी नीति में परिवर्तन कर लेती है तो उस सतही तौर पर तो अधिकांश समय तक उद्योग विरोधी घोषित नहीं किया जा सकता। उद्योग-सिद्धांत के समर्थक सदैव अपने तर्कों में जटिलता को अपनाते रहे और सदैव यह दिखाने का प्रयास करते रहे कि ब्रिटिश भारत की सरकार इस दिशा में काफी कुछ नहीं कर रही है और यदि भारत की अपनी सरकार होती तो वह इससे बहुत अधिकांश

ही करती। यह काम आसान नहीं था और इसके लिए विशेषता की सहायता लेनी पड़ी। राजनीति में तो जब कोई भी काय विशेषता की सहायता में किया जाता है तो उसे जनसाधारण पर प्रभाव की दृष्टि से नष्ट हुआ ही समझना चाहिए। फलतः जहाँ भारत की निधनता के उपाय के रूप में औद्योगिक विकास पर अधिक बल देने की बात थी, इसे शिक्षित वर्ग को प्रभावित करने का साधन तो बनाया जा सकता था परन्तु इसे जनता और सरकार के बीच राजनैतिक सबंध विच्छेद को गहरा करने का शस्त्र नहीं बनाया जा सकता था। इसके मवथा विपरीत सरकार दिखान के लिए यह तक प्रस्तुत कर सकती थी कि उद्योग तो दोनों सरकार और राष्ट्रवादियों के लिए समान रूप से उद्यम का क्षेत्र जुटाता है।<sup>3</sup> तृतीय, उद्योग सिद्धांत के प्रवर्तकों को यह स्वीकार करना पड़ा कि जहाँ दश के औद्योगिक पिछड़ेपन का आशिक आरोप ईमानदारी से ही सरकार पर लगाया जा सकता है, वहाँ आरोप के एक बहुत बड़े भाग के पान स्वयं भारतीय है जिन्होंने स्वयं पूँजी, श्रम उद्यम और तकनीक के उपलब्ध साधनों का उपयोग करने में तत्परता नहीं दिखाई।<sup>4</sup> इसका निष्कर्ष स्पष्ट था कि भारतीयों को अपने शानका पर आरोप लगाने और उनकी आलोचना करने में अपनी सारी शक्तियों का अपव्यय नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य ही रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तथा अपनी प्रतिभा को निजी प्रयाम के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए।<sup>5</sup> बहुत सारे सरकारी प्रवक्तव्यों में राष्ट्रवादियों के निजी प्रयाम के दृष्टिकोण के सरकार के विरुद्ध संचालित राजनैतिक तथा आर्थिक आंदोलन को स्पष्टतः क्षीण बनाने वाला अनुभव किया और वे देश के औद्योगिक और आर्थिक पिछड़ेपन का सारा दोष अपने कंधों से उतार कर स्वयं भारतीयों के ही कंधों पर ढालना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार उदाहरणार्थ, डफरिन ने 1888 में यह घोषणा की कि व्यापार पर लगी पाबन्दियाँ हटाकर और परिवहन के साधनों, मटक, रेल तथा अत्याय यातायात सुविधाओं का बहुगुणा विस्तार करके हम उत्पाद और व्यापारिक गतिविधि को तीव्रता दे सकते हैं और इस समय भी अपनी जोर से यह सब कर रहे हैं परन्तु उत्पादक केंद्रों का वास्तविक काय तो आखिर निजी उद्यमियों को ही करना चाहिए। इसके उपरांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं का आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार जो काम नहीं कर पा रही उसे करने में आप लाग पीछे क्या रह रहे हैं?<sup>6</sup> भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास से इस सबंध में एक घटना को उद्धृत करना बड़ा ही रोचक होगा। 1901 में कांग्रेस ने एक समिति का गठन इस उद्देश्य से किया कि वह प्रतिवेदन प्रस्तुत कर कि क्या अगले अधिवेशन से इस प्रकार के प्रस्ताव उठाए जा सकते हैं जिन्हें अतिसत राज्य की आर्थिक मदी का तथा उत्पादन और वितरण के साधनों के पान के अभाव का भारी दायित्व सरकार पर ढाला जा सके। इस समिति ने भारतीयों से अनुरोध किया कि वे इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति और उसके प्रसार के लिए यत्नशील बनें और इस तथ्य को स्वीकार करें कि पूँजी और साख का प्रश्न निस्मदह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रश्न है परन्तु उसका हल स्वयं हमारे अपने ही हाथ में है। समिति ने भारतीयों से अनुरोध किया कि वे निरंतर और ईमानदारी के साथ पूँजी का संगठन करके देश की आर्थिक दशा के सुधार के माग की कठिनाइयों में से एक का दर

वरन की चेष्टाएँ करें।<sup>1</sup> इन प्रस्तावों में 1890 में पूना में हुए प्रथम औद्योगिक सम्मेलन में लिए गए जस्टिस रानाडे के भाषण की भावना को ही स्थापित किया जाता था। इनके उन्नायक वदाहित लगभग तीन दशकों के बाद कांग्रेस को गत प्रेरणा देने वाले महानुभाव के प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट करता भारत में परन्तु ये प्रस्ताव कभी पारित नहीं हुए। हम गीमित अथवा कांग्रेस द्वारा की गई इन प्रस्तावों की अस्वीकृति का कारण पाते नहीं। हाँ यह अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के नेताओं ने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि ये प्रस्ताव यदि उठाए गए तो सरकार के विरुद्ध राष्ट्रवादी तंत्र के लिए निरंतर और क्रमशः बढ़ते जाने वाले वातावरण के प्रमुख तन्त्र में हटकर राष्ट्रवादी गति विकसित जाएगी। अतः कांग्रेस ने अपना राजात्मक, अराजनात्मक और आराजनात्मक पक्ष को ही अपनाए रखा। उगत देश की गरिबी के लिए निम्नलिखित तत्त्वों पर अनियोग लगाया ही जारी रखा। स्वदेशी उत्पादन का ह्रास, संपत्ति की निकासी, अत्यधिक कराधान अत्यधिक मद्य प्रशासन, तथा भूमि के भारी कर, 'जिन सबके लिए अपने सरकार को उत्तरदायी ठहराया जा सकता था।

इस प्रकार ब्रिटिश सामन और उमरी कुछ आर्थिक नीतियाँ तथा इस विचार का कि भारत की आर्थिक दुबलता का अर्थात् औद्योगिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण प्रमुख रूप से भारतीयों की अपनी ही दुबलताएँ थी, तथा 'निजी प्रयत्न से इन पिछड़ेपनों का दूर किया जा सकता है स्वोपकार करने का यह परिणाम निम्नलिखित कि औद्योगिक मित्रता न भारतीय अभशास्त्रियों के एक आशावादी धर्म को जन्म दिया और कम से कम प्रारम्भ में तथा कुछ समय तक सामन नीतियों के लिए आर्थिक सहायक आधार का काम किया।<sup>2</sup>

इसी प्रकार यहाँ तक कि सरकार की मूराजस्व नीति का एक अतिवादी आलोचक भी भूमि लगान में कटौती कर देने से अथवा भविष्य में किसी प्रकार की वृद्धि न होने से अथवा यहाँ तक कि अपने मतों में सरकार द्वारा कपटपूर्ण ढंग से अतिशयोक्ति दिखाने पर सताए कर लेता था जैसा कि 1901 में आर० सी० दत्त के मामले में भूमि लगान पर अपने प्रस्ताव द्वारा किया। सरकार भी कराधान और व्यय के इन समीक्षकों को दूर उधर गीमित परिमाण में धाँधे बढ़ते कर भार का घटा कर तथा किसी लोक कल्याण अथवा विकास की गतिविधि अथवा विभाग में सरकारी सचिवों को बढ़ाकर थोड़ा-बहुत प्रसन्न कर सकती थी। रत्ना की आलाचना जो पहले बितनी भी व्यायसगत क्या न हो, जब रत्ना के उपयोगी और लाभप्रद सिद्ध हो जाने से क्रमशः धीरे धीरे मद पड़ती जा रही थी। यहाँ तक कि राष्ट्रीय राजनैतिक प्रगति की मांगों से उत्पन्न अतिवादिता का भी थोड़े से प्रयत्न से सावधानी के साथ संगणित राजनैतिक रियायतों और मुद्दों की खुराकें देकर शांत किया जा सकता था। किसी भी स्थिति में भारतीय राष्ट्रवादी फिर भी तब तक संवत्त थे और यह सिद्ध कर सकते थे कि इन सभी मामलों में और साथ ही साथ विदेश व्यापार, मुद्रा तथा श्रम आदि के मामले में ब्रिटेन की आर्थिक नीति स्वायत्तपूर्ण और भारतीय हितों के विरुद्ध थी। इस विषय में सरकारी तर्कों और बहानों के भ्रम जाल को उखाड़ने तथा वास्तविकता को देखने के लिए एक निश्चित परिमाण में राजनैतिक तथा आर्थिक सूक्ष्म दृष्टि अपेक्षित थी। यह सूक्ष्म दृष्टि नेताओं को भल ही प्राप्त हा,



वायलय, ब्रिटेन की पूजा का भारत में विवेक रत्न, विदेश व्यापार, भूमि संपन्न और साम्राज्य के अधीन का पर्यायवाची बताया और लोगों के मन में उठते धीरे धीरे यह विश्वास उत्पन्न कर दिया कि भारत के आधुनिक विद्यार्थियों और राष्ट्रवादी का अग्रणी प्रमुख रूप में स्वयं ब्रिटेन का शासन का भारत में अस्तित्व और ब्रिटीश राज्य की नींव है। वही देश की उन्नति का माग में प्रधान आधार है। भारत परंपरा में दरिद्र नहीं है प्रत्युत स्वयं ब्रिटीश राज्य द्वारा बनाया गया है। मिथिल मवा के यूरोपीय चरित्र पर बनने से भी बड़ी राजनैतिक उद्देश्य सिद्ध होना या उन्नति हममें पर आरंभ जाना के सामने देश की राजनैतिक और आधुनिक पराधीनता का तथ्य को सामने रखा में सहायता मिलनी की और दूसरी ओर हममें हम माग का बन मिलता या कि भारत में ब्रिटीश राज्य अवश्य बना रहे परंतु स्वयं ब्रिटीश शासन का ही बना रहना चाहिए। स्पष्ट है कि हम माग की स्वीकृति की वार्ड सहायता नहीं थी, परंतु हमें शासन के विरुद्ध जाना के माग का राय की भावना का भंग करने में सहायता मिलनी।

हम प्रकार निरासी सिद्धांत न पर ब्रिटीश समस्या को जन्म दिया जोर उम्र हममें का एक ऐसा ही मुभाया कि जिनमें भारत में ब्रिटीश राज्य की जड़ें ही बट जाती थी और एक ऐसे अंतर्विरोध को उजागर किया जिनमें अनिवासी राष्ट्रीय दृष्टिकोण का उद्भव होता था भारत सरकार और जनता के मध्य स्थायी रूप में राजनैतिक मुठभड़ की स्थिति उत्पन्न होती थी और अंततः ब्रिटीश राज्य को उगाड़ फेंकने की आतिवारी राजनैतिक माग को जन्म मिलता था। निवासी सिद्धांत के समयकता राजनैतिक मुद्दों को सतुष्ट होना बाल नहीं थे क्योंकि इन मुद्दों से निवासी जिनमें प्रकार कम होना वाली नहीं थी। अतः राजनैतिक मुद्दों के लिए जान पर भी निवासी पर आधुनिक राजनैतिक मध्य में बंधी नहीं होने जा रही थी।<sup>21</sup> हमें अनिश्चित निवासी सिद्धांत न भारतीय समाज के सभी आंतरिक भंगों को पीछे धकेल दिया तथा सारे समाज का ध्यान ब्रिटीश राज्य को देना निवासी की आरंभ ही समग्रतें केंद्रित कर दिया। इन प्रकार दादा भाई के आधुनिक दृष्टिकोण के निराशावादी चरित्र न 1872 में प्रारंभ में स्वीकार करने के उपरान्त अंत में उम्र छोड़ने का विनाश रानाड के आशावादी दृष्टिकोण की तुलना में, उदाहरण का भविष्यकता बना दिया और 1904 में उस समय निश्चित रूप में नकारात्मक के निराशावादी लक्ष्य के लिए आह्वान देने के योग्य बना दिया।

निवासी सिद्धांत के आतिवारी राजनैतिक अभिप्रायों में इसके समयकता ही नहीं प्रत्युत आलोचक भी बड़ी अधिकांश बट-बट कर परिचित थे। 1886 में भारत राज्य मन्त्रि रडोल्फ चर्चिल ने निर्देश दिया

देश पर थोपे गए विदेशी राज्य के फलस्वरूप समझे जाने वाले और देश के बाहर हुए खर्चों की अतिरिक्त राशि की पूर्ति के लिए समग्रतें भारत रूप में उठाए जाने वाले नए कराधान के भार का अधीरता एक गंभीर राजनैतिक खतरे का रूप धारण कर लेगी। हमें आशंका तो यह है कि भारत सरकार से संबंध अथवा उसकी जानकारी न रखने वाले महानुभाव हमें खतरे की गुरता को समझ ही नहीं पाएंगे परंतु जिनका भारत सरकार की जानकारी है और जिन पर उसके संचालन का दायित्व

है, उन्होंने बहुत पहले से ही इसे एक अत्यंत गंभीर प्रकृति का खतरा बताया है।<sup>35</sup> इसी प्रकार जे० डी० रीस ने अपनी पुस्तक 'दि रियल इंडिया' में दादा भाई को आड़े हाथों लिया कि उन्होंने इस तथ्य को समझा ही नहीं कि गृह प्रभारों के बिना भारत में ब्रिटिश सरकार रह ही नहीं सकती थी।<sup>36</sup> बहुत सारे भारतीयों ने निकासी सिद्धांत के प्रचंड प्रचार का इस आधार पर विरोध किया कि यह देर अवर राजनैतिक स्वतंत्रता की अपरिपक्व मांग को जन्म देगा।<sup>37</sup> इसी कारण कदाचित् रानाडे ने निकासी पर आवश्यकता से अत्यधिक बल देने की प्रवृत्ति का विरोध किया।

सक्षेपत निकासी सिद्धांत अपने राजनैतिक आशयों में क्रांतिकारी तत्त्व था, इसने राजनैतिक अधिकार के प्रश्न को राजनीति का केंद्र बिंदु बना दिया। इसकी स्वीकृति न केवल ब्रिटेन और भारत के स्वाभाविक राजनैतिक मध्य को सतह पर ला दिया प्रत्युत ब्रिटेन के भारत पर राजनैतिक प्रभुत्व को भी अमाय बना दिया। इसमें यह भी स्पष्ट हो गया कि क्यों अंग्रेजों ने ही क्षेत्रों में राष्ट्रवादियों द्वारा की गई ब्रिटिश की अर्थ नीति की आलोचना और उसके फलस्वरूप उन राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा भुंकाए गए उपचारों तथा ब्रिटिश साम्राज्य के प्रबल श्रद्धालुओं को भी स्वीकार थे, परंतु निकासी की बात प्रबलतम क्रांतिकारियों तक को भी माय नहीं थी।

निकासी सिद्धांत ने आर्थिक प्रश्न को राजनैतिक स्तर पर उठाकर सामाजिक जीवन को राजनैतिक प्रशिक्षण देने में भी सहयोग दिया। जहां अल्पसंख्यक आर्थिक प्रश्न कदाचित् आर्थिक उपचारों द्वारा साध्य थे अतः विशेष परिस्थितियों में आर्थिक विवाद की परिधि में ही आते थे, वहां निकासी का हल केवल राजनैतिक था। अतः निकासी सिद्धांत न राजनैतिक निष्प्रियता को सन्नियता में बदलने में भी योगदान दिया।

निकासी सिद्धांत में सर्वसाधारण लोकप्रिय बनने की प्रबल राजनैतिक क्षमता थी। यह एक ऐसी सरल और सीधी सादी धारणा थी कि जिसे एक किसान भी आसानी से समझ पाता था। राष्ट्रवादी वक्ता निकासी पर भाषण करते समय अपने अत्यंत अतिशय श्रोताओं से भी शीघ्र समझ जान की प्रतिक्रिया पा लेते थे। एक देश से दूसरे देश का धन का स्थानांतरण, आर्थिक शोषण के सिद्धांतों का एक ऐसा विषय था जिसे मजदूर आसानी से समझ जा सकता था क्योंकि यह उनके दैनिक अनुभव से संबंधित था। निकासी पर प्रहार को सुनते समय किसान इस प्रकार अनुभव करता था जमकी धन उसकी जेब से बिसक रहा है। उन्हें इस जसा जीर कोई विचार इतना दुर्बल नहीं कर सकता था कि उन पर इसलिए कर लगाए जा रहे हैं कि दूर देश में रहने वाले मुलुखों से उड़ा सकें। अतः निकासी में किसानों के देश को सघटित करने के नारे की सामर्थ्य थी। निकासी नहीं एक ऐसा नारा था, जिसकी सभी सफल क्रांतियों को आवश्यकता रही है और वे इस अपनाती रही हैं। इसे सिद्ध करने के लिए निम्नी प्रकार के ऊंचे और जटिल तर्कों की आवश्यकता नहीं इसके बल्कि स्वतः स्पष्टता तथा इसका आंतरिक गुण है। भारत के विषय में यह स्वतः सिद्ध थी और इस विश्वास में कि भारत सान की ब्रिटिश थी और धीरे धीरे उसकी सारी संपदा लूट ली गई है और उस आज की दरिद्रता और दुर्भाग्य की स्थिति में ला फेंका गया है, जब भारतीय राष्ट्रीयतावादी चरम सीमा पर ही उठ रहे

था, उम समय उन वर्षों में राष्ट्रवादियों की शिरासता न अत्यंत नासप्रिय और प्रजन शक्तिशाली रूप ग्रहण कर लिया। अतः यह आश्चर्य की बात कि निरामीशान्ति पर सरकारी और माय ही माय गैर सरकारी ब्रिटिश जेजुरी ने पूरी शक्ति और निरनरता के साथ तीव्र प्रहार किए। मन्त्रत एका भाष्य विगी भी अथ गिद्दान अथवा माग का नहीं रहा। इस सिद्धांत के प्रमुख जन्मदाता और प्रचारक जेम्स माई नौराजी की, जिनकी ब्रिटिश राज्य के प्रति वफादारी गन्तव्य गहरी थी और जिनका ब्रिटिश जनता में सबसे गहरा विश्वास था, स्वप्नद में और अतिवादी रूप में निरामीशान्ति की गई।<sup>1</sup> यहाँ तक कि उन्हें घूत और छिपा विद्रोही कहा गया।<sup>2</sup> परंतु दूसरी ओर गांधीयुग के राष्ट्रवादियों की दृष्टि में उद्यम शिरासत वाल नवयुवक न 19वीं शताब्दी के सनाई किंगजिनाट महता और गोपाल जग अत्यंत कामन और गम्भीरवादी तताओं का गोडे समय के लिए ही सही, घृणा की दृष्टि में देगा और उन्हें 'अर्जोनिवीम' कहकर उनका निरस्मार किया। गांधी युग के राष्ट्रीय प्रेमो नवयुवक की दृष्टि में उस समय भी दादा भाई अत्यंत सम्मानित थे और भारतीय राष्ट्रवाद के पिता के समाज आदरणीय थे।

## संदर्भ

- 1 नौराजी एगज पृ० 26-50
- 2 वही पृ० 29-31
- 3 वही पृ० 32-3 दादाभाई न इग भेद का भी उजागर किया कि 20 वर्ष से भी काफी पहले भारत पर ब्रिटिश शासन के प्रभावों पर विचार करने के लिए कुछ पाठ से हिंदू विद्यार्थी और विचारशील लोग गुप्त रूप से बैठकें किया करते थे उनको शिवायतो के प्रमुख धर्म थे यह प्रभार विभिन्न रूपों में भारत से इंग्लैंड को संपत्ति का निष्कासन भारत के संप्रदाय का धन है। दग के प्रशासन में योगदान देने तथा विचार अभिव्यक्त करने की सुविधा का अभाव आदि (वही) वास्तव से इससे बहुत पहले ही 1830 के आगपास भारत द्वारा इंग्लैंड को लिए जाने वाले उपहार-शुल्क के विरुद्ध राजाराम माहन राय ने शिरासत की थी (बी० बी० मजूमदार पूर्वोद्धृत पृ० 71-2 पर)
- 4 नौराजी एगज पृ० 39 और दखिए पृ० 40-1 भारत के ससाधनों के विकास के इस विचार को दादाभाई नौराजी के परवर्ती विचार विन्नेजी पूजा के भारत में निवेश का अर्थ है भारत की संपदा का अपहरण से निराम रूप में देवता उचित है
- 5 वही पृ० 97-111
- 6 वही पृ० 112-36
- 7 वही पृ० 123
- 8 वही
- 9 वही पृ० 98-9 108-123
- 10 वही पृ० 133-4
- 11 वही पृ० 135-6

- 12 वही प० 102
- 13 वही, प० 106 -
- 14 नौरोजी स्पीचेज, परिशिष्ट प० 164
- 15 वही परिशिष्ट प० 165 इसके साथ ही उद्देश्ये इम प्रवाह के हानिकारक परिणामों की चर्चा की जहाँ तक इस समय में जाव पड़ताल कर सका है उसमें म इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिस विद्या प्रणाली पर अपना अधिकार करती थी अतिशय भी उनक पद चिह्नों पर चलती हुई उस प्रदेश पर अपना अधिकार कर लता था जब से सिचाई के लिए रेल पथों के सिद्ध तथा अन्य लाखों कायों के लिए अमरीका के साथ युद्धों के साथ ही की दुलभ प्राप्ति लौट कर आई है तब से ऐसा लगता है कि भारत ने जो स्वतन्त्रता उसको कुछ हद तक लौटो है (परिशिष्ट प० 167) तथा देखिए परिशिष्ट प० 172 181
- 16 नौरोजी पावर्टी प० 125
- 17 1901 में उद्घुति इम विषय पर अपमानाकृत अधिक सुप्रसिद्ध लेखों और भाषणों को पावर्टी ऐंड अनवित्तिग क्लब इन इंडिया शीपक एक ही पुस्तक में संग्रहित किया, जिसका शीपक स्वयं ही उनका राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण का सनिष्ठ रूप था उनके अन्य बहुत सारे लेखों तथा भाषणों आदि को, जिनमें से उद्घान प्राप्त सभी में निवासी पर प्रहार किए हैं 1887 में सघहीन किया गया है उनके भाषणों, लेखों, निबन्धों तथा प्रवचनों के संस्करण का सी० एल० पारिस तथा नटसन ने नौराजा स्पीचेज ऐंड राइडिंग शीपक से संपादन किया है अगस्त 1904 में एम्प्लरडम के हुई अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का समर्थन दिया गया उनका एक रोचक भाषण 'इंडिया' के 2 सितंबर 1904 के अंक में उपलब्ध है
- 18 नौराजा पावर्टी, प० 201
- 19 नौराजा स्पीचेज प० 329
- 20 प्रधान और भागवत, पूर्वोद्धत प० 8 दुर्भाग्यवश हम इस भाषण की प्रति अथवा प्रतिबदन का दूढ़न में अक्षय रहे हैं हमारे विचार में कल्पित कोई प्रति उपलब्ध नहीं है
- 21 रानाड एलेज प० 23
- 22 एम० एम० माच 1873 खड II प० 89 90 और देखिए प० 92 3
- 23 दत्त स्पीचेज III प० 27 47 8 61 84
- 24 दत्त ई० एच० I प० XIII और देखिए प० XII
- 25 वही प० 420
- 26 दत्त ई० एच० II प० XIV और देखिए प० 213 344 348 529-9
- 27 जोशी पूर्वोद्धत प० 636-41 683 793-4 राय पावर्टी प० 6-8 242, 278 315 20 328 29 और इंडियन फॉर्मिड प० 37 मालवाय स्वाचर प० 232 3 248 51 बाबा रिप० आई० एन० सी० 1846 प० 62 सी० पी० ए० प० 607-07 रिप० आई० एन० सी० 1898 प० 104 गोयले स्वाचर, प० 15 87 8 908 10 जी० एम० अम्बर बिनारी बंगाल एर III प्रथम 18963 और ई० ए० प० 59 125 128 9 336-8, 357 8 एन० एन० बनर्जी सी० पी० ए० प० 253 5 269-70 637 703 11, बा० एम० मालवाय इंडियन प्रॉब्लम (बर्द 1894) प० 23 'एटलीज इन रि बंगाल रिनि (जानवरी 1908) में अनुनयन भाषा द्वारा संपादित प० 209 पर राजतरायण बोग, आर० एन० प्रधानकर इंडियन पॉलिटिक्स प० 41, ए० नन्वे इंडियन पॉलिटिक्स प० 124 7 28 सितंबर 1897 सन का इंडियन



## 620 भारत में आर्यन राष्ट्रवाद का उद्भव और विनाश

- गोगाइटी द्वारा सम्मेलन में पारित प्रस्ताव दृष्टिया 14 जनवरी 1898 आर० एम० सपानी, गो० पी० ए० प० 351-4 366 गो० वार्ड० चित्तामणि, एच० आर० जनवरी 1902 प० 28-9, एम० व० पटन रिप० आर्द० एन० गा० 1902 पृ० 762 और रिप० आर्द० एन० गा० 1904, प० 114 एन० एम० घोष गो० पी० ए० प० 743 7५0-3
- 28 और दृष्टिया ए० चा० पी० 6 फरवरी 18९0 29 जनवरी और 18 जून 1885 22 मई 1892 24 जून 1876 13 फरवरी और 7 अगस्त 1897 22 फरवरी और 1 8 और 9 जून 1900, 13 नव० 1901
- 29 उन्हाहरण के लिए दृष्टिया माधारणा 31 अक्टू० (आर० एन० पा० वग० 6 नव० 18९0) मराठा 6 फरवरी और 19 जून 1881 तथा 13 अक्टू० 1884 इंडियन स्पेक्टर 25 फरवरी (आर० एन० पी० वग० 3 मार्च 1883) इंडियन स्पेक्टर 18 मई ग्लोब टाइम्स 20 मई (वही 24 मई 1884) समय 30 जून (आर० एन० पी० वग० 5 जुलाई 1884) प्रतिवार 22 अगस्त (वही 6 मित० 1884) मारम्बत पत्र, 6 मित० (वही 13 मित० 1884), पत्तारा 17 जुलाई (वही 25 जुलाई 1885) समय 28 जून (वही 3 जुलाई 1886) वगवासी 7 अगस्त प्रकाश 6 अगस्त (वही, 14 अगस्त 18९6) इंडियन स्पेक्टर 5 जुलाई 1885 भारतीय समाचारपत्रों के मत का संपादकीय सार स. 1 प. 10 गो० पी० आर्द० अक्टू० 1887 दू प्रकाश 5 मित० और टिम्बून 14 मित० (गो० पी० आर्द० अक्टू० 1887) हिंदू 25 जून 1894 7 जुलाई 1898 वगवासी 13 मार्च 1897 हिंदुस्तान 20 जुलाई (आर० एन० पा० एन० 27 जुलाई 1898) स्वतंत्रता मित्र 15 मई (आर० एन० पी० एम० 31 मई 1900) प्रकाश दिस० 1900 और राजहंस, 2 जनवरी (आर० एन० पा० वग० 12 जन० 1901), न्यू इंडिया 16 मित० 1901 वाणिज्य अग्रवार 11 मई (वही, 16 मई 1903) हिंदू निवास 27 मई (वही 30 मई 1903), वक्तव्य चित्तामणि 14 नव० (वही 14 नव० 1903), केसरी 21 जुलाई (आर० एन० पी० वग० 25 जुलाई 1903) हमरी 9 मई (वही 13 मई 1905) 1880 से पहले निवास का विराध करने वाले कुछ समाचारपत्र थे दू प्रकाश 13 मित० (आर० एन० पी० वग० 18 मित० 1875) जाम जमशत 23 अगस्त (वही 26 अगस्त 1876) शुभसूचक 15 जून (वही 23 जून 1877) नटिव ओपिनियन 30 मित० 1877 (वही 5 जन० 1878)
- 30 प्रस्ताव XII
- 31 आर्द० एन० सी० (1897, 1901, 1902 और 1904 के प्रस्ताव सं० I, VIII (ए), III और III
- 32 नीरोजी प्लेज प 30-1 पावर्टी प० 211 638 तथा घतराष्ट्रीय समाजवादी कायदा म दिवा गया भाषण दृष्टिया 2 मित० 1904 प० 116 ए० वा० पी० 28 जुलाई 1870 जामे शमशद 23 अगस्त (आर० एन० पी० वग० 23 अगस्त 1876) शुभ सूचक 15 जून (वही 23 जून 1877) समय 28 जून (आर० एन० पी० वग० 3 जुलाई 1886) वगवासी 7 अगस्त (वही 14 अगस्त 1886) स्वतंत्रता मित्र तिथिरहित (आर० एन० पी० एम० मित० 1887) घोष प्रकाशिका 5 नव० (वही नव 1887) हिंदू 29 जन० 1891 राम पावर्टी प० 251 3 विश्वर नाथ, एल०सी०पी 1898 खंड XXXVII प० 519 वगवासी 25 मई 1901 एम० एन० बनर्जी सी पी० ए० प० 709 दत्त ई० एच० प० 85
- 33 प्रमाण के रूप में केवल इंडियन स्पेक्टर ने अपने 5 जुलाई 1885 के एक म तिवा आप

कह सकते हैं कि जितना आपने हम पर कर लगा रखा है उससे दुगुना कर मुगलों ने हम पर लगाया था उनका कराधान में क्या अंतर था दखिए वे भारत के ही निवासी थे जयवा उद्दान प्रत्येक रूप में भारत को अपना ज-मभूमि के रूप में अपना लिया था कराधान अत्याचार तथा लूटमार द्वारा वे जितना भी राजस्व वसूल करते थे वह सारा इसी देश में खर्च होता था एक कौड़ी भी इस देश से बाहर नहीं जाती थी भले ही वह पसा मिर्चाई नहरा व लवी दूरीवाली सड़कों के और पुलों के अथवा महला और मसजिदों के निर्माण पर और यहां तक कि आतिश बाजा और नाचने वाली मुदरियों पर खर्च होता था यह सारा पसा उन लोगों के पास थापन पहुंच जाता था जिनसे लिया गया था और देखिए ए० बी० पी० 18 जून 1885 राय पावर्टी प० 2513 नोरोजी, स्पीचेज परिशिष्ट प० 41 52, ए० नपी इंडियन पालिटिक्स प० 126, दत्त ई० एच० I प० XII 100 वाचा सी० पी० ए० प० 605 एल० एम० घाय सी० पी० ए० प० 759

34 नोरोजी एसेज प० 30 पावर्टी प० 211 स्पीचेज प० 238 9 अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी काग्रस में दिया गया भाषण इटिया 2 सित० 1904 प० 116 समय 30 जून (आर० एन० पी० वग० 5 जलाई 1884), सिध टाइम्स 20 मई (आर० एन० पी० वग० 24 मई 1884) केसरी 21 जुलाई (वही 25 जुलाई 1903) केसरी 9 मई (वही 13 मई 1905)

35 इस अवधि में भारतीय अव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण चरित्रगत विशेषता थी निर्यातों में वृद्धि जिसकी भारतीय नेताओं ने आलोचना की देखिए इसी पुस्तक में विन्श व्यापार से संबंधित पाचवा अध्याय वास्तव में आवश्यक और समुचित परिणाम में आयातों से निर्यातों की अधिकता बनाए रखने के उद्देश्य से निर्यातों को सरकारी तौर पर ही प्रोत्साहित किया गया था ब्रिटिश शासनकाल में व्यापार का सतुलन बनाए रखने के लिए निर्यातों को बनाने का सरकारी प्रयास भारतीय अव्यवस्था का प्रमुख रूप से संचालक माय ही प्रमुख विरोधा तत्त्व था एक जोर तो सरकारी नीति ब्रिटिश उद्योग के पोषण के लिए निर्यातों में वृद्धि करने की थी और दूसरी ओर आयातों के अपेक्षाकृत प्रचुरता में आयातों पर निर्यातों की अधिकता का समुचित रूप दे दिया और इसका भुगतान सतुलन अव्यवस्थित हो गया और सरकार इन्लड से ऋण लेने का उपाय का अपनाने के लिए विवश हो गई इसका अनिवाय परिणाम यह हुआ कि इन ऋणों के भुगतान के लिए फिर और अधिक परिमाण में निर्यात करने की स्थिति उत्पन्न हो गई इस प्रकार भारत से होने वाले निर्यातों का उपयोग या तो ऋणा का भुगतान के लिए होना अथवा आयातों के भुगतान के लिए इससे भारत में नाभरहित उद्योगों और निर्यातों के हितों का विग्रह का लाभ सपने उद्योगों और निर्यातों के हितों से सधय का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था यह सधय भारत से धन की निकासी पर ब्रिटिश प्रेम के और ब्रिटिश राजनयिता के एक ऋण द्वारा किए गए प्रारंभिक प्रहार को स्पष्ट करता है ब्रिटिश शासन की मारी अवधि में भारत से संपत्ति की निकासी के राजनीतिक प्रभावों और परिणामों के संबंध में विभिन्न स्तर पर मतभेद का ही रह

36 नोरोजी एसेज प० 101 113 4 पावर्टी प० 33 141 198 568 9 574 स्पीचेज प० 317 9 323 381 2 665 7 परिशिष्ट प० 42 3 ए० बी० पी० 28 जुलाई 1870 और 6 फरवरी 1880 मोनानाय च० एम० एम माच 1873 घड II प० 89-90 मराठा 25 मई 1884 सिध टाइम्स 20 मई इंडियन स्पेक्टर 18 मई (आर० एन० पी० वग० 24 मई 1884) जोशी पूर्वोद्धत प० 636-40 683 695 राय पावर्टी प० 78

- मुधोसकर इंडियन पॉलिटेक्निक पृ० 40-1 ए० नन्दी इंडियन पॉलिटेक्निक, पृ० 112 3 125  
 टिप्पणी 7 जनवरी 1898 यू इंडिया 19 अगस्त और 16 मित० 1901, इंडियन पायुस 24 जनवरी  
 1903 एत इन्डि एंड इंडिया पृ० 143 ई० एच० II पृ० 343-4 528 9 स्पीचेज II  
 पृ० 47 8 जी० एम० अम्बर ई० ए० पृ० 336 338 353 357-8 माग्न, स्पीचेज  
 पृ० 87 8 एम० एम० घोष गी० पी० ए० पृ० 750 753 और देखिए पीठ अध्याय 4 मास  
 सतिमवरी द्वारा 26 अप्रैल 1875 के एक भाषण में भी गई इन टिप्पणी का भारतीय नेताओं ने  
 अक्सर इतना किया है कि भारत में सबकुछ में इन फोर्ज का अतिरिक्त रूप में बणन किया जा  
 रहा है कि वहाँ से बिना किसी प्रकार के प्रयोग प्रमाणन के इन अधिकांश राजस्व का निर्यात  
 किया जा रहा है भारत में उन वर्गों में तो मगर मुधोसकर वहाँ में रक्त निवासता ही चाहिए  
 जहाँ उनका अत्यधिक सम्पत्ति है गया है अथवा वह समुचित मात्रा में उपलब्ध है पहले में ही  
 रखा व अभाव से दुर्घटना निम्न और दुर्घटना का तो छात्र ही नहीं जाना (नोरोजी पावर्टी  
 पृ० IX) और देखिए नोरोजी स्पीचेज पृ० 130 233 288 परिशिष्ट पृ० 13 एम० एन०  
 बनर्जी गी० पी० ए० पृ० 708-09 दत्त स्पीचेज II पृ० 84 और देखिए ज्ञान सुधी  
 पाश्चात्तन स्टेटमेंट (वित्त विवरण) 1878 9 बहिष्ता 52 और रिपोर्ट आफ इंडियन फमान  
 बयानन 1880 पृ० 94
- 37 नोरोजी एगज पृ० 113-4 पावर्टी पृ० 33 131, 136 9 198 स्पीचेज पृ० 317 8 381 2,  
 667 और देखिए आर० ए० मुधोसकर इंडियन पॉलिटेक्निक पृ० 41 और जी० एम० अम्बर  
 ई० ए० पृ० 336 7
- 38 उदाहरणार्थ देखिए, गोरजी पावर्टी, पृ० 32-33 उन्होंने कहा कि किसी देश में विदेश व्यापार  
 की सामान्य स्थिति प्रायः यह होती है कि उसका निर्यात के अन्तः सन्व निर्यात के मूल्य और  
 उसके लाभ के समान आयात होता है
- 39 वही पृ० 131 138 196
- 40 वही पृ० 33 139 इनके अतिरिक्त जब वित्तियों बमीशन ने उन पर यह निम्न करने के लिए  
 आग्रह किया कि बताएँ कि प्रचार आप यह कह सकते हैं कि निर्यात का लाभ भारतीय  
 निर्यात के वर्तमान मूल्यों में सम्मिलित नहीं किए गए हैं तो वे इसका सत्यापन और समर्थन  
 उत्तर नहीं दे पाए (स्पीचेज परिशिष्ट पृ० 53-4)
- 41 निम्न उद्धृत गणनाओं में आठवें पॉइंट और रायें दोषों में दिए गए हैं, इनका कारण है यह कि  
 दोषों के अनुपात में प्रायः अंतर आता रहता था
- 42 नोरोजी एगज पृ० 50
- 43 वही पृ० 115
- 44 नोरोजी पावर्टी पृ० 34
- 45 वही पृ० 566
- 46 नोरोजी स्पीचेज पृ० 318 21
- 47 वही पृ० 667
- 48 जोशी पूर्वोद्धृत पृ० 639-40
- 49 सी० पी० ए० पृ० 604 606
- 50 वही पृ० 709
- 51 दत्त ई० एच० II पृ० XIV तथा देखिए पृ० 528-9



- एन० पी० बब 3 मार्च 1883), जोशी, पूर्वोद्घृत, प० 618, 637 8 राय, पावर्टी प० 6 318-21 एन० एन० बनर्जी, गो० पी० ए०, प० 254, आर० एम० सयानी सा० पा० ए०, प० 366 हिंदुस्तान 20 जुलाई (आर० एन० पी० एन० 27 जुलाई 1898), स्वयंसेवक 15 मई (आर० एन० पी० एम० 31 मई 1900), वाचा, सो० पा० ए०, प० 605, दत्त स्पीचर II प० 84 ई० एच० I प० \ III ई० एच० II प० XIV XV 127 215 613 वेसरी 21 जुलाई (आर० एन० पी० बब 25 जुलाई 1903) एन० एम० घाघ सी० पी० ए०, प० 752 3
- 66 1902-03 में यह प्रभारों की राशि 17 700 000 पौंड थी और इसका वितरण निम्नलिखित रूप में किया गया गया था रेल पथ राजस्व घाता 6 900 000 पौंड कृषि का मूल और उनका संचालन व्ययस्था 2 800 000 पौंड भंडार 1, 800 000 पौंड सभा के प्रभावों एवं 1 300 000 पौंड नगर प्रशासन 400 000 पौंड वनस्पति 200 000 पौंड, नगर तथा सभ्य सेवा के बमबाराओं की पैना और अवकाश घाता पर हानि जाने अप्रभावा एवं 4 700 000 पौंड इंपीरियल गजटिपर आफ इंडिया (1903) यह IV प० 194
- 67 नौराजा स्पीचर प० 319 20 397 परिशिष्ट प० 3 राय पावर्टी प० 315-6, दत्त इण्ड एंड इंडिया प० 143 सा० पी० ए०, प० 490, स्पाचर II प० 47 ई० एच० I प० XIII ई० एच० II प० XV XVI 215 20, 373 5 ए० नदी इंडियन पालिटिक्स प० 113 एम० ए० पटल, रिप० आई० एन० सी० 1902 प० 76, जी० एम० अम्बर ई० ए 353- रेनवे के लिए दक्षिण पीछे अध्याय स० 5 भंडारा के लिए दक्षिण नौराजा, पावर्टी, प० 35 37 ए० बी० पी०, 14 अप्रैल 1881 और 17 अप्रैल 1884 राय पावर्टी प० 317 भारत सचिवालय के रख रखाव पर होने वाले व्यय के लिए दक्षिण पीछे अध्याय 12
- 68 दक्षिण इन्दी पुस्तक के अध्याय 3 का पाठ टिप्पणी में उद्धृत भारतीय नेता और ए० बी० पी० 6 फरवरी 1880 पताका 17 जुलाई (आर० एन० पी० बब, 25 जुलाई 1885) जा० एन० अम्बर विलबी बमबारा यह III प्रश्न 18638 हिंदुस्तान 20 जुलाई (आर० एन० पी० एन० 27 जुलाई 1898) स्वयंसेवक 15 मई (आर० एन० पी० एम० 31 मई 1900) हिंदू निशान 27 मई (वही 30 मई 1903) वेसरी 21 जुलाई (आर० एन० पी० बब 25 जुलाई 1903)
- 69 सयानी पूर्वोद्घृत प० 413-4 पर
- 70 नौराजा पावर्टी प० 216 और दक्षिण नौराजा एसेज प० 114 134 पावर्टी प० 141 199 203 217 224 5 655 6 स्पीचर प० 232 250 294 315 384-6 389 616 परिशिष्ट प० 3 23
- 71 ए० बी० पी० 28 जुलाई 1870 29 जन० और 18 जून 1885 22 मई 1892 27 मार्च और 24 अप्रैल 1896 13 फरवरी और 7 अप्रैल 1897 22 फर० 1 4 8 9 जून 3 अगस्त और 1 अक्टू 1900 13 नव० 1901
- 72 भोजानाथ च० एम० एम० खट II (1873) प० 90 93 जाशी पूर्वोद्घृत प० 640 683 794 मालवीय स्पीचर प० 232 3 248 51 514 5 वाचा रिप० आई० एन० सी० 1886 प० 62 स्पीचर परिशिष्ट प० 32 और सो० पी० ए० प० 366 प० 604-07 राय पावर्टी प० 6 7 241 2 278 315 और इंडियन फेरीस प० 37 एन० एन० बनर्जी सी० पी० ए० प० 254 269 637, 708 आर० एम० सयानी सी० पी० ए० प० 366 आर० एन० मधोल कर इंडियन पालिटिक्स प० 46-7 ए० नदी इंडियन पालिटिक्स प० 124-6 28 दिम्बर





एत० अम्पर, ई० ए०, प० 243, हितवादी 3 अन्नू० (आर० एन० पी० वग० 7 नवंबर 1903) और देखिए वाचा रिप० आई० एन० सी० 1886 पृ० 61

102 नीरोजी, स्पीच पृ० 152 3, 196 319 382, परिशिष्ट पृ० 3 5, 7 8 उसन आगे टिप्पणी की कि यदि हमे अपनी पूजा के समूह की पूर्ण स्तनत्रता हो तो हम देश में आने वाली विदेशी पूजा का ईमानदारी से बराबर मुकाबला कर सकते हैं और उस समय विदेशी पूजा में हानि की अपेक्षा बढ़ावित लाभ ही अधिक होगा इस समय हम विदेशी पूजा की हानि से ही रक्षित होना पड़ता है क्योंकि हम असहाय हैं और पतित अवस्था में हैं (वही, परिशिष्ट प० 7) तथा देखिए गोयले के दादाभाई के प्रश्नों के लिए गण उत्तर वित्तवी कमीशन खंड III प्रश्न 18169 71 18183-4

103 वही पृ० 250 1 परिशिष्ट पृ० 6-7

104 वही पृ० 153 663

105 दत्त ई० एच० II, पृ० XIV तथा पृ० 372 3

106 वही प० 348 9 534-6

107 दत्त स्पीचेज II, प० 27 8

108 वाचा रिप० आई० एन० सी०, 1886 पृ० 61

109 देखिए पीछ अध्याय 4 जोशी पूर्वोद्धत प० 641 ए० बी० पी० 17 जुलाई 1892 वाचा रिप० आई० एन० सी० 1898 पृ० 105, जी० एस० अम्पर ई० ए० प० 357 8

109-ए एहम सिमथ दि बल्प आफ नेशंस' (माडन लाइब्रेरी 'यूवाक द्वारा प्रकाशित कनन सस्वरण तिथिरहित) खंड 5 अध्याय 1 भाग III पृ० 710

109-बी ब्रिटिश इनकम्स इन इंडिया 'यूवाक डली ट्रि-यून 21 मितबर 1857 माक्स एंड एजल्स आन बानोनियलि'म (मास्को तिथि रहित) प० 143

109-सी एन० एफ डेनियल्सन के नाम माक्स का पत्र 19 फरवरी 1881 वही प० 304

109-डी स्पोरियल गजटियर आफ इंडिया (1908) प० 201 उदाहरणार्थ अवकाश यात्रा भक्त और सेवानिवृत्ति भत्ते के रूप में इनड में ही भुगतान की गईं राजि भारत के 1902 03 के शुद्ध वार्षिक राजस्व के 12 प्रतिशत के समभग थी (उसमें से ही आकड़ समर्पित किए गए हैं प० 194 201) 1895 में पी सी० राय ने दावा किया कि यह अनुपात 16 प्रतिशत है (पावर्टी, प० 318) बट्टूत सारे भारतीय नेताओं ने भी 1892 के सप्तमीय हिसाब खाते के आधार पर सगणना करने की चेष्टा की सनिका की छोड़कर यूरोपीय कमचारियों द्वारा वेतनों और पेंशनों के रूप में भारत में और इनड में प्राप्त किए जाने वाले धन की राजि सगणना करने पर सचमुच चौकाने वाली थी यह राजि समभग 15 करोड़ रुपये था अथवा दूसरे शब्दों में भारत सरकार के कुल राजस्व का लगभग 30 प्रतिशत थी नीरोजी स्पीचज प० 134 परिशिष्ट प० 6 89 90, मालवीय स्पीचेज प० 232 3 248 515-6 राय पावर्टी प० 325 6 ए० नदी इंडियन पारिटिक्स प 124 वाचा सी० पी ए० प० 607 एत० एन० बनर्जी सी० पी० ए० प 711 दत्त इ० एच० I पृ० XIII, 427 पादटिप्पणी और देखिए गोयले, स्पीचेज प० 118 7 8

110 मसानी पूर्वोद्धत, पृ० 316 पर दादाभाई नीरोजी और देखिए नीरोजी पावर्टी पृ० 142 200-01 203 574-6 स्पीचेज पृ० 115 6 120 361 378 527 529-30 परिशिष्ट, प० 6 26 लॉन इंडियन सोसाइटी द्वारा 14 जून 1898 को पारित प्रस्ताव प० 25 ए० बी० पी० 4 9 जून 1900 28 मार्च 1901





- 124 देखिए पीछे अध्याय 2 जी० ए० अम्बर, ई० एच०, पृ० 85 एम० एन० बनर्जी, सी० पी० ए० पृ० 709
- 125 देखिए पीछे अध्याय 3
- 126 देखिए पीछे अध्याय 12
- 127 केलान पूर्वोद्धत प० 127 तथा देखिए ज० सी० गायत्री 'रानाडज वक एज ऐन इकोनामिस्ट' इंडियन जर्नल आफ इकोनामिक्स जन० 1942 पृष्ठ XXII स० 3 प० 308
- 128 रानाडे एतज पृ० 186 7
- 129 देखें ऊपर
- 130 ज० पी० ए० ए० जुलाई 1881 (खंड IV स० I) पृ० 16
- 131 आई० एन० सी० 1896 और 1897 के प्रस्ताव VII और XI क्रमशः
- 132 ज० बी० जोशी पूर्वोद्धत पृ० 640 683 793-4 गोखले स्पाचेज, पृ० 15 87 8 908 10 और दिनवी कमीशन पृष्ठ III प्रथम 18169 84 1905 तक गोखले के विचार बड़ ही सकोज पूर्वक प्रस्तुत किए गए थे (स्पाचेज पृ० 15 87 8 908 10) परंतु 1905 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने दृढ़तापूर्वक घोषणा की कि अनेक वर्षों में देश से संपत्ति की भारी और विनाशकारी निवासी श्रद्ध आयाता पर निर्धारित की अधिकता के (कोश सहित) रूप में घट रही है पिछले चालीस वर्षों में हुई इस निवासी की राशि 1 अरब स्टर्लिंग पी० स कम नहीं होगी (सी० पी० ए० प० 844)
- 133 निवासीवाद के प्रारंभिक खंडों में एक था जान स्ट्रुची का प्रयास जो उन्होंने 1878 के वित्तीय विवरण में तथा 1880 के रिपोर्ट आफ दि इंडियन फर्मीन कमीशन भाग VIII कडिका-4 में प्रस्तुत किया था विस्तृत खण्ड सवप्रथम 1911 में ही देखने का मिला जो वियोडार मारिसन की पुस्तक दि इकोनामिक ट्रांजीशन इन इंडिया से (सदन 1911) (1916 का पुन मद्रण) अध्याय 7 और 10 में उपलब्ध है
- 134 एल० सी० ए० नोल्स दि इकोनामिक डेवलपमेंट आफ दि ब्रिटिश ओवरसीज एंपायर (सदन 1928) पृ० 392 3 ऐंस्ट पूर्वोद्धत, पृ० 509 11 तथा देखिए जी० फिन्ल शिरास पावर्टी एंड किंडड इकोनामिक प्रान्सेस इन इंडिया (भारत सरकार 1915 तृतीय संस्करण)
- 135 कडिका 52
- 136 मारिसन पूर्वोद्धत प० 193 और देखिए जिसकी पूर्वोद्धत पृष्ठ 397 नोल्स पूर्वोद्धत प० 392 3 केवल जा डी० सी० में तथ्यों की उपेक्षा की और दृढ़तापूर्वक कहा जो कुछ भी बाहर जाता है उस सबका मूल्य चुनाया जाता है और उपभोग की ऐसी सभी वस्तुएं, उदाहरणार्थ मृत्ती सामान और साजा चादी जो कि देश की सर्वाधिक मालों हैं कल्पना कीजिए कि भारत व्यापक परिमाण में अपना निर्यात बंद कर देता है इसका पक्षस्वरूप उसे सभी अनुपात में भुगतान भी कम मिलेगा और तदनुसार उसकी जनता दुखी होगी वस्तुएं बढ़ने में लिया गया सामान अथवा पसा जनता का ही मिलना है न कि सरकार को (पूर्वोद्धत प० 302)
- 137 मारिसन पूर्वोद्धत प० 188 92 नोल्स पूर्वोद्धत प० 392 एम्ने पूर्वोद्धत प० 333 जी० एफ० शिरास पूर्वोद्धत प० 25
- 138 मारिसन पूर्वोद्धत प० 184-6 200-02 नोल्स पूर्वोद्धत प० 392
- 139 कज्जन् स्पाचेज III प० 388 रास पूर्वोद्धत प० 302 यहा तक कि नोल्स का भी अनुमान था कि निवासीवाद के समीक्षकों द्वारा सगणित निर्यातों की अधिकता में सोने चानी व आयात



नहीं है तथा ई० ला एल० सी० पी० 1904 खड XLIII पृ० 538

- 155 नोरोजी स्पाचेज पृ० 320-1, 666
- 156 देखिए पीछ अध्याय 3 नोरोजी पावर्टी, प० 33-4 38 566-9 स्पीचेज प० 133 319 322 615 परिशिष्ट, प० 3 78, 55-6 जो० एस० अय्यर ई० ए० प० 127 8, गोखल विलवी कमीशन खड III प्रश्न 18169, 18183 4
- 157 देखिए पीछे अध्याय 5
- 158 देखिए पीछ अध्याय 3
- 159 दक्षिण अध्याय 5
- 160 दक्षिण अध्याय 3 5
- 161 दक्षिण अध्याय 3 8
- 162 देखिए अध्याय 3
- 163 वहा , 3
- 164 वही
- 165 नोरोजी पावर्टी प० 37, 131 2 136 पादटिप्पणी 141 568 9 574 स्पाचेज प० 382 3, मराठा 25 मई 1884 'यू इंडिया सितंबर 1902 और पीछ अध्याय 4
- 166 नोरोजी पावर्टी प० 3-4 565 स्पीचेज प० 133 319 596 दत्त ई० एच II प० 375
- 167 नोरोजी पूर्वोक्त प० 87 746 इंडियन स्पष्टदर 26 अक्टूबर 1884 मराठा 9 अगस्त 1885 जबकि हम पहले ही निर्देश कर चुके हैं 1860 के जासपास तक तो दादा भाई भी रेन पया के निर्माण के लिए विशेषों से ऋण लेने के पक्ष में थे (एसेज प० 124 6, 132)
- 168 नोरोजी स्पीचेज प० 319 दत्त ई० एच II प० XV जो० एस० अय्यर ई० ए० प० 353
- 169 नोरोजा स्पीचेज पृ० 319 20 दत्त ई० एच० I प० 398 9 406-09 ई० एच० II प० XV XVI 215 20 373 5 604, एक दूसरे सम्म भ भी भारतीयों ने निर्देश दिया कि भारतीयों के रक्त और धन के मुख्य पर ही भारतीय साम्राज्य हविष्या गवा है नोरोजी पावर्टी पृ० 567 640 स्पीचेज 221 2 गोखले स्पीचेज प० 1207 दत्त ई० एच० I पृ० 399
- 170 नोरोजी स्पीचेज पृ० 319-20 गोखल स्पीचेज प० 1205-06 दत्त, ई० एच० II प० XV XVI 604 और देखिए अध्याय XII सनिक् व्यय सबधो भाग
- 171 नोरोजी स्पीचेज प० 320-1
- 172 नोरोजा पावर्टी पृ० 35 37
- 173 दक्षिण पाछे पादटिप्पणी 67
- 174 नोरोजी पावर्टी पृ० 565
- 175 विशयनया देखिए नोरोजी स्पीचेज परिशिष्ट प० 42 3 54
- 176 नोरोजा स्पीचेज प० 196 7 395 और आग 484 5 496 7 506. परिशिष्ट प० 6, 25 32 47 73 171 2 गोखले स्पीचेज प० 908-09 1866 के प्रारम्भ दादाभाई ने 'यूरोपियन ऐंड एशियाटिक रमस' शीर्षक से एक सच लिखा। इस सच का उद्देश्य यह सिमाना था कि भारत और एशिया के लोगों में भी युरोप के लोगों के समान हा ऊंची नतिवता और उच्च स्तर की प्रतिभा है (स्पीचेज पृ० 535 और आग)
- 177 नोरोजा स्पीचेज परिशिष्ट पृ० 47
- 178 गोखले स्पीचेज पृ० 62.

सम्मिलित नहीं थे

- 140 मोरिसन पूर्वोद्धत पृ० 223
- 141 स्ट्रुची फार्मलाना स्टेटमेंट 1878 कडिका 52 रिपोर्ट आफ दि इंडियन फर्मीन कमिशन 1880 भाग VIII कडिका-4 चिमनी पूर्वोद्धत पृ० 397 स्ट्रुची इंडिया (1903) पृ० 195 6 235 6 रोस पूर्वोद्धत पृ० 80 124 289 302 मोरिसन पूर्वोद्धत, पृ० 205 तथा था, 218 222 नोल्स पूर्वोद्धत पृ० 392 ऐंस्टे पूर्वोद्धत, पृ० 509, जॉ० एफ० गिराम पूर्वोद्धत, पृ० 23 4
- 142 मोरिसन पूर्वोद्धत पृ० 224 ऐंस्टे, पूर्वोद्धत पृ० 509 जॉ० एफ० गिराम पूर्वोद्धत पृ० 23-4
- 143 रोस पूर्वोद्धत पृ० 302 मोरिसन पूर्वोद्धत, पृ० 239-41 ऐंस्टे पूर्वोद्धत, पृ० 509-11
- 144 मोरिसन पूर्वोद्धत पृ० 239 40 तथा दक्षिण जॉ० एफ० गिराम पूर्वोद्धत, पृ० 24
- 145 मोरिसन पूर्वोद्धत पृ० 241 तथा नैग्रिण ऐंस्टे पूर्वोद्धत, पृ० 510
- 146 चिमनी पूर्वोद्धत पृ० 397 स्ट्रुची इंडिया (1903) पृ० 194 रोस, पूर्वोद्धत पृ० 289 302 मोरिसन पूर्वोद्धत पृ० 183 204 16 जॉ० एफ० गिराम पूर्वोद्धत पृ० 22 24
- 147 मोरिसन पूर्वोद्धत पृ० 205 229
- 148 वही पृ० 235 6 स्ट्रुची इंडिया (1903) पृ० 236
- 149 स्ट्रुची फार्मलाना स्टेटमेंट 1878 कडिका 52 रिपोर्ट आफ दि इंडियन फर्मीन कमिशन 1880 भाग VIII कडिका 4, चिमनी पूर्वोद्धत पृ० 397 8 जॉ० हेमिन्टन हमाड (चौधी सिरीज) पृ० XCIX 1901 पृ० 1213 स्ट्रुची इंडिया (1903) पृ० 192 5 इपीरियन गवर्नर आफ इंडिया (1908) पृ० 194 मोरिसन पूर्वोद्धत पृ० 237 वी० लावेट पूर्वोद्धत पृ० 236 नोल्स पूर्वोद्धत पृ० 392 ऐंस्टे पूर्वोद्धत पृ० 510 जॉ० एफ० गिराम पूर्वोद्धत पृ० 23 निवामीवाद का पीछे धारणकर्ता का यह विश्वास काम कर रहा था कि राजनीतिक विकास के बिना सामाजिक है प्रत्युत अपरिहार्य भी है इस प्रकार चिमनी ने 1893 में दस्तावेज कहा कि यद्यपि यह प्रसार और यूरोपीय कमचारिया द्वारा अपनी स्वतंत्रता को इंग्लैंड ले जाना था व अथ व रूप में गचमुच ही घन की निवामी थी परंतु इसका लिए शिक्षा देना पूरुष ही था क्योंकि इसका अर्थ तो यह अनमान लगाना होगा कि प्रगति अधिकाधिक द्वारा संचालित प्रगति प्रशासन के अभाव में भारत अपने आप आंतरिक शांति और सुरक्षा प्राप्त कर लता तो लोग इस विश्वास के पीछे जिसे धुंधलक आधार का भी बलना करते हैं एसा लगना है कि उक्त भारत के इतिहास की और भारतीय लोगों की माध्याय भी भी जानकारी नहीं है (पूर्वोद्धत पृ० 398) तथा दक्षिण स्ट्रुची इंडिया (1903) पृ० 194 5
- 150 मोरिसन पूर्वोद्धत पृ० 237
- 151 वही पृ० 241
- 152 नोरोजी एमेज पृ० 36 85 889 101 112-4 स्पेचेज पृ० 665
- 153 नोरोजी एमेज पृ० 101 113 पावर्टी पृ० 33 137 568 9 स्पेचेज पृ० 382 3 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 618 638 9 जॉ० एफ० अय्यर ई० ए० पृ० 339 353 गोखले स्पेचेज, पृ० 87 8
- 154 नोरोजी स्पेचेज पृ० 320-1 382 666 और देखिए नोरोजी पावर्टी पृ० 131 138 196 तथा आगे ऐंस्टे पूर्वोद्धत पृ० 333 की पादटिप्पणी में ध्यान देने की बात है कि आयात की आधुनिक नीति में माल भाड़ा सम्मिलित है परंतु निर्गत के घोषित मूल्य में यह सम्मिलित

नहा है तथा ई० सा, एल० सी० पी० 1904 पृष्ठ XLIII पृ० 538

- 155 नौराजी स्पाचज पृ० 320-1, 666
- 156 दक्षिण पीछे अध्याय 3 नौराजी पावर्टी, प० 33-4 38 566-9 स्पाचज प० 133 319, 322, 615, परिशिष्ट पृ० 3 7 8 55-6 जी० एल० डब्ल्यू ई० ए० प० 127 8 गोखल, विलवो बमगन पृष्ठ III प्रश्न 18169, 18183 4
- 157 दक्षिण पीछे अध्याय 5
- 158 दक्षिण पीछे अध्याय 3
- 159 दक्षिण अध्याय 5
- 160 दक्षिण अध्याय 3 5
- 161 दक्षिण अध्याय 3 8
- 162 दक्षिण अध्याय 3
- 163 बहा , 3
- 164 बहा
- 165 नौराजा पावर्टी, प० 37 131 2, 136 पादटिप्पणी, 141 568 9 574 स्पाचेज प० 382 3, मगटा 25 मई 1884 यू इंडिया सितंबर 1902 और पीछे अध्याय 4
- 166 नौराजी पावर्टी पृ० 3-4 465 स्पाचेज प० 133 319 596 दत्त ई० एच II पृ० 375
- 167 नौराजा पूर्वोच्यत पृ० 87 746 इंडियन स्पेक्टर 26 अक्टूबर 1884 मराठा 9 अगस्त 1885 जगदीश हम पहले ही निर्देश कर चुके हैं 1860 के आसपास तक तो धाना भाइ भी रेल पथा व निर्माण व लिए विन्शा से ऋण लेने व पण म थ (एलेज प० 124 6 132)
- 168 नौराजी स्पीचज प० 319 दत्त ई० एच II प० XV जा० एम० डब्ल्यू ई० ए० प० 353
- 169 नौराजा स्पीचेज प० 319 20 दत्त ई० एच० I प० 399 9 406 09 ई० एच० II प० XV XVI 215 20, 373 5 604 एन दूसरे सन्ध मे भी भारतीयो न निर्देश किया कि भारतया व रवन और धन के मूय पर ही भारतीय साधाय हथियाया गया है नौराजी पावर्टी प० 567 640 स्पीचज 221 2 गखले स्पाचज प० 1207 दत्त ई० एच० I प० 399
- 170 नौराजा स्पाचज पृ० 319-20 गोखले स्पीचेज प 1205-06 दत्त ई० एच० II प XV XVI 604 और देखिए अध्याय XII सत्रिक यय सबधी भाग
- 171 नौराजी स्पीचज प० 320-1
- 172 नौराजा पावर्टी प० 35 37
- 173 दक्षिण पीछे पादटिप्पणी 67
- 174 नौराजी पावर्टी प० 565
- 175 विगपनया देखिए नौराजी, स्पीचेज परिशिष्ट प० 42 3 54
- 176 नौराजा स्पीचज प० 196 7 395 और आग 484 5 496 7 506 परिशिष्ट प० 6 25 32 47 73 171 2 गोखल स्पीचज पृ० 908-09 1876 के प्रारम्भ दादाभाई ने दि यूरोपियन एंड एशियाटिक रसेम' शीपक स एक लेख लिखा । इन लेख का उद्देश्य यह सिखाना था कि भारत और एशिया के लोधा म भी यूरोप के लोगों के समान ही उची नविकता और उच्च स्तर की प्रतिभा है (स्पीचज प० 535 और आग)
- 177 नौराजी स्पीचेज परिशिष्ट, पृ० 47
- 178 गोखले स्पीचेज पृ० 62

632 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदभव और विकास

- 179 देखिए पीछे अध्याय 2  
 180 देखिए पीछे अध्याय 12  
 181 आगे देखिए  
 182 जोशी पूर्वोद्धृत पृ० 640 1 वाचा सी० पी० ए०, पृ० 605 गोखले स्पीचज पृ० 908  
 183 नौरोजी पावर्टी पृ० 227 स्पीचज पृ० 134  
 184 नौरोजा पावर्टी पृ० 52 3 तथा देखिए वाचा सा० पी० ए० पृ० 607  
 185 गोखले स्पीचज पृ० 1188 और देखिए उदाहरण के लिए नौरोजी एसज पृ० 123 374,  
 पावर्टी पृ० 56 8 203 05 225 631 स्पीचज पृ० 134 परिशिष्ट पृ० 171 सी० शकरन  
 नायर सी० पी० ए० पृ० 388 9 गोखले स्पीचज पृ० 120  
 186 नौरोजी पावर्टी पृ० 33  
 187 उदाहरण के लिए देखिए नौरोजी स्पीचज पृ० 316 7 319 329 361, 378  
 188 वही पृ० 339  
 189 वही पृ० 322 और देखिए पृ० 668  
 190 वही परिशिष्ट पृ० 3 यहाँ यह उल्लेखनाय है कि कितन ही और भारतीय नेताओं ने भी इ  
 बात पर ध्यान दिया था कि निवासी के मूल कारण राजनीतिक ही हैं देखिए जोशी पूर्वोद्धृत  
 पृ० 683 राय पावर्टी पृ० 7 242 गोखले स्पीचज पृ० 15  
 191 नौरोजी पावर्टी पृ० 212  
 192 वही पृ० 211 2  
 193 वही पृ० 224  
 194 वही पृ० 225  
 195 वही पृ० 224-5 31 जनवरी 1901 को लंदन के थोनाओ को संबोधित करते हुए उन्होंने  
 दोहराया जिस ढंग से तुम जीवन और संपत्ति की रक्षा दूसरा के द्वारा की जाने वाला  
 हुआ है वही तुम हो उसका वास्तविक रूप यह है कि तुम संपत्ति की रक्षा इसलिए करते हो  
 एसा करना दुख न होता तो जिनकी मज्जाक हो जाती है। जरा आख उठा कर भारत के  
 करोड़ों आत्मियों को देखिए ता सही जो दिन प्रति दिन वष प्रतिवष थोड़ी फमन के  
 अभावप्रस्त जीवन जितान और दुख भागन को विवश हैं (स्पीचज पृ० 228)  
 196 नौरोजी स्पीचज पृ० 389  
 197 नौरोजा स्पीचज पृ० 125  
 198 नौरोजी स्पीचज पृ० 153  
 199 वही, पृ० 153-4  
 200 वही पृ० 400 पृ० 387 भी देखिए  
 201 वही, पृ० 328  
 202 वही पृ० 329  
 203 इंडिया 2 सितंबर 1904 उदाहरण व्यंग्यपूर्वक टिप्पणी की ब्रिटिश इस देश से संपन्न  
 जाते हैं। अब जब देश में फमन कम होती है लाखा करोड़ों मूख से मर जाते हैं  
 ब्रिटिश प्रशासन ने अपनी उदार लोकजीविकारी प्रवृत्ति का यह प्रमाण दिया है।  
 04 नौरोजी, स्पीचज परिशिष्ट पृ० 29 और देखिए वही परिशिष्ट पृ० 45 2'

- सी० पी० ए० प० 158 उहनि फिर भी निवासी के मामले में ब्रिटिश जाग और ब्रिटिश सत्त के निर्णय बताया परंतु ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों भारत और ब्रिटिश सरकार के साथ सचिव को पूरी तरह दोषी सिद्ध किया (वही परिशिष्ट, प० 58-60)
- 205 उदाहरण के लिए देखिए, नौराजी पावर्टी प० 227
- 206 नौराजी, स्पीचेज़, पृ० 120
- 207 वही परिशिष्ट प० 74 और देखिए वही परिशिष्ट प० 43, 75
- 208 नौराजी पावर्टी प० 218 तथा प० 216
- 209 नौराजी, स्पीचेज़ पृ० 334 उहने निखा भारतीयों का प्यार ही एक एमी सुदृढ़ आधार शिष्टा है जिस पर विदेशी धार्मिक मजबूती और निरतस्ता के साथ खड़ा हो सकता है क्योंकि वह एक निरमल की तरह ब्रिद्धर जाणगा (वही, पृ० 332)
- 210 वही प० 368
- 211 नौराजी सी० पी० ए० पृ० 3
- 212 नौराजी, स्पीचेज़, पृ० 392
- 213 वही प० 223
- 214 नौराजी पावर्टी पृ० 659
- 215 उदाहरण के लिए देखिए नौराजी, स्पीचेज़, परिशिष्ट प० 21 2 25 6
- 216 इटिया, 2 सितंबर 1904
- 217 नौराजी स्वाचन, पृ० 671 इही भावों को दादाभाई ने इससे पूर्व नवंबर 1903 में उस समय भा अनिव्यक्त किया था जब उहने हिन्दुस्तान रिव्यू और श्वासस्थ समाचार को भेज गए अपन सन्ध में ब्रिटिश सर्वोच्चता के अतगत स्वशासन अथवा स्वराज्य की मांग की थी। (एच० आर० नवंबर 1903 पृ० 474)
- 218 नौराजी सी० पी० ए० पृ० 863 तथा देखिए प० 883 886
- 219 देखिए 1890 के प्रथम औद्योगिक सम्मेलन में उनका उद्घाटन भाषण एसेज प० 180-94 और देखिए वही प० 119 20
- 220 उदाहरणार्थ 1858 के आरम में महारानी की घोषणा में यह कहा गया था भारत के शांति पूर्ण उद्योग को प्रोत्साहन देना हमारी हार्थिक अभिलाषा है इफरिन ने अपना मुपनिद्ध सेंट्रल एंडमूज भाषण में घोषणा की कि भारत की अरिद्रता को दूर करने के दो ही उपचार हैं उत्पादक उद्योगों का विस्तार और उत्पवास (स्पीचेज़ प० 242) बज्ज ने भी 1903 में बकरान की कि जब से भारत में हू जिन विषयों ने मेरा सन्ध ध्यान आकृष्ट किया है उनमें प्रथम है भारत की औद्योगिक गतिविधि का विकास मेरी दृष्टि में इस पर भारत को भावी आशा निभर है (स्पीचेज़ II पृ० 114) और देखिए वही प० 117 133 139-41 और देखिए जो एस० अथर ई० ए० प० 101-02
- 221 रिपोर्ट आफ दि इंडियन इंडस्ट्रियल कमिशन पूर्वोद्धत 1916-18 पृ 75 8 105 07 ऐल् पूर्वोद्धत प० 210 3 'यायमृति राताडे ने 1890 में घोषणा की यह ठीक है कि सन्ध सहायता कर सकती है परंतु नगण्य रूप से आरंभिक कार्य में नेतृत्व दीजिए सरकार हमारी सहायता को उत्सुक है (एसेज प० 190)
- 222 ऐल् पूर्वोद्धत पृ० 216-26
- 223 राताडे तब ने घोषणा की कि औद्योगिक सत्त में शासकों और शासितों के हितों में किसी प्रकार



का कोई सघन नहीं दोनों ही समान रूप से दश की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति को अग्रसर करने की इच्छा है (एसज प० 180) और देखिए वही, प० 181 190

- 224 रानाड एसेज प० 187 188 193-4 ए० एस० मुदालियर रिप० आर्क० एन० सी०, 1886 प० 65 और पाछे अध्याय 2 तुलनीय जे० सी० गोजाजी रानाडेज बस एज ऐन इरानोमिस्ट्स इंडियन जर्नल आफ इकोनामिक्स जनवरी 1942 खंड XII अध्याय 3 प० 307 16
- 225 रानाड एसेज प० 119-20 187 190-4 जोशा पूर्वोद्धृत प० 805 806 814 और पीछ अध्याय 2
- 226 डफरिन स्पीचेज प० 242 और देखिए कर्जन स्पीचेज III प० 139-41 फिरोजशाह मल्ता खुले तौर पर यूरोपियो पर यह आरोप लगाया की सीमा तक बढ़ गए कि वे औद्योगिक विकास के आन्दोलन का उपयोग भारतीयों की राजनीतिक आन्दोलन से विमुक्त करन के एक साधन के रूप में कर रहे थे (स्पीचेज प० 817) इससे पूज्य माच 1904 में कर्जन यह घोषित कर चके थे कि मैं नहीं समझता कि भारत के विकास के वर्तमान स्तर पर राजनीतिक क्षेत्र में मुक्ति की मांग का कोई औचित्य है ? (स्पीचेज II प० 49)
- 227 आई० एन० सा० 1901 का प्रस्ताव XVI
- 228 आई० एन० सी० 1902 का प्रस्ताव II और 1904 का प्रस्ताव III
- 229 आर० पी० पराजपे 'गोखले के राजनीतिक कार्यक्रम के नरम साधनों का विशेषण निम्न-निहित रूप से किया है उनका यह धारणा थी कि ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत और विश्व में अपना समुचित स्थान पान के लिए 9 10 भाग का कार्य तो भारत में और स्वयं भारतीयों को ही पूरा करना है कार्य के इस बड़े ध्रुव के सपने हो जान पर विदेशी शासन की नीकरशाही के कारण स्वाभाविक धाडी बहुत कठिनाइयाँ का जाना स्वाभाविक ही है परंतु उन्हें दूर करने में बहुत समय नहाने लगना पराजपे ने आगे यह टिप्पणी ठीक ही की कि अपनी सुटियाँ के इतने गहरे ज्ञान का जय यह बनापि नहाने कि जनता के सामने गया पाठ पाठ कर अपन को बुद्धि पापित करने और दूसरा की दृष्टि में नीचे गिरो जापालकृष्ण गोखले (पूना 1915 द्वितीय सस्करण) प० 34 यहा जस्टिस रानाड के स्तुलित राजनीतिक दृष्टिकोण की परिभाषा को जानना भी राधा होगा 1896 में उन्होंने लिखा उपयुक्तता का अर्थ है कि असभव के पीछे भटकन का दम न करना अथवा दुष्प्राप्य की कामना न करना प्रत्युत समझौता और औचित्य की भावना से यथासभव हस्तगत हो सकने वाले लक्ष्य के प्रति स्वाभाविक विकास के रूप में प्रतिबन्धित एक एक पथ कायम करना आर्थिक क्षेत्र में जनता की घोर दरिद्रता का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के उपरांत रानाड ने लिखा हा यह वस्तुस्थिति कल की तो है नहीं और न ही यह विदेशी विजय और प्रतियोगिता का एकमात्र परिणाम है यह तो पुराना और बहुत पुरानी परंपरागत स्थिति है (एसज प० 182)
- 230 मसानी पूर्वोद्धृत प 414 पर
- 231 वही प० 523
- 232 वस्तुतः दादाभाई और पत्रिका दोनों इस निष्कर्ष से सन्तुष्ट न करने पर यह मानने को प्रस्तुत थे कि भारत में भूमि लगान काफी बहुत ऊँच बढ़ गई नही प (नीरंजी स्पीचेज परिशिष्ट प० 52 और ए० बी० पा० 1 जून 1900) पत्रिका ने 18 अक्टूबर 1900 के प्रश्न में भी निर्देश किया कि निष्कर्षों से प्रस्तुत तथ्य के अंतर्गत भूगतान करने के लिए अतत धन की उगाही तो

करनी ही है। यदि भूमि लगान पटाए गए तो देश को किसी और मद स धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी

- 233 उसने इस बात पर भी ध्यान दिया कि दत्त भूमि लगान पर आवश्यकता से अधिक बल देने की अपनी पूर्व स्थिति से बदल चुके हैं और अब भारत को निधन बनाने के लिए निकासी और उद्योग व अभाव पर भी बराबर आरोप लगाने लग हैं
- 234 उदाहरणार्थ, दादाभाई ने 1887 में वाचा को लिखा विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व के सुधार मात्र से तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक साथ में निकासी को बदलने के अत्याय सुधार नहीं अपनाए जाते (मसाली पूर्वोद्धृत, पृ० 316 पर) तथा दक्षिण नौरोजी स्पेचिज पृ० 361
- 235 26 जनवरी 1886 को खजाने को लिखा गया पत्र, जो स० 26 दिनांक 28 जनवरी के डिस्पच आफ सत्रटरी आफ स्टेट टु गवर्नमेंट आफ इंडिया (फाइनाल) में सलग्नक क्रमांक 2 के रूप में भजा गया
- 236 रीस पूर्वोद्धृत पृ० 288
- 237 उदाहरण व रूप में दिसंबर 1881 में बंगाल मगजान ने लिखा इस प्रकार की जगली बात चीत से आमान दादाभाई का क्या अभिप्राय है? राजस्व को जिस हानि पर दादाभाई विलाप करते हैं तभी एक सक्ती है जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तथा स्वयं भारतीयों द्वारा ही प्रशासित होगा परंतु वह दिन आने वाला नहीं है और बहुत देर तक आने वाला नहीं है अतः विन्शिया द्वारा दश व साधना व उपभोग किए जाने की बात करना भ्रमना ही है (पृ० 177-8) और दक्षिण 'यू इंडिया', 7 अप्रैल 1902
- 238 उदाहरण व लिए दक्षिण नौरोजी स्पेचिज परिशिष्ट पृ० 77-8
- 239 1903 में जे० डाली रीस ने लिखा यह सत्य है कि ब्रिटिश राज्य में विश्वास की दृढ़ता के कारण दादाभाई बहुत से अभियोगों से बच निकलते हैं परंतु इस कथन को केवल न्याय फ्रांसासी उचित के समान ही समझा जा सकता है हमारे दुर्भाग्य हमें खाने न जाए उससे पहले ही हमें उह खा जाना चाहिए (पूर्वोद्धृत पृ० 238)

## भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था

सिद्धांत केवल व्यवहार का व्यापक रूप है और समीवर्ती कारणों के सदर्भ में सिद्धांत का अध्ययन ही व्यवहार है।

जस्टिस रानाडे

समाज की प्रचलित परिस्थितियां तथा इसके भावी और समकालीन हित के संबन्ध में व्याप्त मायताएं उन आर्थिक धारणाओं के निर्धारक तत्व हैं जिन्हें चिंतकों का अनुमोदन और राजनीतिज्ञों की स्वीकृति प्राप्त रहती है।

जी० मुन्शरण्य ऐयर

हमारे अध्ययन के अन्तर्गत अर्थात् मे कुठ एक भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने 'भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था की धारणा का जन्म दिया। 1892 में दक्कन कालेज पूना में 'भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर अपने प्रतिष्ठित भाषण में जस्टिस रानाडे ने इस विषय का समग्र और पूर्ण रूप में वैज्ञानिक विदोषण प्रस्तुत किया।<sup>1</sup> भारतीय अर्थशास्त्र के इतिहास में उनके मूल सिद्धांत अत्यन्त प्रसिद्ध हैं, अतः यहाँ उनके विस्तृत विवरण देने की आवश्यकता नहीं। परन्तु जो बात इतनी अच्छी तरह विदित नहीं है वह यह है कि उनके सिद्धांतों का कितना व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय नेताओं में मायता प्राप्त थी। इस विषय पर रानाडे के विचारों का हम यहाँ नीचे संक्षेप में विवेचन करेंगे

कनासिकी राजनीतिक अर्थव्यवस्था को सभी समयों में और सभी स्थानों पर, सावदेशिक रूप से समग्र रूप और प्रमाण रूप से तथा आर्थिक विनाश के सभी स्तरों पर सही मानने का दावा वास्तविकता से कौमो दूर था। क्लामिकी अर्थव्यवस्था का आधार वे प्रकटपनाएँ थीं, जिन्हें सावदेशिक रूप में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता था। वस्तुतः इंग्लैंड की विनोप परिस्थितियाँ ही उनके जन्म के लिए उत्तरदायी थीं अथवा वे उम्र समय के किसी भी समाज के लिए अनुरूप कदापि नहीं थीं।<sup>2</sup> विनोपन भारत जैसा पिछड़े अप्रगतिशील तथा वृषि प्रधान देश के लिए तो, जिसमें प्रतियोगिता के बन्ले यथास्थिति और रस्मों रिवाज ही हावी रहते हैं उनकी शायद ही कोई उपयोगिता थी। द्वितीय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के अनीत में व्यवहार और अर्थ देशों द्वारा किए जा रहे समकालीन

व्यवहार क्लासिकी अथव्यवस्था की मायताओं अथवा प्रकल्पनाओं की कदापि पुष्टि नहीं करन थे।<sup>9</sup> वस्तुस्थिति तो यह थी कि ब्रिटिश सरकार ने रला को प्रतिभूति देत हुए बागान उद्योग का सहायता देते हुए अथवा भूमि पर राज्य स्वामित्व का दावा करते हुए अथवा कानून के द्वारा किसानों की क्षुद्र सम्पत्ति की रक्षा करत हुए इन सिद्धांतों का कठोरता से पालन नहीं किया था।<sup>10</sup> ततीय, क्लासिकी अथशास्त्रियों के दावा के आगे यूरोपीय और अमेरिकन अथशास्त्रियों ने प्रश्न चिह्न लगा दिया था।<sup>11</sup> ग्रहा तक कि उन पर चिन्तन ही अग्रेज अथशास्त्रियों ने भी प्रहार किया था।<sup>12</sup> इसका अतिरिक्त कुछ एक क्लासिकी अथशास्त्री स्वयं अपन आप ही अपन विज्ञान की स्वयंपाकता और समग्रता के दावे को छोड़ने की पूरी चेष्टा कर रहे थे।<sup>13</sup> चतुर्थ क्लासिकी अथशास्त्री अधिक से अधिक निश्चय आर्थिक परिस्थितियों का ही विश्लेषण कर सकते थे परंतु वे गतिशील आर्थिक विकास पर प्रकाश डालने में लगभग असमर्थ थे।<sup>14</sup> इन सब तत्वों का स्पष्ट हुए अपरिहाय निष्पत्त यही निकलता था कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत अथवा नियम भौतिकी और गणित के नियमों के अनुसार अमूर्त तथा सावभौमिक नहीं थे प्रत्युत वे सापेक्ष और ऐतिहासिक दृष्टि से परिस्थिति पर निर्भर तथा इसी से निर्मलते थे। वह समय और स्थान के अनुसार परिवर्तनशील थे।<sup>15</sup> अतः किसी देश की आर्थिक नीतियों के निर्धारण के लिए निर्णायक तत्त्व अमूर्त आर्थिक सिद्धांत न होकर आर्थिक विकास की विशिष्ट अवस्था ही होनी चाहिए।

यहां यह उल्लेखनीय है कि रानाडे ने आर्थिक सिद्धांतों की उपयोगिता तथा अर्थशास्त्र की वैज्ञानिक तत्त्वसंगति को मानने से कभी इनकार नहीं किया।<sup>16</sup> इसके विपरीत उन्होंने अर्थशास्त्र को स्वतः सिद्ध कानूनों की स्थिति को कला का रूप देकर उसका अवमूल्यन करने वालों की विशेष रूप से ही भ्रमना की।<sup>17</sup> वे तो केवल व्यवहारिकता का सुदृढ़ आधार देकर उसे और अधिक सूक्ष्म तथा वैज्ञानिक बनाना चाहते थे।<sup>18</sup> उनका कथन था कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है अतः उसके सिद्धांतों की स्थापना इतिहास के माध्यम से विशिष्ट आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन से ही करनी अपेक्षित है न कि वियोजक रीति के अनुसार, ताकि उन्हें ऐतिहासिक अनुभव, व्यावहारिक निराक्षण तथा सामाजिक यथायथा के साथ निकटता से जोड़ा जा सके। अथवा जैसा कि डी० जी० बर्वे ने लिखा है रानाडे को केवल विस्तृत, समाजशास्त्रीय तथा रचनात्मक आर्थिक दृष्टिकोण ही माय था।<sup>19</sup> 1881 में रानाडे ने स्वतंत्र व्यापार के प्रश्न को समग्र आर्थिक दृष्टिकोण में देखने के लिए तथा प्रश्न के साथ जुड़े राजनतिक तथा सामाजिक तत्वों की उपेक्षा करने के लिए अग्रेज अथशास्त्रियों की तीव्र निंदा की तथा अपना निश्चित मत व्यक्त किया कि यदि राजनतिक आर्थिकता का विद्यालय के अध्यापक की अध्यात्म विद्या से भिन्न रूप में ग्रहण करना है तो आर्थिक पक्ष को जनता के ऊंचे हितों पर आनायास के अधीन ही कर देना चाहिए। वस्तुतः उन्होंने निर्देश किया कि यहाँ कारण है कि तब व्यावहारिक अर्थान् राजनतिक आर्थिकता की दान करत ह्विगुड आर्थिकता की नहीं करते।<sup>20</sup> इस सब में रानाडे क्लासिकी अथशास्त्रियों के व्यवहार के रहे और उन्होंने प्रायः ही आर्थिकता का राजनतिक आर्थिकता के रूप में ही समय आन पर रानाडे की क्लासिकी आर्थिकता की आलोचना में

भारतीय राजनैतिक आर्थिक चिन्तन की आधारशिला रखी। हमारा विश्वास है कि यह विकास प्रमुख रूप से इन दो तत्वों की उपज था (ए) रानाडे का निष्पक्ष, इस विश्वास में उदभूत था कि आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक यथाथ पर अत्यंत निर्भर होने के कारण तथा आर्थिक व्यवहार की प्रतिविधात्मक विशेषता लिए रहने के कारण सापक्षता लिए रहते हैं। इस रूप में क्योंकि भारत के आर्थिक हित और परिस्थितियां इंग्लैंड के आर्थिक हितों और परिस्थितियों से सवथा भिन्न हैं अतः भारत पर लागू होने वाले आर्थिक सिद्धांत भी सवथा भिन्न होने चाहिए।<sup>18</sup> वे तथा अन्य बहुसंख्यक समकालीन राष्ट्रवादियों द्वारा रानाडे के पक्ष और निष्पक्ष की स्वीकृति।

इस प्रकार 1877 में ही के. टी. तलग ने सभी देशों पर राजनैतिक आर्थिकता के सिद्धांतों के समान रूप से लागू न होने के तथ्य के प्रदर्शन के लिए एन. अग्नेज अथशास्त्री टी. ई. कलिफ बेसली को उद्धृत किया।<sup>18</sup> ए. उनका यह भी कथा था कि व्यावहारिक प्रश्नों का निणय करते समय आर्थिक सिद्धांतों के केवल एक तत्व को ही नहीं लिया जा सकता। सामाजिक और राजनैतिक कल्याण के अथ तत्व भी समान रूप में महत्व रखते हैं।<sup>19</sup> दादाभाई ने अपने लेख 'दी पावर्टी ऑफ इंडिया' में यह तक प्रस्तुत किया कि स्वदेशियों द्वारा शासित देशों में राजनैतिक आर्थिकता सही हो सकती है परंतु यह प्रभार और संप्रेषणा की व्यवस्था करने को विदेशी विदेशियों द्वारा शासित देश में कठोरता से इसे लागू नहीं किया जा सकता।<sup>20</sup> पृथ्वीशचंद्र ने भी राजनैतिक आर्थिकता के जन्म सिद्धांतों का लेकर किमी दंग की समाज-शास्त्रीय स्थितियों पर विचार किए बिना ही उन सिद्धांतों को कठोरता से लागू करने की निंदा की। उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में अग्नेज अथशास्त्रियों की आत्मतुष्ट हठधर्मों की गलतियों के प्रमाण के रूप में अमेरिका, आस्ट्रेलिया और यूरोप के महाद्वीपों को उद्धृत किया।<sup>21</sup> जी. वी. जॉर्ज ने आर्थिक सिद्धांत की सीधी चर्चा तो नहीं की परंतु उनके द्वारा राज्य की भूमिका, उ. मुक्त व्यापार, आदि प्रश्नों पर किये गए चिन्तन से रानाडे के मौलिक सिद्धांतिक वाक्यक्रम के प्रति उनकी सहमति और जास्था स्पष्ट सिद्ध हो जाती है। आर. पी. दत्त ने आर्थिकवाद पर विचार प्रकट नहीं किए परंतु उन्होंने इस तथ्य का अवश्य देखा कि जब अग्नेज लागू इंग्लैंड में उ. मुक्त व्यापार के पक्ष में आंदोलन चला रहे थे, उस समय भी इंग्लैंड में प्रवेश करने वाले भारतीय माल पर लगने वाले भारी करा की रिकार्डों, कोडन ब्राइट और रायट पील उपेक्षा ही कर रहे थे। दत्त महोदय ने स्थिति का निष्पक्ष विश्लेषण करने के लिए यूरोपीय अथशास्त्रियों की प्रशंसा की जिन्होंने अग्नेज राजनीतियों के इंग्लैंड और भारत में चरत जाने वाले दोगले व्यवहार की निन्दा की।<sup>22</sup>

यद्यपि वे स्पष्ट रूप से ही रानाडे के चरण चिह्न का अनुकरण कर रहे थे तथापि उनका इस प्रश्न से संबंधित विवेचन ऐतिहासिक महत्ता लिए हुए है। उ. मुक्त व्यापार के प्रश्न पर विचार करते हुए उन्होंने यह दिखाने के लिए कि किसी देश की आर्थिक नीतियों का निर्धारण उस देश की आवश्यकताओं के सदम में होता है न कि आर्थिक सिद्धांतों के परिप्रेष्य में, जर्मनी और अमेरिका की संरक्षक नीतियों का उद्धृत किया। उन्होंने टिप्पणी की कि उ. मुक्त व्यापार की नीति इंग्लैंड की अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के कारण ही



से अनुरोध किया कि वह घोषणा करे कि वह अपने अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त इंग्लैंड से उधार लेने नहीं जा रही है। निम्न रूप में इस राष्ट्रिय आर्थिकता के निर्माण की बजालत की।<sup>31</sup> विपिनचन्द्र पाल के 'यू इंडिया' न भी अपने 21 अप्रैल 1902 के अर्थ म आर्थिक मिद्धान्तों की सापेक्षता पर विचार किया। इसके अनुसार भारत और अर्थ यूरोपीय दशा की जनता में तथा उन दोनों दशा के सामाजिक संगठन और जलवायु तथा ऐतिहासिक वातावरण में व्यापक भेद है। इसी प्रकार नाना दशा के आर्थिक सिद्धान्तों के सामाजिक मूल कारण भिन्न भिन्न हैं। इसमें यह निम्न प्रकार का कि आर्थिक दृष्टिकोण निम्नी दशा के किसी विशिष्ट समय की विशिष्ट औद्योगिक स्थितियाँ का परिणाम है अतः उनका एक युग में दूसरे युग में तथा एक दशा में दूसरे देश में परिवर्तित तथा भिन्न रूप ग्रहण करना अनिवार्य है।<sup>32</sup> बहुत सारे अर्थ राष्ट्रवादी नेताओं ने भारत में उक्त व्यापार के प्रयोग में लाए जाने से विरुद्ध किए जाने वाले आंदोलन के संग्रह आर्थिक सिद्धान्तों की सापेक्षता की आर सवेत किया।<sup>33</sup>

उपयुक्त बहुत सारे नेता इस सवध में रानाडे से एक विषय में जाग बढ़ गए। व यह समझन और कहने में सफल हो गए कि भारत की स्थितियों की इंग्लैंड में तथा यूरोप और अमेरिका के अर्थ बहुत सारे राष्ट्रों की स्थितियों से भिन्नता का कारण इस दशा का राज-नैतिक परिस्थिति ही थी क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था और वित्त पर विदेशी सत्ता का नियंत्रण था।<sup>34</sup>

## राज्य की भूमिका

क्लासिकी अर्थव्यवस्था का एक पक्ष सरकार की तटस्थता नीति का सिद्धान्त था जिस राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों ने निरंतर और बड़ी प्रबलता के साथ चुनौती दी। उन्होंने इस धारणा को सवधा अस्वीकार कर दिया कि सरकार का कार्यक्षेत्र 'याय और व्यवस्था को बनाए रखने तक सीमित है।<sup>35</sup> उन्होंने इस बात की बजालत की कि राज्य की गतिविधि का क्षेत्र इस प्रकार विस्तृत और व्यापक बनाया जाए कि जिससे उन सभी मामलों में, जिनमें राष्ट्रीय प्रयास की अपेक्षा निजी प्रयास कम प्रभावी हो सकते हैं सरकार हस्तक्षेप कर सके।<sup>36</sup> राज्य को राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय इच्छा के सामूहिक अर्थ के रूप में ही कार्य करना चाहिए।<sup>37</sup> उनका यह और भी बड़ मत था कि पश्चिम के विकसित दशा की अपेक्षा भारत जैसे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश में राज्य द्वारा राष्ट्रीय आर्थिक और औद्योगिक हितों के संरक्षण के रूप में कार्य करने की आवश्यकता अधिक प्रबल थी क्योंकि लागो की बसानुगत दुबलताओं पर काबू पान में राज्य ही सहायक हो सकता है। और यह राज्य का कर्तव्य है कि वह देशवासियों की संशकन विदगिया के मुकाबल हीन स्थिति आर जडता से उभरने में सहायता करे।<sup>38</sup> जी० वी० जोशी ने तो विशेष रूप से यह अनुभव किया कि भारत में राज्य का यह कर्तव्य है कि वह प्रतियोगिता के आर्थिक कानूनों के बठोर प्रवर्तन पर इस प्रकार में नियंत्रण कर और माग प्रदर्शन कर कि जिससे दस्तकारी का आधुनिक उद्योगों में अप्रतिहाय परिवर्तन इस प्रकार में नियमित हो जाए कि उसके फलस्वरूप हान वाली आर्थिक अर्थव्यवस्था और दुर्भाग्य 'यूनतम रह जाए।<sup>39</sup> राज्य के





कथन था कि भारत मे तो स्थिति उसमे सक्थ भिन्न है। यहा ता हिता मे किसी प्रकार वा कोई वगगत सघप नही है, अय स्थानो के समान इस देश मे ता वर्गों म किमी प्रकार की कोई मोटी दरार नही है। यहा हम राज्य से एक वग के विरुद्ध दूसरे वग की सहायता करन अथवा पूजीपति वग के प्रति पक्षपात करने के लिए तो नही कह रह ह। हम तो राज्य से सारे समाज की ही वतमान असहाय स्थिति म उसकी सहायता के लिए निबदन कर रहे ह। भारतीय समाज क सभी वग शक्तिशाली विदेशियो स प्रतियोगिता म पिछड रहे ह और दुखी ह और सभी वग समान रूप स भारत के द्रुत आर्थिक विकास म रुचि रखत है।<sup>44</sup>

राज्य के आर्थिक मामला मे हस्तक्षेप तथा निजी हितो के ऊपर सामुदायिक कल्याण को प्राथमिकता देने के जुड़वें सिद्धांत को आधार मानते हुए भारतीय नताआ न भारत सरकार स माग की कि वह देश के औद्योगिक विकास के लिए प्रत्यक्ष, सुविचारित तथा सुनियमित नीति वा अनुसरण करे क्योंकि उनकी दृष्टि मे देश वा औद्योगिक विकास राष्ट्रीय आर्थिक कल्याण की एक आवश्यक शत थी।<sup>45</sup> उनमे से बहुतो न कृषि वा भी राज्य द्वारा अनेक प्रकार से सहायता दिए जाने की बात कही।<sup>46</sup> रानाडे ने तो इम सिद्धांत को इस रूप मे लिया कि 'राज्य तो सारे समाज वा संरक्षक है और जिस किसी भी क्षेत्र मे दुबल को सबल से बचाने की आवश्यकता हो, राज्य वा उधर प्रवत होना कतय बन जाना है।'<sup>47</sup> उहोने किसानो को सुरक्षित करने और साहवारो को नियमित करने के लिए कानून बनाने का समझन किया।<sup>48</sup> उहाने सपत्ति के और अधिक वायोचित वितरण की भी कवालत की।<sup>49</sup> इसी प्रकार जी० एस० ऐयर न श्रमिका के पक्ष मे राज्य के हस्तक्षेप की इस तक के आधार पर कवालत की कि श्रम और पूजी के असमान सघप मे दुबल की रक्षा करना राज्य वा दायित्व है।<sup>50</sup> यहा यह फिर दोहरा दिया जाए कि बहुत सार ग्रन्थ भारतीयो ने शांतिपूर्वक चल रहे निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानो म सरकारी रक्षण के वा तीव्र विरोध किया।<sup>51</sup>

यहा हम अपने पाठको को सावधान करना चाहते कि कहीं के राष्ट्रवादियो के राज्य द्वारा आर्थिक मामलो मे हस्तक्षेप करने के सैद्धांतिक सुरक्षात्मक पग मे और समाजवादी तथा यहा तक कि लाभ कल्याणकारी राज्य की इच्छा से उद्योग के लिए राजकीय सहायता की माग म, जो कि ही मामलो म स्वयं राज्य द्वारा किसी उद्योग के संचालन वा रूप ले सकती थी,<sup>52</sup> घपला न कर बैठें तथा इस विषय मे सचेत रह। समाजवाद और यहा तक कि सरकारी पूजीवाद की कवालत करन की तो कोई बात ही नही थी ये अर्थशास्त्री ता केवल यही चाहते थे कि सरकार कृषि अधव्यवस्था के औद्योगिक पूजीवादी अधव्यवस्था म सत्रमण के लिए प्रेरणा तथा प्रोत्साहन जुटाए। इस रूप मे य नता लाग केवल यही चाहत थे कि भारत जस पिछडे देश म निजी उद्यम की कमियो की प्रति सरकार कर। रानाडे राज्य की भूमिका मे यही अभिप्राय लत थ, इम तथ्य की पुष्टि उनके लवा, 'नीदरलंड्स इंडिया एंड दी कलचर सिस्टम, आइरन इंडस्ट्री, पायनीयस अटैम्पटस तथा 'इंडस्ट्रियल वा फॅस' के अध्ययन मे सुस्पष्ट हा जाती है।<sup>53</sup> उनकी 1886 की एक अग्र सिद्ध रचना स भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। जहा के एक घोर सामाय रूप से भडारा

ए अपेक्षित सामग्री के लिए सरकारी कारखाना में सभी प्रकार के कुशल उत्पादनोत्त करते हैं,<sup>54</sup> वहाँ के 1886 की वित्त समिति के प्रतिवेदन से भी अपनी असहमति करते हुए सरकार पर जेलो के उत्पादन पर लगे समिति द्वारा प्रस्तावित प्रतिबंधों टाने पर तीव्र आपत्ति करते हैं क्योंकि उनके विचार में इससे सरकारी धन की ता से सरकारी अधिकारियों को प्रतियोगिता में निजी उद्यम का पीछे धकेलने में हानि मिलेगा। उन्होंने विशेष रूप से ही सरकारी काप की सहायता से वाष्प यंत्र, खाना, तनू, बागज, गलीचे आदि बनाने के लिए जेलो का उपयोग करने की आलोकी। दूसरे शब्दों में जिस सामान का उत्पादन निजी उद्यमी कर रहे थे, सरकार द्वारा सामान के उत्पादन के लिए जेलो का उपयोग करने पर आपत्ति की।<sup>55</sup>

जी० बी० जोशी ने सरकारी समाजवाद के अथवा सरकारी पूँजीवाद के किसी भी त्र का और भी अधिक सुदृढता और स्पष्टता से विरोध किया। इस प्रकार उन्होंने ) में लिखा, हमारी योजना निश्चित रूप से ही सरकारी समाजवाद जैसी योजना है उदाहरणार्थ जैसे कि 1848 में अस्थायी सरकार ने घातक और दुभाग्यपूर्ण त्वा के साथ चेष्टा की थी।<sup>56</sup> प्रथम, उन्होंने बार बार दाहराते हुए यह णी की कि राज्य की कायबाही का एकमात्र उद्देश्य शक्तिशाली और उन्नत विदे के साथ साधन हीन भारतीय उद्यमियों के असमान सघष में संतुलन की व्यवस्था है ताकि भारतीय उद्यम का आरम्भ में ही गला न घोट लिया जाए।<sup>57</sup> द्वितीय दृढ मत था कि मूल रूप से औद्योगिक विकास निजी प्रयास का ही कायक्षेत्र तथा ारक्षेत्र है। राज्य की भूमिका तो निजी उद्यमी को स्वतंत्र रूप में दायित्व सभा के योग्य बनाने तक ही सीमित है। ज्यों ही निजी उद्यमी अपने पैरों पर खड़ा हो जाए ी सरकार को उसके मांग से एकदम हट जाना चाहिए। उन स्थिति में राज्य के औद्योगिक क्षेत्र पर एकाधिकार का प्रयत्न करना सर्वथा अनुचित ही होगा।<sup>58</sup> तृतीय, ीय सहायता द्वारा निजी उद्यम का नष्ट करने के लिए राज्य के आन्तमक और ं रूप ग्रहण करने की आशंका को स्वीकार करते हुए उन्होंने उसके क्षेत्र दिशा श्रवधि पर कड़ी सीमाएँ लगाने का प्रस्ताव रखा।<sup>9</sup> अन्तिम, उन्होंने सरकार की त्त के लिए आलोचना की कि वह सिंचाई वन मरुस्थल और तकावी भत्ते जैसे कार्यों पने ही अभिकरणों द्वारा पूरा कर रही है जबकि ये सभी काय इस देश के ही निजी ंयों द्वारा संपन्न किए जाने चाहिए और सरकार को तो केवल इस दिशा में निजी ंयों को प्रशिक्षित और प्रोत्साहित करना चाहिए तथा इन कार्यों के संचालन के लिए ावश्यकता हो तो उपदान देना चाहिए।<sup>60</sup>

-लगान कर अथवा किराया

।य नेताओं द्वारा सरकारी सिद्धांतवादी ढांचे पर आपत्ति किया जाने वाला क्षेत्र राजस्व प्रशासन था। मतभेद के प्रमुख विषय थे, भूमि लगान का स्वरूप और कृषि ार अन्तिम स्वामित्व। भारतीय प्रशासकों का यह व्यापक मत था कि अन्त काल से े भूमि पर राज्य का अन्तिम अधिकार चला जा रहा है। अन्त घटती बान वाले अथवा

जमींदार सरकार के किरायेदार है। फलतः जमींदारों द्वारा सरकार को चुकाया जाने वाला लगान किराया है, वर नहीं।<sup>61</sup> राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों और दमरे नेताओं ने इस धारणा को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया। उनका कथन था कि भारतीय जमींदार अपनी भूमि का ठीक उमी प्रकार स्वामी है, निम्न प्रकार विश्व के किसी अन्य भाग का जमींदार अपनी भूमि का है। उन्होंने इस बात को दृढ़तापूर्वक सामने रखा कि अतीत इतिहास की गलत व्याख्या की जा रही है और यद्यत्क भी भूमि पट्टेदारी में निहित सिद्धांतों की भी अवहलना की जा रही है। अतः उनकी मांग यथा थी कि सरकार द्वारा वसूल किया जाने वाला भूराजस्व एक कर है और सरकार की आवश्यकताओं के लिए उस इस ढंग से वसूल किया जा रहा है, जिस ढंग से विदेशों में वहां की सरकारें करती हैं।<sup>62</sup> यह एक रोचक तथ्य है कि सरकारी प्रवक्ता प्रायः इस बात पर बल देते थे कि ब्रिटिश शासक सारी भूमि पर स्वामित्व का दावा करते हुए केवल देश के भूतपूर्व शासकों का ही अनुकरण कर रहे थे। जी० वी० जोशी ने बल देकर कहा कि यह दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सभी तांत्रिक कठारताओं के साथ भारतीय जीवन के तथ्यों पर पश्चिमी सिद्धांतों को अविचारपूर्वक ही लागू किया जा रहा है।<sup>63</sup>

रानाडे और जोशी जी ने भारतीय पद्धति के भूमि लगान के रिकार्डिंग आधार पर भी प्रहार किया। सरकारी दृष्टिकोण और सिद्धांत के पीछे यह धारणा काम कर रही थी कि भारत में राज्य के किरायेदार अथवा जमींदार पूँजीपति किसान हैं और वह 'आर्थिक किराया' चुकाते हैं।<sup>64</sup> यही बढ़िया भूमि के उत्पादन के और सबसे अधिक घटिया भूमि, जिस जोतकर केवल खचा पूरा होता है, के उत्पादन के बीच का मूल्य संबंधी अंतर है। इस परिभाषा के अनुसार जोत के मूल्य के अतःगत किसान के श्रम के मूल्य के साथ ही साथ लाभ की वर्तमान दर पर उसकी पूँजी का मूल्य भी सम्मिलित था।<sup>65</sup> इससे स्पष्ट था कि किराये के इस सिद्धांत के अनुसार सीमांत भूमि पर उत्पादन मूल्य द्वारा निर्धारित मूल्यों में किसी प्रकार की वृद्धि किए बिना तथा मजदूरी को किसी प्रकार से प्रभावित किए बिना ही राज्य भूमि के स्वामी के रूप में भूमि के आर्थिक किराये को भूराजस्व के तौर पर हड़प सकता था।<sup>66</sup> रानाडे और जोशी ने रिकार्डों के किराये के सिद्धांत के मूल रूप की आलोचना नहीं की परन्तु उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि भारत में इस सिद्धांत की कोई उपयोगिता है। क्लासिकी राजनैतिक अर्थव्यवस्था में पूँजीपति किसान का किराया पूँजी की प्रतियोगिता, जनसंख्या के आकार तथा भूमि की विभिन्न स्तरीय उत्पादन क्षमता द्वारा निर्धारित किया जाता है।<sup>67</sup> रानाडे की आपत्ति यह थी कि क्योंकि राज्य देश में एकमात्र भू-स्वामी बन गया है अतः खेतिहरों का प्रतियोगी मूल्य न देकर एकाधिकार के रूप में मनमाना किराया चुकाना पड़ता है। सरकार मनमाने ढंग से जितना चाहे, किराया बढ़ा सकती है और यह प्रायः खेतिहरों के लाभों और परिश्रम पर छापा मारता है।<sup>68</sup> जोशी जी की इससे और अधिक मौलिक आपत्ति यह थी कि उन्होंने निर्दिष्ट किया कि रिकार्डों के सिद्धांत के अतःगत पूँजीपति किसानों की आवश्यकता है और भारत में पूँजीपति किसानों का अस्तित्व ही नहीं। भारतीय किसान जमींदारों और रैयतवादी दोनों इलाकों में अधिक लाभ से प्रेरित पूँजीपति किसानों की अपेक्षा भूस्वामी

से किराये पर लेकर भूमि जातने वाला ही है। उनके अनुसार स्थिति के दो मौलिक पक्ष हैं (क) खेतिहर का तात्कालिक उद्देश्य आजीविका प्राप्ति है न कि निवेशित पूँजी पर लाभ का अजन करना है। (ख) खेतिहरो में भूमि के लिए प्रबल प्रतियोगिता है। इसके कारण बढ़ती हुई जनसंख्या कमश खेति योग्य खाली भूमि की उत्तरोत्तर अनुपलब्ध तथा कृषि उद्योगों की असफलता आदि हैं। इनके फलस्वरूप किसान क्रूर आर्थिक आवश्यकताओं का शिकार बन गया है और उस शीघ्र ही अपनी भूमि से हाथ धाने तथा भूमिहीन मजदूर बनने के बदले सरकार द्वारा जयवा निजी जमींदार द्वारा निर्धारित मनमाने किराये का भुगतान करने के लिए राजी होना पड़ता है, भले ही उस इसके लिए क्या न सामान्य जीवन के स्तर से भी नीचे का जीवन बिताना पड़े।<sup>69</sup>

रानाडे और जोशी जी ने रिवाडों के किराया सिद्धांत के प्राकृतिक परिणाम अनुपाजित आय के सिद्धांत की भी आलोचना की। इस सिद्धांत के अनुसार, यदि किसी भूखंड पर उस समय तक निवेशित पूँजी पर लाभ की चालू दर से अधिक किराया बढ़ाया जाता है तो दोनों का अंतर किराये में अनुपाजित वृद्धि कहलाएगी, जो लाभ की दर में सामान्य गिरावट का तथा समाज की सामान्य प्रगति का परिणाम होगा। अतः उस पर समाज का ही प्रायोचित अधिकार होगा न कि दूमरा के रक्त को चूमने वाल भूखंड के स्वामी का।<sup>70</sup> रानाडे और जोशी जी का तर्क था कि भारतीय भूमि लगान पद्धति में इस सिद्धांत को लागू करने से समाज, अथव्यवस्था तथा किराया ऊँचे हुए है और जमींदारी व्यवस्था की स्थिति स्थिर हुई है। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं था। इंग्लैंड में जहाँ पीढ़ियों से भूमि एक ही परिवार के हाथ में रहनी आती है, वहाँ भारत में उसके विरुद्ध भूमि का स्वामित्व निरंतर बदलता रहता है। फलतः प्रत्येक नया खरीदार भूमि का पूरा ही चानू मूल्य उपाजित और अनुपाजित दोनों का भुगतान करता है। उस प्रक्रिया में भूतकाल की अनुपाजित आय सवथा लुप्त हो जाती है।<sup>71</sup> इसके अतिरिक्त जोशी जी ने टिप्पणी की कि लगान अधिकारी प्रायः ही अनुपाजित आय की खोज में बलपूर्वक ही वृद्धि करने का रास्ता अपनाते हैं और इस प्रकार बेचारे किसानों की आजीविका का ही हड़प लेते हैं।<sup>7</sup>

### उन्मुक्त व्यापार बनाम संरक्षण

राष्ट्रवादी प्रारंभ से ही उन्मुक्त व्यापार बनाम संरक्षण के प्रश्न में गहरी रुचि रखते थे। 1877 में ही अपने विस्तृत लेख 'फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन, में वे ० टी० तैलंग न एक भारतीय के दृष्टिकोण से टिप्पणी की कि यह विषय हमारे देश के समग्र भविष्य सामाजिक, राजनैतिक व औद्योगिक के साथ इतनी घनिष्टता से जुड़ा हुआ है कि इसमें सवध में सही दृष्टिकोण को अपनाने की महत्ता स्वतः निश्चि है, इसमें किसी प्रकार की अतिरजना संभव ही नहीं।<sup>72</sup>

राष्ट्रवादी नेताओं ने लगभग एक मत से ही यह मांग की कि देश के स्वस्थ आर्थिक विकास के हित में भारत सरकार को देश के विकासशील उद्योगों को संरक्षण देकर उगवी, सहायता करनी चाहिए।<sup>73</sup> उदाहरणार्थ जी० सुब्रह्मण्य ऐयर न 1903 में लिखा कृषि

से जलज विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को अस्तित्व में लाना देश की अल्पविकसित महत्वपूर्ण आवश्यकता है और इसकी पूर्ति संरक्षण की नीति को अपनाते के द्वारा ही हो सकती है। जब तक तथाकथित उन्मुक्त व्यापार और असमान प्रतियोगिता की स्थिति जारी है तब तक देश ऐम किसी उज्ज्वल भविष्य की आशा नहीं कर सकता, जिसे भौतिक दृष्टि सपना कहा जा सके। अपने देश के बाजारों में सपत के लिए देश में उत्पादित खाद्यान्न और कच्चे माल के निर्यात पर कर लगाने का माध्यम से उभे देश में ही सुरक्षित बनाना तथा देशी उद्योगों के विकास की दृष्टि से विदेशी प्रतियोगी उत्पादकों के आयात पर प्रतिरक्षात्मक शुल्क लगाकर उस प्रतिबंधित करना, यही एक मात्र नीति भारत का बना सकती है।<sup>5</sup> किंतु, यह कम आश्चर्यजनक बात नहीं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने प्रथम तीस वर्षों के जीवन में एक बार भी संरक्षण की मांग नहीं की। इसका कारण अशत गायद उसके अपने मित्र इंग्लैंड के क्रांतिकारियों को सतुष्ट रखने की भावना थी और अशत ब्रिटेन के उन्मुक्त व्यापार के प्रति दृढ़ और निश्चयात्मक रुझान के कारण हिच-किचाहट स्पष्टतया राजनैतिक दृष्टि में इस मांग को मनवाना संभव नहीं था।<sup>6</sup>

भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने उन्मुक्त व्यापार का, संरक्षण के माध्यम से, भारत के औद्योगिक विकास के मांग की एक प्रमुख बाधा अनुभव करते हुए भारतीय परिस्थितियों में उन्मुक्त व्यापार की उपयोगिता को निरर्थक सिद्ध करना प्रारंभ कर दिया। उनका कथन था कि इसके विपरीत भारत के मुदीघ और व्यापक हितों में संरक्षण लाभदायक है न कि हानिप्रद। इस संबंध में 1877 में सर्वप्रथम और सर्वाधिक वैज्ञानिक प्रयास पूर्वोद्धृत लेख के माध्यम से के.टी. तल्लग ने किया। वाद के बहुत मारे लेखक तल्लग महोदय के लेख को ही आधार बनाते दिखाई देते हैं।

उन्मुक्त व्यापार के विरुद्ध राष्ट्रवादियों का प्रमुख तर्क यह था कि यह भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है।<sup>7</sup> भारतीय नेताओं का कथन था कि इसने इंग्लैंड में उपयोगी भूमिका निभाई होगी परंतु यहाँ भारत में तो उभने उद्योग का बड़ी भारी हानि पहुंचाई है।<sup>8</sup> उन्होंने आगे दृढ़ स्वर में कहा कि वस्तुतः उन्मुक्त व्यापार तो बराबर के देशों के मध्य चल सकता है। यहाँ भारत और इंग्लैंड की स्थिति तो कुछ कुछ ऐसी है कि एक (भारत) भूगा, धन मागा (नीमार) और पगु है तथा दूसरा (इंग्लैंड) केवल शक्तिशाली ही नहीं प्रत्युत उसके पास सजारी के लिए घोड़ा भी है।<sup>9</sup>

कुछ एक भारतीय नेताओं ने इस धारणा, संरक्षण से उपभोक्ता की स्वतंत्रता और उद्योगों की स्वाधीनता प्रतिबंधित हानी है का भी स्पष्ट किया। उनका कथन था कि स्वतंत्रता और स्वाधीनता का जब शायद अमीमित प्रतियोगिता के द्वारा भारत के विकासशील उद्योगों का नष्ट भ्रष्ट करने की विन्निषो को खुली छूट देना नहीं हो सकता। वास्तव में भारतीय स्थितियों में वास्तविक स्वतंत्रता संरक्षण और कृत्रिम पाषण के माध्यम से ही प्राप्त हो सकेगी, जबकि उन्मुक्त व्यापार का अर्थ ही अपक्षाकृत सशक्त दल इंग्लैंड का संरक्षण प्रदान करना सिद्ध हो रहा है।<sup>10</sup> उपभोक्ता के लिए जहाँ तक संरक्षण के मूल्य का संबंध है भारतीय राष्ट्रवादी नेता इस बात से सहमत थे कि राष्ट्र इस भारत का गहन कर लेगा क्योंकि मूल्य के, गिरावट के वेतन और नौकरी में वृद्धि के तथा राष्ट्रीय



भारत में व्याप्त स्थितियों जैसी स्थितियों में संरक्षण की स्वीकृति दी थी।<sup>90</sup> वस्तुतः भारत के लिए एक विदिष्ट स्थिति के रूप में संरक्षण की मांग करने वाले अपने को सिद्धांत रूप में स्वतंत्र व्यापारी सिद्ध करने का ही दावा कर रहे थे।<sup>90</sup>

भारत के मामले में संरक्षण को उचित तथा 'यायमगत सिद्ध करने के लिए भारतीय नेताओं में स कट्टे ने एक बहुत ही उद्विग्न तक प्रस्तुत किया। उदाहरणार्थ 19वीं शताब्दी के मध्य तक इंग्लैंड में भारतीय उत्पादकों के आयात पर घोषित भारी करा को उद्धृत करते हुए वे 0 टी० तैलम ने दक्ष स्वर में कहा, हमारे स्वदेशी उत्पादकों को नष्ट करने के लिए अपनाया गया उपाय यही संरक्षण है। उन्होंने दावा किया कि सभी भारतीयों की यह मांग है कि हमारे विरुद्ध तलवार के रूप में प्रयोग किए गए शस्त्र का प्रयोग जब हमारे रक्षक के रूप में करना चाहिए।<sup>91</sup> इसी प्रकार आर० सी० दत्त ने जली कटी मुनात हुए टिप्पणी की, उद्योगों के विरुद्ध संरक्षण न भारत में जनता की उत्पादन क्षमता का समाप्त कर दिया है और उसके उपरांत प्रतियोगी को पुनः प्रतियागिता में आने से हटाने के लिए भारत पर उन्मुक्त व्यापार थोप दिया गया है।<sup>9</sup>

अपनी संरक्षण की मांग का मजबूत बताने के लिए भारतीय नेताओं ने राजनितिक आर्थिकता के सिद्धांतों के बदले राष्ट्रों के व्यवहार को देखने का अनुरोध किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश किया कि लगभग यूरोप और अमेरिका के सभी स्वतंत्र राष्ट्रों और यहां तक कि कनाडा और आस्ट्रेलिया जैसे ब्रिटेन के अपने उपनिवेशों में विदेशी प्रतियागिता के खतरे के उपस्थित होने पर अपने नवजान उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया है।<sup>92</sup> उन्होंने बड़ ध्यानपूर्वक यह देखा कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में स्वयं इंग्लैंड में संरक्षण की देखभाल में ही अपने आधुनिक उद्योगों का विकास किया है। इसी संरक्षण की कृपा का ही फल था कि औद्योगिक यंत्र गतिशील होकर पूर्णता के उस चरम शिखर पर पहुंचा कि जहां से इंग्लैंड स्वतंत्र व्यापार के सिद्धांत की घोषणा करने में समर्थ हो सका है।<sup>93</sup> आर० सी० दत्त और जी० सुब्रह्मण्यय दत्त देखने में भी नहीं चूके कि जहां 18वीं शताब्दी की समाप्ति के बाद से ऐडम स्मिथ जैसे ब्रिटिश अर्थशास्त्री उन्मुक्त व्यापार के सिद्धांत का गला फाड़कर प्रचार करते चले आ रहे हैं वहां ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने उन्मुक्त व्यापारी का रूप बहुत पीछे ही ग्रहण किया और वह भी तब जबकि उन्हें यह अपने अनुकूल लगा।<sup>94</sup> बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता इस सीमा तक कहने लगे कि ब्रिटेन ईसावारी में उन्मुक्त व्यापार के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता और उसका प्रयोग एक बहाने के रूप में कर रहा है। जी० बी० जोशी ने भारत में अपने उत्पादकों का धकेलने के लिए और प्रतियोगी औद्योगिक विकास को रोकने के लिए इस 'आध्यात्मिक ढांचे' का नाम दिया।<sup>95</sup>

उन्मुक्त व्यापार की आलोचना तथा उद्योगों के लिए संरक्षण की बकालत करते हुए भी किसी महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेता ने संरक्षण के पक्ष में कट्टर सैद्धांतिक नीति नहीं अपनाई। इस संबंध में उनका दृष्टिकोण विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित था। स्वभावतः ही उन्मुक्त व्यापार की अस्वीकृति भी किसी सिद्धांत विशेष पर आधारित नहीं थी। अर्थात् आर्थिक विषय में उनके दृष्टिकोण के समान उनकी सीमा गुल्क नीति भी सामान्य आर्थिक





के अधीन करने की प्रवृत्ति ने भारतीय अर्थशास्त्र का विशिष्ट मूलतत्त्व दिया। आर्थिक विचारों और नीति के इस दृष्टिकोण ने प्रारंभ से ही भारतीय अर्थशास्त्र और भारतीय राजनीति में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर दिए। इसने राष्ट्रीय नेताओं को इस योग्य बना दिया कि वे लगभग प्रत्येक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रश्न को देश की राजनैतिक पराधीनता की स्थिति से जोड़ सकें और भारतीय वास्तविकता के इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनैतिक और आर्थिक पक्ष पर विचार कर सकें कि भारत विदेशी शासक द्वारा आर्थिक शोषण के लिए ही शासित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त जब राष्ट्रवादी नेताओं का आर्थिक चिन्तन समकालीन अंग्रेजी चिन्तन से आगे था और यूरोप तथा अमेरिका के चिन्तन के साथ कदम से कदम मिला रहा था, जबकि वह इस बात पर ज़ोर दे रहा था कि आर्थिक विकास के विभिन्न स्तरों पर विद्यमान देशों के लिए एक से आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग नहीं किया जा सकता और दटनापूर्वक यह मांग कर रहा था कि प्रत्येक देश के लिए आर्थिक सिद्धांतों का विधान संव्यक्त देश की सामान्य आर्थिक आवश्यकताओं के समक्ष ही किया जाना चाहिए, तब भी भारतीय पद्धतियों के किन्हीं नए आर्थिक विचार अथवा सिद्धांतों का उन्मूलन नहीं हुआ।<sup>101</sup> आर्थिक चिन्तन के साथ 'भारतीय राष्ट्रवादी' जैसे विश्लेषण तो अवश्य जोड़े गए परन्तु भारतीय राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों ने ऐम नए आर्थिक नियमों का आविष्कार नहीं किया, जो असामान्य भारतीय परिस्थितियों की उपज हो और जिनका प्रयोग विशिष्ट भारतीय परिस्थितियों में ही संभव हो। हम उनसे जो मिलता है वह है क्लासिकी अर्थशास्त्रियों और उनके परिवर्तित जालाचक्रों के चिन्तन का मिश्रित रूप। वस्तुतः भारतीय राजनैतिक आर्थिकता का आर्थिक चिन्तन की पद्धति न बहकर 'आर्थिक चिन्तन का एक दृष्टिकोण' 'भारतीय आर्थिक समस्याओं पर विचार तथा आर्थिक विचार विमर्श की शैली आदि नाम देना ही अधिक उपयुक्त होगा।

यह व्यापक रूप में इस तथ्य का परिणाम है कि राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों की आर्थिक सिद्धांत में रुचि शून्य अथवा परिस्थिति से उद्भूत थी। वे आर्थिक सिद्धांतों के विकास में अथवा अर्थशास्त्र को भारतीय रूप देने में रुचि रखने वाले व्यावसायिक अर्थशास्त्री नहीं थे। अतः उन्होंने स्वयं सिद्धांत के रूप में उस पर काबू पाने की कोशिश नहीं की। आर्थिक सिद्धांत पर उनके विचारों को वस्तुतः समकालीन आर्थिक समस्याओं पर उनकी बहुत सी रचनाओं से ही निकारा जा सकता है। उनकी राजनैतिक अर्थव्यवस्था संस्था व्यावहारिक विचारों की ही उपज थी क्योंकि भारत के शासक राष्ट्रवादियों की मांग का विरोध करने के लिए क्लासिकी अर्थव्यवस्था का सहारा लेते थे, इसलिए भारतीय अर्थशास्त्रियों ने भी क्लासिकी अर्थव्यवस्था की सावधानता को तथा भारत की परिस्थितियों में उसकी उपयोगिता को चुनौती देना आवश्यक समझा। उनके आर्थिक चिन्तन का इस अपेक्षाकृत लौकिक उदगम को उन्होंने कभी-कभी जानबूझकर अभिव्यक्ति दी। इस प्रकार उन्होंने कहा कि उन्हें तटस्थता नीति के सिद्धांत का खंडन करना है क्योंकि वह उद्योगों को राज्य द्वारा दिए जाने वाले संरक्षण के मांग में आड़े आता है।<sup>102</sup> ब्रिटेन के रिकार्डियन सिद्धांत का खंडन उन्हें इसलिए करना पड़ा क्योंकि इसका उपयोग भूमि लगानों की ऊँची



संदर्भ

- 1 रानाडे एसेज, पृ० 139 वित्तसिक जयशास्त्र पर रानाडे के विचारों का प्रारंभिक परिचय आगस्टस माप्रदिया के फ्री ट्रेड ऐंड इंग्लिश कामस की उनकी समीक्षा से हाता है पृ० पी०एस० एस० जुलाई 1881 (खंड IV सप्टा 1) पृ० 50 और आगे तुननाय मानवर पूर्वोद्धत खंड I पृ० 214 5
- 2 रानाडे के इन्स्टीट्यूट की विस्तृत परीक्षा के लिए देखिए जेम्स बेनाक रानाडे एंड आफ्टर इंडियन जारस आफ इकोनामिक्स जनवरी 1942 (खंड XXII स० 3), भवनोश मत्त, दि बकप्राइड आफ रानाडेज इकोनामिक्स वही ज० पी० बोयाजी रानाडेज बक ऐज ऐन इकोनामिस्ट वही डी० जा० कर्थ रानाडे दि प्रोफिट आफ रिक्वेस्टेड इंडिया (पूना, 1942) अध्याय 4 पी० व० गोपालकृष्णन इवलमेंट आफ इकोनामिक्स आइंडियाज इन इंडिया (दिल्ली 1959) अध्याय 3
- 3 रानाडे एसेज पृ० 2
- 4 वही पृ० 4 5 9 10
- 5 वही पृ० 8 10 22 3 42 3 और रिव्यू आफ फ्री ट्रेड ऐंड इंग्लिश कामस, पूर्वोद्धत पृ० 51
- 6 एसेज पृ० 4 6 14 उद्धृति यह भी निर्देश किया कि भारत की समस्याएं और दशाएं इंग्लैंड के अपेक्षा यूरोप और अमरीकी महाद्वीपों की समस्याओं और दशाओं से अधिक गंभीर हैं। अतः महाद्वीपीय अध्ययन से प्राप्त शिक्षा राजनीतिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में निहित नीतिवादात्मक अपेक्षा अधिक व्यावहारिक प्रभाव डालेगा
- 7 वही पृ० 3, 28 9 32 3 89
- 8 वही पृ० 16-21
- 9 वही पृ० 10 11 34-9
- 10 वही पृ० 6-7 16
- 11 वही पृ० 8 9
- 12 वही पृ० 1 5 21 2 89 90 यहां रानाडे ने इंग्लैंड में अभिन होने के आधार पर भारत के प्राथमिक राजनीतिक संस्थान होने से अग्रेज राजनीतियों के इतना करके पर तो 'यह प्रहार किया परंतु आर्थिक नीतियों का चर्चा करते समय वे इस तथ्य का सबूत भूल गए (वही पृ० 2, 4-5)
- 13 तुननाय वक्ता रानाडे ऐंड आफ्टर, पूर्वोक्त स्थल पृ० 253 कर्षे पूर्वोद्धत, पृ० 54-6.
- 14 रानाडे एसेज पृ० 21
- 15 उन्होंने विद्या व्यापक व्यवहार का नाम ही ता मिद्वंत है तथा अनुमानित कारणों के सम्म में किया गया अध्ययन ही बन्धुन व्यवहार है। मिद्वान का निर्णायक तत्व व्यवहार ही है वही उसका सत्यता की परा न करता है तथा यहूरी जड़ पकड़े स्थाई और विभिन्न मौलिक तथ्यों की मुक्त पकड़ के कारण विभिन्न परिस्थितियों का ग्रहण करता है (वही)
- 16 कर्षे पूर्वोद्धत पृ० 56 और रानाडे की टिप्पणियां भी देखिए एडम स्मिथ न आर्थिक रूप और सामाजिक स्थिति को कभी पृथक करने नहीं देखा और इस प्रकार उपयोगिता की स्थिति बनाए रखा जिस अब उनके उत्तराधिकारियों ने उनके मिद्वान पर आवश्यकता से अधिक बल देते हुए छोड़ दिया है (एसेज पृ० 16)

- 17 'रिव्यू आफ 'श्री ट्रेड ऐंड इन्डिया कामस पूर्वोक्त स्थल प० 51 53-4'
- 18 वही, प० 56, एसेज प० 11 22 और भाग 42 3 89
- 18-ए सलग श्री ट्रेड प्रोटेक्शन— फाम ऐन इन्डियन पाइट जाफ थू (बवई 1877) प० 47 तथा देखिए प० 2 15, 17 69
- 19 वही प० 2 3 53
- 20 नोरोजी पावर्टी, प० 136
- 21 राय, पावर्टी प० 66 सरक्षण बनाम उन्मुक्त व्यापार विचार का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा वास्तव में उन्मुक्त व्यापार और सरक्षण समय और स्थान की स्वतः सिद्ध वस्तुनाए हैं । यह तो औचित्य का प्रश्न है कि प्राकृतिक कानून का (वहा प० 65)
- 22 उपाहरण के लिए देखिए, जोशी पूर्वोद्धृत, प० 749 808 और 886
- 23 दत्त ई० एच० प० 299-302 और देखिए उनकी स्पीचज II प० 122 5
- 24 जी० एस० अम्बर, ई० ए० 104-07
- 25 वही प० 129 30
- 26 वही, परिशिष्ट प० 4
- 27 वही, परिशिष्ट प० 5 उन्होंने व्यापारवाद के उदय से अंतिम जर्मन सप्रशय तक यूरोप में आर्थिक चिन्तन के विकास के संक्षिप्त इतिहास की खोज की (वही, परिशिष्ट प० 7 22) यह भी पर्याप्त रोचक है कि जब उन्होंने व्यक्तिगत साधन पर राष्ट्रीय विकास को शेरब दन के लिए आर्थिक मिद्धातो और उनके ऐतिहासिक माडा की सापेक्षता की सम्यक् सूचा की प्रशंसा की, उस समय उन्होंने यह अपनी सूक्ष्म दृष्टि से दृष्ट किया था कि यह सूचा सामन्तमीन समाज के प्रभावी सुधार में सहायक होने के बरतने व्यापारिता के नए रूप की स्थापना के ताप्य की ही साधक अधिक है (वही, परिशिष्ट प० 22 3)
- 28 वही परिशिष्ट, प० 5
- 29 वही परिशिष्ट प० 1 2 तथा देखिए प० 210-1, 242, 267 और परिशिष्ट प० 4
- 30 वही, परिशिष्ट प० 3
- 31 और देखिए मराठा, 26 मार्च 1899
- 32 और देखिए 'थू इन्डिया 18 निसबर 1902
- 33 एस० एम० बनर्जी स्पीचेज I प० 202 ए० पी० पी० 1 निसबर 1870 सोमनाथ 3 अप्रैल (आर० एन० पी० भाग 8 अप्रैल 1882) मन्गल स्टैंड 21 जनवरी (आर० एन० पी० एम० 25 जनवरी 1902)
- 34 नोरोजी, पावर्टी, प० 136 जोशी पूर्वोद्धृत प० 207 राय पावर्टी प० 18-9 66 'थू इन्डिया 18 दिसबर 1902, जी० एम० अम्बर ई० ए० प० 358 तथा देखिए ए० बी० पी० 6 अप्रैल 1882
- 35 रानाडे एसेज प० 32 जोशी, पूर्वोद्धृत प० 809 आ० एम० अम्बर, ई० ए० प० 155
- 36 रानाडे एसेज प० 32 जोशी पूर्वोद्धृत प० 671 2 74 जी० एम० अम्बर ई० ए० प० 155 परिशिष्ट प० 6 शोधने स्थापन प० 54 5
- 37 रानाडे एसेज प० 87 जोशी पूर्वोद्धृत प० 612 745 749 785 6, 808 जी० एम० अम्बर, ई० ए० परिशिष्ट प० 6 रानाडे ने 1896 में यह टिप्पणी की थी 'आखिर राज का अर्थ क्या है? यह है कि वह अलग अलग सदस्यों की उनके सभी प्रयोगों में सफल बनाई जाए उर्द

अधिक ऊँचा अधिव प्रसन्न अधिव समृद्ध और अधिव पूण बनाए दि मिसलेनियस राईटिंग आफ दि लेन आनरेबल मिस्टर जस्टिस एम० पी० रानाडे (बर्देई 1915) प० 172 तथा दखिए, वही प० 78

38 रानाडे, एसेज पृ० 86, 90-2 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 672 3, 747 3 785 6 807-09 826 हा 1877 म रानाडे के विचार अवश्य कुछ भिन्न थे। पूना सार्वजनिक सभा की ओर से डकन रायटस कमिशन की रिपोर्ट पर लिखे एक पत्र म उन्होने घोषणा की देश का भौतिक सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थिति मे किसी प्रकार का स्याई परिवर्तन लाना सरकार की शक्ति और सामर्थ्य के बाहर है। भारतवासी किसी विदेशी अभिकरण द्वारा सुधार किए जाने म विश्वास नहा रखते। कम से कम विषय की तात्कालिकता की मांग क अनुसार इतने घाट समय में तो कुछ सुधार ही पाना सम्भव नहीं जी० सी० एस० एस० जनवरी 1879 (खंड I सख्या 3) पृ० 36 तुजनीय मानकर पूर्वोद्धृत खंड 1 प० 213

39 जोशी पूर्वोद्धृत प० 680-3 785 6

40 रानाडे एसेज प० 32 तथा लोक का प्रतिनिधित्व करन वाली सरकार को लोक कल्याण का दिशा म सर्वोत्तम रूप से किए जान वाले सभी कार्यों को अपने हाथ म लेने का अधिकार है और यह उसका तन्त्रुरूप नतिक दायित्व है (वही प० 87)

41 जोशी पूर्वोद्धृत प० 822

42 रानाडे एसेज प० 21

43 जी० एम० अय्यर ई० ए० प० 110-1 तथा दखिए वही परिशिष्ट प० 6 10 11

44 आशी पूर्वोद्धृत प० 748 9

45 देखिए पीछे अध्याय 3 उदाहरणार्थ रानाडे एसेज प० 32 4 जाशी पूर्वोद्धृत, प 671 701 752 830 राष्ट्रवादी नेताओ द्वारा औद्योगिक विकासपर दिए बल के लिए देखिए पीछे अध्याय 2

46 देखिए पीछे अध्याय 10

47 रानाडे एसेज प० 31

48 देखिए पीछे अध्याय 10 उदाहरणार्थ देखें एसेज प० 30-1 हां इसत पूव 1881 म उन्होने राज्य द्वारा जमींदारो और किरायादार के सबधो को नियमित करने के किसी भी प्रयास का विरोध किया था। उनके विरोध का आधार यह था कि ये मामले इतने माजुक और तते जटिल हैं कि इ ह मुल्भान की बात निजी प्रयास और आपसी समझौते पर हा छाड दनी चाहिए। इन शिशा म किसी भी प्रकार के सरकारी प्रयास का परिणाम असफलता और नतिक रूप से बूटा क अतिरिक्त और कुछ नही निकलेगा (दि सेंट्रल प्राविसेज लड रेवेन्यू एंड टर्नेसी विल्स जे० पा० एस एस० अप्रैल 1881 खं III सख्या 4 प० 22) और देखिए प० 17 तुजनीय मानकर पूर्वोद्धृत खंड I प० 214

49 उन्होने लिखा 'प्रगतिशील सिद्धांत बड़ा इन स्वतंत्रता की अनुमति देता है जहा दो दन योग्यता और साधना म मुकाबले म बराबर के हैं। परंतु जहा यह स्थिति नहा है वहा समानता और स्वतंत्रता की बात का' मे धाज का काम करता है। सभा भावना स बहुत सार जहरतमना और थोडे से शक्तिशालियाम उत्पादन क वितरण की व्यन्ध्या करनी है अर्थात् साय और औचित्य का ध्यान रखना है। इस प्रकार के मामलो म पुरातनपरियो के प्रतिम स्थिति के दृष्टिकोण का जीवन के सभी आयामा के सदम म नए ढंग से देखना होगा (एसेज प० 31)

- 50 देखिए पीछे अध्याय 8 उदाहरण के लिए ई० ए० प० 227 3 तथा देखिए, मराठा, 1 जनवरी 1888
- 51 देखिए पीछे अध्याय 8 उदाहरण के लिए ब्राह्मी पत्रिका आपीनियम 27 फरवरी 1879, फक्टरी लजिस्टरेशन इन इंडिया जे० पी० एस० एस० जलाई 1881 (खंड IV सन्ध्या 1) प० 31 हनु प्रकाश 9 फरवरी (आर० एन० पी० बच 14 फरवरी 1885) हिंदू 14 मई 1889 26 मार्च 1901
- 52 कम से कम एक लेखक डी० जा० बर्वे यह इस गलती करने से नहा बच सके (पूर्वोद्धत प० 119 132) दूसरी और जेम्स क्लार्क (रानाड, प० 130) बी० दल (पूर्वोद्धत प० 262 272), और गणपालकृष्णन (पूर्वोद्धत प० 124) स्पष्ट ही हम अंतर को देख सके थे
- 53 विशेष रूप से देखिए, एसेज पृ० 89-90 169 190 193 4
- 54 वही पृ० 33
- 55 रिपोर्ट आफ दि फाइनांस कमेटी, 1886 खंड I प० 407
- 56 जोगी, पूर्वोद्धत पृ० 819
- 57 वही पृ० 746-50 820
- 58 वही पृ० 673-4 808 820 826 हिंदू 21 अप्रैल 1902 भी देखें
- 59 जोगी पूर्वोद्धत पृ० 822 3
- 60 वही, पृ० 821 तथा देखिए पृ० 825 861 2
- 61 उदाहरण के लिए देखिए रिपोर्ट आफ इंडियन फिमिन कमीशन 1880 भाग II वग VII कडिका 2 रिचाड स्ट्रेची और जान स्ट्रेची पूर्वोद्धत प० 14 5, चिमनी पूर्वोद्धत प० 31) कजन स्पीचेज I पृ० 128 रिजाय्नुभा आफ दि गवमट आफ इंडिया दिनांक 16 जनवरी 1902 कडिका 9 स्ट्रेची इन्डिया (1903) प० 120 ई० सा एन० सी० पी० 1904 पृ० XLIII पृ० 539 यह उल्लेखनीय है कि कितने ही सरकारों के अधिकारी और लेखक इस व्यापक दृष्टिकोण से असहमत थे उदाहरण के रूप में देखिए लॉस मलट साइ सनिसवरी एच० ई० सुलेवान को कायवाही और लॉस फिमिन इन इंडिया परिशिष्ट एम० एन० बी० ब्यू० में उद्धृत, भारत सरकार के संप्रण दिनांक 8 जून 1880 हाम (पत्रिका) प्राग 45 (ए) जून 1880 बीडन पावेल पूर्वोद्धत प० 49
- 62 माइलिन स्पीचेज, प० 466 488 514-5 जान प्रकाश 3 फरवरी (आर० एन० पी० बच 5 फरवरी 1881) जोगी पूर्वोद्धत, प० 547 8 573-4 824 887 रानाड प्राइमट अगेंट यू इंडियाकर आफ गवनमट इन लॉस पत्रिका जे० पी० एस० एम० अप्रैल 1884 (खंड VI सन्ध्या-4) प० 45 पूना सांख्यिक समाज का 4 जून 1884 का पत्र जे० पी० एम० एम० जलाई 1886 (खंड IX सन्ध्या 1) पृ० 5 स्वदेशमित्र 23 अप्रैल (आर० एन० पी० एम० 30 अप्रैल 1897) पी० मेहता स्पीचेज पृ० 600-2 थाया सी० पी० ए० प० 570 दल फिमिन इन इंडिया प० 94 और आगे, ई० एच० I पृ० 372 4 381 2 ई० एच० II पृ० 140 371 2 और देखिए भोरोडी पावर्टी प० 60 220-1 स्वीचर पृ० 316, परिशिष्ट प० 20 182 जोगी पूर्वोद्धत प० 223 फार्मलिसपी की राय पावर्टी प० 254
- 63 जोगी पूर्वोद्धत पृ० 886 उद्धृति आगे रहा 'यह समाजवादी मित्राल इन बिजनेस ब यूरोप' का अपमानार्थ संबंधी अपमानार्थों का अपमान भाव है और जिसकी व्यावहारिक अभिव्यक्ति निम्न भारत के बाहर भूमि के राष्ट्रीयकरण के भ्रष्टाचारी आन्दोलन के माध्यम से होगी है ।

- जोशी एक दृष्टि से सही थे न तो रिकाडों ने और न ही जेम्स मिल ने यह मुभाव देने का साहस किया कि अनुपाजित आय में निहित प्रातिवारी कर नीति इभिलिश परिस्थितियों में लागू की जाए तुलनीय, स्टोक्स, पूर्वोद्धत, पृ० 89 90
- 64 देखिए स्टोक्स, पूर्वोद्धत विशेष रूप से अध्याय 2 पृ० 108-09 114 137
- 65 वही पृ० 88 डविड रिकाडों दि प्रिंसिपल्स ऑफ पोलिटिकल इकोनोमी ऐंड टैक्सेशन (एबरीमन लायब्ररी सस्वरण लण्डन 1943) अध्याय 2 और 32, एरिक रोन ए हिस्ट्री ऑफ इकोनामिक घाट (यूयाक 1947) पृ० 195 6
- 66 स्टोक्स पूर्वोद्धत पृ० 77 89 93 127 8, 131 3
- 67 वही पृ० 135 तथा रिकाडों पूर्वोद्धत अध्याय 2
- 68 रानाडे एसेज पृ० 30 'लड ला रिफार्म्स एंड ऐग्रीकलचरल बक्स ज० पा० एम० एस०, अक्टूबर 1881 (खंड IV सख्या 2) पृ० 54
- 69 जाशी, पूर्वोद्धत पृ० 892 4 900-01 'यहां यह उल्लेखनीय है कि रानाड और जोशी जान स्टुअर्ट के राजनीतिक अध्ययन के सिद्धांतों पर बहुत विश्वास करके चल रहे थे, अध्याय 10
- 70 स्टोक्स पूर्वोद्धत पृ० 89 90, रिकाडों पूर्वोद्धत अध्याय 2 और 32, उदाहरणार्थ अनुपाजित वृद्धि के सिद्धांत को लाड वजन के 16 जनवरी 1902 के भूमि प्रस्ताव में भी स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलती देखिए कडिका 18 22.
- 71 रानाडे एसेज, पृ० 29 30 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 363 894 6
- 72 जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 894 901 इस सरकारी तब पर कि सरकार के सारे समाज के यासधर होने के नाम उतबे लिए लगान में अनुपाजित वृद्धि का समाज के एक छोटे से वर्ग विशेष के लाभ के लिए छोड़ना कहा का 'याय होगा, टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा 'बाश खेतिहर जनसंख्या का एक छोटा प्रश होते ? (वही पृ० 902) यह सचमुच व्यापारिक भल न हो परंतु विचित्र स्थिति अवश्य है कि इंग्लैंड में मुठठी भर जमींदारों के शोषण से विशाल जन समुदाय को बचाने के लिए इंग्लैंड के लेखक रिकाडों द्वारा दिए गए सिद्धांत का भारत में समाज के हित के नाम पर जनता के विशाल समुदाय पर ऊंचे कर बोपने के लिए प्रयोग किया जा रहा है
- 73 पृष्ठ 1
- 74 भोलानाथ चन्, एम० एम० जून 1873 (खंड II) पृ० 99 109 235 नोरोजा, पावर्टी पृ० 62 तलग पी ट्रड लैंड प्रोटेक्शन पृ० 32 62-4 69 70 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 680-2 749 रानाडे एसेज पृ० 25, राय पावर्टी अध्याय 1 (विशेष रूप से पृ० 44 51), मोखले सिन्धी कमीशन खंड III प्रश्न 18165 7 पी० मेहता स्पीचर्ज पृ० 750, दत्त, इंग्लैंड ऐंड इंडिया पृ० 133 स्पीचर्ज II पृ० 127 8 इन इंडिया 27 नवंबर 1903 जी० एल० अय्यर ई० ए० पृ० 101 107 255 345 6 349 50 ईस्ट ऐंड वेस्ट अगस्त 1903 पृ० 884 पर एल० एन० बनर्जी रिप० आई० एन० सी० 1896 पृ० 136 सी० पी० ए० पृ० 636 जी० आर० एम० वित्तनवीस एल० सी० पी० 1894 खंड XXXIII पृ० 156 पी० ए० चार्ल्स, एल० सी० पी० 1899 खंड XXXVIII पृ० 178 9, बाबा स्पीचर्ज पृ० 442 रास्त्र गुप्तार 24 मार्च (मार० एन० पी० बब 30 मार्च 1878) गुजरात मित्त 7 अप्रैल (वही 13 अप्रैल 1878) मराठा 12 19 जून 4 मित्त० 1881 26 मार्च 1882, 11 अप्रैल 1897 26 मार्च, 21 अप्रैल 1899 11 नवंबर 1900 30 मार्च 1902 'वर्ष समाचार 8 जुलाई (आर० एन० पी० बब 9 जुलाई 1881) ए स्टेटमट ऑफ इंडियन क्वेश्चन्स ज० पी० एम० एल० जुलाई





- 88 तन्त्र पूर्वोक्त स्थल प० 36 7
- 89 तन्त्र पूर्वोक्त स्थल प० 67 मराठा 19 जून 1881 ए० वा० पी० 6 अप्रैल, 1882, रानाडे, एसेज प० 25 राय पावर्टी प० 45 6 एस० एन० बनर्जी रिप० आई० एन० सी०, 1896, प० 136 दत्त इंडिया 27 नवंबर 1903 म
- 90 गोशी पूर्वोद्धत प० 822 पी० मेहता स्पीचेज प० 750 वाचा रिप० आई० एन० सी० 1895 प० 159 स्पीचेज प० 422 पी० मेहता स्पीचेज, की भूमिका प० 14 और तन्त्र स्पीचेज प० XI XII नौरोजी पावर्टी (प० 62) की भूमिकाएँ सी० पी० ए०, प० 881 एल० एम० घोष सी० पी० ए० प० 754 और दक्षिण वर्षे पूर्वोद्धत प० 134
- 91 उद्देश्ये यह तब तक कहा कि भारत में संरक्षण इस्तेमाल के प्रति अन्याय नहीं होगा। यदि यह अन्याय हो भी तो उसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी अतः वह लागू किया जा सकता है (पूर्वोक्त स्थल प० 63 4) और दक्षिण पी० मेहता स्पीचेज प० 750
- 92 दत्त ई० एच० I प० 302 दत्त ने अपनी 'इकानामिक हिस्ट्री आफ इंडिया पुस्तक के दानो खंडों में तथा अपने अनेक भाषणों और लेखों में इस विवरण को विस्तार के साथ प्रमाणित किया और दक्षिण ए० बी० पी०, 30 मार्च 1882 जी० एस० अय्यर, ई० ए० प० 106 242 3 वाचा सी० पी० ए० प० 623 एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए०, प० 692 6
- 93 ए स्टेटमेंट आफ क्वेश्चंस ज० पी० एस० एस० जुलाई 1881 (खंड IV स० 1) प० 15 ए० बी० पी० 30 मार्च 6 अप्रैल 1882 रानाडे एसेज प० 25 राय पावर्टी प० 58 66 मराठा 17 जनवरी 1886 11 अप्रैल 1897 11 नवंबर 1900 दत्त ई० एच० I प० 302 इंडिया 27 नवंबर 1903 एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए० प० 696 जी० एस० अय्यर ई० ए० प० 104 05 109 245 328 ए० प० 526 एम० एन० बनर्जी इन सी० पा० ए० प० 696 जी० एस० अय्यर ई० ए० प० 104-05 109, 245 328
- 94 तन्त्र पूर्वोक्त स्थल प० 65, राय पावर्टी प० 53 8 मराठा 11 अप्रैल 1897 दत्त इंडिया 27 नव० 1903 जी० एस० अय्यर ई० ए०, प० 244 5 328 ईस्ट एंड वेस्ट अफ्स 1903 प० 884 एन० जी० चण्दरकर सी० पी० ए० प० 526 एस० एन० बनर्जी सी० पा० ए० प० 696
- 95 दत्त ई० एच० I प० 302 जी० एम० अय्यर ई० ए० प० 252 3
- 96 गोशी पूर्वोद्धत प० 674 मराठा 17 जनवरी 1886 एस० एन० बनर्जी रिप० आई० एन० सी० 1896 प० 136 राय पावर्टी प० 39 दत्त इंडिया 27 नवंबर 1903 जी० एम० अय्यर ई० ए० प० 116 7 258 9 329
- 97 दत्त स्पीचेज II प० 127 इस प्रकार 22 नवंबर 1903 के अर्थ में मराठा ने घोषणा की कि भारत में तो उन्मुखतः व्यापार चाहता है न ही शुद्ध संरक्षण वह तो दोना का दम रूप में चाहता है जिससे वर्तमान परिस्थितियों के सर्वाधिक अनुकूल उमकी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके और दक्षिण रानाडे रिथ्यू आफ फ्री ट्रेड एंड इन्डिया काममें पूर्वोक्त स्थल प० 56 जाशी पूर्वोद्धत प० 822 राय पावर्टी प० 65
- 98 टिप्पण 1 अप्रैल (आर० एन० पा० पी० 12 अप्रैल 1902) मराठा 5 जुलाई 1903 इन्डियन पीपुल 16 अक्टूबर 1903 हिंदू 27 नवंबर 1903 एच० आर० नवंबर 1903 प० 442 बंगाली 13 फरवरी 1904
- 99 प० 441



## आर्थिक राष्ट्रीयतावाद

वस्तुस्थिति यह है कि कोई भी राष्ट्र एक ही समय विजेता राष्ट्र और परोपकारी राष्ट्र नहीं बन सकता।

अमृत बाजार पत्रिका 22 फरवरी 1892

जाप अपने ब्रिटिश शासन के ईमानदार समर्थक होने की घोषणा करते हैं और उस शासन को बनाए रखने के लिए अनिवार्यतः अपेक्षित तथा अविभाज्य स्थितियाँ और परिणामों की घोषणा करते हैं।

जाज हैमिल्टन

### भारत में ब्रिटिश राज्य के स्वरूप और उद्देश्य का विश्लेषण

हमारे अध्ययन के अंतर्गत अवधि में भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा ब्रिटिश शासन के प्रति अपनाए गए दृष्टिकोण का निधारक तत्व अतः उसके स्वरूप और उद्देश्य का बोध था। उनमें से अधिकांश के बारे में यह जानकारी सैद्धांतिक तर्क नितक अथवा धोरी कल्पनाओं से प्राप्त नहीं थी। उनका सच्चा और व्यावहारिक ज्ञान ही उनकी धारणा का मूल आधार था। उनकी इस जानकारी का एक क्षेत्र आर्थिक नीतियाँ थीं। समकालीन प्रशासन और राजनीति में सबंधित लगभग प्रत्येक आर्थिक विषय पर एक-दूसरे के बीच भारतीयों के बीच आपसी विचार विमर्श का और दूसरी ओर भारतीयों तथा शासकों के बीच हुए तर्क-वितर्क का इस मौलिक राजनैतिक जानकारी पर प्रभाव पड़ा। अतः आर्थिक नीतियों और विभाजन भारत की अग्रदूता के कारणों और परिणामी उपचारों के संबंध में उत्पन्न विविध वादविवादों से राष्ट्रवादी नेताओं के अनेक बड़े वर्गों जी० के० गांधल, जी० वी० जोगी, मुरद्रनाथ बनर्जी, जी० ई० बाबा और आर० सी० त्त आदि को हिचकिचाहट व अस्पष्ट रूप से तथा दाना भाई नौराजी वी० जी० निलक जी० मुद्रहाण्य एयर, अमृत बाजार पत्रिका और मराठा तथा अन्य अनेक राष्ट्रवादी पत्र-पत्रिकाओं आदि जैसा कि साफ तौर पर, यह विद्वानों को विश्वास होना पड़ा कि कुल मिलाकर भारत में ब्रिटिश



आर्थिक मामला के संवध मे हतनता और प्रशंसा का स्थान निरंतर की जाने वाली शिक्वा शिकायत और दोष निकाशन की प्रवृत्ति ने ले लिया।<sup>15</sup> भारतीय नेता यह शिकायत करने लगे कि निधनता इस देश मे जड़ पकड़ रही है। सरकारी राजस्व अधिकारियों द्वारा किसान को लूटा खमूटा जा रहा है। स्वदेशी उद्योग को नष्ट कर दिया गया है और जाधुनिक उद्योग को जानबूझकर निरुत्साहित किया जा रहा है अथवा कम से कम पर्याप्त प्राप्ति नहीं दिया जा रहा है, देश के लिए आवश्यक माद्य सभरण का नियान किया जा रहा है। भारतीय उद्योग और कृषि के हितों के विरुद्ध ही मुद्रानीति अपनाई जा रही है। विदेशियों के स्वामित्व वाले वागान उद्योग मे भारतीय श्रमिक को दास बनाया जा रहा है भारतीय राजस्व और कृषि विकास की आवश्यकताओं की उपक्षा करके रेलों का विस्तार किया जा रहा है। कराधान का भार लागा का निचाड़ रहा है। लाववित्तों का राष्ट्र निमाण के विभागों से हटाकर इतर भारतीय हितों के पापण म, अनावश्यक आजीविका जुटान मे तथा विस्तारवादी युद्ध लडने मे खर्च किया जा रहा है। अतिस, सबसे भारी शिकायत उह यह थी कि भारत मे संपत्ति और पूजा की निकासी की जा रही है। वे यह अनुभव करने लगे कि ये सभी आर्थिक दोष प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भारत मे बरती जा रही ब्रिटिश आर्थिक नीति के ही परिणाम थे। यदि भारतीय आर्थिक जगत असंगठित है तो व्यापक रूप से इसका दायित्व ब्रिटन पर ही है। इस प्रकार ही राष्ट्रवादी नेताओं की दृष्टि मे ब्रिटिश राज्य के भूतकाल के और बतमान काल के अथ सभी लाभ आर्थिक अवगति के सामने निरर्थक म हो जाते हैं।<sup>16</sup> विश्वास के इस भंग ने न केवल ब्रिटिश शासन के परिणामों के संवध मे प्रश्न करने प्रारंभ कर दिए, पत्युत 'क्यों, और किन लिए यह स्थिति है इस पर भी विचार करना प्रारंभ कर दिया भारत न भौतिक पगति क्यों नहीं की? इन सबसे प्रारंभिक जाशाआ की पूर्ति क्यों नहीं हुई? इन असफलता के लिए कौन उत्तरदायी है? क्या भारत को यह क्षति जनजाने पडुची है अथवा जानबूझकर कर पट्टेचाई गई है? दूसरे शब्दों मे भारत मे ब्रिटिश शासन का उद्देश्य क्या था? निष्पत्त रूप से ब्रिटिश राज्य के परोपकारी स्वरूप मे उनका विश्वास उठाने लगा और उह यह दिग्गई दन लगा कि ब्रिटिश शासन भौतिक विकास की दृष्टि मे भारत के लिए हानिकारक ही रहा है।

सैमानि संवविद्रित है विगत सख्या मे भारतीय नेता वर्षों तक यह विश्वास बरत रहे कि भारत की आर्थिक दुगति का कारण ब्रिटिश जनता ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश शासक वर्ग द्वारा भारत की स्थिति से भली प्रकार परिचित न हाना है अथवा अधिस स अधिस यह सब ब्रिटेन की दत्तगत राजनीति का फल है और उसके परिणामस्वरूप गलत नीतियों का प्रवर्तन होता है और नौकरशाही द्वारा सही नीतियां तब का भी गलत ढंग से लागू किया जाता है। इसके अतिरिक्त अशत स्वयंसेवकों द्वारा अपना ही दंग म गलत नीतियां का अपनाया जाना है। दूसरे शब्दों मे भारत के आर्थिक पिछडेपन के लिए शासन का अपमान अथवा निणय मे गलतियां अथवा अधिक से अधिक लोबन्धनीय राजनीति के दोष ही उत्तरदायी थे न कि किसी प्रकार की साच समझकर निर्धारित की गई नीति अथवा इच्छा का यह परिणाम था। अतः दन राष्ट्रवादी नेताओं के लिए तसल्ली का मुख्य



कभी तो एन ही मास में ब्रिटिश स्वायत्तता को उजागर करत रह तथा ब्रिटिश के दूसरा की उन्नति के लिए मिगनरी भाव में अपनी आरणा की भी पुष्टि करत रह, उह अपन राजनैतिक विश्वास और आर्थिक बोध के बीच न सुलभ सकन वाना अतर विराध विचार ही नहीं दिया। उदाहरणार्थ दादा भाई नौरोजी ने भारत में ब्रिटिश शासन का 'जन ब्रिटिश कहकर ऐसा किया।<sup>10</sup> तृतीय, समाचार पत्रों ने प्राय ही जन नताओं की अपभा सामान्य राष्ट्रवादी नेताओं की भावनाओं को अधिक सुस्पष्ट, अधिक प्रत्यक्ष और अधिक साहसपूर्ण अभिव्यक्ति दी। इन पत्रों में आर्थिक प्रश्नों पर और उनके राजनैतिक परिणामों पर लोकप्रिय राष्ट्रीय धारणा को विनसित करन तथा उसे एक विशेष रूप देने में महत्वपूर्ण योग दिया। किसी भी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि जहां तक बहुमतवर्ग भारतीय राष्ट्रीय नेताओं व जातों का संबंध है, भारतीय नेताओं के सभी वर्गों द्वारा आर्थिक नीतियों से संबंधित चलाये गए आंदोलन ने ही ब्रिटिश सरकार के उपकारिता के भ्रम का तोड़ा।<sup>11</sup> ब्रिटिश राजनीतिज्ञों और भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने इस रहस्य को भली प्रकार समझ लिया था कि ब्रिटिश सत्ता का रहस्य केवल शारीरिक शक्ति न होकर नैतिक शक्ति भी था। यह सत्ता चाली तलवार पर टिकी हुई नहीं थी, जिसमें उद्धान्तरस दश को विजित किया था प्रत्युत जनता की लगातार सहमति पर भी आधारित थी।<sup>12</sup> केवल राजनैतिक और भावनात्मक अपीलें ब्रिटिश राज्य के नैतिक आधार का कमजोर नहीं कर सकती थीं। व अधिक स अधिक ब्रिटिश राज्य की परापकारी निरकुशता के तौर पर निंदा कर सकती थीं।<sup>13</sup> मत्स्यता यह है कि बहुत सारे ब्रिटिश प्रशासकों और राजनीतिज्ञों ने अपने शासन के निरकुश स्वरूप को प्रसन्नतापूर्वक न केवल अभिस्वीकार किया प्रत्युत उसका समर्थन भी किया। उनका दावा केवल यह था कि शासन की निरकुशता, मकाले का मुदत शाही निरकुशतावाद अथवा जिसकी प्रसिद्धि पैतृकवाद के रूप में हुई, तोनपकारिता के लिए आवश्यक थी और यह 'शक्ति' के बिना संभव नहीं थी।<sup>14</sup> किसी भी स्थिति में राजनैतिक स्वतंत्रता का अभाव सबके सामने था परंतु यह अभाव एक राजनैतिक दोष था, जिस विपुल रूप में उन सीधे सादे लोगों को गिनाया जाना था, जो अपने आप में इस बुराई को नहीं देख सकते थे। जत ब्रिटिश राज्य के दानो शुभपरिणामों और शुभ भावनाओं, के रूप में लाकोपकारी चरित्र के प्रति लोकप्रिय विश्वास का प्रमाण क्षीण करने वाली आर्थिक नीतियों से संबंधित राष्ट्रवादी जागृकता का अपना एक ऐतिहासिक महत्त्व है। इससे राजनैतिक वफादारी के क्षेत्र में अनिश्चयता विश्वास की भावना क्षीण होने लगी। बहुत सुतर्क हूए नता भले ही कुछ कहते रहत, इस आंदोलन की अवधि में शासन पर लगाए गए आरोपों की प्रवृत्ति के कारण जनसाधारण व मन में वफादारी की भावना रह नहीं सकती थी।<sup>15</sup> इस आंदोलन में सभी राजनैतिक विचार धारा के नेता, मृदु प्रवृत्ति के दादा भाई नौरोजी, रानाडे, दत्त गोखले और जोशी से लेकर उग्रवादी तिलक, दानो भाई शिशिरकुमार और मातीनाल घोष और अग्रगण्य राष्ट्रवादी समाचारपत्रों, न समान रूप में भाग लिया। इस रूप में यह कहना संभव है कि पायसगन हागा कि सभी राष्ट्रवादी नेताओं ने विद्रोह का नहीं तो असंतोष का बीज अवश्य बोया। यद्युत उन दोनों के बीच बराबरी वाम्बिन अंतर केवल यह था कि जहां कुछ एक

जानत हुए भी राजद्रोही थे, वहा दूसर वफादार थे जोर अपनी राज्यभक्ति का प्रिंटारा पीत थे और ब्रिटिश राज्य को स्थायी रूप बन के डचटुव थे। एम उग व्यम्निगन रूप स ब्रिटिश राज्य के अतिम दिना तक वफादार वा रह परंतु उहान जहा भी उपयुक्त मममा, वहा ही वस्तुगत रूप मे ब्रिटिश साम्राज्य की जडे नादन म कोई वमर नही छाडी। वस्तुन वे राजद्रोह के मूलाधार थे जोर यही प्रचान कारण म म एक कारण है कि 1880 1905 की अवधि को बौद्धिक अमताप जोर राष्ट्रीय जागरूकता क प्रसार आधुनिक राष्ट्रीय जादालन को गुफ्रात रा काल कहा जाता है।

यह भी एक पर्याप्त राचक तथ्य है कि बटुन मार समजातीन मरकारी अगिनारिया और ब्रिटिश राजनीतिज्ञो ने इस तथ्य का भली प्रकार ममभ किया कि अपन युग के राष्ट्रवादिवा म सवाधिक मदुभापी नेता भी यनी भूमिका वस्तुगत रूप स निभा रह व। उहाने यह भी अनुभव किया कि मदु जोर समभौतावापी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अपनी मरजा म उपलव्य दापो के प्रति निरंतर आलाचनात्मक टापा वा डवन के वपने उह अछी तरह उधाडन की, प्रवृत्ति क कारण परिवर्तित रूप लेती जा रही थी। एम प्रकार उदाहरण क रूप म भारत सचिव जाज हैमिं टन न 1897 म कांग्रेस की भारतीय प्रशासन पर प्रहार करने का काई अवसर न सान क लिए तथा भारत की जाता पर उम प्रशासन के प्रभाव को क्षीण करने के प्रयास क लिए आलाचना की।<sup>16</sup> जनरल चिसनी न तो कांग्रेस को पूणत राजद्रोही बताया।<sup>17</sup> राष्ट्रवादी प्रेस की भूमिका के मवध म 1886 म डफरिन ने लिखा कि इस ढग से निस्सदह इन पना के पपने वाता के मन म एक भावना जड जमाती जाएगी कि हम अग्रेज साम्राज्यतया मानव जाति के और विरोधतया भारतीयो के बट्टर शत्रु हैं।<sup>18</sup>

### आर्थिक साम्राज्यवाद का विरोध

1880 1905 की अवधि म भारतीय राष्ट्रवादी नेताआ द्वारा आर्थिक नीति क जिस स्वरूप की वकालत की गई उसन इन वर्षों का आर्थिक राष्ट्रीयतावाद के युग का नाम दे लिया। इन नेताआ के अनुसार भारतीय जनमानस का सवाधिक प्रभावित करने वाली ममस्या आर्थिक समस्या थी जिस निधनता का नाम दिया जा सकता है। इसन अति रिक्त यह एक राष्ट्रीय समस्या थी, अर्थात् यह भारतीय समाज क सभी वर्गों के हितों का घुरी तरफ स दुष्प्रभावित करती थी। एमन भी वन चर वन वात यह थी कि भारतीय नेताआ ने इस निधनता का द पित्व न ता प्रति पर शान और न ही भारतीय समाज पर प्रत्युत इसक लिए विदेशी सामका का ही उभरनायी टहगाया। उहान निधनता न छुटकार के कुछ उपचार सुभाए परंतु उह स्वीकार नहीं किया गया। एमका परिणाम यह निष्पत्ति कि बहुत सारे नेता सामका की ईमानदारी पर सन्देह करने लगे जोर एम अनुभव करने लगे कि भारत द्वारा आर्थिक दृष्टि म उन्नति न कर पान रा मृत कारण विदेशी सामकों का और उनकी नीतिया का अस्तित्व ही है। क यह मानने लगे कि जब तक ढग मवप्रथम इन यूरोपीय सामका स छुटकारा नहीं पा जाता तब तक राष्ट्रीय आर्थिक पुनरुद्धार हा ही नहीं सकता।



भारतीय नेताओं द्वारा सुझाए गए उपचारों अथवा उनकी आर्थिक नीतियों का स्वरूप साम्राज्यवाद विरोधी था। वे ब्रिटेन और भारत के मध्य चालू आर्थिक सन्धियों में मौलिक परिवर्तन चाहते थे। यहाँ तक कि जहाँ उनकी राजनैतिक मार्गें मद्धु थीं वहाँ उनकी आर्थिक मार्गें नातिकारी रूप से राष्ट्रीय थीं। उनकी आर्थिक नीतियों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें भारत पर ब्रिटिश के प्रभुत्व अथवा आधुनिक साम्राज्यवाद की पद्धति के जटिल आर्थिक तंत्र की गहरी जानकारी हो गई थी। आर्थिक विनाम के गठन के अंतर्गत सभी आर्थिक प्रश्नों की शृंखला पर विचार करने के तथा समग्र रूप में उनके पारस्परिक संबंधों के मद्देन में अध्ययन करने के उपरांत ही उन्होंने यह सारी जानकारी प्राप्त की। इसके पश्चात् इस पद्धति पर आघत लगभग सभी आर्थिक नीतियों का ही उन्होंने विरोध किया। उन्होंने ममतामयी आर्थिक शापणों के तीन रूपों पर विशेष ध्यान दिया, वाणिज्य के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से तथा वित्त के माध्यम से, और उन्होंने स्पष्ट रूप से समस्या की जड़ को पकड़ा कि ब्रिटिश आर्थिक साम्राज्यवाद या उद्देश्य भारत की अथ व्ययस्था को ब्रिटेन के अधीनस्थ करना है। विदेशी शक्ति द्वारा भारत में उपनिवेशवादी अथव्यवस्था की मूल चरित्रगत विशेषताओं को निम्नलिखित रूप से विकसित करने की चेष्टा का भारतीय नेताओं ने बड़ी तीव्रता से विरोध किया। भारत का कच्चा माल के पूरक देश का रूप देना, ब्रिटिश उत्पादों की मण्डो बनाना तथा विदेशी पूँजी के निवेश का क्षेत्र बनाना। उन्होंने देश के औद्योगिक विनाम में सहाय्य होने के बदले घातक मिद्ध होने तथा देश की औद्योगिक परागति में और अधिक वृद्धि करने वाले मिद्ध होने के कारण सरकार की सीमा शुल्क, व्यापार परिवहन और कराधान की नीतियों का विरोध किया। इन नेताओं में बृहती ने तो दोनों, राजनैतिक तथा आर्थिक, आचारों पर रेलों यागान और उद्योगों में बड़े पैमाने पर विदेशी पूँजी के आयात का तथा सरकार द्वारा इन क्षेत्रों को दी गई मुविधाओं का विरोध किया। मना और असैनिक सेवा पर हो रहे व्ययों पर प्रहार करते हुए उन्होंने ब्रिटिश सर्वोच्चता के भौतिक आधार को ही चुनौती दे डाली। सरकार की भूमि लगान और कराधान की नीतियों पर प्रहार करते हुए उन्होंने ब्रिटिश शासन के आर्थिक आधार को कमजोर करने की चेष्टा की। उन्होंने भारतीय नया और भारतीय वित्त के अशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रसार के लिए प्रयोग की आर्थिक गोपण का एक अर्थ रूप बताते हुए उसकी निंदा की। कुछ नेता तो इन सीमा तक बढ़ गए कि वे स्वयं ब्रिटिश शासन के स्वर्ण के सारे भार का भारतीय वित्त पर डालने के औचित्य पर ही प्रश्न करना लग। निकासी के प्रश्न को तो उन्होंने साम्राज्यवादी प्रयत्न के आर्थिक दृष्टिकोण का सजीव उदाहरण बताया। उन्होंने साधारण लाकप्रिय परंतु सशक्त भावनाओं के अनुसार इन विदेशी आर्थिक शापण का प्रतीक बताया।

उनकी सभी आर्थिक भागों का अंतर्गत मूल आधार यह इच्छा थी कि वास्तविक राष्ट्रीय आर्थिक नीति का निर्धारण इंग्लैंड के नही प्रत्युत भारत के हितों के ही मद्देन में किया जाना चाहिए। इसने अतिरिक्त आर्थिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व भारतीय आर्थिकता की इंग्लैंड की अधीनता का कम करने और यहाँ तक कि समाप्त करने की



साधना में वृद्धि की जा सके। उन्होंने सरकारी राजस्व को इस प्रकार से व्यय करने पर बल दिया जिसमें समाज के अधिचर में अधिक लोभों का अधिक में अधिक लाभ मिल सके। यह ठीक है कि उन्होंने कृषक वर्ग अथवा श्रमिक वर्ग की मांगों को अलग में नहीं उठाया, न ही उन्होंने जमीन की पट्टेदारी की चालू प्रथा में किसी प्रकार के सुधार की मांग को उठाया और न ही कारखानों के मजदूरों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा। यहाँ तक कि यह तत्पर परिवर्तनों समय में भी राष्ट्रवादी आंदोलन की एक दुर्बलता का ही सूचक है परन्तु जहाँ तक यह विवेकपूर्ण दृष्टिकोण था क्योंकि उनका विश्वास था कि इस देश का समाज का सभी वर्ग ब्रिटिश राज्य में आर्थिक दृष्टि में विद्यमान है और उनके आंदोलन का फलस्वरूप हानि वाले राष्ट्रीय आर्थिक पुनरुद्धार का व्यापक कार्यक्रम में सभी का लाभ वित्त प्राप्त होना आवश्यक है।<sup>19</sup> उनका विचार था कि जहाँ वे भारत ही राष्ट्र के लिए आर्थिक न्याय और समानता की प्राप्ति के सघन में सलग वे वे वर्गों में न्याय और आचित्य के प्रश्न को नहीं उठाए ता जूझता है। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था जो निश्चय किया जिससे लोग म अलग-अलग की भावना पनपे जहाँ कि समय की मांग सभी लोग का एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने की थी। इस परिप्रेक्ष्य में, जो उस समय निश्चित रूप में सही था, उन्हें समकालीन यथायथा के अर्थ पक्षा की उपस्था करने के लिए ही विवश किया। भारत की अर्थव्यवस्था की दुर्बलताओं को उनके द्वारा विवेकपूर्ण पत्रों का ही यह परिणाम था कि उन्होंने अपना सारा ध्यान, सारा चिंतन भारत को औपनिवेशिक ढाँचे पर ही केंद्रित किया। इस कारण म कम से कम बौद्धिक प्रवाण की प्रथम चर्चाओं में भारत के आंतरिक संस्थानों के ढाँचे की दुर्बलताएँ उनमें ध्यान में आभल ही हो गई और वे यह न सोच सके कि वे राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की सीमाओं के अंतर्गत दलित वर्गों और समुदायों के हितों के रक्षण के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। इसका अर्थ यह है कि नहीं कि उन्होंने इस दिशा में कुछ किया ही नहीं। अपने द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत उन्होंने विशेषतः किसानों और श्रमिकों के बलाघात के लिए आंदोलन किया। उदाहरण के रूप में उन्होंने वागान मजदूरों के संरक्षण के लिए व्यापक और प्रबल राजनैतिक आंदोलन किया, यहाँ उनके इस कार्य में भारतीयों के किसी अर्थ हित के साथ कोई टकराव नहीं था क्योंकि इन श्रमिकों के नियोजक वागान मालिक विदेशी थे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 19वीं शताब्दी के अंत में कई राष्ट्रवादी नेताओं के दृष्टिकोण में नया श्रमिक समय का रूप दिखाई देने लगा था। किसानों के मामलों में उन्होंने भूमि मालिकों का बल करने और स्थायी बसेवस्तु करने के लिए निरंतर और अंत में थोड़ा सफल आंदोलन किया। बहूतों ने जमींदारों द्वारा बहुत ऊँचे लगान लगाए जाने के विरुद्ध विमानों का संरक्षण करने की वकालत की।<sup>20</sup> इनके अतिरिक्त उनका विश्वास था कि उनका मुख्य संघर्ष विमानों की दरिद्रता में था, वह विमान उनके माने आर्थिक आंदोलन में नगण्य अर्थ मालिकों के रूप में विद्यमान था। यहाँ ही बाद राष्ट्रवादी मांग थी जिसका अंतर्गत विमानों की महत्त्वता में कोई संशय नहीं था। राष्ट्रवादी नेताओं का विश्वास था कि जिस प्रकार आर्थिक साम्राज्यवाद का प्रमुख शिकार विमान था, उसी प्रकार राष्ट्रीय आर्थिक विकास का वह प्रमुख लाभ प्राप्त करने वाला होगा। कुछ मिलाकर राष्ट्रीय

नताआ का कृपि मन्त्री दृष्टिकोण उनकी आर्थिक नीतिया की कदाचित प्रधान दुर्बलता ही रहा ।

इसके साथ ही यह तथ्य भी यहाँ ध्यान देन योग्य है कि जहाँ भारतीय नताआ न किमानो और श्रमिका के वगवग हिता की वरानत करना स्वीकार नहीं किया, वहाँ उहानि उनम से अधिकाग के अपने ही सबविन वग गहरी शिक्षित मध्य वग, के सवुचित हिता के विरुद्ध जाने वाली नीतिया को प्रस्तावित करके एक बहुत ही ऊच स्तर की परोपकारिता के निष्ठात का पानन किया । हमरे ज्ञान म उनकी आर्थिक नीतिया रोजगार तलाग करने वान मध्यमग के हिता मे प्रेरित नहीं थी । यह परिणाम उनकी आर्थिक नीतिया के अध्ययन का ही निष्कप है । संक्षेप म कहा जा सकता है कि यद्यपि मध्यवग विश्वी वस्त्रा का प्रघात उपभोवता था तथापि उहाने कपास पर आयात गुन हटाा की माग की उहानि उद्योगा क संरक्षण की माग की । इसका मूल्य भी अतत इसी वग का चुकाना पडता । यद्यपि बडिया दानदार चीनी का उपयोग इसी वग द्वारा अधिकागत किया जाता था तो भी दानदार चीनी पर लग कर क औचित्य का इस वग के बहुत मार नेनाआ न समथन हा किया । यद्यपि विदेशी सामान अतलाकत अधिक सस्त थ ता भा वन लागान म्बदेशी का प्रचार किया । उहानि स्पये के अवमूल्यन का स्वागत किया यद्यपि इसका स्पष्ट अथ यह था कि आयातित विदेशी सामान के खरीदार हान क नात इस वग क सन्ध्या को, निश्चिन आय वाने शिक्षित कर्मचारी होने के कारण स्पय क निमी प्रकार के अधिमूल्यन न लाभ और अवमूल्यन स हानि ही सभावित थी । वहुना न आयकर का समथन और नमक गुल्म का विराध किया । के ऊच वेतना म कटीनी और निम्न वेतन-भोगिया, चपडामियो, सिपाहिया और कतकों, के वतना म वद्धि चाहन थ । उद्योग की उननि और लोक हितकारी गतिविधिया के लिए के ऊचे पराधान की क्वालत करने का प्रस्तुत थे । उहाने मध्यवग का आगम पहुचान वाने रला क विवाम का विराध किया और उसके बदले गिचाई और उद्योग के विश्वास का पथ ग्रहण किया । बहुत मार राष्ट्र-घादिया न विदेशी पूजी मे राष्ट्र के विवाम का विराध किया यद्यपि इन विवाम स शिक्षित भारतीया के लिए अजीविका के जनक ए क्षेत्र उपनथ हात थ । उहाने मुकदमेराजी द्वारा किमाना का मवनाश करन वाली ब्रिटिश द्वारा निमित्त बचहरिया का स्थान ममकौता ग्यायालया अथवा ग्राम पचायता को दन क लिए सत्रिय आदानन किया । यह ठीक है कि उहाने कुछ एक शहरी मध्यवर्गीय और उच्चवर्गीय लागान की कुछ एक मागो का उठाया परतु भारतीय समाज क सभी वर्गो की आर्थिक मागान क आधार पर किए जा रह आदोलन के एक अग के रूप म ही यह सब कुछ किया ।

इम सबध मे दाना, भारतीय और विश्वी लेखका द्वारा एक गती प्राय ही यह की जाती है कि प्रारम्भिक भारतीय राष्ट्रवादी लेखका लोक नेताआ पत्रकारा और चिन्ता को भारत के नए वर्गो के और भारतीय राष्ट्रीयतावाद के बौद्धिक प्रतिनिधि क रूप म ग्रहण करने के स्थान पर उह मध्यवर्गीय के रूप म ही देगा जाता है । बुद्धिजीवी हान के नात उनम स कुछ एक विभिन्न हिता और वर्गो और ममुदायो का भी प्रतिनिधित्व कर सकते थे और उहाने ऐसा किया भी परतु क्योकि क बुद्धिजीवी थ उनका चिन्तन स्वाय

म प्रेरित न होकर जागरूकता के स्तर पर विचारधारा से ही प्रेरित था। एक चिंतक, एक दार्शनिक और परिभाषा के व्यापक रूप में एक बुद्धिजीवी अपनी जाति, वर्ग, समाज, जहां वह उत्पन्न हुआ है के मनुष्यचित्त स्वार्थों से ऊपर उठ सकता है और प्रायः उठता है। वह अपने निजी स्वार्थों की रक्षा के समुदाय और राष्ट्र के हितों का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है। यह बात द्रुत सामाजिक परिवर्तन के, पुराने सामाजिक राजनैतिक ढांचे के नष्टभ्रष्ट ढांचे के नए वर्गों और आर्थिक तथा राजनैतिक पद्धतियों के उदय के समय और भी विशेष रूप से सही हो जाती है। मरण विषय के सभी इतिहासों में सर्वोत्तम और सर्वोच्च चिंतकों तथा बुद्धिजीवियों के समान 19वीं शताब्दी के भारतीय विचारक और बुद्धिजीवी भी दार्शनिक ही थे, किसी दल अथवा वर्ग के भाड़े के ठठूट नहीं थे। यह ठीक है कि वे वर्गों और समुदायों से ऊपर उठी उठ पाए तथा उन्होंने वर्गों और समुदायों के हितों का विमुक्त रूप में प्रतिनिधित्व भी किया परंतु यह सब उहाने प्रत्यक्ष रूप में उस वर्ग अथवा जाति के सदस्य होने के नाते अथवा उसमें बफादार सेवक होने के नाते नहीं किया प्रत्युत उहाने तो यह सिद्धांत के अंतर्गत किया। दूसरे दृष्टिकोण में उहाने अपना सारा चिंतन व्यक्तिगत रूप में और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ही किया परंतु ऐसा हुआ कि अस्तुगत रूप में तथा अपनी सचेत धारणाओं के परिप्रेक्ष्य के बाहर उनका चिंतन सामाजिक हित से जुड़ने के साथ साथ जसा कि वास्तव में हुआ विभिन्न वर्गों के हितों से भी जुड़ गया। विचारणीय विषय तो यह है कि भारतीय राष्ट्रवादी नताशा और चेतना का चिंतन और उनकी गतिविधियों का सुस्पष्ट रूप में अध्ययन और विश्लेषण किया जाना चाहिए जिससे कि यह दखा जा सके कि वे किसका प्रतिनिधित्व करना चाहते थे और और किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यह किसी राजनैतिक नेता का अथवा व्यवहारशील बुद्धिजीवी का प्रथम किसी एक वर्ग अथवा जाति विशेष से उद्भव मानना जा सकता है पर इस धारणा में उम वर्ग अथवा जाति विशेष का होने का ठप्पा लगाना मानव भौतिकवाद के बंधनगत प्रयास (समाज शास्त्रीय दृष्टि के भी) के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। वास्तव में प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवादी नेता अपने आप में कोई एक वर्ग नहीं थे। उनके जीवन विचार और नीतियों की प्रतिक्रिया का स्तर तथा अर्थों का स्तर विचारकों के थे न कि किसी मनुष्यचित्त निजी स्वार्थों के नाते विभिन्न समुदायों के।

भारतीय राष्ट्रवादी नताशा का आर्थिक दृष्टिकोण मूलतः पूंजीवादी था। आर्थिक जीवन के उगमगत प्रत्यक्ष क्षेत्र में उन्होंने पूंजीवाद के विकास की सामान्यतया और आद्यो गिक पूंजीपतियों के हितों की विशेषता बताना की। परंतु यदि कभी कभी ऐसा लगता है कि भारतीय नताशा ने औद्योगिक पूंजीपतियों पर आवश्यकता से कुछ अधिक ध्यान दिया तो यह इतिहास सही हुआ कि उनका दृष्टिकोण हम वर्ग विशेष के निहित स्वार्थों तक ही सीमित था। वास्तविकता यह थी कि उनका यह विश्वास था कि आर्थिक क्षेत्र में ही पुनरुद्धार का एकाग्र उपाय पूंजीवादी प्रणाली पर औद्योगिक विकास था। अथवा, दूसरे शब्दों में उस समय अस्तुगत रूप में औद्योगिक पूंजीपतियों का हित ही राष्ट्र के प्रमुख हित के माना जाता था। ये पूंजीपतियों के समर्थक थे क्योंकि उनका विश्वास था कि अपना भाषणा और लेखों में जिन द्रुत औद्योगिकरण की वे रणनीति आ रहे थे

उसे यही वग काय रूप दे सकता था। ये बंचल औद्योगिक पूँजीवादी वग का केवल इस रूप में प्रतिनिधित्व करते थे कि उनका आर्थिक चिंतन और कार्यक्रम पूँजीपतियों के पक्ष पर व्यवहार में आने वाले औद्योगीकरण की सीमा के बाहर जा ही नहीं पाया था।

इस सदन में यह बात स्मरणीय है कि 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में भारतीय पूँजीपति वग, औद्योगिक और व्यापारिक मूलतः सरकार समर्थक था और उसने पनपते राष्ट्रवादी आंदोलन को सक्रिय समर्थन नहीं दिया। कांग्रेस के प्रत्येक अविवेक्षण में बोस की बमो के रोने विल्लान के अभिलेख का अध्ययन यह मान को विवश करता है। मुख्य कारिज्य और उद्योग प्रारंभिक राष्ट्रवाद्या का वित्तीय महायत्ना के रूप में एक पाई तक नहीं गैर थे। दादाभाई नौरोजी ए० आ० ह्यूम और विलियम वडररन + इंग्लंड में काम करते समय अपना निजी धन लगाया। सक्रिय रूप से भारत समर्थक अंग्रेज लीडर नेता विलियम डिंगवी को अपने जीवन निवाह के लिए बहुत सारे भारतीय राजकुमारों के निजी हितों के इंग्लंड में प्रतिनिधित्व करने का काम करना पड़ा। जस्टिस रामाडे, ए० एम० बोस, एल० एम० घोष, पी० एम० मेहता + डी० ई० वाचा राजपतराय मन्त भाहन मालवीय और अयान्य का अपनी व्यावसायिक आय पर जीवन निर्वाह करना पड़ा। लोकमान्य तिलक कानून के प्राइवेट छात्रों के लिए खोले गए ट्यूशन के तालेज से अपनी आजीविका चलाते थे। जी० के० गोखले दक्षिण शिक्षा समिति के सदस्य के रूप में घोड़ा मा ही वेतन पाते थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक प्राइवेट कालेज चलाने थे। जी० मुन्शे और विपिनचंद्र पात्र पत्रकार के रूप में काम करते थे। पाल भण्डार्य का कोला तुन्ड वेतन मिलता था। इस युग में राष्ट्रवादी पत्रकार मन्वे अर्जुन वट्ट व्यक्ति हाता था, जो मामूली से वेतन पर और प्रायः भूखे पेट राष्ट्रीय विचारों का प्रसार करता रहता था। इस अवधि में कांग्रेस द्वारा इकट्ठी की गई विपुल धनराशि केवल राष्ट्रीय विचारप्रसार के समर्थक महासभा जैसे राजकुमारों और बड़ बड़ जमींदारों से ही प्राप्त हुई। वसाई सूनी उपड़ा उत्पादन मिनो के प्रवक्ताओं ने यहां तक कि 1905 में भी स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने से इनकार कर दिया। प्रथम विश्वयुद्ध के उपरान्त ही भारतीय पूँजीपति वग राष्ट्रवादी आंदोलन का उल्लेखनीय परिमाण में समर्थन और राष्ट्रवादी नैतता तथा दलों का वित्तीय सहायता देने लगा।

यहां हम इस तथ्य का किन्हीं दोहराना चाहेंगे कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसका सचानत राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी, यदि आप करना चाहें तो सांख्यिक कर रहे थे। उन्होंने पूँजीवादी दृष्टिकोण इसलिए नहीं अपनाया कि इनके पीछे उनके सन्तुलित स्वाधे निहित थे प्रत्युत इनके पीछे उनका य० विश्वास काम करता था कि पूँजीवादी विकास ही एक ऐसा माग था कि जिस पर चलकर भारत आर्थिक दृष्टि से विकसित और संपन्न हो सकता था। बुद्धिजीवी हान के नाम के चानू मुन्शे प्रारंभिक आर्थिक मिद्वान और पश्चिमी व्यवहार के लक्ष्य के अंतर्गत ही काम करते रहे परंतु इस समय के साथ उन्होंने राष्ट्रीय शक्तिवादी स्थिति अपनाई जिसका स्वाभाविक परिणाम भारत में साम्यवाद के वर्तमान ढांचे को उल्लास फेंकना और इस रूप में देश की आर्थिक गतिशीलता को समाप्त करना था। उसके अतिरिक्त ब्रिटिश भारतीय दरवारी अधिकांश

के चिंतन की अपेक्षा इन नेताओं के चिंतन में समकालीन यथार्थता अधिक भवती थी। ब्रिटिश भारतीय आर्थिक नीतियों की अपेक्षा इन नेताओं की आर्थिक नीतियों में भारतीय समाज के सभी वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व प्राप्त था। यह सत्य है कि उनका पूँजीवादी वर्ग को भारत का आर्थिक ऋणधार मानने का विश्वास आर्थिक दृष्टि से उनकी एक बहुत बड़ी दुर्गति सिद्ध हुआ। यह एक ऐसा पक्ष था जिसने प्रारंभिक भारतीय नेताओं को राजनैतिक समर्थन के लिए जनता के कुछ एक उच्च और मध्यम वर्ग पर निर्भर रहने का विवश कर दिया। यही कारण था कि इस अवधि में राष्ट्रीय आंदोलन में न गहराई आ पाई और न ही जन जन में उसे व्यापक समर्थन मिला अतः वह अप्रभावी बन गया।

समय जाने पर आर्थिक आंदोलनाना भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं का राजनैतिक मांग पेश करने का प्रेरित किया क्योंकि वे अब अनुभव करने लगे थे कि राजनैतिक शक्ति प्राप्त होने पर ही आर्थिक नीतियों का भली प्रकार लागू किया जा सकता है। वे अब स्वतंत्र औद्योगिक अव्यवस्था के, विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की दृष्टि से ही राजनैतिक प्रश्नों पर विचार करने लगे। हाँ, उनकी राजनैतिक रियायतों की मांग उनके आर्थिक अभिप्राय में हटकर ही उठाई गई। उनकी प्रशासन में सुधार और राजनैतिक सत्ता में भागीदारी की मांगों का एक महत्वपूर्ण कारण प्रशासन का आर्थिक विकास और लोककल्याण का एक बहुरंगी साधन बनाने की इच्छा थी। जैसा कि हम पहले लिखा चुके हैं कि तृतीय प्रत्येक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रश्न को राष्ट्रवादी नेताओं के एक वर्ग ने जयवा दूसरे वर्ग ने देश की राजनैतिक दृष्टि में पराधीनता की स्थिति के साथ अथवा राजनैतिक स्वशासिता के साथ जयवा कम में कम राजनैतिक अधिकारों में भारतीयों की भागीदारी बनाने की इच्छा के साथ जोड़ दिया।<sup>1</sup> अतः बहुत सारे राष्ट्रीय नेता इस निष्कर्ष को निकालने पर विवश हुए कि क्याकि ब्रिटिश भारतीय प्रशासन केवल शासन के कार्य की पूर्ति का साधन था,<sup>2</sup> अतः देश तभी आर्थिक दृष्टि से विकसित हो सकता है जब विद्युत् ब्रिटिश शासन का स्थान एक ऐसी राजनैतिक व्यवस्था ले जिसमें भारतीय महत्वपूर्ण और प्रभावी भूमिका निभाए।

हमारे अध्ययन के अंतर्गत अवधि में यदि राष्ट्रवादी नेताओं के पास राजनैतिक अथवा आर्थिक शक्ति के रूप में लिखाने के लिए कुछ नहीं था तो इसका कारण क्याचित् उनके राजनैतिक कार्य और आंदोलन का एक अपना ही ढंग था। इस अवधि में राष्ट्रवादी गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण पक्ष निरल अपवादों को छोड़कर, लोकप्रिय आंदोलनों और गतिविधियों तथा राजनैतिक सघर्षों का जभाव था, जिनके बिना प्रस्तावों, स्मरणपत्रों, समाचारपत्रों के सफलताओं और लेखों का कोई राजनीतिक प्रभाव ही नहीं पड़ सकता था। आर्थिक प्रश्नों की गहरी ओर यहाँ तक कि बुद्धिमत्ता पूर्ण जानकारी के बावजूद भारतीय राष्ट्रवादी नेता भारत सरकार की नीतियों का प्रभावित करने में सफल नहीं हो पाए अथवा राष्ट्रवादी आंदोलन को किनेपे शक्ति नहीं दे पाए ता इसका कारण उनकी आर्थिक नीतियों और मांगों के पीछे जनता के आंदोलन और सघर्ष का अभाव था। उनकी असफलता इस दाहर विश्वास का न ताडने में निहित थी कि ब्रिटिश राज्य अपराजेय है और पूँजीवादी उत्पादन पैली एकमात्र समव उपाय है। ब्रिटिश सत्ता

की पूरा दक्खिन को चुनौती देने का आत्म विश्वास और सामर्थ्य जुटान में उन्हें दशाब्दिया लगे गये। उस समय तक ये ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में सुधार की बात कहते थे जिसे कि उस भारतीय आर्थिक विनास का एक अच्छा साधन बनाया जा सके। उन्होंने ब्रिटिश शासन की सुशामन की, उन पर प्रभाव डाला की चेष्टा की परन्तु उम्दाह फेंकने की नहीं सोची। भारतीय नेता इसके अतिरिक्त स्वयं अपने और विशाल जनता के बीच की गहराई चाई को पाट नहीं सके अथवा जनता के विनाश समुदाय को राजनतिक गति विधि में अपना सक्रिय साथी नहीं बना सके। परन्तु उनके पास मनुष्य के मन का अध्ययन करने की प्रतिभा थी। अतएव उन्हीं दोस उपलब्धिया के अभाव का कारण सही आर्थिक जानकारी का अभाव और नीतिया न हानर राजनतिक जन समर्थन का अभाव ही था। यह सुझाया जा सकता है कि यह वस्तुन राजनतिक जन समर्थन था न कि अपेक्षाकृत अच्छी आर्थिक जानकारी अथवा नीतिया अथवा उनकी कालत थी, जो इस अध्ययन के अतगत ज्ञान के समय के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हमारा अध्ययन के अतगत अवधि के आंदोलन से भिन्न करना है। इस प्रारम्भिक काल में ही ब्रिटिश प्रशासन की आर्थिक परिधि की राष्ट्रवादी आलोचना की प्रमुख स्वरूपा का भली प्रकार और वैज्ञानिक ढंग से निर्धारण किया गया। परन्तु राष्ट्रवादिया का तो इस पर बहुत भिन्न करना पडा। निम्नदेह उन्होंने पुराने आर्थिक सत्या और तर्कों का व्यापक परिमाण में प्रचार किया। उन्होंने पुराने सत्या में राजनतिक जीवन फूटा परन्तु फिर भी यह कहा जा सकता है कि वे इनसे आगे नहीं बढ़ पाए।

महत्वपूर्ण विषय यह है कि उन्होंने मुख्य आर्थिक प्रश्नों को इस ढंग से पेश किया कि उससे ब्रिटन और भारत के आर्थिक हितों के मध्य संघर्ष उजागर हो गया। उन्होंने इस तथ्य का निर्देश किया कि भारतीय यथायथा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनतिक और आर्थिक पक्ष यह था कि भारत आर्थिक क्षाण के लिए विदेशी शक्ति द्वारा शासित किया जा रहा था। उनके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का इंग्लैंड तथा यूरोपीय राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में भिन्न पक्ष संक्षेपत यह था कि इस देश की अर्थव्यवस्था और वित्त विदेशी शक्ति द्वारा नियंत्रित है। उन्होंने आर्थिक समस्या के समाधान के लिए स्पष्टतः ऐसे सुझाव दिए जिन्हें ब्रिटिश सरकार कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी, इस रूप में उन्होंने इस तथ्य को सामने रखा कि राष्ट्रीय आर्थिक मागा की पूर्ति के लिए तथा नीतियों को लागू कराने के लिए राजनतिक स्वायत्तता आवश्यक थी। उन्होंने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जिसमें शासक और शासित के बीच टकराव इस प्रकार में बढ़ना गया कि राजनतिक सत्ता अथवा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष अनिवार्य हो गया। एक बार विदेशी शासन और राष्ट्रवादी आंदोलन कर्त्ताओं के बीच जन विवाद के मुख्य विषय इस रूप में प्रस्तुत किए गए जब एक बार भारत व ब्रिटिश शासन के बीच अनविरोध स्पष्ट हो गया तो गहरी रणनीति अपनाता ता समय की बात ही रहे गई। साम्प्रतिक राजनतिक संघर्ष बाद में आ सकता था और आया। शक्तिया और रणनीति को समझने की गतिविधिया का प्रमुख संबंधित विषयों के सम्बन्ध में ठीक किया जा सकता था।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस युग के लगभग सभी राष्ट्रवादी नेताओं की राज-



नैतिक गतिविधि जनता का सावधानी के साथ राजनैतिक शिक्षण देने तथा उन्हें जाधुनिक राजनैतिक और राष्ट्रवादी चिंतन तथा गतिविधि के योग्य बनाने के ही उद्देश्य का लिए हुए थे। भारतीय जनता यह भली प्रकार समझते थे कि उनका कार्य भावी राजनैतिक संघर्ष के लिए भूमिका तैयार करने का ही था। उदाहरणार्थ डी० ई० वाचा का 12 जनवरी 1905 को लिखे एक पत्र में दादा भाई नौरोजी ने लिखा—

कांग्रेस ने जनपती पीढी के मन में स्वयं अपनी मदगति और अप्रगतिशीलता के विरुद्ध असंतोष और अधय के जो भाव उत्पन्न किए हैं, वह अपन जाप में एक उपलब्धि है। यह उसका अपना ही विकास और प्रगति है। कार्य अपेक्षित शक्ति का निरंतर चयन है। भले ही वह हिंसापूर्ण हो अथवा शांतिपूर्ण शक्ति के स्वरूप का निवारण ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश जनता की बुद्धिमत्ता या मूर्खता पर निर्भर रहेगा।<sup>2</sup>

इस युग के नेताओं की उपन्यासात्मक बृत्त है। हा, इसके लिए तात्कालिक लाभ को फलता का मापदंड नहीं बनाना होगा। उन्होंने भारत की जनता को सामान्य आर्थिक शक्ति के प्रति जागरूक किया। उन्होंने भारतीयों का सामान्य शत्रु से परिचित कराया और इस प्रकार एक सामान्य राष्ट्रीयता की भावना को सुदृढ़ बनाने में सहायता दी। उन्होंने जनता को अपनी आर्थिक दुर्दशा और अपमानित स्थिति से तथा उसमें श्रम की संभावना से परिचित कराया। उन्होंने अस्पष्ट आर्थिक जाकाशाका का एक स्पष्ट राष्ट्रवादी स्वरूप दिया तथा आर्थिक विकास के विचारों का प्रचार किया। सुहाने लोगों के मन में राष्ट्रीय मजबूती में वृद्धि करने की लालसा उत्पन्न की और इसके लिए उनसे सामान्य आर्थिक विकास का सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तुत किया तथा आर्थिक उन्नति की प्राप्ति के लिए मार्ग की आर्थिक और राजनैतिक बाधाओं का और उन पर विजय प्राप्त के उपायों का निर्देश किया। इन महान कार्यों का पूरा करने में दोना, मनुष्य और उग्रवादी नेताओं ने समान रूप से ही योगदान दिया। दोनों ने ही आर्थिक वितरण की उच्च स्तर की क्षमता और राष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन किया। हमारा यह प्रश्न निकालना गलत नहीं होगा कि इनकी असफलताओं का वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रीय विभाजन के विकास के लिए सुदृढ़ आधारगिरी रखी। इस प्रकार व जाधुनिक भारत के निधाताओं में गौरवमय स्थान रखते हैं। उस युग के नेताओं में से ही एक के निम्नलिखित श्लोक में बड़े बड़े कदाचित् इस युग के महापुरुषों के कार्यों का आर्थिक उत्तम मूल्यांकन किया जा सकता है

यदि हम यह नहीं भूलना चाहिए कि हम देश की प्रगति ही उस स्थिति में है जहां हमारी नहीं उपलब्धियां का छोटा गिनाई देना स्वाभाविक है तथा हमारे लिए बारबार दुःख दायक असफलता का मुंह देखना भी स्वाभाविक है। इस संघर्ष में यही हमारी नियति है। हम जब सौंप गए कार्य को निभा चुकते हैं तो हमारा उत्तमगतिवत्त्व समाप्त हो जाता है। अब जाग का कार्य देश की भावी पीढी को दिया जाना चाहिए ताकि वे सफलतापूर्वक देश को सवा कर सकें। हम वर्तमान पीढी को तैयार तो प्रमुख रूप से अपनी असफलताओं का साथ ही अपने देश की सवा कराने में मनुष्य बनाना चाहिए। यह कहना जितना ही कठिन क्या त ही हमारी इन असफलताओं

स भावी पीढी को वह शक्ति मिलेगी जिससे वह महा लक्ष्या का प्राप्त कर सकेगी। 4

## संदर्भ

- 1 उदाहरण के रूप में देखिए नीरोजी एसेज पृ० 26-7 और रानाड एसेज पृ० 23 65 6 118 9
- 2 उदाहरणार्थ देखिए, नीरोजी एसेज पृ० 37 131 5 दि एन्सीजसीस आफ प्राग्रस इन इंडिया जे० पी० एल० एल० अप्रिल 1893 (वड X V सख्या 4) पृ० 15-6
- 3 यह तब कि 1904 में विल्ल सदस्य एडवड ला ने उस समय के नेताओं में सर्वाधिक मद्भाग्यो जी० क० गोखले की सतत आलोचना के विरुद्ध उत्तेजित होकर इस प्रकार से चीखे बिल्लाए का 'जब वह सदन में अपना स्थान ग्रहण करते हैं तो वह कर्नाचित अचेतन रूप से हैं वे भादतन विलाप करने वाले की भूमिका और आचरण करने लगते हैं सरकार के दोषों पर उनका शोक और रुग्ण दतना अधिक वर्णनापूा होता है मानो उन्होंने सब अभ्यास आर प्रतिभण द्वारा ऐसा किया है (एल० सी० पी० 1904 वड XLIII प० 542)
- 4 उदाहरणार्थ दादा भाई नीरोजी न लिखा हम बार बार यह याद दिलाना सवया निरपक और ओछापन है कि ब्रिटिश राज्य न अराजकता के बाद व्यवस्था ला दी है हम देश के अनुवर्ती दोषों का तथा देश के भौतिक और नतिक दिवानियेपन का स्याई बहाना नहो बनाया जा सकता आज के भारतीयों ने वह अराजकता न देखी है और न हां वह उलका अनुभव करत हैं भने ही व उसे समझने हैं और व्यवस्था आने के लिए आभार भी प्रकट करत हैं परतु साथ हा वतमान में वे निवासी दुगति और विनाश ही देख रह हैं तथा उस पर विनाप कर रहे हैं (पावर्ती प० 219) इसी प्रकार आर० सा० दत्त ने लिखा ब्रिटिश शासन ने शानि अवश्य स्थापित की है परतु ब्रिटिश प्रशासन ने भारत में राष्ट्रीय सपना के साता का उतन अथवा विस्तत नहो किया है (ई० एच० II प० VII) और बेसरी न अपन 31 माघ 1903 के अत्र में किया भारतीयों में एवता और समानता है परतु यह उसी प्रकार की एवता और समानता है जिस प्रकार की समानता एक स्वामी के सेवकों में पाई जाती है अथवा एक गडरिए की भडा के समुदाय में पाई जाती है हमारे शासक हमें उत्तरदायी काय सौपने की अवका ध्यापार और उद्योग में हमें साम्रीदार बनाने को तयार नही (आर० एन० पी० बख 4 अप्रिल 1903) और देखिए प्रमाण के लिए नीरोजी पावर्ती प० 209-12 224-8 579 652 3 ममाना पूर्वोद्धत प० 443 447 पर उद्धत सी० पी० ए० पृ० 22 पर बगासी 10 मई 1884 मरणा के 6 जून 1886 के अत्र में ए० एल० राय का लेख मल० एम० घोष सी० पी० ए० प० 762 आर० एन० मुघोलनर इंडियन पालिटिक्स पृ० 37 जी० एल० अम्पर, ई० ए० प० 330.
- 5 यह पर्याप्त रोचक तथ्य है कि समझीता पसा नेताओं ने ही नहीं पर्युन अमून बाजार परिषद और बी० जी० तिसव ने भी भारत के उद्ध्य के लिए ब्रिटिश जनता और संसद का ह्दय जीतने की आवश्यकता अनुभव की उदाहरण के लिए देखिए ए० बी० पी० 8 अक्टूबर 1874

## 576 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास

- 26 अप्रैल 1883 तिलक, रिप० आई० एन० सी० 1904 पृ० 150 1, और प्रधान एंड भागवत पूर्वोद्धत, पृ० 80
- 6 यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि विभिन्न नेताओं ने यह धारणा को विभिन्न अवसरों पर और विभिन्न प्रश्नों के संघ में अपनाई उदाहरण के लिए जार० सी० दत्त के लिए सत्रम् 1897 1901 की बाड़ी सी अवधि में अर्थात् इंग्लैंड और इंडिया ट्रेड के तथा इकोनामिक हिस्टरी आफ इंडिया के प्रथम खंड के वर्षों की मध्यावधि में आया
- 7 नीरोजा पावर्टी पृ० V VII 211 214 स्पीचज, पृ० 142 227 8 276-8 328 396 19 जनवरी 1898 के स्टेट्समन में 7 अगस्त 1903 के 'इंडिया' में पृ० 67 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 674-7 राय, पावर्टी, पृ० 37 9 पी० महता स्पीचेज पृ० 815 जी० एस्० अम्बर ड० ए० शापक (प्रथम) पृ० तथा पृ० 116 7 123 5 239 329 ईस्ट एंड वेस्ट 1903 (खंड II) पृ० 883, दत्त ड० एच० I पृ० XV ई० एच० II पृ० XVIII (वस्तुतः उनके इकोनामिक हिस्टरी प्रथम वंशना खंडों में यह भावना अंतःप्रविष्ट है) प्रधान एंड भागवत पूर्वोद्धत, पृ० 72 पर तिलक, एल० एम० घोष सी० पी० ए० पृ० 761, गोखले स्पीचज पृ० 1084 1156 7 30 मई और 6 जून 1886 के मराठा में ए० एल० राय का लेख समाचारपत्रों के लिए देखिए हितचू 25 मार्च (जार० एन० पी०) बब 3 अप्रैल 1880) ए० पी० पी० 19 अक्टू० 1882 4 जून 1883 7 अक्टू० 1886 12 फर० 1892 20 मई 1896 मराठा 21 दिस० 1884 30 दिस० 1894 30 अक्टू० 1904 आन्ध्र बाजार पत्रिका 31 मार्च (आर० एन० पी०) बग० 5 अप्रैल 1884), नवविभाकर 21 अप्रैल (वही 26 अप्रैल 1884) साधारणी 15 जून (वही 21 जून 1884) समय 30 नव० (वही 5 दिस० 1885) शमसुल अखबार 12 अप्रैल (आर० एन० पी०) एम० अप्रैल 1886) खमसुल अखबार 17 जून (वही जून 1886) धूमबतु 20 मई (आर० एन० पी०) बग०, 28 मई 1887) बगवासी 30 जून (वही 7 जुलाई 1888) 14 जून (वही 21 जून 1890) तोहफा ए हिंदू 13 अगस्त, (आर० एन० पी०) एन० 19 अगस्त 1891) हितकारी त्रिपिरहित (आर० एन० पी०) बग० 17 दिस० 1892) बगवासी 1 सित० (वही 8 सित० 1884) पूना बंधव 15 मार्च (आर० एन० पी०) बब 21 मार्च 1896) जमी उल्ल उलुम 14 अप्रैल (आर० एन० पी०) ए० 21 अप्रैल 1896) इंदु प्रकाश 8 अगस्त (आर० एन० पी०) बग० 18 अगस्त 1898 बगाली 9 अप्रैल 1900 केमरा तारीख नहीं है (आर० एन० पी०) बब० 18 जन० 1902) इंडियन पीपुल 27 फर० 1903 हिंदू 13 अक्टू० 1903 हिंदू विजय 8 फर० (आर० एन० पी०) बब 11 फर० 1905)
- 8 उदाहरणार्थ अस्पृश्य 15 मई (आर० एन० पी०) बब 21 मई 1881) ए० बी० पी० 19 अक्टू० 1882 13 फरवरी 1894 साम प्रकाश 21 अगस्त (आर० एन० पी०) बग० 26 अगस्त 1882) हिंदी प्रतीक, जनवरी-फरवरी (आर० एन० पी०) एन० 8 जून 1901) सी० वाइ० चिन्तामणि एच० आर० में फरवरी 1903 पृ० 233
- 9 ए० ओ० ह्यूम ए स्पीच आन टि इन्वियन नेशनल कांग्रेस एंड इंस ओरिजिन एम्स एंड ओइजकस 30 अप्रैल 1888 को इलाहाबाद की जनसभा में किया गया भाषण पृ० 16
- 10 नीरोजगाह महता ने इस धारणा को दूसरे रूप में प्रस्तुत किया उन्होंने राष्ट्रवादी आंगन के ब्रिटिश शासन के बनिया वान भाग से अधिक परिष्कृत खान का एक प्रयाग बनाया (स्पीचज पृ० 483)

- 11 1903 में कांग्रेस के अध्यक्ष लालमोहन घोष ने इसे बड़े ही रोचक ढंग से निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया 'हम क्या यह नहीं पूछना चाहिए कि क्या हम उस नीति पर विश्वास करें जिसने बहुत वर्षों पूर्व हमारे स्वदेशी उद्योगों की हत्या कर दी है अभी बल की ही बात है जिसने बिना किसी प्रकार का सकोच किए उदार प्रशासन के अंतर्गत हमारे सूती उत्पादों पर भारी उत्पादन कर लगा दिए हैं जो निरंतर 200 लाख पौंड की सीमा तक प्रति वर्ष हमारे राष्ट्रीय ससाधनों की निकामी कर रही है और जो हमारी कृषक जनता तथा कृषि उत्पादना पर भारी कर बोध कर अतीत में सबका अनात विपन्न अकालों की तीव्रता व्यापकता और निरंतरता में बढ़ि कर रही है ? क्या हम विश्वास कर कि इन परिणामों को लाने के लिए उत्तरदायी विविध प्रशासनिक कृत्य ब्रिटिश राज्य के लोकोपकारी स्वरूप से ही सीधे प्रेरित थे ? (सो० पी० ए० में प० 743 पर)
- 12 ब्रिटिश दृष्टिकोण के लिए देखिए (जाज हैमिल्टन के विचार) स्टोक पूर्वोद्धत प० 300 पर बजन स्पीचेज I प० VI भारतीय दृष्टिकोण के लिए देखिए नोरोजी स्पीचेज प० 123 332 एतज प० 36 पावर्टी प० 216 सी० पी० ए० प० 181 पर आर० बी० घोष, स्पीचेज प० 152 ए० एम० बोस०, सी० पी० ए० प० 436 जि म्रोवेन प्लेज एंड इटम कांसीक्वेंसेज जे० पी० एस० एम० जुलाई 1879 (खंड II सत्या 1) प० 43 46 मराठा 6 नवंबर 1881 दत्त इग्जिट एंड इडिया प० 118
- 13 उपाहरण के रूप में देखिए 'गोखले स्पीचे प० 1079
- 14 उदाहरणाय बजन स्पीचेज II प० 91 और स्पीचेज III प० 98 जे० स्टुची इडिया (1903) प० 495 6 चिंतनों पूर्वोद्धत प० 390, 394 398 9 इस दृष्टिकोण के विस्तृत विवरण के लिए देखिए स्ट्राक्स पूर्वोद्धत प० 65 और अध्याय 4 जम्स मिल के दृष्टिकोण के लिए देखिए, डिग्वी पूर्वोद्धत प० 264 इफरिन के अनुसार भारत में ब्रिटिश राज्य का आधार हमारी सेनाएं हैं जो अभिक्षित और उदासीन जनता की पराधीनता को बनाए हुए हैं और जनता के शपथ के यह सांकेतिक भावना जड़ पकड़ हुए हैं कि हमारे प्रशासन में बितनी ही सुटियां क्या न हों यह 'पायपरायण निपक्ष और लाभकारी है और इसका एवमात्र विकल्प या तो मुमलमाना की शूरता और अराजकता को वापस लाना होगा अथवा हम को भारत पर विजय (इफरिन टू सेनेटरी आफ स्टेट, 9 जुलाई 1886 इफरिन पेपस) इसी प्रकार 30 फ़रवरी 1897 के भव में 'टाइम्स ने यह शायी बधारी कि उनकी अपनी जाति के इतिहास में एसी कोई उपनिधि नहीं जिसमें अपनी भारत सरकार को प्रपेक्षा ब्रिटिश जनता किसी अन्य में अधिक सब का अनुभव करे किता और में ये सभी गुण साहस 'पाय दूरदृष्टि तथा आत्म त्याग सर्वोत्तम रूप में निरंतर और गौरव के साथ दृष्टिकोण नहीं हुए किन्हीं विषय बानों के लिए बितनी भी आलोचना क्या न की जाए मुख्य तथ्यों को चुनौती नहीं दी जा सकती यह सब विषय के उपरांत उसने घोषणा की भारत में समनैय सरकार के नियम लागू नहीं हो सकते उनमें सिधा कि ऐसा करना अराजकता को बुलावा देना है भारत का जनता किसी भी रूप में स्वशासन के मंत्रणा और पुणनया अपोग्य है और वे अपने देशवासियों द्वारा शासित होना कभी स्वीकार नहीं करेंगे
- 15 1887 में जे० बी० पीने ने इफरिन को लिखे एक पत्र में टिप्पणी का 'भारत में भारत के लोगों को ऐसी कोई शिवायत नहीं है कि जिसमें शुरुय होकर वे शक्ति और धन को पर एक दें तथा शासकों के विरुद्ध समवार निकाल कर यह हो जाए' (2 अक्टूबर 1887 इफरिन पत्र)

प्रारम्भिक राष्ट्रवादियों द्वारा किए गए आर्थिक आंदोलन ने इस शिकायत की भावना को ही जन्म दिया

- 16 हमाड चौधी सिरीज खंड XLV 26 जनवरी 1897 लगभग 534 भारत सचिव जाक हैमिल्टन ने दादाभाई नौरोजी को 6 दिसंबर 1900 को लिखे एक पत्र में शिकायत की आप स्वयं अपने को ब्रिटिश राज्य का सच्चा समर्थक घोषित करते हैं परंतु उस राज्य की व्यवस्था के लिए उसके साथ अविभाज्य रूप से जुड़ी स्थितियों और परिणामों की आप निराग करते हैं (मसानी पूर्वोद्धृत, पृ० 459 पर) 30 दिसंबर 1897 के धर्म के टाइम्स ने इसी प्रकार की भावना व्यक्त की लिखा राष्ट्रवादी नेताओं के प्रति ब्रिटिश के शत्रुनाशक व्यवहार के लिए देशीय एच० एल० मिह पूर्वोद्धृत अध्याय 4 तथा देखिए टॉल्सू० एम० सितो कर दि नेटिव प्रेम आफ इंडिया एशियाटिक क्वार्टरली रिव्यू खंड VII 1889 पृ० 62 रोस, पूर्वोद्धृत अध्याय 10 और पृ० 286-8
- 17 उन्होंने आगे कहा वे मदद ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी का दम भरते हैं परंतु जो प्रस्ताव वेपारित करते हैं उनसे स्पष्ट है कि वे इस सरकार के लिए काम करना असंभव बना देना चाहते हैं (पूर्वोक्त स्थल पृ० 385 (पृ० 482 7 भा देखें)
- 18 डफरिन द्वारा 17 मई 1886 को भारत सचिव का लिखा पत्र डफरिन पक्ष कुछ मनीषों के उपरांत 7 अगस्त 1889 को ए० आ० ह्यूम को लिखे पत्र में डफरिन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह भारतीय समाचारपत्रों की स्वतंत्रता की एक सीमा निर्धारित करना चाहते हैं इस तथ्य को दस्तावेज़ बनाने के उपरांत कि ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वतंत्र प्रसंग आवश्यक उद्देश्य के लिए दिया है कि वह सरकार के कार्यों की यथोचित आलोचना और समर्थन कर तथा जनता की भावनाओं और जाकागमों को अभिव्यक्ति दे उन्हीं प्रेस से जपन निम्नलिखित दो दायित्वा व निम्नान की अपील करते हुए कहा प्रथम सरकार की आलोचना यथाय तथ्या पर जाधत हानी चाहिए सरकार के कल्पित अभिप्रायों अथवा अनुमान पर आश्रित धारणाओं का लेकर किसी प्रकार की निरा कल्पित उचिन नहीं द्वितीय सरकारी नीति की किसी प्रकार की आलोचना क्या न हो ब्रिटिश प्रशासन पर इस दश में अथवा इतना म यह अभियोग नहीं लगाया जाना चाहिए कि वह यह सब कुछ द्रवपूर्ण भावनाओं से प्रेरित होकर कर रहा है (डफरिन पक्ष)
- 19 उन्नाचरण के रूप में दादाभाई नौरोजी ने 1893 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सभापतिपद से भाषण करते हुए इस तथ्य पर बत दिया उन्होंने कहा मैं इस बात को मानता हू कि हम यह पूर्ण विश्वास करना चाहिए कि हम जा भी राजनीतिक व राष्ट्रीय लाभ प्राप्त करें किसी न किसी प्रकार से समान के सभी वय उनमें सामावित होंगे प्रत्येक वय को मिलने वाल लाभ का रूप भिन्न भिन्न होगा हम सबके लिये समान हैं और हम एक ही दिशा में अग्रसर हैं हम इच्छते ही ठहेंगे और इच्छते ही तरेंगे यदि देश संपन्न है और एक को यदि जीवन व एक क्षेत्र में उनलिन का अवसर मिलता है तो दूसरे को दूसरे क्षेत्र में मिलेगा तब कि हमारे यहाँ दश में यह उचित प्रचलित है यदि कुण में पानी होगा तो कुछ में पड़नेगा ही यदि हमारे पास समृद्धि का बूझा है तो हममें से प्रत्येक व्यक्ति अपना भाग ले सकेगा परंतु यदि कच्चा ही मूया है तो हम सबको बिल्कुल प्यासा रहने पर विवश होना पड़ेगा (इस सौ० पी० ए० पृ० 180-1 पर) और ऐलिया जोशी पूर्वोद्धृत पृ० 248-9, आर० एम० सयानी सौ० पी० ए० पृ० 309
- 20 यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 1920 और 1940 के बीच की अवधि के दौरान अधिक प्रगति के

साथ सक्रिय आंदोलन के लिए अग्रिम भारतीय वायस द्वारा ग्रहण की गई भूमि लगाना को कम करने की मांग ही कृषि सबंधी एवमात्र मांग थी 1936 तक ऊंचे लगान से किसानों के सरक्षण के प्रश्न को अलग अलग निजी तौर पर वायसियों के प्रयत्न पर ही छोड़ रखा था 1936 में वायस ने पहली बार वायसकारी पद्धति और भूमि लगान पद्धति में मौलिक परिवर्तन की मांग की उन्होंने कृषि सबंधी करो और लगाना में छूट देकर छोटे किसानों की तत्काल सहायता करने की पत्नी धार हा मांग की (इंडियन नेशनल वायस रिजायूसन आन इकोनामिक पालिसी एंड प्रोग्राम 1924-54 नई दिल्ली 1954 पृ० 13-3) गांधी जी द्वारा प्रस्तुत ग्यारह गुना में कृषि सबंधी एवमात्र मांग का सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के मूल्य के रूप में किसानों को भूमि लगान में कटौती के रूप में राहत (बी० पट्टाभि सीतारामया दि हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल वायस 1885-1935 मद्रास 1935 पृ० 619)

- 21 यह पर्याप्त रोचक है कि आर० सी० दत्त ने कम से कम एक भारतीय को वायसराय की वायसकारिणी परिपद में सम्मिलित करने का तथा उसे भूमि लगान उद्योग और कृषि विभाग सौंपने का अनुरोध किया (सी० पी० ए० पृ० 497-8)
- 22 इंडियन पीपुल, 27 फरवरी 1903 अन्यान्य सदस्यों के लिए देखिए पीछे पृ० 7 पर पान्टिपणी सं० 79
- 23 ममानों पूर्वोद्धृत पृ० 441 पर इसी प्रकार पूना सांघजनिक सभा द्वारा बनी महानत से तयार किए गए शापन पर सरकार की दो पक्षितया के उत्तर पर गोखले ने निराशा प्रकट की तो जस्टिस रानाड ने समझाते हुए कहा आप अपने देश के इतिहास में अपने स्थान को क्यों नहीं समझते ये शापन नाममात्र के लिए सरकार को दिए जाते हैं वस्तुतः ये जाता को संजोड़ित हैं ताकि वे यह समझ सकें कि इन मामलों में उन्हें क्या विचार करना है किसी प्रकार के शापन परिणामों की अपेक्षा किए बिना ही इस वाय का क्यों तक चलाना चाहिए क्योंकि इस देश में इस प्रकार की राजनीति सबंधी एक नई वस्तु है गोखले स्पीचज पृ० 929 पर)
- 24 गोखले स्पीचज पृ० 1113

## ग्रथ सूची

नोट सक्षेप की दृष्टि में केवल ग्रथ में उद्धृत स्रोतों का ही उल्लेख किया जा रहा है। पुस्तक में प्रयुक्त सक्षिप्त शीपव प्रत्येक शब्द के पूरे शीपवों के पश्चात् काष्ठक में दे दिए गए हैं

### प्राथमिक स्रोत

#### (क) पुस्तकें

- ऐक्स्ट्रेक्ट्स आफ दि प्रोवीडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर जनरल आफ इंडिया, कानून और विनियमों की रचना के उद्देश्य से सार्वजनिक (वार्पिक) 1877 1905 (एल० सी० पी०)
- बैनर्जी मुरेंद्रनाथ, स्पीचेज खंड 1 5 कलकत्ता, 1880, 1885, 1890, 1894, 1996 (स्पीचेज I आदि) स्पीचेज ऐंड राइटिंग्स (जी० ए० नारायण ऐंड कंपनी मद्रास द्वारा तिथि निर्देश के बिना प्रकाशित) (एस० ऐंड डब्ल्यू)
- बगाल नेशनल चेंबर आफ कामर्स रिपोर्ट (वार्पिक) 1887 91, 1894 1905 भ्रूचा, एस० बी०, स्पीचेज आफ इंडियन एकोनामिक्स, (बवई तिथि रंगित)
- बवई मिल ओनर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट (वार्पिक) 1885 6 1886 7 चण्दरकर एन० जी० स्पीचेज ऐंड राइटिंग्स क्विनी द्वारा संपादित एन० बी० बवई 1911
- कजल लाड (वेडान्स्टोन) स्पीचेज खंड 1 4 कलकत्ता, 1900 1902 1904, 1906 (स्पीचेज I आदि)
- देसाई, अबानाल गेसरनाल, स्पीचेज ऐंड राइटिंग्स (बवई 1918) भारत सचिव द्वारा तथा भारत सचिव को बिछ गए संप्रेषण 1875-1905
- डफरिन, मारकिंग आफ ऐंड आवा, स्पीचेज (कलकत्ता 1889)
- डफरिन पपम माइक्रोफिल्म प्रतिलिपिया के (नेशनल आर्इव्ज आफ इंडिया, नई दिल्ली)

दत्त, आर० सी०, दि पंजटरी आफ बगाल 1874 इंग्लड ऐंड इडिया, (लदन 1897)

सर फिलिप फ्रांसिस मिनिटस आन दि सबजेक्ट आफ ए परमनेंट सेटलमेंट फार बगाल बिहार ऐंड ओरिसा, आर० सी० दत्त द्वारा भूमिका (कलकत्ता 1901), फॉर्मिस ऐंड लड एर्सेसमेंट इन इडिया, (लदन 1900) (फॉर्मिस इन इडिया), इकोनामिक हिस्टरी आफ इडिया, अर्ली ब्रिटिश रूल, 1956 1901 म लदन मे प्रथम प्रकाशित का मुद्रित रूप (ई० एच० I) इकोनामिक हिस्टरी आफ इडिया इन दि विक्टोरिया एज (लदन मे प्रथम प्रकाशित का छटा संस्करण) (ई० एच० II) स्पीचेज ऐंड पेपस आन इंडियन क्वेश्चस, 1897 1900 (कलकत्ता 1904) (स्पीचेज II) ओपन जैटस टु लाड कजन, (कलकत्ता 1904) (ओपन लटस)

एलमिन ब्रल आफ, स्पीचेज (कलकत्ता 1898)

ऐमिनट इंडियस आन इंडियन पालिटिक्स, सी० एल० पारिल द्वारा संपादित, (बर्द 1892) (ऐमिनट इंडियस)

फाइनाम कमेटी रिपोर्ट आफ 1886

फाइनाशल स्टेटमेंट आफ दि गवर्नमेंट आफ इडिया (वापिक 1877-1905)

घोष, लालमोहा स्पीचेज दो भाग (कलकत्ता 1883 1884)

घोष, डा० रास बिहारी, (स्पीचेज एड राइटिंग्ज, ततीय संस्करण मद्रास तिथि रहित)

गोबल जी० के० स्पीचेज, जी० ए० नाटेशन द्वारा प्रकाशित द्वितीय संस्करण (मद्रास,

1916) पत्र व्यवहार, अप्रकाशित दि लाइब्रेरी आफ दि गासले इस्टीच्यूट आफ

पोलिटिक्स ऐंड इकोनामिक्स पूना

गवर्नमेंट आफ इडिया (भारत सरकार) के अधिनियम, 1880-1905

हसाड (ममदीय विवाद) 1880-1905

होम (पब्लिक) डिपार्टमेंट आफ गवर्नमेंट आफ इडिया, प्रोसिडिंग्ज 1880-1905

ह्यूम, ए० ओ० ए स्पीच आन इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐंड इटस ओरिजिन एम्स ऐंड

आब्जर्वेटस, 30 अप्रिल 1888 म इलाहाबाद म हुई जनसभा म भाषण

इंडियन एसोसिएशन की रिपोर्ट (वापिक) 1880 1905 जिटपुट (स्ट्रे रिपोर्ट)

इंडियन कर्सेसी कमेटी की रिपोर्ट, 1893, (कलकत्ता 1893)

इंडियन कर्सेसी कमेटी, मिनिटस आफ एविडंस ऐंड स्टेटिक्स 1893, नो 7060-2

इंडियन डिबेट्स (हसाड म) फरवरी 1902

इंडियन एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट, 1883

इंडियन फमिन कमीशन की रिपोर्ट, (1880 लदन)

इंडियन फमिन कमीशन की रिपोर्ट (1898 कलकत्ता)

इंडियन फमिन कमीशन की रिपोर्ट (1901 कलकत्ता)

इंडियन लीफनेट्स (इन्डियन) इंडियन अपील टु दि इन्डियन इलकूम पब्लिक ऐंड

इन्स्टीच्यूट्स आन बिहाफ आफ पिपुल आफ इंडिया बाई दि ब्रिटिश इंडिया एम्स

सिएशन आफ कलकत्ता, दि बीवे प्रेमीटोमी एसासिएशन, दि पूना मावतनिक मभा



- आफ मद्रास दि सिंध सभा आफ कराची, नि प्रजा हितवधक सभा आफ सूरत, 1885  
 इंडियन नेशनल कांग्रेस की रिपोर्ट (वार्षिक) 1885-1904 (रिप० जाई० एन० सी०)  
 इंडियन नेशनल कांग्रेस कंटेनिंग फुल टेक्स्ट आफ प्रेसीडेंशियल ऐंड्रेस रिप्रिंट आफ  
 थाल दि कांग्रेस रिजाल्यूशन आदि मद्रास, तिथि निर्देश नहीं (सी० पी० ए०)  
 इंडियन नेशनल कांग्रेस, रिजुल्यूशन आन इकोनामिक पालिसी ऐंड प्राग्राम 1924 54  
 (नई दिल्ली 1954)  
 इंडियन पालिटिक्स, (जी० ए० नटेसन, मद्रास द्वारा 1898 में प्रकाशित)  
 अय्यर जी० सुब्रह्मण्य सम इकानामिक आस्पेक्टस आफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया  
 (मद्रास 1903) (ई० ए०)  
 अय्यर एस० सुब्रह्मण्य (स्पीचेज ऐंड राइटिंगज मद्रास तिथि रहित)  
 जोशी जी० बी० राइटिंग ऐंड स्पीचेज, (पूना 1912)  
 लाजपत राय लाला लाजपत राय, दि मैन इन हिज बड, (मद्रास 1907)  
 लड प्राबन्स इन इंडिया, पेपस वाई आर० सी० अन्त ऐंड अदन, (मद्रास 1902)  
 लड रैवेयू पालिसी आफ इंडियन गवर्नमेन्ट, (कलकत्ता 1902) (इकन्यूटिंग रिजाल्यूशन  
 वाई दि गवर्नर जनरल आफ इंडिया इन कौंसिल न० 1 तिथि 16 जनवरी  
 1902) ।  
 लसडाग, मारनिम आफ स्पीचेज, 1888 94 2 खंड (कलकत्ता 1894)  
 मालाबारी बहुराम जी० एम० दि इंडियन प्रान्तम (बंबई 1894)  
 मालवीय, मद्रामोहन स्पीचेज, (गणेश ऐंड कंपनी मद्रास द्वारा प्रकाशित, तिथि रहित)  
 मार्शलक पी० एन० राइटिंग ऐंड स्पीचेज (बंबई 1896)  
 मेहता फिरोजशाह एम० स्पीचेज ऐंड राइटिंग सी० वाई० चिन्तामणि द्वारा संपादित,  
 (इलाहाबाद 1905) (स्पीचेज) सम अनपब्लिशड ऐंट लेटर स्पीचेज एन् राइ-  
 टिंग (बंबई 1918)  
 मारल ऐंड मटिरियल प्रोग्रेस रिपोर्ट, दि यड डिसेंनियल जे० ए० रेंस द्वारा तयार की  
 गई (लंदन 1894)  
 मारल ऐंड मटिरियल प्रोग्रेस रिपोर्ट, दि फोथ डिसेंनियल फ्रामिस सी० डेक द्वारा तयार  
 की गई (लंदन 1903)  
 नौराजी, दादाभाई एमज स्पीचज ऐंड राइटिंग, सी० एल० पारिख द्वारा संपादित  
 (बंबई 1887) (एसेज) पावर्टी ऐंड अनजस्टिफिड रूल इन इंडिया, (नया 1901)  
 (पावर्टी) स्पीचेज ऐंड राइटिंग (जी० ए० नटेसन ऐंड कंपनी द्वारा प्रकाशित  
 द्वितीय सम्स्करण मद्रास तिथि रहित) (स्पीचेज)  
 पाल, विपिनचंद्र, दि प्रूस्पेरिटी (कलकत्ता 1907)  
 पेपम रिट्रैटिंग टु चेंजेस इन दि इंडियन कर्मेंसी सिस्टम, (शिमला 1893)  
 पालियामेन्टरी पेपम (1876-1905) (पी० पी०)  
 पूना सावजनिक सभा, भारत से साधित विषयों का ईस्ट इंडिया फाइनान्स कमटी के  
 समक्ष रखने के लिए सूचनाएं संप्रहीत करने के लिए नियुक्त पूना सावजनिक सभा

की उपसमितियों की रिपोर्ट, पूना 1873

प्रोसीडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ मद्रास, 1898, 1899, 1902, 1903  
प्रोसीडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बॉम्बे, 1895, 1896, 1899, 1900,  
1901, 1905

प्रोसीडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि लैफ्टिनेंट गवर्नर आफ बंगाल 1898

प्रोसीडिंग्स आफ दि लजिस्ट्रेटिव कौंसिल फार दि एन० टब्ल्यू० पी० एंड अवध 1901  
प्रोसीडिंग्स आफ दि पब्लिक मीटिंग आफ दि इंडियन करेंसी एसोसिएशन 13 जुलाई  
1892

प्रोसीडिंग्स आफ दि पब्लिक मीटिंग हेल्ड ऐट दि फामजी कावसजी इस्टीच्यूट जडर दि  
आस्पीगिज आफ दि वॉरे प्रसीडेंसी एसोसिएशन आन सटरडे 15 जुलाई 1893  
(15 जुलाई 1893 को शनिवार के दिन प्रवाई प्रांतीय सभा द्वारा फामजी कावसजी  
संस्थान में हुई जनसभा की कायवाही)

प्रोसीडिंग्स आफ दि फ्रस्ट नाथ अरकाट डिस्ट्रिक्ट कांफ्रेंस हेल्ड आन 21 22 जुलाई  
1900 एट चित्तौड़

पब्लिक सर्विस कमिशन प्रोसीडिंग्स, 1887 7 खंड (कलकत्ता)

रानाडे, एम० जी० एस्मज आन इंडियन इकोनामिक्स (वर्ष 1898) (एस्सेज) दि  
मिसलेनियस राइटिंग्स, वाइ ग्मावाई रानाडे द्वारा प्रकाशित (वर्ष 1915) 'प्लो  
फार प्रोटेक्शन, इंडियन शुगर इंडस्ट्री,' मई और जून 1890 को टाइम्स आफ इंडिया  
में दिए गए तीन लेख जिनकी भूमिका वी० जी० काले ने लिखी (वर्ष 1915) 'प्लो  
राय, पृथ्वीशचंद्र दि पावर्टी प्रॉब्लम्स इन इंडिया (कलकत्ता 1895) (पावर्टी) दि  
इंडियन गुगर्नर ट्यूटीज (कलकत्ता 1899) इंडियन फर्मिस, देयर काजेज एंड  
रेमेंडीज, (कलकत्ता 1901) (फर्मिस)

रिजान्यूशन आफ दि गवर्नमेंट आफ इंडिया, सकुलर न० 96 एफ 6 59, 19 अक्टूबर  
1888, फॉर्मिन प्राग न० 19, सि० 1888

रिजान्यूशन आफ दि गवर्नमेंट आफ इंडिया, 27 नव० 1893 (जनरल) फाइल न० 95  
सीरियल न० 7

रायल कमिशन आफ दि ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ दि एक्सपेडीचर आफ इंडिया, रिपोर्ट आफ  
खंड 3 और 4 पार्लियामेंटरी पेपर (हाउस आफ कामंस) 1900, खंड 29 सी 130  
और सी 131 (निलबी कमाण्ड)

रणछोडलाल छाटेनाल लैटम आन दि करेंसी प्रश्न (अहमदाबाद 1895)  
सेन, केशवचंद्र लाइफ एंड वकम आफ ब्रह्मानंद केशव प्रेम मुदर वसु द्वारा मकलित,  
(कलकत्ता 1940)

सोस मैटिरियल फार ए हिस्टरी आफ दि प्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, (वर्ष 1957)  
तेलग, के० टी० श्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन फार ऐन इंडियन प्लाइट आफ वू, (वर्ष  
1877) मिलेक्ट राइटिंग्स एंड स्पीचेज (वर्ष 1885) ।

वकील, एम० एच० दि करेंसी प्रॉब्लम इन इंडिया एंड सर डेविड वाररवार, दि गॅंगो

इंडियन, एंड दि रूपी (बंबई 1892)

वाचा, डी० ई० स्पीचेज एंड राईटिंग्स (जी० ए० नटेसन एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित,  
प्रथम संस्करण, मद्रास, तिथिरहित) (स्पीचेज)  
वाडिया, जे० ए० दि आर्टिफिशल कर्सेी एंड दि कामस आफ इंडिया, बंबई, 1902

(ख) पत्र-पत्रिकाए

अमत बाजार पत्रिका, (कलकत्ता) 1870 1905 (ए० बी० पी०) \*

एशियाटिक क्वाटरली रिव्यू, (लदन) 1886 1905

बंगाल मैगजीन, (कलकत्ता) 1873 82

बंगाली, (कलकत्ता) 1890-1905

ब्राह्मो पब्लिक ओपीनियन (कलकत्ता) 1878 1881

कलकत्ता रिव्यू

कनकाड, (कलकत्ता) 1887

डान, (कलकत्ता) 1897 1905

ईस्ट एंड वेस्ट, (बंबई) 1901-1905

हिंदू, (मद्रास) 1880-1905

हिंदुस्तान रिव्यू एंड कायस्थ समाचार (1899 1902) तक कायस्थ समाचार नाम से  
प्रसिद्ध (इलाहाबाद) 1899 1905 (एच० आर०)

इंडिया (लदन) 1890 1905

इंडियन पीपुल (इलाहाबाद) 1903 04

इंडियन रिव्यू (मद्रास) 1901-1905

इंडियन स्पेस्टेटर एंड वायस आफ इंडिया, बंबई 1890-1901, (आर्द० एस० बी० आ०  
आई०)

इंदु प्रकाश, (बंबई) 1883 1895 (छिटपुट प्रतिमा)

जरनल आफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन (लदन) 1867-1895

जरनल आफ दि पूना मावजनिक सभा क्वाटरली (पूना) 1878-1897 (जे० पी० ए०  
एस०)

जरनल आफ दि रायल स्टेटिस्टिकल सामाइटी, 1902, 1911

मराठा, पूना 1881 1905

मुकजी ज मैगजीन, कलकत्ता 1872-1876 (एम० एम०)

\* पत्रिका व तीन विभिन्न संस्करणों में, मुफ्तसिल और विदेश का प्रयोग किया गया है इसकी तिथियां व एक सावधान पाठकों को मिलने वाले अंतर का कारण इन तथ्यों से स्पष्ट हो जाएगा हमारे लिए हमने विवाय और कोई विकल्प नहीं था क्योंकि पत्रिका व कार्यालय में संप्रति पत्रिका के अंक इसी रूप में उपलब्ध हैं इस प्रकार सभी प्रयुक्त तिथियां कार्यालय के संप्रति व हो अनुरूप हैं

- नेटिव ओपीनियन (बवई), 1880-1889 (बिखरी हुई प्रतिपा)
- यू इडिया, (कलकत्ता) 1901-1904 (बहुत सारे सस्करण अप्राप्य)
- रिपोट आफ दि नेटिव प्रेस फार बीजे (साप्ताहिक) 1870-1905 (आर० एन० पी० बव)
- रिपोट आन दि नेटिव प्रेस फार बगाल (साप्ताहिक) 1875 1905 (आर० एन० पी० बग०)
- रिपोट आन दि नेटिव प्रेस फार मद्रास (मासिक और बाद म साप्ताहिक) 1875 1905 (आर० एन० पी० एम०)
- रिपोट आन दि नेटिव प्रेस फार पजाब, नाथ वेस्ट प्राविसेज एंड अवध आदि (साप्ताहिक) 1875 1888 (आर० एन० पी० पी० एन०)
- रिपोट आन दि नेटिव प्रेस फार पजाब (साप्ताहिक) 1888-1905 (आर० एन० पी० पी०)
- स्टेटसमैन, हेमत प्रसाद घोष द्वारा सकलित अखबार की कटिंग
- दि टाइम्स (लदन) (छिटपुट प्रतिपा)
- टाइम्स आफ इडिया, 11 और 18 माच 1896
- वायस आफ इडिया बवई 1883 89 यू सिरीज, 1901 1904 (बी० ओ० आई०)

### गौण स्रोत

- एँस्टे वीरा दि इकोनामिक डेवलपमेट आफ इडिया, (लदन 1949), ततीय सस्करण
- वेडेन पावल, बी० एच० ए शाट एकाउट आफ दि लड रैविंगू एंड इटस ऐडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इडिया विद ए स्कैच आफ दि लड टैयोर (आक्सफोड 1894)
- बागल, जे० सी० हिस्टरी आफ दि इडियन एसोसिएशन 1876 1951 (कलकत्ता, 1953)
- वालफोर लेडी बी० दि हिस्टरी आफ लाड लिटस इडियन एडमिनिस्ट्रेशन 1876 80, (लदन 1899)
- वनर्जी, पी० एन० फिस्कल पालिसी इन इडिया (कलकत्ता 1922) ए हिस्टरी आफ इडियन टक्मेशन (कलकत्ता 1930)
- बैनर्जी, एम० एन० ए नेशन इन मेकिंग, (कलकत्ता 1925)
- बैनर पाल ए० दि पोलिटिकल इकोनामी आफ प्रोय, (इडियन गडिशन, यू दिल्ली 1957)
- बसु बी० डी० दि रूइन् आफ इडियन ट्रेड एंड इडस्ट्रीज, (ततीय सस्करण, कलकत्ता 1935)
- भाटिया, बी० एम० फॉर्मिस इन इडिया 1860 1945, (बवई 1963)
- बाजे फेक्टरी लेबर कमीशन—रिपोट 1885 (बवई)
- बोस, विपिन कृष्ण स्ट्रे थाट्स आन सम इमीडेटस आफ माई लाइफ (कलकत्ता, 1919)
- बुकानन डी० एच० दि डेवलपमेट आफ कपटलिस्टिक इटरप्राइज इन इडिया, (यूवाक, 1934)

- बुक्लड सी० ई० बगाल अडर दि लैपिटनेट गवर्नर 1854-1898, 2 खड (कलकत्ता, 1901)
- चत्रलागी, एच० एल० स्टडीज इन इडियन करेंसी एंड ऐक्सचेंज (बंबई 1931)
- चमनलाल, डी० कुली, दि स्टोरी आफ लेबर ऐंड कॅपीटल इन इडिया, 2 खड, (लाहौर 1932)
- चद्रा, भोलानाथ राजा दिगवर मित्र खड 1 द्वितीय सस्करण 1896, खड 2 (कलकत्ता, 1906)
- चिसने, जनरल जाज इडियन पालिटी (ततीय सस्करण, लदन 1904)
- चौधरी आर० दि इवाल्याशन आफ इडियन इंडस्ट्रीज, (कलकत्ता 1939)
- चितामणि, सी० वार्ड० इडियन पालिसीज सिस दि म्यूटिनी, (इलाहाबाद 1937), 1947 का पुन मुद्रण
- क्लो ए० जी० इडियन फक्टरी लैजिस्लेशन, ए हिस्टोरिकल सर्वे इडियन इंडस्ट्रीज ऐंड लेबर की बुलेटिन स० 37 (कलकत्ता 1926)
- कायाजी, जे० सी० दि इडियन करेंसी सिस्टम 1835 1926 (मद्रास 1930)
- डकोस्टा, जान फॅक्ट्स ऐंड फिन्सीज रिगाडिंग इरिगेशन एज ए प्रिवेंटिव आफ फमिन इन इडिया, (लदन 1878)
- दाम, आर० के० फॅक्टरी लैजिस्लेशन इन इडिया (बर्लिन 1923) दि लबर मूवमट इन इडिया, (बर्लिन 1923), प्लान्टेशन लेबर इन इडिया (बनरत्ता 1931), हिस्टरी आफ इडियन लेबर लैजिस्लेशन, (कलकत्ता 1931)
- डेविम सी० कोलिा दि प्रावन्म आफ दि नाथ वस्ट फटियर, 1890-1908 (ब्रिज 1932)
- डिगरी विलियम 'प्रास्पेरेम' प्रिंटिंग इडिया, (लदन 1901)
- फारस्ट जी० डब्ल्यू० एडमिनिस्ट्रेशन आफ दि मारकिम आफ नसडोन ऐज वायमराय ऐंड गवर्नर जनरल आफ इडिया 1888 1894 (कलकत्ता 1894)
- फ्रेमर लाब्रेट इडिया अडर बजन ऐंड आफ्टर (ततीय मन्वरण, लदन 1912)
- गाडगिल, डी० आर० दि इंडस्ट्रियल इवात्युगन आफ इडिया इन रीसेंट टाइम्स, (चतुथ सस्करण, कलकत्ता 1948)
- घोष, पी० मी० दि डेवलपमट आफ दि इडियन गशनल प्रेस 1892 1909 (कलकत्ता 1960)
- गोपाल, एम० दि वायसरायल्टी आफ लाड रिपन 1880-1884 (लदन 1953)
- गोपालकृष्णन, पी० के० डेवलपमेट आफ इकानामिक आइडियाज इन इडिया 1880-1950, (नई दिल्ली, 1959)
- गुप्ता, जे० एन० लाइफ ऐंड वक जाफ रामेश चद्र दत्त, (लदन 1911)
- हैमिल्टन, सी० जे० दि ट्रेड रिलेगस प्रिन्सिपल इंग्लड ऐंड इडिया (1600-1896), (कलकत्ता 1919)
- गोमथड जान एन० गोपालकृष्ण गंगले, (बनरत्ता 1933)



- मेहता, एम० डी० दि इंडियन काटन टैक्सटाइल इंडस्ट्री, (बंबई 1953)
- मिंटजलेर, लायड ए० दि थयारी आफ इटरनेशनल ट्रेड, ए सर्वे आफ कार्टेम्पररी इकानामिक्स, हारवड एस एलिस, द्वारा संपादित (फिलाडेल्फिया, 1948)
- मिल, जान स्टुअट प्रिंसिपल्स आफ पोलिटिकल इकोनामी (लंदन 1920)
- मिश्र बी० बी० दि इंडियन मिडिल क्लासेज, (लंदन 1961)
- मिथ, बी० आर० लड रैविग्यू पालिसी इन दि युनाइटेड प्रॉविंसेज अंडर ब्रिटिश रूल (बनारस 1942)
- मित्रा, ए० ससस आफ इंडिया 1951 खड-6 वेस्ट बंगाल, सिक्किम और चट्टनगर भाग-1 ए रिपोर्ट (दिल्ली, 1953)
- मोदी, एच० पी० सर फिराजशाह मेहता ए पोलिटिकल बायोग्राफी 2 खडो म (बंबई 1921)
- मौरिसन, थियोडर दि इकानामिक ट्रांजीशन इन इंडिया, (लंदन 1916) 1911 के संस्करण का पुन मुद्रण
- मुर्जी, राधाकमल लड प्रारम्भस आफ इंडिया, (लंदन 1933)
- मुख्तार अहमद फैंक्टरी लेबर इन इंडिया, (मद्रास 1930)
- मुरदोच जान फमिन, फैंक्ट्म ऐंड फैंलेसीज, (तिथि रहित)
- नियोगी, जे० पी० दि इवाल्यूशन आफ इंडियन इनकम टक्स, (लंदन 1929)
- पैसा फड सिल्वर जुवली नंबर (पूना 1935)
- पाल, विपिनचंद्र मिमारीज आफ माई टाइफ ऐंड टाइम, 2 खडो म (कलकत्ता, 1932 और 1951)
- पालेकर, एस० ए० ट्रेड इन इंडिया (बंबई 1944)
- प्रसाद जाई० दुगा सम आसपेंक्टस आफ इंडियन फारेन ट्रेड 1757-1893 (लंदन 1932)
- पिल्लई, पी० पी० इकोनामिक कडीशस इन इंडिया (लंदन 1925)
- प्रधान, जी० पी० और भागवत, ए० वे० लाकमाय तिलक (बंबई 1958)
- पुणेकर, एस० डी० ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया बंबई 1948
- रामगोपाल लोकमाय तिलक (बंबई 1956)
- राव, बी० वे० आर० बी० टैक्मेशन आफ इनकम इन इंडिया (कलकत्ता 1931), एन एस्से आन इंडियाज नेगनर इनकम 1925 29 (लंदन 1939)
- दि नेगनल इनकम आफ ब्रिटिश इंडिया 1931 32, (लंदन 1940)
- राय परिमल इंडियाज फारन ट्रेड मिस 1870, (लंदन 1934)
- रीस जे० डी० दि रियन इंडिया (द्वितीय संस्करण, लंदन 1908)
- रिवाडो, डेविड दि प्रिंसिपल आफ पोलिटिक्स इकोनमी ऐंड टैक्मेशन (एनरीमंम लाइब्रेरी लॉन 1943)
- राल एरिक् ए हिस्टरी आफ इकानामिक थाट सगोहित संस्करण (यूमाक 1947)
- राय पात्रती चरण दि रट क्वेश्चन इन बंगाल (कलकत्ता 1883)

- सायाल, एन डेवलपमेंट आफ इंडियन रेलवेज (कलकत्ता 1930)
- सान्याल, रामगोपाल ए जनरल बायोग्राफी आफ बंगाल सिलिव्रिटीज, (कलकत्ता 1889)
- शास्त्री, शिवनाथ मेन आई हैव सीन (कलकत्ता 1919)
- सेन, अमित नोट्स आन दि बंगाल रिनोसिया (द्वितीय संस्करण, कलकत्ता 1957)
- शाह के० टी० सिक्सटी इयस आफ इंडियन फाइनांस (बंबई 1921)
- शाह, के० टी० और सभात के० जी० वेल्थ ऐंड टैक्सबल कैपसिटी आफ इंडिया (बंबई 1924)
- शिलवकर, के० एस० दि प्राब्लम आफ इंडिया (लंदन 1940)
- शिरास, जी० एफ० पावर्टी एंड किंडड इकोनामिक प्राब्लम्स इन इंडिया (1935 तृतीय संस्करण)
- सिंह, हीरालाल प्राब्लम्स ऐंड पालिसीज आफ दि ब्रिटिश इन इंडिया 1885 1898 (बंबई 1963)
- सीतारमया, बी० पट्टाभि दि हिस्टरी आफ दि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 1935 (मद्रास 1935)
- स्पियर, परसीवल इंडिया, ए माडन हिस्टरी (ऐन आवर 1961)
- स्टेटिस्टिकल ऐब्स्ट्रैक्ट फार ब्रिटिश इंडिया फ्राम 1891 2 टु 1900-01
- स्टोक्स, एरिक दि इंग्लिश युटिलिटेरियन ऐंड इंडिया (आक्सफोर्ड 1959)
- स्ट्रैची जान और स्ट्रैची रिचर्ड दि फाइनासेज ऐंड पब्लिक वक्स आफ इंडिया फ्राम 1869 टु 1881 (लंदन 1882)
- ए० गुप्त (सपा०) स्टडीज इन दि बंगाल रिनेमा (कलकत्ता जादवपुर 1958)
- सहमकर डी० बी० लोकमान्य तिलक (लंदन 1956)
- थाम्प्रसन ई० और गैरेट जी० टी० राइज ऐंड फुनफिलमेंट आफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया (लंदन, 1935)
- थामस, पी० जे० ग्रीय आफ फेडरल फाइनांस इन इंडिया (मद्रास 1939)
- थानर, डेनियल इन्वेस्टमेंट इन एपायर (फिलाडेल्फिया 1920)
- तिवारी, आर० डी० रेलवेज डा माडन इंडिया (बंबई 1941)
- वकील, सी० एन० और मुराजन एस० के० करेंसी ऐंड प्राइमेज इन इंडिया (बंबई 1927)
- वकील, सी० एन० फाइनेशियल डेवलपमेंट्स इन माडन इंडिया (बंबई 1925)
- वाडिया, पी० ए० और मर्चेन्ट के० टी० अवर इकोनामिक प्राब्लम (द्वितीय संस्करण बंबई 1946)





## अनुक्रमणी

अन्तर्देशीय उद्योगिक अर्थशास्त्र, 313	220, 263 286 291, 292, 294,
अन्तर्देशीय व्यापार के अर्थशास्त्रीय मीट्रिक गिदाय, 249	295, 301, 319 321, 370, 387,
अन्तर्देशीय श्रम सम्मेलन 297	391, 399, 404 405 443, 446,
अन्तर्देशीय मन्त्रसभा की सम्मेलन, 608,	457 457 458 460 462, 464,
610, 611	466 467 472 479 513 530,
अन्तर, 14, 513	531 532 544, 576 582 592,
अन्तर, 14 22, 23, 139, 140 171	596 609 615 639 660
173, 213 257, 391, 451, 515	अन्तर सम्मेलन 464
534 574, 577, 592	अन्तर जी० मुद्रास्तर, 9 86 93, 126
अन्तर्देशीय व्यापार, 96 155 457	128, 133 141 158 159 160,
अन्तर्देशीय व्यापार, 101, 409	161, 164 165, 250 286, 305,
अन्तर्देशीय शौचालय, 291	316, 323 324, 364, 419 542,
अन्तर्देशीय हिन्दू, 403	576, 588, 636 639, 641, 642,
अनुप्राय प्राप्त धीरी, 211, 212, 213,	645, 648, 671
215	अन्तर्देशीय, 203 292
अन्तर्देशीय मुद्रा, 195, 421, 602	अन्तर्देशीय बिल, 398
अन्तर्देशीय श्रम, 478, 481	अन्तर्देशीय शौचालय दारी पद्धति, 365
अन्तर्देशीय राजस्व, 478, 479, 480, 481	अन्तर्देशीय पत्र, 139 389, 403
482	अन्तर्देशीय रेंट लेख, 402
अन्तर्देशीय व्यापार विरोध सच, 478, 481	अन्तर्देशीय श्रम और उत्प्रेषण बिल, 314, 315,
अन्तर्देशीय सभा, 479	317
अमृतवाजार पत्रिका, 3, 48, 100, 101,	आन्तरिक, जी० जी०, 291, 396
132, 138, 171, 197, 209, 212,	आधुनिक राष्ट्रीय आन्दोलन, 665
	आन्तर्देशीय पत्रिका, 102, 3

- 480  
 आबकारी नीति, 475  
 आयगार, बी० आर, चन्वर्ती, 457, 458,  
 आयकर, 15, 16, 450, 453, 455, 456,  
 457 458, 459, 461, 462, 472,  
 474 669  
 आयकर बिल, 456  
 आयात शुल्क 194, 196, 197, 202,  
 203, 204 207, 220, 471, 669,  
 आर्थिक आंदोलन, 663, 672  
 आर्थिक राष्ट्रीयतावाद का युग, 665  
 आर्थिक साम्राज्यवाद, 666  
 आय जन रूपालिनी, 101  
 आयोदय, 102  
 इंग्लिश फैक्टरी कानून, 296  
 इंडियन एसोसिएशन, 213 261, 309,  
 310, 311, 395 450, 459 518,  
 इंडियन कर्सेसी एसोसिएशन 247, 265,  
 इंडियन कौंसिल अधिनियम, 542  
 इंडियन टैरिफ बिल 220  
 इंडियन डेली मेल, 403  
 इंडियन नेशनल एसोसिएशन, 101  
 इंडियन पार्लिमेंट, 443  
 इंडियन पीपुल, 91  
 इंडियन पार्लियामेंट एसोसिएशन, 537  
 इंडियन फ़ैक्टरी ऐक्ट, 290, 292, 295,  
 297, 298 303  
 इंडियन माइंस ऐक्ट, 303  
 इंडियन माइंस बिल, 302, 317  
 इंडियन सोशल रिफ़ॉर्मर, 523  
 इंडियन एमिग्रेशन बिल, 309  
 इंडिया कौंसिल 534  
 इंडिया लीग, 62  
 इंदु प्रकाश, 99 158 174, 212, 292,  
 299, 300, 305, 363, 454, 457,  
 462  
 इपीरियल अखबार, 101  
 इपीरियल लैजिस्लेटिव कौंसिल, 140,  
 212, 213, 293, 443, 515, 537,  
 540, 542, 543, 545  
 ईडन, एशले, 397  
 ईस्ट इंडिया कंपनी, 54, 93, 153, 193,  
 205, 350, 369, 523, 575, 586,  
 602  
 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 196, 573,  
 741  
 उग्रवादी दल, 3  
 उग्रवादी नेता, 612  
 उत्तर पश्चिम की महलवादी पद्धति, 365  
 उत्तर पश्चिम प्रांतीय लगान अधिनियम,  
 402  
 उत्पादन शुल्क, 15, 204, 205, 210,  
 453, 460 474  
 उत्पादन शुल्क की राष्ट्रीय प्रतिक्रिया,  
 210  
 उद्योग सिद्धांत, 612, 613  
 उन्मुक्त व्यापार, 193, 195, 212  
 उन्मुक्त व्यापार के सिद्धांत, 193, 218  
 उपकाशकारी, 400, 401 402  
 उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था, 666  
 ऊचा बराधान, 16, 87, 518, 611 669  
 एटकिंसन फेड० जे० 7, 14  
 एमिग्रेशन ऐक्ट, 310, 311  
 एलगिन, लाड 152, 157, 163, 203  
 एलोट, सर चार्ल्स, 7  
 ऐंड्रयूज सेंट, 18  
 औद्योगिक पूजा, 95  
 औद्योगिक पूजापति वग, 306,  
 औद्योगिक पूजावाद 288, 671  
 औद्योगिक पूजावादी अर्थव्यवस्था, 642  
 औद्योगिक संघ, 67  
 औद्योगिक सम्मनन, 67

- कपास आयात कर, 195, 196, 197, 198,  
 199  
 कपास और चीनी पर शुल्क मन्दी सरकारी  
 नीति, 193  
 कपास कर का पूरा निवृत्तन, 197, 200  
 कपास कर के निवृत्तन का विरोध, 197,  
 198  
 कपास शुल्क, 194, 202, 203, 211,  
 251  
 कपास शुल्क बिल, 209  
 कपास सीमा शुल्क, 108, 482  
 कदवा, सोराबजी, 266  
 कजन, लाड, 7, 12, 22, 51, 82, 86, 87  
 91, 93, 94, 160, 163, 174, 175,  
 216, 217, 219, 315, 351, 360,  
 361, 364 365, 367, 368, 520,  
 614  
 करदाता, 454  
 करनोमदार पट्टेदार, 403  
 कर्वे, डी० जी०, 637  
 कराची सिध समा, 518  
 कराधान, 60, 446, 447, 449 450,  
 452, 457, 458, 460, 462, 467,  
 471, 512, 513, 515, 541, 577,  
 614, 667  
 करेसी कपटी, 253  
 काटन, हेनरी, 314  
 कायस्थ समाचार, 171, 323, 544  
 कार्नवालिस, लाड, 364  
 काले ए० डी०, 67  
 काले, वे० वी०, 106  
 काले, वी० जी०, 218  
 कास्तकारी कानून, 394, 396 401  
 किचनर, लाड, 524  
 किचनर कजन मतभेद, 524  
 किसान जनसभाए, 396  
 किसान सघ, 396  
 किसान मन्थन राष्ट्रवादी नेता, 401  
 किसानो की किजूलखर्ची, 21  
 किसानो के मोरुमी हक, 393  
 केन डब्ल्यू० एम०, 480, 536  
 केनेडी प्रिंगल 468, 473  
 केरल चद्विवा, 403  
 केरल सचारी, 403  
 कॅस, जे० एम० 245  
 केमर ए-हित 172, 260, 316, 391,  
 459  
 केसरी, 5 208, 305, 316, 358, 405,  
 419, 442 446, 465, 471, 519,  
 530, 531  
 कोयला खातो के श्रमिक, 302  
 क्रयशक्ति, 17  
 क्लासिकी अथव्यवस्था, 640, 644  
 कपडे, जी० एस०, 474  
 खरे, डी० ए०, 410  
 खा दोख राजा हुसैन, 363  
 खादी आंदोलन, 108  
 खान उद्योग 302, 304  
 खान कानून 304  
 खासिम उल अखवार 208  
 खेतिहर वर्ग, 6, 12 13, 16, 53, 349,  
 352, 353 355, 397, 406 408  
 409, 449  
 खोसले, जी० वे०, 205  
 गागुली, द्वारिकानाथ, 310 311, 396  
 गांधी, महात्मा, 58, 466  
 गांधी युग की राष्ट्रीयता, 618  
 गुजरात दण, 263  
 गुजरात मित्र 459  
 गर खेतिहर जमींदारी, 408  
 गर मोरुसी किसान, 393, 394, 398, 399,  
 400

- शेखरे, गोपालकृष्ण, 12, 13, 14 97,  
133, 152, 210, 252, 254, 256,  
257, 262, 263, 410, 411, 412,  
413, 443, 444, 448, 450, 451,  
452 466, 470 471, 514, 516,  
519, 522, 523, 525 528,  
531, 538, 539, 542, 543, 544,  
546, 576, 589, 590, 596, 604,  
618, 660 664 671
- ग्रामीण ऋणग्रस्तता, 404, 409, 411,  
412 541
- ग्रामीण ऋणदाता साहूकार, 404
- ग्रामीण बजदार, 404, 405
- ग्रामीण दरिद्रता, 413
- ग्रेट इंडिया पेनिमुला रेलवे कपती,  
153
- ग्लडमन 199
- घाघ, एन० एम०, 671
- घाघ, एस० के०, 291, 481, 664
- घोष, जार्जेंद्रचंद्र, 310
- घोष, मोतीनाथ, 132, 291, 362, 530,  
664
- चंद्र, मोतानाथ, 2, 133, 135, 199,  
200
- चंद्रावरकर एन० जी०, 205, 208
- चटर्जी वर्त्मचंद्र, 389
- चमननाथ, डी०, 290
- चंचिल, लाइ रडोल्फ, 527, 616
- चारी चंद्र शुक्ल, 220
- चासंनर, लाट 244
- चातुर्वर्ण व्यवस्था, 65
- चाय उद्योग, 308
- चाय बागान, 306, 307, 308 310,  
311 312, 313, 314
- चाय बागान श्रमिक, 310
- चाय बागान म मत्यु की ऊंची दर, 312
- चारलू, पी० आनंद, 209, 216, 307,  
317
- चितामणि, सी० वाई०, 458
- चिसानी, जनरल, 445, 665
- चीनी शुल्क, 213, 214, 216, 217
- चीनी शुल्क अधिनियम, 215, 216 217  
218
- चीनी शुल्क के विरोधी, 213
- चीनी शुल्क सशोधन अधिनियम, 218
- चीनी शुल्क के समयक, 214
- चुमीकर, 208
- चुकदर चीनी का आयात, 211
- चैपमैन, जान, 157
- चौधरी, जे०, 104
- छोटे किसान तथा मजदूर, 12
- जनता पार्टी निधि, 67
- जन प्रस्ताव पत्र, 99
- जनसंख्या की वृद्धि, 19 20
- जमींदारी तथा रयतबारी पट्टे, 362
- जमींदारी विरोधी विप्लव, 392
- जरनल आफ पूना सावजनिक सभा, 1, 4  
351, 402, 468
- जामे-जमगेद, 292, 321
- जोशी, जी० बी०, 2, 9, 14 19, 20 21,  
53, 55, 63, 67 90, 92, 93, 97,  
99, 128, 132 133 136 137, 156  
158, 159, 161, 162, 165, 166,  
169, 170, 171, 351, 356, 357,  
390, 391, 413, 418, 443, 446,  
448, 449, 451, 458, 459, 460,  
464, 465, 466 467, 468, 469,  
470, 471, 472, 473, 514 516,  
518, 525, 530, 537, 542, 576,  
579 588, 589, 590, 596, 638  
640 641, 643, 644, 645, 648  
660, 664

- टाइम्स आफ इंडिया, 113, 299, 351  
 टाटा जे० एन०, 62, 266, 450  
 टगोर, जिनेंद्रमोहन, 474  
 टैगोर, सुरेंद्रनाथ, 320  
 ट्रिब्यून, 212, 466  
 ठाकरसी, बी० डी०, 254, 266  
 ठेका पद्धति, 476  
 डफरिन जाच, 18  
 डफरिन, लाड, 6, 465, 472, 613  
 डलहौजी, लाड 154, 581  
 डाक कर 15  
 दान, 411, 417  
 डिगबी, विलियम, 7, 671  
 ढाका प्रवास, 402  
 तिल्वत अभियान, 521  
 तिलक, लाकमाय, 5, 66, 67, 103, 104,  
 158, 210, 292, 319, 349, 357,  
 364, 396, 419, 465, 481, 512,  
 514, 519, 531, 538, 612, 660,  
 671  
 तैलग के० टी०, 66, 291, 448, 638  
 645 646 647  
 तोहफा ए हि, 403  
 यामस, पी० जे०, 361  
 दयन ऐग्रीकलचरिस्ट बिल, 407  
 दकन मभा 410  
 दक्षिण के खेतिहरो के दगें, 349  
 दक्षिण भारत की रैयतवारी पद्धति, 365  
 दत्त, आर० सी०, 2, 3, 52, 128, 132,  
 139, 142, 168, 172, 173 200,  
 205 241 247, 248, 256, 257,  
 259, 305, 311, 316, 349 351,  
 355 356 359 360, 361, 365  
 366, 368 369, 389, 390 397,  
 448, 458, 479, 544, 575, 579  
 580 583 584, 591, 594, 605,  
 614, 515, 638, 648, 649, 660,  
 664  
 देशमुख, गोपालराव, 98  
 देसाई, अवालाल, शबरलाल, 254, 266  
 देसी तिजारत कंपनी, 66  
 दैनिक ओ समाचार चद्रिवा, 158, 203  
 नडी, एल्फेड, 14  
 नवदूरी जमीदार, 403  
 नमक कर, 15, 450, 453, 456, 458,  
 460 463, 464 465, 466, 467,  
 468 469, 471, 472, 473, 474,  
 542, 669  
 नमक कर विरोधी आंदोलन, 470  
 नमक पर कराधान की पद्धति, 463  
 नया मजदूर वग, 325  
 न्याय सुधा 402  
 न्यू इंडिया, 3, 312, 322, 323 458,  
 460 640  
 नवविभाकर 399, 401  
 नशाबन्दी 476  
 नसीमे आगरा 101, 403  
 नाइटिंगेल प्लारेंस, 394  
 नातु, बी० आर०, 364  
 नामजोशी, एस० बी० 67, 102  
 नायर त्रिचौलि, 403  
 नाथजुक्, लाड, 195  
 निकासीवाद, 597, 618  
 निकासी सिद्धांत, 572, 573, 574, 575,  
 576 584, 591 594, 597, 598,  
 599, 602, 604, 605, 606, 607,  
 608 609, 612, 615, 616, 617  
 निजी पूजी का निवेश 355  
 निरवशतावाद 664  
 निधनता का औद्योगिक सिद्धांत, 611  
 निर्यात व्यापार 17  
 निश्चय पत्रिका, 99

- नुलवर, राव बहादुर के० एल० 198  
 नेटिव ओपीनियन, 99, 101, 165, 173,  
 292, 293, 299, 305, 418, 573  
 नेशनल लिबरल फेडरेशन, 575  
 नैयर, सी० शकरन, 528  
 नेट्स, एल० सी० ए० 597  
 नौरोजी, दादाभाई, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9,  
 15, 17 65, 84, 88, 89, 90 92,  
 106, 128, 130 131, 138 142  
 158, 160 247, 249, 252, 253,  
 258, 259 261, 265, 290, 305  
 306, 444, 447, 448, 449, 451  
 458, 463, 468, 477, 479  
 481, 512, 514, 516, 522, 523  
 526, 528, 530, 532, 535, 536  
 544, 572, 573, 575, 577, 578,  
 579, 581, 582, 584, 585, 586,  
 587, 588, 589, 590, 591, 592  
 593 594, 596, 603, 606,  
 607, 608, 609, 610, 615, 616,  
 618, 660, 664, 671, 674  
 पंजाब एलिनेशन ऐक्ट, 488 410  
 पंजाब काश्तकारी अधिनियम, 402  
 पंजाब भूमि सन्मण विल, 409  
 पतुलु, वी० एस० 464  
 पराजय एस० एम०, 527  
 पटमन, 59  
 पट्टेदारी पथा, 362, 366, 416, 668  
 पबना दगें, 349  
 परिवहन शक्ति, 158 159  
 परोक्ष बराधान, 349  
 पाश्च, मर जाज, 83  
 पारिव गोकुलदास के०, 351, 410  
 पाल त्रिस्तोत्रस, 394 463  
 पाल विपिनचंद्र 3 82, 85 312, 317,  
 332 612 640, 671  
 पिट्स ऐक्ट, 367  
 पिल्लई, पी० रत्न सभापति, 403  
 पूजी की विकास, 662  
 पूजीनिष्ठ कारखाना पद्धति 305  
 पूजीपतीय औद्योगिकता, 326  
 पूना वैभव, 102  
 पूना सावजनिक सभा, 2, 58, 97, 99,  
 169, 198, 202, 261, 292, 293,  
 407, 410, 450 455, 516, 518,  
 596  
 पेटिट, दिनशा, 472 473, 474  
 पैसा अखवार, 101, 104  
 पैसा निधि, 66, 67  
 प्रभाकर, 98  
 प्रतिव्यक्ति जाय, 13  
 प्रथम औद्योगिक सम्मेलन, 614  
 फडवे का विद्रोह, 349  
 फडवे, चामुदेव, 99  
 फाउलर कमेटी, 1५8, 247  
 फाउलर, हेनरी, 3, 245, 445  
 फाकड, बालाजी रामचंद्र, 290  
 फ्रेजर, 361  
 दगवासी 9, 7, 102, 137 203, 210,  
 219, 389, 399, 402  
 दगल का रेंट ऐक्ट, 368  
 दगल का विभाजन 98  
 दगल काश्तकारी बानून, 392, 416  
 दगल की जमींदारी पद्धति, 365  
 दगल के म्याई बदावस्त, 361, 365  
 दगल बैंकिंग निगम, 66  
 दगल में बिसान संगठन 391  
 दगल में श्रमिकी आन्दोलन, 98  
 दगली, 91, 128, 161 199, 200 201,  
 207, 212 251, 257, 291, 292  
 301, 305, 309, 310 311, 315,  
 380, 391, 395, 396 399, 401,





- 367, 388, 405, 443, 446, 448, 451, 457, 461, 464, 465, 468, 476, 515, 516, 519, 522, 526, 530, 535, 536 538, 539, 540, 544 545, 576, 582, 596, 610, 611 613 615, 646
- भारतीय राष्ट्रीयतावाद, 3, 615, 617, 618, 669
- भारतीय राष्ट्रवादी नेता, 5, 65, 83, 152, 204, 306, 307, 309, 310, 322, 390, 398 402 404, 445 449, 476, 477 512, 540, 634, 660, 661, 701
- भारतीय रेथ पथ का विकास, 155
- भारतीय विनियम, 242
- भारतीय श्रमिक आयोग, 322
- भारतीय श्रमिक की उत्पादकता, 306
- भूमि का स्थाई बदावस्त, 651
- भूमि लगान सिद्धात, 612
- भूमि की पट्टेदारी, 350
- भूराजस्व, 350, 351, 352, 359, 644
- भूराजस्व नीति 407, 614
- मजदूर महिलाएं, 288
- मदिरा उत्पादन शुल्क, 476
- मदिरा की खपत, 475
- मद्रास बागान श्रम अधिनियम, 315, 316
- मद्रास महाजन सभा, 516, 518
- मधोलकर, आर० एन०, 60, 134
- मराठा, 101, 104, 105, 170 171, 172 201, 208, 210 212, 220 248, 256, 259 291, 300, 302, 305, 319 320, 321, 363, 387, 389, 392 396, 397, 407, 412, 410, 457, 462, 466 472, 527, 530 639, 660
- मलाबारी, एस० एम० 458
- मसानी, आर० पी०, 615
- माचेस्टर, 100, 101, 102, 105, 194, 200, 202, 204, 207, 306, 472 513
- माचेस्टर वाणिज्य सदन, 196, 199, 289
- माडलिक, वी० एन०, 291, 456, 531
- मालवीय मदनमोहन, 66 101, 209, 448, 458, 461, 473, 515, 576, 671
- माल्यस सिद्धात, 19
- मारिशस, 211, 212, 214, 215, 216 217
- मिल, जान स्टुअट, 647
- मिश्र, के० के०, 105, 311, 396
- मिश्र, वी० आर०, 361
- मिश्रित पूजी समुदाय, 61, 66
- मित्र, नवगापाल, 99
- मित्र, राजा दिगवर, 463
- मित्र, विश्वनाथ नारायण, 99
- मुखर्जी, आगुतोप, 459
- मुखर्जी, तारापद, 66
- मुखर्जी, प्यार मोहन 394 472, 474
- मुखर्जी, रगलात, 396
- मुखर्जी सतीशचद्र, 58, 324, 325, 326, 411, 417
- मुद्रा अधिनियम, 246, 254
- मुद्रा नीति, 256
- मुद्रा परिवर्तन, 241, 249, 252, 256, 257, 258
- मुरलीधर, लाना, 102, 140, 405
- मेनन, के० पी० करुणाकर, 389
- मेयो, लाड, 445
- मेहता, पी० एम०, 410
- मेहता, फिरोजशाह, 60 193 208, 213, 291, 320 411 513 515 531 537, 539, 618, 671

- मेकाले, 527, 606, 664  
 मेंसी, डब्ल्यू० एन०, 154  
 मोटे कपड़े पर कराधान का भारतीय  
 लोकमत पर प्रभाव, 205  
 मोदवृत्त, 102, 106, 158  
 मोपला विद्रोह, 389, 403  
 मोरिसन, थियोडोर, 593, 597, 598  
 मोरूसी हक, 394, 395, 398, 399, 400,  
 402, 417  
 मोरूसी हकदार किसान, 401  
 मग बगाल, 445  
 यात्रिक भौतिकवाद, 670  
 यूरोपीय पूजावाद, 658  
 रसडन, आर० डी०, 466  
 राषवाचारी, सी० विजय 403  
 राजस्व के स्थाई बढोवस्त, 360  
 रानाडे महादेव गोविंद, 2, 53 54, 56,  
 57, 60, 64 66 90, 91 93 94,  
 95 99 136 141 158, 169,  
 198 212, 214, 216, 217, 218  
 246 290 304 351 352, 355,  
 356, 357, 359, 362 390 407  
 411, 413 414, 415, 416 417,  
 446 481, 575 595, 596, 605  
 612 614 616, 636, 637 638  
 639, 640 641, 642 644 645  
 664 671  
 राय, पी० सी०, 213, 216, 364, 368,  
 390 418, 450, 527 576 579  
 638  
 राष्ट्रीय अर्थशास्त्री, 60, 449  
 राष्ट्रीय आंदोलन, 11, 56, 93, 201,  
 208 209 211 217, 314 317  
 361, 473 477, 529 572, 578  
 664, 668, 671 672 673  
 राष्ट्रवादी समाचार पत्र, 311, 320, 388,  
 399, 457, 461, 462, 605, 606  
 रास्त-नोपतर, 99, 291, 573  
 रिकार्डियन सिद्धांत, 354  
 रिकार्डो, 638  
 रिपन, लाड, 96, 128, 155, 168,  
 200, 201, 366  
 रीस, जे० डी०, 349, 361, 617  
 रेल उद्योग, 162  
 रेल नीति, 161, 175  
 रेल प्रवर समिति, 165  
 रेलों का घातक प्रभाव, 158  
 रेलों के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण, 175  
 रेलवे का निर्माण, 55, 152, 154, 163  
 163 164, 168, 170  
 रयतबारी इलाके 388 391, 644  
 रयतबारी पट्टेदारी, 363, 369  
 रयतबारी पद्धति, 358, 362, 363, 369  
 369 416  
 लकाशायर, 101, 102, 105 107, 108  
 194 198 202 203 204, 205  
 294 295, 296, 301, 304 305  
 लदन डेली नानिक्ल, 450  
 लगान 353 392  
 लगान का स्थाई बढोवस्त, 369  
 लगान मनाही आंदोलन, 358  
 लगान सघ, 396  
 लाइसेंस कर 453, 454, 455, 457  
 लाजपतराय, लाला, 66, 611, 671  
 लायल दुर्भिक्ष आयोग, 12  
 लारेंस जान, 155  
 लिटन, लाड, 195, 196  
 लड रैवेयू अमेडमट  
 लसडौन लाड, 19, 1  
 लोकवम घुल्व, 459  
 लोवनाथन, पी०  
 लोखड, 296, 297

## 700 भारत मे आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास

- वकील, सी० एन०, 452
- वसु, राजनारायण, 99
- वाचा, टी० ई०, 66, 107, 108, 128, 130, 158 161, 174, 204 206, 246, 247, 251, 254, 255 257 264, 321, 322, 443 467 468, 512, 516, 518, 519, 520 529 538 543, 576 579, 588 589, 592 660, 671, 674
- वाडिया, जे० ए०, 266
- वायस आफ इडिया, 456
- वित्ते, एम० डी०, 419
- विदेशी पूजी, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92 93 581 582 600, 601 669
- विदेश व्यापार, 16, 127 128, 129, 130, 138 157 242, 255 667
- विदेशी सामान का बहिष्कार, 211
- विनायक, देवराव 417
- विनिमय क्षतिपूर्ति भत्ता, 259, 260, 261, 262, 263 264
- विनिमय मे गिरावट, 243, 244, 245, 250, 267
- विलवी बन्धीगन, 17, 514, 516, 523, 533 536 538 540 542, 544 546, 586 589 590, 604 606 608
- विलवी लाड 586, 587, 605, 608, 610
- वेंटरमन, जी० 403
- वेडरबन, विलियम, 536, 671
- वेन्टलड, जेम्स 204, 443, 464, 469, 541
- वाह, वे० टी० 360
- मजीबनी 102, 105, 310 311, 313, 317 458 462 472 480
- सरक्षित पट्टेदारी, 414
- ससदीय प्रवर समिति, 155, 157
- सखाराम, राघव, 290
- समभौतावादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 665
- सयानी, आर० एम०, 171, 448
- सड्क शुल्क, 459
- सरकारी रेल नीति, 164, 165
- सहचर, 158, 166, 170, 196, 201, 456
- साधारणी, 399
- सामती अधदास, 415
- साहूकारी पूजी, 95
- सिचाई वाय, 171, 172, 173, 174
- सिचाई आयोग, 174
- सिगनल बमधारियो की हडताल, 318, 319
- सिन्हा शचीन्द्रनाथ, 91
- सिलेक्ट बमेटी, 468, 574
- सीमा शुल्क, 15, 16, 195, 204, 453, 467 482, 666
- सीमा शुल्क नीति, 648 649, 663
- सुरभि पताका, 301
- सूती कपडा उद्योग, 84
- मूदखार, 400
- सैनिसबरी, लाड, 193, 194, 195, 196
- सामप्रकाश, 291, 389, 391, 458 480
- स्टुअट जान, 138, 210
- स्याई बंदोयस्त पद्धति, 350, 359, 360 361 362 363 364 365 366 367, 368, 369 370 371, 391 392 393 397, 668
- स्वदेशी आंदोलन, 98, 101, 102, 103, 104 105 106 107, 108, 310 311, 313 317 671
- हटर, सर डबल्यू०, 7

- ह्यूम, ए० बी०, 663, 671  
 हस्तशिल्प उद्योगों का ह्रास, 52  
 हार्टिगटन, लाड, 196  
 हार्डिंग, लाड, 153  
 हावर्ड, एम० एफ०, 83  
 हितवादी, 139, 303, 319, 402, 462  
 हिंदुस्तान, 96  
 हिंदुस्तान रिब्यू, 171, 323, 544  
 भारत सरकार से रियायती दर पर प्राप्त बागज इस पुस्तक में इस्तेमाल किया गया है
- हिंदुस्तानी, 319, 403, 649  
 हिंदू, 90, 91, 171, 212, 248, 301, 305, 318, 319, 353, 403, 455, 457, 460, 462, 464, 472, 479, 480, 520, 531, 532  
 हिंदू पंच, 102, 203  
 हुसैन, सज्जाद, 389  
 हैमिल्टन, जाज, 1, 12, 252, 660, 665



